

संविधानों की दुनियां

The World Constitutions : UK, USA,
Switzerland, USSR & Japan

Dr PRABHU DUTT SHARMA

M. A. (Pol. Sc. & History) Ph.D. (U.S.A.)

M.P.A. (Pub. Adm.) (U.S.A.) Gold Medalist

Reader, Department of Political Science

University of Rajasthan, JAIPUR

COLLEGE BOOK DEPOT

JAIPUR-2

कलिंग बुक डिपो, जयपुर-२

सर्वाधिकार सुरक्षित
संस्करण 1971-72

बालदेव दिग्गज बीरन दिग्गज एव
रमणीय दिग्गज जयपुर में प्रकाशित

छूसरे सस्करण की भूमिका

सविधानों की धुनियाँ एवं पाठ्य-पुस्तकें के रूप में अपना स्थान बना सकी इसकी हमें प्रसन्नता है।

प्रस्तुत सस्करण अपने सशोधित एवं परिवर्द्धित रूप में अधिक उपयोगी, रोचक एवं ज्ञानवद्ध क सिद्ध होगा ऐसी हमें आशा है।

बिन पाठको ने हमें समय-समय पर अपने सुझावों से लाभान्वित कर इस सस्करण को सुधारने में हमारी सहायता की उनके हम कृतज्ञ हैं।

लेखक

प्रावृत्त्यन्त

प्रस्तुत प्रकाशन राजनीति विज्ञान के एक बहुवर्षीय एवं पुराने परम्परागत विषय पर होते हुए भी एक ऐसा प्रयास है जो कई दृष्टियों से नया है और इसीलिये शायद उपयोगी भी। पाठ्य-पुस्तकों की दुनियाँ भी दुनिया के अन्य सभी पहलुओं की तरह प्रतिद्वन्द्वारम्भ है और शाश्वत विकासशील भी। यतः पुराने क्षेत्र में प्रयुक्त हर नये प्रयास का अपना एक मूल्य है और अपना एक विशिष्ट रथान।

उक्त भावना से अनुप्राणित प्रस्तुत रचना विद्यार्थी-जगत को संविधान की नई-पुरानी विधाओं से परिचित कराने के साथ-साथ उन्हें विश्लेषित एवं मूल्यांकित करने के लिये कुछ नये मान उपस्थित करती है। सामग्री का समीचीनता विवेचन की सरलता एवं नये दृष्टिकोणों से मविधानों को देखने पहिचानने एवं सोलने का यह प्रयास विद्यार्थियों को विषय के प्रति एक जिज्ञासा एवं रुचि दे सके इसकी यथामम्मव निष्ठा से चेष्टा की गई है।

आशा है विद्यार्थी-जगत इस प्रयास का स्वागत करेगा। पुस्तक के प्रणयन में जिन मानक ग्रन्थों से सहायता ली गई है उनके विद्वान् लेखकों के प्रति आभार ज्ञापित करना एक औपचारिकता न होते हुए सच्ची प्रसन्नता है।

लेखक

अनुक्रम

ब्रिटेन का संविधान

1	ब्रिटिश संविधान का विकास व स्वरूप (Growth and Nature of the British Constitution)	3
2	अभिसमय श्रवण वधानिक परम्पराएँ (Conventions of the Constitution)	36
3	राजा तथा राजमुकुट (The King and the Crown)	48
4	प्रिवी परिषद् एवं मन्त्रिमण्डल (The Privy Council and the Cabinet)	71
5	प्रधानमन्त्री (The Prime Minister)	97
6	लोकसेवा (The Civil Service)	108
7	संसद् (The Parliament)	119
8	राजनीतिक दल (Political Parties)	166
9	कानून और न्याय (Law and Justice)	181
10	स्थानीय स्वायत्त (Local Self Government)	199
	Questions	215
	Selected Readings	221

अमेरिका का संविधान

1	अमेरिका के संविधान का विकास व स्वरूप (Growth and Nature of the Constitution of the U S A)	3
2	अमेरिका की संघ व्यवस्था (The American Federal System)	19
3	विधान मण्डल (कांग्रेस) (The Legislature)	26
4	राष्ट्रपति (The President)	57
5	अमेरिका की न्यायपालिका (The American Judiciary)	87
6	राजनीतिक दल (Political Parties)	99
7	राज्य सरकारें (The State Government)	108
8	स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)	119
	University Questions	125
	Select Readings	128

स्विट्जरलैण्ड का संविधान

1	स्विट्स संविधान का विकास व स्वरूप (Growth & Nature of the Swiss Constitution)	3
2	स्विट्जरलैण्ड की संघीय व्यवस्था (The Swiss Federal System)	14
3	स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका (The Swiss Legislative)	21
4	स्विट्जरलैण्ड की कार्यपालिका (The Swiss Executive)	33
5	स्विट्जरलैण्ड की न्यायपालिका (The Swiss Judiciary)	47

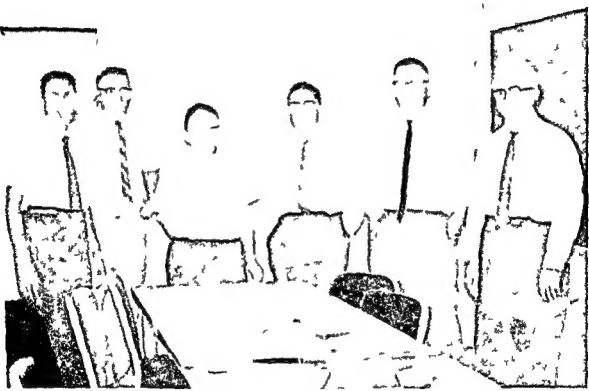
6	स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दल (Political Parties of Switzerland)	
7	प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (Direct Democracy)	62
	Exercises	76
	Select Readings	79

सोवियत रूस का संविधान

1	रूस के संविधान का विकास व उसकी विशेषताएँ (Growth and Salient Features of the Russian Constitution)	3
2	सोवियत सघात्मक व्यवस्था (Soviet Federalism)	17
3	नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं दत्तक्य (Fundamental Rights & Duties of Citizens)	24
4	रूस की सर्वोच्च सोवियत (The Supreme Soviet of the U S S R)	35
5	रूस का प्रेसीडियम (The Presidium of the U S S R)	43
6	रूस की मन्त्रि-परिषद् (The Council of Ministers of the U S S R)	47
7	रूस की न्यायपालिका (The Soviet Judiciary)	53
8	अंगीभूत इकाइयों का शासन (Administration of Federating Units)	66
9	रूस की सोवियत प्रणाली (The Soviet System of the U S S R)	71
10	रूस का साम्यवादी दल (The Communist Party of the U S S R)	76
11	रूस में प्रजातन्त्र (The Democracy in the U S S R)	87
	Exercises	93
	Select Readings	96

जापान का संविधान

1	जापान के संविधान की विशेषताएँ (Salient Features of the Japanese Constitution)	3
2	नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of the Citizens)	9
3	सम्राट (The Emperor)	18
4	मन्त्रिमण्डल (The Cabinet)	24
5	डायट (संसद) (Diet)	32
6	न्यायपालिका (The Judiciary)	47
7	स्थानीय शासन (Local Government)	54
8	राजनीतिक दल (Political Parties)	60
	Exercises	65
	Select Readings	67



अमेरिका के सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रिया के साथ एक सेमिनार में भाग लेते हुए लेखक (बाएँ)

ब्रिटेन का संविधान

[THE BRITISH CONSTITUTION]

“ब्रिटिश साम्राज्य एक नियन्त्रित राजसत्ता द्वारा समुक्त है जो उस प्राचीन नियन्त्रित राजसत्ता के बलात्ता कोई दूसरा नहीं है जिसका गठघ-पन पहले स्काटलैण्ड की राजसत्ता से हुआ और जिसमें बाद में समुद्र पार के दूसरे राष्ट्र भी शामिल कर लिये गए। उसका वर्तमान वैधानिक स्वरूप किसी एक घटना

या आन्दोलन से उत्पन्न न होकर एक ऐसे क्रमिक विकास के कारण है जो प्राचीन नोर्मन (Norman) जाति की विजय के जितना ही प्राचीन है।

पास्तव में हम अपनी दृष्टि नोर्मन-काल से हटा कर और भी पहले के उन सेवक राजाओं पर लगा सकते हैं जिनके आधिपत्य में इंग्लैण्ड के राजा और उसके प्रदेशों का जन्म हुआ। विशेषतया हमारी दृष्टि हमारे राजाओं में सबसे महान एडमंड पर जाकर जमती है, जिसका जीवन व चरित्र अंग्रेजी सविधान का जीता-जागता रूप मालूम पड़ता है।”

—जी० एम० ट्रेविल्पान

‘अंग्रेजी सविधान एक पूरा की हुई वस्तु नहीं है परन्तु बुद्धि या एक प्रश्न है। यह बुद्धिमत्ता व संयोग के मिलन से उत्पन्न बात है जिसका भाग प्रदर्शन कभी आकस्मिक घटनाओं द्वारा और कभी कभी उच्चकोटि की योजनाओं द्वारा हुआ है।

यह एक नदी की भांति है जिसका गतिशील तलपृष्ठ (Surface) भाग मानों किसी के पैर से दूधर उभर से निक्षत कर कभी अंदर व कभी बाहर की ओर धूम कर घोंरे से वह निक्षतता है और कभी कभी पत्तों के झुरमुट में टा भी जाता है।”

—मुन्नी

1

ब्रिटिश संविधान का विकास व स्वरूप

(GROWTH AND NATURE OF THE BRITISH CONSTITUTION)

“हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है। यह ईश्वर की देन है। इस सम्बन्ध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कपा नहीं हुई है।”

—थॉमस डिकिंस

विश्व के संविधानों में ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पीछे सदियों के समर्थ और प्रगति की कहानी छिपी हुई है। यह प्राचीनतम परम्पराओं का सन्तान है। गत पाँच शताब्दियों से इसका विकास धारावाहिक है। ब्रिटिश सांविधानिक व्यवस्था और संस्थाओं ने विश्व की विभिन्न सांविधानिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं के निर्माण में अपना व्यापक प्रभाव डाला है। विश्व के अनेक देशों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश परम्पराओं को अपनाया है। जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चटुल से स्वतंत्र हुए, वहाँ प्रायः ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय प्रजातन्त्र का ही विकास हुआ है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आज के अधिकांश संविधान 'यूनायिड' रूप से ब्रिटिश संविधान की नकल हैं। सव-शक्तिशाली संसद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, द्विभेदनात्मक व्यवस्थापिका, सांविधानिक कार्यपालिका, कानून का शासन, स्वायत्त शासन आदि ब्रिटिश सांविधानिक परम्पराओं की देन हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश संसद को “संसदों की जननी” (The Mother of Parliaments) तथा ब्रिटिश संविधान को “मातृ संविधान” (Mother Constitution) कहा जाता है।

यदि हम विश्व के संविधानों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बर्मा आदि देशों की शासन पद्धतियों का निर्माण ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत ही हुआ है। यहाँ सब कि संयुक्त राज्य-

अमेरिका और सोवियत रूस के संविधान निर्माता भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके।

ब्रिटिश संविधान का महत्व विशेषकर इसलिए भी है कि इसका विकास मानव जाति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए किये गये संघर्ष का इतिहास है। ब्रिटेन का वर्तमान संविधान राजतन्त्र की निरकुशता के विरोध का परिणाम है। यह मानव-स्वतन्त्रता के लिए बलिदान का जीता जागता निशान है।

ब्रिटिश संविधान की राजनीतिक पृष्ठभूमि

(Political Background of the British Constitution)

संविधान के क्रियात्मक रूप का निर्धारण समाजशास्त्रीय तत्वों से होता है। अतः ब्रिटिश संविधान का अध्ययन भी इन तत्वों के संक्षिप्त उल्लेख से करें, तो उपयुक्त होगा —

भूमि (आकार एवं सामुद्रिक घिराव)—ब्रिटेन के छोटे से द्वीप का क्षेत्रफल 93,371 वर्गमील है जो फ्रांस का दो पाँचवाँ, अमेरिका का तीसवाँ तथा रूस का अस्सीवाँ भाग है। ग्रेट ब्रिटेन में लंदन, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित हैं। यह यूरोप के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित है। लगभग 20 मील चौड़ी इंगलिश चैनल इसे यूरोपीय महाद्वीप से अलग करती है। अतीतकाल में ब्रिटिश सुरक्षा की दृष्टि से इस चैनल में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भेदा की थी। इसके द्वारा ब्रिटेन शेष यूरोप में होने वाली क्रान्तियों से अछूता बचा रहा है।

ब्रिटेन का छोटा आकार ही सरकार की एकात्मकता और केन्द्रीकरण का प्रमुख कारण है। ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है अतः यहाँ की जनता अपने को सुरक्षित अनुभव करती रही है। इस सामुद्रिक स्थिति के कारण ही ब्रिटेन जलशक्ति के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र रहा है। सामुद्रिक घिराव ने इसकी इतिहास और संविधानिक विकास का पर्याप्त रूप में प्रभावित किया है।

निवासी और धर्म—ब्रिटेन में लगभग 5 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। मूल रूप से अंग्रेज अनेक जातियों से उत्पन्न हैं पर ये सभी जातियाँ (पेटट्स, रोचन ऐंग्लो सेक्सन, वेल्स, नोमॅस आदि) परम्परा मिलकर एक होती रही हैं। वर्तमान ब्रिटिश शासन प्रणाली इस जातिय एकपत्ता से पर्याप्त प्रभावित है। सभी ब्रिटेनवासी ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। यह धर्म धर्म में एक महान् राजनीतिक महत्व की बात है।

भाषा और साहित्य भी ब्रिटेनवासियों के जीवन में विशेष धर्म रखता है। अंग्रेजी नविक धार्मिक, और राजनीतिक एकता की बनाव रखा है। अंग्रेजी में धर्म की विविधता पाई जाती है। बहुसंख्यक धर्म प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के अनुयायी हैं जबकि कुछ प्राचीन धनीयानी बसोनिव हैं। स्वयं प्रोटेस्टेंट धर्म धनक भाषा में विभक्त फिर भी ब्रिटेन में धर्म-व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि धर्मों में पारस्परिक

मत-विभाजन के साथ-साथ आधारभूत एतता रही है। एर्नेस्ट बार्कर (E Barker) के विचार में 'धर्म की यही व्यवस्था ब्रिटेन में ससदीय जनतंत्र का बहुत कुछ आधार रही है।'

सामाजिक एवं आर्थिक दशा—ब्रिटिश समाज के ज्येष्ठत्व के सिद्धांत एवं पारिवारिक व्यवस्था ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। मोर्मेन विजय ने ज्येष्ठत्व के सिद्धान्त को स्थापित किया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश समाज में एक बुलीन-वर्ग का जन्म हुआ। प्रायः के विपरीत ब्रिटेन में इस वर्ग में नैतिक-सांविधानिक विकास में सहयोग दिया। इस वर्ग के प्रतिनिधि जाता के प्रतिनिधियों के रूप में लोकसभा में बैठते सगे, अतः लोकसभा अपने अपने सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था बन गई जबकि लॉर्ड सभा केवल बर्गों एवं निहित हितों की संस्था रह गई। ब्रिटिश समाज में पारिवारिक व्यवस्था का ढांचा ढीला-ढाला है इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति परिवार ही अपना सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति अधिक प्रेम और भक्तिपूर्ण होता है। ब्रिटिश समाज के इस चरित्र से बड़ा ही राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता का बल मिलता है। पुनश्च, ग्रेट ब्रिटेन एक अत्यधिक औद्योगिक देश है। अतः आज यह मूलतः पूँजीपतियों और श्रमिकों के दो वर्गों में विभक्त है। देश का दलीय ढांचा समाज के इसी विभाजन पर आधारित है। पूँजीपति अपने पूँजीवादी हितों के कारण उच्च माध्यमिक वर्ग के रूप में संगठित हैं। रूढ़िवादी दल (Conservative Party) उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत श्रमिक दल को कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों, बाग़ीचा, कमचारियों और दूकानदारों आदि की एक बहुत बड़ी संस्था का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय है।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि ब्रिटिश-स्वभाव रूढ़िवादी है जो एकदम आधुनिक परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली और उसकी राजनीतिक संस्थाएँ सदियों के अनवरत विकास (Unbroken Development) का परिणाम हैं। वास्तव में ब्रिटिश जाति समझौतावादी है। वह सद्भावपूर्ण भग्नो में न पड़कर केवल व्यावहारिक पहलुओं की ही विशेषता ध्यान में रखती है। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश रहा है, तथापि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से वह मूल रूप से गरीब है।

कुलीनतंत्र से प्रजातंत्र—ब्रिटिश शासन प्रणाली की वर्तमान रूपरेखा पर शक्ति और उत्तरदायित्व के ऐतिहासिक उत्तराधिकार का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। प्रवृत्ति यही रही है कि पुरखों का राजनीतिक आचरण एक बड़ी सीमा तक वर्तमान आचरण को निश्चित करता है। ब्रिटेन में शासन शक्ति और शासन उत्तरदायित्व पहिले राजतंत्र तथा कुलीनतंत्र (Aristocracy) के हाथ में था, किन्तु शर्न शन यह जनता के हाथों में चला आया और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना हो गई। सत्ता का यह हस्तांतरण आधुनिक अथवा जातिकारी रूप से नहीं बल्कि नैतिक विकास द्वारा हुआ। कुलीनतंत्र ने समयानुकूल अपना रंग बदला और प्रजातंत्र के

साथ सामन्जस्य किया। कुलीनतन्त्र प्रजातन्त्र के माग में प्राधा नहीं बना, उल्टे अपने प्रजातन्त्र को गति दी और उसे सुधार तथा नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह कुलीनतन्त्र एवं प्रजातन्त्र के सम्बन्ध से ब्रिटिश शासन-प्रणाली में नई व्यवस्था पैदा हुई और ब्रिटिश समाज में नये समाज का आविर्भाव हुआ।

ब्रिटिश संविधान की परिभाषा

(Definition of the British Constitution)

यू कि ब्रिटिश संविधान का न तो किसी योजनानुसार निर्माण हुआ है और न वह कभी लेखबद्ध हो किया गया है, अतः वह परिभाषा के बिना है। फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है।

परिभाषा

ब्रिटिश संविधान “अवसर और बुद्धि की सन्तान है।”

—Lytton Strachey

ब्रिटिश संविधान “सिद्धांतों और आचरणों का एक समूह है जो एक सहस्र वर्ष के इतिहास का निरीक्षण करने पर ही पक्कित किये जा सकते हैं जिसमें कोई कानून (Statute) यहां मिला तो कोई न्यायिक विनिश्चय वहां, जिसमें राजनीतिक आचरणों को सवर्माय रिवाजों में इकीभूत होते हुए देखा जाता है, और विधि-निर्माण शासन, वित्त, न्याय और निर्वाचन यंत्र के भीतरी भाग को दखना पड़ता है कि किस प्रकार अनीत में ये और किस प्रकार वे काम कर रहे हैं।”

—Ogg and Zink

“इंग्लैंड का संविधान विभिन्न सस्यान्ना, आदर्शों व व्यवहारों का विचित्र मिश्रण है। यह राजपत्रों (Charters), न्यायिक नियमों की विधि (Common Law) नज़ीरा (Precedents) प्रथाओं तथा परम्पराओं का मिश्रण है। यह कोई एक लेख्य (Document) नहीं बल्कि हजारों लेख्य हैं। इसको एक ही स्रोत से न लेवकर अनेक साधना व स्थानों से लिया गया है। यह कोई पूर्णता प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संस्था है, जिसका भाग प्रदर्शन कही आकस्मिकता ने और कही उच्च काटि की योजनाओं ने लिया है।”

—Monro

परन्तु उपर्युक्त सभी परिभाषायाँ व प्रशंसाओं के मध्या विपरीत विचार टोक्यूविली (Tocqueville) और थोमस पेन (Thomas Paine) ने व्यक्त किये हैं। फ्रेंच विचारक टोक्यूविली ने कहा था कि “इंग्लैंड में संविधान जमी कोई वस्तु नहीं है। अमेरिका के थोमस पेन ने भी इसी विचार का समर्थन करते हुए मत प्रकट किया कि “निजी सविधान को वास्तविक बने जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे निगिा रूप में दिनाया जा सके और यू कि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सकता, उसका कोई सविधान नहीं है। जाज बनाइना ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये—“हमारा ब्रिटिश संविधान है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि यह क्या है, यह कहीं भी

लिखा हुआ नहीं है, और न इसमें कोई संशोधन ही किया जा सकता है। हा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, एक वास्तविक मूल, पढ़ा जा सकने योग्य लेख्य है। मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य समझा सकता हूँ।”

टाक्यूविली और थोमस पेन के समान ब्रिटिश संविधान की अस्तित्वहीनता के प्रतिपादक अपने विचार के पक्ष में प्रायः तीन तक देते हैं—

(i) पहिला तक है कि ब्रिटिश संविधान किसी लिखित प्रलेख के रूप में नहीं है जब कि संविधान को एक लिखित, निश्चित और क्रमबद्ध प्रलेख के रूप में होना चाहिये जिसका निर्माण किसी संविधान-निर्मात्री परिषद् या व्यक्ति द्वारा किया गया हो। चूँकि ब्रिटिश संविधान किसी लिखित पत्र के रूप में नहीं है, उसका रूप निश्चित नहीं है, उसकी विषय वस्तु क्रमबद्ध नहीं है और अथ संविधानों की भाँति उसकी कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकती, अतः ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है।

(ii) दूसरा तक है कि एक संविधान को अनम्य (Rigid) होना चाहिये। उसमें संशोधन के लिये विशेष प्रक्रिया का प्रयोग होता चाहिये—ऐसी प्रक्रिया जो सामान्य विधि में संशोधन लाने की प्रक्रिया से सदा भिन्न हो। चूँकि ब्रिटिश संविधान में सामान्य विधि और संविधान में संशोधन लाने की एक ही प्रणाली है अतः यह सत्तार का सबसे नम्य (Flexible) संविधान है और उसे संविधान की श्रेणी में नहीं गिना जाना चाहिये।

(iii) तीसरा तक है कि एक संविधान में उच्च आधारभूत नियमों (Supreme Fundamental Laws) का संरक्षण होना चाहिये जबकि ब्रिटिश संविधान में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संविधान में समदसप्रभु है, संविधान नहीं। संविधान के आधारभूत नियमों में सत्तद स्वेच्छानुसार परिवर्तन और परिवर्धन कर सकती है। चूँकि ब्रिटेन में पवित्र, उच्च और मौलिक नियमों का अभाव है, अतः ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व संदेहप्रद है।

परन्तु थोमस पेन और टाक्यूविली के उपर्युक्त तक भ्रामक हैं। दोनों विद्वानों को अपने समय में यह तक सही इसलिये प्रतीत हुए थे क्योंकि उन दिनों व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिये संविधान की अति-आवश्यक समझा जाता था और उसके लिखित तथा अनम्य (Rigid) स्वरूप पर जोर दिया जाता था। चूँकि अंग्रेजी संविधान को दोनों विद्वानों ने न तो आलेख (Document) के रूप में पाया और न उसका अधिकांश किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित कानून के रूप में ही मिला, अतः उन्होंने यही त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है।

शब्द “संविधान” शब्द से दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक अर्थ से तो संविधान के उस आलेख का बोध होता है जिसको संविधान निर्माताओं ने किसी एक समय में एक स्थान पर बैठकर रचा हो और जिसमें शासन के ढाँचे, शासन के विभिन्न भागों के कार्यों, शासन के विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों, शासकों और प्रजा के

सम्य-धा, 'यायालया, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदि की व्यवस्था के मूल सिद्धान्तों को निष्पाद्यमान' रूप से निश्चित कर दिया गया हो। दूसरे अर्थ में, जो अधिक व्यापक है, संविधान से केवल एक सेल अथवा एक विशिष्ट शासन विधि या ही बाध नहीं होता बल्कि उन सब नियमों, अधिनियमों, परिपाटियों, प्रचलित प्रथाओं तथा रूढ़ियों आदि का भी बोध होता है जो उस शासन विधि से सम्पन्न हैं, चाहे उन्हें बठकर किसी एक समय अथवा स्थान पर किसी ने लेखबद्ध न किया हो। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व इसी पिछले अर्थ में है।

वास्तव में ऐसा एक भी संविधान नहीं है जो पूर्णतः लिखित हो। प्रत्येक संविधान में लिखित तत्व उपस्थित रहते हैं। 'जॉड ग्राइस' के शब्दों में "लिखित संविधान व्याख्या द्वारा विवक्षित, निष्पाद्य द्वारा आभूषित और लोकाचारा द्वारा विस्तृत होते हैं और कुछ समय के पश्चात् उनके अधरश पाठ उनका पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकते।" इसी बात का ध्यान में रखकर मुनरो ने लिखा है—“अमेरिका ने संविधान को समझने में 20 मिनट नहीं बल्कि 20 महीने लगेंगे।” समार की प्रत्येक शासन प्रणाली में किसी न किसी रूप में रीति रिवाजों और परम्पराओं का तत्व अवश्य विद्यमान है। मनुष्य गतिशील है, अतः उसकी राजनीतिक संस्थाएँ भी गतिशील ही हैं। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि संविधान निमित्त अविष्य के लिये भी शासन के अन्तिम स्वरूप को पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय बना दे अथवा निश्चित कर दें। वास्तविकता यही है कि संविधान—निर्माणा संविधान को केवल ढाँचे या कंकाल का स्वरूप प्रदान करते हैं। बाद की आने वाली पीढ़ियाँ उस ढाँचे या कंकाल को नियमों, प्रथाओं, सफटवालीन आवश्यकताओं, आर्थिक विकासों आदि के अनुरूप मानम मज्जा से पूर्ण कर लेती हैं। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का आदर्श नमूना है और वह ही इस प्रकार के विकासों के बाद ही पूर्ण होता है।

अनम्य (Rigid) न होने के आधार पर ही ब्रिटिश संविधान को संविधान की श्रेणी में न रखना भी तर्क संगत नहीं है। किसी भी संविधान की नम्यता (Flexibility) सशोधन प्रणाली पर नहीं बल्कि उसके मौलिक उपबन्धों की प्रकृति और देशवासियों के चरित्र तथा परम्परा पर निर्भर करती है। यदि उपबन्धों के दृष्टि कोण से देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की नम्यता की एक श्रेणी में रखा जा सकता है। देशवासियों के चरित्र और परम्परा की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज जाति सम्भार प्रकृति की है तथा अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहने वाली है। ब्रिटिश जाति को अपनी प्राचीन परम्पराओं और संस्थाओं से अनन्य प्रेम है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में आकस्मिक और अधिकांश परिवर्तन अथवा सशोधन नहीं हो पाया है। जो थोड़े बहुत सशोधन हुए भी हैं वे शनं शनं और बहुत सोच विचार के बाद तथा अधिकांशतः संवसम्मति से ही हुए हैं। फाइनर (Finer) का यह लिखना ठीक ही है कि “व्यवहार में संविधान साधारण विधि की अपेक्षा संविधानिक विधि के सम्बन्ध में अधिक कठोर है।”

उच्च आधारभूत नियमों के अभाव की बात कहकर ब्रिटिश संविधान पर आपत्ति प्रकट करना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। आग और जिंक (Ogg & Zink) ने कहा है “ग्रेट ब्रिटेन में बहुत से आधारभूत सांख्यिक नियम और अभ्यास वर्तमान थे और आज भी हैं।” इन आधारभूत नियमों के बारे में डायसी (Dicey) ने लिखा है कि “य नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सार्वभौम शक्ति के विभाजन और प्रयोग को निर्धारित करते हैं।”

निष्पत्ति यही निश्चिता है कि ब्रिटिश संविधान का भी अन्ध संविधानों की तरह पूरा अस्तित्व है। सिर्फ अन्तर यही है कि अन्ध देशों के संविधानों की भाँति इसे क्रमवद्ध, सहितावद्ध और सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। यह किसी एक की नहीं बल्कि हजारों स्रोतों की उपज है। इसका निर्माण ‘ही बल्कि’ विरासत हुआ है।

निर्माणात्मक तत्त्व या स्रोत या अवयवी भाग

(Sources of the British Constitution)

ब्रिटिश संविधान के विकास में एक नहीं बल्कि अनेक तत्वों ने भाग लिया है जिन्हें हम इस संविधान के स्रोत या अवयवी भाग (Component parts) कहते हैं। ये तत्व प्रधानतः निम्नलिखित हैं—

(1) सांविधानिक समझौते—ये वे ऐतिहासिक लेख अथवा समझौते हैं जो सफटकाल में राजा और प्रजा के बीच तय हुए थे। जब राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो जनता की ओर से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन किये गये। फलस्वरूप राजाओं व प्रजा के बीच अनेक समझौते हुए जिनमें राजा की शक्ति तथा प्रजा के अधिकारों की परिभाषा करने का प्रयास किया गया। वास्तव में ये समझौते वे सांविधानिक सीमाचिह्न (Constitutional Landmarks) हैं जिनके माध्यम से इंग्लैंड का लोकतन्त्रीकरण होने में भारी सहायता मिली है। ये समझौते उन स्थलों का परिचय देते हैं जिनसे इंग्लैंड का लोकतन्त्रीय मार्ग पर बढ़ता गया था।

ब्रिटिश सांविधानिक समझौतों में महान् मानाचित्र, 1215 (Magna Carta, 1215), अधिकारों का प्राथना पत्र, 1628 (Petition of Rights, 1628) और अधिकार पत्र 1689 (Bill of Rights 1689) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हें ब्रिटिश संविधान की ‘बाइबिल’ कहा जाता है।

(2) सांविधानिक कानून या संसदीय विधियाँ—य वे स्रोत हैं जिनके द्वारा संसद ने समय-समय पर राजा की शक्ति को नियन्त्रित किया है अथवा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता या स्थानीय अधिकारियों या स्थानालयों व प्रशासनिक मशीनरी और जनमत को स्थापित तथा परिभाषित किया है। इन संसदीय विधियों में कुछ प्रमुख ये हैं—बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (Habeas Corpus Act) 1679, समझौता अधिनियम (Act of Settlement) 1701, सन् 1832 1867 व 1884 के सुधार अधिनियम (Reform Acts), सन् 1888, 1894, 1929 व 1933 के

स्थानीय मामल प्रधिनियम (Local Govt Acts), सन् 1872 का सप्तरीय तथा म्पुनिसिपल चुनाव प्रधिनियम (Parliamentary & Municipal Elections Act), सन् 1911 का मगरीय प्रधिनियम (Parliamentary Acts of 1911), सन् 1918 और 1948 के जनमन प्रनिनिधित्व प्रधिनियम (Representation of Peoples Act), आदि ।

(3) "यायिक" नियम—ब्रिटिश साविधानिक नियमों का सीगरा गीत न्यायालयों में मुने जात वाले प्रभियोगों के सम्बन्ध में न्यायाधीशों के नियम हैं । इनके द्वारा चाटरी और प्रियिवा के प्रध निश्चित नियम हैं और उनकी सीमायें निर्धारित कर दी गई हैं । इन नियमों ने ब्रिटिश सविधान के विकास में बहुत योग दिया है । इसी कारण डायसी ने कहा है कि "ब्रिटिश सविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है ।" इस प्रकार के यायिक नियम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के समान हैं । अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में वृत्त के मविधान के प्रयत्न को स्पष्ट और विवक्षित करने में बड़ी सहायता गी है । ब्रिटन में "यायिक" नियम ही राजा के परमाधिकारों (Rerogative) और सगद-मन्त्रियों के विशेषाधिकार (Privileges) के अधिकार हैं । कुछ प्रमुख यायिक नियम इस प्रकार उल्लेखनीय हैं—

विल्कीज बनाम वुड (Wilkes V/s Wood) में यह नियम किया गया था कि किसी भी अनाम निदिष्ट (Un named) लेखकों की सलाशी प्रधवा उसके कागजात को प्रधिनार में लेने का सामान्य प्रधिवत्र (General warrant) प्रवर्ध है । सामरसेट (Somerset) के मविधान में प्रधेजा की भूमि में दासत्व को सदा के लिए हटा दिया । हावेल (Howell) के प्रभियोग में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की गारन्टी दी गई । बुशल (Bushell) के प्रभियोग से ज्यूरी प्रधार् न्याय सम्मों की स्वतन्त्रता स्थापित हो गई ।

(4) फाननी टीकायें—साविधानिक विधि के सम्बन्ध में प्रख्यात लेखकों की टीकायें (Commentaries) का भी सविधान के प्रवयव के रूप में उल्लेख किया जा सकता है । इन टीकायों के द्वारा लेखकों ने विविध प्रभिसमयात्मक नियमों (Conventional rules) को क्रमबद्ध किया है उनका सम्बन्ध निश्चित किया है और मूल सिद्धांतों की ओर मन्त करते हुए उन्हें कुछ हद तक एकता की कड़ी में बाध दिया है ।

इन कानूनी टीकायों में निम्नलिखित प्रमुख हैं—

- (i) एनमन रचित "सविधान की विधि और लोकाचार" (Law and Custom of the Constitution by Anson)
- (ii) मे द्वारा रचित 'मसदात्मक प्रथा' (Parliamentary Practice by May)
- (iii) डायसी रचित 'सविधान की विधि' (Law of the Constitution by Dicey)

(iv) बेजहोट रचित “इंग्लैंड का संविधान” (English Constitution by Bagehot)

(5) सामान्य विधि—ब्रिटिश संविधान का अर्थ मुख्य तः सामान्य विधि (Common Law) है। “सामान्य विधि”, मुनरो के शब्द में “उन नियमों का समूह है जिनका संसद विधि से पृथक् विकास हुआ और अन्ततः जिन्हें मारे राज्य में मान्यता मिली।” ये नियम, रीति रिवाजों और परम्पराओं के आधार पर विकसित हुए हैं, संसद द्वारा कभी निर्मित नहीं हुए। “यायाधीशों ने अपने लिए ऐसे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिनमें समय बीतने पर कानून जैसी महत्ता प्राप्त कर ली है। इन सिद्धांतों व नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है। संसद द्वारा पारित न होने पर भी न्यायालय इन्हें मान्यता देते हैं और यदि इनका उल्लंघन होता है तो इनके विषय में न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है और उल्लंघन करने वाला को दण्ड दिया जा सकता है। ये सिद्धांत व्यवहार के कारण शासन प्रणाली के अङ्ग प्रत्यङ्ग में घुस आये हैं।

सामान्य विधि के सिद्धांतों के अन्तर्गत सांविधानिक महत्त्व के बहुत से मुख्य मामले आते हैं। उदाहरण के लिए, राजा ने अपना परमाधिकार (Prerogative) तथा संसद ने अपनी सर्वोच्चता सामान्य विधि से प्राप्त की है। इसी तरह ब्रिटिश जनता की नागरिक स्वतन्त्रताएँ, जो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) में उपलब्ध हैं, सामान्य विधि के नियमों द्वारा संरक्षित हैं।

(6) सांविधानिक परम्पराएँ या अभिसमय—ब्रिटिश संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग अभिसमय (Conventions) पर आधारित हैं। ये अभिसमय लिपिबद्ध नहीं हैं और न्यायालय भी इन्हें कानूनी श्रियावित नहीं कर सकता। फिर भी इन अभिसमयों को कानून का सा हो आदर प्राप्त है और इनका पालन भी कानूनों के समान ही होना है। वास्तव में ये अभिसमय राजनीतिक पद्धति के अलिखित नियम हैं। ऑग और जिंक (Ogden and Zink) के शब्दों में “वे (अभिसमय) उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिल कर बनते हैं जो राजनीतिक नतिकता के नियम माने जाने पर भी बड़ी से बड़ी सांविधानिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के सम्बन्धों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं।” इन्हीं सांविधानिक अभिसमयों के आधार पर ब्रिटिश शासन विधान का समस्त ढांचा निर्भर है और ये ही उसे लचीला बनाते हैं।

ब्रिटिश संविधान में कुछ अभिसमय (सांविधानिक परम्पराएँ) निम्न लिखित हैं—

- 1 वर्ष में कम से कम एक बार संसद अवश्य बुलाई जाती है।
- 2 राजा महारानी को बैठक में सम्मिलित नहीं होना है।
- 3 राजा अपने मंत्रियों का परामर्श सदैव स्वीकार कर लेता है।
- 4 राजा संसद द्वारा पारित विधेयक पर सदैव स्वीकृति प्रदान कर देता है।

- 5 मंत्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- 6 प्रत्येक विधेयक का तीन बार वाचन होना चाहिये जब वही जाकर उस पर अंतिम मतदान होता है।
- 7 लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता।
- 8 लोकसभा के अध्यक्ष का निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिये।
- 9 अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचन होना चाहिये और जिसी बार वह चाह उसे निर्वाचित किया जाना चाहिये।
- 10 लोकसभा का अधिवेशन जब "यायलया" के रूप में होता है तो केवल कानूनी सौंड ही उपस्थित होते हैं।
- 11 प्रायः सभी राजकीय विशेषाधिकारों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा किया जाता है, आदि आदि।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान विभिन्न तत्वों में बना हुआ संविधान है। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश संविधान के अनेक स्तंभ हैं। वह किसी एक आलेख के रूप में नहीं है बल्कि संकटों आलेख उसमें शामिल हैं। ब्रिटिश संविधान के निर्माणक्रम के विषय में विचार व्यक्त करते हुए ग्राहम ने ठीक ही कहा है कि, "लोगों की भावनाओं में अथवा लिखित रूप में विद्यमान प्राचीन उदाहरणों का समूह, बकीलो एवं राज नताओं के कथन विविध प्रयासों गिवाज कल्पनाओं, जिनका प्रभाव सरकार की कार्यप्रणाली पर पड़ता है तथा अनेक मसंगीय कानून ब्रिटिश संविधान में सम्मिलित हैं।

ब्रिटिश संविधान का विकास

(Growth of the British Constitution)

ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसकी जड़े सदियों पुराने इतिहास में जमी हुई हैं। इनका जाल रूप आज हमारे सामने उपस्थित है, वह किसी समय विशेष परिस्थितियों में नहीं बना है बल्कि इसका निर्माण शताब्दियों के अनुभव ने किया है। ब्रिटिश संविधान का विकास लोगों की राजनीतिक चेतना की पुकार के साथ साथ आवश्यकतानुसार धीरे धीरे हुआ है। परिवर्तन एकदम मार्कस्मिक नहीं हुए हैं बल्कि प्रत्येक नया कदम पुराने कदम का स्वाभाविक परिणाम रहा है। यह संविधान लगभग 1300 वर्ष पुराना है। इस संविधान के इतिहास का सार यह है कि निरंकुश राजतंत्र का शांतिपूर्ण ढंग से वंचाधिक राजतंत्र के रूप में रूपान्तरित कर लिया गया है।

ब्रिटिश संविधान का विकास कुछ मुख्य स्तरों का पार करते हुए हुआ है जिनका विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है—
ऐंग्लो सैक्सन काल

ब्रिटेन का लिपिवद्ध इतिहास केल्ट जाति के समय में शुरू होता है जिसने 1 से लगभग 600 वर्ष पूर्व आक्रमण करके यहां बसा जमाया था। केल्ट जाति

की एक शाखा ब्रिटेन के नाम पर इस द्वीप का नाम भी ब्रिटेन पड़ गया। केल्ट जाति के बाद ब्रिटेन रोमन साम्राज्य के चंगुल में फस गया और तब पाचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐंग्लो सैक्सन जाति (Anglo Saxon Tribe) ने ब्रिटेन पर अधिकार जमा लिया। इस जाति का आधिपत्य लगभग 1066 तक रहा। ओग और जिंक (Ogg and Zink) के अनुसार यही वह प्रथम काल था जिसे ब्रिटेन के राजनीतिक संस्थाओं ने विकास का प्रारम्भ कहा जा सकता है। कम से कम दो सत्यायें इस युग की बहुत बड़ी हैं— राजपद और स्थानीय स्वायत्त शासन।

राजपद का प्रादुर्भाव—राजपद ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिस पर सम्पूर्ण ब्रिटिश संविधान केन्द्रित है। इस पद का प्रादुर्भाव ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के समय सातवीं आठवीं शताब्दी में हुआ। उस समय ब्रिटेन में छोटे छोटे कबालों और समुदाय थे। शन शन शक्तिशाली समुदायों ने निबल समुदायों पर विजय प्राप्त करना प्रारम्भ किया और ब्रिटेन में राजकीय शासन की स्थापना हुई। अलग अलग राज्यों की स्थापना के बाद वेसेक्स (Wessex) राजघराने की सर्वोच्चता कायम हो गई और अल्फ्रेड (871 ई०) से लेकर नोर्मन विजय (1066 ई०) तक वस्तुतः पूरे इंग्लैंड पर इसी का शासन रहा।

ऐंग्लो-सैक्सन कालीन राजा का पद कभी परम्परागत होता था और कभी निर्वाचित। इस समय राजा का रूप यद्यपि निरकुश हो गया था तथापि उसकी स्वेच्छाचारिता पर विटनेजमोट (Witenagemot) अर्थात् बुद्धिमानों की सभा का बड़ा प्रभुत्व था। यह राजा की एक प्रकार की परामर्श-दात्री समिति थी जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह राजा को गद्दी से उतार सकते थे और नया राजा चुन सकते थे। शासन प्रबन्ध में इसका पूरा अधिकार था। वास्तव में यह भ्रूणावस्था में प्राधुनिक संसद (Parliament) थी। यह सभा प्रायः अपना अधिकारों का उपयोग नहीं करती थी और राजा का व्यक्तित्व ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। कालांतर में जैसे जैसे शक्तिशाली राजा आते गये, विटनेजमोट की शक्ति घटती गई। राजाओं ने इसमें अपने मित्रों का भरना शुरू कर दिया और यह राजा की हाथ में हाथ मिलाते वाली संस्था मात्र रह गई।

स्थानीय स्वशासन—सांविधानिक दृष्टिकोण से इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण सफलता स्थानीय स्वशासन की स्थापना है। इस समय सम्पूर्ण देश शायरो (Shires) में विभक्त था। शायर स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई थी। ये शायर ही प्राधुनिक काउण्टियों (Counties) की जन्मदात्री हैं। शायर हंड्रेड (Hundred) नामक उप प्रदेशों में विभक्त थे। एक हंड्रेड में अनेक ग्राम सम्मिलित होते थे। हंड्रेड गावों व ग्रहों में विभक्त थे। प्रत्येक गाव अथवा ग्रह में एक टाउनशिप (Township) होती थी जो स्थानीय शासन की सबसे नीचे की इकाई थी। ये सभी इकाइयाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही कार्य करती थीं।

नॉर्मन एञ्जीवन काल

सन् 1066 तक एंग्लो सैक्सन जाति का ब्रिटेन में प्रभुत्व रहा, परन्तु इस वर्ष नॉर्मन (Norman) देश के विलियम आफ नोरमंडी (William of Normandy) ने आक्रमण करके ब्रिटेन में नॉर्मन राज्य की स्थापना की। इस विजय के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यिक विकास का एक नया युग शुरू हुआ।

सामन्तशाही की स्थापना—विलियम ने शासन की सुविधा और जनता की सहायुभूति प्राप्त करने के लिए देश में सामन्तिक शासन की स्थापना की। सम्पूर्ण देश सामन्तिय इकाइयों में बांट दिया गया। प्रत्येक इकाई एक बैरन (Baron) के अधीन रखी गई जो अपने यहां सेना रखता था और आवश्यकतानुसार राजा की सहायता करता था। विलियम ने वितनेजमोट (Witenagemot) को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर एक महान् परिषद् अथवा उच्च स्तरीय समिति (Great Council) की स्थापना की जिसमें बैरन और राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी बुलाये जाते थे। इस महान् परिषद् को मग्नम कांसीलियम (Magnum Concilium) भी कहा जाता था। इस परिषद् का काम राजकीय मालगुजारी को इकट्ठा करना व उसका हिसाब रखना था। समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। वर्तमान चांसलर ऑफ दी एक्स्चैचर (Chancellor of the Exchequer) की उत्पत्ति यहीं से होती है। महान् परिषद् या मग्नम कांसीलियम के भी वही काम थे जो इसकी पूर्वगामी संस्था वितनेजमोट के थे, किन्तु चूंकि राजा की शक्तियां बढ़ गई थीं, अतः महान् परिषद् की शक्ति व वितनेजमोट की तुलना में कम हो गई। विलियम ने एक अनवरित समिति जिसे 'क्यूरिया रेजिम (Curia Regis)' कहा जाता था, की भी स्थापना की। इसमें राज्य के स्थायी अधिकारी होते थे और यह समिति स्थायी होती थी।

मग्नो मंडत एव सीमित राजतन्त्र का सूत्रपात—प्रारम्भ में उपर्युक्त दोनों संस्थाओं (Magnum Concilium and Curia Regis) का क्षेत्राधिकार निश्चित नहीं था। राजा जिस तरह परामर्श लेता था और किसी का भी परामर्श मानने को बाध्य नहीं था। फिर भी प्रायः प्रशासकीय और दलित गार मामलों में क्यूरिया रेजिम तथा एंग्लीक विषया और नीति व मन्त्रिमण में मग्नम कांसीलियम अथवा महान् परिषद् में मतान्तर सी जानी थी। धीरे-धीरे क्यूरिया रेजिम श्रुत उपयोगी संस्था हो गई और एंग्लो अधिपति भी प्रायः मन्त्र हो सगा। राजा में क्यूरिया रेजिम व कुछ विभाग कुछ विदेशियों का करतब और पृथक् मन्त्रियों के रूप में परिणत हो गए। क्यूरिया रेजिम में से ही उत्तम मन्त्रिमण की उत्पत्ति हुई जिसे 'प्रिवी काउंसिल' (Privy Council) कहा गया। 17 वीं और 18 वीं शताब्दी में प्रिवी काउंसिल में 'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स' (Council of Ministers) की तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 'कैबिनेट' (Cabinet) का उद्भव हुआ। ये दोनों संस्थाएँ प्रिवी काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तथा कैबिनेट मात्र ही

विद्यमान हैं। इसी प्रकार महान् परिषद् (Magnum Concilium) से संसद के द्वितीय भवन "हाउस ऑफ लॉर्डस" (House of Lords) का विकास हुआ। मुरो और इयस्ट (Munro and Aycarst) ने ठीक ही लिखा है कि अत्यंत प्रारम्भिक रूप में हम मैग्ना कौन्सिलियम में आधुनिक पार्लियामेंट का और क्यूटिया रेजिस में आधुनिक कैबिनेट का स्वरूप देख सकते हैं।

नोमन कालीन शासन व्यवस्था में बाद में हैनरी द्वितीय ने परिष्कार किया। उसने क्यूटिया रेजिस के न्याय सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में भिन्नता की। महान् परिषद् की अधिक बैठकें बुलाकर और उसको न्याय के लिए प्रायः सभी मामलों को सौंपकर उसे संसद की संस्था बनाया। उसने चल न्यायाधीशों की व्यवस्था की जिससे सब लोगों व स्थानों के लिये सामान्य कानून के विकसित होने में सहायता मिली।

सन् 1196 से 1216 तक ब्रिटेन में एक बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ जिसका नाम जॉन था। उसके अत्याचारों से तंग आकर बड़े बड़े वरत उसके विरुद्ध हो गये। उन्होंने उसे गृह युद्ध की धमकी दी। अन्त में जॉन को मुक्तना पड़ा और उनकी उन भागों की स्वीकार करना पड़ा जो उन्होंने मैग्नाकार्टा (Magna Carta, 1215) नामक प्रपत्र में प्रस्तुत की। इस प्रपत्र अथवा अधिकार पत्र को ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान् सीमा चिह्न माना गया है। इस महान् अधिकार पत्र के मुख्य प्रबंध निम्न थे—

1 महान् परिषद् अर्थात् मैग्ना कौन्सिलियम की सम्मति पर ही राजा सामन्तों पर करारोपण करे।

2 किसी नागरिक को उस समय तक बन्दी न बनाया जाए और न ही उसको निर्वासित किया जाए जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए।

3 किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति एवं अपराध की मात्रा के अनुरूप ही अथ दण्ड दिया जाए। यह अथ-दण्ड नितान्त स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।

4 'कोर्ट ऑफ कॉमन प्ले' (Court of Common Plea) एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे, राजा के साथ ये स्थान स्थान पर दौरे न किया करें।

5 राजा चर्च के संगठन और उसके अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप न करे।

6 प्रभावशाली सामन्तों और पादरियों को महान् परिषद् में अवश्य निमन्त्रित किया जाए।

7 विदेशी व्यापारियों के देश में स्वातंत्र्य विचलन का केवल युद्ध काल में ही प्रतिबंध हो, अन्यथा उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक देश में आने-जाने की आज्ञा हो।

8 सम्पूर्ण राज्य में तौल के एक ही पैमानों का प्रयोग किया जाए।

मैग्नाकार्टा ने इन मौलिक तथ्यों की सृष्टि की कि राजा को कुछ मूलभूत विधियों के अधीन रहना चाहिये और यदि वह उनका उल्लंघन करे तो जनता को अधिकार है कि वह राजा को उन विधियों को मानने के लिए बाध्य करे। अंग

ओर जिंक (Ogg and Zink) के अनुसार "इसके द्वारा सम्मन्तो ने राजा पर यह प्रतिबन्ध लगाकर कि वह अमुक कार्य करे और अमुक नही, देश की निरंकुशवाद की भार प्रवाहित होती हुई घारा को जनतन्त्र की दिशा में मोड़ दिया।

संसद का सूत्रपात—मग्नाकार्टा ने यद्यपि प्रतिनिधित्व के प्रश्न को नहीं उठाया किन्तु इसके बाद आशिक रूप में यह सिद्धांत प्रचलन में आ गया। इसी के साथ-साथ आधुनिक संसद (Modern Parliament) के बीज ब्रिटिश संविधान में दृष्टिगोचर होने लग। हैनरी तृतीय के समय महान परिषद् (Magnum Concilium) को आधुनिक संसदीय व्यवस्था की दिशा में धागे बढाने का अवसर मिला। अभी तक महान परिषद् में केवल बिशप बैरन, राज्य के उच्चाधिकारी आदि ही सम्मिलित होते थे, परन्तु अब इसमें प्रजा के प्रतिनिधियों की वृद्धि हुई। बिशप तथा बैरनों के साथ साथ प्रत्येक शायर से 22 उपाधि प्राप्त व्यक्ति (Knights) तथा प्रत्येक गारो (Borough) से 22 स्वतन्त्र नागरिक बुलाये गए। इस प्रकार बड़े-बड़े लोगों के साथ साथ छोटे छोटे लोगों का भी महान परिषद् में आना प्रारम्भ हुआ और वर्तमान लोकसभा की नींव पड़ी। संसद का यह अधिवेशन 1265 में बुलाया गया।

सन् 1274 ई० में एडवर्ड प्रथम सिंहासन पर बैठा। सन् 1275 में संसद ने वेस्ट मिनिस्टर का प्रथम विधान (First Statute of West Minister) पारित किया जिसमें भूमि कर निश्चित किया गया तथा निर्वाचन व्यवस्था स्वीकृत की गई। सन् 1278 में ग्लोसेस्टर का विधान (Statute of Gloucester) पारित हुआ। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि किस प्रकार भूमिपति किस अधिकार और भूमि का प्रयोग करते रहे हैं। सन् 1279 में पावरियों के अधिकार सीमित कर दिये गए। सन् 1285 ई० में वेस्ट मिनिस्टर का द्वितीय विधान (Second Statute of West Minister) पारित हुआ, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद स्वतन्त्र नागरिकों की भूमि उनके ज्येष्ठ पुत्रों को दिये जाने की व्यवस्था हुई।

सन् 1295 में एडवर्ड प्रथम ने एक संसद (Parliament) बुलाई जिसका नाम आधुनिक संसद (Modern Parliament) रखा गया। इस आयोजन से प्रपञ्ची संसद का विकास एक और चरण आगे बढ़ा। इस संसद में शायरो और बारा (Shires and Boroughs) के 172 बैरनो, नलजियो, बिशपो आदि के 400 प्रतिनिधि थे। इस आधुनिक संसद में वास्तव में जनता के प्रतिनिधि अधिक संख्या में सम्मिलित हुए और जन जन इन जन प्रतिनिधियों की सरया उत्तरोत्तर बढ़ती गई और अन्त में यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक स्थायी तथा अनिवार्य अंग बन गई।

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रारम्भ में आधुनिक संसद (Modern Parliament) की बटन एन सदन के रूप में हुई जिसमें तीन भलग भलग समूह थे—प्रथम सम्मूह ऊँचे लोगों का था जिन्हें नोबल (Noble) कहा जाता था, दूसरा समूह

बारजी लोगो का था और तीसरा समूह साधारण लोगो का। कालान्तर में व्यावहारिक स्वाध ने इन संसद सदस्यों को दो समूहों में बांट दिया। समान हितों के कारण एक और उच्चकोटि के सामन्त तथा पादरी और दूसरी और निम्नकोटि के सामन्त और नागरिक (Commoner) एक साथ मिल गये। दोनों समूहों की अलग-अलग बैठक होने लगी। प्रथम वर्ग के लोगो की सभा का नाम लॉर्ड सभा (House of Lords) तथा दूसरे वर्ग के लोगो की सभा का नाम लोक सभा (House of Commons) पड़ा। इस प्रकार द्विसदनीय संसद का प्रादुर्भाव हुआ। यह द्विसद नात्मक व्यवस्था सन् 1295 के बाद लगभग 100 वर्षों में पूर्ण हुई।

संसद की शक्तियाँ धीरे-धीरे बढ़ती गईं। प्रारम्भ में राजा का खर्चा माल गुजारी से चल जाता था, परन्तु युद्धों के कारण उसकी धन सम्बन्धी आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती गई और उसे संसद को बार-बार करों की स्वीकृति के लिए बुलाना पड़ा। सन् 1340-41 में एडवर्ड तृतीय को संसद ने करों की स्वीकृति उस समय प्रदान की जब उसने निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार कर लिया —

- (1) राजा संसद की स्वीकृति के बिना कोई नये कर नहीं लगायेगा।
- (2) संसद हिसाब-किताब या निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगी।
- (3) राजा के मंत्रियों की नियुक्ति संसद द्वारा की जाएगी।
- (4) संसद के नये अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व मंत्री राजा के समक्ष अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे और अपने विरुद्ध की हुई शिकायतों का संसद को उत्तर देंगे।

इस प्रकार इस युग में संसद की शक्तियाँ तथा वित्त पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। किन्तु अभी भी संसद की शक्ति अधिक नहीं हो पाई थी क्योंकि उसका बुलाना, उसे विमर्जित करना आदि काम राजा के ही हाथ में था। इसके अतिरिक्त उसे विधि-निर्माण सम्बन्धी बोर्ड अधिकार न थे तथा लोक सभा को वित्त के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त न था।

प्लान्टेगेनट व लंकास्ट्रीयन

संसद की शक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता गया। प्लान्टेगेनट वंश के राज्य काल में जो 1154 से 1399 तक रहा इसकी शक्ति से बहुत वृद्धि हुई। इंग्लैंड के इतिहास में सर्वप्रथम सन् 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय का मिहासन से हटाकर रिचर्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा और संसद ने तब स्टीयन वंश के राजा हैनरी को इंग्लैंड के राजसिंहासन पर बिठा दिया।

सन् 1399 से 1485 तक लंकास्ट्रीयन (Lancaster) वंश के हाथ में शासन की सत्ता रही। उस समय संसद को गम्भीर अधिकार मिले जिसमें मुख्य निम्न हैं—

- (1) हैनरी चतुर्थ ने अपने पुत्र हुए मंत्रियों के मन्त्री मण्डल या प्रिवी काउंसिल (Privy council) का नाम दिया जो अब तक चला आ रहा है।

(2) सन् 1401 में लोकसभा ने राजा को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया कि नवीन करों की स्वीकृति देने के पूर्व राजा को जनता की शिकायतों का निवारण करना चाहिये। बाद में यह परिपाटी अपनाई गई और नये करों की स्वीकृति उम समय दी जाने लगी जब राजा जनता की शिकायतों को दूर करने का वचन दे देता था।

(3) सन् 1407 में लोक सभा को स्वयं वित्त विधेयक आरम्भ करने का अधिकार प्राप्त हुआ, हालांकि इस सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति उसे 1911 के अधिनियम के बाद ही मिल सकी।

बिना यह सब कुछ होते हुए भी संसद अपनी शक्ति को संगठित नहीं कर सकी। इसी मध्य 'गुलाबों के युद्ध' (War of Roses) शुरू हो गये और लोग परेशान हो कर यह चाहने लगे कि ऐसा राज्य पुनः अस्तित्व में आये जिस पर संसद का कोई नियन्त्रण न हो।

ट्यूडर काल

सन् 1485 में ट्यूडर राजाओं की निरंकुश सत्ता स्थापित हो गई। ट्यूडर वंश का राज्य 1503 ई० तक चला। ट्यूडर सम्राटों ने दश में निरपेक्ष राजतन्त्र की स्थापना की। इस वंश के शासन काल में संसद की शक्ति को बड़ा आघात पहुँचा जनता ने ट्यूडर शासकों की निरंकुशता को प्रसंगतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने देश में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित की तथा बरनो (Barons) की शक्ति को क्षीण कर दिया। ट्यूडर राजाओं ने विपुल धनराशि एकत्रित कर ली, धन उन्हें समद की बुलान की आवश्यकता ही नहीं हुई। यद्यपि ट्यूडर सम्राटों ने संसद का अपनी स्वामिनी नहीं होने दिया, तथापि उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को भी निर्धारित किया। ऐलिजाबेथ प्रथम ने महत्वपूर्ण विषयों पर समद की राय से काम करना शुरू किया। इस प्रकार यह स्थिति आ गई जिसमें इंग्लैंड के शासन अधिकार समद सहित राजा में निहित हो गये और दोनों में सहयोग चलन लगा। ट्यूडर काल में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पाप के नियन्त्रण से मुक्त हो गई।

स्ट्यूअर्ट काल

स्ट्यूअर्ट राजाओं ने 1603 से 1714 ई० तक राज्य किया। इस अवधि में राजा और संसद एक दूसरे के विरोधी थे। ब्रिटेन में यह भाग की जाने लगी कि राजाओं की शक्ति को मर्यादित करके ब्रिटेन में वैधानिक राजतन्त्र स्थापित किया जाय। स्ट्यूअर्ट काल में संसदीय लोकतन्त्र की आधार शिखा बहुत कुछ रत दी गई। इसी अवधि में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति (Glorious Revolution) हुई। इस क्रांति के बाद विनियम और मरी की समुन्नत शासन स्थापित किया गया। ब्रिटेन में निरंकुश राज्य समाप्त हो गया और समद की प्रभुता स्थापित हो गई। राजा की शक्ति में घटोती गई और विनियम में बढ़ती गई।

स्ट्यूअर्ट काल (Stuart Period) में जो प्रमुख शक्तिकारी सांविधानिक परिवर्तन हुए और संसद शक्ति विकास की जिन अत्यंत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ी—उनका संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है—

1. सर्वप्रथम 1628 में संसद चार्ल्स प्रथम से उस विख्यात “अधिकार याचना पत्र” (Petition of Rights) पर हस्ताक्षर कराने में सफल हुई जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि—

- (क) संसद की स्वीकृति के बिना राजा नये कर न लगाये,
- (ख) संसद की पूरा स्वीकृति के बिना राजा कोई धन उधार न ले,
- (ग) राजा बिना कोई निश्चित कारण बताये हुए ही किसी व्यक्ति को बन्दी न बनाये, एवं

(घ) राजा शांति काल में युद्ध सम्बन्धी कोई कानून लागू न करे।

2. सन् 1679 में “बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम” (Habeas Corpus Act) बनाया गया। यह निश्चित किया गया कि राजा जिन लोगों को बन्दी बनायेगा, उन पर तुरन्त ही न्यायालयों में अभियोग चलायेगा।

3. सन् 1689 में संसद द्वारा अधिकार-पत्र (Bill of Rights) पर विनियम और मेरी के हस्ताक्षर कराये गये। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि—

- (क) राजा संसद की पूरा स्वीकृति के बिना कोई नवीन कर नहीं लगायेगा।
- (ख) राजा को वष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी।
- (ग) राजा संसद की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई सेना नहीं रख सकेगा।
- (घ) अपने स्वाध के लिए “याय काय पर प्रभाव डालने के लिए राजा उच्चा युक्त जैसे नवीन “यामास”ों की स्थापना न कर सकेगा।
- (ङ) संसद के सदस्यों को भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा।

4. सन् 1701 में संसद ने समझौते का अधिनियम (Act of Settlement) पारित किया। यह निश्चय हुआ कि रानी ऐन की मृत्यु के उपरान्त यदि कोई उत्तराधिकारी राज्य का नहीं हो तो हेनारि वंश की राजकुमारी सोफिया और उसके उत्तराधिकारी इंग्लैंड के राजसिंहासन पर आसीन होंगे। इसके अनिवार्य रूप से एकट द्वारा अंग्रेजी जनता के धर्म, “याय और स्वतन्त्रता की रक्षा का आयोजन किया गया। इस सम्बन्ध में तीन धारारों विशेष प्रसिद्ध हैं—

- (i) इंग्लैंड के राजा को इंग्लैंड के चर्च का अनुयायी होना होगा।
- (ii) राजा किसी ऐसे देश की रक्षा के लिए संसद का वाक्य नहीं करेगा जो देश इंग्लैंड के अधीन न हो। उसे ऐसा करने के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (iii) राजा संसद की अनुमति प्राप्त किए बिना ब्रिटिश की सीमा के बाहर नहीं जायेगा।

5 विलियम और मेरी के शासनकाल के समाप्त होने से पहिले ही द्वि-दल प्रथा (Two party System) प्रारम्भ हो गई। इसकी उत्पत्ति सन् 1679-81 में हुई। चूंकि चार्ल्स द्वितीय के कोर्ट सन्तान न थी, अतः उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। संसद यह नहीं चाहती थी कि चार्ल्स द्वितीय का भाई जेम्स द्वितीय राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी हो क्योंकि वह पक्का कैथोलिक था। इसलिए संसद में बहिष्कार विधेयक (Exclusion Bill) रखा गया जिसके अनुसार जेम्स द्वितीय को चार्ल्स के दाद सिंहासन से बहिष्कृत करना था। विधेयक पर बड़ा मतभेद रहा और संसद व्हिग्ज (Whigs) व टोरी (Tories) लोगों के दो दलों में विभक्त हो गई। व्हिग्ज लोग विधेयक के पक्ष में थे जबकि टोरी लोग विपक्ष में। जिस प्रश्न को लेकर मतभेद पड़ा हुआ था वह तो शीघ्र ही हल हो गया लेकिन इन दोनों दलों ने परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों का रूप ले लिया। इसी समय से ब्रिटेन में द्वि-दल प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। वर्तमानकाल में व्हिग्ज लिबरल (Liberals) और टोरी और कन्जर्वेटिव (Conservatives) कहलाते थे।

6 सन् 1693 में राजा विलियम ने संसद के बहुमत वाले दल में से अपने मंत्री मण्डल का निर्माण किया। इस मंत्री मण्डल को उसने जुंटा (Junta) कह कर पुकारा। सभी से यह प्रथा चल पड़ी कि मंत्री मण्डल सदैव उसी दल का होगा जिसका संसद में बहुमत हो। इस प्रकार कैबिनेट (Cabinet) का प्रारम्भ हुआ।

7 सन् 1689 में सैन्य अधिनियम (Army Act) और सन् 1694 में त्रि-वर्षीय अधिनियम (Triennial Act) पास हुए। प्रथम में अनुसार सन्निवसों का एक वर्ष के लिए भर्ती किया जाना निश्चित हुआ जिससे राजा के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह प्रति वर्ष संसद की बैठक बुलाये। द्वितीय के अनुसार संसद की अवधि तीन साल के लिए निश्चित कर दी गई। चौथे ही समय सात वर्षीय अधिनियम (Septennial Act) पारित हुआ जिससे संसद का कार्यकाल सात वर्ष कर दिया गया।

8 सन् 1707 में स्कॉटलैंड का संयोग अधिनियम (Act of Union with Scotland) भी पास हो गया जिसने अनुसार वहां से भी साठ सभा और लोक सभा में क्रमशः 16 और 45 सदस्य भेजने की अनुमति मिल गई।

अंतिम चरण

ब्रिटिश संविधान के अंतिम चरण का प्रारम्भ हम सन् 1714 से मान सकते हैं जब हैनोवर वंश के जाज प्रथम का राज गद्दी मिली और तत्पश्चात् संसद की सदैव के लिए सर्वोच्चता स्थापित हो गयी। इस शक्ति वृद्धि के दो प्रमुख कारण थे—

(1) प्रथम तो संसद ने द्वारा ही सन् 1701 के गमनीय अधिनियम (Act of Settlement) के अनुसार वह राजा बनाया गया। इस परिस्थिति में उसे संसद के प्रति वृत्त होना पड़ा।

(11) दूसरे अंग्रेजी न जानने के कारण उसे प्रत्येक बात के लिए ससद पर ही निर्भर रहना पड़ा ।

कैबिनेट का विकास अथवा प्रधान मंत्री द्वारा मंत्री मंडल की अध्यक्षता का सूत्रपात—चूंकि हैनोवर राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने ससद व मंत्री-मंडल को स्वेच्छानुसार व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया । उन्होंने मंत्री मंडल की बैठकों में सम्मिलित होना और उसका समापन करवाना भी त्याग दिया । उनके स्थान की पूर्ति मंत्रियों में से ही एक ने प्रारम्भ कर दी और वह मंत्री प्रधानमंत्री कहलाया । इस प्रकार मंत्री मंडलीय (Cabinet) पणाली द्वारा, जिनमें एक प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री हों, शासन का कार्य करने की प्रथा ने बल पकड़ा । राजाओं के प्रसाधारण अधिकार धीरे धीरे उनके हाथों से निकल कर मंत्रियों और ससद के हाथ में आने लगे । राजा वास्तविक शासन न रहा, वह सांविधानिक प्रधान बन गया ।

मताधिकार एवं लोकसभा की शक्तियों का विस्तार—हैनोवर वंश के प्रारम्भ होत ही ससद के अधिकारों में वृद्धि अवश्य हुई फिर भी आंतरिक रूप में वह शक्ति शाली न थी क्योंकि वह जनता के एक अत्यंत छोटा भाग का प्रतिनिधित्व करती थी । वास्तव में 1714 के पश्चात् का इतिहास मताधिकार और लोकसभा की शक्तियों के विस्तार का इतिहास रहा । ससद ने अपनी शक्ति वृद्धि के लिए अनेक सुधार अधिनियम पारित किए जिनमें प्रमुख ये हैं—

(1) सन् 1716 में सप्त वर्षीय अधिनियम (Septennial Act) द्वारा लोक सभा की अवधि तीन वर्ष से सात वर्ष पर दी गई ।

(2) 1732 के अधिनियम द्वारा ससद में मध्यम श्रेणी के लोगों के प्रतिनिधियों का आना प्रारम्भ हुआ ।

(3) 1835 में ससद ने म्युनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार स्थानीय संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई ।

(4) सन् 1837 के सुधार नियम द्वारा मध्यम वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों के लोग और शहर के मजदूरों का भी मतदान का अधिकार मिला ।

(5) सन् 1884 के सुधार अधिनियम द्वारा वेतीहर मजदूरों का मताधिकार मिला गया ।

(6) सन् 1888 का स्थानीय सरकारी अधिनियम (Local Government Act) द्वारा काउन्टी बोर्डों की स्थापना हुई जिसे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे ।

(7) 1894 के स्थानीय सरकारी अधिनियम द्वारा प्रशासकीय काउन्टी प्रदेशों को महरी और देहाती जिलों में बांट दिया गया और इस बात की व्यवस्था की गई कि उनकी समितियां निर्वाचित हों ।

(8) सन् 1911 का संसदीय अधिनियम (Parliament Act) पारित हुआ जिसके अनुसार वित्त विधेयकों पर लोकसभा का एकाधिकार स्थापित हुआ और साद

सभा को केवल यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे विधेयकों को केवल दो वर्ष तक के लिए निलम्बित कर सके। सन 1949 में थम दल की सरकार ने उसकी शक्ति पर और भी अधिा प्रतिबंध लगा दिए। इन दोनों अधिनियमों ने लोकसभा की शक्ति में इतनी अभिवृद्धि कर दी कि वह संसार की जनतन्त्रात्मक निकायों में सर्वोपरि हो गई।

(9) सन् 1918 के अधिनियम द्वारा तीस वर्ष में अधिक आय की स्त्रियों को भी मतधिकार प्राप्त हुआ।

(10) सन 1926 के अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष में अधिक आय वाले स्त्री पुरुषों का मतधिकार मिला।

(11) बैंस्ट मिनस्टर का महत्वपूर्ण कानून बना, जिसके द्वारा राजा और उप निवेशा के पारस्परिक सम्बन्धों का नियम किया गया।

उपरोक्त विवरण लगभग 1300 वर्ष पुराने ब्रिटिश संविधान के विकास की कवचा मान सक्षिप्त रूपरेखा ही प्रस्तुत करते हैं, किन्तु इनसे यह स्पष्ट है कि विश्व के मध्य किसी भी देश में ऐसा राजनीतिक विकास नहीं हुआ जो इतने लम्बे समय तक निरंतर चलता रहा हो। ब्रिटिश संविधान में अनेक परिवर्तन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। विनाम का कम रखा नहीं है, वह अनिश्चित है।

ब्रिटिश संविधान का स्वरूप अथवा उसकी विशेषताएँ

(The Nature or Salient features of the British Constitution)

ब्रिटिश संविधान की कुछ निराली विशेषताएँ हैं। यह विश्व में सबसे प्राचीन है और अनेक राजनीतिक प्रणालियाँ इससे निराली हैं। इसके द्वारा अनेक प्रकार के राजनीति के क्षेत्र में विश्व का पथ प्रदर्शित हुआ। आज के अधिकांश संविधान बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान की ही नकल हैं। सब शक्तिशाली संसद, उत्तरदायी मंत्रि मण्डल, द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका, संविधानिक गणपालिका, कानून का शासन, स्वायत्त शासन आदि ब्रिटिश संविधानिक परम्परा की देन हैं। मुनगे ने ब्रिटिश संविधान को 'मातृ संविधान' (Mother Constitution) और ब्रिटिश संसद को 'मातृ संसद' (Mother Parliament) ठीक ही कहा है।

ब्रिटिश संविधान के स्वरूप और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं —

(1) अनुभव-जनित संविधान—ब्रिटिश संविधान जनता के अनुभव से प्रादुर्भूत हुआ है। ब्रिटिश जनता ने अपने अनुभव में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तित किया है। जनता के अनुभव के आधार पर उसमें जोड़ और घटाव होत रहे हैं। इसीलिए इसे 'अवसर और नुद्धि की सन्तान' कहा गया है। यह जासमुदाय का एक ऐसा भवन है जिसमें एक के बाद दूसरे अधिकारियों ने अपनी सुविधा और समय की परिस्थिति के अनुसार सुधार करने के लिए बड़ा प्रतिश्रम, सिद्धियाँ, बराबरी और स्तम्भों के रूप में योग दिया है।" आर्थर और जेन ने ठीक

ही लिखा है कि "ब्रिटिश संविधान "सिद्धांतों और आचरणों का एक समूह है जो एक सहस्र वर्ष के इतिहास का निरीक्षण करने पर ही एकत्र किये जा सके हैं।"

(2) अलिखित संविधान — ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता उसका अलिखित होना है। पर जैसा कि कहा जा चुका है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई लिखित कानून ब्रिटिश संविधान का अंग है ही नहीं। इसका आशय केवल यह है कि ब्रिटिश संविधान गंभीर लिखित (Partly written) और बहुत कुछ अलिखित (Mostly unwritten) है। यह कोई पूर्व निश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार शासन का संचालन होता चाहिए। इसका जान बूझ कर कभी निर्माण नहीं किया गया है। इसका विकास धीरे धीरे शताब्दियों में हुआ है। इसमें लिखित भाग में वे सब कानून हैं जिन्हें संसद ने समय समय पर बनाया है जैसे 1215 का मगना कार्टा 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1911 व 1949 के संसदीय कानून आदि। इस संविधान के अलिखित भाग में उन सांविधानिक परम्पराओं या अभिसमयों का स्थान है जो लिखित न होने पर भी लिखित कानून के समान ही मान्य है। इस प्रकार यह संविधान लिखित कानूनों और अलिखित प्रथाओं व परम्पराओं का मिश्रण है।

(3) विकसित संविधान — ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है जिसमें अपना वर्तमान स्वरूप युगों के विकास के बाद प्राप्त किया है। विचित्रता यह है कि इसका विकास एक ओर तो बिना पूर्व योजना के अवसर और आवश्यकतानुसार हुआ है तथा दूसरी ओर नियोजित ढंग से भी। उदाहरणार्थ, संसदीय कानून जहाँ सुनियोजित व्यवस्थापन द्वारा अस्तित्व में आये हैं वहाँ सांविधानिक परम्पराएँ अथवा अभिसमय या रूढ़िवादी परिस्थितियों की उपज हैं। फिर भी यह अवश्य है कि ब्रिटिश संविधान की योजना का तत्त्व सुविचारित न हो कर अधिराजत अस्त-व्यस्त सा है। इनमें जोड़ और छटाव होते रहते हैं। "यह एक ऐसा ढाँचा है जिसने मालिकों ने समय समय पर इसमें खम्भे, गोखे बरण्डे, आदि जोड़े हैं, जैसी उनमें आवश्यकताएँ प्रतीत होती गईं।" अनेक बार तो पुरानी बातों का समाप्ति किये बिना ही गई बातों का व्यवस्था कर दी गई है। इसी कारण इस संविधान में अनेक असंगतियाँ दृष्टों का मिलती हैं। वास्तव में ब्रिटिश संविधान एक बहुत पुरानी इमारत के समान है जिसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं और जो अब वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर ली गई हैं।

ब्रिटिश संविधान के धीरे धीरे विकसित होने के कुछ विशेष कारण रहे हैं। सबसे प्रथम तो अंग्रेजों का स्वभाव अधिराजत रूढ़िवादी है। वे ज्यादातर उन्हीं आवश्यक परिवर्तनों का स्वीकार करते हैं जिनसे अधिक से अधिक परम्परागत संस्थाओं की रक्षा की जा सके। दूसरे, अंग्रेज लोग सिद्धान्तवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। सिद्धान्तों की उपयोगिता की व्यावहारिकता की दृष्टि से पर, इस तरह वे सन्तुलन और बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। इस प्रकार आदिम परिवर्तनों

का खतरा मोल लेना वे अधिकतर पसन्द नहीं करते। इतिहास यताना है कि ब्रिटेन में प्राति द्वारा परिवर्तना की तुलना में विकास द्वारा परिवर्तना को ही अधिक पसन्द किया गया है।

ब्रिटिश संविधान के विकासशील होना एक कुछ निश्चित लाभ मिले है। इसी कारण ब्रिटिश संविधान प्रगतिशील रह सका है। इसी कारण नई परिस्थितियों से समझौता करके आवश्यकतानुसार वह अपना स्वरूप बदलता रहा है। ऊपर से ब्रिटिश संविधान पृथक् प्रतीत होता है पर आन्तरिक भावना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में राजतन्त्र कायम है किन्तु वह निरंकुश राजतन्त्र नहीं, बल्कि लोकतन्त्र है। यह तदनुरूपता यथाय है कि 'ब्रिटिश संविधान का प्रतीत वतमान में प्रवाहित हो रहा है और वतमान भविष्य में प्रवाहित होगा।'।

ब्रिटिश संविधान की विकासशीलता कुछ दृष्टियों में हानिकारक भी रही है। योजनाबद्ध ढंग में निर्माण न होने के कारण इसमें अनेक असंगतियाँ आ गई हैं। राजपद और लोकमता शानुग होने के कारण लोकतन्त्र में पूर्ण असंगत हैं। राजतन्त्र और लोकतन्त्र का सहस्रस्थित्व भी असंगतपूर्ण है। पर विशेषता इस बात में है कि इन असंगतियों के बावजूद संविधान का प्रवाह और परिवर्तन धीरे-धीरे रूप में चला रहा है। ब्रिटिश संविधान विकास और अविधि नता का आदर्श प्रस्तुत है। यह हजार वर्षों से भी अधिक होन वाले क्रमिक विनाश और विस्तार का फल है।

(4) सिद्धान्त और व्यवहार में अंतर— ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें सिद्धान्त और व्यावहारिक रूप में बड़ा अंतर पाया जाता है। 'इंग्लैंड में कोई बात जैसी दिखाई देती है वसी नहीं है और जैसी है वसी दिखाई नहीं देती।' बेजहाट (Bagehot) ने संविधान के इन दो रूपों का एक दूसरे के प्रतिफल बतलाया है। उसमें लिखित रूप में वह सजीवता नहीं है जो उसमें व्यावहारिक रूप में है और उसमें व्यावहारिक रूप में वह शासीता नहीं है जो उसमें लिखित सिद्धान्त में है।

बाहरी रूप तथा वास्तविक तथ्या के बीच अंतर अन्य संविधानों में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए संविधान में अनेक मतभेदों का दृष्टि से लोगों में पूर्ण स्वतन्त्रता है, लेकिन यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनमें जीवन का प्रत्यक्ष पक्ष साम्यवादी दल में नियंत्रित है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सबसे संविधान की सहायता में ही उस की सर्वोच्च संविधान (Supreme Soviet) या मंत्री परिषद् (Council of Ministers) का वास्तविक महत्त्व समझना चाहे तो वह नहीं समझेगा। पुनश्च, यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान का अनुशीलन करता रहे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बहुत गलत धारणा बना लेगा। परन्तु जमा कि प्रायः एकम् जिह (Og and Zink) ने लिखा है—'सभी शासकों में भिन्नता और अन्तर में अनेक भेद पाया जाता है लेकिन जिह प्रकार यह भेद ब्रिटिश नामक व्यवस्था का लाना जाना जाता है, यथा व्यवस्था नहीं करी है।

ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के इस महान् अन्तर को कुछ उदाहरणों द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है —

(1) सिद्धान्त इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है। सांविधानिक दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट सर्वोपरि है। उसी में सम्पूर्ण शक्ति निहित है। वह सम्पूर्ण विधि और धर्म का स्रोत है। वही संसद को ग्राह्य करता है तथा उसका विघटन और समावसान करता है। राज्य व सैनिक और द्रसेनिक अधिकारियों को वही नियुक्त और प्रपदस्थ करता है। सम्राट ही जल, धन और नभ सेवा का स्वामी है। युद्ध की घोषणा शांति एवं संधियाँ उगी के नाम से होती हैं। और तो और विरोधी दल भी राजा का है (His Majesty's Loyal Opposition), परन्तु यह सब उसका अवार्तविक अथवा सद्धान्तिक रूप है। व्यवहार में सम्राट इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता। उसकी सम्पूर्ण शक्तियाँ संसद अथवा मंत्रि मन्त्र के हाथ में आ गई हैं। राजा मंत्रि मण्डल का हाथ की कठपुतली है, यहाँ तक कि राजा संसद का अधिवेशन में जो भाषण देता है वह भी मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। बैजहोट (Bag-hot) का ठीक ही लगाया है कि यदि संसद के पाना सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उससे पात भेज दें तो उस पर भी उस हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। राजा केवल शक्ति का प्रतीक है, वास्तविक शक्ति उसके हाथ से निकल चुकी है।

आज ब्रिटन में जनता सम्प्रभु है और उस वास्तविक सम्प्रभुता का प्रतीक राजा (King) का हाथ में मुकुट (Crown) है। मुकुट प्रणामार्थी संस्था है, जबकि राजा प्रणामार्थी का व्यक्तिगत प्रतीक है। मुकुट की शक्ति यथाथ एवम् वास्तविक है जबकि राजा की शक्ति केवल नाम मात्र की। इस मुकुट की संस्था में मंत्री राजा प्रियी कमिल तथा संसद सम्मिलित हैं। वास्तव में यह एक विचित्र अवार्तविकता है कि ब्रिटन में सद्धान्तिक रूप से संसद और मंत्री मंडल केवल परामर्शदात्री संस्थायें हैं और राजा उनके परामर्श को मानने अथवा न मानने को पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह संस्थायें ही सर्वशक्तिमान हैं। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का इस भेद का आग में इन शब्दों में प्रकट किया है — 'इंग्लैंड की शासन पणाली अंतिम सिद्धान्त में निरंकुश राजतंत्र दलने में सीमित धार्मिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।

(2) ब्रिटिश संविधान की अवार्तविकता का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि सिद्धान्तानुसार संसद सर्वोच्च है, किंतु व्यवहार में संसद मंत्रि मंडल के हाथ की कठपुतली है। इसी तरह सद्धान्तिक रूप में सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद राजा (The King in Parliament) द्वारा किया जाता है लेकिन व्यवहार में अधिकांश व्यवस्थापन मंत्रि मंडल द्वारा ही होता है। ब्रिटिश मंत्रि मंडल इतना शक्तिवान है कि अपने बहुमत के बल पर वह मनस पर छाया रहता है और उसे अपने इशारे पर उठाता रहता है। बैजहोट (Baghot) के शब्दों में, "मंत्रि मंडल (संसद का) उत्पादन है,

लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादा कर्ताओं को भी समाप्त कर सकती है ।”

(3) सिद्धांत में लॉर्ड सभा के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है और वह अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, परन्तु वास्तव में न्याय सम्प्रदायी काय कानून के लार्डों (Law Lords) द्वारा ही सम्पादित किया जाता है ।

(4) ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और वास्तव में अंतर का एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत रूप में शक्ति का पृथक्करण दोषों की मिल्ता है जब कि वास्तव में वहां शासन की शक्ति पूर्णतः केन्द्रीकृत है । मर्यादित दृष्टि से विधि निर्माण की शक्ति संघद में, प्रशासकीय शक्ति मंत्री मण्डल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है । इसी सैद्धांतिक रूप से अभिनित होकर मोटस्वू ने अपनी रचना “स्प्रिट ऑफ लॉ” (Spirit of Laws) में लिख दिया था कि ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण का एक उत्तम उदाहरण है । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से हम यही देखने को मिलता है कि ब्रिटिश संविधान शक्ति पृथक्करण का पूरी तरह पम्पुन नहीं करता । आग एय जिक (Ogg and Zink) का मत है कि चाहे स्थायी न्याय पालिका के अस्तित्व की व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में शक्ति का आंशिक पृथक्करण हो परन्तु वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति का मिश्रण है । रामसेमूर (Ramsay Muir) ने भी ऐसा ही मत प्रकट करते हुए कहा है कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का मिश्रण है । हीवट (Hewart) ने अपनी पुस्तक “यू डेस्टाटिस्म” में यह प्रतिपादित किया है कि व्यवस्थापिका के विस्तार के कारण अब न्यायपालिका की शक्ति मंत्री मण्डल में केंद्रित होती जा रही है ।

ब्रिटिश संविधान की अवांछितताओं का तब इतना प्रबल है कि इसका न केवल ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे के बारे में भावनाओं में पड़ा की बल्कि कतिपय विद्वानों को यह कहने के लिए भी बाध्य कर दिया कि ब्रिटेन में संविधान जमीन किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है । मुनरो (Munro) ने इस तरह की बहुत सुंदर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—“किसी पदाधिकारी के नाम से कोई पदाधिकारी कार्य करता है संविधान के अनुसार तब किसी और तरह होना चाहिये, लेकिन पदाधिकारी उन कार्यों को किसी और ही ढंग से करते हैं । यही कारण है कि अपनी शासन प्रणाली का समर्थन करने में प्रसिद्धी लेता प्रयास प्रयासों में जो कुछ होना चाहिये उसका विचार करते हैं और अपने प्रयासों में यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तविकता उसमें मथवा मिला है । एती श्या में यदि डी गेबोविली ने वय का परित्याग करके न्यायवादीक स्वर में यह कह दिया कि ब्रिटेन में संविधान जमीन कोई वस्तु नहीं है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।”

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार की अवास्तविकता क्यों मिलती है? इन अवास्तविकताओं अथवा अंतरों के तीन प्रधान कारण हैं—वैधानिक विकास की प्रमिता, स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाने के बाद भी परम्परागत स्वरूप को बनाये रखने की प्रवृत्ति और अधिकांश परिवर्तना का परम्पराओं द्वारा अस्तित्व में आना। वास्तव में अंग्रेजों ने अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं को आमूल नष्ट नहीं किया है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हुए भी उन्होंने अपनी प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को उनके अवास्तविक रूप में ही बने रहने दिया है।

(5) लचीलापन—ब्रिटिश संविधान विश्व के लचीले संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। देश की व्यवस्थापिका संविधान में बिना किसी विशेष प्रक्रिया के उसी सरलता में थोड़े-थोड़े परिवर्तन या सज्जन कर सकती है जिस सरलता से वह साधारण कानून पास करती है। ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण करने वाली तथा संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति एक ही है। दूसरे शब्दों में सांविधानिक व साधारण दोनों प्रकार के कानूनों का एक सा स्तर है और दोनों में संशोधन सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। लॉर्ड ब्राइस (Lord Byles) के शब्दों में “संविधान के ढाँचे को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकतानुसार उस लीचा और मोड़ा जा सकता है।”

लचीला होने के कारण ब्रिटिश संविधान में यह विशेषता है कि अक्सर घाने पर परिस्थितियों के अनुरूप यह सुगमता और शीघ्रता से अपने में परिवर्तन कर सकता है। इससे उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलने हैं। सन् 1936 में जब एडवर्ड अष्टम ने गद्दी से त्यागपत्र दिया तो ब्रिटिश संसद ने केवल मात्र आठ घंटे के भीतर ही उसे बर्ध कर लिया। इसी तरह विगत महायुद्ध में संसद की निर्धारित अवधि बढ़ा दी गई। सन् 1939 में अंग्रेजों ने अपना प्रधानमंत्री भी बर्तल लिया, क्योंकि वह जर्मनी से युद्ध करने और कुशलतापूर्वक युद्ध संचालन के योग्य न था। शायद कहीं भी ऐसा उदाहरण सम्भवतः नहीं मिलेगा।

मैरियट (Marriot) के मतानुसार ब्रिटिश संविधान में लचीलापन इसलिए और भी अधिक पाया जाता है कि औपचारिक संशोधनों के बिना भी उसमें संशोधन हो सकते हैं। संविधान में परम्पराओं के परिवर्तन द्वारा जो संशोधन होते हैं वे इसी प्रकार के गमोचन हैं।

(6) एकात्मक—ब्रिटिश संविधान एकात्मक (Unitary) है। शासन की समस्त शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित हैं। सम्पूर्ण शक्तियाँ सन्दर्भ में अधिष्ठित केन्द्रीय सरकार में हैं, वही से समस्त देश का प्रशासन होता है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बड़ा विभेदिकरण को अपनाया गया है, किन्तु केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों में किसी प्रकार का विषयो का कानूनी बटवारा नहीं है।

स्थानीय सरकारों पर प्रणामन का उत्तरदायित्व है, परन्तु शक्ति का स्रोत एक ही है। स्थानीय संस्थाएँ अपनी शक्तियाँ सघीय अधिनियमों से प्राप्त करती हैं। केन्द्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छानुसार संकुचित या विस्तृत कर सकती है। ब्रिटेन में अनिश्चित संविधान के होने हुए भी शासन व्यवस्था का कार्य चला रहा है और इसका कारण शासन के एकात्मक स्वरूप की विद्यमानता है। सघात्यक राज्य व्यवस्था के लिए तो संविधान लिखित और कठोर होना बहुत आवश्यक है।

(7) सांविधानिक राजतन्त्र—सामान्यतः संविधान” और “राजतन्त्र” सहगामी नहीं हो सकते क्योंकि जहाँ संविधान शासनतन्त्र के लिए अकुल और मर्यादा का प्रतीक होता है वहाँ राजतन्त्र निरंकुशता का चिह्न। जैकिन ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादा का प्रतीक संविधान और निरंकुशता का चिह्न राजतन्त्र दोनों साथ साथ विद्यमान हैं। ब्रिटिश शासन का स्वरूप “समुकुट लोकतन्त्र” (Crowned Democracy) का है। ब्रिटिश साम्प्रदायिक विकास की यह विशेषता रही है कि समय की गति के साथ निरंकुश राजतन्त्र अपनी जननीकरण की दिशा में प्रसरण होता गया और इस तरह उसने अपना आधुनिक रूप ग्रहण कर लिया।

(8) मन्त्रीय शासन व्यवस्था—ब्रिटिश संविधान देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय शासन के अनुसार ब्रिटेन में कार्यपालिका की दृष्टता बनमान है। सम्प्रति (अथवा साम्प्रति) सिर्फ नाम मात्र का वैधानिक प्रबन्ध है जब कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ उन मंत्रियों के हाथ में हैं जो संसद के सदस्य होने हैं और उससे विश्राम-गपत अपने पद पर रहते हैं।

कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। प्रधानमन्त्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संसद के बहुमत दल में से होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मंत्रिमण्डल संसद के सम्मुख होने के नाते विधायक या सभार करता है और उन्हीं व्यवस्थापिका में प्रस्तुत व मंचालित करता है। मन्त्री एक सभारता अधिष्ठाता प्रबन्ध (Executive heads) होते हैं और दूसरी ओर संसद सदस्य। इस नाते व शासन के विधायी और अधिष्ठाता (कार्यकारी) भाग में सम्मिलित स्थापित करता है। वे होट (Bigshot) न इमीनिए कहा है कि इंग्लैंड में मन्त्रिमण्डल एक ऐसा यंत्र है जो जोड़ता है, एक ऐसा बंधुषा है जो अधिष्ठाता तथा विधायी विभागों का धारण में बाधता है। दूसरी ओर व्यवस्थापिका भी प्रदत्त कटोरी प्रस्तावों अविवकाश प्रस्तावों आदि द्वारा कार्यपालिका पर पूरा नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल लोक-गणों के विश्राम-गपत ही पालीन रहता है। शासन का विभागों के दले पर या तो विरोध दल नया मन्त्रिमण्डल बनाता है या जोर लगा भग हा कर नये निर्वाचन होने हैं और

फिर बहुमत दल मंत्रि मण्डल का निर्माण करता है। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एकता का मूल तत्व सग्न बने रहता है।

उपयुक्त प्रसंग में मोनटेस्क्यू के इस मत पर टिप्पणी आवश्यक है कि ब्रिटेन में शासन के तीनों अंगों का वाय क्षेत्र पूरातः पृथक् पृथक् है। पर वास्तव में ब्रिटेन में तो शासन की शक्ति केन्द्रीभूत है। यद्यपि ओग एंड जिंक (Ogg and Zink) के अनुसार इंग्लैंड में 'शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आशिक रूप में लागू हुआ है जिसका प्रयोग केवल न्यायपालिका के विषयों में होता है,' पर आज पवर्ति यह है कि व्यवस्थापन के विस्तार के कारण न्यायपालिका की शक्ति भी कार्यपालिका में केन्द्रित होती जा रही है। बीसवीं शताब्दी में विकसित प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासकीय न्याय-व्यवस्था इंग्लैंड के शक्ति एकीकरण सिद्धांत को सबल करती है। इसका प्रतिरिक्त लाड सभा व्यवस्थापिका का अंग होते हुए भी अपील के अन्तिम 'न्यायालय' के रूप में कार्य करती है और तब मंत्रि मण्डल का सग्न लाड का सलर मुख्य 'न्यायाधीश' के पद पर आसीन होता है। इन सब व्यवस्थाओं के कारण यह कहना आतिपूर्ण है कि इंग्लैंड में शक्ति का पृथक्करण है।

संसदीय शासन-प्रणाली की तीसरी मुख्य बात कार्यपालिका के कार्यकाय का अनिश्चित होना है। यह विशेषता ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में विद्यमान है। ब्रिटिश न्यायपालिका का कार्य काल अनिश्चित है क्योंकि लोअसभा का विश्राम होने पर वह कभी भी समाप्त हो सकती है।

(9) संसद की सर्वोच्चता—ब्रिटिश संविधान की मूलभूत विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। वैधानिक दृष्टि से उसकी प्रभुसत्ता असीम है। कार्यपालिका उसी के प्रति उत्तरदायी है। कानून बनाने, संशोधन करने, रद्द करने अथवा कानून का विस्तार करने आदि का उसे पूरा अधिकार है। साधारण कानूनों के निर्माण के साथ ही साविधानिक कानूनों के निर्माण में भी वह उत्तरी ही सत्ताधान है। संसद में पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार 'न्यायपालिका' की नहीं है। संसदीय कानून अन्तिम होता है जिह देश की कोई समस्या चुनोती नहीं दे सकती है।

यह स्मरणीय है कि संसद की सर्वोच्चता केवल वैधानिक दृष्टि से ही है। व्यावहारिक दृष्टि से उसकी सर्वोच्चता पर अनेक नैतिक और परम्परागत बातों का प्रकुश लगा रहता है। वह परम्परागत साविधानिक अभिसमयों की उपक्षा नहीं कर पाती और न ही लांघन की अवहेलना कर सकती है। संसद का सपूर्ण कार्य सदैव उत्तरदायित्व की भावना के साथ होता है। संविधान का संशोधन करते समय उसे विभिन्न मनावैज्ञानिक और स्व आरोपित प्रतिबंधों का ध्यान रखना होता है। इसके अतिरिक्त उसके लिए यह भी संभव नहीं है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय

1 पहला प्रमुख लक्षण यह है कि "व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड दिया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं।" इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्रिटेन में तब तक किसी भी व्यक्ति को साम्प्रतिक अथवा शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता जब तक कि देश के न्यायालयों द्वारा तथा सामान्य कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत यह निश्चय न हो जाय कि वह व्यक्ति कानून के उल्लंघन करने का दोषी है।

2 दूसरा अर्थ "कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानून के अधीन होना है।" दूसरे शब्दों में, केवल राजा को छोड़कर, क्योंकि वह पदेन कोई अपराध नहीं कर सकता, ब्रिटेन का प्रत्येक व्यक्ति एक ही कानून को मानने के लिए बाध्य है और उस पर साधारण न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है। इस बार में सरकारी कर्मचारी अथवा साधारण व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। ब्रिटेन में केवल एक ही प्रकार की विधि है जो सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है और यहाँ एक ही प्रकार के न्यायालय हैं तथा सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति उनके द्वारा दण्डनीय हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश 'विधि शासन' की पद्धति के स्थान पर फ्रांस में 'प्रशासनिक कानून' (Administrative Law) की पद्धति है, जिसके अन्तर्गत वहाँ साधारण नागरिक और सरकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के कानूनों के समूह और दो ही प्रकार के पृथक् न्यायालय हैं।

स्मरणीय है कि 'कानून के सम्मत् सब की समानता' के कुछ अपवाद (Some exceptions) भी हैं, जो निम्न हैं—

(क) 'राजा कोई गलती नहीं कर सकता', यह इंग्लैंड की एक कानूनी कहावत है। इंग्लैंड में ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जिसमें राजा पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सके।

(ख) यदि राज्य कर्मचारी अपने प्रशासकीय कृत्यों का पालन करते हुए कोई भूल करता है तो उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(ग) न्यायाधीश भी अपने गैर सरकारी कार्यों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुक्त हैं, यद्यपि यह सिद्ध हो जाय कि उन्होंने दुष्प्रवृत्ति से कार्य किया है।

(घ) सेना के लागू अथवा धर्माधिकारियों भी सामान्य कानून के क्षेत्र से बाहर हैं। उनमें लिए आश्रित सैनिक अथवा ऐक्जिस्टिंग्स लॉ (Ecclesiastical Law धर्म कानून) जैसे अन्य कानूनों की व्यवस्था है।

3 आखिरी के अनुसार विधि शासन में तीसरा अर्थ यह निहित है कि "ब्रिटेन के विधान के सामान्य सिद्धान्त न्यायाधीशों के लिए या के परिणामस्वरूप हैं जो उनके सामने लगाय गये अभियोगों में धराजकीय (साधारण) व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण करते हैं।" सरस शब्दों में हमका तात्पर्य यह निकलता है कि कानून से सामान्य में, जिनकी संविधान में स्पष्टता नहीं है, न्यायालयों के लिए ही अन्तिम

मान गये हैं। इन 'यायिक' नियमों में हम सामाजिक तत्त्व मिलते हैं और व्यक्ति-स्वतंत्रता सम्बन्धी विधियाँ इन्हीं नियमों का परिणाम हैं।

स्पष्ट है कि 'विधि शासन' नागरिकों की स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध रक्षा और कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है। वह कानून के धामे सब वर्गों के व्यक्तियों की समानता स्थापित करता है और अन्त में संविधान को देश के सामान्य कानून पर आधारित करता है। विधि शासन स्वेच्छाचार से भिन्न है। शासन की शक्तियाँ मनमाने ढंग से नहीं बल्कि कुछ सुनिश्चित और बंधनकारी नियमों के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। विधि शासन नागरिकों की स्वतंत्रता का महान् प्रतीक है जिसे ब्रिटिश जाति ने शताब्दियों के संघर्ष के उपरान्त प्राप्त किया है।

विधि शासन से प्राप्त नागरिक अधिकार—ब्रिटिश संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं है किन्तु ब्रिटिश नागरिकों को अन्य किसी भी देश से कहीं अधिक मौलिक अधिकार 'विधि शासन' के अंतर्गत मिले हैं जो संसद के विविध अधिनियमों, 'यायिक' नियमों और सामान्य विधि में अन्तर्निहित हैं। कुछ मुख्य मौलिक अधिकार ये हैं—

(1) नागरिकों को शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता है, उनसे अत्यधिक जमानत नहीं माँगे जाने की व्यवस्था है उन्हें अमानवीय व असह्यारण दण्ड नहीं दिए जाते उन्हें संसद में शरीर शिकायतों के प्रायना पत्र भेजने का अधिकार है।

(2) ब्रिटिश नागरिकों का भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। वे अपने विचार अभिव्यक्त करने और उन्हें प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं अर्थात् कि वे वास्तव में प्रपमानकारी और अश्लील न हों।

(3) नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। शासन न धर्म निरपेक्षता का आदेश प्रपनाया है केवल राज्य का अध्यक्ष 'अंग्रेजी चर्च' को मानने वाला होना चाहिये।

(4) समाज और सम्मेलन करने की उन्हें स्वतंत्रता है—परन्तु इस पर कुछ आवश्यक मर्यादाएँ हैं—सभाओं की प्रजाजनों की दृष्टि में निराना, असंतोष व राय उत्पन्न करना, जनता को अशांति, हिंसा और अव्यवस्था के लिए उत्तेजित करना शासन और संविधान के विरुद्ध घृणा पैदा करना या शारीरिक शक्ति द्वारा कानून में परिवर्तन करना राजद्रोह है।

(5) ब्रिटिश नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता है, किन्तु संघ का उद्देश्य और उसने साधन धार्मिक होना चाहिये। नागरिकों की जीवन की व शारीरिक स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी कार्यवाही के प्राण अथवा शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

विधि शासन का ह्रास—आधुनिक काल में विधि शासन की ओर कुछ अथवा प्रकट हो गयी है। विधि के नियम का स्वरूप आज कुछ बर्तन सा गया है। इन पर विशेषतः निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ा है—

- 1 हस्तान्तरित कानून का प्रचलन,
- 2 ससद् के विशेष अधिनियम, एवं
- 3 विभिन्न विभागों के 'याय सम्बन्धी अधिकार ।

आज राज्य का स्वरूप तेजी से जन-वत्याणकारी राज्य होता जा रहा है । ब्रिटेन में ही नहीं सर्वत्र राज्य का कार्य-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है । अतः ससद् को इतना समय नहीं मिलता कि कानून बनाते समय सब विवरण की बातों को भी वह उगमे सम्मिलित कर सके । ससद् समयान्तर के कारण अधिकांश कानूनों को पूर्ण रूप में न बनाकर उनकी स्थूल रूप-रेखा मात्र बना देती है और शेष कार्य विभागीय अध्यक्ष करते हैं । इनको हस्तान्तरित कानून की सजा दी जाती है । यही नहीं, बहुधा विभागाध्यक्षों को मूल नियमों में भी परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है जिससे विभागीय अध्यक्षों की नई निरंकुशता (New Despotism) को प्रोत्साहन मिलता है । इसी कारण कुछ व्यक्तियों का कहना है कि या तो विधि-शासन केवल बहकावा है या पौराणिक कथा मान, वस्तुतः आज ससदीय कानून के शासन का महत्त्व कम होता जा रहा है और कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार शासन का आधिक्य होता जा रहा है ।

विधि शासन के ह्रास होने का दूसरा कारण यह है कि ससद् के विशेष अधिनियम बहुधा जनता के अधिकारों की सीमाएं कर देते हैं । उदाहरणार्थ, सन् 1893 को 'सार्वजनिक' कर्मचारी रक्षा सम्बन्धी अधिनियम (Public Authorities Protection Act of 1893) जिसका संशोधन 1939 के (Limitation Act of 1939) द्वारा हुआ था और सन् 1947 का 'क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट' (Crown Proceeding Act, 1947) जैसे अधिनियम नागरिकों के अधिकारों का राज कर्मचारियों के विरुद्ध नियन्त्रित करते हैं । इन अधिनियमों के द्वारा साधारण व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा पर कुठाराघात हुआ है, क्योंकि जहाँ एक ओर इनसे सामान्य नागरिकों के अधिकारों व उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगे हैं वहाँ दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को सामान्य कानून (Common Law) की पकड़ में आने से बचाने की व्यवस्था भी की गई है । सन् 1902 के 'शिदा' अधिनियम, 1919 के 'विश्व' अधिनियम, 1912 के 'राष्ट्रीय बीमा' अधिनियम आदि ने विभागीय पदाधिकारियों की शक्तियों में आशातीत वृद्धि की है ।

विधि शासन के ह्रास का तीसरा प्रमुख कारण यह है कि विभिन्न विभागों के 'याय सम्बन्धी अधिकार' बढ़ते जा रहे हैं और बहुधा उनके निणयों के विरुद्ध अपील संभव नहीं होती । मुकदमे चलाते चले के हाथ ही में निणय करने की शक्ति देना 'याय' की उपेक्षा करना है । आधुनिक समय में ब्रिटेन में विधि-शासन के अनेक अपवाद नज़र आते हैं । फौजी लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया

जाता है, डाक्टरों के लिए मेडिकल कौन्सिल हैं जो उन पर अभियोग चलाती हैं और पादरिपा की काय-नुति दिखाने पर दण्ड देने का अधिकार धार्मिक न्यायालया की है।

उपरोक्त समस्त तर्कों से यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि ब्रिटन में नागरिकों की स्वतन्त्रता की स्थिति सुरक्षित नहीं है और विधि शासन महत्वहीन अथवा मृत हो चुका है। विधि शासन आज भी ब्रिटिश राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग और जनता के अधिकारों व स्वतन्त्रता का प्रहरी है। ब्रिटिश न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी आज भी संदेह से परे है। ब्रिटेन में चाहे ऐसे कानून निम्न हो गए हों कि जिनमें विधि शासन की भावना को ठस पहुँचती है, परन्तु वेड व फिलिप्स (Wade and Philips) के शब्दों में जनता का यह विश्वास अब भी है कि "कर्मचारीगण साधारण न्यायालया के काम क्षेत्र से बचे हुए नहीं हैं और इंग्लैंड के कानून की दृष्टि में असाधारण न्यायालया द्वारा निवटाए गए अपराधों का कोई महत्त्व नहीं है।"

संक्षेप में, ये ही ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वास्तव में ब्रिटिश संविधान राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र का सर्वोत्तम और कल्याणकारी मिश्रण है। परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को बदल लेने की इसमें क्षमता है। इसे बीसवीं शताब्दी का एक न्यायिक प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील संविधान कहा जा सकता है।

ब्रिटिश संविधान की कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ

(Modern Tendencies of the British Constitution)

कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ ब्रिटिश-शासन के स्वरूप को बदल रही हैं। ये मुख्यतः इस प्रकार हैं—

(i) ब्रिटिश संविधान प्रमुखतः अलिखित है, किन्तु अब इसमें परिवर्तन लाने के लिए अधिकांश लिखित कानूनों का सहारा लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

(ii) ब्रिटिश सामान्य-प्रवस्था एकात्मक है किन्तु सन् १९२२ में इसमें विवेकीकरण के चिह्न प्रकट होत जा रहे हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स का संघीय शासन सम्बन्धी स्वायत्तता देने की मांग गत वर्षों में की गई है। उत्तरी आयरलैंड में पृथक् संसद के संस्थापन ने इस आन्दोलन को बल प्रदान किया है।

(iii) शासन-व्यवस्था में जनतन्त्र का अधिकाधिक विकास हुआ है। उदाहरणार्थ, १९४९ में लॉर्ड-मैग्ना की शक्तियों को एकदम घटा दिया गया, १९४८ में विश्वविद्यालयों के छात्रसभा में प्रतिनिधित्व का संपादन कर दिया गया और स्त्रियों को लॉर्ड-मैग्ना की सदस्यता का अधिकार दिया गया।

(iv) संसद की शक्ति का ह्रास और मन्त्रीमण्डलीय शक्ति में वृद्धि ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख आधुनिक प्रवृत्ति है। मन्त्रीमण्डल के हाथ में देश की वास्तविक प्रशासकीय और विधायिकीय शक्ति इतनी अधिक चली आई है कि अब मन्त्रीमण्डलीय निरंकुशता अधिक यथार्थ दिखाई देती है।

(v) ब्रिटिश उपनिवेशों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है और अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश स्वतन्त्र हो गए हैं। 1949 में राष्ट्रमण्डल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट है और स्वतन्त्र गणतन्त्र बनने के उपरान्त भी भारत, पाना, पाकिस्तान आदि राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं।

(vi) ब्रिटेन के दोनो प्रमुख दलों में साविधानिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अधिक सहमति और निकटता बढ़ने की प्रवृत्ति है। एक ओर श्रमिक दल की प्रतिवादी विचारधारा में संशोधन हुआ गया है और दूसरी ओर अनुदार-दल की विचारधारा में पर्याप्त प्रगति हो गई है।

2

अभिसमय अथवा वैधानिक परम्पराएं (CONVENTIONS OF THE CONSTITUTION)

“अभिसमय राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं, जिनकी स्थापना
परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परम्पराओं के
अनगत नहीं बल्कि इनसे पर्यवर्तित उनके प्रकट के रूप में और
उनसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है।

ब्रिटिश संविधान में यह उद्देश्य है—

कामपालिका और व्यवस्थापिका को

जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी

बनाना।”

—हर्मान फाइनर

विश्व की लगभग प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अभिसमयों अथवा
वैधानिक परम्पराओं (Constitutional Conventions) का महत्वपूर्ण स्थान
रहा है। संविधान के लिखित या अलिखित सभी स्वरूपों में इन्होंने उसके विस्तार
में काफी महयोग दिया है। ब्रिटन को तो ‘अभिसमयों की शास्त्रीय भूमि’ (Classic
Land of Conventions) कहा जाता है। वास्तव में ब्रिटिश संविधान के जन्म,
जीवन और मरण की कहानी अभिसमयों की कहानी है। इनकी बहुलता के कारण
ही ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहा जाता है। इन्हें अच्छी तरह समझे बिना
ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अधूरा ही है। अमेरिका, कनाडा, स्वीटजरलण्ड,
भारत आदि देशों में भी अभिसमयों का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

अभिसमयों का स्वरूप

(Nature of Conventions)

हायती ने अभिसमयों को ‘संविधानिक परम्पराओं (Constitutional
Conventions), ज. एम. मित्र ने ‘संविधान के अलिखित नियम (Unwritten

Maxims of the Constitution) और ए-सन ने 'साविधानिक रीति रिवाज, (Customs of the Constitution) कहा है। आग एव जिक ने अभिसमयो का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है—“इनका निर्माण उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर होता है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम-मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी मायजतिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के सम्बन्धों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। ये अभिसमय कानून के सूखे ढाँचे पर मांस चढ़ाते हैं, कानूनी सविधान को चालू रखते हैं और उसे, बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक विचारों के अनुसार सन्तुष्ट करते रहते हैं।”

अभिसमय कानून द्वारा सुरक्षित न होते हुए भी कानून की तरह माय होते हैं। समाज में उनका इतना सम्मान होता है कि लोग सामान्यतः उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करते। ब्रिटेन में तो इन अभिसमयों अथवा वैधानिक परम्पराओं पर ही शासन विधान का अधिकांश ढाँचा निर्भर है। अभिसमयों के कारण ही ब्रिटिश संविधान सभ्यता का सबसे लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान के लिखित तत्त्व तो राजकीय प्रक्रिया के केवल छोटे से भाग का ही नियमन कर पाते हैं, शेष कमियों को ये अभिसमय ही पूरा करते हैं और इन तरह कानूनी संविधान को काय-रूप देते हैं।

अभिसमयों के इस स्वरूप में उनकी निम्नलिखित तीन प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं—

(1) अभिसमयों का स्रोत संसद की विधि निर्मात्री शक्ति नहीं है बल्कि प्रथाएँ हैं। धीरे-धीरे प्रयोग और व्यवहार में आते आते कुछ प्रथाएँ प्रशासन के दैनिक संचालन के लिए अनिवार्य हो जाती हैं और तब उनका रूप वैधानिक परम्पराओं या अभिसमयों का हो जाता है।

(2) अभिसमयों को कानून द्वारा मायता नहीं दी जाती और न्यायालयों द्वारा उन्हें क्रियाचित नहीं किया जाता। अभिसमयों का पालन किए जाने का कारण उनकी महान् उपयोगिता है। एक लम्बे समय से धीरे-धीरे प्रयोग में आते-आते अभिसमय ऐसी उपयोगिता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि जनमत उनकी अवहेलना करने वालों की दृष्टि से नहीं देखता।

(3) समय के साथ अभिसमय उसी प्रकार का पवित्र स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जैसा साविधानिक कानूनों का होता है।

अभिसमयों की उत्पत्ति

अभिसमयों का जन्म प्रायः दो कारणों से होता है—

(1) यदि देश के कानूनी ढाँचे और तत्कालीन वैधानिक विचारधारा में भिन्नता होती है तथा तत्कालीन वैधानिक विचारधारा में जनता इतनी थका रहती है कि कानूनी ढाँचे को इसके अनुकूल बनाना अनिवार्य हो जम्ब तो बहुधा यह

अनुकूलता प्राप्त करने के लिए अभिसमयों की सहायता ली जाती है। इंग्लैंड का कानूनी ढांचा राजन्यायीय है जबकि प्रचलित विचारधारा प्रजातन्त्रीय है। दोनों में अनुकूलता पैदा करने के लिए अनेक अभिसमयों का जन्म हुआ है, जैसे सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जनता की संसद द्वारा पास किया हुआ होता है और इसी प्रकार मन्त्रीमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

(2) अभिसमयों की उत्पत्ति का दूसरा कारण यह है कि कभी-कभी कानून कोई गैर (Gap) छोड़ देता है और उसकी पूर्ति के लिए अभिसमयों या प्रथाओं का जन्म होता है।

कानून और अभिसमय के भेद

मायता की दृष्टि से समान प्रभाव रखते हुए भी, कानूनों और अभिसमयों में पाए जाने वाले अंतर प्रधानतः तीन हैं—

(1) सांविधानिक अभिसमयों की अपेक्षा सांविधानिक कानून अधिक पवित्र और माननीय समझा जाता है। अभिसमय केवल राजनीतिक नैतिकता का विषय होता है जबकि कानून किसी विधि-निर्मात्री शक्ति की इच्छा का परिणाम है। अतः जहाँ परम्परा के पालन का आधार इच्छा होती है, वहाँ कानून के पालन का आधार शक्ति है। कानून का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य करना पड़ता है, जबकि प्रत्येक अभिसमय के पालन के पीछे 'अनिवार्य' शब्द नहीं जुड़ा रहता। उदाहरण के रूप में यह एक अभिसमय है कि कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन प्रत्येक सदन में होने चाहिए, परन्तु यदि इस अभिसमय को भंग करके संसद दो ही वाचनों के बाद विधेयक को कानून बना दे तो इसमें 'अनिवार्यता' टूटने वाली कोई बात नहीं होगी और न ही किसी कानून का उल्लंघन होगा।

परन्तु इससे यह अनिवार्य बंदापि नहीं लेना चाहिए कि अभिसमयों का महत्त्व कानूनों से शीघ्र है। अनेक अभिसमयों के महत्त्व का तो कानूनों से भी बड़ा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह सोचना भी कठिन है कि कोई मन्त्रीमण्डल लोकसभा का विद्रोह होने पर भी त्याग पत्र न दे अथवा दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक पर सम्राट या सम्राज्ञी हस्ताक्षर न करे।

(2) कानून सामान्य रूप में सटीक और सुनिश्चित दायित्वों में व्यक्त होता है लेकिन अभिसमयों का निर्माण ऐसे नहीं होता। अभिसमय तो प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होते हैं और उनमें परिवर्तन भी प्रचलित प्रथा के आधार पर होता है। कभी-कभी यह ज्ञात करना भी कठिन हो जाता है कि कोई प्रथा अभिसमय बन गई है अथवा नहीं। कानून विधि निर्मात्री शक्ति द्वारा निश्चित रूप में विहित किया जाता है, जबकि अभिसमय सदा जलित हो रहा है।

(3) कानूनों की 'मायता' की शक्ति प्राप्त रहती है। मायताओं के

द्वारा उह लागू किया जाता है, परन्तु अभिसमयों की शक्ति प्राप्त नहीं रहती और न ही 'यायालयों' द्वारा उह लागू किया जाता है। 'यायालय' कानूनों के समान अभिसमयों की रक्षा नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा किसी अभिसमय अर्थात् वैधानिक परम्परा का उल्लंघन किया जाय तो उसने लिए 'यायालय' में अभियाग नहीं चलाया जा सकता, परन्तु यदि किसी कानून का उल्लंघन हो तो व्यक्ति और सरकार दोनों ही 'यायालय' की शरण ले सकते हैं और 'यायालय' से दण्डनीय हैं।

सब पूछा जाए तो कानून और अभिसमय में कोई स्पष्ट विभाजन देना सीखना कठिन है। दोनों ही शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्त्व हैं। दोनों का पालन समान रूप से होता है। दोनों अनेक बार साथ साथ चलते हैं। विशिष्ट बात मूलतः केवल यह है कि दोनों के पालन के आधार भिन्न भिन्न हैं। कानून का पालन इसलिए होता है कि उसके पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है, जबकि अभिसमय का पालन इसलिए होता है कि उसके पीछे 'उपयोगिता' और 'जनमत' का बल होता है।

ब्रिटेन के साविधानिक अभिसमयों का वर्गीकरण

ब्रिटिश साविधानिक अभिसमयों की पूरी सूची देना यहाँ संभव नहीं है। ब्रिटिश अभिसमय अनेक प्रकार के हैं। कुछ का सम्बंध राजा (या रानी), उसके कानून और उसकी शक्तियों से है। कुछ मन्त्रिमण्डल से सम्बंधित हैं। इसी तरह कुछ अभिसमय संसद के विषय में हैं तो कुछ राष्ट्रमण्डल के बारे में। इन अभिसमयों में उल्लेखनीय ये हैं—

(क) राजा से सम्बंधित अभिसमय—(1) राजा अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है।

(2) मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए राजा लोकसभा के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

(3) प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित मन्त्रिमण्डल को राजा अपने मन्त्रिमण्डल के रूप में स्वीकार कर लेता है।

(4) राजा संसद को प्रतिवर्ष एक बार अवश्य आहूत (Summon) करता है।

(5) राजा मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता।

(6) प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राजा लोकसभा का विघटन करता है।

(7) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये विधेयकों पर राजा को अनुमति (Assent) देनी ही होती है।

(ख) मन्त्रिमण्डल से सम्बंधित अभिसमय—इस समूह में प्रमुख ये हैं—

(1) मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से संसद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी है।

(2) मंत्रिमण्डल सामूहिक और सम्मिलित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार काम करता है।

(3) मंत्रिमण्डल को लोकसभा का विश्वास-पात्र न रहने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो राजा को लोकसभा का विघटित करने का परामर्श दे सकता है।

(4) मंत्रिमण्डल को अपने सम्पूर्ण प्राधिकार के साथ धरे हुए सकट का प्रतिहार करना चाहिये, लेकिन उसे तुरन्त संसद् को आमंत्रित करके उससे मन्त्रणा अवश्य करनी चाहिये।

(ग) संसद् से सम्बन्धित अभिसमय—इनमें उल्लेखनीय ये हैं—

(1) लोकसभा के अध्यक्ष को निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिये और उसे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन में खड़ा होने से पूर्व अपने दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए।

(2) अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन होना चाहिए और जितनी बार वह चाहे, उसे निर्वाचित किया जाना चाहिए।

(3) अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करना चाहिए कि मनस्व स्वयं नियंत्रण कर सके।

(4) लार्ड-सभा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती हो, तब कानूनी लॉर्डों (Law-Lords) को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और उन्हें छोड़कर अब किसी लॉर्ड अथवा पीयर को लार्ड-सभा के न्यायिक मामले में भाग नहीं लेना चाहिये।

(5) लोकसभा किसी वित्तीय विधेयक पर तभी विचार करती है जबकि उसे राजा (अर्थात् कैंब्रिज) की सिफारिश पर पेश किया जाये।

(6) लोकसभा अनुदान की मांग (Demand for grant) में कमी कर सकती है और उसे अस्वीकार कर सकती है किन्तु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती।

(7) कानून बनने से पहिले प्रत्येक विधेयक का तीन बार वाचन (Read ing) होना चाहिये।

(8) शासक-दल की ओर से एक भाषण हान के पश्चात् दूसरा भाषण विरोधी दल के सदस्य का होता है।

राष्ट्रमण्डल से सम्बन्धित अभिसमय—इस श्रेणी के प्रमुख अभिसमय ये हैं—

(1) राष्ट्र-मण्डल सम्बन्धी विषयों में राजा को अपने राष्ट्र-मण्डलीय विभाग के मंत्री से परामर्श करना चाहिये।

(2) किसी भी उपनिवेश के सम्बन्ध में संसद् सभी वार्ड कानून बनायगी

जब उपनिवेद की ओर से इस बारे में स्पष्ट प्राथना की गई हो और ऐसा करने की उसकी ओर से स्पष्ट अनुमति दी दी गयी हो।

ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके अतिरिक्त इन अभिसमयों का रूप प्रगतिशील है, अतः वे समय की प्रगति के साथ, और लोगों के व्यवहार के अनुरूप बदलती व बढ़ती रहती है।

अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है ?

यह कहा जा चुका है कि अभिसमयों के पीछे कानून जैसी कोई शक्ति नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि अभिसमयों का पालन क्यों होता है ? विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न प्रकार से दिया है। डायसी के अनुसार, अभिसमयों के पालन का कारण कानून के भंग होने का भय है। लावेल (Lowell) ने इस पालन के पीछे जनमत के बल का तर्क दिया है। लास्की (Laski) के अनुसार अभिसमयों का पालन इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये 'प्रचलित सामयिक सांविधानिक सिद्धांतों' के अनुरूप होते हैं और दूसरे सभी राजनीतिक दल देश के सामाजिक व राजनीतिक ढाँचे की आधारभूत बातों के बारे में प्रायः एक मत रहते हैं। दूसरे शब्दों में लास्की के अनुसार, अभिसमयों के पालन का मूल कारण उनकी विपुल उपयोगिता है। अग्रिम पक्षितों में हम इन विचारकों के तर्कों का कुछ विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

डायसी—का निष्कर्ष है कि अभिसमय और कानून गहरे गुंथे हुए हैं। किसी अभिसमय का उल्लंघन किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है या इस उल्लंघन से उसे क्षति पहुँचती है। चूँकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः स्वभावतः अभिसमयों का भी पालन करना ही पड़ता है। अभिसमय और कानून के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को डायसी ने उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है।

डायसी ने बताया है कि प्रतिवष ससद् का सत्र बुलाना एक अभिसमय है। यदि ससद् का मात्र प्रतिवर्ष न बुलाया जाए तो अभिसमय ही भंग होगा कानून नहीं। लेकिन अभिसमय के इस उल्लंघन से अनेक कानूनी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का स्वतः ही पतरा पैदा हो जायेगा। ब्रिटेन में दो महत्त्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाएँ हैं—प्रतिवष बजट स्वीकृत हो तथा प्रतिवष सेना सम्बन्धी कानून का नवीनीकरण हो। ससद् का अधिवेशन वर्ष में एक बार भी न बुलाने पर इन दोनों ही कानूनी व्यवस्थाओं का निश्चित रूप से उल्लंघन हो जायेगा। इन कानूनी व्यवस्थाओं के उल्लंघन से सम्पूर्ण शासन-तंत्र विगड़ जायेगा, न किसी विभाग पर कुछ व्यय किया जा सकेगा न कोई नया ढर्र लगाया जा सकेगा।

इस उदाहरण से डायसी ने यही प्रतिपादित किया है कि अभिसमयों के पीछे कानून के भंग होने का भय है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में "बहु शक्ति जिसके

कारण अतन्त्र वैधानिक ऐतिरिक्ता या पाठन करता पढ़ता है, स्वयं कानून की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किसी पूर्णतः परम्परागत नियम का उल्लंघन, चाहे वह पूर्णतया अज्ञात और वस्तुतः कानून के विपरीत प्रथा का उल्लंघन ही क्यों न हो, उल्लंघन करने वाले या देश के निश्चित कानून से विमुख कर देता है।"

रायसी या तब पूर्ण-मर्याद नहीं है, हा आशिरा रूप में अवश्य मर्याद है। यह तर्क सभी अभिसमयों पर समान रूप से लागू नहीं होता। अभिसमय और कानून सर्वत्र साध-माय चलें, यह भी आवश्यक नहीं। कानून के अनुसार, इंग्लैंड प्रतिवर्ष संसद् का सत्र चलाने के लिए विवश नहीं है। सम्प्रभु-सम्पा होने के कारण ब्रिटिश संसद् तेना सम्बन्धी कानून कई वर्षों के लिये पालन कर सकती है अथवा वर्तमान वार्षिक बरा को अनव वर्षों के लिये स्वीकार कर सकती है और छोटे भांटे सबों का आकस्मिक निधि ग पूरा कर सकती है। यदि डायसी का यह मत स्वीकार कर लिया जाये कि परम्पराओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, तो उसमें संसद की व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वोच्चता खण्डित हो जाती है, क्योंकि तब संसद उन कानूनों के द्वारा म स्वच्छ दत्तापूर्वक अपने अधिकार का प्रमाण नहीं कर सकेगी जो अपने पालन के लिये परम्पराओं के पालन पर निर्भर करते हैं। डायसी ने कानून और अभिसमयों को जो एकदम अ-या-याधित मान लिया है, वह अनुचित है।

इसके अतिरिक्त अनेक अभिसमय ऐसे हैं जिनके भग होने से किसी कानून का अतिरिक्त नहीं होता। यदि अध्यक्ष (Speaker) पद पर निर्वाचित होने के पश्चात् अपने दल की सदस्यता का त्याग न करे, प्रधानमंत्री लार्ड-भभा में लिया जाये या लोकसभा के कार्य संचालन सम्बन्धी अभिसमयों का पालन न किया जाये, तो इनमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

स्पष्ट है कि अभिसमयों का पालन मूलतः कानून के भग होने के मय से नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता के कारण होता है। फिर यह स्मरणीय है कि देश की परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों की मांग होने पर पूर्वोदाहरणों या पूर्व दृष्टान्तों का तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिये, डिजरेली (Disraeli) ने 1868 में आम निर्वाचन में पराजित होने पर संसद् के सम्मुख उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र देकर परम्परागत रूढ़ि की उपेक्षा की थी। इसके विपरीत 1929 में बाल्डविन (Baldwin) ने पुनः पुराने अभिसमय का अनुकरण करते हुए संसद के समक्ष उपस्थित होकर उसका निणय प्राप्त किया था।

लॉवेल (Lowell)—डायसी के विपरीत लॉवेल का विचार है कि अभिसमयों का पाठन इसलिए किया जाता है कि उन्हें जनमत का परम्परागत समर्थन प्राप्त है। अंग्रेज लोग अपनी प्राचीन प्रथाओं को बनाय रखने के लिए अपने जीवा में अनव अमरतिया तक स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि ये अभिसमयों का जो परम्परागत प्रथाओं के आधार पर निमित्त हो जाते हैं आदर में हैं। एनी अवस्था में सरकार सुगमता से उन अभिसमयों की उपेक्षा नहीं

कर सकती। जब राष्ट्र चाहता है कि ससद् का अधिवेशन प्रति वर्ष हो और मन्त्रीमण्डल लोक सभा में बहुमत न रहने पर त्याग पत्र दे दे, तो फिर सामान्यतः ऐसा कोई कारण पैदा नहीं होता कि सरकार इन अभिसमयों का पालन न करे।

लॉरेल का मत डायसी के मत की अपेक्षा अधिक सत्य है, तथापि वह पूर्णतः माय नहीं ठहराया जा सकता। जनमत के समर्थन का आधार कोरा रुढ़िवाद नहीं है। अंग्रेज लोग किसी परम्परा अथवा प्रथा का समर्थन केवल इसीलिए नहीं करते कि यह पुरातन काल से चली आ रही है, इसके विपरीत उनका समर्थन अधिकांशतः इसलिए होता है कि वह परम्परा या प्रथा प्राचीन-कालीन होने के उपरान्त भी वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी है।

लास्की (Laski)—लास्की के मतानुसार अभिसमयों का पालन मुख्यतः दो कारणों से होता है—

(1) पहला कारण यह है कि अभिसमय “प्रचलित सामयिक सांविधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इनके अतिरिक्त ये उनके श्रियाचयन में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में किसी समय मन्त्रीमण्डल की बैठकों का सभापतित्व स्वयं राजा करता था, किन्तु जॉर्ज राजाओं ने मन्त्रीमण्डलीय बैठकों में सभापतित्व करना बंद कर दिया। परिणामतः राजा के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा मन्त्रीमण्डलीय बैठकों का सभापतित्व करने की परम्परा बन गई। दान-दान लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ यह परम्परा राष्ट्र की पूरी तरह माय हो गई। इसने इस तरह एक अभिसमय (Convention) का रूप धारण कर लिया और आज भी यह अभिसमय आदर का पात्र है।

(2) लॉस्की के अनुसार अभिसमयों के मायता का दूसरा कारण यह है कि ब्रिटेन के राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व सामाजिक ढाँचे के मौलिक रूप के विषय में एकमत हैं और इस कारण इस ढाँचे से सम्बंधित परम्पराएँ भी उन्हीं समान रूप से माय हैं। उदाहरणार्थ, सभी ब्रिटिश राजनीतिक-दल राजतन्त्रीय लोकतन्त्र (Monarchic Democracy) में विश्वास करते हैं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्थाओं को ब्रिटिश सामाजिक ढाँचे के लिए उपयोगी मानते हैं। अतः इन व्यवस्थाओं से सम्बंधित अभिसमय भी उनके (दलों के) लिए सम्माननीय हैं। यदि देश के सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे की आधारभूत बातों पर ब्रिटिश राजनीतिक दलों में मतभेद न होता तो अभिसमयों का पालन सहदेहस्पद हो जाता और उनकी पवित्रता एक प्रश्न बिह बन जाती।

यद्यपि अभिसमयों की मायता के विभिन्न कारण बतलाये गये हैं, पर वास्तव में अभिसमयों के पालन का सर्वाधिक शक्तिशाली कारण उनकी उपयोगिता है। वे न केवल वैधानिक शासन और लोकतन्त्र के सिद्धांतों से ही सम्बंध रखते हैं, प्रत्युत वे व्यक्तियों के ऊपर आधारित होते हैं। शासन के सफल तथा निर्वाध संचालन के लिए यह आवश्यक है कि अभिसमयों का सम्यक् रूप से पालन किया

जाय। यदि इनका पालन नहीं होगा तो प्रशासन यत्र अस्तव्यस्त हो जायगा और शासन-संचालन में विभिन्न अवरोध उपस्थित हो जायेंगे। उपयोगिता के अतिरिक्त लोकमत की शक्ति के कारण भी परम्परायें सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। शासन की अन्तिम शक्ति जनता अर्थात् निर्वाचकों की शक्ति से ऊपर आधारित है। अतः लोकमत समर्थित अभिसमयों का यदि आदर न किया जाय तो इससे जनमप्रभु (Popular Sovereign) की भावनाओं का चोट पहुँचेगी, और कोई भी लोकतन्त्रात्मक सरकार इस बात के लिये तैयार होना पसन्द नहीं करेगी।

ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्त्व

(Importance of Conventions in British Constitution)

अभिसमय संविधान को पूर्ण बनाते हैं और साथ ही व्यावहारिक भी। उनके अभाव में संविधान समुचित रूप में कार्य नहीं कर पाता। ब्रिटिश संविधान में तो अभिसमयों का महत्त्व 'शरीर में आत्मा' जैसा है। ब्रिटिश संविधान के निर्माण और किया कथन में इनकी कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, यह निम्नलिखित वर्णन में स्पष्ट हो सकेगी—

(1) ब्रिटिश संविधान के निर्माण में योगदान—ब्रिटिश संविधान बहुत कुछ अभिसमयों की उपज है। इनका कारण उनके विकास को बरत मिला है और निरंकुश राजतन्त्र आज के लोकतन्त्रात्मक शासन में बदल गया है। यह एक उदाहरण से भली-प्रकार स्पष्ट है। स्ट्यूअर्ट राजतन्त्र राजा ही मन्त्रिमण्डलीय बैठकों का सम्भाषित्व करते थे। राजा की उपस्थिति में मन्त्रीगण अपनी इच्छानुसार नियम नहीं ले पाते थे, किन्तु हनोवर बर्सीय राजाओं की, अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञता और ब्रिटिश राजनीति में विविध रवि न होने के कारण, समद तथा मन्त्रिमण्डल को स्वेच्छानुसार व्यवहार करने के लिए छूट दिया। हनोवर राजा न तो मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सम्मिलित होते थे और न उनका सम्भाषित्व करते थे।

हनोवर नरेशों के व्यवहार से यह परम्परा बन पड़ी कि राजा मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होगा, इनकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री द्वारा ही की जाएगी। इन-गर्न दीपकालीन प्रयोग के कारण, यह परम्परा इतनी पक्की हो गयी कि आज तृतीय मन्त्रिमण्डलीय बैठकों का पुनः सम्भाषित्व करने के प्रयत्न में असफल रहा।

इस तरह कानून द्वारा नहीं बल्कि सांविधानिक परम्परा या अभिसमय द्वारा राजाओं के अभाषारण अधिकार धीरे-धीरे मन्त्रियों और समद के हाथ में आते गये। निरंकुश राजतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रात्मक शासन में बदल गया। अतः मन्त्रिमण्डल में ही गयी कि आज राजा वास्तविक शासन नहीं है, वह सांविधानिक प्रधानमन्त्री है वह शक्ति प्राप्त करता है, शासन नहीं।

कथन उदाहरण अभिसमय ही नहीं, बल्कि 18वीं शताब्दी के अन्त तक

मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था के लगभग सभी अभिसमय स्थापित हो गए। और तो और, ब्रिटेन के वर्तमान शक्ति और रूढ़िवादी दलों का अम्युदय भी परम्परा से ही हुआ। राजपद, संसद, मंत्रिमण्डल आदि स्वयं भी अभिसमयों की ही उपज हैं।

(2) अभिसमयों द्वारा ब्रिटिश संविधान के क्रिया वयन में योग—ब्रिटिश संविधान की और प्रशामन यंत्र को सुगमतापूर्वक चलाये रखने में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ाते हैं। वे शासन के कठोर वैधानिक समूह को बदलते हुए राजनीतिक विचारों और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उसे संशोधित करते हैं। अनेक अभिसमय इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके न होने पर भीषण राजनीतिक कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं और ब्रिटिश संविधान का कानूनी ढांचा लडखड़ाकर गिर सकता है।

उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में कुछ ऐसे अभिसमय हैं जो कानूनी सम्प्रभु और राजनीतिक सम्प्रभु के बीच मेल जोल बनाए रखते हैं। राजा कानूनी सम्प्रभु है और मंत्रिमण्डल तथा संसद व जनता राजनीतिक सम्प्रभु। कानूनी दृष्टि से सम्पूर्ण शासन शक्ति राजा (अथवा रानी) में निहित है। कानूनी रूप से राजा मंत्रिमण्डल के परामर्श का मानने या संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि राजा विच्युद्ध रूप से इस कानूनी आचरण पर चलना शुरू करदे तो राजनीतिक सम्प्रभु अर्थात् मंत्रिमण्डल, संसद और जनता से उमका सघर्ष शुरू हो जाएगा। पर ऐसी स्थिति को टालने का महान् कार्य आज केवल एक अभिसमय पर आधारित है और वह यह है कि राजा को मंत्रिमण्डल का परामर्श मानना चाहिए तथा संसद द्वारा पारित कानूनों पर अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। जब तक इस अभिसमय का पालन होता रहेगा तब तक कानूनी सम्प्रभु और राजनीतिक सम्प्रभु के टकराने की नीवत नहीं आएगी।

अब जरा यह भी देख लेना चाहिए कि यदि राजा इस अभिसमय का उल्लंघन करे तो क्या होगा। मान लीजिए कि राजा प्रधानमंत्री का परामर्श ठुकरा देता है तो पहला परिणाम यह होगा कि प्रधानमंत्री और साथ ही सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होगा? अब राजा के पास दो ही रास्ते बच जायेंगे या तो विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या लोकसभा का विघटन करके नए निर्वाचनों का आदेश दे। विरोधी दल का नेता प्रथम तो, लोकसभा में बहुमत का समर्थन न होने से आमंत्रण स्वीकार ही नहीं करेगा और यदि कर लेगा तो लोकसभा में उसके मंत्रिमण्डल को प्रत्येक प्रश्न पर मुंह की खानी पड़ेगी। अतः, बहुमत का समर्थन पाने के लिए सामान्य निर्वाचन कराने होंगे। अब यदि नया प्रधानमंत्री निर्वाचनों में हार जायगा तो यह संकटाट की हार होगी। यदि राजा सीधे लोकसभा को भंग करके नये निर्वाचन करायेगा तो निर्वाचन मुख्यतः इसी प्रश्न पर लड़ा जायेगा कि राजा ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया

है। इस स्थिति में राजा स्वयं को राजनीतिक सभ्य में घिरा पाएगा। अभिप्राय यह हुआ कि केवल एक अभिसमय के उत्पन्न से राजा और राजतन्त्रीय मस्याओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। स्पष्ट है कि ऐसी मूसला चाई भी राजा नहीं करना चाहता।

कानूनी और राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छाओं में मध्य सामंजस्य बनाये रखने वाला एक अर्थ प्रमुख अभिसमय यह है कि राजा लोकसभा के बहुमत दलीय नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तथा उसके द्वारा चुन हुए मंत्रियों को मंत्रिमण्डल के रूप में स्वीकार करेगा। इस अभिसमय के मूल में यह भावना निहित है कि शासन की चांगटोर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहनी चाहिए।

और भी अनेक अभिसमय ब्रिटिश समदीय शासन के मुसवालेन में सहायक हैं उनके कारण मंत्रिमण्डल और लोकसभा में सहयोग बना रहता है। उदाहरणार्थ, लोकसभा का विश्वास खो देने पर मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र देने का अभिसमय देश को उस सभ्य की स्थिति में बचाता है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में मतभेद होने पर पैदा हो सकती है। इसी तरह लोकसभा का बहुसंख्यक दल ही मंत्रिमण्डल बनाए—यह अभिसमय मंत्रिमण्डल से लोकसभा में निवृत्ततम सम्पर्क और सामंजस्य बनाए रखता है। लोकसभा वही स्वेच्छाचारी और व्यय की अटगेवाजी द्वारा मंत्रिमण्डल का अनुचित विरोध करके प्रशासकीय यंत्र को न गड़बड़ करद, इसके लिए भी अभिसमय विद्यमान है, वह यह है कि प्रधानमंत्री राजा से अनुरोध करके अवाचित लोकसभा को भंग करा सकता है और दुबारा निर्वाचित कराके राष्ट्र का पुन विश्वास प्राप्त कर सकता है।

ब्रिटन में कुछ सांविधानिक अभिसमय ऐसे हैं जिनसे शासन काय का स्तर उन्नत होने में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ, यह अभिसमय है कि कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होने चाहिए। इस अभिसमय से विधेयक पर निश्चित रूप से सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह एक अभिसमय यह है कि लाइ-सभा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करे तो उसमें सिर्फ कानूनी लाइ (Law Lords) ही बैठें। इस अभिसमय का सुधारात्मक प्रभाव यह होता है कि न्यायिक कार्य ठीकतौर पर चलता रहता है तथा कानून से अनभिज्ञ दूसरे एजेंट यापिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते।

इन कुछ उदाहरणों में ही स्पष्ट है कि ब्रिटिश प्रशासन में अभिसमयों की कितनी उपयोगिता और महत्ता है। जेनिंग्स ने ठीक ही लिखा है कि "अभिसमय परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुकूल शासन-व्यवस्था का ढालते हैं और शासक वर्ग को शासन-यंत्र संचालित करने की योग्यता प्रदान करते हैं। व्हीयर (Where) के अनुसार "अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, विधान मण्डल के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते हैं, व्यवस्थापिका के सगठन को निर्धारित करते हैं, व्यवस्थापिका और

कार्यपालिका के सम्बन्ध को निश्चित करते हैं, राजनीतिक दलों और शासनागों के सम्बन्ध निर्धारित कर, शासन की रूपरेखा को मजबूत करते हैं तथा शासन व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुकूल लचीली और परिवर्तनशील बनाते हैं।”

अतः मेरा सारांश में ब्रिटिश संविधान के अतः अभिसमयों के महत्व के बारे में कहा जा सकता है कि—

(1) “अभिसमयों ने ब्रिटिश राजपद को सीमाबद्ध और उसके सब अधिकारों को मंत्रिमण्डल को हस्तांतरित किया है।

(2) अभिसमयों ने मंत्रिमण्डल के लोकसभा के प्रति सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को विकसित किया है।

(3) अभिसमयों के कारण ही आज सांविधानिक विकास इस अवस्था को पहुंच गया है कि मंत्रिमण्डल का निर्माण और विघटन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक करते हैं।

(4) अभिसमयों के द्वारा ही ब्रिटिश शासन-व्यवस्था नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल प्रगतिशील हो सकी है।

(5) ब्रिटिश शासन प्रणाली की मूल संस्थाएँ—राजपद, संसद, मंत्रिमण्डल, प्रधानमंत्री आदि अभिसमयों की ही उपज हैं। संसद का दो सदनों में संगठन होना, उसकी कार्य-पद्धति का एक बड़ा भाग, सम्राट की स्थिति, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सीमा विभाजन आदि व्यवस्थाएँ किसी कानून पर आधारित नहीं हैं बल्कि अभिसमयों पर आधारित हैं।”

अभिसमयों के बाहुल्य के कारण ही यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है।

3

राजा तथा राजमुकुट (THE KING AND THE CROWN)

“काउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभुशक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भण्डार है।”

—सर सीरिस एमीस

राजमुकुट का साविधानिक अर्थ और अतीत में राजा व राजमुकुट

ब्रिटिश इतिहास में एक समय ऐसा रहा था जब राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा स्वयं ही कानून बनाता, ताम्र करता तथा 'याय का काय' करता था अर्थात् वह ब्रिटेन का वास्तविक एवं निरंकुश शासक था। परन्तु राजा को ये अपरिमित शक्तियाँ राजतिलक होने के साथ ही प्राप्त होती थी, उसके पूर्व नहीं। इससे जम्दा न राजा इन शक्तियों का अधिकारी तब होता था जब वह सिंहासनाख्त होकर राजमुकुट या ताज (Crown) पहनने का अधिकारी हो जाता था। इनका वास्तविक अन्तिमार्थ यही हुआ कि विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ अविनश्वर रूप में राजा की न होकर राजमुकुटधारी राजा की होती थी, अर्थात् पहले का शक्ति विहीन व्यक्ति विशेष राजतिलक होने पर जब राजमुकुट धारण कर लेता था तो वह शक्ति युक्त हो जाता था।

आशय यही हुआ कि राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ चाहे 'राजा के सिर की टोपी' (जिसे वह राष्ट्रपद के चिह्न स्वरूप पहनता है) हो, परन्तु साविधानिक दृष्टि से शासन का वह माकार रूप हुआ जिसमें विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका सम्बन्धी सभी शक्तियाँ निहित हो। इसीलिए जब व्यक्ति-विशेष (राजा) राजमुकुटधारी बनता है तो उसे स्वतः ही उन सब शक्तियों का प्रयोग का अधिकार मिल जाता है, जो राजमुकुट में निहित हैं।

उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि राजा व राजमुकुट में अन्तर है। राजा वह व्यक्ति विशेष है जो राजमुकुट में निहित शक्तियों का प्रयोग करता है, अर्थात् सांविधानिक दृष्टि से राजमुकुट शासन का प्रतीक है। राजा नहीं यह अन्तर आज भी विद्यमान है और भूतकाल में भी था। फक्त सिर्फ यही है कि भूतकाल के इस अन्तर का कोई बंधानिय महत्त्व नहीं था, लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय राजमुकुट की सम्स्त शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत राजा करता था, आज की तरह अनेक मन्त्रियों का समूह नहीं। राजमुकुट की शक्तियाँ अबके राजा में केन्द्रीभूत थी, अतः राजा राजमुकुट था व राजमुकुट राजा, जबकि आज राजमुकुट की शक्तियाँ सामूहिक रूप से अनेक मन्त्रियों या व्यक्तियों (ज्वजामात्र शासक राजा एव वास्तविक शासक मन्त्र व मन्त्रिमण्डल तथा प्रिवी कौंसिल आदि) में निहित हैं। आज अनेक मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, पहले 'एक राजा—मान व्यक्तिगत राजमुकुट की शक्तियाँ का प्रयोग करता था। 'राजतन्त्र के लोकतन्त्रीकरण' के कारण इस अन्तर का बड़ा महत्त्व हो गया है जिसे समझे बिना ब्रिटिश संविधान को भी अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता।

राजा तथा राजमुकुट का अन्तर

(Distinction between the King and the Crown)

राजा और राजमुकुट में अन्तर को दिए गए इतने महत्त्व से स्वभावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ऐसा क्यों है? अतः इन दोनों के अन्तर पर प्रकाश डालने में पूर्व इस अन्तर या भेद के महत्त्व के कारणों को समझ लेना चाहिए।

राजा व राजमुकुट के भेद का महत्त्व

राजा और राजमुकुट का महत्त्व मुख्यतया दो कारणों से है—

(1) हमें ब्रिटिश संविधान के वास्तविक स्वरूप की समझने में सहायता मिलती है। यह पता चलता है कि जिस राजा के नाम से सम्पूर्ण शासन चलता है वह व्यावहारिक दृष्टि से केवल नाममात्र का शासक है। शासन की शक्तियों का प्रयोग राजा (अथवा रानी) द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट द्वारा किया जाता है जिसमें राजा, समद, मन्त्रिमण्डल तथा लोक सभा के सदस्य आदि शामिल होते हैं। समद और मन्त्रिमण्डल जो राजमुकुट के प्रतीक हैं, देश के वास्तविक शासक हैं।

(2) राजा व राजमुकुट के अन्तर को समझने से हम ब्रिटिश संविधान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में पाये जाने वाले अन्तर को समझ सकते हैं। हमें पता चलता है कि सिद्धांत शासन सम्राट में निहित है किंतु व्यवहारतः वास्तविक शक्तियाँ मुकुट में चली आई हैं जो समद व मंत्रियों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। सिद्धांत

म समुद्र और मन्त्रि-मण्डल राजा की परामर्शदात्री सस्यायें हैं किंतु व्यवहार में राजा उनके हाथ की बंधपुतली है और दक्षिण का प्रतीक—मात्र है।

यथायथे राजा और राजमुकुट के अन्तर का महत्त्व इंगित्ये है कि "ब्रिटिश शासन मिठातत निरंकुश राजतन्त्र, स्वल्प म भीमित शासन और व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र है। यहा राजतन्त्र और लोकतन्त्र दोनों साथ चल रहे हैं—प्रथम का प्रतीक राजा है और द्वितीय का प्रतीक राजमुकुट। राजा से जहा राजन के अधिकारी व्यक्ति का नाम होता है, यहा राजमुकुट से व्यवज—मात्र शासक, मन्त्रि मण्डल तथा ससद आदि वास्तविक शासकों का बोध होता है।

इस पृष्ठ भूमि के उपरान्त राजा व राजमुकुट का अन्तर समझना अधिक सुगम है।

राजा व राजमुकुट में अन्तर

ब्रिटन के साविधानिक इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि पहले निरंकुश राजतन्त्र था, लेकिन धीरे धीरे मसद् निरन्तर दक्षिण ग्रहण करती चली गई। समय के साथ राजतन्त्र रूपी मस्या के चारों तरफ विशेष प्रकार के कार्यों और शक्तियों का घेरा डाल दिया गया। इस प्रक्रिया से कालान्तर में राजा के सभी काम बान्धव और परम्पराओं के अधीन हो गये। दक्षिण के इस स्थानांतरण के बाद राजा और राजमुकुट में जो वर्तमान अन्तर है, उसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है—

राजमुकुट एक मस्या, राजा एक व्यक्ति—राजमुकुट एक मस्या है जबकि राजा एक व्यक्ति है, जो राजपद को सुशोभित करता है और राजमुकुट रूपी मस्या में निहित शक्तियों का प्रयोग करना है। राजमुकुट वह मस्या है जो शासन की प्रतीक है। इसमें व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय तीनों से सम्बन्धित शक्तियाँ सम्मिलित हैं। राजा इस मस्या का एक अगमान है और अग भी ऐसा कि जिसके पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं।

राजमुकुट स्थाई, राजा अस्थायी—राजमुकुट एक मस्या के रूप में सदैव बनी रहने वाली वस्तु है जिसका नाश नहीं होता, परन्तु राजा एक जीवित प्राणी के रूप में नाशवान है। राजमुकुट सदा से चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा लेकिन राजा व्यक्ति के रूप में सदा नहीं रहता। एक राजा मरता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस तरह राजाओं के आने-जाने का चक्र चलता रहता है। परन्तु राजमुकुट अविनाशी (Immortal) है। "राजा मर गया, राजा चिरजीवी हो" का जयघोष राजा के व्यक्तिगत रूप और राजमुकुट के मस्यागत रूप के अन्तर पर प्रकाश डालता है। इसका अर्थ यही है कि राजा विषय की मृत्यु हो सकती है, लेकिन राजमुकुट या राजपद (Institution of Kingship) स्थिर है। राजा और राजमुकुट के अन्तर को ब्लेकम्टोन के शब्दों में—“हैनरी, एडवर्ड या जॉन मर सकते हैं, लेकिन राजा (क्राउन) कभी नहीं मरता।”

राजमुकुट सामूहिक, राजा वैयक्तिक—राजमुकुट का रूप सामूहिक है, राजा का वैयक्तिक। राजमुकुट एक बहुत बार्थेकारणों है जिस में ससद, मन्त्रिमण्डल और लोकसभा के सदस्य आदि सम्मिलित हैं। इसके विपरीत राज वैयक्तिक का नाम पालक है। राजमुकुट के सामूहिक रूप को बतलाते हुए वेड तथा फिलिप्स (Wade and Phillips) ने लिखा है कि, “राजमुकुट शब्द से शासन की सम्पूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है और वह वायपालिका का पर्यायवाची है। राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिये कहा जा सकता है, कुछ का प्रयोग राजा मंत्रियों के पूर्ण दायित्व पर करता है और कुछ के प्रयोग में उम्मा कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि कानूनों पर आधारित अधिकांश शक्तियाँ मंत्रियों का ही प्राप्त होती हैं यद्यपि उनका प्रयोग राजा के नाम पर किया जाता है तथापि वे मन्त्रिमण ही सरकारी तौर पर उसका वास्तविक प्रयोग करते हैं।”

राजमुकुट का इच्छा का प्रतीक, राजा सजावट मात्र—चूँकि राजमुकुट शासन की वास्तविक सत्ता अधिकारी है जिनकी दस्तियों का प्रयोग ससद, मन्त्रिमण्डल आदि के द्वारा किया जाता है, अतः उसे जन इच्छा का प्रतीक कहा जाता है। इसके विपरीत, जो स्वजमान शासक है, एक सजावट मात्र है जिसे “स्वर्णिम शून्य” (Golden Zero) कहा गया है वह ब्रिटिश शासन की गोमा बगाना है।

अतः सत्य में कहा जा सकता है कि राजमुकुट (Crown) राजा, मन्त्री और ससद तीनों का संयोजक है। बहुत जय में राजमुकुट का अभिप्राय “पूरी सरकार” (The Government) से है।

राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत

(Sources of the Power of the Crown)

राजमुकुट की शक्तियाँ अत्यन्त पूर्ण और व्यापक हैं। इन शक्तियों के प्रधान स्रोत ये हैं—

(1) **संसदीय कानून**—ये वे कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर ससद में राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। संसदीय कानूनों में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत शासन के विभिन्न विभागों के संचालन सम्बन्धी और स्थानीय या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण से सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित हैं। संसदीय नियम वस्तुतः राजमुकुट की शक्ति के बड़े उपजाऊ स्रोत बन गये हैं।

(2) **विशेषाधिकार या परमाधिकार**—राजमुकुट के विशेषाधिकार का अर्थ है—राजमुकुट की स्वतन्त्र शक्ति या अधिकार। दूसरे शब्दों में, राजा या उसके सेवक संसदीय अधिनियमों के बिना भी केवल अपने अधिकार से क्या-क्या कर सकते हैं? यही विशेषाधिकारों का व्याख्या है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनन के उदय ने पूरा राजा की शक्तियों को विरोधाधिकार या परमाधिकार कहा जाता था। यह अधिकार उसे सामंती होने के माते प्राप्त थे। किंतु संसदीय गौतन के विकास के साथ राजा के व्यक्तित्व से निहित सभी विरोधाधिकार टिन गये या गूट हो गये। 'ता गप रा', उन्हें जान राजमुकुट ने गठन कर लिया है।

राजमुकुट के बतना विरोधाधिकार भी इनमें अधिक और जटिल है कि वह महा सूचीपत्र करना पड़ा है। फिर भी, कुछ मदद रहित विरोधाधिकार गिना जात है—गमद का आग्रह करना, युद्ध व्यवस्था सटवारा की घोषणा, संधि का अनुममयन, नागरिक पदा पर नियुक्ति, राज-मन्त्री की बजास्तगी, पीयरी की नियुक्ति विरोधाधिकार का समाधान, आदि।

राजमुकुट का विरोधाधिकार का सबसे बड़ा सहायक इम बात है कि इमने एक ऐसे सुगम-नत्र (Convenient Mechanism) का जन्म होता है जिसमें शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण काम-उत्पाद चलते रहते हैं।

(3) विरोधाधिकारों का कानून का मिथण—राजमुकुट की शक्तिया का एक तृतीय सात विरोधाधिकारों और कानूनों का मिथण है। राजमुकुट की कुछ शक्तिया इस प्रकार की है जो प्रारम्भ में विरोधाधिकार जतित थी लेकिन गिहें बाद में संसद ने भी कानून बना कर माया प्रदान कर दी है और इम तरह इनका सात कानून और विरोधाधिकार दोनों ही हैं।

राजमुकुट के अधिकारों की परिवर्तनशीलता

उपयुक्त धनन में स्पष्ट है कि राजमुकुट की शक्तिया निरंतर परिवर्तनशील रही हैं। मग्ना कार्टा (Magna Carta) के समय में ही वे घटती उठती रही है। राजा की व्यक्तित्व शक्तियों को कम करने में जन-आंदोलन और संसदीय कानूनों दोनों का विशेष हाथ रहा है। जन आंदोलन के फलस्वरूप मग्ना-कार्टा स्वीकृत हुआ, जिसके द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। इसी तरह अधिकार याचिका (Petition of Rights) के द्वारा राजा पर यह अंकुश लगा दिया गया कि वह न तो मनमाने ढंग से लोगों को जेल में डाक मकेगा और न संसद की पूरा स्वीकृति के बिना कोई कर लेगा सकेगा। संसदीय कानूनों की दृष्टि से अधिकार पत्र (Bill of Rights) का उदाहरण पग लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह न तो देश के प्रचलित कानूनों को निलम्बित कर सकेगा और न उसे समाप्त ही कर सकेगा। राजा के कुछ अधिकार दीर्घकाल तक प्रयोग में न आने के कारण स्वत ही समाप्त हो गये। उदाहरणार्थ, ट्युडर का समय से राजा ने लोक-सभा में प्रतिनिधि नियुक्त करने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया, तथा उससे कुछ पहिले से लॉर्ड-सभा में आज्ञा पीयर (Peer) नियुक्त करने के (संसद की स्वीकृति के बिना) अधिकार का भी प्रयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप यह

मान लिया गया कि राजा के ऊपर लिखे दोनो अधिकार समाप्त हो गये हैं और वह स्वेच्छा से मसद के सदनों की सदस्य मर्यादा बढ़ाने का अधिकार नहीं रखता। परंतु यह स्मरणीय है कि राजा की वैयक्तिक क्षमताओं के क्षीण होने के साथ साथ राजमुकुट की शक्तियां बढ़ती गईं क्योंकि जो जो शक्तियां राजा से छीनी गईं, वे जनता को हस्तांतरित होनी गईं और उनका प्रयोग उसके प्रतिनिधियों द्वारा राजमुकुट के माध्यम से किया जाना लगा। यह पहिले भी कहा जा चुका है कि राजमुकुट में जनता के प्रतिनिधि अर्थात् मंत्रिगण और मसद सदस्य सामूहिक रूप से सम्मिलित हैं।

पुनश्च, यह भी उल्लेखनीय है कि राजमुकुट की शक्ति राज्य विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं आदि के कारण भी उनमाने युग में बढ़ती ही जा रही है। मंत्रिमण्डल, कायपालिका के विभाग, सिविल सैन्य, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, गृह-संस्थाएं, वित्त-रक्षा, चक्ष, आयाज्य आदि जनक ऐसे विभाग हैं जो राजमुकुट द्वारा ही नियंत्रित हैं। वस्तुतः उद्यो-उद्यो लाख कल्याणकारी राज्य के विचार का विस्तार हाता जायेगा और राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार बढ़ता जायेगा राजमुकुट की शक्तियां भी बढ़ेंगी। त्रिटित मविधान का यह एक विरोधाभास ही है कि प्रजातन्त्र के विकास के साथ साथ राजमुकुट की शक्तियों में वृद्धि होती है।

राजमुकुट की शक्तियां, अधिकार और कार्य

(Powers, Functions and Rights of the Crown)

राजमुकुट में कायपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सभी शक्तियां निहित हैं। उनकी व्यापक शक्तियों का अध्ययन हम निम्नलिखित वर्गों में कर सकते हैं—

(क) कार्यपालिका शक्तियां

राजमुकुट की कायपालिका शक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यापक और निरंतर वृद्धिशील हैं। इसकी कायपालक शक्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है—

(1) प्रशासन निर्देशन—अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति ही राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य प्रशासन का निर्देशन करना है। इस नाते वह समस्त राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वित करता है और सब प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करता है। वही उच्च कायपालक एवं प्रशासन अधिकारियों तथा न्यायाधीशों व सैनिक अधिकारियों की नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों का छोड़कर अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही कर सकता है और उन्हें पदच्युत कर सकता है। न्यायाधीशों का पदच्युत करने के लिए मसद के दोनो सदनों की सम्मिलित आवश्यकता होती है। राजमुकुट ही राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है। राष्ट्रीय बजट

उसकी आर से प्रस्तुत किया जाता है और समद की स्वीकृति के बाद, उसी के द्वारा माय रूप लया जाना है। कमचारियों की सेवा स्थिति की उचित व्यवस्था करना उसी का कर्तव्य है। वह राष्ट्रीय सैनिक सेवा आ आ सर्वोच्च सनापति है। उसका एक प्रमुख काय स्थानीय सरकारों के कार्यों की देख भाल व उनका नियंत्रण करना है। राजमुकुट ही देश के दैनिक प्रशासन का नियंत्रण और उसका संचालन करता है। स्पष्ट है कि प्रशासकीय क्षेत्र में राजमुकुट की शक्ति, काय और अधिकार अत्यंत व्यापक हैं।

(ii) वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन—शासन के प्रमुख के रूप में राजमुकुट ही ब्रिटन के वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन करता है। समस्त विदेशी मामलों में विदेशी काय उसी की ओर से अथवा उसी के नाम से हाते हैं। विदेशी में सभी राजदूतों और उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति वही करता है। वही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि—मंडल भेजता है। विदेशी में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को कार्य व नीति प्रियक निदेश भेजता है, उसी का काय है। विदेशी राजदूत अपना प्रमाण-पत्र उसी को दिखाते हैं और वही उनका स्वागत करता है। युद्ध की घोषणा करने अथवा तत्सम्बन्धी संधि करने का अधिकार भी उसी का है। उसके द्वारा ही हुई संधियों पर समद की स्वीकृति की उस समय तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसमें ससदीय स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें न हों अथवा जब तक उसमें कोई ऐसा मामला अस्त न हो (जैसे स्व भूभाग का परित्याग, धन की अदायगी अथवा देश के प्रचलित कानून में परिवर्तन) जिसकी विधि अनुकूल बनाने के लिय समद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

यद्यपि राजमुकुट कुछ संधियों को स्वीकृति के लिए समद में प्रस्तुत करता है किन्तु ऐसा करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। समद अपनी वजह पारित करने की शक्ति से राजमुकुट के परराष्ट्र सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित कर सकती है, परन्तु कानूनी रूप से राजमुकुट बाधित नहीं है कि वह सब अंतर्राष्ट्रीय संधियों को समद में प्रस्तुत करके उसकी प्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त करे। ध्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राजमुकुट अनेक गोपनीय वैदेशिक संधियों का समद में प्रस्तुत नहीं कर सकता।

(iii) उपनिवेग व राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी अधिकार—ब्रिटिश उपनिवेगों व गुरुरक्ष्य अपीन प्रदेशों का शासन का राजमुकुट ही वास्तविक अध्यय है। सम्राट (साम्राजा) राष्ट्रमण्डलीय दलों का औपचारिक प्रधान है। पर अब राजमुकुट की राष्ट्रमण्डल व उपनिवेग सम्बन्धी शक्तियां कम हो गई हैं। समग्र सभी ब्रिटिश उपनिवेग पूरे अंतर्राष्ट्रीय परराष्ट्र सम्बन्धी अथवा नागरिकों का व्यवसाय सम्बन्धित नहीं हैं। राजमुकुट उपनिवेगों का मंत्रिमण्डल की परामर्श में बलों का सर्वोच्च मामलों की नियुक्ति सम्पाद करता है और वे राजमुकुट की प्रतिनिधि भी कहलाते हैं, परन्तु यह सब

केवल औपचारिक हैं। राजमुकुट के राष्ट्रमण्डलीय कार्य तो और भी औपचारिक हैं क्योंकि भारत, पाकिस्तान जैसे पूर्ण स्वतंत्र राज्य भी राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं।

(स) विधायनी शक्तियाँ

राजमुकुट को व्यवस्थापन सम्बन्धी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये शक्तियाँ सभ्यसद राजा अर्थात् राजा महित सभ्य (King in Parliament) में निहित हैं। सभ्यसद राजा ही कानून निर्माण का अधिकारी माना जाता है। विधायी क्षेत्र में राजमुकुट की शक्तियाँ, उनके कर्तव्यों और अधिकारों को निम्नलिखित उपशीर्षकों में बाटा जा सकता है—

(1) सभ्य से सम्बन्धित—मध्यम राज्य अमेरिका के सभ्य विपरीत ब्रिटन में कानूनपालिका और व्यवस्थापिका का एक-दूसरे में भिन्न रखा गया है। विधायी शक्तियाँ सभ्य सहित सभ्य के हाथों में हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राजा की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। राजा को सभ्य के दानो सदना से पारित विधायी भी विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने या उसका निषेध (Veto) करने का अधिकार है। परन्तु सन् 1707 के बाद से राजा द्वारा निषेध शक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया गया है। अब यह शक्ति शून्य के समान ही है, हालांकि सिद्धांत रूप में यह विद्यमान है। आजकल तो राजा स्वयं विधेयकों पर अपनी स्वीकृति भी नहीं देता, अपितु पाच कमिशनर, जिनकी नियुक्ति राजमुकुट राजनीय साईन मैनुअल (Sign Manual) के अनुसार करता है, अपनी स्वीकृति देते हैं।

सभ्य में विधेयकों के प्रस्तुत होने के सम्बन्ध में भी राजमुकुट का हाथ रहता है। राजमुकुट की सिफारिश पर ही वित्त विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अन्य सरकारी विधेयक भी मंत्रियों द्वारा ही पेश किये जाते हैं और उन्हें ऐसा करने का अधिकार राजमुकुट के मंत्री होने के नाते प्राप्त है।

राजमुकुट को सभ्य से सम्बन्धित और भी अनेक अधिकार हैं। सभ्य के निर्माण के सम्बन्ध में उसे पीयर (Peer) बनाने का अधिकार है। केवल वे ही लोग लार्ड-सभा के सदस्य हो सकते हैं, जो राजा द्वारा पीयर बनाये जाते हैं।

लोक सभा के निर्वाचन की तिथि की घोषणा भी राजमुकुट द्वारा ही की जाती है। राजमुकुट के मंत्री सभ्य के सदस्य भी होते हैं और वे सभ्य की कार्यवाहियों पर निगाह तथा नियंत्रण रखते हैं और यह निष्पक्ष करते हैं कि सभ्य में अमुक विषय पर किस प्रकार सुगमता से कार्यवाही की जा सकती है?

राजमुकुट ही लार्ड-सभा का स्थगन और विघटन करता है। लार्ड-सभा के बारे में उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वह एक स्थायी सभा है। सभ्य का सत्रावसान भी राजमुकुट ही करता है।

जब नई सभ्य का सम्मेलन होता है तो प्रायः राजा ही लार्ड-सभा में, जहाँ लोक सभा के सदस्य भी होते हैं, स्वयं उपस्थित होकर अपना सिंहासन भाषण

(Speech from the Throne) देता है और उसके द्वारा संसद का स्वागत करता है। परंतु राजा के इस भाषण की वास्तव में मंत्री ही तैयार करते हैं और उसे राजा की पढ़ने-माथ के लिए दे देते हैं।

(ii) **परिषद आदेश (Orders in Council)**—राजमुकुट का एक अन्य प्रमुख कार्य है सं परिषद आदेश निकालना। इनका अनिवार्य यह है कि संसद विधायकों की माटो तपरेला मात्र पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति का कार्य राजमुकुट पर छाड़ देती है जिसे वह अपने मंत्रियों द्वारा करता है। इस प्रकार के उपस्थित्यापन व अन्तर्गत मंत्रिमण्डल विभिन्न आदेश निकालता है जो राजमुकुट के नाम से जारी किये जाते हैं। इन आदेशों को सं परिषद आदेश (Orders in Council) कहा जाता है। इनका महत्व वास्तव में समान ही होता है।

(ग) **न्यायिक शक्ति**

राजमुकुट का कार्य का सात (Fountain of Justice) कहा जाता है। परंतु अब यह कथन केवल औपचारिक बन गया है क्योंकि ब्रिटन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व है। फिर भी न्यायालय राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नहीं है। ब्रिटन में सभी न्यायालय राजा के न्यायाधीश हैं, और संसद न्याय राजा के नाम से होते हैं। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की सहमति से उन्हें पदच्युत भी कर सकता है।

राजमुकुट प्रिवी कांसिल की न्याय समिति की परामर्श में उपनिवेशों से आयी हुई अपील का निणय करना है। संसद अधिकारियों का राजमुकुट के नाम से दण्डित किया जाता है।

राजमुकुट के न्यायपालिका संबंधी अधिकार कुछ दृष्टियों में प्रतिबन्धित हैं। उदाहरणार्थ, राजमुकुट का यह अधिकार नहीं है कि वह कोई नवीन न्यायालय बना सके। इसी तरह यह किसी वर्तमान न्यायालय के मण्डल और उसकी कार्यविधि में भी परिवर्तन नहीं कर सकता। न्यायाधीशों की गरजा, उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, विधि और वेतन आदि में भी कोई परिवर्तन करने का उसे अधिकार नहीं है। अपील का अंतिम न्यायालय भी राजमुकुट में होकर चल रहा है। राजमुकुट की न्यायिक शक्ति का वारे में ओग (Ogg) ने ठीक ही लिखा है कि राजा यह केवल एक प्रथा ही है कि उसे गौरव के साथ न्याय का खौन कहा जाता है अथवा इसमें वास्तविकता बहुत कम है।

राजमुकुट की न्यायिक शक्ति में ही हम उसके महत्वपूर्ण अधिकार समादाय व दण्ड स्वयं को ल सकते हैं। राजमुकुट की यह विशेषाधिकार है कि यह उस अपराधी का क्षमा कर दे जा जो ज़िदारी मामला में दोषी हो। यह कार्य उसके गृह सचिव (Home Secretary) द्वारा किया जाता है। ज़िदारी मामला में राजमुकुट बहुत दण्ड प्राप्त अपराधी तक को क्षमा कर सकता है। दोषी मामला में राजमुकुट का ऐसे बड़े विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।

(घ) धार्मिक शक्तियाँ

राजमुकुट वा विभिन्न धार्मिक शक्तियाँ (Ecclesiastical Powers) भी प्राप्त हैं। ब्रिटेन में एंग्लीकन (Anglican) और प्रेसबिटेरियन (Presbyterian) चर्च राज्य के अवयव के रूप में हैं। उनका नियंत्रण राजमुकुट व संसद द्वारा होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च का प्रमुख होने के नाते वह कई तरह की शक्तियाँ तथा पावर के ऑफ-विशेषों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा की अनुमति से ही 'चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा' (National Assembly of the Church of England) की समस्त कार्यवाहियाँ होती हैं। चर्च के 'कन्वोकेशन' केवल राजमुकुट ही बुला सकता है। कन्वोकेशन द्वारा पारित नियमों के लिए राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन सम्बन्धी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी है। धार्मिक अदालतों (Ecclesiastical Courts) से अपीलें प्रिबी कोसिल की 'याचक समिति' के पास आती हैं। स्कॉटलैंड के स्थापित चर्च (Established Church of Scotland) अर्थात् प्रेसबिटेरियन चर्च के सम्बन्ध में राजमुकुट की शक्तियाँ, उनकी महत्वपूर्ण नहीं हैं।

व्यक्तिगत रूप से राजा का यह धार्मिक दायित्व है कि वह किसी रामन कैथोलिक से विवाह न करे, क्योंकि वह एंग्लीकन व प्रेसबिटेरियन दोनों ही धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रमुख है। अपनी धार्मिक शक्तियों के कारण ही राजा 'धर्म रक्षक' (Defender of the Faith) कहा जाता है।

(ङ) संरक्षण और सम्मान की शक्तियाँ

राजमुकुट को 'सम्मान का स्त्रोत' (Fountain of Honours) भी कहा जाता है। यही नागरिकों को राजनीतिक व सामाजिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। उदाहरणार्थ 'पीयर बनाया जाना' यदि राजनीतिक सम्मान है तो 'नाइट' (Knight) की उपाधि देना सामाजिक सम्मान है। प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही सम्राट द्वारा लोगों को उपाधियाँ से मुहोभित किया जाता है।

राजमुकुट की शक्तियाँ किस प्रकार व्यवहार में लाई जाती हैं ?

ऊपर वर्णित शक्तियाँ और अधिकार वैधानिक दृष्टि से राजमुकुट में निहित हैं, किन्तु व्यवस्था में उन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता, समस्त राजाओं ने सदस्यों आदि के द्वारा किया जाता है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा (या राजा) स्वयं नहीं करता। ये शक्तियाँ राजा के नाम पर अन्य लोगों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। व्यवस्था राजमुकुट की शक्तियों व शक्तियों के सत्ता के प्रति उत्तरदायी मन्त्री ही होते हैं। उक्त नियंत्रण का मीमांसा यह है कि राजा व हुकूमत व्यक्तिगत सेवकों से, छाड़ कर अन्य सभी अधिकारियों का नियुक्ति अथवा छोट सब मन्त्रियों के हाथ में है। राजा का कोई जादू तब तक नहीं चलता जब तक

जब तक कोई मंत्री उस पर हस्ताक्षर न कर दे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजमुकुट जो भी करता है, चाहे परमाधिकार का प्रयोग हो या संसदीय कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग, वह ब्रिटिश जनता के कार्यपालिका प्रतिनिधि के रूप में करता है और ये सभी कार्य संसद के नियंत्रण के अधीन हैं।

राजा की वास्तविक स्थिति, उसके विशेषाधिकार और प्रभाव (The Actual Position, Privileges and Influence of the Sovereign)

राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग में लाना वह प्रश्न उठता है कि राजमुकुट में निहित शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं ही कर सकता है? हमारे शास्त्रों में राजमुकुट की मर्यादा में राजा की वास्तविक स्थिति क्या है? वह केवल मात्र एक 'स्वर्णम शून्य' (Golden Zero) अथवा 'रबर की मुहर' (Rubber Stamp) है अथवा शासन में कुछ प्रभाव और विशेष स्थिति का भी उपयोग करता है? इस सवाल में राजा की वास्तविक स्थिति का मनन के लिए हम निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा—

- (1) 'राजा कोई गलती नहीं कर सकता' (The King can do no wrong)
- (2) "राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता" (The King reigns, but does not govern)
- (3) राजा के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (Royal Privileges and immunities)
- (4) विभिन्न कारणोंवश राजा का विस्तृत प्रभाव।

राजा कोई गलती नहीं कर सकता

इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि राजा को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि लॉवेल (Lowell) के शास्त्रों में "संविधान के पुराने सिद्धांत के अनुसार सभी लोग राजा का सहायक होते थे। उनका काम था सलाह देना और राजा का काम था निर्णय करना। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। राजा से मलाह ली जाती है किंतु नियम मंत्री करते हैं। वास्तव में इस उक्ति के दो रूप हैं—कानूनी और राजनीतिक। कानूनी रूप से राजा अपने शक्तियों के लिए कानून से ऊपर है क्योंकि वह स्वयं स्वयं विवेक से कोई शपथ नहीं करता बल्कि मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य भी करता है। राजनीतिक दृष्टि से जायज है कि यदि राजा कोई राजनीतिक भूल करे या किसी अपराध का परामर्श दे तो भी उसका विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। उस भूल के लिये सम्बंधित शिमाय का मंत्री ही उत्तरदायी ठहराया जायेगा और वह स्वयं कानूनी या संविधानिक अपराध का दावा भी नहीं करेगा।

“राजा कोई गलती नहीं कर सकता” इस सूत्र को अधिक सरलता से इसके निम्नलिखित तीन अर्थों द्वारा समझा जा सकता है—

(i) राजा कानून से ऊपर है —इसका अर्थ है कि राजा विधि और याय का स्रोत है। उस पर किसी भी विधि के अन्तर्गत दोष आरोपित नहीं किया जा सकता। राजा पर न किसी न्यायालय में अभियोग ही लगाया जा सकता है और न किसी न्यायालय द्वारा उस अपराधी ही घोषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि राजा किसी की हत्या भी कर देता भी ब्रिटिश विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिनके द्वारा उस पर अभियोग चलाया जा सके।

(ii) राजा दूसरों से भी गलत बात नहीं कर सकता—यह अर्थ पहिले अर्थ से ही निकलता है। जब राजा स्वयं कोई भूल नहीं कर सकता तो वह दूसरों से भी गलत बात नहीं करा सकता अपवा किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि कोई मंत्री कोई कानूनी या सांविधानिक अपराध करता है तो वह यह कहकर अपनी रक्षा नहीं कर सकता कि उसने यह काम राजा की आज्ञानुसार किया है। दूसरे शब्दों में कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किय गये किसी अवधानिक कृत्य के लिए राजा की कानूनी उन्मुक्ति (Legal Immunity) की शरण नहीं ले सकता। कोई भी अपराधी यह बात कह कर अपनी सफाई नहीं दे सकता कि राजा के कहने से उसने यह गलती की है। सन 1678 में ‘डेनबी कास’ (Danby's case, 1678) में इस सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया गया था। विदेश मंत्री डेनबी ने फ्रांस के साथ एक गुप्त संधि बिना अन्य मंत्रियों की सलाह लिये कर ली थी। जब मसद ने उस पर राजद्रोह का अभियोग लगाया तो डेनबी ने अपने बचाव में यह तर्क पेश किया कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था, और चूँकि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वह दोषी नहीं है। अपने महाभियोग के समय उसने राजकीय क्षमा भी उपस्थित की। लेकिन, मसद ने सब दलीलों को अस्वीकार करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अपने कार्यों के लिए मंत्री ही उत्तरदायी हैं और वे किसी भी अवधि या असंवैधानिक कृत्य के लिए ‘राजा के आदेश’ की शरण नहीं ले सकते।

(iii) राजा के कार्यों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी होना चाहिए—उपरोक्त दूसरे अर्थ से ही तीसरा अर्थ यह निकलता है कि यदि राजा न स्वयं भूल कर सकता है, न दूसरे व्यक्ति, से भूल करवा सकता है, तो किसी न किसी व्यक्ति को उसके गलत कार्य के लिये उत्तरदायी होना चाहिए। राजा की किसी भी भूल का उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से उस मंत्री पर होता है जिनके परामर्श से उसने यह भूल की। उस प्रकार यह कथन मंत्रियों के उत्तरदायित्व की स्थापना करता है जो ब्रिटिश शासन-प्रणाली की आधारशिला है।

स्पष्ट है कि ब्रिटेन का राजा व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य नहीं करता उसे सभी कार्य मंत्रियों की सलाह पर करने पड़ते हैं और उसके सभी कार्यों के

मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। इन मन्त्रियों में ग्लेडस्टन (Gladston) ने नृत्य ही कहा था कि, "राजा के जीवन में उसके राज सिंहासन पर आमीन होने के समय से उसकी मृत्यु तक एक भी क्षण ऐसा नहीं जाना जाय कि उसने कहीं के लिए कोई न कोई मसदा के प्रति उत्तरदायी न हो और राजा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि कोई मंत्री उसका उत्तरदायित्व वहन करने का तैयार न हो।"

वास्तव में मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के परिणामस्वरूप राजा आज राजनीतिक दखल दी से अलग हो गया है और पदाब्द मंत्रिमण्डल को ही यह अवकाश प्राप्त होता है कि राजा का।

राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता।

ब्रिटिश राजा की स्थिति को इन बहुचर्चित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि "राजा राज्य करता है, शासन नहीं।" इसका अभिप्राय यह है कि वैधानिक दृष्टि से तो राजा का आज भी प्राचीन राज जैसा ही महत्व है, लेकिन वास्तव में वह अब उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जिनका प्राचीनकाल में प्रयोग किया जाता था। प्रजातन्त्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल सांविधानिक अथवा नाममात्र का "शासन प्रमुख" रह गया है। उसकी उक्त सभी वास्तविक शक्तियाँ "राजमकुट" नामक अमृत या काल्पनिक संस्था में निहित हो गई हैं। "राजमकुट" की किसी भी शक्ति का प्रयोग राजा या रानी व्यक्तिगत रूप से नहीं करना। इनका प्रयोग उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाना है। इस प्रकार यह कहना सब है कि राजा के हाथों में शासन की कहीं शक्तियाँ नहीं हैं, अर्थात् राजा शासन नहीं करता पर तु राजा राज्य करता है अर्थात् नाम मान का राजा है क्योंकि शासन के सभी णाय उसी के नाम से होते हैं और उसे राजा जैसा सम्मान प्राप्त है।

पर तु "राजा शासन नहीं करता" इससे यह नहीं समझना चाहिए कि राजा सबका प्रभावहीन है और उसका कोई महत्व नहीं है। पारम में वास्तविक शक्तियाँ न होते हुए भी राजा शासन पर काफी असर डालता है। वजहों के अनुसार उसे शासन के दोन में तीन महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं—

(i) परामर्श देने का अधिकार,

(The Right to be consulted)

(ii) प्रोत्साहन देने का अधिकार,

(The Right to Encourage)

(iii) चेतावनी देने का अधिकार

(The Right to Warn)

आज राजा शासन का आलोचन, परामर्शदाता और मित्र है। उसके परामर्श देने के अधिकार का आशय है कि वह मंत्रियों के कार्यों की पूर्ण जागरूकी रखे और उन्हें आवश्यकतानुसार उचित परामर्श दे। प्रोत्साहन देने के अधिकार का अर्थ है कि राजा यदि किसी नीति को राज्य के लिए कल्याणप्रद समझे तो मंत्रियों

को उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। चेतावनी देने के अधिकार का मतलब है कि यदि मंत्रियों द्वारा कोई गलत निर्णय किया जाय या उनका कोई काम देश के लिए हानिप्रद हो तो राजा उन्हें चेतावनी देने और गलती दूर करने के उपाय भी बतलाये, किन्तु चेतावनी के अधिकार का यह अर्थ समझना भ्रामक होगा कि राजा मंत्रियों का विरोध करने की क्षमता रखता है। राजा चेतावनी दे सकता है, लेकिन मंत्रियों का अधिकार है कि वह राजा की बातों को मानें या न मानें।

वास्तव में एक प्रभावशाली राजा अपने प्रयुक्त अधिकारों से प्रशासकीय मामलों और घटना-चक्र को प्रभावित करने में बहुत कुछ सफल हो सकता है। अपने इन अधिकारों के कारण वह केवल प्रतिमा मान या स्वर्णिम शून्य नहीं बन पाया है। ब्रिटेन का इतिहास बतलाता है कि विभिन्न अवसरों पर ब्रिटिश राजाओं और रानियों ने प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की सरकार की नीति को बड़ा प्रभावित किया है पर यद्यपि सब कुछ वस्तुतः राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उनकी औपचारिक शक्तों पर नहीं।

राजा के कुछ विशेषाधिकार

राजा की वास्तविक स्थिति को आंकने की दिशा में उसके विशेषाधिकारों का अध्ययन भी सहायक है। यद्यपि शासन से सम्बंधित कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता उसे नहीं है, फिर भी वह अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मविधान शास्त्रियों के अनुसार राजा के अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये हैं—(1) प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का, (2) लोकसभा को भंग करने का, (3) मंत्रियों को बर्खास्त करने का, (4) लोगों को पीयर बनाने का, एवं (5) विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने या न देने का।

प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का विशेषाधिकार—सरकार का प्रमुख होने के नाते राजा को अधिकार है कि वह अपनी समझ से उपयुक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करदे। परन्तु अपन इस चुनाव में राजा पर यह प्रतिबंध है कि वह व्यक्ति एक स्थायी मंत्रिमण्डल बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का विश्वासपात्र होना चाहिए। अपने इस निर्णय में वह इन परम्परा से निर्देशित होता है कि लोकसभा का नेता कौन है। हा, कुछ असामान्य परिस्थितियों में राजा को अपनी ओर से प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अवसर मिल सकता है। उदाहरणार्थ, किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके त्यागपत्र दे देने पर या लोकसभा में किसी दल का बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री पद के अनेक उम्मीदवार हो और यह निश्चित न हो पाय कि बहुमत का नेतृत्व किसके हाथ में है तो राजा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। सन् 1894 में रानी विक्टोरिया ने उस अवस्था में लार्ड रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया, जब उस पद के कई प्रत्याशी थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति

मे राजा के स्व विवेक के प्रयोग का एवं अथ उदाहरण उस अवसर का है जब कि आर्थर हण्डरमन के लोक सभा के बहुमत वाले दल का नेता चुन लिए जाने पर भी राजा ने रमज मैकडोनेल्ड को संपूर्ण सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इस घटना को 1931 की राजमहल की क्रांति (Palace Revolution of 1931) की भांति दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक परम्परा के अनुसार राजा आमतौर से स्वयं पदच्युत प्रधानमंत्री से उसके उत्तराधिकारी के बारे में सलाह लेता है, परंतु वह ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं है। 1956 में जब स्वयं सकट पर एथोनी ईडन ने त्याग पत्र दिया तो महारानी एलिजाबेथ ने दूसरे प्रधानमंत्री के लिए ईडन से नहीं बल्कि दो बुजुर्ग राजनीतिज्ञ—चर्चिल और लाड सेलिसबरी से सलाह की तथा चर्चिल की राय मानते हुए मैकमिलन को नया मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया।

जहां तक अन्य मन्त्रियों की नियुक्तियों का प्रश्न है, प्रधानमंत्री का परामर्श ही प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है। हा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला राजा (या रानी) मन्त्रियों के चयन में प्रधानमंत्री को प्रभावित कर सकता है, किंतु इस विषय में प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया जा सकता।

लोकसभा को भंग करने का विधायिकाधिकार—राजा का एक अन्य विधायिकाधिकार प्रधानमंत्री के परामर्श पर अथवा उसकी प्रार्थना पर लोकसभा को भंग करने से सम्बंधित है। इस विषय में दो प्रमुख मत प्रचलित हैं—एक मत तो यह है कि राजा का लोकसभा का विघटित करने का विधायिकाधिकार वास्तविक है, जबकि दूसरा मत यह है कि राजा का यह अधिकार अवास्तविक है। पहले मत के समर्थक 'सरक्षता-सिद्धांत' (Theory of Guardianship) को मानते वाले हैं। उनका विचार है कि राजा संविधान का संरक्षक है, अतः उसका यह वास्तविक विधायिकाधिकार है कि लोकसभा के विघटन के प्रश्न पर वह स्व विवेक से कार्य करे। इस विचार के समर्थकों में ए.सन, कौप और क्विंटिन हॉग (Quintin Hogg) प्रमुख हैं। दूसरे मत के समर्थक 'लोकतन्त्र-सिद्धांत' (Democratic Theory) अथवा 'संसदीय सिद्धांत' (Parliamentary Theory) को मानते वाले हैं। इनका विचार है कि संसद के विघटन का राजा का विधायिकाधिकार अवास्तविक है। संविधानिक प्रमुख हान के नाते उसका अस्तित्व है कि वह अपने सभी विधायिकाधिकारों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श से करे ताकि संविधान की रक्षा और संसदीय शासन प्रणाली का निर्वाह हो सके। सारांश का निष्कर्ष है कि अनेक हित अथवा स्वायत्त भी दृष्टि से राजा की मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही अपने विधायिकाधिकारों का प्रयोग करना चाहिये अथवा राजा का प्रभाव धर्मिक दल के विरोध में और अल्पतरु दल के पक्ष में प्रयुक्त हो सकता है। एतद्वत् तब यह भी है कि यदि राजा का संविधान का संरक्षण मान लिया जायेगा तो उसकी निर्दोषता का प्रोत्साहन मिलेगा।

व्यावहारिक और तार्किक दोनों ही दृष्टियों से राजा के विशेषाधिकारों के प्रयोग के विषय में ससदीय या गैरकृत्यात्मक मिश्रितवादियों का मत ही अधिक उपयुक्त है। वैसे भी मन् 1784 के बाद से अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि राजा ने लोकसभा के विघटन से सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीय परामश को न माना हो।

मन्त्रियों की बर्खास्तगी का विशेषाधिकार—राजा के इस विशेषाधिकार की वास्तविकता के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मत है कि मन्त्रियों की बर्खास्त करने सम्बन्धी राजा का विशेषाधिकार वास्तविक है। मन् 1783 में जॉज एचम ने लाड नाथ फॉक्स के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त करके अपने इस अधिकार का प्रत्यक्ष परिचय दिया था। जेनिंग्स का कहना है कि यदि राजा को यह विश्वास हो जाये कि सासक दल बहुमत द्वारा समर्थित नहीं रहा है तो इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके और भली प्रकार आश्वस्त होने के बाद ही यह मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने अथवा लोकसभा का विघटन करने की बात पर बल दे सकता है और यदि मन्त्रिमण्डल राजा की बात न माने तो उसे मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ करने का अधिकार है। परन्तु श्रुति यह मांग कटकाकीण है, अतः जेनिंग्स का विचार है कि उचित यही है कि या तो राजा अपने मन्त्रियों को इस बात के लिये तैयार करले कि वे उसे लोकसभा के विघटन का परामश दें या त्याग पत्र दे दें।

इस सम्बन्ध में अधिकांशतः माय मत यही है कि राजा स्वेच्छा से अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रायः नहीं कर सकता। पूरे मन्त्रिमण्डल की बर्खास्तगी का उसका प्रयत्न निष्फल रहेगा, यदि उस मन्त्रिमण्डल का लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। व्यक्तिगत मन्त्रियों का बर्खास्त करने का साहस वह प्रधानमन्त्री से क्षान्ता मोल लेकर नहीं करेगा क्योंकि लोकसभा में बहुमत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमन्त्री स्पष्ट होकर राज-पद के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। व्यक्तिगत मन्त्रियों की वह प्रधानमन्त्री के परामश पर ही बर्खास्त करेगा।

पीयर बनाने का विशेषाधिकार—राजा का एक उल्लेखनीय विशेषाधिकार लोगों को 'पीयर' (Peer) बनाने से सम्बन्धित है। यदि लाड सभा लोकसभा द्वारा पारित किये गये विधेयक का विरोध करे तो राजा प्रधानमन्त्री के परामश पर लाड-सभा के विरोध को दबाने के लिये नये पीयरों का निर्माण कर सकता है। परन्तु यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमन्त्री से यह कह सकता है कि वह विवादग्रस्त विधेयक को विषय बनाकर पुनः साधारण निर्वाचन कराये और यह देखे कि सत्तारूढ़ दल को सम्पूर्ण राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है या नहीं। लाड-सभा की शक्ति के अत्यधिक घट जान से राजा के विशेषाधिकारों का अब महत्व अधिक नहीं रहा है।

विषयकों पर स्वीकृति देने या न देने का विद्याधिकार—राजा का यह विशेषाधिकार वर्तमान परिस्थितियाँ में अवाम्त्विक ही है। यद्यपि सन् 1852 में डिनरली ने राजा के इस अधिकार को वास्तविक बतलाया था, किन्तु 1707 से जब तक इस अधिकार का प्रयोग किसी राजा द्वारा नहीं किया गया है और जब इस अधिकार को मतप्राय नमस्सा जाता है। आज ता स्थिति यह है कि राजा स्वयं विषयका पर स्वीकृति नहीं देता बरन यह कार्य उसके कमिश्नर करते हैं।

राजा की शक्ति और उसके व्यावहारिक प्रयोग के विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अंतिम रूप से राजा एक सांविधानिक प्रमुख है जो केवल राज्य करता है, शासन नहीं। अपने विशेषाधिकारों के विषय में भी वह स्वविवेक से कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है और उस अपने मंत्रियों के परामर्शानुसार ही कार्य करता पड़ता है। परन्तु फिर भी अपने बुद्धिबल विवेक व्यक्तित्व, अनुभव और निष्पक्ष व्यवहार तथा पद की श्रद्धा आदि के कारण वह शासन को आवश्यकतानुसार प्रभावित करने की क्षमता अवश्य रखता है। हमें राजा की इस क्षमता अथवा उसके प्रभाव को बनाय रखने वाली इन विभिन्न बातों पर भी विचार करना चाहिये।

राजा मतप्राय स्वर्णिम शून्य अथवा मिट्टी की मूर्ति मात्र नहीं है, अपितु उसका विशिष्ट प्रभाव और महत्व है। वज्रहाट के इन शब्दों से राजा के प्रभाव की गहराई का पता चलता है कि, “प्रामाण्य और नीति निर्माण के सम्बन्ध में सम्राट के तीनों राजनातिक्रम अधिकार हैं, यथा परामर्श के लिए पूछे जाने का अधिकार, प्राप्ताहृत देने का अधिकार और वेतावनी देने का अधिकार। यद्यपि राजा के ये अधिकार मुख्यतः मर्यादित हैं, फिर भी उसे प्रभावशाली बनाने में इनका बहुत हाथ है। इन अधिकारों का विश्लेषण पहले किया जा चुका है। इनके प्रतिष्ठित राजा के महत्व और प्रभाव के कुछ अन्य प्रमुख कारण ये हैं—

व्यक्तित्व—राजा के प्रभाव का सबसे प्रमुख कारण उसका व्यक्तित्व है। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो मंत्रिगण स्वतः ही उसके परामर्श के बाग नतमस्तक होते हैं, किन्तु यदि राजा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं रखता तो उसे मंत्रियों के हाथों की खर की मुहर बन कर रहना पड़ता है। लास्की का मत है कि प्रामाण्य पर राजा का प्रभाव व्यक्तित्व के अनुपात की समस्या है, प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व उच्च है तो सम्राट का प्रभाव कम होगा।

अनुभव—राजा के प्रभाव का दूसरा कारण उसका विस्तृत अनुभव है। राजा स्वयं जीवन पयत्त शासन का प्रमुख रहता है जब कि मंत्रिमण्डल निरन्तर बदलते रहते हैं। इस प्रकार वह अपने राज्यकाल में अनेक मंत्रिमण्डलों का उत्थान और पतन की कहानी पढ़ता है तथा परिवर्तित होते रहने वाले मंत्रियों

की तुलना में उसका प्रशामनिक अनुभव उत्तरोत्तर गहरा होता चला जाता है। उसकी स्थिति एक ऐसे अनुभवी शासन कुशल व्यक्ति की सी हो जाती है जो अपने विशाल अनुभव के बल पर मंत्रिमण्डल को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखता है।

संसदीय शासन की कार्य विधि—ब्रिटिश संसदीय शासन की कार्य विधि भी राजा के प्रभाव की वृद्धि में विशेष सहायक है। राजा संसदीय शासन का अध्यक्ष होता है। अतः मंत्रिमण्डल की कार्यवाहियाँ उसके समक्ष प्रस्तुत होती हैं, विदेश विभाग के महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार भी उनके पास प्रतिदिन पहुँचते हैं और संसदीय वाद-विवादा का सरकारी प्रतिवेदन व ममाचार-पत्रों में प्रकाशित विवरण भी रोजाना उसके सम्मुख पेश किये जाते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमण्डलीय निणयो और महत्वपूर्ण शासन कार्यों से राजा को निरन्तर अवगत कराता रहे। राजा का स्वयं का कमचारी मण्डल होता है और उसका एक मंत्री (Conscience Keeper) भी होता है जिसका काम सभी राजनीतिक घटनाओं की सूचना राजा को देते रहना है। स्पष्ट है कि संसदीय शासन की इस कार्य विधि के कारण राजा को सम्पूर्ण शासन के बारे में इनका ज्ञान हा जाता है जितना कि अलग-अलग मंत्रियों को सम्भवतः नहीं होता। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होना है कि आवश्यकता पड़ने पर वह मंत्रिमण्डल के मदस्यों का उपयोगी परामश दे सकता है, मंत्रिमण्डल के कार्य विशेष के दाप गिना सकता है और मंत्रिमण्डल की किसी त्रुटिपूर्ण नीति के सम्भावित परिणामों के बारे में चेतावनी दे सकता है।

निष्पक्षता—राजा के प्रभाव का चौथा महत्वपूर्ण कारण उसकी राजनीतिक निष्पक्षता है। जनता की, राजा से, उसकी इस निष्पक्षता के कारण अपूर्व भक्ति है और राजा जिस बात को अच्छी मानता है, जनता के लिए भी वह बहुत उत्तम हो जाती है। राजा की राजनीतिक तटस्थता के कारण ही सभी दलों के मंत्रिमण्डल उसके परामश को समान रूप से सम्मान देते हैं। राजा शासन का प्रमुख होते हुए भी राजनीतिज्ञ दृष्टि से तटस्थ है और इसीलिए विरोधी दल भी उसका भपना (His Majesty's Loyal Opposition) होता है।

गौरवपूर्ण पद—राजा के प्रभाव का एक प्रमुख कारण उसके पद की महत्ता है। राजा की गौरवपूर्ण स्थिति उसके परामश और विचार को गुरुता प्रदान करती है। अतीत काल से चले आने वाले राज पद के प्रति सम्पूर्ण ब्रिटिश जनता में अनन्य भक्ति भाव है। अतः कोई भी मंत्रिमण्डल राजा के प्रति उपेक्षा-भाव प्रदर्शित करने का साहस नहीं करता। महान राज पद का प्रभाव मंत्रिमण्डल पर अवश्य पड़ना है क्योंकि वे ब्रिटिश जनता के ही तो प्रतिनिधि होते हैं।

निष्कप रूप में अपने पद के स्थायित्व, विशाल अनुभव, राजनीतिक तटस्थता और अनुपम व्यक्तित्व के कारण एक योग्य राजा ब्रिटेन के शासन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इस प्रभाव से मुह नहीं मोड़ा जा सकता।

राजपद का औचित्य

(Justification of Monarchy)

इ गलैण्ड के राजपद के अध्ययन के प्रसंग में यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि आसिर आधुनिक युग के इस महान प्रजातान्त्रिक राज्य में राजतन्त्र अभी तक क्या चालू है अथवा राजपद की क्या आवश्यकता है ? जबकि विश्व के प्रत्येक देश में राजतन्त्र का सूय डूब रहा है उन्हा ब्रिटनवासी 'महारानी चिरजीवी हो' के गीत का रस हैं। वास्तव में ब्रिटन में राजपद का होना एक आश्चर्यजनक असंगति है क्योंकि वह न केवल ममदीय शासन का जन्म स्थान है बल्कि आधुनिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रों के लिए आदर्श प्रजातन्त्र का नमूना भी है। जवश्य ही ब्रिटन में राजतन्त्र अथवा राजपद के प्रचलन के पीछे कुछ निश्चित उपयोगी कारण छिपे हुए हैं।

ऐतिहासिक कारण

ब्रिटन में राजपद के अस्तित्व को बनाए रखने में मुख्यतया इन ऐतिहासिक कारणों ने योग दिया है—

(1) राजपद एक ऐतिहासिक वस्तु है—ब्रिटन का राजपद लगभग 1150 वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक धरोहर है। ब्रिटनवासी जिन राजतन्त्र के सम्पर्क में सताब्दियों से रहते आये हैं, उनसे अलग होने की बात साचना भी उन्हें अस्वाभाविक लगता है। स्वभाव से रुढ़िवादी और परम्परावादी ब्रिटिश जनता के लिए राजपद एक ऐतिहासिक परम्परा है, अतीत का वर्तमान से तथा वर्तमान को अतीत में जोड़ने वाली बड़ी है।

(2) राजपद का सराहनीय इतिहास—अंग्रेजों का राजपद तो इसलिए भी स्थायी है कि उसका अतीत बड़ा गौरवमय तथा देश के हितों का रक्षण रहा है। केवल स्ट्यूअर्टवालीन राजाओं को छोड़कर अन्य सभी राजाओं ने व्यक्तिगत स्वार्थों की तुलना में राष्ट्रीय हितों और गौरव की रक्षा की है। आज पण्डितों अपनी महानता, फर्मठता और प्रजावाग्म्यता के कारण 'अपने प्रजातान्त्रिकों के विना' तब रहलाने सके थे। आज के अंग्रेज बालक जब अपने महान सम्पत्तियों के महान्तु वारों की गोमा परते हैं तो उनमें राजपद के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और सम्मान की भावना पैदा हो जाती है।

(3) राजतन्त्र का शांतिपूर्ण जनतन्त्रीकरण—ब्रिटन में राजपद इसलिए भी अति लोकप्रिय है कि उसने अपने को जनता की इच्छानुसार ढाला है। ब्रिटन का निरंकुश राजतन्त्र ने लोकतन्त्र के उदय और प्रसार में बाधा बनने की चेष्टा नहीं की है, बरन् अपना शांतिपूर्ण जनतन्त्रीकरण ही ज्ञान दिया है। यदि ब्रिटिश राजा स्वयं के जारों और शासकों के लुई पण्डितों की तरह विवेकहीन व्यवहार करते तो ब्रिटन का राजतन्त्र भी अभी का सम्पाद हो गया होता। वास्तव में एंग्लो ने

ठीक ही लिखा है कि "ब्रिटेन में राजतन्त्र ने अपने को लोकतन्त्र के हाथ में ऐसे बेच दिया है मानो वह इसी का प्रतीक हो।"

मनोवैज्ञानिक कारण

राजपद के अस्तित्व के मूल में मनोवैज्ञानिक उपयामिता भी बड़ी उत्तरदायी रही है—

(1) ब्रिटिश जाति का रुढ़िवादी स्वभाव—अंग्रेज स्वभाव से रुढ़िवादी और पुरातन प्रिय है। वे अपनी प्राचीन पद्धतियों और मर्यादों को, मर्यादनुसार सुधारते हुए, बनाये रखना अति पसंद करते हैं। प्राचीनकाल से चली आ रही सत्ताशा और ऐतिहासिक परम्पराओं की मौलिकता और प्राचीनता को बनाये रखकर भी उन्हें आधुनिकतम परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेना, ब्रिटिश जनता का स्वभाव है। यही कारण है कि ब्रिटिश मानव राजतन्त्र जैसी गौरवपूर्ण प्राचीनतम राजनीतिज्ञ मर्यादा के विनाश की कल्पना से भी कांप उठता है। अंग्रेजों ने अपनी स्वभावगत विशेषता के कारण राजतन्त्र को बनाये रखा है। उन्होंने उसका जनतन्त्रीकरण किया है, पर इस तरह कि राजतन्त्र के परम्परागत स्वरूप को कोई आंच नहीं आयी है। राजतन्त्र बिल्कुल कायम है, किन्तु उसकी आत्मा का जनतन्त्रीकरण कर दिया गया है।

(2) राजपद में स्थानाधिक सम्मान—राजपद के अस्तित्व का दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण उनमें एक अदभुत सम्मान और आदर का होना है। उसमें वह राजाशाही शान-शीलता होती है जो किसी अन्य शासन में नहीं है। जर्मन के अनुसार 'लाकृत शासन का शासन वहाँ और नीरस नीतियों तक ही सीमित नहीं है। उसमें कुछ शीलता, कुछ सज्जनता होती ही चाहिये और ऐसी स्पष्ट सज्जनता और शान देवने की मिलेगी जमी कि गहरी पोशाक (Royal Purple) में लिपटी है।' राजपद की महानता और शान ही राजतन्त्र के नीचे और उसके प्रति निष्ठा का सम्मान प्रदान करने के लिए राजाश्री का गहरी धूम धारा त गहरी पर फैलते हैं।

राजपद सुरक्षा का प्रतीक—अंग्रेजों की भावना के अनुसार राजा उनकी एकता, दृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्हें यह अनुभूति होती है कि राजपद के बिना उनके देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पाया। यह बस्तु एक विचित्रता है किन्तु साथ ही ब्रिटिश जनता के लिए गौरवपूर्ण बात है कि राजा अथवा रानी उनके लिए एक महान औपधि स्वयं है। अंग्रेज मानते हैं कि "यदि राजा वरिष्ठतम राजप्राज्ञ मन्त्रि, राज्य, शासन और नीति का नीर सोते हैं। अंग्रेजों का विचार है उनका राजतन्त्र प्रजातन्त्र का सार और स्वरूप है।

राजनीतिक कारण

ब्रिटन का संविधान

ब्रिटन में राजपद कुछ सदाकत राजनीतिक कारणों के आधार पर भी अपना अस्तित्व बनाये हुए है, जा निम्न हैं—

(1) राजतंत्र का लोकतन्त्रात्मक रूप ग्रहण करना—ब्रिटन में निरंकुश राजतंत्र ने सांविधानिक राजतंत्र का रूप ले लिया है। राजतंत्र के जनतंत्रीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और अश्रिताशत स्वाभाविक ढंग से हुई है। इंग्लैंड के अधिकांश राजा हवा के रूप को पहचानने में साहिर रहे हैं और जिस गान से वे निरंकुश राजा-जा के रूप में शासन करते थे उसी शान से सांविधानिक राजाओं के रूप में कार्य करने को उद्यत हो गये। ऐसे राजतंत्र को बनाय रखना ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के लिये बड़ा आवश्यक है। मुनरो का मत है कि यदि राजतंत्र हटाया गया तो उसके स्थान पर कोई अयसस्था पुन स्थापित करनी पडगी क्योंकि संसदीय शासन में दूसरी कार्यपालिका की आवश्यकता होती है तथा प्रधानमन्त्र किसी प्रजातान्त्रिक देश में स्वयं माय अव्यक्त के रूप में कार्य नहीं करता। यदि राजतंत्र अथवा राजा को लोप किया गया तो उसके स्थान पर या तो अमरिका की तरह जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति या कुछ अय देशों की भांति ममद द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति लाने की आवश्यकता हागी। इस तरह निर्वाचित राष्ट्रपति को पदासीन करने पर स्वभावतः उसे कुछ शक्तिया प्रदान करनी हागी। यदि अमरिका के समान राष्ट्रपति बनाया गया तो कैबिनेट का अस्तित्व खतरे में पडगा और संसद की सर्वोच्चता समाप्त हागी। यदि फ्रांस नमून का राष्ट्रपति लाया गया तो इसका अय राजतंत्र को ही दूसरे नाम से स्थापित करना हागा। यह निश्चित है कि निर्वाचित राष्ट्रपति कभी भी अधिकारों की माग करके शासन में गतिराय पदा कर सकता है। अतः यश परम्परागत राजतंत्र ही उत्तम है क्योंकि राजा निष्पक्ष भा रहता है और कभी अधिकारों की माग भी नहीं करेगा और देग राष्ट्रपति के चुनावों की भारी संसद अथवा गडबड से यचा रहेगा।

(2) राजनीतिर निष्पक्षता—राजपद बन रहन का दूसरा राजनीतिर कारण राजा की निष्पक्षता है। संसदीय शासन प्रणाली के लिये वही व्यक्त संविधान उपयोगी प्रधान हागा जा राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी दल विाप का न हा और दलगत संस्थाओं से ऊपर हो। राजा वंशानुगत होने के कारण इन दलगत भावनाओं से ऊपर उठा होता है। अपनी महनी स्थिति के कारण, एक महान् गौरवपूर्ण सामग्री का अधिपति होने के कारण वह एक संयथा भिन्न आत्मा एक गरिमायय वातावरण में विचरता है। परिणामस्वरूप वह सदाय पणपण रहिन हाकर काम करता है। अपनी राजनीतिक संटस्थता के कारण वह एक आत्मा मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाट करता है अपनी प्रतिष्ठा य अपने प्रभाव द्वारा राजनीतिर पतमदा को तय करता है और विरोध की प्रचण्ड भावना को कम करता है।

(3) शासन कार्य का क्रम बनाये रखने में सहायक—राजपद शासन-कार्यक्रम अथवा व्यवस्था बनाये रखने में बड़ा सहायक है। एक मंत्रीमण्डल के पद त्यागने और दूसरे मंत्रीमण्डल के पद ग्रहण करने के बीच के समय में शासन का भार राजा ही होता है। राजपद के कारण ही बिना उथल-पुथल हुए ही सरकार में सरलता से परिवर्तन हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कारण

राजपद के बने रहने के अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी हैं—

(1) राजा राष्ट्र की एकता का प्रतीक—ब्रिटेन का राजा दूर-दूर बिखरे हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकता का अपरिहार्य प्रतीक है। बाल्डविन (Baldwin) ने एक बार एडवर्ड अष्टम (Edward VIII) से कहा था “सम्राट ही हमारे एकमात्र उचित साम्राज्य की अंतिम कड़ी है। यदि इस कड़ी को तोड़ दिया जाय तो स्वतंत्र राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच कुछ भी सामान्य प्रतीक नहीं रहेगा।” वेस्टमिनिस्टर के अधिनियम (Statute of Westminster) द्वारा एकता के इस प्रतीक को दृढ़ बनाने की चेष्टा की गई है। इसी एक धारा में उल्लिखित है कि जब कभी राजसिंहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन हो तो उस समय इसके लिये राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्य राष्ट्रों की अनुमति आवश्यक होगी। परन्तु इस सम्बन्ध में लास्की (Laski) का यह कथन याद रखना होगा कि ‘सम्राट राष्ट्रमण्डल का भौतिक आधार है और जब तक राष्ट्रमण्डलीय यन्त्र विभिन्न देशों के लिए लाभदायक बना रहेगा, तब तक ही सम्राट का एकता के प्रतीक रूप में महत्व रहेगा।’

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विकास—राजपद का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, पहले साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी बड़ा महत्व था। राजतन्त्र ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नीतिप्रदान करता था, ब्रिटेनवासी सुदूर प्रदेशों को जीतने के लिए उत्साहित था और साम्राज्य के पालन में योग देता था। अंग्रेज लोग ‘साम्राज्यिक मुकुट में उपनिवेश विजय’ (New Jewel for the Imperial Crown) तथा ‘साम्राज्यिक परिवार में नया सदस्य’ (New Child for Imperial Family) जोड़ते थे। ब्रिटेन का राजा विभिन्न देशों से उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने में भी बड़ी महायत्ना पहुँचाता है। यदा-कदा की जाने वाली ब्रिटिश राजाशा (या रानियों) की मैत्री यात्राएँ ब्रिटिश प्रतिष्ठा का बढ़ाने वाली होती हैं।

आर्थिक कारण

राजपद को बनाये रखने का एक आर्थिक औचित्य (Economic Justification) भी है। ब्रिटिश-शासन के लिए यह एक महती सत्ता नहीं है। इसने प्रतिष्ठापन पर राष्ट्रीय बाट के एक प्रतिशत का औसत भाग भी खर्च नहीं होता। लेकिन तुलना में राजनीतिक चेतना के रूप में बाय की माना बहुत ज्यादा है। बार्कर (Barker) के धनानुसार “राजतन्त्र पर व्यय राजनीतिक भावना तथा

विचार के रूप में लौट जाता है, जो समाज को दृढ़ बनाना है।" इसी उपयोगी और ऊपर से कम सर्चिली मस्या का खोने में ब्रिटिश जाति को काई लाभ नहीं दिखाई देता। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का राजा ब्रिटिश समाज के लिए आय का एक स्रोत भी है। राज-परिवार से सम्बन्धित उत्सवों, फिल्मों आदि से काफ़ी आमदनी होती है।

सामाजिक कारण

ब्रिटिश राजा के पद के अस्तित्व का एक कारण यह भी है कि वह ब्रिटेन के साम्राज्य का धारक महत्वपूर्ण व्यक्ती है। वह इंग्लैंड के सामाजिक व मनोरंजन क्षेत्र का नेता है। राजकीय परिवार नृतिपता फैशन, कला, साहित्य आदि क्षेत्र में आदर्श स्थापित करता है और उत्साहवर्धक कार्य करता है। लॉ (Lord) के अनुसार—“बिभी भी संगठन के साथ ‘राजकीय’ शब्द जुड़ जान से सफलता अवश्यम्भावी हो जाती है।” राजा का अवगमन मिल जाने से कोई भी सारजनिक कार्य लोकप्रिय बन जाता है। और तो और दैनिक जीवन के फैशन तक पर राजपरिवार का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

वस्तुतः संसार में कोई भी राजपद इतना सुरक्षित जगह जनता द्वारा सम्मानित नहीं है, जितना कि ब्रिटेन का, और उनके प्रति जनता की आस्था बढ़ती ही जा रही है। तभी तो अंग्रेज बड़े विद्वानों के साथ यह कहते हैं कि संसार में केवल पाँच राजा रहेंगे—चार राजा खेलेने वाले ताशों के और एक इंग्लैंड का राजा।

4

प्रिवी परिषद् एवं मंत्रिमण्डल (THE PRIVY COUNCIL AND THE CABINET)

‘यह (मंत्रिमण्डल) वह केन्द्रीय बिंदु है जिसके चारों ओर
समस्त राजनीति का घूमना है।’

—जॉन मेरियट

ब्रिटिश राज्य की प्रशासकीय शक्ति कार्यपालिका में निहित है जिसमें मंत्रिमण्डल सर्वप्रमुख है और शासन की वास्तविक धुरी है। वैसे कार्यपालिका को पांच विभाग हैं जिनके द्वारा ममत्व द्वारा निर्मित नियमों का पालन होता है और सम्पूर्ण शासन-कार्य संचालित किया जाता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं—

- (1) राजा
- (2) प्रिवी परिषद्
- (3) मंत्रिमण्डल (कैबिनेट)
- (4) राज्य के विभिन्न विभाग
- (5) लोक सेवा (Civil Service)

राजा के बारे में, जो कि औपचारिक कार्यपालिका है, हम पढ़ चुके हैं। अब और अगले परिच्छेदों में यथास्थान अन्य समस्याओं का वर्णन किया जायगा।

प्रिवी परिषद् (The Privy Council)

प्रिवी परिषद् एक सावधानिक यंत्र है। इसके द्वारा राजा के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य सम्पादित होते हैं परन्तु कार्य और शक्ति की दृष्टि से यह इतनी नगण्य हो गई है कि अब यह एक औपचारिक और नाममात्र की संस्था रह गई है। उत्पत्ति तथा विकास

प्रिवी परिषद् की उत्पत्ति नोमन काल की प्राचीन क्यूरिया रेजिस (Curia Regis) से हुई जो राजा की एक परामशदात्री संस्था थी। क्यूरिया रेजिस के कार्य

धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। फलतः इसकी दो शाखाएँ हो गईं। प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलायी। यह राजा को परामश भी देती थी और उसके प्रशासन में दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता भी दिया करती थी। राजा उच्चवर्गों से इसके सदस्यों को चुनता था। एडवर्ड वंश के राज्यकाल में प्रिवी परिषद राजाओं की निष्कृशता की शक्तिशाली माध्यम बन गई और यह उन सभी कार्यों को करने लगी जिन्हें आज मंत्रिमण्डल करता है। कालांतर में इसके आकार में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि राजा के लिये पूरी प्रिवी परिषद में परामश करना अ-यावहारिक हो गया। चान्स द्वितीय ने प्रिवी परिषद के कुछ विश्वसनीय सदस्यों को एक समिति बनाई जिसका नाम 'क्बाल' (Cabal) पड़ा। शान शान इस 'क्बाल' अर्थात् अंतरंग समूह के हाथों में वास्तविक शक्ति आ गई और इसने मंत्रिमण्डल या कैबिनेट का रूप धारण कर लिया, परंतु प्रिवी परिषद समाप्त नहीं हुई, वह भी बराबर चली रही। आज शानम व्यवस्था में इसकी स्थिति औपचारिक रह गई है लेकिन फिर भी वह प्रतिष्ठापूर्ण है।

वर्तमान समय में प्रिवी परिषद में लगभग 320 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति राजा प्रधानमंत्री की परामश से करता है। सभी वर्तमान एवं भूतपूर्व मंत्री, राजनीतिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, गणमाय वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार, चर्च के अधिकारी, अवकाश प्राप्त 'यायाधीन' और प्रशासकों आदि को प्रिवी परिषद् का सदस्य बना दिया जाता है। व्यक्ति अपनी विद्वत्ता एवं योग्यता के कारण ही इसके पदाधिकारी हो पाते हैं। इस परिषद की सदस्यता जीवन पयन्त रहती है और सदस्यों को 'महामाय' (Right Honourable) की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इसके सदस्यों में कुछ उपनिवेशी के लोग भी होते हैं। कुछ भारतीय भी इसके सदस्य बनाए गए थे, जस मर नेज बहादुर सन्नू।

प्रिवी परिषद की बैठकों में प्रायः बहुत कम सदस्य आ पाते हैं। इसकी सारी कामवाही केवल चार या पांच सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाती है जो सदस्य सचिव हैं। समस्त परिषद को केवल विचार अवसरों पर ही आमंत्रित किया जाता है। समस्त प्रिवी परिषद प्रायः केवल दो अवसरों पर सम्मिलित होती है—प्रथम जबकि राजा की मृत्यु होती है द्वितीय जब राजा या रानी अपन विवाह इच्छा की घोषणा करते हैं। राज्याभिषेक के समय भी लगभग पूरी परिषद उपस्थित होती है। लॉर्ड प्रेसिडेंट (Lord President) जो कैबिनेट का मंत्री होता है प्रिवी परिषद की सभाओं का सभापतित्व करता है।

प्रिवी परिषद का वर्तमान कार्य

प्रिवी परिषद का वर्तमान कार्य बहुत मिला-जुला है। सचिव यह मुख्यतः

कायपालिका सम्बन्धी वस्तुओं का निबहान करती है। यह मन्त्रिमण्डल के निणयो पर औपचारिक स्वीकृति देती है। चूँकि राजा मन्त्रियों के परामश पर काय करता है, अतः प्रिवी परिषद् के निर्णय सत्तासदृश शासन की नीतियों को प्रकट करते हैं। प्रिवी परिषद् जो भी काय करती है, वह ससदीय अधिनियमों के अधिकार के अन्तर्गत निकाले गये 'सपरिषद् आदेशों' (Orders in Council) और उद्घोषणाओं (Proclamations) के रूप में व्यक्त किये जाते हैं। उद्घोषणाएँ अधिक महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्ध रखती हैं। परिषद् में स्वीकृत होन पर इन्हें राजा मुद्रांकित रूप से निष्कालता है। सपरिषद् आदेशों को राजा प्रिवी परिषद् की मुद्रा (Privy Council Seal) के अन्तर्गत निकालता है। ये सपरिषद् आदेश, जो राजा के परमाधिकार सम्बन्धी परिषद् आदेशों से भिन्न होते हैं, सरकार के काय मन्त्रालय और उपनिवेशों से सम्बन्धित नियम-उपनियम होते हैं।

प्रिवी परिषद् के कुछ गैर राजनीतिक काय भी होते हैं, उदाहरणार्थ कुछ ऐसे छांटों को स्वीकार करना जो बचानिक व औद्योगिक गवेषणा के लिये तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार करने के लिये कमीशनो की स्थापना करते हैं।

प्रिवी परिषद् के सामने मन्त्री और अन्य उच्च पदाधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं। परिषद् आर्थिक एकीकरण के लिए प्रवर्ध करती है और ब्रिटिश ब्रॉड-कास्टिंग कोर्पोरेशन की नीति निर्धारित करती है। प्रिवी परिषद् के कार्यों के संचालन के लिए अनेक समितियाँ होती हैं। इनमें सर्वप्रमुख 'यायिक समिति' है, जिसका निर्माण 1833 में किया गया था। इसमें विख्यात कानून वेत्ता, विशेषकर 'यायाधीश गण और भूतपूज लाड चांसलर (Lord Chancellors) होते हैं जो दीवानी मुकदमों में अपील के 'यायालय' के रूप में बैठते हैं। यह समिति ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ उपनिवेशों तथा कुछ हद तक स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों का सर्वोच्च न्यायालय है। धर्मोपदेश विषयक और प्राइज-कोर्ट (Prize Court) सम्बन्धी समस्त मामलों के लिए भी यह समिति सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट के रूप में काय करती है, परन्तु यह निणयात्मक सत्ता नहीं है, अपितु राजा को केवल परामश देती है। राजा समिति की रिपोर्ट पर काय करता हुआ दिये गये सम्बन्धित सपरिषद् आदेश का अनुपादन करता है।

अतः में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रिवी परिषद् कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो स्वयं नीति निर्धारित करे और शासन काय चलाये। इसके काय विभिन्न विभागों ने ले लिए हैं और उन्हीं पर अलग अलग उनका उत्तरदायित्व है। दूसरे शब्दों में प्रिवी परिषद् के समस्त कार्यों की जगहवेही मन्त्रिमण्डल के ऊपर रहती है। यह परिषद् प्राचीनकाल में शक्ति की प्रतीक थी, परन्तु आज उस शक्ति के गौरव की प्रतीक है।

कार्यपालिका सम्बन्धी कृतव्यो का निर्वहन करती है। यह मन्त्रिमण्डल के निणयो पर औपचारिक स्वीकृति देती है। चूँकि राजा मन्त्रियों के परामर्श पर कार्य करता है, अतः प्रिवी परिषद के निणय सत्ताह्व शासन की नीतियों को प्रकट करते हैं। प्रिवी परिषद जा भी कार्य करती है, वह ससदीय अधिनियमों के अधिकार के अन्तर्गत निकाले गये 'सपरिषद् आदेशों' (Orders in Council) और उद्घोषणाओं (Proclamations) के रूप में व्यवहृत किये जाते हैं। उद्घोषणाएँ अधिक महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्ध रखती हैं। परिषद में स्वीकृत होने पर इन्हें राजा मुद्रांकित रूप से निकालता है। सपरिषद् आदेशों को राजा प्रिवी परिषद की मुद्रा (Privy Council Seal) के अन्तर्गत निकालता है। ये सपरिषद् आदेश, जो राजा के परमाधिकार सम्बन्धी परिषद आदेशों से भिन्न होते हैं, सरकार के कार्य-संचालन और उपनिवेशों से सम्बन्धित नियम उपनियम होते हैं।

प्रिवी परिषद् के कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं, उदाहरणार्थ कुछ ऐसे चांटरो को स्वीकार करना जो वैज्ञानिक व औद्योगिक गवेषणा के लिये तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार करने के लिये कमीशनो की स्थापना करते हैं।

प्रिवी परिषद के सामने मंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी शपथ ग्रहण करते हैं। परिषद आधिकारिक एकीकरण के लिए प्रवर्ध करती है और ब्रिटिश ब्राड-कास्टिंग कोर्पोरेशन की नीति निर्धारित करती है। प्रिवी परिषद् के कार्यों के संचालन के लिए अनेक कमितियाँ होती हैं। इनमें सर्वप्रमुख न्यायिक समिति है, जिसका निर्माण 1833 में किया गया था। इसमें विख्यात कानून वेत्ता, विशेषकर 'यायाधीश गण और भूतपूष लाड चान्सलर (Lord Chancellors) होते हैं जो दीवानी मुकदमों में अपील के 'यायालय के रूप में बैठते हैं। यह समिति ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ उपनिवेशों तथा कुछ हद तक स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों का सर्वोच्च 'यायालय है। घमों-उद्देश-विषयक और प्राइज-कोर्ट (Prize Court) सम्बन्धी समस्त मामलों के लिए भी यह समिति सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट के रूप में कार्य करती है, परन्तु यह निष्पात्मक मस्या नहीं है, अपितु राजा को केवल परामर्श देती है। राजा समिति की रिपोर्ट पर कार्य करता हुआ दिया गये सम्बन्धित सपरिषद् आदेश का अनुपादन करता है।

अन्त में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रिवी परिषद कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो स्वयं नीति निर्धारित करे और शासन कार्य चलाये। इसके कार्य विभिन्न विभागों ने ले लिए हैं और उन्हीं पर अलग-अलग उनका उत्तरदायित्व है। दूसरे शब्दों में प्रिवी परिषद के समस्त कार्यों की जवाबदेही मन्त्रिमण्डल के ऊपर रहती है। यह परिषद प्राचीनकाल में शक्ति की प्रतीक थी, परन्तु आज उस शक्ति के गौरव की प्रतीक है।

धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। फलतः इसकी दो शाखाएँ हो गईं। प्रशा करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलायी। यह राजा को परामश और उमक प्रशासा में दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता भी दिया राजा उच्चवर्गों से इससे सदस्यों को चुनता था। टयडरवश के राज्य परिषद राजाओं की निष्कुशता की शक्तिशाली माध्यम बन गई और कार्यों को करने लगी जिन्हें आज मन्त्रिमण्डल करता है। कालांतर में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि राजा के लिये पूरी प्रिवी परिषद में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी परिषद के सदस्यों की एक समिति बनाई जिसका नाम 'कबाल' (Cabal) इस 'कबाल' अर्थात् अन्तरंग मन्त्रियों के हाथों में वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल या नेविनट का रूप धारण कर लिया, परन्तु इस नही हुई, वह भी बराबर बनी रही। आज शाखा व्यवस्था औपचारिक रह गई है लेकिन फिर भी वह प्रतिष्ठापूर्ण है। प्रिवी परिषद का वर्तमान समूह

वर्तमान समय में प्रिवी परिषद में लगभग 320 सदस्य राजा प्रधानमन्त्री की परामश से करता है। सभी वर्तमान राजनीतिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, गणमाय या कलाकार, चर्च के अधिकारी, अवकाश प्राप्त यायापीतों और प्रिवी परिषद् का सदस्य बना दिया जाता है। व्यक्ति अपनी कारण ही इसके पदाधिकारी हो पाते हैं। इस परिषद की सदस्यता ही इसके सदस्यों को 'महामाय' (Right Honour) रहती है और सदस्यों को 'महामाय' (Right Honour) विभूषित किया जाता है। इसके सदस्यों में कुछ उपनिवेशों कुछ भारतीय भी इसके सदस्य बनाये गए थे, जैसे मर तेज बहा प्रिवी परिषद की बैठकें

प्रिवी परिषद की बैठकों में प्रायः बहुत कम सदस्य आयायाही कबल चार या पांच सदस्यों की उपस्थिति में ही मन्त्रिमण्डल के भी सदस्य होते हैं। गणपूर्ति (Quorum) तीन सदस्य ही है। समस्त प्रिवी परिषद में केवल विषय अवसरो पर ही है। समस्त प्रिवी परिषद प्रायः केवल दो अवसरो पर सम्मिलित होती है। लॉर्ड प्रसीडेंट (Lord President) जो अब नेविनट है प्रिवी परिषद की सभाओं का सभापतिवत् करता है। प्रिवी परिषद के वर्तमान कार्य

प्रिवी परिषद के वर्तमान कार्य बहुत मिले जुले हैं तथापि

मन्त्री इस सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि एक मन्त्री अपनी इच्छा से सामान्य नाम करके सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को उसके लिए उत्तरदायी बना दे। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ यह बात निरिक्त है कि यदि कोई मन्त्री ऐसा गलत काम करता है जिसे वारे में मन्त्रिमण्डल ने कोई निणय नहीं लिया है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रि-मंडल असहमत है तो वह सामूहिक उत्तरदायित्व ही जाट लेकर अपना बचाव नहीं कर सकता। ऐसे कार्य के लिए वह स्वयं दंडित होगा कि सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल। उदाहरणार्थ, एटनी मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष मन्त्री ह्यूग (Hugh Dalton) ने एक प्रिय पत्रकार को घड़त की कुछ बातें बतला दी थी जिससे वे मन्त्रिमण्डल में घड़त पैदा होने से पहले ही एक पत्र में प्रकाशित हो गई। यह ह्यूगडाल्टन की व्यक्तिगत भूल थी और उसे मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देना पड़ा। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल पर कोई आघात नहीं आया।

कभी-कभी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का गलत प्रयोग भी होता है। मन्त्रिमण्डल के निणय के अनुसार किए गए किसी कार्य को यदि मन्त्रिमण्डल का समर्थन नहीं मिलता तो मन्त्रिमण्डल सामूहिक त्याग पत्र से बचने के लिए उन कार्य का उत्तरदायित्व मन्त्री विशेष पर डालकर उनसे त्याग पत्र दिला देता है। इस तरह एक मन्त्री को बर्तन का बकरा बनाने पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को बचा लिया जाता है। सन् 1935 में सर सेमुअल होर इसी प्रकार की दुरभिमति का शिकार बना था। इटालियन प्रधानमन्त्री म्याडो के साथ एक गुप्त समझौता मन्त्रिमण्डल के पूर्व-निणय के अनुसार किया गया लेकिन सदन के विरोध करने पर इस समझौते के लिए श्री होर को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा दिया गया। इस प्रकार होर के जलियान द्वारा सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का पतन बचा लिया गया।

सामूहिक उत्तरदायित्व की उदात्तता पर एक दृष्टि—सामूहिक उत्तरदायित्व की यह व्यवस्था कुछ दृष्टियाँ स उपयोगी तथा कुछ दृष्टियाँ से अनुपयोगी दोनों हैं।

इस व्यवस्था की उपयोगिता ये हैं —

(1) मन्त्रिमण्डल में पारस्परिक सहयोग की भावना का उदय होता। वे पारिवारिक गदस्यों की भाँति मिलकर और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। टीम भावना के कारण मन्त्रीगण व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक हितों की बात सोचते हैं।

(2) यह व्यवस्था मन्त्रिमण्डल को शक्ति प्रदान करती है। जब पारस्परिक सहयोग पर आधारित मन्त्रिमण्डल एक स्वर से लोकसभा में कोई विचार या विधेयक प्रस्तुत करता है अथवा राजा को परामर्श देता है तो दोनों ही उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते।

भी भार रहता है। एक मंत्री की आलोचना पूरे मंत्रिमण्डल की आलोचना समझी जाती है और एक मंत्री की प्रशंसा पूरे मंत्रिमण्डल की प्रशंसा। व्यावहारिक दृष्टि से सामूहिक उत्तरदायित्व के कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं, जो ये हैं—

(1) मंत्रिमण्डल एक इकाई के रूप में ही शासन सत्ता सम्भालता है। उसी प्रकार वह एक इकाई के रूप में ही राज्य सत्ता त्यागता है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कोई महत्व नहीं होता। वह मंत्रिमण्डल का अंग होता है और उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कार्य में मंत्रिमण्डल के नियम के अनुसार चले। प्रत्येक मंत्री को सब कार्य इस दृष्टि से करने हाने हैं कि सब कार्यों के लिए सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल उत्तरदायी है।

(2) मंत्रिमण्डल की बैठक में वाद विवाद और विचार-विनिमय की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। मंत्रिमण्डल एक दूसरे के मत का विरोध भी कर सकते हैं, पर यह केवल तभी तक सम्भव है जब तक कि कोई नियम नहीं ले लिया जाता। एक बार नियम हो जाने पर प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह उसे स्वीकार करे और उसे कार्य-रूप देने में अपना सहयोग दे। पूर्णतः असहमत मंत्री के लिए त्याग पत्र देकर मंत्रिमण्डल से अलग हो जाने का माग ही खुला है। मंत्रिमण्डल में विरोधी विचार वालों के लिए प्रायः कोई स्थान नहीं है। ऐसे मंत्री का सहन नहीं किया जा सकता जो मंत्रिमण्डल के नियमों के विरुद्ध हान पर भी त्याग पत्र न दे। यदि कोई मंत्री त्याग पत्र न देने पर अट ही जाए तो प्रधानमंत्री के लिए माग खुला है कि वह अपना त्याग पत्र देकर सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का, सदन का अपन बहुमत के कारण, पुनर्निर्माण कर ले।

(3) यदि किसी मंत्रालय के कार्यों या नीति को लोकसभा अस्वीकृत कर देती है और उस मंत्रालय के वे कार्य मंत्रिमण्डल के नियम पर आधारित होते हैं, तो सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का त्याग-पत्र देना होता है न कि एक मंत्री का। इसका अभिप्राय यह है कि एक मंत्रालय की नीति अथवा उसके कार्य सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के समझे जाते हैं।

इस तरह मंत्रिमण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का सार है—परस्पर अधीनता अथवा सम्मिलित मोर्चा (Solidarity or Common Front)। मंत्रिमण्डल के सब मंत्री या तो साथ साथ ही डूबते हैं या साथ साथ ही तैरते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी मंत्रिमण्डल का पतन होता है तो सारे दल का भी पतन हो जाता है और उसके साथ ही सारे राजनीतिक अधिकारी वगैरह का भी पतन हो जाता है।

उल्लेखनीय है कि यद्यपि मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, प्रत्येक मंत्री का कार्य सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का कार्य समझा जाता है, तथापि

मंत्री इस सिद्धान्त का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि एक मंत्री अपनी इच्छा से मनमाना काम करके सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल को उसके लिए उत्तरदायी बना दे। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ यह बात निहित है कि यदि कोई मंत्री ऐसा गलत काम करता है जिसके बारे में मंत्रि-मंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया है या कोई ऐसा काम करता है जिससे मंत्रि-मंडल अथवा मंसद असहमत है तो वह सामूहिक उत्तरदायित्व की जाड़ लेकर अपना बचाव नहीं कर सकता। ऐसे काम के लिए वह स्वयं दंडित होगा न कि सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल। उदाहरणार्थ, एटनी मंत्रि-मंडल के अध्यक्ष-मंत्री ह्यूग (Hugh Dalton) ने एक प्रिय पत्रकार को बजट की कुछ बातें बतला दी थी जिनसे वे मंसद में बजट पेश होने से पहले ही एक पत्र में प्रकाशित हो गई। यह ह्यूग डाल्टन की व्यक्तिगत भूल थी और उसे मंत्रि-मंडल से त्याग-पत्र देना पड़ा। सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल पर कोई आघात नहीं आई।

कभी-कभी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का गलत प्रयोग भी होता है। मंत्रि-मंडल के निर्णय के अनुसार किए गए किसी कार्य को यदि मंसद का समर्थन नहीं मिलता तो मंत्रि-मंडल सामूहिक त्याग-पत्र से बचने के लिए उस कार्य का उत्तरदायित्व मंत्री विशेष पर टालकर उसमें त्याग-पत्र दिला देता है। इस तरह एक मंत्री को बर्तन का बकरा बनाकर सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल को बचा लिया जाता है। सन् 1935 में सर सेमुअल होर इसी प्रकार की दुरभिमति का शिकार बना था। इटालियन प्रधानमंत्री लावेर के साथ एक गुप्त समझौता मंत्रि-मंडल के पूर्व-निर्णय के अनुसार किया गया लेकिन मंसद के विरोध करने पर इस समझौते के लिए श्री होर को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा दिया गया। इस प्रकार होर के जल्दबाजी द्वारा सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल का पतन बचा लिया गया।

सामूहिक उत्तरदायित्व की उपादेयता पर एक दृष्टि—सामूहिक उत्तरदायित्व की यह व्यवस्था कुछ दृष्टियाँ से उपयोगी तथा कुछ दृष्टियाँ से अनुपयोगी दोनों है।

इस व्यवस्था की उपयोगिताएँ ये हैं —

(i) मंत्रियों में पारस्परिक सहयोग की भावना का उदय होता है। वे पारिवारिक सदस्यों की भाँति मिलकर और एक-दूसरे के रूप में काम करते हैं। टीम भावना के कारण मंत्रीगण व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक हितों की बात सोचते हैं।

(ii) यह व्यवस्था मंत्रिमण्डल को सविन प्रदान करती है। जब पारस्परिक सहयोग पर आधारित मंत्रिमण्डल एक स्तर से लोचसभा में कोई विचार या विधेयक प्रस्तुत करता है अथवा राजा को परामश देता है तो दोनों ही उसकी अपेक्षा नहीं कर पाते।

(110) सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था मंत्रिमण्डल को स्थायित्व प्रदान करती है। सभी मंत्री संसद में अपने अपने समर्थकों को निरंतर अपने प्रभाव में रखे रहने को प्रयत्नशील रहते हैं ताकि मंत्रिमण्डल संसद के बहुमत का निरंतर विद्वांसमाजन रह सके।

सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था कुछ दृष्टियों से अनुपयोगी भी है—

(1) इस व्यवस्था के कारण मंत्रिमण्डल अत्यधिक शक्तिशाली बन कर कभी-कभी तानाशाही के शान्ते पर चलने लगता है।

(2) इस व्यवस्था से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना कमजोर होती है। कुछ मंत्रिगण सामूहिक उत्तरदायित्व की आड़ में स्वेच्छाचारी आचरण करने की ओर अग्रसर होते हैं।

(3) मंत्री अपने स्वतः न निणय अथवा विचार के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। मंत्री यदि नीति को ठीक नहीं समझता तो भी उसे अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध उसी नीति पर चलना पड़ता है।

(4) इस व्यवस्था का दुस्प्रयोग न केवल उन मंत्रियों को दवाने के लिए किया जा सकता है जो मंत्रिमण्डल के बहुमत से सहमत न हों बल्कि इसका दुस्प्रयोग सामूहिक निणय के आधार पर किये हुए कार्य को किसी मंत्री-विशेष का कार्य बतलाकर मंत्री-मण्डल के पतन को बचाने के लिये किया जा सकता है।

(5) सामूहिक शक्ति के कारण मंत्री मण्डल के ऐसे निणय भी राजा व संसद को मानने पड़ सकते हैं जो स्पष्टतः अनुचित अथवा नुतिपूर्ण हों।
गोपनीयता

मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता गोपनीयता (Secrecy) है। ब्रिटिश मंत्रिमण्डल एक गुप्त निकाय है। इसका विचार-विमर्श गुप्त रीति से होता है और इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा रहता है। सावजनिक रूप से मंत्रिगण केवल उन्हीं बातों को प्रकट करते हैं जो मंत्री मण्डल के निणयों के अनुरूप हों।

मंत्रिमण्डल की गोपनीयता की विधि और अभिमन्यो न भी सुरक्षण प्रदान किया है। प्रत्येक मंत्री मण्डलीय मंत्री को प्रिवी परिषद के सम्मुख यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह मंत्री-मण्डल के भेद किसी पर प्रकट नहीं करेगा। इसके लिए 'शासन भेद-अधिनिषेध, 1920' (Official Secrets Act, 1920) यह व्यवस्था देता है कि सरकारी प्रश्नों अथवा अन्य गोपनीय सूचना को अवैध व्यक्ति अथवा व्यक्तिमा पर प्रकट करना दण्डनीय है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महायुद्ध तक मंत्रिमण्डलीय कार्यवाहियों का कोई लेखा (Record) भी नहीं रखा जाता था, केवल मंत्रिमण्डल के निणयों का सक्षिप्त लेखा 1917 से रखा जाने लगा है। मंत्रिमण्डल का यह लेखा (Record)

अत्यन्त गोपनीयता से रक्षित रहता है और उसकी औपचारिक रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती ।

मन्त्रिमण्डलीय 'गोपनीयता' का विशेष महत्व है । इससे राजनीतिक एकमतता (Unanimity) उत्पन्न होती है । गोपनीयता और राजनीतिक एकमतता के कारण मन्त्रिमण्डल में उत्तरदायित्व की भावना का संचार होता है ।

एकता व एकरूपता

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की अंतिम प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें एकता का भाव समस्त मन्त्रिमण्डल का एक सूत्र में बाध रहता है । मन्त्रिमण्डल का दलगत आधार होता है । मन्त्रिमण्डल प्रायः एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं । समान उद्देश्य, विचार और वायव्यम वाले व्यक्तियों की एक समिति होने के कारण मन्त्रिमण्डल में वह राजनीतिक एकता और एकरूपता बनी रहती है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वाह को सम्भव बनाती है । मन्त्रिमण्डल की इस एकता व एकरूपता के कारण ही शासन का वायव्य सुचारु रूप से चलता है और वायव्य मंचालन में एकरूपता बनी रहती है ।

कभी-कभी कुछ विशेष सकटवाली परिस्थितियों में मधुक्न या राष्ट्रीय सरकारों (Coalition or National governments) का भी निर्माण होता है, परन्तु ब्रिटेन में वे लोकप्रिय नहीं हैं । मिश्रित सरकारें सकट समाप्त हो जाते ही भंग हो जाती हैं ।

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की उपयुक्त सभी विशेषताओं का ससदीय शासन-व्यवस्था वाले अन्य देशों में अनुकरण किया गया है, तथापि अन्य देशों में वे उतनी आदर्श रूप में विद्यमान नहीं हैं जितनी कि ब्रिटेन में ।

मन्त्रिमण्डल का गठन अथवा उसका निर्माण

(Composition or Formation of the Cabinet)

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का निर्माण राजा (अथवा रानी) करता है । परन्तु यह केवल औपचारिक है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से इसका निर्माण नहीं कर सकता । सर्वप्रथम राजा प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है और तब उसके परामर्श पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है । प्रधानमन्त्री सामान्यतः लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है । यदि लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं हाता है तो प्रधानमन्त्री पद पर उस व्यक्ति को आसीन किया जाता है जो मधुक्न मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने में समर्थ हो ।

हर नया प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रियों की सूची तैयार करता है, उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राजा आवश्यक परामर्श आदि देने के बाद (यदि वह आवश्यक समझे तो) मर्देव ही इस सूची को स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार मन्त्रियों की नियुक्ति हो जाती है । मन्त्रियों के चयन में कुछ प्रचलित अभिसमयों,

नियमों और व्यवहार की दृष्टि से प्रधानमंत्री को प्रायः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है—

(1) मंत्रियों का चयन अपने ही दल के सदस्यों में से करे।

(11) सब क्षेत्रीय हिता की तुष्टि करने का प्रयास करे।

(111) मंत्रियों का चयन मगद के दोनों सदनों में से करे। वर्तमान नियम यह है कि कम से कम तीन मंत्री लाउसभा से अवश्य लिये जाने चाहिये। लाउसबलर के अतिरिक्त कुछ छोटे मंत्री भी लाउसभा से लिये जाते हैं, क्योंकि परम्परा ऐसी है कि कोई मंत्री केवल उसी सदन में भाषण दे सकता है, जिसका वह सदस्य हो। कुछ मंत्री स्वयं अपने पद के वांछ्य मंत्रिमण्डल के सदस्य बन जाते हैं, जैसे, चांसलर ऑफ दी एक्सचेंजर, लाउ प्रिवीकोल आदि।

मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री दल के प्रभावशाली सदस्यों की प्रायः उपेक्षा नहीं कर पाता। यह स्मरणीय है कि प्रत्येक मंत्री का सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि विशेष कारणवश किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर आसीन कर दिया जाय जो मगद का सदस्य न हो तो यह आवश्यक है कि वह छ मास के अंदर सदन का सदस्य बन जाय।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। आरम्भ में इसमें 7-8 सदस्य होते थे और अब इनकी संख्या 18-20 या इससे भी अधिक होती है। राज्य कार्यों में घटाव बताव होने पर मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है।

सब मंत्रियों का महत्व बराबर एक था नहीं होना है। अतः उनके वेतन भिन्न भिन्न हैं। प्रधानमंत्री को 10,000 पौण्ड वार्षिक मिलते हैं और पद मुक्ति के बाद उसे 2,000 पौण्ड वार्षिक पेंशन दी जाती है। अन्य मंत्रियों का वेतन 5000 पौण्ड और कुछ मंत्रियों व सेक्रेटारियों का वेतन 1,500 पौण्ड से लेकर 3,000 पौण्ड वार्षिक तक है।

मंत्रिमण्डल के विभाग वितरण, प्रधानतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर है कि वह किमको क्या विभाग सौंपता है। एक सदस्य के पास एक से अधिक विभाग भी हो सकते हैं।

मंत्रिमण्डल व मंत्रालय में अंतर

(Distinction between Cabinet and Ministry)

प्रायः लोग मंत्रिमण्डल और मंत्रालय (जिसे कुछ लेखकों ने मंत्रि परिषद भी लिखा है) का एक ही अर्थ लेते हैं, किंतु यह भ्रमात्मक है। मंत्रालय मंत्रिमण्डल का व्यापकतर रूप है। दोनों के कार्यों, संगठन, शक्तियों आदि में बहुत अंतर है। मंत्रालय एक बृहत्त संस्था है जिसमें छोटे बड़े सभी मंत्री रहते हैं। नव निर्वाचित प्रधानमंत्री प्रशासन के संचालन के लिए मसद के 60-70 या इससे भी अधिक सदस्यों की नियुक्ति राजा से कराता है जो सभी सदन के प्रति उत्तरदायी

होते हैं। इन सभी राजपदाधिरारिया के सामूहिक संगठन का मंत्रि परिषद या मन्त्रालय कहा जाता है। किन्तु मन्त्रिमण्डल मन्त्रालय के अलग एक छोटा सा समूह होता है जिसमें निम्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। इस लघु-समूह में प्रायः वे व्यक्ति नियुक्त होते हैं जो मन्त्रालय के वयान्त, प्रभावशाली और अनुभवी नेता होते हैं तथापि कुछ प्रमुख पदों के मंत्री अनिवार्यतः इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे—राष्ट्र चांसलर, लाइ प्रिवीसीट, चांसलर आफ दी एक्स्टचेजर गृहमंत्री, विदेश मंत्री, आदि।

स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रालय का सदस्य होता है, परन्तु मन्त्रालय के कुछ इन्ने गिन सदस्य ही मन्त्रिमण्डल के सदस्य हो सकते हैं। मन्त्रालय की एक समिति के रूप में बैठें नहीं हानी किन्तु मन्त्रिमण्डल मन्त्रालय की वह कार्यकारिणी समिति है जो एक साथ एकत्रित होती है, किसी विषय पर सम्मिलित रूप से विचार करती है और सामूहिक निर्णय देती है, जिसे मन्त्रालय के समस्त सदस्यों को मानना होता है।

दोनों प्रकार के मंत्रियों में वेतन सम्बन्धी अंतर भी होता है। यह अंतर स्वयं मन्त्रिमण्डलीय मंत्रियों में भी होता है और मन्त्रिमण्डलीय मंत्रियों तथा मन्त्रालय के मंत्रियों में भी। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री 10,000 पौण्ड वार्षिक पाते हैं जबकि अन्य मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री 5,000 पौण्ड वार्षिक। मन्त्रालय के साधारण मंत्रियों का वार्षिक 1,500 से 3,000 पौण्ड वार्षिक तक होता है।

दोनों प्रकार के मंत्रियों में कार्य क्षेत्र सम्बन्धी अंतर भी विद्यमान है। मन्त्रिमण्डलीय मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण शासन-विभाग होते हैं। अपने अपने विभागों को सम्भालने के अतिरिक्त उन्हें विविध विभागों के कार्यों में उनकी नीतियों में सामंजस्य बनाने रखना होता है। मन्त्रालय के साधारण मंत्रियों को इन सामंजस्यकारी कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता और न नीति निर्धारण में ही उनका कोई भाग होता है। मन्त्रालय के समस्त मंत्रियों व सदस्यों की सामंजस्य बैठकें तभी होती हैं। उनके ऊपर केवल अपने अपने विभाग से सम्बंधित प्रशासन का दायित्व होता है जिसे वे मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुरूप निभाते हैं। फिर भी सामूहिक उत्तरदायित्व में वे सभी सम्मिलित होते हैं जो मन्त्रालय में किसी भी राजनीतिक पद पर नियुक्त हैं। उन सभी का लोकसभा के समान समान रूप से उत्तरदायित्व है।

मन्त्रिमण्डल की कार्यप्रणाली

(The Working of the Cabinet)

मन्त्रिमण्डल की बैठकें एकांत में होती हैं और उनकी कार्यवाही पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। सरकारी भेद अधिनियम (Official Secrets Act) के अंतर्गत मन्त्रिमण्डल और राज्य के गुप्त पदों का प्रकाशन करना दंडनीय है।

त्याग-पत्र देते समय भी मंत्री राजा की अनुमति से ही त्याग पत्र के कारणों पर प्रकाश डाल सकता है। शांतिकाल में मंत्रिमण्डल की प्रति सप्ताह सामान्यतः दो बैठकें होती हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री इसकी बैठक कभी भी बुला सकता है। मंत्रिमण्डलीय उठको में शासन के नीति सम्प्रदाय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय किया जाता है। किसी प्रश्न या मामले की जांच करने के लिए मंत्रिमण्डल बाह्य आयोग (Royal Commission) की भी नियुक्ति करता है। मंत्रिमण्डल का बहुत सा कार्य विभिन्न समितियों द्वारा होता है जो साधारणतः दो प्रमुख वर्गों की होती हैं—स्थायी समितियाँ (Standing Committees) और तदर्थ समितियाँ (Adhoc Committees)। मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रायः उन मंत्रियों को (जो मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते) भी आमन्त्रित किया जाता है। विभागों से सम्बंधित मामलों पर मंत्रिमण्डल में विचार होता है। ये मंत्री समितियों के सदस्य हो सकते हैं।

मंत्रिमण्डल की बैठकों की कार्यवाही का विस्तृत विवरण नहीं रखा जाता। सारांश रूप में केवल प्रमुख तर्क और अंतिम निर्णय ही लिखे जाते हैं। कार्यवाही का प्रसारण भी बड़ा सीमित रहता है। इस कार्यवाही का उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल के सचिवालय (Cabinet Secretariat) पर होता है।

मंत्रिमण्डल के कार्य और अधिकार

(Functions and Powers of the Cabinet)

ब्रिटिश मंत्रिमण्डल कायों व अधिकारों की दृष्टि से सर्वोच्च नियंत्रक शक्ति है। राज-पद के सब अधिकारों, शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग राजा के नाम से मंत्रिमण्डल ही करता है। पर इतनी शक्तिवान इस संस्था की शक्ति का आधार कानूनी न होकर परम्परागत है। कानूनी दृष्टि से मंत्रिमण्डल राजा की परामर्शदात्री समिति मात्र है जब कि परम्परा अथवा अभिसमयों की दृष्टि से वह वास्तविक कार्यपालिका बन गया है। राजतन्त्र के लोकतन्त्रीकरण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर घटती हुई राजा की शक्तियों का स्थान क्रमशः मंत्रिमण्डल लेता गया है और आज शक्तियों व कार्यों की दृष्टि से व्यावहारिक ब्रिटिश राजनीति तथा प्रशासन में मंत्रिमण्डल सर्वोच्च है।

मंत्रिमण्डल के अधिकारों और कार्यों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं।

- (1) व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य,
- (2) नायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य,
- (3) वित्त सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य।

व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार एवं कार्य

कानून बनाने के सम्बन्ध में समस्त शक्तियाँ व्यवस्थापिका को ही प्राप्त

हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में संसद पर मन्त्रिमण्डल ही नियन्त्रण रखता है। मन्त्रिमण्डल कानून निर्माण में अगुआई करता है और हर कदम पर कानून का स्वरूप निर्धारित एवं नियन्त्रित करता है। मन्त्रिमण्डल सारे कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। विधेयक पेश करना, उसकी व्याख्या करना और उसे पास कराना मन्त्रिमण्डल का ही कार्य है। विधेयक यद्यपि लाह-सभा में भी पेश होते हैं और वे सदस्य भी जा मंत्री नहीं हैं, विधेयक पेश कर सकते हैं, परन्तु अधिवाश और महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रियों द्वारा ही पेश किये जाते हैं। वित्त विधेयक मन्त्रिमण्डल द्वारा ही लोकसभा में पेश किये जाते हैं। जिस विधेयक को मन्त्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त नहीं होता, उसमें कानून बनने की सम्भावना बहुत ही कम होती है।

मन्त्रिमण्डल का ही यह निश्चय करने का अधिकार है कि कब संसद की बैठक बुलाई जाय, कब उसका सत्रावसान किया जाय और कब विघटन किया जाय ? उम भाषण को भी मन्त्रिमण्डल ही तैयार करता है, जिसे राजा संसद का उद्घाटन करते समय देता है और जिसमें आगामी सत्र के लिये शासन की सामान्य नीति व उसके कार्यक्रम आदि का सांकेतिक विवरण होता है। संसद के कार्यक्रम का नियंत्रण भी मन्त्रिमण्डल ही करता है।

कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार और कार्य

मन्त्रिमण्डल मूलरूप से शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है और राजपद में निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग राजा के नाम से करता है। सन् 1918 में 'शासन यन्त्र मिति' (Machinery of Government Committee) के अनुसार कार्यपालक क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल के तीन मुख्य कार्य हैं—

- (i) संसद में उपस्थित की जाने वाली नीति का प्रतिपक्ष निर्धारण,
- (ii) संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियन्त्रण,
- (iii) राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सीमा का निर्धारण करना और उनमें सदा सामंजस्य बनाये रखना।

मन्त्रिमण्डल 'नीति का कुम्भक' है। वह समस्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता है और उन पर निर्णय देता है। मन्त्रिमण्डल के निर्णयों को सम्बन्धित विभाग क्रियान्वित करते हैं। अपने निर्णयों को वैधानिक रूप देने के लिए वह प्रशासनिक विधियाँ और संसदीय विधियों के निर्माण माग चुनता है। मन्त्रिमण्डल विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करता है।

मन्त्रिमण्डल का परम्परागत कार्य संसद द्वारा पारित कानून या विधियाँ को क्रियान्वित करना और प्रशासन का संचालन करना है। ब्रिटेन में समस्त कार्यपालिका शक्ति राजा के हाथ में है, लेकिन यह एक संस्थात्मक सत्य मात्र है। व्यवहारतः वास्तविक कार्यपालिका राजमुकुट है, परन्तु वह कि राजमुकुट (Crown) एक कल्पना है, अतः उसके नाम पर शक्तियों का उपयोग मन्त्रिमण्डल करता है।

मन्त्रीगण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का मंचालन और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्पूर्ण मन्त्रालय को मन्त्रिमण्डल के आदेशों का पालन करना पड़ता है और उसके द्वारा निर्धारित नीतियों व निणयों को क्रियान्वित करना होता है।

मन्त्रिमण्डल, सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, विभिन्न विभागों का एव-सूत्र में बाँधता है और देखता है कि उनके कार्यों में अन्तर्विरोध न हो, वे एक-दूसरे के कार्य-क्षेत्र का अतिगमन न करें और सभी के कार्यों में समन्वय रहे। राजनयिक स्तर पर बड़े-रटे पदाधिकारियों का चयन भी मन्त्रिमण्डल ही करता है। राजा उन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है।

प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) की शक्ति ने मन्त्रिमण्डल के नायपालिका सम्बन्धी अधिकारों को और भी विस्तृत कर दिया है। सदन कानूनों की वेबल मोटी रूपरेखा बना देती है और मन्त्रिमण्डल नियमों व नियमों द्वारा आवश्यक यूनताओं को पूरा करता है। चूँकि इन नियमों व नियमों का निर्माण सदन प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत होता है, एवं उनकी भाव्यता वसी ही जाती है जैसी कि सदन द्वारा निर्मित कानूनों की।

सदन में प्रशासन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं, और मन्त्रिमण्डल व शासन के विविध विभागों की आलोचना की जाती है। इन सबका उत्तर मन्त्रिमण्डल को ही देना पड़ता है। उसे प्रशासन की उन दोषों से भी मुक्त करना होता है जिनके कारण सरकार की आलोचना होती है।

स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल का नायपालक कार्य क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।

वित्त सम्बन्धी अधिकार और बजट

वित्तीय क्षेत्र में भी मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मन्त्रिमण्डल ही राज्य के समस्त व्यय के लिये उत्तरदायी है और उस समस्त व्यय के लिये आवश्यक वित्त जुटाना उसी का काम है। वार्षिक राजकीय बजट (Budget) को प्रस्तुत करना मन्त्रिमण्डल का अधिकार है। बजट निर्माण करते समय वित्तमन्त्री (Chancellor of the Exchequer) केवल प्रधानमन्त्री के आदेशों और मुलाह में अपना लेखा तैयार करता है। वह सम्बन्धी आगामी नीति गुप्त रखने की दृष्टि से बजट मन्त्रिमण्डल में प्रायः नहीं रखा जाता और न उस पर मन्त्रिमण्डल में कोई विचार ही होता है। विविध विभागों के मन्त्री अपने-अपने विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और अपने-अपने विभागों के बजट की आवश्यकताओं को अपनी-अपनी प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर बजट तैयार कर लेता है। बजट का मसदा मन्त्रिमण्डल में प्रस्तुत किये जाने से कुछ दिन पूर्व अख्य मन्त्रियों को इसकी गोपनीयता सूचना मिल जाती है। पर जब बजट मसदा मन्त्रिमण्डल में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो प्रत्येक मन्त्री का अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकताओं और बजट प्रस्तावों का समझना पड़ता है तथा तत्सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर भी देना

पहता है। ससद में बजट प्रस्तावों की आलोचना का उत्तर देना और ससद सदस्यों के बटीनी प्रस्तावों के सरकारी पक्ष में रखा करता मन्त्रिमण्डल का ही कार्य है। मन्त्रिमण्डल बजट को ससद में उपस्थित करने के बाद भी उसमें आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। सभी प्रकार के वित्त विधेयक राजा की सिफारिश पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं।

सरकार के उत्तरदायित्व पर दृष्टि लेने की व्यवस्था भी मन्त्रिमण्डल ही करता है। यह निर्णय करने का अधिकार भी मन्त्रिमण्डल को ही है कि कौन सा व्यय संचित निधि (Consolidated Fund) और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से किया जायगा।

स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल को व्यवस्थापन, पायपालन और वित्तीय सभी क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण तो इसका कार्य और अधिक क्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया है।

मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व

या

मन्त्रिमण्डल और लोकसभा का सम्बन्ध

मन्त्रिमण्डल के कार्यों और उसकी शक्तियाँ को देखने से हमें यह स्पष्ट होता है कि विधि निर्माण और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में मन्त्रिमण्डल प्रधान है। रैम्जो म्योर का विचार है कि इतना व्यापक और विनाशकारी हानि के कारण मन्त्रिमण्डल वास्तव में अधिनायक हो गया है क्योंकि अपने बहुमत के बल पर वह अपने एकमात्र अनुसूचित ससदीय नियंत्रण से भी मुक्त हो गया है। ससद का परम्परागत मिथ्यात है कि वह जनता का आर से जनता के हित में सरकार को सीमित और नियंत्रित कर, परन्तु लोकसभा में बहुमत का मतदान करने के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्ति का इतना बढ़ गई है कि वह ससद की नियंत्रण शक्ति के अधीन नहीं रहा है, अपितु बहुमत के बल पर ससद का मनावच्छिन्न प्रयोग भी करता है। दलीय संगठन और अनुशासन इतना बढोरे एव दृढ़ होता है कि ससद के सदस्यगण सचेतकों (Whips) की आज्ञा करने का साहस प्रायः नहीं करते। इस प्रकार ससद मन्त्रिमण्डल के प्रस्तावों का बहुधा यथावत समर्थन करने के लिए विवश रहती है।

मन्त्रिमण्डल की व्यापक शक्तियों का सही मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब कि लोकसभा के साथ उससे सम्बन्धों पर बानूनी जयवा मायिवातिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से अलग-अलग विचार किया जाय। बानूनी दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में डायसी (Dicey) प्रमुख है, तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करने वालों में रैम्जो म्योर (Ramsay Muir) एण लास्की (Laski) उल्लेखनीय हैं।

नियन्त्रित एवं मर्यादित करती है। समद प्रश्नों, मन्त्रिमण्डलीय नीति की आलोचना या अस्वीकृति, कटौती प्रस्ताव, कार्य-स्थगित प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि द्वारा मन्त्रिमण्डल पर अपना अकुशल रखती है।

स्पष्ट है कि विधि निमाण, वित्त व्यवस्था तथा प्रशासन पर नियन्त्रण करना ब्रिटिश मसद् का मुख्य अधिकार क्षेत्र है और कानूनी दृष्टि से ससद् सर्वोच्च सत्तावान है। मन्त्रिमण्डल अपनी नीतियाँ एवं कार्यों के लिये ससद् के समर्थन पर आश्रित है और अपने जीवन के लिये समदीय बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। यही मसदीय प्रभुता का सिद्धान्त है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण और ससद् की महत्ता

परन्तु लोकसभा और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध पर यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाय, तो स्थिति पूर्णतः भिन्न है। समद और मन्त्रिमण्डल का उपयुक्त परस्परगत सम्बन्ध फलट गया है और अब समद मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण नहीं करती अपितु मन्त्रिमण्डल ससद् का नियन्त्रण करता है। मन्त्रिमण्डल की यह महत्ता निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट है—

(1) **व्यवस्थापन क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल**—इस क्षेत्र में व्यावहारिक स्थिति यह है कि जो भी प्रमुख कानून पारित किये जाते हैं, उनका प्रारूप मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है। मसद् द्वारा प्रायः उन्हें उसी रूप में पारित कर दिया जाता है जिस रूप में वे मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किए जाते हैं। उनमें संशोधन भी केवल तभी हो पाते हैं जब वे मन्त्रिमण्डल को मान्य होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, अतः लोकसभा मन्त्रिमण्डल की इच्छानुसार विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर देती है। वास्तव में दलीय संगठन और अनुशासन इतना कड़ा है कि मसद् के सदस्य अपने दलीय नेताओं का विरोध करने, उनके आदेशों के विरुद्ध आलोचना अथवा मतदान करने का साहस भी नहीं करते। अतः मन्त्रिमण्डल जो कि बहुमत दल के प्रमुख नेताओं का ही मण्डल मान है, अपने दलीय सदस्यों के समर्थन के आधार पर अपनी नीति व अपने कार्यों के लिए मसदीय स्वीकृति प्राप्त कर सकने में पूर्ण विश्वास और निश्चितता रखता है। गैर-सरकारी विधेयक तभी मसद् की स्वीकृति प्राप्त कर पाते हैं, जब उन पर मन्त्रिमण्डल की कृपा-दृष्टि हो। मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध विरोधी पक्ष का किसी भी प्रस्ताव को पास करा लेना या समाप्त कर देना एकदम कठिन है।

(2) **कार्यपालन क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल**—कार्यपालन क्षेत्र में भी व्यावहारिक रूप से मसद् की अपेक्षा मन्त्रिमण्डल की ही उच्चतर स्थिति है। नीति निर्धारण का वास्तविक काम मन्त्रिमण्डल ही करता है और वही अपने बहुमत के दल पर मसद् से उसे स्वीकृत कराता है। मन्त्रिमण्डल समद का कार्यक्रम और उसकी कार्यप्रवृत्ति को निर्धारित करता है। वही यह नियम करता है कि ससद् का अधिवेशन कब होगा, क्या-क्या काम उसमें होगा, कितना समय किस काम के लिए दिया

जायगा और गमद के गम का अवमान व उसका विघटन बच होगा ? इससे अतिरिक्त लोकसभा का अधिकार गमम मन्त्रिमण्डल हटाने जाता है । परन्तुकारी सदस्यों का विधि प्रस्ताव पर विवाद का पूरा बचसर ही नहीं हो पाता ।

यदि लोकसभा अविश्वाम प्रस्ताव या अन्य किसी साधन द्वारा मन्त्रिमण्डल का जीवनलीला समाप्त कर सकती है तो मन्त्रिमण्डल को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा का विघटन कराके उसके संस्था को पुनर्निर्वाचन की दशा का भित्तारी बनादे । लोकसभा द्वारा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वाम का प्रस्ताव पारित कर देने पर भी यह मन्त्रिमण्डल की इच्छा पर निर्भर है कि वह त्यागपत्र का मार्ग चुनता है अथवा नए निर्वाचन करा कर जनमत जानने के लिए रास्ता से वह कर लोकसभा को भग करवाने का रास्ता अपनाता है । स्पष्ट है कि लोकसभा अपना जीवन बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग में, प्रायः मन्त्रिमण्डल के पतन की सीमा तक नहीं मोचती ।

(3) वित्तीय क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल—इस क्षेत्र में व्यावहारिक दृष्टि से मन्त्रिमण्डल ही वज्रत तैयार करता है, उसे पारित करवाना है और तब उसे लागू करता है । राज्य की सम्पूर्ण आर्थिक नीति का मंचालन मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है । मन्त्रिमण्डल ही राज्य की व्यवस्था का विचारण करता है, राजकीय आय के व्यय का निश्चय करता है । लोकसभा वित्त विधेयकों की जांचोचना कर सकती है किंतु वह मद का खर्च बढ़ा नहीं सकती और न कोई नया कर जमान सकती है । वह नए करो का सुझाव भी नहीं दे सकती, केवल प्रस्तावित करो में कमी कर सकती है, लेकिन वह भी एंडी छोटी का जोर लगा कर ही बयोजि जायजता का बहुमत मन्त्रिमण्डल का समर्थक होता है ।

प्रकट है कि व्यवहार में मन्त्रिमण्डल ही लोकसभा का स्वामी बन गया है । विरोधी दल मन्त्रिमण्डल की सुलझ जांचोचना करता है, परन्तु मन्त्रिमण्डल यह भली प्रकार जानता है कि जब लोकसभा न बहुमत उसका समर्थक है, तब उससे प्रस्ताव निश्चित रूप से पारित होते रहेगे ।

राष्ट्री का निष्पक्ष

राष्ट्री का निष्पक्ष है कि व्यवहार में मन्त्रिमण्डल की शक्ति समझ में अधिक अवश्य है, पर वह अधिनायक की तरह परमसत्तावान नहीं है । उमन इस मत का घण्टन किया है कि मन्त्रिमण्डल का लोकसभा के अधिकारों का अपहरण करके उसे अपने अधीनस्थ कर लिया है और वह स्वयं निरुत्तम हो गया है । राक्षसी का कहना है कि मसदोय प्रणाली की लक्ष्यता इसी में है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा लोकसभा का नियंत्रण हो, क्याकि सत्त नियंत्रण का उद्देश्य एक समानुगत कायधन को लागू करना और उसके लिये सविधान के अनुसार गमद की सहमति प्राप्त करना है । राक्षसी के अनुसार गमद में सहमति प्राप्त की मन्त्रिमण्डलीय योजना पर ही सम्पूर्ण गमनतंत्र की सफलता निर्भर है । यह सहमति प्राप्त करना एक

नष्टि पाय है। असद के भीतर और बाहर होने वाली आलोचनाओं के बावजूद, अपने मसौदों की अपन प्रति निष्ठा बनाये रखना एक महत्वपूर्ण और निरंकुश कार्य है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल को प्रत्येक नीति और प्रस्ताव के बारे में पूर्ण जागरूक रहना पड़ता है। चूंकि जरासी भी असावधानी उसके बहुमत का हिला सकती है। बहुमत का बनाये रखना कोई साधारण और सरल कार्य नहीं है। मंत्रिमंडल लोकसभा को बड़े मनोवैज्ञानिक एवं चातुर्यपूर्ण ढंग से संचालित करता है। मंत्रिमंडलीय जीवन के लिए लोकसभा का कठोरता से संचालन खतरनाक है। अत्यधिक एवं अनावश्यक गोपनीयता, त्यागपत्र अथवा विघटन की बारम्बार धमकी, क्रुद्ध लोकमत की उपेक्षा आदि ऐसी बातें हैं जो सर्वत्र विद्रोह पैदा करती हैं। मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रण निरकुशता के ढंग पर नहीं हो सकता। लोकसभा मंत्रिमंडल के निर्देशन को तभी तक सहन करती है जब तक वह उसके (लोकसभा के) द्वारा समर्थित नीति के विरुद्ध नहीं जाता। मंत्रिमंडल को यह समझना चाहिए कि सब झुकना उचित है और सब नहीं, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दान के साथ झुकना ही महत्वपूर्ण है। निरंकुश आचरण करने वाला और अपनी नीति का स्वेच्छाचारी रूप में लागू करने की इच्छा रखने वाला मंत्रिमंडल पतनोन्मुख होता है।

मंत्रिमंडल की शक्ति में प्रसार के कारण

(Reasons of Growing Importance of the Cabinet)

मंत्रिमंडल और लोकसभा के सम्बन्धों के कानूनी और व्यावहारिक रूप में इतना विशाल अंतर देखने पर, स्वभावतः यह प्रश्न सस्तिष्क में उठता है कि मंत्रिमंडल की इस सर्वव्यापकता अथवा महत्ता या शक्ति में प्रसार के कारण क्या हैं। यदि इसके कारणों पर विचार किया जाय तो यह सिद्ध होगा कि यह प्रसार अनिवार्य है। मंत्रिमंडल की महत्ता या शक्ति-प्रसार के कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

1 दल प्रणाली—मंत्रिमंडल की शक्ति में प्रसार का सबसे प्रमुख कारण ब्रिटेन की दल प्रणाली है। ब्रिटेन में प्रधानतः दो दल ही राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, और उनमें से स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाला दल अपना मंत्रिमंडल बनाता है। तीसरा दल यदि कोई होता भी है तो देश की राजनीति में उसकी कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं होती। लोकसभा के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल को अपने कार्यों के लिये लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त होती है। यदि ब्रिटेन में दो दलों की प्रमुखता न होकर फ्रांस की भांति अनेक दलों की प्रमुखता होती तो वहाँ के मंत्रिमंडल की दशा भी फ्रांस के मंत्रिमंडल जैसी होती। तब शक्ति के लिये विविध दल परस्पर खींचतान करते रहते, मंत्रिमंडल को स्थायित्व नहीं मिल पाता और न ही आज के समान महत्व और शक्ति का वह स्वामी होता।

2 **दलीय अनुशासन**—ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की महत्ता का दूसरा कारण दलीय अनुशासन है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई सदस्य अपने दल के विरुद्ध मत नहीं दे सकता और न ही दल की नीति और उसके कार्यों को अपना समय देने से मना कर सकता है। दलीय अनुशासन के कारण सदस्य स्वच्छापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सदस्य दल के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि इसका परिणाम दल से बहिष्कार और अन्ततः राजनीतिक आत्मघात भी होता है। स्पष्ट है कि चुनाव के समय जब कोई दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उसका वह बहुमत सरलता से टूट नहीं होता। परिणामतः मंत्रिमण्डल पूर्ण विश्वास के साथ अपने नियोजित कार्यक्रम पर चलता रहता है। अनुशासनबद्ध बहुमत का स्वाभाविक ब्रिटिश मंत्रिमण्डल को इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि वह लोकसभा पर छाया रहता है।

3 **प्रशासनिक समस्याओं की जटिलता**—ब्रिटिश मंत्रिमण्डल को जटिल प्रशासनिक समस्याएँ भी शक्ति प्रदान करती हैं। लोक-स्वायत्तकारी राज्य के विचार के प्रादुर्भाव के कारण प्रशासकीय समस्याएँ अत्यन्त व्यापक और जटिल हो गई हैं। सदस्य के सामान्य सदस्य इन योग्य नहीं होते कि वे इन समस्याओं को भली प्रकार समझ सकें और राजनीतिक प्रशासनिक, आर्थिक एवं तकनीकी मामलों में मंत्रिमण्डल का मार्ग निर्देशन कर सकें। इस असमर्थता का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि लोकसभा इन विभिन्न समस्याओं की जानकारी के लिए मंत्रिमण्डल पर ही अधिवास्तुतः निर्भर रहती है और इन प्रकार मंत्रिमण्डल की महत्ता बढ़ गई है।

4 **कार्यभार की अधिकता**—काम की अधिकता के कारण भी लोकसभा को प्राप्त होने वाली महत्ता मंत्रिमण्डल का प्राप्त हो जाती है। लोकसभा का कार्य इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं इनका निपटारा तिरौटगण अथवा संघात्मक करने में असमर्थ है। मंत्रिमण्डल द्वारा जो विषय और काम लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें प्रथम तो सभी संसद्-सदस्य अच्छी तरह समझ भी हो असमर्थ हैं। और दूसरे उन सब विषयों पर भली प्रकार विचार करना भी समय ही नहीं मिलता। यह परिणाम यह निकला है कि मंत्रिमण्डल के अधिकांश विषयों को लोकसभा द्वारा किसी विशेष कठिनाई या वाद विवाद के स्वीकार कर ली है। इन प्रकार मंत्रिमण्डल के नियम ही लोकसभा के नियम हो जाते हैं। विधियाँ का प्रारम्भ होता करता, उन्हें संसद् में प्रस्तुत करता और संसद् में स्वीकृत करवाता मंत्रिमण्डल का ही कार्य हो गया है। कार्यभार की अधिकता के कारण ही प्रत्यक्ष अधिनियम (Delegated Legislation) व्यवस्था प्रचलित हो गई है, जिससे विधि निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमण्डल बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गया है।

5 **मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व**—मंत्रिमण्डल का उत्तरदायित्व व्यवस्था के मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व का भी अंग है। इन विचारों के

अतः एक मंत्री की पराजय का अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रिमंडल का पतन होता है, अतः सभी मन्त्रिगण टीम भावना से कार्य करते हैं। मन्त्रिमंडल एक बहुत ही दृढ़ छोटा सा निकाय बन जाता है जो अमंगलित और विभिन्न दलों से निमित्त ससद् की तुलना में विशेष शक्तिशाली बना रहता है। संगठन की दृढ़ता शक्ति की स्रोतक है।

6 लोकसभा के विघटन की व्यवस्था—ब्रिटिश मन्त्रिमंडल आवश्यकता पड़ने पर राजा द्वारा लोकसभा का विघटन कराने का अधिकार रखता है। ब्रिटेन में यह एक साविधानिक अभिसमय है कि जब कोई मन्त्रिमण्डल लोकसभा में पराजित हो जाता है, तो उसे तुरन्त पद-त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि यदि वह यह अनुभव करे कि मन्त्रिमण्डल की नीतियों और कार्यों को राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह राजा से लोकसभा को भंग करने की प्रार्थना कर सकता है और राजा उसकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकता। यदि नए निर्वाचन में मन्त्रिमंडल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे पद-त्याग की आवश्यकता नहीं होती। स्पष्ट है कि यदि लोकसभा मन्त्रिमंडल को पद-त्यागने के लिए विवश करने का अधिकार रखती है तो मन्त्रिमंडल को भी लोकसभा को भंग कराकर सदस्य को पुनः निर्वाचन की दया का भित्तारी बना देने का अधिकार है। अतः लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचन की अनिश्चितता से बचन के लिए प्रायः मन्त्रिमंडल का समर्थन करते रहते हैं।

7 लाइसभा के अधिकारों की कटौती—मन्त्रिमण्डल की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि, लाइसभा अब लगभग शक्तिहीन सदन बना दिया गया है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के पारित होने के बाद लाइसभा ससद् का दूसरा सदन नहीं रहा अपितु दूसरे दर्जे का सदन हो गया। इन अधिनियमों के कारण अब लाइसभा मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को पारित होने से नहीं रोक सकती है। उनके पारित होने में केवल कुछ देर लगा सकती है और उसकी आलोचना कर सकती है। इस तरह मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व अब केवल एक ऐसे सदन (लोकसभा) के प्रति ही रह गया है, जो उसके ही दल के बहुमत के कारण उसका अपाता होता है।

8 संसदीय कार्य विधि—मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि का एक कारण ससद् की कार्य विधि (Procedure) है। संसदीय कार्यवाहियों के नियमों द्वारा ससद् सदस्यों के हाथ बंधे रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रहता है। मन्त्रिमण्डल वाद विवाद को समाप्त करवा सकता है अथवा उसे सीमित कर सकता है। सामान्य समापन (Simple Closure) द्वारा पर्याप्त वाद विवाद हो चुकने पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। गुल्लोतीन (Guillotine) के अनुसार विधेयक को बनेबने भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग के लिए समय निर्दिष्ट कर दिया जाता है। कंगारू समापन (Kangaroo Closure) के द्वारा समापन कुछ मसौदों

पर वाद विवाद की आज्ञा ही नहीं देता। इन उपायों के अतिरिक्त दल सचेतक (Party Whips) मसद-सदस्यों की रतनता पर पूरा नियन्त्रण रखता है। इन मसदीय कार्य विधियों का अंतिम परिणाम मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि है।

■ **संसदीय जीवन की स्थिति**—संसदीय जीवन की स्थिति भी मन्त्रिमण्डल की शक्ति में वृद्धि का कारण है। प्रायः संसद के अवकाशकाल में सदस्यों को पता नहीं रहता कि मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें केवल समाचार-पत्रों के माध्यम से ही कुछ बातों का पता चलता रहता है। संसद सदस्यों की यह बेसवरी की अवस्था मंत्रियों को प्रभावपूर्ण बनाने में बड़ी सहायक होती है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल सन्त से अधिक शक्तिशाली अवश्य है, किन्तु अधिनायक नहीं है। मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व साविधानिक है, निरंकुश नहीं, उत्तरदायी है, स्वेच्छाचारी नहीं। मन्त्रिमण्डल बहुमत के मद में घूर होकर विरोधी दल या जनमत की अवहलना नहीं कर सकता। संसद की प्रचलित प्रथाएँ भी बहुमत दल के शासन को अधिनायकवादी होने से बचाती हैं। विरोधी दल को शासक दल पर अंकुश रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न साधनों और संसद मन्त्रिमण्डल को उसकी गलती के प्रति सजग रखती है। सामान्यतः मन्त्रीगण संसद के सम्मुख झूठ बोलना अनैतिक समझते हैं। अतः वे, मन्त्रिमण्डल जनमत पर टिका रहता है। सरकार जनता की इच्छा को व्यावहारिक रूप देने का साधन है। अतः प्रत्येक मन्त्रिमण्डल यह ध्यान रखता है कि उसे भविष्य में अपने कारनामों का हिमायत चुकाना पड़ेगा। इंग्लैण्ड में यह एक मान्य सिद्धांत है कि शासन प्रजा की सम्मति से ही सम्भव हो सकता है।

है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसके प्रतिद्वंद्वी उसका स्थान ग्रहण कर सकते हैं।

प्रधानमन्त्री पद की औपचारिकता

ब्रिटेन की अल्प संख्याओं की नाति प्रधानमन्त्री का पद भी औपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधानमन्त्री पद की उत्पत्ति परम्परा अथवा निरुद्धि द्वारा हुई है। सन् 1878 से पहले प्रधान मन्त्री पद का नाम भी किसी सरकारी प्रपत्र में नहीं आया था। 1937 के 'क्राउन मन्त्री अधिनियम' (The Minister of the Crown Act, 1937) में पहली बार कानूनी रूप में प्रधान मन्त्री के पद को मान्यता प्रदान की। इसमें 'प्रधान मन्त्री व सरकारी काम के प्रथम लाड' के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए 10 हजार पौण्ड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। इस अधिनियम से प्रधान मन्त्री की केवल सांविधानिक स्थिति को मान्यता मिली, उस वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की गयी। आज भी यही स्थिति बतमान है, अर्थात् प्रधानमन्त्री पद के अधिकारों और उसकी शक्तियों का कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधान मन्त्री को सभी अधिकार सांविधानिक अभिसमया से मिले हुए हैं और उन्हीं अभिसमया से वे मर्यादित भी हैं।

उल्लेखनीय है कि 1937 के 'क्राउन मन्त्री अधिनियम' में 'विरोधी पक्ष के नेता' को भी मान्यता प्रदान की गयी और उसके लिए 2000 पौण्ड वार्षिक वेतन स्वीकार किया गया। अक्टूबर, 1964 के एक संशोधन के अनुपालन में अब प्रधान मन्त्री का वेतन 14 हजार पौण्ड तथा विरोधी पक्ष के नेता का वेतन 4,500 पौण्ड वार्षिक है।

प्रधान मन्त्री की नियुक्ति

(The Choice of the Prime Minister)

संविधानगत प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राजा द्वारा होती है। लेकिन वर्तमान सरकार के विकास ने यह परम्परा स्थापित कर दी है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधान मन्त्री या तथा मंत्रिमण्डल का निर्माण करे। इस प्रकार प्रधान मन्त्री के चुनाव में राजा की शक्ति नगण्य हो गई है। फिर भी कुछ परिस्थितिमा है, जिनका राजा स्व निणय (Discretion) के अनुसार काम कर सकता है। ऐसी दशाएँ मुख्यतः तीन हो सकती हैं—

1 जब लोकसभा में दो स अधिक दल हों और उनमें से किसी को भी सार्ध स अधिक मत अर्थात् स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। इस स्थिति में राजा का कर्तव्य है कि यह ऐसे व्यक्ति को पद भार सम्भालने हेतु आमन्त्रित कर जो लोकसभा का बहुमत अपनी सरकार के लिए प्राप्त करने में सफल हो।

2 जब बहुमत दल का नेता स्पष्ट न हो। यह स्थिति तब पैदा हो सकती

है जब एक प्रधानमन्त्री अचानक त्यागपत्र दे दे या मृत्यु को प्राप्त हो जाय और आंतरिक द्वन्द्व के कारण दल अपना नेता चुनने में असमर्थ हो।

3 जब मसद् में दलीय स्थिति अथवा देश की परिस्थितिवश एक मिश्रित मन्त्रिमण्डल का बनाया जाना आवश्यक हो, परन्तु प्रधानमन्त्री के सम्बन्ध में विभिन्न दलों में मतैक्य न हो। गेम्बरी ने लिखा है कि “जब 1931 में श्री मैकडॉनल्ड ने पद त्याग किया तो उनसे तथा विरोधी दलीय नेताओं से राजा का व्यक्तिगत अनुरोध ही उनको मिश्रित सरकार के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित कर सका।”

उल्लेखनीय है कि प्रधानमन्त्री पद के सम्बन्ध में अब यह सन्माय धारणा हो गई है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा में ही चुना जाए, हालांकि प्रथागत नियम यही है कि प्रधानमन्त्री या तो बोर्ड पीयर (Peer) हो अथवा लोकसभा का सदस्य हो। वास्तव में 1902 के बाद से ही कोई प्रधानमन्त्री लाइ-सभा की सदस्यता में से नहीं चुना गया है। अक्टूबर, 1963 में जब लार्ड ह्यूम को प्रधानमन्त्री बनाया गया तो स्पष्ट कर दिया गया कि उन्हें अपनी उपाधिया का परित्याग कर देना होगा। लार्ड ह्यूम ने अपनी उपाधि त्यागने और लोकसभा के लिए उप चुनाव लड़ने के निश्चय की घोषणा की। चुनाव 7 नवम्बर को हुए जिनमें ह्यूम विजयी घोषित किया गया। प्रधानमन्त्री को लोकसभा का सदस्य ही होना इसलिए आवश्यक माना जाता है कि वह तथा उनका मन्त्रिमण्डल केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। दलीय संगठन की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा में से ही चुना जाए।

प्रधानमन्त्री पद के लिए योग्यताएँ

यद्यपि नियमत प्रधानमन्त्री पद के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसने लिए कुछ योग्यताओं और व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। प्रथम तो सांविधानिक प्रथाओं में ही यह आवश्यक बना दिया है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो अथवा लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में समर्थ हो। द्वितीय, उसे विभिन्न व्यक्तिगत गुणों का धनी होना चाहिए। एलासी ने प्रधानमन्त्री के गुणों का विशद वर्णन इस प्रकार किया है—“विवेक की भाँति, मनुष्या पर शासन करने की शक्ति, विश्वसनीय व्यक्तिगत पहचान, प्रभावशाली बक्तव्य देने की क्षमता, ऐसा शिशात्मक नियम ले सके कि वह दल तथा लोकमत से जागे तो अवश्य हो लेकिन इतना न हो कि उसका सुगमनापूर्वक पालन न हो सके, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो बागे तो बढ़ाए पर साथ ही आकस्मिकता के प्रदर्शन में सजग हो, व्यक्तियों या पापों के बारे में तत्कालीन नियम के समय मर्यादित व्यग्रता—ये सब ऐसे गुण हैं जिनके बिना प्रधानमन्त्री का काम नहीं चल सकता।”

वस्तुतः ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पद तक पहुँचने का मार्ग बड़ा जटिल है। काटर ने लिखा है कि—“सर्वप्रथम लोकसभा में व्यक्ति को राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित प्राप्त करनी होती है। मन्त्रिमण्डल की सदस्यता और फिर सम्भवतः प्रधानमन्त्री पद की आकांक्षा साधारणतः व्यक्ति अनेक पदा पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राप्त कर सकता है।”

प्रधानमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य

(Powers and Functions of the Prime Minister)

जैसा कि कहा जा चुका है प्रधानमन्त्री वास्तविक रूप में, अध्यात्मिक रूप में नहीं, राज्य का प्रधान है। उसके गमान विद्याल सत्ता सत्सार में सम्भवन किसी वैधानिक प्रधान का प्राप्त नहीं है। जब तक उसके दल का मसद में बहुमत रहता है, वह अनेक ऐसे काम कर सकता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह पहले से ही इस बात का उचन द सकता है कि उक्त संधि पर हस्ताक्षर हो जायेंगे या उसका अनुमोदन हो जायगा, या कोई विशेष विधान पारित हो जायगा, या किसी भी धन राशि के व्यय की मसद् द्वारा स्वीकृति मिल जायगी। प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण शासन सून का केन्द्र है। उसकी व्यापक शक्तिशा और उसके अधिकारों व कर्तव्यों का विवेचन हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं—

प्रधानमन्त्री का मन्त्रिमण्डल

प्रधानमन्त्री ही मन्त्रिमण्डल के निमाण, जीवन तथा मरण का केन्द्र स्थल है और उसका प्रभावशाली संचालन उसी पर निर्भर करता है।

मन्त्रिमण्डल का निर्माण—प्रधानमन्त्री पद की बागदोर सम्भालने के बाद उसका पहला कर्तव्य होता है—मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना। इसके लिए वह सदस्यों की सूची तैयार करता है, जिस राजा विधिवत स्वीकार कर लेता है। राजा द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति करना केवल एक औपचारिकता मात्र है। कौन व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में लिया जायगा, कौन मन्त्रिपद पर नियुक्त किया जायगा, इसका निर्णय प्रधानमन्त्री ही करता है। इस नियम में दलीय एकता एवं सुदृढ़ता, राजा की इच्छा, सांविधानिक अनिश्चय, राजनीतिक स्थिति आदि विचार तत्त्व प्रभावशाली होते हैं, परन्तु अंतिम निश्चय करना प्रधानमन्त्री का अधिकार है। यदि वह किसी व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करना चाहता है तो राजा राज नहीं सकता और यदि वह किसी व्यक्ति को सम्मिलित करना नहीं चाहता है तो राजा उसे दिवंग नहीं कर सकता।

फिर भी मन्त्रियों के चयन में प्रधानमन्त्री मनमाना नहीं कर पाता। उस यह देखना पड़ता है कि उससे दल के प्रमुख सदस्य मन्त्रिमण्डल में जा जायें क्योंकि ऐसा न होने पर दल के भीतर फूट पड़ सकती है और उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। यही नहीं तो उसे ऐसे व्यक्तियों का भी मन्त्रिमण्डल भरना पड़ता है जिनसे वह नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें नहीं रगने से शासन सचट में पड़ सकता है।

कभी कभी उन राज्यों की शक्तों पर भी घटना पड़ता है और उन्हें उनकी इच्छा का विभाग देना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यथाम्भव वे ही लोग उसमें आयें जो परस्पर सहयोग की भावना से काय कर सकते हों। प्रधानमन्त्री को अपने सहयोगियों के चयन में विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, नवयुवक राजनीतिज्ञों आदि के प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखना पड़ता है। राजा की इच्छा पर भी, चाहे सौजन्य के कारण ही सही, प्रधानमन्त्री को उचित ध्यान देना होता है।

मन्त्रिमण्डल का सञ्चालन—प्रधानमन्त्री न केवल मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है बल्कि उसे जीवन और गति भी देना है। वही अपने मन्त्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। फिर भी कुछ सदस्य इतने प्रभावशाली और सक्षम हो सकते हैं कि विभाग वितरण करते समय प्रधानमन्त्री उनकी इच्छा का आदर करें। परन्तु साधारणतः विभागों के वितरण के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री का निष्पक्ष अन्तिम होता है।

प्रधानमन्त्री को यह भी देखा पड़ता है कि मन्त्रिमण्डल का काय सुचारु रूप से चलता रहे। समस्त प्रशासन का मुखिया होने के नाते वह सभी विभागों का निरीक्षण करता है। कभी कभी मन्त्रियों में परस्पर मतभेद उठ खड़े होते हैं, तब प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप करके औचित्य अनौचित्य के निष्पक्ष द्वारा उनके मतभेदों को दूर करता है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलीय जीवन को सहयोग एवं सहोद्दयपूर्ण बनाये रखने का उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री पर ही है। वही सबको एक सूत्र में पिरोये रखता है।

प्रधानमन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की बैठकों का समापनित्व और उनकी समस्त कार्यवाहियाँ का सञ्चालन करता है। मन्त्रिमण्डल की कार्यविधि (Agenda) पर उसका नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल के निर्णयों और नीति निर्धारण में प्रधानमन्त्री का ही सर्वोपरि हाथ रहता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य वाद विवाद के लिए जो भी विषय विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें मानने या न मानने की उसे स्वतन्त्रता होती है।

परन्तु यह स्मरणीय है कि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रियों का अधिनायक नहीं है। अथवा मन्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय वह इस ध्यान का ध्यान रखता है कि वह उनके साथ अनुचित व्यवहार करेगा या उन पर अनुचित दबाव डालेगा तो उसकी अपनी दृग्गत स्थिति बिगड़ सकती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रधानमन्त्री के दास या अधीनस्थ नहीं होते वरन् वे उसके सहयोगी होते हैं। उनका वह अपने विचारों को मानने के लिए फुमला सकता है किन्तु विवश नहीं कर सकता। इस रूप में उसकी स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति की स्थिति से पूर्ण रूप से भिन्न है। वह अपने सहयोगी मन्त्रियों की राय की कभी भी पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता। हा, यह अवश्य है कि उसकी स्थिति अथवा मन्त्रियों की कुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली

होती है और वह मन्त्रियों से अपने विचारों को मनवा ही लेता है। व्यवहार में पहल उसी की रहती है और मन्त्रीगण बहुधा उसका अनुसरण करते हैं।

मन्त्रीमण्डल का अन्तः—प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का सिर्फ निर्माता एवं पालनकर्ता ही नहीं है, बल्कि महारकर्ता भी है। मन्त्रियों के मन्त्रित्व की समाप्ति तथा मन्त्रिमण्डल के भंग करने के विषय में उसकी इच्छा का वस्तुतः पर्याप्त महत्व है। मन्त्री मन्त्रियों का अधिपति उसी के नाथ बचा हुआ है। प्रधानमन्त्री के साथ ही अन्य मन्त्री भी चलते या दबते हैं। उसके त्यागपत्र के साथ पूरा मन्त्रीमण्डल भंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमन्त्री के साथ किसी मन्त्री के मध्य कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमन्त्री उस असंतुष्ट मन्त्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है, या स्वयं अपना त्यागपत्र देकर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का विघटित कर सकता है। किसी भी मन्त्री का प्रधानमन्त्री से मतभेद होने पर मन्त्रिपद से हट जाना आवश्यक है अथवा वह मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व से उम्बर नहीं हो सकता। प्रधानमन्त्री एक नहीं बल्कि अनेक मन्त्रियों का एक साथ पद भूक्त होने के लिए वाध्य कर सकता है जैसा कि 1962 में प्रधानमन्त्री मैकमिलन ने किया था। वैधानिक रूप से मन्त्रियों को पदच्युत का अधिकार राजा या बिदोपाधिकार है, लेकिन व्यवहार में यह परम्परा बन गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमन्त्री की मजबूती पर ही निर्भर है। इस प्रकार मन्त्रियों की पदच्युति का अधिकार प्रधानमन्त्री का ही अधिकार बन गया है।

स्मरणीय है कि प्रधानमन्त्री अपनी स्थिति का अनुचित प्रयोग प्रायः नहीं करता और अकारण ही किसी मन्त्री को पदत्याग के लिए बाध्य नहीं करता क्योंकि उसे अपनी दलील स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। वह उसे किसी भी कार्य में बचने की कोशिश करता है जिसमें स्थिति बिगड़ने का जो संशय हो।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के निर्माण, जीवन और मरण का केन्द्र बिन्दु है। वह मन्त्रिमण्डल की मेहराब की आधारशिला है, परन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह मन्त्रिमण्डल का मानिक नहीं है। मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य उसके नीकर नहीं, बल्कि सहयोगी हैं।

शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमन्त्री

सिद्धांततः देश का शासन प्रमुख राजा है, पर व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। प्रधानमन्त्री ही राजा के नाम पर देश का पूरा शासन संचालित करता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ या तो प्रधानमन्त्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या राजा द्वारा उसके परामर्श से की जाती हैं। राजकीय सम्मानों के प्रदान कराने के अधिकार का प्रयोग भी राजा प्रधानमन्त्री के परामर्श पर ही करता है। प्रशासकीय विभागों का संचालन उसी की देखरेख में होता है। देश की परराष्ट्रीय नीति के

सम्बन्ध में समस्त महत्वपूर्ण घोषणायें उसी के द्वारा होती हैं, न कि विदेश मंत्री के द्वारा। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे प्रधानमन्त्री के पास हो या न हो, परराष्ट्र सम्बन्धों का सुचारु संचालन उसका दायित्व समझा जाता है। अन्य प्रशासकीय विभागों पर भी प्रधानमन्त्री देखरेख करता है और मन्त्रिमण उसका परामर्श लेकर ही कोई महत्वपूर्ण निणय करते हैं। देश की शासन सम्बन्धी नीति का निर्धारण मन्त्रिमण्डल के परामर्श से प्रधानमन्त्री ही करता है। वही विविध मन्त्रालयों के कार्य में सामञ्जस्य बनाये रखता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही अपने निर्णय करने को बाध्य नहीं है। वह बिना मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन रखे किसी भी नवीन नीति अथवा योजना को सावजनिक रूप से घोषित कर सकता है तथापि शासन के संचालन में प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों की परवाह न करके मनमाता व्यवहार नहीं कर सकता। उसे अपने सहयोगियों का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि उसकी सफलता बहुत कुछ उनके सहयोग पर निर्भर है। सहयोगियों के विश्वास को ठुकराकर वेच्छाचारी आचरण करने वाला प्रधानमन्त्री अपने घर, समूह और राष्ट्र का श्रमान खो बैठता है। सभी की दृष्टि सदैव प्रधानमन्त्री के कार्यों पर लगी रहती है। वह और सरलतापूर्वक अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता।

अंतिम रूप से प्रधानमन्त्री धजद के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए राजकीय बजट को प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री ही अंतिम रूप देते हैं। लोकसभा में प्रेषित करने से पूर्व मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति इस बजट के लिये नहीं ली जाती, यद्यपि मन्त्रिमण्डल को बजट का एक मौलिक विवरण दे दिया जाता है।

राजा के परामर्शदाता के रूप में प्रधानमन्त्री

केवल प्रधानमन्त्री ही राजा के परामर्शदाता का कार्य करता है। सिद्धांततः प्रधानमन्त्री का कार्य राजा को शासन सम्बन्धी परामर्श देना है और राजा इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह प्रधानमन्त्री के परामर्श को माने या न माने। किन्तु व्यवहारतः राजा प्रधानमन्त्री के परामर्श को सदैव मानता है।

प्रधानमन्त्री, राजा और मन्त्रिमण्डल को एक दूसरे से सम्बद्ध रखने वाली कड़ी का काम करता है। वह मन्त्रिमण्डल के निणयों और वातालापों की सूचना राजा को देता है। आपातकाल में राजा सगुप्रथम प्रधानमन्त्री से ही सलाह लेता है। प्रधानमन्त्री राजा के व्यक्तिगत जीवन के मामलों को भी नियन्त्रित करता है। राजा कितन-कितन सरकारी कार्यों में भाग लेगा, साम्राज्य या राष्ट्रमण्डल के किस भाग की यात्रा करेगा आदि बातों का निणय प्रधानमन्त्री ही करता है।

संरक्षण और उपाधियों सम्बन्धी शक्ति

प्रधानमन्त्री के पास संरक्षण और कृपा के अपार स्रोत हैं। उपाधियां प्रदान करता राजा का विशेषाधिकार है, किन्तु उनका वितरण प्रधानमन्त्री के परामर्श पर ही किया जाता है। विशेष रूप से राष्ट्रसभा की मददगारता का भंडार ऐसा है

जिसका प्रधानमन्त्री राजनीतिक प्रयोग कर सकता है। दल के अमनुष्य नेताओं को सन्तुष्ट करन, दल के समर्थकों और सेवकों को पुरस्कृत करने, दल के व्योवृद्ध एवं प्रतिष्ठित नेताओं को संसद में स्थान देने तथा दल के लिए धन एकत्रित करने आदि के लिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के सरक्षण अधिकार (Patronage) का यही मुख्य स्रोत है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महोत्सव के अवसरों पर प्रधानमन्त्री उपाधियाँ व सम्मान वितरित करते समय विरोधी दल के सुझाव भी आमन्त्रित करता है।

आपातकालीन अधिकार

युद्ध, अथ सबोट या अन्य इसी प्रकार के संकटा के समय ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की शक्ति बहुत दृढ़ होती है। यद्यपि ब्रिटिश संविधान के अन्तर्गत भारतीय संविधान की भाँति कोई आपातकालीन प्रावधान नहीं दिये गये हैं, किन्तु फिर भी सुरक्षा कदम उठाने के लिये अथवा विपत्ति के समय सम्पूर्ण राष्ट्र की शक्ति प्रयुक्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वायपालिका निम्न रूप से शक्तिशाली बन जाये। यह एक तथ्य है कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन जैसे प्रजातांत्रिक राज्य में कांग्रेस ने हिटलर और मुसोलिनी व समान अधिनायकीय शक्तियों का प्रयोग किया किन्तु यह प्रयोग सांविधानिक उल्लंघन से हुआ। वास्तव में आपातकाल के समय ब्रिटेन में सांविधानिक अधिनायकत्व की स्थापना हो जाती है, जिसका तानाशाह प्रधानमन्त्री होता है। कभी-कभी तो सीधे कार्य करने की दृष्टि में प्रधानमन्त्री स्वयं नियंत्रण कर देता है और तब कार्य पूरा करने के बाद उसे मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचार विमर्श के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

दल का नेता

शासन का प्रधान होने के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बहुमत दल का नेता होता है और उसकी सर्वोच्च शक्ति का राज उसकी यह दलीय स्थिति ही है। विजित दल का नेता होने के नाते ही वह प्रधानमन्त्री बन पाता है। इन स्थिति में उसका व्यक्तिगत सार्वजनिक रूप से नेता है। रेडियो, वादूँ, प्रेस आदि द्वारा उसका व्यक्तित्व जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह दलीय एकता का प्रमुख स्तम्भ और प्रतीक होता है, जिसके विरुद्ध अकारण ही अगुली उठाना दल के साथ विश्वासघात माना जाता है। प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व का ही केन्द्र बनाकर सामान्य निर्वाचन (General Election) लड़ा जाता है। अनिश्चित मतदाता का वास्तव में चुनावों का नियंत्रण करते हैं किसी दल विशेष अथवा नीति का समर्थन नहीं करके केवल एक नेता का समर्थन करते हैं। इसलिए प्रधानमन्त्री की प्रभावशाली महत्त्व करना पड़ता है।

वस्तुतः निर्वाचन के द्वारा प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है, उससे व्यक्तित्व में दल की प्रतिष्ठा और शक्ति समीक्षित हो जाती है और तब

उसे नेता पद से निकाल फेंकना एक अत्यधिक दुष्कर कार्य हो जाता है। यह कह देना कोई अतिशयोक्ति न हागे कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर ही दल बहुत कुछ टिका रहता है।

लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री लोकसभा (House of Commons) का नेता होता है। यद्यपि आजकल ऐसा चलन है कि वह अपने किसी साथी को लोकसभा का नेता मनोनीत कर देता है, ताकि इस उत्तरदायित्व से उसे छूटकारा मिल जाय, किंतु तब भी लोकसभा के नेता के रूप में अंतिम उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही है। लोकसभा का नेता होने व अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा को अपने नियंत्रण में बनाये रखता है। इस सम्बन्ध में उसकी स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति से बहुत भिन्न है जिसका वहाँ की प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। लोकसभा का नेता होने के नाते मुख्य नीति सम्बन्धी घोषणाएँ प्रधानमंत्री को ही करनी पड़ती हैं। उनसे ही विभाग विभाग या प्रशासन की आम आलोचना से सम्बन्धित प्रश्न किये जाते हैं। वही इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मसद् का सीधा सामना करता है। प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण वाद विवादों को आरम्भ करता है और वही रक्षा विभाग विदेश विभाग या गृह विभाग से सम्बन्धित वाद विवाद में हस्तक्षेप करता है। यदि मंत्रियों से कोई भूल हो जाय तो प्रधानमंत्री उस भूल को सुधार सकता है। अपने मंत्रियों के साथ उसे ही मसद् में सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है। मसद् के दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। उन्हीं के द्वारा वह लोकसभा के अपने दल के सदस्यों का आवश्यक आदेश देता रहता है। मुख्य सचेतक की सहायता से वह सदन को समय सूचक कार्यवाहियाँ निर्दिष्ट करता है, कार्य व्यवहार बतलाता है और विरोधी दल की राय जान कर प्रत्येक कार्यवाही के लिए समय निर्दिष्ट करता है। प्रधानमंत्री राजा से कहकर लोकसभा को विघटित कराने का महत्वपूर्ण अधिकार रखता है और राजा साधारणतया उसके इस परामर्श को अस्वीकार नहीं कर सकता।

परन्तु अपनी इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण प्रधानमंत्री मनमानी नहीं कर सकता। उसे मसद् मसद् सदस्यों की नाडी पर हाथ रखे हुए यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसके क्रिया कलापों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अपने दलीय सदस्यों और जनमत की वह उपेक्षा नहीं कर सकता। लोकमत की अवहेलना से वह बचता है क्योंकि उसका और उसके दल का भावी निर्वाचन अनुकूल लोकमत पर ही निर्भर करता है।

प्रधानमंत्री की स्थिति की वास्तविकता

ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति एक अधिनायक के समान है, केवल अन्तर यही है कि एक अधिनायक अथवा तानाशाह मनमाने तरीके से अपनी

दायित्वों का प्रयोग करता है जबकि प्रधानमंत्री स्थापित नियमों, परम्पराओं और अभिसमयों के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धों के मातहत हाकर देश का शासन करता है और इन प्रतिबन्धों की अवहेलना करने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। प्रधानमंत्री एक सांविधानिक तानाशाह है जो अपने मंत्रियों को उचित सम्मान देता है और उनके मत का उचित आदर करता है। यद्यपि सलाहकारी का अक्सर उपस्थित होने पर वह अपनी ही चलाता है और ज्ञान के ज्यादा बढ़ने पर उसे नहीं बल्कि मंत्रियों की पदत्याग करना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों की तुलना में उनकी स्थिति अधिक महत्त्व की है और वही मंत्रिमण्डल के निर्माण, संचालन व पतन के लिए उत्तरदायी होता है, परन्तु फिर भी विविध मंत्रियों के सम्बन्ध में उनकी स्थिति इनकी शक्तिशाली नहीं है जितनी संयुक्त राज्य, अमेरिका के राष्ट्रपति की है। लास्की के शब्दों में "अमेरिका में मंत्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के 'दास' हैं जबकि ब्रिटन में वे प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं।" प्रधानमंत्री को समस्त मंत्रिमण्डल के विचारानुसार चलना पड़ता है। मंत्रियों के अपन कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें वे प्रधानमंत्री व मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से निभाते हैं।

प्रधानमंत्री और उसके सहायियों में क्या सम्बन्ध है, इसे ब्रिटिशों ने विनिश्चय रूपों में व्यक्त किया है। लॉर्ड मॉर्ली (Morley) ने प्रधानमंत्री को "समक्षों में प्रथम" बनलाते हुए कहा है कि— "मंत्रिमण्डल में यद्यपि सभी मंत्रियों का स्थान एक सा है, उनकी आज्ञा एक-सी है और सभी-सभी जब मतभेद के समय मत लिए जाते हैं तो उनके मत भी समानता पर आधारित 'एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धांत के अनुसार गिने जाते हैं, फिर भी मंत्रिमण्डल का अग्रगण्य समान पदवालो में प्रथम है और जब तक वह पद पर रहता है उसकी स्थिति अमाधारण व अद्वितीय अधिकार की रहती है।" लॉर्ड मॉर्ली उन्नावरवादी लैंग्वर रम्से म्योर (Ramsay Muir) ने इस विचार को निरस्त करने के लिए लिखा है कि "प्रधानमंत्री का समक्षों में प्रथम कहना मगया नममूल्य है क्योंकि वह अपने सहयोगियों को नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता है। विधि में नहीं, लेकिन व्यवहार में वह राज्य का वास्तविकी प्रधान है, जिसकी शक्तिशाली स्थापना है जितनी कि विश्व के किसी भी सांविधानिक शासन का तब की अमेरिकन राष्ट्रपति, को भी प्राप्त नहीं है।" हेरबर्ट मॉरीसन (Herbert Morrison) के मतानुसार भी प्रधानमंत्री का "समक्षों में प्रथम" कहा जाना उसकी स्थिति की कम आशंका है। जेनिंग के अनुसार "प्रधानमंत्री केवल समक्षों में प्रथम ही नहीं है और न केवल गिनतारा के बीच चन्द्रमा ही बल्कि वह तो सूर्य के समान है जिसका चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। हेरबर्ट मॉरीसन मंत्रिमण्डल में प्रधानमंत्री की शक्ति अनुशासनिक के साधन-मात्र में सीमित नहीं है।

प्रधानमंत्री की स्थिति का महत्व केवल शक्तिशाली मंत्रियों के सम्बन्ध में ही नहीं

है, अपितु उसकी स्थिति शासन सूत्र के सभी पहलुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंत्रिमण्डल के अध्यक्ष के रूप में, शासन-प्रमुख के रूप में, राजा के परामशदाता के रूप में, दल के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री विशाल शक्तियों का स्वामी है। इसलिए जेनिंग्स (Jennings) ने कहा है कि “प्रधानमंत्री को सम्पूर्ण संविधान की आधार-गिला कहना ही उपयुक्त है। फाइनर (Finer) ने लिखा है कि “प्रधानमंत्री की छेठना इस बात से प्रकट होती है कि वह मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष, मसद का नेता, सामान्य नीति से सम्प्रवित विषयों पर सम्राट से विचार-विमर्श की प्रमुख कड़ी, देश में दल का सामान्य नेता तथा सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान रूप है।” किन्तु फिर भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है। इसको फाइनर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है— “वह जीन पर दृढ़ता से अवस्थित है, लेकिन वह मजा हुआ सवार है या लुङ्गने वाला, भाड़े के टट्टू के लायक है या फौजों और घुड़दौड़ के घोड़े के लायक, यह उस पर निर्भर करता है। पुनश्च, लास्की के इस विचार में पर्याप्त बल है कि “प्रधानमंत्री की स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है।” राजनीतिक दल का नेता बने रहने और लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त किए रहने तक ही वह राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति समझा जाता है किन्तु उमोही वह दलीय समर्थन से वंचित हो जाता है और लोकसभा के बहुमत का विश्वास खो बैठता है, उसका सम्पूर्ण महत्व लुप्तप्राय हो जाता है। वस्तुतः अपना महत्व बनाये रखने के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तित्ववान होना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व द्वारा अर्जित किए गए महत्व के अनुरूप ही वह अपने पद का महत्व दे पाता है।

6

लोकसेवा

(THE CIVIL SERVICE)

“यह द-त्रिटेन में शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा नहीं और न ही व्यक्तिगत
मनियों द्वारा बल्कि लोकसेवकों द्वारा किया जाता है।”

—वेब

किसी भी देश की सामान्य व्यवस्था की सफलता अथवा विफलता उसके लोकसेवकों के ऊपर निर्भर करती है। देश का वास्तविक प्रशासन इन लोक-सेवकों के हाथ में होता है। मन्त्रीगण तो केवल नीति निर्धारण मात्र ही करते हैं। उस नीति का प्रिया वयन इन लोकसेवकों द्वारा ही किया जाता है। यदि ये कर्मचारी भाग्य तथा कुशल होते हैं तो प्रशासन अच्छा होता है अन्यथा नहीं।

ब्रिटिश लोकसेवा का सामान्य परिचय

लोकसेवा का सदस्य अथवा लोकसेवक (Civil Servant) इंग्लैंड में राजमुकुट (Crown) का कर्मचारी होता है जिसका पद न तो मायिक ही होता है और न राजनीतिक ही। उमाको राजकाय से वेतन प्राप्त होता है। राज्य के प्रशासनिक विभागों के सभी स्टाई कर्मचारी लोक सेवा (Civil Service) के सदस्य होते हैं। लोक सेवा के सदस्यों को समद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सन 1937 में यह कानून भी निर्दिष्ट हो गया है कि उनका राजनीतिक विचार उनके व्यक्तिगत मामले हैं उनका विचार उनके कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अथवा राज्य के लिए गलत फैसला करने वाले नहीं हैं। लोकसेवा के सदस्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी सरकारी रहस्य अथवा सूचना का प्रकाशन नहीं कर सकते। यद्यपि लोक सेवा वैधानिक रूप से राजमुकुट के सेवक होते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें अपने विभागीय मन्त्री के अधीन रहना

पड़ता है। वे मंत्रियों को नीति निर्माण में परामर्श देते हैं और उनके निणयों को कार्यान्वित करने में सहायक होते हैं।

समय-समय पर मन्त्रीगण बदल जाते हैं, पर लोक सेवक स्थाई रूप से बने रहते हैं। ब्रिटेन में सरकार के परिवर्तन के कारण लोक-सेवा के लोगो में परिवर्तन नहीं होता। वे स्थाई रूप से सभी सरकारों के अधीन कार्य करते रहते हैं।

ब्रिटेन में लोक सेवा का विहास

लोक सेवा अपने आधुनिक रूप में लगभग 100 वर्ष पुरानी है। ग्राहम वालास (Graham Wallas) ने इसे "इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी की महान् राजनीतिक खोज" कहा है। प्रारम्भ में शासन का कार्य राजघराने के लोग चलाते थे, किन्तु मन्त्रिमण्डलात्मक शासन के विकास के साथ साथ प्रशासन मंचालन के लिए मन्त्रियों द्वारा अधिकारियाँ की नियुक्ति होने लगी, जो प्रायः जब तक स्वास्थ्य उत्तम रहता था, पदासीन रहते थे। किन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त में और 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बक, बेंथम, कार्लाइल आदि ने इस प्रकार की नियुक्ति प्रथा पर आक्षेप किये। आलोचनाओं के फलस्वरूप लोक सेवकों की नियुक्ति-प्रथा में नये नये सुधार होने लगा। 1870 ई० में लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक प्रतिभागिता परीक्षणों का श्रोगणेश हो गया। बाद में शैड्सटन के आुरोध पर, लोक-सेवा आयोग (Civil Service Commission) की स्थापना की गई। अथ परीक्षाओं के संचालन और लोक सेवा के सदस्यों की भर्ती की व्यवस्था यही आयोग करने लगा। इसके बाद और भी विभिन्न सुधार लाये गये। सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, स्त्रियाँ भी प्रवेश पाने लगी तथा पेनन, सरकारी आदि सब कुछ निश्चित हो गया। पिछले 50 वर्षों में लोक-सेवा की भर्ती की प्रतिभागिता का संक्षिप्त स्तर भी काफी उन्नत बना दिया गया है। अनेक आयोगों और जांच समितियों की नियुक्ति की गई है तथा उनके प्रतिवेदनों के आधार पर लोक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। शासक लोक-सेवक किसी विभाग विभाग का कामकारी नहीं होता, बल्कि वह अब सम्पूर्ण लोक सेवा का एक सदस्य होता है और उसे योग्यतापूर्वक आने पर वह पेनन आदि की सुरक्षा प्राप्त होती है। आज सम्पूर्ण ब्रिटिश लोक सेवा में एकरूपता आ गई है। ब्रिटिश लोक-सेवकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है।

लोक सेवा का नियंत्रण, संगठन और उससे व्यय

ब्रिटिश लोक-सेवा पर वित्त मन्त्रालय का माध्यारण्य नियंत्रण रहता है। वित्त मन्त्रालय ही लोक सेवा की भर्ती के नियमों के निर्धारण, सरकारी सेवाना आदि के लिए उत्तरदायी होता है। जनचारियों की संख्या निर्धारित करना, उच्च पदा के स्पातों का बढ़ाना तथा मन्त्रियों की प्रतिनिधित्व करना आदि की व्यवस्था करना भी इस मन्त्रालय का ही कार्य है। लोक सेवा के संगठन में प्रशासनिक या, कार्यवाही

वर्ग, विशिष्ट वर्ग, लिपिक वर्ग सहायक लिपिक वर्ग, सदेश बाहक एवं निम्न वर्ग सम्मिलित है। प्रशासनिक वर्ग लोक-सेवा का आधार है, जिसमें स्थायी सचिव से लेकर सहायक प्रधान तक के अधिकारी आते हैं। यह वर्ग नीति-निर्माण के कार्यों में मंत्रियों को परामर्श देता है। कायपालक वर्ग का दायित्व निर्धारित नीति के अनुसार दैनिक शासन-कार्य का संचालन करना होता है। विशिष्ट वर्ग में अकाउंटेंट, वकील, सर्वेयर, वैज्ञानिक आदि होते हैं जो विशिष्ट सेवाएँ निभाते हैं। लिपिक और सहायक लिपिक वर्ग शासन संचालन में लिखने पढ़ने, टाइप करने आदि के कामों में प्रयुक्त होता है। सदेश बाहक और निम्न वर्ग में चपरासी, सफाई करने वाले कमचारी आदि सम्मिलित हैं। इनके अलावा विभागीय वर्ग (Departmental Classes) भी होते हैं जिनके लिए भरती पथक पृथक विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है।

ब्रिटेन में सितम्बर 1966 तक लोक-सेवा वर्ग के कमचारियों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 8 लाख 22 हजार थी।

उत्तरीय आयरलैंड की लोक सेवा

उत्तरी आयरलैंड की सरकार लोक-सेवा का एक पथक संगठन रखे हुए है। इसके द्वारा उन कार्यों का सम्पादन किया जाता है जिन्हें सन् 1920 के आयरलैंड के सरकारी अधिनियम (Govt of Ireland Act, 1920) के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड की सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है। उत्तरी आयरलैंड की लोक-सेवा का संगठन प्रायः ग्रेट-ब्रिटेन के समान ही है तथापि उसके लिए भर्ती आदि के लिए एक पृथक लोक सेवा आयोग स्थापित है।

लोक सेवा कमचारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, कायकाल आदि

आरम्भ में ब्रिटिश लोक-कमचारियों की नियुक्ति शासक वर्ग द्वारा मनमाने रूप द्वारा होती थी, किन्तु धीरे-धीरे प्रतियोगिता की प्रथा चल पड़ी। इसका शीर्गणेश तो 1870 में हुआ गया था, किन्तु प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत 1910 में एक सपरिषद् आदेश (Order in Council) द्वारा हुई। आज भी लोक-कमचारियों की भर्ती का आधार यही है। भर्ती का कार्य एक लोक सेवा आयोग द्वारा होता है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। इस आयोग का स्थापन सन् 1885 में हुआ था।

लोक-सेवा कमचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। प्रशिक्षण का कार्य मुख्यतः विभागों द्वारा संचालित होता है। कमचारियों को साधारण और तकनीकी दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। भर्ती होने वाले कमचारियों को तो विधिवत् प्रशिक्षण दिया जाता है, नौकरी करते हुए कमचारियों को भी माध्यमिक शिक्षण (Refresher Courses) दिए जाते हैं। प्रशिक्षण काय बहुत ही

“...” तरीकों से सम्पन्न कराया जाता है।

पदाधिकारियों का नौकरी के आरम्भ में एक विभाग से दूसरे विभाग में और एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरण होता रहता है ताकि वे अधिकाधिक स्थानों व पदासन का अनुभव प्राप्त कर सकें। वैसे भी पदाधिकारियों का प्रायः नियमित रूप से स्थानान्तरण होता रहता है। अधिकांशों का देश-विदेश की यात्रा करने के अवसर भी दिए जाते हैं। इससे उनके प्रशासनिक ज्ञान में वृद्धि होती है।

लोक सेवा कर्मचारियों की पदोन्नति की समुचित व्यवस्था है। पदोन्नति कार्य की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर भी की जाती है और खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा भी। बिना परीक्षा लिए पदोन्नति देते समय कर्मचारी का वरीयता योग्यता आदि का ध्यान रखा जाता है। प्रायः प्रत्येक विभाग में पद-वृद्धि आयोग पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आयोग की सिफारिश से असंतुष्ट हो तो उसे अपील करने का अधिकार होता है।

लोक सेवा कर्मचारियों का कायकाल मर्याद की इच्छा-पयत होता है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि वे पद-निवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं। यह आयु साठ वर्ष है, कारण विशेष पर पहले भी पदनिवृत्त हो सकते हैं। सरकार के परिवर्तन का कायकाल पर कोई असर नहीं पड़ता। उनसे यही आशा की जाती है कि वे प्रत्येक दल के मंत्रियों की निष्पक्षतापूर्वक सेवा करेंगे। पहले जमद्वार, 1936 तक विवाहित महिला कर्मचारियों के पद की सुरक्षा नहीं थी, किन्तु वर्ष (1946 में ही) विवाह के प्रतिबंध का हटा लिया गया है।

लोक कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों का निर्णय राष्ट्रीय व्हिटले कौंसिल (National Whitley Council) द्वारा किया जाता है जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं। सभी कर्मचारियों का सामान्यतः इतना वेतन मिल जाता है, जितना वस ही काम के लिए उन्हें भ्रम भी मिल सकता हो। कर्मचारियों के साथ के घंटे भी निश्चित हैं। पद निवृत्त होने के बाद पेंशन दिए जाने की व्यवस्था भी है।

मंत्रिगण और लोक-सेवक

(Ministers and the Civil Servants)

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था अविशेषज्ञों (Amateurs) और विशेषज्ञों (Experts) के समन्वय पर आधारित है, अर्थात् ब्रिटिश शासन-सूत्र का संचालन करने वाले लोग दो प्रकार के हैं—मंत्रिगण और लोक सेवक। मंत्रियों में प्रशासनिक अनुभूति होती है, जबकि लोक सेवकों में प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता होती है। मंत्रिगण प्रशासनिक दृष्टि से अनुभूति अथवा अविशेषज्ञ किस प्रकार है और लोक-सेवक विशेषज्ञ कौन हैं? यह निम्नलिखित विवरण से समझ में आ सकेगा।

मंत्रियों की प्रशासनिक अनुभूति

मन्त्री अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, किन्तु विभाग के वास्तविक

अनुभवों और प्रशासनिक कारीगरों का उन्हें प्रायः ज्ञान नहीं होता। उनका प्रशासनिक ज्ञान स्थूल होता है न कि विविष्ट। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। प्रथम तो मन्त्रीपद पर उनकी नियुक्ति राजनीति के आधार पर होती है, किसी विविष्ट प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं। दूसरे, उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, वे किसी विभाग के स्थायी अध्यक्ष नहीं होते। तीसरे, राजनीतिक प्रश्नों और गतिविधियों में वे इनके फल रहे हैं कि प्रशासन के वास्तविक कार्य का संचालित करने का प्रायः उन्हें बहुत कम अनुभव हो पाता है। इसी मध्य कारणों से मन्त्रियों को नीतिनिर्णय या अधीनस्थ (Amateurs) कहा जाता है, अर्थात् वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पेशेवर प्रशासक नहीं होते, जिन्हें प्रशासन सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता और जिन्हें प्रायः प्रशासन का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। वे केवल राजनीतिक प्रशासक मात्र हैं।

इस बात का अब एक लोकात्मिक सिद्धांत माना जाने लगा है कि मन्त्रिगण प्रशासन के विभाजन नहीं होते।

लोक सेवकों की प्रशासनिक विविष्टता

शामन-सूत्र चलाने वाला दूसरा वर्ग लोक सेवकों (Civil Servants) का है जो प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ (Experts) होते हैं। शामन का वास्तविक संचालन ये लोक सेवक ही करते हैं। ये प्रशासन के मामलों में दक्ष होते हैं, मन्त्रियों को नीति-निर्धारण में सहायता देते हैं और विधियों को प्रभावित करते हैं, परन्तु ये विशेषज्ञ-कर्मचारी अधीनस्थ या नीतिविद्य (Amateurs) के अधीन रहते हैं, जो शामन के विभागों के अध्यक्ष होते हैं।

लोक-सेवकों को उनका प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण और अनुभव शामन कार्य का विशेषण बना देता है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है, न कि राजनीतिक आधार पर। एक बार योग्यता सम्बन्धी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद यह निश्चय हो जाता है कि उन्हें स्थायी रूप से प्रशासन के ही किसी पद पर कार्य करना है। धन प्रशासनिक कार्य में उनकी अधिकाधिक रचि होनी जाती है। वे समझते हैं कि जितना अधिक वे प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त होंगे उतने ही अधिक अवसर उन्हें पदावधि के प्राप्ति होंगे। एक ही प्रकार का काम अधिक दिनों तक करते रहने के कारण और अधिकाधिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के, उपयुक्त अवसरों के मिलते रहने के कारण लोक-सेवक विभागीय दाव पेशा को भली भाँति समझते हैं। राजनीतिक प्रश्नों से दूर रहते हुए अपने पद के स्थायित्व के कारण उन्हें अपने विभाग की भीतर की बातों और उनके परिणामों का गूढ़ ज्ञान होता है। वे मन्त्रियों को उचित परामर्श देते हैं और उनके द्वारा निर्धारित नीति को कार्यरूप में परिणित कराते हैं। मन्त्रियों को प्रशासन चलाने के लिए और प्रशासकों की कारीगरियों के लिए लोक सेवकों पर, जो प्रशासनिक विशेषज्ञ होते हैं, प्रायः पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है।

अविशेषज्ञ और विशेषज्ञ के समन्वय से लाभ

अविशेषज्ञों और विशेषज्ञों—इन दो तत्त्वों के त्रिटिस प्रशासन में योगदान तथा समन्वय के विषय में मुनरो (Munro) ने लिखा है कि “प्रथम तत्त्व द्वारा प्रशासन में जनतन्त्र की और द्वितीय तत्त्व द्वारा मन्व्यतन्त्र की स्थापना होती है। दोनों ही अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रथम तत्त्व से शासन जनप्रिय और द्वितीय से कुशल बनता है। सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि जातजन और कार्य-कुशलता में सफल संयोग हो।” मन्निगण राजनीतिक नेता होते हैं जिनका कार्य है—राष्ट्र की नाडी की गति पहचानना। जनता की इच्छा के अनुसार वे नीति-निर्धारित करते हैं और उसे विधि का रूप देते हैं, परन्तु विधियों (Laws) को कार्यरूप देने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और प्रशासकवर्ग इसी कमी को पूरा करता है। पुनश्च, लोक सेवक ही मन्त्रियों को उचित मार्ग दिखाते हैं। विधान में उनके लिए नीति निर्माण में कोई स्थान नहीं, पर उन्हीं के परामर्श पर प्रायः शासन का कार्य होता है।

क्या मन्त्रियों का प्रशासनिक विशेषज्ञ न होना उपयोगी है ?

प्रश्न उठता है कि क्या मन्त्रियों को विशेषज्ञ होना चाहिए ? समझने का कहना है कि मन्त्रियों के प्रशासनिक विशेषज्ञ न होने से गौकरसाही प्रोत्साहित होती है। अतः व्यावसायिक जानकारों और अनुभवी व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए, जैसा कि फ्रांस और अमेरिका में प्रायः होता है।

परन्तु इन तक में विचार बल नहीं है। हम यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विशेषज्ञ न होने से मन्त्रियों का प्रशासन की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता। विशेषज्ञ न होते हुए भी प्रशासन के लिए उनकी विशेष उपयोगिता होती है और यदि सचमुच देखा जाय तो वे उपयोगी इसलिए और भी अधिक होने दें कि उन्हें प्रशासनिक तान की विशिष्टता नहीं आती। निम्नलिखित विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा—

(1) मन्त्रियों का पदला प्रमुख कार्य यह है कि वे प्रशासन की नीतियों का निर्धारण इन प्रकार करें जिनसे अनिवाधित नागरिकों को अधिक और लोक-मत को समुचित आदर प्राप्त हो सके। अतः वे नीति-निर्माण में एक प्राथमिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनका दृष्टिकोण समन्वितान्त्रिक और प्रगतिशील विचारों वाला होता है। इनसे विपरीत विचारों का दृष्टिकोण मनुजित होता है। वे छोटे-मोटे पारिभाषिक बातों को विशेष महत्व देते हैं और नीतिगत पर प्रायः एकमत नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि मन्त्री राज-सेवा की तरह प्रशासन विभागा न हो, बल्कि यदि मन्त्री भी लोक-सेवा के मन्त्रियों का तरह ही प्रशासन विभाग होने लगें तो उन्हीं के समान ही नीति-निर्माण की कार्यवाही को फायदे के बड़े प्रान्तर रह जायेंगे। तब वे प्रशासन का तानाबाना, निर्देशन और नियंत्रण इन प्रकार नहीं कर सकेंगे, जिससे देश की साम्यविक सेवा हो सके। इनके अनिश्चित व जनता

के साथ अपना निकट सम्पर्क भी स्थापित नहीं कर सकेंगे और जनता के कष्टों को अपना कष्ट नहीं बना सकेंगे। रैमजे मैकडानल्ड (Ramsay Mac Donald) ने ठीक ही कहा है कि “मंत्रिमंडल जनता और विशेषज्ञ तथा सिद्धांत व व्यवहार को जोड़ने वाला पुल है।”

(2) मंत्रिमंडलीय शासन का सार है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व। वे व्यक्तिगत विभागीय हितों के साथ साथ सम्पूर्ण प्रशासन के हितों को भी ध्यान में रखते हैं। एक मंत्री सिर्फ अपने महकमे से ही सम्बन्ध नहीं रखता, उसे दूसरे महकमों की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। वह इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकता कि मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण किसी दूसरे मंत्री की हार का नतीजा सम्पूर्ण मंत्रिमंडल का पतन हो सकता है। इस अनुभूति के कारण वह अपने विभागों के कार्यों का अन्य विभागों के कार्यों के साथ इस प्रकार सामंजस्य करता है कि सम्पूर्ण सरकार एक सामूहिक इकाई के रूप में कार्य कर पाती है। सम्पूर्ण प्रशासन के सर्वोपरि हितों को अविशेषज्ञ मंत्री ही सोच सकता है न कि विशेषज्ञ लोकसेवक। विशेषज्ञ तो विभागीय प्रशासनिक पंचडों में फंसा रहता है। उसका विभागवाद उसे विशाल दृष्टिकोण नहीं अपनाने देता। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ लोक-सेवक ज्ञान की एक शाखा का विशयण होता है और यह पचास सम्भव है कि दूसरे विषयों में उसका ज्ञान शून्य हो।

(3) मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके लिये आवश्यक है कि वे अपने हृदय में लोकसभा और उसके सदस्यों के प्रति आदर-भाव रखें। मंत्री यदि विशेषज्ञ होंगे तो हाँ सकता है कि स्वयं को इतना ज्ञानवान समझने लगे कि साधारण विधायकों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानने में अपमानित हाना अनुभव करने लगे। इस प्रकार की भावना का मन्त्र होने से मंत्री स्पष्टतः लोकसभा के प्रति अपने वास्तविक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे। उनमें उत्तरदायित्व के स्थान पर निरकुशता के विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात संसदीय शासन-व्यवस्था के लिए एक गम्भीर आघात होगी।

निम्न रूप में यह कहा जा सकता है कि मंत्रियों के विशेषज्ञ न होने से प्रशासन में अथवा राजनीति में क्षेत्र में उनकी उपयोगिता और महत्व को कोई आघात नहीं पहुँचता, प्रत्युत विविष्ट दृष्टियाँ से यह लाभदायक ही है।

मंत्रियों और लोकसेवकों का पारस्परिक संबंध

(Relationship between the Ministers and the Civil Servants)

मंत्रियों और लोकसेवकों का पारस्परिक सम्बन्ध एक अत्यंत विवादप्रस्त विषय है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि लोकसेवकों का ब्रिटिश प्रशासन में इतना प्रभाव है कि मंत्रीगण उनके सवैतों पर चलते हैं, वे उनके हाथों का मिलीला बनकर

कार्य करते हैं। उनका आरोप है कि ब्रिटेन में वस्तुतः नीकरशाही का आधिपत्य स्थापित हो गया है। इसके विपरीत—विद्वानों के दूसरे वर्ग का कहना है कि ब्रिटेन में नीकरशाही के आधिपत्य की बात करना भ्रामक है। यह सही है कि ब्रिटिश प्रशासन के मूल में लास्क—सेवकों का काफी प्रभाव है, परन्तु फिर भी वास्तविक नियंत्रण शक्ति मंत्रियों में ही निहित है। मंत्रियों में, अपने विभाग के लिए नए होते हुए भी, नीति-निर्धारण और नियंत्रण करने की क्षमता होती है और वे ऐसा करते भी हैं। लास्को (Laski) का कहना है कि दोनों का सम्बन्ध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। यदि मंत्री का व्यक्तिगत शक्तिशाली है तो वह लोकसेवकों पर हावी रहता है, और यदि मंत्री एक कमजोर और ढीला-ढाला व्यक्ति है तो उसे लोकसेवकों के झूठारों पर चलना पड़ता है।

वैधानिक स्थिति यही है कि प्रशासन का अन्तिम उत्तरदायित्व मंत्रियों पर ही है अतः लोकसेवकों को उसी की इच्छा के अनुरूप चलना पड़ता है। मंत्री ही मन्त्रिमण्डल द्वारा किए गए नियमों की सीमा के अन्तर्गत अपने अपने विभाग की नीति निर्धारित करते हैं और लोकसेवकों के माध्यम से उनका क्रिया-व्ययन करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में लोकसेवकों का मंत्रियों पर हावी रहने का तब तक कोई प्रश्न नहीं उठता जब तक कि मंत्री स्वयं स्वेच्छा से अथवा अनजाने में उन्हें ऐसा अवसर न दें।

अब हम विस्तार से यह देखने का प्रयास करेंगे कि नीकरशाही की शक्ति क्या है, अर्थात् मंत्रियों पर लोकसेवकों का क्या प्रभाव है और क्या मंत्री लोकसेवकों के हाथों भी पठपुतली होते हैं?

मंत्रियों पर लोकसेवकों का प्रभाव

यह प्रायः सभी मानत हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में नीति निर्धारण और योजनाओं के प्रारूप बनाने से लेकर उनकी अन्तिम सफलता तक लोकसेवकों के सहयोग का निश्चित मूल्य होता है। शासन-मूत्र में उनके इस प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण ये हैं—

प्रथम, मन्त्रीगण प्रशासन के विशेषज्ञ नहीं होते जबकि लोकसेवक उसके विशेषज्ञ होते हैं। अतः मंत्रियों को उनसे विभिन्न मामलों में परामर्श लेना पड़ता है। लोकसेवक प्रशासन का तकनीकी पक्ष और उसकी वारीकियाँ मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं ताकि वे (मंत्री) अपने नियंत्रण करने में यथासम्भव कोई भूल न कर पाएँ।

दूसरे, मंत्रियों की यह विशेष प्रवृत्ति होती है कि वे प्रशासन की किसी बात को प्रयोग पर नहीं छाड़ते। ऐसा करने से उनकी दृष्टिवा प्रवाश में आती है, जिनका उनके स्वयं के भविष्य पर, उस राजनीतिक दल पर, जिनके वे सदस्य हैं विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से बचे रहने के लिए मन्त्रीगण प्रायः प्रत्येक प्रशासन सम्बन्धी कार्य लोकसेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर करना ही अधिक अच्छा समझते हैं। रैम्से म्यूर (Ramsay Muir) का मत है कि नीति निर्माण,

निर्णय और उनके श्रिया यजन में मंत्रियाँ पर लाकसेवकों का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि मंत्रियों को लाकसेवकों के हाथ की कठपुतली मात्र समझा जाना चाहिए। यह मत न सिद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण है, किन्तु इससे प्रशासन के क्षेत्र में लोकसेवकों के प्रभाव की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है। रंज्जे म्पोर की तुलना में लास्की (Laski) का यह विचार अधिक संतुलित है कि मंत्रियों और लोकसेवकों का सम्बन्ध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित है।

तीसरे, मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अनेक प्रशासनिक समस्याएँ सगंथा मन्थन न हाकर पहले से चर्चा हुई होती हैं। अब उनके मध्य में आगे की योजना बनाने के लिये यह जान लेना जरूरी होता है कि उन समस्याओं पर पहले क्या-क्या किया जा चुका है और उसका क्या परिणाम हुआ? यह आवश्यक जानकारी मही रूप में लाकसेवकों ही मंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे मामलों में मंत्रियों को प्रायः जोरसंकोच पराभव का पूर्ण आदर करना पड़ता है। क्या मंत्री लोकसेवकों के हाथ की कठपुतली होते हैं?

अथवा

क्या लोकसेवकों के आधिपत्य का आक्षेप सही है?

स्पष्ट है कि औद्योगिक रूप से लोक-सेवा यद्यपि मंत्रियों के अधीनस्थ है पर व्यावहारिक रूप में वे मंत्रियों के श्रियाकलापों पर अपनी पर्याप्त छाप छोड़ते हैं, किन्तु यह मानना कि मंत्री लाकसेवकों के हाथ की कठपुतली मानें अथवा त्रिस्तन में लोकसेवकों के शासन का आधिपत्य स्थापित हो गया है, निश्चित रूप से एक भ्रमक धारणा है।

मन्त्री-पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवश्य ही प्रतिभा का धनी होता है और मन्त्री पद प्राप्त करने में पूर्व वह प्रायः ऐसी अनेक परिस्थितियों से गुजरता है जिनसे उस प्रशासनिक बातों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अनेक व्यक्ति मन्त्री बनने से पहले प्रायः विभिन्न अस्थायी व स्थायी समितियों के सदस्य अथवा समन्वय समिति आदि के रूप में अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। इस प्रकार उन विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं का इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वे प्रशासनिक विवेका द्वारा सरलता से उनको नहीं बनाया जा सकने वाला-सर्वकार की उनकी इन बातों में भ्रम होने है अब वे किसी समस्या का प्रशासनिक मन्त्रियों द्वारा विचारों का उनके सामने रखा हुआ यह अनुभव नहीं करते कि वे सामान्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने रखा है जो तब मौन कर उठते (लाकसेवकों के) रतनाय हुए मात्र पर चर्चे में ही अपना व्यापक समर्थन देते हैं। लाकसेवकों मंत्रियों की तुलनाशुद्धि के प्रति सदैव चौकसे रहते हैं। वस्तुतः मंत्रियों में इतना अनुभव होता है कि वे लाकसेवकों द्वारा दिये हुए परामर्श का शीघ्रता से अनात्मिक दूर नहीं और निज पर चर्चे कि अमुक परिस्थिति में क्या करना अधिक उचित होगा? मन्त्री के मतानुसार मन्त्री-पद के अधिकारों का 'पड़ता मुझ सामान्य विवेक है, दूसरा

मनुष्य को परखने की बात है, और फिर उससे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि जानाये कम दी जाती है और वैसे यह देखा जाता है कि उनका पालन हो रहा है या नहीं।

मंत्रियों का लोक सेवकों के हाथों की बटपुतली मानने की भावना विचार-धारा का एक दूसरा आधार यह है कि प्रशासन को समीत या उच्च जैसी कहा माना जाता है, जिनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बगलवार को विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। किंतु प्रशासन एक ऐसी बात नहीं है जिसके लिये सतत अभ्यास की आवश्यकता है। कुशाग्रबुद्धि वाला और दैनिक सामान्य प्रशासन की समस्याओं को समझने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्रि पद सम्भाल सकता है और सावधानी तथा विवेक से कार्य करते हुए प्रशासन चला सकता है। बाहिर लोकसेवा के सदस्यों को भी सम्पूर्ण प्रशासनिक समस्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उनसे सामने की प्रायः जीवनतम समस्याएँ उपस्थित होती रहती हैं, जिनका समाधान वे अपने सामान्य विवेक से करते हैं। अतः स्पष्टतः अंतर केवल यही है कि लोकसेवा यदि किसी प्रशासनिक कार्य को सरलता या कुछ परिश्रम से सम्पन्न कर लेते हैं तो मंत्रियों को उन्हीं कार्य को करने में अपेक्षाकृत कुछ अधिक परिश्रम की आवश्यकता है।

मंत्रियों को लोक सेवा के सदस्यों के हाथों में हिलौना मानने वालों का तीसरा भावना आधार यह है कि वे सम्भवतः सभी मंत्रियों को प्रशासनिक नौसिखियों और सभी लोक सेवकों को प्रशासनिक विरोध मान कर चलते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि न तो सभी मंत्री नौसिखियों होते हैं और न ही सभी लोक सेवक विशेषज्ञ। यदि कुछ नौसिखियों और बुद्धिमान मन शक्ति एक व्यक्तित्व वाले मंत्री लोकसेवा के प्रभाव में रहते हैं तो कुछ मंत्री इतने प्रतिभावान, दृढ़ मन शक्ति और व्यक्तित्व वाले होते हैं कि वे लोकसेवकों पर छाया रहते हैं।

लास्की ने मंत्रियों और लोकसेवकों के सम्बन्ध की वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित माना है। इस दृष्टि से उनमें मंत्रियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है—शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले, लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले एक भाग्य के सहारे चलने वाले।

शक्तिशाली एक प्रविभा सम्पन्न व्यक्तित्व वाले मंत्री लगभग सभी प्रशासनिक समस्याओं को अपने सामान्य विवेक से समझ लेते हैं और उनके समाधान के लिये लोकसेवकों पर आश्रित नहीं रहते। वे हम बात के प्रति पूर्ण सजग रहते हैं कि लोकसेवक स्वयं कोई गलती नहीं कर उठें और लोकसेवक स्वयं इस भाव से आशंकित रहते हैं कि कहीं उनकी असावधानी न हो जाय।

दूसरे मंत्री अपनी लोकप्रियता के बल पर लोक सेवकों पर हावी रहते हैं। उह लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासकीय बाधकियों की परवाह

नहीं होती। वे तो प्रत्येक निर्णय और नीति को जनता की पसंदगी की तराजू में तोलते हैं। वे लोकसेवकों को बतला देते हैं कि जनता क्या पसंद करेगी और क्या नहीं? लोकसेवक उन्हें ऐसा कोई सुझाव या परामर्श देने का साहस नहीं करते जो जनता को नाराज करने वाला हो।

कुछ मंत्री भाग्य के भरोसे चलने वाले होते हैं। उन्हें अपने प्रभाव व व्यक्तित्व की नहीं प्रत्युत अपने पद की चिन्ता बनी रहती है। वे प्रायः स्व निर्णय की अपेक्षा लोकसेवक-विशेषज्ञों के परामर्श पर अधिक आश्रित रहते हैं। फिर भी उन्हें यह अवश्य ध्यान रखना पड़ता है कि उनका विभाग दलीय-कायन्म और मंत्रिमण्डल द्वारा किये गये निर्णय के अनुरूप चलता रहे क्योंकि ऐसा न करने पर उनका मंत्रीपद पतरे में पड़ सकता है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि मंत्रियों के क्रिया-कलापों पर लोकसेवकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और लोकसेवकों का सहयोग प्रशंसनीय यान को सुगमतापूर्वक चलाने के लिये बाछनीय भी है। परन्तु मंत्रीगणों की स्थिति लोकसेवकों के हाथों की कठपुतली जैसी नहीं है। नीति के निर्माता मंत्री ही हैं और लोकसेवकों को व्यवहार में उनकी इच्छा का पालन करना पड़ता है। वस्तुतः ब्रिटन में अविशेषज्ञों और विशेषज्ञों का विशेष प्रकार का मेल है। सरकारी कर्मचारी मंत्रियों को आवश्यक जानकारी एवं तथ्य प्रदान करते हैं और सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। वे शासन पर छा जाने का प्रयास नहीं करते, प्रत्युत शासन की प्रकृति व स्वरूप को बनाने में सहायक होते हैं।

7

संसद् (THE PARLIAMENT)

“चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें ब्रिटिश संविधान मण्डल संसार में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई विधान मण्डल नहीं है। इसका अधिकार-क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति असीम है।”

—मैरियट

ब्रिटेन को संसद् संसार में प्राचीनतम मानी जाती है। इसे 'संसदों की जननी' कहा जाता है। लगभग प्रत्येक प्रजातन्त्रात्मक देश ने किसी न किसी रूप में ब्रिटेन की महान समझ का अनुकरण किया है। ब्रिटिश संसद् में दो मदन हैं—लाउ-सभा (House of Lords) तथा लोकसभा (House of Commons)। इन दोनों में लाउ-सभा अधिक प्राचीन है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक लाउ-सभा लोकसभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था किन्तु शर्न शर्न उसकी शक्तियाँ घटती गयीं और आज वह द्वितीय मदन नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन बन गया है। लोकसभा को निम्न-सदन (Lower House) और लाउ-सभा को उच्च सदन (Upper House) भी कहा जाता है।

संसद् की सम्प्रभुता (Sovereignty of Parliament)

ब्रिटेन में संसद् ही सम्प्रभु है। उसकी सत्ता सर्वोपरि, असीमित और निरंकुश है। संसद् ही मारे शासन यंत्र को संचालित करती है। वह मन्त्राट को भी अपदस्थ कर सकती है। वह राजा को चुन सकती है और राजतन्त्र को समाप्त कर सकती है। एडवर्ड वॉक, डी लोमे, डायसी आदि ने संसद् की सम्प्रभुता के महान् गीत गाये हैं। वस्तुतः वैधानिक और कानूनी रूप में संसद् किसी प्रकार भी

मर्यादित नहीं है। यह किसी भी विषय से सम्बन्धित कानून बना सकती है, वैधानिक रूप से देश में स्थापित भ्रम तथा वास्तविकता के बीच अन्तर को दूर करने के लिए समर्थन देने में सक्षम है। अथवा उसे पूरा नहीं करने दे सकती है। सारांश में वैधानिक रूप में समर्थन देने में सक्षम है—चाहें हम या नहीं चाहे।

संसद की सम्प्रभुता का मूल्य

परन्तु समर्थन की यह सम्प्रभुता केवल एक कानूनी कल्पना है। इसमें व्यावहारिक पहलू की उपेक्षा कर दी गयी है। व्यवहार में समर्थन सभी कुछ नहीं कर सकती, वह हर प्रकार के कानून का निर्माण या भंग नहीं कर सकती। वैधानिक रूप से पूर्ण सम्प्रभुता सम्पन्न होने के लिए भी व्यावहारिक दृष्टि से आचार विधान और राजनीतिक-राज्यमय मर्यादों की शक्ति में बाधा आती है तथा उसकी सम्प्रभुता को सीमित बनाती है। संसदीय सम्प्रभुता व्यवहार में निर्मित होती है—

(1) जनता का विश्वास—संसदीय सम्प्रभुता पर यह सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रतिबन्ध है। विधि सम्बन्धी सारे प्रस्ताव इसी कमीटी पर किये जाते हैं कि व्यावहारिक तथा नैतिक दृष्टि से उनका महत्व क्या है? यह ध्यान रखना पड़ता है कि विधि कहीं प्राकृतिक नियमों, ज्ञान की इच्छा और परम्पराओं के विरुद्ध न हो। समर्थन मंजूर इस बात का ध्यान रखती है कि वह अपने-आपको व्यावहारिक मर्यादा में रखे।

(2) मंत्रिमण्डल की शक्ति—समर्थन का कमी और कार्य की अधिकता के कारण समर्थन अपनी अपार शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। मंत्रिमण्डल उसका नेतृत्व करता है। विधि निमाण, वित्त नियंत्रण तथा प्रशासकीय मामलों में मंत्रिमण्डल का ही बोल-बाज रहता है। जब तक मंत्रिमण्डल का सदन में बहुमत रहता है तब तक वह समर्थन का सेवक नहीं बनकर स्वामी बना रहता है।

(3) प्रवक्तृ विधान—कायभार की अधिकता और समय-समय के कारण संसद विधि निर्माण सम्प्रभु की कुछ कार्य-अवसर-आवृत्तियों को छोड़ कर अपना बोल-हल्ला करती है। कहीं कहीं राजा अपने ऐकाधिकार अधिकार के आधार पर आश्रय निकालता है, जिसे सपरिषद् आदेश (Orders-in-Council) कहते हैं। संसद ऐसे नियम भी पारित कर देती है जिसके द्वारा वह मंत्री, विभाग या किसी संस्था को अधिकार देती है कि वे आचार्य निकालें। समर्थन उन सब पर न तो पूर्ण अंकुश ही रखती है और न रख ही सकती है।

(4) निर्वाचक मण्डल—वास्तविक सम्प्रभुता संसद में नहीं, अपितु निर्वाचक मण्डल (Electorate) में निहित है। निर्वाचक मण्डल ही संसद को चुनते हैं और हटा भी सकते हैं। इन संसद को निर्वाचकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य करना पड़ता है।

(5) **संसद का अधिकार**—मसद् अपनी सम्प्रभुता और जीवन काल को स्वयं भी निश्चित कर सकती है। मसद् ने ही अपने विनियम, 1911 (Parliament Act of 1911) द्वारा अपना जीवनकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। संसद की सम्प्रभुता पर इस अर्थ में भी अकुल है कि वह अपने जीवनकाल में तब तक वृद्धि नहीं कर सकता जब तक कि गण्ट की मौन सम्मति उसके पास न हो। द्वितीय महायुद्ध काळ में राजनीतिक दलों और राष्ट्र के मौन सम्मति के बल पर ही संसद ने अपना जीवनकाल लगभग 8 वर्ष रखा था।

(6) **विवि का शासन**—ब्रिटेन में मसद् की सम्प्रभुता और विवि का शासन (Rule of Law) दोनों एक दूसरे से मिट्टे-जुलें हैं। विवि शासन का अर्थ है कि देश का आम कानून सब पर लागू होता है। किसी के नाम कोई मनमानी शक्ति नहीं है और कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं। संसद की सम्प्रभुता तभी तब महा है जब तक 'विवि का शासन' चलता है। मसद् उसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

(7) **अन्तर्राष्ट्रीय कानून**—संसद यद्यपि वैधानिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध विधियों का निर्माण कर सकती है, किंतु व्यवहार में उसे उनका आदेश करना पड़ता है। वेस्ट रैण्ड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में यह स्वीकार कर लिया गया था कि "जो कुछ मध्य राष्ट्रों ने निर्णय किया है, वह हमारे देश में भी माना जाना चाहिये।"

में कार्य करती चली आ रही है। ब्रिटेन की व्यवस्थापन प्रणाली में यह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह ब्रह्म की स्रोत-त्र पर आधारित शासन प्रणाली का एक अंग है।

लाइस-सभा की रचना

लाइस-सभा विदेश की सबसे बड़ी विधायी सभा है। इसकी सदस्य संख्या बदलती रही है। जुलाई, 1966 में इसकी सदस्य संख्या 1029 थी।

लाइस-सभा की रचना विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है जो निम्नलिखित सात श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—

राजवंश के सदस्य—यह लाइस-सभा के प्रथम श्रेणी के सदस्य होते हैं। इनकी संख्या बहुत थोड़ी लगभग 3-4 होती है। ये सदस्य लाइस-सभा की बैठक में प्राथमिकता नहीं पाते।

मानुषिक या वंश परम्परागत पीयर द्वितीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। लाइस-सभा की सदस्यता का यह सम्बन्ध भाग इसी वर्ग का है। जुलाई, 1966 में इन वंशानुगत लोगों की संख्या 853 थी। इस प्रकार के सदस्यों में सना, कला, संस्कृति अथवा गीत आदि क्षेत्रों के विविध व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसी सदस्यता वंश परम्परा में सदस्य के बड़े छद्मों की प्राप्ति होती है। इन सदस्यों की पाँच श्रेणियाँ हैं—बैरन (Baron), विस्काउण्ट (Viscount), अर्ल (Earl), मार्क्विज (Marquis), और ड्यूक (Duke)। ये पीयर पहले स्वयं राजा द्वारा बनाये जाते थे, किन्तु अब इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राजा द्वारा की जाती है। वर्तमान काल में स्थिरता में लाइस-सभा की सदस्यता हो सकती है।

धार्मिक लाइस भी लाइस-सभा के सदस्य होते हैं। ये लोग पीयर नहीं होते बल्कि धर्मगुरु (Lords of Spiritual) होते हैं। इनकी संख्या 26 होती है। इनमें से पाँच तो कैथोलिक और बाक बाकिविशेष तथा लॉटन डरहम और बिचेस्टर के बिशप होते हैं। शेष 21 पदों पर इंग्लैंड के ज्यूर (Senior) बिशपों की नियुक्ति की जाती है।

स्काटलैंड के प्रतिनिधि पीयरों का निर्वाचन सन् 1707 के स्काटलैंड और इंग्लैंड के एकीकरण कानून के उपबन्धों के अनुसार होता है। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि स्काटलैंड लाइस-सभा के लिये 16 सदस्य भेजेगा जिनका निर्वाचन स्काटलैंड के पीयर करेंगे। अब 1963 की नयी व्यवस्था के अनुसार स्काटलैंड के सभी पीयर लाइस-सभा में बैठ सकते हैं। चूँकि एकीकरण अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं थी कि नये पीयर भी होंगे, अतः पुराने पीयर धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं और एक समय ऐसा आया जब लाइस-सभा से स्काटलैंड के प्रतिनिधि पीयरों का वर्ग ही समाप्त हो जायगा।

आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर भी लाई—सभा में अब नहीं रहे हैं। सन् 1932 में आयरलैंड के स्वतंत्र हो जाने के बाद से नवीन आयरिश पीयरों का मनोनयन बंद हो जाने से इनकी संख्या निरंतर घटती गई और सन 1958 में केवल एक आयरिश पीयर रह गया तथा वह भी 1961 में चल बसा।

आजीवन पीयर 1958 की 'Life Peetrages Act' के अनुसार राजा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सरकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि कितनी संख्या तक ऐसे पीयर मनोनीत किये जावेंगे? इस दंग के अंतर्गत प्रायः वयोवृद्ध नेताओं की नियुक्ति हुआ करती है। उक्त अधिनियम का प्रयोजन यह है कि इंग्लैंड के प्रतिष्ठित नर नारियों का लाई—सभा का सदस्य बनाया जा सके। आजीवन पीयरों को कोई वेतन नहीं मिलता। उन्हें भाग व्यय अवश्य मिलता है।

विधि लाई या साधारण जपील लॉर्डों की संख्या 9 है। ये लाई जीवन भर के लिये चुने जाते हैं। इन लाई के द्वारा ही लाई—सभा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है। सन् 1876 के अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार इनकी नियुक्ति विधि-विशेषज्ञों, न्यायाधीशों आदि में से की जाती है।

लाई-सभा के सदस्यों के उक्त वर्गों का देखने से स्पष्ट है कि इसकी रचना में पत्रिकाधिकार, नियुक्ति और निर्वाचन तीनों ही सिद्धांतों का सम बराबर धिया गया है। अधिकांश सदस्य पत्रिकाधिकार अथवा वशानुगत रूप से सदस्यता प्राप्त करते हैं। स्काटलैंड के प्रतिनिधि पीयर चुनाव द्वारा सदस्य बनते हैं तो 'यार्ल्ड' और धार्मिक लाई नियुक्ति के द्वारा।

एक बार लाई बनने पर वह आजीवन इस पद और उपाधि का उपभोग करता है। उसके देहांत पर उसका ज्येष्ठ पुत्र इस पद और उपाधि का उत्तराधिकारी होता है। सन 1963 के पीयर एज एक्ट के अनुसार अब वशानुगत लाई अपनी उपाधियों का परित्याग कर सकता है और लाई-सभा के चुनाव लड़ सकता है। लाई सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से बनाए जाते हैं। सामान्यतः सम्राट के जन्म दिवस पर, नववर्ष दिवस पर तथा राज्याभिषेक और संसद-विघटन के दिवस पर इस सम्मान का वितरण किया जाता है। वैसे जब प्रधानमंत्री आवश्यक समझे, उसके परामर्श से सम्राट यह सम्मान प्रदान कर सकता है। लाई बनाए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

विधेयाधिकार और नियोग्यतायें

लाई-सभा के सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति करने, संसद के अधिवेशन बुलाने, सदन के बहुमत दल के निधियों के विरुद्ध संसद् की पत्रिकाओं में लिखित विरोध प्रकाशित करने आदि के विधेयाधिकार (Privileges) हैं, साथ ही उनकी कुछ नियोग्यतायें (Disabilities) भी हैं, जैसे—उह संसदीय चुनाव में मनाधिकार

प्राप्त नहीं है, वे लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्यागी के रूप में गठे नहीं हो सकते, आदि। 1963 के पीयरएज गेट के वन जान के बाद उपाधि का परित्याग करके लोकसभा की सदस्यता निवाचा द्वारा ग्रहण की जा सकती है। पीयरएज का एक बार परित्याग कर देने पर निर्णय बापिम नहीं लिया जा सकता। मसौदा वाद के लिए पीयरों को कोई वतन नहीं मिलता, किंतु यदि वह सब बैठका में से एक तिहाई बैठकों में शामिल हो तो उन्हें यात्रा व्यय दिया जाता है।

मणपूर्ति और वाप-प्रणाली

मसदा के दोनों सदनों का प्रारम्भ और मश्रावनाय माय माय ही होता है। लाउ सभा का अधिवेशन सप्ताह में केवल चार दिन—मोमवार से गुरुवार तक होता है और वह भी लगभग 2 घण्टे प्रतिदिन। सदन में उपस्थिति बहुत ही कम होती है। मस 1957 के सुधार अधिनियम के परिणामस्वरूप अब औसतन उपस्थिति 120 हो गई है। सभा के कोरम की पूर्ति केवल 3 सदस्यों की उपस्थिति से ही जाती है। विधि पारित करते समय 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

लाउ सभा के विवाद प्रायः उच्च-स्तरीय होते हैं। इसकी समिति पद्धति लोकसभा की समिति पद्धति से सरल है। एक समिति तो पूरे सदन की है और दूसरी एक स्थाई समिति है जो प्रथम समिति द्वारा पारित विषयों का सन्तोषन लाती है। सभा की समकालीन और प्रवर समितियाँ भी होती हैं जो विवाद प्रकार के मामलों पर विचार करती हैं। स्थाई समितियों और समापन प्रस्ताव (Closure Motion) की व्यवस्था नहीं है। केवल दो स्थाई आदेश (Standing Orders) हैं। एक के अनुसार कोई भी सदस्य एक ही विषय पर दो बार भाषण नहीं दे सकता। दूसरे आदेश के अधीन वाद-विवाद विषय से जलम अथवा असम्बद्ध नहीं हो सकता।

समूह (लाउ सभा का पदाधिकारी)

लाउ-सभा का महापतित्व लाउ चांसलर (Lord Chancellor) करता है। वह वूल सैक (Wool-sack—लाउ चांसलर की विशिष्ट गद्दी) पर बैठकर वाकवाहियों का निर्देशन करता है। पदेन सदन का अध्यक्ष (Speaker) होता है। राजा की तरफ से कुछ अथवा एम पीयरों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करने हैं। उह उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) कहा जाता है। लाउ चांसलर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राजा द्वारा की जाती है। सदन में अनुत्तममन सम्बन्धी अधिकार पूरी सभा का प्राप्त है, न कि लाउ चांसलर का। मस्यमण समापति को नहीं बल्कि सदन को सम्बोधित करके गवाय 'माय लार्ड्स' (My Lords) कह कर अपने भाषण शुरू करते हैं। लाउ चांसलर का निर्णायक मत देने का अधिकार भी नहीं होता। उनकी पक्षिमा लोकसभा के अध्यक्ष की समितियों से बहुत ही कम है।

वित्त विधेयक है या नहीं। लाइसेंस-सभा की धन विधेयको में सशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित होने के एक माह उपरांत धन विधेयक निश्चित रूप की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है, चाहे लाइसेंस-सभा उस स्वीकार करे या न करे। यदि लाइसेंस-सभा किसी वित्तीय विधेयक को मशायित करके भेजे तो भी लोकसभा को यह अधिकार है कि वह उन सशोधनों को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे।

जहां तक अन्य विधेयकों का सम्बन्ध है, वे किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यद्यपि आजकल महत्वपूर्ण विधेयक अधिकांशतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, किन्तु अनेक अवसरों पर वे लाइसेंस-सभा में भी प्रस्तुत किए गए हैं और उन पर उसने बड़ा उपयोगी कार्य किया है। लोकसभा लाइसेंस-सभा द्वारा प्रस्तावित मशायतों को औचित्य के कारण ही स्वीकार करती है, अथवा अंतिम निर्णय लोकसभा का ही चलता है। सन 1949 के सशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि लाइसेंस-सभा लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को (Other than Money Bills) केवल एक बार अस्वीकृत कर सकती है, पर यदि लाइसेंस-सभा द्वारा अस्वीकृत ऐसे विधेयक को लोकसभा दूसरी बार पारित कर देती है, और इसी मध्य एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति के पदचान्दान बन जाता है, चाहे लाइसेंस-सभा न उसे स्वीकार किया हो या नहीं किया हो। एक वर्ष के समय का हिसाब लगाने की व्यवस्था यह है कि वह विधेयक के पहिले पारायण (Reading) के दूसरे पावन की तिथि से लेकर उसके दूसरे पारायण के तीसरे पावन की तिथि तक लगाया जाता है। पहिले 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लाइसेंस-सभा का यह अधिकार था कि वह सारे विधेयकों (Other than Money Bills) को दो वर्ष तक रोक रखे।

स्पष्ट है कि लाइसेंस-सभा की स्थिति आज देर करने वाली सभा की है, अथवा उसके पास विधि निर्माण मन्त्र की अधिकार नहीं है। फिर भी वह अपने सम्मोच विधेयकों के सम्बन्ध में अपना विचारों के अनुरूप सरकार और जनता को प्रभावित निश्चित रूप से करती है।

संविधानीय नियमों तथा आदेशों पर विचार

विधेयक सम्बन्धी लाइसेंस-सभा का एक अन्य कार्य संविधानीय उपनियम तथा आदेशों (Statutory rule and orders) पर विचार करना है। प्रायःपालिका अधिनियमों को संसदीय अधिनियमों के अन्तर्गत विरक्त नियम और उपनियम मानने का अधिकार है तथा लाइसेंस-सभा उनकी संपादितता की जांच करती है। 1947 में लाइसेंस-सभा के इस अधिकार के विरुद्ध कुछ आचार्य उगाई गई थीं, किन्तु यह दावित था और जिन जांच की बार्ड प्रभावशाली बाध नहीं करी।

लॉर्ड-सभा के पक्ष और विपक्ष में तर्क

(Arguments for and against the House of Lords)

लॉर्ड-सभा शक्ति एवं प्रभाव के विचार में आज अपना महत्व खो चुकी है। जनतन्त्र के विकास के साथ-साथ लॉर्ड-सभा की शक्ति के अत्यधिक बढ़ जाने से प्रायः यह प्रश्न उठना रहता है कि, जहाँ लॉर्ड-सभा की आवश्यकता क्या है? अनेक राजनीतिज्ञ लॉर्ड-सभा का समूल नाश करना आवश्यक समझते हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था में उसका अस्तित्व असंगति के रूप में है।

लॉर्ड-सभा के विषय में हमारा मत यह है कि हमका बना रहना तो आवश्यक है, परन्तु इसका सुधार होना चाहिए। अधिकतर जनता का मत भी यही है।

लॉर्ड-सभा के विपक्ष में मत

लॉर्ड-सभा का विरोध सबसे अधिक मजदूर दल का है। मजदूर दल में प्रायः साइज (Sicys) का यह कथन दोहराया जाता हुआ सुना जाता है कि "यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो उपद्रवी है, और यदि सहमत होता है तो व्यर्थ है।" जे आर क्लायन (J R Clynes) के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि "लॉर्ड-सभा एक ऐसी सस्था है जिसको ठीक में सुधार नहीं जा सकता। उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

हमें देवना चाहिए कि इतनी पुरानी सभा आज किस आलोचना का शिकार बन रही है—

(1) अप्रजातांत्रिक—लॉर्ड-सभा अप्रजातांत्रिक है, जिसके लगभग 90 प्रतिशत सदस्य बड़े-बड़े जागीरदार और कुलीन घराने के व्यक्ति हैं। ये सदस्य निर्वाचित नहीं होते बल्कि अशानुगत रूप में सदस्यता प्राप्त करते हैं। सगठन की दृष्टि से उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता। उसमें केवल धनी माने और उच्च व्यापारिक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व है। ऑगस्टाइन बिरेल (Augustine Birrell) के शब्दों में "लॉर्ड-सभा अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती।"

(2) धनिया व निहित स्वार्थों का बंध—लॉर्ड-सभा धनियों और निहित स्वार्थों का बंधन है, जिसमें माना निहित सम्पत्तियों के मन्त्रालयों का प्रधान स्थान मिले हुए है। लॉर्ड-सभा वस्तुतः महान उद्योगों और व्यापारिक सत्त्वानों द्वारा नियंत्रित है। फाक्टर के अनुसार "लॉर्ड-सभा धन एवं विशेषाधिकार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि बड़े तो मध्य धन और विशेषाधिकार का दुर्ग है।"

(3) एक दल की प्रभुता—लॉर्ड-सभा में सदस्य कन्ट्रिब्यूटरी दल का ही प्रभुत्व बना रहता है। जबकि सामाजिक विचारों और नीतियों के अनुसार दलीय स्थिति में परिवर्तन होते रहना लोकतन्त्र की एक प्रमुख विशेषता है। जतिम न लॉर्ड-सभा को अनुदार दल की जगह बड़ा है। आम निर्वाचनों में चार-पाँच भी दल की जीत

हो, लाड सभा पर नियंत्रण प्रतिगामी तत्वों का ही बना रहता है क्योंकि सदस्यता का मुख्य आधार निर्वाचन नहीं, उत्तराधिकार है। यही कारण है कि जब शासन-सत्ता रुढ़िवादी दल के हाथ में होती है तो लाड सभा हर बात में लोक सभा का समयन करती है किन्तु जब सरकार अथ किसी दल की होती है तो यह लोकसभा के प्राय सभी कार्यों का विरोध करती है। मैरियट (Marriot) के शब्दा में "जब रुढ़िवादी दल की सरकार होती है तो लाड-सभा गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अथ अवसरों पर खूमार भेड़िये की तरह।"

(4) सदस्यों की अधिकता व उदासीनता—लाड सभा की कार्यप्रणाली में भी कई दोष हैं। सदस्यों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमें से अधिकांश सभा की कार्यवाही में भाग लें तो कार्य-संचालन ही कठिन हो जाए। पर इससे भी बड़ा दोष यह है कि व्यवहार में सभा के अधिकांश सदस्य इसकी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं और अपने विधायी कर्तव्यों के प्रति कोई रुचि प्रदर्शित नहीं करते। सन् 1919 के बाद केवल 12-13 अवसर ही ऐसे आय हैं जहाँ उपस्थित सदस्य संख्या 200 से अधिक रही है। आलाचको का तब है कि जब लाड सभा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागृत नहीं है तो उसे बनाये रखने का कोई लाभ नहीं है।

(5) दोषपूर्ण ससदीय प्रक्रिया—मदन की गण-पूर्ति (Quorum) केवल तीन सदस्यों से हो जाती है जबकि लोक-सभा की गण-पूर्ति की संख्या 40 (धालीस) है। विषय के किसी भी द्वितीय सदन के इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में सभा की कार्यवाही नहीं चला सकती। इनके अतिरिक्त लाड-सभा का संगठन और अनुशासन भी दोषपूर्ण है। सभा के अध्यक्ष को सदस्यगणों की अनुशासित करने का अधिकार नहीं है। किसी भी मस्य के विरुद्ध अध्यक्ष नहीं, वरन् पूर्ण सदन ही कोई कदम उठा सकता है। इसी कारण आलोचकों ने इसे एक नियमबद्ध सदन नहीं, बल्कि एक 'गड़बड़ घोटाला' सदन कहा है।

(6) विधायी और कार्यकारी शक्तियों की निरर्थकता—लाड-सभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि मात्र-मण्डल केवल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी उसकी उद्योति अत्यन्त फीकी है। फिर एक पक्षीय एवम् प्रतिस्पर्धावादी स्वरूप के कारण इसके विधि सम्बन्धी सुझाव प्रायः व्यावहारिक एवम् अप्रगतिशील होते हैं। इसी कारण लास्की इस सभा को उठा देने के पक्ष में हैं।

(7) देर लगाने की शक्ति हानिवारक—लास्की एवम् लेंसडान (Laski and Lansdowne) आदि आलोचकों को कहना है कि लाड सभा कार्य को ठीक से नहीं कर रही है। यह विधेयक-अवरोध की शक्ति का प्रयोग करने में निष्पक्ष नहीं रहती। लाड-सभा के सदस्य सदैव अनुदार दल का समयन करते हैं और मजदूर दल का विरोध। लाड-सभा की यह अवरोधन शक्ति कभी कभी तो अत्यन्त आक्षेप-

जाक हो जाती है योफि इसका प्रयोग पूर्णतः पक्षपात और दृष्टान्तवादी विधि जाना है। सर्वदलील मालूम मना अपनी इस गति का दुरुपयोग के कारण सरकार का कुछ समय के लिये पशु बना देती है। अतः लाउ-सभा की विलम्बकारी गति हानिकारक है।

(8) विधेयको दोहराने की शक्ति आचार्यक—लाउ सभा का एक नाम लोकसभा के उदात्तलपन को रोकना और विधेयको को बाहराना है। परन्तु लाउ सभा उनके इस कार्य की आलोचना दो कारणों से करता है। प्रथम तो, लाउ सभा अपनी इस शक्ति का प्रयोग सर्वदा अनुदार दल की उपेक्षा में करती है और दूसरे, लाउ-सभा एक निष्पक्षित सदन नहीं है, अतः उनके विरोध को जनता का अनुमति नहीं रहती। इसके अतिरिक्त आज के प्रजातान्त्रिक युग में समस्त विधेयक प्रस्तुत करने के पछि दल-यंत्र के द्वारा जनमत का मान प्राप्त कर लिया जाता है तथा रडियो, टेलीवीजन प्रेम आदि साधनों द्वारा उस पर काफी धारा-विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाउ-सभा द्वारा विधेयको को बाहराने का कार्य अनावश्यक और गति का कारण अपव्यय है।

लाउ-सभा का पक्ष

लाउ-सभा की आलोचनाओं से यही लगता है कि यह एक व्यय सदन है जिसे समाप्त करना चाहिए, किन्तु ऐसा मोचना ठीक नहीं है। इंग्लैंड में जन साधारण का और राजनीतिज्ञों का मन यही रहा है कि लाउ-सभा का अस्तित्व तो बना रहे पर इसके मगठन में समयानुवृत्त परिवर्तन की व्यवस्था कर दी जाय। समय समय पर जो सबदलीय सम्मेलन हुए हैं उनमें भी यही निश्चय दोहराया गया है कि लाउ सभा में सुधार करके इसे जीवित रखा जा सकता है। यहाँ हम उन आचार्यों का लेंगे जो लाउ सभा को बनाए रखने के पक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(1) लोकतन्त्र की सुरक्षा—लाउ-सभा लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि व्यवस्थापन पर किसी एक संस्था अथवा दल का एकाधिकार नहीं रहे और लोगों की स्वतन्त्रता एवं उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी बनी रहे। लोकतन्त्र की भाव है कि व्यवस्थापिका द्विमतान्तरण है और एक गद्द के व्यवस्थापन काय की दृष्टिसे दूसरा सदन करता रहे। लाउ-सभा की आवश्यकता इसलिए भी है कि ब्रिटन में अमेरिका की भांति न तो 'जुडिशियल पुनर्विचार' (Judicial Review) की व्यवस्था है, न संविधान रूढ़ि की तरह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है और न ही रिटजरतड के जनमत संग्रह का प्रावधान है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के अभाव में यह आवश्यक है कि एक सदन की सत्तासाही का शक्ते के लिए दूसरे सदन को बनाए रखा जाय।

उत्प्रेक्षणीय है कि प्रॉमवेल्स ने कुछ समय के लिए लाउ-सभा का समाप्त किया था लेकिन हमने बिना यह काम नहीं खला सारा और उसने लाउ-सभा की पुनर्स्थापना की। पुनश्च, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि संसार के अधिकांश

लोकतन्त्रात्मक देशों के विधानमण्डलों में दो सदन की ही व्यवस्था की गयी है। जिन देशों में प्रारम्भ में दो सदन नहीं थे वयना बहादुर बाद में द्वितीय सदन को उठा दिया गया था, वहाँ हमारे सदन को पुनः स्थापित किया गया है।

(2) लोकसभा के जोश और उत्साहपूर्ण परीक्षण—लाउ-सभा इस दृष्टि से विशेष उपयोगी है कि यह लोकसभा के उद्देश्यों और जाति को नियंत्रित करती है तथा उसकी असुविधा पर राय उठाती है। राय की अविश्वस्यता, समय की कमी, दलगत दबाव, कानूनी कार्रवायों के कम जान, आदि के कारण लोकसभा के सदस्य विधेयकों पर पूरी तरह चाद-बिबाद और विचार विमर्श नहीं कर पाते। किन्तु लाउ-सभा के सदस्य अपने विस्तृत और लम्बे अनुभव के कारण गलत माग पर जाती हुई लोकसभा का सही माग दर्शन कर सकते हैं। जॉर्ज एव जिंक (Ogg and Zink) का विचार है कि अनेक अवसरों पर द्वितीय सदन ने राष्ट्रीय रक्षा की व्याख्या प्रथम सदन से अधिक ठीक की है और कई बार देश को जल्दबाजी एवं दम सोच विचार पूर्ण कानूनों से बचाया है।

(3) विधि निर्माण में सहायक—विधि निर्मात्री सदन का रूप में लाउ सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य विधेयक पहले लाउ-सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं और लोकसभा प्रायः सामान्य चाद बिबाद के बाद ही उन्हें पारित कर देती है। इस तरह लोकसभा के समय की बचत हो जाती है और उसका काम भी हल्का हो जाता है। लाउ सभा निजी विधेयकों के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। लाउ सभा का पारित समय रहता है, अतः ये निजी विधेयकों की पूर्णता से परीक्षा कर सकते हैं और सदन की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। यदि लाउ-सभा का उद्देश्य कर दिया जाय तो लोकसभा का कार्य बहुत अधिक, प्रायः दुगुना हो जाएगा जिसे वह सम्भवतः नहीं कर सकेगी।

(4) योग्यता का अन्वेषण—लाउ-सभा एक गुणवत्त सदन है जिसमें आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक प्रतिभा वाले व्यक्ति सदस्य होते हैं। देश की सेवा के प्रमुख सभासद करते हैं, जिन्होंने उसकी समृद्धि का बनाया है, उसके महान् साम्राज्य का प्रबन्ध किया है और कूटनीति और शासन, युद्ध, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्राप्ति की है। अपनी विशाल योग्यता के उल पर लाउ सभा सच्चे अर्थों में लोकसभा का पोषणालय (Nursery) है। फाइनर (Finer) ने लिखा है कि लाउ सभा के सदस्य पक्षपात पूर्ण राजनीति से परहेज कर अपनी मेवाएँ अर्पित करते हैं। उनके लिए यह सम्भव इसलिए है क्योंकि वे सामान्य निर्वाचन पर आश्रित नहीं रहते और लोकसभा के सदस्यों की तरह कार्यभार से दबे न रहने के कारण उन्हें सोच विचार का पर्याप्त समय मिलता है।

राजनीतिज्ञों का मत है कि राजा लाउ सभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करके अपने अधिकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को लाउ बनाएँ, जो देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, विद्वान और वैज्ञानिक हो तथा निष्पक्ष रहकर देश की सेवा करने

की क्षमता रखते हो। यदि ऐसा किया गया तो लार्ड-सभा नि सदेह एक ऐसी मस्या बन जाएगी जो देश की महान् सेवा कर सकेगी और आलोचना का पात्र नहीं रहेगी।

लार्ड सभा के सुधार के सुझाव

(Proposals for Reform of the House of Lords)

पक्ष और विपक्ष का कसौटी पर कमाने के उपरांत निष्पत्ति यही निकलती है कि लार्ड-सभा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसमें आवश्यक सुधार लाए जाने चाहिए। लार्ड-सभा के बहुत आलोचक मिडनी एवं वेब भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यद्यपि एक आदर्श विधान सभा में लार्ड-सभा के लिए कोई स्थान नहीं तथापि लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को किसी न किसी के द्वारा दुहराया जाना तथा सतुलित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त कारणों से ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का ध्यान लार्ड-सभा को मिटाने की जगह सुधारने की ओर अधिक आकर्षित हुआ है तथा समय समय पर हम सम्भव है अनेक सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(1) वंश-परम्परानुसार पीयर बनाने की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। उसके स्थान पर राजा को चाहिए कि वह योग्य और अतिशय प्रतिभावान व्यक्तियों को लार्ड-सभा का आजीवन सदस्य नियुक्त करे तथा इस कार्य में एक निर्वाचित समिति से सहायता ले।

(2) वर्तमान पीयर अपने में से कुछ को निश्चित मर्यादा में लार्ड-सभा का प्रतिनिधि चुन दें। धीरे धीरे इनका प्रतिनिधित्व हो जायगा और एक समय ऐसा आयेगा जब वंशानुगत पीयर बग ही नहीं रहेगा।

(3) सदस्यों को कुछ निश्चित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये और पारिश्रमिक की मात्रा उनकी उपस्थिति पर निर्भर होनी चाहिये। ऐसा होने से सदस्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सज्जित हो जायेंगे।

(4) सदस्यों को यह छूट होनी चाहिये कि वे लोक-सभा का सदस्य बनने के लिये लार्ड-सभा की सदस्यता का परित्याग कर सकें।

(5) इस प्रकार की व्यवस्था हानी चाहिये कि लार्ड-सभा विधेयकों को केवल निश्चित समय के लिये ही रोकने का अधिकार रखते हुए भी व्यवस्थापन कार्य में महत्वपूर्ण भाग ले सके और लोकसभा की सज्जित सहायिनी बन सके।

ऊपर केवल प्रमुख सुझावों को गिनाया गया है जो समय समय पर लार्ड सभा के सुधार के लिए दिए जा चुके हैं। जहाँ तक इनके इतिहास का प्रश्न है, उन पर अनेक समितियों, आयोगों और सम्मेलनों द्वारा अब तक विचार किया जा चुका है। इनमें रोज़बरो समिति, लायड जॉज आयोग, व्राइस आयोग, आदि प्रमुख हैं। सुधारों के अब तक के इतिहास ने यही प्रकट किया है कि जनता लार्ड-सभा

के विपक्ष में नहीं बरन् उसमें सुधार लाने के पक्ष में हूँ। यदि निरंतर प्रयास करने पर भी लाउ-सभा का पुनर्गठन नहीं हो पाया है तो इसके कुछ मुख्य कारण ये रहे हैं—

(i) ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में अभी तक यह समझौता नहीं हो सका है कि लाउ सभा का सुधार जिस आधार तथा विन सिद्धांतों के ऊपर किया जाए।

(ii) अभी तक कोई भी सतोपजनक सुधार योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

(iii) ब्रिटिश जीवन में परम्पराओं का भारी महत्व है और जिस प्रकार सविधान में परम्पराओं की जमेद्य स्थिति है, वही लाउ-सभा के सम्बंध में भी है।

(iv) राजतंत्र में द्वितीय सदन को पूर्ण सतोपजनक आधार पर बनाना एक कठिन कार्य है।

(v) लाउ-सभा की शक्तियाँ पहले ही अत्यधिक क्षीण हो गयी हैं, अतः उसमें सुधार करने के साथ-साथ उसकी शक्तियों का पुनर्जीवित करने का कठिन प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।

लोकसभा

(House of Commons)

लोकसभा सभार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। इंग्लैंड के व्यवस्थापक अंग के रूप में यह इतना महत्वपूर्ण है कि बोलचाल में हम उसे प्रायः ससद् का पर्यायवाची मान लेते हैं।

लोकसभा की रचना

सन् 1948 के प्रतिनिधित्व सम्बंधी कानून के पारित होने के बाद से लोकसभा अब पूर्णतः एक प्रतिनिधि-सभा हो गई है। 1955 से इसकी कुल सदस्य संख्या 630 रही है जिसमें इंग्लैंड से 511, वेल्स से 36, स्कॉटलैंड से 71 तथा उत्तरी आयरलैंड से 12 प्रतिनिधि होते हैं। सभी सदस्य पृथक्-पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों से "एक व्यक्ति एक मत" के आधार पर वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों को निश्चित वेतन मिलता है, साथ ही मुफ्त रेल यात्रा करने की सुविधा भी मिली हुई है। उनकी सदस्यता ससद् के कार्यकाल के साथ-साथ चलती है।

सदस्यता के लिए योग्यता

ब्रिटिश राज्य के सभी स्त्री-पुरुष, चाहे वे साम्राज्य के किसी भी भाग में निवास करते हों निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं बशर्ते कि—

(i) उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में हो,

(ii) उनकी आयु नियमानुसार हो, एवं

(iii) वे राष्ट्र तथा देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो।

परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति लोकसभा की सदस्यता के योग्य नहीं हैं—

(i) जो लाइसेंस-सभा के सदस्य हैं, किन्तु अभी हाल ही के एक नियम के अनुसार लाइसेंस-सभा का सदस्य लाइसेंस त्याग कर लोकसभा के लिए अब चुनाव लड़ सकता है।

(ii) जो नावालिग है।

(iii) जो विदेशी, पागल दिवालिया या फौजदारी कानून के अनुसार दण्डित है।

(iv) जो पादरी, नगरो के मेयर और जार्जटियों के सेरिफ ह।

(v) जो नाउन से वेतन पाने वाले तथा राजकीय सेवा में नियुक्त व्यक्ति हैं।

(vi) जो सरकारी ठेका या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा रक्षित होते हैं।

लोकसभा का कार्यकाल

सामान्यतः ब्रिटिश लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष है। लेकिन एक तो इसे मकट-ताल में बढ़ाया जा सकता है और दूसरे राजा को विशेषाधिकार है कि वह प्रधानमन्त्री की प्राथमता पर अवधि के पूर्व भी उसे भंग करदे।

उत्पत्ति

संसद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और संसद का अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक की अवधि में किसी भी सदस्य का दीवानी मामले में बन्दी नहीं बनाया जा सकता। संसद में सदस्यों का भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। उनका द्वारा कहा गया कोई भी शब्द किसी कानूनी प्रावधानों का विषय नहीं बनाया जा सकता।

लोकसभा का संगठन (पदाधिकारी आदि)

नई संसद चुनाव के लगभग दो सप्ताह के भीतर ही जुलाई की जाती है। जब पहली बार संसद बुलाई जाती है तो लाउड-सभा (House of Lords) का एक सदस्यवाहक जिसे "जेंटिलमन अफ़र आफ़ दी ब्लैक रॉड" (Gentleman Usher of the Black Rod) कहते हैं, संसदसभा का सदन में "लाउडसभा में जाने के लिए कहता है। वहाँ पर लाउड चाणक्य लाउडसभा के सदस्यों का अपना अध्यक्ष (Speaker) चुनने के लिए कहता है। अध्यक्ष का जतिरिक्त सदन में अन्य पदाधिकारी भी चुन जाते हैं। इन संसद के अधिवारियों में गणना समिति का अध्यक्ष (Chairman of the Committee of the ways & means), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) प्रमुख होते हैं। उपाध्यक्ष गणनीय अधिवारियों में गणना का क्लर्क (Clerk of the House) व सर्जेंट अट आर्म्स (Sergeant at arms) चैपलैन (Chaplain) प्रमुख होते हैं। गणना समिति के सदस्य हैं। यह गणना की जायजा पर हस्ताक्षर करता है, लाउडसभा में आता है व लाउडसभा का भवन

जाने वाले विधेयको को पृष्ठांकित (Endorse) करता है, सदन को वाचवाही का लेखा रखता है और सरकारी पत्रिका (Official Journal) का अध्यक्ष की सहायता से तैयार करता है। सांजेंट एट आम्स का नाम सदन की आन मान व शान को बनाए रखना है। वह सदन की सब आज्ञाओं का लागू करवाता है। द्वारपाल एवं मदगवाहनों का सदन देता है तथा सदन के अधिपत्र (Warrants) पर अमल करता है।

लोकसभा की गणपूर्ति (Quorum) 40 सदस्यों से होती है। प्रचलित पद्धति के अनुसार लोकसभा का बप म कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होता है क्योंकि कुछ आवश्यक विधेय एक बार में केवल एक ही बप के लिए पास किए जाते हैं।

लोकसभा की बैठकें व कायवाही सम्बन्धी कुछ प्रमुख नियम

संसद की बैठकें वेस्ट मिनिस्टर भवन (Palace of the West Minster) में होती हैं। दोनों सदन अलग अलग बैठते हैं। कुछ विरोध अवसरों पर दोनों सदन की संयुक्त बैठक भी होती है, जैसे संसद् के उद्घाटन के समय तथा राजकीय मददों, भाषणों आदि का सुनने के लिए। लोकसभा की बैठकें सप्ताह में प्रथम 5 दिन होती हैं। शनिवार को साधारणतया बैठक नहीं होती। मकटकाल में संसद् का कभी भी आमंत्रित किया जा सकता है।

लोकसभा की कायवाही अधिकांशतः परम्परा और अवसर पर आधारित है। फिर भी कुछ स्थायी आदेश हैं जिनमें सदन को सुचारु रूप से चलाने के नियम हैं। सरकार और विरोधी दल की व्यापकता भाग का समन्वय कराने के उपाय भी इन स्थायी आदेशों के अन्तर्गत हैं।

वाद विवाद मसद् का प्रमुख काय है। समय की बचत के दृष्टिकोण से हम पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और वाद विवाद के प्रारम्भ व समापन के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। प्रथम तो विरोधी और मन्त्रालय दल के सदस्यों के बीच समन्वय हो जाता है कि किस विषय पर कितना समय दिया जाए? यदि ऐसा समन्वय नहीं हो पाता तो अवरोधक (The Closure), विभाजन अवरोधक (The Closure by Compartments), कंगारू समापन (Kangaroo Closure), गिलोटिन (The Guillotine), कार्यक्रम (The time Table), विभाजन (Division) आदि उपायों द्वारा वाद विवाद का समापन किया जा सकता है। वस्तुतः वाद-विवाद सदन का आवश्यक और महत्वपूर्ण काय है। एक दृष्टि से तो यह काय विविध निम्न या वित्तीय नियंत्रण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। विनियोग और राजस्व सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकारी नीतियों की व्यापक आलोचना होती है। यदा कदा स्थान प्रस्ताव जयन्ता कामरोको प्रस्ताव द्वारा सावजनिक महत्व के प्रश्न पर बहस प्रारम्भ की जाती है। इंग्लैंड जैसे देश में वाद विवाद लोकतन्त्र के प्राण है।

लोकसभा की शक्तियाँ और उसके कार्य

(Powers and Functions of the House of Commons)

ब्रिटिश लोकसभा की शक्तियाँ महान् हैं। प्रायः कहा जा सकता है कि इसकी शक्ति और महत्ता पर अधिक चोटलाना सूर्य को दीपक दिसलाना है। किन्तु इतना यथागान सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक कम। हमें ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का भेद प्रतीत करना है।

लोकसभा के व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार व कर्तव्य

ब्रिटन में संसद् का अर्थ है राजा, लार्ड-सभा एवं लोक-सभा। निम्न व्यवहारतः इसकी शक्तियों का उपयोग लोकसभा ही करती है क्योंकि लाकनिश सम्प्रभुता उसी में निहित है। लोक सभा ही मूलतः व्यवस्थापिका संस्था है जिसे साधारण और मासिकानिष दाना प्रकार के कानूनों के निर्माण करने का अधिकार है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में अंतिम निर्णय लोकसभा का ही चलता है। लार्ड-सभा केवल विधेयकों के कानून बनने देने में कुछ विलम्ब कर सकती है। धन विधेयकों पर लार्ड-सभा को केवल 1 महीना और साधारण विधेयकों पर 1 वर्ष का स्थगन-निषेधाधिकार प्राप्त है। राजा की स्वीकृति देने की शक्ति औपचारिक मात्र है। लोकसभा देश के प्रत्यक्ष स्थान, वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। उसकी शक्ति पर मासिक पुनर्विचार जैसा कोई बंधन नहीं है।

लोकसभा की व्यवस्थापन शक्तियों का यह पक्ष सैद्धांतिक अधिक है। क्योंकि उसकी व्यवस्थापन शक्तियाँ व्यवहारतः मंत्रीमण्डल के हाथों में पहुँच गई हैं, परन्तु यह अवश्य है कि मंत्रीमण्डल लोकसभा पर केवल तब छाया रहता है जब तक वह लोकसभा के बहुमत दल का विश्वासपात्र है।

लोकसभा के वित्तीय अधिकार व कर्तव्य

राष्ट्रीय वित्त पर लोकसभा का एकछत्र नियंत्रण है। वित्तीय विधेयकों की स्थापना लोकसभा में ही हो सकती है। उसका ही प्रवर्तन के सम्बन्ध में एकाधिकार प्राप्त है। लार्ड-सभा दिन-विधेयकों को अधिक से अधिक एक माह के लिये विरामित कर सकती है।

परन्तु वित्तीय क्षेत्र में भी लोकसभा की शक्तियों का व्यावहारिक महत्त्व दूरा है। राजकीय बजट का विभाग मंत्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री (Chancellor or Exchequer) द्वारा ही उस गणना में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी वित्तीय विधेयक राजमण्डल की विचारणा पर ही लाया जाना ही होता है और राजमण्डल की विचारणा, व्यवहार में मंत्रीमण्डल की ही विचारणा होती है। जब तक राजमण्डल की शक्ति में मासिकता की गई हो, वह न तो कोई वित्तीय कानून बना कर सकती है और न कोई कर ही लगा सकती है। बजट

पेश हो जाने के बाद भी लोक सभा को उसमें कटौती करने या उसे अस्वीकार करने का ही अधिकार है। वह अपनी ओर से व्यय में कोई वृद्धि नहीं कर सकती और न कोई नवीन व्यय या कर प्रस्तावित कर सकती है। मन्त्रिमण्डल दलीय बहुमत के कारण किसी भी वित्तीय विधेयक या बजट को प्रायः उसी रूप में पारित करा लेता है, जिस रूप में वह उसे प्रस्तुत करता है।

फिर भी लोकसभा राष्ट्रीय वित्त का विभिन्न तरीकों से नियमित करती है, जैसे अर्थोपाय अथवा उपायों और साधनों की समिति (The Committee of the Ways and Means) में वाद विवादों तथा वित्तीय अधिनियम (Finance Act) द्वारा धन एकत्र करने पर नियंत्रण रखती है, मक्काई समिति (Appropriation Act) और कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के द्वारा धन के विनियोग पर नियंत्रण रखती है, सावजनिक हिसाब-किताब की समिति के द्वारा हिसाब किताब की जांच करती है और प्रश्नों एवं वाद विवादों के द्वारा व्यय करने के तरीकों की आलोचना करती है।

लोकसभा का कायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं कर्तव्य

मन्त्रिमण्डल के हाथ में कायपालिका सम्बन्धी इतनी शक्तियाँ हैं कि यदि उसे नियमित न किया जाये तो वह तानाशाह बन सकता है। इसीलिए लास्की ने लिखा है कि, "सरकार बनाना तथा उसे राज-काज करने का नियमित अधिकार प्रदान करना या न करना लोकसभा का ऐसा प्रमुख कार्य है जिस पर अन्य सब कार्य निर्भर करते हैं।" लोकसभा यदि सरकार को प्रशासन काय चलाने के लिए आवश्यक नियमित अधिकार प्रदान न करे और उसे अपना आवश्यक समर्थन न देती रहे तो सरकार का काम चलना अमभव हो जायगा और सम्पूर्ण प्रशासन यत्र ठप्प पड़ जायेगा। मैदातिक रूप से मन्त्रिमण्डल की स्थिति लोकसभा की एक समिति जैसी है। लोकसभा प्रश्न, आलोचना, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास, वित्तीय अधिकार आदि विभिन्न साधनों से उसे नियमित करती रहती है तथा उसके कार्यों का निरीक्षण करती है।

पर इस क्षेत्र में भी व्यावहारिक दृष्टि से लोकसभा बहुत हद तक मन्त्रिमण्डल के हाथ में विलीन है। दलीय अनुशासन और बहुमत के कारण मन्त्रिमण्डल लोकसभा पर छाया रहता है और उसमें अपनी इच्छानुसार प्रत्येक विधेयक पारित करवा लेता है। व्यवहार में नीति निर्माण सम्बन्धी अधिकांश विषय मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किये जाते हैं, लोकसभा की स्वीकृति केवल औपचारिक होती है। इसके अतिरिक्त लोकसभा मन्त्रिमण्डल से कुछ मामलों की जानकारी मात्र ही प्राप्त कर सकती है। लोकसभा के कटौती प्रस्तावों या स्थगना और अविश्वास प्रस्तावों का भी व्यावहारिक महत्व अधिक नहीं है क्योंकि लोकसभा को अधिकांशतः वही करना पड़ता है जो मन्त्रिमण्डल चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में भी सदस्यों को यह भय

रहता है कि कही प्रधानमंत्री राजा से कहकर राजाभा का ही भग बरा दे और इस प्रकार उह पुन असमय म ही, निवाचना ही दया ना भित्तारी बना द ।

लोकसभा द्वारा जनता की शिक्षाओं का निवारण

लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि है । व जनता की शिक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, और उनका निवारण करने के लिये उसे बाध्य करते हैं । वास्तव में लोकसभा का विराधी-दल जनता को स्वतंत्रता का रक्षक है । सदस्य विचारकर, विराधी दल के सदस्य, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं । ये प्रश्न डाकघर के किसी अधिकारी के दुष्प्रयोग, गाय की गलियाँ की गंदगी आदि से लेकर देश की परराष्ट्र एवं जातिगत नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी हो सकते हैं । लोकसभा के आलोचनात्मक कार्य के फलस्वरूप उदासीन एवं अक्षम प्रशासन से जनता का पथान मरुतन प्राप्त होता है ।

लोकसभा लोकतांत्रिक शासन का यह आधारभूत स्तम्भ है जिसके बिना लोकतन्त्र चल ही नहीं सकता । लोकसभा के ही कारण राष्ट्र का शासन जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की अनुमति और महमति से चलता रहता है ।

संसदीय विपक्ष या प्रतिपक्षी दल

(Opposition in the Parliament)

ब्रिटिश संसदीय कार्य प्रणाली में विपक्ष की उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सकारात्मक । विपक्ष की उतना ही गुणवर्ति है जितना कि सत्तापक्ष । विपक्ष का मुख्य कार्य है कि वह सत्तापक्ष पर ही स्वस्थ आलोचना करके जनमत को अपनी ओर मोड़े तथा निर्वाचना में विजय प्राप्त करने सत्तापक्ष होने का प्रयत्न करे ।

ब्रिटिश राजनीति की यह विशेषता है कि सगठित विपक्ष को राजकीय मायता प्रदान की गयी है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी निर्णय पर अल्प-मत को अपने विचार प्रकट करने का पथापन अवसर और अधिकार मिले, ताकि शासन-कार्य की स्वस्थ और माय-दक्ष व आलायता होनी रहे । सरकार अपने ही विरुद्ध विपक्ष का अविविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करने तक के लिए समय देती है । जिस मंत्री की विपक्ष आलोचना करना चाहता है, सरकार उसके मन्त्रालय के लिए धन-माग (Vote of Supplies) करने का निश्चय करती है ताकि विपक्ष को उस पर प्रहार करने का अवसर मिल जाय ।

सरकार विपक्ष का पूरा आदर करती है और उस "राजा का विरोधी दल" (His or Her Majesty's Opposition) कहा जाता है । गदन का वायजम निर्दिष्ट करने से पहले सरकार विपक्ष की सटमति प्राप्त करना का प्रयत्न करती है । गदन की समितिवा में सभी दलों को म्याद दन का प्रयास किया जाता है । अल्प-मत या विपक्ष से यह आशा की जाती है कि उनका विराध भातिमय और

समस्या का रूप से होगा। विपक्ष के नेता का गारंटी वोट से 2 हजार पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है तथा अन्य मंत्रियों की भांति एक कमरा दिया जाता है। राजा या राणी द्वारा समद का उद्घाटन करते समय विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता है। वास्तव में उमरी म्युनि ब्रिटिश प्रधानमंत्री (Alternative Prime Minister) की हांति है। ब्रिटिश में विपक्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है कि वहां सामान्यतः दो ही महत्वपूर्ण दल हैं जिनके हाथ में सत्ता आती-जाती रहती है।

विपक्ष का संगठन

ब्रिटेन में विपक्ष के सब सदस्य—सदस्य का संसदीय दल के रूप में संगठित होता है। इसका नतत्व 'छाया मंत्रिमण्डल' (Shadow Cabinet) करता है, जिसमें विपक्ष के नेता का स्थान सर्वोच्च होता है। शासक दल की तरह ही विपक्ष के भी अपने सचेतक (Whips) होते हैं। शासक दल के मंत्रिमण्डल के समान ही विपक्ष का 'छाया मंत्रिमण्डल' भी नियमित रूप से अपनी बैठकें करता है। 'छाया मंत्रिमण्डल' में भी शासन के विविध विषय पर एक-एक व्यक्ति को वे सुपुर्द होते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी तौर पर विपक्ष भी मंत्रिमण्डल के रूप में संगठित रहता है। इस प्रकार के संगठन के दो विशेष महत्व हैं—एक तो विपक्षी दल को संगठित किया जाता है और दूसरे विपक्षी दल शासन की हाथ में लेने के लिये सदा तैयार रहता है। 'छाया मंत्रिमण्डल' को विपक्ष की 'नीति समिति' (Policy Committee) अथवा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) कहा जाता है।

ब्रिटेन में प्रमुख राजनीतिक दल दो हैं—श्रमिक दल व अनुदार दल। श्रमिक दल का अनुदार दल की अपेक्षा अपने सदस्यों पर अधिक कठोर नियंत्रण एवं अनुशासन है। संसदीय श्रमिक दल की बैठकें मासिक अथवा सप्ताह में दो बार होती हैं जिनमें सामान्य नीति के प्रश्नों पर निर्णय लिया जाता है और संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। संसदीय श्रमिक दल में लोक सभा के सदस्य प्रति-वर्ष एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचेतक और बारह कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये पंद्रह सदस्य तथा तीन श्रमिक लॉर्ड्स (Peers) संसदीय श्रमिक दल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, जिसका प्रतिवर्ष पुनर्निर्वाचन होता रहता है। यह समझा जाता है कि दल के सत्तामंड होने पर वही प्रधानमंत्री होगा।

अनुदार दल में नेता की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली होती है। निर्वाचन में दल की पराजय होने पर अनुदार प्रधानमंत्री यदि लोक सभा का सदस्य रहता है, तो वही प्रायः विपक्ष का नेता बन जाता है। संसदीय दल द्वारा एक बार चुन लिए जाने पर पद मुक्त होने तक वह अपने पद पर बना रहता है। अनुदार नेता अपने साधियों को चुनने में स्वतंत्र है और यदि वह चाहे तो एक उपनेता भी

कर सकता है। यदि दल का बहुमत न रहने पर अनुदार प्रधानमंत्री विरोधी पक्ष का नेता बन जाता है तो उपप्रधानमंत्री की स्थिति प्रायः विरोधी पक्ष के उपनेता की होती है।

विपक्ष के कार्य

(1) आलोचना—विपक्ष का सबसे प्रमुख कार्य सरकार के कृत्यों की आलोचना करना और उसके दोषों को प्रकट करना है। विपक्ष सरकार को यह सूचित करता है कि देश के विभिन्न भागों में सरकारी नीति और कार्यों की क्या प्रतिक्रिया है। वह सरकारी प्रस्तावों का रचनात्मक विरोध करता है और उस पर अपनी नीति एवं कार्यक्रम में सुधार करने के लिए दबाव डालता रहता है।

(2) शासन की वैकल्पिक नीति का प्रचार—विपक्ष सरकारी नीतियों के दोष बताकर अपनी वैकल्पिक नीति का प्रचार करता है तथा जनमत को सरकार के विरुद्ध और अपने पक्ष में करता है। वह सरकारी प्रस्तावों पर विभिन्न सुझाव रखता है तथा मसौदा में अपने दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत करता है जिससे जाता को यह पता होता रहता है कि विपक्ष की शासन-नीति की रूपरेखा क्या है। जब जनता शासन की वैकल्पिक नीति को समर्थन देने लगती है तो विपक्ष शासन की बागडोर सम्भाल लेने में सक्षम हो जाता है।

(3) शासन नीति को प्रभावित करना—विपक्ष अपनी रचनात्मक आलोचना और सूझ-बूझ से सरकारी नीति तथा दृष्टिकोण को प्रभावित करता रहता है। सरकार इस बात के प्रति सतत जागरूक रहती है कि कहीं विपक्ष का दृष्टिकोण जनता पर हावी न हो जाए। अतः वह अपनी प्रशासनिक नीतियों को यथासम्भव अधिकाधिक कल्याणकारी बनाने की कोशिश करती है। वह अपने कार्यों को ऐसा रूप देती है जिससे विपक्ष की आलोचना प्राणघातक न रह पाये।

(4) लोकतंत्र की सुरक्षा—उपरोक्त सभी कार्यों से विपक्ष लोकतंत्र की सुरक्षा प्रदान करता है। वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है और उसे बाध्य करता है कि वह सरकारी नीतियों को कल्याणकारी रूप प्रदान करे। इतना ही नहीं, विपक्ष जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। विपक्ष की आलोचना सरकार को नियंत्रित करती रहती है। विपक्ष के माध्यम से ही अल्पमत के विचारों का प्रभावशाली प्रकाशन होता है और सरकार सावधान रहती है कि विस्तृत अल्पमत कहीं बहुमत में न परिणत हो जाए।

विपक्ष का मूल्यांकन

प्रायः कहा जाता है कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक उचित अनुष्ठान का विरोध करना और ऐन-ऐन प्रकार से सत्ता को हथियाना होता है। लेकिन यह स्थिति भारत में भल ही नहीं हो, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में नहीं होती है। ग्रिफेन में इस तथ्य का कभी विमर्श नहीं किया जाता कि विपक्ष की स्थिति एक वैकल्पिक सरकार (Alternative Govt) की होती है और बहुमत दल द्वारा

जनता का विश्वास खो बैठने पर उसे (विपक्ष को) शासन की बागडोर सम्भालनी पड़ती है। इसी कारण विपक्ष सरकार की कोई निरर्थक आलोचना नहीं करता तथा ऐसी कोई बातें भी नहीं कहता जिन्हें वह स्वयं सरकार बनाने के बाद पूरी न कर सके। ब्रिटेन में विपक्ष एक पूर्ण उत्तरदायी दल की भाँति कार्य करते हुए व्यवस्थापन कार्य की सही स्थिति पर प्रकाश डालता है।

ब्रिटेन में विपक्ष का पूर्ण सम्मान किया जाता है। बहुमत दल को यह पूर्ण आशा रहती है कि विपक्ष का विरोध सदैव वैधानिक तथा न्यायात्मक ही होगा। ब्रिटेन में विपक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भी भाग लेता है। उदाहरणार्थ, परम्परानुसार विपक्ष ही यह निर्णय करता है कि किन मंत्रालयों की घन मांगों पर वाद विवाद किया जाय। वह अध्यक्ष (Speaker) के पुनर्निर्वाचन में प्रस्तावित नाम का समर्थन करता है। औपचारिक अवसरों पर सदन के नेता के उपरांत विपक्ष को बोलने का अवसर मिलता है। सरकारी पक्ष और विपक्ष के सचेतक परस्पर वार्तालाप करके यह निर्णय करते हैं कि 'राजा या रानी को भेजे सदेश' में से किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाय। विदेशी मामलों में और विशेषकर किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संकट के उपस्थित होने पर प्रधानमंत्री विपक्ष से निरंतर सम्पर्क रखता है और उससे आवश्यक विचार-विमर्श करता रहता है। कभी-कभी विपक्ष के नेताओं को साम्राज्य-सुरक्षा-परिषद् में भी आमन्त्रित किया जाता है। कभी-कभी प्रधानमंत्री विपक्षी नेता को अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चलने को आमन्त्रित करता है। राष्ट्रीय संकट के समय विपक्ष और सरकारी दल एक हो जाते हैं तथा संयुक्त सरकार देश के शासन का संचालन करती है। वस्तुतः सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे के अस्तित्व का पूर्ण आदर करते हैं। ब्रिटिश ससद् दोनों दलों के स्वस्थ और सम्मानजनक संघर्ष की युद्धस्थली है जिसमें कोई एक-दूसरे का नाश नहीं चाहता बल्कि राष्ट्रीय सेवा करने के लिए सत्ताह्वय होने की प्रतियोगिता करता रहता है।

संसदीय प्रतिनिधित्व

(Parliamentary Representation)

ब्रिटिश ससद् में लार्ड सभा का स्वरूप एक प्रतिनिधित्व रहित संस्था का है और लोक सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सन 1948 के प्रतिनिधित्व कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि लोक सभा के सदस्यों की संख्या 613 से न तो बहुत अधिक और न बहुत कम रखी जायगी। सभी सदस्यगण सम्पूर्ण संयुक्त राज्य (United Kingdom) अर्थात् इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं उत्तरी आयरलैंड के विविध निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुने जाने की व्यवस्था है।

निर्वाचनों की योग्यतायें

सन् 1949 के प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार लॉक-सभा का निर्वाचन गुप्त मतदान पत्रों (Secret Ballots) द्वारा होता है। लॉक सभा के सदस्य का छाठकर, प्रत्येक स्त्री और पुरुष यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और किसी प्रकार की वान्छी जयोग्या के अन्तर्गत नहीं है, ब्रिटिश प्रजातन्त्र या राष्ट्र गणतन्त्र का नागरिक है, तो लॉक सभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकारी है। निर्वाचन के लिए जयाभ्य घोषित व्यक्तियों में आयरलैंड के कुछ पीयरों को छोड़कर अन्य सब पीयर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड व रोमन कैथोलिक वर्गों के वर्ज्जों व दिवालियों के अनिश्चित के व्यक्ति भी शामिल हैं जो 'गाम अधिकारी, लोक सेवक, सैनिक, पुलिस सेवक, राष्ट्र मण्डल के बाहर के किसी देश के विधायक अथवा अन्य किसी माध्यामिक पद के अधिकारी हैं। मतदान के लिये उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का मतदान सूचि में नाम दर्ज कराया जाता है जिसमें अमुक निर्वाचक 3 मास से रह रहा है।

निर्वाचन पद्धति व उसके गुण दोष

ब्रिटेन में जिस निर्वाचन पद्धति का प्रयोग है उसे साधारण बहुमत पर आधारित एक सदस्यीय निर्वाचन (Simple Majority with One Ballot) की प्रणाली कहा जाता है। सभी उम्मीदवारों में से जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन सम्बन्धी विवादों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय अपने किंग्स (King's Bench) निर्वाचन में से दो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यदि सफल उम्मीदवार के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो जाता है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाता है और अन्य चुनाव की व्यवस्था की जाती है।

ब्रिटेन में निर्वाचन अभियान का स्तर बहुत ऊँचा है। मतदानियों को फुलाना, उन्हें घूस देना, निर्वाचन के दौड़ों तक उन्हें मुफ्त सवारी में ले जाना, प्रचार के लिए किराये के प्रचारकर्त्ता नियुक्त करना आदि कार्य भ्रष्टाचार कहे जाते हैं और इनका प्रयोग करने वाले उम्मीदवार का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है।

ब्रिटिश निर्वाचन-पद्धति इस दृष्टि से बड़ी अच्छी है कि मतदाताओं और सदस्यों के बीच सीधा सम्पर्क बना रहता है। व्यय भी अपेक्षाकृत कम होता है और स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में दो प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं, जिनमें से एक मताच्छेद होता है और दूसरा विरोधी दल। इसी कारण ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अधिकांशतः स्थायी रहता है।

किंतु इस निर्वाचन प्रणाली के कुछ निश्चित दोष भी हैं—

प्रथम, कभी कभी अत्यन्त कम सत्या के समर्थन से ही सदस्य निर्वाचित घोषित हो जाता है।

दूसरे, इस निवाचन प्रणाली के कारण लोकसभा में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व उनके उम्मीदवारों का प्राप्त कुल मतों के अनुपात में नहीं होता, विशेष रूप से जल्प सख्य दलों का बहुत कम प्रतिनिधित्व हो पाता है।

तीसरे, मतदाताओं के मत में छोट से परिवर्तन से भी स्थानों के वितरण में बड़ी बड़ा परिवर्तन हो जाता है।

चौथे, ब्रिटिश थाम चुनावों से जनमत का एक विविध विकृत स्वरूप दिखाई देता है। यदि तीन दल चुनाव लड़ रहे हों तो हाँ सनता है कि एक दल को यदि सबसे अधिक मत मिले तो भी वह लोकसभा की एक ही सीट जीत पाया हो। ऐसा तब होता है जब दल के उम्मीदवारों की बहुत से चुनाव क्षेत्रों में घीच की स्थिति हो और विरोधी दलों के उम्मीदवार वही अल्प बहुमत से जीत जाते हो और वही भारी बहुमत से हार जाते हो। यह दल भी जिसका देश में अल्पमत हो, लोकसभा में बाकी बहुमत प्राप्त कर सकता है। परिणाम यह होता है कि चुनाव एक प्रकार का जुआ बन जाता है।

पाचवें ब्रिटिश निर्वाचन पद्धति बहुमख्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर देती है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल मतदाताओं का लगभग 60 से 70 प्रतिशत या तो घटनाओं को प्रभावित नहीं कर पाता या उसे उन नीतियों और सिद्धांतों का समर्थन करना पड़ता है, जिनसे उनका मतभेद होता है। साथ ही निर्विरोध चुनाव से भी अनजान मतदाताओं के मत छिन जाते हैं। इसी तरह धनपल उम्मीदवारों के पक्ष में पड़ने वाले मत व्यर्थ चले जाते हैं। कुछ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते क्योंकि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं जाता। इसी तरह कुछ मतदाता अनिच्छा से ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मत देते हैं जिसके मत से उनका मत नहीं मिलता।

छठे, ब्रिटिश चुनाव प्रणाली में निर्वाचन स्थानीय प्रभाव के कारण संकुचित विचारों के आधार पर होता है। अतः निर्वाचन प्रतिनिधियों में स्थानीय महत्त्व की बातों पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है।

ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति को सुधारने के लिए समय समय पर विभिन्न सुझाव दिये जाते हैं। इंग्लैण्ड की आनुपातिक प्रतिनिधित्व सोसाइटी (Proportional Representation Society) के सदस्यों ने समस्या के समाधानाथ एकाकी हस्तान्तरणीय (Single Transferable) मत-प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि बहुमत पर आधारित मत प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए 'एकत्रमत प्रणाली' (Cumulative Vote System) अपना ली जाय। एक अन्य सुझाव 'संशुद्ध मत-प्रणाली' (Restrictive Vote System) को अपना लेने का है, किंतु ये सभी विकल्प भी दोषमुक्त नहीं हैं। इन प्रस्तावों की

सबसे बड़ी बुराई यह है कि इनसे ब्रिटेन की द्वि-दलीय प्रणाली समाप्त हो जाएगी और राजनीतिक दलों की वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप देश की राजनीतिक स्थिरता में अंतर पड़ेगा और स्थायी मंत्रिमण्डलों का बनना कठिन हो जायेगा। यही कारण है कि अंग्रेज अपनी वर्तमान प्रणाली को ही अधिक ठीक समझते हैं और यह मानते हैं कि दवाई बीमारी से भी बुरी है। आज ससार के अधिकांश देशों में ब्रिटिश-निर्वाचन पद्धति ही अपनाई जा रही है।

फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसद् को विगुद्ध रूप से प्रतिनिधि संस्था बनाना लगभग असम्भव था है। 630 व्यक्तियों की संसद् करोड़ों व्यक्तियों की सम्पूर्ण विचारधाराओं को प्रतिबिम्बित नहीं कर सकती और विचारधाराओं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना एक नितांत अव्यावहारिक कल्पना होगी। ऐसा कोई पथक निर्वाचन क्षेत्र निर्मित होना असम्भव है जिसके अंतर्गत एक ही विचारधारा के निर्वाचकगण पाये जाते हों।

सर्वोपरि ध्यात यह है कि निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी दल विशेष का ही प्रतिनिधि नहीं रहता बल्कि सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधि हो जाता है, और सम्पूर्ण देश के हितों का ध्यान में रखकर ही कार्य करने की उससे आशा की जाती है। सरल शब्दों में सदस्यगण क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित होते हुए भी सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधि होते हैं।

लोकसभा का अध्यक्ष

(Speaker of the House of Commons)

ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष को 'स्पीकर' (Speaker) कहा जाता है। यह ऐतिहासिक पद संसद् के प्रारम्भिक काल से ही चला आ रहा है। प्रमाण-पत्रों से ज्ञात होता है कि सन् 1936 में सर थॉमस हंगरी फोर्ड (Sir Thomas Hungry Ford) ने पहले पहल इस उपाधि की वैधानिक रूप से ग्रहण किया था।

'स्पीकर' का शाब्दिक अर्थ है 'बोलने वाला'। उसे स्पीकर इसलिए कहा गया कि प्रारम्भ में राजा और प्रजा के बीच वह कड़ी का रूप था। वह जनता का प्रवक्ता था जिसके द्वारा राजा के समक्ष जनता की आवाज पहुँचाई जाती थी। उस समय लोकसभा केवल प्रायनापत्र भेजने वाली संस्था थी और स्पीकर का काम था कि लोकसभा के ऐसे प्रायनापत्रों को वह राजा के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी ओर से राजा के समक्ष बोलें। अब राजतन्त्र के लोकतन्त्रीकरण के बाद से लोकसभा पहले के समान एक प्रायनापत्र करने वाली संस्था मात्र नहीं रही है वरन् लोक-सम्प्रभुता की प्रतीक बन गई है। अब आज स्पीकर एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष है जो लोक-सम्प्रभुता की प्रतीक और उसकी निरीक्षिका है।

सन् 1919 के छठे दफ्तर के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बॉनिट के लार्ड प्रेसीडेंट (Lord President) के बाद आता है। वह वेस्ट मिस्टर भवन

में रहता है और पद मुबन होने के बाद उसे पीयर (Peer) बनाया जा सकता है। स्पीयर के अधिकार और उसकी शक्ति को सभी दल मानते हैं।

अध्यक्ष की शक्ति अथवा उसकी मान्यता का आधार

ब्रिटिश संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष का पद महान गौरव और शक्ति का है। इस मान्यता के अनेक आधार हैं—

प्रथम, मदन म धायवाहियों के समुचित निष्पक्ष और चायपूर्ण सम्पादन के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष इसकी पूर्ति करता है।

द्वितीय अध्यक्ष का पद एक गौरवपूर्ण और प्राचीन पद है जिसका संसद् के साथ ही निजान हुआ है। अध्यक्ष समद द्वारा राजा से जीती हुई सावभौमिकता का प्रतीक है। भूतवा में भी वह लोकसभा का प्रतीक और रक्षक था तथा आज भी है।

तृतीय, अठारहवीं शताब्दी में अध्यक्ष पद को उच्च प्रतामकीय और न्यायिक पदों, यहाँ तक कि प्रधानमन्त्रित्व की प्राप्ति के लिए भी पहला चरण माना जाने लगा। फलस्वरूप इसका महत्व बहुत बढ़ गया।

चतुर्थ, निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष एक पूर्णतः निरदलीय व्यक्ति रहता है जो सदन के सभी दलों को समान रूप से बालने का अयसर प्रदान करता है।

पंचम, अध्यक्ष की सजधज और तडक भडक का भी इस पद की महत्ता और प्रभाव की वृद्धि में पर्याप्त हाथ रहा है। वह रौबीला चोगा और भारी टोप पहनता है तथा चढ़वा वाली कुर्मी पर बठता है। उसे करमुक्त दस हजार पीण्ड वार्षिक वेतन और निवृत्ति के बाद चार हजार पीण्ड वार्षिक पेंशन मिलने की व्यवस्था है। इन सब बातों से उसके प्रभाव का प्रसार होता है।

इसकिन में (Erskine May) ने ठीक ही लिखा है कि "लोकसभा का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही और उसकी शान के सम्बन्ध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सदन का अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति होता है।" अध्यक्ष का निर्वाचन

प्रारम्भ में राजा ही अध्यक्ष की नियुक्ति करता था किन्तु आज उसकी स्वीकृति महज औपचारिकता है। आजकल अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के बाद ही के दिन सर्वप्रथम किया जाता है। प्रधानमंत्री और प्रतिपक्षी दल के नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल और प्रतिपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। परम्परागत प्रथा के अनुसार लोकसभा के सदस्य लड़ सभा द्वारा आमन्त्रित किए जाने पर वहाँ पहुँचते हैं और शांति से खड़े हो जाते हैं। उस समय लार्ड चांसलर घोषणा करता है कि ग्राउन की इच्छा है कि वे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लें। तब लोकसभा के सदस्य अपने सदन में घापिस आकर अध्यक्ष का

चुनाय करते हैं। व्यवहार में अध्यक्ष यही चुना जाता है जो सरकार का मान्य होता है। इसीलिए मुरा ने लिखा है कि "साधारण मन्त्रियों द्वारा प्रस्ताव एवं अनुमादा केवल इस वास्तविक बात का पूरा ध्यान के लिए ही किया जाता है कि चुनाव मंत्रियों द्वारा न हाथ पर मदन द्वारा हुआ है।"

चुनाय के बाद अध्यक्ष अपा पद को धारण करता है। अध्यक्ष के चुनाव का पुष्टिकरण बाद में संसद द्वारा होता है। उसका निर्वाचन लोकसभा की ध्वज के लिए ही किया जाता है किन्तु परम्परा के अनुसार पुराने ही अध्यक्ष का निर्वाचन उस समय तक निविराध रूप से होता रहता है जिस समय तक वह काम करने की तैयार हो। यह पद्धति इतनी भाव्य है कि अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से बाइकल सम्मेलनवार प्रायः यही राइड नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि "एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष" (Once a Speaker is always a Speaker)

अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष रखने के लिए मामा-यन निम्नलिखित प्रथाओं का पालन किया जाता है—

1 अध्यक्ष सम्पूर्ण सदन के लिये निर्वाचन होता है। तास में वह कबल एक सत्र के लिये ही निर्वाचित होता है।

2 अध्यक्ष उस समय तक बार-बार चुना जाता है जब तक कि उनका मृत्यु नहीं हो जाती या वह स्वयं त्याग पत्र नहीं देता।

3 अध्यक्ष का निर्वाचन सवमम्मति से होता है और उसे निवाचन लड़ना नहीं पड़ता। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपने दलीय सम्बन्धों का परिहारा कर देता है।

4 उसे अपने निर्वाचन क्षमता को अपनी मुठठी में रखने की आवश्यकता नहीं होती।

5 वह वाद-विवादों में भाग नहीं लेता।

6 अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है किन्तु इसका प्रयोग वह बहुत कम करता है, और जब करता है तो बयास्थिति को बनाये रखने के लिए ही। अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य

(क) लोकसभा का प्रतिनिधित्व—अध्यक्ष कई प्रकार से सदन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह निम्न देह सदन का शिवाशील एवं साधनिक प्रतिनिधि होता है। सदन के प्रतिनिधि के रूप में उसकी शक्तिशाली और कार्य है—

(1) अध्यक्ष सदन और राजा के बीच कड़ी का काम करता है। सत्य उसके माध्यम से राजा के पास प्रतिवेदन और धन-वाद या निन्दा का प्रस्ताव भेजते हैं। यदि सदन का शिष्टमण्डल राजा से भेंट करना चाहता तो उनके साथ अध्यक्ष का नेता के रूप में होना आवश्यक है। अध्यक्ष ही वित्त विधायक को राजा के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। राजा की ओर से यदि कोई सदस्य सदन

अर्थात् लोकसभा को प्रेषित किये जाते हैं तो उन्हें भी अध्यक्ष ही पढ़कर मुनाता है। राजा की ओर से वही लाकसभा के लिपिक (Clerk of the House) को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आदेश देता है। वही उनके लिए चुनावों की घोषणा करता है। लोकसभा और लाकसभा की सम्मिलित बैठक के लिए जब लोकसभा के सदस्य जाते हैं तो उनका नेतृत्व भी अध्यक्ष को ही करना पड़ता है।

(11) लोकसभा और लाकसभा के पारस्परिक सम्बन्धों और व्यवहारों में भी अध्यक्ष ही लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। वही निश्चय करता है कि कोई विधेयक वित्त-विधेयक है अथवा नहीं। वित्त-विधेयकों को लाकसभा में प्रस्तुत करना उसी का कर्तव्य है। वित्त-विधेयकों के बारे में लाकसभा की प्रतिक्रिया के औचित्य के बारे में अध्यक्ष ही निर्णय करता है, अर्थात् वही यह स्थापित करता है कि वही लोकसभा के अधिकारों पर आघात तो नहीं होता। यदि वह संशोधन या परिवर्तनों को लोकसभा के अधिकारों पर आघात पहुँचाने वाले समझता है तो उन्हें हटा सकता है और अपने निर्णय की सूचना लाकसभा को भेज सकता है।

(111) बाह्य जगत में भी अध्यक्ष ही लोकसभा का नेतृत्व करता है। जो सदस्य प्रतिनिधि मंडल विशेष जाते हैं उनका नेतृत्व प्रायः उसे ही करना पड़ता है। लोकसभा के निर्णयों की सूचना बाह्य अधिकारियों को वही देता है और वही यह भी बतलाता है कि उन्हें किस प्रकार प्रियाचित करना है। अध्यक्ष के माध्यम से ही लोकसभा को वे सूचनाएँ और याचिकाएँ प्राप्त होती हैं जो बाहर से उसे भेजी जाती हैं।

(ख) लोकसभा की अध्यक्षता—अध्यक्ष की वास्तविक और मुख्य शक्तियाँ लोकसभा की अध्यक्षता से सम्बन्धित हैं—

1 अध्यक्ष यह देखता है कि लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ में आवश्यक उपस्थिति है अथवा नहीं।

2 वह सदन की बैठकों का सभापतित्व करता है और वाद-विवादों तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता है। वही उन्हें लागू भी करता है।

3 बिना अध्यक्ष की आज्ञा के कोई भी सदस्य भाषण नहीं दे सकता और न किसी विधेयक के सम्बन्ध में विचार ही प्रकट कर सकता है। अध्यक्ष ही निश्चित करता है कि कौनसा सदस्य बोलेगा। समस्त भाषण, वक्तव्य और प्रश्न उसी को सम्बोधित करके किये जाते हैं।

4 अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह सदस्यों को पथ भ्रष्ट न होने दे। इसका सम्बन्ध वाद-विवाद की उचित व्यवस्था तथा प्रमत्त से है। वह देखता है कि सदस्यगण वाद-विवाद के मुख्य विषय से न हटें और अप्रसंगिक बात न करने लग जायें।

5 अध्यक्ष को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है। प्रचलित प्रथा के अनुसार वह अपने इस अधिकार का प्रयोग यथा स्थिति (Status)

quo) के लिए अपना मत देकर करता है। यदि किसी प्रस्ताव द्वारा विषय पर लोकसभा की विचार-अवधि हटाने का निश्चय हो तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग 'नहीं' के लिए करता है। यदि विचार-अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव हो तो वह अपने मत का प्रयोग "हाँ" के लिए करता है ताकि अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में सदन का ही करना पड़े।

6 वह किसी प्रश्न या कामरोक प्रस्ताव को ठहरा सकता है, वरन् वह उन्हें सभा के नियमों के विरुद्ध समझता हो। यदि वह देखता है कि बहुत सारा समय भागे हुए है और समय बहुत कम है, तो वह महत्वपूर्ण सजावनों का छोड़कर सब को ठुकरा देता है। इसको "कंगारू समापन" (Kangaroo Closure) कहते हैं।

7 अध्यक्ष सारजेंट-एट आर्मस की सहायता से सदन में अनुशासन रखा है, अनुशासन भंग करने वाले को रोक्ता है, तथा अप्रिय व्यवहार करने वाले को सदन में चले जाने तक के लिए बाध्य कर सकता है। जख्मबन्धा बंध जाने पर वह सभा को 15 मिनट स्थगित कर सकता है। गम्भीर दुराचार करने पर वह बापी सदस्य को सत्र भर के लिए निलम्बित (Suspend) भी कर सकता है।

8 अध्यक्ष लोक-सभा में अल्पसंख्यकों के हितों का भी रक्षक होता है।

(ग) लोक-सभा सम्बन्धी प्रशासन—अध्यक्ष उस प्रशासनिक विभाग का प्रभार भी होता है जिसे लोक-सभा को स्वीकार का विभाग कहा जाता है। इस विभाग में सदन का क्लर्क, लाइब्रेरियन, और कुछ अन्य सेवकगण होते हैं। इनके अतिरिक्त निजी विधेयकों के सम्बन्ध में निरीक्षक, कतिपय अधिकारी जिनका सम्बन्ध मतदान कार्यालय (Voting Office) से होता है एवं कुछ और व्यक्ति हात हैं। अध्यक्ष यह देखता है कि लोक-सभा की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे।

कभी कभी अध्यक्ष को ऐसी नाविधानिक सम्मेलनों का सभापतित्व भी करना पड़ता है, जैसे 1914 का बुकिंगहम महल सम्मेलन (Buckingham Palace Conference of 1914) अथवा 1920 का स्पीकर सम्मेलन (Speakers Conference of 1920)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश अध्यक्ष की शक्ति का और उसके कर्तव्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष एक ऐसा आदर्श व्यक्ति है जिस पर सदन को पूर्ण विश्वास होता है। वह जो कुछ कहता है, सबका मान्य होता है। वास्तव में वह लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं का प्रतीक और मरक्षक है।

ब्रिटिश समिति-प्रणाली

(The British Committee System)

विधि निर्माण के ब्रिटिश ढाँचा को भली प्रकार सम्पादित करने के लिए ब्रिटन में समिति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, और आज समितियाँ मसदीय शासन बढ़ति का अनिवार्य अंग बन गई हैं। संसद की लगभग सभी व्यवस्थापिकाएँ अपने

कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए, समय की बचत के लिए और विधेयकों का प्राथमिक तथा समुचित परीक्षण करने के लिए समितियों का प्रयोग करती है।

ब्रिटिश समिति-प्रणाली का प्रारम्भ रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ, जब विधेयकों पर अच्छी तरह विचार करने के लिए उन्हें प्रवर-समितियों के सुपुर्द किया जाने लगा। इन प्रणाली का समुचित ढंग से संगठन सर्वप्रथम 1882 में किया गया। ज्ञान लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के विकास के साथ-साथ समिति-प्रणाली अधिकाधिक व्यवस्थित और समुन्नत होती गयी तथा आज हालत यह है कि उनका बिना विधि-निर्माण के कार्य को ढंग से सम्पादित किया जाना ही अनि कठिन है।

समितियों के प्रकार

ब्रिटेन में कई प्रकार की समितियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (1) सम्पूर्ण सदन की समिति (The Committee of the Whole House)
- (2) विशिष्ट अथवा प्रवर समितियाँ (Select Committees)
- (3) स्थायी समितियाँ (Standing Committees)
- (4) गैर-सरकारी विधेयक समितियाँ (Committees on Private Bills)
- (5) संयुक्त या सम्मिलित समितियाँ (Joint Committees)

अब हम प्रत्येक प्रकार की समिति का अलग-अलग रूप से विवेचन करेंगे।

सम्पूर्ण सदन की समिति—यह सबसे प्रमुख समिति है। इसमें सदन के समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें और सदन में अंतर केवल यही होता है कि (i) सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है जबकि समिति की अध्यक्षता इसके (समिति) द्वारा निर्वाचित सभापति करता है। (ii) समिति का सभापति अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठता, बल्कि टेबुल के पास रखी सदन के लिपिक (Clerk) की कुर्सी पर बैठता है। (iii) अध्यक्ष की शक्ति की प्रतीक मर्दा (Mace) भी मेज से हटा कर उसके नीचे रख दी जाती है। (iv) सदन से निम्न समिति में किसी प्रस्ताव के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। (v) समिति में एक सदस्य चाह जितनी बार बोल सकता है सदन के समान इसमें बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और न ही 'पूर्व प्रश्न' (Previous Question) का प्रस्ताव करके वाद विवाद को समाप्त किया जा सकता है।

सम्पूर्ण सदन की समिति में सभी विधेयकों पर विचार नहीं किया जाता। प्रमुख वित्त विधेयक ही विचाराय लिए जाते हैं। सभी वित्त विधेयकों के प्राय दो भाग होते हैं—एक भाग का सम्बन्ध व्यय से होना है और दूसरे भाग का आय से। सम्पूर्ण सदन की समिति जब व्यय से सम्बन्धित भाग पर विचार करती है,

तब उसे "सम्भरण समिति" (Committee of Supply) कहा जाता है और जब धाय से सम्बन्धित भाग पर विचार करती है तब उसे उपाय व साधन समिति या अर्थोपाय समिति (Committee of Ways and Means) के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

घन-विधेयका के अतिरिक्त निम्नलिखित विधेयक भी सम्पूर्ण सदन की समिति में भेजे जाते हैं—

(1) ऐसे विधेयक जो अस्थायी आदेश की पुष्टि करते हों एवं

(2) ऐसे विशेष विधेयक जिनके बारे में सदन यह निश्चित करता है कि वे सम्पूर्ण सदन की समिति के सामने रख जायें।

अन्य प्रकार के विधेयक विभिन्न समितियों में उनके क्षेत्रानुसार भेजे जाते हैं।

जब समिति का कार्य समाप्त हो जाता है, तब सीमित वापिस सदन के रूप में बदल जाती है। अध्यक्ष की गदा (Mace) मेज पर रख दी जाती है, अध्यक्ष पुन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और सदन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। स्मरणीय है कि कोई समिति स्थायी रूप से सदन के लिए नियुक्त नहीं की जाती। समिति एक अस्थायी निकाय होती है, जो आवश्यकतानुसार किसी भी दिन नियुक्त की जा सकती है।

विशिष्ट समितियाँ

घन सम्बन्धी विधेयक के अतिरिक्त अन्य सावजनिक विधेयकों के लिए विशिष्ट या प्रचुर समितियाँ होती हैं। ये दो प्रकार की हैं—तदर्थ विशिष्ट समितियाँ (Adhoc Selection Committee) तथा सत्रीय विशिष्ट समितियाँ (Sessional Select Committees)। तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और विधेयक के विचार की समाप्ति के साथ ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सत्रीय विशिष्ट समितियाँ सदन द्वारा प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नियुक्त की जाती हैं और सत्र के अन्त तक चलती हैं। इनमें से कुछ समितियों के नाम ये हैं—प्रचुर समिति (The Selection Committee), लोक लेखा समिति (The Committee of Public Accounts), स्थायी आदेश समिति (The Standing Order Committee), विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति (The Committee of Privileges), परिनियत विधेय प्रचुर समिति (The Selection Committee of Statutory Instruments)।

लोक सभा स्वयं निर्णय करती है कि कौन कौन सी विशिष्ट समितियाँ बनाई जाएँ और वही उन समितियों के लिए सदस्यों के नामों का चयन करती है।

ये समितियाँ अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती हैं। उन्हें मुख्य अधिवेशन करने का अधिकार होता है। ये लोक-सभा में तथ्यों का सग्रह करती हैं, सत्यता की परीक्षा करती हैं, और अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त करती हैं, जिससे सम्बन्धित विषय के बारे में उचित पदम उठाया जा सके। पर इनको यह अधिकार नहीं है कि किसी

व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने की बाध्य कर सके अथवा उसके कागजात या अभिलेख तलब कर सके जब तक कि सदन उन्हें विशेष रूप से इसका अधिकार न दे दे। अथ ममिनिया विधेयकों के मसौदा निम्न पक्ष का नहीं देखती, वे केवल उनके प्रारूप सम्बन्धी पक्ष को ही देखती हैं। कि तु विविष्ट ममिनिया सार्वजनिक मामलों के विषय में जान समिति का वाय करती हैं। उन्हें यह देखने का भी अधिकार होता है कि किसी विधेयक में निहित गिद्दान कहा तक ठीक अथवा वाछनीय हैं। लोक सभा प्रायः इन समितियों के विचारों का सम्मान करती है।

स्थायी समितियाँ

विशिष्ट समितियों में अति महत्वपूर्ण स्थायी समितियाँ हैं। इनकी संख्या 4-5 हैं और वे A, B, C, D, E जादि के नामों से पुकारी जाती हैं। एक्स्कॉटलंड सम्बन्धी मामलों की समिति (Committee of Scottish Affairs) भी होती है। यह केवल उन्हीं विधेयकों पर विचार करती है जिनका सम्बन्ध स्कॉटलंड से होता है। यह समिति अथ समितियों के आकार से लगभग तीन गुनी होती है और इसमें कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 15 तक रिगषन होते हैं। इसके अतिरिक्त एक महा-समिति (Grand Committee) भी होती है। यह भी स्कॉटलंड के मामले पर ही विचार करती है। इसी प्रकार वेल्स और मध्य मायर (Wales and Manmouth Shire) के निवाचन क्षेत्रों के लिये 16 सदस्यों वाली वेल्स-महानसमिति (Wales Grand Committee) भी होती है।

स्थायी समितियाँ प्रत्येक सत्र के निर्माण के पश्चात् प्रथम अधिवेशन पर बना दी जाती हैं और तब तक रहती हैं जब तक कि उस सत्र के अन्त में समाप्त न हो जाए। स्कॉटलंड की समिति को छोड़कर A, B, C, D, E स्थायी समितियाँ न केवल प्रत्येक के सदस्यों की संख्या 20 होती है, कि तु किसी विशय विधेयक के विचाराय इनमें 30 तथा और सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं अर्थात् 50 तथा इनके सदस्यों की संख्या हो सकती है। नये सदस्यों की नियुक्ति तत्सम्बन्धी विधेयक के प्रति उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर होती है। एक चयन करने वाली समिति (Committee of Selection) इन समितियों का नामांकित करती है। सभी राजनीतिक दलों के सदस्य इन समितियों में उसी अनुपात से लिये जाते हैं जिन अनुपात में सदन में उनकी संख्या होती है। सदन का अध्यक्ष स्थायी समिति के लिये समापति का चुनाव उन समापतियों की सूची में से करता है जिनका नामांकन चयन समिति करती है। इस सूची में कम से कम 10 नाम अवश्य होते हैं। स्थायी समिति के समापति (चेयरमैन) की बड़ी क्षमता है जो माधन समिति के समापति की होती है। माथ ही उसे यह भी अधिकार है कि वह वाद विवाद की समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर ले और किसी मुखवर्ष (Guillotine) द्वारा वाद विवाद बन्द कर दे।

व्यवस्थापन का अधिकतर कार्य स्थायी समितियों के द्वारा ही होता है। अधिकांश विधेयक इन्हीं समितियों के सुपुट कर दिये जाते हैं। ब्रिटिश स्थायी समितियों की यह एक विशेषता है कि उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित अथवा विशिष्ट नहीं होता। उनका कार्य विधेयकों के प्राप्ति में सशोधन करना होता है और वे उनके मित्रों तो वे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। स्थायी समितियाँ विधेयक का रूप बदल सकती हैं किन्तु उसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती। प्रत्येक विधेयक को उन्हें पुनः लोकसभा के समक्ष अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है और यह लोकसभा की इच्छा पर है कि वह समितियों द्वारा प्रस्तावित सशोधनों को स्वीकार करे या न करे।

स्थायी समितियों द्वारा प्रस्तुत सशोधनों को लोकसभा प्रायः स्वीकार कर ही लेती है, क्योंकि उनके मुझाव बड़े लाभकारी होते हैं। परन्तु स्थायी समितियाँ दोषमूक्त नहीं हैं। जिन कारणों से इन समितियों की आलोचना की जाती है, वे प्रमुखतया ये हैं—(1) समितियों की सदस्य संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वे प्रायः गम्भीर विचार के उपयुक्त नहीं रहती। (ii) समितियों पर कार्यभार इतना अधिक है कि 4-5 समितियों से काम नहीं चल सकता। (iii) समितियों के सदस्य विधेयकों के विषय में विरोध नहीं करते।

संयुक्त समितियाँ

कभी-कभी लाइसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त समितियाँ की भी नियुक्ति होती है। ये संयुक्त समितियाँ ऐसे विषयों पर विचार करती हैं और अनुमति देती हैं जिनके बारे में दोनों सदनों में उत्तेजना पैदा होती है। परन्तु ब्रिटिश संसदीय जीवन में इनका प्रचलन बहुत ही कम है। इन समितियों का स्वरूप विनिष्ट समितियों के समान होता है।

गैर सरकारी विधेयक समितियाँ

गैर सरकारी विधेयकों के परीक्षण के लिये गैर सरकारी विधायकों की समितियाँ होती हैं। इन समितियों की कार्य प्रणाली विशिष्ट या प्रवर समितियों जैसी है। इनकी नियुक्ति का भार चयन समिति (Committee of Selection) पर है। ये समितियाँ स्थायी होती हैं। लोकसभा द्वारा निर्मित ऐसी समितियों में 4 तथा लाइसभा द्वारा निर्मित ऐसी समितियों में 5 सदस्य होते हैं। ये समितियाँ फ्राम व अमेरिका में नहीं हैं क्योंकि वहाँ सार्वजनिक (Public) और व्यक्तिगत या गैर-सरकारी (Private) विधेयकों में कोई अंतर नहीं है।

इन समितियों की शक्ति बड़ी होती है। ये उन गैर-सरकारी विधेयकों का परीक्षण करती हैं जिनका द्वितीय वाचन (Second reading) में विरोध किया जाता है। ये समितियाँ अर्ध-न्यायिक पद्धति (Quasi Judicial line) पर कार्य करती हैं। ये विधेयकों के रूप पर विचार करके उन्हें उन्नत बनाती हैं और उनमें

अतर्निहित मिद्धाता पर विचार, करके उनकी वाछनीयता-अवाछनीयता के आधार पर आवश्यक फेर-बदल भी करनी ह। प्रस्तावित व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोगो को और उन लोगो का, जिह हानि हाने की सम्भावना हो, गवाही के लिये आमन्त्रित करने का भी इहे अधिकार है। य लोग स्वय तथा अपन वकीलो के द्वारा अपना पक्ष समितियो के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते ह। यह निणय समितिया ही कर सकती हैं कि किसी विधेयक का निर्माण होना चाहिये या नही और यदि होना चाहिये तो उसका रूप क्या होगा ? समितियो का निणय प्राय अतिम होता है, क्योंकि व्यवहार मे यही पाया गया है कि लाक्सभा इन समितियो के प्रतिवेदन के विरुद्ध काय नही करती है।

समितियों के कार्य का मूल्यांकन

स्पष्ट है कि समितियो का काय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और ये लोकसभा के व्यवस्थापन काय मे बड़ी सहायक है। ब्रिटेन मे इन समितियो को सदन के लघु रूप की सजा दी जाती है। परन्तु इससे यह आशय नही है कि व्यवस्थापन काय मे समितियो का कार्य मुख्य और संसद का काय गौण हो गया है। हरमन फाइनर के शब्दो मे "अपनी स्थिति एवं अपने काय की दृष्टि से समितिया सम्पूर्ण सदन के अधीनस्थ ह। उनकी शक्ति इतनी नही है कि वे विधेयको को जीवित रख सकें या उहे समाप्त कर सकें। मसोधनो की मफाई करने के लिये वे नीचे काम करने वाली सहायक, परिचारिकायें हैं और उनका काय पूर निमित्त विधेयक के द्वितीय वाचन, अपने प्रतिवेदन तथा विधेयक के ततीय वाचन (जब उनके काय का पुनरावलोकन हाता है) तक ही सीमित है।'

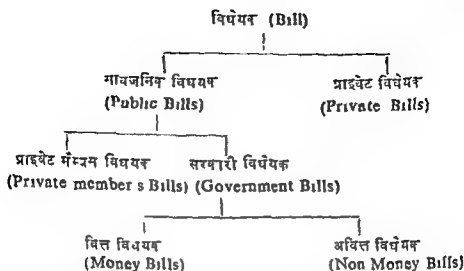
विधि निर्माण प्रक्रिया

(Legislative Process)

ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कानूनों का निर्माण संसद का सबसे प्रमुख काय है। संसद देश के लिये व्यवस्थापन करती है जिसको देश की कायकारिणी क्रियावित्त करती है। ब्रिटेन की विधि निर्माण-प्रणाली का, जो अत्यन्त वैधानिक रूप मे व्यवस्थित है लगभग सम्पूर्ण विश्व के विधान मण्डलो पर प्रभाव पडा है।

विधेयकों के प्रकार

ब्रिटिश विधेयको के विभिन्न प्रकार अग्रिम पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है—



प्रकट है कि समस्त विधेयक जिन्हें मसदा प्राप्त करती है, स्वरूप में दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, सार्वजनिक विधेयक और द्वितीय प्राइवेट या असार्वजनिक या व्यक्तिगत विधेयक। इन दोनों प्रकार के विधेयकों के अन्तर का समान लेना चाहिए।

सार्वजनिक विधेयक—सार्वजनिक विधेयक वे होते हैं जिनका सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण जनता या जनता के बहुत बड़े भाग से हो। उदाहरणार्थ, जनता पर कर लगान वाला विधेयक प्रशासकीय विभाग की प्रारम्भ करने वाला विधेयक, मताधिकार सम्बन्धी विधेयक, अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विधेयक आदि। ऐसे विधेयकों का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित की साधना होता है।

इन सार्वजनिक विधेयकों के पुन दो प्रमुख भेद होते हैं—गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (Private member s Bills) एवं सरकारी विधेयक (Government Bills)। जब कोई सार्वजनिक विधेयक प्राइवेट अर्थात् व्यक्तिगत या गैर सरकारी सदस्य द्वारा रखा जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। इस प्रकार के विधेयकों का सरकारी सहयोग के अभाव में पारित होना बड़ा ही कठिन होता है। जब सार्वजनिक विधेयकों को सरकार द्वारा अर्थात् मन्त्रिमण्डल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। इन विधेयकों को मसदा से पारित कराना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। सदन का अधिकांश समय इन्हीं विधेयकों का पारित करने में व्यतीत होता है।

सरकारी विधेयक भी दो श्रेणियों में रख जा सकते हैं—प्रथम वित्त विधेयक और द्वितीय साधारण अथवा अवित्तीय विधेयक। वित्त विधेयक मन्त्रिमण्डल के सदस्य द्वारा राजा की विचारिश पर लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। इन्हें लाउड सभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वीन या विधेयक वित्त विधेयक

हैं और कीम मा नहीं, इनका निषेध अव्यय (Speaker) करता है। वित्त विधेयको को छोड़कर जो अन्य सावजनिक विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तावित होते हैं, वे अवित्त या साधारण विधेयक कहलाते हैं।

व्यक्तिगत या सावजनिक विधेयक—ये वे विधेयक हैं जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण देश की जनता से न हानर किन्ती स्थान विशेष की जनता से अथवा किसी स्थान या मन्था में होना है और जो जनता के साम्प्रतिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते। उदाहरणार्थ वह विधेयक जो किसी नगरपालिका या निगम से सम्बन्धित हो या विशेष प्रकार के मजदूरों के हितों के लिए हो या किसी विशेष स्थान पर सुधार योजना के लिए हो, व्यक्तिगत या असावजनिक विधेयक (Private Bill) कहलाता है। ऐसे विधेयक प्रायः नगरपालिकाओं और नगर-निगमों जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथना पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके पारित होने की भी उस समय तक उचित सम्भावना रहती है जब तक कि सरकार उनका समर्थन नहीं करे। स्मरणीय है कि व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयकों (Private Members Bills) तथा व्यक्तिगत विधेयकों (Private Bills) में बहुत अंतर है। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक और सरकारी विधेयक सावजनिक विधेयकों के अन्तर्गत आते हैं जिनका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर पड़ता है। इन विधेयकों के पारित होने के लिए संसद में एक भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। व्यक्तिगत विधेयकों का सम्बन्ध सावजनिक हित से न होकर विनिष्ट हित से होता है। ये विधेयक न तो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और न साधारण संसद सदस्यों द्वारा, बरन प्रायः स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथना पत्र भेजकर प्रस्तुत किये जाते हैं। इनको पारित करने के लिये संसद् में सावजनिक विधि निर्माण प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनायी जाती है।

सावजनिक विधेयकों (वित्त विधेयकों को छोड़कर) से सम्बन्धित विधि निर्माण प्रक्रिया

इन विधेयकों की विधि निर्माण प्रक्रिया त्रयश निम्नलिखित स्तरों (Stages) में पूरी होती है।

प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम वाचन—सिद्धान्ततः ये दोनों बातें भिन्न-भिन्न हैं कि तु ब्रिटेन में विधेयक का प्रस्तुतीकरण तथा प्रथम वाचन एक साथ ही होता है।

कोई भी सावजनिक विधेयक संसदीय रूप में किसी भी संसद् सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण सावजनिक विधेयक सरकार की ओर से किसी न किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। वित्त विधेयक अनिवार्यतः वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत होता है, और वह भी लोकसभा में ही। अन्य विधेयक संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। परन्तु महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रायः लोकसभा में ही प्रस्तावित करने का चलन है।

विधेयको का प्रस्तुत करने की तीन विधिया प्रचलित है—

- (i) साधारण प्रस्तुतीकरण (Dummy Introduction),
- (ii) दस मिनट के नियम का प्रस्तुतीकरण (Introduction under the Ten Minutes Rule), एवं
- (iii) विधेयक की व्यवस्था पर प्रस्ताव डालने वाला प्रस्तुतीकरण (Introduction under the leave to introduce provision)

साधारण प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत विधेयक के प्रस्तावक को विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व कोई भाषण नहीं देना पड़ता। वह केवल विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना मदन के लिपिक (Clerk of the House) को दे देता है। तत्पश्चात् अध्यक्ष विरोध को विधिवत् प्रस्तुत करने के लिये उसे बुलाता है। वह आकर अपने विधेयक को सदन के लिपिक के पास जमा करा देता है और वह स्वयं अथवा लिपिक विधेयक के शीपक को पढ़ देता है। इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुतीकरण की प्रिया पूरी हो जाती है। तत्पश्चात् यह प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक को पहली बार पढ़ा हुआ (First Reading) समझा जाय और उसे छपवाने की आज्ञा दी जाय। सामान्यतः यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और इस तरह विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है।

दस मिनट के नियम के प्रस्तुतीकरण का प्रयोग सरकार द्वारा विवादपूर्ण और महत्त्व के विधेयको के लिये किया जाता है। प्रस्तावक तो और विपक्ष के एक सदस्य को थोड़े-थोड़े समय में यह अवसर दिया जाता है कि प्रस्तावक विधेयक का उद्देश्य और उसका महत्त्व तथा विपक्ष उम्मीद आलाचना मक्षय म सदन के सम्मुख प्रकट करे। तत्पश्चात् यह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन पूरा समझा जाय और उसे छपवाने की आज्ञा प्रदान की जाय। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर विधेयक का प्रस्तुतीकरण और प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है।

विधेयक की व्यवस्था पर प्रस्ताव डालने वाले प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत प्रस्तावक अपने विधेयक के सिद्धांतों और उनके लागू रहने के लिये एक लम्बा भाषण देता है और यह प्रस्ताव रखता है कि मदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। विरोध करने वाले सदस्य प्रस्तावित विधेयक के सिद्धांतों के दोषों को सदन के सम्मुख प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। अंत में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि मदन का निर्णय प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो मदन के समक्ष यह प्रस्तावित किया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन (First Reading) पूरा समझा जाय और उसे छपवाया जाय। अधिक समय लगने के कारण इस विधि का अर्थ प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता।

द्वितीय वाचन—प्रथम वाचन के पश्चात् जब विधेयक छप जाता है, तब कैलेंडर (Calender) पर जा जाता है। विधेयक के दूसरे वाचन के लिये एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। इस तारीख को प्रस्तावक यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक को हमारे वार पढ़ा जाय।

द्वितीय वाचन (Second Reading) के समय विधेयक पर वास्तविक वादविवाद होता है। यह विधेयक के जीवन-परण का मग्न होना है। इस वाचन में विधेयक के शीर्ष, उद्देश्य, प्रयोजन और सिद्धांत आदि पर चर्चा कर वादविवाद किया जाता है। विधेयक के सिद्धांत, और उसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों पर पूर्ण विचार किया जाता है। इस अवस्था में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। मदन सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर देता है। यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित हो तो उसके अस्वीकृत हो जाने का तात्पर्य यह माना जाता है कि मदन का मंत्रिमण्डल पर विश्वास नहीं रह गया है। परन्तु ऐसे अवसर प्रायः बहुत ही कम आते हैं। द्वितीय वाचन के समय बहुमत की पूरी शक्ति इस बात पर केन्द्रित हो जाती है कि सरकार को हार न हो पाये। फिर भी सरकार विपक्ष की वजनदार आलोचना से प्रभावित अवश्य होती है और जिन संशोधनों को उचित समझती है, स्वयं स्वीकार कर लेती है।

द्वितीय वाचन में विधेयक को अस्वीकार करने के लिये प्रायः दो ढंग प्रयोग में लाये जाते हैं—प्रथम, सीधे मन्त्रिमण्डल में यह प्रस्ताव रख दिया जाता है कि अमुक विधेयक सिद्धांत रूप से दोषपूर्ण है, अतः उसे कानून न बनाया जाय, द्वितीय, विधेयक का प्रस्तावक जब यह प्रस्ताव करे कि विधेयक का दूसरा वाचन हो, तो विरोधी पक्ष की ओर से विधेयक को इतने समय बाद दूसरी बार पढ़ने का संशोधन रखा दिया जाय कि सदन का मंत्र ही समाप्त हो जाए। यह विधेयक को मन्त्रतापूर्ण ढंग से अस्वीकार करने की विधि है, जिसके द्वारा विधेयक स्पष्टतः अस्वीकार भी नहीं किया जाता और समाप्त भी हो जाता है।

गर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रायः द्वितीय वाचन की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं। यदि उन्हें सरकारी समर्थन प्राप्त हो जाय तो बात अलग है।

समिति स्तर—द्वितीय वाचन के बाद विधेयक किसी समिति के सुपुर्द किया जाता है। यदि वह वित्त-विधेयक है तो सम्पूर्ण सदन की समिति में भेजा जाता है, अन्यथा दोष सभी विधेयकों को प्रायः स्थायी समितियों में से किसी एक में अध्ययन द्वारा भेज दिया जाता है। सभी विधेयक को किसी विशिष्ट समिति (Select Committee) को भी दे दिया जाता है और वहां से लौटने पर या तो सम्पूर्ण सदन की समिति में या किसी स्थायी समिति में जाता है।

समिति स्तर का भी विधेयक के जीवन में बड़ा महत्व है। समिति में विधेयक के अर्थ-प्रत्यय पर विचार किया जाता है और इसकी धाराओं व

विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं अतः वहाँ विचार होने के उपरांत पुनः लाउ सभा में भेज दिया जाता है। सदन का लिपिक विधेयक को दूसरे सदन में ले जाता है। दूसरे सदन में भी फिर वही सप्ताह प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, ममिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर तथा तृतीय वाचन दोहराये जाते हैं। अन्तर केवल इतना होता है कि लाउ सभा में समिति स्तर पर स्थायी समितियों और विशिष्ट समितियों का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन् सम्पूर्ण सदन की समिति का प्रयोग होता है। यदि लाउ सभा विधेयक को स्वीकार कर लेती है, तो वह हस्ताक्षर के लिये राजा के पास भेज दिया जाता है, यदि वह विधेयक से असहमत होती है और उसमें संशोधन कर देती है तो विधेयक पुनः लोकसभा में लाउ आता है। लोकसभा में लिपिक (Clerk) प्रत्येक संशोधन का पढ़ना है और मंत्री उसके साथ, प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाय, इस आशय का प्रस्ताव रखता है। यदि प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक राजा की स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद विद्यमान रहते हैं तो उन्हें दूर करने के लिये दो विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं—

(1) दोनों सदन के कुछ प्रतिनिधि, जो प्रबंधक (Managers) कहलाते हैं अपने सम्मेलन द्वारा मतभेदों का समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन में लोकसभा के प्रबंधकों की सरया लाउ सभा के प्रबंधकों की सरया की दुगुनी होती है। यह सम्मेलन स्वतंत्र (Free) और अन्तरंग (Closed) दोनों प्रकार का हो सकता है। स्वतंत्र सम्मेलन में प्रबंधक मतभेदों के आधारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करके उनके पक्ष में विस्तारपूर्वक विचार प्रकट कर सकते हैं। यद्यपि मतभेदों को सुलझाने का यह एक अच्छा ढंग है, किंतु 1836 से इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अन्तरंग सम्मेलन में मतभेद के आधारों को एक लिखित वयान के रूप में विरोधी सदन के प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रथा का प्रारम्भ सन् 1851 में हुआ था। इस उपाय से दोनों सदन अपने मतभेदों को लिखित संदेशों द्वारा दूर कर सकते हैं।

(2) यदि उक्त ढंग से भी दोनों सदनों के मतभेद समाप्त न हो तो सन् 1949 में संशोधित 1911 के मसदीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कायदाही करके लोकसभा विधेयक को पारित करा सकती है, जिसके अनुसार लाउ सभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अधिक से अधिक एक साल विलंबित कर सकती है और उसके बाद राजा के हस्ताक्षर में विधेयक स्वतः कानून बन जाता है।"

राजा की स्वीकृति—विधेयक के जीवन का अन्तिम स्तर राजकीय स्वीकृति (Royal-Assent) का होता है। यह स्तर केवल औपचारिक है। विधेयक इस अन्तिम अवस्था में राजा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और अध्यक्ष की उपस्थिति में उनके शीपक लाउ-सभा में पढ़े जाते हैं। राजा के प्रतिनिधि द्वारा

घाषणा की जाती है कि "राजा एना चाहते हैं।" और इस तरह राजकीय स्वीकृति का फायदा समाप्त हो जाता है तथा विधेयक कानून बन जाता है एवं उसे सविधि पुस्तक (Statute Book) में लिख दिया जाता है।

व्यक्तिगत सदस्यों के प्रस्तावों और विधेयकों से

सम्बन्धित प्रक्रिया को विशेषताएं

कुछ सार्वजनिक विधेयक माध्याम सदस्यों द्वारा अथवा सरकारी या व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन पर विचार शुक्रवार को ही होता है। सदस्यगण अपने पक्ष लिपिक (Clerk) की सहायता में, जो मेज पर खड़ा रहता है, डाटा देते हैं। लिपिक उन पक्षों का एक-एक करके पढ़ता है। जिसका पक्ष पहले लिख आता है वही सदस्य अपना विधेयक सत्र के पहले शुक्रवार को प्रस्तुत करता है, दूसरे पक्ष वांग दूसरे शुक्रवार को और तीसरा तीसरे शुक्रवार को आदि। इस प्रकार लगभग सब शुक्रवार सरकारी सदस्यों (Private Members) के विधेयकों हेतु काम में आते हैं। स्पष्ट है कि इन सदस्यों के प्रस्तावों और विधेयकों के लिए मसद के कार्यक्रम में बहुत कम समय मिलता है। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक ऐसे नहीं हो सकते जो सार्वजनिक धन के व्यय से सम्बन्धित हों।

सार्वजनिक (व्यक्तिगत) विधेयकों से सम्बन्धित

विधि निर्माण प्रक्रिया

व्यक्तिगत विधेयक प्रायः नगरपात्रिकाओं और नगर निगमों जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रायः पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं और इनका सम्बन्ध सार्वजनिक हित माधन से न होकर विशिष्ट हित साधन से होता है। व्यक्तिगत विधेयक का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कोई निवृत्ति का अथवा अधिकार देना हो सकता है, या किसी स्थानीय संस्था को कोई कार्य करने की स्वीकृति देना हो सकता है, बशर्ते कि वह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप न करे।

इन विधेयकों के पारित होने की निम्नलिखित प्रक्रियाएँ हैं—

(1) प्रत्येक विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रायः मसद के बाहर से व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा भेजा जाता है।

(2) विधेयक प्रस्तावित करने के लिए मसविदे के साथ साथ एक याचना पत्र (Petition) भेजना अनिवार्य है। इसके भेजने से पूर्व उन व्यक्तियों को प्रकाशित सूचना देनी पड़ती है, जिनके निजी हितों पर इसका प्रभाव पड़ता हो। सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित सरकारी विभाग को भेजनी पड़ती है। यह सब कामवाही करने से पूर्व विधेयक पर किसी प्रकार का विचार करना सम्भव नहीं होता।

विधेय का प्रस्तुतीकरण चाहने वाला उतनी घन-राशि सरकारी कोष में जमा करा देता है जितनी उसमें व्यय होने की सम्भावना हो।

(3) विधेय संसद् में प्रस्तुत याचा का संसद् के दोनों सदन के एक एक अधिकारी—जिन्हें 'अमाउजनिंग विधेयको' या 'प्रायना-पत्र का परीक्षक' (Examiner of Petition of Private Bills) कहते हैं—द्वारा देखा जाता है और उस विधेयक की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जांचे द्वारा विचार किया जाता है। परीक्षक द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नियमानुसार प्रमाणित कर देने के बाद विधेयक को संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसका प्रथम वाचा हो जाता है।

(4) द्वितीय वाचा में विधेयक के सिद्धांतों पर विस्तारपूर्वक विवाद होता है और यदि विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हो जाता है तो उसे 'निर्विरोध विधेयको की समिति' (Committee of Unopposed Bills) में भेज दिया जाता है। यह समिति विधेयक की धाराओं पर विस्तार से विचार करती है और अपने प्रतिवेदन के साथ उसे सदन को लौटा देती है।

यदि द्वितीय वाचन में विधेयक का विरोध होता है तो उसकी व्यक्तिगत विधेयको की विभिन्न समितियों में से किसी एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति विधेयक के विषय में 'न्यायिक जांच' (Judicial Enquiry) करती है। समिति अपनी जांच केवल विधेयक की प्रस्तावना (Preamble) तक ही सीमित रखती है और विधेयक के सिद्धांतों पर ही पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनती है। यदि समिति विधेयक को कानून बनाने के अयोग्य समझती है तो वह समाप्त समझा जाता है, किंतु यदि समिति विधेयक सम्बन्धी सब बातों से सन्तुष्ट हो जाती है तो वह, विधेयक की धाराओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त, अपने प्रतिवेदन के साथ उसे सदन को वापस भेज देती है।

इसने बाद प्रतिवेदन स्तर पर द्वितीय वाचन व्यक्तिगत विधेयको का उत्ती तरह होता है, जिस तरह मावजनिंग विधेयको का। जिस विधेयक के पास समिति अपना प्रतिवेदन दे देती है, वह सदन में प्रायः बिना किसी बाद विवाद के पारित हो जाता है। जब सदन से स्वीकृत होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है वहाँ भी प्रायः इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तत्पश्चात् राजकीय स्वीकृति के बाद वह कानून बन जाता है।

वित्त विधेयको से सम्बन्धित विधि निर्माण प्रक्रिया

वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनका सम्बन्ध करो के आरापण, परिवर्तन या रद्द करने से, और सावजनिक कोषों के नियोजन (Appropriation of the Public Funds) से होता है। वित्त विधेयको की एक विविष्ट स्थिति होती है और ये अनिवार्यतः लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा वित्त विधेयको को सशोधित या दस्वीकृत कर सकती है, किंतु अब अनुदान के

लिए मांग की जाए तब यह प्राथित राशि का काम या अस्वीकार तो कर सकती है, पर उसे बढ़ा नहीं सकती। वित्त विधेयक पर लाइट सभा का कोई बल नहीं होता। वित्त विधेयक लोकसभा में उस समय तक प्रस्तावित नहीं किए जा सकते जब तक उन पर इस सम्प्रदाय में सम्राट की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। इस तरह लोकसभा आय व्यय के बजट (Budget) की पूरी जांच करती है और वित्तीय नीति पर पूरा-पूरा नियंत्रण रखती है।

वित्त विधेयकों की विधि निर्माण सम्प्रदायी प्रक्रिया निम्न प्रकार है—

(क) सभी वित्त-विधेयक राजा या रानी की सिफारिश पर सरकार की ओर से साधारणतः वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) द्वितीय वाचन में सिद्धांत के स्वीकार होने के उपरांत वित्त विधेयक सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House) में विचाराय प्रस्तुत होता है। सम्पूर्ण सदन की समिति में वित्त मंत्री विधेयक के सम्प्रदाय में भाषण देता है और विधेयक पर वाद विवाद होता है। जब सम्पूर्ण सदन की समिति विधेयक के व्यय से सम्बंधित भाग पर विचार करती है तब वह सम्भरण समिति (Committee of Supply) कहलाती है, और जब वह विधेयक के आय के साधनों से सम्बंधित भाग पर विचार करती है, तब उसे अर्थोपाय या साधन समिति (Committee of Ways and Means) कहा जाता है।

(ग) वित्त विधेयक भी विधि निर्माण-प्रक्रिया की उन समस्त सीढ़ियों को पार करता है जो सावजनिक विधेयकों के लिए वर्णित की गई हैं।

(घ) लोकसभा संपारित होने के बाद वित्त विधेयक लाइट-सभा में जाते हैं जो उन्हें पारित करने में अधिक से अधिक एक माह का देर कर सकती है। इस अवधि में लाइट सभा यदि विधेयक को पारित नहीं करती तो भी विधेयक सम्राट या मायाजी के पास भेज दिया जाता है और उसके हस्ताक्षर होकर अधिनियम का रूप धारण कर लेता है।

अस्थायी आदेश

(Provisional Orders)

सामाजिक अथवा व्यक्तिगत विधेयकों के विधि निर्माण प्रणाली के दापो को अस्थायी आदेश (Provisional Orders) द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया गया है। मसूदा विभिन्न सरकारी विभागों का यह अधिकार देती है कि वे व्यक्तिगत हितों की पूर्ति अस्थायी आदेश जारी कर सकते रहें ताकि लोगो का समग्र का मविधान भंगन की आवश्यकता न पड़े। व्यक्तिगत हितों से सम्बंधित लाभ अपने प्राप्ति पर सम्बंधित विभाग का दत्त है जिनमें यह धरलाया जाता है कि किस प्रकार के अस्थायी आदेश द्वारा उनका आवश्यकता पूरी हो सकती है। आवश्यकता अन्य

पडताल के बाद विभाग आदेश जारी कर देते हैं जिन्हें बाद में संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जब अस्थायी आदेशों की सरमाप्यता हो जाती है तो उन्हें एकत्र करके एक विधेयक के रूप में विभागीय मंत्री संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। इस विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया व्यक्तिगत विधेयकों जैसी होती है। प्रस्तुतीकरण और प्रथम वाचन के बाद द्वितीय वाचन होता है। तत्पश्चात् उसे अर्थात् पुष्टिकरण विधेयक (Confirmation Bill) को निर्विरोध विधेयकों की समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति आवश्यक विचार विमर्श के बाद अपने प्रतिवेदन सहित विधेयक को संसद को लौटा देती है और तब सार्वजनिक विधेयक की प्रक्रिया द्वारा वह पारित कर दिया जाता है।

अस्थायी आदेश प्रायः छ प्रकार के निकाले जाते हैं। प्रथम, कुछ आदेशों को प्रभावी होने के लिये संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। द्वितीय, कुछ आदेश गुरु स ही प्रभावी हो जाते हैं, परंतु उन्हें संसद के संक्षेप प्रस्तुत करना आवश्यक है। तृतीय, कुछ आदेश ऐसे हैं जिन्हें प्रभावी बनाने के लिये 40 दिन पूर्व संसद के दोनों सदनों के सम्मुख लाना आवश्यक होता है। चतुर्थ, कुछ आदेश केवल तभी तक प्रभावी रहते हैं जब तक कोई बाहरी निरायण न पति न करे। अंतिम, कुछ आदेश हर हालत में अस्थायी होते हैं और तब तक प्रभावी नहीं बनते जब तक ये अस्थायी आदेश पुष्टिकरण अधिनियम (Provisional Orders Confirmation Act) का अंग बनकर संसद द्वारा पारित न हो जायें।

प्रदत्त व्यवस्थापन

(Delegated Legislation)

प्रदत्त व्यवस्थापन के नियम और विनियम हैं जिनका प्रभाव विधियाँ के समान होता है और जिन्हें संसद के दिये हुए अधिकार के आधार पर प्रशासनिक विभाग जारी करते हैं। इनको प्रकारानुसार से सविधिगत आदेश (Statutory Instruments) कहा जा सकता है।

इंग्लैण्ड में पहले जहाँ प्रशासनिक क्रिया काल्प बहुत सीमित थी तो विधान-मण्डल मध्यमाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा विधियाँ बनाते थे और विनियम अधिकारी उन्हें लागू करते थे। इस तरह उस समय विधान मण्डल तथा प्रशासन के मध्य अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी स्पष्ट विभाजन होता था। शून्य शून्य प्रशासनिक कार्यों और सार्वजनिक समस्याओं में वृद्धि होती रही। आज स्थिति यह है कि संसद पर व्यवस्थापन सम्बन्धी विनाल-कार्य-भार आ पड़ा है। संसद के पास प्रायः इनका समय नहीं बचता है कि वह विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर पूरी तरह विचार कर सके। इसके अलावा संसद सदस्यों में इतनी प्राविधिक योग्यता भी नहीं होती कि वे विधेयकों पर आवश्यक सूक्ष्मता के साथ विचार करें।

इन कठिनाइयों के कारण अब बहुत कुछ विधि निर्माण जिन व्यवस्थापिका के

हाथों से लिमन वर नायकारिणी के हाथों में आ गयी है। जाधुनिक माल में समुद्र बहुत ही साधारण शब्दों में (In general terms) बानून पाम कर देती है। और उनके स्पष्टीकरण का कार्य वायकारिणी के कंधा पर आ पड़ता है, जिसे मन्त्रिण प्रशासकीय अधिकारियों पर छोड़ देते हैं। इस तरह विभागों को यह छूट मिल जाती है कि वे विधि के सम्प्रदाय में आवश्यक विनियम पान कर दें जिनका प्रभाव भी विधियाँ के समान ही होता है। माराश यह हुआ कि आज समुद्र द्वारा व्यवस्थापन सम्बन्धी अपने अधिकार एक वर्ग नीमा तक प्रशासनिक विभागों को सौंप दिये गए हैं। यही प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) है।

ब्रिटन में प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रगति

प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रगति मसदीय कार्यों के विकास के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। 17वीं जार 18वीं सदियों में यह प्रवृत्ति बहुत कम थी किन्तु बिनापतया 1832 के बाद से वायकारिणी विभागों को व्यवस्थापन की गतिमा देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। डॉ० जेनिम के अनुसार ज्या ज्यो समूहवाद (Collectivism) के विकास के कारण सरकारी गतिन बढ़ती जाती है त्यो-त्या प्रदत्त बानूना की सख्या में भी वृद्धि होती जाती है। सन 1906 से केन्द्रीय सरकार का अनक प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्य द दिये जाने के बाद में विभागों द्वारा निमित्त नियमां और व्यवस्थापन की मरमा बहुत ही बढ़ गयी है।

प्रदत्त व्यवस्थापन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अनुमान इसी एक सत्य से लगाया जा सकता है कि 1927 में सदन ने ता देवल 43 सविधियाँ (Statutes) पास की थी, एकिन विभागों ने 1949 आदेश जारी किये थे। 1970 में तो यह प्रवृत्ति 1927 की तुलना में बहुत ही अधिक जोर पकड़े हुए है। प्रदत्त व्यवस्थापन के महत्व पर टिप्पणी करते हुए सेमिल टी कार (Cecil T Carr) ने लिखा है कि 'बानून की किताय उस वकत तक अधूरी ही नहीं, अमात्मक भी होती है जब तक कि उस प्रदत्त विधान के साथ मिलाकर न पढ़ा जाए, जिसने द्वारा उसका बहुत कुछ बिम्बार और सगोधन हा जाता है।'

प्रदत्त व्यवस्थापन पर आवश्यक टाक

प्रशासकीय विभाग बानूनी नीमा के अंतर्गत ही आदेश जारी कर सकते हैं। ये बानून की इस पवार तोड़ मरोड़ नहीं सकते कि उनका प्रमाणन ही समाप्त हो जाय। नागरिकों को बानून विरायी विगी भी आयेन के विरुद्ध अपील करन का अधिकार हाता है। 'याया'य ऐसे आदेश को अपने विनय के अनुसार अवैध घोषित कर सकते हैं। सदन-मदस्य भी सदन में ऐसे आदेश की पञ्जियाँ उठा सकते हैं। समुद्र उस आयेन का समाप्त कर सकती है।

प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण

(1) विधि-निर्माण का काम इतना बढ़ गया है कि समयाभाव के कारण संसद् उसे दीव दग से निभा नहीं पाती।

(2) संसद के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह दिन प्रतिदिन की प्रशासकीय कारीबारों का पूर्ण पाठ रग सके।

(3) विभागीय अधिकारी संसद सदस्यों की तुलना में कानून की कारीबारों को समझने में अधिक दक्ष होते हैं।

(4) जनता की इच्छानुसार संसद नीति की रूप रेखा तो नहीं प्रसार बना सकती है किन्तु उसके सम्बन्धित बूढ़ बातों का समझ कर आवश्यक आदेश प्रशासकीय विभाग ही जारी कर सफ़्त है।

(5) संसद का जयिवेशन हर समय नहीं होता, अतः आवश्यकता होने पर कार्यपालिका अपने ही उत्तरदायित्व पर नियम बना देती है और आदेश जारी कर देती है।

प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना और मूल्यांकन

अनेक विद्वानों ने प्रदत्त व्यवस्थापन की निम्न जाधारों पर आलोचना की है—

(1) प्रदत्त व्यवस्थापन संसद की सर्वोच्च शक्ति पर आघात करने वाला है।

(2) इस व्यवस्था द्वारा नीकरशाही की शक्ति का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह 'नई निरपुंसता' (New Despotism) है जिससे अधीन विभाग अपनी शक्ति का दुरुपयोग बड़ी सरलता से कर सकते हैं।

ऑग (Ogg) की मान्यता है कि "प्रदत्त व्यवस्थापन के विरोध का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि जिस समय इस पर विचार करना आरम्भ किया जाता है, यह उसी समय समाप्त हो जाता है।"

समर्थकों का कहना है कि—

(1) इस व्यवस्था के कारण संसद को इनका समय मिल सकता है कि वह विधेयक के उद्देश्यों और निष्ठाओं पर पूरा विचार-विमर्श कर सके।

(2) प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा अज्ञात भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार ठीक समय पर उत्तर के मुताबिक कानून में, बिना किसी सहायन के, काम चलाने की शक्ति मिल जाती है।

(3) प्रदत्त विधान द्वारा तबे परीक्षण करने और उनसे प्राप्त अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर मिलता है।

(4) संसद और आन्तरिक आवश्यकताओं के लिए आदेश जारी करने हेतु प्रदत्त विधान की व्यवस्था ही एकमात्र सुगम उपाय है।

(5) संसद में कानून प्रायः जटिलवादी में पाम किए जाते हैं, अतः असंतोष-जनक रहते हैं। प्रदत्त विधानों द्वारा नियम विनियम खूब मोच विचार कर तैयार किए जाते हैं जो अधिक बोधगम्य और तर्कसम्मत होते हैं।

इही कारणों से लाम्बे का मत है कि "प्रदत्त विधान एक ऐसी प्रारम्भिक प्रक्रिया सम्बन्धी सुविधा है जो एक विधियात्मक राज्य (Positive State) के लिए नितात आवश्यक है।



राजनीतिक दल (POLITICAL PARTIES)

“राजनीतिक दल अनिवार्य हैं।

कोई भी बड़ा स्वतन्त्र देश उनके बिना
नहीं रहा है। किसी ने भी यह नहीं बिताया
है कि उनके बिना प्रतिनिधि सरकार कैसे काम कर सकती है ?”

—लाइबर्ट

आज के प्रजातान्त्रिक युग में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। यद्यपि सभी राजनीतिक दलों का मानून के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना प्राप्त नहीं होती और वे आवश्यक रूप से सरकार के अंग भी नहीं होते, तथापि लोकतन्त्रात्मक शासन के सफल संचालन के लिए उनका होना अनिवार्य है। आधुनिक युग प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि प्रजातन्त्र का युग है। आधुनिक प्रजातन्त्रीय राज्या के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता का कम नहीं लिया जा सकता। अपने बलवान् महत्व के कारण ही उन्हें ‘प्रजातन्त्र का प्राण’ और ‘सरकार का चतुर्थ अंग’ कहा गया है। वास्तव में प्रजातन्त्र के लिए राजनीतिक दल प्रेरक-शक्ति हैं। उनके अभाव में प्रजातान्त्रिक सरकार सम्भार के साथ चल ही नहीं सकती।

प्रजातन्त्र में विभिन्न विरोधी दलों का अस्तित्व स्थापित भी आवश्यक है कि सत्ता के दुरुपयोग का विरोध हो सके और वे आग बंधू आर्थें। प्रजातन्त्र में सत्ता के दुरुपयोग का विरोध करने के लिए विरोधी दल उनकी स्वतन्त्रता का उपयोग करके उसे संभाल सकते हैं। वे सामान्य रूप से निर्वाचन करके ही सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। प्रजातन्त्र में विरोधी दलों की उपस्थिति संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा में सहायक है।

निम्न आधुनिक युग का स्थापक दल राजनीतिक दल है। वे राजनीतिक

दल के महत्व को इंगित करते हुए लाफ़ी ने कहा है "राजनीतिक दल देश में क़ैसरशाही (Caesarism) से हमारी रक्षा करने के सर्वोत्तम साधन हैं।"

ब्रिटिश दल प्रथा का विकास

(The Development of the British Party System)

ब्रिटिश प्रजातन्त्र को वायावित करने में राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग रहा है। राजनीतिक दलों के विकास ने राजतन्त्र का लोकतंत्रीकरण करने में बड़ी महायत्ना पटु चायी है। पहले राजा ही सरकार होता था और राजा तथा उसके दरबारी मित्र सरकार चलाते थे। सरकार द्वारा किये जाने वाले अत्याचार राजा के अत्याचार माने जाते थे। पर समय के साथ लोग यह समझ गये कि अत्याचारों के लिए राजा नहीं बल्कि उसके दरबारी अधिक उत्तरदायी ह, अतः दरबारियों को ज़ात देना उचित होगा। धीरे-धीरे जनता में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजा को बनाये रखें और भी सरकार को राष्ट्रीय मनसूबे के प्रति उत्तरदायी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर शासन मत्ता अपने हाथ में लेने के प्रयत्नों के कारण विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। कालांतर में लागू यह अच्छी तरह समझ गये कि राजनीतिक दल समूह के माध्यम में राजा की सरकार पर वांछित नियंत्रण रखने में और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने में सक्षम हो सकते हैं।

धीरे-धीरे राजनीतिक दल क़ानून धनिकों की वस्तु नहीं रहे बल्कि जनमाधारण में लोकप्रिय हो गये और उनके राष्ट्र-ध्यापी संगठन बन गये। लोकहितकारी राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़े जाने लगे और प्रत्येक दल का यह प्रयत्न रहने लगा कि वह जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करके मन्दीय बहुमत पाये। ब्रिटेन में जिम प्रणाली का प्रचलन हुआ, उसने जनता में अनेक दलों को पनपने का अवसर नहीं दिया। अतः ब्रिटेन में मन्दीय दो ही दलों की प्रधानता रही, और यदि दो से अधिक दल हुए भी तो उनकी प्रभावशालीता सा रहा। आज भी यही अनुशासन और श्रमिक दल ही सर्वोपरि हैं। नए दलों का महत्त्व नहीं उभराने दे।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल स्टुअर्ट राजाओं और उनकी मन्दीयों के बीच हुए साविधानिक संघर्ष से पैदा हुए। प्रारम्भ में दल इन राजनीतिक नहीं थे, बल्कि उनका रूप दल दे दिया था। उनका तरीका उन्ने अमन्य और उग्र थे। ब्रिटेन में मन्दीयवादीन युगों में ये दल आपस में समझ में नहीं, अपितु युद्ध योग्य भी उठा करते थे। पहला अवसर चार्ल्स प्रथम के शासन काल में गृह युद्ध (Civil War) 1641-1649 का था। राजा के समर्थक रॉन्डहेड्स (Roundheads) कहे जाते थे। पुनर्स्थापना (The Restoration) के कुछ समय के लिए इन दोनों के परस्पर मतभेदों का

कम कर दिया, किंतु रक्तहीन शान्ति (Glorious revolution) न इनको पनपना दिया। जो व्यक्ति कभी जेम्स द्वितीय का और उसके पुत्र का समयन करने थे, वह टोरी (Tories) कहा जाने लगा और जो रक्तहीन शान्ति तथा हाना-घराना (House of Hanover) का समयन करते थे, उन्हें विह्म (Whigs) कहा जाने लगा। टोरियो ने बहुत दूर तक कैबेलियर की परम्पराओं का अनुसरण किया जबकि विह्म राजपट्टावृत्त के मतों पर चले। परंतु इस अवधि में राजनीतिज्ञ दलों के दृष्टिकोण में एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब दल सरकार बदलने के लिए राजा का बदलना जरूरी नहीं समयने लग चले के समूह पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे।

कालांतर में विह्म और टोरियो ने अपनी प्रकृति बदल ली और उन्होंने लगभग विशुद्ध राजनीतिक आचरण अपना लिया। कालांतर में इन दोनों के नामों में परिचय हुआ। विह्म और टोरी का स्थान क्रमशः उदार या लिबरल (Liberal) और ज़रुदार या कंजर्वेटिव (Conservative) ने ले लिया। 1830 के बाद कुछ विराट् दलों को छोड़कर उदार दल 1874 तक पदावृत्त रहा और उमक बाद मॉर्गन अवस्थाओं को छोड़ कर 1905 तक अनुदार दल के हाथ में सत्ता रही।

दूसरी चीज सन 1832, 1867 और 1884 के सुधार अधिनियमों ने ब्रिटिश राजनीति में एक नयी तत्त्व का प्रवेश दिया। इन अधिनियमों ने मतदान के अधिकार को बहुत उदार बना दिया तथा विधान प्रणाली के अनन्य दावों को दूर कर दिया। 'लैबोर पार्टी' (Labour Party) का मत देना का अधिकार प्राप्त गया जिससे एक नयी राजनीति व्यवस्था का जन्म हुआ। लैबोर पार्टी (Labour Party) का प्रारम्भ था जो 1902 में अस्तित्व में आई। प्रथम महापुरुष के सम्मान होने तक उमक उदार दल का स्थान ऐसा गुरु कर दिया। 1966 के निर्वाचनों में जहाँ लैबोर दल ने 363 वहाँ थर्मिन्स विराधी अनुदार दल ने 253 स्थान जीते, वहाँ उदार दल का मत में केवल 12 स्थान मिले।

ब्रिटिश दल-प्रणाली की विशेषताएँ

(Characteristics of British Party System)

द्वि-दल प्रणाली—द्वि-दल प्रणाली में प्रवृत्ति द्वि-दल प्रणाली की ओर है। भारत में प्रथम दो समय कंग्रेस और तथा राजपट्टावृत्त नामक दो दल थे जो बाद में द्वितीय में समय टोरी और विह्म दल प्रमुख रहे। तत्पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी में अनुदार और उदार दल प्रमुख रहे और आज अनुदार तथा विह्म दल की प्रणाली है। द्वि-दल प्रणाली का मत है कि द्वि-दलीय प्रणाली में विधानमंडल में विचार, सुझाव और मांगों का मंचार होता है। उमक दल व्यवस्था की स्थिति और उमक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान होता है तथा दलों में मतों का वितरण होता है जिसका सुरक्षा नहीं करता।

केन्द्रीयकरण—वादी की एकरूपता और शुद्ध भौगोलिक आधार के कारण ब्रिटिश दल की प्रवृत्ति केन्द्रीयकरण की है। सम्पूर्ण दल ज़रूर में नीचे तक एक सूत्र में आवद्ध रहना है। दलीय नेताओं तथा दल के केन्द्र का पूरे दल पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीय संगठन का सदस्य अस्तित्व बना रहना है और उसका ध्यान मुख्यतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर लगा रहता है। ब्रिटेन के विपरीत अमेरिका में दलों की विविधता विकेन्द्रीयकरण की है।

धनशासन एवं साहचर्य—ब्रिटिश दल बहुत ही अनुगामी है। दल के सचेतक ही निर्णय करते हैं कि मतदाता में किन दलीय सदस्यों को वोट और क्या बोलना है अथवा किस विधायक के पक्ष या विपक्ष में मत देना है? प्रत्येक दल की अपनी नीति है, अपना आदर्श और कार्यक्रम है। दलीय सदस्यों में साहचर्य की भावना प्रबल रूप से विद्यमान रहती है। दल की सदस्यता ऐच्छिक है किन्तु सदस्य दलीय सूत्र में आवद्ध रहने के कारण परस्पर अति निकट हो जाते हैं। दल का समर्थन दल की एक व्यक्ति का रूप देता है और उसे संगठित तथा अनुशासित बनाता है।

नेता का महत्व—ब्रिटेन में दल का नेता दल का केन्द्र स्थल और दल का प्रतीक माना जाता है। वह आधुनिक चुनाव पणाली रूपी नाटक में केन्द्रीय व्यक्तित्व की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दल की नीतियों का दलीय नेता के व्यक्तित्व के माध्यम से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मतदाता वस्तुतः किसी उम्मीदवार विशेष का नहीं बल्कि भावी प्रधानमन्त्री का मत देता है और चुनाव बहुत कुछ नेता के व्यक्तित्व के इव-गिड लड्डा जाता है, न कि नीति और दल के आधार पर। दल के नेता की इस महत्वपूर्ण स्थिति को प्रत्येक सत्ता संस्था समझता है और इसलिए वह नेता को पूर्ण समर्थन देता है।

सदस्य सदस्यों पर नियंत्रण—सदस्यगण दल नियंत्रण के समर्थन पर विजयी होते हैं। दलीय कार्यक्रम के आधार पर उन्हें मत मिलते हैं और जीन में दलीय नेता की लोकप्रियता का अधिक हाथ रहता है। अतः प्रत्येक सदस्य यह समझता है कि दलीय कार्यक्रम या नेता से पक्षक स्वतंत्र कदम उसका राजनीतिक अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। परिणामस्वरूप वह दलीय नियमों और दलीय शासन के अधीन रहता है।

यंग प्रवृत्ति एवं सैद्धान्तिक मतभेद—ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का वर्ग के आधार पर सरलतापूर्वक पक्षकारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सभी वर्गों से मत प्राप्त करने की कांक्षा करते हैं और अनुदार एवं मजदूर दोनों दल मध्यम वर्ग से मत की जागृ कर रहे हैं। किन्तु मजदूर दल साम्यवाद मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े व्यवसायियों तथा पूँजीपतियों को कमजोर बनाने के पक्ष में है। इससे विपरीत अनुदार दल सामान्यतः धनिक एवं कुलीन वर्गों का नेतृत्व करता है। स्पष्ट है कि दलों ने बीच इतना व्यापक वैभिन्न्य रहता है कि मतदाता को

वामनविश्र छाट का अवसर मिलता है। दलों के मतभेद मँडारित्व होते हैं, केवल दलीय नहीं। मतदान का मस्य छाटने के साथ-साथ कार्यक्रम की छाट करनी होती है। मजदूर दल समाजवाद में विश्वास करता है तो अनुदार दल स्वतंत्र एवं निजी उद्योगों का समर्थक है। मजदूर दल का विश्वास राष्ट्रीयकरण अथवा एकाधिकारी उद्योग के मजदूरीकरण अर्थात् उन पर राज्य के स्वामित्व की स्थापना में है जबकि उदार दल राजनीय केन्द्रीयकरण अथवा समाजवादी नीतिरहाही का विरोधी है।

उच्च उद्देश्य, गम्भीर प्रकृति एवं सतत कार्यशीलता—ब्रिटिश राजनीतिक दलों के कामकाज में उच्च उद्देश्यों में राजनीति में भाग लेने हैं, नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और निरंतर कार्यशील रहते हैं। वे व्यक्तिगत हितों और स्वाध्याय उद्देश्यों के लिये सामान्य राजनीति में प्रवेश नहीं करते। तूट प्रथा तथा अवलम्बन का ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था में अभाव है। सामान्य निर्वाचन में जीत के बाद विद्यमान दल के स्पेच्छाधिकार में अमेरिका के समान नीरसियों या धन की भरमार नहीं रहनी। ब्रिटिश में राजनीतिक दल सामान्य निर्वाचनों, के बीच भी तदैव कार्यशील रहते हैं इसलिए कि निर्वाचन हो जायें, यह कहना कठिन है। इसलिए दल आम निर्वाचन के प्रति सदैव तैयार रहते हैं। शीघ्र कार्य करना, माहित्य तैयार करना, मनाये बुलाना, स्थानीय नालाओं का संगठित करना स्थानीय शासन के चुनावों में भाग लेना आदि मसल व मंत्रिमण्डल के सदस्यों में सम्पर्क स्थापित करना आदि ऐसे काम हैं जिन्हें राजनीतिक दल अवकाश के समय करते हैं। अतः में, ब्रिटिश राजनीतिक दलों का जाचरण और व्यवहार बड़ा उच्च कोटि का होता है। वे ईदर का महत्ता में विश्वास करते हैं और अपनी क्रिश्चियन प्रकृति का सरलता से परित्याग नहीं करते।

प्रमुख राजनीतिक दल

(Major Political Parties)

उन समय ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल ये हैं—

- (1) अनुदार या रूढ़िवादी दल (Conservative Party),
- (2) श्रमिक दल (Labour Party), एवं
- (3) उदारवादी दल (Liberal Party)।

अनुदार या रूढ़िवादी दल

जेनिंग्स (Jennings) के अनुसार 'जून 1812 में व्हिग टांगा (Whigs) के प्रभुत्वकाल में मृदारवादी अधिनियम पारित हो गया तो टारी दल के अनुसरणियों ने यह आवाज उठाई कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व खतरे में है। उस समय उन्होंने उसी टांगा के रूप में अपने दल का नाम व उरवेडिय अर्थात् रंग रंग रंग करने वाला दल रखा।'

नोति एव वायक्रम—अनुदार दल आकस्मिक और आमूल परिवर्तनों का विरोधी है। यह परम्परागत मस्थाओं, प्रथाओं और विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है। रूढ़िवादी दल परिवर्तन को विलुप्त नहीं फ़क़ देता, बल्कि मावधानी पूर्ण एवम् म थर (Slow) परिवर्तन पर जोर देता है और प्राचीन सामाजिक ढाँचे को यथामुम्भव ज्यों का त्यों रखना चाहता है। यह पूँजीवादी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पोषक है। इसकी राष्ट्रीयता कट्टर राष्ट्रीयता है। यह विश्वास करता है कि अंग्रेज़ जाति अन्य सब जातियों में श्रेष्ठ है तथा अन्य जातियों को सम्पत्ता मिश्रित उन्नति कर्तव्य है। ब्रिटिश राजमुकुट की छत्रछाया में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और उन्नति विस्तार करना इस दल का सर्वोपरि न्येय रहा है। अनुदारवादी नेता बर्लिन अपने मन्त्रित्व-काल में भारत को स्वतन्त्रता देना का सदैव विरोध करते रहे और श्रमिक-दल की सरकार बनने पर ही भारत को स्वतन्त्रता मिल पाई। जिन राजनीतिक मस्थाओं को अनुदार या रूढ़िवादी दल बनाये रखना चाहता है वे हैं— राजमुकुट के विशेषाधिकार लाड—सभा की स्वतन्त्रता, इंग्लैंड के नौबे की विशेष स्थिति, राष्ट्रीय एकता, शक्तिशाली नौकरशाही, सर-सरकारी सम्पत्ति की राज्य के हस्तक्षेप में विमुक्ति, साम्राज्यवादियों और जमींदारों व पूँजीपतियों के हितों की रक्षा।

अनुदार दल, आर्थिक धन में, व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत व्यवसायों पर आधारित समाज व्यवस्था का पोषक है। अतः स्वभावतः यह उद्योगों के समाजीकरण का विरोध करता है। अनुदारवादी ऐसी किसी आर्थिक व्यवस्था का समर्थन नहीं करते जिसमें अतन्त्र राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक समानता का पक्ष लेते हुये उत्पादन के साधनों और व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण का प्रतिपादन किया जाता हो।

अनुदार दल म टोरी लोग अन्य भी हैं और उ होने दल के दक्षिण पक्ष का निर्माण किया है। ये दक्षिण पक्षी पूर्ण अपरिवर्तनवादी अथवा रूढ़िवादी हैं, किन्तु दल के अधिकांश सदस्यों की मान्यता यह होगी जा रही है कि पूँजीवादी व्यवस्था को अपने-आप को इस रूप में बदल लेना चाहिये कि उसे धनियों का ही नहीं अपितु सभी वर्गों का समयन प्राप्त हो जाय। उनकी यह भी इच्छा है कि प्रजातन्त्र की रक्षा हो और राज्य सामाजिक सेवाओं के माग पर अग्रसर होता रहे। वे यह भी कहते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था के पतन-पापण का यह अभिप्राय नहीं है कि समस्त उद्योगों पर व्यक्तिगत अधिकार स्थापित हो जाए, अपितु हाना यह चाहिये कि सग्वार उद्योगों के विज्ञान व प्रति महानुभविपूर्ण रख रखे और आवश्यकतानुसार प्राइवेट उद्योगों का प्रगुल्ला (Tariffs), आर्थिक सहायता (Subsidies) एवम् बाजार मगठन (Market Organisation) द्वारा मदद दे। राष्ट्रीय भावनाओं और उद्योगपतियों के हितों, इन दोनों में प्रभावित होकर

अनुदार दल अब बेकारी की समस्या के समाधानार्थ गृह-उद्योगों के गहराई को प्रोत्साहन देने लगा है।

श्रमिक दल के उद्देश्यों के कारण अनुदार दल के कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। इस दल के युवक सदस्य चाहते हैं कि दल का कार्यक्रम उतना ही प्रगतिशील और ओजस्वी (Progressive Vigorous) बने जितना कि श्रमिक दल का है।

रूढ़िवादी दल अन्तर्राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों में दृढ़ विश्वास नहीं रखता। वह प्रयत्न और दृढ़ भेदिक नीति का समर्थक है। उसका मन है कि शांति रक्षा के लिए ब्रिटन का अपनी सैनिक शक्ति और शस्त्रों की प्रचुरता पर निर्भर रहना चाहिये। इस और अमेरिका के बीच चलने वाला शीत युद्ध में यह ब्रिटन के दायित्व का समर्थक है।

सदस्यता—इस दल की सदस्यता प्रायः धनीमानी वर्ग के लोगों की है। कुछ सरप्रास में उच्च माध्यमिक वर्ग के एक व्यक्ति भी हैं जो श्रमिकों की अपेक्षा स्वयं की घमिका के अधिक निकट समर्थते हैं और उनकी प्रवृत्ति पूँजीपतियों के साथ मिलने की है। सदस्य प्रायः उच्च और माध्यमिक वर्ग के लोग ही अनुदार दल के सदस्य हैं। निर्वाचन में विजय के लिए अनुदार दल को निम्न माध्यमिक वर्ग एवं काम करने वाले वर्ग के मतदाताओं का भी आश्रय लेना पड़ता है।

संगठन—अनुदार दल का एक गतिशील और सुदृढ़ संगठन है। इसका एक अतिरिक्त देशीय या राष्ट्रीय संगठन है जिसे 'कंसर्वेटिव यूनियन ऑफ कन्जर्वेटिव एण्ड यूनियनिस्ट एसोसियेशन्स' (National Union of Conservative and Unionist Associations) कहा जाता है। राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलीय सभा की स्थापना करना, दल के सभी संगठनों के बीच सम्पर्क स्थापित करना और दल के केन्द्रीय कार्यालय से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखना है। राष्ट्रीय संगठन का अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है, जिसमें दल के वार्षिक विचार-सत्रों का विह्वलोरन किया जाता है और आगामी वर्ष के लिए दलीय कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इस वार्षिक अधिवेशन में केन्द्रीय कार्यालय के सदस्य, क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय संगठन और केन्द्रीय संगठन के प्रमाणित एजेंट तथा संस्थापक आदि भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में दल का नेता प्रायः भाग नहीं लेता, परन्तु वह एक सार्वजनिक सभा में भाषण देता है जो सम्मेलन समाप्त होने के तुरन्त बाद आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय संगठन की एक प्रमुख समिति होती है जिसे केन्द्रीय परिषद (Central Council) कहते हैं। यह वार्षिक सम्मेलन का प्रतिष्ठित रूप है। इसकी बैठक भी सामान्यतः वर्ष में एक बार होती है, यद्यपि आवश्यकतानुसार वितर्कित

बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। केन्द्रीय परिषद राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों को चुनती है। कार्यकारिणी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करती है और राष्ट्रीय संगठन के नियमों में संशोधन लाती है। यह दलीय एवं सांख्यिक प्रश्नों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करती है और अपने निर्णय दल के नेता को भेजती है। केन्द्रीय परिषद की सदस्यता लगभग 2000 है।

राष्ट्रीय संगठन की एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) होती है जिसकी सदस्य संख्या लगभग 150 है। दल के संसदीय और सांख्यिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी या प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। समिति की बैठक साधारणतया दो मास में एक बार होती है। इसका एक सभापति होता है जिसका चुनाव यह स्वयं करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं—राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नामांकन सुझाव देना, किसी क्षेत्रीय संगठन की कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रेषित किसी मतभेद अथवा विवाद पर निर्णय करना, आवश्यकता पड़ने पर अथवा राष्ट्रीय परामर्शदात्री समितियों की स्थापना करना, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव अथवा मुद्दे पर विचार विमर्श करना, वार्षिक सम्मेलन और केन्द्रीय परिषद की अपनी कार्यवाहियों पर रिपोर्ट देना तथा केन्द्रीय परिषद की बैठकों के अंतर्काल में उसके कार्यों को सम्पन्न करना।

राष्ट्रीय संगठन का एक अन्य छोटा निकाय सामान्य उद्देश्य समिति (General Purposes Committee) है, जिसमें लगभग 56 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक साधारणतया प्रतिमास होती है। इसके प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं—कार्यकारिणी समिति को दिये गए अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय संगठन के सब साधारण व असाधारण कार्यों को सम्पन्न करना, केन्द्रीय परिषद और वार्षिक सम्मेलन की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करना, प्रांतीय परिषदों, क्षेत्रीय संगठनों एवं केन्द्रीय सचों द्वारा पारित प्रस्तावों पर विचार करना आदि।

अनुसार दल प्रांतीय और क्षेत्रीय संगठनों की दृष्टि से भी बड़ा सुव्यवस्थित व सुगठित है। इंग्लैंड और वेल्स को दलीय संगठन की दृष्टि से 12 प्रांत (Areas) में बांट दिया गया है। प्रत्येक प्रांतीय संगठन का एक प्रधान होता है। प्रधान के अतिरिक्त अध्यक्ष, कुछ उप प्रधान, गोप्याध्यक्ष और सचिव इनके पदाधिकारी होते हैं। प्रांतीय संगठन की केन्द्रीय परिषद को प्रांतीय परिषद (Area Council) कहा जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों और सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करती है। प्रांतीय संगठन का प्रधान प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों के सचिव का नेता और प्रमुख होता है।

अनुसार दल में सबसे नीचे के स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संगठन, जिसे निर्वाचन क्षेत्रीय मंडल भी कह सकते हैं, होता है। इस क्षेत्रीय संगठन या निर्वाचन-क्षेत्रीय-संघ (Constituency Association) का काम

अपने क्षेत्र में दल का प्रचार करना और निर्वाचन के समय दल के प्रत्यासी के लिए समर्थन प्राप्त करना होता है। ये राष्ट्रीय संगठन दल के वैदेशीय कार्यालय के परामर्श से मसद् की सदस्यता के लिए प्रचारियाँ का चयन भी करते हैं। क्षेत्रीय संगठनों के अतिरिक्त अनुदार दल के लगभग 1500 क्लब भी हैं। ये क्लब जनता से सम्पर्क रखते हैं और इनका एक-एक प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन का सदस्य होता है।

अब दल की तरह अनुदारवादों दल का एक वैदेशीय कार्यालय (Central Office) भी है जो लंदन में स्थित है। यह दल के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे चलाने के लिए एक प्रधान मंचालन होता है। यह कार्यालय दल के संगठन का केन्द्र है और इसकी क्रियाशीलता पर ही दल का संगठन व दल की उन्नति निर्भर है। आवश्यकतानुसार नये स्थानीय संगठनों की स्थापना करता, उनका मार्ग-निर्देशन करना, दलीय कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार करना, दलीय साहित्य का सशुद्ध वितरण करना, निर्वाचन के समय दलीय उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन करना आदि इस वैदेशीय कार्यालय के प्रमुख काम हैं।

अनुदार दल का सदस्यीय संगठन भी है, जिसका कार्य सदस्यीय दल के उद्देश्यों की साधना करना होता है। दल का सदस्यीय संगठन दल के नेता का निवाचन करता है। यदि दल शासक दल के रूप में प्रकट होता है, तो जिस व्यक्ति को वह अपना नेता निर्वाचित करता है, उसे राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जब दल शासक दल के रूप में नहीं होता, तब यह संगठन लोकसभा के लिए दल के नेता का चुनाव करता है। दल का सदस्यीय संगठन प्रत्येक सदन में होता है। लोकसभा में अनुदार दल के संगठन को '1922 की समिति' (Committee 1922) के नाम से पुकारा जाता है। सदस्यीय संगठन और उसकी कार्यकारिणी समिति की साप्ताहिक बैठकें होती हैं, जिनमें व्यावसायिक समितियाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, सचिवक (Whips) आगामी सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और दल एवं सरकार की नीति पर विचार किया जाता है। दल का सचिवक सदस्यों को अनुशासनबद्ध रखता है। लॉर्ड्स-सभा में दलीय संगठन महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अनुदार दल का प्रभाव स्पर्धा रूप से है, अतः उसे संगठन अथवा अनुशासन की कोई चिन्ता नहीं रहती।

अनुदार दल में दल के नेता का बड़ा महत्व है। उसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वही दल की नीति का निर्माण और उसकी व्यवस्था करता है। दल सत्तारूढ़ हो अथवा विरोधी पक्ष में, अपने मुख्य साधनों का वह स्वयं चुनता है। दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वाय्वाध्यक्ष आदि उसी के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस तरह दल कार्यालय (Central Office) उसके अधीन होता है। दल के वार्षिक सम्मेलन के प्रस्ताव नियमित रूप से उसको भेजे जाते हैं, परन्तु वे उसे बाध्य नहीं कर सकते। मुख्य सचिव (Chief whip) की

निष्ठित भी वही करता है। चूंकि मरय स्वतंत्र संसदीय दल पर नियंत्रण करता है, अतः उसके माध्यम से नेता संसदीय दल पर अपना प्रभुत्व बनाये रखता है।

1965 से पूर्व अनुदार दल में नेता का औपचारिक चुनाव करने की परिपाटी नहीं थी, परन्तु 1965 में यह नियम अपना लिया गया कि अनुदार दल में भी श्रमिक दल के समान नेता के चुनाव की परिपाटी अपनायी जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि एक बार नेता चुन लिये जाने पर इच्छा प्य त वह इस पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका स्वास्थ्य अथवा उसके विरुद्ध दलीय असंतोष उसे पदत्याग करने पर विवश न कर दे अथवा उसकी मृत्यु ही न हो जाए। सत्ताहठ होने की दशा में अनुदार दल और श्रमिक दल के नेताओं की स्थिति लगभग समान है क्योंकि दल का नेता ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है और हेतुछानुसार अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करता है। परन्तु अनुदार दल जब विपक्षी दल के रूप में होता है तब भी नेता लोक सभा के सदस्यों में से अपने छाया मंत्रिमण्डल (Shadow Cabinet) के सदस्यों का चयन करता है, जबकि श्रमिक दल में ऐसा नहीं है। यहां दल के सदस्य प्रति दल नेता और छाया मंत्रिमण्डल का चुनाव करते हैं।

उदारवादी दल (Liberal Party)

उदारवादी दल आज ब्रिटेन का मुख्य राजनीतिक दल नहीं रहा है। उसका स्थान श्रमिक दल ने ले लिया है। फिर भी इस दल के सदस्य अपनी योग्यता और अपने नेतृत्व के गुणों के कारण ब्रिटेन में सम्मान के पात्र हैं।

उदारवादी दल अंग्रेजी नाम 'लिवरल पार्टी' (Liberal Party) का हिंदी रूपान्तर है। त्रिरत्न पार्टी के नाम से यह दल केवल 19वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आया, परन्तु उदारवादियों का कहना है कि उनके दल का अस्तित्व गृह युद्ध और स्वर्णिम शान्ति के समय से चला आ रहा है और वे व्हिग्स (Whigs) के उत्तराधिकारी हैं। व्हिग पार्टी में जिस परम्परागत दृष्टिकोण को उदारवादी दल ने लिया, उसके बारे में थोड़ी बेली (Baili) का कहना है कि "विगत तीन शताब्दियों में व्हिग दल अथवा उदारवादी दल (जो नाम इस दल का 19वां शताब्दी में हो गया था) कई पहलुओं से गुजर चुका है। कभी यह धनिकों का दल रहा है तो कभी यह पद-दलितों का संरक्षक रहा है, कभी इनन शांति का दल और कभी बठोर प्रतिहार करने वाले दल का रूप धारण किया है। कभी यह युद्धमायम का समर्थक बना है तो कभी आर्थिक नियोजन का पक्ष पाया रहा है, कभी यह साम्राज्यवाद का दल रहा है तो कभी इससे केवल छोट से इंग्लैंड का समर्थन किया है। साधारणतः यह सहिष्णुता का समर्थक रहा है, परन्तु कुछ अवधिवादी बड़ी विवट असहिष्णुता की भी रही है।"

नीति और कार्यक्रम—उदार दल का विचार है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसलिए "नए अनुभव को स्वीकार किया जाय तथा स्वतंत्र विचार

की समझन दिया जाय।" यह दल परम्परा के पक्ष में नहीं है, अपितु वदनी हुई परिस्थितियाँ के साथ-साथ समाजित एवं आर्थिक परिवर्तनों के पक्ष में है। उदार दल स्थापित अधिकारों का छोड़ मानव के अधिकारों पर विशेष बल देता है। इस दल के सविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि "उदार दल का उद्देश्य एक ऐसे स्वतन्त्र जनतापूषण समाज की रचना करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता सम्पत्ति और गुणों प्राप्त हो तथा कोई भी दरिद्रता, अज्ञान अथवा बेरोजगारी का शम नहीं होगा।"

यह दल व्यक्ति की सब प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थन है। दल ने व्यवहार में भी सदैव इस कायधर्म पर आचरण दिया, जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा होती रही। इसने धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हुए विशेषकर ना-कॉन्फॉर्मिस्ट (Non Conformists) को स्वतन्त्रतापूषक धार्मिक पूजा करने के सम्प्रदाय में और उन्हें अनिवार्य धार्मिक एवं सामाजिक नियोगिताओं से मुक्ति दिलाने के बारे में सराहनीय प्रयास किये। इस दल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता का समर्थन करते हुए एक राजनीतिक सुधारों को लाने के प्रयास किये जिसमें सभी लोगों को समान भागीदारी प्राप्त हो सके, लोक प्रिय आधार पर निर्वाचित लोक-सभा की पूर्ण अधिकार मिले और उसे अन्तिम प्रभुसत्ता प्राप्त हो। 1911 का संसदीय अधिनियम उदार दल की जीत थी जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्थापन क्षेत्र में लोक-सभा का अन्तिम नियम करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी दल उद्योग धर्मियों को प्रोत्साहन देकर जनसाधारण का आर्थिक उत्थान का उद्योग चाहता है। वह स्वतन्त्र व्यापार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता के पक्ष में है। उसने 'यदभाभ्यम नीति' (Laissez-faire) का समर्थन किया है और शासन की ओर से प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। परन्तु कुछ अवसरों पर दल के द्वारा ऐसे सामाजिक और आर्थिक सुधारों का भी समर्थन किया गया है जो व्यक्तिवाद और यदभाभ्यम नीति से भिन्न नहीं थात जीन अब तो उदारवाद, यह भी मानने लगा है कि एक आवश्यक स्वतन्त्रता धर्मियों की स्वतन्त्रता भी है जिसकी व्यवस्था ऐसी ही चाहिए। उनका यह आग्रह अवश्य है कि राजनीतिक निमग्न आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिये।

उदारवादियों के लिए पूँजीवाद अथवा समाजवाद की समस्या का उत्तर महत्व नहीं है जितना समस्या जाना है। न तो उन्हें अनुत्तरदायी नानि ही पसंद है जिसके कारण पूँजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है और न उन्हें समाजवादी नीति ही पसंद है जो सन्नद्धवादी राजनीतिक नियमन द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही समाप्त कर देना चाहता है।

धर्मियों के कल्याण के लिए उदारवादी सम्पत्ति विस्तार के पक्षपाती हैं। वे चाहते हैं कि धर्मियों को उद्योगों और व्यवसायों में भागीदार बनाया जाना

चाहिये। वे यह भी चाहते हैं कि उद्योगों का प्रजानाम्यीकरण हो और प्रत्येक उद्योग का प्रबंध एक औद्योगिक परिषद (Industrial Council) के हाथों में दे दिया जाय जिसमें श्रमिकों और मालिकों दोनों के प्रतिनिधि हों।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादी समाजवादी न होते हुए भी समाजवाद की दृष्टि से बहुत ही मानते हैं—पथ, उन सभी उद्योगों का समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये, जिनका प्रबंध राज्य सुगमता से स्थापना से कर सकता हो, और द्वितीय, उद्योगों से श्रमिकों के हितों का उचित संरक्षण दिया जाना चाहिये। उदारवादियों का दावा है कि वे किसी बग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं, अपितु नमस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उदारवादी आधुनिक भूमि व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं। वे चाहते हैं कि भूमि उन लोगों से छीन ली जाय जो स्वयं खेती नहीं करते, और उह दे दी जाय जो स्वयं करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि जिन लोगों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति प्राप्त है उन पर भारी कर लगाया जाय।

विदेश नीति के सम्बंध में उदारदल चाहता है कि राष्ट्रों और देशों को साम्राज्य के अंतर्गत अधिकधिक अधिकार प्रदान किये जाएं। यह स्मरणीय है कि उदारवादी मन्त्रिमण्डल ने ही आयरलैण्ड को स्वशासन देने का प्रस्ताव किया था जिसका एडिंबरो ने घोर विरोध किया था।

एक समय था जबकि उदारदल अपनी उन्नति के शिखर पर था, कि तु अब इसकी शक्ति में निरंतर ह्रास हो रहा है। इसके पतन का मुख्य कारण यह है कि इस दल के पास कोई स्पष्ट और सीधा कार्यक्रम नहीं है। यह पूरा जीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग ग्रहण करना चाहता है, अतः इस के पक्ष में न तो घनिष्ठ ही है और न श्रमिक ही।

सदस्यता—जिस समय उदारदल अपनी उन्नति के शिखर पर था, उसमें कई प्रकार के सदस्य थे। उनमें ग़ैवर, व्यापारी मध्यमवर्ग के नागरिक, छोटे-छोटे दुकानदार, कुछ धनिक कृषक और तब के श्रमिक शामिल थे। वर्तमान स्थिति में इसे न युग्ममय कुलीन-वर्ग का समर्थन प्राप्त है और न ही श्रमिक वर्ग का, क्योंकि कुलीन वर्ग आज अनुदार दल की सहायता का निर्माण करता है, जबकि श्रमिक वर्ग का आदर्श श्रमिक दल है।

संगठन—उदारवादी दल का एक राष्ट्रीय संगठन है जिसे 'राष्ट्रीय उदारवादी संघ' (National Liberal Federation) कहते हैं। इस संगठन की प्रतिवर्ष एक बार बैठक होती है, जिसे उदारवादी वार्षिक सम्मेलन (Liberal Annual Assembly) कहा जाता है। यह सम्मेलन दल के अधिकारियों को चुनता है, दल के क्रिया-कलापों का सिद्धान्तोपन करता है और दलीय नीति का निर्धारण करता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यगण प्रत्येक से होते हैं—सब उदारवादी

मनमदस्य एव पीयर, सब समद्रीय प्रत्यागी, उदारदलीय परिषद (Liberal Council) के सदस्य, क्षेत्रीय मगठनों के प्रतिनिधि एव यूनिवर्सिटी लिबरल सोसाइटियों के सदस्य गण ।

दल के मगठन की सबसे निम्नस्तरीय इकाई क्षेत्रीय मगठन या निर्वाचन क्षेत्रीय सघ (Constituency Association) है । इन मगठनों के कार्य अपने अपने क्षेत्रों में दलीय मिट्टाओं और विचारों का प्रचार करना, निर्वाचन के समय केन्द्रीय कार्यालय के परामर्श से दलीय सदस्यों को चुनना और उनकी सफलता के प्रयत्न करना आदि हैं ।

अब्य दल की भांति उदार दल का भी एक केन्द्रीय कार्यालय है, जिसे 'उदारवादी केन्द्रीय मगठन' (Liberal Central Association) कहा जाता है । इस केन्द्रीय मगठन के अधिकार अनुदारवादी दल के केन्द्रीय कार्यालय जैसे नहीं हैं । न तो यह प्रचार कार्य के लिए धन एकत्रित ही करता है और न क्षेत्रीय मगठनों की सहायता के लिए धन संच ही करता है । दलीय कोष पर अधिकार केन्द्रीय कार्यालय का नहीं अपितु प्रधानतः क्षेत्रीय मगठनों का होता है ।

श्रमिक दल (Labour Party)

श्रमिक दल की स्थापना फरवरी सन 1899-1900 में ब्रुड यूनियन कांग्रेस के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप हुई । उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति (Labour Representation Committee) रखा गया, जिसे सन 1906 में बदल कर श्रमिक दल (Labour Party) कर दिया गया । 1920 में मार्क्सवादी विचारधारा के लागू इस दल से पृथक् हो गए और उन्होंने साम्यवादी दल का निर्माण कर लिया । आज भी यह दल स्वयं को मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद से पृथक् रख रहा है । लोकप्रियता की दृष्टि से यह दल निरंतर प्रगति कर रहा है ।

नीति और कामकाज—श्रमिक दल एक 'नवीन सामाजिक' ढांचे की रचना करना चाहता है । उसका घोषित उद्देश्य 'हाथ और मस्तिष्क के कार्य करने वाले श्रमिकों को व्यवसायों से पूरा लाभ दिलाना, जहां तक सम्भव हो सके उत्पादन, वितरण व वित्तियम के साधनों की सावधानी के आधार पर उसका अधिक से अधिक औचित्यपूर्ण वितरण करना तथा प्रत्येक व्यवसाय की सेवाओं से सम्भवतः अधिक से अच्छा लोकप्रिय प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था करना है ।'

यद्यपि श्रमिक दल का ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना करना है, किंतु वह समाजवाद की अपेक्षा लोकतन्त्र को अधिक महत्त्व देता है । वह समाजवाद की स्थापना लोकतन्त्रीय विधि के द्वारा करना चाहता है ।

श्रमिक दल पूँजीवाद के स्थान पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में है जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्थान पर सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति जनता के हाथ में होगी । दूसरे शब्दों में वह व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करता है । यह दल बहुव्यपूण व्यवसायों अथवा

उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहता है। राष्ट्रीय महत्व के विशालकाय उद्योगों का छोड़कर, विशेष व्यवसायों में श्रमिक दल चाहता है कि स्वामित्व चाहे व्यक्तिगत भले ही रहे, किन्तु उन पर सरकार अवश्य होनी चाहिए, ताकि उनका संचालन राज्य के आर्थिक नियोजन के अनुसार हो सके। दल का मत है कि देश के आर्थिक नियोजन का संचालन लोकतन्त्रात्मक रीति से निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और नियोजन के नाम पर व्यक्ति की नागरिक स्वतन्त्रताओं का हनन नहीं होना चाहिए।

श्रमिक दल सामाजिक समानता (Social equity) का प्रबल समर्थक है। यह समाज में समता और एकात्मता पैदा करना चाहता है। वह समान शिक्षा, समान सम्पत्ति तथा समान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुखसुविधाओं का पक्षपाती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही वह पूँजीवादी ढाँचे को लोकतांत्रिक उपकरणों के सहारे से बदलना चाहता है।

दृष्टि के क्षेत्र में श्रमिक दल चाहता है कि आयात और पैदावार के वितरण में इस प्रकार अकुल रखा जाए कि कृषक इस बात के प्रति आश्वस्त रह कि उसे अपनी पैदावार का निश्चित मूल्य मिलेगा और उसके बदले में कृषक को अच्छी तरह से प्रबंध करना चाहिये तथा मजदूरों की स्थिति सतोषजनक रखनी चाहिये।

स्पष्ट है कि श्रमिक दल के कार्यक्रम को लोकतन्त्रात्मक समाजवादी कार्यक्रम की मज्जा दी जाती है। श्रमिक दल की वास्तविक इच्छा यही है कि जन्म से मरण तक व्यक्ति को किसी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमयता का शिकार न होना पड़े। अपनी इस इच्छा को कार्यक्रम में परिणत देखने के लिये श्रमिक दल राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के पक्ष में है। साम्राज्य के सम्बन्ध में श्रमिक दल की यह इच्छा है कि वह उन सभी प्रदेशों को, जिनमें स्वशासन नहीं है, जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। इस दिशा में इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वह चाहता है कि उपनिवेशों के प्राकृतिक साधनों को विकसित और उत्तम किया जाए, उनमें सामाजिक सेवाओं का विकास किया जाए, तथा ट्रेड यूनियनों और सहकारी आन्दोलनों को उत्साहित किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्रमिक दल साम्राज्यवाद का विरोधी है और उपनिवेशों को स्वशासन देने के पक्ष में है। इस दल का अंतिम उद्देश्य है—संसार में विश्व समाजवादी सरकार (Socialist Commonwealth) की स्थापना करना, परन्तु उसकी वर्तमान नीति मधुक्त राष्ट्र संधि (United Nations) के माध्यम से संसार के राष्ट्रों में मधुर सम्बन्धों की स्थापना करना और विश्व शांति को बनाये रखना है।

सदस्यता—श्रमिक दल की सदस्यता अधिकांशतः उन व्यक्तियों की है जो श्रमिक हैं। उनमें से अधिकांश नगर के लोग हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांतों और

से यह दल ब्रिटन की सामान्य जाति में भी बहुत अधिक लोकप्रिय है, जो श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। स्थितियों के मतानुसार और अन्य अवधारणों का समर्थन करने के कारण यह दल ब्रिटन में नारी वर्ग में भी काफी लोकप्रिय है। पर्याप्त संख्या में मध्यम वर्ग के लोग भी, जो पूँजीवादी समाज व्यवस्था के विरोधी हैं, श्रमिक दल का समर्थन करते हैं।

संगठन—श्रमिक दल किसी भी अन्य दल की अपेक्षा अधिक संगठित है। दल का संगठन मधीय आधार पर किया गया है। इसमें श्रमिक मध्य, समाजवादी समर्थन, जिसमें फेडरेशन मामायाटी, समाजवादी वकीलों की सोसायटी, समाजवादी डाक्टरों और अध्यापकों की सोसायटी, श्रमिकों की राष्ट्रीय संघा आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च उपकरण श्रमिक दल सम्मेलन (Labour Party Conference) है, जिसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है। अधिकांश की दृष्टि में यह सबसे ऊँच स्तर की समस्या है। यह अक्सर ही दलीय विधान में परिवर्तन कर सकता है। इसमें स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों, ट्रेड यूनियनों, महिला मध्यों और समाजवादी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यह दलीय नीति का निर्धारण करते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन करते हैं। अनुदात दल की तरह से श्रमिक दल का कोई नेता नहीं होता। समदीय श्रमिक दल का नेता ही श्रमिक दल का नेतृत्व करता है।

श्रमिक दल की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee) होती है। इसके द्वारा केन्द्रीय कार्यालय का संचालन और दल का नीति का निर्धारण होता है। इस समिति में 27-28 सदस्य होते हैं। इसी के द्वारा समद के उम्मीदवारों का नामांकन होता है। इस किसी भी सदस्य या संगठन का बहिष्कृत करने का अधिकार होता है, जिसकी अपील सम्मेलन (Labour Party Conference) को की जा सकती है। साधारणतया सम्मेलन द्वारा कार्यकारिणी समिति के निर्णय और प्रस्तावों का अनुमोदन होता रहा है।

अन्य दलों की तरह श्रमिक दल का भी संसदीय संगठन है। दल के नेता का निर्वाचन प्रतिवर्ष यही संगठन करता है। यद्यपि नेता का ही नीति निर्धारण का अधिकार है, परंतु उसे दलीय सम्मेलन और कार्यकारिणी समिति के निर्देशन में चलना पड़ता है।

अन्य राजनीतिक दल

उपरोक्त तीनों दलों के अतिरिक्त ब्रिटन में कुछ अन्य छोटे छोटे दल भी हैं, जिसमें प्रमुख साम्यवादी दल, फासीवादी दल तथा स्वतंत्र श्रमिक दल। साम्यवादी दल की स्थापना मंत्री होने के कारण जनता उस पर मत नहीं करनी। फासीवादी दल का भविष्य भी कुछ उज्ज्वल नहीं है। स्वतंत्र श्रमिक दल यद्यपि बहुत पुराना है किन्तु इसका महत्व भी प्रायः नगण्य है। यह पहिले श्रमिक दल से मित्र-गुप्त रहता था, परंतु सन 1931 में यह उससे अलग हो गया, क्योंकि इसकी दृष्टि में श्रमिक दल अधिक प्रगतिशील नहीं था।



कानून और न्याय (LAW AND JUSTICE)

“सामान्य कानून सबसे ठीक जमाने और मानव का सर्वोत्तम
उत्तराधिकार है। सामान्य कानून का उद्भव एक प्रसार
वैधानिक इतिहास के एक मुख्य अनुच्छेद का निर्माण
करता है।”

—ब्लकस्टोन

ब्रिटेन की कानूनी व 'यायिक' व्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम कानूनी और 'यायिक' व्यवस्थाओं में से एक है। ब्रिटेन में जिस तरह राजनय का लोकनयिकरण हुआ है और लोकनयिक विधान का विकास हुआ है, उसी तरह कानूनी और 'यायिक' व्यवस्था भी अभिवृद्धि विधान का ही फल है। ब्रिटिश कानूनी और 'यायिक' व्यवस्था पर लोकनयिक विधान का यह प्रभाव दाँटा में दिखाई पड़ता है—प्रथम रूप यह है कि वहाँ कानून के कलेवर का अधिकांश निमित्त कानून के रूप में न होकर सम विकसित कानून के रूप में है जिसे सामान्य कानून (Common Law) के नाम से पुकारा जाता है। यह सामान्य कानून ब्रिटिश लोक-जीवन के रीति-रिवाजों पर आधारित है और ब्रिटिश लोक-जीवन में गुंथ गया है। प्रभाव का दूसरा रूप यह है कि ब्रिटिश कानूनी और 'यायिक' व्यवस्था लोकनयिक के साथ ही पनपी तथा विकसित हुई है। उन उमर व्यक्ति के अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लोकनयिक सिद्धांतों का सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ब्रिटेन में शासन शासक का नहीं, अपितु कानून का है और यायिकीय कानून के शासन (Rule of Law) को लागू करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने हैं।

मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परंतु जब सरकार शिक्षा संचालन, किसी राष्ट्रीयता व्यवसाय का संचालन, धर्मिका की दशा न सुधार आदि कार्यों का सम्पादन करती है तो उक्त अधिनियम के अनुसार यह माना जा सकता है कि सरकार "अपने स्वामित्व या व्यापारिक रूप" (Proprietary or business capacity) में कार्य कर रही है। अतः ऐसी दशा में यदि न्याय के कार्य से किसी का अहित होता है तो उसके लिए सरकार के विरुद्ध कानूनी कागजाती की जा सकती है।

(ii) डायमी की तृतीय व्याख्या की व्यावहारिकता—डायमी ने सीमरे पहलू में इस बात पर बल दिया है कि कानून का गानन ही, व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है और दश के न्यायालय सामान्यतः उमके अनुसार ही अपने निणयो द्वारा उन अधिकारों की रक्षा करते हैं। वह समदीय कानूनों या सधियों से प्राप्त अधिकारों की ओर ध्यान नहीं देता। आज वास्तविकता यह है कि ससदीय कानूनों का क्षन इतना व्यापक हो गया है कि सामान्य कानून (Common Law) द्वारा प्रदत्त अधिकारों—वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार, स्वरक्षा का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार आदि का समदीय कानूनों की कारण लेनी पड़ती है। आज अनेक व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित निणय देश के न्यायालय सामान्य कानून के अंतर्गत नहीं करन प्रायः ससदीय कानूनों के अंतर्गत देते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार की ओर से लोगों की गिरफ्तारी की व्यवस्था सामान्य कानून (Common Law) के अनुसार नहीं करन अपराधी न्याय अधिनियम, 1925' (Criminal Justice Act, 1925) जस ससदीय कानूनों के अनुसार भी चलती है। नावजनिता सभाओं का आयोजन करना व उनमें भाषण देना आदि अधिकार यद्यपि सामान्य कानूनों द्वारा सरक्षित हैं, परंतु 1936 के नावजनिक व्यवस्था अधिनियम (Public Order Act, 1936) के अनुसार भी उनके बारे में आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, सामान्य कानून का अक्ष हाते हुए भी, घरी प्रत्य गीकरण (Habeas Corpus) या अपमानजनक लेख—कानून (Law of Libel) को अधिनियमों का रूप दिया गया है।

कानून के शासन के अर्थ अपवाद—कानून के शासन के अर्थ अपवादों में राजा और नायाधीश प्रमुख हैं। राजा कोई गलती नहीं करता—इस कानूनी सिद्धांत के अनुसार राजा पर कोई दोषानी या फौजदारी अभियोग नहीं लगाया जा सकता। राजा केना भी कोई अपराध करे उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। उसे पागल करार देकर उमकी चिकित्सा करायी जा सकती है परंतु ब्रिटिश कानून में किसी भी पद्धति में उसी के न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी मन्त्र की मामलों में या प्रजा के किसी व्यक्ति की राजा द्वारा हानि हो जाए तो वह व्यक्ति केवल राजा से प्राधना कर सकता है, और राजा चाहे तो अपनी तृपा दृष्टि से न कि प्राथी के अधिकार को राजा के लिए, उस क्षति का पूरा कर सकता है। ब्रिटेन में नायाधीश भी कानून के

है। फौजदारी कानून का सम्बन्ध पूरे समाज अथवा राज्य के विरुद्ध किये गये अपराधों से होता है जबकि दीवानी कानूनों का सम्बन्ध समाज के सदस्यों अर्थात् व्यक्तियों के अधिकारों, उनके कर्तव्यों और दायित्वों से सम्बन्धित झगडा से होता है। फौजदारी कानून के अतःगत अभियोग का संचालन (Prosecution) राज्य द्वारा किया जाता है जबकि दीवानी कानून के अतःगत अभियोग व्यक्तियों की ओर से चलाये जाते हैं। फौजदारी न्यायालयों में काम का तरीका अन्वेषण-सम्बन्धी (Enquisitorial) होने की अपेक्षा प्रायः दोषी सम्बन्धी (Accusatorial) है।

न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का न होना—ब्रिटेन की ससद वहाँ की प्रभु (Sovereign) है। उसके द्वारा पारित अधिनियमों का वैधानिक अथवा अवधानिक ठहराना ब्रिटिश न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ब्रिटिश न्यायालयों का कार्य समझ के कानूनों के अनुसार न्याय-काय करना है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की ही भाँति व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की भी वसी व्यवस्था नहीं है, जैसी व्यवस्था अमेरिका अथवा भारत में है फिर भी वहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं की उतनी ही रक्षा होती है जितनी अमेरिका अथवा भारत में, क्योंकि संविधान की एक आधारभूत विशेषता है किसे न्यायालय कानून के शासन को लागू करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

जुरी-प्रथा—कानून के शासन की सफलता में जूरियों का बड़ा हाथ है। वे जनमत और मानवता को सदैव ध्यान में रखते हैं और कभी-कभी न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं या अभियुक्त को दण्ड देना अस्वीकार कर सकते हैं। ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था का इतिहास बताता है कि जुरी नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये देश के सकुचित और बठोर कानूनों पर समय-समय पर प्रहार करते रहें हैं। उन्होंने अपनी निष्पक्षता, निडरता और समझदारी के लिये विरासत में प्राप्त की है। ब्रिटेन में फौजदारी व दीवानी दोनों प्रकार के वादों में जूरियों के प्रयोग की व्यवस्था पाई जाती है पर दीवानी मुकदमों में प्रायः जुरी का प्रयोग कम होता है।

न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता—ब्रिटिश कानून एवं न्याय-व्यवस्था में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता प्रशंसनीय है। न्यायाधीशों पर न्यायपालिका का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता और न ही वह उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है। परिणामस्वरूप सर्वत्र सत्य एक ही न्याय चरता जाता है। ब्रिटन में न्यायाधीशों का वेतन और पद की सुरक्षा प्राप्ता है। ससद के दोनों सदन की प्राथम्यता पर ही वे राजा द्वारा हटाये जा सकते हैं। पदोन्नति की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है जिससे न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव पड़ सके।

शासन के अपवाद ह । यायाधीश का अपने सरकारी काम में किसी से दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यदि यायाधीश अपने अधिकार में अनजाने में कोई अपराध कर दे तो वैयक्तिक रूप से अपराधी न सकता ।

ब्रिटिश कानून एवं न्याय-व्यवस्था की विशेषता (Features of the British Law and Judicial System)

कानून एवं न्याय-व्यवस्था की दृष्टि से सम्पूर्ण देश (Uniformity) का अभाव है । पूरे ग्रेट-ब्रिटेन में न्यायालयालयों का व्यवस्थापन और उनका समान संगठन नहीं है । इंग्लैण्ड और वेल्श न्याय की व्यवस्था अलग तरह की है, स्कॉटलैण्ड की अलग तरह उत्तरी आयरलैण्ड की भी अलग तरह की है । फिर भी चले आ रहे निम्न सम्पत्ति के कारण सभी भागों की कानून में न्याय पर्याप्त समानता आ गई है और हम सम्पूर्ण संयुक्त राज्य (U.K.) कुछ ऐसी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर सकते हैं जो सभी प्रदेशों की सामान्य हैं ।

असहितावद्ध रूप—सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में कानून का संहिताबद्ध (Codified) नहीं है, अपितु उस रूप में है जिसे सामान्य कानून (Law) की सजा दी जाती है और जिसे हम न्यायालयों के विनिर्णयों में देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त असहितावद्ध कानून का वैयक्तिक निष्पत्ति (Equity) में प्राप्ति है ।

स्मरणीय है कि अधिकांश कानून के असहितावद्ध होने से लेना चाहिये कि संहिताबद्ध कानून है ही नहीं । जो जया समयीय अविस्तार हो रहा है, वही वही ब्रिटिश कानून का एक बड़ा भाग है और प्रवृत्त व्यवस्थापन (Statute Law and Delegated Legislation) में संहिताबद्ध कानून का कलवर धारण करता जा रहा है ।

साधारण कानून और साधारण न्यायालयों की प्रभुता—ब्रिटिश कानून और प्रशासनिक कानून में प्रभुता साधारण कानून की है । साधारण न्यायालयों व प्रशासनिक न्यायालयों में प्रभुता न्यायिक है । अधिकांश बात यही है कि कानून का शासन प्रशासनिक अधिकारों के सामान्य नागरिकों में कोई भेद नहीं मानता । सभी का उही सामान्य में उपस्थिति होना पड़ता है और सब के ऊपर वही सामान्य विधि लक्ष्य । फिर भी यह अवश्य है कि यह ब्रिटेन में न्यायिक प्रशासनिक न्याय विकसित होता जा रहा है ।

फौजदारी व दोषी कानूनों का अंतर—ब्रिटिश कानून व फौजदारी (Criminal) और दोषी (Civil) कानून के अंतर में

न्याय-मायना अथवा औचित्यपूर्ण विधि—सामान्य कानून की भूमि पर ही औचित्यपूर्ण निर्णय (Equity) की नींव पड़ी है। समय-समय पर न्यायाधीशों के सामने ऐसे अनेक मामले जाये, जिनमें सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता था और कभी-कभी अस्पष्ट न्याय तक हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में जम-तुष्ट लोग न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध राजा से अपील करते थे। राजा को अपना निर्णय स्वविवेक से मामले में औचित्य (Equity) के आधार पर ही देना पड़ता था। कानून के अन्तर्गत ऐसी अपील की मर्यादा बल दी तो राजा ने उन्हें अपने चांसलर के पास भेजना प्रारम्भ कर दिया। वह चांसरी नाम के न्यायालय (The Court of Chancery) का प्रमुख होता था। इन न्यायालयों का कार्य औचित्य के आधार पर कानून तथा न्याय में सामंजस्य स्थापित करना था। इसके द्वारा जो निर्णय दिए गए और उनसे कानून के जिस रूप का विकास हुआ, उन्हें औचित्यपूर्ण विधि (Equity) की भाँति ही माना गया। इसका उद्देश्य सामान्य कानून (Common Law) की कठिनाई को दूर करके जनता को वास्तविक एवं सच्चा न्याय प्रदान करना था। इन पृष्ठभूमि में हम यह कह सकते हैं कि औचित्यपूर्ण विधि का आधार विवेक है और यह इस मायना पर आधारित है कि न्याय का कार्य केवल कानून के सूखे ढाँचे के अनुसार ही चलना नहीं है बल्कि सूखे ढाँचे पर मांस बढ़ाने का कार्य करना भी है ताकि कानून सामाजिक नैतिकता के माप-दण्ड पर खरा उतर सके। चूँकि औचित्यपूर्ण विधि का उद्भव सामान्य कानून की भूमि पर हुआ है, अतः दोनों की अनेक बातें एक-सी हैं। दोनों ही का रूप अनसूचित कानून (Uncodified Law) का है तथा दोनों ही न्यायाधीशों के निर्णयों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहाँ सामान्य कानून का उद्भव मूलतः प्रथाओं से हुआ है वहाँ औचित्यपूर्ण विधि का उद्भव विवेक तथा सामाजिक नैतिकता के आधार पर हुआ है।

संसदीय कानून—ब्रिटिश कानून का तीसरा प्रकार संसदीय कानून (Statute Law) का है। सामान्य कानून के साथ-साथ ही संसदीय कानून या सविधि का भी विकास हुआ। अन्तर्गत यही है कि सामान्य कानून का रूप जहाँ विकसित कानून का है, वहाँ संसदीय कानून का रूप निर्मित कानून का। प्रारम्भ में संसदीय कानून या सविधियों का निर्माण राजाओं के द्वारा ही हुआ, परन्तु ज्यों-ज्यों राजाओं की शक्तियाँ कम होती गई, त्यों-त्यों उनकी कानून निर्माण की शक्ति भी घटती गई और यह शक्ति के हाथ में पहुँचती गई। अब वर्तमान स्थिति यह है कि कानून निम्नान्त 'महद् संहिता राजा' (King in Parliament) है। संसदीय कानून ही एक प्रकार में पक्का कानून है। यही सर्वोपरि कानून है। जहाँ इसमें और सामान्य कानून में विरोध होगा, वहाँ इसे ही माना जाता है। इसका आशय यह नहीं है कि संसदीय कानून सामान्य कानून का नियंत्रण करता है, बरन ये तो उसे लचीला बनाते हैं और उसकी कमियों को पूरा करने हैं।

न्याय की शीघ्रता और प्रवीणता—ब्रिटेन में न्यायिक वायवाही शीघ्र होती है। मुकदमों के निणयों में प्रायः देर नहीं की जाती। इसके कुछ कारण हैं—प्रथम, उन आवश्यक सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है जो न्याय व्यवस्था की प्रवीणता के लिए अनिवार्य हैं, जैसे, जुरी प्रथा, स्वतंत्र न्यायाध्यक्ष वकील रखने की प्रथा आदि। द्वितीय, ब्रिटिश न्यायाधीशों को वैधिक परिभाषाओं (Legal Technicalities) के निबन्धन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली हुई है। तृतीय, न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम एक विनिष्ट 'न्यायिक नियम समिति' (Judicial Rule Committee) के द्वारा तैयार किये जाते हैं।

वकीलों की दोहरी प्रणाली—ब्रिटेन के वकील दो वर्गों में विभाजित हैं। प्रथम वर्ग में बैरिस्टर (Barrister) लोग आते हैं जिनका कार्य केवल न्यायालय में मुकदमों के पक्ष अथवा विपक्ष में सहस्र करना ही होता है। द्वितीय वर्ग में वकील सोलिसिटर (Solicitors) कहलाते हैं जो न्याय चाहने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करके उनके मुकदमों तैयार करते हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता—अतिम उल्लेखनीय विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से निर्बल हो, वह दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय (High Court) तथा अपील के न्यायालय (Court of Appeal) के मामलों में इंग्लैंड और वेल्स में तथा दोरी न्यायालय (Courts of Sessions) व शेरिफ न्यायालयों (Sheriff Courts) के मामलों में स्काटलैंड में कानूनी सहायता मिल सकती है। इसके अनिश्चित कुछ विनिष्ट प्रकार के दीवानी मामलों में काउंट्री न्यायालयों व दोरी न्यायालयों में कानूनी सहायता की व्यवस्था है।

ब्रिटिश कानून के प्रकार

(Kinds of British Law)

ब्रिटेन में तीन प्रकार के कानून हैं—

- (1) सामान्य कानून (Common Law)
- (2) न्याय नावना अथवा जीवितपूर्ण विधि (Equity), और
- (3) मनदीय कानून (Statute Law)

सामान्य कानून—यह सबसे प्राचीन ब्रिटिश कानून है जिसका आधार लगभग 800 वर्ष पुरानी प्रथाओं पर मिलता है। सामान्य कानून का निर्माण न तो राजा या डाक किया गया है और न ही द्वारा ही। इसका निर्माण तो न्यायाधीशों ने किया है। इसका मूल ये प्रथाएँ हैं जिन पर आधार पर राजा और नगर-नगर पर अपने निषेध आते रहे हैं। व्यवस्था के अन्त में यह (सामान्य कानून) सर्वोच्च न्यायाधीश और न्याय के सर्वोच्च उच्च न्यायाधीश हैं।

न्याय-मायना अवया औचित्यपूर्ण विधि—सामान्य कानून की भूमि पर ही औचित्यपूर्ण निणय (Equity) की नींव पड़ी है। समय-समय पर यायाधीशों के सामने ऐसे अनेक मामले जाते, जिनमें सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता था और कभी-कभी अस्पष्ट थाय तब हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में अंतर्दृष्टि लोग यायाधीशों के निणयों से विरुद्ध राजा से अपील करते थे। राजा को अपना निणय स्वविरा से मानने के औचित्य (Equity) के आधार पर हो देना पड़ता था। कालांतर में जब ऐसे अपीलों की संख्या बढ़ गई तो राजा ने उन्हें अपने चांसलर के पास भेजना प्रारम्भ कर दिया। वह चांसरी नाम के न्यायालय (The Court of Chancery) का प्रमुख होता था। इस न्यायालय का कार्य औचित्य के आधार पर कानून तथा न्याय में सामंजस्य स्थापित करना था। इसके द्वारा जो निणय दिए गए और उनसे कानून के जिस रूप का विकास हुआ, उन्हें औचित्यपूर्ण विधि (Equity) की भाँति देा गई। इसका उद्देश्य सामान्य कानून (Common Law) की नुस्तियों को दूर करके जनता को वास्तविक एवं सच्चा न्याय प्रदान करना था। इस पण्डितों में हम यह कह सकते हैं कि औचित्यपूर्ण विधि का आधार विवेक है और यह इस मायना पर आधारित है कि न्याय का कार्य केवल कानून के सूखे ढाँचे के अनुसार ही चलना नहीं है बल्कि सूखे ढाँचे पर मांस बढ़ाने का कार्य करना भी है ताकि कानून सामाजिक नैतिकता के माप-दण्ड पर खरा उतर सके। चूँकि औचित्यपूर्ण विधि का उद्भव सामान्य कानून की भूमि पर हुआ है अतः दोनों की अनेक बातें एक सी हैं। दोनों ही का रूप असंहिताबद्ध कानून (Uncodified Law) का है तथा दोनों ही यायाधीशों के निणयों के फलस्वरूप विनियमित हुए हैं। महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहाँ सामान्य कानून का उदय मूलतः प्रथाओं से हुआ है वहाँ औचित्यपूर्ण विधि का उदय विवेक तथा सामाजिक नैतिकता के आधार पर हुआ है।

संसदीय कानून—ब्रिटिश कानून का तीसरा प्रकार संसदीय कानून (Statute Law) का है। सामान्य कानून के साथ-साथ ही संसदीय कानून या सविधि का भी विकास हुआ। अंतर यही है कि सामान्य कानून का रूप जहाँ विकसित कानून का है, वहाँ संसदीय कानून का रूप निमित्त कानून का। प्रारम्भ में संसदीय कानून या सविधियों का निमाण राजाओं के द्वारा ही हुआ, परन्तु ज्यों-ज्यों राजाओं की शक्ति कम होती गई, तथा तथा उनकी कानून निमाण की शक्ति भी घटती गई और यह मन्द के हाथ में पहुँचती गई। अब वर्तमान स्थिति यह है कि कानून निर्माता 'संसद् महित राजा' (King in Parliament) हैं। संसदीय कानून ही एक प्रकार से पक्का कानून है। यही सर्वोपरि कानून है। जहाँ इसमें जोर सामान्य कानून में चिरवी होता है, वहाँ इसे ही माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसदीय कानून सामान्य कानून का निषेध करते हैं, बल्कि वे तो उसे लचीला बनाते हैं और उसकी कमियों को पूरा करने हैं।

न्याय की शीघ्रता और प्रवीणता—ब्रिटेन में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र होती है। मुकदमों के निष्पत्ति में प्रायः देर नहीं की जाती। इसके कुछ कारण हैं—प्रथम, उन आवश्यक सिद्धांतों का अनुसरण बिना जाता है जो न्याय व्यवस्था की प्रवीणता के लिए अनिवार्य हैं, जैसे, जुरी प्रथा, खान्ना न्यायालय चकील रखने की प्रथा आदि। द्वितीय, ब्रिटिश न्यायाधीश को वैधानिक परिभाषाओं (Legal Technicalities) के निबधन में पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। तृतीय न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम एक विशिष्ट 'न्यायिक नियम समिति' (Judicial Rule Committee) के द्वारा तैयार किये जाते हैं।

वकीलों की दोहरी प्रणाली—ब्रिटेन के वकील दो वर्गों में विभाजित हैं। प्रथम वर्ग में बैरिस्टर (Barrister) लोग आते हैं जिनका कार्य केवल न्यायालयों में मुकदमों के पक्ष पथवा विपक्ष में बहस करना ही होता है। द्वितीय वर्ग में वकील सोलिसिटर (Solicitors) कहलाते हैं जो न्याय चाहने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करके उनके मुकदमों तैयार करते हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता—अनिम उल्लेखनीय विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से निबल हो, उन्हें दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय (High Court) तथा अपील के न्यायालय (Court of Appeal) के मामलों में इंग्लैंड और वेल्स में तथा दौरा न्यायालय (Courts of Sessions) व शेरिफ न्यायालय (Sheriff Courts) के मामलों में स्काटलैंड में कानूनी सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के दीवानी मामलों में काउंटी न्यायालयों व दौरा न्यायालयों में कानूनी सहायता की व्यवस्था है।

ब्रिटिश कानून के प्रकार

(Kinds of British Law)

ब्रिटेन में तीन प्रकार के कानून हैं—

- (1) सामान्य कानून (Common Law)
- (2) न्याय भावना तथा जीवितपण विधि (Equity), एत
- (3) संसदीय कानून (Statute Law)

सामान्य कानून—यह प्राचीन ब्रिटिश कानून है जिसका ज्ञान लगभग 800 वर्ष पुरानी प्रथाओं में मिलता है। सामान्य कानून का निर्माण न तो राजाओं द्वारा किया गया है और न ही न्याय द्वारा ही। इसका निर्माण तो न्यायाधीशों ने किया है। इनका मूल प्रथाएँ हैं जिनके आधार पर न्यायाधीश समय-समय पर अपने निष्पत्ति देते रहते हैं। स्ट्रेट्सोन के मतों में यह (सामान्य कानून) सर्वोच्च न्यायाधिकार और मानवता का सर्वोत्तम उत्तराधिकार है।

न्याय-मायना अथवा औचित्यपूर्ण विधि—सामान्य कानून की भूमि पर ही औचित्यपूर्ण निणय (Equity) की नींव पड़ी है। समय-समय पर न्यायाधीशों के सामने ऐसे अनेक मामले जाये, जिनमें सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता था और कभी-कभी अस्पष्ट न्याय तक हो जाना था। ऐसी परिस्थिति में अगस्तुष्ट लोग न्यायाधीशों के निणयों के विरुद्ध राजा से अपील करते थे। राजा को अपना निणय स्वविवेक से मामले के औचित्य (Equity) के आधार पर ही देना पड़ता था। कालांतर में जब ऐसी अपीलों की संख्या बढ़ गई तो राजा ने उन्हें अपने चांसलर के पास भेजना प्रारम्भ कर दिया। वह चांसरी नाम के न्यायालय (The Court of Chancery) का प्रमुख होता था। इस न्यायालय का कार्य औचित्य के आधार पर कानून तथा न्याय में सामंजस्य स्थापित करना था। इसके द्वारा जो निणय दिए गए और उनसे कानून के जिस रूप का विकास हुआ, उन्हें औचित्यपूर्ण विधि (Equity) की संज्ञा दी गई। इसका उद्देश्य सामान्य कानून (Common Law) की त्रुटियों को दूर करके जनता को वास्तविक एवं सच्चा न्याय प्रदान करना था। इस पष्ठभूमि में हम यह कह सकते हैं कि औचित्यपूर्ण विधि का आधार विवेक है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि न्याय का कार्य केवल कानून के सूखे ढांचे के अनुसार ही चलना नहीं है बल्कि सूखे ढांचे पर मांस बढ़ाने का कार्य करना भी है ताकि कानून सामाजिक नैतिकता के माप-दण्ड पर खरा उतर सके। चूंकि औचित्यपूर्ण विधि का उद्भव सामान्य कानून की भूमि पर हुआ है, अतः दोनों की अनेक बातें एक सी हैं। दोनों ही का रूप अमहितावद्ध कानून (Uncodified Law) का है तथा दोनों ही न्यायाधीशों के निणयों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहां सामान्य कानून का उदय मूलतः प्रथाओं से हुआ है वहां औचित्यपूर्ण विधि का उदय विवेक तथा सामाजिक नैतिकता के आधार पर हुआ है।

संसदीय कानून—ब्रिटिश कानून का तीसरा प्रकार संसदीय कानून (Statute Law) का है। सामान्य कानून के साथ-साथ ही संसदीय कानून या मविधि का भी विस्तार हुआ। अंतर यही है कि सामान्य कानून का रूप जहां विकसित कानून का है, वहां संसदीय कानूनों का रूप निर्मित कानून का। प्रारम्भ में संसदीय कानून या मविधियों का निर्माण राजाओं के द्वारा ही हुआ, परन्तु ज्यों-ज्यों राजाओं की शक्ति कम होती गई, तथा तथा उनकी कानून निर्माण की शक्ति भी घटती गई और यह समय के हाथ में पहुँचती गई। अब वर्तमान स्थिति यह है कि कानून-निर्माता संसद सहित राजा (King in Parliament) है। संसदीय कानून ही एक प्रकार से पक्का कानून है। यही सर्वोपरि कानून है। जहां इसमें और सामान्य कानून में विरोध होता है, वहां इसे ही माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसदीय कानून सामान्य कानून का निषेध करते हैं, परन्तु ये तो उसे लचीला बनाते हैं और उसकी शक्तियों को पूरा करने हैं।

ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का संगठन (Organisation of the British Judiciary)

ब्रिटेन की आधुनिक न्याय-व्यवस्था सन् 1870 के बाद के अधिनियमों द्वारा विनियमित होती है। इससे पहले यहाँ के न्यायालयों में एकस्यता का पूर्ण अभाव था। देश में विभिन्न प्रकार के न्यायालय बिखरे हुए थे और उनके कार्य अत्यंत सुनिश्चित नहीं थे। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, इक्विटी न्यायालय, धार्मिक न्यायालय आदि के कार्य-क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे और न्यायिक व्यवस्था बड़े जटिल रूप में थी। देश के इन समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए और इनके संगठन एवं कार्य पद्धति में समानता लाने के लिए संसद ने 1873 और 1879 में जूडीकेचर अधिनियम (Judicature Act) पारित किये। देश के सब न्यायालयों को एक ही सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न शाखाओं का रूप दे दिया गया। परंतु फिर भी अब तक सम्पूर्ण ब्रिटेन में एक-सं न्यायालय नहीं पाये जाते। इंग्लैंड और वेल्स में तो एक से ही न्यायालय है, किन्तु स्कॉटलैंड में भिन्न प्रकार के हैं तथा उत्तरी आयरलैंड में भी भिन्न प्रकार के हैं। हम पहले इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों का वर्णन करेंगे और तत्पश्चात् स्कॉटलैंड व आयरलैंड के न्यायालयों के संगठन को भी संक्षेप में देखेंगे।

इंग्लैंड और वेल्स के विधि न्यायालय

इंग्लैंड और वेल्स में एक से ही न्यायालय हैं। ये तीन प्रकार के हैं—

(1) दीवानी न्यायालय (Civil Courts)—ये न्यायालय नागरिकों के आपसी मामलों का निपटारा करते हैं, जैसा कि भारत में होता है।

(2) फौजदारी न्यायालय (Criminal Courts)—ये उन मामलों का निपटारा करते हैं, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक कानून के उल्लंघन से होता है और जिनमें कानूनी कामवाही का मर्यादित राज्य की ओर से किया जाता है।

(3) प्रिवी परिषद् की न्यायिक समिति (Judicial Committee of the Privy Council)—यह समिति ब्रिटिश उपनिवेशों और ब्रिटेन के अधीनस्थ राज्यों से आने वाली अपीलें भी सुनती है। इसमें इंग्लैंड के धार्मिक न्यायालयों से आने वाली अपीलें भी सुनी जाती हैं। इसके सदस्य प्रायः वे ही होते हैं जो न्याय के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of Judicature) के रूप में चंठते हैं और लाइ-सभा के सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम एक न्यायाधीश किसी उपनिवेश या उस राज्य से आता है, जहाँ से अपीलें आनी गई हैं।

यह स्मरणीय है कि दीवानी व फौजदारी दोनों ही न्यायालयों के अनेक उपविभाग हैं। केन्द्रीय अथवा उच्चतर न्यायालय अधिनायक लंदन में हैं जबकि स्थानीय एवं छोटे न्यायालय देश भर में बिखरे हुए हैं। दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों का निपटारा स्थानीय न्यायालय हाउस ऑफ (House of

Lords) है। लाइ सभा न्यायालय के रूप में लाइ चान्सेलर की अव्यवस्था में बैठती है और इसमें केवल न्यायकर्ता लाइ ही सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार उपनिवेशों और अधीनस्थ राज्यों से आई हुई अपीलें सुनने के लिए प्रिवी परिषद् की न्याय समिति बैठती है।

इंग्लैंड की वर्तमान न्यायपालिका का संयोजन निम्न रेखाचित्र से भली प्रकार समझ में आ जाएगा।

(1) फौजदारी न्यायालय (Criminal Courts)

लाइ सभा (House of Lords)

(राज्य का सर्वोच्च न्यायालय)

आपराधिक मामलों में अपील का न्यायालय
(Court of Criminal Appeal)

क्वार्टर सेशन
(Quarter Sessions)

हाईकोर्ट के ऐसाइजेज
(Assizes of High Court)
(सिर्फ बड़े-बड़े अपराधों के लिए)

पेट्टी सेशन
(Petty Sessions)

कारोनर्स कोर्ट
(Coroners Court)

(2) शीवानी न्यायालय (Civil Courts)

लाइ सभा (House of Lords)

(राज्य का सर्वोच्च न्यायालय)

अपील का न्यायालय
(Court of Appeal)
न्याय का उच्च न्यायालय
(High Court of Justice)

हाई कोर्ट के ऐसाइजेज सम्राट की न्याय
(Assizes of High Court) मंडली (King's Bench Division)

चांसरी डिवीजन
(Chancery Division)

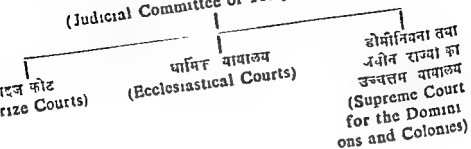
प्रोबेट, तलाक
(Probates, Divorce and Admiralty Division)

क्वार्टर सेशन
(Quarter Sessions)

काउंटी न्यायालय
(County Courts)

विशेष मुकदमों के न्यायालय

प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति
(Judicial Committee of Privy Council)



फौजदारी न्यायालय (Criminal Courts)

फौजदारी न्यायालयों में उन अभियोगों की सुनवाई होती है जो मावजिनक कानून के उल्लंघन में सम्पादित होते हैं, उदाहरणार्थ हत्या, चारों, उकती, लडाई आदि। फौजदारी न्यायालयों का ढांचा इस प्रकार है—

(1) पैटी सेशन या शोट आफ समरी जूरिस्टिडिक्शन (Petty Sessions Court of Summary Jurisdiction) — ये न्यायालय सबसे छोटे न्यायालय हैं और इनमें स्थानीय मजिस्ट्रेट जो शांति न्यायाधीन (Justices of Peace) कहलाते हैं, पाय करते हैं। ये अवतनिक (Honorary) होते हैं। लंदन और अन्य बड़े-छोटे नगरों में ये प्रायः पैतनिक (Stipendiary) भी होते हैं। इन शांति न्यायाधीशों की लाय चासलर नियुक्ति करता है। इनका अनाधिकार केवल काउण्टी तक ही सीमित है। प्रत्येक काउण्टी कई जिलों में विभक्त होती है और प्रत्येक जिले में एक एक पैटीमस न का न्यायालय होता है। पैटीमस न के न्यायालय में एक न्यायाधीश मामूली फौजदारी मुकदमों में सुनता है। जब मुकदमे सुनते हैं। एक न्यायाधीश मामूली फौजदारी मुकदमों में सुनता है। जब दो या अधिक न्यायाधीश मुकदमे सुनते हैं तो उनके न्यायालय का 'Court of Summary Jurisdiction' कहा जाता है और यह न्यायालय 6 महीने तक का कारावास और 50 पौण्ड से लेकर 100 या किसी किसी स्थानीय मामलों में 500 पौण्ड तक जर्माना कर सकते हैं। कुछ स्थानीय मामलों में कारावास की अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है।

(2) कोरोनर कोर्ट (Coroner's Court) — यह न्यायालय वास्तव में न्यायालय नहीं है। इसमें एक कोरोनर (Coroner) होता है जो प्रायः डाक्टर या वकील होता है। यह काउण्टी अथवा बरा परिषद (County or Borough Council) द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह जुरी की सहायता से अथवा उसके बिना भी अपना काम करता है। उसका कार्य किसी व्यक्ति की रहस्यमय, आकस्मिक

अथवा अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों का पता लगाना है। इसकी नियुक्ति जीवन भर के लिए की जाती है।

(3) क्वाटर सेंशंस (Quarter Sessions)—ये न्यायालय सब काउण्टियो (Counties) में और सब बरो (Boroughs) में होते हैं। इनमें छोटे न्यायालयों की अपीलें जाती हैं और ये प्रायः उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिनमें मृत्यु दण्ड की आवश्यकता होती है या जो मामले जराबिक पेचीदे होते हैं परन्तु हत्या, देसद्रोह, कपट-लेखन आदि के मामले इनके क्षेत्र में नहीं आते। न्यायालयों का सत्र 3 मास होता है और ये वर्ष में पांच 4 बार याप काय करते हैं।

(4) ऐसाइजेज (Assizes)—इन न्यायालयों का रूप उच्च न्यायालय (High Court) की शाखाओं का होता है। ये अमनशील न्यायालय हैं। इनके न्यायाधीश वर्ष में तीन या चार काउण्टियो या नगरों में जाकर फौजदारी या दण्ड सम्बन्धी मामलों सुनते या निणय देते हैं। इन न्यायालयों में गम्भीर मामलों की सुनवाई होती है। कल्ल आदि के मुकदमों की ये भी सुनवाई कर सकते हैं। उनको क्वाटर सेंशंस से आई हुई अपीलें सुनने का अधिकार है। इनके अधिकार क्षेत्र में मौलिक मामले भी आते हैं।

(5) क्राउन न्यायालय (Crown Courts)—लीवरपूल तथा मैनचेस्टर में हाई की अधिकता के कारण दो विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिन्हें क्राउन न्यायालय कहा जाता है। ये न्यायालय इन स्थानों में क्वाटर सेंशंस का भी कार्य करते हैं और दक्षिण लंदनायर के लिए ऐसाइजेज न्यायालय का भी कार्य करते हैं।

(6) अपील का न्यायालय (Court of Criminal Appeal)—क्वाटर सेंशंस, ऐसाइजेज और क्राउन न्यायालयों के निणय के विरुद्ध अपील, फौजदारी की अपील न्यायालय (Court of Criminal Appeal) में सुनी जाती हैं। फौजदारी की अपील वातूनी आधार पर अभियुक्त की ओर से भी हो सकती है और अभियुक्ता की ओर से भी। अपील न्यायालय में लार्ड चीफ जस्टिस (Lord Chief Justice) तथा उच्च न्यायालय की समाट बच मण्डली (King's Bench Division) के कम से कम तीन न्यायाधीश होते हैं। माजारणत इन न्यायालय के निणय अंतिम होते हैं।

दीवानी न्यायालय (Civil Courts)

दीवानी न्यायालयों में नागरिकों के पारस्परिक मामलों को तय किया जाता है, उदाहरणार्थ, लोगों में सम्पत्ति विषयक विवाद, मान हानि विवाद आदि दीवानी न्यायालयों का ढांचा इस प्रकार है—

(1) काउंटी न्यायालय (County Courts)—ये न्यायालय दीवानी मामलों में सबसे निम्न स्तर के न्यायालय हैं। इनकी संख्या लगभग 400 है और

इनकी स्थिति ऐसी है कि सभी क्षेत्रों के लिए 'यायालय अधिक दूरी पर नही पड़ते। एक 'यायाधीश के दोरा क्षेत्र में एक या एक से अधिक 'यायालय बांटे हैं। काय अधिक होने पर अतिरिक्त 'यायाधीशों की नियुक्ति भी कर दी जाती है। काउंटी यायाधीशों की नियुक्ति लाड चांसलर के परामर्श पर सम्राट द्वारा की जाती है। काउंटी 'यायालय किसी निश्चित स्थान पर नही रहता बरन् भ्रमण करता रहता है।

काउंटी यायालयों के 'याय क्षेत्र में वे सब मुकदमे बांटे हैं, जिनमें दावे की रकम 400 पौण्ड या इससे कम होती है या भूमि पर अधिकार प्राप्ति के मुकदमा में उस भूमि का मूल्य 100 पौंड बापिक होता है। इस सीमा से ऊपर के मुकदमा की सुनवाई सम्बन्धित पक्षा की सहमति से काउंटी 'यायालयों में ही हो सकती है अथवा उन्हें उच्च यायालयों में भेजा जा सकता है। आजकल काउंटी यायालयों का क्षेत्राधिकार बहुत बढ़ गया है। ये कुछ मामलों में दिवालिया सम्बन्धी मुकदमे सुन सकते हैं, जहाँ कम्पनी की पूंजी 1,000 पौंड से अधिक नहीं हो। मान हानि भादि से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई काउंटी 'यायालयों में नहीं हो सकती।

(2) याय या उच्च 'यायालय (High Court of Justice)—वह 'याय के सर्वोच्च यायालय (Supreme Court of Judicature) का ही एक भाग होता है। इसका याय क्षेत्र प्रारम्भिक व अपील सम्बन्धी दोनों ही प्रकार का होता है और इसके अन्तर्गत दीवानों के समस्त तथा फाजदारी के कुछ मामले आते हैं। इसमें 'लाड वीक जस्टिस' जीर लगभग 30 अन्य 'यायाधीश होते हैं। सुविधा के लिए इस 'यायालय के तीन विभाग कर दिये गये हैं—

(1) राजा या रानी का बच विभाग (King or Queen's Bench Division),

(ii) चांसरी विभाग (Chancery Division), एवम्

(iii) वसीयत, वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद व समुद्र विभाग (Probate, Divorce and Admiralty Division)

उक्त तीनों विभाग मिलकर, सर्वोच्च 'यायालय (Supreme Court of Judicature) कहलाते हैं, यद्यपि ये सब सदा अलग-अलग ही अपना याय काम करते हैं। रानी का बच विभाग साधारण दीवानों की सुनवाई करता है। चांसरी विभाग मुख्यतः औचित्यपूर्ण निपटाय नैमिक विधि (Equity) के मामलों की सुनवाई करता है। वसीयत, वैवाहिक, सम्बन्ध-विच्छेद व समुद्र विभाग, जसा कि नाम से स्पष्ट है, वसीयत, वैवाहिक सम्बन्ध व विच्छेद जयवा तलान एव समुद्र के मामलों की सुनवाई करता है।

यद्यपि विभिन्न विभागों के विभिन्न काय क्षेत्र हैं तथापि कोई भी 'यायाधीश किसी भी विभाग में काम कर सकता है और एक विभाग से दूसरे विभाग में मुकदमा जा सकते हैं। यदि मुकदमा की मालियत काउंटी यायालय के क्षेत्राधिकार

से बाहर हो तो उच्च न्यायालय के किसी विभाग में सुनवाई होती है। प्रारम्भिक स्तर के मामलों में न्यायाधीश सुनवाई करते हैं, अपील के मामलों में प्रायः तीन न्यायाधीश सुनवाई करते हैं और कुछ मामलों में दो न्यायाधीशों द्वारा तथा बहुत कम मामलों में एक न्यायाधीश द्वारा मुकदमें सुने जाते हैं।

(3) अपील का न्यायालय (Court of Appeal)—यह न्यायालय काउंटी न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपीलें सुनता है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय का ही एक भाग है। इसमें 'लाइ चामलर' तथा अथ 'लाइ जस्टिस' होते हैं, जो लार्ड चांसलर द्वारा मनोनीत किये जाने पर राजा या रानी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। मास्टर ऑफ रोल्ल्स (Master of Rolls) इसका अध्यक्ष होता है। लार्ड जस्टिस की संख्या 8 होती है। इस न्यायालय में अपीलें केवल विधि तथा तथ्य (Fact) के प्रश्न पर ही होती हैं।

(4) राज्य का सर्वोच्च न्यायालय लार्ड सभा (House of Lords)—लार्ड सभा इंग्लैंड में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Judicature) है। यह न्यायालय इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था का केन्द्र है जिसकी दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के क्षत्राधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय दोनों सर्वोच्च न्यायालय के दो विभाग हैं।

जब अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में लार्ड सभा कार्य करती है तो उसमें केवल 9 साधारण अपील लार्ड्स (Lords of Appeal in Ordinary) भाग लेते हैं और न्यायालय की गणपूर्ति (Quorum) कम से कम तीन न्यायाधीशों से होती है। इसके अतिरिक्त लार्ड सभा के वे सदस्य भी भाग ले सकते हैं, जो न्यायिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त हो या रहे हों। जब लार्ड सभा न्यायालय के रूप में बैठती है तो मुकदमों की सुनवाई व्यवस्थापिका भवन के एक समिति कक्ष (Committee Room) में होती है और लार्ड चामलर उसका अध्यक्ष होता है।

प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति

(Judicial Committee of Privy Council)

दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के अतिरिक्त ब्रिटेन में एक अन्य न्यायालय भी है जिसको 'The Judicial Committee of Privy Council' के नाम से पुकारा जाता है। इसके समक्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ प्रदेशों के उच्चतम न्यायालयों द्वारा किये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। इससे अतिरिक्त कतिपय अन्य अपीलें भी इसमें सुनी जाती हैं—

(क) ब्रिटेन के चर्च के न्यायालय (Ecclesiastical Courts) के निर्णय के विरुद्ध अपील।

(ग) प्राइज कोर्टों (Prize Courts) व निष्पक्षीकरण के विषय में।
 (घ) प्राइज कोर्टों (Prize Courts) व निष्पक्षीकरण के विषय में।
 (ङ) प्राइज कोर्टों (Prize Courts) व निष्पक्षीकरण के विषय में।

कोर्टों का लक्ष्य प्रेसीडेंसी और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के अपील लॉन्डन के निम्नलिखित विषयों पर है। इन मामलों के द्वारा निष्पक्षीकरण की घोषणा नहीं की जाती। यह याचिका समिति के द्वारा राजा के निष्पक्षीकरण व निष्पक्षीकरण में विशेष प्रारंभ का निष्पक्षीकरण देने का परामर्श देती है। इन याचिकाओं में भी अपील की जा सकती है। इसके द्वारा एक नव सम्मत निष्पक्षीकरण दिया जाता है। इसके निष्पक्षीकरण में विराधी मत का कोई उल्लेख नहीं होता। यह याचिका अपने पूरे निष्पक्षीकरण में प्रतिबद्धित नहीं होता।

स्कॉटलैंड के विधि याचिका फौजदारी याचिका (Solemn Procedure) द्वारा होती है। याचिका निम्नलिखित की मुनवाई पूरा प्रक्रिया (Summary procedure) के अनुसार की जाती है जिसमें याचिका प्रक्रिया (Summary procedure) के अनुसार की जाती है जिसमें याचिका प्रक्रिया (Summary procedure) के अनुसार की जाती है। स्कॉटलैंड में फौजदारी याचिकाओं का दावा मुख्यतः इस प्रकार है—
 बग याचिका—स्कॉटलैंड में बग या पुलिस याचिका (Burgh or Police Courts) सबसे नीचे स्तर पर है। ये अत्यंत साधारण मामलों की मुनवाई करते हैं।

जस्टिस ऑफ़ पीस याचिका—बग याचिका से ऊपर के स्तर पर जस्टिस ऑफ़ पीस याचिका (Justice of Peace Courts) है इनमें अव्यक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी प्रक्रिया (Summary Procedure) के अनुसार अभियोग की मुनवाई की जाती है।

शरिफ़ न्यायालय—जस्टिस ऑफ़ पीस याचिका से ऊपर के स्तर पर शरिफ़ न्यायालय (Sheriff Courts) है जिनमें शरिफ़ न्यायालय याचिकाओं का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है।

उच्च न्यायालय—जस्टिस ऑफ़ पीस याचिका से ऊपर के स्तर पर उच्च न्यायालय (High Court of Judiciary) है। प्रारम्भिक याचिका क्षेत्र का यह सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसका कार्यालय एडिनबरा में है, यद्यपि इसके न्यायाधीश दोरे पर याचिका करने जाते हैं। लॉर्ड जस्टिस जनरल (Lord Justice General) व दोरे न्यायालय (Court of Sessions) का भी अध्यक्ष होता है, लॉर्ड जस्टिस क्लर्क (Lord Justice Clerk) और 13 लॉर्ड कमिशनर्स (Lord Commissioners) जो दोरे न्यायालय के न्यायाधीश भी होते हैं, में से

काई भी उच्च न्यायालय में याचावीश की हेतियत से मामला की सुनवाई कर सकता है।

फौजदारी अपील—स्काटलैंड में फौजदारी के मामले की अपील की व्यवस्था यह है कि उच्च न्यायालय के व्यक्तिगत न्यायाधीशों या शरिफ न्यायालय के अभियाग की पूर्ण प्रक्रिया (Solemn Procedure) द्वारा जिस मामले का निर्णय किया गया हो, उन निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। यदि अपील का आधार कानूनी हो तो उच्च न्यायालय की जांच या व्यक्तिगत न्यायाधीश के प्रमाण पत्र के बिना ही अपील की जा सकती है। लेकिन हमारे मामले में अपील तभी सम्भव है जब या तो उच्च न्यायालय इसके लिए अनुमति दे दे या व्यक्तिगत न्यायाधीश यह प्रमाण पत्र दे दे कि मामला अपील के योग्य है। किसी भी अपील की सुनवाई के लिये उच्च न्यायालय के तीन या तीन से अधिक न्यायाधीश बैठते हैं और वे जो भी निर्णय देते हैं वह अंतिम होता है। संक्षेप प्रक्रिया (Summary Procedure) द्वारा दण्ड प्राप्त व्यक्ति भी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, परंतु उनकी अपील केवल कानून और प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकती है।

स्काटलैंड के दीवानी न्यायालय

शरिफ न्यायालय—इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रायः सभी साधारण दीवानी मामले आ जाते हैं। शरिफ और उप शरिफ (Sheriff and Sub-Sheriff) याच-काय का संपादन करते हैं। 5 पौण्ड से कम मूल्य के लाने जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय निपटा सकता है।

बोरो न्यायालय—इस न्यायालय (Court of Sessions) का याच क्षेत्र सब-न्यायी है किन्तु यह एडिनबरा में ही रहकर न्याय काय करता है। विवाह-विच्छेद के मामलों में इसका एकाधिकार है। इस न्यायालय के दो भाग हैं—आउटर हाउस (Outer House) तथा इनर हाउस (Inner House)। आउटर हाउस का अधिकार क्षेत्र प्रारम्भिक है जबकि इनर हाउस प्रमुखतः अपील का न्यायालय है। इनर हाउस के निर्णय के विरुद्ध लांड सभा में अपील की जा सकती है।

स्काटिश भूमि न्यायालय—स्काटलैंड में स्काटिश भूमि न्यायालय (Scottish Land Court) एक विशिष्ट प्रकार का न्यायालय है जो भूमि-मालिकों के बीच मामलों की सुनवाई करता है और बोरो न्यायालय के याचाना के लिये अपील का कोई भी न्यायाधीश इस न्यायालय की अव्यवस्था कर सकता है।

उत्तरी जामरलैंड न्याय व्यवस्था

उत्तरी जामरलैंड के न्यायालयों का उगठन 1874 की उच्च न्यायालय अधिनियम और 1885 के समान है, केवल स्थानीय ग्रामपंचायतों द्वारा जमाने के लिये दिये गए हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Judicature) इसके दो भाग हैं—उच्च न्यायालय (High Court of Justice) और

न्यायालय (Court of Appeal)। इसके अतिरिक्त फौजदारी अपील न्यायालय (Court of Criminal Appeal) है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रारम्भिक भी है। इसके भी तीन विभाग हैं—चांसरी विभाग (Chancery Division), रानी का बेंच विभाग (Queen's Bench Division) और दौरा न्यायालय (Circuit Court) अर्थात् ऐसाइजज (Assizes) विभाग। लाड चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दो साधारण न्यायाधीश होते हैं। अपील न्यायालय में लाड चीफ जस्टिस व दो ग्रांड चीफ ऑफ अपील होते हैं।

उपयुक्त उच्च स्तरीय न्यायालयों के अतिरिक्त उत्तरी आयरलैंड में निम्न स्तर के न्यायालय काउंटी कोर्ट्स (County Courts) व पटी सेशंस (Petty Sessions) होते हैं। काउंटी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है जब कि पटी सेशंस में केवल एक न्यायाधीश के ही होते हैं। विशेष अनियोग के लिए इसमें दो न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र सरसरी का होता है।

10

स्थानीय स्वशासन (LOCAL SELF GOVERNMENT)

‘ इंग्लैण्ड के नागरिकों की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ध्येय उनकी स्थानीय संस्थाओं को है। अपने प्रयत्न सत्रों के समय से अंग्रेज लोगों ने अपने ही द्वार पर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त किया है ।’

—एल.एस.टोन

ब्रिटिश स्थानीय शासन की प्रमुख बातें उसका स्वरूप

ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की समस्या का बहुत अधिक महत्व है और इन्हीं के द्वारा वहाँ के प्रजाजन अपनी स्वतंत्रता का उचित उपयोग करते आये हैं। स्थानीय मामलों में उनकी स्वतंत्रता उनके गौरव का विषय है। ब्रिटिश शासन के एकदमक होने से स्थानीय संस्थाओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ग्राम के नागरिक जितनी दिलचस्पी स्थानीय मामलों में लेते हैं उतनी केन्द्रीय मामलों में नहीं लेते।

आधुनिक ब्रिटिश स्थानीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते समय हम तीन प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं—

1 यह प्रथा अविनाशित अतीत की जाहारी है और बहुत प्राचीन काल से ही इंग्लैण्ड में स्वशासन किसी न किसी रूप में चलता आ रहा है।

2 ब्रिटिश स्थानीय शासन व्यवस्था समयानुसार परिवर्तित होती रही है, यह स्थिर नहीं रही है। इंग्लैण्ड की स्थानीय संस्थाओं का निरन्तर विकास होता रहा है और आधुनिक काल में तो इनने इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि उनका प्राचीन स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है।

3 स्थानीय संस्थायें अपने अधिकारों की बहुत कुछ रक्षा करती हुई अधिकाधिक स्वतंत्र होने का प्रयास करती हैं, तथापि उन पर बंध का नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 75 वर्षों में उन पर समुद्र का नियंत्रण पर्याप्त बढ़ गया है। फिर भी स्थानीय शासन नफरतापूर्वक कार्य करता चला जा रहा है।

ब्रिटिश स्थानीय शासन का संक्षिप्त ऐतिहासिक अवलोकन

इंग्लैण्ड अखिल ब्रिटेन में स्थानीय शासन का जन्मदाता है। इंग्लैण्ड की वर्तमान स्थानीय शासन व्यवस्था ऐंग्लो सैक्सनकालीन व्यवस्था से सम्बद्ध है। उस समय से जब तक इसका क्रमबद्ध रूप से निर्वाह विकास हुआ रहा है। सैक्सन राजाओं के समय में शायर (Shires), हण्ड्रेड्स (Hundreds) तथा बरो (Boroughs) थे और ये नामों विजय के बाद काउण्टी (County), मनर (Manor) तथा म्यूनिसिपैलिटी (Municipalities) में परिवर्तित हो गये। इसी बीच में पैरिश (Parishes) की स्थापना हो गई और उन्होंने टाउनशिप (Townships) का स्थान ले लिया। इस प्रकार इंग्लैण्ड में स्थानीय स्वशासन की ये संस्थायें—काउण्टी, बरो तथा पैरिश अठारहवीं शताब्दी तक चलती रहा। इनके संगठन और पाय क्षेत्र में टमंडर व स्टुजट सम्राटों ने कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया। काउण्टी का शासन जस्टिस ऑफ दी पीस (Justice of the Peace) करते थे, और बरो का शासन उसका फ्रीमन (Freeman) करता था। बरो और पैरिश का शासन-संगठन लोकतन्त्रात्मक था और लोग अपने-अपसरो को स्वयं ही चुनते थे।

परन्तु अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यावसायिक क्रांति (Industrial Revolution) ने भारी परिस्थिति बदल दी। लोग गांव छोड़ कर नगरों में जाने लग गये और नगरों में सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, निधन-महायता तथा नगर-सुधार-समस्याएँ उपस्थित हो गईं। इन विभिन्न नवीन समस्याओं का सामना करने के लिये समुद्र भा संस्कार हुई। उन्होंने पुरानी संस्थाओं का हटाना उचित नहीं समझा, और नई-नई संस्थायें स्थापित की, जिनसे उन समस्याओं का हल हो। पुरानी संस्थाओं को रफते हुए नई-नई संस्थाओं की स्थापना का परिणाम यह हुआ कि नई और पुरानी संस्थाओं का कार्यभार धमके में पड़ गया और ठीक-ठीक विभाजन नहीं हो पाया। स्थानीय संस्थाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और उनके कार्यभार का भी बहुत विस्तार हो गया। अब स्थानीय शासन को सुधारने व पुनर्गठित करने पर विशेष ध्यान दिया जान लगा। सन् 1835 में समुद्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट (Municipal Corporation Act) पारित किया जाया द्वारा बरोज (Boroughs) की प्रशासन व्यवस्था का संगठन हुआ। सन् 1888 में स्थानीय सरकार अधिनियम (Local Governments

Act) पारित हुआ जिसके द्वारा काउन्टिया के प्रशासन की व्यवस्था संगठित हुई। सन् 1894 के एक अधिनियम के अनुसार ग्राम और नगरीय जिले (Urban and Rural Districts) का गठन हुआ। सन् 1929 और 1933 के स्थानीय शासन अधिनियमों (Local Government Acts) ने द्वारा स्थानीय निकायों को केन्द्र से सहायता मिलने जगह और उनके अधिकारों की कानूनी व्याख्या हो गई। सन् 1936 के मावजिनिक स्वास्थ्य और निवास अधिनियम ने स्थानीय अधिकारियों के कार्यों को और भी स्पष्ट कर दिया। 1950 के स्थानीय सरकारी अधिनियम ने स्थानीय सरकार के क्षेत्रों और अधिकारों के परिचयन और निरीक्षण के लिए व्यवस्था स्थापित की और काउन्टी सेवाओं को कुछ जिम्मेदारी सौंपने का प्रबंध किया तथा स्थानीय सरकार की अधिक व्यवस्था में परिचयन किया। इस प्रकार इंग्लैंड और वेल्स के स्थानीय स्वशासन का ढांचा पूरा हुआ।

समरणीय है कि विकास का यह क्रम मुख्यतः इंग्लैंड और वेल्स का है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्थानीय प्रशासन का विकास क्रम इससे भिन्न रहा है।

ब्रिटिश स्थानीय शासन की विशेषताएँ

(Characteristics of British Local Self Govt)

विकासशील—ब्रिटिश स्थानीय शासन का वर्तमान रूप सदियों के क्रमिक विकास का फल है। लोगों की राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ इसने प्रगति की है। यद्यपि विकास की यह प्रक्रिया अधिकांशतः अनियमित और अनियोजित रही है तथापि स्थानीय शासन की समस्याओं ने अपने महत्व और उपयोगिता का पूरी तरह उभारा रखा है। इसके अतिरिक्त उनकी वर्तमान व्यवस्था में प्राचीनता के भी पर्याप्त दर्शन होते हैं। वर्तमान में उनके प्राचीन स्वरूप की विद्यमानता यह अनुभूति करा देती है कि वे इतिहास की गंगा हैं।

लिखित कानून द्वारा रचना—ब्रिटिश स्थानीय शासन की रचना लिखित कानूनों द्वारा हुई है। संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित करके स्थानीय संस्थाओं के भविष्य और उत्तरदायित्वों का स्वरूप निर्धारित किया है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे करने के लिए कानून द्वारा उन्हें शक्ति नहीं दी गयी हो।

त्रिके प्रोत्तरण—ब्रिटिश स्थानीय स्व शासन की तीसरी विशेषता त्रिके प्रोत्तरण की है। वर्तमान व्यवस्था में काउन्टी बोर्डों का पूर्णतः स्वतंत्र निकाय बनाया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर काउन्टी द्वारा शेष भाग की सेवा की जाती है। नगरपालिका बोर्डों का भी अधिकतम स्वतंत्र शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनके क्षेत्र में कुछ कार्य काउन्टी परिषद् द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। पर त्रिके प्रोत्तरण का यह रूप संवैधानिक अधिक है व्यावहारिक कम। फाइनर के शब्दों में "हमारे यहां

विके द्रोकरण नहीं है, बरन पूण स्वन प्रता का एक छाटा भाग है, जो कि मुख्यतः राष्ट्रीय इच्छा पर आधारित संगठन एकीकरण के माध्यम मिलकर इसे स्वतंत्र इच्छा द्वारा स्वानीय परिस्थितियों के अनुकूल क्रियावित करने का प्रयास करता है। इस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाना चाहिए, हम नहीं जानते।

समस्यात्मक एकीकरण का विवास—ब्रिटन में राष्ट्रीय एवं स्वानीय सत्ताओं के बीच समन्वय की दृष्टि से एकीकरण का जन्म हो रहा है। यह एकीकरण वर्तमान परिस्थितियों की एक अनिवार्य उपज है। वे द्रवीय सरकार की अतिशय नियंत्रण की मांग और स्वानीय सरकारों की अतिशय स्वतंत्रता की मांग के बीच पहले जैसे विरोध की स्थिति नहीं रही है। आज दोनों सरकारें एक दूसरे की सहायक और हिस्सेदार बन गयी हैं। दोनों ने राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बनाना अपना उद्देश्य स्वीकार कर लिया है।

समिति व्यवस्था का प्रयोग—ब्रिटिश स्वानीय प्रशासन में समिति व्यवस्था का इतना प्रयोग किया जाता है कि समितियों को स्वानीय सरकार के वास्तविक कारखाने कहा जाने लगा है। ये समितियाँ मुख्यतया पांच प्रकार की होती हैं—स्वानीय समितियाँ (Standing Committees), सुझावदात्री समितियाँ (Persuasion Committees), विशेष एवं सामयिक समितियाँ (Special and Adhoc Committees), कानूनी समितियाँ (Statutory Committees), और उप समितियाँ (Sub Committees)। इन विभिन्न समितियों द्वारा स्वानीय सत्ताओं अपने विविध उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करती हैं। वितीय समितियों द्वारा विभिन्न स्वानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

दलीय राजनीति—संवैधानिक रूप से अनुचित होते हुए भी दलीय राजनीति स्वानीय शासन में पूरी तरह प्रवेश कर गयी है। स्वानीय सत्ताओं में दलीय राजनीति का सक्रिय रूप एक स्पष्ट तथ्य है। उनमें राजनीतिक दल भली प्रकार संगठित रूप में प्राप्न होते हैं। फिर भी कुछ स्वानीय संगठन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप में विगण प्रभावित नहीं रहते, उदाहरणार्थ देहाती क्षेत्र के कुछ मविधान।

एक रूपता की कमी—ब्रिटिश स्वानीय शासन व्यवस्था में एकरूपता की कमी है। एक इकाई दूसरी से मविधान और वनावट की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है। इकाइयों के नियम और उप नियम भी अलग अलग हैं। कोई स्वानीय निकाय जनसंख्या के आधार पर ता कोई प्रदेश के आधार पर और कभी कोई वित्त या विनीय आधार पर संगठित किया जाता है। फिर भी आधुनिक प्रवृत्ति एकरूपता स्थापित करने की है। इन प्रयासों के मूल में यह भावना छिपी है कि विभिन्न स्वानीय समस्याओं के अधिकार क्षेत्र के निवारणों का जीवन स्तर के द्रवीय सरकार द्वारा निवारित स्तर से नीचा न हो।

ब्रिटिश स्थानीय शासन एवं केन्द्रीय सरकार :

पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण

(Local Govt and Central Govt

Supervision and Control)

स्थानीय शासन सत्ताये अपने आप में कोई पूर्णतः पृथक् अस्तित्व नहीं रखती, वरन् केन्द्रीय सरकार का ही एक आवश्यक और अभिन्न अंग होती हैं। उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों और विषयों पर केन्द्रीय सरकार के नियमों और अधिनियमों का पर्याप्त प्रभाव रहता है तथा विरोध की मूर्त में केन्द्रीय इच्छा की प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु उचित यही समझा जाता है कि केन्द्रीय सरकार अनुचित नियन्त्रण से बचे और स्थानीय समस्याओं को उनके प्रायः क्षेत्र में प्रथा सम्भव पूर्ण स्वतन्त्रता दे।

कई बार सदेह किया जाता है कि केन्द्रीय नियन्त्रण के रहने पर स्थानीय स्वायत्तता नहीं रह सकती, अतः स्थानीय शासन समस्याओं को पूर्णतः स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए। लेकिन व्यावहारिकता का तर्काज है कि उपयोगी और आवश्यक केन्द्रीय नियन्त्रण अवश्य ही रहे क्योंकि केन्द्र पर ही सम्पूर्ण देश के प्रशासन का मूलतः उत्तरदायित्व होता है और यदि स्थानीय शासन सत्ताओं को पूरी तरह नियन्त्रण विहीन छोड़ दिया गया तो प्रशासनिक व्यवस्था फेल मकनी है तथा स्थानीय समस्याओं की कार्य कुशलता समाप्त हो सकती है। केन्द्रीय नियन्त्रण की अनिवार्यता निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है—

(i) स्थानीय शासन के साधन सीमित होते हैं, और वह केन्द्रीय शासन के अनुदानों के अभाव में अपने दायित्वों का सतोपजनक रूप से पान्न नहीं कर सकता।

(ii) स्थानीय शासन का अनुभव सीमित होता है और उसके पास सभी आवश्यक सूचनाएँ भी संग्रहीत नहीं हो पाती। केन्द्रीय नियन्त्रण के माध्यम से ही वह अधिक योग्य बन पाता है क्योंकि देश भर की स्थानीय सत्ताओं के अनुभवों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(iii) केन्द्रीय शासन सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शासन समस्याओं को अप्रतिपाद्यत स्वेच्छा का अधिकार नहीं दे सकता।

(iv) स्थानीय सत्ताओं जनेक हानाई विनमे समन्वय तथा एकरूपता लाने के लिए और उनकी गठित नीतियों को मिटाने के लिए केन्द्रीय शासन का नियन्त्रण आवश्यक है।

(v) स्थानीय समाज में गति सम्पन्न स्थाय गिर न उठावें, इसलिए भी केन्द्रीय हस्तक्षेप जरूरी है।

(vi) जनेक स्थानीय सवायें एम्ही हैं जिनके कुशल संचालन पर सम्पूर्ण देश का कल्याण निर्भर करता है, उस जन-स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, शिक्षा, यातायात

आदि इन सेवाओं में समान और उच्च स्तर बनाये रखने के लिए के द्रीय शासन का उचित नियंत्रण जरूरी है।

अ न म हम सर मैकनेल्टी (Sir A S MacNalty) के शब्दों में कह सकते हैं कि "स्थानीय सेवाओं के उचित निर्देशन, एकीकरण और समन्वय के लिए के द्रीय सत्ता के नियंत्रण के किसी भी प्रकार का होना परम आवश्यक है। ऐसा न होने पर विभिन्न जिलों में इन सेवाओं का स्तर और प्रकार असमान रहेगा तथा यह कुल जनसंख्या के लिए अवायव्य होगा।"

ब्रिटेन में स्थानीय शासन पर के द्र का नियंत्रण और उसका रूप पहले ब्रिटिश स्थानीय संस्थाएँ जिला, गैस, विजली आदि का प्रबंध बिना के द्रीय नियंत्रण और महायता के सम्पन्न कर सकती थी, किंतु आज इन कार्यों का राष्ट्रीय महत्त्व हो गया है और के द्रीय शासन पर यह उत्तरदायित्व है कि वह इन सेवाओं के प्रबंध की उपयोगिता देखे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में शासन का रूप एकात्मक होने से भी यह स्वानाधिक है कि स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ अपने कार्यों में यथा सम्भव स्वतंत्र होते हुए भी के द्र के उचित नियंत्रण में रहें।

ब्रिटेन में हम पाते हैं कि के द्रीय शासन ही अपनी तरफ से स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना करता है और उन्हें अपनी ओर से कार्य करने की कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है जहाँ साथ ही उन पर नियंत्रण रखने की आवश्यक शक्ति अपने लिए भी सुरक्षित रखता है। ब्रिटेन में शासन सम्बन्धी सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है और उसी के द्वारा स्थानीय संस्थाओं की स्वतंत्रता की सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है। स्थानीय संस्थाओं के शासन प्रबंध की दखलान के द्रीय सरकार के विभिन्न शासन विभाग करते हैं।

परंतु इन सबमें यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि ब्रिटेन में के द्रीय शासन और स्थानीय शासन संस्थाओं के वत या या उद्देश्यों में भिन्नता है। उन दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है अर्थात् यह है कि देश पर अच्छे से अच्छे ढंग से शासन करना और जनता को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना। इसलिये वे दोनों बड़े सामंजस्य से काम करते हैं। ब्रिटेन में स्थानीय शासन संस्थाओं पर के द्रीय नियंत्रण न तो यूरोप के समान कठोर है और न जर्मनी की तरह विस्तृत होता है। के द्र स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ पर जिन विभिन्न ढंगों में नियंत्रण करता है, उसका विवेक हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं—

व्यवस्थापन सम्बन्धी—के द्रीय नियंत्रण का सर्वाधिक मौलिक रूप यह है कि संसद द्वारा लाया गया है। संसद का स्थानीय सत्ताओं के क्षेत्रों में विनियमित करने का व्यापक अधिकार है। स्थानीय सत्ताएं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती हैं और उन्हीं शक्तियों का सम्पन्न करती हैं जो के द्रीय संसद द्वारा उन्हें सौंपी जाय। संसद का अधिकार है कि वह स्थानीय प्रशासन की नवीन इकाइयों की स्थापना करने के लिए बाजमान इकाइयाँ का समाप्त करने के लिए

और उनके क्षेत्र तथा कार्यों के निर्धारण के लिए आवश्यक कानून बनाए। नसद को यह भी अधिकार है कि स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के कार्यों पर समुचित नियंत्रण के लिए आवश्यक नियमों के निर्माण का अधिकार केन्द्रीय शासन को दे दे।

वित्तीय नियंत्रण—स्थानीय प्रशासनिक मस्याएँ अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत-कुछ क्षेत्र पर निर्भर हैं। वे क्षेत्र आर्थिक सहायता देने पर यह देखता है कि सहायता का प्रयोग ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। केन्द्रीय गामन के प्रतिनिधि स्थानीय निगमों के कार्यों का निरीक्षण करके जो प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पर क्षेत्र आर्थिक अनियमितताओं को दूर करने, आर्थिक प्रयत्न अपने हाथ में लेने या स्थानीय प्रशासनिकों को भी मिलिबत करके कोई अन्य प्रयत्न या आयोजन नियुक्त करने का कदम उठा सकता है। वास्तव में अपने वित्तीय अनुदानों के दल पर केन्द्रीय शासन स्थानीय प्रशासन पर पर्याप्त नियंत्रण और दबाव रख सकता है।

प्रशासनिक नियंत्रण—स्थानीय स्वशासन की इकाइयों पर केन्द्रीय नियंत्रण विभिन्न विभागों द्वारा लाया जाता है। उदाहरणार्थ स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य, सफाई व स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में, यातायात विभाग, सड़कों व बन्दरगाहों के क्षेत्र में और शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रणकारी विभाग सम्बन्धित विषयों में स्थानीय निकायों को आवश्यक सूचना देते हैं, उनका विस्तृत सिकायती की सुनवाई करते हैं, निकायों और व्यक्तियों की बीच के झगड़ों का निपटारा करते हैं, निकायों के संगठन और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित नियम बनाते हैं तथा यह देखते हैं कि निकाय कहीं अपनी क्षमता का दुरुपयोग न करें।

यह स्मरणयोग्य है कि ब्रिटेन में केन्द्र स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों पर वांछित और आनन्दक नियंत्रण ही रखता है। केन्द्रीय विभागों का कार्य मुख्यतः यह देखना है कि स्थानीय निकाय अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करें, कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करें और कानूनों का समुचित क्रियान्वयन करें। हरमन फाइनर के शब्दों में "केन्द्रीय शासन अनावश्यक रूप से घगडाहू का कर नहीं रहता। वह स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की स्वतन्त्रता का सम्मान करता है और अच्छा यही समझता है कि हस्तक्षेप ही आवश्यकता के बिना वे अपनी स्वतन्त्रता का उचित प्रयोग कर सकें।" आज इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि केन्द्रीय शासन का नियंत्रण उन कार्यों तक सीमित कर दिया जाय जो अच्छी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इस नियंत्रण का व्यवहार और प्रशासन इस रूप में किया जाय कि स्थानीय सत्ताओं को यथाम्भन अधिकार से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।

स्थानीय शासन का वर्तमान संगठन

(The Present Structure of the Local Govt)

स्थानीय प्रशासन सुविधा की दृष्टि से पाच प्रमुख धारा में विभाजित है—

(क) काउण्टी

(ख) बरो (Borough), काउण्टी बरो तथा म्युनिसिपल बरो

(ग) नगर जिला (Urban District)

(घ) ग्राम्य जिला (Rural District)

(ङ) परिस (Parish)

शासन की दृष्टि से सम्पूर्ण देश लगभग 114 काउण्टियाँ में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक काउण्टी को ग्राम्य व नगर जिलों में विभक्त किया गया है तथा ग्राम्य और नगर जिलों को ग्रामीण एवं नगरीय परिशों में बाँटा गया है। इस तरह स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिश है और सबसे बड़ी काउण्टी। यदि किसी काउण्टी के अंदर किसी क्षेत्र को अलग बाँटकर मिल जाता है तो वह बरो कहलाता है।

ब्रिटिश स्थानीय शासन में कोई स्थानीय शासन मन्त्रालय या अधिकारी व्यक्ति कानूनी अधिकार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। उसकी इच्छा कानून की सीमा से प्रतिबंधित रहती है। दूसरे, स्थानीय शासन स्वतंत्र है, अंगीकृत नहीं है। प्रत्येक इकाई को अपने अधिकार क्षेत्र में इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता है, केवल तब यह है कि उनकी सब कार्यावाही सब नाबना से होनी चाहिये।

(1) काउण्टी (County)—काउण्टी स्थानीय शासन का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काउण्टी दो प्रकार की है—(क) ऐतिहासिक काउण्टी (Historic County), और (ख) प्रशासकीय काउण्टी (Administrative County)।

(क) ऐतिहासिक काउण्टी—ऐतिहासिक काउण्टियाँ इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 52 हैं। यायिक-प्रशासन भी इनका क्षेत्र है। इनका महत्व इसलिये भी है कि इन्हें नगरीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। ये स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं होती, अतः इनकी कोई प्रश्न अवधारणी समिति नहीं होती और कोई स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य भी नहीं होता। इनमें एक शरिफ, एक लाड लेफ्टिनेंट और एक जस्टिस जाफ पीस रहता है। इन सबकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा होती है।

(ख) प्रशासकीय काउण्टी—स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से प्रशासनिक काउण्टियों का महत्व है। सन् 1688 के स्थानीय सरकार अधिनियम (Local Government Act) के अनुसार 62 प्रशासकीय काउण्टियाँ की स्थापना हुई। लंदन की काउण्टी को मिलाकर इसकी कुल संख्या 63 है। प्रत्येक प्रशासकीय काउण्टी में एक काउण्टी-परिषद होती है जिसमें समापति, 'एलडरमैन' तथा

'काउन्सिलर' हात है। कौन्सिलर का चुनाव करते समय सारे काउण्टी को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसलिए जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक काउण्टी कौन्सिलर की संख्या भिन्न भिन्न है। लन्दन काउण्टी में ये कौन्सिलर (परिषद् सदस्य) अपनी मर्यादों के छठे हिस्से के बराबर अपने में सही ऐल्डरमैन चुन लेते हैं। अन्य काउण्टियाँ में 'ऐल्डरमैन' की संख्या कौन्सिलर की एक तिहाई होती है। ये ऐल्डरमैन बाहर के व्यक्ति भी चुने जा सकते हैं। कौन्सिलर 3 साल तक और ऐल्डरमैन 6 साल तक अपने पद पर रहते हैं। दोनों को मत देने का समान अधिकार है तथा दोनों मिलकर अपने में से किसी एक को या अन्य किसी को बाहर से परिषद् का सभापति चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ एक साल के लिए होता है तथा वह "जस्टिस ऑफ पीस (Justice of Peace) का कार्य करता है। परिषद् अपने सभापति का चयन तथा अपने सदस्यों को परिषद् कार्य करने के लिए यात्रा-व्यय भी दे सकती है।

परिषद् के सदस्यों का चुनाव प्रति तीन वर्षों में होता है। मतदान का आधार घरेलू मतदाधिकार नहीं है, बल्कि यही मतदाना हो सकता है जो निश्चित कर देता है या जिसके पास निश्चित भूमि है। परिषद् का प्रति प्रतिदिन का कार्य वतनिक कमचारियों द्वारा संचालित होता है। परिषद् में समितियाँ होती हैं।

काउण्टी-परिषद् वर्ष में कम-से-कम चार बार अपनी सभा करती है। इसके अधिकार विस्तृत हैं और काम विभिन्न हैं। यह ग्राम जिले की कौन्सिल के काम की देखभाल करती है। बड़ा सड़क की मरम्मत, आगमो, बाल-अपराधियों का चारन सुधारना, स्कूलों व औद्योगिक स्कूलों को खोलना, पुलिस का इंतजाम करना, परिषद् के अवनों की देख रेख करना आदि काम इस परिषद् (Council) का करने पड़ते हैं। शिक्षा का काम कवल इसी को करना पड़ता है। बुढ़ावस्था की पेंशन का भी काम यही करती है और यही कर लगा सकती है।

कार्य की सुविधा के लिए काउण्टी परिषद् का विभिन्न समितियों में विभक्त कर दिया गया है, जैसे—(1) वित्त-समिति, (2) शिक्षा-समिति, (3) निधनता-निवारण समिति, (4) जन स्वास्थ्य समिति (5) गृह-निर्माण समिति, (6) कृषि-समिति, (7) प्रसूता तथा शिशु-कल्याण समिति (Maternity and Child Welfare Committee), (8) स्थानीय निवृत्तिका (पेंशन) समिति, (9) कर-विधायक समिति, (10) मानसिक विकृति वालों की देख-भाल करने वाली समिति, और (11) दुकान अधिनियम समिति (Shop Act Committee)।

चूँकि प्रत्येक काउण्टी में छोटी छोटी पुलिस की इकाइयों के रहने की सम्भावना नहीं है अतः क्वार्टर मैश में व काउण्टी-परिषद् की संयुक्त समिति बनती है, जिसे पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

काउण्टी के प्रशासन कार्य के लिए स्थाई कमचारी होते हैं, जो राजनीतिक दलों के समर्थन या सन्मुख होते हैं। कमचारियों में प्रमुख काउण्टी लिपिक, कोषाध्यक्ष

स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वेक्षक (Surveyor) होते हैं। इन सब कर्मचारियों की नियुक्ति काउण्टी परिषद द्वारा होती है और इन्हीं के ऊपर काउण्टी के प्रबंध की कुशलता निर्भर करती है। वस्तुतः स्थानीय काउण्टी प्रशासन बड़ा बड़ा होता है और इस दक्षता का प्रमुख कारण परिषद के स्थाई कर्मचारी वर्ग का ऊँचा स्तर ही है। उनका कार्य काल सुरक्षित होता है और उन्हें प्रतिवर्ष अपनी नौकरी को स्थिर रखने के लिए तिकड़म तरीक़ा निहानी पड़ती।

(2) बरो (Borough)—स्थानीय शासन में बरो का विशेष महत्व है। इनकी जनसंख्या अधिक होती है। प्रत्येक बरो एक आबाद पत्र (Charter) द्वारा स्थापित होता है जिसे प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें करनी पड़ती हैं। बरो प्रायः तीन प्रकार के माने गये हैं—(क) ससदीय बरो (ख) म्युनिसीपल बरो, एवं (ग) काउण्टी बरो।

(क) ससदीय बरो—ये लाकसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की इकाइयाँ हैं। इनका स्थानीय शासन से कोई सम्बंध नहीं होता, जसा कि ऐतिहासिक काउण्टियों का होता है।

(ख) म्युनिसीपल बरो—वह प्रशासकीय काउण्टी का ही एक भाग है परंतु अलग चाटर मित्र जान से इस काउण्टी की सब शक्तियाँ प्राप्त होनी हों और यह काउण्टी के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। जब इसकी जनसंख्या 75 हजार से अधिक हो जाती है तब यह स्वास्थ्य मन्त्रालय की अर्जी देकर काउण्टी बरो का पद प्राप्त कर लेता है।

(ग) काउण्टी बरो—जमा कि ऊपर बताया गया है किमी बरो की आबादी 75 हजार से अधिक होने पर वह काउण्टी बरो बना दिया जाता है एवं काउण्टी बरो की काउण्टी की शक्तियाँ दे दी जाती हैं। यद्यपि वह काउण्टी का ही एक भाग होता है परंतु उसकी शक्ति और अधिकार पक्के होते हैं।

म्युनिसिपल बरो और काउण्टी बरो दोनों के समान ही कार्य हैं और समान शक्तियाँ हैं—

बरो का शासन—प्रबंध बरोपरिषद द्वारा होता है जिसमें मेयर, कार्डिनल तथा ऐल्टरमैन होते हैं। कानिलम की अवधि 3 वर्ष होती है तथा एक निहाइ प्रतिवर्ष निवृत्त हो जाते हैं। ऐल्टरमैन 6 वर्ष के लिये चुने जाते हैं। कानिलम और ऐल्टरमैन मिलकर अपने आप में या बाह्य में एक मेयर चुन लेते हैं जिसकी अवधि एक वर्ष होती है। मेयर, बरो में अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, वह परिषद की बैठक में समाविष्ट बनता है और बरो के सब जलसों और सम्पत्ति में पुठाया जाता है। उमरा पद वंशानुगत नहीं होता, परंतु अनेक बरो में उसे वंशानुगत दिया जाता है। मेयर की पत्नी मेयरस बहुलाती है और उनसे नमस्त सामाजिक जीवन में भाग लेने की आशा की जाती है। यदि मेयर अविवाहित या विधवा है तो उसकी स्थितदार मेयरस का काम करती है।

बरो-परिषद् के कार्य वैधानिक और कायपालिका सम्बन्धी दोनों प्रकार के होते हैं। वह अपने कर्मचारी नियुक्त करती है और अपने विभिन्न भागों में सफाई, जल का प्रबंध, सड़कों, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य आदि की देखभाल करती है। कार्य की सुविधा के लिए प्रदेश के बरो में समितियाँ होती हैं, जैसे वित्त समिति, शिक्षा-समिति, निधनता-निवारण समिति, बुढ़ावस्था निग्रहिका (पेंशन) समिति, अग्नि रक्षा समिति, पुलिस सम्बन्धी देखभाल समिति आदि। बरो परिषद् का विधायी कार्य यह है कि वह अपने उपनियम (Bye Laws) बनाती है, किन्तु इसके लिये स्वास्थ्य-विभाग से उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। कायभार के अनुसार बरो परिषद् की बैठकें मासिक, पाक्षिक अथवा साप्ताहिक होती हैं।

(3) नगर जिला (Urban Districts)—जब किसी ग्राम-जिला अथवा प्रशासकीय काउण्टी के किसी भाग की जनसंख्या अधिक हो जाती है तब काउण्टी-परिषद् उस नगर जिला बना देती है। नगर जिलों की इगलड में वर्तमान सराया लगभग 572 है। इनके भी वही कार्य हैं जो ग्राम जिलों के हैं। यदि किसी नगर जिले की जनसंख्या 20 हजार से अधिक हो जावे तो उसे प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर नियंत्रण का अधिकार भी मिल जाता है। 25 हजार की आबादी पर वहाँ एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है। ये कॉमिलें अपना अध्यक्ष चुनती हैं और कार्य सुविधा के लिए अपनी कमेटो बना लेती हैं। नगर-जिले के बरो में कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल म्यूरिसिपल कांफरिशन एक्ट के अंतर्गत उन बरो का रूप नहीं दिया जाता। बरो और नगर जिले की कांसिल का ढांचा एक समान ही होता है। नगर जिले का प्रबंध करने वाली समिति का कार्य राजमार्गों की देख-रेख, मकानों का प्रबंध, सफाई, पारिवर्तनिक स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, गैस, बिजली व टारम मार्गों आदि की देख रेख का प्रबंध करना है।

(4) ग्राम जिला (Rural Districts)—जितने ग्राम पैरिश हैं वे सब ग्राम जिला में संगठित हैं। इन ग्राम जिला की अपनी-अपनी प्रतिनिधि परिषदें हैं। इन परिषदों में 300 निवासियों वाले पैरिश का एक प्रतिनिधि होता है। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन 3 साल के लिए होता है और एक-तिरुई प्रतिनिधि प्रति ग्य पद नियुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 10 प्रतिनिधियाँ चुनाए जा सकते हैं। चुनाव शराका पद्धति द्वारा होता है, हाथ उठा कर नहीं। परिषद् की बैठक एक माह में एक बार अवश्य होती है। वह अपना कार्य समितियों की सहायता से करती है। जिला परिषद् का अध्यक्ष परिषद् के सदस्यों में या बाहर से भी चुना जाता है। सफाई, जल, जन स्वास्थ्य आदि का प्रबंध, छाटी सड़कों की देखभाल करना, कुछ लार्डमेंसों का देना, आदि काम ये परिषदे करती हैं। किन्तु जायवृत्तिक काल में जब उसे इगलड का ग्राम्म रूफ सहररी रूप में बदलता जा रहा है, तब वस इन परिषदों का महत्त्व भी घटता जा रहा है। यदि परिषदें कम-से-कम कार्यवाही को बरो में बपरवाही दिलाती हैं तो वे श्रीय सरकार उक्त काम में हस्तक्षेप कर सकती हैं।

(5) पैरिश (Parish)—पैरिश ब्रिटिश स्थानीय शासन का सबसे छोटा अंग है। देश का प्रत्येक निवासी किसी न किसी पैरिश में रहता है। पैरिश को जनसंख्या अलग-अलग है। जिस पैरिश की जनसंख्या 300 या इससे अधिक होती है, वहाँ साधारणतया एक परिषद् बना दी जाती है, जिसकी सदस्य संख्या 5 से 15 तक होती है। ये सदस्य तीन वर्ष के लिए चुन जाते हैं। चुनाव राय उठाकर होता है। 300 से कम आबादी वाले पैरिशों का प्रबंध कर दाताओं की एक समिति द्वारा होता है जिसमें सभी कर-दाता भाग लेने के अधिकारी होते हैं, या उसके प्रबंध के लिए काउन्टी परिषद् की अनुमति से एक पैरिश परिषद् (Parish Council) की स्थापना की जा सकती है तथा उसके अंतर्गत कई पैरिश सम्मिलित हो सकते हैं। 300 से अधिक जनसंख्या वाले पैरिशों का प्रबंध आवश्यक रूप से 5 से 15 सदस्यीय एक परिषद् द्वारा होता है। पैरिश-परिषद् के अधिकार निम्न प्रकार के और बहुत कुछ विभिन्न हैं, पर उन पर जिला परिषद् और काउन्टी-परिषद्—इन दो उच्चाधिकारी संस्थाओं का नियन्त्रण रहता है। स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, नडका के दानी आर वन पथ मार्गों की मरम्मत करना, पानी, प्रकाश व सफाई का प्रबंध करना, प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना आदि कार्य पैरिशों के कार्य-क्षेत्र हैं। पैरिश को कर लगाने का भी अधिकार है, पर कर 1 पौण्ड पर 3 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। पैरिश का हिसाब किताब की जांच जिला लेखा परीक्षा (District Auditors) करते हैं। पैरिश का एक महत्वपूर्ण अधिकार यह प्राप्त है कि प्रबंध ठीक न हो। पर यह ग्राम्य जिला परिषद् या काउन्टी परिषद् से आवदन कर सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि पैरिश कई प्रकार के होते हैं। कुछ पैरिश धार्मिक (Ecclesiastical) होते हैं कुछ भूमि-कर (Land Tax) के होते हैं और तीसरे प्रकार के पैरिश दीवानी (Civil) होते हैं। स्थानीय स्वशासन के प्रथम में दीवानी पैरिश का ही महत्व है। दीवानी पैरिश ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के होते हैं। नगरीय पैरिश अब नगर जिला समितियों में मिला दिये गये हैं जबकि ग्रामीण पैरिश अब भी स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

लन्दन का शासन (Government of London)

लन्दन का स्थानीय शासन उसके ऐतिहासिक विकास, उसके आकार और कुछ अन्य कारणों से इंग्लैंड में अपने ढंग का अनुपम है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही लन्दन देश के गेप भाग से पृथक् समझा जाता रहा है। विषयतया इसी कारण लन्दन का अपना विशिष्ट स्थानीय शासन है और उसकी अपनी विशिष्ट समस्याएँ एवं योजनाएँ हैं। शासन प्रबंध के लिए लन्दन तीन प्रमुख इकाइयों में बंटा हुआ है जो कि जनसंख्या, क्षेत्रफल में एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं और उनका शासन

संगठन भी एक-दूसरे से पृथक है। इन तीनों इकाइयों को लन्दन नगर (The City of London), लन्दन काउण्टी (The County of London) एवं लन्दन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट (London Metropolitan Police District) कहते हैं।

1 लन्दन नगर—यह क्षेत्र वर्तमान राजधानी का एक बहुत छोटा अंग है। इसका क्षेत्रफल एक वर्ग मील है और यह आधुनिक जातन की अपेक्षा मध्यकालीन का ही अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यह आधुनिक राज्य का केवल प्राचीन अंग है, जिसकी पुरानी सीमाएँ और पुराने ढंग की सरकार बिल्कुल नहीं बदली।

लन्दन नगर का स्थानीय शासन एक कॉर्पोरेशन अथवा निगम (The Corporation of the City of London) के द्वारा होता है। कॉर्पोरेशन अपना कार्य एक महापौर या नगर-प्रमुख (Lord Mayor) एवं तीन समितियों के द्वारा करता है। ये समितियाँ निम्नलिखित हैं—

- (क) कोर्ट ऑफ एल्डरमन (Court of Aldermen)—इसमें नगर प्रमुख अर्थात् लॉर्ड मेयर और 26 विशिष्ट सदस्य (Aldermen) होते हैं। ये जीवन भर के लिए चुने जाते हैं। इस समिति का कार्य दलालों को लाइसेंस देना और नगर के अभिलेखों (Records) का सुरक्षित रखना है।
- (ख) कोर्ट ऑफ कॉमन काउंसिल (Court of Common Council)—यह नगर की वास्तविक प्रशासकीय संस्था है, जिसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमन के 26 सदस्य तथा लगभग 206 अन्य सभासद (Councillors) होते हैं जो प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। यह संस्था या समिति नगर के लिए उपविधियाँ (Bye laws) बनाती है और अग्नि-रक्षा, नालियों, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहर की रेलों को छोड़कर सब काम करती है। यह पुलों की देख-भाल करती है और पुलिस, सिविल कोर्ट व फौजदारी अदालतों आदि का निरीक्षण करती है। यह अपनी सुविधा के लिए कई समितियाँ बना लेती है।
- (ग) कोर्ट ऑफ कॉमन हॉल (Court of Common Hall)—इसमें कोर्ट ऑफ एल्डरमन के सदस्य तथा नगर की प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधि (Liverymen) सम्मिलित होते हैं। यह समिति अथवा परिषद् प्रतिवर्ष एक शरिफ (Sheriff) और उन दो एल्डरमनों का चुनाव करती है, जिनमें से कोर्ट ऑफ एल्डरमन एक लॉर्ड मेयर चुनते हैं।

लॉर्ड मेयर बड़ी ध्यान शोकाट का व्यक्ति होता है। वह उपयुक्त तीन परिषदों का सभापति होता है और उसे 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है।

उसे कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं मिले हुए हैं। वह नगर के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं करता और न ही कोई नए कार्यकारी कर्तव्य करता है। उत्पन्न नगर का प्रतिनिधित्व करना उसी का काम है।

2 लंदन काउण्टी—लंदन के स्थानीय स्वशासन की दूसरी इकाई लंदन काउण्टी है। इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 117 वर्गमील और इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है। लंदन की इस प्रशासकीय काउण्टी का शासन प्रबंध लंदन काउण्टी समिति (London County Council) के हाथ में है। इस समिति अध्यक्ष परिषद में 124 निर्वाचित सदस्य और 20 एल्डरमैन होते हैं। सदस्य 3 वर्ष के लिये चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद अपने में से या बाहर से एल्डरमैन चुनते हैं, जो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, केवल प्रति 3 वर्ष प्रायः उनमें से आधे हट जाते हैं। परिषद के निर्वाचित सदस्य और एल्डरमैन मिलकर अपने में से किसी व्यक्ति को महापति चुनते हैं। सदस्य (Councillors) और एल्डरमैन का महान अधिकार मिले होते हैं केवल पिछाचार की दृष्टि से ही उनमें भेद होना है। इस काउण्टी परिषद के अंतर्गत जो अधिकार प्रायः वैसे ही हैं, जैसे अन्य बड़े काउण्टी परिषद के हाथ में हैं। परिषद स्वयं प्रशासकीय संस्था है और स्वयं अपने कर्मचारियों को नियुक्त करती है। परिषद का अधिक समय सामान्य शासन-निष्ठाओं का निश्चित ध्यान में ही व्यतीत हो जाता है। इन सिद्धांतों एवं नियमों को कार्यान्वित करने का परिषद समितियों पर छोड़ दिया जाता है। काउण्टी परिषद अपने धन का सफाई, स्वच्छता, सड़कों, पुलों, जल-सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह निर्माण, शिक्षा, सार्वजनिक मेलों मनोरंजन गृहों, द्रव्य मार्गों आदि से सम्बंधित कार्यों के लिये उत्तरदायी है। सरकारी सहायता, कर, निर्यात व विद्यालयों का शुल्क, स्थानीय कर आदि परिषद की आय के प्रमुख साधन हैं। परिषद जिन विभिन्न समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती है, उनकी संख्या 18 है। इन समितियों के महापति व उप महापतियों को परिषद चुनती है। अधिकांश समितियाँ अपनी उप समितियों की बनाती हैं। परिषद की एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) है, जिसके सदस्य उपर्युक्त 18 समितियों के महापति होते हैं।

लंदन की प्रशासकीय काउण्टी में 28 बर्रो (Borough) हैं। इन पर लंदन काउण्टी परिषद (London County Council) की देख रेख रहती है। इनका प्रबंध भी समितियों या परिषदों (Councils) के द्वारा होता है। प्रत्येक परिषद में पूर्ववत् सदस्य, एल्डरमैन और अध्यक्ष होते हैं। इनका कार्य मुख्यतः जनता का निर्माण करना व उनकी भरणपोषण करना तथा सार्वजनिक मेलों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रसारण, शिक्षा, पुस्तकालय स्थापना आदि से सम्बंधित कार्य करना होता है। अतः नए, पुराने समितियाँ लंदन काउण्टी समिति के द्वारा ही तरह-तरह

करती हैं और उन नमस्त कार्यों में, जो काउण्टी के कार्य-क्षेत्र के होते हैं, काउण्टी की महायता करती है।

3 लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट—लंदन नगर के चारों ओर मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 700 वर्ग मील है। इस इकाई का स्थानीय प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल पुलिस प्रशासन या गति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए है। लंदन नगर की पुलिस अलग है। पुलिस लंदन की नमस्त वाउण्टिया की देखभाल करती है। इसका प्रधान एक पुलिस कमिश्नर है। लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना राबर्ट पील ने सन 1829 में की थी।

स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्य और सेवाएँ

(Functions and Services of Local Administrative Institutions)

स्थानीय संस्थाएँ साधारण कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन विभिन्न सावजनिक कार्यों जयवा विशेष शक्तियाँ पाने पर अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करती हैं। इन संस्थाओं के उत्तरदायित्व सामान्यतः इनके पथक पथक रूप में निभार करते हैं। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में वेल्थ तथा उत्तरी आयरलैंड में काउण्टी वरी परिषदें सभी प्रकार के काम करती हैं जबकि काउण्टी व काउण्टी जिला परिषदें केवल कुछ विनिष्ट प्रकार के काम ही करती हैं, और पैरिश की स्थानीय संस्थाएँ बहुत ही सीमित काम करती हैं। इन सभी द्वारा सामान्यतः जिन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, उन्हें हम तीन समूहों में रख सकते हैं—

(1) पर्यावरण सम्बन्धी सेवाएँ (Environmental Services)—इनका उद्देश्य नागरिकों के पर्यावरण को सुधारना व अच्छा बनाना है। इन सेवाओं में उल्लेखनीय हैं—पानी के बहाव व नदी नालियाँ की व्यवस्था, मार्गों की रोशनी, गदगी को हटवाना व उसका उचित प्रयोग करना, अच्छे पानी की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, वातावरण की सफाई, पार्कों और मनोरंजन-स्थानों की व्यवस्था, सार्वजनिक बाग़ों (Public Nuisances) को रोकना आदि।

(2) रक्षा सेवाएँ (Protective Services)—इन सेवाओं में नागरिकों की अभि सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था व नागरिक प्रतिरक्षा आदि सम्मिलित हैं।

(3) व्यक्तिगत सेवाएँ (Personal Services)—इन सेवाओं का उद्देश्य व्यक्तियों की श्रष्ट नारीरिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों को विकसित करना है। जन्मावत, शिक्षा, न्याय, गृह निर्माण मनाविनोद की व्यवस्था आदि के काम इन सेवाओं में आते हैं। सेवाओं के इसी समूह में कुछ स्वास्थ्य सेवाएँ, बूढ़ों और अपाहिणों की सेवा, पुस्तकालयों, अजायबघर व कला-गैलरियाँ आदि की व्यवस्था भी सम्मिलित हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएँ व्यापार बाय भी करती हैं तथा वातावरण, नचार, वन्दरगाहों की व्यवस्था आदि कार्यों का लाभ प्राप्ति के आधार पर सम्पादन किया जाता है। परन्तु ऐसा अब उतना कम होता है।

ग्रिटन स्थानीय शासन की यह विशेषता है कि पुलिस स्थानीय मस्याओं के अधीन है। ग्रिटन में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा स्थानीय शासन संस्थाओं के हाथ में ही है। माध्यमिक उपयोगिताओं की संवादा के लिये मुख्यतः यही संस्थाएँ उत्तरदायी हैं।

स्थानीय निकायों के आर्थिक साधन

(Resources of Local Bodies)

स्थानीय निकायों की आय का सबसे प्रमुख स्रोत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। पहले केन्द्रीय राजान से विशेष कामों के लिए ही विनाश अनुदान दिए जाते थे, परन्तु अब सामान्य अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

स्थानीय करा, नहणा, व्यापारिक आय, किराये, सुल्क आदि अब अनेक साधनों से भी स्थानीय निकायों को बहुत कुछ आय होती है, परन्तु कुल व्यय का लगभग 1/3 भाग प्रायः सरकारी अनुदान से ही पूरा हो पाता है। स्थानीय करा में व कर शामिल होते हैं, जिन्हें स्थानीय निकाय भूमि व नयनों के मालिकों और किरायदारों को लगाते हैं। स्थानीय निकाय बड़े खर्चों जैसे जमीन प्राप्त करने, इमारतें सज्जी करने और इसी प्रकार के अन्य स्थायी कामों के लिए धन का प्रयोग करने को नहण ले सकती हैं। इन कर्जों के लिए गृह निर्माण विभाग और स्थानीय सरकार के मन्त्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

एक स्थानीय निकाय के वित्तीय मामलों पर उनकी वित्तीय समिति नियंत्रण रखती है और गृह निर्माण एवं स्थानीय सरकार के मन्त्रालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों (Auditors) द्वारा यह कि इस मामले में लेखा परीक्षकों की व्यावसायिक क्षमता द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा (Audit) की जाती है, यद्यपि यह अंतिम प्रणाली अधिकतर प्रयोग में नहीं लायी जाती।

EXERCISES

Chapter—1

- 1 Describe the different sources of the British Constitution. Discuss the main elements that go to make the British Constitution.
ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। उन तत्वों का विवेचन कीजिए जो ब्रिटिश संविधान का निमाण करते हैं।
- 2 Examine briefly the landmarks in the development of the British Constitution.
ब्रिटिश संवैधानिक विकास के प्रमुख बिंदुओं की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए।
- 3 "The British Constitution is the result of development and not of design." Discuss.
"ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का।" समीक्षा कीजिए।
- 4 Critically examine the nature of the British Constitution.
ब्रिटिश संविधान की प्रकृति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- 5 Briefly describe the salient features of the British Constitution.
ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 6 What is meant by 'Rule of Law' in Great Britain? What recent developments seem to threaten its existence?
ग्रेट ब्रिटेन में 'विधि शासन' से क्या अभिप्राय है? वर्तमान में ऐसी कौनसी बातें हो गई हैं जो इसके प्रति खतरनाक हैं?

Chapter—2

- 1 What is the importance of 'Constitutional Conventions' in the working of the British Constitution? Explain with examples.
'संवैधानिक अभिसमयों' का ब्रिटेन के संविधान के कार्यान्वयन में क्या महत्त्व है? उदाहरण देकर समझाइये।

- 2 Distinguish between the Laws and Conventions of the Constitution Why do Conventions arise and what is the sanction behind them ? Give some important Conventions of British Constitution

संविधानिक कानून और अभिमतया में क्या अंतर है ? अभिमतयो का उदय क्या होता है और उनका पालन क्या किया जाता है ? ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अभिमतया का वर्णन कीजिए ।

Chapter-3

- 1 State briefly what do you understand by the term 'Crown' in the British Constitution and distinguish it from the King

'क्राउन' शब्द से आप क्या समझते हैं ? सम्राट और क्राउन में क्या अंतर है ?

- 2 Examine the position and functions of the Crown in the British Constitution

ब्रिटिश संविधान में क्राउन की स्थिति और दृष्टा का वर्णन कीजिए ।

- 3 Discuss the position of the monarch in the British Constitution Why does monarchy survive ?

ब्रिटिश सम्राट की स्थिति की विवेचना कीजिये । सम्राट अब अभी तक अस्तित्व में क्या है ?

- 4 "The King can do no wrong" Explain the meaning and implication of the statement

'सम्राट भूल नहीं कर सकता । इस कथन का अर्थ और महत्व बतलाइये ।

- 5 Discuss the utility of monarchy in Britain

ब्रिटिश में राजतन्त्र की उपयोगिता का वर्णन कीजिए ।

- 6 "The Government of the United Kingdom is in ultimate theory an absolute monarchy, in form a limited monarchy and in actual character a democratic republic" Explain "ब्रिटिश शासन सिद्धांततः निरंकुश राजतन्त्र, स्वरूप में सीमित राजतन्त्र और व्यवहार में लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र है ।" इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Chapter-4

- 1 What are the features of the Cabinet system of Government ? How far they are present in Britain ?

मंत्रिमण्डलात्मक पद्धति की सरकार के कौन कौन से लक्षण हैं ? वे कहा तक ब्रिटिश में विद्यमान हैं ?

- 2 **Examine the position and functions of the Privy Council in Britain**
ब्रिटेन में प्रिवी परिषद् की स्थिति तथा कृत्यों का वर्णन कीजिए ।
- 3 **Explain the structure, role and functions of the Cabinet in the British Constitution**
ब्रिटिश संविधान में उसकी मंत्रिमण्डल के संगठन, कृत्य तथा स्थिति का वर्णन कीजिए ।
- 4 **Examine critically the statement that "the Cabinet in Britain is the steering wheel of the ship of the State and the steersman is the Prime Minister"**
'ब्रिटिश मंत्रिमण्डल राज्यरूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक' । इस कथन की विवेचना कीजिए ।
- 5 **'Today it is not the House of Commons which controls the Cabinet but the Cabinet which controls the House' Explain and account for this development**
'वर्तमान युग में लोक सभा मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमण्डल ही लोक-सभा पर नियन्त्रण रखता है ।' इस विकास की व्याख्या कीजिए एवं कारण बताइए ।
- 6 **Is there Cabinet dictatorship in Britain ? Give reasons in support of your answer**
क्या ब्रिटेन में मंत्रिमण्डलीय अधिनायकत्व है ? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए ।

Chapter—5

- 1 **Describe the powers, functions and position of the British Prime Minister Is he 'The first among the equals' ?**
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कृत्य और स्थिति का वर्णन कीजिए । उसे क्यों 'समकक्षों में प्रथम' कहा जा सकता है ?
- 2 **'The fact cannot be got around, however, that to all interests and purposes the powers of pulse is no longer in the Parliament but rather in the cabinet Discuss**
'तथ्य तो यह है कि सभी दृष्टियों से शक्ति अब संसद के हाथ में नहीं रही, अपितु मंत्रिमण्डल के हाथ में चली गई है ।' विवेचना कीजिए ।

Chapter—6

- 1 ब्रिटिश संविधान में विशेषज्ञों तथा अविशेषज्ञों के कृत्यों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 2 "The British Parliament is a tool in the hands of the ministers and the ministers are as tools in the hands of the Permanent officials" Examine 'ब्रिटिश संसद मंत्रियों के हाथ में और मंत्री स्थायी कर्मचारी वर्ग के हाथ में बिलों के समान है।' इस कथन की विवेचना कीजिए।

Chapter—7

- 1 How far it is correct to call the sovereignty of the British Parliament a myth ? Account for the progressive decline of the actual powers of the British Parliament 'ब्रिटिश संसद की सम्प्रभुता' को भ्रम कहना कहा तक उचित है ? ब्रिटिश संसद की शक्तियों के ह्रास का कारण बताइये।
- 2 Discuss the composition, functions and powers of the House of Lords and critically examine its utility in the British Constitutional system लाइसन्स की रचना, कृत्य तथा शक्तियों का वर्णन और ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्था में इसकी उपयोगिता की परीक्षा कीजिये।
- 3 'The House of Lords should be either ended or amended' Comment upon this statement 'लाइसन्स का या तो अंत होना चाहिए या सुधार।' इस कथन की समीक्षा कीजिए।
- 4 Describe the composition, powers and functions of the House of Commons in England ब्रिटिश लोक सभा की रचना, अधिकार तथा कृत्यों का वर्णन कीजिए।
- 5 Explain the procedure for the passing of Laws in England and compare the same with that in the U S A ब्रिटेन में प्रचलित विधि निमाण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये और उसकी तुलना अमेरिकन प्रक्रिया से कीजिए।
- 6 Critically examine the committee system in England and compare it with that of America ब्रिटिश समिति पद्धति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा अमेरिकन पद्धति से इसकी तुलना कीजिए।

- 7 'What is meant by 'Delegated Legislation' ? Account for its growth in Great Britain in modern time and discuss its merits and demerits

'प्रदत्त विधायन' से आप क्या समझते हैं ? इसके विकास के कारणों का विवेचन कीजिए और गुण और दोषों का वर्णन भी कीजिए ।

- 8 How is the Speaker of the British House of Commons elected ? Describe his powers and functions : Compare and contrast them with those of the Speaker of the House of Representatives in U S A

ब्रिटिश लोक सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है ? इसके अधिकारों तथा कृत्या का वर्णन कीजिये । इनकी तुलना से रा अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ व कृत्यों से कीजिए ।

Chapter—8

- 1 Mention the main features of the British party system and compare them with those of America and France
ब्रिटिश दल प्रथा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और अमेरिका तथा फ्रांस से उनकी तुलना कीजिए ।

- 2 Describe the organisation, aims and methods of parties in Britain

ब्रिटिश राजनीतिक दलों के संगठन, उद्देश्य तथा कार्य-पद्धति की विधि का वर्णन कीजिए ।

- 3 'What advantages has the two party system given to Britain ? What are the reasons for its strength ?

द्वि-दलीय पद्धति की प्रधानता से ब्रिटेन को क्या लाभ हुए हैं ? ब्रिटेन में इस पद्धति के स्थायित्व के क्या कारण हैं ?

- 4 Describe the parliamentary organisation of the British Political Parties What is the relationship between it and the party organisation outside parliament ?

ब्रिटिश दलों के संसदीय संगठन का वर्णन कीजिए । दल के बाह्य संगठन से उसका क्या सम्बन्ध है ?

Chapter--9

- 1 Point out the main features of judicial system in Pr
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

- 2 What is meant by 'Rule of Law' ? How far does it guarantee the rights of the people ?
 'कानून के शासन' का क्या अर्थ है ? यह नागरिकों के अधिकारों का क्या
 तक सुरक्षित रखता है ?

Chapter--10

- 1 Describe briefly the importance of Local Administration. Give an account of the gradual growth of British System of Local Government. Also discuss the salient features of this system in Britain.
 स्थानीय शासन के महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ब्रिटेन में स्थानीय शासन के क्रमिक विकास का बतलाते हुए उसकी विशेषताओं को प्रकट कीजिए।
- 2 Describe the chief organs of Local-Self Government in Britain and their functions. How does the Central Government exercise control over these local bodies ?
 ब्रिटेन की स्थानीय निकायों के मुख्य अंग तथा उनके कर्तव्य का वर्णन कीजिए। उन पर केन्द्रीय सरकार किस तरह से नियन्त्रण स्थापित करती है ?
- 3 Write short note on the Government of London.
 लंदन की सरकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- 4 Discuss the functions and resources of Local Government in Britain.
 ब्रिटेन में स्थानीय शासन के कार्यों और साधनों की विवेचना कीजिए।

SELECTED READINGS

- | | |
|----------------|---|
| 1 Bagehot | : The English Constitution |
| 2 Bailey | British Parliamentary Democracy |
| 3 Dicey | : Introduction to the Law of the Constitution |
| 4 Jennings | The British Constitution |
| 5 Laski | Parliamentary Government in England |
| 6 Lowell | The Government of England |
| 7 Ogg & Zink | Modern Foreign Governments |
| 8 Wheare | Modern Constitution |
| 9 Amos | The English Constitution |
| 10 Carter | : <i>Government of Great Britain</i> |
| 11 Greaves | : The British Constitution |
| 12 Keith | : British Cabinet System |
| 13 Marriot | Mechanism of the Modern State |
| 14 Martin | The Magic of Monarchy |
| 15 Munro | : The Governments of Europe |
| 16 Ogg | English Government and Politics |
| 17 Standard, H | : The Two Constitutions |
| 18 Finer | Governments of Greater European Powers |
| 19 Finer | The British Civil Services |
| 20 Taylor | The House of Commons at Work |
| 21 Bailey | Political parties and the Party system in Britain |
| 22 Bulmer | The Party system in Great Britain |
| 23 Malenzie | British Political Parties |

- | | |
|-------------------------|---|
| 24 Barker | Britain and the British People. |
| 25 Briers and
Others | Papers on Parliament A Symposium |
| 26 Neumann | European and Comparative
Governments |
| 27 Jennings | Law of the Constitution |
| 28 Robsen | : Administrative Law in England |
| 29 Robsen | Britain, An Official Hand-Book,
1963 ed |
| 30 Maud | : Local Government in Modern England |
| 31 Finer | : English Local Government |
| 32 Jackson | Local Government in England and
Wales |
| 33 Robsen | <i>The Development of Local
Government</i> |
| 34 Clarke | : The Local Government of the United
Kingdom |
| 35 Cole | Local and Regional Government |
-

अमेरिका का संविधान

(THE AMERICAN CONSTITUTION)

“जैसे अमेरिका अफ्रेजी बन गया वैसे ही उपनिवेशों में अफ्रेजी सदयों
 अमेरिकी बन गई । इन सस्थाओं ने पथक पृथक उपनिवेशों के
 राजनैतिक जीवन की नयी स्थितियों व नई सुविधाओं के
 अनुकूल अपने आपको ढाल लिया । ये उपनिवेश प्रारम्भ
 में कठिनाइयों से लड़े, फिर विस्तृत हुये और
 अन्त में विजयी हुये । इन्होंने बिना अफ्रेजी
 स्वभाव छोड़े अमेरिकी रूप व
 रस प्राप्त कर लिया ।”

—बुड्रो विलसन

“अमेरिका का विधान सब कुछ काट छाट के बाव भी सत्तार के समस्त
 विधानों से अछूट है, क्योंकि इसकी योजना अति सुन्दर है, यह
 जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है, यह सरल और
 सक्षिप्त है, इसकी भाषा स्पष्ट है और इसमें सिद्धांतों
 की निश्चितता के साथ साथ विस्तृत विवरणों
 के लिये लचीलापन है ।”

—लार्ड ब्राइट

1

अमेरिका के संविधान का विकास व स्वरूप (GROWTH AND NATURE OF THE CONSTITUTION OF THE U S A)

“हमारा यह अटल निश्चय है कि मतको का मरना व्यर्थ नहीं जायेगा ।
ईश्वर के अधीन इस जाति में स्वतंत्रता का नया जन्म होगा
और ऐसी सरकार जो जनता की होगी, जनता के
द्वारा होगी और जनता के लिए होगी,
इस पृथ्वी से समाप्त नहीं
होने पावेगी ।”

—अब्राहम लिंकन

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वर्तमान लिखित संविधानों में सबसे प्राचीन है । इसका जन्म उस समय हुआ था जबकि फ्रांस में ‘राजतन रोम में ‘पवित्र साम्राज्य (Holy Empire), कुस्तुतुनिया में सुल्तान खलीफा (Sultan Caliph), पर्किया में ‘स्वर्ग आदेश’ (Mandate of Heaven) में विभूषित सम्राट और जापान में ‘मृत साम्राज्य (Hermit Empire) था । किन्तु ये सभी राज्य वर्षों पूर्व अतीत के गम में विलीन हो गये, जबकि अमेरिका का संविधान नदियों के सहायकों को घेरते हुए आज भी सिर उठाये जादस प्रस्तुत कर रहा है ।

अमेरिकन संविधान की उत्पत्ति और उसका विकास (Origin and Development of the American Constitution)

संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान शासन-पद्धति का आधार सन 1787 में फ्रिडलैंडफोर्ग कांफ्रेंस द्वारा निर्मित संविधान है, जो सन 1789 का संविधान कहलाता है । पूर्णतः निर्मित और लिखित संविधान होते हुए भी विगत लगभग 180 वर्षों में यह निरन्तर विकसितमान रहा है । यह संविधान अस्तित्व में बंसे आया— इसके पीछे एक लम्बी कहानी है —

उपनिवेश निर्माण

वालम्बस द्वारा अमरिका के विनाल महाद्वीप की खोज करने के बाद गन शन यूरोप की जातियां नए प्रदेस की भूमि पर अपने उपनिवेश कायम करना शुरू कर दिया। प्रारम्भ में अंग्रेज जागमनशाहिया का ही प्रधानता रही, परन्तु शीघ्र गने विभिन्न कारणों से, जमनी, पुर्तगाल, स्पेन, डच, स्वीडिश, डेन्मार्क, फ्रांस आदि सभी देशों विनाल महाद्वीप में अमरिका और उनके विविध भागों में बसे गये। यूरोपवाणियों का बाढ़ अमरिका में निरन्तर जाती ही गई। फरव्वरूप जहाँ 1690 में अमरिका की जनसंख्या लगभग 2½ लाख थी, वहाँ 1775 में वह लगभग 25 लाख हो गई।

इंग्लैंड और युरोप से आये हुए लोग अपनी भाषा, संस्कृति और विचार धारों में अपने साथ लाये। इन सभी लोगों के परस्पर घुलन मिलन से अमरिका में एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ जिनमें इंग्लैंड और युरोप दोनों की संस्कृतियों के बीज थे। व्यवस्था प्रिय हान के कारण अविश्वसनीयता लगातार यह उचित समझा कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंग्लैंड की मातृ सरकार से आज्ञा प्राप्त कर ली जाय। इंग्लैंड के राजा ने प्रपत्र (Charters) के रूप में विविध व्यक्तियों और संस्थाओं को इस प्रकार की आज्ञाएं प्रदान कीं। फरव्वरूप उपनिवेशों की स्थापना का सिलसिला जारी हुआ और सन् 1776 तक अमरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हुई जो आंतरिक मामलों में स्वशासन होने लगे थे।

यस प्रकार जिन उपनिवेशों की स्थापना अमरिका में हुई, वे मुख्यतः तीन प्रकार के थे — सम्राट के उपनिवेश (Royal or Crown Colonies) स्वाम्याधीन उपनिवेश (Proprietary Colonies), चार्टर या अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश (Charter colonies)। सम्राट के उपनिवेशों की संख्या सबसे अधिक थी। ये उपनिवेश पूरी तरह सम्राट के नियंत्रण में थे। सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में इनमें गवर्नर नियुक्त होते थे। स्वाम्याधीन उपनिवेशों का शासन ऐसे व्यक्तियों के अधिकार में था जिन्होंने शासन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इनका शासन प्रबंध अपना था किन्तु सम्राट का विधि पर वीटो (Veto) का अधिकार था। चार्टर-उपनिवेश कंपनियों द्वारा बसाये गये थे। ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे और इंग्लैंड की विधियों के प्रतिबल विधि निर्माण नहीं कर सकते थे। स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के उपनिवेशों की स्थिति में परस्पर कुछ अंतर था। पर सबकी सामान्य बात यह थी कि अपनी आंतरिक नीति का निर्णय करने में यद्यपि वरिष्ठता रूप से स्वतंत्र थे, किन्तु इनके वैदेशिक मामलों व सैन्य एवं युद्ध सम्बन्धी मामलों तथा कस्टम (Custom) सम्बन्धी विषयों का सलाह इंग्लैंड की सरकार द्वारा होता था।

स्वतन्त्रता की ओर

अन्नी प्रकार कम जाने के उपरान्त उपनिवेशों के निवासियों में शर्म-शर्म सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत होती गई तथा इंग्लैंड से उनका भावात्मक सम्बन्ध पहले के समान घनिष्ठ नहीं रहा। जब उनमें पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित पूर्ण स्वायत्तता की इच्छा उत्पन्न होती है तो और इंग्लैंड का नाम मात्र का आधिपत्य भी उन्हें सहन नहीं लगता। विभिन्न प्रशासनिक और आर्थिक कारणों से ब्रिटन के विरुद्ध उपनिवेशवासियों का असन्तोष बढ़ता गया। सन् 1963 में फ्रांस के विरुद्ध सप्त वर्षीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड ने माना कि अमेरिका के उपनिवेशों इस युद्ध का व्यय वहन करने में भागीदार बने। ब्रिटिश सरकार ने इच्छा प्रकट की कि उपनिवेशों की रक्षा और सामान प्रवाह पर हानि बाध खर्च का कुछ भाग उन्हें (उपनिवेशों की) भुगतान करना चाहिए।

उक्त निश्चय के अनुसार जब ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवासियों पर नये-नये कर लगाना शुरू किया तो उनमें विद्रोह की लूनी भावना नष्ट नहीं उठी। ब्रिटिश समर्थ द्वारा आरोपित करा का चुकाना ज़रूरी बन गया। उन्होंने नारा लगाया कि "बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं" (No Taxation without Representation) अर्थात् ब्रिटिश मसदा, जिसमें हम (उपनिवेशों का) प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर कर नहीं लगा सकती। उपनिवेशवासियों की आवाज का नाम (Sam), जॉन एडम्स (John Adams), पैट्रिक हेनरी (Patrick Henry) थॉमस जैफ़रसन (Thomas Jefferson) जैसे क्रांतिकारियों ने बोल-बनाया। जब इंग्लैंड द्वारा जागृकित जवाहरित कानून का आवाज का सुला उत्कलन किया जान लगा। ब्रिटिश मसदा ने दमनकारी रूप अपनाया जिससे उपनिवेशों में रोष का माहुर उमड़ उठा।

महाभूतों के निवासियों ने प्रतिनिधित्व का नारा दिया। उनका प्रयास कि स्वतन्त्रता सन् 1774 में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किंगडमलिया नगर में हुआ, जिस "प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस" (The First Continental Congress) कहा जाता है। कांग्रेस द्वारा एक महाद्वीपीय संगठन (Continental Association) की स्थापना की गई ताकि ब्रिटिश का नंगलन हो सके। सन् 1775 में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस (The Second Continental Congress) हुई। कांग्रेस ने क्रांतिकारी दल का एक विभाग में दूर 13 उपनिवेशों में फैला। यह कांग्रेस विचार रूप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि मार्च, 1781 को एक 'उत्तर उपनिवेशों' की सरकार का आधिकारिक था (Official Organ) का रूप में कार्य करने लगा। इस तरह नई अमेरिका की प्रथम राष्ट्रीय सरकार थी।

स्वतन्त्रता की घोषणा

द्वितीय दलित नरों के कारणों से स्वतन्त्रता का माहुर स्वयं दिखाई देने लगा। जब इंग्लैंड ने उनका दमनकारी दमन किया तो वे, जो पहले

वार्शिंगटन के नातृत्व में तेरह के तेरह उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत करते हुए 4 जुलाई सन् 1776 को ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी स्वामिभक्ति का त्याग कर दिया। वे स्वतंत्र और प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य बन गये।

स्वतंत्रता की घोषणा के तुरन्त बाद ही उपनिवेशवासियों ने सबसे पहले अपना ध्यान सर्गाठित होकर युद्ध करने पर दिया। यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला और अन्त में उपनिवेशों की जीत हुई। इंग्लैंड में लॉर्ड नाथ की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा नयी सरकार ने निश्चय किया कि स्वतंत्रता की घोषणा (The Declaration of Independence) के आधार पर शांति संधि कर ली जाए। 1783 में संधि पर विधिवत् हस्ताक्षर हो गये जिसमें यह मान लिया गया कि सभी 13 उपनिवेश पूर्णतया स्वतंत्र तथा प्रभुतासम्पन्न राज्य होंगे।

राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना, 1776

1783 में उक्त संधि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व 12 जून, 1776 को, महाद्वीपीय कांग्रेस ने प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लेकर एक समिति का निर्माण किया था जिसका काम एक ऐसे मध्य (Confederation) के संविधान का विचार करना था जिसके अंतर्गत एक होकर सभी उपनिवेश स्वाधीनता प्राप्त की चला सकें और आंतरिक व्यवस्था बनाए रख सकें। नवम्बर 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने (जो सभी उपनिवेशीय राज्यों की सम्मिलित सभा थी) स्थायी सभ के निर्माण से सम्बन्धित धाराओं का स्वीकार कर लिया। पहली मार्च 1781 तक सभी राज्यों में सभ या सदन की इन धाराओं (Articles of Confederation) पर अपनी स्वीकृति दे दी और उसी दिन ये धाराएँ लागू हो गईं। ये धाराएँ अथवा अनुच्छेद ही मयुक्तराज्य अमेरिका के 'प्रथम संविधान' थे। उल्लेखनीय है कि इस मधीय व्यवस्था का अस्थायी रूप से तो लागू सन् 1777 में ही कर दिया गया था ताकि युद्ध में बाधा न पहुँचे।

उपरोक्त संविधान के अंतर्गत एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की स्थापना की गयी जिसके अधिकार निश्चित और सीमित थे। संविधान की प्रथम धारा के अनुसार मध्य का नाम मयुक्तराज्य अमेरिका रखा गया। एक अन्य धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता और सत्ता की रक्षा स्वीकृत की गयी। प्रभुता राज्यों में निहित रखी गयी और केन्द्रीय सरकार की शक्ति सीमित मानी गयी। मधीय शक्तियों का कार्यान्वित करने के लिए एक कांग्रेस की स्थापना की गयी जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गये। यह आवश्यक रखा गया कि प्रत्येक राज्य कम से कम दो और अधिक से अधिक सात प्रतिनिधि भेज बिन्दु प्रत्येक राज्य की नवल एवं मत देने का अधिकार (One State One Vote) हो। यह भी व्यवस्था की गयी कि किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 13 राज्यों में से

9 का बहुमत आवश्यक होगा। कांग्रेस का रूप एकसदनीय (Unicameral) रखा गया। महाद्वीपीय कांग्रेस की अपेक्षा इस सवर्ग या सभ की कांग्रेस के अधिकार निश्चित और स्पष्ट रख गये जिनके आधार पर वह सभी राज्यों का सामान्य हित साधन कर सकती थी।

संघीय व्यवस्था की असफलता और उसके पुनर्परिणाम

उपरोक्त व्यवस्था के कारण सभ वस्तुतः बहुत ही निबल था। उसके पास वास्तविक शक्ति का सवधा अभाव था। कांग्रेस को कायपालिका सम्बन्धी कोई अधिकार प्राप्त न थे। इस बात की भी व्यवस्था नहीं थी कि यदि कोई राज्य केन्द्र के आदेश या उसके द्वारा की हुई मर्चिया के दायित्वों का पालन न करे तो केन्द्र क्या कारवाई कर सकेगा? केन्द्रीय अथवा मधीय सरकार को यह अधिकार भी नहीं था कि वह कर लगा सके तथा राज्यों के बीच होने वाले व्यापार का नियंत्रण कर सके।

इन निबलताओं के कारण सभ की व्यवस्था स्थायी सिद्ध न हो सकी। कुछ ही समय में राज्यों के पारस्परिक सहयोग का अन्त हो गया। मधीय व्यवस्था उन्हें कोई वास्तविक एकता प्रदान नहीं कर सकी। वस्तुतः सभ की स्थिति प्रारम्भ से ही उस बालू की रस्मी के समान थी जो किसी को बाध मक्ते में असमर्थ थी। गुनरा के शब्दों में “इस सभ की दुर्बलता यह थी कि इसके पास व चार वस्तुएं नहीं थी जो प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के पास होनी चाहिए अर्थात् कर एकत्रित करने, ऋण देने, व्यापार का नियंत्रण करने तथा सेना एकत्रित करके रक्षा की पूर्ण व्यवस्था की शक्ति। ये शक्तियाँ सन् 1787 के नये संविधान द्वारा कांग्रेस को दी गयी।”

संघीय व्यवस्था की दुर्बलता के कारण शीघ्र ही अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो गयी। राज्या में अमान्ति फल गयी और कई जगह पर विद्रोह भी हो गये। चारों तरफ असंतोष, आर्थिक परेशानियाँ, ईप्सा और प्रादेशिकता का बालूवाला हा गया।

फिलाडेलफिया सम्मेलन और नये संविधान का निर्माण

शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि सन् 1776 की संघीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। इस दृष्टि से संविधान की धाराओं में सुधार क जो भी प्रयत्न किए गये वे सफल न हो सके और राज्यों में गृह युद्ध छिड़ जान का भय उत्पन्न हो गया। इस स्थिति का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि केन्द्र का शक्तिशाली बनाने के लिए और विधान में तुरन्त परिवर्तन करने का ठिए सम्पूर्ण देश में एक आन्दोलन सा उठ खड़ा हुआ। जॉज वाशिंगटन ने स्पष्ट शब्दों में कहा “एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक दिनों तक तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक किसी स्थान पर एक ऐसी सत्ता की स्थापना न करें जो इतनी शक्ति के साथ राज्य सरकारों, विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं।”

जॉर्ज वाशिंगटन का मत धीरे-धीरे जनता का मत हो गया और 1787 में कांग्रेस ने संघीय नियमावली का मसौदा तैयार करने तथा संघ की दृढ़ बनाने की दृष्टि से एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव पारित किया। फलस्वरूप मई, 1787 फिलाडेल्फिया में महान सम्मेलन हुआ जिसमें 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधि आए। केवल रोड द्वीप (Rhode Island) ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। सम्मेलन का सभापतित्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। प्रतिनिधियों ने सारी समस्या को बड़े अल्पे दल से मुलाना आरम्भ किया। उनका उद्देश्य एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार की स्थापना करना था जिसके साथ साथ राज्यों की भी अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्थापित रहे।

फिलाडेल्फिया सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि 1776 के संघीय ढांचे में सुधार मात्र से काम नहीं चलेगा वरन् एक पूर्णतः नवीन सांविधानिक ढांचा तैयार करना होगा जिसमें स्वशासित राज्यों और शक्तिशाली केन्द्र की शक्ति का उचित सामंजस्य होगा। लगभग 4 माह के बाद 17 सितम्बर, 1787 का सर्वसम्मति से एक प्रलेख (Document) बन पाया जिसमें नूतन शासन विधान स्वीकार किया गया। यह निश्चय किया गया कि इसे लागू करने के लिए 13 में से कम से कम 9 राज्यों का सम्मेलन उसे अलग अलग स्वीकार कर ले।

इसके बाद ही संविधान में की गयी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर राज्यों में गम्भीर मतभेद व्याप्त हो गया और 1787 के अन्त तक केवल 3 राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हो सकी। वास्तव में सम्पूर्ण देश दो दलों में बंट गया। एक दल के लोग संघ विरोधी (Anti-Federalists) थे। वे केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में नहीं थे और चाहते थे कि केन्द्रीय शासन स्वतन्त्र राज्यों का एक सिविल संगठन मात्र बना रहे। दूसरे दल के लोग संघ समर्थक (Federalists) थे जो केन्द्रीय सरकार का पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते थे। नये प्रस्तावित संविधान का बहुत से लोगों द्वारा दम आवाज पर भी विरोध किया गया कि उसमें अधिकार पत्र (Bill of Rights) की व्यवस्था नहीं की गयी थी और इस कारण लोगों की स्वतन्त्रता का मतलब पदा हो सकता था। मघात्मक शासन के समर्थक (Federalists) ने संविधान में अधिकार-पत्र (Bill of Rights) की बात न केवल मान ली बल्कि संविधान में प्रथम दम नये सभाघन करके उस लागू भी कर लिया। परिणाम यह निकला कि उन राज्यों ने जो अब प्रस्तावित संविधान का स्वीकार कर लिया जिन्होंने अब तक कोई निणय नहीं किया था। 21 जून, 1788 तक नये संविधान को राज्यों की आवश्यक संख्या द्वारा स्वीकृति दी दे गयी और तब संघ (Confederation) की कांग्रेस ने एक विधि द्वारा यह आदेश दिया कि नये संविधान के अनुसार निर्वाचन हो तथा नया सरकार 4 मार्च, 1789 से देश का शासन भार सम्भाले। अब निर्वाचन हुए, माउट के सभासद और कांग्रेस के

प्रतिनिधिमण चुने गए तथा जॉर्ज वाशिंगटन के राष्ट्रपतित्व में नयी सरकार का कार्यभार सम्भाला। इस प्रकार पुराना मघ या संघ (Confederation) समाप्त हो गया और नया मघ अस्तित्व में आया।

आज अमेरिका के संयुक्त राज्य में 50 राज्य सम्मिलित हैं जो उसी संविधान से बंधे हुए हैं जिसे सन् 1789 का संविधान कहा जाता है। अमेरिकावासी का अपने इस संविधान में बड़ा प्यार है।

अमेरिकन संविधान का स्वरूप अथवा उसकी विशेषताएँ

(Salient Features of the American Constitution)

(1) लिखित संविधान—अमेरिकन संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित और निश्चित संविधान (A Written and Inacted Constitution) है। यद्यपि इसमें संशोधन और परिवर्तन हाथ रहे हैं, तथापि सम्पूर्ण संविधान एक क्रमबद्ध विधान के रूप में है जिसे आधे घण्टे में पढ़ कर समाप्त किया जा सकता है।

यह एक छोटा प्रलेख है, जिसमें शासन के मूल सिद्धांत शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों और कार्यक्षेत्रों, नागरिकों के अधिकारों आदि का लिखित किया गया है। इसका यह आशय नहीं है कि संविधान का अलिखित अंग है ही नहीं। ब्रिटिश संविधान की भांति इसमें भी अनेक परम्पराओं और अभिसमयों का प्रवेश हुआ गया है। ये परम्पराएँ या अभिसमय उसी रूप में मान्य हैं जिस रूप में मूल संविधान। किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए दो बार से अधिक निर्वाचित न होना, मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था सीनेट की सीनेटोरिया (Senatorial Courtesy), दल पद्धति, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन आदि के सम्बन्ध में संविधान मौन है।

(2) संक्षिप्त संविधान—लिखित होने के नाते ही अमेरिकन संविधान अति संक्षिप्त भी है। इसमें केवल ७ अनुच्छेद हैं। कुल चार हजार शब्दों का यह संविधान दो बार पृष्ठों में छपा हुआ है और इसकाई भी आधे घण्टे मात्र में पढ़ सकता है। संविधान इतना संक्षिप्त इसलिए है कि इसमें आधारभूत सिद्धांतों (Fundamentals) का प्रतिपादन किया गया है और विस्तार की बातों का परम्परा व्यवस्था प्रशासनिक आज्ञाओं द्वारा निर्णीत किए जान के लिए छोड़ दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस एक 'स्ट्रेट जैकेट' (Strait Jacket) के रूप में तैयार नहीं किया था वरन् उन्होंने केवल उसका ढांचा तैयार किया था जिसे भावी मन्त्रिमन्त्रियों ने रतत मान देकर पूर्ण जीवन दिया है।

संविधान की इस संक्षिप्तता का प्रभाव हम बड़े दिशाओं में स्पष्ट दिखाई देता है—

(1) कानून व परम्पराओं दोनों से ही संवधानिक ढांचे का निष्पन्न। जिसमें परम्पराओं का बलवर कम तथा कानून का अधिक है।

(11) संविधान अनेक बातों के विषय में मौन है। उदाहरणार्थ, वकील, वज्र निमाण, कृषि, श्रम, शिक्षा आदि के सम्बन्ध में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(111) तीसरा प्रभाव संविधान के भारी विकास पर पड़ा है जो तीन रूपों में प्रकट हुआ है—(क) सक्षिप्तता के कारण संविधान का महत्व बढ़ गया है क्योंकि जिन विषयों पर यह मौन है उनके बारे में समय-समय पर दिये गये यायिक निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं और संविधान का विकास होता रहता है, (ख) इस सक्षिप्तता के फलस्वरूप निहित शक्तियाँ के सिद्धांत (Doctrine of Implied Powers) का उदय हो गया है एवम् (ग) इस सक्षिप्तता के कारण ही लाभदान की प्रणाली (Spoil System) का उदय हुआ है। इस प्रणाली का यद्यपि आज भी प्रचलन है कि तु इसका प्रभाव पहले के समान नहीं रहा है।

(12) इस सक्षिप्तता ने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने में मदद की है।

(3) निर्मित संविधान—यह एक पूर्णतया निर्मित संविधान है जिसकी रचना एक सभा द्वारा हुई थी जो इसी कार्य के लिये निश्चित रूप में फ़िलाडेलफ़िया में 1787 में चुनाई गई थी। निर्मित संविधानों में विकास का और विकसित संविधानों में निर्माण का कुछ न कुछ तत्त्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। अमेरिका के निर्मित संविधान में भी विकास के तत्त्व मौजूद हैं। एक निश्चित समय पर निर्मित होने के पश्चात् इस संविधान में समय और आवश्यकताओं के अनुसार विकास होता रहा है और एसी अनेक परम्परायें विकसित हुई हैं जिन्होंने संविधान के स्वरूप का निर्धारण किया है। यह विकास कांग्रेस के व्यवस्थापन, संविधान के संशोधन और यायिक निर्णयों के द्वारा भी हुआ है।

(4) कठोर संविधान—यह कठोर या जबर (Rigid) संविधान है जिनमें संशोधन आवश्यक विधि-निर्माण करने की प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड के विपरीत अमेरिका में विधि निर्माण करने वाले निकायों में और विधान में संशोधन करने वाले निकायों में बहुत कुछ अंतर है। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की एक विशिष्ट पद्धति है, जो जटिल और धीमी है। यही कारण है कि पिछले लगभग 180 वर्षों में संविधान में केवल 25 ही संशोधन हो पाये हैं।

संशोधन प्रक्रिया—संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधियाँ हैं, जिनमें (1) संशोधन प्रस्तावित किया जाता है एवं (2) प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाता है। पुष्टिकरण के उद्देश्य से संशोधन संवैधानिक रूप में मान्य होता है। इन दोनों विधियों का विशिष्ट निम्न प्रकार में है—

संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दो प्रकार में किया जा सकता है—

(1) कांग्रेस द्वारा संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, यदि ऐसा करना

मे पृथक 2 दो-तिहाई बहुमत उसकी आवश्यकता को स्वीकार करता हो।

(ख) दो तिहाई राज्या की व्यवस्थापिकायें भी कांग्रेस से सशोधन की प्रायना कर सकती हैं। ऐसा किये जाने पर कांग्रेस को इन सशोधनो का प्रस्ताव करने के लिये एक सम्मेलन बुलाना पड़ता है।

सशोधन किसी भी विधि से प्रस्तावित किय गये हों, वे माय उसी अवस्था में हो सकते हैं जबकि उन्हें निम्नलिखित विधियां में से किसी एक द्वारा पुष्टिकरण प्राप्त हो जाए—

(क) तीन चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकायें उनका पुष्टिकरण कर दें, अथवा।

(ख) इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया तीन-चौथाई राज्यों का सम्मेलन (Convention) उसका पुष्टिकरण कर दे।

स्पष्ट है कि संघीय सरकार और उप राज्य दोनों ही का संविधान के सशोधन में हाथ रहता है और यह सशोधन-रीति सरल भी नहीं है।

पुष्टिकरण सम्बंधी समय की सीमायें—कांग्रेस सशोधनो के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय सीमा भी निश्चित कर सकती है कि अमुक अवधि तक यह पूरा हो जावे। वर्तमान समय में प्रत्येक दशा में 7 साल की अवधि निश्चित कर दी गई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है। यदि सात वर्षों तक कोई सशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सके तो वह विफल हो जाता है।

सशोधन की सीमा—संविधान की प्रथम धारा की 9 वीं उपधारा के पहिले के चौथे उपबन्धों पर किसी संवधानिक सशोधन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और इस सम्बंध में भी कोई सशोधन राज्य की अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य किसी भी विषय पर न तो विरुद्ध राय देगा और न दो राज्य मिलकर ही कोई बात तय करेंगे—जब तक कि उन राज्यों की धारा सभायें उनके सम्बंध में स्वीकृति न दे दें।

(1) संविधान में सशोधन की इस प्रणाली के आधारों पर एक व्यक्ति भी सशोधन में रुकावट डाल सकता है। उदाहरण के लिये, यदि सीनेट में 100 सदस्यों में से 85 उपस्थित हों, जिसमें से 56 सशोधन के पक्ष में मत दें और 29 उनके विरोध में मत प्रकट करें तो वह सशोधन सीनेट में दो-तिहाई मध्या पक्ष में न होने से स्वीकार नहीं समझा जा सकता, चाहे प्रतिनिधि सभा में वह दो तिहाई मत से पास हो चुका हो।

(ii) सशोधन प्रणाली अत्यंत मंथर है। यह बड़ी ढीली और लम्बी है।

(iii) यह बहुमत नामन की निरनुशता का उदाहरण है। सशोधन के प्रस्ताव के सम्बंध में 34 सीनेटर दोनों सदनों के बहुमत को रद्द कर सकते हैं।

(11) संविधान अनेक बातों के विषय में मौन है। उदाहरणार्थ, वकील, वज्र निमाण, ऋषि, श्रम, शिक्षा आदि के सम्बन्ध में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(111) तीसरा प्रभाव संविधान के भारी विकास पर पड़ा है जो तीन रूपों में प्रकट हुआ है—(क) सक्षिप्तता के कारण संविधान का महत्व बढ़ गया है क्योंकि जिन विषयों पर यह मौन है उनके बारे में समय-समय पर दिये गये 'यायिक निर्णय' संविधान के अंग बन जाते हैं और संविधान का विकास होता रहता है, (ख) इस सक्षिप्तता के फलस्वरूप निहित शक्तियाँ के सिद्धांत (Doctrine of Implied Powers) का उदय हुआ है एवम् (ग) इस सक्षिप्तता के कारण ही लाभदान की प्रणाली (Spoil System) का उदय हुआ है। इस प्रणाली का यद्यपि आज भी प्रचलन है किंतु इसका प्रभाव पहले के समान नहीं रहा है।

(1V) इस सक्षिप्तता ने संविधान का स्थायित्व प्रदान करने में मदद की है।

(3) निर्मित संविधान—यह एक पूर्णतया निर्मित संविधान है जिसकी रचना एक सभा द्वारा हुई थी जो इसी कार्य के लिये निश्चित रूप से फिलाडेलफिया में 1787 में बसाई गई थी। निर्मित संविधानों में विकास का और विकसित संविधानों में निर्माण का कुछ न कुछ तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। अमेरिका के निर्मित संविधान में भी विकास के तत्व मौजूद हैं। एक निश्चित समय पर निर्मित होने के पश्चात् इस संविधान में समय और आवश्यकताओं के अनुसार विकास होता रहा है और एनी अनेक परम्परायें विकसित हुई हैं जिन्होंने संविधान के स्वरूप का निर्धारण किया है। यह विकास कांग्रेस के व्यवस्थापन, संविधान के संशोधन और 'यायिक निर्णयों' के द्वारा भी हुआ है।

(4) कठोर संविधान—यह कठोर या अचल (Rigid) संविधान है जिसमें संशोधन साधारण विधि-निमाण करने की प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में होते हैं। इंग्लैंड के विपरीत अमेरिका में विधि निर्माण करने वाले निकायों में और विधान में संशोधन करने वाले निकायों में बहुत कुछ अंतर है। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की एक विशेष प्रवृत्ति है, जो जटिल और धीमी है। यही कारण है कि पिछले लगभग 180 वर्षों में संविधान में केवल 25 ही संशोधन हुए हैं।

संशोधन प्रक्रिया—संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधियाँ हैं, जिनमें (1) संशोधन प्रस्तावित बिना जात है एवं (2) प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाता है। पुष्टिकरण के बाद ही संशोधन संवैधानिक रूप से मान्य होता है। इन दोनों विधियों का विवरण निम्न प्रकार में है—

संविधान के संशोधन का प्रस्ताव दो प्रकार में किया जा सकता है—

(क) कांग्रेस स्वयं ही संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, यदि दोनों सदनों

में पृथक 2 दो-तिहाई बहुमत उसकी आवश्यकता का स्वीकार करता हो।

(ख) दो तिहाई राज्यों की व्यवस्थापिकाओं भी कांग्रेस से संशोधन की प्राप्ति कर सकती हैं। ऐसा नियम जान पर कांग्रेस को इन संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिये एक सम्मेलन बुलाना पड़ता है।

संशोधन किसी भी विधि से प्रस्तावित नियम हो, व माय उसी अवस्था में हो सकते हैं जबकि उन्हें निम्नलिखित विधियाँ में से किसी एक द्वारा पुष्टिकरण प्राप्त हो जाए—

(क) तीन-चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाओं उनका पुष्टिकरण कर दें, अथवा।

(ख) इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया तीन चौथाई राज्यों का सम्मेलन (Convention) उसका पुष्टिकरण कर दे।

स्पष्ट है कि संघीय सरकार और उप राज्य दोनों ही का संविधान के संशोधन में हाथ रहता है और यह संशोधन रीति सरल भी नहीं है।

पुष्टिकरण सम्बन्धी समय की सीमाएँ—कांग्रेस संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय सीमा भी निर्दिष्ट कर सकती है कि अमुक अवधि तक यह पूर्ण हो जाव। वर्तमान समय में प्रत्येक दशा में 7 साल की अवधि निर्दिष्ट कर दी गई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय न भी मान लिया है। यदि सात वर्षों तक कोई संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सके तो वह विफल हो जाता है।

संशोधन की सीमा—संविधान की प्रथम धारा की 9 वीं उपधारा के पहिले व चौथे उपबन्धों पर किसी संवधानिक संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। संयुक्तराज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में दो प्रतिनिधि भजने का अधिकार है और इस सम्बन्ध में भी कोई संशोधन राज्य की अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी राज्य किसी भी विषय पर न तो विरुद्ध राय देगा और न दो राज्य मिलकर ही कोई बात तय करेंगे—जब तक कि उन राज्यों की धारा सभाये उनके सम्बन्ध में स्वीकृति न दे दे।

(1) संविधान में संशोधन की इस प्रणाली के आधारों पर एक व्यक्ति भी संशोधन में सकावट डाल सकता है। उदाहरण के लिये, यदि सीनेट में 100 सदस्यों में से 85 उपस्थित हो, जिसमें से 56 संशोधन के पक्ष में मत दें और 29 उसके विरोध में मत प्रकट करें तो वह संशोधन सीनेट में दो-तिहाई मर्यादा पक्ष में न होने से स्वीकार नहीं समझा जा सकता, चाहे प्रतिनिधि सभा में वह दो तिहाई मत से पास हो चुका हो।

(ii) संशोधन प्रणाली जल्द मंजूर है। यह बड़ी टूटी और लम्बी है।

(iii) यह बहुमत धामन की निरकुशता का उदाहरण है। संशोधन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 34 सीनेटर दोनों सदनों के बहुमत को रद्द कर सकते हैं।

(7) प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य—अमेरिकन संविधान की एक अन्य विशेषता है—प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य (Representative Republic) का होना। प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य में जनता प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, देश के बड़े आकार के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं ले सकती। गणराज्य के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह दोनों ही बातें विद्यमान हैं। वहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो निश्चित अवधि तक शासन का संचालन करते हैं, और साथ ही राष्ट्रपति भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यों की शासन प्रणाली भी प्रतिनिधिमूलक और गणतन्त्रात्मक है। यद्यपि राज्यों के अपने अलग संविधान हैं, किन्तु मधीय संविधान और राज्यों का गणतन्त्रात्मक शासन की गारंटी दी गई है। संविधान में प्रत्येक राज्य को विदेशी आक्रमण, सुरक्षा तथा राज्य के उचित प्राधिकारी द्वारा भाग दिये जान पर जातिरिक्त विद्रोह के समय सहायता की गारंटी दी गई है।

(8) राष्ट्रीय स्वरूप—संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सभी दृष्टिकोणों से सघातमक है।

प्रारम्भ में अमेरिकन संघ में तेरह राज्य थे, आज ५० हैं जो म्याई रूप से संघ में सम्मिलित हैं। सघातमक पद्धति के जननार के द्वीय और राज्यों की शक्तियां संविधान में निर्धारित की गई हैं। साधारणतः यह सिद्धांत अपनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय मधीय सरकार का और स्थानीय महत्व के विषय राज्यों की सरकार को सौंप गये हैं, जबकि शक्तियां राज्य के पास हैं, यद्यपि आधुनिक काल में मधीय सरकार की शक्तियां अनेक कारणों से बढ़ती ही जा रही हैं। शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है। व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन सीनेट में संघ के सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी मशावरन वैध नहीं समझा जायेगा। सघातम प्रक्रिया का राज्यों में प्रस्तावना करने में और उसके पुष्टीकरण करने में पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। अन्य में मधीय संविधान के अनुसार अमेरिका का संविधान लिखित एवं दुष्परिवर्तनीय है।

(9) न्यायिक सर्वोच्चता—अमेरिका के संविधान की एक अन्यतम विशेषता न्यायिक प्रभुता (Judicial Supremacy) का सिद्धांत है।

प्रथम, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के नियमों के तहत में सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण अन्तिम होता है। द्वितीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review) का अधिकार है, जिसके द्वारा वह विधान मंडल के बनाये गये किसी भी ऐसे कानून को जो सांविधानिक नियमों के विरुद्ध हैं और नागरिकों की स्वतन्त्रता

तथा उनके अधिकारों पर नुठाराघात करता हो, जबैय घोषित कर सकता है और उन्हें देश में लाशू होने से रोक सकता है। इस प्रकार का कार्ड कानून कांग्रेस ने ही नहीं चला राज्या के विधान मंडल ने भी बनाया है या कार्यपालिका ने लाशू किया है, तो भी उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रान और सोवियत मध्य में न्यायालय का न्यायिक पुनरावगमन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इन देशों में विधान-मण्डल की सर्वोच्चता (Legislative Supremacy) के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

(10) मौलिक अधिकारों का समावेश—अमेरिकन संविधान भारतीय संविधान की भाँति ही जनता के अनेक मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है। जनता को भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक एकत्र हान तथा कण्टो के निवारण के लिए सरकार को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। कोई सरकार बिज ऑफ अटैण्डर (Bill of Attainder) का पाम नहीं कर सकती जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का बिना मुकदमा चलाये फाँसी दी जा सके। किसी भी व्यक्ति को न तो मनमाने ढंग से पकड़ा हो जा सकता है और न कद ही किया जा सकता है। युद्ध अथवा विद्रोह के समय के अतिरिक्त कभी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus) में इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अभियुक्त यह माग कर सकता है कि उस पर निष्पक्ष जूरी द्वारा सावजनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाये। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक जमानत नहीं माँगी जा सकती और न ही कानूनी कायवाही की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति का जीवन, उसकी स्वतंत्रता और सम्पत्ति छीनी जा सकती है। मूल वश, रंग, लिंग अथवा दासत्व की पूछ दशाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को मतधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का आन जान और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है तथा समान कानूनी सारक्षण प्राप्त है। यह भी व्यवस्था है कि सरकार बिना उचित मुआवजा दिय किसी नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति हस्तागत नहीं कर सकती। जनता का सस्त्र रखने और लेकर चलने का अधिकार है।

संविधान के एक और संशोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की गणना करने का यह अब कदापि नहीं हो सकता कि जनता ने संप्र अधिकारों का परित्याग कर दिया है। वास्तव में संप्र अधिकार जनता में निहित है और उनकी किसी प्रकार भी अप्रतिष्ठा नहीं की जा सकती।

सुरक्षा की दृष्टि से संविधान में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनेक ऐसे उपबंध हैं जो नागरिक अधिकारों पर सीमाएँ लगाते हैं। युद्ध के समय या शांति और सुव्यवस्था के लिये उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(11) शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवम् सातुलन की प्रणाली—अमेरिकन संविधान की एक प्रमुखतम विशेषता शक्ति का पृथक्करण और नियंत्रण व सातुलन प्रणाली है। संविधान के निर्माता लोक एवम् मानदेस्क्यू के राजनीतिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। वे इस विचार से महमत थे कि व्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिये

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ का पृथक्करण किया जाए। सरकार का ये तीनों जग परस्पर स्वतन्त्र हो ताकि वे एक दूसरे की निरबुद्धता का शक सकें अथवा परस्पर नियंत्रण करते हुए सरकार पर सन्तुलन स्थापित कर सकें। अतः शक्ति पृथक्करण और परस्पर नियंत्रण तथा सन्तुलन अमेरिकन शासन-व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन गई और सविधान निर्माताओं ने अमेरिकन सविधान में शक्ति-पृथक्करण सम्बन्धी व्यवस्था कर दी। तदनुसार कांग्रेस विधि निर्माण करती है, राष्ट्रपति विधि लागू करता है और सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों की शब्दानुसंगता का परीक्षण करता है। कोई भी विभाग दूसरे विभाग के कार्यों का हथिया नहीं सकता। एक विभाग अपनी शक्ति को दूसरे विभाग को प्रत्यायोजित (Delegate) अथवा हस्तांतरित (Transfer) नहीं कर सकता। सविधान के संरक्षक के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायालय सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि उपयुक्त मात्रा बनी रहे।

अमेरिकन सविधान में शासन के तीनों विभागों को केवल अलग-अलग ही नहीं किया गया है, अपितु उन्हें जबकि से अधिक एक दूसरे को स्वतन्त्र करने की व्यवस्था भी की गई है। तीनों विभाग अपने-अपने क्षेत्र में सम्प्रभु एवं स्वतन्त्र हैं तथा एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। राष्ट्रपति जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है और कांग्रेस उस-उसके कार्यकाल की अवधि में साधारणतया नहीं हटा सकती। कांग्रेस के पास केवल महाभियोग (Impeachment) का हथियार है जिसे काम में लेना अत्यन्त दुष्कर है। इसी प्रकार कांग्रेस की स्थिति भी स्वतन्त्र है क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। न्यायपालिका की भी स्वतन्त्रता की यही स्थिति है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहाय्य कांग्रेस निश्चित करती है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परन्तु एक बार पदातीन हो जाने के बाद उन न्यायाधीशों का महाभियोग की कठिन प्रक्रिया का सहारा लिये बिना पदच्युत नहीं किया जा सकता।

नियंत्रण व सन्तुलन प्रणाली—यद्यपि अमेरिकन सविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों विभागों को पृथक् कर दिया, फिर भी उन्हें यह विदित था कि तीनों विभागों के मध्य परस्पर सम्बन्ध तथा सम्पर्क स्थापित करना भी सकल शासन के लिए परमावश्यक है। अतः उपयुक्त शक्ति विभाजन को व्यावहारिक बनाने के लिए उन्होंने सविधान में नियंत्रण और सन्तुलन प्रणाली (System of Checks and Balances) की व्यवस्था की। इसके अनुसार शासन के तीनों अंगों की शक्तियों के लिये ऐसा प्रबंध कर दिया गया कि वे एक दूसरे पर इस तरह नियंत्रण बनाये रखें जिससे शक्ति का सन्तुलन बना रहे। यदि कोई विभाग कभी अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान खो बैठे तो दूसरा विभाग उसे सचेत कर कार्य करने के लिए मजबूर कर दे।

अमेरिकन सविधान में नियंत्रण और सन्तुलन की इस प्रणाली को कुछ उदाहरणों द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्रपति संसार का

सबसे अधिक शक्तिशाली कार्यपालक कहा जाता है। किन्तु उनकी समावृत्ति निरकुशता पर नियन्त्रण रखने के लिए कांग्रेस का कुछ अधिकार दिये गये हैं। कांग्रेस प्रतिवष देश का बजट स्वीकार करती है और राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह उस स्वीकृत बजट के अनुसार राष्ट्र को धन का उपयोग करे। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष और परराष्ट्र नीति का संचालक होने के नाते कभी भी देश का युद्ध में जोर नहीं देता है, किन्तु संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा की गयी युद्ध की घोषणा का कांग्रेस द्वारा पुष्टिकरण होना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा की गयी संधि भी तभी मान्य होती है जब सीनेट या तिहाई बहुमत ने उनकी पुष्टि करदे। अतः में कांग्रेस का यह भी अधिकार है कि वह शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले राष्ट्रपति का महाभियोग की कार्यवाही द्वारा हटा दे।

कहा कांग्रेस निरकुश न बन जाए, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों में भी विशेष शक्तियाँ सौंपी गयी हैं। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बन सकते हैं जब उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि यह व्यवस्था है कि कांग्रेस अस्वीकृत विधेयक का पुनः दो तिहाई बहुमत से पारित करदे तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी पड़ेगी, तथापि यह एक अति कठिन प्रक्रिया है। विधेयक को दुबारा इतने प्रबल बहुमत से पारित करना टेढ़ी खीर है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को अपने उन सभी विधेयकों की स्वीकृति के लिए पूर्णतः राष्ट्रपति पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें वह अपने अधिवेशन के अंतिम १० दिनों में पारित करनी है।

व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निरकुश न हो जायें, इसके लिए न्यायपालिका का नियन्त्रण है। सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति बड़ा जबरदस्त हथियार है। न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सम्पादिका पर महाभियोग की कार्यवाही की व्यवस्था है।

स्पष्ट है कि अमेरिकन संविधान शक्ति पंचाकरण और नियन्त्रण एवं संतुलन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है।

संवैधानिक विकास की रीतियाँ

(Process of Constitutional Development)

अमेरिका का राज का संविधान सिर्फ 1787 ई० का लिखित प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि समय और परिस्थिति की मार के अनुसार विभिन्न साधनों के आधार पर यह प्राप्त विकसित हो चुका है। मुनरो के शब्दों में "1787 ई० के निमाताओं ने उस नवनयी भाषा मात्र उठायी थी, जिसमें पिडकी, दरवाजे व सम्म इत्यादि का निमाण उनकी मस्तान न किया है।" हम देखना चाहिए कि संविधान में विकास और परिवर्तन के कौन से प्रमुख साधन हैं—

(1) न्यायिक व्याख्याएं (Judicial Interpretations)—संविधान का विकास करने में न्यायापालिका के निर्णयों का योग देखते हुए व्याख्याकारों ने कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय अविरल गति से चलने वाली एक संवैधानिक परिपक्वता (Continuous Constitutional Convention) है।” वस्तुतः संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने का कार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है और आज उसके निर्णय अंतिम तथा सार्वभौम हैं। व्याख्याओं ने संविधान के मूल लेखों की स्वतंत्र रूप में व्याख्या करके और उन व्याख्याओं का अपनी गण्टीवली में प्रयुक्त करके यह सब कुछ किया है। उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालय ने ही संविधान की धारा 1 को परिभाषित करके पूर्ण शक्तिपूर्ण राष्ट्रपति को प्रदान की है। इसी प्रकार उसने वाणिज्य सभा, सार्वजनिक परिवहन आदि सेवाओं की उदार व्याख्याएं करके कांग्रेस के संवैधानिक अधिकारों का काफी व्यापक बनाया है।

(2) प्रशासकीय निर्णय (Administrative Decisions)—न्यायिक निर्णयों के अतिरिक्त प्रशासकीय निर्णयों ने भी अमेरिकन संविधान का विकास में काफी योग दिया है। विभिन्न विभागों और प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा संविधान की धाराओं के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लिए जाने हैं जिन्हें प्रायः न्यायिक मान्यता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटन की भांति अमेरिका में भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन (Delegated Legislation) की प्रथा प्रभावी है। कांग्रेस कानून का सिद्धान्त और ढांचा तैयार कर देती है तथा प्रशासकीय क्षेत्रों को यह अधिकार देती है कि वह कानून की कमियाँ की पूर्ति विनियमों एवं आदेशों द्वारा करे। मुनरो ने इन नियमों और उपनियमों का “संविधान की छाया” कहा है।

(3) संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendment)—समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों द्वारा मौलिक संविधान का रूप बदलता और विकसित होता रहा है। अब तक हुए 25 संशोधनों ने संविधान का बहुत कुछ विस्तार कर दिया है। उदाहरणार्थ, संशोधन के पत्रस्वरूप ही मीनट के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति का प्रावधान हुआ है, नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया है और महिलाओं का मतधिकार मिला है।

राजनीतिकों और नागरिकों की व्याख्याएं (Interpretation by Politicians and Citizens)—संविधान के विकास में राजनीतिज्ञों और नागरिकों की व्याख्याओं का भी भाग रहा है। उदाहरणार्थ राजनीतिक दलों और लाखों अमेरिकन मतदाताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का बदल दिया है। आज राजनीतिक दल अमेरिकन शासन व्यवस्था के अनेक अंग बन चुके हैं।

संवैधानिक अभिसमय (Conventions)—ब्रिटन की भांति ही अमेरिका में भी संविधान की मौलिक रूपरेखा में विविध रीतियाँ और परम्पराएँ ने अपना

परिवर्तन कर दिया है कि बिना उ हें समये 'संविधान' को भली प्रकार नहीं समया जा सकता। कुछ प्रमुख अमेरिकन संवैधानिक अभिनमय निम्नलिखित हैं--

(i) संविधान में दल प्रणाली की चर्चा नहीं है कि तु व्यवहार में दल प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण बन गई है कि उसके अभाव में अमेरिकन शासन व्यवस्था का पालन ही सम्भव नहीं है।

(ii) संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति है, किन्तु प्रयाशों ने उस प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है।

(iii) मंत्री मण्डलीय व्यवस्था भी प्रथा व्यवस्था परम्परा का ही परिणाम है।

(iv) प्रतिनिधि सदन की प्रनिया, स्पीकर की शक्तियाँ, महत्व आदि भी प्रथाओं पर आधारित हैं।

(v) अभिनमय द्वारा ही यह नियम बन गया है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हों।

(vi) धन विधयका का प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित होना भी प्रथा पर ही आधारित है।

(vii) संचालन समिति (Steering Committee) बहुमत के पक्ष में लीडर तथा काउंस (Causes) का विकास भी अभिनमयों द्वारा ही हुआ है। यह सही है कि संवैधानिक अभिनमयों द्वारा शासन की वास्तविक कार्य पद्धति व्यवहार में आई है।

संविधानों की व्याख्या (Statutory Elaboration) -- संविधान निमाताओं ने केवल संविधान की रूपरेखा का निर्माण किया था। उन्हें विस्तृत करने का कार्य सरकार के लिये छोड़ दिया था। फरस्वरूप बाद के वर्षों में सरकारी व्याख्याओं ने संविधान को कुछ से कुछ बना दिया है। आज हम संविधान के पक्षों में अमेरिकन शासन प्रणाली का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। असली बात तो संविधानों की पुस्तक और प्रसामकीय नियमावली के बड़े बड़े पोथों में मिलती है। उदाहरणार्थ, संविधान कांग्रेस की समितियों के वारे में मौन है और आधुनिक विधि निर्माण प्रनिया की विभिन्न बातों के वारे में भी कुछ नहीं कहता। इन सबकी व्यवस्था कांग्रेस द्वारा ही की जाती है। कांग्रेस ने संविधानों द्वारा संविधान का नतीजा विकास किया है और वीयड के सन्धि में "सर्वोच्च न्यायालय भी यह घोषणा कर चुका है कि वह कांग्रेस द्वारा की गई व्याख्याओं का बहुत जादर करेगा तथा उनका तभी अभाव ठहरायेगा जब वे स्पष्ट रूप से बहुत हैं।

2

अमेरिका की सघ व्यवस्था (THE AMERICAN FEDERAL SYSTEM)

‘यह (संयुक्त राज्य अमेरिका) सदा जसुण
बने रहने वाले राज्यों का सघ है ।’

—बियर्ड

अमेरिकन संविधान एक ऐसा संघीय संविधान है जिसका अनुकरण अन्य संघीय संविधान वाले देशों ने किया है और जिसके आधार पर संघीय संविधानों के गुणों तथा दोषों का विवेचन किया जाता है ।

संघीय व्यवस्था अपनाय जाने के कारण

प्रथम, वर्तमान संविधान के निर्माण के पहिले से ही अमेरिका महाद्वीप में अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में विद्यमान थे जिनमें अपने-पक्षक अस्तित्व के प्रति मोह था । लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का तकाजा था कि विविध राज्य अलग-अलग रहते हुए एक ही । ऐसा न होने पर उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था । चूंकि ये दोनों बातें सघात्मक शासन-व्यवस्था में ही पूरी हो सकती थी, अतः अमेरिकन संविधान निर्माताओं और अमेरिका की जनता ने यही उचित समझा कि संघीय व्यवस्था अपनायी जाये ।

द्वितीय, उस समय आवश्यक की भांति जावागमन व स-दसबाहन के साधन विकसित न थे । इस परिस्थिति में, अपने देश के क्षेत्रफ़्त की विस्तारता के कारण, अमेरिकावासियों से संघीय व्यवस्था का अपना आवश्यक समझा ।

तृतीय, तत्कालीन राजनीतिक दल स्थानीय और विकेंद्रोक्त अधिक थे, राष्ट्रीय व केन्द्रीय न थे । अतः वे केन्द्र की अपेक्षा राज्यों को शक्तिशाली बनाने रखने के पक्ष में थे । अतः यह स्वाभाविक था कि देश की शासन व्यवस्था का रूप सघात्मक हो ।

चौथे, संविधान निर्माता व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रबल समर्थक थे और सघात्मक व्यवस्था ही इनकी रक्षा का उपाय ।

क्याकि यह राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करके साहसी सुरक्षा प्रदान करता है।

उपरोक्त सभी कारणों का यह भी मलित प्रभाव हुआ कि अमेरिकन जनता ने सम्पूर्ण देश के लिए सघातमक शासन व्यवस्था को ही उचित समझा जा निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। प्रारम्भ में जहाँ केवल 13 राज्य सघातमक बहा अब 51 राज्य हो गये हैं और व सभी समान अधिकारों का उपभोग करते हैं।

अमेरिका की संघीय व्यवस्था के आवश्यक तत्व

(Essentials of American Federal System)

संघीय शासन व्यवस्था वह है जिसमें यह स्वतंत्र राज्य मिलकर, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नव सरकार की स्थापना करते हैं। व समान हित वाले विषयों को एक केन्द्रीय सत्ता के सुपुर्न कर देते हैं जिस पर सम्पूर्ण देश के शासन की जिम्मेदारी होती है। इस केन्द्रीय या संघीय सरकार कहते हैं। इस तरह संघीय व्यवस्था में द्वय शासन होता है—एक केन्द्रीय शासन और दूसरा राज्यों या प्रांतों का शासन। दोनों ही की अलग अलग शासन व्यवस्था होती है। प्रायः प्रत्येक नागरिक की भी दो प्रकार की भक्ति होती है—एक संघीय शासन के प्रति और दूसरी राज्य सरकार के प्रति। इसके अतिरिक्त संविधान की सर्वोपरिता होती है। राज्य और सघातमक दोनों ही इस संविधान का सर्वोच्च मानते हैं जिसके अंतर्गत सघातमक की रचना हुई है। सघातमक की अंतिम आवश्यकता एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है जो सघातमक और राज्य सरकारों के बीच उठ खड़ा होने वाले विवादों का निणय कर सके। अन्त में फाइनर (Fetter) के शब्दों में 'सघातमक वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग एक केन्द्रीय सत्ता में, जो स्वयं स्थानीय क्षेत्रों के स्वच्छिन्न सम्मिलन में निर्मित होती है। इन दोनों में से किसी को दूसरे के अधिकारों और शक्ति का अपहरण करने का अधिकार नहीं होता।' अमेरिकन शासन-व्यवस्था में सघातमक संविधान के ये सभी लक्षण उपस्थित हैं।

राज्यों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य

अमेरिका महाद्वीप में वनमान संविधान बनने से पहले अनेक उपनिवेश विद्यमान थे। सुरक्षा की दृष्टि से व सघातमक रूप में एक हाकर भी अपन पथक अस्तित्व का बनाय रखना चाहते थे। फलस्वरूप अनेक राज्य का जो सामंजस्य उनमें आज भी राज्यों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता नामक द्वय पूर्ण रूप से विद्यमान है।

द्वय शासन तथा शक्तियों का वितरण

संघीय व्यवस्था के अनुरूप अनेक राज्य अमेरिका में दो प्रकार की सरकारें हैं—सघातमक और राज्य सरकार। संविधान एक स्वतंत्र संघीय संविधान है क्योंकि इसका सघातमक स्वरूप समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी

राज्य के अस्तित्व को भी नहीं मिटाया जा सकता। इसके अतिरिक्त दोनों सरकारों के पथक सामान-यन्त्र हैं। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, केवल तब यह है कि सरकार का स्वरूप गणतन्त्रात्मक हो और राज्य का संविधान सघीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल हो। पुनश्च, दाना सरकारें अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर नहीं, बल्कि संविधान पर आश्रित हैं।

सघीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति वितरण की समुचित व्यवस्था है जिसमें सघीय सरकार का पद अधिक महत्वपूर्ण और शक्ति सम्पन्न है। संविधान द्वारा शक्तियाँ का विभाजन निम्नलिखित आधार पर हुआ है—(i) सघ सरकार की अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्पष्ट रूप से संविधान में दी गयी हैं, (ii) सघ सरकार को कुछ निहित शक्तियाँ (Implied Powers) भी प्राप्त हैं, (iii) कुछ शक्तियाँ राज्यों के लिए आरक्षित (Reserved) हैं, (iv) कुछ शक्तियाँ समवर्ती हैं, अर्थात् उनका प्रयोग सघीय एवं राज्य सरकारें दोनों ही कर सकती हैं, (v) कुछ शक्तियों की मनाही सघ सरकार के लिए की गयी है, एवं (vi) कुछ शक्तियों की मनाही राज्य सरकारों के लिए की गई है।

शक्तियों के उपरोक्त वितरण में गणना तथा अवशेष के सिद्धांत (Principle of Enumeration and Residuum) को काम में लाया गया है। केन्द्रीय सरकार के अधिनार निश्चिन कर दिये गये हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ विभिन्न राज्यों को प्राप्त हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय सघीय सरकार के कार्यक्षेत्र में ही रखे गये हैं क्योंकि उन पर सम्पूर्ण दब के लिए समान नीति आवश्यक होती है।

सघ और राज्यों में मतभेद

संविधान और उनके अन्तर्गत बनाये गये कानून, मयुक्त राज्य अमेरिका की सत्ता के आधीन की गयी अथवा की जान वाली मधियाँ पूरा राज्य के सर्वोच्च कानून हैं। यदि कभी सघ और राज्यों के बीच किसी प्रश्न पर कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उसका अंतिम निणय सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसी समय किसी शक्ति अथवा अधिकार के सम्बन्ध में मतभेद उपस्थित हो जान पर वह शक्ति उस समय तक राज्य की होती है जिस समय तक यह निश्चिन नहीं हो जाता कि उस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार राज्य का नहीं है अथवा उस पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार है।

दोहरी नागरिकता

संयुक्त राज्य अमेरिका के सघ की स्थापना के बाद यद्यपि राज्यों के निवासी सघ के नागरिक बन गये, तथापि उनकी अपने अपने राज्य की नागरिकता का भी लोप नहीं किया गया, इस प्रकार दोहरी नागरिकता का उदय हुआ एवं सघ की ओर दूसरी राज्य की। आज अमेरिका के निवासी राज्यों के भी नागरिक हैं और सघ के भी।

संविधान की सर्वोपरिता

संविधान की छठी धारा की दूसरी उप धारा में स्पष्ट रूप से लिखा

सर्जोपरितु प्रतिष्ठित कर दी है। जब कभी मध्य सरकार के जयवा किसी उप राज्य के कानून का संविधान से विरोध रखा जाता है, तो संविधान की विधि होती है क्योंकि इस विरोध में सर्वोच्च न्यायालय का निष्पत्ति अंतिम होता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान ही मध्य सरकार तथा राज्य सरकारों की शक्ति का स्रोत है। यही शासन शक्ति का विभाजन करता है। जन शक्तियों के अतिरिक्त का अर्थ संविधान पर अतिरिक्त है। संविधान की व्यवस्था मध्य सरकार और राज्य सरकारों के लिये पञ्जीय वस्तु है। ये संविधान का परिपालन पूरी तरह से होता है या नहीं, यह देखने के लिये ही न्यायपालिका का उद्देश्य सम्पूर्ण का कार्य सारा गया है। संविधान की पवित्रता बनाय रखने के लिये संविधान की शक्ति का भी बड़ा कठोर रखा गया है।

स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका

संविधान की धारा 3 (अ) के अनुसार संयुक्त राज्य की न्याय शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और समय समय पर कायम द्वारा स्थापित न्यायालयों को सौंप दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और उसका अंतिम निर्णय करता है। संविधान के प्रतिकूल समझने पर वह किसी भी कानूनी कार्य जयवा आदेश को अवधानिक ठहरा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही इस विषय में कोई कार्य नहीं करता। वह अपना कार्य तभी करता है जबकि उसके लिये कोई पक्ष उसके समक्ष आवेदन करे।

अथ सहायक तत्व

यह अथ शीघ्र तत्व ही अमरिका की राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र का निर्माण करने वाली इकाइयों को उचित महत्व देने के लिये प्रायः दो व्यवस्थाओं का अनुसरण किया जाता है— प्रथम व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है एवं द्वितीय, राष्ट्र का निर्माण करने वाली इकाइया का संविधान के संशोधन में उचित भाग दिया जाता है। अमरिका की राष्ट्रीय व्यवस्था में ये दोनों ही व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं। कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में सभी राज्यों को अपने दो दो प्रतिनिधि नेशन का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वे अपने दो तिहाई बहुमत में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। साथ ही कोई भी संशोधन पारित भी तभी समझा जाता है जबकि राज्यों की 3/4 संख्या उसकी पुष्टि करे।

एंड्रॉ लेव्हेन के शब्दों में हम दोहरा सकते हैं कि अमरिकन राष्ट्रीय व्यवस्था एक “आदर्श राष्ट्रीय व्यवस्था” (A True Federal Model) है।

अमेरिकन राष्ट्रीय व्यवस्था तथा निहित शक्तियों का सिद्धान्त
(The American Federal System and the Doctrine of Implied Powers)

सिद्धान्त का उद्देश्य

संयुक्त राज्य अमरिका का संविधान अत्यन्त शक्तिशाली है। इस विधान की

एक माटी रूप रेखा मात्र ही दी गई है। इसके विस्तार को समयानुकूल एवं आवश्यकतानुसार करने के लिए छोड़ दिया गया है। सघीय सरकार की शक्तियां निश्चित रूप से वर्णित और स्थिर की हुई हैं। परन्तु इन शक्तियों की सूची बड़ी सामान्य है। उसमें ऐसी विभिन्न शक्तियां की कोई चर्चा नहीं है जिनका प्रयोग किये बिना सघ अपनी उन शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह नहीं कर सकता, जिनकी चर्चा सघीय सूची में है। इन स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि समय समय पर संविधान में प्रदत्त अपनी मुख्य शक्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक अन्य शक्तियों का भी सघीय सरकार अपने हाथ में इस आधार पर लेती गई कि वे शक्तियां भी संविधान में वर्णित मूल शक्तियों में निहित हैं। इससे अमेरिका में उस सिद्धान्त का उदय हुआ, जिसे हम निहित शक्तियों के सिद्धान्त (Doctrine of Implied Powers) के नाम से जानते हैं। इसका उदय एक परम्परा के रूप में हुआ है जिसे आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय के निष्पत्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। इस तरह वह अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया।

निहित शक्तियों का अनिप्राय और संविधान के

विकास में उनका योगदान

सर्वोच्च न्यायालय के निष्पत्ति द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस को ऐसे समस्त कानूनों के निर्माण की शक्ति दी है जो संवैधानिक उपबन्धा के अनुसार कांग्रेस की शक्तियों का, तथा गामन और विभागों की शक्तियों का कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और उचित हैं। इस प्रकार निहित शक्तियों का अभिप्राय उन शक्तियों से हुआ जो सघीय सरकार की मूल शक्तियों का कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उनमें निहित मानी जाएं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सघीय सरकार की इन निहित शक्तियों का रूप कि ही मूल शक्तियों का नहीं है बल्कि ये तो वे ही शक्तियां हैं जो मौलिक शक्तियों में निहित हैं अथवा मौलिक शक्तियों का अंग हैं। ये निहित शक्तियां मौलिक शक्तियों को कार्यान्वित करने की साधन मात्र हैं।

ये निहित शक्तियां निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जिनका सम्बन्ध किसी न किसी मूल शक्ति के क्रिया-व्ययन से हो। ऐसा न होने पर उनका निहित शक्तियों की मंजा नहीं दी जा सकती। कोई शक्ति निहित शक्ति है अथवा नहीं, इसका अंतिम निणय करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है।

निहित शक्तियों के इस सिद्धान्त ने अमेरिकन संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। इसका प्रयोग अनेक बार हो चुका है। ऐसा करने में न्यायाधीशों ने संविधान की उन धाराओं की व्याख्या करते हुए, जिनसे राष्ट्रीय सरकार को विधायनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, संविधानिक शक्तियों के उदार व बहुत अर्थ लगाये हैं। परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार की शक्तियां में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके कुछ उदाहरण निम्न लेखित हैं—

(1) संविधान की आठवीं धारा के अनुसार "राष्ट्रीय सरकार को वदेशिक तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति" मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं द्वारा वाणिज्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लगाया है और उसमें कांग्रेस के रेलों, मोटरों, तार व टेलीफोन कंपनियाँ, हवाई यातायात जहाजरानी रडियो संचार स्टेशन स्टॉक एक्सचेंज आदि अनेक विषयों में सम्मिलित कानून बनाने के अधिकार को घुसा माना है।

(2) संविधान ने कांग्रेस को सैनिकों को एकत्रित करने और उन्हें आवश्यक सामग्री देने की व्यवस्था की है। इन शब्दों द्वारा दी गई शक्ति के अंतर्गत कांग्रेस ने लाखों व्यक्तियों को फौज में गठित करने के लिए केवल युद्धकाल में ही नहीं बरन शांतकाल में भी कानून बनाये हैं। सैनिकों को आवश्यक सामग्री देने का भी विस्तृत अर्थ लगाया है और यहाँ तक कि सैनिकों को भोजन देने के लिए जनता के खान पान में कमी करने का कानून भी कांग्रेस पास कर सकती है।

(3) संविधान की एक धारा के अनुसार कांग्रेस को सर्व-साधारण के कल्याण के लिए विधि निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सामान्य कल्याण की साधना का दायित्व इतना व्यापक है कि उसके अंतर्गत विस्तृत निहित शक्तियाँ कांग्रेस का प्राप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने रोजगार और बुढ़ावस्था पेंशन की व्यवस्था जैसा कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

(4) संविधान के अनुसार कांग्रेस को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह संयुक्त राज्य की ओर से ऋण ले सकती है। अपने इस अधिकार के द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रीय ऋण की देखभाल करने की शक्तियाँ हस्तगत कर ली हैं। स्पष्ट है संविधान में बिना संशोधन किये हुए ही निहित शक्तियाँ कतिपय निहित शक्तियों के प्रतिबंध निर्णायक कांग्रेस नहीं बरन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनक संशोधन हो गये हैं और विभिन्न कानूनों का निर्माण हो गया है।

व्यावहारिक रूप से कांग्रेस को निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर कार्य भी शक्ति स्वच्छानुसार और सरलता से प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि यदि इन शक्तियों के विषय में यह निर्णय दे दिया जाए तो न्यायालय नहीं और उसका निर्णय मनी पावर के लिए अनिवार्य माना जाएगा। सुनरो ने कहा है कि अनेकानेक प्रकरण आये हैं जहाँ कांग्रेस के निहित शक्ति सम्बंधित दावों का उभरण अस्वीकार कर दिया है।

निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रभाव

प्रथम, मघीय सरकार का मविधान प्रदत्त कत्तव्यों को पूरा करने मे वडी सहायता मिलती है ।

दूसरे, मविधान क विकास म वडी सहायता मिली ह । उमम परिस्थितिया की माग के अनुसार आवश्यक परिवतन बहुत कुछ सम्भव हो सके है ।

तीसरे, केद्रीय सरकार की शक्तिया म भारी वृद्धि हुई है और राज्या के स्वशासन के अधिकार पर व्यापक आघात हुआ है ।

चौथे, यायपालिका का प्रभाव और महत्व बढा है ।



3

विधान-मण्डल (कांग्रेस) THE LEGISLATURE (CONGRESS)

“प्रशासन क बढ़ते हुए विंगिट क्षेत्र और फलत शासन को बढ़नी हुई शक्ति की परिस्थिति में, यह अनिचाय है कि शासन के कृत्यों पर नियंत्रण रखने क लिये और उनमें सामंजस्य रखने के निमित्त कोई व्यवस्था होनी चाहिये। यह कांग्रेस ही कर सकती है और मेरे विचार में कांग्रेस का भविष्य इसी में है कि वह अपना सपठन इसी उद्देश्य से करे।”

—रोलैंड यंग

अमेरिकन व्यवस्थापिका अर्थात् कांग्रेस द्विसदनात्मक मस्या है। इसका प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और द्वितीय सदन सीनेट (Senate) के नाम से पुकारा जाता है। निचला सदन (प्रतिनिधि सभा) उच्च सदन (सीनेट) की अपेक्षा कम शक्तिशाली है। सीनेट को मतार का सवाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है।

अमेरिकन शासन में, कांग्रेस अति शक्तिशाली हाते हुए भी ब्रिटिश मसद की तरह सर्वोच्च नहीं है क्योंकि उसके द्वारा निमित्त कानून मविधान विराधी हाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किये जा सकते हैं। साथ ही वह उन विषयों पर जा, राज्या के पास हैं कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती। इसके अतिरिक्त अमेरिका में शक्ति मतुलन का सिद्धांत इतना व्यापक है कि शासन का कोई अंग चाह कर भी तानाशाह नहीं बन सकता।

कांग्रेस की शक्तियाँ और कर्तव्य

(Powers and Functions of The Congress)

1 विधायी शक्तियाँ

ये निम्नलिखित पांच भागों में विभाजनीय है—

(1) अभिव्यक्त शक्तियाँ (Expressed Powers) — ये वे शक्तियाँ हैं

जिनका सविधान मण्डल रूप से उल्लेख है—उदाहरणार्थ, कर लगान एवं वसूल करने की, युद्ध की घोषणा करने की, डाकघरों की स्थापना करने की, वैदेशिक एवं अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन करने की विदेशी मुद्रा का मूल्य निर्धारण करने की शक्तियाँ आदि ।

(ii) निहित शक्तियाँ (Implied Powers) —ये वे शक्तियाँ हैं जो अभिव्यक्त शक्तियों में निहित होती हैं । अभिव्यक्त शक्तियों के प्रयोग के लिये ये आवश्यक हैं । सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं में अभिव्यक्त शक्तियों में से गभित शक्तियों का स्पष्टीकरण किया है । उदाहरणार्थ सविधान में लिखा है कि 'कांग्रेस को वाणिज्य व्यवसाय का नियन्त्रण करने का अधिकार है । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों की व्याख्या १०० से भी अधिक निम्नलिखित व्याख्याओं दी है । उनके द्वारा कांग्रेस का बड़े विस्तृत अधिकार मिल गये हैं ।

(iii) समवर्ती शक्तियाँ (Concurrent Powers) —ये वे शक्तियाँ हैं जिन पर राज्य व विधान मण्डल और कांग्रेस दोनों को विधि निर्माण करने का अधिकार है । ये शक्तियाँ निम्नलिखित रूप में लिख दी गई हैं । सविधान के अनुसार वे शक्तियाँ मध्य को प्रदान नहीं की गयी हैं, व राज्यों की हैं जयवा जनता की ।

(iv) निर्देशात्मक एवं अनिवार्य शक्तियाँ (Mandatory and Permissive Powers) —सविधान द्वारा कांग्रेस को दिये गये अधिकार अधिकांश अनिवार्य शक्तियाँ हैं अर्थात् कांग्रेस चाहता उन्हें प्रयोग में ला सकती है और चाहता नहीं तो नहीं । उदाहरणार्थ कांग्रेस का ऋण लेने का अधिकार है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह ऋण ले ही । कांग्रेस का कुछ अधिकार वास्तव में ऐसे भी प्राप्त हैं जो निर्देशात्मक हैं, उदाहरणार्थ सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थानीय अधिकार प्राप्त है और कांग्रेस के नियमों के अन्तर्गत आने पर ही किसी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में मामल उपस्थित की जा सकती है । यदि कांग्रेस इन अधिकारों का प्रयोग करती है तो राज्य का मामला खटाई में पड़ जाएगा क्योंकि कांग्रेस हर जगह अपनी दाग डगती रहता । परन्तु कांग्रेस की इच्छा है कि अपनी विचार-शक्ति का प्रयोग करके वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे शासन के अन्य विभागों की व्यवस्था खराब हो जाए ।

(v) संशोधन की शक्तियाँ (Powers of Amendment) —सविधान तब तब संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक कि संशोधन कांग्रेस के दाहिनाई बहुमत द्वारा स्वीकार न हो जाए । सविधान का एक शब्द भी कांग्रेस की स्वीकृति के बिना नहीं बदला जा सकता ।

कांग्रेस की मूल शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में ही हैं । यह कानून निर्माण करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा होता है, क्योंकि संसद विधायक कांग्रेस द्वारा पारित किये जाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के द्वारा ही वे कानून का रूप धारण कर पाते हैं ।

राष्ट्रपति का वाग्रम द्वारा पारित विने कृण विधया को निषेध (Veto) करने का अधिकार है, परन्तु वाग्रसे विधयक का दाविहार्द बहुमत स पुन पास करके उत्त निषधाधिकार का प्रभावहीन कर गतती है। सविधानिक मणोपन व विषय म राष्ट्रपति का निषधाधिकार गणु नहा हाना।

2 वेग को सुरक्षा का अधिकार—वाग्रसे की दा की रगा करने स सम्प्रधित गकिनया प्राय जमीमित ह। इन पर गनिष न म केवल एन ही प्रतिग्रह है जोर यह यह है कि राष्ट्रपति प्रयान सनापति हागा तथा गना क निपाजन दा वप स अधिक नही किय जाया। वाग्रम सनागा का निमाण और उनकी यवस्था कर सतती है। वह जन सना तथा सनिव दत्ता का निमाण कर सतती है और राज्या की सना क मगठन को भी व्यवस्था पर सतती है। वाग्रसे ही युद्ध की घोषणा करती है। वह प्रत्यक्ष समय व्यक्ति का राष्ट्रीय सुरक्षा म भाग लेने को बाध्य कर सतती है। वही दा की सना व व्यय व लिय धन स्वीकार करती है। वही यह निश्चय करती है कि सना नितनी मरुपा म रखना उपयोगी होगा और सेना को किन शस्त्रास्त्रा से मुसज्जित किया जाए। राज्य भी सना क क्षेत्र म काग्रस के अधीन ह क्याकि वे शाति क समय भी बिना वाग्रस की अनुमति के स्थायी सेना अधवा जहाज नही रग सतते।

3 महाभियोग लगाने का अधिकार—काग्रस को राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति एव मधीय मरकार के अय मुरय व उच्च पदाधिकारिया पर तथा यायाधीशों पर महाभियाग चक्रान का अधिकार प्राप्त है। अभियाग प्रतिनिधि मभा द्वारा चलाय जाते हैं और नीनेट उनका निणय करती है। यदि सीनेट का निणय महाभियोग के पक्ष म हो ता अपराधी पदाधिकारी का अपना पद त्याग करना पडता है। वाग्रसे के दोना सदना को अपन अपने मदना क मदस्या के विरुद्ध भी कायवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

4 निर्वाचन सम्मधी अधिकार—राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय किसी व्यक्ति का पूण बहुमत प्राप्त न होने पर काग्रम को उनम स राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। काग्रम का सीनटरा और प्रतिनिधिया क चुनाव के समय स्थाना और विधि क सम्म व म भी कानून बनान की शक्ति है। काग्रम ही अपन मदस्या की निर्वाचन सम्म की याम्यता निश्चित करती है और निणय करती है कि बाद चुनाव कब है या जब। इसक अतिरिक्त वह सीनेट आर प्रतिनिधि सभा क निर्वाचन का रद्द कर सतती है यदि वह ऐसा करना याय मगत मगश।

5 सधियों की पुष्टि का अधिकार—सीनेट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित सधिया की पुष्टि करती ह और चतुर राष्ट्रपति उनको वास्तविक रूप म स्वीकृत करने स पूव सीनेट का समथन प्राप्त कर लत हैं। बिना सीनेट की स्वीकृति क राष्ट्रपति किसी सधि या युद्ध की घोणा नही कर सकना। राष्ट्रपति विलसन द्वारा की गई 1919 की बरनाय की सधि का सीनेट न मानन म इकार कर दिया था।

6 कायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ—शक्ति विभाजन के सिद्धान्त के होते हुए भी कांग्रेस बहुत हद तक कार्यकारीणी के विभाग पर नियन्त्रण करती है। वह विनियमनो द्वारा मन्त्रीमण्डल की छोटी से छोटो बात का विनियमन कर सकती है, जैसे विभागों की संख्या नियत करना, उनके आंतरिक संगठन की व्याख्या करना, मंत्रियों और अन्य उच्चाधिकारियों का वतन नियत करना, कायस्थ नियत करना आदि। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ में भी कांग्रेस का हाथ होता है। समस्त उच्च वर्गीय नियुक्तियों के लिये, जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, सीनेट की अनुमति लेना आवश्यक है जयवा वे नियुक्तियाँ माय नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त 'सीनेट के प्रति गिफ्टाचार (Senatorial Courtesy)' की मांग है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में केवल उन व्यक्तियों का नियुक्त करना चाहिये, जिनको उस राज्य से सम्बन्धित उसके दल का सीनेटर पसंद करे।

7 वित्तीय अधिकार—कांग्रेस का कर लगाने, वसूल करने और चुकाने का अधिकार है। वह देश की सुरक्षा और सामान्य हित के लिए नियोजन (Appropriation) कर सकती है। कांग्रेस द्वारा लगाये गये सब कर मारे देश के लिये एक हो सकते हैं, किंतु राज्यों के आयात पर वह कर नहीं लगा सकती। यद्यपि व्यवहार में राष्ट्रीय बजट राष्ट्रपति के संरक्षण में तैयार किया जाता है, परन्तु इसको पारित कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस का ही उमम ससाधन करने का अधिकार है। कभी कभी तो वह उममे ऐस परिवर्तन कर देती है कि उसका वास्तविक स्वरूप ही बदल जाता है। अपने इस अधिकार के प्रयोग द्वारा कांग्रेस प्रशासकीय विभागों पर अपना पर्याप्त नियन्त्रण और प्रभाव रखती है।

धन नियोजन करने की कांग्रेस की शक्ति प्रायः असीमित है। एक अपवाद केवल यह है कि सना के नियोजन एक मास दो घण्टों से अधिक समय के लिये नहीं किये जा सकते। देश की मौद्रिक व्यवस्था (Monetary System) का विनियमन पूरा रूप से कांग्रेस के हाथ में है। वह मिके डलवा सकती है, उनका मूल्य निर्धारण कर सकती है और विदेशी सिक्का का मूल्य निश्चित कर सकती है। कांग्रेस को यह भी अधिकार है कि वह देश के धन को अन्य राज्यों की सहायता के लिये व्यय करे और अन्य देशों को ऋण के रूप में धन दे।

8 व्यापार—यवसाय सम्बन्धी शक्तियाँ—कांग्रेस को विदेशी व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह उनको नियन्त्रण कराने के लिये कानूनों का निर्माण कर सकती है। सम्पूर्ण राज्य के लिये वह दिवालियेपन के बारे में एक स कानून बना सकती है। वह माप-तोल का नियमित करने, कापीराइट और पेटेंट के नियमों की व्यवस्था करना, कागजाना में मजदूरों के काय की दशा निश्चित करने आदि के सम्बन्ध में नियम बना है। वाणिज्य शब्द का अर्थ बड़ा व्यापार लिया गया है और नसम ५

साधन तथा समागम की सब महत्वपूर्ण शाखाएँ, जैसे रज, तार, डाक आदि शामिल हैं।

9 राज्य सम्बन्धी शक्ति—नये राज्यों का मेष म सम्मिलित करने और विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक परिवर्तन करने का अधिकार भी कांग्रेस का ही प्राप्त है। प्रारम्भ में संयुक्त राज्य संघ के अंतर्गत १३ राज्य थे जबकि आज उनकी संख्या ५० है। यह कार्य संघ द्वारा ही किया गया है।

10 "यायिक शक्तियाँ"—कांग्रेस "यायिक" कार्य भी करती है। कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और दूसरे संघीय अधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है और उनकी जांच सीनेट करती है। कांग्रेस संघीय कानूनों के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या कर सकती है परंतु उसे सामान्य अपराधों की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के क्षेत्र में आता है। वही यह निश्चय करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने "यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति में भी सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत कांग्रेस "यायाधीशों का बतन भी नियंत्रित कर सकती है और पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction) की व्यवस्था कर सकती है। निम्नवर्गीय संघीय न्यायालयों का निर्माण भी कांग्रेस की स्वीकृति से ही किया जाता है और वही इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करती है।

समय में, अमेरिकी कांग्रेस की बहुमुखी और विविध शक्तियों की यह रूपरेखा है अथवा उसकी शक्तियाँ वस्तुतः बहुत महान हैं।

सीनेट (Senate)

शक्ति और सम्मान की दृष्टि से सीनेट का विषय महत्व है। वह कांग्रेस के प्रथम सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। समय के साथ सीनेट की शक्तियों में इतनी वृद्धि हुई है कि उसे आज विश्व के द्वितीय सदन में सर्वाधिक शक्ति सम्मान कहा जाता है।

रचना, निर्वाचन, पदाधिकारी आदि
अमेरिकन सीनेट का निर्माण राज्यों की समानता के संघीय सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। सभी राज्य अपने-अपने यहां से दो प्रतिनिधि चुनकर सीनेट के लिए भेजते हैं। इस समय अमेरिकन संघ में 50 राज्य हैं, जब सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है।

सीनेट का सदस्य होना के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो और वह उस राज्य का निवासी हो जिससे उसका निर्वाचन हुआ है।

निर्वाचित होन पर सीनेट का सदस्य अमेरिकन शासन के किसी वैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता ।

सीनेट के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य अपन पद को रिक्त कर देते हैं और उनका स्थान नव निर्वाचित सदस्य ग्रहण करते हैं । संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार अब सीनेटरो का निर्वाचन अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष हो गया है । एक व्यक्ति एक बार सीनेटर होने पर भी अगले बार पुन चुनाव लड़ सकता है ।

अमेरिका का उप राष्ट्रपति सीनेट का पदेन (ex officio) सभापति होता है । उस बाद विवाद में भाग लेने का अधिकार नहीं है और न ही मतदान करने का । समान मत आन पर उसको निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है । उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए सीनेट के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष (President pro tempore) का निर्वाचन करते हैं । सीनेट के सचिव, सारजेंट एट जामस आदि अन्य पदाधिकारी भी होते हैं ।

सीनेट की शक्तियाँ एवं कार्य

सीनेट की शक्तियाँ को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—व्यवस्थापन सम्बन्धी, कार्यपालिका सम्बन्धी एवं न्यायपालिका सम्बन्धी ।

1 व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ—कांग्रेस के दोनों सदन समान पदेय हैं और व्यवस्थापन के क्षेत्र में उनकी शक्तियाँ समान हैं ।

कोई भी विधेयक उस समय तक कानूनी विताय में स्थान नहीं पा सकता जब तक वह सीनेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता । वित्त विधेयक यद्यपि प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किये जाते हैं, किन्तु सीनेट उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार रखती है उनमें संशोधन कर सकती है अथवा उन्हें रद्द कर सकती है । सीनेट वित्त विधेयक की प्रारम्भिक धारा (Enacting Clause) में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, परंतु नए विधेयक में यह इतना संशोधन कर सकती है कि विधेयक का रूप ही बदल जाए । कुछ वर्ष हुए सीनेट ने एक आयात निर्मात-कर सम्बन्धी विधेयक में उसका नाम छोड़कर सभी कुछ काट दिया था । एक अन्य अवसर पर एक विधेयक में उनमें 847 संशोधन लगा दिए थे ।

साधारण विधेयक—वित्तों की सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में दोनों सदनों का समान अधिकार प्राप्त है । दोनों सदनों द्वारा स्वीकार होने पर ही कोई विधेयक कानून बन सकता है । यदि मतभेद हो तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा उसे दूर किया जाता है, जहाँ सीनेट ही सदा लाभदायक स्थिति में रहती है ।

सांविधानिक विषयकों के विषय में भी दोनों सदनों की स्थिति समान है । दोनों ही सदन में संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयक

सकते हैं और प्रत्येक ऐसे विधायक को पारित समझा जान के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने-अपने दो-तिहाई बहुमत से सहमति प्रदान करें।

2 कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ—कार्यपालिका सम्बन्धी महत्वपूर्ण शक्तियों में सीनेट को ममार के समस्त उच्च मन्त्रों से अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की है। सत्र में महत्वपूर्ण अतिरिक्त शक्तियों को पुष्टि करने सम्बन्धी है। राष्ट्रपति द्वारा विदेश के साथ की गई संधियाँ तब तक पूर्ण नहीं मम्ची जाती जब तक उन्हें सीनेट अपने दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित न कर दे। इस शक्ति ने उस राष्ट्र के वैदेशिक मामलों के नियन्त्रण और निद सत्र में काफी हाथ दे दिया है और विदेश नीति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्ति की भागीदार बना दिया है।

प्रायः कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रशासकीय समन्वयों की प्रथा के कारण इस शक्ति का महत्व घट गया है। राष्ट्रपति प्रशासकीय समन्वयों को गुप्त रख सकता है, परिणामस्वरूप उसके वैदेशिक मामलों पर सीनेट का नियन्त्रण ढीला हो जाता है। पर यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। राष्ट्रपति यदि ऐसे प्रशासकीय समन्वयों को ले जा सीनेट को अवगतित हो तो राष्ट्रपति बहुत समय तक उन्हें काममें नहीं रख सकता और यह पूर्ण सम्भव है कि सीनेट कानून द्वारा उस प्रथा को ही समाप्त कर दे।

सीनेट की दूसरी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नियुक्तियों के विषय में, यदि सीनेट अपने निष्पक्ष पर दृढ़ हो तो, राष्ट्रपति सीनेट के बताये हुए मार्गों पर चलता है। व्यवहार में माध्याम्यतया सीनेट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों का अनुमोदन कर देती है पर विशेष मामलों में उन्हें रद्द भी कर सकती है।

तीसरी शक्ति विविध विभागों के विभिन्न शक्तियों की जाच से सम्बंधित है। इस बारे में सीनेट का नियम अंतिम होता है। सीनेट को नव प्रकार के कार्यों में जाच पड़ताल (Investigations) करने का अधिकार है। सीनेट द्वारा की जाने वाली 'जॉर्ज' बहुत गहन होती हैं। बहुत से अधिकारी विरोधी कार्यक्रम सदन से बहुत घबराने हैं। सीनेट की लाजें बहुत प्रसिद्धि पाती हैं और बहुधा इन वायवहियों की 'न्यू रील' (News reel) बनाई जाती है या इन्हें टेलीविजन कमरो में दिखाया जाता है।

सीनेट का यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से किसी विदेशी शक्ति से किसी विषय पर वार्ता करने की प्रार्थना करें। परंतु आरम्भ में शक्ति (Initiative) सीनेट के पास न होकर राष्ट्रपति के पास होती है।

सीनेट की अन्तिम कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति युद्ध की घोषणा के समय की है। इस विषय में प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट भी युद्ध की घोषणा किए जाने से पहले उस अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। नैतिक रूप से सीनेट की शक्ति

यद्यपि प्रतिनिधि मन्त्रालय के समकक्ष ही है परन्तु सन्धियों के पुष्टिकरण की शक्ति के मान सीट का महत्व इस शक्ति के बारे में भी प्रतिनिधि मन्त्रालय से बढ़ जाता है।

(3) **याय सम्बन्धी शक्तियाँ**—सीनेट को समस्त महाभियोगों को मुक्त या एकाधिकार प्राप्त है। सीनेट राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राजदूत, मित्र मण्डल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य उच्च न्यायिक अधिकारियों के अभियोगों का मुकदमा सुनने के लिए न्यायालयों का कार्य करती है। दापागण प्रतिनिधि मन्त्रालय के प्रस्तावों द्वारा सीनेट के समक्ष रखा जाता है और दा-तिहाई बहुमत से सीनेट इन महाभियोगों के निणय देती है। महाभियोग की सुनवाई का समय सीनेट का अध्यक्ष न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और काम के लिए दा-तिहाई सदस्यों का उपस्थिति आवश्यक है। महाभियोग की जांच करने की प्रक्रिया में सीनेट सभी काम, जैसे जांच जारी करना, गवाहों को बुलाना उन्हें गवाह दिलाना, आदि करती है।

(4) **अन्य अधिकार**—सीनेट अधिवेशन के सभाघन में भाग लेती है, मन्त्र मन्त्र राज्य के प्रवेश को स्वीकृति देती है और राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किये गये मतदान की गणना करती है। यदि उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी व्यक्ति का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो दो सर्वाधिक मत प्राप्त वाले प्रत्याशियों में से किसी एक को उप-राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। सीनेट ही अपने निर्वाचनों, निर्वाचन-विवरणों और सदस्यों की योग्यताओं की नियामक है।

सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति को प्रकट करते हुए कहा जा सकता है कि 'कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति और सीनेट निम्न सदन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना भी कर सकती है और ऐसे काम भी हैं जिन्हें निम्न सदन और राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काम बहुत कम हैं जिन्हें निम्न सदन और राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कर सकते हैं।' ग्राहम के शब्दों में 'सीनेट न सदन के बीच एक सम्मिलितता का क्षेत्र स्थापित करके अधिवेशन के निमाताओं द्वारा इसे बनाने के उद्देश्य की पूर्ति कर दी है। हमने एक बार तो प्रतिनिधि सदन के अनुरोध में सहज उपायों का शक्ति की काशिश की है और दूसरी बार राष्ट्रपति की राजतन्त्रीय भावनाओं का शक्ति की काशिश की है। और इस प्रकार हमने दोनों ओर प्रतिबाध लगाये हैं दोनों के मध्य में आने की वजह से सीनेट दोनों ही की प्रतिद्वन्द्वी या विरोधी हो गई है। अब कांग्रेस बिना सीनेट के कुछ नहीं कर सकती है। इसे विरोधी होने पर राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। यह सीनेट या नकारात्मक कार्य करता है, परन्तु हमको सकारात्मक कार्य भी करना है और उनकी वजह से इन राष्ट्रपति मण्डलों में भी है और हमने काफी आदर पाया है।'

(1) संविधान निर्माताओं की इच्छा—संविधान निर्माता सीनेट का सधान शासन प्रणाली की रीढ़ की हड्डी (Backbone) बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति द्वारा गतिशीलता का स्वच्छाचारी प्रयोग न हो, इसके लिए सीनेट का प्रतिपक्ष ऐसी सन्तुष्टि प्रदान की गई कि यह निरन्तर न चल सके और स्थिर मनुलन बना रहे। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की मनमानी पर अनुशासन के लिए व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी सीनेट का प्रतिनिधि सभा का समान पदी बनाया गया और यह व्यवस्था की गई कि सभी प्रकार के विधायक कानून तभी बन सकेंगे, जबकि उन पर दोनों सदनों की सहमति हो जाए। स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने सीनेट को एक ऐसे मनुलन के रूप में स्थापित करना चाहा जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों का अपनी सीमाओं में रख सके। उनकी इच्छा का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि आज सीनेट संसार के सभी द्वितीय सदनों से अधिक गतिशील है।

(2) प्रतिष्ठित सदन और प्रभावशाली रंगमंच—सीनेट कानून बनाने वाले लोग का प्रतिष्ठित सदन है। वह राज्या का राजनीतिक इरादों के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। आज की स्थिति में सीनेट के सदस्य राज्या के प्रतिनिधि नहीं बरन समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि सभा में स्थानीय हितों का प्रमुख रहा है परन्तु सीनेट में ऐसा नहीं है। इससे द्वितीय सदन का स्वभावतः प्रथम सदन से श्रेष्ठता मिल गई है और उसका सम्मान भी बढ़ गया है।

(3) राष्ट्रपति पद के बाद अमरिका में मानित ही सबसे प्रभावशाली रंगमंच (Effective Platform) है। राष्ट्रपति की ही तरह प्रमुख मीनेटरों के भाषण और विचारों को समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया जाता है। सीनेटों के विचार जनमत को पचाए रूप से प्रभावित करने हैं। सीनेटर सरकार की किसी भी धांधली को प्रकाश में लाकर जनमत को सरकार के विरुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त वे किसी भी रहस्यपूर्ण विषय पर कामपालिका से सूचना मांग सकते हैं। फलस्वरूप मीनेट के प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(4) आकार एवं रचना—सीनेट संगठन भी उनके सम्मान का एक सहायक अंग है। प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा मीनेट एक छोटा सदन है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं जबकि सीनेट में 100 सदस्य हैं। सीनेट के छोटे आकार के कारण उसमें प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व होता है। एक छोटा सा गुट, यहाँ तक कि एक सदस्य भी कभी कभी इनकी कार्यवाही में निष्पक्षतात्मक भाग लेता है।

(5) स्थायित्व और स्थिरता—मीनेट के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष की होती है, जब वे पचासवें वर्ष तक प्रमाणित वा अनुभव प्राप्त करके प्रमाणित की कुशलता प्रदान करते हैं। प्रायः सीनेटर दूसरी और तीसरी बार भी निर्वाचित होते रहते हैं और इस लम्बी अवधि के कारण वे बहुधा ज्ञान के भण्डार होते हैं। कामकाल की अधिकता के कारण प्रतिभाशाली लोग मीनेट में जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिनिधि सभा के सामान्य सदस्य जब वहाँ सम्मान प्राप्त कर लेते हैं तो

सीनेट में चुन लिए जाते हैं। अपनी स्थिरता के कारण यह आकस्मिक परिवर्तनों के विरुद्ध एक स्क्वाट का काम करती है। ब्राइम के शब्दों में, "सीनेट सरकार की कार्यकारिणी मशीनरी को स्थिरता से सम्हाले रखने में बहुत कुछ सहायता करती है। यह सार्वजनिक भावना के झंझोरे से आमानी से प्रभावित नहीं होती।"

(6) विधिदृष्ट क्रिया प्रणाली—सीनेट की क्रिया प्रणाली भी उसकी शक्ति का स्रोत है। सीनेट की कार्य विधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने का समय प्रायः निश्चित नहीं किया जाता। सीनेटर जब एक बार बोलने खड़ा हो जाता है, सब जितनी देर चाहे वह सीनेट में बोल सकता है। यद्यपि 1917 में यह नियम बन गया है कि सीनेट का दो तिहाई बहुमत किसी भी सीनेटर को एक घण्टे से अधिक बोलने से रोक सकता है, परन्तु इस नियम का प्रायः बहुत कम प्रयोग किया जाता है। भाषण की स्वतन्त्रता ने सीनेट को पर्याप्त सम्मान प्रदान किया है, क्योंकि इसमें सदन के द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार किया जा सकता है।

(7) दल नियम का अभाव—व्यवस्थापिका के सदस्यों की घटती हुई शक्ति और प्रभाव के पीछे प्रायः दलीय अनुशासन का बहुत बड़ा हाथ है। इसके कारण सदस्यों की स्वतन्त्रता जाना रहती है। परन्तु सीनेट में दल संगठन, दल-नतत्व तथा दलीय अनुशासन का अभाव है। सीनेट के सदस्य स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी समय और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से यह निश्चय करते हैं कि कौनसा रास्ता अपनाया जाए अथवा किस पक्ष को मत दिया जाए। इसके अतिरिक्त सीनेट के सदस्य को किसी वग विशेष अथवा सत्ता का तनिव भी भय नहीं होता। वे न केवल सरकार की अपितु सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञाकारी करने में भी नहीं हिचकते।

(8) मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था का अभाव—मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था के अभाव से भी अप्रत्यक्ष रूप से सीनेट को विशेष शक्तिशाली बनाने में मदद पहुँचाई है। अद्यत्ता के प्रथम सदन द्वितीय सदन की तुलना में इसलिये अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे मन्त्रिमण्डल को बना या गिरा सकते हैं, परन्तु अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं है।

(9) नियंत्रणकारी कार्य-कारिणी एवम् "यायिक" शक्तियाँ—सीनेट के पास महत्वपूर्ण कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ हैं। वह राष्ट्रपति को नियुक्ति पर रोक का कार्य करती है, उसका मधिया एवं नियुक्तियों में अन्तिम शब्द रहता है। जान ह (John Hay) के अनुसार "यदि का सीनेट में भजना एक बेल को बसादे में भजने के समान है। वहाँ में उसका जा-भग हुय बिना जीवित लोटेने को आशा कभी नहीं की जा सकती।" "यायिक" शक्तियाँ के रूप में सीनेट एक प्रमुख जीव निजाय (Investigating Body) का कार्य करती है। सीनेट द्वारा की

जाने वाली खोजें इतनी नयानक होती हैं कि बहुत से अधिकारी विराधी कार्यन सदस्या के प्रश्नों से बहुत घबराते हैं। इनके अनिश्चित चीनट को ही समस्त मता भिन्नगो को सुनने का अधिकार प्राप्त है और उसके नियम अतिम हात हैं।

(10) प्रत्यक्ष निर्वाचन—सीनेट का गठित का एक जय कारण उसके सदस्या के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। 1913 से इस प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही निर्वाचन प्रत्यक्ष होने लगे हैं। अतः जब गाना हो सम्बन्धित क सम्बन्धित स्वयं का जनता का प्रतिनिधि बहून के अधिकारी हैं।

सीनेट आज सरकार के सम्बन्धित का केंद्र (A Centre of Gravity in the Government) है और राज्य के वर्य एक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

सीनेट के विपक्ष में बहुत कुछ कहा जाता है—

प्रथम, सीनेट धनी वर्ग का क्लब (Richmen's Club) है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरा जीपति हो राजनीतिक सम्बन्धित का वास्तविक स्वामी है। सीनेट उनका प्रतिनिधि बन करती है।

दूसरे, सीनेट में सभी राज्या के दो-दो प्रतिनिधि हैं, परन्तु यह प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र की भावना के अनुकूल नहीं है क्योंकि इस प्रकार सीनेट राज्या की प्रतिनिधि सत्ता हो जाती है, जनता की नहीं।

तीसरे, सीनेट काय विधि का भी जादू नहीं कहा जा सकता। इसके नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को दल के सदस्यों का मुँह जाहला पड़ता है। संधि के अनुसमर्थन के अधिकार ने परराष्ट्र नीति को नकारात्मक बना दिया है। यह भी अनुचित है कि किसी भी सदस्य पर नायण के विषय में कोई गंभीर रोक नहीं है और वह जितने समय तक सीनेट में विचारणीय विषय पर बातना चाहें, बोल सकता है।

चौथे, प्रतिनिधि सभा के समान पदी के रूप में इसके अस्तित्व के कारण सब एक बड़ी कठिनाई उपस्थित हो सकती है, जब दोनों सदना में किसी विधायक पर गतिगंध पड़ा हो जाय। संविधान में ऐसा गतिराव की दशा के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। प्रायः विरोध की व्यवस्था में सीनेट की स्थिति अधिक दुर्द रहती है।

पांचवें, सीनेट जितना समय नष्ट करती है उतनी बहुत कम विधान सम्बन्धित नष्ट करती है।

छठे अधिकार हात हम भी प्रगाना के सम्बन्धित में सीनेट का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, जो अनुचित है।

सातवें, जब कभी नियुक्तियों का प्रश्न आता है तो सीनेट साठिन और संयुक्त रूप में कार्य करने का आदेश अपने सदस्यों का देती है जिसके कारण सीनेट के प्रति गिष्टार (Senatorial Courtesy) जैसी प्रथा का चलन है। इस नायण-संगत नहीं कहा जा सकता।

आठवें, सीनेट अनेक बार अपने अधिकारों का दुर्लभयोग करने को तैयार रही है। साथ ही यह अपने विशेषाधिकारों के प्रति आवश्यकता से अधिक भावुक रहती है। सीनेट के इतिहास में एक अवसर आये है जब इस देश के हित की अपना राष्ट्रपति की नीति का भंग (Wreck) करना ही अपना उद्देश्य और लक्ष्य समझा है। अपनी स्वतंत्रता दिखाने के लिए यह कितनी ही बार लापरवाही से ही काय करने लगती है।

परन्तु उपर्युक्त दोषों का बावजूद सीनेट एक सफल, विनाल और अद्वितीय द्वितीय सदन के रूप में उभरी है और इसने अपने निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति की है। अमेरिकन शासन व्यवस्था में सीनेट ही एक ऐसा सदन है, जो व्यावहारिक एवं कारगर रूप में राष्ट्रपति के अधिकारों का नियंत्रण रख सकने में समर्थ हो सका है। मानव अमेरिकन प्रशासन यंत्र की धुरी है। यदि उसे निकाल दिया जाये तो अमेरिकन शासन व्यवस्था धाराशाही हो जायेगी। अमेरिकन सीनेट को हटाने का अर्थ संघीय सरकार की आँतें निकाल देना है। सर हैनरी मैन के शब्दों में, "जब से आधुनिक लोकतन्त्र का ज्वार बढ़ा है, तब से कितनी भी समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें यही केवल एकमात्र पूर्णतया सफल समस्या रही है।"

प्रतिनिधि सभा

(The House of Representatives)

पटमन के अनुसार—"प्रतिनिधि सभा लघु (Miniature) रूप में अमेरिकन राष्ट्र है। यह अमेरिकन जीवन की सुन्दर तस्वीर है जिसमें बड़ा की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा स्वाभाविक विभिन्नताओं, उग्रताओं तथा मध्यमावस्थाओं का पूर्ण चित्रण है। इसके सदस्य विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर चुने जाने के कारण इसमें अमेरिका के जीवन की विविध रूपता दिखाई देती है।" यह एक ऐसा प्रथम सदन है जो मसारा के अन्य सब प्रथम सदनो की तुलना में कम शक्तिशाली है।

प्रतिनिधि सभा की रचना

संविधान में मुख्यतः केवल इतना लिखा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30 हजार लोगो का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, उन्हे उस राज्य की जनसंख्या 30 हजार से कम हो क्यों न हो।

प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, किन्तु बाद में जनसंख्या के अनुसार यह बढ़ती गई। सन 1960 की जनगणना के अनुसार सदस्य संख्या 435 निश्चित कर दी गई है।

सदस्यों की योग्यतायें, उनका निर्वाचन, कार्यकाल, वेतन आदि—
बाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य

का निवासी हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो, निर्वाचन के समय वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो और उन विशेष निवास योग्यताओं को भी रखता हो जो राज्य विशेष निर्धारित करे। संविधान ने कुछ नियोनियतायें भी उपबोधित की हैं—(ग) कोई व्यक्ति मनुष्य राज्य की सेवा में रहते हुए कांग्रेस के किसी सदस्य का सदस्य उस समय तक नहीं हो सकता, जब तक वह उस पद पर आमीन हो, एवं (घ) कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता का प्रथम किसी ऐसे मावजनिव पद पर नियुक्त नहीं हो सकता जिसका निर्माण उसी काल में हुआ हो अथवा जिस पद का वेतन उसी सदस्यता काल में वह सदस्य अपनी व्यवस्थापिका की सदस्यता के प्रभाव के कारण बढ़वा ले।

प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रति दो वर्ष चुन जाते हैं, अर्थात् सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का है। प्रतिनिधि सभा का राज्या में जनसंख्या का आधार पर चुनाव होता है। चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष का मत देने का अधिकार है।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को अन्य विभिन्न भत्तों के अतिरिक्त 22,500 डॉलर प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। भत्तों में स्टेशनरी, यात्रा, सचिव का वेतन आदि प्रमूक्त हैं। सदस्यों को बहस के समय वाद विवाद की स्वतन्त्रता होती है। सदन की कार्यवाही में भाग लेने जाते समय, सदन के अन्दर या सदन से वापस जाते समय उन्हें महाअपराध, देशद्रोह या शांति नष्ट करने के अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सदन के अन्दर अपन भाषण में या विवाद के समय बही गई किसी बात के लिए सदन के बाहर उत्तरवाची नहीं ठहराया जा सकता और न ही इस सम्बन्ध में कोई न्यायालय आपत्ति कर सकता है।

मीनट के समान प्रतिनिधि सभा ही सदस्यों की योग्यतायें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को बाहर निकाल सकती है।

सभा के अध्यक्ष का स्पीकर (Speaker) कहल है जिनका निर्वाचन सभा के सदस्य स्वयं करते हैं। अमेरिकन स्पीकर न केवल दायबदी में फँसा रहता है बरन वह प्रतिनिधि सभा के बहुमत का नेता भी होता है।

प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और उसके कार्य

प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और उनके कार्य मीनट के समान व्यापक नहीं हैं। कुछ क्षत्रों में यद्यपि वह मीनट के समान है किन्तु अन्य क्षत्रों में वह मीनट से बहुत कम शक्तिशाली है।

(1) व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ—इस क्षत्र में मीनट एवं प्रतिनिधि सभा का समान शक्ति प्राप्त है, केवल जिस विषयों का प्रस्तुतीकरण इनमें ही हो सकता है, सानट में नहीं। इस सभा में सभी प्रकार के विषय प्रस्तुत किये जा

सकते हैं और कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक सीनेट के समान ही प्रतिनिधि सभा की सहमति भी उस पर प्राप्त न हो जाए। इस क्षेत्र में ब्रिटिश लोकसभा स्पष्ट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसे व्यवस्थापन क्षेत्र में अन्तिम निणय का अधिकार प्राप्त है। सर्वानामिक विधेयको के सम्बन्ध में भी सभा की शक्ति सीनेट के ही समकक्ष है।

दोनों सदनों में यदि किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो उसका निणय दोनों सदनों की एक सम्मिलित समिति द्वारा किया जाता है और यदि सम्मिलित समिति में कोई समझौता नहीं हो पाता तो अन्त में सीनेट की ही विजय होती है।

दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से युद्ध की घोषणा करने का भी अधिकार है।

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ—सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं। सधिया के पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति एवं विविध विभागों की जाच-पड़ताल आदि में सम्बन्धित कार्यकारी शक्तियाँ केवल सीनेट को ही प्राप्त हैं, प्रतिनिधि सभा को नहीं। परन्तु उसे यह महत्वपूर्ण अधिकार अवश्य है कि विशेष परिस्थिति में वह राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है। जब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचकों की पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत पाने वाले तीन प्रत्याशियों में से एक को राष्ट्रपति-पद के लिए छोट सकती है।

प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों की योग्यता की जाच-पड़ताल करती है और उनके चुनावों की वैधानिकता की भी परीक्षा करती है।

(3) न्यायिक शक्तियाँ—न्यायिक क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को केवल महा-भियोग से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च अधिकारियों पर महाभियोग चला सकती है। वह इन पर महा-अभियोग का आरोप ही लगा सकती है, परन्तु शेष सब कुछ अर्थात् अभियोग को सुनना, अभियोग की जाच करने एवं उस पर निणय देने का अधिकार सीनेट का प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकती है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा दे सकती है, जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा व्यवधान पड़ता हो।

प्रतिनिधि सभा के कम शक्तिशाली होने के कारण

(1) यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद का सुल्झान के लिए चलायी गई दोनों सदनों की सम्मिलित समिति में कोई समझौता नहीं हो पाता तो सीनेट की विजय होती है। वित्त विधेयकों में भी सीनेट जयन मगाधन करने के अधिकार द्वारा किसी भी वित्त विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है अथवा

एक प्रकार से नया प्रस्ताव ही रख देती है। इस प्रकार¹ से प्रतिनिधि सभा का इस अधिकार का कोई विनाश महत्व नहीं रह जाता कि वित्त विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत हो।

(2) राष्ट्रपति द्वारा उच्चवर्गीय नियुक्तियाँ पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है न कि प्रतिनिधि सभा की। विदेशों से की जाने वाली संधियाँ भी सीनेट की ही निहाय पुष्टि होना अनिवार्य है, न कि प्रतिनिधि सभा की। अपनी इस शक्ति द्वारा सीनेट राष्ट्र के वृद्धिकामलों में महत्वपूर्ण भाग लेती है। प्रतिनिधि सभा उसे किसी भी शौरव से वंचित है।

(3) प्रतिनिधि सभा केवल महा अभियोगों का आरम्भ कर सकती है जबकि महा अभियोगों का मुनना उसकी जांच करना और उन पर निर्णय देना आदि सब कुछ सीनेट का अधिकार है। इस तरह प्रतिनिधि सभा की शक्ति इस क्षेत्र में भी सीनेट की अपेक्षा अत्यधिक गौण है। इसके अतिरिक्त केवल सीनेट की ही यह अधिकार है कि वह प्रत्येक मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल या खोजबीन करे।

(4) अमेरिका में शक्ति विभाजन का सिद्धांत लागू होने से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर स्वतंत्र हैं। फिर भी सीनेट नियुक्तियाँ, संधियाँ, जांच पड़ताल एवं महा अभियोगों के क्षेत्र में अपने विशेष अधिकारों द्वारा कार्यपालिका (राष्ट्रपति) पर पर्याप्त अकुशल रख पाती है, जब कि प्रतिनिधि सभा इस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है।

(5) प्रतिनिधि सभा में ऐसे मर्यादायुक्तता का अभाव होता है, जो सदन के समक्ष राष्ट्रीय नीति की रूप रेखा प्रस्तुत कर सके और विधायी प्रस्ताव उसमें सम्मिलित कर सके। अधिवृत्त नेता के अभाव में प्रतिनिधि-सभा की शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं।

(6) प्रतिनिधि सभा में दलीय एकता का अभाव भी उसकी दुर्बलता का एक मुख्य कारण है। सीनेट में सदस्यगण अधिकांशतः पारम्परिक एकरा के सिद्धान्त को लेकर काम करते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में सभी एकरा नहीं दिखाई देती। सदनगण स्थानीय हितों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका निर्वाचन स्थानीय विजय के अनुसार होता है।

(7) प्रतिनिधि सभा की अवधि केवल दो वर्ष की होती है। जिस प्रकार से इस सभा का नया चुनाव आता है उससे यह अवधि और भी कम हो जाती है। सभी वर्षों का ग्यारह महीने बाद ही सदस्यों का चुनाव लड़ना पड़ जाता है। अतः ऐसी अवस्था में प्रतिनिधि सभा महत्वपूर्ण कार्यों का सीनेट पर ही छोड़ देती है जो एक स्थायी सदन है और जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है।

(8) अमेरिका में ऐसी द्विसदनीय व्यवस्था का अस्तित्व है जिसमें व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ दाना सदना की महमति से ही कोई विधेयक पारित हो सकता है, जबकि इंग्लैंड में लाउ सभा के विरोध के होते हुए भी लाउ सभा द्वारा पारित विधेयक अन्त में पारित हो जाता है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापन के क्षेत्र में अंतिम निर्णय नहीं रखती। उसके द्वारा पारित विधेयक तब तक बिलान नहीं बन सकता जब तक कि सीनेट भी उन्हें स्वीकार नहीं करले।

(9) अमेरिका का उच्च सदन (सीनेट) भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अतः वह निर्वाचित प्रतिनिधि सभा से कम महत्वपूर्ण अस्तित्व नहीं रखता।

(10) प्रतिनिधि सभा में विचार विनिमय जघिन नहीं होता जाता अतः इसके निर्णय अधिकांशतः उतने विवेकपूर्ण नहीं होंगे जितने कि सीनेट के होते हैं।

(11) प्रतिनिधि सभा एक विशाल सदन है जिसमें 435 सदस्य हैं। वहाँ राजनीतिक दलों की चाले इतनी अधिक काम करती हैं कि उन पर नियन्त्रण करना और उन पर ठीक अनुशासन स्थापित करना कठिन हो जाता है। इनके विपरीत सीनेट एक छोटा सदन है जिसमें कुल 100 सदस्य हैं। ये सदस्य अनुभवी, योग्य और शासन के कार्यों का समझने वाले होते हैं। साथ ही ये अपने अपने राज्य के राजनीतिक दलों के नेता भी होते हैं।

उपरोक्त सभी कारणों से प्रतिनिधि सभा में केवल सीनेट की अपेक्षा कम शक्तिशाली है, अपितु विश्व के अन्य निचले सदना से भी कम प्रभावपूर्ण है। अमेरिका में सीनेट का अद्वितीय अस्तित्व है और संविधान द्वारा उसे इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि प्रतिनिधि सभा उसके सामने लगभग महत्वहीन रह गयी है। पर यह समझ लेना भ्रामक होगा कि प्रतिनिधि सभा का अमेरिका के शासन नियन्त्रण में कोई प्रभाव नहीं है। वस्तुतः प्रतिनिधि सभा ही जनता की सही रूप में प्रतिनिधि संस्था है और लोकसत्ता की प्रतीक है। व्यवस्थापन का कार्य, बजट निमाण और युद्ध की घोषणा की स्वीकृति आदि से सम्बंधित उसके प्रमुख कार्यों के महत्व को कम नहीं आका जा सकता।

इंग्लैंड के समान ही अमेरिका में भी निचले सदन का अध्यक्ष स्पीकर (Speaker) कहलाता है। परन्तु इंग्लैंड के अध्यक्ष की अपेक्षा अमेरिका का अध्यक्ष बहुत अधिक शक्तिशाली है। पद के प्रभाव की दृष्टि से वह राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति माना जाता है और उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति का पद अध्यक्ष को ही मिलता है।

अध्यक्ष का निर्वाचन

सिद्धान्त में तो प्रतिनिधि सभा ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, परन्तु व्यवहार में दलीय काँकस (Caucus) द्वारा यह निश्चय कर लिया जाता है कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। विविध राजनीतिक दल अपनी अपनी दलीय बैठकों में अध्यक्ष

पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी चुन लेते हैं। बाद में जब प्रतिनिधि सभा की बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिये होती है तो सब दल अपने अपने प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करते हैं। मतदान के बाद जिसे बहुमत मिलता है, वह अध्यक्ष माना जाता है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

संविधान अध्यक्ष के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन नहीं करता, अतः उसके अधिकारों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहा है। आरम्भ में उसका पद अधिक शक्तिशाली नहीं था परन्तु समय के साथ इस पद का प्रभाव एवं शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। वह मदन के तानाशाह की स्थिति में आ गया और विधेयकों के जीवन-मरण का विधाता बन बैठा। अतः में अध्यक्ष की यह स्थिति डेमोक्रेटिक दल के विरोध का शिकार बनी और सन 1910-11 में यह दल अध्यक्ष की शक्तियों को कम करने पर तुल गया। 1910 में अध्यक्ष कैन के विरुद्ध सभा में विद्रोह हुआ और अध्यक्ष के अनेक महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिये गये। बाद-विवाद के नियमों में कई परिवर्तन हुए। अध्यक्ष को नियम-निर्माणी शक्ति से हटा दिया गया और स्मार्थ समितियों का चुनाव प्रतिनिधि सभा करने लगी। अध्यक्ष की स्वीकृति का अधिकार (Power of Recognition) भी छीन लिया गया। इन क्रान्तिकारी संशोधनों के परिणामस्वरूप अध्यक्ष पहले के समान शक्तिशाली नहीं रहा। परन्तु फिर भी अपनी स्थिति और अपने विशेष कर्तव्यों के कारण वह विशिष्ट शक्तियों का स्वामी बना रहा। आज अध्यक्ष जिन शक्तियों का उपयोग करता है, वे निम्नानुसार हैं—

सभापतित्व करना और बोलने की व्यवस्था करना—अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। वही सभा की बैठकों का आरम्भ और समाप्त करता है तथा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है। उसके आदेश पर ही सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में वह दलीय पक्ष-पात से ऊपर उठा हुआ नहीं रहता।

अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखना—मदन के अनुशासन, सम्मान और उनकी व्यवस्था बनाये रखने का मुख्य दायित्व अध्यक्ष का ही है। इस दायित्व का निर्वहण करने के लिए उस अधिकार है कि वह सदस्यों का मौखिक चेतावनी दे सके। मदन में अशान्ति और व्यवस्था हानि पर वह अपना गैबल (Gable) लटका कर लागा का अनुशासन होने के लिए मकत कर सकता है। यदि कोई सदस्य अनुशासन नग्न करने पर ही उतावला हो तो अध्यक्ष उसका नाम लहर उस शिष्टक सकता है और अत्यन्त व्यवस्था की स्थिति में वह उस समय तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है जब तक उसका नियमन माना नहीं जाता। वह एक सैनिक अधिराज (Sergeant at Arms) का भी शक्ति स्थापित करने के लिए आदेश दे सकता है, सविन श्रेष्ठ स्थिति का आरम्भ के अध्यक्ष के समान वह किसी

सदस्य को किसी प्रकार से दंडित करने का अधिकार नहीं रखता और न ही सदस्य को सभा भवन से बाहर निकल जाने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी आज्ञा तो स्वयं सभा ही दे सकती है।

नियमों की व्यवस्था और उनको कार्यान्वित करना—अध्यक्ष का तीसरा प्रमुख वस्तु नियमों की व्याख्या करना व उन्हें लागू करना है। परंतु वह इस अधिकार के प्रयोग में स्वच्छाचारी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे नियम निर्मात्री समिति (Committee of Rules) द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करना पड़ता है। फिर भी, जहाँ नियमों की व्यवस्था अस्पष्ट अथवा अप्रत्याप्त हो वहाँ अध्यक्ष को अपने विवेक में बहुत कुछ काम करने का अधिकार है। स्मरणीय है कि किसी नियम पर कोई भी अध्यक्ष की व्यवस्था को सदन का बहुमत अमान्य घोषित कर सकता है। अतः ब्रिटिश अथवा भारतीय अध्यक्ष की भाँति अमेरिकन अध्यक्ष का नियम अंतिम नहीं होता।

नियमों की व्यवस्था के अधीन अध्यक्ष प्रश्नों पर मत लेता है सदन द्वारा पारित अधिनियमों, मापना, मयुक्त प्रस्तावों, विटो, वारंटों और समना (Summons) पर हस्ताक्षर करता है। वह कार्य के क्रम (Order of Business) तथा मतदान के क्रम की घोषणा करता है।

अपनी अधिकार—मुख्य पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष बराबर मतों की स्थिति में अथवा जब गुप्त मतदान होता हो तब अपना मत दे सकता है। परंतु दलीय व्यक्ति होने के कारण उनका मत अपने दल के पक्ष में ही होता है। अध्यक्ष को यह भी अधिकार है कि वह प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के रूप में सभा की कार्यवाही में भाग ले और वाद विवाद में हिस्सा बटावे। सदन की सूची के विषय में प्राथमिकता का निर्णय करना उसी का काम है। 1911 तक अध्यक्ष ही समस्त स्थाई समितियों और नियम समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता था, परंतु अब वह केवल प्रवर समितियाँ और उन कार्यो में समितियाँ नियुक्ति करता है जिनके लिये प्रतिनिधि सभा उनका कह। ब्रिटिश परम्परा के विपरीत उसे यह अधिकार है कि वह अपना पद हस्तांतरित कर सके। परन्तु ऐसा वह केवल तीन दिनों के लिए ही कर सकता है। वह किसी भी सदस्य से यह आग्रह कर सकता है कि वह उनका पद तीन दिनों के लिए सभाले।

प्रतिनिधि सभा की ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष से तुलना

(1) ब्रिटन में लोकसभा का अध्यक्ष दलीय सिद्धांत पर नहीं चुना जाता, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर निर्वाचित होता है।

(2) अध्यक्ष निर्वाचन के पश्चात् निरदलीय व्यक्ति (Non Party man) हो जाता है किंतु अमेरिका में वह तब भी दलीय व्यक्ति (Party man) बना रहता है।

(3) ब्रिटिश अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में निष्पक्ष होकर कार्य करता है जबकि अमेरिकन अध्यक्ष अपनी नीति निष्पक्ष नहीं होता।

(4) ब्रिटन में अध्यक्ष सक्रिय दलीय राजनीति में अपनी भी भाग नहीं लेता जबकि अमेरिकन अध्यक्ष सदन में अपने दल का नेतृत्व करता है और अपने दल के विधेयक तथा प्रस्तावों का पाम करवाने में योगदान करता है। वह विरोधी दल के विधेयक तथा प्रस्तावों का पाम हान में रोकथाम डालता है। वह वास्तव में सदन के सभापति तथा राष्ट्रपति से परामर्श करता है। यदि वह एक राजनीतिक दल के हाथ में तो इस प्रकार का प्रयत्न करता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव तथा विधेयक सीधे-सीधे प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित कर दिए जाय।

(5) प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की भांति निर्विवाद नहीं चुना जाता और उस चुनाव में हार पड़ता है और अपने निर्वाचकों की भांति रखा रहता है।

(6) प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष नियमों का निमाण और नियंत्रण बहुत कुछ अपने विषयों के आधार पर करता है। जबकि ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए नियमानुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करता है।

(7) ब्रिटिश लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को उसका 'नाम' लेकर निर्लज्ज कर सकता है, जबकि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है।

किंतु दोनों अध्यक्षों में कुछ समानताएँ भी हैं। ब्रिटन के अध्यक्ष की तरह अमेरिका में भी अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा का सभापति होता है, वह बैठकों में अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है, सभा में अनुशासन रखता है, विवादग्रस्त प्रश्नों को तय करता है, सदन के कार्यक्रम बनाता है तथा उसकी सीमा निर्धारित करता है। प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। फर्दर कथनों में 'अध्यक्ष पद का महत्व राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरे नम्बर पर ही आता है। ब्रिटन में अध्यक्ष के पास इतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि प्रभाव। अमेरिका में अध्यक्ष का इतना प्रभाव नहीं होता जितनी उसको वास्तविक शक्ति होती है।'

अमेरिका में विधि-निर्माण-प्रक्रिया

(The Law making Process in America)

समुच्चय राज्य अमेरिका में किसी भी विधेयक का पारित होने से पूर्व निम्न-लिखित स्थितियों में संशुद्धि पड़ता है।

(1) प्रस्तावना (Introduction)

(2) छोट व प्रथम वाचन (Sorting and First Reading)

(3) समिति स्थिति (Committee Stage)

- (4) कलेंडर अवस्था (Calendar Stage)
- (5) द्वितीय वाचन (Second Reading)
- (6) तृतीय वाचन (Third Reading)
- (7) विधेयक दूसरे सदन में (Bill in the other house)
- (8) विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष (Bill before the President)

प्रस्तावना या प्रस्तुतीकरण

अमेरिकन कांग्रेस में भी ब्रिटिश संसद की भांति ही विधि निमाण प्रक्रिया की प्रभावशाली विधेयक के प्रस्तुतीकरण की है। वित्त विधेयक का छाड़कर अन्य कोई भी विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक सब प्रथम केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक—(क) कांग्रेस के किसी भी सदस्य के द्वारा, (ख) कांग्रेस की किसी भी स्थाई समिति द्वारा, अथवा (ग) राष्ट्रपति या किसी कार्यकारी अधिकारी के कहने पर निर्मित कांग्रेस की विशेष समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

विधेयक का प्रस्तुत करने की प्रणाली भी अत्यंत साधारण है, जो इस प्रकार है—

(क) यदि सदस्य सीनेट में विधेयक को प्रस्तावित करना चाहते हैं तो वह उसकी एक प्रति सचिव की मेज पर रखे सन्दूक पर डाल देते हैं।

(ख) यदि सदस्य विधेयक को प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित करना चाहते हैं तो उसकी प्रति लिपिक (Clerk) की मेज पर रखे हुए सन्दूक पर डाल देते हैं, जिसे 'हूपर' (Hooper) कहते हैं।

दोनों दशाओं में अंतर केवल यही है कि सीनेट में उक्त व्यक्ति को 'सचिव' कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा में उसे 'क्लर्क'।

प्रस्तावित विधेयक उस समय तक जीवित रहता है जब तक कि उनका निवटारा नहीं होता अथवा जब तक वर्तमान कांग्रेस समाप्त नहीं होती। यदि कांग्रेस-काल में विधेयक निवटारा नहीं जाता, तो उसके प्रस्तावक को उसे दूसरी कांग्रेस में पुनः प्रस्तावित करना पड़ता है। सदन में संसत् प्रस्तावित विधेयको को एक क्रमिक संख्या प्रदान कर दी जाती है और प्रत्येक प्रस्तावित विधेयक पर प्रस्तावक का नाम लिख दिया जाता है।

अमेरिका में विधेयक की प्रस्तुतीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड की प्रक्रिया से भिन्न है—

प्रथम, इंग्लैंड की प्रक्रिया अमेरिका की प्रक्रिया जितना सरल नहीं है। इंग्लैंड में विधेयक का प्रस्तुतीकरण दो विधियाँ होना हैं, जिसमें एक माध्यम प्रस्तुतीकरण (During Introduction) और दूसरी दस मिनट के प्रस्तुतीकरण (Introduction Under ten minutes Rule) की जबकि कहानी है।

अमरीका की प्रस्तुतीकरण की अवधि द गजट की पहली प्रकार की अवधि से मेल नहीं खाती है, जिसके अन्तर्गत विधायक के प्रस्तावक की विधायक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उष पर एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं होती।

द्वितीय, अमरीका में विधेयको का विभाजन इन प्रकार का नहीं है जसा कि ब्रिटन में है। ब्रिटन में तीन प्रकार के विधायक—मावजनिक, व्यक्तिगत सदस्या द्वारा प्रस्तावित मावजनिक विधायक एवं अमावजनिक विधायक—सदन के सामने प्रस्तावित किये जाते हैं और इन तीनों ही प्रकार के विधायको के पारित होने की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न है। किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में समस्त विधायक गैर सरकारी अर्थात् सदस्यों के ही होते हैं।

छाट व प्रथम वाचन

यह विधेयक के जीवन का दूसरा चरण है। प्रस्तुतीकरण के बाद सदन का लिपित विधेयको को विषयवार छाट लता है। तत्पश्चात् यह उद्दे सरकारी सूचना के रूप में छपा लेना है। इस प्रकार विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है।

अमरीका की व्यवस्थापन प्रक्रिया की प्रथम वाचन की तुलना यदि ब्रिटिश व्यवस्थापन की प्रक्रिया के प्रथम वाचन से की जाए, तो अनेक अंतर दिखाई देते हैं—(1) ब्रिटन में विधेयक की छाई तभी होती है जब प्रस्तुतकर्ता का यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है कि विधेयक का प्रथम वाचन हो और उसे छपवाने की आज्ञा दी जाए, एवं (ii) ब्रिटन में प्रस्तुतीकरण और प्रथम वाचन सम्मिलित होते हैं जबकि अमरीका में समय की दृष्टि से दोनों अलग-अलग होते हैं।

समिति अवस्था

अमरीका में विधायक के जीवन का तीसरा चरण समिति अवस्था का है। प्रथम वाचन के बाद विधेयक उस विषय की समिति के पास जाता है, जिस विषय से सम्बन्धित वह विषय होता है। अमरीका में समितियाँ विषयवार बनाई जाती हैं। यदि विवाद उत्पन्न हो जाए कि विधेयक किस समिति को सुपुर्द किया जाना है तो नियम सदन का अध्यक्ष करता है। उसके नियम के विरुद्ध सदन से अपील भी की जा सकती है।

समिति अवस्था विधायक के जीवन और मरण की स्थिति होती है। समितियाँ विधेयको के स्वरूप और उससे सम्बन्धित मामलों में नामश्रिया एकत्र करती हैं। पूरा जांच पड़ताल के बाद समिति एक गोपनीय बैठक में यह निश्चित करती है कि विधायक पर उसे क्या नियम देना है। वह अपने नियम अग्रलिखित रूप में से किसी भी एक रूप में दे सकती है।

(क) विधेयक के प्रस्तावित रूप को स्वीकार करे बिना किसी मसौदा के लिए अपना प्रतिवेदन दे सकती है।

(ख) विधेयक पर मसौदा सहित प्रतिवेदन दे सकती है।

(ग) विधेयक को पूर्ण रूप से बदल सकती है, केवल उसके प्रस्तावित स्वरूप और विषय वस्तु का छोड़ कर।

(घ) विधेयक पर कोई प्रतिवेदन न दे कर उसकी हत्या कर सकती है। समिति द्वारा ऐसा किये जाने को विधेयक को कबूतर के दरबे में डाल देना [Pigeon Holding] कहा जाता है।

अमरीका में चूँकि सभी विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होते हैं, अतः वे प्रायः सब तरह से पूर्ण नहीं होते। परिणाम यह निकलता है कि वहाँ लगभग 90 प्रतिशत से भी अधिक विधेयकों के जीवन का अन्त समिति अवस्था में ही हो जाता है। कांग्रेस को यद्यपि यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी विधेयक को, जिस पर समिति ने कोई प्रतिवेदन देना उचित नहीं समझा है, अपने समक्ष विचाराय प्रस्तुत करा ले, तथापि व्यवहार में ऐसा प्रायः बहुत कम किया जाता है। जब कभी किसी विधेयक पर समिति के सदस्यगण एक मत नहीं होते तो व्यवस्था यह है कि बहुमत और अल्पमत दोनों के ही प्रतिवेदनों के साथ विधेयक कांग्रेस को लौटाया जाता है। समिति के प्रतिवेदन भी छाप जाकर विधेयक के साथ सदस्यों को दिये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में अमरीकन व्यवस्थापन प्रक्रिया और ब्रिटन की व्यवस्थापन-प्रक्रिया में अनेक अन्तर हैं—(i) ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के पश्चात् विधेयक को समिति में भेजा जाता है, जबकि अमरीका में उसे प्रथम वाचन के बाद ही समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है, (ii) ब्रिटेन में मसद ही विधेयकों के सिद्धांतों पर विचार द्वारा निणय करती है जबकि अमरीका में विधेयकों के सिद्धांतों और उसकी उपयोगिता आदि पर विचार व निणय पहले समिति में ही हो सकता है और कांग्रेस को अक्सर वाद में मिलता है (iii) ब्रिटेन में समितियाँ उतनी समर्थ और शक्तिपूर्ण नहीं जितनी अमरीका में, एवं (iv) ब्रिटेन में समितियाँ आवश्यकतानुसार बनती हैं। वे विषयवार नहीं होती, और अधिकांश पूर्ण स्थाई भी नहीं होती। यहाँ कुछ समितियाँ होती हैं जिनमें विधेयकों के विषय के अनुसार कुछ विशेषण और जोड़ दिये जाते हैं। किन्तु अमरीका में समितियाँ का निम्न विषयवार और स्थाई रूप से किया जाता है, अतः उनमें विषयों का जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सूचीकरण अथवा कैलेंडर व्यवस्था

विधेयकों के जीवन का चाया चरण सूचीकरण का आता है। इस स्तर पर विधेयक को अग्रलिखित पाँच सूचियाँ (Five Calendar) में से किसी एक में रखा दिया जाता है।

(1) संघीय सूची (Union Calendar)—इसमें राजस्व विनियोग तथा नावजनिक सम्पत्ति में सम्मिलित विधायक, जिन पर पक्ष में प्रतिवदन दिया जाता है जाता है।

(2) सदन सूची (House Calendar)—इसमें प्रथम श्रेणी की सूची में जान बाउ विधेयक का छाटना और सभी नावजनिक विधायक, जिनका सम्पत्ति में नहीं रहना, जान है।

(3) सम्पूर्ण सदन सूची (Calendar of the Whole House)—इसमें विधायक रखे जाते हैं जो स्थानीय विषय व निजी निगमा आदि से सम्बन्धित होते हैं, अथवा नावजनिक या सम्पूर्ण राष्ट्रीय रिता से सम्बन्धित नहीं होते।

4 सहमति सूची (Consent Calendar)—जिन विधायक में कोई विरोध नहीं होता उनका किसी भी सूची से निकाल कर इस सूची में रखा जा सकता है अथवा जो विधायक राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिन्हें नवमसमिति से पारित किया जाता होना है, व इसमें आते हैं।

(5) निवृत्ति सूची (Discharge Calendar)—इसमें वे विधायक रखे जाते हैं जिन्हें सदन के बहुमत द्वारा समितियों के पास से निकाला जाता है। यदि कोई विधायक समिति के पास 30 दिन तक रखा हो तो उसका प्रस्तावक सदन के बहुमत से उस विधेयक को समिति के पास से निकाल सकता है।

द्वितीय वाचन

विधायकों का वर्गीकरण हाकर और उन्हें उचित सूची में रखे जाने के बाद नियत दिनांक का सदन उन पर विचार करता है। इसके लिए सदन सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House) के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अध्यक्ष (Speaker) उठ जाता है। ऐसा प्रत्येक विधेयक के विषय में होता है। सम्पूर्ण सदन की समिति विधायक के निवेदनात्मक स्वरूप पर पूरी तरह विचार करती है। इस द्वितीय वाचन की अवस्था में सदस्यगण विधायक के पर और विषय में वाद करते हैं और उनमें मतभेद के मुद्दाएँ रख सकते हैं। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक मस्य का वाचन का एक बार अवसर दिया जाता है और कोई भी सदस्य एक विधायक पर एक घण्टे से अधिक नहीं बात सकता है। सीनेट में इस प्रकार का कोई प्रवचन नहीं है। वहाँ कोई भी सदस्य कितनी ही बार व कितनी ही समय तक बात कर सकता है। विधायक का वास्तविक विवरण और परीक्षा इन द्वितीय वाचन के समय ही होता है।

विधायक व द्वितीय वाचन के विषय में भी अमेरिकन व ब्रिटिश व्यवस्थापन प्रणाली में अंतर है—(1) अमेरिका में द्वितीय वाचन में पूर्व समिति अवस्था आती है जबकि ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के बाद, (2) ब्रिटेन में द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं और तत्पश्चात् केवल उनका रूप ठाढ़ करने का

लिए उसे समिति को सौंपा जाता है, किन्तु अमेरिका में प्रथम वाचन के उपरांत ही विधेयक को समिति को सौंप दिया जाता है जिसे विधेयक के सिद्धान्ता और रूप में भी परिवर्तित करने का अधिकार होता है। (iii) अमेरिका की तरह ब्रिटेन में कलेण्डर व्यवस्था नहीं है, (iv) अमेरिका में प्रस्तावित होने के उपरांत बजट प्रतिनिधि सभा की उपाय व साधन समिति (Ways and Means Committee) में विचार के लिए भी चला जाता है जबकि ब्रिटेन में लोकसभा ही सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House) के रूप में बजट पर विचार प्रस्तुत करती है, (v) ब्रिटेन में सदस्य के निचले सदन अर्थात् लोकसभा के सदस्य पर भाषण सम्बन्धी कोई प्रतिबंध नहीं है जबकि अमेरिकन कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्य का भाषण सम्बन्धी वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जो ऊपरी सदन (Senate) के सदस्य को प्राप्त है, एवं (vi) ब्रिटेन में द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांतों पर ही विचार होता है, जबकि अमेरिका में केवल विधेयक के सिद्धांतों वल्कि उसके रूप पर भी पूर्ण विचार होता है।

तृतीय वाचन

विधेयक के जीवन का छठा स्तर तृतीय वाचन का होता है। यह वाचन केवल औपचारिक होता है। विधेयक के सिद्धांत पर केवल माटे रूप से ही विचार किया जाता है। उसकी धाराओं, उपधाराओं, वाक्यों और शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता। यदि कोई सदस्य विधेयक के पूरे पढ़े जाने की मांग न कर तो केवल विधेयक का शीर्षक (Title) ही पढ़ दिया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष सदन का अंतिम निर्णय लेता है। इसकी चार रीतियाँ हैं—मौलिक मतदान, खड़े हान्तर, गणका द्वारा, एवं 'हाँ' या 'ना' द्वारा।

ब्रिटेन व अमेरिका में व्यवस्थापन प्रणाली का तृतीय वाचन उभयत्र एक ही है, केवल मतदान के ढंगों के विषय में अंतर है। ब्रिटेन में मतदान प्रायः गणका के द्वारा अथवा खड़े होकर होता है। अमेरिका में खड़े होकर व 'हाँ' या 'ना' बोल ढंग का अधिक प्रयोग किया जाता है।

विधेयक दूसरे सदन में

विधेयक के जीवन का सातवाँ चरण वह है जब तृतीय वाचन के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रायः उही अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिन अवस्थाओं में उसे पहले वाले सदन में गुजरना पड़ा था। दूसरा सदन विधेयक को पहले वाले सदन की पुनः विचारणा छोड़ सकता है और उसे किसी समिति को भेज सकता है, जहाँ विधेयक पूर्णतः समाप्त हो सकता है।

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेदों का अभाव हो जाए तो एक सम्मेलन समिति (Conference Committee) बनाई जाती है।

जिमम दाना मदना क बराबर उराउर प्रतिनिधि हान है। यह समिति विवाद न्त विषया पर गुप्त रूप म वाद विवाद उरती है और समाधान करने क उपाय ए विचार करती है। यदि समिति समाधान करन म नफउ रहती है तो उमक सदन अपन जपन सदनों के समक्ष उम प्रस्तुत करत ह। यदि प्रत्येक सदन समिति द्वारा प्रस्तावित सुझावा का स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक दाना सदन द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है। किन्तु यदि ये सुझाव स्वीकृत नहा हाते हैं तो विधेयक का वहाँ अन्त हो जाता है। यह भी सम्भव है कि यदि सम्मेलन-समिति निश्चित हल ज्ञात न कर सक तो एसी दशा म भी विधेयक का अन्त हो जाण।

इस सम्बन्ध म ब्रिटिश व अमेरिकन प्रणाली म भिन्नता है। अमेरिका म का भी विधेयक दोनों सदन के मतभेद के बिना पारित नहीं हो सकता, जबकि ब्रिटेन म दाना सदन क मतभेद की अवस्था में लाइ सभा बिना विधेयक को अधिक से अधिक एक माह तक और अन्य विधेयक को अधिक से अधिक एक माल के लिये रोक सकती है। वहा विधेयक के पारित होने म अन्तिम शब्द लाइसभा का होता है, लाइ सभा इस दृष्टि स अमहाय है।

विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष

दोना मदना की स्वीकृति के पश्चात विधेयक का राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए भेज दिया जाता है और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर वह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। विधेयक के सम्बन्ध म राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प हाते हैं—पहला विकल्प यह है कि वह 10 दिन के भीतर विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरा विकल्प यह है कि वह विधेयक का अस्वीकार करद और कारण बताते हुए उसे कांग्रेस का पुन विचारार्थ लौटा दे। विधेयक उसी सदन को लौटाया जाता है, जिसन उस प्रारम्भ किया था। किन्तु यदि विधेयक की स्वीकृति के दो तिहाई बहुमत से विधेयक का पुन स्वीकृत कर दें तो राष्ट्रपति को उसे आवश्यक रूप से स्वीकार करना पडता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विधेयक की स्वीकृति के विषय म अन्तिम रूप स केवल विलम्ब करन का निषधाधिकार प्राप्त है। तीसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति तटस्थ रहन क उद्देश्य से विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करता है और न उस लौटाता ही है। ऐसी दशा म विधेयक स्वत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है और कानून बन जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को न लौटाये और 10 दिन के अन्दर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाय, तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा बिना अस्वीकार किए हुए ही जस्वीकृत हो जाता है। इस राष्ट्रपति का जेबी निषधाधिकार (Pocket Veto) कहा जाता है। यह अधिकार बंधानिक न होकर केवल परम्परागत है।

कांग्रेस के अधिवेशन की समाप्ति के बाद सनी कानूना, प्रस्तावा, सधियों आदि का सविधि पुस्तक (Statute Book) म संग्रहीत कर दिया जाता है। राज्य सचिव (Secretary of State) विधियों को घोषित करता है।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटन में मसद द्वारा पारित विधेयको को सम्राट की स्वीकृति मिल ही जाती है। उसका निषेधाधिकार केवल नाम मात्र का ही है जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति का निषेधाधिकार वास्तविक है और वह उसका प्रयोग भी बहुत अधिक करता है।

अमेरिका की समिति प्रणाली

(Committee System in the U S A)

आधुनिक विधि निर्माण में गति और सुचारुता लाने के लिए समितियाँ का प्रयोग कितना अधिक होने लगा है, कहने की आवश्यकता नहीं। अर्थ दशा की व्यवस्थापिकाओं के समान ही अमेरिकन कांग्रेस में भी समिति व्यवस्था का अपना विशेष महत्व है। अमेरिकन समितियों की शक्ति ब्रिटन की समितियों से अधिक है क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ कार्यपालिका और कांग्रेस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से व्यवस्थापन का पूरा दायित्व कांग्रेस के सदस्यों पर ही है और कांग्रेस की समितियों को ही अधिकांशतः यह दायित्व निभाया पड़ता है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्थापन के सम्बन्ध में जो कार्य मन्त्रिमण्डल करता है, अमेरिका में वही कार्य समितियाँ करती हैं।

कांग्रेस में समितियाँ कायम मठन

अमेरिकन कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों में पृथक्-पृथक् रूप से समितियाँ की व्यवस्था की गई है। इन समितियों की नियुक्ति सदन स्वयं करता है। उनमें बहुमत दल और अल्पमत दल दोनों के ही सदस्य होते हैं। समितियों के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनकी उत्पत्ति और इसका विकास आवश्यकताओं का परिणाम है। अमेरिका में प्रायः निम्नलिखित महत्वपूर्ण समितियाँ पायी जाती हैं—

- 1 स्थाई समिति (Standing Committees)
- 2 नियम समिति (Committee of Rules)
- 3 प्रवर समितियाँ (Select Committees)
- 4 सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House)
- 5 सम्मेलन समिति (Conference Committees) एय
- 6 संयुक्त समितियाँ (Joint Committees)।

स्थायी समितियाँ—इनका अमेरिकन समिति व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटन की तुलना में ये सभ्यता में अधिक हैं, किन्तु इनमें सदस्य संख्या अपेक्षाकृत कम है। साधारणतः इनमें 12 से लेकर 30 तक सदस्य होते हैं यद्यपि कुछ समितियों में सदस्य कभी-कभी 50 तक रहते हैं। स्थायी समितियों की नियुक्ति सदन स्वयं करता है पर वास्तव में निम्न राजनीतिक दल अपनी शक्ति का आधार पर करते हैं। सदन तो केवल अनुमोदन करता है। इन समितियों के सभापति बहु-

मत दफ़ के प्रमुख नेता होते हैं। सन 1946 तक अमेरिकन स्याई समितियों का संख्या 47 थी पर 1946 के विधायी पुनगठन द्वारा इनकी संख्या प्रतिनिधि सभा में 19 तथा सीनेट में 15 कर दी गई है। प्रत्येक स्याई समिति अपने-अपने सदन में व्यवस्थापन के निश्चित विभाग की देख रेख करती है। अनेक समितियाँ उप समितियों से भी काम लेती हैं जिनमें से कुछ स्याई होती हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट की समितियों का नामकरण लगभग समान है।

अमेरिकन कांग्रेस की यह स्याई समितियाँ व्यवस्थापन क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। कांग्रेस के दानो सदन में विगत वर्षों में लगभग 10 हजार से 15 हजार के बीच विधायक प्रस्तुत किए जाने रहे हैं और इन मारे विधायकों पर विचार करना कांग्रेस के लिए कठिन ही नहीं, असंभव सा है। इनने भारी बोझ को हल्का करना इन स्याई समितियों का ही कार्य है। यही कार्य सभा अधिकांग व्यवस्थापन कार्य करती हैं।

नियम समिति (Committee of Rules)—इस महत्वपूर्ण समिति में लगभग 12 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य कांग्रेस की वाय विधि का मन्व्य में विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करना होता है। सदन के प्रत्येक कार्यकाल के प्रारम्भ में यह कार्य विधि मन्व्य की नियमों का प्रस्तावित करती है। सदन का अन्तर्गत का यह अधिकार होता है कि विना परिस्थितियाँ में वह उन नियमों को न भी माने। ये नियम प्रत्येक नए सदन के निर्माण के साथ साथ बदल जाते हैं।

नियम समिति ही विधायकों का छांटन का काम करती है और यह नियम भी लेती है कि कौनसा विधायक विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाय। समितियों द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट किए गए विधायकों का नियम समिति के पास भी भेजा जाता है। यह समिति जिन विधायकों का महत्वपूर्ण ठहरा देती है उन पर सदन की जासानी में विचार कर लेता है। इस प्रकार यह समिति सदन और स्यायी समितियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इसके पास विधायकों को विलम्ब में डालने की शक्ति भी है। इस अधिकार है कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय मध्य पर उन्हें सदन के कार्यों में हस्तक्षेप करने और आवश्यक होने पर नियमों की आड़ लेकर नए प्रस्ताव प्रस्तुत करे। बाग एव वे ने लिखा है कि "यह स्वयं ही किसी विधायक का प्रस्तुत कर सकता है और दूसरे दिन ही सदन की कार्यवाही के लिए उत्तर रख सकती है तथा विषय समिति के पास बिना भेजे हुए ही उस पान तक करवा सकती है।"

प्रवर या विनिष्ट समितियाँ (Select Committees)—इन समितियों की नियुक्ति समय-समय पर किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है और सदस्यों की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है। अपना काम पूरा करत हों व समाप्त हो जाती हैं। इनकी स्थापना मन्व्य निश्चित नहीं है।

सम्पूर्ण सदन की समिति (Committee of the Whole House)—यह समिति वित्त विधेयको सहित अन्य महत्वपूर्ण एवं विवादग्रस्त विषयों पर विचार विमर्श करती है। यह समिति वस्तुतः सदन के सब सदस्यों की होती है। जब कोई सदस्य ऐसी समिति के लिये प्रस्ताव रखता है तो सदन समिति का रूप धारण कर लेता है। सदन और समिति में अन्तर केवल इतना ही होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष सभापतित्व करता है जब कि समिति की बैठक में वह नहीं बैठता। उसके स्थान पर समिति के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति सभापतित्व करता है। मेम (Mace) जो अध्यक्ष का अधिकार चिह्न होता है, मेज के नीचे रख दिया जाता है। सम्पूर्ण सदन समिति की गणपूर्ति के लिए केवल 100 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसमें भाषण की सीमा केवल पांच मिनट प्रति व्यक्ति प्रति विधेयक निधारित होती है जब कि सदन की बैठक में एक विधेयक पर एक व्यक्ति एक घण्टा तक बोल सकता है। सम्पूर्ण सदन समिति का प्रयोग अधिकांशतः प्रतिनिधि सभा में ही होता है, सानेट उसका प्रयोग बहुत ही कम करती है।

सम्मेलन समिति (Conference Committee)—इस समिति का निर्माण उस समय किया जाता है जब किसी विधेयक पर कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद होता है। इस समिति में दोनों सदनों में से बराबर बराबर सदस्य लिये जाते हैं—प्रायः तीन तीन सदस्य, किन्तु बिनाप दशा में पांच पांच सदस्य भी लिये जाते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर मतभेद सुलभान का प्रयत्न करते हैं। मतभेद का सुलझाने के अपने प्रयत्नों की समाप्ति के बाद सम्मेलन समिति स्वयं ही समाप्त हो जाती है। समिति की बैठकें गुप्त होती हैं और इसकी कार्यवाही का कोई लेखा नहीं रखा जाता। मसौदा तैयार हो स समिति विधेयकी के केवल विवादग्रस्त भागों पर ही विचार करती है, परन्तु व्यवहार में अन्य भागों पर भी विचार करके यह इस बात का प्रयत्न करती है कि दोनों सदनों के मतभेद किसी प्रकार समाप्त हो जाय। सम्मेलन समिति में प्रत्येक सदन एक इकाई के रूप में मत देता है। सदस्यों का अपने-अपने सदनों से भी आदेश दिये जा सकते हैं। प्रायः सीनेट के सदस्य ही जो परिपक्व राजनीतिज्ञ होते हैं और जिन्हें ममदीय अनुभव होता है, अंत में सफल होते हैं।

संयुक्त समितियाँ (Joint Committees)—ऐसे विषयों की जांच के लिये जिनमें संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता हो या जिन पर दोनों सदनों का समवर्ती अधिकार क्षम हो, उनका तय करने के लिए कांग्रेस द्वारा संयुक्त समितियों का निर्माण किया जाता है। कार्य की समाप्ति पर ये समितियाँ भी समाप्त हो जाती हैं।

हाचलन समिति (Steering Committee)—अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण होने से ब्रिटेन की तरह मन्त्रिमण्डल विधि निर्माण

कृत्रिम नहीं करता। 'अतः' प्रश्न पर संचालन समिति का निमाण किया जाता है जिसका कार्य बहुमत दल की तरफ से विधि निमाण का कार्य करना होता है। इस समिति का चयन नदन के बहुमत दल द्वारा अपन दल के सदस्यों में से किया जाता है और नदन के बहुमत दल का नेता इसका अध्यक्ष होता है। बहुमत दल की ओर से यही समिति विधेयकों का रजम प्रस्तुत करती है और अपन दल के सम्मेलन केवल पर उने सदन में पारित भी करती है।

समितियों के महत्व का दस्तावेज हुए अध्यक्ष Thomas B Reed का मत है कि "समितियाँ सदन की आयुवान हाथ और सभी-जो वृद्धि का कार्य भी करती है।" राष्ट्रपति विलसन ने समितियों का 'लिटिल यन्त्राधिकार' (Little Legislatures) कहा है।

अमरिका की समिति व्यवस्था पर्याप्त प्रभावशाली साबित हुई थी कुछ प्रमुख दोष लिये हैं—(i) एक समिति के कार्य और दूसरी समिति के कार्य के बीच प्रायः सामंजस्य नहीं होता। अतः समितियों द्वारा एक ही विषय पर अपने कानूनों में परस्पर भय, विरोध तथा भ्रम फलन की गुंजाइश रहती है। (ii) समितियाँ सदन के सब मतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यद्यपि सभी समितियाँ प्रायः द्वि-दलीय होती हैं किन्तु वे बहुधा विविष्ट हितों की साधना करने वाली बन जाती हैं। (iii) अनेक समितियाँ प्रायः निष्क्रिय रहती हैं। उनके पास बहुधा कोई कार्य नहीं रहता।

समितियों का अध्ययन

अमरीका में समितियों के अध्ययन का पद विद्यमान महत्व का होता है। वह पण्डितता के आधार पर समिति का अध्ययन करता है और समिति की बैठक बुलाने तथा समिति के विभिन्न समचारियों के चयन की कार्यवाही करता है। समिति के अन्तर्गत नियुक्त का जाने वाली उप-समितियों के सदस्यों की भी नियुक्ति उसी के हाथ में है। सदन में वही विधेयकों का संचालन करता है। यद्यपि सजातिक रूप में समिति को यह अधिकार है कि वह अध्ययन द्वारा सन्नि प्रयोग पर नियन्त्रण रखे, लेकिन व्यवहार में बहुत कम समितियाँ ही ऐसी हैं जो अपन अध्ययन पर अपनी-अपनी शक्तियों का स्वतन्त्र प्रयोग करते हैं उल्टा व परस्पर एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हुए कार्य करते हैं, बल्कि प्रद और एकतावद्ध कानूनों को स्वीकार करने के लिये परस्पर कोई सम्पर्क नहीं करते और एक मत होने का कोई प्रयास नहीं करते। उनमें एक सहकारी नस्थान के रूप में कार्य करने का निम्नी प्रकार का विचार नहीं होता। इनके अतिरिक्त व निष्पत्ति का कोई ध्यान न रखते हुए पण्डित अपने दलीय हितों की साधना व निहित स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं।

ब्रिटिश व अमेरिकन समिति व्यवस्था पर एक तुलनात्मक टाँट

(1) स्थायी समितियों की संख्या ब्रिटेन और अमेरिका में भिन्न भिन्न है। ब्रिटेन में स्थायी समितियाँ लोकसभा में केवल 5 हैं, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में इनकी संख्या 10 तक है। समितियों के सदस्यों की संख्या में भी दोनों देशों में अंतर पाया जाता है। ब्रिटिश समितियों के सदस्यों की संख्या प्रायः 20 से 30 तक होती है और आवश्यकतानुसार अस्थायी सदस्य सम्मिलित होकर उनकी संख्या 30 से 50 तक हो जाती है। परंतु अमेरिका में यह सदस्य संख्या प्रायः 30 से अधिक नहीं हो पाती। हाँ, कुछ विशेष अवस्थाओं में अवश्य बढ़ जाती है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका में अनिश्चित सदस्यों को लेने की व्यवस्था नहीं है। अमेरिकन समितियों में केवल नियमित सदस्य ही रहते हैं।

(2) ब्रिटेन में जहाँ सभी स्थायी समितियाँ सदैव क्रियाशील रहती हैं, वहाँ अमेरिका में केवल कुछ ही स्थायी समितियाँ कार्यशील रह पाती हैं। 12 से लेकर 15 तक समितियाँ तो इस प्रकार की हैं कि जिनके पास प्रायः कोई कार्य नहीं रहता।

(3) ब्रिटेन की लोकसभा में विभिन्न समितियों का चुनाव 'चयन समिति' (Selection Committee) के द्वारा होता है, जबकि अमेरिका में दलों के नेता समितियों के लिए एक समिति को चुनते हैं और यह समिति विभिन्न दलों के सदस्यों को चुनती है। इसके अलावा समितियों में सदस्य-संख्या सदन के दलों के सदस्यों की संख्या के अनुपात में होती है। परन्तु यह समानता अवश्य है कि दोनों ही जगह सिद्धांततः सदन ही समितियों का निर्माण करते हैं।

(4) अमेरिका में स्थायी समितियों के निर्माण के आधार विषय होते हैं और उसी विषय के अनुसार, जिसे वह समिति निपटाती है, उसका नामांकन किया जाता है। परंतु ब्रिटेन में समितियों का निर्माण विषयवार नहीं होता। वहाँ किसी भी समिति में कोई भी विषयक भेजा जा सकता है। इसके अनिश्चित वहाँ वर्णमाला के क्रमानुसार समितियों का नाम 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' आदि रख दिया जाता है।

(5) ब्रिटिश समितियों में सदस्यों की ज्येष्ठता या वरिष्ठता (Seniority) पर इतना विचार नहीं होता, जितना अमेरिका में। यही नहीं, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी दोनों देशों में भिन्न प्रकार से की जाती है। अमेरिका में समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति बहुमत दल की वही एजेंसी करती है जो समिति के बहुमत दल के सदस्यों की सूची बनाती है। इसके विपरीत ब्रिटेन में यह काम चयन समिति करती है। वह कुछ नियुक्तियों का एक पैनल (Panel) बना देती है और वे लोग मिलकर अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं। ब्रिटेन में सदस्यों की व्यक्तिगत योग्यताओं को ही महत्व दिया जाता है न कि ज्येष्ठता को। ब्रिटिश समितियों के अध्यक्ष नियुक्त

होकर कार्य करते हैं, अतः वहाँ यह आवश्यक नहीं होता कि समिति का अध्यक्ष बहुमत दल का ही हो।

(6) अमेरिका में समितियों का स्थान व्यवस्थापन क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें विधेयक का अन्त करने तक का अधिकार है यह भी आवश्यक नहीं है कि वे विधेयक की रिपोर्ट सदन को दें। ब्रिटन में समितियाँ विधेयक के साथ जीवन और मौत का खेल नहीं खल सकती। उनके लिये यह भी जरूरी है कि वे सदन को प्रत्येक विधेयक की रिपोर्ट दें।

(7) अमेरिका में समितियाँ का स्वयं ही उप समितियाँ (Sub Committees) बनाने का अधिकार है, परन्तु ब्रिटन में समितियाँ ऐसा नहीं कर सकती।

(8) अमेरिका के सदन ब्रिटन में कोई सम्मेलन समिति, नियम समिति और मंचालन समिति नहीं पाई जाती दूसरी ओर, ब्रिटन की तरह संघीय समितियाँ और व्यक्तिगत विधेयक समितियाँ (Sessional Committees and Private Bills Committees) अमेरिका में नहीं पाई जाती।

(9) ब्रिटन में लोकसभा की समितियों के अध्यक्षों को विधायक प्रतिनिधि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वे तटस्थ होते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में समितियाँ व अध्यक्ष दलगत राजनीति में फसे रहते हैं और उन्हें इतनी प्रमुखता प्राप्त होती है कि महत्वपूर्ण विधेयकों के नाम तक समितियों के अध्यक्षों के नामों पर रख दिए जाते हैं।

(10) ब्रिटन में सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पथक-पथक समितियों में भेजे जाते हैं। परन्तु अमेरिका में गैर सरकारी और सरकारी विधेयकों के बीच इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वहाँ सरकारी विधेयक भी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। इस तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि अमेरिका में ब्रिटन की अपेक्षा समितियों की शक्ति बहुत अधिक है। व एक प्रकार से विधायिनी शक्ति के यंत्र में तल का काम करती है। यह कहना युक्तियुक्त है कि ब्रिटन में विधि निर्माण सम्बन्धी महत्व कार्यपालिका को प्राप्त है, जबकि अमेरिका में विभिन्न समितियों का।



राष्ट्रपति (THE PRESIDENT)

“एक बार प्रकट हो गई यह शका कि राष्ट्रपति ‘निरंकुश शासक’ हो जाएगा, निमूल सिद्ध हो गई है। राष्ट्रीय मस्तिष्क में अमेरिका की सरकार के सिद्धान्तों की जड़ें इतनी गहराई तक पहुँच गई हैं कि उनके उल्लंघन करने का प्रयत्न करते ही देश में असंतोष का तूफान उठ खड़ा होगा।’

—ब्राइस

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद, विश्व की कायपालिकाओं में शक्ति और सम्मान की दृष्टि से अत्यन्त महत्व और प्रभान का पद माना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक ही है, मर्यादात्मक नहीं। परन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति में ये दोनों ही बातें हैं।

योग्यताएँ, पदावधि, वेतन, पदव्युक्ति आदि

संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख इस प्रकार है—(क) वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, (ख) ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एवम् (ग) कम से कम १४ वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इन सांविधानिक योग्यताओं के अतिरिक्त राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का व्यावहारिक रूप से निर्धारण राजनीतिक दल करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति का ही छांटते हैं जो अधिकाधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल हो सके।

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल ४ वर्ष है। इस अवधि में वह स्वयं त्याग पत्र देकर अथवा मृत्यु हो जाने पर अथवा महाभियोग द्वारा ही अपने पद से पृथक् हो सकता है या किया जा सकता है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है और उमकी सुनवाई सीनेट द्वारा होती है। सुनवाई के समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। दो-तिहाई बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति का अपराधी घोषित कर सकता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सिद्ध नहीं किया जा सका है। यह अभियोग देशद्रोह, घूसखोरी अथवा अन्य गम्भीर अपराधों के कारण ही लगाया जा सकता है।

संविधान में राष्ट्रपति पद पर एक ही व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कुछ नहीं कहा गया था। जय १८५७ के एक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति दो बार से अधिक नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल ३६६ दिन वास्तव में पदवात्त आने वाले वर्ष की २० जनवरी की दोपहर का समाप्त होता है।

राष्ट्रपति के वजन में अति अधिक के सम्बन्ध में संविधान मौन है। इनका निश्चय कार्य में ही करना है जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। १९४६ में अमेरिकन राष्ट्रपति का १ लाख डॉलर वार्षिक वेतन दिया जाता है। जय वर्षों के लिये ५० हजार डॉलर वार्षिक और मिलता है जिस पर आय-कर नहीं लगता। रहने के लिये १७ एड्ड भूमि घरे हुए "हाइट हाउस" (White House) नामक सुंदर भवन मिला हुआ है। इनके अनिश्चित राष्ट्रपति का और भी विपुल सुविधाएं मिली हुई हैं। जगम्भ १९५८ के एक विधायक के अनुसार नवभूत राष्ट्रपतिया का और उनकी विधायी का पेशान की व्यवस्था कर दी गई है।

राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में नहीं भी आ जा सकता है। किसी भी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जबल महाभियोग ही एक अपवाद है। इन चलाने का अधिकार भी केवल कांग्रेस का ही प्राप्त है।

उत्तराधिकार के सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उस राष्ट्रपति उत्तराधिकारी होता है और यदि दोनों ही नहीं हों तो कांग्रेस ही नियम करती है कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। १९४७ में राष्ट्रपति और उस राष्ट्रपति के उत्तराधिकार का एक नया क्रम कांग्रेस द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

(Election of the President)

राष्ट्रपति का निर्वाचन आज अमेरिका के राजनीतिक जीवन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात बन गई है। संविधान निमाताओं ने यह कभी नहीं चाहा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा जटिल और सुविधाहीन कार्य हो जिससे सम्पूर्ण देश में उत्था-मुल्ल मच जाए। उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि करोड़ों मतदाता अमेरिकन राष्ट्रपति को चुनने का निर्णय करेंगे। वास्तव में अमेरिकन संविधान निमाताओं का दावा था कि वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करके ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकते हैं। वास्तव में वास्तव में कार्य का प्रभुत्व बना रहता दूसरा यह था कि यदि राष्ट्रपति का जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करेगी तो इस बात की सम्भावना रहेगी कि उत्साही राजनीतिज्ञ (Demagogues) इस पद पर पहुँच जाए। अतः इन दोनों ही भयों

से मुक्त रहने के लिए सविधान-निर्माताओं ने राष्ट्रपति पद को भरने के लिए दोनो में से किसी भी रीति को न अपनाकर एक ऐसी रीति अपनाई जो आसुल और दुब्यवस्था का यथासम्भव कम सम्भव हो सके। जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सविधान निर्माताओं ने सविधान-में सन्द्घाति की जो निर्वाचन पद्धति दी वह इस प्रकार है—

“प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार कुछ निर्वाचित चुने और उन निर्वाचकों की सभ्या उस राज्य की सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होगी। समय आने पर निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्र हों और लिखित रूप में अपने वाट दा व्यक्तिगत रूप से जिनमें कम से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे नियुक्त हुए हैं। इसके बाद वाट दा का सङ्कलन मिला जाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाये जो वाट दा के दोना सदना की उपस्थिति में उनका गिने और परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति का सबसे अधिक वाट प्राप्त हुए हो वही राष्ट्रपति बने वरन्हीं कि वह सब व्यक्तियों में से पूर्ण बहुमत से निर्वाचित हो। उससे कम वोट पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उप राष्ट्रपति बने।” यह भी व्यवस्था की गई है कि मत-गणना के परिणामस्वरूप यदि किसी भी प्रत्याशी का आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न प्रतिनिधि सभा को भेज दिया जाये जो सबसे अधिक मत पाने वाले उन तीन प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति का चयन करें जिनके नाम सीनेट के अध्यक्ष द्वारा उसके पास भेजे जाए। प्रतिनिधि सभा इस प्रकार जब राष्ट्रपति का चुनाव करे तो सभा के सदस्य राज्यवार मतदान करें और उनके मतों की गणना “एक राज्य एक मत” के आधार पर हो। उप राष्ट्रपति के विषय में आवश्यकता पडने पर ऐसा ही सीनेट में किया जाये।

अमेरिकन सविधान निर्माताओं ने ‘टुमल्ट’ और अव्यवस्था (Tumult and disorder) की टालन की दृष्टि से निर्वाचकगण (Electoral Club) की पद्धति का अपनाकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election) की व्यवस्था की। प्रथम दो निर्वाचन सत्राधिक उपराध के वास्तविक अर्थ के अनुकूल सम्पन्न हुए, लेकिन तृतीय निर्वाचन (१७९२ ई.) में कुछ तथा चौथे निर्वाचन (१८०० ई.) के समय स्पष्ट परिवर्तन हो गया और आज तो व्यवहार में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा ही नहीं है। ग्रिफिथ (Griffith) के बयानानुसार, “राष्ट्रपति का निर्वाचन अब ‘प्रयाग का एक ऐसा ढांचा बन गया है जिसका सविधान में कोई सम्भव नहीं है, पर जिनके कारण मूल उद्देश्य बहुत कुछ बदल गया है।”

राष्ट्रपति का निर्वाचन आज केवल सिद्धांततः अप्रत्यक्ष है, अथवा व्यवहार में वह पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव अब राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा न होकर सीधे जनता द्वारा होता है और जनता जिस दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति

पद के निर्वाचक मंडल के लिए चुन देनी है, उसी दल का प्रत्याशी राष्ट्रपति बनता है। वर्तमान समय में देश में दो शक्तिशाली राजनीतिक दल विद्यमान हैं। ये दोनों ही दल राष्ट्रपति पद के लिए अपने-अपने प्रत्याशी सट्टे करते हैं और जैता निर्वाचक मंडल के सदस्य का चुनकर ही प्रायः यह निश्चित कर देती है कि किस दल का प्रत्याशी राष्ट्रपति होगा।

वर्तमान में व्यवहार में राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न रीति से होता है—
(1) प्रत्याशियों का नामांकन और प्रचार—राष्ट्रपति निर्वाचन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी प्रत्याशियों का नामांकन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूरे जनवरी के महीने में प्रत्येक राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय सम्मेलन (National Convention) बुलाता है। प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पदों के लिए अपने-अपने दल के उम्मीदवारों को नामांकित (Nominate) करता है।

उप राष्ट्रपति पद के लिए प्रायः उसी व्यक्ति का लिया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से भिन्न राज्य का निवासी हों। प्रायः ऐसा भी किया जाता है कि यदि राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी देश के एक भाग का निवासी है तो उप राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी देश के दूसरे भाग का निवासी होता है। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का नामांकन कर देने के उपरांत तुरंत ही दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में देश व्यापी प्रचार प्रारम्भ कर देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की यह लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई समझी जाती है।

(2) राष्ट्रपतीय निर्वाचकों का निर्वाचन—राष्ट्रपति के निर्वाचन की दूसरी सीढ़ी राष्ट्रपतीय निर्वाचकों (Presidential Electors) का निर्वाचन है। प्रारम्भ में निर्वाचक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित होते थे। बाद में इस प्रणाली को त्याग दिया गया और एक नई प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा जिसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल या तो अपनी प्राथमिक मस्यौदा (Primaries) या राज्यों के सम्मेलनों (State Conventions) द्वारा प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार पेश करती है। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने उसका क्षेत्रफल के क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन व्यक्तिगत नहीं होता है। निर्वाचक मंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों को मतदान करना होता है, जो मतदान के बाद ही निर्वाचक मंडल के निर्वाचक मंडल के लिए होता है क्योंकि जिस दल के प्रायः जितने निर्वाचक मंडल के लिए चुना है, वही स्वतः ही निर्वाचक मंडल के लिए चुना जाता है।

तत्पश्चात् नवम्बर माह के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को (जो निर्वाचन का दिन होता है) सब मतदाता अपने अपने राज्य में एकत्र होकर इन निर्वाचकों के लिए अपना अपना मत देते हैं। इस निर्वाचन में प्रत्याशियों की योग्यता पर प्रायः कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उनका किस दल से सम्बन्ध है, इसी का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्पष्ट है कि वह दल जो राज्य में बहुमत प्राप्त करता है, समस्त निर्वाचकों को निर्वाचक-मण्डल में भेज देता है। इस प्रकार राष्ट्रपतीय निर्वाचकों का निर्वाचन ही, जो कि प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन निश्चित कर देता है। संविधान द्वारा निश्चित राष्ट्रपति के निर्वाचन-पद्धति की शपथ सीढ़िया केवल औपचारिक मात्र हैं।

(3) निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान—निर्वाचित होने पर ये निर्वाचक अपने-अपने राज्यों की राजधानी में एकत्र होते हैं और दिसम्बर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले पहिले सोमवार को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं।

(4) मतगणना व परिणाम—तत्पश्चात् सभी राज्यों के मतपत्रों को प्रमाणित करके सील किये हुए लिफाफों में सीनेट के अध्यक्ष के पाम वाशिगटन भेज दिया जाता है वहाँ सीनेट के अध्यक्ष द्वारा व लिफाफे बाग्स के दाना सदनों के सदस्यों के सामने खोल जाते हैं, मतगणना की जाती है और परिणाम की घोषणा की जाती है। जो प्रत्याशी निर्वाचकों के मतों का पूरा बहुमत प्राप्त कर लेता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

यदि मतगणना का परिणाम ऐसा निकलता हो जिसमें किसी भी प्रत्याशी की आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा प्रथम अधिकतम मत पाने वाले उन तीन प्रत्याशियों में से एक को राष्ट्रपति चुन लेती है, जिनके नाम सीनेट का अध्यक्ष उसके पास भेजता है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि इस निर्वाचन में सदस्य व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं करते। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों से मिलकर उस राज्य का एक प्रतिनिधि मण्डल बनता है और प्रत्येक मण्डल केवल एक ही मत देता है। गणपूर्ति (Quorum) के लिए दो तिहाई राज्यों की उपस्थिति आवश्यक है। उप राष्ट्रपति पद के विषय में आवश्यकता पड़ने पर ऐसा ही सीनेट द्वारा किया जाता है।

पद व शपथ-ग्रहण—निर्वाचित राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति, संविधान के बीसवें संशोधन के अनुसार, 20 जनवरी का दोपहर के समय पद ग्रहण करते हैं। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराते हैं।

यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा न हुआ हो अथवा राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर पाय तो उसके स्थान पर उप राष्ट्रपति कार्य करेगा।

यदि उप-राष्ट्रपति भी उस दिन मर जाय तो न सम्हाल तो कांग्रेस को यह अधिकार होता है कि वह इसका उचित प्रबंध करे।

राष्ट्रपतिक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन वास्तव में रुपये का खेल है जिसमें पीछे छिपी पद्धतियाँ छिप छिप में संचरित रहती हैं। विशेष प्रकार के उम्मीदवारों के प्रति झुल और छिपे तौर पर पूरे धारणाएँ संचरित रहती हैं, अवांछनीय चारों चली जाती हैं और नकली उम्मीदवार लड़े गये जाते हैं। बाद में मौका आते ही पहले से सोचे समय उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित हो जाता है।

(2) दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों का वातावरण भी तनावपूर्ण, उलझन भरा और गम रहता है।

(3) निर्वाचन के समय छल-बपट अफवाह, अनुचित पड्यन्त्रों आदि का काफी जोर रहता है।

(4) राष्ट्रपतीय निर्वाचक के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसे उस राज्य के सभी निर्वाचकों को चुनने का अधिकार मिलता है। इसका दूषित स्वरूप यह है कि यदि किसी राज्य में किसी दल को 49 प्रतिशत भी मत मिल तो भी वह अपने दल का एक भी निर्वाचक रखने का अधिकारी नहीं होता। यह पर्याप्त सम्भव है कि राष्ट्रपति को जनता का बहुमत मिले भी और न भी मिले, किन्तु निर्वाचक का बहुमत उसके पक्ष में होगा। लिवन और विलसन के चुनाव में यही स्थिति थी।

(5) यह भी अनुचित है कि एक बार साधारण जनता द्वारा निर्वाचक मण्डल के चुन लिए जाने के बाद निर्वाचक मण्डल के सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र रहते हैं कि वे किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। अनेक ऐसे अवसर आए हैं कि जब दल के निर्वाचक मण्डल के सदस्यों ने दूसरे दल के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को मत दिया है।

(6) यह भी सम्भव है कि निर्वाचक मण्डल के मतदान के फलस्वरूप किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो और ऐसी स्थिति में जब निर्वाचक का अंत प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाए तो परिणाम उससे भिन्न निकल जायेगा सामान्यतः होना चाहिए। यह आलोचना अधिक व्यावहारिक नहीं है। अब तब केवल एक बार सन 1824 में ही ऐसा हुआ था जबकि बार प्रत्याशियों में से किसी को भी आवश्यक बहुमत नहीं मिला।

(7) अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का जो व्यावहारिक रूप बन गया है, उसने कारण पद पर अयोग्य व्यक्तियों का आना सम्भव है। निर्वाचक दल के इसारे पर मत देता है न कि उम्मीदवार की योग्यता के कारण। वास्की ने इन निर्वाचकों की तुलना कठपुतलियाँ से की है जो दल की इच्छानुसार मार मरते हैं।

यह आलोचना आसिक रूप से ही मर्यादित है क्योंकि विगत पचास सालों में राष्ट्रपति पद पर अद्भुत योग्यता रखने वाले अनेक राष्ट्रपति आए हैं।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार के सुझाव

राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में जो कतिपय दोष विद्यमान हैं, उन्हें दूर करने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित सुझाव दिये जाते रहे हैं—

(1) राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन हो, चूंकि यह तरीका सरल, प्रजातांत्रिक एवं बहुमत के अनुकूल है।

(2) राज्य निर्वाचकों का चुनाव पूरे राज्य (State at large) के आधार पर न करके क्षेत्रों (Districts) के आधार पर करें।

(3) निर्वाचक गण और निर्वाचकों का मत दे दिया जाए, परन्तु निर्वाचक मत की पद्धति व्यवहार में रहे। राज्यों में राष्ट्रपतीय निर्वाचन के पर्चे (Presidential election bullet) रहे जो लोकप्रिय मत के आधार पर प्रत्याशियों को दिये जाए।

(4) प्रत्येक राज्य में प्रत्यक्ष एवं व्यक्त मताधिकार के आधार पर मतदान हो, तथा राष्ट्रपति पद के लिये प्रत्याशियों का प्राप्त लोकप्रिय मतों के अनुपात में निर्वाचक मत (Electoral vote) मिले।

यद्यपि ये सुझाव अमेरिकावासियों के समक्ष एक-एक कर के रखे जा चुके हैं, परन्तु किसी भी सुझाव के प्रति जनता का मतापजनक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसका अधिकार

(Powers and Functions of the President)

आज राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से व्यापक है। उसकी ये विद्याल शक्तियाँ वस्तुतः अनेक स्रोतों का परिणाम हैं। प्रथम स्रोत संविधान है। यद्यपि संविधानिक उपबंध थोड़े और सीमित हैं, लेकिन उनमें जिस ढंग से राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके विषय अधिकारों को परिभाषित किया गया है, उससे राष्ट्रपति की शक्तियों का भारी प्रसार हुआ है। कांग्रेस को यह भ्रम प्राप्त नहीं है कि वह राष्ट्रपति की संविधानिक शक्तियों को छीन सके या कम कर सके। दूसरा स्रोत याविक निष्पत्ति है जिनके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों के क्षेत्र को उन स्थलों पर परिभाषित किया गया है जहाँ संविधान अस्पष्ट या अत्यन्त सीमित है। इन परिभाषाओं से राष्ट्रपति को अनेक निहित शक्तियाँ (Implied Powers) मिली हैं। तीसरा स्रोत कांग्रेस के अधिनियम हैं जिनसे समय-समय पर राष्ट्रपति को स्व विवेक की शक्तियाँ (Discretionary Powers) मिली हैं। चौथा स्रोत परम्पराएँ एवं प्रथाएँ हैं। इनके द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

यद्यपि अमेरिकन राष्ट्रपति महान् शक्तियाँ का स्वामी है, तथापि वह उपा परिसीमाओं (Limitations) के अन्दर काम करता है और किसी भी दशा में संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अधिक से अधिक वह इतना कर सकता है कि अपनी शक्तियों के प्रयोग के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर ले। राष्ट्रपति की विशाल शक्तियाँ और अधिकारों का निम्नलिखित शीपको के अन्तर्गत प्रकट कर सकते हैं—

कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ को अध्ययन की सुविधा से विभिन्न उप-शीपको के अन्तर्गत प्रकट करना उपयोगी होगा—

(1) शासन संचालन और विधि का पालन कराने की शक्तियाँ—राष्ट्रपति प्रमुख शासक होने के नाते राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय सरकार के प्रशासन सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। प्रशासकीय विभागों का संगठन और विस्तार ता काँग्रेस करती है पर उनका पुनर्गठन और कार्यों का निरीक्षण करना राष्ट्रपति के अधिकार में है। वह देखता है कि संविधान, संविधियाँ और न्यायिक निष्पत्तियों का पालन समस्त देश में हो रहा है या नहीं। शासन के सफल संचालन के लिए उन विभिन्न आदेश, नियम, उपनियम आदि जारी करने का अधिकार है। वह किसी भी विभाग के अधिकारी से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन अवकाश माँग सकता है।

राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह काँग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को पूरी तरह लागू कराए चाहे वह उनमें सहमत हो अथवा नहीं। किसी भी कानून की बाध नीयता अथवा अवांछनीयता का पालन का काम काँग्रेस का है और उनकी वक्षता या अवक्षता का परीक्षण करने का कार्य कार्यपालिका का है।

राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय शपथ लेनी पड़ती है कि वह सशुद्ध राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और उसका पालन करेगा। अतः इस शपथ को निभाने के लिए राष्ट्रपति सदैव सचेष्ट रहता है। यदि किसी ओर से राष्ट्रपति का कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है तो उस अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सेना को उस विरोध का सामना करने के लिए प्रयोग में लाए।

(II) नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियाँ—इन शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अधिकारों की निष्ठा और काँग्रेस के सदस्यों की सक्रिय सहायता प्राप्त होती है। संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह काँग्रेस के निदेशों और कानूनों का क्रियान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार नियुक्तियाँ करे। इनमें उच्चवर्गीय नियुक्तियाँ भी शामिल हैं और निम्न वर्गीय भी। उच्च-वर्गीय पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति और सीनेट दोनों की स्वीकृति से होती हैं जबकि निम्नवर्गीय पदों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही भर सकता है उच्च वर्गीय पदों में मंत्री अथवा सचिव, विज्ञान

म अमेरिकन राजदूत, वाणिज्य दूत, विशेष दूत, सर्वोच्च न्यायालय के यायाधीश, सुरक्षा समिति तथा सर्वोच्च परिषद के सदस्य, केन्द्रीय शासन के अध्यक्ष आदि बड़े-बड़े अधिकारियों के पद सम्मिलित होते हैं। इन सभी की नियुक्तियाँ के मन्त्रालय में मन्त्रिमण्डल के अनुसार सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। व्यवहार में प्रायः सीनेट इन पर अस्वीकृति नहीं देती। 'यायालय के यायाधीश' की नियुक्ति पर जयवा किसी अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति पर निश्चय ही सीनेट बड़े-बड़े विवाद के बाद स्वीकृति देती है। ऐसे ही अवसर आए हैं जब सीनेट ने कुछ नियुक्तियों पर अपनी अस्वीकृति प्रदान की है।

निम्नस्तरीय पदां पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार यद्यपि राष्ट्रपति का है तथापि सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति ने यह भार विभिन्न विभागों के अध्यक्षों पर डाल दिया है।

उल्लेखनीय है कि उच्च स्तरीय नियुक्तियों के विषय में सीनेट के अनुमोदन का आ प्रतिबन्ध है, उसका प्रभाव व्यवहार में राष्ट्रपति की नियुक्ति सम्बन्धी शक्ति पर विशेष नहीं पड़ता। इसका प्रमुख कारण उस प्रथा का प्रचलन है, जिसे सीनेट की 'शालीनता या सौहार्दता' (Senatorial Courtesy) कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा सचीव प्रणालि में की गयी नियुक्तियों को इन्निष्ठ स्वीकार कर लेते हैं कि राष्ट्रपति राज्यां में उनकी पसंद के व्यक्तियों का नियुक्त कर दे। इस परम्परा का लाभ वे सीनेटर भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रपति के दल के नहीं हैं। सीनेट और राष्ट्रपति की इस पारस्परिक सम्बन्ध की प्रथा के प्रचलन ने मन्त्रिमण्डल निर्माताओं के उस उद्देश्य को लगभग सम्पन्न ही कर दिया है, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने नियुक्तियों पर सीनेट की सहमति की व्यवस्था की थी।

राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियाँ उस समय भी कर सकता है जब सीनेट का अधिवेशन नहीं हो रहा है। ऐसी नियुक्तियाँ 'अन्तरिम नियुक्तियाँ' (Recess appointments) कहलाती हैं। पर सीनेट का सत्र आरम्भ होते ही राष्ट्रपति का इन नियुक्तियों के लिए उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है। यदि सीनेट स्वीकृति देने से इन्कार कर दे तो राष्ट्रपति सीनेट का अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद इन नियुक्तियों का पुनर्जीवित कर सकता है। अन्तरिम नियुक्तियों की इस शक्ति के कारण राष्ट्रपति का प्रभाव क्षेत्र बहुत कुछ बढ़ गया है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का दुरुपयोग न करने लगे, इसके लिए यह अनुशङ्का लगा दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति ऐसी किसी जगह पर नियुक्ति करता है, जहाँ सीनेट के अधिवेशन काल में विद्यमान थी, तो उस पर नियुक्त व्यक्ति को तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक उनकी नियुक्ति की पुष्टि सीनेट विधिवत न कर दे।

(11) पदच्युति की शक्तियाँ—इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल ही है तथापि कार्य में प्रायः अन्तिम रूप से यही निष्पत्ति लिया गया है कि पदच्युति का अधिकार

पूरा अधिकार होगा कि वह किसी को भी पदच्युत करे, और इसमें लिए सीनेट की अनुमति आवश्यक नहीं होती। पर इन सम्प्रदाय में निम्नलिखित तीन वर्ग अपवाद हैं, अर्थात् इन वर्गों के अधिकारियों को राष्ट्रपति स्वयं पदच्युत नहीं कर सकता—

(क) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।

(ख) कांग्रेस द्वारा स्थापित विभिन्न आयोगों और बोर्डों के सदस्य, जिन्हें कांग्रेस द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही अलग किया जा सकता है।

(ग) लोक सेवा नियमों (Civil Service Rules) के अनुसार हुई नियुक्तियाँ, जिन्हें केवल तभी विमुक्त किया जा सकता है जब उनके द्वारा लाक-सेवा की कार्यकुशलता में बाधा पड़े।

वस्तुतः राष्ट्रपति के हाथ में राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे पर नियन्त्रण रखने की इतनी अधिक शक्ति है कि वह उसके बल पर लोगों को स्वयंसेवक त्यागपत्र देने पर बाध्य कर सकता है। यह तथ्य भी स्मरणीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निश्चित किया गया है कि मोनेट जयवा कांग्रेस राष्ट्रपति का, किसी अधिकारी को पदच्युत करने के लिए विवक्षित नहीं कर सकती।

(iv) सैनिक शक्ति—युद्ध और शांति दोनों ही समय के लिए राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का प्रधान मेनापति है। इस नाते वही उच्च सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है पर इन नियुक्तियों के लिए सीनेट का अनुमोदन आवश्यक होता है। युद्ध काल में राष्ट्रपति सभी प्रकार के सैनिक अधिकारियों को बलात् करने का अधिकार रखता है। वह आवश्यकता पड़ने पर सभी सेनाओं का फायर करने का आदेश दे सकता है। सरकार के प्रदत्त विरासत की स्थिति में, सब के परि नियमों के अन्तर्गत, वह संयुक्त राज्य की सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। देश की प्रतिरक्षा और शत्रु को पराजित करने के उद्देश्य से वह प्रत्येक आवश्यकता करने का अधिकारी है। वह अमेरिकन सेनाओं को विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति कांग्रेस की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता तथापि युद्ध का समाप्त करने तथा निलम्बित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का ही है। यद्यपि सीनेट की सम्मति से ही वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, किन्तु अपना व्यापक अधिकार और प्रभाव के कारण ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है जयवा सेना का सभी व्यवस्था में लड़ना कर सकता है कि युद्ध अनिवार्य हो जाय।

सेना के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि युद्धकाल में जिन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की जाय, उन पर वह इच्छानुसार शासन करे। विजित प्रदेशों का शासन एक अधिनायक की भाँति वह उस समय तक चलाता है जब तक कांग्रेस नागरिक प्रशासन की व्यवस्था न कर दे।

(v) **वदेशिक विषयो से सम्बन्धित शक्तियाँ**—वदेशिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति ही देश का सबसे प्रमुख प्रवक्ता है। राष्ट्रीय विदेश नीति तथा उसकी परिणामों का उत्तरदायित्व उसी पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को स्वीकार किया है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सवधानिक उपबन्धों के अनुसार हो।

राष्ट्रपति का राजदूतों और विदेशों में अपने दल के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है। विदेशी राजदूता, वाणिज्य दूतों और विशेष दूतों के प्रमाणपत्र वही स्वीकार करता है और इस प्रकार विदेशी सरकारों को मान्यता देता है। किसी राष्ट्र से असन्तोष प्रकट करने के लिए वह उस राष्ट्र के राजनीतिक प्रतिनिधि को हटा सकता है अथवा सम्बन्धित राष्ट्र से मांग कर सकता है कि वह अपने प्रतिनिधि अथवा राजदूत को वापिस बुला ले। राष्ट्रपति ही विदेशों से संधियाँ सम्पन्न करता है और उन पर हस्ताक्षर करता है। यद्यपि इन संधियों अथवा समझौतों पर सीनेट के दो तिहाई मत के अनुममथन (Ratification) की आवश्यकता पड़ती है, तथापि संधि का प्रारूप तयार करने और उसके बारे में सम्बन्धित विदेशी राष्ट्र से बातें करने जादि का कार्य राष्ट्रपति का ही है। व्यावहारिक दृष्टि से वही विदेश नीति की रचना और घोषणा करता है। विदेश नीति का रूप अन्तरस्वयं राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है।

प्रशासकीय अथवा कार्यपालिका समझौते (Executive Agreement) करने का राष्ट्रपति का एकाधिकार है। इन पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त नहीं करनी होती। इन्हें राष्ट्रपति किसी भी अन्य देश के साथ अपने अधिकार से ही कर लेता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध काळ में विश्वमक समुद्री अड्डों के बारे में और ब्रिटिश उपनिवेश का पट्टा पर लेने के सम्बन्ध में जो समझौते ब्रिटेन से किये गये थे, वे प्रशासकीय समझौते ही थे।

वैदेशिक सम्बन्धों के मन्त्रालय में राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकतानुसार गुप्त समझौते भी कर लेता है। अपने व्यापक प्रभाव और अधिकार क्षेत्र के कारण वह गुप्त रूप से किसी विद्वान् को अपने साथ और अपने को किसी विद्वान् के साथ किसी नीति विषय पर चर्चा के लिए बचनबद्ध कर सकता है।

(vi) **स्वविवेकीय शक्तियाँ**—इन शक्तियों के बल पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को किसी काम को करने से राक म्वता है अथवा किसी काम का करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग में न्यायालय रुकावट नहीं डालता। वस्तुतः राष्ट्रपति अपनी व्यापक शक्तियों का स्वामी है कि न्यायालय भी अपने निष्पक्ष का वायाचित्व कराने में राष्ट्रपति पर ही निर्भर है।

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

संविधान निमाताओं का प्रयत्न यह रहा था कि कार्यपालिका के अधिकारों का व्यवस्थापन में कोई हाथ न रहे, किन्तु आज यह देखकर विस्मय होता है कि

सर्वोच्च न्यायपालिका अधिकारी अथवा राष्ट्रपति का विधि निमाण में बहुत बड़ा हाथ है। व्यवस्थापन कार्यों में भाग लेने की शक्ति राष्ट्रपति ने नवविधान के इन शब्दों से ग्रहण कर ली है—“राष्ट्रपति समय समय पर राष्ट्र का स्थिति के सम्बन्ध में कांग्रेस का सूचना देता रहेगा और साथ ही उसके विचार के लिए वह व्यवस्थाओं की स्थापना की सिफारिश भी करता रहेगा जिनका वह आवश्यक तथा उपयुक्त समझना हो।

व्यवस्थापन के क्षेत्र में राष्ट्रपति का निम्नलिखित मुख्य अधिकार हैं—

(i) सन्देश भेजने का अधिकार—राष्ट्रपति कांग्रेस को आन्तरिक और बाह्य परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए सन्देश भेज सकता है और यह सुझाव भी दे सकता है कि क्या किया जाना चाहिए। सन्देश कांग्रेस के ब्लक के पास मौखिक या लिखित रूप में भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति अपने सन्देश में उपायो सुझावों और विवेकों तक का वर्णन कर देता है। ये सन्देश राष्ट्रपति की नीति का स्पष्ट करते हैं और कांग्रेस में उन्हें अपनी कार्यवाही में प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति के सन्देश सामान्यतः पत्रों में प्रकाशित होते हैं जिनके द्वारा वह लाक्षणिक को प्रभावित करता है और कठस्वरूप कांग्रेस राष्ट्रपति के सन्देशों के अनुसार आचरण करने को बाध्य हो जाती है। वैधानिक रूप में कांग्रेस राष्ट्रपति के सन्देशों को मानने का बाध्य नहीं है किन्तु व्यवहार में इन सन्देशों के अनसार ही वह अपना विधायी कार्य प्रारम्भ करती है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बहुत से कानूनों का सूत्रपात केवल राष्ट्रपति के सन्देशों से ही होता है।

(ii) प्रशासकीय आदेश—हाल ही में यह प्रथा चल पड़ी है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रशासकीय आदेश जारी करता है जिनका कानूनी के समान ही बल होता है। सामान्यतः सरकार के कामों को स्वरूप और विस्तार का नियंत्रण करने वाले सामान्य कानून कांग्रेस द्वारा बनाए जाते हैं अतः उनके सम्बन्ध में उपनिर्णय का निर्माण राष्ट्रपति करता है।

(iii) विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार—नवविधान राष्ट्रपति को कांग्रेस के विषय अधिवेशन को आमन्त्रित करने की शक्ति देता है। यह विधि अधिवेशन कुछ दिनों तक चल सकता है अथवा उस समय तक चल सकता है जब तक कि नियमित अधिवेशन आरम्भ न हो। राष्ट्रपति कांग्रेस में नियमित अधिवेशन में अधिन काल तक बैठने के लिए भाग कर सकता है ताकि कानून बनाये जा सकें और यदि वह इस्कार करता है तो वह नियमित अधिवेशन बुलाने के साधन का प्रयोग कर सकता है।

(iv) विलम्बनकारी विरोधाधिकार—राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा बनाये गये विधेयों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। परन्तु यह प्रतिवन्ध या विरोध (Veto) केवल विलम्बनकारी होता है, पूर्ण नहीं (Only suspensive veto, not absolute)। व्यवस्था यह है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के

अनुमति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाकर अनुमति के त्रये जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया हो, उस राष्ट्रपति अपने आभेपा सहित दस दिना (रविवारी को छोड़कर) के भीतर वापिस लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति का निलम्बनकारी निषेधाधिकार अथवा निर्यामित निषेधाधिकार (Suspensive or Regular Veto) कहलाता है। इस प्रकार लौटाये गये विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकते, जब तक कि कांग्रेस के दोनों सदना म दो-तिहाई बहुमत से जम के तसे पाम न हो जाय। यदि विधेयक कांग्रेस द्वारा पुनः पाम कर दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति का निलम्बनकारी निषेधाधिकार बहुत काम का है क्योंकि इससे वह जन्मदाजी से विधेयक व्यवस्थापन पर फिर से विचार करने के लिये कांग्रेस को बाध्य कर सकता है।

(४) जेबी निषेधाधिकार—विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक अन्य प्रकार का भी निषेधाधिकार प्राप्त है जिसे जेबी निषेधाधिकार (Pocket Veto) कहा जाता है। व्यवस्था यह है कि जब कांग्रेस का सत्र चल रहा हो, उसमें यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिये जाता हो और राष्ट्रपति की ट्रेजिल पर ही दस दिन पड़ा रह जाता हो तो वह स्वतः ही कानून बन जाता है चाहे राष्ट्रपति ने उन पर निगाह भी न डाली हो, परन्तु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास कांग्रेस-सत्र के अंत के निकट भेजा जाता है और दस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही सत्र विघटित हो जाता है तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई कार्यवाही न करके उसकी हत्या कर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कांग्रेस का सत्र के अन्तिम दस दिना में वह किसी भी विधेयक का बिना स्वीकृति या अस्वीकृति दिए पड़ा रहने देता है, तो उसे कांग्रेस फिर अपने दो-तिहाई बहुमत से भी पारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका सत्र समाप्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह विधेयक बिना अस्वीकृति के ही अस्वीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार कोई कार्यवाही न करके ही (By mere inaction) विधेयक को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार (Pocket Veto) कहलाता है।

राष्ट्रपति की निषेध शक्ति का वर्णन करते हुए फाइनर ने कहा है कि 'यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ व्यय नहीं करना पड़ता और जिसके प्रयोग करने से सफलता की आशा तो रहनी है, दण्ड का भय नहीं रहता। देश के विधान मंडल में लड़ी हुई व्यवस्था सम्बन्धी लड़ाई को कांग्रेस का कोई भी पक्ष केवल इतनी ही दूर भेज सकता है जितनी दूर राष्ट्रपति ने कुछ दूसरे ध्यानात्मक शब्द लिखने में लगावे। इस 'न' का उल्लेख पुनर्विचार द्वारा दो तिहाई मत से ही हो सकता है जो कांग्रेस की बहुलता और दोनों सदना में पक्षों की विभिन्नता के कारण सम्भव नहीं है।'

स्मरणीय है कि राष्ट्रपति की नियुक्तियों का प्रयोग प्रस्तावित सावधानीव सन्तोषना पर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण विधायक का वोटो विभाजित जाता है, असा का नहीं।

(vi) संरक्षण शक्तियाँ—राष्ट्रपति अपनी विनाश संरक्षण शक्ति द्वारा कांग्रेस में अपने विधायकता का समर्थन करा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा बहुसंख्यक नियुक्तियों की जाती हैं और कांग्रेस में सदस्य अपने दल के अनुयायियों के लिए लोक रियासत हैं। इनको नागरिकों द्वारा किये गये बहुधा राष्ट्रपति का समर्थन करती है।

(vii) जनता से अपील—राष्ट्रपति राष्ट्र का सम्मानित नेता होता है। जब वह कांग्रेस को अपने विरुद्ध समझना है तो वह जनता से सीधे अपील करके कांग्रेस में अपने विराधियों के विरुद्ध लोकमत बनाने की सफल चेष्टा कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपतियों में कई बार इस शक्ति का उपयोग कांग्रेस को सही पथ पर लाने के लिये किया है।

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

संविधान के अनुसार वित्त सम्बन्धी अधिकार यद्यपि कांग्रेस का ही प्राप्त है, परन्तु व्यवहार में वित्तीय क्षेत्र में भी कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। वजेट के सम्बन्ध में नीति निर्धारण या दोनों सदनों के मध्य सहयोग के लिए कोई प्रभावशाली निकाय नहीं है, अतः व्यवस्थापिका नतदब के लिए गुप्ततः कार्यपालिका पर निर्भर करती है। सन् 1921 के वजेट एंड अकाउंटिंग अधिनियम (Budget and Accounting Act of 1921) ने राष्ट्रपति को वजेट का निर्देशक बनाकर व्यवहार में उसे सरकार का व्यावसायिक प्रबन्धक (Business Manager) बना दिया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त के मामले में कांग्रेस को पूरी सूचना देता है। वही आगामी वर्ष के लिए नियोजित याजना तयार करके उसे प्रस्तावित करता है और नये वर्ष का प्रस्तावित करता है। भारत वजेट राष्ट्रपति के संरक्षण में तयार किया जाता है और कांग्रेस उस बहुधा पारित कर देती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी आज कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कुछ राष्ट्रपति के हाथ में आ गया है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस क्षेत्र में मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनेक ऐसे अवसर आये हैं जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित आरुढा में कटौतियाँ और परिवर्तन किये हैं।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

प्रधान प्रशासनाधिकारी होने के कारण राष्ट्रपति को अपराधों को क्षमादान करने, उसके प्राणदण्ड को स्थगित करने के विधायक अधिकार हैं। अपने क्षमादान के अधिकारों का प्रयोग यद्यपि राष्ट्रपति कांग्रेस एवं यामान्यों से पूरा स्वतंत्र होकर करता है, तथापि इनके प्रयोग में उस पर दो वैधानिक सीमाएँ

है—1 जिस व्यक्ति को महाभियोग द्वारा दण्डित किया गया हो, राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता, एव 2 राष्ट्रपति केवल उही मामले में अपने क्षमादान के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिनमें अपराध सघीय कानूनों के विरुद्ध किया गया हो, न कि किसी राज्य के कानून के विरुद्ध।

यदि अपराधी राष्ट्रपति को क्षमादान के लिये प्रार्थना पत्र भेजे तो राष्ट्रपति उस प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित कोई भी कायवाही कर सकता है—

1 पृष्ठ छद्म वा बिना शर्त क्षमादान, 2 शर्तों के आधारे पर क्षमादान, 3 बिना क्षमा किये अभिवचन (Parole) पर मुक्ति, 4 दण्ड घटा देना, 5 प्राण-दण्ड का स्थगित करने अथवा बिना विधिवत् स्थगन के दण्ड देने में विलम्ब करना, एवम् 6 कोई भी कायवाही करने से इन्कार कर देना।

राष्ट्रपति ऐसे अपराधियों को सामूहिक क्षमादान भी दे सकता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप में नहीं अपितु सघीय कानून का भंग करने के अपराध में एक साथ दण्डित किया गया हो। राष्ट्रपति क्षमादान के अपने अधिकार का प्रयोग याय विभाग की सिफारिश के अनुसार ही करता है। साधारणतया राष्ट्रपति का कार्य सिफारिश को लागू करना मात्र होता है, परन्तु जो कुछ भी किया जाता है उसका अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और इस दशा में वह कार्यस एव न्यायालयों से पूर्ण स्वतन्त्र होता है।

दलीय नेता और राष्ट्र नेता के रूप में

राष्ट्रपति को दलीय नेता और राष्ट्रीय नेता के रूप में महती शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को दलगत स्थिति से ऊपर रहने की योजना बनाई थी, परन्तु वे सफल न रहे। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में दल पद्धति का अस्त्युदय हो जाने के बाद से राष्ट्रपति दल के नेता और प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होने लगे और आज तो राष्ट्रपति द्वारा दल का नेतृत्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के दलीय नेतृत्व के कार्यक्रम से कम महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। दल के नेता के रूप में ही वह निर्वाचित होता है और दल के अनुयायी उसके मलाहकार होते हैं। अपनी विधायी योजनाओं के लिये राष्ट्रपति अपने दल के कार्ग्रेन सदस्यों पर निर्भर करता है। सम्पूर्ण दल में राष्ट्रपति ही दल का एक मात्र सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है और दलीय नीतियों के शिरोधार्य के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र की आँखें उसकी तरफ लगी रहती हैं। राष्ट्रपति का दल के सर्वोच्च नेता और निदेशक की स्थिति प्राप्त हुई है। इस स्थिति में वह दल की राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष हो जाता है और कार्ग्रेस एव अन्य पदा के लिये प्रत्याशियों का चयन मुख्यतः उन्हीं के हाथ में चला जाता है।

राष्ट्रपति केवल अपने दल का ही नेता नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्र का नेता होता है। ब्रिटिश मन्त्रिमंडल की भाँति वह अपने राष्ट्र का प्रताप है और अमरिवन राजनीतिक जीवन की धुरी है। उसे देश का नायक विधाता तथा रक्षक कहा

जाता है। वह सभी मामलों में राष्ट्र का प्रबलता है। महत्वपूर्ण एवं नाजुक वस्तुओं के व्यवहार में राष्ट्र के लिए गहरी अभिरुचि का विषय बन जाते हैं। अतः वह राष्ट्रीय राजनीति के रणमंच का केंद्र बिंदु है। उसमें राष्ट्रीय जीवन की एकता को रखने की शक्ति है।

संकटकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)

युद्ध आन्तरिक अशांति जयवा आर्थिक संकट से उत्पन्न राष्ट्रीय संकटों के समय राष्ट्रपति अपार शक्तियों का स्वामी हो जाता है। जब तक संकटकाळ रहता है तब तक जितने भी अधिकारों की वह मांग करता है और जितने भी अधिकारों का वह प्रयोग करता है वे उस प्राप्त हो सकते हैं। 17 मार्च, 1954 को राष्ट्रपति जॉर्ज डी. एम्स ने घोषणा की कि यदि अमेरिका का राष्ट्रपति दश पर आक्रमण होने पर उसका सामना करने और आक्रान्तों को पीछे हटाने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं करता है (बाह्य युद्ध घोषित करने के लिये उस समय का प्रसंग की स्वीकृति मिल सकती है या न मिल सकती हो) तो वह मृत्यु दण्ड पाने योग्य है। फिर भी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ पर तीन प्रतिबंध पर्याप्त प्रभाव रखते हैं—

- 1 संकट वास्तविक होना चाहिये,
- 2 संकट से सम्बन्धित कारणों का कोई पूरा कानून न हो एव
- 3 संकट की आन्तरिक उत्पत्ति के कारण कारणों से का समुचित कदम उठाने का अवसर न मिल पाया हो।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ न घटने के कारण

- 1 वर्तमान युग में राज्य के कार्यों में आसानी बढ़ गई है और अमेरिका जैसे महान् राज्य के कार्यों के विस्तार का तात्पर्य अन्तर्गत लगे हुए ही रहित है। अतः ऐसे महान् राज्य का वास्तविक प्रमुख हानि के कारण राष्ट्रपति की शक्ति भी बढ़ना स्वाभाविक है।

- 2 अमेरिका में कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति आन्तरिक तथा बाह्य संकटों का मुकाबला करने में अधिक मजबूत और साहसी तथा दृढ़ निश्चयी सिद्ध हुए हैं। कृत्रिम राष्ट्रपति के अधिकारों में स्वतः बढ़ि हुई है।

- 3 दलीय व्यवस्था के विकास के कारण जोर निर्वाचन के प्रत्यक्ष हो जाने के कारण भी राष्ट्रपति की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी है।

- 4 गृहयुद्ध तथा विद्रोह तथा आधुनिक आविष्कारों ने राष्ट्रपति का महत्त्व और शक्ति और तात्पर्य में जोड़ा है। प्रगति, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा वह जाता है और लोगों के सम्पर्क में रहता है। इनके माध्यम से उमन गहरी अर्थों में अपने को जोड़ने में सक्षम हो जाता है। इन भौतिक साधनों के कृत्रिम राष्ट्रपति के प्रभाव में वृद्धि हुई है। चार्म बोयलर न लगा है कि 'पात्र' आविष्कार,

संघानिक संशोधन में उन्नत राष्ट्रपति की शक्तियाँ अधिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।

5 अमेरिकन जनता मजबूत स्थिति में मिला ऐसी व्यक्ति का नतद्व चाहती है जो सम्पूर्ण देश को एकवद्ध कर सके। अमेरिकन शासन व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के अतिरिक्त और नहीं हो सकता। अतः यही मायता जोर पकड़ रही है कि राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए।

6 अमेरीका के राजनीतिक मंच पर ऐसे राष्ट्रपति हो गये हैं जो नाविक-घानिक उपबन्ध की सरल व्याख्या से मनुष्य नहीं रह पाये और जिन्होंने अपनी शक्तियों की बृहत् व्याख्या की। उन्होंने राष्ट्र नेता के रूप में देश हित के लिए प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया।

7 आधुनिक युग में प्रशासनिक जटिलताओं के बढ़ जाने के कारण कांग्रेस कार्यपालिका से नेतृत्व की आशा करने लगी है। फलस्वरूप राष्ट्रपति के प्रभाव और शक्ति में स्वभावतः वृद्धि हुई है।

8 संविधान में वदेशिक मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। संविधान-निर्माताओं का सम्भवतः यह विचार था कि राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार हों चाहिए कि आवश्यक पड़ने पर परिस्थितियों के अनुरूप तेजी से कार्य कर सके और समस्याओं का सामना कर सके। यदपि क्षेत्र में अमेरीका को जो आज विशाल दायित्व निभाने पड़ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस या सीनेट पूरी तरह नहीं निभा सकती। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति अधिकारिण शक्तिशाली बनता जाय।

9 स्वाटज (Swartz) ने कहा है कि 1949 और 1956 के पुनर्गठन अधिनियम (Re-organisation Act of 1949 and 1956) के अधीन शक्ति के उपयोग ने राष्ट्रपति का अमेरिकन प्रशासन के प्रधान के रूप में अपनी स्थिति अधिक दृढ़ और विस्तृत करने का अवसर प्रदान किया है।

10 अतः, कार्यपालिका में उदारतापूर्वक संविधान की व्याख्या करके राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है।

अमेरिकन राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री

(The American President and the British Prime Minister)

दोनों ही संविधानिक सीमाओं और व्यवहार-पद्धति में बड़े हुए अत्यधिक शक्ति का उपयोग करते हैं। दोनों की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग प्रणालियाँ हैं। शक्ति और अधिकारों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कम भी है और अधिक भी।

चुनाव कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व—दोनों ही अपने-अपने राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ब्रिटिश प्रधान-मंत्री जनता की अप्रत्यक्ष पसन्द (Ct.)

होता है। निर्वाचक गण उसके दल को मत देकर उन्हीं पद पर वासीन करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मित्र वह अधिक ध्यान आवेष्टित करता है।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री का कार्यकाल मरद के विश्वास पर निर्भर है जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष मुनिश्चित है। प्रधानमंत्री अपने मन्त्रिमण्डल सहित मसद के प्रति उत्तरदायी है। उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है और उसे जब म ही त्यागपत्र रखे रहना पड़ता है। राष्ट्रपति का राष्ट्रसभा के प्रति ऐसा कोई उत्तर दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रसभा की आलोचना और अविश्वास की परवाह नहीं करता। कांग्रेस के केवल महाभियोग सिद्ध करके ही उसे हटा सकती है, जो अत्यन्त ही कठिन है।

अधिकार एवं शक्त—इन क्षेत्र में वही प्रधान मंत्री का पलड़ा भारी है तो वहीं राष्ट्रपति का।

(क) राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल का सब सर्वाधिकार होता है। मनानमन और पदच्युति के सम्बन्ध में उनका एकाधिकार है। राष्ट्रपति की मन्त्रिपरिषद् एक परामर्शदाता मस्या के रूप में है जिसके परामर्श की मानना या ठुकराना पूर्णतः राष्ट्रपति की इच्छा पर है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह मन्त्रिपरिषद् से परामर्श लें। दोनों का सम्बन्ध बहुत कुछ स्वामी और सेवक सा है। दूसरी ओर वह मन्त्रिपरिषद् का स्वामी नहीं अपितु एक माय नेता होता है जिसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने मन्त्रियों की सलाह लेनी पड़ती है और उस सलाह की इज्जत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री को अनेक अवसरों पर मन्त्रिपरिषद् के बहुमत के दृष्टिकोण को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनाना पड़ता है क्योंकि प्रभावशाली मन्त्रियों से ठुकराने पर उसका नतन और पद दोनों ही व्यर्थ में पड़ सकते हैं। किसी मंत्री से त्यागपत्र मांगने से पूर्व उस अपनी मजबूती का आकलन पड़ता है।

(ख) विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री से कहीं कम है। इन क्षेत्र में प्रधानमंत्री और उसका मन्त्रिमण्डल ही एक प्रकार से व्यवस्थापिका का कार्य करता है। राज्य की विधायी नीति और कार्यों का पथ प्रदर्शन करना, विधायकों को मसद में प्रस्तावित करना और बहुमत के दल पर वहाँ से पारित कराना प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगियों का काम है। मौखिक रूप से मसद वाक्यों का काम होता है। व्यवस्थापिका में बहुमत ने विश्वास का भरोसा प्रधानमंत्री व्यवहार में व्यवस्थापिका का स्वामी बना रहता है और सभी इच्छित विधायकों को वहाँ से पारित कराने में सक्षम होता है। उनका यह क्षेत्र ऐसा व्यापक है कि अमेरिकन कोई विधायी शक्तियाँ नहीं हैं। वह व्यवस्थापिका का भाग ही नहीं है। न वह किसी

कानूनी कार्यवाही में भाग ले सकता है और न इच्छित विषयको का कांग्रेस से पारित ही करा सकता है। वह केवल कांग्रेस से सिफारिश कर सकता है और कांग्रेस को पूर्ण अधिकार है कि वह उसकी सिफारिश को माने या ठुकरा दे। अमरीका की जनता बुरे कानूनों के लिये अपने राष्ट्रपति को दोषी नहीं मानती जबकि ब्रिटन की जनता उनके स्थि प्रधानमंत्री को ही दोषी ठहराती है।

(ग) आर्थिक क्षत्र में भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ही अधिक शक्तिया प्राप्त हैं। बजट का प्रधान मंत्री की देख रेख में तैयार करता है और लोक सभा में उसे पारित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और उसके सहयोगियों का है। यदि बजट में नाममात्र के संशोधन किये भी जाते हैं तो वे प्रधानमंत्री की सहमति से ही किये जाते हैं। किन्तु अमरीका में राष्ट्रपति का वित्तीय क्षेत्र में ऐसा कोई हाथ नहीं है। यद्यपि वहां भी बजट राष्ट्रपति की देख रेख में तैयार किया जाता है किन्तु कांग्रेस के समक्ष न तो वह स्वयं उसे प्रस्तुत कर सकता है और न उसके मंत्री ही। राष्ट्रपति को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति यह भरोसा नहीं होता कि बजट कांग्रेस द्वारा अपन मूल रूप में पारित हो जायेगा। अमरीकन राष्ट्रपति के बजट को पास करना या ठुकरा देना पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में है जबकि ब्रिटन में प्रधानमंत्री बहुमत के बल पर लोकसभा में उसे इच्छानुसार पारित करा लेता है।

(घ) अधिकांश क्षेत्र में अवश्य अमरीकन राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश प्रधान मंत्री से कुछ अधिक दृढ़ है। अमरीकन राष्ट्रपति प्रधान द्वाधिकारी और स्थल, जल व वायु सेना का प्रधान सनापति है। वह सीनेट की सहमति से उच्चवर्ग की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उन्हे पदच्युत करने का भी उसे अधिकार है और इस विषय में उसे सीनेट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। निम्न वर्गीय नियुक्तियां वह स्वविवेक से करता है। इस प्रकार उसे विशाल सरक्षण शक्ति प्राप्त है। राज्य के कानूनों के उचित पालन होने का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। वह अपने विवेक से अभ्यादेश जारी कर सकता है एवं प्रशासकीय समर्थता कर सकता है। सीनेट की सहमति से वह सविया सम्पन्न करता है। अपने व्यापक अधिकारों के बल पर वह ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न कर सकता है कि राष्ट्र अनिवार्यत युद्ध में फँस जाय। मरुत काल में राष्ट्रपति एक प्रकार से पूर्ण तानाशाह बन जाता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथ में नायकारिणी शक्तियां तो होती ही हैं किन्तु साथ ही वह लोकसभा का नेता भी होता है और उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह एक अतिशय विरोधी एवं अव्यक्त लोकसभा को मंत्राट से कह कर बग करा दे। व कि लोकसभा के सदस्य गण नव निर्वाचन का खतरा माल लेना पसंद नहीं करते अतः व प्रायः प्रधानमंत्री का विरोध एक सीमा तक ही करते हैं। यह बात अमरीकन

राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। वह स्वयं मान जायगी या नहीं, यह प्रश्न है, न वह बाध्य मानना है और उन बातों का भंग करने की शक्ति ही प्राप्त है। एक और भी दृष्टि में ब्रिटिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अधिक शक्ति सम्पन्न है और यह है कि उस पर किसी प्रकार के पार्ष्णिक बंधन विधिप्रभाव नहीं डालते। यदि वह संविधान विरोधी तोड़ कर पर भी उस विधि का सर्वोच्च मासाल्य उस अवस्था में मानना होगा कि वह विधान के अमरीकन राष्ट्रपति का पक्ष में मानना होगा कि वह विधान के विपरीत है। किन्तु इसका विपरीत पक्ष है कि यथा सर्वोच्च मासाल्य उन बातों का अर्थ में मानना ही मानना होगा।

कायपालिका की उपरान्त राजाधिकार का अर्थ में मानना ही मानना होगा। इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बिना राजाधिकार के अमरीकन राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से निम्न है ता कि राजाधिकार में वह उच्च अधिकार प्राप्त है। मचाई तो यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में महत्ता बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। राजनीति एक ऐसा खेल है जहाँ निजी व्यक्तित्व की महत्ता बड़ा भाग बना करती है।

राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल (Cabinet of the President)

ब्रिटन की भाँति ही अमेरिका में मन्त्रिमण्डल है किन्तु दोनों की स्थितियाँ में आकाश-पाताल का फर्क है। ब्रिटन में मन्त्रिमण्डल एक महानिर्णयों का समूह है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और एक साथ नैतिक या दूबते हैं। प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है, किन्तु उसकी स्थिति महानिर्णयों में प्रथम की होती है। इसके विपरीत अमेरिकन राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल उसका परिचायक मात्र है जिसके सदस्यों की बात का मानना या दुर्गरा दना पुरा तरह उसकी मर्जी पर है। यद्यपि अपने मन्त्रियों अर्थात् मन्त्रियों की नियुक्ति पर वह सीनेट की स्वीकृति लेता है किन्तु यह केवल मात्र औपचारिकता है। राष्ट्रपति मन्त्रियों को कभी भी पदच्युत कर सकता है और इसका उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः दोनों का सम्बन्ध मालिक और सेवक जमा है।

अमेरिकन संविधान में किसी मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख नहीं है। केवल अनुच्छेद द्वारा २ में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासनिक विभागों के प्रधान पदाधिकारियों से उन विषयों पर लिखित रूप में परामर्श ले सकता है जिनका उन विभागों के साथ सम्बन्ध है। यह व्यवस्था करते हुए संविधान निर्माताओं में से अधिकांश का विचार था कि सीनेट के सदस्य ही राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में कार्य करेंगे। इस विचार का कारण यह था कि सीनेट उस समय एक छोटी सी संस्था थी जिसमें २६ सदस्य थे। दुर्भाग्य-

बश, सीनेट द्वारा परामर्श लेने की परम्परा चल नहीं सकी क्योंकि सीनेट ने राष्ट्रपति की इच्छाओं का खुरकर निरस्कार किया। हार कर, वार्निंगटन ने शासन के प्रमुख अधिकारियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सलाह लेना शुरू कर दिया। सन् १७६१ के बाद ता उ होन प्रमुख विभागाध्यक्षों का प्रायः नियमित सम्मेलन प्रारम्भ कर दिया। उनमें नीति निर्माण के प्रश्नों पर भी सलाह ली जाने लगी। ये ही विभागाध्यक्ष बाद में सामूहिक रूप में मन्त्रिमण्डल (Cabinet) कह जाने लगे। सम्भवतः सन् १७६३ से सर्वप्रथम उनके लिये मन्त्रिमण्डल (Cabinet) शब्द का प्रयोग होने लगा। धीरे-धीरे यह स्थायी व्यवस्था या मस्था के रूप में स्थापित हो गया।

मकट है कि अमेरिकन मन्त्रिमण्डल किसी मश्रंधानिक कानून की उपज नहीं है। टैफ्ट (Taft) ने उनकी सही स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि “मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रपति की इच्छा का उत्पादन है। वह एक ऐसी सस्था है जिनका कोई कानूनी या सवधानिक आधार नहीं है। उसका अस्तित्व केवल प्रथागत है। यदि राष्ट्रपति उसे समाप्त करना चाहता है तो वह कर सकता है।” फिर भी व्यावहारिक रूप में आज मन्त्रिमण्डल की स्थिति सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग की बन चुकी है।

नियुक्ति एवं सगठन

राष्ट्रपति के मन्त्रियों को सचिव (Secretaries) कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या ११ है। ये विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने मन्त्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है, किन्तु सीनेट प्रायः राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करती है। राष्ट्रपति के मन्त्री न कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही उनके प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के गठन में पूर्ण स्वतन्त्र है, तथापि व्यवहार में उसे कुछ बाधा का ध्यान रखना पड़ता है—

(i) यदि किसी एक दो व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का निवाचन में इस आधार पर महत्वपूर्ण सहयोग दिया है कि उन्हें मन्त्रिमण्डल में लिया जाएगा तो राष्ट्रपति उन्हें प्रायः अपने मन्त्रिमण्डल में स्थान देता है।

(ii) राष्ट्रपति यथासम्भव अपने दल के प्रमुख लोगों को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व देता है ताकि दलगत एकता बनी रहे।

(iii) राष्ट्रीय मकट के समय कभी कभी महत्वपूर्ण स्तम्भा को भी मन्त्रिमण्डल में शामिल करना पड़ता है।

(iv) राष्ट्रपति भौगोलिक प्रदेशों तथा विभिन्न प्रमुख वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है।

(v) राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्तियों का मन्त्रिमण्डल में स्थान देने का प्रयत्न करता है जो मन्त्रिमण्डल का साथ काय कर सकें।

मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों का पद साधारण रूप से समान होता है, तथापि विदेशी सचिव को अथवा सहायियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। १६४७ के राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार वास्तुतः द्वारा भी उसका स्थान अथवा महत्त्वपूर्णता में प्रथम रखा गया है।

राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल का पारस्परिक सम्बन्ध

मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक समिति मात्र है जिसमें आलोचना ने उसका परिवार तक कह दिया है। मन्त्रियों की निष्पत्ति पर राष्ट्रपति को सीनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है, किन्तु सीनेट प्रायः राष्ट्रपति की इच्छा का विरोध नहीं करती। कोई भी नया राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद ही अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नाम घोषित कर देता है और वे लोग सामान्यतया तब तक अपने पदों पर काम करने की अपेक्षा रखते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति जब चाहें तब उन्हें पदच्युत कर सकता है और ऐसा करने में उसे सीनेट की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती। और क' वगैरों में, "मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को यह समझ लेना चाहिए कि वह राष्ट्रपति की छत्र छाया में ही जलित रह सकता है।" अमरीका में वास्तविक कार्यपालक केवल एक ही व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपति है और मन्त्रिमण्डल के दूसरे सदस्य तो केवल उसके सहायक मात्र हैं। उनका उत्तरदायित्व पूर्णतः राष्ट्रपति के प्रति ही है। प्रा० लास्की ने लिखा है "अमरीकन मन्त्रिमण्डल यूरोप के प्रतिनिधि वामन के आधार पर स्थापित मन्त्रिमण्डल से विलक्षण भिन्न है। संविधान के अनुसार अमरीकन मन्त्रिमण्डल के सदस्य कायस के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और न वे किसी बाध विवाद में भाग ले सकते हैं। मन्त्रिमण्डल के अधिकारी एकमात्र राष्ट्रपति के सलाहकार हैं। वे कायस का सूचना दे सकते हैं। वे किसी बैठक में अपनी नीति का समर्थन करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। वे जनता में भाषण दे सकते हैं। परन्तु इतना सच कुछ होना पर भी अमरीकन मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति का भावना की उदारता पर निर्भर हैं। यह बात स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति में विमुख नहीं हो सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके लिए सिवाय त्याग पत्र देने के दूसरा कोई मार्ग नहीं रहता। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपनी बैठक में वाक्य बहम कर सकते हैं और राष्ट्रपति को अपना मतभेद प्रकट कर सकते हैं, परन्तु जब राष्ट्रपति कोई बात निश्चयात्मक रूप से कह देता है तब सबको उस स्वीकार करना ही पड़ता है। मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। राष्ट्रपति अपना निम्न मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते उनसे परामर्श ले सकता है, उनसे परामर्श करके अपना निम्न दे सकता है और उनका निम्न अनिवार्य होता है, चाहें समस्त सदस्य उसके निम्न के विरुद्ध क्यों न हों। राष्ट्रपति लिखन द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव वा जब उसके छाता मन्त्रियों ने विरोध किया तो उसने कहा या कि "सात प्रस्ताव के विपक्ष में हो

और एक प्रस्ताव के पक्ष हो, और जोत एक की ही हाती है (Seven naves one ayes and ayes have it) ।”

स्पष्ट है कि अमेरिका में मन्त्रिमण्डल मान एक सलाहकार मण्डल है और वहाँ एक मात्र राष्ट्रपति की इच्छा ही शासन करती है। हर विषय में राष्ट्रपति की ही शक्ति और उसके ही गौरव तथा उत्तरदायित्व की शलक मिलती है। अमरीकन मन्त्रिमण्डल की बैठका का वस्तुतः वह महत्त्व नहीं है जो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की बैठको का है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की बैठको को नियमित रूप से बुलावे ही। वह जब आवश्यक समझता है, मन्त्रिमण्डल की बैठक बुला लेता है। इन बैठको की कार्यवाही प्रायः गुप्त होती है, उनका कोई लेखा नहीं रखा जाता। प्रत्येक विभाग के मामलों के विषय में राष्ट्रपति विभागीय मंत्रियों के साथ पथक पथक वार्ता करता है। अतः पूरे मन्त्रिमण्डल की बैठको में प्रायः सामान्य नीति से सम्बन्धित प्रश्न ही विचाराधीन आते हैं और इसमें भी उद्देश्य केवल राय जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता।

मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य के त्याग पत्र का राष्ट्रपति की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रिटन में या फ्रांस में जब मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है तो प्रधान मंत्री वा सिद्ध चक्रा जाता है और उसके प्रधान मन्त्रित्व तन्त्र का खतरे में पड़ जाने का डर रहता है। लेकिन अमरीका में राष्ट्रपति का कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य जिसे वह पदभ्रष्ट करता है, राष्ट्रपति की स्थिति को खतरे में नहीं डाल सकता। वह समझता है कि मन्त्रिमण्डल तो उसके एक प्रकार से सेवक है जिसकी शक्ति को घटाना बढ़ाना उसके हाथ में है।

स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल का रूप सिर्फ वही है जो राष्ट्रपति उस देना चाहता है। कांग्रेस ने सीनेट को यद्यपि मंत्रियों की नियुक्ति की स्वीकृति का अधिकार दिया है, लेकिन व्यवहार में यह केवल औपचारिकता मात्र है। हाँ, कांग्रेस को यह प्रभावशाली अधिकार अवश्य है कि वह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के अधीनस्थ विभिन्न विभागों में सुधार और परिवर्तन कर सकती है, किसी भी विभाग का अन्त कर सकती है, उनके कार्यों की जाँच के लिए समिति बना नियुक्त कर सकती है और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध महाभियोग भी चला सकती है।

अमरीकन मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली के सुधार के उपाय

अमेरिकन मन्त्रिमण्डल का उपरोक्त निर्बल स्थिति से उबारने के लिए विद्वानों ने समय-समय पर अनेक सुझाव दिये हैं, जैसे (i) मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का यह अधिकार दिया जाए कि वे कांग्रेस के दोनों सदनों में भाग ले सकें, चाहे उनको मतदान का अधिकार न हो, (ii) मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपनी इच्छानुसार

जब चाहे प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही में उपस्थित रह सकें और वहाँ अपने विचार प्रकट कर सकें, (111) संयुक्त व्यवस्थापिका—कार्यकारिणी परिषद या मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाए ताकि शासन के दोनों विभागों में प्रभावशाली ढंग से कानूनी सम्बन्ध स्थापित हो सके आदि ।

प्रा० कारबिन ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का अपने मन्त्रिमण्डल सदस्य कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों में से चुनने चाहिये । कुछ अन्य उल्लेखनीय सुझाव प्रस्ताव हमन फाइनर ने दिये हैं, जो इस प्रकार हैं—

- 1 राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डलीय साथी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो तथा मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति कहलाय । इस प्रकार ग्यारह राष्ट्रपतियों का एक नवीन मन्त्रिमण्डल निर्वाचित किया जाये और इन सबका निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ ही हो ।
- 2 सीनेट का सभापति राष्ट्रपति न हो ।
- 3 मन्त्रिमण्डल के सब सदस्य प्रशासनिक कार्य से ही सम्बद्ध हों ।
- 4 मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों का निर्वाचन काल चार वर्ष हो ।
- 5 कांग्रेस के दोनों सदन भी राष्ट्रपति के ममानान्तर चार वर्ष के लिए ही निर्वाचित हों ।
- 6 राष्ट्रपति का यह अधिकार मिले कि वह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को पदच्युत कर कांग्रेस के सदस्यों में से नये सदस्य चुन सकें ।
- 7 मन्त्रिमण्डल में उसी व्यक्ति को लिया जाए जो कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य हो, अथवा उसका चार वर्ष तक सदस्य रह चुका हो ।

राष्ट्रपति और कांग्रेस

(The President and the Congress)

संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यात्मिक शासन प्रणाली है और इसीलिए कांग्रेस एवं राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं । संविधान के अनुसार स्वतन्त्रता की जो स्थिति राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों को प्राप्त है, वह उन्हें परस्पर अति क निकट नहीं आने देती, बल्कि दोनों ही जनता द्वारा निर्वाचित हात हैं, अतः वे स्वयं का एक दूसरे में अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एक दूसरे के प्रति विरोध सतर्क रहते हैं । शक्ति विभाजन की सांविधानिक व्यवस्था के कारण दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हैं और न व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नग्न कर सकता है (महानिवाय की प्रक्रिया को छोड़कर) और न कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका का भंग करने का अधिकार रखती है । इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने पद पर राष्ट्रीय निर्वाचन के परिणामस्वरूप आता है, अतः अधिकांश नमस्कारों पर उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होता है । इनके विपरीत कांग्रेस उन सदस्यों की संस्था है, जो अपने-अपने राज्यों से दोनो-दोनों

पर निर्वाचन होते हैं। फलस्वरूप समस्याओं पर उनके विचार क्षेत्रीय दृष्टिकोण से प्रभावित रहते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों के मध्य प्रत्यक्ष सामंजस्य प्रायः नहीं हो सकता।

परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान विलग रहते हैं। शक्ति विभाजन और पारस्परिक स्वतन्त्रता के हात हुए भी शासन के इन दो प्रमुख अंगों में सम्बन्ध पाया जाता है और साथ ही नियन्त्रण एवं सन्तुलन प्रणाली के माध्यम से यह व्यवस्था भी दायन की मिलती है कि एक का दूसरे के स्वच्छाचारिता पर नियन्त्रण रहे। कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्धों और एक दूसरे के पारस्परिक नियन्त्रणों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अली प्रकार कर सकते हैं—

प्रशासकीय क्षेत्र में कांग्रेस व राष्ट्रपति

राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका है। परन्तु कार्यपालिका शक्तियाँ का वह एकछत्र स्वामी नहीं है, उनके प्रयोग में कांग्रेस और राष्ट्रपति की सहभागिता है। मुख्य कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति राज्य के विभिन्न उच्च एवं निम्न वर्गीय पदों पर नियुक्तियाँ करता है परन्तु केवल निम्नवर्गीय नियुक्तियाँ ही वह पूर्णतः स्वच्छा से कर सकता है उच्चवर्गीय नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। व्यवहार में सीनेट प्रायः राष्ट्रपति की नियुक्तियों का अस्वीकृत नहीं करता किन्तु महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर वह निश्चय ही बड़ा वाद-विवाद करती है और उमन अनक बार ऐसी नियुक्तियों पर अपना अस्वीकृति भी देती है। इसी तरह उक्त से पदों का जब कांग्रेस द्वारा सृजन किया जाता है, तब भी उन पर नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है, यदि कांग्रेस ऐसा निश्चय करे। फिर नियुक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का व्यावहारिक रूप से प्रायः 'सीनेट की गारंटी' (Senatorial Courtesy) की प्रथा का पालन करना पड़ता है और वह विभिन्न नियुक्तियों, जो विभिन्न राज्यों में करी होती हैं, सीनेट की सिफारिशों के अनुसार ही कर देता है। पुनश्च, यद्यपि राष्ट्रपति को, जब सीनेट का अधिवेशन नहीं हो रहा है, अन्तरिम नियुक्तियाँ (Recess Appointments) करने का अधिकार है, लेकिन सीनेट का सत्र आरम्भ होने पर उसे इन नियुक्तियों के लिए सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। चूँकि राष्ट्रपति सीनेट का अधिवेशन समाप्त होत ही उन नियुक्तियों को पुनर्जीवित कर सकता है जो सीनेट ने ठुकरा दी हो अतः उनकी मनमानी पर अकुश रहने के लिए यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति यदि ऐसी किसी जगह पर नियुक्ति करता है, जो सीनेट के अधिवेशनकाल में विद्यमान थी, तो उस पर नियुक्त व्यक्त का तब तक बतन नहीं मिलेगा, जब तक उसकी नियुक्ति की सीनेट द्वारा विधिवत पुष्टि न हो जाय।

लेकिन जहाँ उच्च पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट की स्वीकृति का प्रतिबंध राष्ट्रपति पर लगा हुआ है, वहाँ कुछ वर्गों के पदों

का छोड़कर (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कांग्रेस द्वारा स्थापित आपागों और के सदस्य तथा लायसेवा के नियमांक अनुसार नियुक्त पदाधिकारी) अन्य अधिकारों को राष्ट्रपति स्वच्छा से हटा सकता है और ऐसा करने में उसे सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पदभ्रुति के अपने इन अधिकारों के बल पर राष्ट्रपति एक विरोधी सभ्य पर उससे महानग्न रहने का दवाव डाल सकता है। कांग्रेस के सदस्य अपने मित्रों और रिश्तेदारों की नियुक्तियों के लिए सदैव लालायित रहते हैं और इसीलिए वे राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध नहीं करते।

पर राष्ट्र नीति के संचालन के रूप में राष्ट्रपति विदेशों से संधियाँ करता है और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का संचालन भी करता है। परन्तु अपने इन कार्यों के सम्पादन में भी वह किसी न किसी रूप में कांग्रेस पर निर्भर है। संधियाँ देना पर लागू नहीं हो सकती है जहाँ सीनेट के बहुमत से उनकी पुष्टि कर दे। सीनेट की विदेशी मामलों की समिति राष्ट्रपति की पर राष्ट्र नीति पर सदैव गिटहॉटि रखती है और राष्ट्रपति को उसकी राय का उचित आदर करना पड़ता है। इसी तरह विदेशों के साथ युद्ध की घोषणा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कांग्रेस के दाना मदना की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त करे। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस उस क्षेत्र में राष्ट्रपति को पूरी तरह नियमित रखती है। अपनी महान शक्तियों के बल पर और एक राष्ट्र के वास्तविक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति ऐसे कूटनीतिक मन्त्र्य बना सकता है या ऐसी विषय परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है जैसा सेना का एमी अवस्था में खड़ा कर सकता है कि युद्ध अनिवार्य हो जाय। आधुनिक समय में राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति ने वास्तविक रूप में कांग्रेस के युद्ध की घोषणा के अधिकार को निगल लिया है। फिर भी अन्ततोगत्वा कांग्रेस के एक दृढ़ निश्चय के सामने उसे झुकना पड़ता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कायपालन सम्बन्धी कार्यों पर कांग्रेस का पर्याप्त प्रभाव रहता है और उससे जलक पाय ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस महभागिनी रहती है, परन्तु साथ ही कांग्रेस इतनी शक्ति सम्पन्न भी नहीं है कि वह कायपालन सम्बन्धी कार्यों में राष्ट्रपति का अन्तस्त्व करे।

व्यवस्थापन क्षमता में कांग्रेस व राष्ट्रपति

संविधान के शक्ति विभाजन के अनुसार व्यवस्थापन के क्षेत्र में कांग्रेस का एकाधिकार है और राष्ट्रपति का उससे कुछ प्रयोजन नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि व्यवहार में राष्ट्रपति एक बड़ी सीमा तक कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य का सहभागी है। स्वयं संविधान में एक स्थल पर यह उल्लिखित है कि "राष्ट्रपति समय समय पर सभ की स्थिति के बारे में कांग्रेस को सूचना देगा और ऐसे प्रस्तावों

की सिफारिश उसक विचाराथ करेगा, जि हे वह आवश्यक समझे।" स्पष्टतः इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह समय समय पर, आंतरिक व बाह्य परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए कांग्रेस को अपने लिखित या मौखिक संदेश भजता रहे। चूंकि प्रशासन के क्षेत्र में और वैदेशिक मामलों में राष्ट्रपति का अनुभव प्रायः बड़ा गहन होता है और देश का वह मुख्य कार्यपालक होता है, अतः कांग्रेस राष्ट्रपति के इन संदेशों को पर्याप्त महत्व देती है और प्रायः बहुत से कानूनों का सूत्रपात राष्ट्रपति के इन्हें संदेशों से होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को भेजे जाने वाले अपने संदेश में देश की सामान्य दशा का विवेचन करते हुए कांग्रेस को सुझाव देता है कि विद्यमान परिस्थितियों या समस्याओं का सामना करने के लिए सामान्यतया किस प्रकार का व्यवस्थापन आवश्यक है। अपने संदेश के अन्तर्गत राष्ट्रपति विशिष्ट कानूनों के निर्माण का भी सुझाव भजता है। यद्यपि सिद्धान्त रूप में अथवा सांविधानिक दृष्टि में कांग्रेस राष्ट्रपति के संदेशों व सुझावों को मानने न मानने के लिए स्वतन्त्र है तथापि व्यवहार में वह उन्हें अपनी कार्यवाहियों में प्राथमिकता देती है। बिना किसी गम्भीर कारण के कांग्रेस राष्ट्रपति के प्रस्तावों को प्रायः ठुकराने का साहस नहीं करती, क्योंकि उसे भी अनेक बातों के लिए राष्ट्रपति पर निर्भर रहना पड़ता है।

कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के संदेशों का प्रायः आदर ही होता रहा है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के संदेशों की अवहेलना करे तो राष्ट्रपति नीचे जनता से अपील करके जार अथवा प्रचार से लोकमत का प्रभावित कर सकता है और तब जनता कांग्रेस को संस्था की राष्ट्रपति की इच्छानुसार आचरण करने के लिये बाध्य कर सकती है। अब यह प्रथा पूरी तरह स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति नियमित रूप से कांग्रेस का संदेश भजता है और व्यवस्थापन का अधिकार काय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के संदेशों के आधार पर ही किया जाता है।

व्यवस्थापन कार्यक्रम में अपनी इच्छा वापन की दृष्टि से राष्ट्रपति अनेक प्रकार से काम करता है। प्रथम, प्रमुख कांग्रेस सदस्यों की इच्छा के अनुकूल नियुक्ति करके वह उन्हें व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य के लिये अपने अनुकूल बना सकता है। दूसरे, विरागी कांग्रेस सदस्यों को वह उनके द्वारा दिये हुए लाभों को छीन लिये जाने का भय दिखाकर (उदाहरणार्थ उच्च पदा पर नियुक्त होने मित्र व रिश्तेदारों आदि का पदच्युत करने की घमकी दूसरे) भी अपने अनुकूल बना सकता है। तीसरे, कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके और उन्हें आंतरिक प्रशासनिक आवश्यकताओं व वर्तमान समस्याओं की समझाया व अवगत कराकर भी राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों का मन बात के लिये तन्मय कर सकता है कि वे उसी इच्छानुकूल व्यवस्थापन करने में द्वाया में लग्न करें। चौथे, एक प्रमुख राजनीतिज्ञ दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण भी वह अपनी इच्छानुकूल

व्यवस्थापन कराने में पर्याप्त मजबूत है। राष्ट्रपति जिस दल का नेता होता है, उसी दल के सदस्य भी कांग्रेस के सदस्य होते हैं और कभी कभी तो उसी दल के सदस्यों का वाशिंगटन में बहुमत भी होता है। चूंकि दलीय नेता कम्यूसन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस में उसके दल के सदस्य स्वयं इस बात के लिये प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके नेता राष्ट्रपति द्वारा चुनाया हुआ व्यवस्थापन कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा पारित हो जाये।

कांग्रेस के व्यवस्थापन के एकाग्रित राष्ट्रपति अपनी नियंत्रण शक्ति (Veto Power) द्वारा भी नियंत्रित करता है। विधि निर्माण काय कांग्रेस का है, परन्तु कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधायक बिल तभी बन सकता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करदे। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधायक पर अपना निरन्धन प्रतिषेध (Suspensory Veto) लगा सकता है, किन्तु कांग्रेस के दो सदन द्वारा 2/3 बहुमत से उन विधायक का पुनः पारित करने पर राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा पारित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अग्रिम कानून के निर्यात भेजे गये विधायक को Pocket Veto कर सकता है। राष्ट्रपति Veto शक्ति का प्रयोग करके ही नहीं प्रत्युत उसे प्रयुक्त करने की असी दूर नीति का पालन पर अपना प्रभाव डाल सकता है। वस्तुतः देश के निम्न मन्त्रालय लड़ो हुई व्याख्या जितनी दूर में राष्ट्रपति नहीं एवं कुछ दूरी व्याख्यात्मक गहरा लिये। परन्तु जहाँ राष्ट्रपति कांग्रेस का विरोध करने की ठानेता है वहाँ कांग्रेस अग्रे पर अपनी नियंत्रण शक्ति द्वारा एक विधायक का दुबारा पारित करने की शक्ति द्वारा राष्ट्रपति को सीमा में रहने को विवश कर सकती है। मविधान के अनुसार बिल सम्बन्धी अधिकार पूर्णतः कांग्रेस को ही प्राप्त हैं। व्यवहार में यद्यपि बहुत राष्ट्रपति के संशोधन में तैयार किया जाता है किन्तु उस स्वीकार अस्वीकार या कन करना पूर्णतः कांग्रेस पर निर्भर है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा चाह गये वन में कमी करके कांग्रेस उनकी सारी योजनाओं पर तुल्यता कर सकती है और प्रभावशाली शक्ति में उन अक्षम बना सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापन शक्ति में जहाँ राष्ट्रपति कांग्रेस के विधानों पर पर्याप्त प्रभाव डालता है, वहाँ कांग्रेस भी मदद इस स्थिति में रहती है कि वह राष्ट्रपति के स्वेच्छाचारी आचरण पर रोक रख सके। एक अर्थ में दुबारा राष्ट्रपति का हाथ डिटाना ग्याम कानून कांग्रेस का पर महानिर्णय का भाग अन्तर्गत है, यद्यपि व्यवहार में यह अर्थ अन्तर्गत ही निर्यात है और अन्तर्गत निम्न में राष्ट्रपति का अपराधी नहीं रहता जा सका है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों सवधानिक व्यवस्थाओं और प्रथाओं के अनुसार एक-दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हैं और अपने-अपने-अवरोध व मतुलत प्रणाली के कारण ज-यो-या-प्रति हैं। फिर भी व्यवहार में अपनी विनाश स्थिति के कारण कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति का अधिक महत्व और शक्ति प्राप्त है। आधुनिक समय में राष्ट्रपति के अधिकारों में निरंतर वृद्धि हुई है। गियोर्डान रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन और आइजन हावर जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति कांग्रेस का नहीं बरन कांग्रेस राष्ट्रपति का अनुगामिनी रही है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 12 वर्ष के कार्यकाल में 631 विधेयकों पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया जिनमें से केवल 9 विधेयकों को ही कांग्रेस ने पुनः पारित किया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 251 बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया जिनमें केवल 12 को कांग्रेस ने नहीं माना। राष्ट्रपति आर्जन्त होवर ने यद्यपि निषेधाधिकार का प्रयोग केवल 137 बार किया, लेकिन उनके द्वारा निषिद्ध विधेयकों में से एक को भी फिर से कांग्रेस में पारित नहीं किया।

उपराष्ट्रपति (Vice President)

संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उसका कार्य उन्नीसवें संवत्सरे में प्रारम्भ होता है जिस समय राष्ट्रपति का अपना पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि उन्नीसवें संवत्सरे की है जमी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के निर्वाचक दो बोट देते हैं—एक राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए। जिन व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है वही उपराष्ट्रपति बनता है, किन्तु इस सम्बन्ध में बात यह है कि उनका पद में आधे से अधिक मत जान चाहिए। यदि किसी का भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सीनेट दो उम्मीदवारों में से एक को चुन लेती है और वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाता है। यह निश्चय करने के लिए कि कौन उपराष्ट्रपति हो, सीनेट के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है तथा उपराष्ट्रपति का कुल महत्त्वा का आधे से अधिक मत प्राप्त होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही राज्य के तो नहीं हैं।

उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिये—

- (क) संयुक्त राज्य अमेरिका का वह जन्मजात नागरिक हो।
- (ख) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
- (ग) वह कम से कम 14 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो।

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का निश्चय करने के लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है—

(क) उपराष्ट्रपति उस भौगोलिक भाग का निवासी न हो जिस भौगोलिक भाग का निवासी राष्ट्रपति है। यदि राष्ट्रपति उत्तर या पूर्व का है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण या पश्चिम का निवासी होना चाहिए।

(ख) उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों एक पार्टी के विंग (Wings) से सम्बन्धित नहीं हो वरन् भिन्न भिन्न विंग के हों।

जहाँ तक उपराष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का सम्बन्ध है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। उपराष्ट्रपति को प्रायः दो मुख्य कार्यों को पूरा करना पड़ता है—प्रथम, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण जयबा जय विभी कारण उसका पद रिक्त हो जाय तो दोष अवधि के लिये उनका कार्य भाग सम्भालना। द्वितीय उपराष्ट्रपति को कुछ शक्ति प्रदान करने के लिये मंत्रिगण निर्माताओं ने उस सीनेट का अध्यक्ष (Chairman) बनाया है। परन्तु सीनेट में भी वह केवल निर्णायक मत ही दे सकता है किसी नये मतदान में वह भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह सीनेट का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की नीतियाँ और योजनाओं से परिचित होना होकर बाहर का व्यक्ति होता है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को यह लाभ है कि वह विधि निर्माण क्षेत्र में होने वाले कार्य कलापों को जान सकता है। वह कि उपराष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की नीतियाँ और योजनाओं से परिचित होना लाभप्रद ही है, अतः भूतकाल में रहकर उपराष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डलीय बैठकों में सम्मिलित किया जाता रहा और राष्ट्रपति रुजवेल्ट के समय से तो उसे प्रायः नियमित रूप से मन्त्रिमण्डल में आमन्त्रित किया जाता है। राष्ट्रपति आइजन हावर के काल में उपराष्ट्रपति का पद अधिक सशक्त हुआ है और अधिक सम्मानजनक व प्रभावशाली भी। 1949 से उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य भी होता है। 1954 में यह घोषणा की गई कि जब कभी राष्ट्रपति परिषद की बैठकों में अनुपस्थित हों तो उपराष्ट्रपति ही इनका सभापतित्व करेगा। राष्ट्रपति के अन्वेषण होने की दशा में उपराष्ट्रपति ही मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापति करता है। अब शनैः शनैः उपराष्ट्रपति का पद का महत्व बढ़ता जा रहा है और उपराष्ट्रपति को एक राजनीतिक गण प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में विनियमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का 45 हजार डॉलर प्रतिवर्ष वेतन मिलता है और नियमानुसार दूसरे भत्ते दिये जाते हैं।

5

अमेरिका की न्यायपालिका (THE AMERICAN JUDICIARY)

“यदि अदालतें कानून के वास्तविक अर्थों और
परिचालन की व्याख्या और अर्थ निर्धारण
करें तो ये मूल अक्षरों के समान हैं।”

—एलेग्जेंडर हेमिल्टन

अमेरिकन संविधान निर्माताओं की संभवतः सबसे अधिक गौरवपूर्ण देन एक ऐसे संघीय न्यायालय की स्थापना है जो सब प्रकार से स्वतंत्र और शक्तिशाली होने के अतिरिक्त संविधान में एक विशेष महत्त्व रखता है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि एक ऐसे संघीय न्यायिक शक्ति की स्थापना की जानी चाहिए जो संघीय व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की शक्ति में सामंजस्य बनाये रखे और ऐसी राष्ट्रीय न्यायपालिका के रूप में कार्य करे जो न केवल स्वयं अपने में पूर्ण हो बल्कि सब एक राज्यों के जय सभी न्यायालयों में उच्चतर है तथा देश की कानूनी व्यवस्था के लिए अतिम रूप में उत्तरदायी हो। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि एक ऐसा सर्वमान्य मध्यस्थ जरूर होना चाहिए जो समस्त राज्य और संघ के हितों में ऊपर हो तथा निष्पक्ष रूप से इनके नाटकों को निपटायें।

अतः यही संघ सांचे समय पर अमेरिकन संविधान की तीसरी धारा में यह व्यवस्था की गयी कि “न्याय सम्बन्धी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगा, जिनकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस विधि द्वारा समय-समय पर करेगी।” इन अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का ‘आदर्शित’ (Mandatory) बनाया गया और निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की शक्ति पर छोड़ दिया गया। संविधान में उन सब बातों की भी स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी जिनके द्वारा न्यायपालिका की

सर्वोच्चता और नभमता कायम रह नके। उदाहरणाय, संविधान की तीसरी उपधारा व दूसरी भाग म यह उल्लेख कर दिया गया कि मधीय 'यायपालिका' की शक्ति सर्वापरि और सब व्यापक होगी। 'यायपालिका' की निष्पन्नता बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था की गयी कि 'यायाधीश' का कार्यकाल सदाइ होगा तथा नियुक्ति व नभय निश्चिन किये हुए वतन वा उनके वायकाल म घटाया नहा जा नकेगा।

संघीय न्यायालयो का संगठन

(Composition of Federal Judiciary)

संघीय 'यायान्य' दो प्रकार के हैं—

1 व्यवस्थापिक 'यायालय' एवं

2 मर्यादनािक न्यायालय

व्यवस्थापिक 'यायालय' (Legislative Courts)

ये व 'यायालय' हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस अपनी विधायिनी शक्ति द्वारा करती है। इन 'यायालयो' द्वारा संविधान की तीसरी धारा म उल्लिखित याधिक शक्ति का उपनाग नहा किया जाता। उनका कार्य तो उन वातूनो के क्रियाचयन म प्रशासन का नहयाग देना है जिन्हें कांग्रेस अपनी निहित शक्ति (Implied Power) अथवा प्रदत्त शक्ति (Delegated Power) का प्रयाग करन के लिए बनाती है। फालम्बिया जिला तथा उन प्रदेशा के लिए, जिन पर मयुक्त राज्य अमरिका का अधिशासन है कांग्रेस द्वारा 'यायालया' की स्थापना की गयी है।

इन व्यवस्थापिका 'यायालया' के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं—

दावा 'यायालय' (Court of Claims)—1855 म स्थापित इस 'यायालय' म मधीय गानन के विरुद्ध नागरिका के दावा की सुनवाई हाती है।

आयाग निर्यात शुल्क 'यायालय' (Court of Customs)—इसम आयाग-निर्यात शुल्क एकरित करन याउ अधिनारियो के निणयन क विरुद्ध अपीले मुनी जाती है।

आयाग निर्यात तथा पेटेण्ट्स अपील 'यायालय' (Court of Customs and Patents Appeal)—यह 'यायान्य' आयाग निर्यात शुल्क और पेटेण्ट्स क निणया व विरुद्ध तथा सीमा कर जायग (Tariff Commission) की आपात्रो क विरुद्ध अपील की सुनवायी करता है।

कर 'यायालय' (Tax Court)—इसम पर सम्बन्धी विवादा की सुनवाई हाती है।

व्यवस्थापक 'यायान्या' (Legislative Courts) और संवधानिक 'यायान्य' (Constitutional Courts) म प्रमुख अन्तर ये हैं—

(1) दानो की उत्पत्ति के स्रोत भिन्न हैं। उनके द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मामले भी भिन्न होते हैं। व्यवस्थापक न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिनका सम्बन्ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मार्गजनिक धन का व्यय, करो की वसूली आदि से होता है। सवधानिक न्यायालय उन विवादों का निणय करते हैं जिनकी चर्चा संविधान के तीसरे अनुच्छेद में की गयी है।

(11) सवधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश रह सकते हैं जबकि व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होती है।

संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Courts)

इन न्यायालयों की स्थापना संविधान के अनुच्छेद तीन द्वारा की गयी है। ये न्यायालय तीन श्रेणियों में विभक्त हैं —

(क) जिला न्यायालय (District Courts)

(ख) मध्यम अपील न्यायालय (Federal Courts of Appeal)

(ग) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

1. जिला न्यायालय—मध्यम न्यायालयों में ये सर्वोच्च न्यायालय हैं। सम्पूर्ण देश लगभग 91 जिलों में विभाजित है जिनमें 91 जिला न्यायालय काम करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक जिले का होना अनिवार्य है। न्यायाधीशों की नियुक्ति अद्वार्त्त जनरल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिस पर मीनेट की स्वीकृति आवश्यक है।

2. जिला न्यायालयों में एक ही न्यायाधीश अभियोगों का निणय करता है जिसके विरुद्ध अपील उचित अपील न्यायालय में की जाती है। किन्तु यदि किसी अभियोग में मध्यम परिणयों की सवधानिकता को चुनौती दी जाय तो तीन न्यायाधीशों द्वारा निणय आवश्यक है। अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय को की जा सकती है।

मध्यम अपील न्यायालय—देश में इस प्रकार के ग्यारह न्यायालय हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहले इनके न्यायाधीश याचकाय के लिए दौरा करते थे, किन्तु अब ऐसा बहुत कम होता है। मध्यम न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार का हल्का करना है। प्रत्येक मध्यम अपील के न्यायालय में तीन से लेकर छ न्यायाधीश होते हैं। जिलों न्यायाधीशों का भी सहयोग लिया जाता है। इनका याच क्षेत्र अपीलीय है। इनमें जिला न्यायालयों और मध्यम अभिकरणों के निणयों के विरुद्ध अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को उनके निणयों के पुनरावलोकन का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court)

“न्यायालया की व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है। इसकी व्यवस्था स्वयं संविधान में की गई है। इसकी स्थापना सन् 1789 में चाय कालिफा अधिनियम द्वारा की गई थी। अमरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, और इसीलिए उसकी व्याख्या करने वाली शक्ति के रूप में अमरिका में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत महत्ता पा ली है। सर्वोच्च न्यायालय मध्य में उस न्यायिक शक्ति की आवश्यकता का प्रतीक है, जिसने जिसमें संविधान के निरूपण का और केवल तथा राज्यों के अंगों राज्यों के नागरिकों के समक्ष को नियंत्रण का काम है। इन शक्तियों के कारण उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अमरिकन सर्वोच्च न्यायालय कायन या राज्यों के विधान मण्डल द्वारा पास किये गए अधिनियमों का अवलोकन कर सकता है। अमरिकन नागरिक उस अपने अधिकारों के मरतबे के रूप में दर्शन हैं। हश्किन (Haskin) के शब्दों में “सर्वोच्च न्यायालय गृहा में शासन नियंत्रण का सतुलन चक्र है जबकि शासन के अर्थ निर्माण जनमत के भीम और तब प्रकार से हिला दिये जाते हैं, तब वह अपने न्यायिक-सतुलन को कायम रखता है। उसका कर्तव्य है कि हर समय और हर परिस्थिति में देश के सर्वोच्च कानून के रूप में वह संविधान का कायम रखे।” समस्त जनता की भलाई के लिए इस शक्ति का कार्यान्वित होना आवश्यक है। रचना

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। प्रारम्भ में इनके न्यायाधीशों का एक मुख्य न्यायाधीश तथा पाँच अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सन् 1801 में इन संख्या को 5, 1807 में 7, 1837 में 9, 1863 में 10 और 1866 में पुनः 7 कर दिया गया। अतः सन् 1869 में कायम द्वारा 9 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई और उस समय से यह संख्या अब तक स्थिर चली आ रही है। यद्यपि इसमें परिवर्तन आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इन संख्या के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रचना एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीशों से होती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा होना आवश्यक है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकृत कर सकती है। उदाहरणार्थ 1930 में जॉन पार्कर के मनोनयन को रद्द कर दिया गया था। न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ नरत समय राष्ट्रपति प्रायः न्यायालय के वर्गीय, धार्मिक एवं दलीय गठन को ध्यान में रखता है।

न्यायाधीश जब तक सदाचारी रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। यदि किसी न्यायाधीश ने 10 वर्ष तक निरन्तर सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है तो 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पूर्ण वेतन सहित वह अवकाश ग्रहण कर सकता

है। भारत में यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था के बाद पद निवृत्त हो जाते हैं और स्विट्जरलैण्ड में उनका कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष है। अमेरिकन यायाधीशों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे राजनीति में भाग न लें, किंतु यथावत वे राजनीतिक गतिविधियों से बाहर ही रहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के यायाधीशों का वार्षिक वेतन 25 हजार डॉलर है। मुख्य यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों से 500 डॉलर वार्षिक अधिक मिलता है। यह वेतन कांग्रेस ने अधिनियम द्वारा निश्चित किया है और किसी भी यायाधीश के कार्यकाल में उसमें कमी नहीं की जा सकती। वेतन के अतिरिक्त यायाधीशों को अनेक प्रकार के भत्ते मिलते हैं।

किसी भी यायाधीश की उसकी इच्छा के विरुद्ध त्याग पत्र देना मजबूर नहीं किया जा सकता, किंतु यदि वह रिक्त होता है अथवा कोई मनीषा अपराध करता है तो उसे महाभियोग (Impeachment) द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार नहीं है। अब तक महाभियोग के केवल 9 मामले चले हैं जिनमें से केवल 4 को ही महाभियोग के आधार पर दण्डित किया जा सका है। स्वच्छा से अवकाश ग्रहण करने के मामले भी आधे से कम ही हुए हैं।

यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कोई प्रायः ऐसे व्यक्तियों को यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, सामाजिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अधिकारियों के परामर्शदाता रह चुके हों।

कार्य प्रणाली

सर्वोच्च न्यायालय का कार्य अक्टूबर में प्रारम्भ होता है और मई के मध्य तक चले जाते हैं। इस प्रकार केवल आठ महीने काय होता है। शीत और पतझड़ के समय दो सप्ताह की छुट्टी रहती है, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार और शुक्रवार को मुकदमों सुन जाते हैं। शनिवार को न्यायाधीश आपस में मिलकर उन पर विचार विनियम करते हैं। निणय बहुमत से लिया जाता है और सोमवार का सुना दिया जाता है। मुकदमों की सुनवाई तथा निणय के लिए 6 यायाधीशों की गणपूर्ति (Quorum) आवश्यक है। निणय के पक्ष में मत देने वाले किसी भी यायाधीश को निणय लिखने के लिए कहा जा सकता है, अतः सभी यायाधीश सभी मुकदमों में काफी सचेत रहते हैं। यद्यपि मुकदमों का निणय बहुमत से होता है तथापि बहुमत के निणय के विरुद्ध कोई यायाधीश भिन्न मत (Dissenting opinion) भी दे सकता है। भिन्न मत होने वाले का निणय यद्यपि महत्वहीन होता है, फिर भी कभी कभी प्रचार के फलस्वरूप जनमत पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार अतः वे वह देश की विधियों को प्रभावित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के विचारों तथा निर्णयों का 'संयुक्त राज्य रिपोर्ट्स' (United States Reports) में प्रकाशित किया जाता है जो मरिधानिक कादून के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली में ऐसा भी होता है कि कभी-कभी पुराने निर्णयों को उलट दिया जाता है और उनके स्थान पर पूर्णतः नवीन निर्णय व मिद्वान्ता का प्रतिपादन कर दिया जाता है। अब तक अनेक ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया है। क्षेत्राधिकार एवं कार्य

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गई है। तन्नुसार इसके अधिकार क्षेत्र और कार्यों का विवरण हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं—

- 1 प्रारम्भिक अथवा मूलिक श्रेयाधिकार (Original Jurisdiction)
- 2 अपीलिय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)
- 3 'न्यायिक पुनरावलोकन' का अधिकार (Power of Judicial Review)
- 4 संविधान तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षक तथा अभिरक्षक (Custodian and guardian of the Constitution and the rights of Citizens)
- 5 अन्य अधिकार (Miscellaneous Powers)

(1) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)—सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र अत्यंत सीमित है। संविधान में स्पष्टतः कहा गया है कि 'उन सभी मामलों में जिनका सम्बन्ध राजदूतों से, राज्य के मन्त्रियों से अथवा अन्य दाय्य अधिकारों से है और उन सभी मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अथ प्रारम्भिक होगा।' यद्यपि कांग्रेस इस अधिकार क्षेत्र का घटा बढ़ा नहटा सकती फिर भी वह कादून और अपने विवेक के अनुसार उक्त मामलों के लिए नीचे के न्यायालयों में अनुमति दे सकती है।

यद्यपि संविधान में इस मामले पर, जिनका सम्बन्ध राजदूतों, नागरिक दूतों अथवा अन्य प्रकार के विदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों से है, प्रारम्भिक अधिकार का प्रदान करता है, परन्तु आधुनिक युग में ऐसे सगड़े राष्ट्रीय न्यायालय में प्रायः नहीं उठाये जाते हैं क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय विषय तथा प्रयासों के अन्तर्गत आते हैं।

अपनी न्यायालयों द्वारा केवल उन मामलों की सुनवाई हो सकती है जिनका सम्बन्ध राजनयिक छूट (Diplomatic immunity) के अन्तर्गत न आने वाले दायें अधिकारियों से है और जिनमें राज्य एक पक्ष है। ऐसी दशा में भी ऐसे मामलों की सुनवाई तभी हो सकती है जबकि दूसरा पक्ष बाह्य और राज्य हो।

(2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)—सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश मुकदमों में पुनर्विचार जहाँ अपील के लिए आते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों के उच्च न्यायालयों और निम्न मधीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करना ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है। महत्त्वपूर्ण रहने योग्य बात है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों की अपील नहीं हो सकती जिनमें निम्न न्यायालयों के निर्णयों से किसी पक्ष को असंतोष हो। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के अपील सम्बन्धी न्याय क्षेत्र का स्पष्ट करते हुए मुनरो ने लिखा है कि “केवल उस देश का छोड़ कर जिसमें—(क) राज्य के उच्चतम न्यायालय ने राज्य के किसी ऐसे कानून को वैध घोषित कर दिया है जिस पर संघीय संविधान के विरुद्ध होने का आरोप लगा है, जहाँ (ख) उसने किसी मधीय कानून जहाँ या किसी को अवैध घोषित कर दिया है, किसी भी पक्ष को राज्य के मधीय न्याय क्षेत्र के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है।” फिर भी उन मामलों में जिनमें राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपील की अनुमति दे दी है, अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संविधानिक मामलों में है और साधारण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी होती है जब कि राज्य के उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी हो।

न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन का अधिकार (Power of Judicial Review)—अनुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के महान् प्रभाव और सम्मान का आधार वह सिद्धांत है जो उसे न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के सम्बन्ध में प्राप्त है। इस शक्ति के अधीर वह संविधान की व्याख्या करता है और कौंग्रेस तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कानूनों एवं अन्य प्रशासनिक आदेशों की वैधानिकता एवं अवैधानिकता का निर्णय करता है जैसी कि भ्रान्त धारणा है, सर्वोच्च न्यायालय को अकेले पुनरावलोकन या नमोना का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय का इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार होता है कि राज्य का अमुक कानून संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं और मधीय जिला न्यायालय तथा अपील न्यायालय जहाँ किसी संघीय कानून, राज्य-कानून या राज्य के संविधान की किसी भा व्याख्या का मधीय संविधान के प्रतिकूल घोषित कर उस लागू करने से अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन मधीय संविधान के विरुद्ध होने

के सब अभियोगों का अन्तिम निणय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि इस मामले सघीय निम्न न्यायालया और राज्य के उच्च न्यायालया में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं परन्तु उनका निणय अन्तिम नहीं होता। उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। प्रो० ब्रोगन (Prof Brogan) ने लिखा है कि "सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को हम एक राजनैतिक सत्ता और एक ऐसे तृतीय सदन के रूप में समझ सकते हैं जो कार्यपालिका और विधानमण्डल के कार्यों को विशेष सिद्धान्तों के अनुसार नियमित करता है।"

न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार—कुछ विचारकों के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान निर्माता का भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि "कार्यपालिका को इस प्रकार की किसी शक्ति से विभूषित किया जाए। राष्ट्रपति जैफरसन ने कहा था कि यदि कार्यपालिका कांग्रेस एवं राष्ट्रपति अर्थात् व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन करने का अधिकार का प्रयोग करती है तो न केवल यह शक्ति पक्ष-वकरण के सिद्धान्त का ही उल्लंघन है, बरन संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अन्याय है।

पर तु अधिकांश विचारकों का निश्चित मत है कि संविधान की दो धाराओं में न्यायपालिका की वह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप में निहित है, जिसका उपयोग करते हुए वह कांग्रेस एवं राष्ट्रपति के कार्यों का अर्थात् व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये दो धारायें हैं—(1) संविधान की चौथी धारा की दूसरी उपधारा, एवं (2) संविधान की तीसरी धारा की दूसरी उपधारा। संविधान की चौथी धारा की दूसरी उपधारा में उल्लिखित है कि "यह संविधान और समुक्त राज्य के वे कानून, जो उसके अनुसार बनाये जायें, एवं वे संविधान, जो समुक्त राज्य के अधिकार के अन्तर्गत की गई हों या की जायें, देश के सर्वोच्च कानून होंगे।" संविधान की धारा तीन की उपधारा दो में कहा गया है कि "कानून और नीति के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सभी मामले आयेंगे, जो इस संविधान, समुक्त राज्य के कानूनों एवं उनके अन्तर्गत की गई श्रवणों का जान वाली मधिया के अन्तर्गत उत्पन्न हों।

संविधान की चौथी धारा स्पष्टतः प्रतिपादित करती है कि संविधान का देश का सर्वोच्च व आधारभूत कानून माना जाना चाहिये। तीसरी धारा का आशय है कि वे सभी मामले, जो उस आधारभूत कानून के अन्तर्गत उत्पन्न होंगे, न्यायिक शक्ति के क्षेत्राधिकार में होंगे। इस प्रकार इन दोनों ही धाराओं का निष्पत्ति यह है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहें और किना भी प्रकार उसका उल्लंघन न हो—यह दखना न्यायपालिका का कर्तव्य है। न्यायपालिका अपने इस काम को उचित रूप से तभी सम्पादित कर सकती है जब वह संविधान और व्यवस्थापिका के कानूनों की व्याख्या करने में एवं संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल पाये जाने

वाले कानूनों को अवैधानिक घोषित करने की अधिकारिणी हो। 'न्यायिक पुनरावलोकन' की यह शक्ति संविधान की धारा 6 (खंड 8) द्वारा भी समर्पित होती है जिसमें न केवल यह कहा गया है कि 'संविधान और इसके अंतर्गत निर्मित संयुक्त राज्य के समस्त कानून तथा संयुक्त राज्य की ओर से की गई या की जाने वाली समस्त संधियाँ इस देश के सर्वोच्च कानून हों' बरन यह भी स्पष्टतः कह दिया गया है कि 'प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उन्हें मनाने के लिये बाध्य होंगे, उनसे अमंगल राज्य के संविधान या कानूनों को नहीं।' स्पष्ट है कि संविधान राष्ट्रीय सर्वोच्चता (National Supremacy) के सिद्धान्त को मायसा देता है जिसके अनुसार राष्ट्रीय संविधान और कानूनों के विपरीत जय किसी भी कानून या कार्य को अधिक मायसा नहीं दी जाएगी। इसका स्वाभाविक अर्थ यह निकलता है कि कोई कार्य या कानून संवैधानिक है अथवा नहीं, इसकी जांच 'न्यायपालिका' करने की अधिकारिणी होगी। संविधान के उपबन्धों के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं तथा विधिवेत्ताओं ने भी संघीय न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति का समर्थन किया है।

मुख्य 'न्यायाधीश' मार्शल ने 1803 में 'मार्बरी बनाम मडिसन' (Marbury v/s Madison) नामक प्रसिद्ध मुकदमे में 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्तियाँ की स्पष्ट रूप से व्याख्या की और अपना निणय देते हुए बताया कि संविधान समस्त देश का सर्वोच्च कानून है तथा 'न्यायाधीशों' का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे इसी के अनुरूप निणय दें एवं जब कभी कांग्रेस द्वारा पारित कोई अधिनियम देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान के विरुद्ध पाया जाय तो 'न्यायालय' का कर्तव्य है कि वह संविधान को प्रथम स्थान दे। इस निणय के बाद से ही अमरीकन 'न्याय' व्यवस्था में यह मुनिश्चित हो गया है कि न्यायपालिका का 'न्यायिक पुनरावलोकन' का अधिकार है।

स्मरणीय यह है कि 'न्यायपालिका' 'न्यायिक पुनरावलोकन' के समय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों और संविधान के शाब्दिक रूप पर ही विचार नहीं करती बल्कि उसकी आत्मा पर भी विचार करती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका केवल किसी कानून का संविधान की किसी व्यवस्था के प्रतिकूल होने पर, अवध हो घोषित कर सकती है अपन निणय को अंगीकारित करना उनके अधिकार की बात नहीं है। उन निणय पर अमल करना कार्यपालिका का कर्तव्य है।

'न्यायिक पुनरावलोकन' का प्रभाव—अमरीका के राजनीतिक जीवन पर 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्ति का पर्याप्त संवैधानिक प्रभाव पड़ा है—

(1) इस शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय में राज्य विधान-मण्डलों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित सबको नियमों को अवैधानिक घोषित

करके 'याधिक सर्वोपरिता (Judicial Supremacy) का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है।

(ii) इनके आधार पर राज्या की तुलना में सभ की स्थिति सुदृढ़ हो गयी है। तबु साथ ही इन शक्ति न राज्या के अधिकारा की रक्षा करने में भी सहायता प्रदान की है।

(iii) इनका व्यापक प्रभाव राज्य के पुलिस अधिकार (Police Powers) पर पड़ता है जिसमें मावजनिक सुरक्षा, जनकल्याण, स्वास्थ्य, नतिकता आदि सामाजिक विषय सम्मिलित हैं।

(iv) इसन सामाजिक विधायन के क्षेत्र में संघीय सरकार के अधिकारा का प्रभावित किया है।

(v) इस शक्ति के बल पर सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान की आत्मा और भाषा का ही निवाचन नहीं किया है बल्कि नीतियों का निर्धारण भी किया है। इसीलिए 'यायाजीता का संविधान का नया निर्माता (New Makers of the Constitution) तब कह दिया गया है। अनेक अवसरों पर संघीय न्यायालया ने राज्या की प्रांतीयता की मकीण प्रवृत्ति को रोक कर राष्ट्रीय एकता का समर्थन बनाया है।

'याधिक पुनरावलोकन की आलोचना—सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के महान प्रभाव और महत्व के हाते हुए भी विपक्ष में अनेक बातें कही गयी हैं—

(i) सर्वोच्च न्यायालय में इन शक्ति के आधार पर व्यवस्थापिका के कार्यों का इतना अधिक अपना लिया है कि प्रतिनिधि सभा जनता की इच्छा को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। इन शक्ति के सहारे सर्वोच्च न्यायालय अनिवाचित उच्चतर व्यवस्थापिका बन बैठा है और उसका रूप एक तृतीय व्यवस्थापिका सदन का हो गया है। जोगन के शब्दों में 'सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्यों का एक तृतीय सदन के रूप में नियमित करने लगा है और अपने मौलिक कार्यों की समुचित ढंग से नहीं निभा पाता।'

(ii) इस शक्ति के बल पर राज्या के विभिन्न कानूनों की वैधता पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय इनके सामान्य औचित्य पर भी विचार कर लेता है। यह उचित नहीं है क्योंकि उसको तो केवल उनकी वैधता अवधता पर ही विचार करना चाहिए।

(iii) सर्वोच्च न्यायालय की नीति में अथवा इसका नियमों में एक रूपता का अभाव रहा है। ऐसा देखा गया है कि संघीय न्यायालय के निर्णय कभी उदार रहें हैं तो कभी संकीर्ण और कभी सभ के पक्ष में। अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब नियम विपुल वैधता या अवधता पर आधारित न हाकर 'यायाजीता की अपनी भावनाओं और उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे हैं।

(iv) 'यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जाधुनिक सामाजिक और आर्थिक त्थाओं के लिए अनुपयुक्त है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के सहारे कई अवसरों पर 'यायपालिका निहित स्वार्थों का नरक्षण करती है और प्रगतिशील एवं लोकतन्त्रात्मक नीतियाँ का विरोध करते हुए कुलीनतन्त्र का पक्ष लेती है।

(v) 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल पर कांग्रेस द्वारा कठोर परिश्रम से निमित्त विधि 'यायपालिका द्वारा कभी-कभी अवांछित रूप में नष्ट कर दी जाती है। फलस्वरूप जनता के प्रतिनिधियों के प्रयासों का कोई साकार फल नहीं निकलता।

उपयुक्त आलोचनाओं के प्रकाश में यह साफ़ की जाती है कि 'यायिक अत्याचार से बचन के लिए सर्वोच्च 'यायालय की 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर राक लगाई जानी चाहिए। अन्यथा देश की प्रगति रुक जाने और लोक-व्यवस्थाकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकने का भय विद्यमान रह्य। यह भी सम्भव है कि समय-समय पर व्यवस्थापिका और 'यायपालिका तथा 'यायपालिका में मध्य की परिस्थितियाँ पैदा हों। भूतकाल में ऐसा हुआ है।

यह उत्साहजनक नक्के है कि जनता की प्रतिक्रिया में सर्वोच्च 'यायालय की विराधी प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लगाना है। इसीलिए 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विरोध भूतकाल की तुलना में कम होता जा रहा है। शरम्भ में दारा-योगी की प्रवृत्ति प्रतिक्रियावादी जैसा थी किन्तु अब प्रवृत्ति यह है कि कांग्रेस के विधान क्षेत्र में कम से-कम हस्तक्षेप किया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायन क्षेत्र में सर्वोच्च 'यायालय ने कांग्रेस के नतुत्व का स्वीकार कर लिया है। 'यायाधीश डग्लस (Justice Douglas) के अनुसार तो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति अब मजबूत हो गयी है।

4 सविधान तथा नागरिक अधिकारों का रक्षक एवं अभिभावक—सर्वोच्च 'यायालय अमेरिकन जनता के अधिकारों, स्वतन्त्रताओं तथा सविधान का रक्षक एवं सशोध व्यवस्था का अभिभावक है। यह सविधान की अंतिम व्याख्या करना है और इस प्रकार उनका अंतिम निर्णय करता है। सविधान के विकास में अपनी सविधानिक व्याख्याओं द्वारा उनसे बहुत सहाय्य प्रदान किया है। निहित शक्तियों का विकास उनके उमन केन्द्र की शक्तियों में वृद्धि की है। इमोशन्स जेम्स ब्रैक न कहा है, 'सर्वोच्च 'यायालय केवल एक 'यायालय मात्र नहीं है बल्कि यह विषय अर्थों में एक सतन्त्र सविधान निमात्री नग्न है।

इन 'यायालयों में अमेरिका के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। वह निर्देश आदेश, परमादेश, तन्त्र, प्रतिषेध-अधिकार आदि द्वारा मौलिक अधिकारों एवं सविधानिक शांति का रक्षा करता है।

5 अन्य अधिकार—सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे मोटे काय भी करता है। उदाहरणार्थ निम्न धोणी के कर्मचारियों, जैसे मदेशवाहक, स्टेनोग्राफर आदि को नियुक्ति करता है, दीवानी एवं फौजदारी कार्य विधेयको का निदेशन करता है और अपनी आज्ञाओं का लागू करना है। आदेश (Writs) के माध्यम से इस काय को किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उस परामर्श देने का अधिकार नहीं है, जो अधिकतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

उपर्युक्त विवरण से यही निष्पन्न निकलता है कि संयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रेजोड दायित्व प्राप्त कर ली है और उसे देश के संविधान का चौथा पहिया कहने में कोई अतिशयाक्ति नहीं है।

6

राजनीतिक दल (POLITICAL PARTIES)

“एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही
सच्चे लोकतन्त्र की पहिचान है।”

—लास्की

अमेरिकन संविधान-निर्माताओं की कल्पना, इच्छा जाकाक्षा के संस्था विरुद्ध आज राजनीतिक दल अमेरिका के शासन मंचालन में गैधानिव संस्थाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं। मुनरो के शब्दों में “संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था, वही शिला शासन पद्धति का प्रमुख काना बन गई है।” राजनीतिक दल वास्तव में अमेरिकन सांविधानिक ढांचे को मानस और रुधिर प्रदान करके गतिशील तथा कार्यकारी बनाए हुए हैं। वे अमेरिका में प्रभाव-शाली ढंग से प्रजातांत्रिक तरीके पर सरकार चलाने का कार्य करते हैं। वे अमेरिकन राजनीतिक जीवन का अविच्छिन्न अंग बन गये हैं और अमेरिका के सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन पर छा रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार से अमेरिका के संविधान में परिवर्तन-सा कर दिया है। उन्हीं के प्रभाव से राष्ट्रपति का चुनाव, जो पहले अप्रत्यक्ष था, अब प्रत्यक्ष रूप से होना लगा है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच की खाई को बम फरक शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और मंचालन के सिद्धान्तों के कुपरिणामों को रोकने में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योग है। दलों के द्वारा ही राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मध्य सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।

अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय

अमेरिकन संविधान निर्माता दलीय व्यवस्था में विद्वान्ता नहीं करते थे। यद्यपि वे दलों की निरवृत्त दृष्टि से देखते थे और ऐसी गलत व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो राजनीतिक दलों को गुटबंदी द्या से मुक्त हो, तथापि उन्हें यह

आपका भी थी कि जिस प्रकार क लातन नी प स्थापना करने जा रहे थे, उन्हें राजनीतिक दला का विकास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं फ़िलाडेल्फिया सम्मेलन में ही दला का अकुर नी फूट उठा था। प्रतिनिधि दलीय आधार पर विभाजित हान लग थे, नल ही उ हान एमा अनुन न रिया हा। फ़िलाडेल्फिया सम्मेलन में प्रतिनिधिगण दा गुटा में विभवन र—सघवादी और नप-विराधी (Federalists and Anti federalists)। सघवादी सघाय सरकार को पक्ति शाली बनाना चाहत थे जकि सघ विराधी राज्य सरकारा को पतिगानी बनाने के पक्ष में थे।

इस पष्ठभूमि में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन के शानन काल में ही अमेरिका में राजनीतिक दला का स्पष्ट प्रस्फुटन हो गया। हैमिल्टन के अधीन एक दल एनी काय नीति का समर्थक था जिसमें यह माना गया था कि सघीय सरकार सक्तिगाली हा तथा व्यापक अधिकारों का प्रयोग कर। इस काय नीति के समर्थका का सघवादी (Federalist) कहा जाने लगा। दूसरी ओर वे लोग थे जिनकी थड़ा राज्य सरकारा के पक्ष में था। थामस जफरसन के नेतृत्व में इन्होंने अपने-आपका रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन (Republican or Democratic Republican) कहना आरम्भ कर दिया। ये ही आज के डेमोक्रेटिक दल के पूज्य हैं। सघवादिया और रिपब्लिकन में परराष्ट्र नीति, कानून निर्माण आदि के प्रश्नों पर ता मतभेद थे ही, नाथ ही सविधान की व्याख्या करने में भी ये एकमत नहीं थे। इस प्रकार स्पष्ट रूप से दो विभिन्न दल जन्म ले चुन थे जिनके अपने-अपने नेतागण थे और जिनके सिद्धांतों तथा विचारों में परस्पर अन्तर था।

फिर भी अभी तक राजनीतिक दल देग के राजनीतिज्ञ सघ पर अपने पूण रूप में प्रकट नहीं हुए थे। वॉशिंगटन ने अपने मन्त्रि मण्डल में दोना गुटों के नेताओं हैमिल्टन और जफरसन का स्थान दिया तथा दोना गुटों की खाई का पाटने का प्रयत्न किया। किन्तु राजनीतिक दल के जा अकुर प्रस्फुटित हो चुके थे, वे बंधों का रूप धारण करने से रुक नहीं सके। सन 1796 के राष्ट्रपति के चुनाव का सभ्य दलबन्दी स्पष्ट उभर आई जिसमें सघ वानिया (Federalists) ने राष्ट्रपति बनने (White House) में प्रवेश किया। अगले चुनाव में सत्ता जफरसन के अनुयायियों के हाथ में पहुँच गई। धीरे धीरे सघवादिया को इतनी शक्ति पहुँची कि सन 1815 के बाद कुछ ही समय में वे राजनीतिक रंग सघ में उभर हा गये।

फिर तु जब रिपब्लिकन न्माकटिक दल ता गटा में विभवन हो गया—एक गुट नेशनल रिपब्लिकन (National Republican) कहलाया और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन (Democratic Republican)। सन 1852 से 1859 तक नेशनल रिपब्लिकन दल हा पूण विघटन हो गया। उनके अनुयायियों में एक नया दल का जन्म हुआ जिन्का नाम रिपब्लिकन दल (Republican Party) रखा गया।

प्रकार मौलिक रिपब्लिकन दल के अवरोध पर वर्तमान दोनों राजनीतिक दलों उदय और विकास हुआ—रिपब्लिकन दल तथा डेमोक्रेटिक दल ।

सन 1860 में रिपब्लिकन दल के हाथ में शानन सत्ता आई और लिबरल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । इसके बाद से ही अब तक लगभग 110 वर्षों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल के बीच ही शासन का उलट फेर होता रहा है । अमेरिका में दोनों ही दल उगभग समान रूप से शक्तिशाली भिन्न हुए हैं । लोकमत कभी एक के पास में तो कभी दूसरे के पास में होता रहता है ।

अमेरिका में उपर्युक्त दोनों दलों की ही प्रधानता है, तथापि यह आशय नहीं है कि तीसरा दल कभी पैदा हो नहीं हुआ । समय-समय पर विशेष उद्देश्यों लेकर अनेक दल पैदा हुए लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठित न हो सकने के कारण बालांतर में वे समाप्त होते गये । यदि आज किसी अन्य दल का अस्तित्व भी तो केवल नाममात्र का है ।

दोनों प्रणाली के उदय के परिणाम

1 कभी कभी यह विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक दल और कांग्रेस के निर्वाचन में दूसरा दल विजयी हो जाता है । फिर भी अधिकांशकाल ऐसा बहुत कम होता है । सन् 1848 के बाद सन् 1956 में ही ऐसा अवसर आया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में रिपब्लिकन दल की जीत हुई जब कि कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेटिक दल का नियंत्रण रहा ।

2 दोनों ही दलों के समान रूप से शक्तिशाली होने के कारण दोनों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है । इस स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतियोगिता का ही यह परिणाम है कि दोनों दलों के कार्यक्रमों और नीतियों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया जाता ।

राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अमेरिकन राजनीतिक क्षेत्र में अनेक मण्डल, क्लब, गुट, समुदाय समितियाँ, संगठन और अन्य प्रकार की संस्थाएँ समय-समय पर जन्म लेती रहती हैं जो यथा शक्ति समकालीन राजनीति में प्रभावशाली बनने का प्रयत्न करती हैं और प्रस्तावित कानून या सरकारी नीति का समर्थन अथवा विरोध करती हैं ।

दलीय कार्यक्रम

(Party Issues or Programme)

अमेरिकन राजनीतिक दलों में कोई महत्वपूर्ण सैद्धांतिक मतभेद नहीं पाये जाते । अतएव इनका कोई निश्चिन्त ध्येय और कार्यक्रम नहीं रहा है । प्रजातन्त्रीय और प्रतिनिधि शासन के बारे में दोनों का—समान मत रहा है और दोनों ही दल एक ही शासन पद्धति में विश्वास रखते हैं । फिर भी समय-समय पर उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद पैदा होता रहा है ।

कुछ समय से रिपब्लिकन दल का कानून यह रहा है—देश के समस्त राज्यों के बीच मुहृद गगठन, मयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, सावित्र हस एव सायवाद के विरोध म वडि, राष्ट्रवादी चीन का अधिक ने अधिक सहायता देना, सनिक तैयारी, साम्यवादी चीन की मायना का विरोध करना, अमिका क लिए वीमा और सामाजिक वीम की याजनाने, उत्पादना तथा अमिका क हितो म अयनर की नीति उद्यागा के राष्ट्रीयकरण का विराध आदि। दूसरी ओर "मोक्रटिक दल के कार्यक्रम म भी लगभग इसी तरह के लय मम्मिलित है—निजी उद्यागा का समर्थन मध सरकार का समर्थन और राज्या म जाति भेद का जत, सयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, साम्यवाद का विराध, साम्यवाद के समर्थन का सरकारी पयो से हटाना, सावित्र मध को प्रसज करने की नीति का विराध, उत्तर एटलांटिक संधि का समर्थन, पिछडे देशो को आर्थिक सहायता, साम्यवादी चीन को मायता न देना, आदि। स्पष्ट है कि दोनो ही दला की वैदेशिक तथा आर्थिक नीति म कोइ विषय आदि। स्पष्ट है कि दोनो ही दला की वैदेशिक तथा आर्थिक नीति म कोइ विषय आदि। स्पष्ट है कि दोनो ही दला की वैदेशिक तथा आर्थिक नीति म कोइ विषय आदि।

अंतर नहीं है। इसीलिए ग्राइस न कहा है कि "अमेरिका के राजनीतिक दल दो बातों का समान हैं जो साली हैं और जिन पर अलग अलग खबल लग हुए हैं।" फोइनर क अनुसार "अमेरिका मे केवल एक दल रिपब्लिकन नम डेमोक्रटिक है जो एक या नाम रिपब्लिकन तथा दूसर का डेमोक्रटिक है।" मेकार्थी का विचार है कि इस शताब्दी म डेमोक्रटिक दल न जातरिक और वैदेशिक मामला म नय निणय किये हैं। इसने राष्ट्र मध का प्रस्ताव रखा और सयुक्त राष्ट्र मध की स्थापना म भाग लिया। इसन सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम का स्थापित और विकसित किया एा अर्थिक प्रव बक सम्बन्धों के विषय म कतिपय आधारभूत कानून बनाये। मेकार्थी के मतानुसार डेमोक्रटिक दल की तुलना म रिपब्लिकन दल परिवर्तन और नवीन बातों को स्वाकार करन म अपेक्षाकृत धीमा रहा है।

दलीय संगठन

(Organisation of the American Parties)

अमरिका के दाना प्रधान दला का संगठन प्राय समान-ना है। दानो ही दला का संगठन राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तरा पर है। राष्ट्रीय या केन्द्रीय स्तर पर दलीय संगठन

बन्ध और राज्य जाना ही स्तरा पर दला का नगठना बना मुय्यवस्थित है। दल अपनी चार इकाइया द्वारा गठन कृत हैं। वेद म य चारा इकाइया निम्ना-नुसार हैं

राष्ट्रीय सम्मेलन—बन्धो-स्तर पर एा सम्या राष्ट्रीय सम्मेलन (National Convention) नहीं जाती है जिनके सदस्यो की गम्या लगभग 1,400 सदस्यो तक होती है। यह राष्ट्रीय दल का सर्वोच्च जय हुता है। यह विभिन्न विधियों व

निर्वाचित एक विशाल प्रतिनिधि मन्त्रालय है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जिन वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उनी वर्ष इसका अधिवेशन होता है। दूसरे शब्दों में, सामान्यतः यह सम्मेलन प्रति चौथे वर्ष होता है। इसे केवल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पदा के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करने और चुनाव आन्दोलन के लिए दलीय कार्यक्रम निर्धारित करने का ही नहीं, बल्कि देश के मूठभूत नगठन और नियमों के 'विधान' को भी नियन्त्रित करने का अधिकार होता है। कांग्रेस की सदस्यता के प्रत्याशियों के विषय में यह सम्मेलन कुछ नहीं करता। साथ ही कांग्रेस के सदस्यों को यह इन बातों के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता कि वे दलीय कार्यक्रम का ही समर्थन करें।

राष्ट्रीय समिति—देश के सामान्य कार्य संचालन के लिए प्रत्येक दल की एक स्थायी कार्यकारिणी समिति होती है जिसे राष्ट्रीय समिति (National Committee) कहा जाता है। रिपब्लिकन दल की राष्ट्रीय समिति में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र के 2 प्रतिनिधि होते हैं—एक पुरुष और एक महिला। डेमोक्रेटिक दल में भी यही व्यवस्था है, केवल अंतर यह है कि उसमें पनामा नहर क्षेत्र और वर्जीनिया-जार्जिया के भी प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि सामान्यतः राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये राज्यों से निर्वाचित प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा चुने जाते हैं।

राष्ट्रीय समिति का मुख्य कार्य अपने में से दो कार्यकारिणी समितियाँ का निर्माण करना है, जो उसके लगभग सभी कार्यों का संचालन करती हैं। इन समितियों के नाम हैं—कांग्रेसीय आंदोलन समिति (Congressional Campaign Committee) तथा सीनेट निर्वाचन आंदोलन समिति (Senatorial Campaign Committee)। इन समितियों के मुख्य कार्य हैं—राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना, दल के व्यय के लिए काश एकत्रित करना, राज्य के प्रतिनिधियों की समस्या निश्चित करना, प्रतिनिधि आगार एवं सीनेट के निर्वाचन कार्य का संचालन करना, आदि। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रीय समिति स्वयं भाग लेती है। इस निमित्त वह प्रत्येक चौथे वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन का आमन्त्रित करती है, डेमोक्रेटिक दल की राष्ट्रीय समिति ने लगभग 108 सदस्य होते हैं और रिपब्लिकन दल की समिति में लगभग 147।

राष्ट्रीय अध्यक्ष—राष्ट्रीय संगठन की एक अन्य इनाइ राष्ट्रीय अध्यक्ष (National Chairman) होता है, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के निर्वाचन के बाद प्रत्येक 4 वर्षों बाद चुना जाता है लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रायः वही व्यक्ति होता है जिसे मनोनीत राष्ट्रपति चाहता है। समिति ना केवल उसके द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के नाम का पुष्टिकरण मात्र करती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अभियान का संचालन करना होता है। दल के, राज्य के और क्षेत्र के मण्डलों से उनका निकट सम्पर्क रहता है। जब उनकी शक्ति व्यवहार में कम होती जा रही है।

राष्ट्रीय समिति सचिवालय--अमेरिका में दलीय संगठन के कार्य का वास्तविक मन्त्रालय बहुत कुछ जन लोग की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है जो राष्ट्रीय समिति के सचिवालय में होते हैं। प्रत्येक दल के सचिवालय का संगठन भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी विविध प्रकार के हैं। सचिवालय ही नेताओं का आस पकड़ने का और उनका हिमायत रखता है। मंत्रिमंडल का देश की राजनीति में उतार चढ़ाव पर ध्यान रखना पड़ता है। स्थानीय और राज्य के दलीय संगठनों से पत्र व्यवहार करना यदि सचिवालय के कार्य में हो सम्मिलित है।

राज्य स्तर पर भी दोनों दलों का संगठन समान सा है। हर राज्य में दोनों दलों की एक-एक केन्द्रीय समिति (State Central Committee) है जिसका आकार और निर्माण विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार का है। अनेक राज्यों की केन्द्रीय समितियों में केवल राज्य की काउण्टी समितियाँ के जेयरमन ही होते हैं। इन समितियों के सदस्य सामान्यतया प्रारम्भिक इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं और इनमें स्त्री तथा पुरुष सदस्यों की संख्या समान होती है। राजकीय केन्द्रीय समिति द्वारा राज्य के समस्त दलीय संगठनों पर नियंत्रण रखा जाता है। वह धन एकत्र करती है तथा छांट पड़ा के लिए दलीय उम्मीदवारों का नामांकन करती है। इसकी भी अपनी एक कार्यकारिणी समिति और अपना कोषाध्यक्ष होता है। समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दल के गवर्नर या स्थानीय स्तर पर संगठन

को का निम्नतम संगठन स्थानीय संगठन कहलाता है जिस विभागीय संगठन (Precinct Organisation) भी कहते हैं। जहाँ तक इस संगठन का प्रश्न है अमेरिका की दलीय व्यवस्थाओं में समानता नहीं पाई जाती। फिर भी स्थानीय संगठन इस प्रकार हैं—

- 1 प्रिंसिपल समिति (Precinct Committee)
- 2 वार्ड समिति (Ward Committee)
- 3 काउण्टी समिति (County Central Committee)
- 4 नगर समिति (Town Committee)

इन स्तर पर सबसे छोटी इकाई प्रिंसिपल समिति है जिसकी दल में सरासरी लगभग 100 से लेकर 500 तक मतदाता होते हैं। हर समिति में हर दल का एक नेता और एक कप्तान होता है जिस समिति अधिनारी भी कहा जाता है और जिसकी नियुक्ति वनी कभी उच्चतर दलीय संगठन द्वारा की जाती है किन्तु उसे सामान्यतः Precinct के मतदाताओं द्वारा ही होती है। इस मतदान समितियों की कार्य कुशल-

लगा पर दल की हार या जीत निर्भर करती है। वास्तव में ये दलीय व्यवस्था के प्राण हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियाँ भी हाती हैं जो शहरी मतदान समितियाँ के कार्य का संचालन करती हैं। वार्ड मतदान और अन्य शहरी दलीय माठन की इकाइयों के कार्यों के निरीक्षण हेतु हर दल की नगर समिति (City Committee) हाता है। ग्रामीण संगठन की इकाइयाँ का काम इस प्रकार है—

1 ग्रामीण मतदान में समितियाँ (Rural Precinct Committees)—यह सबसे छोटी इकाई है।

2 ग्राम एवं तस्वा समितियाँ (Village and Township Committees) इनके द्वारा ग्रामीण मतदान समितियाँ के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दलीय इकाइयाँ के ऊपर काउण्टी संगठन है जिसका संचालन काउण्टी समिति द्वारा किया जाता है। इन काउण्टी समिति में चेयरमैन तथा एक केंद्रीय काउण्टी समिति होती है जिसका कार्य नीचे की स्थानीय इकाइयाँ के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। समिति का चेयरमैन बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होता है और वह कुछ ऐसे पदों की नियुक्ति भी करता है जिनका राजकीय या सघीय सेवाओं से संबंध होता है। ये काउण्टियाँ सारे दस में लगभग तीन हजार से भी अधिक हैं। इन सबके ऊपर जिला संगठन होता है। हर जिले में हर दल की एक जिला समिति हाती है।

अमेरिका में अनेक ऐसे चुनाव होते हैं, जिनमें विजयी होने के लिए व्यक्ति का किसी न किसी दल से निर्वाचित होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण पद जिनके लिए निर्वाचित होता है, ये हैं—राष्ट्रपति का, कांग्रेस का, राज्यों के गवर्नरों का, 'याया-घोषों का। इन पदों की प्राप्ति के लालच से ही छोटे दलों में घुसते हैं और कठोर श्रम करते हैं, यह सोच कर कि कहीं ऐसा न हो कि समेल में तो फस जायें और प्राप्ति कुछ न हो।

अमेरिकन दल पद्धति की विशेषताएँ (Features of American Party System)

विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ के दल स्वरूप और कार्यप्रणाली में भिन्न हैं, अतः इनकी मुख्य विशेषताओं को देख लेना रोचक होगा।

कठोर संगठन—अमेरिका में दलीय संगठन बड़ा कठोर, नियंत्रित और केंद्रित होता है। दल प्रणाली करीब-करीब एक मशीन बन गई है जिसने जनता को अपनी मूठों में दबा लिया है। अनेक लोग प्रतियोगिता की भावना से कार्य करते हैं। कुछ लोग दलीय भावना से इनका कार्य करते हैं परन्तु अधिकांश लोग इसलिए इनमें कार्य करते हैं कि उन्हें कोई नौकरी मिल जावगी। दलीय संपर्क में लोगों का स्थायी स्वाद्य होता है। प्रॉफाइल के अनुसार "अमेरिका में जितने आदमी दलीय संगठनों पर कार्य करते हैं उतने पाँच सौ सभ्य समाज के किसी भी देश में काम नहीं करते।"

परम्पराओं पर आधारित—अमेरिकी दलीय व्यवस्था भी ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की भाँति परम्पराओं और प्रथाओं पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने दलीय व्यवस्था को सरारत, अष्टाचार और अनतिक्रम करने वाला तत्त्व कह कर संविधान से निकाल दिया था। किंतु दलीय व्यवस्था को बनाये रखने की उनकी यह भासा पूरा नहीं हुई और आज तो इन व्यवस्था के अभाव में अमेरिकी शासन का जनतन्त्र नीय ढाँचा लड़खड़ा कर गिर पड़ा है। लाइ ब्राह्म ने स्पष्ट लिखा है कि, दल का गठन संविधान द्वारा स्थापित राजनीति के माध्यमों से एक दूसरे ही सरकार बना हुआ है जिसका कानून में कहीं जिक्र तक नहीं है।

वर्गीय मतभेद—अमेरिकन दल में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद हैं। वहाँ राजनैतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परम्परा एवं औपचारिक प्रभाव का आधार अधिक है। वहाँ अमेरिकन किनी दल को प्रायः इस कारण नहीं अपनाता है कि वह दल उनकी विचारधारा के अनुकूल है, अपितु इसलिए ग्रहण करता है कि उनके पिता या सम्बन्धियों ने उसे अपना रखा है या वह दल उसके समाज जाति व्यवसाय या रम के माध्यम जुड़ा है। वस्तुतः अमेरिका दल हितों के गुट है सिद्धान्तों के समूह नहीं। इसके अतिरिक्त दल का वर्गीय आधार अधिक व्यवस्था पर निर्भर है। अमेरिकन उद्योगपतियों के अपने-अपने संगठन हैं और इनका यह एक प्रमुख वाय है कि धन व्यय करके किसी एक राजनीतिक दल पर अपनी सत्ता जमाये रखी जाए।

द्विदल प्रणाली—अमेरिकन दलीय व्यवस्था द्विदलीय है। अब दल यदि मदान में जाते भी हैं तो निराचन में सफलता के निकट नहीं पहुँच पाते। अमेरिकन राजनीति में दल व्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न विफल हो चुके हैं। इनका प्रमुख कारण यह है कि छोट छोट दल जिस कार्यक्रम का लेकर उठते हैं वहाँ उक्त दोनों दलों के द्वारा अपना लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे दलों के पास माध्यम तत्त्व और अधिक हठना की भी कमी रहती है। एक अन्य बात यह भी है कि अमेरिका में जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद आदि का कोई महत्व नहीं है, अतः वहाँ अन्य दल नहीं बन पाते।

मौलिक सैद्धांतिक मतभेदों का न होना—अमेरिका के राजनीतिक दलों में मौलिक सैद्धांतिक मतभेद लगभग नहीं हैं और न ही उनका कोई सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्य है। दल ही दलों का मुख्य नीतियाँ लगभग समान हैं।

दलीय नेता का महत्व—अमेरिका में दल के नेता का महत्व ब्रिटिश दलीय नेता की तुलना में बहुत ही कम है। वहाँ की संसदीय दल का एक मात्र और सर्वोच्च नेता नहीं होता है। ब्रिटिश नेता का समान बड़ा दल का नागरिक विधायक नहीं होता और न ही दल के जनसभा निर्वाचक दल से उनका अनुसरण ही करते हैं। फिर भी वर्तमान प्रगतिशील नेता का महत्व उठाने की आरंभ है। एक राष्ट्रपति पद का लिए नेता निर्माण में महत्व रखते हैं।

स्थानीय हितों को महत्व—अमेरिका की दल प्रणाली में स्थानीय हितों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाता है चाहे वहाँ के दलों के संगठन का रूप केन्द्रीकरण का हो या विकेन्द्रीकरण का हो। दलों का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं के बराबर है, परन्तु विकेन्द्रीकृत संगठन उनकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने वाला है, कम करने वाला नहीं। इसका मुख्य कारण यही है कि अमेरिका में राजनीतिक दल स्थानीय और राष्ट्रीय हितों के विषय में समन्वयतावादी प्रवृत्ति में काम लेते हैं। परिणामस्वरूप दलों का संगठन पक्का बना रहता है।

अमेरिकन दल प्रणाली की आलोचना

(1) अमेरिकन दल व्यवस्था का रूप विकेन्द्रीकरण का है। अमेरिकन दलों के स्थानीय, राज्यीय और केन्द्रीय संगठनों में उस सामन्तजस्य के दर्शन नहीं होते, जो एक सुसंगठित दल में होना चाहिए। फलस्वरूप दल शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के अपने प्रमुख कार्य का निर्वहन नहीं कर पाता। मतदान के समय का दलीय दायित्व भी समाप्त होता जाता है जिससे अमेरिकन लोकतन्त्र की आत्मा कुप्रभावित होती है।

(2) अमेरिका की शासन प्रणाली में दल प्रणाली से अधिक उल्लंघन में डालने वाली और कोई मस्या नहीं है। 'दलीय संगठनों में स्थानीयवाद एवं गुटवाद की भावना, दलों में निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम, नीतियाँ तथा सिद्धांतों का अभाव, समस्याओं में दलीय अनुशासन का अभाव, व्यवस्थापिका में दल के द्वारा निर्धारित किये हुए प्रस्तावों के समर्थन के लिए उद्देश्य में दल के प्रति निष्ठा का न होना या बहुत कम होना आदि बातें अमेरिकन राजनीतिक दलों को 'स्वार्थों का एक गुट' बना देती हैं। एक अस्थायी नेता के चारों ओर समर्थकों का एक दल एकत्रित हो जाता है जो उस पर यथा शक्ति प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है।

(3) अमेरिकन दलीय व्यवस्था में 'स्पाइल सिस्टम' (Spoil System) की दूषित प्रथा पायी जाती है। अमेरिका में अनेक पद ऐसे हैं जो अस्थायी होते हैं। जब किसी राष्ट्रपति के दूसरे दल का होता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पद से हटाना पड़ता है और उनमें स्थान पर राष्ट्रपति अपने दल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार की जा नियुक्तियाँ की जाती हैं, उनका आधार योग्यता अथवा अनुभव नहीं होकर मुख्य रूप से दण्डनीयता होता है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक कुशलता घटती जाती है। प्रशासकीय पदाधिकारी भी प्रशासन की कुशलता की दृष्टि से नहीं बरन दलों के सम्बन्धों का निर्वहन की दृष्टि से कार्य करने हैं।

उपरोक्त बातों के बावजूद भी अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली अक्षय्यापूर्वक चल रही है। इसी कारण मनना न पड़ता है 'जब द्विदलीय प्रणाली का उगम से कार्य करना रही है, तो तामर तथा बोध दण्ड की मोह आवश्यकता नहीं है।'

राष्ट्रीय संधि सविधान पर निर्भर नहीं है। इन सविधानों के आधारभूत सिद्धांत एक हैं जो इंग्लैंड में बसे हुए जपान साथ लाये थे। भूमि के विस्तार, जन्मभूमि, भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक अवस्था आदि की दृष्टि से राज्यों में पारस्परिक विभिन्नताएँ हैं।

राज्यों के सविधान (States' Constitutions)

प्रमुख विशेषताएँ

अमेरिका के सभी राज्यों के सविधान मोटे रूप से एक से होते हुए भी विवरण की बातों में परस्पर भिन्न हैं। फिर भी सभी सविधानों में प्रायः निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ पायी जाती हैं—

1 राज्य के सविधान सघीय सविधान से विल्कुल पृथक् हैं। उनकी शक्ति का स्रोत पथक पृथक् राज्यों की जनता है।

2 सघीय सविधान की तरह राज्यों के सविधान भी लिखित हैं। प्रत्येक राज्य को अपने सविधान के निर्माण, उन्मूलन और उसके संशोधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

3 प्रायः सभी सविधानों में अधिकार पत्र की व्यवस्था है, जिसमें कुछ नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की गई है।

4 सविधानों में शासन के ढांचे की रूप रेखा दी गई है और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।

5 प्रत्येक राज्य में द्वि-मंडलीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था है।

6 सामान्यतः सभी सविधानों में शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को स्थान दिया गया है। राज्यपालों, न्यायाधीशों तथा विधान-मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है।

7 राज्य की शक्तियाँ एवं दायित्वा का वर्णन किया गया है। राज्य सरकारों की शक्तियाँ मौलिक (Original) हैं और सघीय सरकार की शक्तियाँ प्रदत्त या प्रत्यायोजित (Delegated)।

8 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन—जनमत संग्रह (Referendum), आरंभक (Initiative), प्रत्याह्वान (Recall) की व्यवस्था है।

9 स्थानीय शासन की व्यवस्था भी है।

10 राज्यों की पथक नागरिकता है। इन प्रकार बहना चाहिए की प्रत्येक राज्य में दाहरी नागरिकता है—प्रत्येक राज्य का जोर राज्य की।

11 राज्य सविधान में सघीय सविधानों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शासन पद्धति का अंगण दिया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका व प्रति उत्तरदायी नहीं है और न्यायपालिका का सविधान में विधान शासन का अधिकार है।

12 प्रायः सभी संविधानों में एक धारा इस उद्देश्य की भी दांग है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जायेगा।

राज्य का शासन-संगठन

(Administrative Organs of States)

राज्यों की शासन व्यवस्था के भी तीन प्रधान अंग हैं—

1 कार्यपालिका (The Executive)

2 व्यवस्थापिका (The Legislature)

3 न्यायपालिका (The Judiciary)

कार्यपालिका (राज्यपाल)

राज्यों की कार्यपालिका में अलग-अलग राज्यपाल उपराज्यपाल, राज्य सचिव, महा-न्यायवादी, लेखा परीक्षक, कोषाध्यक्ष तथा निरीक्षक होते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल (Governor) होता है। राज्य शासन में राज्यपाल (Governor) की वही स्थिति है जो संघ शासन में राष्ट्रपति की है। राज्यपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

योग्यताएँ—राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति की (क) आयु कम से कम 30 वर्ष हो, (ख) वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो, एवं (ग) वह उस राज्य में कम से कम 5 वर्ष से रहता हो।

निर्वाचन—अमेरिका में मिसौसिपी राज्य का छोड़कर सभी राज्यों में राज्यपाल जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से बहुमत के द्वारा निर्वाचित होते हैं। समान मतों की प्राप्ति की दशा में अंतिम निर्णय राज्य की व्यवस्थापिका करती है।

कार्यकाल—राज्यपाल का कार्यकाल विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। वह अपने पद पर 2 से 4 वर्ष तक कार्य करता है। उसका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। वह राज्य के व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किंतु महाभियोग द्वारा उस हटाया जा सकता है। नीचे का सदन महाभियोग लगाता है और ऊपर का सदन महाभियोग की सुनवाई करता है। कभी कभी महाभियोग की सुनवाई ऊपरी सदन का सभापति करता है। महाभियोग का प्रयोग अभी तक बहुत कम हो पाया है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। कुछ राज्यों में प्रत्याहरण (Recall) द्वारा भी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि कुछ निश्चित सस्या में मतदाता प्रायणा करें तो किसी राज्यपाल को समय से पहले पद से हटाया जान के विषय में मत-मग्नह किया जा सकता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ

राज्यपाल की शक्तियाँ विविध प्रकार की हैं —

कार्यपालिका व्यवस्था—संविधान के अनुसार राज्यपाल (Governor) राज्य का सर्वोच्च प्रशासक है जिसका यह कर्तव्य है कि वह इस बात का प्रवर्ध करे

वि कानून नृत्य निष्ठा में लागू किया जाय। इस रूप में वह प्रशासक का मुख्य निदेशक तथा निरीक्षक होता है लेकिन इन विषयों में उसे जो अधिकार प्राप्त हैं वे बड़े अपेक्षा हैं। अपने आदेशों का पालन करवाने के लिये अधिकांशतः उसे अपने अधीनस्थ कमचारियों एवं प्रधान, अन्य प्रशासनाधिकारियों पर जोसे उप राज्यपाल (Lt Governor), अभिलेख मंत्री, कोषाध्यक्ष, महायायवादी (Attorney General), शिक्षा मंचालक, ऑडिटर और कंट्रोलर जनरल, स्थानीय निर्वाचित काउण्टी अधिकारी, सरकारी वकील, विभिन्न राज्य न्यायालयों के जनता द्वारा निर्वाचित यायाधीश आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। इन अधिकारियों पर राज्यपाल का प्रत्यक्ष और प्रभावशाली नियंत्रण नहीं होता। राज्यपाल के साथ ही निर्वाचित प्रशासनाधिकारी समझते हैं कि वे राज्यपाल की अपेक्षा जनता के प्रति विसंग उत्तरदायी हैं।

राजकीय नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्यपाल तो यद्यपि व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु उनकी व्यापकता नियमित नियुक्ति प्रणाली के प्रचलन से काफी कम हो गई है। वस्तुतः राज्यपाल उन्हीं पदों पर नियुक्ति कर सकता है जिनकी संविधान में उसके द्वारा नियुक्ति की जाने की व्यवस्था की गई हो या जिनकी नियुक्ति अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में वही कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ पदों पर व्यवस्थापिका से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत वह नियुक्ति कर सकता है, परन्तु इस पर अनेक प्रतिबंध लग चुके हैं। किसी भी स्थिति में राज्यपाल उन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करता जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं और जो राज्यपाल के साथ ही स्वतंत्र रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिये चुने जाते हैं। यह प्रतिबंध राज्यपाल की शक्तियों पर एक बड़े अकुश का कार्य करता है क्योंकि इस बात की सदैव सम्भावना रहती है कि ये अधिकारी राज्यपाल से सहाय्य न करें और इस प्रकार वह कठिनाइयों में पड़ जाय तथा राज्य के शासन में गतिरोध और संघर्ष पैदा हो जाय। अटोर्नी जनरल (Attorney General), कंट्रोलर्स (Controllers), ऑडिटर्स (Auditors) व सुपरिन्टेण्डेंट्स (Superintendents) आदि की नियुक्ति राज्यपाल करता है किन्तु इनका पुष्टिकरण राज्य की सीनेट द्वारा होना आवश्यक है।

अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर राज्यपाल का नियंत्रण इस कारण और भी कम हो जाता है कि प्रशासन अधिकारियों को निदेशित करने और उन्हें पदच्युत करने का उसका अधिकार भी नगण्य ही है। मुख्य निर्वाचित अधिकारियों को केवल महाभियोग द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है अतः इसके द्वारा पदच्युति के मामले बहुत ही कम होते हैं। जहां राज्यपाल को कुछ अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार दिया भी गया है वहां यह प्रतिबंध है कि राज्यपाल उन्हें केवल सीनेट की स्वीकृति से ही पदच्युत कर सकता है, अन्यथा नहीं। साधारणतः राज्यपाल जिन अधिकारियों को नियुक्त

करता है उन्हें हटा भी सकता है, पर तु जिनकी नियुक्ति वह सीनेट की स्वीकृति से करता है उन्हें सीनेट की स्वीकृति से ही हटाया जा सकता है।

राज्यपाल के मधीय सरकार (Federation) के प्रति भी कुछ कृतव्य है। राज्यपाल ही मधीय सरकार द्वारा प्रेषित आदेशों को प्राप्त करता है और वही मधीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य माध्यम का कार्य करता है। जब नयी मधीय सरकार राज्य का महयाग प्राप्त करना चाहती है तो वह सम्बन्धित सरकार के राज्यपाल को ही लिखती है।

सैनिक शक्तियाँ—राज्यपाल राज्य की सीनेट और राज्य रक्षक सेना का नाममात्र का मुख्य सेनापति होता है। उसकी सैनिक शक्तियाँ अब पहिले के समान नहीं रही हैं क्योंकि रक्षा का विषय अब मधीय हो गया है। फिर भी उन राष्ट्रीय मरनका (Home Guards) पर उसका नियन्त्रण रहता है, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में नियमित सैनिक कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है। राज्यपाल का आन्तरिक सेना (Military) पर भी नियन्त्रण रहता है और वह आन्तरिक गड़बड़ के समय उसे कार्य पर लगा सकता है। हड़ताल आदि के समय भी राज्य की सत्ता का शांति व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयोग राज्यपाल कर सकता है। सैनिक कार्यों में राज्यपाल की सहायता उसका एडजुटन्ट जनरल (Adjutant General) व उसके अधीन कमचारी करते हैं।

विधायी एवं वित्तीय शक्तियाँ—राज्यपाल का कुछ विधायी अधिकार भी प्राप्त है। वह मविधान-मण्डल के विशेष निर्वाचना के लिये आदेश दे सकता है, राज्य के विभिन्न बोर्ड और आयोगों का सदस्य होता है, विधानमण्डल में सदन भेज सकता है और राज्य के लिये आवश्यक विधियाँ को स्वीकृत करने की सिफारिश कर सकता है। अपने नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार के कारण वह विधान मण्डल के सदस्यों को प्रभावित कर सकता है। राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत विधियाँ के विपक्ष रूप से नियम उप-नियम बनाना सकता है। उसे विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम का पुनर्विचार के लिये भेजने का अधिकार प्राप्त है। वह अधिनियम के किसी अंश का निषेध कर सकता है। अव्यादेश जारी करने का भी वह अधिकारी है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल व्यवस्थापिका में भाषण दे सकता है और उसके द्वारा जनता को अपना सदेश पहुँचा सकता है।

राज्यपाल को महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वित्त 30 या 40 वर्षों में अनेक राज्यों में राज्य का राजस्व और विनियोग (राज्य के बजट का तयार करना) के मध्य व में राज्यपाल के अधिकारों में बहुत वृद्धि हुई है। अनेक राज्यों में उसे बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है और इसीलिये उसको जबवा उनके प्रति उत्तरदायी अधिकारियाँ और कतिपय अधिकारियाँ को यह कार्य सौंपा गया है कि वे विभिन्न विभागों और सम्बन्धों में बजट तैयार कराने से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत बजट को प्राप्त क

आधार पर ही विधान मंडल प्रायः राज्य का बजट स्वीकार करता है। व्यय विनियोग विधायक पर राज्यपाल को किसी भी मत पर निषेधाधिकार लागू करने का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय मामलों में राज्यपाल की स्थिति वस्तुतः पर्याप्त महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है क्योंकि राज्य का प्रमुख प्रशासनाधिकारी हान के नाते उससे अधिक किन्हीं का भी प्रशासकीय विभागों की आवश्यकताओं का पान सम्भवतः तही हो सकता है।

व्यापक शक्तियाँ—व्यापक श्रेष्ठ में राज्यपाल को क्षमादान आदि देने का अधिकार है ताकि 'राज्यपालिका' की ओर से की हुई त्रुटियों के विरुद्ध वह जनता की रक्षा कर सके। अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग राज्यपाल एक परामश-दात्री समिति के परामर्श के अनुसार करता है।

यह स्पष्ट है कि राज्य के सचिवान के अनुसार राज्यपाल का कार्य प्रमुख कार्यपालक (Chief Executive) के रूप में सामान्य रूप से राज्य के प्रशासन की देखभाल करना है। कुछ राज्यों में सघीय परम्परा को अपनाते हुए राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विविध विभागों के अध्यक्षों से प्रशामन सम्बन्धी प्रतिवेदन माग सके।

राज्यों के प्रशासनिक विभाग साधारणतः ये होते हैं—1 वजट निर्माण अथवा वित्त विभाग, 2 जाय अथवा कर विभाग, 3 सावजनिक सुरक्षा विभाग, 4 सैनिक विभाग, 5 कृषि विभाग, 6 स्वास्थ्य विभाग, 7 बीमा विभाग, 8 स्वच्छता विभाग, 9 राजकीय माग विभाग, 10 राजकीय मन्थार्य, 11 लोक-कल्याण विभाग, आदि।

कुछ विभाग उप विभागों में भी बटे रहते हैं और उनके अधीनस्थ विभागों के अधीन तथा उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुछ विभागों का प्रबन्ध विविध परिपदी या समितियों के द्वारा या उनके परामर्श के अनुसार होता है।

व्यवस्थापिका

एक दो राज्यों का छोड़कर अन्य सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। कहीं उसे व्यवस्थापिका (Legislature) कहा जाता है, तो कहीं साधारण सभा (General Assembly), कहीं व्यवस्थापिका का साधारण अधिवेशन (General Court) भी कहा जाता है। सभी राज्यों में ऊपरी सदन का नाम देखा जाता है, लेकिन नीचे के सदन को कहीं तो प्रतिनिधि सदन (House of Representative) के नाम से, तभी केवल सभा (Assembly) के नाम से, कहीं प्रतिनिधि सभा (House of Delegates) और कहीं साधारण सभा (General Assembly) के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

सीनेट का आकार निम्न सदन से छोटा होता है। इसमें सामान्यतः निम्न सदन के सदस्यों के एक तिहाई व्यक्ति सदस्य होते हैं। सीनेट की सदस्यता जहाँ 6 से लेकर 67 सदस्यों तक की है वहाँ निम्न सदन की सदस्यता 35 से लेकर

400 तक है। इस प्रकार यदि सीनेट की सदस्यता का औसत 37 सदस्य का जाता है तो निचले सदन के सदस्यों का औसत 120 का आता है।

प्रतिनिधि सभा अर्थात् निचले सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है और सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन समान प्रतिनिधित्व के आधार पर काउन्टी के द्वारा। अधिकांशतः राज्यों में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का है। साथ ही अधिकांश राज्यों में सीनेट की अध्यक्षता उप-राज्यपाल (Lt Governor) करता है।

राज्य की व्यवस्थापिकाओं को प्रायः वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सभ्य सरकार को प्रदत्त नहीं हैं। सभ्य राज्य की व्यवस्थापिका को अपने कार्यक्षेत्र के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों में कर लगाना, कुछ करों का समाप्त करना, संविधान के संशोधन प्रस्ताव पर मत देने आदि प्रमुख हैं। कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकारों में व्यवस्थापिका के दानों की सदन समक्ष है। परम्परा के अनुसार साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है, किन्तु धन विधेयक की प्रथम प्रस्तावना प्रतिनिधि सभा अर्थात् निचले सदन में ही होती है। सीनेट को समस्त विधेयकों के सम्बन्ध में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति पाकर अधिनियम बन जाते हैं। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनः विचारार्थ लौटा देता है और व्यवस्थापिका दूसरी बार निर्धारित मतों द्वारा उसे स्वीकार कर देती है तो बिना राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुए ही वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। निर्धारित बहुमत विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। यदि दोनों सदनों में विधेयक की स्वीकृति पर मतभेद विद्यमान रहता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है।

राज्यपाल या अन्य उच्चाधिकारियों पर महाभियोग चलाने के अधिकार भी दोनों सदन की सम्मिलित रूप से हैं। निचले सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाता है और उच्च सदन न्यायालय के रूप में उसकी सुनवाई करता है व उस पर निर्णय देता है।

सभी व्यवस्थापिकाओं की भाँति राज्य व्यवस्थापिका भी समितियों का व्यापक प्रयोग करती है। निचले सदन में समितियों की नियुक्ति दलीय नेताओं के परामर्श में अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है अथवा दल के अंतरंग मण्डल से ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जाता है। सीनेट में या तो बहुमत दल के नेता की सिफारिश पर ऊपरी सदन समितियों के सदस्य चुनता है या अध्यक्ष (Lt Governor) या अस्थायी अध्यक्ष इस कार्य को सम्पन्न करता है।

न्यायपालिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रकार के न्यायालय समानान्तर रूप में कार्य करते हैं। एक प्रकार के न्यायालय वे हैं जो सभ्य कानूनों को क्रियान्वित करते

हैं और दूसरे प्रकार के न्यायालय वे हैं जो राज्या के कानूनों को क्रियावित करते हैं। अमेरिका की इस व्यवस्था के विपरीत भारतवर्ष में केवल एक ही प्रकार के न्यायालय के द्वीय और स्थानीय दोनों ही प्रकार के कानूनों को क्रियावित करते हैं।

जहां तक राज्यों के कानूनों के क्रियान्वयन का प्रश्न है, अमेरिका के प्रत्येक राज्य में अपने-अपने सविधान के अन्तर्गत न्यायपालिका स्थापित है, अतः प्रत्येक राज्य की न्याय व्यवस्था बिल्कुल पथक और स्वतंत्र है। राज्य के न्यायालय सघीय न्यायालयों के आधीन नहीं होते प्रत्युत वे एक पथक न्यायपालिका के अंग होते हैं जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी स्वतन्त्रता व शक्ति रहती है। सामान्य संगठन की दृष्टि से ये न्यायालय सघीय न्यायालयों से बहुत कुछ मिलते हैं। मघीय और राज्यीय दोनों न्याय प्रणालियों में छोटे बड़े न्यायालय होते हैं जिनके कार्य और अधिकार एक दूसरे से भिन्न, कम या अधिक होते हैं। राज्या के न्यायालय प्रायः दो बड़ी बातों से मघीय न्यायालय से भिन्न हैं। पहिला महत्वपूर्ण अद तो यह है कि राज्य न्यायपालिका के न्यायाधीश प्रायः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं जबकि मघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायपालिका नियुक्त करती है। केवल 10 राज्य ऐसे हैं जिनके न्यायाधीश निर्वाचित न होकर कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा प्रमुख भेद यह है कि प्रत्येक राज्य में न्याय पद्धति भिन्न भिन्न है, अतः मग राज्या में न्याय-व्यवहार में समानता नहीं पाई जाती।

राज्यों के न्यायाधीशों पर व्यवस्थापिका का निबन्धन सदन अभियोग लगा सकता है और सीनेट अर्थात् उच्च सदन अभियोग की जांच करके उन्हें दोषी ठहरा सकता है और उनके पद से हटा सकता है। 12 राज्यों में यह प्रथा प्रचलित है कि व्यवस्थापिका में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होने से ही किसी न्यायाधीश का पदच्युत किया जा सकता है। 9 राज्यों में राज्यपाल व्यवस्थापिका की प्रायोजना पर न्यायाधीशों को हटा सकता है। कुछ राज्यों में जनता न्यायाधीशों को प्रत्याहरण (Recall) कर सकती है। इसके लिये पदच्युत करने की प्रायोजना पर जनता का प्रत्यक्ष मत लिया जाता है। इन राज्यों में न्यायालयों के कुछ निर्णयों को भी जनमत से वापिस किया जा सकता है।

अमेरिका में राज्यों के न्यायालयों की व्यवस्था का वगन मोटे रूप से इस निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत कर सकते हैं—

1 सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)—राज्यों की न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो राज्य के न्यायिक मामलों में सबसे ऊँचा न्यायालय है और जिसके निर्णय व विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इसमें साधारणतः 5 से 7 न्यायाधीश कार्य करते हैं जो प्रायः निर्वाचित होते हैं। परन्तु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील का न्यायालय होता है और निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना है। सर्वोच्च

‘यायालय केवल कानून के आधार पर अपील के मामला की सुनवाई करता है। वे निम्न यायालयों के निर्णयों को माय अथवा अमाय ठहराते हैं। इनके निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं और वे निम्न यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक राज्य के सर्वोच्च यायालय उस राज्य के मजिस्ट्रेट की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी होता है। कुछ राज्यों में यह व्यवस्था भी है कि सर्वोच्च यायालय राज्यपाल अथवा व्यवस्थापिका द्वारा मागे जाने पर आवश्यक परामर्श प्रदान करे।

2 माध्यमिक न्यायालय (Intermediary Courts)—सर्वोच्च यायालय के बाद माध्यमिक न्यायालयों का स्थान है। प्रत्येक राज्य में यह यायालय भी प्रमुख अपील का यायालय होता है। इन माध्यमिक यायालयों का कुछ राज्यों में अपील न्यायालय (Courts of Appeal) ता कुछ राज्यों में उच्चतर यायालय (Supreme Courts) कहते हैं। इनमें प्रायः तीन से लेकर 9 यायाधीश कार्य करते हैं, जो साधारणतः निर्वाचित होते हैं। माध्यमिक न्यायालयों का संगठन एवम उनकी कार्य प्रणाली सर्वोच्च यायालय जैसी है।

3 जिला या काउंटी न्यायालय (District and County Courts)—माध्यमिक अथवा अपील न्यायालयों के नीचे जिला अथवा काउंटी यायालय होते हैं। इनका कार्य अभियोगों की सुनवाई करना है। इनमें हत्या, रिश्वतखोरी, मारपीट, हानि आदि के मुकदमों की सुनवाई होती है। ये यायालय व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित जिला की सीमा में कार्य करते हैं। विविध राज्यों में इन्हें जिला यायालय, काउंटी न्यायालय, उच्चतर यायालय तथा सर्किट न्यायालय (Circuit Courts) आदि नामों से पुकारा जाता है। इनका न्याय क्षेत्र प्रारम्भिक व अपीलीय दोनों है।

4 छोटे यायालय (Justices Courts)—राज्य की याय व्यवस्था में सबसे नीचे के स्तर के न्यायालय जस्टिसों के यायालय (Justices Courts) हैं। इनमें शान्ति न्यायाधीश (Justices of Peace) यायिक कार्य करते हैं। ये न्यायालय दीवानी और फौजदारी के छोट मुकदमों की सुनवाई करते हैं।

5 विशेष यायालय—उपयुक्त यायालयों के अतिरिक्त नगर यायालय (Municipal Courts) होते हैं। ये न्यायालय विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यायिक कार्य करते हैं। इन यायालयों में अनेक यायाधीश कार्य करते हैं जो फौजदारी, दीवानी तथा अन्य एसी ही प्रणालियों का कार्य करते हैं।

अमेरिकन राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र

(Direct Democracy in the States of America)

सुसुत राज्य अमेरिका और इसके अन्तर्गत राज्यों के नागरिक प्रतिनिधि रक्षात्मक प्रणाली स्वीकार की गई है जिसके अनुसार प्रचलन पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार रहता है। किन्तु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र या नागरिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस नागरिक व्यवस्था

मे कानून निर्माण और प्रशासकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के तीन भाग हैं—

- 1 आरम्भण (Initiative)
- 2 प्रत्याहरण (Recall)
- 3 जन-निर्देश (Referendum)

आरम्भण एवं निर्देश की प्रथा अधिकांश राज्यों में है किन्तु प्रत्याहरण की प्रथा केवल कुछ ही राज्यों में पाई जाती है।

1 आरम्भण (Initiative)—आरम्भण द्वारा संयुक्त राज्य के 14 राज्यों के संविधानों में मगोधन हुआ सकते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की अधिकारिणी होती है। सलाह करने के इच्छुक व्यक्ति सलाह का प्रारूप तैयार कर लेते हैं और तत्पश्चात् उस पर एक निश्चित मन्त्रालय में मतदाताओं के हस्ताक्षर कराके वह राज्य के पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य के 19 राज्यों में मतदाताओं की आरम्भण के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वे जिस कानून का पालन करना चाहते हैं उसे विधान मंडल के सामने रखें। विधान मंडल के द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर वह कानून बन जाता है। किन्तु यदि विधान मंडल उसका अस्वीकार कर देता है तो वह कानूनी प्रस्ताव मतदाताओं के समक्ष उपस्थित किया जाता है और बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार बनाया गया कानून विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम ही समझा जाता है, यद्यपि बाद में विधान मंडल को यह अधिकार है कि वह उस रद्द कर दे। किन्तु जहाँ तक संविधान में संशोधन करने वाले प्रस्ताव का प्रश्न है, उसे रद्द करने का अधिकार विधान मंडल को नहीं है।

2 प्रत्याहरण (Recall)—राज्यों के विधानमंडल राज्यपाल एवं न्यायिक सरकारी पदाधिकारियों का निर्वाचन अवधि नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है किन्तु प्रत्याहरण के अंतर्गत जनता को यह अधिकार है कि वह अवांछित पदाधिकारियों का उनकी अवधि से पूर्व ही हटा दे। इसके लिए प्रक्रिया यह है कि जनता की एक निश्चित संख्या हस्ताक्षर करके पदाधिकारी को हटाने की मांग करती है। तत्पश्चात् इस प्रस्ताव पर मतदाताओं के मत लिये जाते हैं। यदि मतदाताओं का बहुमत प्रस्ताव का मंजूर करता है तो पदाधिकारी को पद त्याग करना होता है और मतदाता रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये दूसरे व्यक्ति का निर्वाचन करते हैं। यह व्यक्ति उतने समय के लिये पदासीन रहता है जितने समय के लिये प्रत्याहरण किये गये व्यक्ति को नाश करना था।

3 जन-निर्देश (Referendum)—जननिर्देश के अंतर्गत जनता को यह अधिकार है कि वह विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अधिनियम के सम्बन्ध में जनता की राय प्राप्त करने की मांग करे। इसके लिए जनता के कुछ भाग द्वारा एक आवेदन-पत्र उपस्थित किया जाता है और तब प्रस्ताव जनता के सामने रखा जाता है।

जनता बहुमत से उस प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना निर्णय देती है। जन निर्देश का महत्व इसी से प्रकट होता है कि विधानमंडल द्वारा अधिनियम पारित होते ही उसे लागू नहीं किया जाता बल्कि कुछ समय के लिये इस बात की प्रतीक्षा की जाती है कि यदि जनता चाहता है तो इस सम्बन्ध में जन निर्देश भेज दे। यहाँ यह स्मरणीय है कि अति आवश्यक समझे जाने वाले अधिनियमों को तुरन्त भी लागू किया जा सकता है किन्तु ऐसे अधिनियमों का विधान मण्डल के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

उपराक्त प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की उपयोगिता के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न धारणायें हैं। कुछ के मत में यह इसलिये उपयोगी है कि इसके द्वारा जाता प्रत्यक्ष रूप से अपनी वास्तविक इच्छा प्रकट कर पाती है और शासन पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ ही जनता और व्यवस्थापन विभाग का सम्पर्क बना रहता है। यह सम्पर्क मतदाताओं को दलबंदी के विनाशकारी एवं विकृत प्रभाव से मुक्त रखता है। किन्तु अनेक विद्वान प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की इस उपयोगिता के बारे में सदेहशील हैं। उनका तर्क है कि साधारण व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और उचित-अनुचित का निर्णय करने जैसा उनका बौद्धिक स्तर नहीं होता है। इस कारण वह अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त एक विशाल जनसंख्या वाले देश में व्यावहारिक रूप से भी इस प्रथा की सफलता अत्यंत मद्दिग्ध है।

8

स्थानीय शासन (LOCAL SELF GOVERNMENT)

“स्थानीय स्वशासन की सस्था सरकार के किसी
अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।”

—लास्की

स्थानीय स्वशासन से लाकतन का प्रशिक्षण मिलता है, अतः इसे लोकतन्त्र की प्रथम पाठशाला कही है। इसके माध्यम से लोग म प्रशासन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उनका सहयोग बढ़ता है। इससे प्रशासन में दक्षता उत्पन्न होती है क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं और केन्द्रीय अथवा प्रांतीय अधिकारियों की अपेक्षा उनको अच्छी तरह हल कर सकते हैं। अमेरिका में स्थानीय शासन का जो रूप है, वह अमेरिकन लोकतन्त्रीय परम्परा के बहुत कुछ अनुकूल है।

अमेरिकन शासन की विशेषताएँ

1 अमेरिका में स्थानीय शासन को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता है। कौंसिल मनेजर योजना का विकास इसका अच्छा प्रमाण है।

2 राज्य स्तर से नीचे प्रशासन की इकाइयाँ एक प्रकार से राज्य शासन की प्रतिनिधि हैं। उनकी शक्तियाँ और संगठन की परिभाषा राज्य के कानूनों द्वारा की गई है।

3 स्थानीय शासन का गठन न केवल प्रत्येक राज्य में भिन्न प्रकार का है बल्कि एक ही राज्य में कई स्थानों पर कई प्रकार के स्थानीय निकाय उपलब्ध हैं।

4 विभिन्न राज्यों में विभिन्न इकाइयाँ कहाँ तक स्वायत्तता का उपयोग करें, इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर हैं।

जनता बहुमत से उस प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना निर्णय देती है। जन निर्देश का महत्व इसी से प्रकट होता है कि विधानमण्डल द्वारा अधिनियम पारित होते ही उसे लागू नहीं किया जाता बल्कि कुछ समय के लिये इस बात की प्रतीक्षा की जाती है कि यदि जनता चाहे तो इस सम्बन्ध में जन निर्देश भेज दे। यहाँ यह स्मरणीय है कि अति आवश्यक समझे जाने वाले अधिनियमों का तुरन्त भी लागू किया जा सकता है किन्तु ऐसे अधिनियमों का विधान मण्डली के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

उपरोक्त प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की उपयोगिता के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न धारणायें हैं। कुछ के मत में यह इसलिये उपयोगी है कि इसके द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अपनी वास्तविक इच्छा प्रकट कर पाती है और शासन पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ ही जनता और व्यवस्थापन विभाग का सम्पर्क बना रहता है। यह सम्पर्क मतदाताओं को दलबंदी के विनाशकारी एवं विकृत प्रभाव से मुक्त रखता है। किन्तु अनेक विद्वान प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की इस उपयोगिता के बारे में सदेहशील हैं। उनका ध्यान है कि साधारण व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और उचित-अनुचित का निर्णय करने जैसा उनका बौद्धिक स्तर नहीं होता है। इस कारण वह अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त एक विशाल जनसंख्या वाले देश में व्यावहारिक रूप से भी इस प्रथा की सफलता अत्यन्त मरिभ्य है।

8

स्थानीय शासन (LOCAL SELF GOVERNMENT)

“स्थानीय स्वशासन की सस्था सरकार के किसी
अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है।”

—लास्की

स्थानीय स्वशासन से लोकतन्त्र का प्रशिक्षण मिलता है, अतः इसे लोकतन्त्र की प्रथम पाठशाला कही है। इसके माध्यम से लोगो में प्रशासन के प्रति रूचि उत्पन्न होती है और उनका सहयोग बढ़ता है। इससे प्रशासन में दक्षता उत्पन्न होती है क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं और केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय अधिकारियों की अपेक्षा उनको अच्छी तरह हल कर सकते हैं। अमेरिका में स्थानीय शासन का जो रूप है, वह अमेरिकन लोक-तन्त्रीय परम्परा के बहुत कुछ अनुकूल है।

अमेरिकन शासन की विशेषतायें

1 अमेरिका में स्थानीय शासन को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता है। कौंसिल-मैनेजर याजना का विकास इसका अच्छा प्रमाण है।

2 राज्य स्तर से नीचे प्रशासन की इकाइया एक प्रकार से राज्य शासन की प्रतिनिधि हैं। उनकी शक्तियों और मगठन की परिभाषा राज्य के कानूनों द्वारा की गई है।

3 स्थानीय शासन का गठन न केवल प्रत्येक राज्य में भिन्न प्रकार का है बल्कि एक ही राज्य में कई स्थानों पर कई प्रकार के स्थानीय निकाय उपलब्ध हैं।

4 विभिन्न राज्यों में विभिन्न इकाइया कहा तक स्वायत्तता का उपभोग करे, इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों में अलग अलग स्तर हैं।

5 विभिन्न राज्या में वराल आज प्रकार की स्थानीय सरकारें हैं, जिन स्थानीय समुदाय का भी यह विचारित करती रखा गया है कि क्या यहाँ वित्तों प्रकार की समस्याएँ रहेंगे।

स्थानीय शासन की इकाइयाँ

अमेरिकन स्थानीय शासन संस्थाएँ ब्रिटिश परम्परा की हैं। औपनिवेशिक काल में ही ये संस्थाएँ विद्यमान थीं, जिनमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए और नवोन्मेषी प्रजातंत्रों का जन्म हुआ। आज अमेरिका में इतनी अधिक स्थानीय शासनिक इकाइयाँ हैं तथा उनमें परस्पर काफी विभिन्नता है कि बिना उन्हें इस तरह समझने में पड़ जाता है।

मनुष्य राज्य अमेरिका में स्थानीय शासन संस्थाओं का सामना पत दा पर्वों में बाँटा जाता है—नगर शासन (City Government) एवं ग्रामीण शासन (Rural Government) स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई काउंटी (County) है। अमेरिकन देश में लगभग तीन हजार काउंटियाँ हैं। इन तीनों हजार काउंटियों में से अधिकतर पुनः दो हजार कस्बे (Towns) या उपनगर (Townships) बनाये गये हैं और इन दो हजार कस्बों या उपनगरों में से लगभग मीलहू हजार नगर प्रशासनिक इकाइयाँ (Urban Municipalities) बंवाई गयी हैं, जिन्हें नगर (Cities) कहते हैं। स्थानीय शासन की इन नियमित इकाइयों के अतिरिक्त अमेरिका में लगभग आठ हजार अन्य प्रकार की (Miscellaneous) इकाइयाँ हैं, जिन्हें विविध जिले (Special Districts) कहा जाता है। ये इकाइयाँ विविध प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे सिंचाई अथवा मल प्रवाह (Irrigation and Sewage) के कार्य आदि। इनके अतिरिक्त अमेरिका में लगभग एक लाख शिक्षण क्षेत्र या विद्यालय भी जिले हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अमेरिका में दस लाख के आस-पास स्थानीय शासनिक निकाय हैं जिनके नाम सभी राज्यों में एक से नहीं हैं।

काउंटी (County)—यह स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई है। इनकी संख्या लगभग तीन हजार है। प्रत्येक राज्य काउंटियों में बाँटा गया है। सभी काउंटियाँ का क्षेत्रफल समान नहीं है। फिर भी माधुराणत, एक काउंटी का क्षेत्रफल लगभग एक हजार वर्ग मील है। प्रायः प्रत्येक काउंटी का प्रशासन एक समिति अथवा परिषद् (Council or Board) चलाती है, जिसमें चार से लेकर पचास तक सदस्य होते हैं। वे तिहाई काउंटी परिषद या समितियाँ (County Boards or Councils) में, 6 से कम ही सदस्य रहते हैं। काउंटी परिषद या समिति का कार्य नियम बनाना है। वह काउंटी शासन के वित्तीय प्रशासनिक अधिकारों का भी प्रयोग करती है। काउंटी शासन में समिति या परिषद के अतिरिक्त कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, जैसे शेरिफ (Sheriff), लिपिक (Clerk), अभियोग संचालक वकील (Prosecutor Attorney) तथा म्यूजिकवान्ति (Cozoner) आदि। ये सब अधिकारी निर्वाचित होते हैं और उन प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन करते हैं

जिन्हें परिषद जयवा समिति स्वयं नहीं करती। काउण्टी के न्यायाधीश भी अलग निर्वाचित होते हैं या नियुक्त किये जाते हैं।

टाउन (Town)—अमेरिका के कई राज्या में काउण्टी को पुन विभाजित कर टाउन (Towns) और नगर (Cities) में बांट दिया गया है। टाउन देहाती स्थानीय शासन के मुख्य निकाय हैं और नगर (Cities) शहरी स्थानीय शासन के मुख्य निकाय हैं। टाउन या कस्बा का वास्तव में एक ग्राम या देहात ही समझा जाना चाहिए जिसके साथ साथ जानपास की भूमि या प्रदेश सम्बद्ध रहता है। टाउनो में ही देहाती स्थानीय शासन का क्रियात्मक स्वरूप देखने को मिलता है और वही हमको वास्तविक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के दर्शन हाते हैं। टाउन का शासन एक कम्पा या टाउन समिति (Town Council) द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सभी अधिकारी मतदाता भाग लेते हैं। इस समिति की बैठक प्रायः वार्षिक होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अधिक बैठकें भी आयोजित हो सकती हैं। ये समितियाँ नियम बनाने और बजट स्वीकार करने के लिए होती हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के लिए वित्तिष्ट व्यक्तियों की एक परिषद (Board of Selectmen), जिसे टाउन समिति (Town Council) भी कहते हैं तथा एक शिक्षा परिषद (School Board) का निर्वाचन भी करती हैं। इनके अतिरिक्त ये कुछ अन्य अधिकारियों का भी चयन करती हैं। इन सभी का कार्य टाउन सभा (Town Meeting) के कार्यकाल के लम्बे विराम काल में स्थानीय शासन को चलाना होता है।

टाउनशिप (Township)—मन्युक्त राज्य अमेरिका में कुछ भागों में ग्राम स्वशासन की इकाईयाँ टाउनशिप (Township) कहलाती हैं। टाउनशिप का प्रबंध छोटी सी निर्वाचित परिषद (Board) द्वारा होता है जिसमें प्रमुख अध्यक्ष को नगर प्रमुख (Mayor) या सभापति (Chairman) कहा जाता है। मयर निर्वाचित भी हो सकता है और परिषद के सदस्यों में से भी हो सकता है तथा उसको विशेष अधिकारों से सज्जित भी किया जा सकता है। टाउनशिप की परिषद एक नियम निर्मात्री मस्या है, जो वसूलीयों को नियुक्त करती है और बजट स्वीकार करती है।

नगर (City)—अमेरिका में स्थानीय शासन की सबसे अधिक क्रियाशील और दिलचस्प इकाईयाँ नगर (Cities) हैं जिन्हें म्यूनिसिपैलिटियाँ (Municipalities) में संगठित कर लिया गया है। टाउन एवं टाउनशिप की तरह नगर भी काउण्टी के नगरीय उपविभाग होते हैं। इनकी संख्या लगभग 16 हजार है। अमेरिका में नगर की (City) प्रायः वही स्थिति है जो इंग्लैंड में बर्रो (Burrough) या काउण्टी बर्रो (County Burrough) की है। नगर इकाईयाँ वास्तव में देहाती स्थानीय शासनिक इकाईयाँ की अपेक्षा कहीं अधिक स्वशासन रहता है।

प्रत्येक नगर का शासन प्रबंध एक अधिकार पत्र (Charter) के अनुसार होता है, जिस पर वो राजकीय व्यवस्थापिका द्वारा प्रदान किया जाता है, या जिसे नगर सभा अपने नगर-स्वशासन के अधिकार के अन्तर्गत स्वयं बनाती है। नगर के

5 विभिन्न राज्यों में न केवल अनेक प्रकार की स्थानीय समस्याएँ हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी यह निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है कि वे अपने यहां किसी प्रकार की समस्याएँ रखेंगे।

स्थानीय शासन की इकाइयाँ

अमेरिकन स्थानीय शासनिक समस्याएँ ब्रिटिश परम्परा की दृष्टि से हैं। औपनिवेशिक काल में ही ये समस्याएँ विद्यमान थीं, लेकिन समय के साथ उनका परिवर्तन हुआ और नयी नयी प्रणालियाँ कायम हुईं। आज अमेरिका में इतनी अधिक स्थानीय शासनिक इकाइयाँ हैं तथा उनमें परस्पर इतनी विभिन्नता है कि बिना किसी उर्ध्व देख कर चक्कर में पड़ जाता है।

मनुष्य राज्य अमेरिका में स्थानीय शासन समस्याओं को सामान्यतः दो वर्गों में बाँटा जाता है—नगर शासन (City Government) एवं ग्रामीण शासन (Rural Government) स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई काउण्टी (County) है। समस्त देश में लगभग तीन हजार काउण्टियाँ हैं। इन तीन हजार काउण्टियों में से अधिकतर पुनः दस हजार कस्बे (Towns) या उपनगर (Townships) बनाये गये हैं और इन दस हजार कस्बों या उपनगरों में से लगभग सौ हजार नगर प्रशासनिक इकाइयाँ (Urban Municipalities) बनाई गयी हैं, जिन्हें नगर (Cities) कहते हैं। स्थानीय शासन की इन नियमित इकाइयों के अतिरिक्त अमेरिका में लगभग आठ हजार अन्य प्रकार की (Miscellaneous) इकाइयाँ हैं, जिन्हें विशेष जिले (Special Districts) कहा जाता है। ये इकाइयाँ विशेष प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे सिंचाई अथवा मल प्रवाह (Irrigation and Sewage) के कार्य आदि। इनके अतिरिक्त अमेरिका में लगभग एक लाख शिक्षण क्षेत्र या शिक्षा समूह भी जिले हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अमेरिका में डेढ़ लाख के आस-पास स्थानीय शासनिक निकाय हैं जिनके नाम सभी राज्यों में एक से नहीं हैं।

काउण्टी (County)—यह स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई है। इनकी संख्या लगभग तीन हजार है। प्रत्येक राज्य काउण्टियों में बाँटा गया है। सभी काउण्टियों का क्षेत्रफल समान नहीं है। फिर भी साधारणतः एक काउण्टी का क्षेत्रफल लगभग एक हजार वर्ग मील है। प्रायः प्रत्येक काउण्टी का प्रशासन एक समिति अथवा परिषद् (Council or Board) चलाती है, जिसमें चार से लेकर पचास तक सदस्य होते हैं। दो तिहाई काउण्टी परिषदों या समितियों (County Boards or Councils) में, 6 से कम ही सदस्य रहते हैं। काउण्टी परिषद् या समिति का कार्य नियम बनाना है। वह काउण्टी शासन के कतिपय प्रशासनिक अधिकारों का भी प्रयोग करती है। काउण्टी शासन में समिति या परिषद् के अतिरिक्त कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, जैसे शेरिफ (Sheriff), लिपिक (Clerk), अभियोग संचालक वकील (Prosecutor Attorney) तथा मृत्युदानिक (Coroner) आदि। ये सब अधिकारी निर्वाचित होते हैं और उन प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन करते हैं

जिन्हें परिषद अथवा समिति स्वयं नहीं करती। काउण्टी के यायावीश भी अलग निर्वाचित होते हैं या नियुक्त किये जाते हैं।

टाउन (Town)—अमेरिका के कई राज्यों में काउण्टी को पुन विभजित कर टाउन (Towns) और नगर (Cities) में बांट दिया गया है। टाउन देहाती स्थानीय शासन के मुख्य निकाय हैं और नगर (Cities) शहरी स्थानीय शासन के निकाय हैं। टाउन या कस्बा को वास्तव में एक ग्राम या देहात ही समझा जा चाहिए जिसके साथ साथ जामपास की भूमि या प्रदेश सम्बद्ध रहता है। टाउन देहाती स्थानीय शासन का त्रिात्मक स्वरूप देखने को मिलता है और वही वास्तविक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के दगन होते हैं। टाउन का शासन एक कस्बा टाउन समिति (Town Council) द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सभी अधिकारी शता भाग लेते हैं। इस समिति की बैठक प्रायः वार्षिक होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अधिक बैठकें भी आयोजित हो सकती हैं। ये समितियाँ नियम ले और बजट स्वीकार करने के लिए होती हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के लिए सैलिट व्यक्तियों की एक परिषद (Board of Selectmen), जिसे टाउन समिति (Town Council) भी कहते हैं तथा एक शिक्षा परिषद (School Board) का चिन्तन भी करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ अन्य अधिकारियाँ का भी चयन करती हैं। इन सभी का कार्य टाउन सभा (Town Meeting) के कार्यकाल के लम्बे समय काल में स्थानीय शासन को चलाना होता है।

टाउनशिप (Township)—मन्युक्त राज्य अमेरिका में कुछ भागों में ग्राम शासन की इकाईयाँ टाउनशिप (Township) कहलाती हैं। टाउनशिप का एक छोटी सी निर्वाचित परिषद (Board) द्वारा होता है जिसके प्रमुख अध्यक्ष नगर प्रमुख (Mayor) या सभापति (Chairman) कहा जाता है। मयर निर्वाचित भी हो सकता है और परिषद के सदस्यों में से भी हो सकता है तथा उसको शेष अधिकारों से सज्जित भी किया जा सकता है। टाउनशिप की परिषद एक समय निर्मात्री मस्या है, जो कमचारियों को नियुक्त करती है, और बजट स्वीकार करती है।

नगर (City)—अमेरिका में स्थानीय शासन की सबसे अधिक त्रिाशील और शक्य इकाईयाँ नगर (Cities) हैं जिन्हें म्यूनिसिपैलिटियों (Municipalities) संगठित कर लिया गया है। टाउन एवं टाउनशिप की तरह नगर भी काउण्टी के शरीय उपविभाग होते हैं। इनकी संख्या लगभग 16 हजार है। अमेरिका में नगर (City) प्रायः वही स्थिति है जो इंग्लैंड में बर्रो (Burrough) या काउण्टी बर्रो (County Burrough) की है। नगर इकाईयाँ वास्तव में देहाती स्थानीय सनिक इकाईयाँ की अपेक्षा नहीं अधिक स्वायत्त रहता है।

प्रत्येक नगर का शासन प्रबंध एक अधिकार पत्र (Charter) के अनुसार होता है, जिसे माँ तो राजकीय व्यवस्थापिका द्वारा प्रदान किया जाता है या जिसे नगर सभा अपने नगर-स्वशासन के अधिकार के अन्तर्गत स्वयं बनाती है। नगर के

लिए इस अधिकार-पत्र का वही महत्व है जो किमी राज्य या सम्पूर्ण देश के लिए सविधान का है। अधिकारो पत्रों (Charters) के द्वारा साधारणतः तीन प्रकार के स्थानीय शासनो की स्थापना होती है, जिन्हें इन नामा से पुकारा जाता है—

- 1 मेयर कांसिल फार्म (Mayor Council Form),
- 2 कमीशन फार्म (Commission Form), एवं
- 3 कौंसिल मैनेजर फार्म (Council Manager Form)

1 **मेयर कांसिल फार्म (Mayor Council Form)**—इसमें विभिन्न क्षत्रों से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक परिषद (Council) होती है। उसका अध्यक्ष मेयर होता है। इसके भी दो मुख्य रूप होते हैं—**अशक्त मेयर (Weak Mayor)** और **शक्तिशाली मेयर (Strong Mayor)**। प्रथम प्रकार के मेयर की शक्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। वह परिषद का सभापति होता है। प्रशासन के सब विभाग किमी न किसी आयोग (Commission) या परिषद (Board) के अधीन होते हैं जिनके सदस्य या तो प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुने जाते हैं या कौंसिल द्वारा। मेयर कुछ मुख्य-मुख्य पदों की नियुक्ति करता है, पर यह आवश्यक है कि उनका पुष्टिकरण कौंसिल द्वारा किया जाए। कुछ विषयों में मेयर को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त होना है, लेकिन कौंसिल उनके निषेध का दो तिहाई बहुमत से समाप्त कर सकती है। सिद्धांत रूप से मेयर का बाय विभिन्न विभागों का नियंत्रण और निरीक्षण करना है लेकिन व्यवहार में वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दूसरे प्रकार के अर्थात् शक्तिशाली मेयर टाइप (Strong Mayor Type) के स्थानीय शासन का आधार शक्ति पध्दत का सिद्धांत है। कौंसिल नीति का निर्धारण करती है और मेयर का जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, कार्यपालिका शक्ति रखते हैं। मेयर ही महत्वपूर्ण अधिकारियों का नियुक्ति करता है और उन्हें अपने अधिकार स हटा भी सकता है। नगर इकाई के सभी समचारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा होती है और नगर के बजट पर उसका नियंत्रण होता है। उसे कौंसिल के निषेध पर कुछ प्रतिबंध का अधिकार भी हात है। इस प्रकार शक्तिशाली मेयर (Strong Mayor) वस्तुतः नगर के प्रशासन का अध्यक्ष होता है।

2 **कमीशन फार्म (Commission Form)**—नगर की दृष्टि से यह एक रूप है जहाँ एक आयोग नगर शासन सम्भालता है। इसने द्वारा अशक्त मेयर वाला नगर के शासन की क्रिया दूर हो जाता है और शासन का रूप सरल हो जाता है। नगर इकाई के इस रूप में नगर की व्यवस्थापन और प्रशासन मुख्य भी शक्तियाँ एक छोटे आयोग में निहित रहती हैं, जिसके सदस्य समान पाले जाते हैं और जिन्हें जनता चुनती है। इसमें से एक आयोग का सभापति अथवा मेयर होता है। सम्पूर्ण आयोग नीति निर्धारण करता है और आयोग का प्रत्येक सदस्य एक प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है, अर्थात् नगर का सम्पूर्ण प्रशासन उस ही विभागों में बांट दिया जाता है, जिन सदस्य नगर के आयोग में हात हैं और आयोग का प्रत्येक

सदस्य एक विभाग का कार्य भार अपने पाम रखता है। इस पद्धति के दो मुख्य लाभ हैं—प्रथम, इसमें शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विभाजन नहीं होता, एवं द्वितीय, पांच या सात व्यक्ति सामंजस्य के साथ कार्य कर सकते हैं यह बात 50 60 या अधिक व्यक्तियों के लिए लागू नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही इस पद्धति के दोष भी हैं। पहला दोष यह है कि आयोग के सदस्यों की संख्या इतनी कम है कि उसमें जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। दूसरा दोष यह है कि इसमें सभी सदस्यों की क्षमता समान होती है और कोई भी सदस्य अर्थात् कमिशनर दूसरों से बड़ा नहीं होता जो सब के कार्यों में सम-वय रख सके। वस्तुतः इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि आयोग के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर गतिरोध पैदा हो जाए तो उसे कोई नहीं सुलझा सकता।

नगर प्रशासन का यह रूप अत्यंत बड़े नगरों में लोकप्रिय नहीं है और ऐसे किसी भी नगर में प्रायः इस पद्धति को नहीं अपनाया गया है जिसकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक है। हा, 25 हजार के आसपास के आवादी वाले छोटे नगरों में यह पद्धति अवश्य लोकप्रिय है।

3 कौंसिल मैनेजर फॉर्म (Council Manager Form)—सन् 1908 में इस प्रकार की एक संस्था थी, परंतु अब यह व्यापक रूप से नगरों में प्रचलित है। इस पद्धति में नगराध्यक्ष का कार्य तो कौंसिल करती है तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व एक विशेष योग्यता प्राप्त कुशल अधिकारी मैनेजर पर हाता है। मैनेजर साधारणतः कौंसिल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति के बाद दैनिक प्रशासन के लिए वह लगभग पूर्णतः उत्तरदायी होता है। कौंसिल मैनेजर फॉर्म वस्तुतः कमिशनर फॉर्म का ही मशोधित रूप है और इसका मुख्य लाभ कुशल प्रशासन है। अमेरिका में प्रचलित उपयुक्त सभी नगर प्रशासन प्रणालियों में कौंसिल मैनेजर फॉर्म सबसे अधिक सफल प्रणाली मानी जाती है। इसकी सफलता का मुख्य कारण यही है कि इस प्रणाली में नीति निर्माण एवं प्रशासन का अलग कर देने से प्रशासन में विशेष कुशलता आ जाती है।

स्थानीय शासन का कार्य क्षेत्र

अमेरिका में स्थानीय शासन के अंतर्गत सामान्यतः पुलिस, अग्निरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, सार्वजनिक मार्ग शिक्षणालयों का संचालन, सार्वजनिक उपयोगिता के काम, चुनाव कराना आदि विभिन्न कार्य आते हैं। स्थानीय शासन ग्रामीण क्षेत्रों में कम विकसित है तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित है। लेकिन दोनों का कार्य-क्षेत्र लगभग एक सा है। स्थानीय प्रशासन के अनेक कार्यों में राज्य सरकारों भी प्रायः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। वस्तुतः स्थानीय शासन अमेरिकन शासन व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है जो राज्य की विभिन्न जातियों व वर्गों की सुख शांति के लिये आवश्यक है।

स्थानीय शासन की अव्यवस्था आय के साधन

वर्तमान काल में स्थानीय प्रशासन का व्यय अत्यधिक बढ़ गया है। यह

अनुमान लगाया गया है कि केवल विगत 50 60 वर्षों में ही स्थानीय प्रशासन का व्यय 1200 गुना अधिक हो गया है। व्यय का इस वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है। दूसरा मुख्य कारण स्थानीय सेवाओं की व्यापकता और उसके स्तर का बढ़ जाना है। आज पूर्वापेक्षा इन बातों की अधिक मांग है कि स्कूलों की संख्या अधिक हो, सड़कें पक्की हों और पुलिस एवं अग्नि सुरक्षा आदि से सम्बंधित सेवाएं अधिक कुशल हों।

इस बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति करना एक विषट्क समस्या है, क्योंकि जनता एक तरफ तो अधिकाधिक सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करना चाहती है और दूसरी तरफ कम से कम कर बहन करना चाहती है। दोनों मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की समस्या सदैव उपस्थित रहती है। स्थानीय शासन का प्रयास यही रहता है कि सेवाओं का स्तर भी ऊंचा हो और जनता पर कर भार भी इतना अधिक न पड़े कि वह उसे सहन न कर सके।

जनसंख्या निरंतर ग्रामों से नगरों की ओर बढ़ती जा रही है, अतः स्थानीय शासन के नगर निकायों का काम, उत्तरदायित्व और व्यय बहुत बढ़ गये हैं। नगर निकायों के आय के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं—य विभिन्न प्रकार के कर अथवा रेंट लगाते हैं और इन्हें राज्य तथा संघ सरकार में विभिन्न योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता भी मिलती है। कर लगाने में नगर निकायों को राज्य के कानूनों के अनुसार ही चलना पड़ता है। सामान्यतः राज्य सरकार इस सम्बंध में कुछ प्रतिशत निश्चित कर देती है और उसके भीतर ही नगर निकाय कर लगा सकते हैं। करो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति कर है। भूमि, मकान, मशीन, पशु, व्यक्तिगत सामान आदि सभी प्रकार की सम्पत्ति पर यह कर लगाया जा सकता है। घर का सामान, धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति आदि पर निकायों का कर नहीं लगता है। सम्पत्ति कर के अतिरिक्त नगर निकायों की आय का प्रमुख स्रोत आय कर भी है। निर्वाचन कर, ध्यानार कर, आमोद प्रमोद कर, आदि विभिन्न करों के द्वारा भी नगर निकायों को आय होती है। नगर निकायों की आय का एक साधन जुमान व फीस है। विभिन्न व्यवसायों के लिये लाइसेंस देने, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों के संचालन आदि से भी स्थानीय शासनिक संस्थाओं को आय होती है।

अमेरिकन स्थानीय शासन के मध्य व अन्तिम उल्लेखनीय बात यह है कि ब्रिटेन के समान ही इस पर भी वैदेशीकरण की काली छाया अधिकाधिक घनी होती जा रही है। मध्य और राज्य सरकारें स्थानीय शासनिक इकाइयों का पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता देती हैं और उदर में उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखती हैं। सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों को सहायता की राशि का प्रयोग करने के लिये कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के सुधार के लिये और उनकी काम कुशलता का बढान, के लिये उनका कार्यों पर आवश्यक देख रेख रखती है।

UNIVERSITY QUESTIONS

Chapter 1

- 1 Summarise the circumstances leading to the origin of the constitution of the U S A
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण कैसे हुआ।
- 2 What are the distinctive features of the constitution of U S A ?
अमेरिका संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें।
- 3 Critically examine the fundamental rights embodied in the constitution of the U S A
अमेरिकन संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का वर्णन करें।
- 4 There are almost as many conventions in the constitution of the U S A as in that of Great Britain. Discuss
अमेरिका के संविधान में भी ब्रिटिश संविधान के सदृश अनियमितताओं का स्थान है। व्याख्या करें।

Chapter 2

- 1 Describe the system by which powers have been divided between the Federal Government and State Government in the U S A
अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन की पद्धति का वर्णन करें।
- 2 Analyse the main features of the American federal system and show how far they have been modified by the principle of Checks and Balances ?
अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 'अवरोध एवं संतुलन' के सिद्धान्त का इस पर क्या प्रभाव है ?
- 3 Examine critically the working of the principle of 'Separation of Powers and Checks and Balances' in the political frame work of the U S A
संयुक्त राज्य अमेरिका में 'शक्तियों के पृथक्करण' तथा अवरोध एवं संतुलन के कार्य-कलाप का वर्णन करें।
- 4 Discuss the Doctrine of Implied Powers. In what manner it has increased the importance of the American Courts ?
निहित शक्तियों के सिद्धान्त का वर्णन कीजिये। इसके द्वारा अमेरिकन न्यायालयों के महत्व में किस प्रकार वृद्धि हुई है ?

Chapter 3

- 1 Critically examine the composition, powers and functions of the American Senate
अमेरिकी सीनेट के संगठन, अधिकार तथा कार्यों की समीक्षा कीजिए।
- 2 'The American Senate is the most powerful second chamber in the world' Discuss.
'अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदन में सर्वाधिक शक्तिशाली है।' इस कथन की विवेचना करें।

- 3 Discuss the position and powers of the American 'Senate, clearly bringing out the factors which have given it primacy over the House of Representatives
अमेरिकी सीनेट के अधिकारों तथा स्थिति का वर्णन करें और उन कारणों का उल्लेख करें जिनसे प्रतिनिधि सदन से इसकी स्थिति सबल है।
- 4 Examine critically the relation between the two Houses of the Congress in the U S A
अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के बीच के सम्बन्धों का वर्णन करें।
- 5 Discuss the composition and functions of the House of Representatives in the U S A
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के गठन तथा कार्यों का वर्णन करें।
- 6 How is the Speaker of the House of Representatives elected? Describe his powers and functions
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उसके अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करें।
- 7 Compare and contrast the procedure of law making in England with that of United States of America
अमेरिकी तथा ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया का तुलनात्मक वर्णन करें।
- 8 Critically examine the nature, working and importance of Committee System in the U S A
अमेरिका में समिति-पद्धति का स्वरूप, कार्यकरण तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

Chapter 4

- 1 Explain the process of Presidential election in the U S A How far it has become direct election in practice? 11
अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्यवहार में यह कहाँ तक प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया है?
- 2 Summarise the powers and functions of the President of the U S A
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कृत्यों का वर्णन करें।
- 3 Discuss the constitutional and political relations between the president and the congress in the U S A
अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच संवैधानिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों का वर्णन करें।
- 4 'The U S A President combines in his person the office of King and Prime Minister Discuss
'संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद में सम्राट और प्रधान मंत्री के पद सम्मिलित हैं।' इस कथन की विवेचना करें।
- 5 The American cabinet differs in fundamental respects from the British cabinet In the light of this statement

compare between the features of American cabinet and the British cabinet

'अमेरिकी मंत्रिमण्डल और ब्रिटिश मंत्रिमण्डल में मौलिक अंतर है।' इस वचन के प्रकाश में अमेरिकी तथा ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की तुलना करें।

Chapter 5

- 1 Discuss the composition and powers of the Supreme Court of the U S A How far it is correct to say that it has established itself as the third Legislative Chamber of the Congress ?

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। यह कहना कहाँ तक ठीक है कि यह कांग्रेस का तृतीय सदन बन गया है ?

- 2 "The judiciary is the cement which has fixed from the federal structure" Comment

" न्यायपालिका वह सीमेन्ट है जिसने संघीय व्यवस्था को दृढ़ बनाये रखा है" व्याख्या करें।

- 3 What do you understand by Judicial Review ? How far does it exist in the U S A ?

न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं ? अमेरिका में यह कहाँ तक 'उपलब्ध' है ?

- 4 Describe the distinctive features of the Judicial system in the U S A

अमेरिका की न्याय व्यवस्थाओं की विशिष्टताओं का वर्णन करें।

Chapter 6

- 1 Discuss the role played by the Party system in the workings of American constitution

अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों के कार्यकरण का वर्णन करें।

- 2 Compare and contrast the organisation of political parties in the England and in U S A

अमेरिकी तथा ब्रिटिश राजनीतिक दलों की तुलना करें।

- 3 What are the salient features of the Party-system in U S A ?

संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

Chapter 7

- 1 Describe the position and functions of State in the U S A

संयुक्त राज्य के राज्यों की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन काजिए।

- 2 Give an estimate of functions and powers of the Governor of States in the U S A

संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के राज्यपालों के कार्यों एवं अधिकारों का विवरण दीजिए।

Chapter 8

- 1 What are the different forms of local government in U S A ?

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय सरकार के क्या विभिन्न रूप हैं ?

- 2 Describe the main functions and sources of income of the local government in U S A.

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय सरकार के मुख्य कार्यों और आय के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिये।

SELECT READINGS

- 1 Beard, C A : American Government and Politics
- 2 Brogan, D W : The American Political System, 1948
- 3 Bryce, James : The American Commonwealth, 1888
- 4 Bryce, James : Modern Democracies
- 5 Burns and Peltason : Government by the People
- 6 Clark, J P : The Rise of a New Federalism, 1938
- 7 Johnson : Government in the United States
- 8 Laski : The American Democracy
- 9 Munro, W B : The Government of the United States, 1947
- 10 Ogg and Ray : Introduction to American Government
- 11 Patterson : Presidential Government in the United States
- 12 Potter, Allen, M : American Government and Politics
- 13 Pritchett, C H : The American Constitution, 1959
- 14 Willoughby : The Constitutional Law of the United States
- 15 Rogers : The American Senate
- 16 Alfrange : The Supreme Court and the National Will
- 17 Haines, C G : The American Doctrine of Judicial Supremacy,
- 18 Hughes : The Supreme Court of the United States
- 19 Holcombe : The New Party Politics
- 20 Clark : The Rise of New Federalism
- 21 Ogg and Ray : Essentials of American Government
- 22 Granes, W Brooks : American State Government
- 23 Holecombe, Arthur, N : State Govt. in the United States
- 24 Mc Donald : American City Government Administration
- 25 Phillips J Cass : Municipal Govt and Administration
- 26 Stone : City Manager Government in the United States
- 27 Swisher C B : American Constitutional Development
- 28 Zink, Harold : Govt and Politics in the United States
- 29 Greaves, W B : Public Administration in Democratic Society
- 30 Swisher, C B : The Constitutional Power in the United States
- 31 Bone, H A : American Politics and Party System
- 32 Stannard, H : The Two Constitutions

स्विट्जरलैण्ड का संविधान

(THE SWISS CONSTITUTION)

“स्विट्जरलैंड ही अधिनियम, उपक्रम और लोक-निर्णय का प्राचीन निवास स्थान है। स्विस् कैंटनो में बहुत बड़े-काल से प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रों में सस्याये किसी-न-किसी रूप में चालू रहो हैं, और स्विट्जरलैंड से ही प्रजातन्त्र के दोष मार्गों द्वारा चल पद, ये अथ देशों में पहुँची हैं जिनमें समुक्त राज्य भी हैं। प्रजातन्त्र से उत्पन्न सस्याजो में ये कदाचित् अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये किसी विधान-मण्डल के हस्तक्षेप बिना ही विधि-निर्माण का साधन है, दूसरे शब्दों में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य। आधुनिक प्रजातन्त्र के विद्यार्थी के लिये स्विस् राजनीतिक प्रणाली में इससे अधिक शिक्षाप्रद और कोई बात नहीं है।”

—मुनरो

“भाषा तथा धर्म-सम्बन्धी स्पष्ट विविधता के होते हुए भी जिस कोटि की राष्ट्रीय एकता स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, उसने अन्तराष्ट्रीय मामलों के अनेक अध्ययन-कर्त्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें उससे यह प्रमाणित होने की आज्ञा बिलाई देती है कि उन राष्ट्रों में भी उच्चकोटि का सत्योग संभव है, जिनमें संस्कृति सम्बन्धी व्यापक भिन्नता पाई जाती हो तथा जिनमें स्वतन्त्रता की गतिगाली परम्परा चली आई हो।”

—जॉन ब्राउन मैसन

1

स्विस संविधान का विकास व स्वरूप

(GROWTH AND NATURE OF THE SWISS CONSTITUTION)

“स्विट्जरलैण्ड राजनीति के साहसिक कार्यों की प्रयोगशाला है तथा
उसकी सफलता से समस्त लोकतन्त्रीय देशों की सुरक्षा
भिरती है।”

—यू. एच.

यूरोपियन महाद्वीप के मध्य स्थित लगभग 15,944 वर्गमील का छोटा सा देश स्विट्जरलैण्ड आधुनिक विश्व का सबसे अधिक लोकतन्त्रीय राज्य समझा जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से रमणीय यह एक पर्वतीय देश है जिसके उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में इटली और पश्चिम में फ्रांस है। इस देश की कोई ऐसी प्राकृतिक सीमा नहीं है जो इस पर्वतीय राष्ट्रों से स्पष्ट रूप में पृथक् कर सके। राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए स्विट्जरलैण्ड एक ऐसा देश है जिसके संविधान का और राजनीतिक स्वरूप का अपना विशेष महत्व है। यदि इंग्लैंड समर्पण पद्धति की संस्थाओं का जन्मदाता है और अमेरिका संघारमक व्यवस्था का आविर्भाव है तो स्विट्जरलैण्ड को प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) के प्रयोग की राजनीतिक प्रयोगशाला होने का गौरव प्राप्त है।

स्विट्जरलैण्ड का सांविधानिक महत्त्व

(Constitutional Importance of Switzerland)

स्विट्जरलैण्ड का विविष्ट सांविधानिक महत्त्व इस बात में है कि यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का गढ़ है, जहाँ जनता की सम्प्रभुता को व्यावहारिक और वास्तविक रूप देने का महान् कार्य किया गया है। विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की संस्थाएँ अधिक विकसित और विस्तृत हुई हैं और

भाज तक व्यवहार में लाई जा रही हैं। यह भी कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि सघातमक शासन की सकुचित सीमाओं के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ इस देश में पनप रही हैं।

सुविधा की दृष्टि से स्विट्जरलैंड को साविधानिक महत्त्व का हम निम्नांकित उपशीर्षक में विभाजित कर सकते हैं—

गणतन्त्रीय परम्परा

स्विट्जरलैंड सभ पश्चिमी जगत का सबसे प्राचीन गणतन्त्रीय लोकतन्त्र है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के गणतन्त्रीय संविधान के उदय के भी लगभग 500 वर्ष पूर्व से गणतन्त्र का प्रयोग होता चला आ रहा है। स्विस नागरिकों में गणतन्त्रवाद इतना प्रबल है कि वहाँ राजा की ही नहीं बरन किसी शासक की भी निरंकुश शक्ति को सहन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि स्विस कायपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है। स्विस कायपालिका को बहुल (Plural) रखा गया है जिसमें कायसत्ता सभी सदस्यों के हाथ में दी गई है। सब सदस्य इतने अधिक समान-पदीय हैं कि कायपालिका को अध्यक्षता बारी-बारी से करते हैं और अध्यक्ष का दर्जा भी अन्य सदस्यों के बराबर ही होता है। उसे विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का गढ़

स्विट्जरलैंड की न्यायिता उनके प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रयोग के कारण है। आरम्भिक (Initiative) और जनमत संग्रह (Referendum) वहाँ के राजनैतिक जीवन के जागृत तत्त्व हैं। इनसे जनता को तामन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक सभाएँ (Primary Assemblies) भी जनता का प्रशासनिक नीति के निमाण में भाग लेने का अवसर देती हैं। स्विट्जरलैंड का सच्चे अर्थ में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के लिए विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जा सकता है।

बिबिधता में एकता

स्विट्जरलैंड की साविधानिक महत्ता का तीसरा कारण यह है कि इस देश में यद्यपि विभिन्न भाषा-भाषी और वर्मावलम्बी पाए जाते हैं तथापि उनमें एक राष्ट्रीय एकता विद्यमान है। स्विस गणतन्त्र राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता का अपूर्व आदर्श है। देश के 19 पूरे कंटोन और 6 अर्ध-कंटन में कई प्रजातियाँ रहती हैं जो विभिन्न भाषाओं और धर्मों की अनुगामनी हैं। देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या जर्मन भाषा भाषी है, लगभग पाँचवा भाग फ्रेंच भाषा भाषी है और शेष इटालियन भाषा बोलते हैं। लगभग 1 प्रतिशत लोग रोमान्च (Romansch) नामक आदि-भाषा बोलने वाले हैं। धार्मिक भिन्नता की दृष्टि से लगभग 58 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेंट, 41 प्रतिशत रोमन कथालिक और 1 प्रतिशत यहूदी हैं। इन विभिन्नताओं के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएँ भी

हैं। किन्तु इन सब विविधताओं में एकता का अद्भुत अस्तित्व स्विट्जरलैंड में देखने का मिलता है।

स्विट्जरलैंड की इस विविधता में एकता के निम्नलिखित ही कुछ कारण हैं। प्रथम, स्विट्जरलैंड में धार्मिक और भाषायी क्षेत्रों की सीमाएँ एक न होकर भिन्न-भिन्न हैं। एक धर्म के अनुयायियों की अन्य भाषाएँ हैं और एक भाषा-भाषी निरधर्मों का मानने वाला है। द्वितीय, कानून की सीमाएँ भी एक और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं में भिन्न हैं। एक ही कण्टन के अन्तर्गत विभिन्न धर्मपरिवारों और भाषा-भाषी पाये जाते हैं तथा एक ही एक और भाषा के लोग हैं कण्टनों में रहते हैं। तृतीय, स्विस संविधान भी धर्म भाषा और मरुतुन के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता। संविधान ने देश की सभी भाषाओं को राजभाषाओं स्वीकार किया है। कुल मिलाकर इन सभी कारणों का यह परिणाम है कि स्विट्जरलैंड में विराधाभावा के बीच भी एकात्मकता दिखाई देती है। विभिन्नताओं के मध्य भी स्विस जनता की नव-नव में राष्ट्रीय चेतना का संचार है।

स्थाई तटस्थता

स्विट्जरलैंड की सांविधानिक महत्ता का अंतिम प्रमुख कारण उसकी विलक्षण स्थाई तटस्थता है। प्रबल और गठित राज्या—जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि से घिरा होने पर भी वह अपनी तटस्थता और स्वतन्त्रता की सुरक्षा करता चला आ रहा है। राष्ट्रों की भाग्य-निर्णायक मधियों में भी स्विट्जरलैंड की तटस्थता को स्वीकार किया है। राष्ट्रमध्य और बाद में अब मयुक्त राष्ट्रमध्य में भी स्विट्जरलैंड इसी दृष्टि पर सम्मिलित हुआ कि उसकी तटस्थता को मायता मिलती रहेगी। और तो और हिटलर तथा मुसालिनी ने भी स्विट्जरलैंड की तटस्थता को भंग नहीं किया। तटस्थता की नीति के कारण ही बोडी के अधिकांश अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड में ही होते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की तटस्थता 'एकाकीपन' नहीं है। यह देश विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं का सन्निध सदस्य है। पर उसका प्रत्येक कार्य राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता धारण किये रहता है। आज के गुटबन्दी-पूर्ण जगत में उसका यह दृष्टिकोण बहुत ही सराहनीय है।

स्विस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(The Historical Background of the Swiss Constitution)

स्विस संविधान का वर्तमान रूपवस्तु एक क्रमिक विकास का परिणाम है। इसके संविधान-इतिहास को प्रायः 5 हिस्सों में बाटा जाता है—(1) प्राचीन सभ (1291-1798), (2) हैल्वटिक प्रजातंत्र (1798-1803), (3) नेपोलियन काल (1803-1815), (4) सभ-राज्य (1815-1848), एवं (5) सन् 1848 से अब तक का वर्तमान सभ-शासन।

प्राचीन सघ अथवा संघ (1291 - 1798)

पहली अगस्त सन 1291 का अपनी आत्मरक्षा की दृष्टि से तथा आस्ट्रिया के प्रभुत्व को कम करने के लिए उरी, श्वेज तथा अण्टरवाल्डेन नामक तीन सम्प्रभु राज्यों ने एक 'स्थायी सघ' (Perpetual League) की स्थापना की। यही भावी स्विस्-सघ का बीजारोपण था। इस स्थायी सघ के लिए ही चौदहवीं शताब्दी के मध्य 'स्विट्जरलैण्ड' नाम का प्रयोग आरम्भ हुआ।

सघ बनने पर आस्ट्रिया के राजा ने राज्या अथवा कैंटनो (Cantons) पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध में कैंटनो की विजय हुई। सन् 1353 में स्थायी मैत्री सघ आठ कैंटनो का सघ (Confederation) बन गया। फ्रेच-नान्ति (1789) के समय सघ में 13 स्वतंत्र राज्य थे जिनमें अनेक समन्वितों द्वारा यह निश्चय हुआ था कि किसी एक राज्य पर हमला होने की सूरत में सभी राज्य तुरंत सहायता करेंगे। आपसी विवादों के हल के लिए पंच-फैमले (Arbitration) की व्यवस्था थी।

पर यह सघ शासन-प्रणालियाँ में विभिन्नता, धार्मिक मत-भेद, केन्द्रीय सत्ता की कमी आदि के कारण बहुत ही निबल था। यह एक भौगोलिक सघ (Geographical Expression) माना था। सघ शासन का एक मात्र अंग 'डाइट' (Diet) अप्रभावी सत्ता थी जिसके नियम सब कैंटनो पर लागू नहीं हो सकते थे।

हैल्वेटिक प्रजातन्त्र (1798 - 1803)

यद्यपि सभी कैंटनो में आय दिन सघ होते रहते थे, तथापि सघ अपना राजनैतिक व्यक्तित्व किसी न किसी तरह बनाये रहा। बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए उनका सघ-रूप में एक बने रहना आवश्यक था। किंतु 1789 की फ्रेंच क्रांति के बाद नैपोलियन ने आक्रमण करके स्विट्जरलैण्ड पर अधिकार कर लिया। नैपोलियन ने फ्रांसीसी नमूने पर 'हैल्वेटिक गणतन्त्र' (Helvetic Republic) की स्थापना की। स्विट्जरलैण्ड में एकात्मक संविधान की स्थापना की गई। गणतन्त्र में सब कैंटन के केंद्रीय सरकार के प्रासन्निक क्षेत्र बना दिये गये। सारे देश के शासन के लिए सीनेट (Senate) तथा ग्रांड कौंसिल (Grand Council) नाम के दो सदन का विधान-मण्डल बनाया गया। कार्यपालिका शक्ति पाँच व्यक्तियों की एक ऐसी संचारण समिति (Directory) में निहित की गयी जिम्मा निर्वाचन विधान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा किया जाना था।

यह नवीन प्रशासन चल नहीं सका। एक तो स्विस् जनता ऐसे केंद्रीयकृत प्रशासन की अभ्यस्त नहीं थी और दूसरे फ्रेच-सत्ता का आचरण स्विस् जनता को बदाशत नहीं हो सका। फ्रेंच-स्वरूप कैंटनो में विद्रोह खड़ा हो गया। साथ ही जब फ्रांस और आस्ट्रिया में युद्ध छिड़ा तो स्विट्जरलैण्ड इस मध्य में युद्ध-भूमि बन गया।

नैपोलियन युग (1803 ~ 1815)

स्विस लोगो के विद्रोह से बाध्य होकर 1803 में नैपोलियन को कैंटनों की स्वतन्त्रता फिर से स्वीकार करनी पड़ी। 1803 के मध्यस्थता अधिनियम (The Act of Mediation 1809) द्वारा स्विट्जरलैण्ड में पुनः एक संघात्मक राज्य की स्थापना की गई। केंद्र में एक महासभा (Diet) की स्थापना हुई। 6 नए कैंटन स्थापित किए गए। इस प्रकार कुल कैंटनों की संख्या 19 हो गई। लगभग 10 वर्ष तक देश में शांति रही किंतु नैपोलियन के पराभव के बाद कैंटनों के आपसी संबंधों में कुछ हास हुआ। मविधान का पूरा निरादर होने लगा।

सन् 1815-1848 का सन्तुलन

उपरोक्त स्थिति अस्थिर समय तक नहीं चल सकी। यूरोप के मित्र राष्ट्रों (Allied Powers) ने 1814 में स्विस डाइट (Diet) का एक नया सविधान बनाने के लिए विवश किया। यह नवनिर्मित सविधान 1815 के पेरिस सम्मेलन (Pact of Paris) के रूप में वियना कांग्रेस (Congress of Vienna) द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके द्वारा कैंटनों का शासन के उस रूप में बनाये रखने की अनुमति दे दी गई, जो उनमें पुराने सविधान में प्रचलित थी। वियना कांग्रेस ने जहाँ एक ओर स्विट्जरलैण्ड की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित की, वहाँ स्थायी रूप से इसको तटस्थ करके सदस्य के लिए इसकी बहिष्कृत नीति भी निर्धारित कर दी गई। यह वस्तुतः इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी वाक्य था। पेरिस सम्मेलन ने स्विस संघ में तीन अन्य सदस्यों की भी वृद्धि की—वालेस (Valais), न्यूशैटेल (New Chatel) तथा जेनेवा (Geneva)। ये कैंटन अभी तक फ्रांस के अधीन थे। इनके स्विस संघ में मिल जाने से स्विस राज्य-संघ की सदस्य संख्या 22 हो गई। इन 22 कैंटनों में से प्रत्येक कैंटन से दो अर्द्ध-कैंटन बनाए गए, अतः इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड में कैंटनों की कुल संख्या 25 हो गई अर्थात् 19 पूर्ण कैंटन और 6 अर्द्ध-कैंटन।

सन् 1815 के पेरिस सम्मेलन द्वारा अनुमति प्राप्त सविधान के अन्तर्गत सब कैंटनों का समान राजनीतिक-स्तर का मान लिया गया और स्थानीय मामलों में उन्हें पूरी स्वाधीनता दे दी गई। इस व्यवस्था के फलस्वरूप सन् 1815 से 1830 तक देश में शांति और समृद्धि रही, परन्तु उदारवादी भावना और लोकतन्त्र की प्रगति को अवश्य धक्का पहुँचा। लेकिन जुलाई, 1830 में फ्रांस में पुनः शांति हाथ ही स्विट्जरलैण्ड में भी उदारवादी क्रान्ति का विगुल बज गया। इसके फलस्वरूप देश में प्रजातन्त्र के सिद्धांतों का आधार पर एक आंदोलन का प्राग्भूत हुआ जिसका उद्देश्य यहाँ भी कैंटनों के सविधान में परिवर्तन किया जाए। राज्य परिषद् या डाइट (Diet) ने मधीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समिति नियुक्त की। किंतु कैंटनों में विद्यमान धार्मिक मतभेदों के कारण यह समिति कार्य नहीं कर सकी। सन् 1845 में कैथोलिक बहुमत वाले कैंटनों ने अपना अलग संघ

बना लिया। संध की स्थापना से गृह युद्ध प्रारम्भ हुआ, किंतु इसे एक मास के अंदर ही समाप्त कर दिया गया और कैथोलिक लोगों की रुढ़िवादिता का जन्म से मिटा सा दिया गया।

कैथोलिक केन्टोन की पराजय से राष्ट्रीय एकता के आंदोलन की विजय हुई। डाइट (Diet) ने एक नया संविधान बनाया जिस लोगो ने जनमत संग्रह द्वारा स्वीकार किया। इससे वह संविधान अस्तित्व में आया, जिसे सन 1848 का संविधान कहा जाता है और जो समय समय पर विशेषकर 1874 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ आज भी प्रभावी है।

स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(Salient Features of the Swiss Constitution)

सन 1848 के मूल संविधान का 1874 में पूरतया संशोधित किया गया रूप ही स्विटजरलैण्ड की वर्तमान दामन प्रणाली का आधार है। इस संविधान द्वारा जिस दामन प्रणाली की रचना हुई है, वह अमर देखने का नहीं मिलती। यह न तो विगड़ मसदात्मक है और न विगुड़ अध्यक्षतात्मक ही बल्कि इसमें दोनों का संयोग है। स्विस मधीय व्यवस्था भारत और अमेरिका की मधीय व्यवस्थाओं के बीच का रास्ता अपनाती है। स्विस संविधान जिन प्रमुख विशेषताओं के कारण अनुपम और पठनीय है, वे निम्न हैं—

निर्मित एवं लिखित संविधान

स्विटजरलैण्ड का संविधान अपने मूल रूप में निर्मित और लिखित है जिसे एक आयोग ने काफी सावधिचार के बाद तयार किया था और जो संध की डाइट द्वारा स्वीकृत किया जाकर 12 सितम्बर, 1848 से दश में लागू किया गया था। बाद में सन 1874 तक संविधान में पुन व्यापक परिवर्तन लाए गए और यही संशोधित तथा परिवर्धित संविधान आज विद्यमान है।

स्विटजरलैण्ड का संविधान अमेरिकन संविधान की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक लम्बा है। इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जो संविधानिक प्रवृत्ति की नहीं हैं। उदाहरणार्थ संविधान में मछली मारना, सिक्का चलाने, जुआ खेलने आदि के बारे में भी उल्लेख है। स्विस संविधान इसलिए भी लम्बा है कि उसमें संध और कंटोनों का अधिकार क्षेत्र विस्तार से उल्लेख किया है। जहाँ अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत को महत्ता दी गई है वहाँ स्विटजरलैण्ड के संविधान में स्पष्टतया वर्णित शक्तियों को अधिक महत्त्व दिया गया है और इसीलिए संध तथा कंटोनों में सामान्यतः कोई विरोध नहीं हास पाया गया है।

लिखित संविधान के साथ ही कुछ परम्परागत व्यवस्थाओं का अविनाश भी स्विस संविधान में हुआ है। उदाहरणार्थ संविधान द्वारा विधायिका का नारीकरण (Naturalization) संघीय सरकार का अधिकार है, किंतु कोई भी कंटोन किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष नियमा के अनुसार, यदि अपनी

नागरिकता प्रदान करता है तो सघ चिन्तित अभिमनय के कारण, उसे सघीय नागरिक मान लेता है।

कठोर सविधान

इस देश का सविधान कठोर है, जिसमें सशोधन करने की रीति साधारण विधि निमाण की नीति से भिन्न है। फिर भी यह सविधान इतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का। स्विस मविधान की कठोरता ही यहाँ की मयात्मकता की रक्षा किए हुए है, पर सविधान में परिस्थितियों के अनुरूप ठगने की क्षमता भी है।

स्विटजरलैण्ड में सशोधन करने वाली और विधिनिर्माण करने वाली संस्थाएँ भी अलग अलग हैं, उनके ढाँच और कार्य भी अलग अलग हैं। मशोधन के लिए व्यवस्थापिका के दोना सदन प्रस्ताव करें और फिर उस पर लोक निणय (Referendum) तथा बहुमत में फैसला द्वारा यह पारित हो जाए, तब सविधान में मशोधन हो सकता है, अथवा 50 हजार से अधिक मतदाता हस्ताक्षर सहित याचिका दें और फिर उस पर लोक निणय लिया जाए तो सविधान में मशोधन हो सकता है। सविधान की इन मशोधन प्रक्रिया की स्पष्टता से निम्नानुसार समझा जा सकता है—

सशोधन प्रक्रिया—स्विस सविधान में दो प्रकार के सशोधन का आयोजन है—

(अ) पूरा सशोधन (Complete amendment)

(ब) आंशिक सशोधन (Partly amendment)

(अ) पूरा सशोधन—(1) सविधान में पूरा सशोधन करने का प्रस्ताव सघीय व्यवस्थापिका के एक सदन अथवा दानो सदन की ओर से आ सकता है। यदि दानो सदन उस पर सहमत हो तो उस पर लोक-निणय लेना आवश्यक है, जिसमें सम्पूर्ण नागरिकों के बहुमत तथा समस्त कानून की बहुसंख्या का समर्थन होना चाहिए। उसके पश्चात् ही वह मशोधन स्वीकृत हो सकता है। इस रीति को हम अनिवार्य लोक-निणय (Obligatory Referendum) कहते हैं।

(11) यदि दाना में से एक सदन मशोधन से सहमत न हो अथवा पचास हजार स्विस नागरिक उसकी मांग का प्रस्ताव रखें तो उस प्रश्न को लोक-निणय के हेतु उपस्थित कर दिया जाता है तो उसका पुनर्निरीक्षण करने के लिए दोनो सदन का पुनर्निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन के पश्चात् नव-निर्वाचित विधान-मण्डल उसका पुनर्निरीक्षण करता है। यदि दोनो सदन सहमत हो तो यह प्रस्ताव नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता परन्तु उसके सशोधित प्रारूप की जनता की स्वीकृति के लिए रखना आवश्यक है।

(ब) आंशिक सशोधन—इस प्रकार के सशोधन में उपयुक्त दाना रीतियाँ से उपस्थित किये जा सकते हैं। केवल इसमें यह नज़र यह है कि यदि दूसरी

के अनुसार आंशिक संशोधन का प्रस्ताव 50,000 नागरिकों के द्वारा उपस्थित होता है तो वे उस अनिर्णित उपक्रम (Unformulated Initiative) प्रस्तुत कर सकते हैं। उस पर विधान मंडल यदि अपनी स्वीकृति दे देती है तो वह स्वयं विधेयक का प्रारूप तैयार करके लोक-निर्णय के लिए भेज देती है, परंतु यदि उसे वह अस्वीकार करे तो भी उस प्रश्न का जनता के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है। यदि जनता इस मिझात को स्वीकृत कर लेती है तो उसे विधेयक तैयार करके लोक-निर्णय को भेजना पड़ता है।

यदि वह संशोधन का भाग विधेयक के रूप में होता तो उसे मसदा का गोप्य ही जनमत संग्रह के लिए भेजना पड़ता है परंतु इसके साथ वह अपना भी विधेयक प्रस्तुत करती है। दोनों ही लोक-निर्णय के लिए रखे जा सकते हैं। परंतु इनमें भी आवश्यक है कि संशोधन आवश्यक के तना में अविनाश मतदाताओं द्वारा स्वीकृत हो। कंटनों का बहुमत जानने के लिए पूर्ण कंटन का एक मत तथा जेड-कण्टन का आधा मत गिना जाता है। जत स्वीकृति के लिए 11½ कंटन की महमति आवश्यक है।

अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान के अनुसार जनता और संघीय व्यवस्थापिका दोनों ही संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं तथा उसकी अंतिम स्वीकृति नागरिकों पर ही निर्भर है।

निराला सघात्मक स्वरूप

स्विस संविधान का सघात्मक स्वरूप कुछ विलक्षण ही है—

प्रथम स्विटजरलैण्ड बाइम कंटन (अथवा 16 पूर्ण तथा 6 जेड-कण्टन) का शासन संघ है। उसके कण्टनों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वयं संघ भी समाप्त नहीं हो सकता।

दूसरे, अमेरिका की भांति नयी इकाइयों को संघ में सम्मिलित करने की भी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है।

तीसरे, अमेरिकन संविधान अर्थात् संघवाद की सम्प्रभुता पर स्थिर है वहां स्विस संविधान में कण्टनों की सम्प्रभुता को महत्त्व दिया गया है।

चौथे, स्विस संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है केन्द्र और कण्टनों के मध्य शक्ति वितरण का व्यवस्था भी है, किंतु यायपालिका का, विधिया को अवध घोषित करने, संविधान की व्याख्या करने अथवा यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। यायाधीशों का निर्वाचन एक नियत अवधि के लिए व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। यायपालिका का संविधानिक विवादों को तय करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

पांचवां, स्विस संविधान सांस्कृतिक संघ की भी स्थापना करता है। उसमें विविध भाषाओं धर्मों और संस्कृतियों के रूप में एक राष्ट्र के रूप में बंध गये हैं। संविधान

में चारों भाषाओं को राज-भाषा का स्तर दिया गया है और सभी को अपने धर्म-पालन की पूरी छूट है। राज्य का रूप भी धर्म निरपेक्ष रखा गया है।

अतः में, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। प्रत्येक नागरिक अपने कण्टन का तथा मध्य अथवा राज्य मण्डल का नागरिक है। संविधान लिखित है जिसमें प्रशासन के विभिन्न शाखाओं के कार्यों का निर्देश है। विधान मण्डल द्वि-सदनीय है तथा उच्च नदनों में सब इकाइयों का समान अनुपात में प्रतिनिधित्व है। संविधान सदीय व्यवस्था के अनुरूप कठोर है।

गणतंत्रयादी स्वरूप

स्विस संविधान का स्वरूप गणराज्य का है। जनता में ही प्रभुसत्ता निहित है। राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। संविधान के छोटे अनुच्छेद म कण्टनों का गणतन्त्रीय स्वरूप देने और अपनी सत्ताओं को गणतन्त्रीय ढंग पर निर्मित करने का उल्लेख है। कुलीनतन्त्रीय और ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियों को रोकने का समुचित प्रयत्न किया गया है।

अनुपम लोकतंत्र

स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यहाँ प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों का सर्वाधिक सफल प्रयोग हुआ है। शासन के प्रत्येक कार्य में जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य भाग लेती है। जनता की इच्छा का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर हुआ है। कण्टनों से अधिक महत्त्व कम्यूनी का है और मध्य से अधिक महत्त्व कण्टनों का है। संविधान में जनता द्वारा मण्डन किया जाता है। आरम्भिक, लाज नियम आदि द्वारा सर्वे साधारण की इच्छा का सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है। स्विस संविधानों में अन्य संविधानों की अपेक्षा, स्वतन्त्रता और समानता पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ तक कि कार्यपालिका के सभी मन्त्री भी परस्पर स्वतंत्र और समान हैं।

स्विस लोकतंत्र और भी अनेक दृष्टियों से निराला है। स्विट्जरलैंड में वामपक्ष भत्ताधिकार का प्रयोग मतदाताओं की मर्जी पर ही नहीं छाड़ दिया गया है, अपितु कुछ कण्टनों में उसे अनिवार्य बना दिया गया है और यदि कोई मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं करता तो उसे जुर्माना देना होता है। फिर भी दुर्भाग्यवश स्त्रियाँ अभी तक भत्ताधिकार से वंचित हैं। स्विस लोग यह उपयुक्त नहीं समझते की स्त्रियाँ राजनीति में भाग लें।

अनूठी कार्यपालिका

स्विस कार्यपालिका, जो मधीय परिषद् (Federal Council) कहलाती बड़ी अनूठी है। व्यवस्थापिका के दोना नदना द्वारा निर्वाचित मात सदस्या स। मल्कर यह बनी है। इस बहुल कार्यनारिणी (Plural Executive) के सभी सदस्या ती गवितया लगभग समान है। जध्यम नी जय सदस्यो के बराबर के दर्जे का होता है। सभी सदस्य बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। म्यिना ५

इस दृष्टि से भी अनोखी है कि उसमें उत्तरदायित्व और स्वायत्तता दोनों ही के गुण हैं। एक ओर तो वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है तथा दूसरी ओर व्यवस्थापिका द्वारा हटायी भी नहीं जा सकती। मंत्रिमण्डल वेतनभोगी धर्मनिरपेक्षता की तरह है जो व्यवस्थापिका के आचारानुसार काम करते रहते हैं।

अनूठी संसदीय व्यवस्था

स्विस संसदीय व्यवस्था अनेक दृष्टियों से अनूठी है। प्रथम, स्विस शासन व्यवस्था न पूरी तरह संसदीय ही है न पूरी तरह अध्यात्मिक ही। गणतन्त्र का प्रमुख (President) राजा भी है और प्रधानमन्त्री भी, तथा नाम मात्र का शासन प्रमुख भी है और वास्तविक शासन प्रमुख भी। दूसरे, स्विस कांग्रेसालिका संसद में से ली जाती है, संसदीय कार्यवाही में भाग लेती है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है, किन्तु संसद के अविश्वास के फलस्वरूप उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। तीसरे, स्वायत्तता की दृष्टि से स्विस शासन यद्यपि अत्यन्त आत्मिक है, किन्तु शक्तियों का पथक्करण नहीं पाया जाता। कांग्रेसालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। चौथे मंत्रिमण्डल, संसदीय व्यवस्था की तरह, उत्तरदायित्व और पारस्परिक सहयोग की भावना में काम करते हैं किन्तु सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम पर वह अपनी आत्मा का बलिदान नहीं करना पड़ता। वे न केवल मंत्रिमण्डल वरन् संसद की बैठक में भी अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त कर सकते हैं। पाँचवें, स्विस व्यवस्थापिका द्वि-सदनीय है और दोनों सदनों के अधिकार

। सी एफ स्ट्राग के शब्दों में "संसार में स्विस व्यवस्थापिका ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्य में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है।"

मूल अधिकार

भारतीय जैसा अमेरिकन संविधानों के विपरीत स्विस संविधान में किसी भी औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव है। फिर भी बीसिया अनुच्छेद सम्पूर्ण प्रलेख में बिखरे पड़े हैं जो नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं।

अनुच्छेद चार के अनुसार सब लोग कानून की दृष्टि में समान हैं। अनुच्छेद 27 यह व्यवस्था करता है कि कृषकों के स्कूलों में भी धर्म निरपेक्षता के साथ प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर सकने की सबका सुविधा होगी। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि किसी भी स्विस नागरिक को मध्य या अल्प जम की कृषि की सीमा के बाहर निवासित नहीं किया जायगा। अनुच्छेद 49 के अनुसार सब का धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता होगी है। अनुच्छेद 55 द्वारा प्रेस एवं प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता होगी है, यद्यपि कि इसका दुरुपयोग न किया जाए। अनुच्छेद 56 नागरिकों का सम्मेलन बनाने की स्वतन्त्रता देता है। अनुच्छेद 60 द्वारा स्विस नागरिकों का यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी कृषि में स्वतन्त्रतापूर्वक रह जाँगे और उनके माथ कोई भी नहीं होगा।

इन मूल अधिकारों के उद्देश्य में यह तथ्य स्मरणीय है कि जहाँ भारत और

अमेरिका में मूल अधिकारों की रक्षा का भार स्वतन्त्र न्यायपालिका का दिया गया है वहाँ स्विट्जरलैण्ड में ऐसा नहीं। शासन संचालन पर जनता का इतना कठोर नियंत्रण है कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक समझी ही नहीं जाती। पर साथ ही यह बात भी है कि अन्य लोकतंत्रीय देशों के समान ही स्विट्जरलैण्ड में भी यह अधिकार अनियंत्रित नहीं है। वहाँ भी समाज के सार्वजनिक हितों की दृष्टि से इनके प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष रूप में, स्विस् सविधान बहुत ही मौलिक और अनूठा है तथा सम्पूर्ण सवैधानिक जगत के लिए विशेष आदर्श का केन्द्र है।

स्विस् सविधान का भविष्य (नया सविधान निर्माण के दौर में)

स्विट्जरलैण्ड का वर्तमान सविधान सम्भवतः निकट भविष्य में ही पूर्णतः परिवर्तित अथवा मशोर्धित हो जायेगा। सन् 1965 में संघीय व्यवस्थापिका में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि 1974 में वर्तमान मशोर्धित सविधान को 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे, अतः नयी समस्याओं और विज्ञान अनुभवों के आधार पर यह उचित होगा कि एक नया आशिय अथवा पूर्णतः मशोर्धित सविधान बनाया जाकर 1974 तक राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। इन प्रस्ताव पर स्विस् जनता की बहुत ही अनुकूल प्रतिक्रिया हुई थी। वर्तमान में सन् 1966 से ही यह कार्य एक सविधान ध्याग के अधीन है। यह तो भविष्य ही बतलायना कि 1974 तक आने वाले नये स्विस् सविधान का यथापि स्वरूप क्या होगा ? तथापि यह अवश्य है कि अभी इस सम्बन्ध में विवाद समस्याओं और मतभेदों को पार करना है। नारी मतधिकार, संघीय न्यायपालिका का पुनर्गठन, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का सम्बन्ध, कण्टना एग केन्द्र का सम्बन्ध, आदि प्रश्न ऐसे हैं जिनका समुचित समाधान ढेढी-घीर है।

2

स्विट्जरलैण्ड की संघीय व्यवस्था (THE SWISS FEDERAL SYSTEM)

“स्विट्जरलैण्ड का संघ (Confederation) विद्यमान संघीय राज्यों में सबसे पुराना है। ऐसा नाम होते हुए भी अब यह संघ न रहकर जिसका अर्थ शक्तिशाली के श्रेय सत्ता से विहीन राज्यों का एक शिथिल संघीय है, वास्तविक रूप में एक संघ बन गया है।”

—सी एक स्ट्राय

स्विट्जरलैण्ड संघ (Federation) है या नहीं, इस प्रश्न पर काफी मतभेद है। संघ न मानने वालों का तर्क है कि सन् 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ है वह कोई संविधान नहीं है और इसलिए इसका किसी संविधान पर आधारित संघ मानने की अपेक्षा एक संघ (Confederation) कहना चाहिए जिसका तात्पर्य राज्यों के ढीले ढाले गठन बन सकता है। उनका यह तर्क भी है कि संविधान में भी स्विट्जरलैण्ड का संघ (Confederation) कहा गया है न कि संघ (Federation)।

आज मान्यता यही है कि स्विट्जरलैण्ड संघ न होकर संघ है। यह ढीला ढाला गठबंधन नहीं है बरन उसमें के द्र को पर्याप्त शक्ति सम्पन्न बनाया गया है। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग महज एव औपचारिकता है, अथवा प्रस्तावना में स्वयं संघ की स्थापना का उद्देश्य यह है कि “अवयवी कण्टों के संघ को मुहूर्त बनाया जाय तथा उसके द्वारा स्वयं राष्ट्र की एकता, शक्ति और सम्मान की रक्षा एवं वृद्धि की जाय।” वे भी बहोचर ने ‘संघ’ और ‘संघ’ को इस स्थल पर पर्यायवाची माना है। संविधान ने अनुच्छेद दो के अंतर्गत भी एक ठोस और एकतापूर्ण संघ बनाने का विचार प्रकट किया गया है। संघ की दृष्टि से भी संविधान द्वारा एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की गयी है। उदाहरणार्थ दाहरे शासन की व्यवस्था है तथा वे श्रेय और कण्टों की सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट बणन

किया गया है। इसके अलावा कैंटनो को भू-भाग का निर्माण करने वाले समान भागीदारों के रूप में माना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सघ को सदैव के लिए अटूट और स्थायी बनाया गया है। सर्वगं में इकाइया इच्छानुसार अपने-प्रायः अलग कर सकती हैं, लेकिन स्विस् सघ में ऐसी व्यवस्था है कि उसकी कोई इकाई स्वेच्छा से सघ से पृथक् नहीं हो सकती। इसीलिए स्विस् सघ को शाश्वत कैंटनो का शाश्वत सघ (Indestructible Union of Indestructible Cantons) कहा गया है।

इस सघ में 19 पूरे कैंटन और 6 आधे कैंटन सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में बर्न प्रमुखताधारी कैंटनो (जिनमें 3 कैंटनों का विभाजन कर दिया गया है अर्थात्, 19 पूरे और 6 आधे कैंटनो) से मिलकर स्विस् सघ का निर्माण हुआ है। प्रत्येक अर्द्ध-कैंटन भी पूरा स्वतन्त्र है। वह किसी भी पूरे कैंटन से केवल दो बातों में भिन्न है—प्रथमतः वह राज्य परिषद (Council of State) में केवल एक प्रतिनिधि भेजता है जबकि पूरा कैंटन को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, एवं द्वितीयतः वह उन सब प्रश्नों पर जिनका सम्बन्ध मन्त्रिमण्डल में संशोधन करने से है केवल आधे मत का अधिकारी है।

स्विस् सघ और उसमें सघात्मकता के तत्त्व

स्विट्जरलैंड के सघीय व्यवस्था में उन सभी मुख्य तत्त्वों का समावेश है जो एक सघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। निम्न विवेचन से यह भली प्रकार स्पष्ट हो सकेगा।

दोहरी शासन व्यवस्था

सघ व्यवस्था के अनुरूप स्विट्जरलैंड में दोहरी शासन प्रणाली है। यह सघ 25 कैंटनो के सम्मेलन से बना है—जिनमें 19 पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्द्ध-कैंटन। अर्द्ध कैंटन भी पूरा कैंटन के समान ही स्वतन्त्र है। केवल दो बातों में वे पूरे कैंटन से भिन्न हैं—पहली बात यह है कि प्रत्येक अर्द्ध कैंटन उच्च न्यायिक राज्य परिषद में केवल एक प्रतिनिधि भेजती है, जबकि प्रत्येक पूरा कैंटन को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक अर्द्ध-कैंटन को उन सभी प्रश्नों पर जिनका सम्बन्ध मन्त्रिमण्डल में संशोधन करने से है, केवल आधे मत का अधिकार है। स्विस् सघ में केन्द्रीय और इकाई सरकारें अपने निमाण और जीवन के लिए एक-दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। वे संविधान की कृति हैं। वे स्वयं एक-दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन द्वारा ही किसी के अस्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। पुनश्च, सघ और कैंटनो की सरकारों को समान स्थिति प्राप्त है। संविधान द्वारा निर्धारित अपने-अपने काम-क्षेत्र में दोनों ही स्वतन्त्र हैं और एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

स्विस् सघीय व्यवस्था की यह विशेषता है कि सभी कैंटन समान हैं। प्रत्येक कैंटन का निजी संविधान है। उनकी नागरिकता के अपने अलग-अलग नियम

है, उनकी अपनी निजी विधियाँ और प्रथाएँ हैं। आशय यह है कि महात्मक व्यवस्था के अनुकूल स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता है, दाँटेर अधिकार हैं और दाहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार दोहरी शासन व्यवस्था का सघात्मक तत्त्व स्विस संघ में पूरी तरह विद्यमान है।

शक्तियों का वितरण

केन्द्र और अवयवी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन दूसरा महत्वपूर्ण सघीय सिद्धांत है। स्विट्ज़रलैंड में अन्य सघीय संविधानों की तरह ही संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण किया गया है। शक्तियों के वितरण में 'गणना व अवशेष' का सिद्धांत (Principle of Enumeration Residuum) का प्रयोग किया गया है। सघीय सरकार की शक्तियाँ को गिना व अवशिष्ट शक्तियाँ को कैंटनों की सरकारों का माना गया है। राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सरकार के कार्य क्षेत्र में सौंप दिये गये हैं और गैर विषय कैंटनों के अधिकार में रखे गये हैं। संविधान में शक्तियों का वितरण निम्नलिखित चार भागों में बाँटा जा सकता है—

1 **सघीय अधिकार क्षेत्र**—कुछ कार्य जनक रूप से (Exclusively) सघीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में रखे गये हैं, जैसे विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, सभा नियंत्रण करना, कण्टों के झगड़ों का निपटाना, आदि।

2 **समवर्ती अधिकार**—कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कैंटन तथा संघीय सरकार दोनों का समवर्ती अधिकार-क्षेत्र (Concurrent Jurisdiction) है। परन्तु यदि संघ और कैंटन के कानूनों में विरोध हो, तो सघीय कानून ही मान्य होते हैं, कैंटनों के नहीं।

3 **विभक्त अधिकार**—स्विस शासन व्यवस्था में शक्तियों के वितरण की एक विशेषता यह है कि वहाँ एक सूची विभाजित-विषयों की है। ऐसे विषयों का कुछ भाग केन्द्र के अधिकार में है और कुछ भाग कैंटनों के अधिकार में है। उदाहरणस्वरूप, विदेशों से संधि करना सघीय अधिकार क्षेत्र में है, परन्तु कैंटन अपने निकटवर्ती देशों से संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कुछ विषयों पर संधि कर सकते हैं। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था और संचालन का कार्य भी संघ तथा कैंटनों में बाँटा हुआ है। अनिवार्य और निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना कैंटनों का कर्तव्य है परन्तु संघ का यह निरीक्षण करने का अधिकार है कि कैंटन अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं। कृषि और विवाह जैसे विषय विभाजित विषयों की सूची में सम्मिलित हैं।

4 **अवशिष्ट अधिकार**—उपरोक्त अधिकारों को छोड़ कर अवशिष्ट सब अधिकार (Residuary Powers) कैंटनों को सौंपे गये हैं। इन अवशिष्ट अधिकारों का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

इस तरह स्पष्ट है कि स्विस मविधान में सघात्मकता का आशय तत्त्व-नित्यता का वितरण विद्यमान है।

सविधान की सर्वोच्चता

संघीय व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि सविधान का सर्वोच्च होना है। यह तत्त्व भी स्विस सविधान में लगभग पूरी तरह विद्यमान है। सविधान लिखित है तथा इसका पक्ष में विवाद का निवारण सविधान के उद्देश्यों के अंतर्गत ही होता है। सविधान वहाँ सबसे उच्च मान्यता है और आमन के सभी अंगों को उसी के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। कानून की सरकारों का पास करने की अधिकार के प्रदत्त न होने पर सविधान द्वारा दिए हुए हैं। सविधान जन्मे मध को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है उसी प्रकार यह कण्टनों को भी स्वायत्त अस्तित्व प्रदान करता है और यह कण्टन दाता ही के लिए वह समान रूप से माय है। दाता में सकार्श भी सविधान की अवलगा नहीं कर सकता। किंतु इस मद में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सविधान सर्वोच्च है पर उस पर जनमत-संग्रह (Referendum) और आरम्भण (Initiative) के उपकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता में निर्णय लिया गया है। सविधान की सर्वोच्चता के विषय में अंतिम बात यह है कि संघीय न्यायाधिकार को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है।

न्यायाधिकार की सर्वोच्चता

न्यायाधिकार की सर्वोच्चता का विषय में स्विस जूरलण्ड सघात्मकता की कसौटी पर पूरा तहो उतरता है। इस सम्बन्ध में वह अमेरिका के मध्य में भिन्न है। स्विस संघीय न्यायालय को संघीय राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के समान सविधान की व्याख्या करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि स्विस जूरलण्ड का न्यायालय किसी भी संघीय कानून को संघीय सविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिरिक्त कानून माना जाता है। यह शक्ति तो स्पष्ट रूप से सविधान मण्डल के लिए छोड़ दी गई है जो कि विधि-अथवा कानून को पारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से सम्पन्न न करके मूल में प्रमुखता यही कारण रहा है कि स्विस लोग वस्तुतः जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में विश्वास करते हैं।

ऊपरी सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व

संघीय व्यवस्था का एक सहायक तत्त्व यह है कि व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यद्यपि निचले सदन में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है।

स्विस सघात्मक व्यवस्था में यह सहायक तत्त्व भी पूरी तरह विद्यमान है, यद्यपि वहाँ पूरे पण्डना व जड़ - कण्टनों में अंतर अवश्य देखा जाता है। विधान-मण्डल के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक पूरा कण्टन

दो और जट्ट-कैप्टन एक प्रतिनिधि भेजता है। स्विस् व्यवस्था की यह विशेषता भी है कि वहाँ कैप्टनों को अपने प्रतिनिधियों का कायकाल स्वयं निश्चित करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप वहाँ उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं, वे अलग अलग कायकाल के होते हैं। अमेरिका में कायकाल सम्बन्धी यह विभिन्नता नहीं पाई जाती और न ही राज्यों को अपने प्रतिनिधियों का कायकाल स्वयं निश्चित करने का अधिकार है।

सशोधन काम में इकाइयों का अधिकार

मधीय व्यवस्था के अनुरूप स्विट्जरलैंड में सशोधन के प्रस्तावित करने में और उसकी प्ष्टि करने में मध की इकाइयों में जनता का पूरा पूरा हाथ है। संविधान में कोई भी सशोधन केवल तभी पारित समझा जा सकता है जबकि आधे से अधिक कैप्टनों द्वारा वह स्वीकार कर लिया जाए। अहाँ अमेरिका में स्वीकृति राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की होती है, वहाँ स्विट्जरलैंड में स्वीकृति कंटनों के लागो की जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ यायपालिका की सर्वोच्चता के तत्त्व को छोड़कर स्विट्जरलैंड का संविधान में सघ शासन पद्धति के सभी लक्षण विद्यमान हैं। यायपालिका की प्रधानता के सदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि स्विट्जरलैंड में अंतिम निर्णय स्वयं जनता के हाथों में रहता है। अब जसा कि मी एफ स्ट्रॉग (C F Strong) ने कहा है, "वहाँ मधीय यायालय की यायिक पुनरावलोकन का सम्पूर्ण अधिकार देने की आवश्यकता ही नहीं उठती है।"

केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति एवं कण्टनों और सघ सरकार के आपसी सम्बन्ध

अब देना की तरह स्विट्जरलैंड में भी, सघात्मक शासन के बावजूद केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति उद रही है। निम्नलिखित तथ्य इन प्रवृत्ति के परिचायक हैं—

1 स्विस् के द्वीय मत्ता बहुत शक्तिशाली है और आवश्यकता पड़ने पर कण्टनों में मन्त्रि शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

2 केंद्र को अधिकार है कि आ तरिक अव्यवस्था हान पर किसी भी कण्टन का शासन अपन अधिकार में लले।

3 प्रत्येक सघ में मधीय संविधान के नियम लागू हाने हैं। इस प्रकार कैप्टन यथायत कहीं भी सम्प्रभुता-सम्पन्न नहीं है।

4 कण्टन का कोई कानून यदि मधीय कानून के प्रतिकूल हा तो मधीय कानून तो ही मायना मिलती है।

5 कण्टनों का पाम केवल स्थानीय महत्त्व की शक्तिशाली है जबकि सघीय सरकार के पास सम्प्रभुता पूर्ण शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम में वह कण्टनों पर शास्य रह सकता है। अन्त में मुदा एवं यव व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकार ही

इतना व्यापक है कि उसके प्रयोग से केन्द्र समस्त कण्टनो के आर्थिक और व्यापारिक जीवन पर नियन्त्रण कर सकता है।

6 कण्टनो का अन्तराष्ट्रीय विधि के अनुसार कोई व्यक्तित्व नहीं है।

7 कण्टन के सघीय क्षेत्र में हस्तक्षेप को केन्द्र अनेक उपायों से रोक सकता है पर सघीय हस्तक्षेप को रोकने के साधन कण्टनो के पास नहीं हैं।

8 कण्टनो के झण्डों में सघ की ही निर्णायक शक्ति प्राप्त है।

9 कण्टन न सघ से पृथक् हो सकते हैं और न परस्पर कोई संधि ही कर सकते हैं।

10 बहुत बड़ी सीमा तक कण्टन सघ की वित्तीय सहायता पर आश्रित हैं। अशान्ति अथवा उपद्रव के समय भी उन्हें सघ से सहायता की याचना करनी पड़ती है।

11 कण्टनो का अपने सवधानिक सशोधनों पर सघ की स्वीकृति लनी पड़ती है। कण्टन का सशोधन सघीय सविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता।

12 सघीय 'यायालय' कण्टन के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, पर सघीय कानून को अवैध घोषित करने का उसे अधिकार नहीं है।

उपयुक्त व्यवस्थाओं के कारण ही डूपरेज ने कहा है कि "स्विट्जरलैंड के सविधान ने मक्क को वस्तुतः ऐसा रूप प्रदान कर दिया है, मानो वह कण्टनो का शिक्षक और निरीक्षक है"।

उपयुक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि कण्टन की साविधानिक शक्ति घूँस है। सूक्ष्मता से देखने से मालूम होगा कि स्विम राजनीति का आरूपण-केन्द्र कण्टन हैं और कण्टनो की अपनी राजनीति तथा उनका अपना जीवन भी है। यदि केन्द्रीय सरकार अनाधिकार रूप से कण्टनो की शक्तियों का प्रहार करती है तो कण्टनो के पास अपनी रक्षा के साधन आरम्भिक और जनमत राश्र है। छोटे या बड़े सभी कण्टनो को स्विट्जरलैंड के ऊपरी मदन में समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है और इसके द्वारा कण्टनो के हितों का संरक्षण होता है तथा केन्द्र द्वारा कण्टनो की शक्ति को कुचलने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त नागरिकों के जीवन में सघ की अपेक्षा कण्टनो का प्रभाव ही अधिक व्यापक है। कण्टन राजनीतिक प्रयोगशालाओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। स्विस जनता को स्वतन्त्रता प्रिय है और कण्टनो की स्वायत्तता उनके लिए महत्त्वपूर्ण है। वह समझती है कि नविक व सांस्कृतिक जीवन की पवित्रता अभी रह सकती है, जब कण्टनो की स्वाधीनता अक्षुण्ण बनी रहे। कण्टन इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके सरकारी अधिकारी सघीय मसद के सदस्य हो सकते हैं। पुनश्च, कण्टनो का अवशिष्ट विषया पर अधिकार है और ये अधिकार व्यापक हैं क्योंकि ये सघीय अधिकारों के समान स्पष्ट और अंकित नहीं हैं। साथ ही कण्टन समवर्ती विषयों पर भी कानून बना सकते हैं, शत केवल इतनी ही है कि वे

संघीय कानून के प्रतिकूल न हो। फिर, संघीय कामपालिका में अधिक से अधिक कैंटनों की प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया गया है और राज्य परिषद या ऊपरी सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को प्राप्त करने के लिए बारी बारी से अलग अलग कंटनों को अवसर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बात भी महत्वपूर्ण है कि संघ की सरकार जनता पर स्वयं सीधे कर नहीं लगा सकती। स्विट्जरलैंड की जनता ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अभी तक अस्वीकार ही किया है। फिर यह भी नहा भूलना चाहिए कि नागरिकता राजनीतिक जीवन का आधार होती है। स्विट्जरलैंड में नागरिकता का निवास कंटनों में है। प्रत्येक व्यक्ति को संघ का नागरिक होने के लिए आवश्यक है कि वह किसी न किसी कंटन का नागरिक हो। अतः नागरिकता की दृष्टि से भी कंटन अधिक महत्वपूर्ण है।

अतः में यही कहा जा सकता है कि संघ के हाथों में शक्ति का केन्द्रीयकरण इतना नहीं हुआ है कि कैंटनों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रह गया है। फिर भी केन्द्रीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के जिस खतरे के प्रति अण्ड्रे ने संकेत किया है, उसके प्रति स्विस जनता का सचेत रहना उचित ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री अण्ड्रे ने लिखा है कि “इस विकासमान के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति में यह अथ निहित है कि ज्यो-ज्या केन्द्रीय शक्ति अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ायेगी, त्या-त्यो कंटनों की प्रभुता नष्ट होती जाएगी और अतः में वे साधारण प्रशासन के जिले मात्र रह जायेंगे और केन्द्रीय शासन की प्रत्येक आज्ञा को मानना-भर ही उनका काम रह जाएगा।”

3

स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका (THE SWISS LEGISLATIVE)

“जनता द्वारा कठनो के अधिकारों की व्यवस्था के साथ, सघ
की सर्वोच्च-सत्ता का प्रयोग सघीय सभा द्वारा किया
जाता है।

—स्विस सविधान

स्विट्जरलैंड की सघीय सरकार के चार अंग हैं—

1 व्यवस्थापिका जिसे सघीय सभा (Federal Assembly) कहते हैं
और जो जनता के प्रतिनिधियों के आधार पर संगठित की जाती है।

2 कार्यपालिका जिसे सघीय परिषद् (Federal Council) कहते हैं,
जिसके सात सदस्य होते हैं।

3 न्यायपालिका जिसे सघीय न्यायालय (Federal Tribunal)
कहते हैं।

4 जनता के प्रत्यक्ष जनतन्त्र के माध्यम जन-मत-संग्रह (Referendum)
तथा आरम्भक (Initiative)।

स्विस सविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार सघीय व्यवस्थापिका, जिसे
सघीय सभा (Federal Council) के नाम से पुकारा जाता है, शासन सूत्र में
सर्वोच्च-सत्ता (Supremacy) का उपभोग करती है और यह द्वि-सदनात्मक है।
स्विस जनता तथा कठनो के अधिकारों को छोड़कर वह सघ की सर्वोच्च शक्ति का
उपभोग करती है। शासन के अंग दो अंगों अर्थात् सघीय परिषद् (Federal
Council) तथा सघीय न्यायालय (Federal Tribunal) की सत्ता उसके
नीचे है।

सघीय व्यवस्थापिका की विशेषताएँ

(The Peculiarities of the Swiss Legislature)

सत्ता की सर्वाधिकारिता—प्रायः सघीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और

व्यवस्थापिका पर यायपालिका का अधिकार रखा जाता है किन्तु स्विस व्यवस्थापिका इस दृष्टि से निरालापन लिए हुए है। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता इस सीमा तक स्थापित की गई है कि यायपालिका भी उसके द्वारा बनाए गये कानूनों के पुनरावलोकन (Judicial Review) का अधिकार नहीं प्राप्त नहीं है। और तो और कुछ मामलों में तो उस संघीय यायपालिका के निर्णयों को भी रद्द कर देने का अधिकार है। मघीय सभा ही स्विस कार्यपालिका अर्थात् संघीय परिषद (Federal Council), के सदस्यों का निर्वाचन करती है तथा मघीय न्यायालय के यायाधीशों का भी चयन करती है। वस्तुतः स्विस संघीय सभा की स्थिति अमेरिकन कांग्रेस और भारतीय संसद दोनों से ही उच्चतर है। कंटन के कानून से संघीय कानून की उच्च स्थिति भी संघीय व्यवस्थापिका की सर्वोच्च शक्ति को इंगित करती है।

इस सम्बन्ध में संविधान के अनुसार संघीय सभा पर एक प्रतिबंध अवश्य है। संविधान में स्पष्टतः लिखा दिया गया है कि "नागरिकों और कंटनों के अधिकारों के अधीन संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग संघीय-सभा करती है।" भाष्य यह हुआ कि व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र में किन्हीं मामलों में जनता और कंटन भी उसके सहअधिकारी हैं और वे अपने इन अधिकारों का प्रयोग जनमत संग्रह (Referendum) तथा आरम्भिक (Initiative) का प्रयोग करके करते हैं। इन साधनों के द्वारा जनता और कंटन संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकते हैं।

समानपदीय द्वि-सदनीय व्यवस्था—स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों राष्ट्रीय सभा (National Assembly) तथा राज्य सभा (Council of State) समानपदी हैं। नी० एफ० स्ट्रांग के शब्दों में स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की तरह ही वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है, संसार में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका जिसके ऊपरी सदन का शक्ति निचले सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है।

विविध भाषाओं का प्रयोग—स्विस व्यवस्थापिका के सदस्य देश की विविध भाषाओं का प्रयोग करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत उन सभी भाषाओं को राजकीय मान्यता प्राप्त है। संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन भी जर्मन, फ्रेंच तथा कभी कभी इटालियन भाषा में किया जाता है।

संघीय सभा का संगठन

(Organisation of the Federal Assembly)

स्विस व्यवस्थापिका अथवा संघीय सभा का निम्न द्वि-सदनात्मक प्रणाली के आधार पर हुआ है। इसके दोनों सदन निम्न हैं—

(1) राष्ट्रीय सभा (National Council)—यह निचला सदन है।

(2) राज्य सभा (Council of State)—यह ऊपरी सदन है।

राष्ट्रीय सभा

(National Council)

रचना—इसका निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। प्रत्येक कैंटन या ज़द्ध-कैंटन को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं की गयी है। प्रत्येक 24 हजार व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है किन्तु 12 हजार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से भी एक प्रतिनिधि लिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कैंटन और ज़द्ध-कैंटन को दो-एक प्रतिनिधि भेजने का अवसर अवश्य दिया जाता है। वर्तमान काल में राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 196 है जो सन् 1940 की जनसंख्या के आधार पर है। सभा की सदस्य संख्या 200 की सीमा में ही रहे, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वह जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है, जिस पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। पहले दो बार ऐसा किया भी जा चुका है। सन् 1931 में यह संख्या 20 हजार से बढ़ा कर 22 हजार और 1940 में 24 हजार कर दी गयी थी।

चूँकि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है, अतः स्वाभाविक रूप से बड़ी जनसंख्या वाले कैंटनों के प्रतिनिधि अधिक हैं और छोटी जनसंख्या वाले कैंटनों के प्रतिनिधि कम हैं।

कार्य-काल, बैठकें, वेतन आदि—राष्ट्रीय सभा का कार्य-काल चार वर्षों का है। पूरी की पूरी सभा का निर्वाचन प्रति चार वर्षों बाद होता है। संविधान के पूर्ण मशोधन पर मतभेद की सूरत में इस सदन का विघटन 4 वर्षों से पहले भी किया जा सकता है। सभा की बैठकें राज्य सभा की बैठकों के साथ-साथ ही होती हैं।

यदि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में एक-चौथाई लोग या कैंटनों की सम्पूर्ण संख्या के एक-चौथाई कैंटनों की ओर से मांग की जाय तो संघीय परिषद् (Federal Council) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है।

राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता। सदन की बैठक के समय केवल दैनिक भत्ता और भाग-व्यय दिया जाता है। अतः अपने जीवन-निर्वाह के लिए सदस्यों को प्रायः दूसरे वित्तनिक राजनतिक पद पर कार्य करना पड़ता है।

सदस्यों की योग्यता—राष्ट्रीय सभा की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जो मतदाताओं के लिए अर्थात् मतधिकार प्राप्त प्रत्येक स्विस नागरिक सदस्य बन सकता है। यह प्रतिबन्ध है कि धर्माधिकारी (Clergy) तथा राज्य सभा एवं संघीय-परिषद् के सदस्य राष्ट्रीय सभा के सदस्य नहीं बन सकते।

मतदाता—20 वर्ष की आयु पूरी कर चुकने वाला प्रत्येक पुरुष राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। कटन की नागरिकता से वंचित कर दिये गये व्यक्तियों और स्त्रियों को मताधिकार नहीं है। विभिन्न कटनों में दिवालिया, भिक्षु तथा दुष्चरित्र व्यक्तियों को मताधिकार नहीं दिया गया है।

निर्वाचन प्रणाली—इस सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से गणतन्त्र मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्येक कटन एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें विविध ढल अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक सूची में उसने ही नाम होते हैं जितने स्थान उस कटन के हैं और मतदाता उस ही मत देने का अधिकारी है जितने सदस्यों का निर्वाचन उस कटन में होना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उन्हीं कटनों में किया जाता है जहाँ एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन हो। गिनत कौनों में वरन् एक सदस्य चुना जाता है वहाँ मतदान साधारण प्रणाली द्वारा होता है।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष—राष्ट्रीय सभा का प्रत्येक साधारण और असाधारण सत्र के लिए अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। अब, परम्परा के अनुसार, ये अधिकारी प्रत्येक अविवर्तन में नहीं बरन् प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। काइस सदस्य लगातार दो वर्षों तक अध्यक्ष नहीं बन सकता और न कोई, जो एक वर्ष अध्यक्ष रह चुका हो, अगले वर्ष के लिए पुनः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय सभा की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाय रखने, सदन के सम्मान और सुविधाओं की सुरक्षा का ध्यान रखने का उस पर उत्तरदायित्व है। उस नियायक मत देने का भी अधिकार है। सदन में जो विभिन्न समितियाँ का निर्वाचन होता है तो अध्यक्ष भी साधारण सदस्यों के समान मतदान करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष ही सभापति बनता है।

राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता। उसका पद उतना निष्पक्ष भी नहीं होता जितना ब्रिटिश लोक-सभा या अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का होता है। प्रभाव और शक्ति की दृष्टि से भी यह पद विशेष महत्व का नहीं है। फिर भी यह पद पावे को सभी लागायिन रहते हैं क्योंकि अध्यक्ष को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चुनकर गवर्नर में यह पद आदर का है जिनकी जाकाया बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ नेता करते हैं।

राज्य सभा (Council of State)

राज्य सभा स्विस संघीय सभा का उच्च या द्वितीय सदन (Upper or Second Chamber) है। संविधान के अनुसार यह निम्न सदन का अधीनस्थ (Subordinate) नहीं बल्कि समकक्ष (Co-equal) सदन है।

रचना—राज्य सभा की सदस्य संख्या 44 है। प्रत्येक कैंटन के दो प्रतिनिधि और प्रत्येक ज़ुद्ध—कैंटन का एक प्रतिनिधि होता है। अतः 19 कैंटन दो प्रतिनिधि के हिसाब से 38 प्रतिनिधि तथा 6 ज़ुद्ध कैंटन एक प्रतिनिधि के हिसाब से 6 प्रतिनिधि भजत हैं। यह सदा कैंटन का ही प्रतिनिधित्व करता है, सवग के नागरिकों का नहीं।

कायकाल व बैठकें—स्विम राज्य सभा के सदस्यों के कायकाल में भी असमानता है। विभिन्न कैंटन अलग-अलग अवधियों के लिए सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। फरस्वरूप राज्य सभा के 35 सदस्य 4 वर्ष के लिए, 5 सदस्य 3 वर्ष के लिए और 4 सदस्य केवल एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रायः उनका बार-बार पुनर्निर्वाचन होता रहता है। राज्य सभा की बैठकें राष्ट्रीय सभा की बैठक के ही साथ साथ होती हैं। किसी भी विषय पर सम्मिलित रूप से विचार करने के लिए राज्य सभा और राष्ट्रीय सभा की सम्मिलित बैठक भी हो सकती है, यदि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का एक चौथाई भाग या कैंटन की एक-चौथाई संख्या सघीय परिषद (Federal Council) से प्रायना पर सघीय परिषद ऐसी सङ्गठित बैठक जामात करे।

सदस्यों की योग्यता व प्रतिषेध एवं निर्वाचन आदि—सदस्यों की योग्यताये, उनकी निर्वाचन पद्धति, पदावधि आदि निर्धारण कैंटन के हाथ में है। चार कैंटन के प्रतिनिधि बहा के विधानमण्डल द्वारा एक कैंटन तथा तीन ज़ुद्ध—कैंटनों के प्रतिनिधि सावजनिक सभाओं द्वारा और शेष 14 कैंटनों तथा 3 ज़ुद्ध—कैंटनों के प्रतिनिधि व्यवस्क नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। वतन और भत्ता आदि के निश्चय के सम्बन्ध में कैंटनों का स्वतन्त्रता है।

राज्य सभा के सदस्यों पर यह प्रतिषेध है कि वे राष्ट्रीय सभा व सघीय परिषद के सदस्य नहीं हो सकेंगे। सघीय न्यायालय का सदस्य होना पर भी प्रतिषेध है। साथ ही कैंटन की अधिकार है कि वे अपनी सरकार के सदस्यों को राज्य सभा की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—राष्ट्रीय सभा की भांति ही राज्य सभा भी अपने सदस्यों में से ही अपना अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है, किन्तु यह चुनाव एक वर्ष के लिए किया जाता है। विधान के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि किसी एक कैंटन के प्रतिनिधियों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगातार दो वर्ष तक नहीं चुने जा सकते। इस व्यवस्था का स्वनामिध परिणाम यह है कि समस्त कैंटन के प्रतिनिधियों को इन पदों पर जानीबूझकर का अवसर मिल जाता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार एक सत्र का उपाध्यक्ष टारो सत्र में अध्यक्ष बना दिया जाता है। राज्य सभा के अध्यक्ष का भा वे ही अधिकार प्राप्त है जो राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का मिले हुए हैं। वही सभा की बैठकों का सभापतित्व करता है, सदन में शांति

और सुव्यवस्था रखता है, सदन के नियमों का क्रियान्वयन करता है तथा समान मत होने पर निर्णायक मत देता है।

संघीय सभा की शक्तियाँ और कार्य

(Powers and Functions of the Federal Assembly)

राष्ट्रीय सभा और राज्य सभा के संयुक्त रूप संघीय सभा को प्रत्येक वे ही व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं जो साधारणतः अन्य व्यवस्थापन संस्थाओं को प्राप्त होते हैं।

प्रशासन सम्बन्धी शक्तियाँ

(1) संघीय सभा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद् के सदस्यों, उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों, संघीय बीमा निकाय (Federal Insurance Tribunal) के सदस्यों, सर्वोच्च सेनापति, विशेष जन अभियोजन (Extra ordinary Public Prosecutor), चांसलर आदि का निर्वाचन करती है। संघीय विधि द्वारा इसका अन्य किसी भी अधिकारी का चुनाव करने अथवा किसी चुनाव की पुष्टि करने का अधिकार दिया जा सकता है।

(11) संघीय सभा संघ शासन और संघ न्यायपालिका की कार्यवाहियों पर दृष्टि रखती है। संघ की सामान्य अधिनियम शक्ति को क्रियान्वित करने, मन्त्रिपरिषद् को क्रियान्वित कराने तथा मन्त्रों के कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कराने का प्रयत्न करना इस सभा का अधिकार है।

(111) कानूनों की शासन व्यवस्था पर भी संघीय सभा का नियंत्रण रहता है। उसे यह अधिकार है कि वह कानूनों के संविधाना तथा उनके संशोधनों की उचित जाँच करे और उन्हें स्वीकार करे। कानून व विदेशों से यदि कोई संधि-समझौते हों तो उनकी भी जाँच करना और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना संघीय सभा के कार्यक्षेत्र की बात है। आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिए वह संघीय सेना का प्रयोग तक करने की अधिकारिणी है। यह कार्य व्यवहार में वस्तुतः संघीय परिषद् द्वारा किया जाता है और संघीय सभा उसके द्वारा किये हुए कार्य पर अपनी स्वीकृति-मात्र देती है।

(1V) संघीय सभा के अन्य प्रमुख प्रशासकीय कार्य हैं, जैसे दंडित अपराधियों को क्षमादान (Pardon) अथवा सामूहिक क्षमादान (Amnesty) प्रदान करना, संघीय सेना का नियंत्रण व नियंत्रण करना तथा संघीय प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन करना आदि। संघीय सभा को यह अधिकार भी है कि वह सरकार के अन्य अंगों के कार्यों के प्रतिवेदन प्राप्त कर सके। इन प्रतिवेदनों की जाँच करके वह सम्बन्धित अंगों को उसकी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाते हुए भूल सुधार के लिए कह सकती है। संघीय परिषद् के विषय में नियम यह है कि संघीय सभा उसके निर्णयों को पलट नहीं सकती। उसके आदेशों को अविविध में मानना संघीय परिषद् के लिये आवश्यक होता है।

(v) वदेशिक सम्बन्ध पर संघीय सभा का पूर्ण नियंत्रण है। राष्ट्र के बाह्य भागमणों से रक्षा करना, उसकी स्वतन्त्रता और तटस्थता की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना, मधियों और समझौतों को करना आदि सभी काय संघीय सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संधि वार्ता सामान्यतः संघीय परिषद द्वारा की जाती है, परन्तु जब उसका रूप अंतिम हो जाता है तो वे उसे संघीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। संघीय सभा यदि आवश्यक समझती है तो उन मधियों को स्वीकार करने के लिये संघीय परिषद को अनुमति दे देती है। यह उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में संघीय सभा प्रायः अध्यादेश (Arretes) पारित कर देती है यद्यपि कुछ संधियों के विषय में अध्यादेशों पर वैकल्पिक जनमत संग्रह का प्रतिबंध भी लागू है।

व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ

संघीय व्यवस्थापिका संघीय विषयों पर कानून बनाती है। कार्यकारिणी भी विधेयक आदि तैयार करके व्यवस्थापिका के विचार विमर्श और स्वीकृति के लिये उन्हें प्रस्तावित करती है, किन्तु प्रायः व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय सभा ही विधि निर्माण के प्रस्ताव अपनी ओर से प्रस्तावित किया करती है, यद्यपि उसकी इस शक्ति पर जनमत संग्रह तथा जनता की पहल-बदली का अकुश रहता है। जनता अपने वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत संग्रह (Optional Legislative Referendum) के अधिकार के अन्तर्गत संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों को अस्वीकार कर सकती है परन्तु ऐसा केवल उसी व्यवस्थापन के विषय में होता है जिसे नियम के अन्तर्गत 'Law' की मंजा दी जाती है। संघीय सभा प्रायः दूमरे प्रकार के व्यवस्थापन का अधिक आश्रय लेती है जिसे अध्यादेश (Arretes) कहा जाता है। उन अध्यादेशों पर वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत संग्रह का प्रतिबंध नहीं होता जो सबव्यापी (Universally binding) न हों अथवा जिन्हें संसद के दोनों सदनों के सब सदस्यों ने "आवश्यक" (Urgent) घोषित कर दिया हो। वैकल्पिक जनमत संग्रह के प्रतिबंध से बचने के लिये ही व्यवस्थापन का अधिकांश भाग प्रायः अध्यादेशों (Arretes) के रूप में होता है।

संघीय सभा के निष्णयो को अथवा उसके द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यकारिणी अर्थात् संघीय परिषद को निषेध (Veto) करने का अधिकार नहीं है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि यद्यपि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, किन्तु व्यवस्थापिका उसे पदच्युत नहीं कर सकती।

वित्त सम्बन्धी अधिकार

संघीय सभा को सघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण है। वह सघ के आय-व्यय के लेख को स्वीकार करती है और सघ की आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखती है। उसको करो की मात्रा निश्चित करने तथा सरकारी आय को व्यय करने का अधिकार है। संघीय सभा ही संघीय सरकार के प्रमुख पदों की

उत्पत्ति और उनके लिए वेतन आदि विषय में नियंत्रण करती है। सभा की ओर से दिये जाने वाले ऋणा के विषय में भी नियंत्रण करना सभा का ही काम है। बजट पर सभा की स्वीकृति अंतिम होती है, क्योंकि इस पर वक्लिफ़ जनमत संग्रह का प्रतिबंध नहीं होता।

सभा पर परिषद का अपना वित्त सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सभा को भेजना पड़ता है। सभा पर परिषद पर वित्त नियंत्रण रखने के लिये सभा के दोनों सदनों की वित्त समितियों (Finance Committees) के तीन-तीन सदस्यों का एक वित्तीय प्रतिनिधि मण्डल (Financial Delegation) नियुक्त है जो सभा पर परिषद के व्यय पर नियंत्रण रखता है।

व्यापिक शक्तियाँ

सभा व्यवस्थापिका ही सभा व्यवस्थापिका का निरीक्षण तथा निर्देशन करती है। व्यापिक संगठन सम्बन्धी कानून बनाती है तथा सभा व्यवस्थापिका के व्यापिकों को निर्वाचित करती है। सभा व्यवस्थापिक अपनी वार्षिक रिपोर्ट सभा के सामने हा प्रस्तुत करता है। सभा कई मामलों में स्वयं अंतिम नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। यह सभा पर परिषद और सभा व्यवस्थापिक अथवा बीमा न्यायालय के मध्य उत्पन्न विवादों या इन दोनों न्यायालयों में परस्पर उत्पन्न विवादों का नियंत्रण देती है। प्रशासन विधि सम्बन्धी मामलों में सभा पर परिषद के नियंत्रण के विरुद्ध यह सभा अपील सुनती है और उन पर अपना अंतिम नियंत्रण देती है। अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध भी यह कार्यवाही कर सकती है। सभा के वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा दंडित व्यक्तियों व मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को यह क्षमादान भी दे सकती है।

स्पष्ट है कि जितने बहुमुखी और विविध कार्य स्विस व्यवस्थापिका द्वारा किये जाते हैं उतने कार्य समार की बहुत कम व्यवस्थापिका करती हैं। परंतु यह उस सीमा तक सर्वोच्च नहीं है जिस सीमा तक ब्रिटिश मसद है। हमकी शक्ति पर संविधान द्वारा विविध प्रतिबंध लगा दिये गए हैं, जिन जनता के अधिकार, कानूनों के अधिकार तथा संविधान द्वारा अन्य सभा व्यवस्थापिका को दिये गये अधिकार। मन्त्र यह है कि स्विस शासन प्रणाली में मसदीय सम्प्रभुता (Parliamentary Sovereignty) की अपेक्षा लोकप्रिय या माधुनिक सम्प्रभुता (Popular Sovereignty) का उच्च स्थान प्रदान किया गया है। जनमत संग्रह और आरम्भिक के द्वारा जन मता स्वयं वधानिक एवं संविधानिक कार्य में सश्रित रूप से भाग लेती है तथा स्वयं विधि निर्माण की प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रित करती है। वैकल्पिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत संग्रह (Optional Legislative Referendum) की व्यवस्था का प्रतिबंध सभा को सभा की शक्ति पर माधुनिक दृष्टि से तो है हाँ परंतु व्यवहार में भी उसका प्रयोग पचास होता है। सभा सभा का महत्व इस दृष्टि से भी पुनर्प्राप्त कम हुआ है कि सभा

परिपद ने स्विस् शासन सूत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अन्य देशों के समान ही स्विट्जरलैंड में भी व्यवस्थापन काय इतना अधिक बढ़ गया है कि सघीय सभा अधिकांश काय के लिये सघीय परिपद का मुह ताकती है। इमीलिये रेपाड (Reppard) ने कहा है कि 'सघीय सभा के साविधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नन्तु स्पष्टतः सघीय परिपद के हाथ में चला गया है।'

विधि-निर्माण-प्रक्रिया

(The Law making Procedure)

अपने देशों की तरह स्विट्जरलैंड में भी कानून निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया प्रयोग में लायी जाती है, किंतु यह प्रक्रिया अन्य देशों की अपेक्षा निराली है। स्विस् कानून निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख स्तरों का विवेचन हम निम्नांकित शीर्षकों में कर सकते हैं—

विधेयक का प्रस्तुतीकरण

स्विट्जरलैंड में सघीय सभा के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के पारम्भ में सघीय सभा के दोनों सदनों के अध्यक्ष परस्पर वातालाप करके यह निश्चित कर लेते हैं कि कौनसा सदन किस विषय या विधेयक पर पहले विचार करेगा? उन विधेयकों को छोड़कर, जिन्हें सघीय परिपद ने 'आवश्यक' (Urgent) घोषित कर दिया है, सभी विधेयकों का काय विभाजन दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। 'आवश्यक' (Urgent) विधेयकों के विषय में जो भी नियम सदन के अध्यक्ष कर लेते हैं, वही सब के लिए मान्य होता है। काय विभाजन के विषय में यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है तो फिर लाटरी (Lottery) द्वारा नियम किया जाता है।

सदनों में विधेयक चार प्रकार से प्रेषित या प्रस्तावित किया जा सकता है—(1) सघीय परिपद द्वारा, (2) प्रत्येक कण्टन या अर्द्ध-कण्टन द्वारा (3) सघीय सभा के किसी भी सदन द्वारा, एवं (4) सघीय सभा के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा अपने सदन में। वास्तव में अब विधेयकों का तैयार करने और उनका प्रस्तुतीकरण करने का कार्य धीरे-धीरे सघीय परिपद में केन्द्रित हो गया है। व्यवहार में अधिकांश विधेयकों का प्रस्तुतीकरण परिपद ही करती है। कण्टन तो अपना इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वित्तीय विधेयकों पर सघीय परिपद का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। साधारण सदस्या का वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जब कभी भी सघीय परिपद यह आवश्यक समझती है कि प्रशासनिक कृतव्या के निवहन के लिए किसी कानून का बनाना आवश्यक है तो वह अपने कमचारियों की सहायता से विधेयक का प्रारूप तैयार करती है और उसे अपने विचारों के प्रतिबदन के साथ सघीय सभा के दोनों

सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। मधीय सभा के किसी भी सदन द्वारा विधायक प्रस्तावित करने का केवल यह अर्थ है कि जब कोई विधेयक किसी सदन में स्वीकार हो जाता है तब दूसरा सदन उस पर विचार करता है। उसे किसी औपचारिक ढंग से प्रेषित या प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं होती।

किसी भी प्रकार प्रस्तुत किये गये किसी विधेयक के विषय में यदि सधीय सभा का यह मत होता है कि इस विषय में किसी अन्य प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है, तो वह उस पर विचार प्रारम्भ न करके सधीय परिषद से कायबाही करने के लिए कहती है। सधीय सभा ऐना दो विधियों द्वारा करती है—प्रस्ताव (Motion) की विधि द्वारा एवं सुझाव (Postulate) की विधि द्वारा। प्रस्ताव (Motion) एक प्रकार का आदेश है जो सधीय सभा की ओर से सधीय परिषद को दिया जाता है। च कि इस प्रकार का आदेश सधीय सभा के दोनों सदनों ही मिलकर दे सकते हैं, अतः प्रस्ताव दोनों ही सदनों द्वारा मिलकर पारित किया जाना अनिवार्य है। सुझाव (Postulate) के द्वारा सधीय परिषद का आदेश नहीं दिया जाता बल्कि उसे विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 'सुझाव' 'प्रस्ताव' से कम महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दोनों सदनों की ओर से दिया जाय। प्रस्ताव या सुझाव प्राप्त होने पर सधीय परिषद सम्बन्धित विधेयक पर सधीय सभा के सुझावों के आधार पर पुनः विचार करके विधेयक के प्रारूप को अपने प्रतिवदन महित पुनः सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। मधीय परिषद यह मत प्रकट कर सकती है कि विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाय।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सधीय सभा द्वारा दिये गये 'प्रस्ताव' व 'सुझाव' का बड़ा महत्व होता है और सामान्यतः सधीय परिषद उन पर चलती भी है। लेकिन उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उन पर वह कार्य करे। 'प्रस्ताव' पर यदि दो वर्ष तक कोई विचार ही न हो अथवा यदि सधीय परिषद 4 वर्ष तक उसका कोई उत्तर ही न दे, तो वह प्रस्ताव समाप्त समझा जाता है। 'सुझाव' का जीवन तो और भी छोटा है यदि सधीय परिषद कोई कायबाही न करे तो वह समाप्त हो जाता है।

सधीय सभा द्वारा विचार

काय-विभाजन—विधेयक के जीवन का दूसरा स्तर सधीय सभा द्वारा उन पर विचार करना है। चूंकि सभा के दोनों ही सदनों सभी विधेयकों पर विचार कर सकते हैं, अतः सधीय परिषद सभी विधेयकों एवं संदेशों की प्रतियां दोनों के अध्यक्षों का द देती है जो परस्पर मिलकर यह निर्णय करते हैं कि किसका सदन किस विधेयक पर पहले विचार करेगा? उन विधेयकों को छोड़कर जिन्हें सधीय परिषद ने आवश्यक घोषित कर दिया हो, सभी विधेयकों का काय-विभाजन दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यदि इस सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद

हो तो लाटरी द्वारा निणय कर लिया जाता है। 'आवश्यक' (Urgent) विधेयको पर 'प्रथम विचार' सम्बन्धी दोनों सदनों के अध्यक्षों में हुए निणय को सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती।

समिति स्तर—विधेयक के सदन में प्रेषित होने पर उसके सिद्धांतों पर विचार किया जाता है और यदि सदन उनसे सहमत है तो उसे उचित समिति के पास विचाराय भेज दिया जाता है। स्विटजरलैंड की समितिया अपना अधिकांश कार्य उस समय में करती हैं, जो सदनों की बैठकों के सर्गों के बीच में खाली रहता है। समितिया अपनी बैठकों केवल राजधानी में नहीं करती, वरन् देश के विभिन्न नगरों में भी अपना काम करने जाती हैं। समितिया स्थाई और अस्थाई—दोनों ही प्रकार की होती हैं तथा सभी विधेयक उनके समक्ष भेजे जाते हैं। समितियों के संगठन के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि समितियों की सदस्यता में सदस्य के राजनीतिक दलों के अनुपात में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का स्थान मिले।

स्विटजरलैंड में समितिया विधेयको पर निष्पक्ष और विस्तृत रूप से विचार करती हैं। वे मायारणन विधेयको के सार को नहीं बदलती हैं, पर में उनमें अनेक सुधारण अवश्य करती हैं। आवश्यक विचार करने के उपरान्त समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। यदि समितियों के सदस्यों में गम्भीर मतभेद होता है तो बहुमत के प्रतिवेदन के साथ-साथ अल्पमत के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रतिवेदन एवं स्वीकृति—समितियों के प्रतिवेदन के साथ विधेयक पुन सदनों में आता है। विधेयक के ऊपर विचार करने के लिए' (Entering upon the matter) प्रस्ताव रखा जाता है और तदुपरा में उसके प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद-विवाद (Article by article debate) होता है। प्रत्येक सदन में विधेयका पर तीन प्रमुख भागों में विचार होता है—पहले सदन यह निश्चय करता है कि विचार के लिए किम विधेयक की प्राथमिकता दी जाय ? इस निश्चय के उपरान्त सदन विधेयक पर धारा प्रति धारा (Article by article) विचार करता है एवं सस्पेंडात् विधेयक पर एक साथ मत लिया जाता है। यदि मतदान के परिणाम—स्वरूप विधेयक स्वीकार हो जाता है तो उस दूसरे सदन में विचाराय भेज दिया जाता है, जहाँ उपयुक्त प्रक्रिया पुन दोहराई जाती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में विधेयक के भागों पर दोनों सदनों में साथ साथ विचार हो सकता है और एक सदन द्वारा स्वीकार किय जाने पर विधेयक के भागों को दूसरे सदन में विचाराय भेज दिया जाता है।

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाता है, या एक सदन उसे अस्वीकृत कर देता है या विधेयक में ऐसे सुधारण या परिवर्तन उपस्थित करता है जो दूसरे सदन को स्वीकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के प्रतिनिधियों की एक मध्यस्थ समिति (Arbitration Committee) की

नियुक्ति की जाती है। इस समिति में दाना सदना के सदस्य उमान मरदा में होते हैं। मनुष्य सम्मेलन समिति विधेयक पर विचार करके यदि ममज्ञोता करने की चेष्टा करती है। यदि वह कोई ममज्ञोता कर सदन में प्रोपय रहती है तो विधेयक का मधाय मना द्वारा जम्बीकार किया हुआ समझा जाता है, परन्तु यदि कोई ममज्ञोता हा जाता है तो उस पर दाना सदा विचार करत है। यदि दोनों सदना को वह मन गीता स्वीकार नहीं हुआ तो भी विधेयक रह ममया जाना है, परन्तु ऐसा प्राय बहुत कम हाता है।

प्रकाश

जब कोई विधेयक ममान रूप में मधाय उमा के सोम सदनी द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो मध की चामलरी द्वारा उमका रूप तयार किया जाता है, जिन पर दानों सदना के अध्यक्ष और सचिवों के हस्ता पर हाते हैं। हस्ता पर होने के उपरांत विधेयक कानून बन जाता है और उसे मधाय परिषद के पाम प्रकाशन एवं क्रिया-व्ययन के लिए भेज दिया जाता है। जनमत संग्रह द्वारा उमका विरोध न किया जान पर, कानून की दी हुई तिथि के, यदि ऐसी कोई तिथि दी गई हो, अथवा प्रकाशन के पाच दिन बाद लागू हो जाता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि वित्तीय विधेयकों पर जनमत संग्रह की मान नहीं की जा सकती। साधारण कानूनों पर तीन मास तक 30 हजार मतदाता जनमत संग्रह किय जाने की माग कर सकते हैं। यदि जनमत संग्रह में किसी कानून को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त न हो तो वह कानून रह हा जाता है, परन्तु वित्तीय विधेयक इस व्यवस्था में मुक्त हैं।

कैंटनो की व्यवस्थापिका

(Legislative of Cantons)

प्रायः प्रत्येक प्रतिनिधिक कैंटन में एक सत्तीय (Unicameral) व्यवस्था पिका है जिसे महापरिषद् (Grand Council) या कैंटन परिषद (Cantonal Council) कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या और उनका कार्यकाल विभिन्न कैंटनो में भिन्न भिन्न है। सदस्य संख्या प्रायः 50 से लेकर 200 तक हाती है और कार्यकाल 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। व्यवस्थापिका का संगठन जनमध्या के आधार पर किया जाता है और अधिकतर कैंटनो में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। कैंटन परिषद (Cantonal Council) कानून बनाती है, कर लगाती है, वार्षिक बजट स्वीकार करती है, संविधान में संशोधन करती है और सरकार का निरीक्षण करती है।

4

स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका (THE SWISS EXECUTIVE)

स्वित्स सभ्य की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका
शक्ति सात व्यक्तियों की एक संघीय परिषद्
द्वारा प्रयुक्त की जाती है।

—स्वित्स संविधान, धारा 95

स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को 'संघीय परिषद् (Federal)' कहा जाता है। यह विश्व की 'संघीय संस्थाओं' में सबसे बनीसी है। यह बहुत 'संघीय' (Plural Executive) है, तथापि 'सम' जैसा 'संघीय' और 'संघीय' व्यवस्था का 'संघीय' प्रमाण है। न तो यह 'व्यवस्थापिका' का 'संघीय' प्रदर्शन करती है और न 'संघीय' द्वारा 'संघीय' की जा सकती है। 'संघीय' ही यह 'व्यवस्थापिका' में 'स्वातंत्र्य' भी है। इसका 'निर्वाचन' किसी 'राजनीतिक दल-विरोध' के 'कार्यक्रम' में पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। उसे किसी 'पक्ष' की नीति 'निर्धारित' नहीं करनी पड़ती, 'निर्वाचन' के 'पक्ष' के 'रंग' से यह कुछ न कुछ 'रंगी' अवश्य रहती है।

संघीय-परिषद् का संगठन

(Composition of the Federal Council)

सदस्य संख्या—जहाँ 'संघीय' के 'सभी' 'संघीय' की 'कार्यपालिका' 'संघीय' में या 'राष्ट्रपति' में 'निहित' होता है वहाँ 'स्विट्जरलैंड' की 'कार्यपालिका-शक्ति' 'संघीय' 'संघीय' 'परिषद्' में 'निहित' है।

चुनाव एव कार्यकाल—परिषद् में 'संघीय' 'संघीय' का 'चुनाव' 'संघीय-सभा' द्वारा होता है। 'संघीय' 'चुना' लिए 'जा' के 'बाद' 'संघीय-सभा' की 'सदस्यता' 'त्याग' देनी पड़ती है। 'चुनाव' के 'सम्बन्ध' में 'कुछ' 'सांविधानिक' 'पतिवचन' तथा 'अभिसमय' ये हैं—

(1) परिषद् में 'एक' 'कदम' 'संघीय' 'एक' 'व्यक्ति' ही 'निर्वाचित' हो सकता है।

(2) "ऐसे कोई भी लोग जो स्वतन्त्र या वैवाहिक सम्बन्धों से प्रत्यक्ष वंश-परम्परा में कभी तक भी तथा अप्रत्यक्ष परम्परा में चौथी पीढ़ी तक परस्पर सम्बन्धित हों, जिन्होंने बहनों से विवाह कर लिया हो तथा जो नादरश जाने के कारण परस्पर सम्बन्धित हों, एक समय पर परिषद् के सदस्य नहीं हो सकते।"

(3) एक अभिसमय के अनुसार दा सबसे बड़े और प्रमुख कटन—वरन तथा ज्यूरिच—का सदस्य ही परिषद् में प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेषाधिकार सबसे बड़े फ्रेंच भाषा—भाषी कटन यॉर्ड (Vaud) को भी प्राप्त है।

(4) एक अन्य अभिसमय द्वारा परिषद् के संगठन को व्यापक प्रतिनिधित्व मिला है, जैसे प्रमुख धर्मबलम्बियो, भाषा—भाषियों तथा राजनीतिक दलों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

अस्तुत यह एक विचित्र बात है कि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के घर स्विटजरलण्ड में भी कायपालिका को लागू प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलते। किन्तु इसके दो विचार कारण हैं। प्रथम, स्विस मसद के सदस्य जनता के इतने निकटतम सम्पर्क में रहते हैं कि उनके द्वारा किये गये निर्वाचन वास्तव में जनता द्वारा किये हुए निर्वाचन ही होते हैं। द्वितीय प्रत्यक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप दलीय-दलगत पक्ष हो जाने की सम्भावना से स्विस जनता बचना चाहती है।

संघीय-परिषद् का कार्य काल इतना ही है जितना संघीय-सभा का अवकाश पारथक्य। परिषद् के सदस्य प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद नये सिरे से चुने जाते हैं। यदि अवधि से पूर्व राष्ट्रीय-सभा विघटित कर दी जाती है तो संघीय-परिषद् भी विघटित हो जाती है और नया संघीय-परिषद् संघीय-सभा के नये चुनाव के बाद चुनली जाती है। परिषद् का कोई स्थान पदावधि से पहिने रिक्त हो जाता है तो उस स्थान को संघीय-सभा अपनी अगली बैठक में पदावधि के साथ समय के लिए भर लेती है।

परिषद् के सदस्य के बारम्बार चुने जाने पर कोई साविधानिय प्रतिबन्ध नहीं है। यही कारण है कि कुछ सदस्य तो लगभग की सेवा 25 से 30 वर्ष तक निरन्तर करते रहे हैं। योग्य सदस्यों के कारण ही यह परिषद् एक शक्तिशाली और जादरणीय कार्यपालिका सिद्ध हुई है।

सदस्यों की योग्यताएँ व वेतन—संविधान की धारा 96 के अनुसार संघीय परिषद् के सदस्य उन सभी स्विस नागरिकों में से चुने जाते हैं जो राष्ट्रीय-सभा की सदस्यता की योग्यता रखते हैं। धारा 97 यह प्रतिबंध लगाती है कि परिषद् के सदस्य संघ या कanton के अलगत न तो कोई अन्य पद ग्रहण कर सकते हैं और न कोई अन्य व्यवसाय ही कर सकते हैं। सदस्यों को संघीय निर्धि से 80 हजार फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है। 55 वर्ष की उम्र वाले सदस्यों को पेंशन दी जाती है यद्यपि कि वे 10 वर्षों तक सदस्य रह चुके हों।

॥ १५ प्रणाली—साधारणतया परिषद् की बैठकें सप्ताह में दो बार होती हैं।

कायवाही गुप्त रहती है। गणपूर्ति के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निणय बहुमत से होता है। अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार है। सघीय चांसलर (Federal Chancellor), जो व्यवस्थापिका तथा सघीय परिषद् के कार्यालय का अध्यक्ष होता है, परिषद् के सचिव के रूप में परिषद् की बैठकों में सम्मिलित रहता है। चांसलर के बदले कोई उप-चांसलर भी उसके कार्यों को कर सकता है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति)—सघीय परिषद् अपने सदस्यों में से ही प्रतिवर्ष अपने सभापति और उप-सभापति का निर्वाचन करती है जिन्हें सघ का राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति कहा जाता है। दोनों ही वर्षों के लिए व्यक्ति द्वारा चुने जा सकते हैं किंतु उनका चुनाव लगातार दो बार नहीं हो सकता। यही कारण है कि लगातार दो वर्ष नहीं लेकिन अनेक बार लोगो ने इन पदों पर कार्य किया है। उदाहरणार्थ श्री फिलिप इटर सन 19 9 1942 1947 और 1953 में परिषद् के अध्यक्ष रहें। उपाध्यक्ष पद पर रहने के बाद व्यक्ति अध्यक्ष चुना जा सकता है। आजकल की परम्परा के अनुसार उपाध्यक्ष अर्थात् उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चता के सिद्धांत (Seniority System) पर परिषद् सदस्यों में से होता है। अध्यक्ष या राष्ट्रपति को परिषद् के अन्य सदस्यों के समान ही वतन मिलता है, केवल 10 हजार फ्रैंक अतिरिक्त भत्ता कम्प में और दिय जाते हैं।

अध्यक्ष की स्थिति न तो अमेरिकन राष्ट्रपति जगती होती है और न ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान। उसे कोई विधिाधिकार प्राप्त नहीं होते। अपने सचिवों के समान वह भी एक विभाग का अध्यक्ष होता है। बार-बार बालो में एक होन के कारण ही उसे विशेष महत्व-रहित अर्थ में कहा जाता है। अध्यक्ष की विनियमा बहुत ही कम हैं। देश के शासन के लिए अन्य समस्याओं की अपेक्षा किसी भी प्रकार वह अधिक उत्तरदायी नहीं है। समस्त निणय सघीय परिषद् ही एकल सत्ता (Single Authority) के रूप में करती है। अध्यक्ष न किसी अधिकारी की नियुक्ति करता है और न कोई सचिवावार्ता जादि ही कर सकता है। किसी विधेयक पर उसे निष्पाद्यक अधिकार भी नहीं है। उसकी शक्ति की सीमा इतनी ही है कि वह सघ की सभाओं का सभापतित्व करना है, विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों को देखता है, विभिन्न प्रशासकीय विभागों के कार्य का सामान्य निरीक्षण करना है और किसी मामले पर बराबर का मतभेद हो जाने पर अपना निर्णायक मत (Casting Vote) देता है। उसकी स्थिति वास्तव में एक प्रतीकात्मक प्रधान नी-सी है। वह सावजनिक उन्वो पर स्वयं प्रजापति का प्रतिनिधित्व करता है।

सघीय परिषद् के अध्यक्ष या सघ का राष्ट्रपति की स्थिति का सार लोवेन के इन शब्दों में प्रकट होना है कि "बहु सारस्य न राष्ट्र की वाय शास्त्रा समिति का अध्यक्ष होन के नाते यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके मापी क्या कर

रहे हैं ? वह राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों का पूरा करता है।' इतना होने पर भी अध्यक्ष पद प्रत्येक राजनीतिज्ञ के लिए सर्वोच्च पद है और उस जन-सेवा का सर्वोच्च पुरस्कार समझा जाता है।

प्रशासकीय विभागों का वितरण—स्विस प्रशासन के सभी कार्यों का सात विभागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विभाग एक संघीय परिषद के सदस्य के अधीन होता है जो उसके कार्य-प्रचालन के लिए सम्पूर्ण परिषद् के प्रति उत्तरदायी होता है। विभागों का वितरण औपचारिक रूप से परिषद् द्वारा किया जाता है किन्तु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि कौनसा सदस्य किस विभाग को सौंपेगा ? एक विभाग के प्रमुख की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए प्रत्येक विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग का उप-प्रमुख होता है।

परम्परा के अनुसार परिषद के सदस्य द्वारा निर्वाचित हो सनत हो और उन्हें पहिने वाले विभाग ही सांप दिये जाते हैं। फलस्वरूप विभागों के मंत्री नीमितिष्ट नहीं रहते, चरन उनमें भी अधिकांश अपने-अपने विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हैं। उत्तमान समय में स्विट्जरलैण्ड के प्रशासनिक विभाग (Administrative Departments) में हैं—राजनीतिक विभाग, गृह विभाग, सैनिक विभाग, न्याय एवं पुलिस विभाग, वित्त एवं प्रशुल्क विभाग, सावजनिक अथ विभाग, तथा डान और रेल विभाग।

संघीय परिषद् के अधिकार एवम् कर्तव्य

(Powers and Functions of the Federal Council)

प्रशासकीय अधिकार एवम् कर्तव्य

संघीय परिषद स्विस संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और संघीय आजागी तथा कानूनों के अनुसार सम्पूर्ण संघ के प्रशासन का नियंत्रण करने का अधिकार इसे प्राप्त है। यह निरीक्षण करती है कि संघीय संविधान तथा संघीय कानूनों का पालन हो रहा है अथवा नहीं और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करती है। प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय परिषद का मुख्य कर्तव्य है कि वह संघ में शांति एवम् व्यवस्था का उचित प्रबंध कर तथा देश की बाह्य आजागी एवम् आंतरिक उपद्रवों से रक्षा कर। साथ ही स्विट्जरलैण्ड की स्वतंत्रता और तटस्थता की सुरक्षा करे। यद्यपि आंतरिक शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था कानूनों का उत्तरदायित्व है लेकिन यदि आंतरिक गड़बड़ी हो जाए तो संघीय-सभा (Federal Assembly) निर्णय करती है कि क्या कार्यवाही की जाए और संघीय परिषद उसकी आज्ञाओं को क्रियान्वित करती है।

आपातकाल की स्थिति में यदि संघीय संसद का सत्र अथवा कार्यकाल नहीं है तो संघीय परिषद को अधिकार है कि शांति एवम् व्यवस्था की स्थापना के लिए वह सेनाओं का प्रयोग जिस प्रकार उचित समझे, करे। किन्तु परिषद के लिये यह आवश्यक है कि यदि दो हजार से अधिक सैनिकों की उपयोगिता कायम

आवश्यकता पड़ी हो अथवा यदि उन सैनिकों को तीन सप्ताहों से अधिक युद्धरत रहना पड़ा हो, तो तुरंत सदन का सत्र (Session) आहूत करे।

संघीय मसद् (Federal Assembly) के कानूनों और अधिनियमों, संघीय न्यायालय के निर्णयों तथा विभिन्न कानूनों के पारस्परिक मगड़ों के समाधान के लिये किये गये समझौतों और मध्यस्थों को लागू कराने का प्रबंध भी संघीय परिषद् करती है। वही संघीय प्रशासन के सब अधिकारियाँ एवम् कमचारियों के व्यवहार, कार्य एवम् चरित्र का निरीक्षण करती है। जिन पदों पर संघीय-सभा, संघीय न्यायालय अथवा अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया हो, उन पर संघीय-परिषद् ही नियुक्ति करती है। व्यवहार में संघीय-परिषद् अपने नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारों को प्रशासन के विभिन्न विभागों को प्रत्यायाजित कर देती है और विभिन्न नियमों एवं अन्य स्वतन्त्र सत्ताओं अथवा निकायों को मौप देती है।

स्विट्जरलण्ड के वार्षिक सम्मेलनों के नियमों और उनकी देखभाल का अधिकार भी संघीय परिषद् को ही दिया गया है। संघीय-परिषद् ही उन विभिन्न संघियों का परीक्षण करती है जो या तो कानून आपसे में करते हैं अथवा कानून विदेशों के साथ करते हैं। यदि वे संघीय उचित होती हैं तो उन पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, अन्यथा संघीय-परिषद् अव्याजित संघीय संघियों के विरुद्ध संघीय सभा में अपील करती है और उन्हें रद्द करने की सिफारिश करती है।

संघीय परिषद् अपने समस्त कार्यों एवम् कार्यकलापों की रिपोर्ट संघीय सभा के समक्ष प्रत्येक साधारण सत्र में प्रस्तुत करती है। देश की आंतरिक स्थिति के बारे में प्रतिवेदन करती है और सबके विदेशों के साथ सम्बन्धों के ऊपर भी आवश्यक प्रकाश डालती है। परिषद् संघीय सभा के विचाराय ऐसे प्रस्ताव अथवा विधायक भी प्रस्तुत करती है जो उसके मतानुसार सब-साधारण ने कल्याण की दृष्टि से लाभदायक एवम् आवश्यक हो। यदि कभी संघीय सभा या उनका कोई सदन विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो संघीय-परिषद् आवश्यक रिपोर्ट भजती है।

संघीय परिषद् के नियन्त्रण में समस्त संघीय सेना और उनके प्रशासन की शाखाएँ भी रहती हैं जिन पर कि संघ का नियन्त्रण है।

संघीय-परिषद् कानूनों द्वारा पारित सभी कानूनों और उनके सभी अध्यादेशों का भी परीक्षण करती है। कानूनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सभी कानूनों और अध्यादेशों को संघीय परिषद् में स्वीकृत करावायें। साथ ही संघीय परिषद् कानूनों के प्रशासन व शाखाओं पर भी नियन्त्रण रखती है जहाँ का नियन्त्रण परिषद् के अधिकार क्षेत्र में हो। संघीय सभा की स्वीकृति के लिये आये हुए कानून विधान में मशायद के प्रस्तावों का संघीय परिषद् जांच करती है और विधान मण्डल में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। किसी भी कानून में उपद्रव

मथवा अशांति की स्थिति में, संघीय परिषद् ही संघीय हस्तक्षेप का निश्चय करती है और संघीय सभा का अनुमोदन प्राप्त-कर आवश्यक कामवाही करती है।

विधायी अधिकार एवं कर्तव्य

विधि निर्माण में भी परिषद् का काफी हाथ रहता है। संविधान की धारा 102 के अनुसार उसे अधिकार है कि वह कानून के विधेयक मसद में प्रस्तुत करे। प्रस्तुत लगभग 95 प्रतिशत विधेयक संघीय परिषद् द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। सदस्यों के अपने विधेयक भी प्रायः पहिले परिषद् के पास आवश्यक सुधार और सुझावों के लिए भेजे जाते हैं और तत्पश्चात् उन पर सदन विचार करती है।

संघीय परिषद् को अध्यादेशों को जारी करने का एवं प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) की प्रणाली के अंतर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है। परिषद् के अध्यादेशों का एवं प्रदत्त व्यवस्थापन व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया उसके नियमों का प्रभाव कानूनों के समान ही होता है और न्यायालयों द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। अध्यादेशों के विषय में किसी भी प्रकार के जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है, जबकि कानूनों के विषय में ऐसा है। अध्यादेशों के जारी करने की शक्ति संघीय परिषद् की स्थिति और उसके महत्त्व को बड़ा सम्बल प्रदान करती है।

संघीय परिषद् के सदस्य विधान सदनो की बैठकों में उपस्थित हो सकते हैं। वे अपने विचार, मत और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विचाराधीन विषयों पर प्रस्ताव रख सकते हैं। परिषद् के सदस्य संघीय सभा के वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और संघीय सभा भी उनके विचारों को, मतों को तथा वाद-विवादों को बड़े आदर से सुनती है और उन्हें ग्रहण भी करती है। संघीय सभा की समितियों में भी संघीय परिषद् के सदस्यों का स्थान और प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। समितियों के प्रतिवेदनो को बनाने में मन्त्रियां अर्थात् परिषद् के सदस्यों के विशेष ज्ञान की सहायता समितियां अवश्य लेती हैं।

वित्तीय अधिकार एवं कर्तव्य

वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय परिषद् को पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। प्रति वर्ष संघीय बजट इसी के द्वारा तयार किया जाकर संघीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसी के द्वारा उसको सभा से स्वीकृत भी कराया जाता है। यह संघीय भाग व्यय की देखभाल करती है और राजस्व संग्रहित करती है। वित्तीय व्यवस्था की सुचारुक्रता और मुचार्स प्रवृत्ति के लिए संघीय परिषद् उत्तरदायी होती है। भाग व्यय का समुचित हिमांश रखने का उत्तरदायित्व परिषद् पर ही है।

न्यायिक अधिकार एवं कर्तव्य

संघीय परिषद् को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। वह कुछ विशेष प्रकार की अंतरराष्ट्रीय मधियां और संविधान की कतिपय धाराओं के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के सम्बंध में की गई अपील पर निणय देती है। संघीय रेल्वे प्रमाणन एवं विभिन्न प्रणालिकीय विभागों के निणयों के विरुद्ध की गई अपीलों की

भी मुनवाई करती है। इस सम्बन्ध में यह याद रखने की बात है कि सघीय परिषद् अंतिम अपील की 'यायालय' नहीं है, इसके निम्न के त्रिरुद्ध अपील सघीय 'यायालय' तथा मजद को दी जा सकती है। क्षमादान (Pardon) का अधिकार अन्य देशों में प्रायः वायपालिका को प्राप्त होता है परन्तु स्विन सघीय परिषद् को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

सकटकालीन अधिकार एवं कर्तव्य

संविधान के द्वारा सघीय परिषद् को कोई सकटकालीन विद्यमान अधिकार नहीं दिये गये हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक मंदी या ऐंसे ही अन्य सकट के समय सघीय सभा अपने सब अधिकार सघीय परिषद् को सौंप सकती है और ऐसा कई अवसरों पर हा चुका है। उदाहरणार्थ, 1849, 1853, 1859 और 1870 में देश की तटस्थता की रक्षा, 1914 तथा 1939 में विश्व युद्ध के समय राष्ट्र की तटस्थता, स्वतंत्रता एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए और 1930 में आर्थिक गड़बड़ का सामना करने के लिए सघीय परिषद् को 'पूर्णधिकार' सौंपे गये थे।

लोवेल (Lowell) के शब्दों में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि "सघीय परिषद् को मुख्य शक्ति स्रोत कहा जा सकता है और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय सरकार का सन्तुलन चक्र है।"

सघीय परिषद् की विशेषताएँ

(Unique Features of the Federal Assembly)

वस्तुतः सघीय परिषद् की स्थिति विश्व में अनूठी और विशिष्ट है। यह न तो विगुड रूप में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल से ही मिलती है और न अमेरिका के अठ्ठाक्षर वायपालिका के ही समान है, फिर भी इनमें दोनों के गुण और लक्षण विद्यमान हैं।

बहुल कार्यपालिका

स्विन कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका (Plural Executive) है। इसकी तुलना में ब्रिटेन, अमेरिका आदि में वायपालिका एकल (Singular) है। बड़ा कार्यपालन के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर अर्थात् प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर होता है। इसके अतिरिक्त एकल कार्यपालिका वाले देशों में मंत्रिमण्डल के सदस्यों में किसी एक की स्थिति अन्य की तुलना में अधिक महत्व का होती है। स्विन सघीय परिषद् इन सबसे अनूठी है क्योंकि वाय पालन शक्ति एवं धर्मन में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित है जो सब एक दूसरे के बराबर के पद के हैं। यहां तक कि परिषद् का अध्यक्ष भी कोई विशेषाधिकार नहीं रखता। परिषद् एक मण्डलीय मर्यादा के समान है उसके अध्यक्ष की स्थिति बराबर वाली में से एक की है। अंगन साथियों को चुनवानी की का उस को अधिकार नहीं होता है।

संसदीय अर जव्यजात्मक प्रणालियों का मध्य मार्ग

स्विम नागरिकाओं का दूसरा झुंडापन यह है कि वह न तो समदात्मक है और न जव्यजात्मा, यरन उमम दाना पद्धतियों की विपत्तियों का मन्थन है। इसम दाना पद्धतियों के गुणों का अपनान और अवगुणों से बचने का प्रयत्न किया गया है। यह संसदीय दमलिय है कि (क) उमक सदस्य का निगमन व्यवस्थापिका द्वारा और प्राय व्यवस्थापिका म स ही हाता है, (ख) उमके सदस्यों को व्यवस्थापिका की बैठकों म उपस्थित रहन और विधायक का प्रस्तुत करन का अधिकार है, (ग) उमके सदस्य हा व्यवस्थापिका से विधायक पारित करवाते हैं। स्विम कायकारिणी असंसदीय दमलिय है क्यकि—(क) उमक सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हाते। कायकारिणी के सदस्य चुन जान के बाद व व्यवस्थापिका के पदों स जलम हो जात है, (ख) उसका कायकाल निश्चित है क्यकि व्यवस्थापिका सभा म अपनी हार हो जान पर यह पदच्युत नहीं, हांकी और न ही सप स प्रगन अधिकाारी का उह अपने पद से जलग करन का अधिकार है।

उत्तरदायित्व और स्वायत्त का स्वस्थ मिथन

स्विस संघीय परिषद के उत्तरदायित्व और स्वायत्त का बड़ा उपयोग एवं स्वस्थ माग है। संघीय परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है—इम अर्थ म कि उसके सदस्य प्रश्नों प्रति प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सरकार की नीति का औचित्य निश्चि करते हैं। कायकारिणी पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण भी होता है। व्यवस्थापिका कायकारिणी को विशेष नीति अपनाने और काय करने के लिए आदेश दे सकती है और उनको मानना उनके लिय अनिवार्य है। लेकिन उत्तरदायित्व केवल यही तक सीमित है क्यकि त्रिटिंग प्रणाली के समान व्यवस्थापिका काय कारिणी को प च्युत नहीं कर सकती। यदि किसी विषय पर कायकारिणी के सदस्य हार जाते हैं तो वे इ गलब और फास के मन्त्रियों की तरह पद त्याग नहीं करते। वे अपनी माग को छिपा लते हैं तथा व्यवस्थापिका के निणय का मान लते हैं और यह काय अत्यंत मरलता से कर लिया जाता है। मुनरो न इसी बात को प्रकट करते हुए कहा है कि 'संघीय परिषद विधि-निर्माण के काय मे पूण सक्रिय रूप से भा ले परंतु यदि उसका सुचाव न माना जाए तो वह अपना अपमान भी न ममये—ऐसी आशा संघीय परिषद से की जाती है।'

निदलीय चरित्र

मन्त्रिमण्डलीय शासन म संयुक्त सरकारें (Coalition Government) असाधारण काल मे ही संगठित की जाती है किंतु संघीय परिषद म व्यवस्थापिका के लगभग सभी प्रमुख दल प्रतिनिधित्व करते हैं। परिषद आ कुछ भी करना चाह, वह किसी दल के य न के रूप म नहीं करती। उम सदस्य परिषद का बैठका म भी और ससद की बैठकों म भी अपने अपने मत व्यक्त करन के लिए पूण स्वतंत्र हाते हैं। इतन ही नहीं, आवश्यकता पडने पर वे ससद म अपने मांभी सदस्यों के निर्णयों के विरुद्ध भी बोल सकते हैं। इस प्रकार स्विटजरलैंड म यह एक विशिष्ट

किन्तु जादश व्यवस्था है कि सघीय परिषद् मे और सघीय सभा मे जो कुछ भी होता है वह प्रायः दल व दो की सीमा से उठकर होता है और उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की साधना करना होता है।

व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन

जहां अमेरिका में कायपालिका के मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ब्रिटन में वंश राजा द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं, वहां स्विट्जरलैण्ड में कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुने जाते हैं।

विशेषज्ञों का मन्त्रीमण्डल

स्विस सघीय परिषद् की अंतिम विशेषता यह है कि उसमें मन्त्रीगण प्रायः नौनिमित्त नही रहते। सदस्यों के वारम्बार निवाहन हो जाने के कारण उन्हें लम्बे समय तक राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसी कारण उचित निष्पक्ष और कृत्य परायणता आदि क विशिष्ट गुण उनमें पाये जाते हैं। सघीय सभा सघीय परिषद् में शासन सम्बन्धी सभी विषयों में विचार विमर्श करती है और प्रायः उसके परामर्श की अवहेलना करने का साहस भी नहीं करती। जनता को भी यह पूरा विश्वास रहता है कि सघीय परिषद् निरन्तर जनकल्याण में निमग्न है और स्वायत्तता तथा दलबन्दी के प्रभाव से ऊपर है। स्विट्जरलैण्ड में ऐसे उदाहरण हैं कि सघीय परिषद् के सदस्य 25 से 30 वर्ष तक पदासीन रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे सदस्य अपने विषयों के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इमीलिए लावेल ने कहा है कि "स्विट्जरलैण्ड में परिषद् के सदस्य अपने-अपने विभागों के राजनीतिक अध्ययन और प्रमुख उपसचिव दोनों होते हैं।"

यद्यपि स्विस कायकारिणी अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही अनुभवी और प्रशसनीय है तथापि उसमें कुछ दोष भी हैं। कायकारिणी के सदस्य न किसी एक नेता के प्रति बफादार होते हैं और न उनमें पारस्परिक एकता की भावना ही होती है। प्रायः ऐसा भी होता है कि कायकारिणी के सदस्य शासन की बागडोर अपनी अपनी ओर खींचते हैं और शासन नीति में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। ब्रिटन जैसी मन्त्रीमण्डलीय व्यवस्था स्विट्जरलैण्ड में विकसित नहीं हो पाती।

सघीय परिषद् का सघीय सभा से सम्बन्ध

(Relation of the Federal Council with the Federal Assembly)

स्विट्जरलैण्ड में सघीय कायकारिणी का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध जय दशा की अपेक्षा नितान्त भिन्न है। न तो स्विस कायपालिका अमेरिका की तरह व्यवस्थापिका से पूर्णतया स्वतंत्र ही है और न ब्रिटन की तरह उसका अंग ही है। स्विट्जरलैण्ड में दोनों ही देशों के संविधानों की अच्छी बातों का ग्रहण किया गया है।

स्विस कायपालिका के सदस्यों का धुं व वहाँ की व्यवस्थापिका

प्रायः व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। किन्तु व्यवस्थापिका में चुन जाने के बाद उन्हें व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देना होता है। कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका द्वारा चुने तो जाते हैं तथापि वे उसके द्वारा हटाये नहीं जा सकते। पदव्युत्ति के सम्बन्ध में उन्हें व्यवस्थापिका से कोई भय नहीं रहता। कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य न होने पर भी व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में भाग लेते हैं, उनमें विधेयक प्रस्तुत करते हैं, विधेयकों को वहाँ से पारित भी करवाते हैं और अपनी योग्यता एवं अनुभव के कारण व्यवस्थापन मंत्रालय में व्यवस्थापिका का पर्याप्त पथ प्रदर्शन करते हैं। साथ ही व्यवस्थापिका को यह अधिकार है कि वह कायपालिका के कार्य की आलोचना कर सकती है, उन पर वाद विवाद कर सकती है, मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और यदि आवश्यक समझे तो उनके किसी भी कार्य या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकती है। कायपालिका अपने कार्यों के लिए संघीय सभा के सामने जवाबदेय है। यह आवश्यक है कि वह अपने उन सब कार्यों का विवरण साधारणतः व्यवस्थापिका को दे जिनका विवरण वह चाहें और उन सब प्रश्नों का उचित उत्तर दे जा व्यवस्थापिका द्वारा उससे पूछ जावें। परन्तु यदि व्यवस्थापिका कायपालिका के कार्यों से असहमति प्रकट करे या कायपालिका की आलोचना करे अथवा उसके किसी भी कार्य को, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अस्वीकृत कर दे, तो कायपालिका का त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए बाध्यता नहीं है कि वह व्यवस्थापिका की आलोचना से लाभ उठाकर अपने कार्य और अपनी नीति में सुधार करे तथा व्यवस्थापिका द्वारा किए गए "असम्मान को अपनी जेब में रख ले और व्यवस्थापिका की इच्छा शक्ति के सम्मुख झुक जाए।"

प्रश्न यह उठता है कि उत्तरदायित्व की ऐसी निराली व्यवस्था स्विटजरलैंड में क्यों रखी गई है। डायसी (Dicey) के अनुसार इसका 'मूल कारण' स्विस लोगो का प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रति अगाध प्रेम है। स्विस लोग एक ऐसी व्यवस्था के पक्षपाती हैं जिसमें लोकतन्त्रात्मक मायताओं की अधिकाधिक व्यवहार में लाया जाय और प्रशासकीय शक्ति का वास्तविक प्रयोग अधिकाधिक जनता के हाथ लग। इसी कारण उन्होंने अनेक बातों के निश्चय के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था रखी है और मन्त्रीमण्डलीय उत्तरदायित्व की भी ऐसी व्यवस्था रखी है कि जिसमें मन्त्रिपरिषद् अर्थात् स्विस कायपालिका जनता की प्रतिनिधि संघीय सभा के विधेयों को कार्यान्वित करने का यत्न करती रहे, मन्त्रीमण्डल की भाँति मन्त्रिपरिषद् न बन जाय। डायसी ने मतानुसार स्विस कायपालिका के निराल उत्तरदायित्व का दूसरा कारण स्विस लोगो का यह विश्वास है कि परिषद् के सदस्य उनसे भिन्न मत के होत हुए भी, यदि उनके विधेयों को उचित रूप से कार्यान्वित करते रहते हैं तो उनके मत की भिन्नता का, व्यवस्थापिका का अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए और मतभेदों के होते हुए भी व्यवस्थापिका का परिषद् का काम करने रहना चाहिए। डायसी की मायता

है कि स्विस लोग राजनीति को एक व्यवसाय मानते हैं, अतः उन्हें केवल इस बात की परवाह रहती है कि उन व्यवसाय को पालनेवाले परिपद् के सदस्य काय कुशल बने रहें। यदि वे कायकुशल हैं तो व्यवस्थापिका के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि उनमें मत व्यवस्थापिका की इच्छा से कितने भिन्न हैं? ब्राइस (Bryce) का विचार यह है कि "स्विस जनता की दृष्टि से मतों की भिन्नता न केवल स्वाभाविक है बल्कि आवश्यक है। उनका विश्वास है कि भिन्न भिन्न मतों के मथन के परिणामस्वरूप जो निर्णय लिया जाता है उसका स्वरूप अधिक विवेकपूर्ण तथा लोकतन्त्रात्मक होता है।" अतः यदि सघीय परिपद् और सघीय सभा में मत-भेद विद्यमान हैं तो दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के प्रति दृष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें तो इसी भावना से काय करना चाहिए कि उन सबका श्रेष्ठ राष्ट्रीय हित है।

यह निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा कि सघीय परिपद् की स्थिति महत्वहीन है और वह सघीय सभा की सेविका है। नाविधानिक दृष्टि से भले ही सघीय परिपद् शासन का एक स्वतन्त्र अथवा सहयोगी अंग न होकर सघीय सभा की सेविका है परन्तु वास्तविक स्थिति ठीक इसके विपरीत है। वर्तमान में लगभग सभी देशों में व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास हो रहा है और कार्यपालिका के अधिकारों में विकास। यह प्रवृत्ति 'स्विट्जरलैण्ड' में भी प्रभावी है। परिपद् के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रभावशाली नेता होते हैं और वे वास्तविक रूप से व्यवस्थापिका में जनमत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे स्याई रूप से वषा तक पदासीन रहने के कारण अनुभवी, पानी जीर कुशल प्रशासनिक होते हैं। अतः व्यवहार में सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थापिका काय उही के नियंत्रण और मार्ग-दर्शन में चलता है। आज अथ देशों की भाँति, स्विट्जरलैण्ड में भी विधायी एवं वित्तीय उपक्रम सघीय परिपद् के हाथ में चला गया है। सघीय परिपद् सघीय सभा का "विधायी प्रारूप बनाने वाली प्रतिष्ठित विभाग" (Glorified Legislative Drafting Bureau) हो गई है। परिपद् पर सघीय सभा का नियंत्रण शिथिल पड़ता जा रहा है। व्यवहार में परिपद् अपनी इच्छानुसार विधेयक पारित करवा लेती है। प्रशासन का संचालन वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती है। संसदकाल में तो उसकी शक्ति प्रायः असीमित हो जाती है। सघीय परिपद् की इसी प्रभावपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करते हुए द्रुपूज ने कहा है कि जो आज सघीय परिपद् सघीय सभा की कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) न होकर राष्ट्र की कार्यपालिका (National Executive) है। ब्राइस ने ठीक ही कहा है कि "वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेवक होते हुए भी व्यवहार में सघीय परिपद् ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के बराबर एवं फ्रेंच मंत्रिमण्डल से अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। वह पथ प्रदर्शक भी है और साधन भी। बहुधा वह सुझाव भी देती है और मसविदा भी तैयार करती है।"

स्विस सघीय कार्यपालिका का ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल और अमेरिकन कार्यपालिका से तुलना

(The Swiss Federal Executive Compared with the
British Cabinet and American Executive)

स्विस कार्यपालिका के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह न तो पूर्णतया ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के ही अनुसार है और न अमेरिकन अध्यक्षीय प्रणाली से मेल खाती है। उगम इन दोनों प्रणालियों से मौलिक असमानताएँ विद्यमान हैं, पर साथ ही समानताएँ भी पाई जाती हैं।

संगठन सम्बन्धी तुलना

स्विस कार्यपालिका ब्रिटिश एवं अमेरिकन मन्त्रिमण्डल से अत्यन्त छोटी है और इसके सदस्यों की संख्या भी निश्चित है। ब्रिटिश में प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की मर्यादा का निवारण करता है और अमेरिका में राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में हेरफेर कर सकता है जबकि स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका के अध्यक्ष को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। स्विट्जरलैण्ड और ब्रिटेन दोनों देशों में कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्यों में से ही लिये जाते हैं तथापि जहाँ ब्रिटेन में सामान्यतः एक ही दल के सदस्य चुने जाते हैं वहाँ स्विट्जरलैण्ड में वे विभिन्न दलों के होते हैं। अमेरिका में यह आवश्यक नहीं है कि मन्त्रिमण्डल कांग्रेस में से ही लिए जाए।

कार्यकाल सम्बन्धी तुलना

स्विस कार्यपालिका की अवधि चार वर्ष के लिए निश्चित होती है क्योंकि पदच्युति के सम्बन्ध में वह व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी है। इसके विपरीत ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल संसद के विश्वास पर मूलतः रहता है। अमेरिकन कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, किन्तु मन्त्रिमण्डल पूर्णरूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

उत्तरदायित्व सम्बन्धी तुलना

स्विस कार्यपालिका ने ब्रिटिश शासन पद्धति के उत्तरदायित्व को तो ग्रहण किया है परन्तु पदत्याग के अर्थ में उसको नहीं किया है। ब्रिटिश संसद की नाति ही स्विस व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका पर प्रश्नो, प्रतिप्रश्नो, प्रस्तावो, निषेधो और अन्य आदेशों द्वारा नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका सभाओं में उपस्थित होते हैं, वाद-विवादों में भाग लेते हैं, विधायक प्रस्तुत करते हैं और पुनः उन्हें पारित कराने का उत्तरदायित्व भी वहन करते हैं। लेकिन ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के समान स्विस मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका द्वारा अधिवेशन प्रस्ताव के अधिकार नहीं रखते। जहाँ ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल लोकमता के विरुद्ध प्रस्ताव पेश कर सकता है वहाँ स्विस कार्यपालिका के सदस्यों का

व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर हार हो जाये पर पदत्याग नहीं करना पड़ता।
स्विस कार्यपालिका व्यवस्थापिका की इच्छा को सहज स्वीकार कर लेती है।
अमेरिकन कार्यपालिका भी कांग्रेस के प्रति अनुत्तरदायी होती है। यह अंतर
जबदप है कि स्विस कार्यपालिका के सदस्यों की भाँति अमेरिका में मंत्री अथवा
सचिव व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं होते और उसकी किसी कार्यवाही में प्रत्यक्ष
रूप से कोई भाग नहीं लेते।

कार्यपालिका के अध्यक्ष-पद की तुलना

स्विस कार्यपालिका के प्रधान की स्थिति 'बराबर वालो में एक' की है
जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'समकक्षा में प्रथम' होता है और अमेरिकन राष्ट्रपति
अपने मंत्रिमण्डल का 'स्वामी'। स्विस कार्यपालिका का अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री
के समान अपने मंत्रियों का चुनाव नहीं करता और न ही विधायकमण्डल का नेतृत्व
करता है। इसी प्रकार की गौण स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति की तुलना में है।
अमेरिकन राष्ट्रपति कार्यपालिका-अग्निकार का प्रभु होता है। मंत्रियों का
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति माँगा जाता है। स्विट्जरलैण्ड में
कार्यपालिका के अध्यक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। एक बड़ा अंतर यह है कि
अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति द्वारा किया
जाता है जबकि स्विस कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा होता है।
वह व्यवस्थापिका ही नहीं बरकरा कार्यपालिका के अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन भी
मधीय व्यवस्थापिका ही करती है। ब्रिटन में मन्त्रिमण्डल या सांझाणी द्वारा लोकमना
का बहुमत के तहत का प्रधानमंत्री पद का शिष्ट आमंत्रित करना होता है और
उनके द्वारा वसलायत गये अन्य व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना पड़ता है। यदि
कोई मंत्री सदस्य का सदस्य न होता छमाह के भीतर निर्वाचन लड़कर उसे
सदस्य बनना पड़ता है अथवा मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है।

दलीय सदस्यों का अंतर

स्विस कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होता।
उनमें सभी दलों के सदस्य होते हैं। वह दलीय भावना ने प्रायः ऊपर उठी हुई होती
है और बहुमत की आवाज की ही नहीं बरकरा राष्ट्र और देश की सर्वोत्तम चेष्टा होती
है, किंतु अमेरिका और ब्रिटन दोनों ही में कार्यपालिका के सदस्यों का निर्वाचन प्रायः
पूर्णतः दलीय आधार पर होता है। वे अपने पदों पर रहते हुए भी अपने दल के
पक्ष में कार्य करते हैं।

कार्यपालिका के विभागों की वितरण सम्बन्धी तुलना

स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका के सात विभाग होते हैं जो सातों सदस्यों में
विभाजित कर दिए जाते हैं। विभागों का वितरण औपचारिक रूप से परिपक्व द्वारा
किया जाता है और यह परम्परा है कि जो सदस्य दुबारा निर्वाचित होते हैं उन्हें
प्रायः पहले वाला विभाग ही सौंप दिया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका

सदस्य अधिकांशतः अपने-अपने विभाग के विशेषज्ञ बन जाते हैं और वे लोक सेवा के अधिकारियों के हाथ की बँठपुतली नहीं बन रहते ।

परन्तु ब्रिटेन और अमेरिका में कार्यपालिका के विभागों का वितरण प्रायः व्यक्ति की योग्यताएँ एवं वायकुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक महत्व के आधार पर होता है । दूसरा अंतर यह भी है कि दोनों देशों में विभागों के वितरण में शासन प्रमुख की इच्छा का ही प्रायः प्रधानता मिलती है । स्विटजरलैंड में अन्तर को इस सम्बन्ध में किसी तरह की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है ।

स्पष्ट है कि स्विटजरलैंड की संघीय कार्यपालिका अर्थात् फ़ेडरल कौंसिल में तो ब्रिटेन की और न अमेरिका संघ की कार्यपालिका के समान है । वह वास्तव में दोनों व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है और उसमें दोनों व्यवस्थाओं के गुण और लक्षण निहित हैं । फिर भी वह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के अधिक निकट है ।

कैन्टनों की कार्यपालिका

(The Executive of Cantons)

संघीय कार्यपालिका के समान प्रत्येक कैन्टन में एक सामूहिक या बहुसंख्य कार्यपालिका (Collegial Executive) होती है । इस कार्यपालिका को राज्य परिषद (Council of State) या लघु परिषद (Small Council) कहते हैं । जिसमें प्रायः 5 से लेकर 11 सदस्य होते हैं । ये सभी सदस्य कैंटन के विधान मंडल द्वारा एक से लेकर पाँच वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं । मध्य की भाँति कैन्टनों में भी पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की प्रचलित है । संघीय परिषद (Federal Council) की भाँति ही कैन्टन की कार्यपालिका के भी सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है । कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य शासन के विभाग का एक अध्यक्ष होता है । कार्यपालिका कैंटन के विधान मंडल के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होती है । संघीय परिषद की भाँति उसे अधिकांश कानूनों का प्रारूप तैयार करना पड़ता है, वह उन्हें प्रस्तावित करती है और व्यवस्थापिका का अनुमोदन करने के साथ-साथ उसका पथ-प्रदर्शन भी करती है ।

5

स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका [THE SWISS JUDICIARY]

“समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग जनता की इच्छा के पालन अर्थात् लोकतन्त्र को संविधान की इच्छा के पालन अर्थात् विधान तन्त्र से ऊँचा समझते हैं।”

—हन्स ह्यूबेर

स्विट्जरलैंड की संघीय न्याय-प्रणाली में एकमात्र न्यायालय “संघीय न्यायालय” (Federal Tribunal) है, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। गणराज्य अमेरिका की भाँति स्विट्जरलैंड में संघीय घरातल पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिरिक्त निम्न न्यायालय (Subordinate Courts) नहीं हैं। हाँ, संघीय न्यायपालिका के संगठन में उन अनेक निम्न न्यायालयों का किया जा गया है जो केन्द्रीय न्यायपालिकाओं के सम हैं, क्योंकि वहाँ भी न्याय में उदात्तता है और किन्हीं न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है, उन्हीं केन्द्रीय न्यायालय ही संघीय कानूनों को कार्यान्वित करते हैं।

संघीय न्यायालय (Federal Tribunal) अथवा बुन्दसजेरिख्त (Bundesgericht) की स्थापना इन 1848 के संविधान द्वारा हुई थी और उन्हीं से अत्यन्त सीमित अधिकार प्रदान किए गए। बाद में संविधान में कुछ संशोधनों के द्वारा इसकी शक्ति में भी वृद्धि हो गई।

संघीय न्यायन के क्षेत्र प्रदान कीर्मान्य जर्मन-भाषी केन्द्रीय न्यायालय के क्षेत्र में है, किन्तु सर्वत्र न्यायालय अधिकार स्थायी रूप से अल्प-संख्यक भाषी भाषी केन्द्रीय न्यायालय (Lausanne) न्याय की अधिकता के कारण इनकी बंटक निरन्तर चल रही है।

की 'यायिक व्यवस्था का अध्ययन संविधान के विद्वानों के लिए विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि उसका वहाँ कोई ऐसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जमा कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का है।

संघीय न्यायालय (Federal Tribunal)

संगठन

संघीय न्यायालय के संगठन में संविधान कोई मिश्रण नहीं करता है। यह अधिकार संघीय सभा (Federal Assembly) को सौंप दिया गया है जो अपने दोनो सदन के संयुक्त अधिवेशन में न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। संविधान द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप यह संख्या निरंतर परिवर्तनशील रही है। 1943 में एक कानून द्वारा उनकी संख्या 9 से बढ़ाकर 26-28 कर दी गयी तथा उप-न्यायाधीशों की संख्या 11-13 की गयी। उप-न्यायाधीश न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में उनके पद पर कार्य करते हैं। संघीय सभा सच-न्यायालय के न्यायाधीशों में से ही एक अध्यक्ष (President), एक उपाध्यक्ष (Vice President) का दो वर्षों के लिए निर्वाचन करती है। न्यायाधीशों का चुनाव इस भाँति होता है कि वे तीनो राष्ट्र भाषाओं (फ्रेंच, जर्मन एवं इटालियन) का प्रतिनिधित्व कर सकें। यह न्यायाधीश 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के कारण इनका कार्यकाल स्थायी माना ही हो गया है।

न्यायाधीशों का संघीय सभा अथवा संघीय परिषद की मदद से निर्णय कर दिया जाता है। कोई भी स्वयं नागरिक या राष्ट्रीय परिषद (National Council) की सदस्यता की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था है कि अपने कार्यकाल में न्यायाधीश मध्य अथवा कठिन के अलग-अलग किसी पद पर नहीं रह सकते हैं और न कोई व्यवसाय या नौकरी ही कर सकते हैं। परन्तु उप-न्यायाधीशों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता क्योंकि उन्हें कोई वाणिज्य वेतन नहीं दिया जाता, केवल जिन दिनों वे कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से कुछ भत्ता दिया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन के रूप में 45150 फ्रैंक प्रतिवर्ष मिलता है। इनके अतिरिक्त 3150 फ्रैंक भत्ता के रूप में प्रतिवर्ष दिया जाता है। न्यायाधीशों को पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है।

संघीय न्यायालय का अपना सचिवालय (Chancellery) है जिसमें संगठन और कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का भार उसी पर है।

कार्य प्रणाली

न्यायालय की अंतरंग कार्य प्रणाली निश्चित करना, विविध विभागों का वास्तविक समय करना और कार्य करने के लिए नियम आदि का निर्माण करना

लिए पूरे सघीय न्यायालय की बैठक हाती है। इसके अतिरिक्त उन मामलों की सुनवाई भी पूरे सघीय न्यायालय द्वारा होती है जिनके विषय में सघ के किसी कानून अथवा न्यायालय के किसी नियम के अनुसार ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है।

काय की सुविधा की दृष्टि से स्विस् न्यायालय का चार भागों में बांट दिया गया है। इनमें दो विभाग दीवानी मुकदमों पर विचार करते हैं, तीसरा विभाग सावजनिक विधि सम्बन्धी विवादों पर विचार करता है और चौथा विभाग नृप तथा दिवालिया से सम्बन्धित मुकदमों पर विचार करता है। इन सभी विभागों का मगठन पूरा न्याय्य दोष के लिए करता है।

फौजदारी मुकदमों पर भी विचार करने के लिए सघीय न्यायालय के चार विभाग किए गए हैं—1 फरियाद विभाग (Chamber of Complaints), 2 फौजदारी विभाग (Criminal Chamber), 3 सघीय दंड विभाग (Federal Penal Court) एक, 4 सवधानिक विभाग (Court of Cessation)। फौजदारी विभाग वही कभी भ्रमणशील न्यायालय के रूप में काय करता है। फौजदारी अभियोगों पर विचार करते समय ज्यूरियों की सहायता ली जाती है।

न्यायालय के काय सम्मेलन के नियम अधिक नहीं हैं और वे बहुत कठोर भी नहीं हैं। उनका सम्मेलन न्यायाधीशों की गणपूर्ति (Quorum), न्यायालय की सावजनिक अथवा गुप्त बैठकों आदि से है। न्यायालय का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी प्रकार के पक्षपात का दावा सिद्ध हो जावे तो वह न्यायाधीश के पद के लिए अयोग्य हो जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति स्विस् सघीय न्यायालय के पास अपने नियमों का लागू करने के लिए अपने कमचारों नहीं होते। इसके लिए सघीय न्यायालय बेटनों पर निर्भर रहते हैं और यदि कोई बेटन कृतव्यन्यायन से विमुक्त हो तो सघीय परिषद् (Federal Council) से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

अधिकार क्षेत्र

अमेरिका और आस्ट्रालिया की भांति स्विस् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की मरिधान में व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि स्विस् विधान मण्डल को इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार है। फिर भी इसका क्षेत्राधिकार पर्याप्त विस्तृत है और उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (1) दीवानी (Civil)
- (2) फौजदारी (Criminal)
- (3) सवधानिक (Constitutional)
- (4) प्रशासकीय (Administrative)

(1) दीवानी क्षेत्राधिकार—दीवानी मामले में मधीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारम्भिक (Original) और अपीलीय (Appellate) दोनों प्रकार का है। प्रारम्भिक (Original) के रूप में संविधान की धारा 110 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के दीवानी मामले न्यायालय के समक्ष निणय के लिए लाये जा सकते हैं —

(1) सघ तथा कंटनों के मध्य उत्पन्न विवाद।

(2) सघ और किसी निगम (Corporation), कम्पनी अथवा साधारण नागरिकों के मध्य उत्पन्न विवाद। इसमें यह आवश्यक है कि वादी (Plaintiff) नागरिक अथवा निगम हो, सघ नहीं, और विवादग्रस्त राशि चार हजार फ्रक से कम न हो।

(3) विभिन्न कंटनों के बीच पारस्परिक विवाद।

(4) किसी एक कंटन तथा साधारण नागरिक अथवा निगम के बीच उत्पन्न विवाद, वशर्ते कि विवादग्रस्त राशि चार हजार फ्रक से कम न हो।

(5) विभिन्न कंटनों में कम्पनियों के बीच नागरिकता तथा अबिवास (Domicile) सम्बन्धी विवाद।

(6) यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक (Original) रूप में बहुत कम दीवानी मामले मधीय न्यायालय के समक्ष निणय हेतु लाये जाते हैं। उदाहरणार्थ सन् 1950 में ही मामलों की कुल संख्या केवल 10 थी। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश दीवानी मामले का निवटारा कंटनों के न्यायालय में ही हो जाता है।

मधीय न्यायालय के समक्ष दीवानी अपीलीय (Appellate) क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित प्रकार के मामले आते हैं —

(क) 10 000 फ्रक या उससे अधिक धन राशि के मुकदमों की अपील इसमें की जा सकती है परन्तु इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

(ख) कंटनों के न्यायालयों के निणयों के विरुद्ध भी यह अपील सुनने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के मुकदमों की अपील निणय के सुनान के बाद 30 दिन के अन्दर करदी जानी चाहिए।

(2) फौजदारी क्षेत्राधिकार

संविधान की धारा 112 के अनुसार मधीय न्यायालय को निम्न प्रकार के फौजदारी मामलों में निणय करने का अधिकार है—

(1) सघ के विरुद्ध राजद्रोह (High Treason) तथा मधीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह अथवा हिंसा के मामले।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध एवं दुराचार के मामले।

(3) राजनीतिक अपराध अथवा दुराचार के ऐसे मामले जिनके कारण मधीय सैनिक हस्तगत की आवश्यकता पड़ी हो।

(4) उच्च सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये फौजदारी आरोप।

(3) सवैधानिक क्षेत्राधिकार

सघीय न्यायालय को निम्न प्रकार के सवैधानिक मामलों के निर्णय का अधिकार है—

(1) सघीय और कैंटनों के प्राधिकारियों के पारस्परिक सक्षमता सम्बन्धी विवाद ।

(2) सघ एंव कैंटनों के मध्य उत्पन्न सवैधानिक विवाद ।

(3) कैंटनों के मध्य पारस्परिक सावजनिक कानून सम्बन्धी विवाद ।

(4) संविधान में सम्मिलित नागरिक अधिकारों के अतिक्रमण या संधि और समझौता की शर्तों की अतिक्रमण सम्बन्धी नागरिकों की शिकायतें—पर सघीय न्यायालय अभीला को तब तक नहीं सुनता जब तक सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कैंटनों के न्यायालयों द्वारा न की जा चुकी हो । व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा उस दशा में करता है जब उनका उल्लंघन कैंटनों की सरकारों द्वारा किया जाव । सघीय सरकार के कार्यों का पुनरावलोकन (Review) वह नहीं कर सकता और उसके कार्य की वैधानिकता व अवैधानिकता का विषय में वह कोई निर्णय नहीं दे सकता ।

(5) कैंटनों के कानूनों का अवैधानिक घोषित करने का अधिकार—सघीय न्यायालय का याचिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में उसका अधिकार कैंटनों के कानूनों तक ही सीमित है । सघीय कानूनों की व्याख्या अवश्य वह कर सकता है लेकिन उनकी वैधानिकता अथवा अवैधानिकता का श्रेष्ठ निर्णय देने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है ।

(4) प्रशासनिक क्षेत्राधिकार

स्विस सघीय न्यायालय प्रशासनिक अभियोगों, सरकारी कर्मचारियों के वैधानिक क्षमता सम्बन्धी विवादों, रेल प्रशासन सम्बन्धी विवादों, करारोपण सम्बन्धी प्रशासनिक मामलों आदि पर विचार करता है ।

अतः, स्विस न्यायालय के अधिकारों का स्पष्ट चित्र केवल सवैधानिक उपबंधों से ही नहीं मिल सकता । संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त सघीय कानूनों द्वारा भी न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि की जा सकती है । सघीय सभा की स्वीकृति से कैंटनों के विधान मण्डल भी कुछ दीवानी मामले सघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रख सकते हैं । न्यायालय के मन्त्र प्रस्तुत होने वाले लगभग 95 प्रतिशत मामले इन वृद्धिगत अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत ही आते हैं ।

कैंटनों की न्यायपालिका

(Judiciary of the Cantons)

सघीय कानूनों के क्रिया वयन का दायित्व कैंटनों के न्यायाधीशों पर ही है, अतः वे भी इस दृष्टि से सघीय न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं । दीवानी, फौजदारी और व्यापार सम्बन्धी कानूनों का एकीकरण हो जाने के बाद ही लगभग

सभी कैंटना के 'यायालय एव-से ही कानूना के अनुसार 'याय-कार्य करत हैं, फिर भी यायालयों के बाये जादि की व्यवस्था करना कैंटना के अधिकार क्षेत्र की बात है। इसीलिए विविध कैंटना के 'यायालय के ढांचो में व 'याय-निर्णय में विभिन्नता पायी जाती है।

उच्च 'यायालय (Superior Cantonal Courts)

प्रायः प्रत्येक कैंटना में 'याय प्रशासन के लिए एक उच्च 'यायालय (Superior Cantonal Court) होता है जिसमें 7 से 13 'यायाधीन होते हैं। इसका निर्वाचन कैंटना की विधान सभा द्वारा होता है। उच्च 'यायालय का दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुद्दमों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, परन्तु उसे कानूना की नवधानिकता पर विचार करने का अधिकार नहीं है। उच्च 'यायालय के अधीन कुछ दीवानी और फौजदारी यायालय हैं जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

(क) दीवानी 'यायालय—दीवानी क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक कैंटना के उच्च 'यायालय के अधीन नवशा प्रादेशिक यायालय (District Court) व 'गाति यायाधीशों (Justices of Peace) के 'यायालय हैं। प्रादेशिक अथवा जिला 'यायालय (District Courts) का 'याय क्षेत्र एक जिला या ज़रण्डाइनमेन्ट होते हैं, जबकि सबसे नीचे के स्तर के 'गाति यायाधीश (Justice of Peace) के 'यायालय का 'याय क्षेत्र प्रायः कानून होता है।

निम्न-स्तर के 'यायालय से ऊपर के स्तर के 'यायालय का 'याय क्षेत्र वादों के मुख्य व अनुसार बढ़ता जाता है। इसमें अतिरिक्त निम्न 'यायालय के निणयो के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी ऊपर के 'यायालय करत है।

(ख) फौजदारी 'यायालय—फौजदारी क्षेत्र में सबसे नीचे के स्तर का 'यायालय पुलिस 'यायालय (Police Tribunal) होता है। कहीं-कहीं 'याय 'गाति 'यायाधीश व 'यायालय भी फौजदारी के सबसे नीचे के स्तर के 'यायालय का कार्य करते हैं। फौजदारी में भी जिला 'यायालय (District Court) होता है। सबसे उच्च-स्तर का 'यायालय ऊपर वर्णित उच्च 'यायालय (Superior Cantonal Court) होता है।

नीचे के स्तर के 'यायालय से ऊपर के स्तर के 'यायालय का 'याय क्षेत्र अपराध की गम्भीरता तथा दण्ड की मात्रा की अविकला के आधार पर बढ़ता जाता है। कैंटनों के उच्चतम 'यायालय (Superior Cantonal Courts) के निणयो के विरुद्ध मघीय 'यायालय (Federal Tribunal) को अपील की जाती है।

कैंटनों में 'यायाधीश स्पष्टतः निर्वाचित होते हैं। उनका निर्वाचन या तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा कैंटना की व्यवस्थापिकाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 'यायाधीशों की सेवा की शर्तों जादि का निर्धारण कैंटना द्वारा ही किया जाता है। यह व्यवस्था है कि 'यायाधीश पुनर्निर्वाचित किये जा सकते हैं।

6

स्विट्जरलैण्ड के राजनीतिक दल (POLITICAL PARTIES OF SWITZERLAND)

“स्विट्जरलैंड के दलों की विचारधारा एवम उनके सामाजिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं हैं।”

—कोडिगन

आधुनिक युग में राजनीतिक दल लोकतन्त्र की धुरी हैं। यद्यपि किसी भी लोकतान्त्रिक देश के संविधान में राजनीतिक दलों की मना की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है तथापि लोकतन्त्र का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में होना असम्भव सा है। स्विट्जरलैंड विश्व का प्राचीनतम और अग्रणी लोकतान्त्रिक राज्य है जहाँ राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप एक स्वाभाविक बात है। किन्तु आश्चर्य यह है कि वहाँ राजनीतिक दलों का इतना महत्त्व नहीं है जितना कि अन्य लोकतान्त्रिक देशों में पाया जाता है। मतदान के समय किसी दल की हार या जीत को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता। जहाँ देशों के समान संगठित दलों की भी कमी है। प्रजातान्त्रिक राज्यों में दलीय व्यवस्था के जो गम्भीर दोष दिखाई देने हैं वे स्विट्जरलैंड में नगण्य हैं। स्विस राज्य ऋषी जहाँज दलबन्दी की राहों द्वारा कभी डगमगाया नहीं है। वहाँ अन्य देशों की तुलना में दलीय संघर्ष बहुत कम पेचीदा और दलीय भावना बहुत ही कम है। स्विट्जरलैंड की यह विशेषता कुछ तो वहाँ के संविधान के कारण और कुछ स्विस नागरिकों के चरित्र के कारण है।

दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण

(Causes of Weak Party System)

1 स्विस कार्यकारिणी का स्थायीपन स्विस दलबन्दी की दुर्बलता और अस्थिरता का प्रमुख कारण है। अपने कार्यकाल में फेडरल कोन्सिल के सदस्य हटाये नहीं जा सकते, अतः वे दलों की चक्कर में नहीं पड़ते। साथ ही कार्यकारिणी को हटाने के लिए जनता में भी दलबन्दी की भावनाएँ उत्पन्न नहीं होती।

2 कार्यकारिणी अथवा फडरल कांसिल (संघीय परिषद) का निर्माण भी दलीय आधार पर नहीं होता और उससे दल का कार्य करने की आशा नहीं की जाती।

3 संघीय परिषद के सदस्य प्रायः पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। अतः वहाँ दलबंदी का सवाल ही पड़ा नहीं होता, क्योंकि दलबंदी तो वही ज़ोर पकड़ती है जहाँ सत्ता का हथियाने के लिये हाथ व दौड़ लगती है।

4 दलबंदी सदैव भ्रष्टाचार प्रणाली (Spoil System) से जोर पकड़ती है, क्योंकि इसके द्वारा शक्ति प्राप्त करने पर शासक दल के लोगों को पदा पर नर दिया जाता है। सोभाग्यवश स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली नहीं है। प्रथम तो वहाँ पर नियुक्तियाँ ही योग्यता के आधार पर की जाती हैं और द्वितीय पक्षों की समस्या भी इतनी अधिक नहीं होती कि कोई दल अपने समर्थकों को भर सके।

5 स्विट्जरलैंड में पक्षों के वेतन भी इतने नहीं हैं कि वे महत्वाकांक्षी मनुष्यों को आकर्षित कर सकें।

6 स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय सभा की विधायी शक्तियाँ सीमित हैं और इस सीमित क्षेत्र में भी उसकी शक्ति अंतिम नहीं है वहाँ अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। लोक-निर्णय, निवर्धन-उपक्रम तथा प्रत्याहरणता (Referendum, Initiative and Recall)—जनतन्त्र के इन तीन अस्त्रों की प्रधानता के कारण दलबंदी को स्विट्जरलैंड में अधिक स्थान नहीं मिल पाया है। इनके कारण वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र प्रचलित है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लोक निर्णय द्वारा तय किये जाते हैं। फलतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि कोई दल अपने किसी स्वायत्त-विशेष को लेकर दलीय चक्कर चलावे।

7 स्विट्जरलैंड में अधानिक एवम् विदेशी मामलों में कोई मतभेद नहीं होता, अतः दलगत तीव्रता पड़ा होने की गुंजायमान नहीं रहती।

8 स्थान व्यवस्थापिका का अधिवेशन बहुत थोड़े दिनों तक चलता है। वह प्रायः एक महिना से अधिक नहीं चलता। इस अल्प अवधि में व्यवस्थापिका के सदस्य अपने कार्यों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको दलबंदी के भय से फसने का अवकाश ही नहीं मिलता।

9 स्थान नागरिकाओं में आर्थिक विषमता बहुत कम है। न धनी अधिक धनी हैं और न गरीब अधिक गरीब। इस निश्चितता के वातावरण में लोग दलबंदी के चक्करों में फँस कर अपना शक्ति भंग करने को उत्सुक नहीं रहते हैं।

10 स्थान जनता का बहुत सरल एवम् दानवत चरित्र राष्ट्रीय स्तर को घेरकर विरोध में पुरस्कृत करता है। देश की नीतिगत स्थिति या जनता को पारस्परिक मतभेद का मुद्दा एवम् भली प्रकार समझित रहने की प्रेरणा देता है। उनके चुनाव के समय अत्यंत घर्षण एवम् गति में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड द्वारा तरफ से चार विशाल सैनिक अभियानों द्वारा घिरा हुआ है। अतः उनके सतरे

से दूर रहने के लिए स्विस नागरिक दलवादी के धक्कर में पड़ कर अपने दिलों में अंतर नहीं आने देते । वे नहीं चाहते कि उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाए ।

लाइब्राइम ने स्विट्जरलैंड में दलवादी के अस्तित्व होने के अनेक कारण बतलाए हैं । उनके कथनानुसार "देश के सामने बहुत समय तक कोई बड़ी बड़ी समस्याएँ न हान, आर्थिक व्यवस्था के प्रति संतुष्ट रहना, तथा प्राचीन धार्मिक मतभेद और वर्ग भेद के प्रति धना होने के कारण वहाँ पर प्रबल दलवादी नहीं पाई है । वहाँ पर व्यक्तिगत आकांक्षाओं तथा नेतृत्व ग्रहण करने की लालनाओं का अभाव है । वहाँ पर सांघजनिक जीवन में व्यक्तित्वों के लिए बहुत कम आकांक्षा है । बड़ी बड़ी समस्याएँ सीधी जनता द्वारा तय कर ली जाती हैं । इन्हीं सब कारणों से दलवादी जो अन्य जनतन्त्रीय देशों में विशाल-धारा का रूप धारण कर लेती है, स्विट्जरलैंड में एक छोटी सी तरह ही पदा कर पाती है । '

दल प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास

(Brief History of the Swiss Party System)

यों तो बहुत पहले ही स्विस राजनीति में विभाजन उत्पन्न हो गये थे, किंतु सन् 1848 में संविधान के निर्माण के समय तक दलीय स्थिति स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो चुकी थी । उस समय तीन दलों की नींव पड़ चुकी थी—(i) उदारवादी दल (Liberal Party), (ii) क्रांतिकारी या उग्रवादी दल (Radical Party), तथा (iii) कथोलिक अनुदार दल (Catholic Conservative Party) । ये तीनों दल आज भी विद्यमान हैं ।

उदार दल का निर्माण बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और किसानों ने मिल कर किया था । ये लोग सन् 1815 के समझौते (The Pact of 1815) द्वारा स्थापित सामंतिक व्यवस्था के विरोध में थे । सन् 1830 के उदार दल के विद्रोह प्रयासों के फलस्वरूप ही अधिकांश कटना में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सकी, जिसमें लगभग सभी की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी । सन् 1832 में उदार दल का वाम पक्ष दल से अलग हो गया और उसने अपना नाम क्रांतिकारी लाइबर्टारियन दल (Radical Democratic Party) रख लिया । इस दल का उद्देश्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना था, जिसमें सब व्यक्ति का राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सके । उदार दल और क्रांतिकारी दल का विरोध करने के लिए एक नवीन 'धार्मिक अनुदार दल' (Catholic Conservative Party) का उदय हुआ । यह कथोलिक बहुमत दल वाल कटना में इस दल के लोग का पूर्ण प्रभाव था । सन् 1845 में सातवाँ कथोलिक कटना ने अपना अलग सपना बनाया जिसका नाम साउंडरबॉन्ड (Sounderbound) रखा गया । इन सब की स्थापना से गृहयुद्ध का संशय उत्पन्न हुआ जिसे एक मात्र में ही समाप्त कर दिया गया । कथोलिकों की हार वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की विजय थी । सन् 1848 में जब नवीन संविधान का निर्माण हुआ तो उदार दल एवं क्रांतिकारी दल

कर उम प्रगति का प्रतीक बनाने का प्रयत्न किया और वैशालिक दल के उग्र विरोध के बावजूद वे काफी हद तक उस समय सफल भी हुए।

परन्तु सन् 1848 के बाद उदारवादी और नातिकारी दलों में महत्त्व नहीं बना रह सका, क्योंकि उदारवादी उन मुद्दों का समर्थन नहीं कर सके, जिन्हें नातिकारी करना चाहते थे। नातिकारी दल का जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और उम समय के आधार पर नातिकारी दल ने संविधान में सन् 1874 का संशोधन करवाया। तत्पश्चात् सन् 1919 तक नातिकारी दल का प्रभुत्व चलता रहा, यद्यपि इसी मध्य 1890 में देश के राजनीतिक मंच पर समाजवादी दल (Socialistic Party) नामक एक नवीन दल का अन्वुदय भी हो गया। सन् 1918 में नातिकारी दल का पुनर्विभाजन हुआ। इसके कुछ सदस्यों ने दल की ग्रामीण नीति से असन्तुष्ट होकर एक नए दल "कृषक दल" का गठन किया। सन् 1919 में एक जनमत संग्रह द्वारा जनता ने व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की प्रणाली स्वीकार की। फलस्वरूप सन् 1919 में चुनाव हुए और उसमें स्वतन्त्र राजनीतिक दल प्रणाली का रूप बहुदल प्रणाली (Multi Party System) का हो गया।

उपयुक्त कथोलिक, उदारवादी नातिकारी, समाजवादी व कृषक दलों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में और भी अनेक छोटे छोटे दल अस्तित्व में आये। सन् 1935 में स्वतन्त्र दल का जन्म हुआ। 1935 में युवा कृषक दल (Young Farmers Party) का जन्म हुआ। इसने कृषक दल से अलग होकर एक पथक दल बनाया। सन् 1941 में प्रजातन्त्रवादी दल का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल भी अस्तित्व में आया।

स्विट्जरलैंड की दल प्रणाली का इस प्रकार का बहुदलीय रूप बना, वह अब तक चला आ रहा है और किसी भी एक दल को इतना प्रभुत्व प्राप्त नहीं हुआ है कि उसे शासन सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त हो सके।

दलों का संगठन

(Organisation of the Parties)

स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ आदि की तुलना में राजनीतिक दलों के संगठन अत्यधिक ढीले ढाले (Loose) हैं। यहां तक कि कंटोना की दलीय संगठन भी राष्ट्रीय संगठन के अधीन नहीं है। रेपांड ने कहा है कि "केवल समाजवादी दल को छोड़ कर स्विट्जरलैंड में अन्य दलों के स्वतन्त्र राष्ट्रीय संगठन नहीं हैं।" वस्तुतः स्विस मतदाता दलों की अपेक्षा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्त्व देने के अभ्यस्त हैं। अनेक सदस्य राष्ट्रीय सभा में चुने जाने के उपरान्त यह निश्चय करते हैं कि वे किस दल से सम्बन्धित रहें। इसके अतिरिक्त सदस्यों में प्रतिनिधियों के बैठने का प्रवर्धन दल के अनुसार न किया जाकर प्रदर्शों के

अनुसार किया जाता है। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी आधुनिक काल में राजनीति में केन्द्रीयकरण होने के साथ साथ दलों के संगठन में कुछ सुदृढता और नियमितता आने लगी है।

संगठन अथवा ढांचे की दृष्टि से माया यत प्रत्येक दल के तीन प्रमुख अंग हैं—डायट (Diet), केन्द्रीय समिति (Central Committee) एवं कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)। डायट दल की सर्वोच्च सभा होती है। इसकी बैठक वर्ष में प्रायः एक बार की जाती है जिसमें दल की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक आय व्यय, समकालीन समस्याओं आदि पर दल के रुख और दल की नीतियों पर विचार विमर्श होता है और निणय लिए जाते हैं। केन्द्रीय समिति दल की कार्यकारिणी समिति होती है जिसका निर्वाचन प्रत्येक वर्ष डायट द्वारा होता है, परन्तु आकार बड़ा जाने के कारण यह एक छोटी कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का निर्वाचन करती है। दल के प्रमुख अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि होते हैं।

विविध दलों की नीतियाँ

(Policies of different Parties)

कैथोलिक दल

इस दल को कैथोलिक अनुवाद या रूढ़िवादी दल (Catholic Conservative Party) भी कहा जाता है। यह स्विटजरलैंड का एक अत्यन्त प्रमुख दल है। साउण्डरवन्द के युद्ध के समय से यह दल कैथोलिक चर्च की रीतियों नीतियों की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। ग्रामीण वर्गों में कैथोलिक चर्च के प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह दल कर्णों के अधिकारों या सम्पत्ति और सघीय शक्ति के केन्द्रीयकरण का विरोधी रहा है। इस दल की निरन्तर यह चेष्टा रही है कि स्विस संविधान से उन भागों को निकाल दिया जाए जो चर्च के फायदलापों पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। यह दल सरकार के पारिवारिक सम्बन्ध और शिक्षा में हस्तक्षेप का भी विरोधी है। दल का विद्वान है कि सामाजिक शक्ति और अनुशासन तब ही सम्भव है जब कि धर्म और शिक्षा का प्रसार हो तथा उसका पूरा उत्तरदायित्व चर्च पर हो।

कैथोलिक दल व्यक्ति की स्वतन्त्रता के उस रूप या पक्ष पापक है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को अनीमित माना जाता है। यह दल इस बात का विरोधी है कि लोक-व्यापार के नाम पर व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार से वंचित किया जाय और उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जायें। आधुनिक काल में इस दल में एक समाजवादी पक्ष का और उदय हो गया है जो अधिक प्रगतिशील विचारों का है। इन पक्षों के प्रभाव के कारण कैथोलिक दल अब धर्मिकों के सम्बन्ध में उदार विचार रखने लगा है और धर्मिकों के अधिकार, पारिवारिक नैतिकता एवं धर्मिक सभा का प्रोत्साहन जैसी बातों का अपन

राज्यक्रम में स्थान दे दिया है। उपरान्त, श्रमिकों पर छात्रों राजगार वाक लोगों के प्रति इस दल की उद्बोधन नीति को नजराने जा रही है। अपना इसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए, समय के अनुसार बहने की दृष्टि से यह दल अपने नाम का अब कैथोलिक अनुसर दल (Catholic Conservative Party) के स्थान पर क्रिश्चियन समाजवादी अनुसर दल (Christian Social Conservative Party) कहने लगा है।

क्रांतिकारी दल

क्रांतिकारी दल (Radical Party) कुछ मामलों में कथोलिक दल का समर्थन करता है तो कुछ मामलों में समाजवादी दल का साथ देता है। इस तरह यह दल न तो अत्यधिक अनुदार हो है और न अत्यधिक प्रगतिशील हो।

क्रांतिकारी दल का विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए मधीय सरकार को शक्ति सम्पन्न बनाया जाय। परन्तु साथ ही यह कण्टनों के अधिकारों का एवढम कम कर दिये जाने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः कण्टनों का ही दल है और इसके समर्थक देश के सभी भागों तथा जनता के सभी वर्गों में पाये जाते हैं। वर्तमान में इस दल का मुकाबला भी और है कि जो अधिकार केन्द्र को प्राप्त हैं, उनका प्रयोग यह यथामुम्भव कण्टनों के साथ करे लेकिन यह सहायक इस तरह है कि मधीय शासन की शक्ति में ह्रास न आ पाये। पर्याप्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए यह दल सैनिक संगठन की स्थापना पर जोर देता है। धर्म-निरपेक्षता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र में इस दल की पूर्ण आस्था है और विदेशी मामलों में यह निष्पक्षता चाहता है। यह कथोलिक पक्ष की शक्ति की वढोत्तरी का और धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप का विरोधी है।

समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल

समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल (Social Democratic Party) सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और सभी व्यक्तिगत एकाधिकारों पर सामूहिक अधिकार चाहता है। उसकी नीति में इस बात पर दल नहीं दिया जाता कि राजनीतिक शक्ति प्रमुख रूप से श्रमिकों के हाथ में हो। यह श्रमिकों के लिए अधिक वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के बंधन में सहायता, सभी को काम देने, स्त्रियों को मताधिकार देने और मधीय परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पक्षपाती है। यह दल इस बात का भी समर्थक है कि संगठित वर्गों द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, श्रमिकों को अपनी दशा सुधारने के प्रयत्न करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये और राज्य का तभी हस्तक्षेप करना चाहिये जबकि संगठित वर्गों असफल हो जाय। इस दल का मत है कि स्विटजरलण्ड को संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य बनना चाहिये।

यह दल अब इस बात का मानने लगा है कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था से

व्यक्ति और समाज दोनों का ही कल्याण हो सकता है । सन 1959 के दलीय कार्यक्रम में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया था कि "व्यय और सम्पत्ति सम्बन्धी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं योग्यता का विकास करने के लिये स्वतन्त्र होगा ।" वस्तुतः यह दल जन सहयोग, सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था तथा पूँजीवाद और समाजवाद के समन्वय का पक्षपाती है । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह दल शांतिपूर्ण और जनतन्त्रिय ढंग अपना देने का समर्थक है ।

कृषक दल

कृषक, श्रमिक तथा मध्य-वर्गीय दल (Agrarian, Artisans and Middle Class Party) को संक्षेप में कृषक दल (Farmers Party) का नाम दिया जाता है । इस दल का जन्म 1918 में उदार दल के विखर जाने के परिणामस्वरूप हुआ था । यह स्विट्जरलण्ड के विभिन्न छोट-छोट दलों में सबसे प्रमुख है । इसका प्रधान ध्येय किसानों, बारीगरों और मध्यवर्गीय जनता की रक्षा में मुद्धार करना है । नीति सम्बन्धी घोषणाओं के बजाय यह दल उन कार्यों के करण में अधिक विद्वान् करता है जिनसे उपश्रुक्त लोगों की दशा सुधर सके । इस दल का प्रमुख राजनीतिक नारा है—प्रबल राष्ट्रीय सुरक्षा, महान् केन्द्रीयकरण, विद्यालय सघीय आर्थिक सहायता, अनाज की उत्पत्ति को बढ़ावा, अनाज पर सरकार का पूर्ण अधिकार तथा सरकार द्वारा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ।

साम्यवादी दल

साम्यवादी दल का वर्तमान नाम श्रमिक दल (Labour Party) है । यह दल अभी तक कोई उन्नति नहीं कर सका है । इस दल पर 1936 में और 1940 में प्रतिषेध लगा दिया गया था जो बाद में 1945 से हटा लिया गया । इसकी नीति मुख्यतः पुरातन साम्यवाद पर आधारित रही है और इसीलिये इसे देश में महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया है । इस दल की कुछ मांगें हैं—बड़े व्यापारों का केन्द्रीयकरण, बुद्धि का बीमा, स्त्री भ्रताधिकार, सप्ताह में 40 घंटे काय आदि ।

उदारवादी दल

उदारवादी दल (Liberal Party) भी स्विस् राजनीति में प्रधान दल था जिसे क्रांतिकारी दल (Radical Party) के साथ सन 1848 का संविधान के शीर्षणश के समय ग्रासन सभाला था । किंतु धीरे-धीरे इस दल की शक्ति में ह्रास होता गया और आज यह एक प्रभावहीन दल है । यह दल परम्परागत उदारवाद एवं यथेच्छाचारिता (Laissez faire) का पोषक है और समाजवाद तथा प्रत्यक्ष सघीय करो का विरोधी । अधिकांश धनिक प्रोटेस्टैन्ट्स इसके समर्थक हैं ।

स्विस दल पद्धति की विशेषतायें (Features of Swiss Party System)

(1) स्विस राजनीतिक दलों का आधार कण्टन है न कि सभ अथवा राष्ट्र। इसके लिये दो कारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं— (क) साधारण स्विस नागरिक का यह विश्वास है कि उसके भाग्य का निर्धारण अधिकांशतः स्थानीय राजनीति द्वारा होता है संघीय नीतियों द्वारा नहीं। (ख) दलों के निर्माण और संगठन का आधार प्राथमिक रूप में स्थानीय प्रश्न है। स्विट्जरलैण्ड में राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते। स्विट्जरलैण्ड में बहुत-दल प्रणाली के भी कुछ विशेष कारण हैं। प्रथम, स्विस लोगों में अनेक प्रकार की विविधतायें हैं। द्वितीय, स्विट्जरलैण्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार चुनाव होते हैं जिसके अन्तर्गत छोटे छोटे दल भी जीवित रहते हैं। तृतीय, स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका के सदस्य एक दल के नहीं होते। वे कई दलों के सदस्य हो सकते हैं और यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एक ही सामान्य कार्यक्रमों को मानने वाले हों। संघीय सभा के दोनों सदनों और संघीय परिषद में भी अनेक दलों के प्रतिनिधि होते हैं।

(2) स्विट्जरलैण्ड में अमेरिका एवं अन्य यूरोपियन देशों जैसी विषम एका कटु दलवादी का अभाव है। दलगत भावना का अभाव स्विस दल पद्धति की एक अनुपम विशेषता है।

(3) अमेरिका के समान ही स्विट्जरलैण्ड में भी राजनीतिक दलों को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है बरन समय की गति के साथ उनका विकास हुआ है। कण्टनों के संविधानों में भी दलों के विषय में प्रावधान नहीं है। जब से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया गया है तब से राजनीतिक दलों को अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में स्थान मिल गया है।

(4) स्विट्जरलैण्ड में विभिन्न दलों में पारस्परिक सहयोग, सम्पर्क, सह-अस्तित्व एक समझौते की भावना विद्यमान हैं। वे विषमता, विरोध तथा वैमनस्य की भावना से कार्य नहीं करते। संघीय परिषद और संघीय सभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों में यही भावना स्पष्टतः पाई जाती है। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने स्विस शासन व्यवस्था को बहुदलीय (Multi-party) की अपेक्षा निदलीय (Non partisan) कहना अधिक उचित समझा है।

(5) यद्यपि स्विट्जरलैण्ड में भाषा, जाति एवं हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का स
से किसी आधार पर न होकर
आधार पर हुआ है।

एवं विद्यमान
) इनमें
के

(6) स्विस दलों में एक
इंग्लैण्ड और भारत में । इसका

(7) स्विस् दल के चुनाव आदि के तरीके औचित्य की सीमा के भीतर रहते हैं। व अनुचित व्यय नहीं करते और राजनीतिक जीवन में सच्चरित्रता का ध्यान रखते हैं। स्विस् जनता पर जितना कम व्यय होता है, उतना चायद कहीं भी नहीं होता होगा। स्विस् दलीय संगठन अमेरिका के मशीन जैसे संगठन की बुराइयों से मुक्त है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलण्ड में दलीय पद्धति के दोष, जो व य सभी जगह पाये जाते हैं, जनमत संग्रह की पद्धति द्वारा सीमाओं के भीतर रहते हैं। दंग का छोटा आकार, स्विस् लोग में पारस्परिक सहिष्णुता, दल का ठोला-ढाला संगठन, दलों में पारस्परिक सहयोग की भावना, योग्यता के आधार पर निर्वाचन आदि ऐसे कारण हैं जिन्होंने मिलकर देश में अमाधारण मुख्यमय स्थिति स्थापित कर दी है।

7

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (DIRECT DEMOCRACY)

आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्जरलैंड को प्रायः सबसे अधिक लोकतंत्रीय समझा जाता है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड को आधुनिक लोकतंत्रीय प्रणालियों में सबसे कम लोकतंत्रीय भी कहा जा सकता है। —कोडिंग्स

प्रजातन्त्र शासन के दो भेद माने गये हैं—(1) शुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (Pure or Direct Democracy), (2) प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (Representative or Indirect Democracy)। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सरकार में जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य के शासन में भाग लेती है। इसमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से अधिनियम बनाने नये विधेयको का प्रस्तावित करने तथा विधायी सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द करने का अधिकार होता है। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र उस ही राज्या में सम्भव है जिनका आकार बहुत छोटा हो। आधुनिक राज्या में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को चलाना सम्भव नहीं है, तथापि कुछ प्रत्यक्ष प्रजाताधिक उपायों का मसार के कुछ राज्यों में अभी तक चलाया जाता रहा है जिनमें लोकनिर्णय (Referendum), आरम्भ (Initiative) प्रत्यावर्तन (Recall) आदि सम्मिलित हैं। विश्व में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र प्रचलित है। प्रजातन्त्र के जो भी साधन हैं, उनका प्रयोग इस देश से अधिक अन्यत्र नहीं होता।

स्विट्जरलैंड का प्रजातन्त्र वा घरेलू इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वहाँ प्राचीन यूनान के नगर राज्या जैसा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र है। वस्तुतः स्विट्स प्रजातन्त्र न केवल प्रत्यक्ष है बल्कि ग्रिटन जैसा अप्रत्यक्ष भी है। उसे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का घरेलू इसलिए कहा जाता है कि वहाँ हमारा जितना व्यापक और सफल प्रयोग हुआ तथा हा रहा है, उमा अन्यत्र कहीं दखन को नहीं मिलता।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की विधियाँ (Methods of Direct Democracy)

स्विटजरलैंड के निवासियों ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के तीन मुख्य साधनों को लगभग पूर्ण रूप से अपनाया है—

- (1) प्रारम्भिक सभायें (Primary Assemblies),
- (2) जनमत संग्रह (Referendum), और
- (3) आरम्भिक (Initiative) ।

प्रारम्भिक सभायें

प्रारम्भिक सभाओं का अभिप्राय यह है कि निर्धारित समय पर देश के सभी वैयक्तिक नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर कानूनों का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करेंगे । इस प्रक्रिया में नागरिक अपनी प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं । यह प्रजातन्त्र का सबसे विशुद्ध और सबसे प्राचीन रूप है ।

प्रारम्भिक सभाओं की व्यवस्था स्विटजरलैंड के 4 अर्द्ध-कान्टों तथा 1 पूर्ण कान्टन में प्रचलित है । इन लोकसभाओं को 'लैंड्सजीमाइन्' (Lands gemeinde) कहते हैं । ये लोकसभायें जिन कान्टों में हैं, वहाँ कान्टों के स्वतन्त्र नागरिक इन सभाओं के सदस्य होते हैं । इन सभाओं का वाणिज्य बैठक होती है जो सामान्यतः उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार व्यवस्थापिका सभायें करती हैं । प्रतिवर्ष कान्ट के सभी वयस्क पक्ष नागरिक एक जुट मदान में एकत्रित होकर संविधान में संशोधन, सामान्य कानूनों का निर्धारण, करारपण, मतान्तरिकार, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अधिकारों का निश्चय आदि कार्य का पूरा करते हैं ।

यद्यपि प्रारम्भिक सभाओं अथवा लोकसभाओं का यह रूप, देश की जनसंख्या और आकार में वृद्धि एवं प्रशासन की आधुनिक पेशीदमियों आदि के कारण आधुनिक काल में अभ्यावहारिक होता जा रहा है । धीरे-धीरे इनका टाट हो रहा है ।

जनमत संग्रह या लोकनिर्णय

जनमत संग्रह का सामान्य अर्थ यह है कि विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों अथवा प्रस्तापित कानूनों पर जनता का मत लिया जाए । इस तरह जनमत संग्रह की विधि के माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक एवं साधारण कानूनों पर अपना मत पकट करके सामन्य कार्य में लागू करते हैं । यदि जनमत पक्ष में हो तो कानून पारित समझा जाता है और यदि विपक्ष में हो तो अस्वीकृत । इस प्रकार जनमत संग्रह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जनता का हाथ में व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों पर नियन्त्रण बनाया जा सकता है । जनता का हाथ में यह एक नकारात्मक अस्त्र है । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में यह ढाल (Shield) का काम

करता है जिसके द्वारा जनता अवाञ्छनीय कानूनों को दूर कर सकती है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह का प्रयोग केन्द्र व कैंटन दोनों में ही होता है।

आरम्भिक या उपक्रम

आरम्भिक या उपक्रम वह साधन है जिससे नागरिका की कुछ भरी स्वर कानूनों को प्रस्तुत कर सकती है अर्थात् व्यवस्थापिका कानूनों के सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केन्द्र व कैंटन दोनों में होता है। आरम्भिक वस्तुतः एक सलवार है जिसके द्वारा जनता अपनी इच्छा अथवा विचारों को कानून बनाने के लिए मांग साफ करती है। यह नागरिका को विधि निमाण में सकारात्मक अधिकार प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यवस्थापिका की अनिच्छा के बावजूद जनता विधि निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है।

केन्द्र में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र

(Direct Democracy in the Centre)

केन्द्र में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की जनमत संग्रह और आरम्भिक की दो विधियाँ ही प्रयुक्त होती हैं—

जनमत संग्रह अथवा लोक निर्णय (Referendum)

जनमत संग्रह में हमारा तात्पर्य व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए कानूनों को जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए रखने से है—

स्विट्जरलैंड में जनमत दो प्रकार का है—

- (क) अनिवार्य जनमत संग्रह (Compulsory Referendum),
- (ख) एच्छिक अथवा वैकल्पिक जनमत संग्रह (Optional Referendum)।

(क) अनिवार्य जनमत संग्रह—जब व्यवस्थापिका द्वारा पास किया हुआ प्रत्येक कानून अनिवार्यतः जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो वह अनिवार्य जनमत संग्रह (Compulsory Referendum) कहलाता है। यह अनिवार्य जनमत संग्रह सन् 1848 के संविधान द्वारा प्रचलित किया गया था। मविधान की धारा 123 में इस विषय में यह व्यवस्था है कि “संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अथवा सभी क्रियावित हो सकेगा, जब मत देने वाल स्विस नागरिका का बहुमत तथा राज्यों का बहुमत उसे स्वीकार कर लें।” संविधान में दी गई इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि—

- 1 जनमत संग्रह का रूप अनिवार्य जनमत संग्रह का हो।
- 2 यह व्यवस्था केवल संविधान के संशोधन सम्बन्धी कानूनों के विषय में हो।
- 3 संशोधन सभी पूरा होना सम्भव जाता है जबकि उस स्विट्जरलैंड के उन नागरिका के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाए जो उससे सम्बन्धित

जनमत संग्रह में मतदान करें, तथा इसके अतिरिक्त उसे कटनों के बहुमत द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाए।

4 जनमत संग्रह पूरे मन्त्रिपरिषद् के विषय में भी हो सकता है और उसके किसी अंग के मन्त्रागण के विषय में भी।

चूँकि उपर्युक्त जनमत संग्रह अनिवार्य है और इसका सम्बन्ध संविधान से है, अतः इसे अनिवार्य जनमत संग्रह (Compulsory Constitutional Referendum) कहा जाता है।

(ए) ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह—ऐच्छिक जनमत संग्रह वह होता है जब व्यवस्थापिका द्वारा पारित किया हुआ कानून उन्नी अवस्था में जनता के समक्ष अपनी स्वीकृति हेतु रखा जाता है जब नागरिका को एक निश्चित सत्या इस सम्बन्ध में प्राथमा करे। ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था स्वीस कानूनों के लिए सन् 1874 में की गयी थी। मन्त्रिपरिषद् की 89वीं धारा के अनुसार यह व्यवस्था है कि सभ के सब कानूनों और सब पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों (Arreates) को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए, मन्त्राधिकार रखने वाले 30 हजार स्विस् नागरिक अथवा 8 कैंटनों के 30 हजार स्विस् नागरिक उनके विषय में ऐसी मांग करें। ऐसा मांग के लिए 90 दिन का समय नियत है। किसी कानून अथवा आदेश के प्रकाशन के लिए 90 दिन के अन्दर यदि ऐसी मांग पेश की जाए तो उस कानून अथवा अध्यादेश पर जनमत संग्रह लेना आवश्यक समझा जाता है।

सामान्यतः सभी कानूनों को, जिनके विषय में जनमत संग्रह की मांग की जाए, जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करना होता है। केवल मानव अधिकारों के विषय में एक अपवाद है और वह यह है कि यदि किसी अध्यादेश को व्यवस्थापिका द्वारा 'आवश्यक' (Urgent) अथवा 'सब पर लागू न होने वाला' (Not universally binding) घोषित कर दिया जाए तो उस पर जनमत संग्रह की मांग नहीं की जा सकती। लेकिन वर्तमान काल में होता यह है कि जनमत संग्रह की मांग में बचने के लिए व्यवस्थापिका प्रायः उन सब कानूनों को अध्यादेशों का रूप दे देती है जिनका सम्बन्ध वजह जाति महत्त्वपूर्ण बातों से होता है और ऐसे अध्यादेशों को 'आवश्यक' अथवा 'सब पर लागू न होने वाला' घोषित कर देती है। कहीं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इस ढंग से अपनी शक्ति का स्वार्थी रूप में दुरुपयोग न करने लगे इसके लिए सन् 1949 के एक मसौदा द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि 'आवश्यक' व 'सब पर लागू न होने वाले' आदेश (Arreates) एक वर्ष बाद स्वयं समाप्त समझे जायेंगे यदि उनके विषय में वैकल्पिक जनमत संग्रह की मांग की जाए और उन्हें उसके द्वारा स्वीकार न किया जाए। ऐसे अध्यादेशों के विषय में जिनसे संविधान की किसी व्यवस्था का उल्लंघन होता हो, यह व्यवस्था की गयी है कि उन्हें प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर जनता एवं कटनों द्वारा

अवश्यमेव स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे स्वयं ही समाप्त हो जावेंगे।

ऐच्छिक अथवा वैकल्पिक जनमत संग्रह की व्यवस्था उन अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर भी लागू हो, जो या तो अनिश्चित काल के लिए की जायें या जो 15 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए हो। यदि 30 हजार सक्रिय नागरिक अथवा 8 कटन मांग करें तो उन पर जनमत संग्रह लेना आवश्यक होता है।

यह स्मरणीय है कि वैकल्पिक जनमत संग्रह के लिए जो भी कानून या अध्यादेश या सचिव अथवा समझौता प्रस्तुत होता है, वह कार्यान्वित तभी किया जा सकता है जब उसे स्विट्जरलैंड के उन मतदाताओं के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, जो मतदान में भाग लें।

आरम्भक या निबन्ध उपक्रम (Initiative)

आरम्भक वह साधन है जिससे नागरिका की कुछ सख्या स्वयं कानूनों को प्रस्तुत कर सकती है अर्थात् व्यवस्थापिका कानूनों के सुझाव रख सकती है। गभीर शासन-व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान के संशोधन अथवा पुनर्निरीक्षण (Revision) के सम्बन्ध में आरम्भक की व्यवस्था की गयी है, सारे कानूनों के सम्बन्ध में नहीं। दूसरे शब्दों में नागरिका को केवल संविधान में संशोधन करने की मांग का अधिकार है, समस्त विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग करने का वह कोई अधिकार नहीं है। चूंकि आरम्भक के प्रयोग की व्यवस्था केवल संविधानिक संशोधनों के विषय में की गई है, अतः इसे संविधानिक आरम्भक (Constitutional Initiative) भी कहा जाता है। वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसके अनुसार संविधान के पूरे संशोधन (Total Revision) अथवा आंशिक संशोधन (Partial Revision) दोनों के ही विषय में आरम्भक का प्रयोग किया जा सकता है। इस आधार पर आरम्भक का रूप दो प्रकार का हो जाता है—पूरा संशोधन सम्बन्धी आरम्भक (Initiative for Total Revision) एवं आंशिक संशोधन सम्बन्धी आरम्भक (Initiative for Partial Revision)। दोनों ही प्रकार के आरम्भक का प्रयोग मतदान के अधिकारी 50 हजार मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त मस्यौदा में निम्न नागरिक, पूरा अथवा आंशिक संशोधन के लिए याचिका दें तो उस याचिका पर जनमत संग्रह लागू आवश्यक होता है।

यदि जाता है आरम्भक द्वारा संविधान के पूर्ण संशोधन या पुनर्निरीक्षण (Total Revision) की मांग की है अथवा यदि पूरा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव का आरम्भक व्यवस्थापिका के विरुद्ध एक सदन में किया है, अतः दूसरा सदन उचित परिमन नहीं है, तो इन दो दस्तावेजों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाने की व्यवस्था है—

(i) प्रस्तावित सशोधन स्विस मतदाताओं के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जायेगा कि मशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(ii) मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सघीय व्यवस्थापिका का पुनर्निर्वाचन होगा। यहाँ कंटनों के बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) पुनर्निर्वाचन के पश्चात् नयी सघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित मशोधन पर विचार करेंगे और उनके बहुमत द्वारा पारित होने पर वह सशोधन प्रस्ताव सर्व साधारण और कंटनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जावेगा तथा लोकनिर्णय के पक्ष में होने पर वह सशोधन प्रस्ताव त्रियाशील होगा।

आंशिक सशोधन (Partial Revision) के लिए प्रस्तुत आरम्भक के विषय में यह व्यवस्था है कि वह प्रस्ताव पूरे विधेयक के रूप में (Formulated) भी दिया जा सकता है और भाँटे सुझावों के रूप में (Unformulated) भी दिया जा सकता है।

यदि आंशिक सशोधन का आरम्भण भाँटे सुझावों के रूप में (Unformulated) होता है तो निम्नलिखित दो व्यवस्थाएँ हैं—

(i) सघीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत होने पर उसका विधेयक तैयार होगा और उस विधेयक को सर्वसाधारण तथा कंटनों की स्वीकृति (Ratification) मिलने के बाद क्रियावित किया जायेगा।

(ii) यदि सघीय व्यवस्थापिका सशोधन प्रस्ताव के विषय में है तो वह सशोधन प्रस्ताव का सर्वसाधारण के निर्णय के लिए भेज देगी। यहाँ पर कंटनों के मत जानने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बहुमत मशोधन के पक्ष में होगा तो सघीय व्यवस्थापिका प्रस्ताव के अनुरूप विधेयक तैयार करेगी और उसे सर्वसाधारण तथा कंटनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करेगी।

यदि आंशिक मशोधन की माँचिका पूरे विधेयक के रूप में (Formulated) प्रस्तुत की जाती है, तो इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है—

(i) सघीय व्यवस्थापिका, पक्ष में होने पर, उस विधेयक को सर्वसाधारण एवं कंटनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ii) सघीय व्यवस्थापिका, विपक्ष में होने पर, दो माँग अपना सकती है—प्रथम, वह सिफारिश कर सकती है कि प्रस्तावित मशोधन स्वीकृत कर दिया जाए अथवा द्वितीय, वह जनता द्वारा प्रस्तावित प्रारूप के साथ एक अपने द्वारा बनाया हुआ प्रारूप भी जनमत संग्रह के लिए रख सकती है। मशोधन प्रस्ताव का जनमत संग्रह में जनता और कंटनों दोनों के बहुमत का समर्थन मिलना आवश्यक है।

उपयुक्त प्रथम में यह स्मरणीय है कि साधारण कानूनों के विषय में स्विट्जरलैंड में आरम्भक (Initiative) की व्यवस्था नहीं है फिर भी स्विस

लोग मन्वेधानिक मसोधना के नाम से साधारण कानूनों से भी सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। बन्दावस्था का बीमा, जानवरों का काटा जाना, गहू की पशुवार की वृद्धि आदि से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव मन्वेधानिक मसोधन के नाम से प्रस्तुत किये गये हैं और उनमें से अनेक सविधान या जय वन चुक चुके हैं।

कैंटनो में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र

(Direct Democracy in Cantons)

कैंटनो में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का प्रयोग की तीनो ही विधियाँ काम में लायी जाती हैं—स्थानीय सभायें जनमत संग्रह और आरम्भक। कैंटनो में इन तीनों का प्रयोग निम्नानुसार है—

स्थानीय सभायें (Landsgemeinde)

इस प्रकार की लान्द सभायें जो प्रत्यक्ष रूप से कैंटनों के शासन काय में भाग लेती हैं, इन समय उरी (Uri) व ग्लारस (Glarus) के दो पूरे कैंटन तथा अन्टरवाल्डन (Unterwalden) श्वेज (Schweyz), जुग (Zug) व अप्पेजिल (Appenzill) के चार आधे कैंटन काम करती हैं। इन कैंटनो में विवाधी शक्ति सीधी जनता में निहित है। इन कैंटनो के बारे में यह ठीक ही कहा गया कि 'वे मुक्त वायुमण्डल के लान्दतन्त्र (Democracies of the open air type) हैं।'

स्थानीय सभायाँ जयन्ता स्थानीय लोकसभायाँ (Landsgemeinde) का रूप स्वतन्त्र नागरिकों की राजनीतिक सभायाँ या हाता हैं, जो प्रत्येक वर्ष एक निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में खुले में होती हैं। विधियों का निर्माण करने और कैंटनो के अधिकारियों का चुनाव करने के लिए नागरिक प्रत्येक वर्ष अप्रैल या मई के महीने में किसी रविवार के दिन छाल मदान में एकत्र होते जाते हैं। व समस्त पुरुष नागरिक जिन्होंने मताधिकार की अवस्था प्राप्त करली है, इन लोकसभायाँ में उपस्थित हो सकते हैं और उनका कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। मित्रात रूप से सभी वयस्क नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सम्बन्धित क्षेत्र अथवा कैंटन की स्थानीय सभा में उपस्थित हों। कुछ कैंटनों में तो उन अनुपस्थित सदस्यों पर जुर्माना लगाने की प्रथा है जो बिना किसी उचित कारणों के सभायाँ से अनुपस्थित रहते हैं। स्थानीय सभायाँ कानून बनाती हैं और उन कानूनों का पुष्टिकरण करती हैं, जो उनके द्वारा निर्वाचित कार्यवाहिणी समिति ने बनाये हों। वह विविध उपयोगी प्रस्ताव पारित करती हैं और वित्त एवं नागरिक बापों के विषय में विभिन्न महत्वपूर्ण नियम करता है। स्थानीय सभायें कार्यवाहिणी एवं शासन समितियों का चयन करती हैं तथा प्रमुख अधिकारियों का चयन या त्यागोक्ति का निष्पत्ति करती हैं। स्थानीय सभायाँ की शक्तियाँ और उनके अधिकार भिन्न भिन्न कैंटनो में भिन्न भिन्न हैं—सविधान का पूरा व आंशिक संशोधन, कानूनों का

निर्माण, कर निर्धारण, ऋण लेना और अनुदानों को स्वीकार करना, कायपालिका एवं न्यायाधीशों का निर्वाचन तथा नवीन पदों की स्वीकृति और वेतन वृद्धि का निर्धारण आदि।

स्थानीय सभाओं की अधिकारी-विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि तु रपट (Rappard) का कहना है कि—“यह विश्वास करना कठिन है कि लाभभावे अनिश्चित कार्य तब बना रह सकती है। ये आदिम लोकतन्त्र के अनुयायी नमूने या चीने हुए दिनों के समान चिह्न हो के रूप में रह सकती हैं।”

जनमत संग्रह (Referendum)

कैटोना में जनमत संग्रह की व्यवस्था इस प्रकार है—

(1) प्रत्येक प्रतिनिधि कैटोना में सार्वजनिक सभाघरों के लिए अनिवार्य जनमत संग्रह (Compulsory Referendum) की व्यवस्था है। सविधान में किसी प्रकार का सभाघर तब तक नहीं हो सकता, जब तक उसे कैटोना की जनता स्वीकार न कर ले।

(11) साधारण कानून के सम्बन्ध में कैटोना में अनिवार्य जनमत संग्रह और कुछ में वैकल्पिक जनमत संग्रह (Optional Referendum) की व्यवस्था है। दस पुराने एक साथ कैटोना में अनिवार्य (Compulsory) तथा आठ-दस व एक साथ कैटोना में यह वैकल्पिक (Optional) है।

(111) पाँच एक कैटोना और चार अलग कैटोना में जहाँ स्थानीय सभाओं की व्यवस्था है जनमत संग्रह का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(114) कुछ कैटोना में वित्तीय मामलों के लिए भी जनमत संग्रह की व्यवस्था है। कुछ में यह व्यवस्था अनिवार्य है और कुछ में वैकल्पिक। 16 कैटोनों में वित्तीय प्रस्तावों पर अनिवार्य जनमत संग्रह और 5 कैटोनों में वैकल्पिक जनमत संग्रह की व्यवस्था है, यदि वह प्रस्तावों की धन राशि एक निर्धारित सीमा से अधिक हो। प्रत्येक कैटोना में यह सीमा भिन्न है।

आरम्भक (Initiative)

रेबल जनता को उठाकर, जहाँ सिर्फ सार्वजनिक आरम्भक (Constitutional Initiative) की ही व्यवस्था है, अथवा सब कैटोनों में सार्वजनिक और व्यवस्थापन सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के आरम्भक की व्यवस्था प्रचलित है। दोनों में कब-कब अन्तर पड़ती है कि सार्वजनिक आरम्भक के लिए अधिक और व्यवस्थापन सम्बन्धी आरम्भक के लिए कम लोगों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। किन्हीं-किन्हीं कैटोना में दोनों ही प्रकार के आरम्भकों के लिए बराबर मतदाताओं के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का मूल्यांकन (Evaluation of the System of Direct Democracy)

पक्ष ।

(1) इससे द्वारा प्रजातन्त्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और जनता को दैनिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अनिवार्य लोक निर्णय के कारण जनता का समय-समय पर मतदान करना पड़ता है और इस प्रकार उसे प्रशासन में अपनी महत्ता का अनुभव होता है। ऐच्छिक लोक निर्णय में जनता अपनी खुशी से भाग लेती है और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करती है।

(2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण प्रणाली के द्वारा जनता पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अधिनियम नहीं थोपा जा सकता।

(3) जब कानूनों का जनता स्वयं बनाती है तो स्वाभाविक है कि वह उनका उचित रूप में पालन भी करती है।

(4) इनके द्वारा जनता का राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। शासक इनका सरलतापूर्वक प्रभावित नहीं कर सकते। राजनीतिक विषयों पर विचार करने और उन पर मताधिकार प्राप्त होने से जनता के प्रशासकीय ज्ञान की वृद्धि होती है।

(5) लोक निर्णय के कारण दलबन्दी उद्यम नहीं हो पाती। जनता को नागरिकता की शिक्षा मिलती है और उसमें एकता की भावना का उद्भव होता है।

(6) जनता की इस दायित्व के भय से व्यवस्थापिका अधिकार प्रस्ताव पास करने में दूर रहती है। समय-समय पर ऐसे प्रस्तावों को, जो लोक इच्छा के विरुद्ध हो सकते थे, व्यवस्थापिका न ठुकराया है।

(7) लोक-निर्णय और आरम्भण दोनों जनता में इस चेतना की आरम्भ करते हैं कि वे ही विधि को बनाने वाले हैं और उनका शासन में प्रत्यक्ष हाथ है। इस प्रणाली में इसलिए न तो बहुमत की निरंकुशता मिलती है और न अल्प-मतवादी की निराशा।

(8) व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों को जनता से सदा सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। उसको जनता की मांगों तथा उनके हितों का सदा ध्यान रखना पड़ता है।

(9) बांजोर (Banjor) लोक-निर्णय को राजनीतिक वातावरण का सुन्दरतम बरोमीटर मानता है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष वात पर जनता की इच्छा मालूम हो सकती है।

(10) इसके द्वारा जनता का औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग शासन पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता।

विपक्ष

(1) सब साधारण जनता में इतनी जागरूकता नहीं होती कि वह विधि निर्माण

जैसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य में उचित रूप से भाग ले सके। जनता को यह अधिकार प्रदान करना देश के लिए घातक है।

(2) इसके कारण व्यवस्थापिका के सदस्यों का महत्व कम हो जाता है और वह पूर्ण रीति तथा तत्परता से कार्य नहीं करते।

(3) लोक नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों की उपेक्षा होती है और मूक तथा साधारण बातों को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगता है।

(4) मतदान की उपेक्षा या मतदान में जालसाजी के कारण लोक-नियंत्रण जनता की वास्तविक इच्छा का द्योतक नहीं रहता। कभी-कभी सुगठित अल्पमत लोक-नियंत्रण में सफलता पाकर जनता की वास्तविक इच्छा का प्रदर्शन करने लगता है।

(5) एक साधारण काम-काजी आदमी को कानून बनाने के काम में विशेष दिलचस्पी नहीं होती। न उसे फुरसत होती है न इच्छा। वह अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देना पसंद करता है। यह बात इसी से प्रकट है कि कभी कभी प्रति सैकड़ा बहुत कम मतदाताओं की सख्या चुनाव में भाग लेती है।

(6) वल्टी (Wells) ने लिखा है कि "जनता व्यावसायिक कानून बनाने वाले का स्थान नहीं ले सकती और न उसका काम ही चला सकती है। जटिल शासन कार्यों में साधारण नागरिकों में उपयुक्त नियंत्रण की आशा करना रेत में कूटल निकालना है।"

(7) प्रत्यक्ष विधि निर्माण में समझौता या संशोधन की गुंजाइश नहीं होती। जनता को किसी विधेयक के प्रश्न पर ज्यों के त्यों हा या ना सूचक सम्मति देनी होती है। व्यक्ति का विचार विमर्श का अवसर नहीं होता और न जनमत संग्रह में पूर्व व्यक्ति का प्रश्न या स्वरूप निश्चित करने में कोई हाथ रहता है। उसे यही कहा जाता है कि यह बात इस तरह आपके आगे है बोला मानते हो या नहीं।

(8) वर्तमान में अधिकांश कानून राष्ट्रीय जायिक नीति से सम्बंधित होते हैं। नागरिक इनमें प्रत्यक्ष रूप से स्वाधीन होने के कारण इन पर निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार नहीं करते। ऐसी दशा में सलाहों की पेंटी का परिणाम आदर्शों या विचारों का लड़ाई का फल न होकर निहित हिता के संपर्क का प्रतिबिम्ब होता है।"

(9) जनता द्वारा स्वीकृत हो सके इसके लिए सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, समझौते की भावना लेकर चलते हैं, कोई निर्भीक कार्य क्रम नहीं।

(10) जनता अधिकांशतः अविश्वासी तथा रुढ़िवादी होती है, अतः वह प्रगतिशील कानूनों का विरोध करती है।

(11) यह पद्धति अत्यन्त खर्चीली और अडग्रा लगाने वाली है। इसमें थोड़े-थोड़े समय के बाद देश के अन्दर उथल-पुथल मचती रहती है। भारत सरीखे देश में तो इसका प्रयोग सम्भव ही नहीं है।

(12) कई बार ऐसा भी सम्भव है कि लोक निर्णय के अनुसार मत लेने का अवसर उपस्थित होने तक प्रश्न सामयिक न रहकर अनावश्यक रह जाता है। प्रस्तुत्स्थिति

स्विस राजनीति का इतिहास बताता है कि वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का प्रयोग में आलोचना की बातों की बजाय प्रशंसा की बातों को ही अधिक स्थान मिला है—

1 स्विट्जरलैंड ने दिखा दिया है कि प्रत्यक्ष-प्रजातन्त्र का प्रयोग बिना भ्रष्टाचार के किया जा सकता है। वहाँ के प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में अनुचित दबाव, मत पत्रों की खरीद, जाली हस्ताक्षर करना, मतदाताओं को बहकाना आदि भ्रष्ट बातों का प्रयोग नहीं किया जाता।

2 स्विस जनता अविवेकी, आवेशपूर्ण जयवा समस्याओं के प्रति अज्ञानी नहीं है। सन् 1848 से 1952 तक 104 बार मर्यादित सभाधारा के सम्बन्ध में मत-दान हुए। इनमें सघीय सभा द्वारा 61 प्रस्तावों पर अनिवार्य जनमत संग्रह हुआ जिसमें से 43 प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार किया और 18 को अस्वीकार। लगभग इसी समय के अंतर्गत 34 संविधान सम्बन्धी आरम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनमें से 6 स्वीकार हुए। इसी तरह 46 व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत संग्रह (Legislative Referendum) लिया गया, जिनमें से 17 पर जनता ने अपनी स्वीकृति प्रकट की। दो बार संविधान के पूर्ण मशवरे के प्रस्ताव आए— 1880 ई० में और 1935 ई० में, परन्तु दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये। सन् 1874 से सन् 1954 तक स्थान सघीय सभा ने 500 से अधिक कानून निर्मित किए जिनमें से केवल 63 पर जनमत संग्रह की मांग की गई और इनमें 23 कानून जनमत संग्रह द्वारा स्वीकृत कर दिए गए और 40 कानून अस्वीकृत।

स्पष्ट है कि स्विस जनता ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधनों का प्रयोग संविधान में समायोजित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में किया है। स्विस जनता ने अपरिपक्व तथा अयोग्य पूर्ण आरम्भिक का अस्वीकृत कर दिया, लेकिन जब उसी विषय से सम्बन्धित विवेकपूर्ण मधोम परिपक्व द्वारा उभार लिया गया तो जनता ने उसे स्वीकृत कर लिया है। स्विस जनता के समक्ष जो प्रस्ताव आते हैं उन पर वह इस दृष्टि से विचार नहीं करती कि जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं या सरकार द्वारा, बरन् वह उन पर विचार और उद्धारना का विचार कर अपना मत प्रकट करती है। इसीलिए के० वा० सी० व्हीयर (K V C Wheare) ने कहा है कि 'स्विट्जरलैंड का संविधान यदि अच्छा है तो स्विट्जरलैंड का नाग अच्छा है।'

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता के कारण

(Causes for the Success of Direct Democracy)

यद्यपि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का प्रयोग अमेरिका में भी आरम्भ हुआ था किन्तु वहाँ है लेकिन स्विट्जरलैंड में यह जितना सफल और सम्भव हुआ है, उसकी तुलना

किसी से नहीं की जा सकती। इस सफलता के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दो पक्ष हैं—सैद्धांतिक पक्ष की दृष्टि से स्विस जनता की मायता है कि प्रभुसत्ता प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से जनता में निहित होनी चाहिए। अतः ऐसी व्यवस्था की गई है कि दिन-प्रतिदिन का कार्य प्रतिनिधि गण करें लेकिन अंतिम सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथ में रहे। व्यावहारिक पक्ष में, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जो अत्यन्त घन वस्त्र हुए कटनों में विभाजित है और इसलिए यह सम्भव हो सका है कि सभी नागरिक प्रशासनिक कार्यों में सीधे रूप से हाथ बटा सकें।

स्विस प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की इतनी अधिक सफलता का रहस्य जिन कारणों में छिपा है, वे ये हैं—

जनता का चरित्र

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जनता का सीधा साधन है, जिसकी सफलता जनता की दुरुयोग्यता पर निर्भर करती है। सोभाग्यवश स्विस जनता अपने वक्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूर्ण निष्ठावान और जागरूक है, जो योग्य व्यक्तियों को ही चुनती है। स्विस निवासियों में व्यवहार-कुशलता, राष्ट्र प्रेम, राजनीतिक जागरूकता, उदारता जैसे सभी नागरिक गुण पाये जाते हैं। शिक्षा में भी इस देश की जनता बहुत आगे बढ़ी हुई है। विधि निर्माण के लिए आवश्यक नियम तक की ओर घात स्वभाव यहाँ की जनता में पाया जाता है। स्विस लोग न तो अत्यन्त रुढ़िवादी हैं और न अत्यन्त उग्रवादी ही। उनकी वृत्ति मध्य-मार्ग पर चलने की है और इसीलिए प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की व्यवस्था द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों का वे अति विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं।

प्रजातान्त्रिक परम्पराएँ

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की सफलता का दूसरा कारण वहाँ प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की परम्पराएँ हैं जो मकड़ों वगैरहों से सुचारु रूप में चलती आ रही हैं। जनमत संग्रह तथा आरम्भिक साधना के अनुरूप लाभ स्विट्जरलैंड में स्पष्टतः देखने को मिलते हैं। यह सावजनिक सम्प्रभुता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देता है, व्यवस्थापिका पर अंकुश का कार्य करता है, नागरिकों में देशप्रेम, जनमेवा एन कर्तव्य-परायणता के भाव भरता है, दलगत भावना को जनता को घात करता है तथा लगभग प्रत्येक प्रश्न पर जनता के निर्णय को अंतिम ध्यान देता है। इन साधनों के परिणामस्वरूप ही जन-इच्छा के नियमित होने के साथ साथ प्रशासन का सुचारु राजनीतिको के अनुभव का भरपूर लाभ मिलता रहता है।

तटस्थता की नीति

स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो स्थायी रूप से मुक्तकाल से तटस्थ नीति पर चलता आ रहा है। परिणामस्वरूप यह देश उदय विश्व सन्तुष्टि से मुक्त रहा है

और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर जो देश में मतभेद पैदा हो जाते हैं, उनके विपरीत प्रभाव से लगभग अछूता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तटस्थता का रख अपनाते के कारण स्विट्जरलैंड की समस्याएँ सरल हो गई हैं और वह आंतरिक मामलों की ओर अधिक ध्यान सका है। उसकी यह स्थिति देश में प्रजातन्त्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई है।

देश का छोटा आकार

वर्तमान युग में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय प्रणाली सर्वाधिक सफल रूप में स्विट्जरलैंड में इसीलिए चला पा रही है क्योंकि वह एक छोटा पहाड़ी देश है और वहाँ जनता की राय मानना सुगम है। स्विट्जरलैंड छोटे छोटे कंट्रॉल में विभाजित है। अतः वहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले सकते हैं और लोक सभाओं, आरम्भिक एवं जनमत संग्रह के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

सीमित जनसंख्या

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का करोड़ों की जनसंख्या वाले राष्ट्रों में सफल होना सम्भव नहीं है क्योंकि इतनी जनसंख्या में लोक निर्णय और आरम्भिक की सफलता असम्भव है। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या 80 लाख के लगभग है अतः वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का सफल होना आवश्यक की बात नहीं है।

स्पानीय स्वशासन की परम्परा

स्विस प्रजातन्त्र की सफलता का प्रमुख कारण वहाँ की स्पानीय स्वशासन समस्याएँ हैं जिनकी तीन महत्वपूर्ण देन हैं—

(क) दश शासन, (ख) स्पानीय स्वतन्त्रता एवं प्रेम, और (ग) नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा एवं अनुभव।

स्विस प्रजातन्त्र का मूल सिद्धांत है—“पहले कम्प्यून फिर कंट्रॉल और बाद में राज्य मंडल।” वहाँ की राज-सत्ता का आधार स्पानीय स्वायत्त समस्याओं में है और जनता की इच्छा यही से प्रतिबिम्बित होकर ऊपर बढ़ती है।

राष्ट्रीय एकरूपता

स्विट्जरलैंड में विविध भाषाओं, धर्मों और जातियाँ पायी जाती हैं, फिर भी यहाँ राष्ट्रीय एकता विद्यमान है, विविधता में एकरूपता मौजूद है। धर्म और भाषाएँ स्विस राष्ट्रीय एकरूपता के माध्यम में बाधक नहीं हुई हैं। पर्यवर्तन की प्रवृत्तियाँ प्रजातन्त्र के लिए मददगार होती हैं, लेकिन स्विज प्रजातन्त्र इस अभिप्राय से मददगार नहीं रहा है।

अन्य कारण

प्रथम, पुनर्गठित राजनीतिक दल अस्तित्व में प्रजातन्त्र को प्राप्ताहित करते हैं किन्तु स्विट्जरलैंड में ऐसा दल का अभाव है प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के विकास का बड़ा मित्र है।

द्वितीय, स्विस् निवासियों में आर्थिक अंतर बहुत कम है। आर्थिक विषमता के न होने से उनमें वैमनस्य नहीं रहता। देश की सामाजिक और आर्थिक समानता स्विस् जनता को एकता के सूत्र में बाधती है।

तृतीय, स्विट्जरलैंड हजारों वर्षों से एक स्वाधीन देश रहा है, अतः यहाँ की जनता की प्रवृत्ति स्वतन्त्र रहने की है। इसीलिए उनमें सहवासिता, उदारता और उत्तरदायित्व की भी भावना है जिनके द्वारा ही स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है। इस स्वतन्त्र भावना ने ही स्विट्जरलैंड की प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली को विशिष्ट रूप दिया है।

चतुर्थ, स्विट्जरलैंड में भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं। उनकी भाषायें और उनके रीति रिवाज सभी कुछ परस्पर भिन्न हैं। अतः वे प्रशासन पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में नहीं रहते और शक्तियों का केन्द्रीयकरण न करके विकेन्द्रीयकरण से ही प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की नींव जमाते हैं।

स्विट्जरलैंड में अस्तुतः विशिष्ट दशा में प्रजातन्त्र है। आज ससार में प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक पद्धति का वह एक अनुकरणीय आदर्श बना हुआ है और उसे ससार के सभी देशों का विपुल सम्मान प्राप्त है।

EXERCISES

Chapter I

- 1 Trace the history of the Constitutional Development of Switzerland since 1798

1798 से स्विट्जरलैण्ड के नवैधानिक इतिहास का वर्णन कीजिये।

- 2 What do you regard as the special features of the Swiss Constitution ? To what extent have they contributed to the establishment and efficiency of the Government of Switzerland ?

आपके मत में स्विस् संविधान की विशेषताएँ क्या हैं ? क्या तक उ होने स्विट्जरलैण्ड में सरकार को स्थिरता और कुशलता प्रदान की है ?

Chapter II

- 1 "Swiss Constitution is not a confederation but a federation " Do you agree ?

"स्विस् संविधान एक राज्य मण्डल नहीं, संघ है।" क्या आप इससे सहमत हैं ?

- 2 Bring out the special features of the Swiss Federal System and describe the relationship between the Federal Government and the Cantons

स्विस् संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिये और बतलाइये कि संघ सरकार और कंटन में क्या सम्बन्ध है ?

- 3 Describe the method of amendment of the Swiss Constitution How is Constitution amended ?

स्विट्जरलैंड ने संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। स्विस् संविधान में संशोधन किम प्रकार किया जाता है ?

Chapter III

- 1 Describe the composition and functions of both the Houses of the Federal Assembly of Switzerland

स्विस् संघीय सभा के दोनों सदनों में संसदन तथा न्यायो का वर्णन कीजिये।

- 2 What limitations have been imposed on the supremacy of the Federal Assembly ? Compare and contrast the powers and position on the Swiss Federal Assembly with that of the British Parliament

संघीय मभा की सर्वोच्चता पर कौन-कौन से प्रतिबन्ध हैं ? स्विस् संघीय सभा की शक्ति और स्थिति की तुलना ब्रिटिश संसद से कीजिये ।

Chapter IV

- 1 Discuss the unique character of the Swiss Federal Executive How far does it combine stability with responsibility ?

स्विस् संघीय कार्यपालिका की विशेषताओं की विवेचना कीजिये । यह स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व का किस प्रकार समन्वय करती है ?

- 2, "The Swiss Federal Executive is neither Parliamentary nor Presidential" Discuss

"स्विस् संघीय कार्यपालिका न तो संसदात्मक है, न अध्यक्षतात्मक ।" विवेचना कीजिये

- 3 Describe the composition and powers of the Swiss Federal Council (Plural Executive)

स्विस् संघीय परिषद के संघटन और उनकी शक्तियों का वर्णन कीजिये ।

Chapter V

- 1 Describe the organisation and jurisdiction of the Federal Judiciary in Switzerland

स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के संघटन एवं न्याय क्षेत्र की विवेचना करें ।

- 2 Compare and contrast the Swiss Federal Tribunal and the American Supreme Court

स्विस् संघीय न्यायालय तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बीच समता तथा अन्तर उल्लेख करें ।

Chapter VI

- 1 Describe the Party organisation in Switzerland Why in Switzerland parties play a far inferior role to that of a party in England or the U S A ?

स्विट्जरलैंड के दल संगठन का वर्णन कीजिये। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड या या अमेरिका की अपेक्षा दलों का महत्त्व क्या कम है ?

- 2 Critically examine the characteristics of the Swiss party system

स्वयं दल-पद्धति की विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।

Chapter VII

- 1 What do you understand by Direct Democracy ? Write a short essay on its working in Switzerland

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र से आप क्या समझते हैं ? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की क्रियाविधि पर एक छोटा-सा निबंध लिखिये।

- 2 Examine the working of Direct Democratic checks in Switzerland How far they are successful ?

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक अवरोधों की समीक्षा कीजिये। यह कहाँ तक सफल हुआ है ?

SELECTED READINGS

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Banjour | A short History of Switzerland |
| 2 Brooks | Government and Politics of Switzerland |
| 3 Bryce | Modern Democracies |
| 4 Rappard | The Government of Switzerland |
| 5 Coddings | The Federal Government of Switzerland |
| 6 Hughes | The Federal Constitution of Switzerland |
| 7 Huber | How Switzerland is Governed ? |
| 8 Buell | Democratic Governments in Europe |
| 9 Ghosh, R C | The Government of the Swiss Republic, 1953 |
| 10 Lloyd and Holson | The Swiss Democracy |
| 11 Lowell, A L | Government and Parties of Continental Europe, 1918 |
| 12 Banjour | Real Democracy in Operation |
| 13 Munro | Governments of Europe |
| 14 Shotwell and Others | Governments of Continental Europe |
| 15 Theghes | The Federal Constitution of Switzerland |
| 16 Wheare | Federal Government |
| 17 Mason | Foreign Governments |
| 18 Olg and Zink | Modern Foreign Governments |

- | | |
|------------|--|
| 19 Strong | Modern Political Constitutions |
| 20 Zurcher | Governments of Continental Europe |
| 21 Banjam | : Real Democracy in Operation |
| 22 Rappard | : American Political Science Review,
1924 The Initiative and Referen-
dum |
| 23 Rappard | : Political Science Quarterly, June
1925 Democracy Vs Demogogy :
The Swiss Referendum and Confis-
catory Taxation |
-

“सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में लगे हुए लोग कुछ ऐसे स्तर और निरिक्त सम्बन्ध स्थापित कर बैठते हैं जो उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते। ये उत्पादन सम्बन्ध भौतिक शक्तियों की एक विशेष अवस्था से मिलते-जुलते हैं। इन्हीं सम्बन्धों के योग से समाज के आर्थिक ढाँचे और प्रणाली का निर्माण होता है। समाज का यही आधार है जिस पर कानून और राजनीति का भवन बनता है।”

—कार्ल मार्क्स

“यही सोवियत राष्ट्र में—धर्मिकों के आतंकवादी देश में—यह तथ्य कि एक भी महत्वपूर्ण राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रश्न का निराकरण हमारे सोवियत तथा अन्य जन-राष्ट्रवादी पार्टियों से निर्देश प्राप्त किये बिना नहीं करती पार्टियों के सर्वोच्च नेतृत्व की अभिव्यक्ति समझना चाहिये।”

—स्टालिन

रूस के संविधान का विकास व उसकी विशेषताएँ (GROWTH AND SALIENT FEATURES OF THE RUSSIAN CONSTITUTION)

सोवियत रूस की राजनतिक व्यवस्था मनोखे ढंग की है। समाजवाद के आधार पर निर्मित होने के कारण यह अन्य देशों की शासन-व्यवस्था से बहुत कुछ भिन्न है। यद्यपि गत वर्षों में उसके बारे में काफी लिखा गया है, तथापि आज भी यह एक पहेली (An Enigma) है। वर्षों के अस्तित्व के बाद भी सोवियत शासन-व्यवस्था का सही और सन्तुलित चित्र प्रस्तुत करना एक जटिल समस्या है। फिर भी सरकारी प्रलेखों घोषणाओं विदेशी भ्रमणकारियों द्वारा लिखित पुस्तिका, रूस से भागे हुए मरणाधिकियों के विवरणों शोध संस्थाओं द्वारा किये गये शोध कार्यों, विद्वानों की व्याख्याओं आदि के आधार पर सोवियत शासन-व्यवस्था की बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा चुकी है। इनके अलावा समाजशास्त्रीय तत्व भी सोवियत शासन व्यवस्था के समझने में सहायक है।

सोवियत रूस एक महान् देश है। यह आस्ट्रेलिया तथा यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह देश बारह समुद्री और बारह देशों से घिरा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण की स्थलीय सीमा के कारण ही इसकी अतीत में नपोलियन और हिटलर जैसे आक्रामकों का सामना करना पड़ा था, यद्यपि आज यह भय समाप्त-सा हो गया है क्योंकि सीमावर्ती देश इसके ही अनुयायी हैं।

रूस का क्षेत्रफल 87,07,870 वर्गमील है जो विश्व के लगभग 1/6 भू भाग पर फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल यू० एस०ए० के क्षेत्रफल से ढाई गुना, भारत के क्षेत्रफल से आठ गुना और ब्रिटेन के क्षेत्रफल से 100 गुना अधिक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से रूस का विश्व में तीसरा स्थान है। इसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग साठ इक्कीस करोड़ है।

भौतिक साधनों की बहुलता की दृष्टि से भी रूस का विशाल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश प्राकृतिक साधनों की दृष्टि में बहुत ही धनी है। यहाँ हर प्रकार की जलवायु वाला भू-भाग पाया जाता है। हर प्रकार की उपज होती है और प्रायः सभी प्रकार के पशु मिलते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इस देश

जापान युद्ध (1904-1905) में रूस की पराजय ने रूसी निरंकुश शासकों के मान को एक गम्भीर ठेस पहुँचाई।

साम्राज्यीय शासन (1905-15)

सन् 1905-6 में रूस में एक ऐसी क्रांति हुई कि जार को कुछ सुविधायें दान और एक प्रकार की बयानिक सरकार की स्थापना करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगस्त, 1905 में जार को एक घोषणा पत्र निकालना पड़ा और 'इसके द्वारा व्यक्ति के शरीर, आत्मा, वाणी, सम्पदा तथा मुक्त व्यवहार के वास्तविक अधिकारों के आधार पर' जनता को नागरिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई। मई सन् 1906 में ससद् (Duma) का पहला अधिवेशन बुलाया गया जिसे जुलाई में बिना कोई नियम लिये ही विघटित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मत प्रबल हो गया। फलतः दूसरी ससद् का चुनाव हुआ। इस ससद् को भी शीघ्र ही भग होना पड़ा, क्योंकि जार शक्ति देने के लिए तयार नहीं था। सब और रोष फैला और तृतीय ससद् (Duma) का निर्माण किया गया। शासन की दृष्टि से यह ससद् कुछ सफल सिद्ध हुई। फलतः यह अपने पूरा पांच वर्ष के कार्य काल तक अपना कार्य करती रही। तब चतुर्थ ससद् का निर्माण हुआ जो प्रथम महायुद्ध तक कार्य करती रही। चतुर्थ ससद् भी जनता की सन्तुष्टि के लिए कुछ न कर सकी और जारशाही का उल्लाह फटने के लिए रूस के अन्दर और बाहर क्रांतिकारी शक्तियाँ प्रबल होती गईं। इन परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में आरम्भ हुआ। रूस ने जर्मनी के साथी आस्ट्रिया के विरुद्ध सर्बिया के पक्ष का समर्थन किया। जर्मनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। युद्ध रूस की जनता में लोकप्रिय नहीं हुआ। जन समूह के वृष्ट बढ़ गए और 1916 के अन्त तक तो स्थिति बहुत ही बिगड़ गई।

क्रांति एवं सवहारा वग के अधिनायकत्व की स्थापना

शासन की ओर से किसी उद्धार की संभावना नहीं देखकर अन्त में ड्यूमा (Duma) ने कदम उठाये। जार को राज्य छोड़कर चले जाने की माँग दी गयी ल्वोव (Lvov) के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया जिसने अनेक मुषारों की घोषणा की और यह उद्देश्य घोषित किया कि वह रूस में ससदीय प्रकार के लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहती है। लेकिन इन सब दायित्वों को पूरा करने की सामर्थ्यता इस अस्थायी सरकार में नहीं थी।

इसी समय अप्रैल 1917 में लेनिन ने समाजवादी क्रांति का नारा बुलन्द किया। उसने अस्थायी सरकार को अमान्य घोषित करत हुए यह माँग की कि सैनिका को शान्ति मिल, कृषकों को खेतों की भूमि मिले। श्रमिका को कारखाना प्राप्त हो और सम्पूर्ण शक्ति पंचायतों में निहित हो। लेनिन के नारे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। यद्यपि उसे कुछ दिनों के लिये रूस छोड़ कर बाहर जाना पड़ा परन्तु क्रांति बुझी नहीं प्रभुत्व निरन्तर आगे बढ़ती ही रही। इसी मध्य करेन्सकी नायक मार्शालिक

की धरती में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वस्तुतः सोवियत संघ एक सर्वसम्पन्न और आत्मनिर्भर राष्ट्र है।

यह देश विविध जातियों, धर्मों और भाषाभाषा का घर है। इन सब में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव डाला है। रूस में लगभग 187 विभिन्न जातियाँ (Nationalities) हैं। यहाँ अनेक धर्म हैं जिनमें इसाई, इस्लाम, बौद्ध और यहूदी प्रमुख हैं। लगभग 147 भाषाएँ बोली जाती हैं। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि सोवियत सरकार के लिए विविध जातियाँ भाषाभाषा और धर्मों को एक प्रशासन के अधीन बनाए रखना सदैव गम्भीर सिरदर्द रहा है। फिर भी साम्यवादी सरकार ने एक राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था की सीमाओं के अन्तर्गत इन्हें सांस्कृतिक स्वायत्ता (Cultural Autonomy) देकर राष्ट्रीयता की समस्या को हल किया है। सोवियत सरकार एक बहु-राष्ट्रीय (Multi national) अथवा अंतराष्ट्रीय (Unmultinational) राज्य निर्मित करने में सफल हुई है।

यह भी एक प्रशंसनीय तथ्य है कि सोवियत शासन-व्यवस्था आज भी अतीत से सम्बन्ध जोड़े हुए है। भूतकालीन जारों की निरंकुशता की छाया साम्यवादी दल के अधिनायकत्व के दण्ड में प्रतिबिम्बित होती है। जारकालीन रूस की भाँति सोवियत रूस की नीति, अप्रत्यक्ष उपनिवेशीकरण की अर्थात् भगल-बगल के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने की है। जारों के समान ही आज भी साम्यवादी नेता जनता को अंधेरे में रखने की- चेष्टा करते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 'अंधेरे अतीत' (Dark past) के कारण ही रूस में साम्यवादी प्रयोग सफल बन सका है। रूसी शासन व्यवस्था का अभिनव प्रयोग इस दृष्टि से बहुत ही सफल कहा जाएगा कि आज विश्व की भावी जनसंख्या साम्यवादी सिद्धांत के प्रभाव क्षेत्र में है।

संविधान की पृष्ठभूमि और उसका विकास (Background and Development of the Constitution)

सोवियत रूस के संवैधानिक इतिहास को संविधान की दृष्टि से हम निम्न-लिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं—

जारों का निरंकुश शासन (1700-1905)

1905 ई० के पूर्व रूस में जारों का निरंकुश शासन था। रूस की जनता पिछड़ी हुई थी और शासन में उसका कोई हाथ नहीं था। महान् पीटर और कैथरीन के गौरवपूर्ण कार्यो के होते हुए भी सामान्य जनता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अलक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में कुछ क्षेत्रों में सामान्य सुधार किये गये किन्तु रूसी-शासन की निरंकुश भावना बची रही। 1881 में अलक्जेंडर द्वितीय को बम्ब से मार दिया गया। उस समय देश में औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) का शीतलण्डन हुआ, किन्तु अलक्जेंडर तृतीय के काल में कोई प्रगति नहीं हुई और जनता गरीबी एवं निरंकुश शासन की चक्की में पिसती रही।

द्वितीय के शासनकाल में घटनाओं ने एक गम्भीर मोड़ दिया। रूस-

जापान युद्ध (1904-1905) में रूस की पराजय ने रूसी निरंकुश शासक के मान का एक गम्भीर टेंस पहुँचाई।

साम्राज्य शासन (1905-15)

सन् 1905-6 में रूस में एक ऐसी क्रान्ति हुई कि जार को कुछ सुविधायें देने और एक प्रकार की बौयानिक सरकार की स्थापना करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रगस्त, 1905 में जार को एक घोषणा पत्र निकालना पड़ा और "इसके द्वारा व्यक्ति के गरीब, आत्मा वाली समुदाय तथा मुक्त व्यवहार के वास्तविक अधिकारों के आधार पर" जनता की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मई सन् 1906 में ससद् (Duma) का पहला अधिवेशन बुलाया गया जिसे जुलाई में बिना कोई नियम लिये ही विघटित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मत प्रबल हो गया। फलतः दूसरी ससद् का चुनाव हुआ। इस ससद् का भी धीघ्र ही अंग होना पड़ा क्योंकि जार शक्ति देने के लिए तैयार नहीं था। सब और राय फला और तृतीय ससद् (Duma) का निर्माण किया गया। शासन की दृष्टि से यह ससद् कुछ सफल सिद्ध हुई। फलतः यह अपने पूरे पांच वर्ष के कार्य काल तक अपना कार्य करती रही। तब चतुर्थ ससद् का निर्माण हुआ जो प्रथम महायुद्ध तक कार्य करती रही। चतुर्थ ससद् भी जनता की सन्तुष्टि के लिए कुछ न कर सकी और जारशाही का उखाड़ फकने के लिए रूस के अंदर और बाहर क्रान्तिकारी शक्तियाँ प्रबल होती गईं। इन परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में आरम्भ हुआ। रूस ने जर्मनी के साथी आस्ट्रिया के विरुद्ध सर्बिया के पक्ष का समर्थन किया। जर्मनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। युद्ध रूस की जनता में लोकप्रिय नहीं हुआ। जन समूह के मूँट बढ़ गए और 1916 के अन्त तक तो स्थिति बहुत ही बिगड़ गई।

क्रांति एवं सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना

शासन की ओर से किसी उद्धार की संभावना नहीं देखकर अंत में ड्यूमा (Duma) ने बंदम उठाये। जार को राज्य छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गयी ल्वोव (Lvov) के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया जिसने अनेक सुधारों की घोषणा की और यह उद्देश्य घोषित किया कि वह रूस में ससदीय प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। लेकिन इन सब दायित्वों को पूरा करने की सामर्थ्यता इस अस्थायी सरकार में नहीं थी।

इसी समय अप्रैल 1917 में लेनिन ने समाजवादी क्रांति का नारा बुलंद किया। उसने अस्थायी सरकार को अमान्य घोषित करते हुए यह मांग की कि सैनिका को शान्ति मिले, कृषकों को खेती की भूमि मिले। थर्मकों को कारखाना प्राप्त हो और सम्पूर्ण शक्ति पंचायतों में निहित हो। लेनिन के नारे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। यद्यपि उसे कुछ दिनों के लिये रूस छोड़ कर बाहर जाना पड़ा परन्तु क्रांति बुझी नहीं प्रश्रुत निरंतर आगे बढ़ती ही रही। इसी मध्य करेसकी नामक में शविक

नेता ने शासन या नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, परन्तु वह भी जन प्रादोलन को दबाने में सफल न हो सका।

सितम्बर 1917 में लेनिन वापिस रूस लौट आया। आते ही उसने क्रान्ति में नवजीवन फूँक दिया। अस्थायी सरकार का पतन हो गया और शासन की बागडोर लेनिन तथा उसके बोल्शेविक (Bolshevik) दल के हाथों में आ गयी। लेनिन ने उस संविधान निर्मात्री सभा को भंग कर दिया जिसकी स्थापना अस्थायी सरकार ने संसदीय शासन का संविधान बनाने के लिए की थी। लेनिन की दृष्टि में ऐसा करना क्रान्तिकारी अधिनायकत्व (Revolutionary Dictatorship) की स्थापना के लिए आवश्यक था। इसी तरह भक्तवर, 1917 की क्रान्ति के फलस्वरूप रूस में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व (Dictatorship of the Proletariat) की स्थापना हुई। इस क्रान्ति की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी सच्चे जन प्रादोलन को दमनकारी उपायों से कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन सदैव के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। जन भावनाओं का ज्वालामुखी जब अपना महा विस्फोट करता है तो निरकुश से निरकुश सत्ता भी उसके सामने अपना अस्तित्व खो बैठती है।

संविधान निर्माण-काल (1918-1935)

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व ने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद एक और नया अपनी विरोधी शक्तियों को समाप्त करने का कार्य किया और दूसरी ओर देश में स्थायित्व लाने का दृष्टि से समाजवादी संविधान का मसविदा तैयार किया जो समस्त सोवियतों की 5वीं अखिल रूसी कांग्रेस (Fifth All Russian Congress of Soviets) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस कांग्रेस ने रूसी समाजवादी सोवियत सोवियत गणराज्य (Russian Socialist Federative Soviet Republic) के इस संविधान को स्वीकार किया और उसकी घोषणा 10 जुलाई सन् 1918 को कर दी गई।

सन् 1918 के संविधान के अनुसार रूस का शासन 6 बंध चला। इस अवधि में नवीन व्यवस्था की जड़ें मजबूती से जम गईं और यह भय जाता रहा कि प्राचीन व्यवस्था की स्मृति पुनः सिर उठा सकेगी। इसी मध्य ट्रांसकाकेशिया (Transcaucasia) बाइलो रूस (Byelo-Russia) तथा यूक्रेन (Ukraine) नामक तीन अलग-अलग क्षेत्र भी सोवियत संघ में सम्मिलित हो गये और जुलाई 1923 में प्राचीन संविधान के आधार पर एक नवीन संविधान का निर्माण किया गया जो जनवरी, 1924 में लागू हुआ। इसका नाम 'सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ' (Union of Soviet Socialist Republic) रखा गया। इस संविधान में राज्य शक्ति के वितरण या विभाजन (Division of Powers) के सिद्धान्त को अपनाया गया और प्रत्येक गणराज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह जब चाहे संघ से अलग हो सकता है। इस संविधान के अनुसार सोवियत संघ कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रेसीडियम एवं पिपुल्स कमिस्सार कॉन्सिल शासन के इन प्रमुख

की स्थापना की गई। सोवियत संघ कांग्रेस में समस्त गणराज्यों की सदस्यता दी गई। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में दो सदना की व्यवस्था की गई— दो यूनियन ऑफ सोवियत्स तथा दो सोवियत ऑफ नेशनलिटीज (The Union of Soviets & the Soviet of Nationalities)। यूनियन ऑफ सोवियत्स जनता का प्रतिनिधित्व करती थी तथा सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होता था। सोवियत ऑफ नेशनलिटीज राज्यों का सदन था और यूनियन ऑफ सोवियत्स की प्रपक्षा कहीं अधिक छोटा था। प्रेसीडियम में 27 सदस्या की व्यवस्था की गई थी। उनमें से 9 सदस्य यूनियन ऑफ सोवियत्स, 9 सोवियत ऑफ नेशनलिटीज तथा दोष 9 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में से चुने जाते थे। पिपुल्स कमिस्सार् कौंसिल (The Council of Peoples Commissar) संघ की कार्यकारिणी का कार्य करती थी। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति करती थी। इस कौंसिल के अध्यक्ष की स्थिति प्रधान-मंत्री के समान थी। स्टालिन इसी पद पर नियुक्त था और इसी कारण वह समस्त सरकारी कार्यों का संचालन करता था।

स्टालिन संविधान (1936)

प्रथम संविधान के समान द्वितीय संविधान का कार्यकाल भी अल्प ही रहा। सन् 1924 के संविधान के अन्तर्गत रूस का शासन केवल 12 वर्ष चला। इस बीच में नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy) और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा रूस ने बहुमुखी उन्नति की और समाज को समाजवादी बनाने के लिए कार्य किया। फलस्वरूप सोवियत संघ समाजवाद की दशा में द्रुतगति से आगे बढ़ा। 7 फरवरी, 1935 को केन्द्रीय कार्यपालिका समिति (Central Executive Committee) ने स्टालिन की अध्यक्षता में 31 सदस्या के एक संविधान-आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग ने संविधान के जिस प्रारूप की रचना की, उसे केन्द्रीय कार्यपालिका समिति के प्रेसीडियम (Presidium) ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् जनमत जानने के लिए उसे प्रकाशित कर दिया गया। संविधान के प्रारूप में लगभग 5,27,000 सभाओं में विचार किया गया, जिनमें लगभग साठे लाख करोड़ लोगों ने भाग लिया। प्रारूप में लगभग 1,54,000 संशोधन प्रस्ताव आये। अन्त में प्रारूप एवं प्रस्तावित संशोधनों पर '8वीं संघीय सोवियत कांग्रेस' ने विचार किया। इस सभा में 2016 प्रतिनिधि थे जो 63 जातियों के थे और जिनमें प्रायः सभी वर्गों के लोग थे। लेकिन सभी सदस्य साम्यवादी विचारधारा के थे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी दल से सम्बन्धित थे। 5 दिसम्बर सन् 1936 को सोवियत कांग्रेस ने 43 संशोधनों के साथ संविधान के इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया जो सन् 1936 का स्टालिन का संविधान कहलाया।

यद्यपि अब तक इस संविधान में अनेक संशोधन किये जा चुके हैं लेकिन उनके कारण संविधान की भावना में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ है। इन संविधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे की पंक्तियों में करेंगे फिर भी यहां इतना जान लेना उचित है कि सोवियत संघीय व्यवस्था और प्रत्यक्षी इकाइयों की शासन व्यवस्था में कई बार परिवर्तन लाये गये हैं और अब सोवियत संघ में पत्र

सघीय गणराज्य शामिल हैं। कुछ समय पूर्व गणराज्यों की संख्या 16 थी किन्तु हाल ही में कोला फिनिश गणतन्त्र को रूसी सघीय समाजवादी गणतन्त्र में मिला लिया गया है।

सोवियत संविधान की विशेषताएँ (Salient Features of the Constitution of U S S R)

विशिष्टी ने सोवियत संघ को एक नये प्रकार का राज्य कहा है। सोवियत संविधान एक अनुपम शासन प्रणाली को स्थापना करता है और विश्व के अन्य संविधानों से कुछ समानता रखते हुए भी अविश्वस्य महत्वपूर्ण अंतर लिए हुए है। इसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ ये हैं—

संविधान का नया अर्थ

रूसी दृष्टिकोण के अनुसार संविधान इस बात का संकेत करता है कि शासन किस माग से होकर चला है। इसके विपरीत अन्य देशों में संविधान यह बताता है कि देश किस पथ पर चले। स्टालिन के शब्दों में—“व्यवहार में जो कार्य कर लिये जाते हैं और जिनमें सफलता मिल सकती है संविधान उसी को पजीबद्ध करने या वैधानिक रूप देने का कार्य करता है।”

संविधान सम्बंधी इस दृष्टिकोण के कारण सोवियत संविधान और अन्य संविधानों में बड़ा अंतर आ गया है—(क) अन्य देशों में एक ही संविधान कुछ संशोधनों के साथ दोष समय तक चलता रहता है जब कि रूस में सामाजिक प्रगति के अनुरूप संविधान भी परिवर्तित होता जाता है। (ख) अन्य देशों में संविधान एक आदर्श को प्रस्तुत करता है। संविधान को अति पवित्र माना जाता है और उसकी पुरातनता उसके सम्मान का बढ़ाती है किन्तु सोवियत संविधान गन्तव्यमूलक है और उसकी प्राचीनता विशेष आदर की वस्तु नहीं है। रूस में प्रतिवर्ष ही संविधान कुछ न कुछ बदलता रहता है। (ग) पाश्चात्य एवं अन्य प्रजातांत्रिक संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और शासन की शक्तियाँ को सीमित करने के उद्देश्य से बने हैं जबकि सोवियत संविधान में मार्क्सवादी सर्वोच्चारिथ्या की तानाशाही को बदन देने के लिये सरकार में शक्ति का अक्षीयकरण दिखाई देता है।

लिखित स्वरूप

अमेरिकन संविधान की भांति सोवियत संविधान भी छद्म-भा प्रत्यक्ष है, जिसमें सामाजिक ढांचे ज्ञान के विभिन्न अंग एवं उनकी शक्तियाँ, नागरिकों के अधिकार और वक्तव्यों, राज्य के स्वरूप आदि का विवरण है। इसमें कुल 13 अध्याय (Chapters) 147 धाराएँ (Articles) और दो परिशिष्ट (Appendices) हैं।

कम अचल संविधान

सोवियत संविधान अचल (Rigid) होता है यही उतना बलशाली नहीं है जितना अमेरिकन संविधान का संविधान है। यह कमजोर दृष्टि से अचल है कि संविधान कम

संघाधन से सम्बन्धित कानूनों को पारित होने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) के दोनों सदनों का दो-तिहाई बहुमत उद्देश्य स्वीकार करे। रूसी संविधान का ऋण वस्तु परिवर्तनशीलता की ओर है। संघाधिक संघोपनों के प्रस्तुतीकरण (Initiation) और उनके पारित होने की विधियाँ पर विचार करने से रूसी संविधान की वह परिवर्तनशीलता पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी।

प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से रूस में संघोपन सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सदन के निर्दिष्ट बहुमत के द्वारा प्रस्तुत किया जाये। इसके प्रतिरिक्त संघोपन को प्रस्तावित करने के विषय में संघ की इकाइयों को कोई अधिकार नहीं है।

संघोपन के अन्तिम रूप से पारित होने के लिए रूसी संविधान में केवल यह व्यवस्था है कि संघोपना को व्यवस्थापिका के प्रत्येक सदन के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाये। रूस के संघ में सम्मिलित गणराज्यों को संघोपन के पुष्टिकरण आदि का कोई अधिकार नहीं है। रूस की यह व्यवस्था भारत, अमेरिका और स्विटजरलैंड सभी से भिन्न है।

इस तरह स्पष्ट है कि रूस का संविधान अचल होते हुए भी अचल संविधानों (Rigid Constitutions) में सबसे अधिक लचीला (Flexible) है। साथ ही संविधान की संघोपना सम्बन्धी व्यवस्था एकात्मक (Unitary) राज्य जैसी अधिक प्रतीत होती है, बवनाकि संघ की इकाइयों को न तो संघोपन प्रस्तावित करने का ही कोई अधिकार है और न उसका पुष्टि करने का ही।

सोवियत शासन व्यवस्था की विशेषता यह भी है कि वहाँ पर सामूहिक आवश्यकताओं के अनुरूप बहुधा संविधान के विरुद्ध कार्य भी कर लिये जाते हैं और उन्हें प्रसंघाधिक घोषित नहीं किया जाता, प्रत्युत उनके अनुरूप बाद में संविधान में, यदि आवश्यक समझा जाता है तो संघोपन कर लिया जाता है।

समाजवादी लोकतन्त्रात्मक संविधान

रूसी संविधान द्वारा एक समाजवादी लोकतन्त्र (Socialist Democracy) की स्थापना की गई है जिसमें राज्य और समाज को उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर अपना स्वामित्व रखना है और उनका प्रयोग समाज के लिए इस तरह करना है कि अधिक समानता पर आधारित एक वगन्हीन समाज की स्थापना हो सके, जिसमें न कोई शोषक हो न शोषित, न कोई पूँजीपति हो न श्रमिक और सभी को कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो तथा सभी की जीवन की सुविधाओं की समानता उपलब्ध हो।

सामाजिक समानता से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने की दृष्टि से ही रूस के संविधान में उन विविध बातों की चर्चा नहीं की गई है जिसके कारण लोकतन्त्र प्रायः सामाजिक असमानता के शिकार हुए हैं। उदाहरणार्थ रूसी संविधान जनता की प्रभुता (Sovereignty of the people) की चर्चा

करता। साम्यवादी नेताओं की मायता है कि जनता की प्रभुसत्ता की ग्राह्य मन्त्री लोग निधना के मतों का खरोद लेते हैं और इस तरह जन प्रभुसत्ता के स्थान पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। रूसी संविधान जनता की प्रभुसत्ता के स्थान पर श्रमिकों और कृषकों की प्रभुसत्ता (Sovereignty of the workers and peasants) की चर्चा करता है, क्योंकि सच्ची समाजवादी व्यवस्था में प्रभुसत्ता का उन्हीं के हाथों में रहना आवश्यक है।" संविधान के व्यवहारोपकरण से श्रमिक वर्ग के हाथों में ही सत्ता की बागडोर है और राज्य संचालन का कार्य श्रमिक वर्ग के द्वारा ही सम्पादित होता है। संविधान की विभिन्न धारारें इस व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान करती हैं।

रूसी संविधान में सम्पत्ति के उस व्यक्तिगत अधिकार की भी बात नहीं की गई है जिसके कारण पूँजीवाद का प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत रूसी संविधान में उत्पादन के साधनों, उनके स्वामित्व और वितरण की व्यवस्था का संचालन समाज द्वारा एवं समाज के लिए किये जाने की बात कही गई है।

रूस में उत्पादन के साधनों पर स व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर देना यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वहाँ लोगों के पास ऐसी कोई वस्तु हो नहीं होनी जिस वे अपनी कह सकें। वस्तुतः वहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार का रूप अत्यन्त सीमित है। यद्यपि लोगों को अपनी व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत बचत और घर की अन्य वस्तुओं पर अधिकार है तथा इन चीजों को लोग उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त भी करते हैं पर सोवियत शासन व्यवस्था सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार की ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती जो पूँजी के एकाधिकार को प्रोत्साहित करे और समाज को शोषक व शोषिता के विरोधी वर्गों में विभाजित करे। रूस की अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय आर्थिक आयोजना (National Economic Plan) द्वारा निर्दिष्ट और निर्देशित की जाती है जिसका उद्देश्य जन सम्पत्ति को बढ़ाना जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक-स्तर को ऊँचा उठाना तथा प्रति रसात्मक समृद्धि का दृष्टिशील बनाना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संविधान एक ऐसे समाजशास्त्री लोरेन्स की स्थापना करता है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक समानता व वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राजनीतिक नागरिकों की स्थापना की दृष्टि से भा संविधान वर्तमान समय लोकतन्त्रात्मक संविधानों में प्रथम है। रूसी संविधान का 136 वाँ धारा में नागरिकता मतदाताधिकार (Universal Suffrage) की व्यवस्था है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि "प्रत्येक नागरिक का एक मत का अधिकार है और सभी नागरिक निर्वाचन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है।" दूसरा महत्वपूर्ण धारा 137 स्त्रियाँ के मतदाताधिकार का स्पष्ट करता है— "पुरुषों व स्त्रियों को भी किसी भी पुनर्निर्वाचन का अधिकार है और स्वयं व पुनर्निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है।" रूसी संविधान नागरिकता का विचार नागरिकता और नागरिकता के अधिकारों के आधार पर नहीं प्रदान करता है। नागरिकता के इन अधिकारों का आधार नागरिकता का अधिकार ही प्रदान करता है। नागरिकता के इन अधिकारों का आधार नागरिकता का अधिकार ही प्रदान करता है।

है यह एक भिन्न बात है, लेकिन कानूनी रूप से सोवियत संविधान एक राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की होड़ में पीछे नहीं है।

विचित्र संसदीय व्यवस्था

सोवियत संविधान संसदीय शासन-व्यवस्था का रूप कुछ विचित्र है। शासन प्रमुख (Head of Government) का रूप सामुदायिक (Collective) व बहुल (Plural) है, जिसे सामुहिक रूप से प्रेसीडियम (Presidium) कहा जाता है। यह प्रेसीडियम दुनिया की सभी संस्थाओं में एक अनोखी संस्था है। इसमें 33 सदस्य होते हैं जो पद एवं शक्ति की दृष्टि से उसी प्रकार समान होते हैं जिस प्रकार कि स्विस संघीय परिषद् (Swiss Federal Council) के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम केवल वधानिक अथवा नाममात्र की ही शासन प्रमुख नहीं होती, अपितु देश के शासन संचालन में सक्रिय भाग लेती है।

मंत्रिमण्डल की रचना की दृष्टि से भी रूस संसदीय व्यवस्था विचित्रता लिए हुए है। रूस में मंत्रिमण्डल दो प्रकार के होते हैं—संघीय मंत्री (Union Ministers) और गणतन्त्रीय मंत्री (Union Republic Ministers)। संघीय मंत्री संघीय विषयों का प्रबंध करते हैं जो संघ का इकाईयों के अधिकार क्षेत्र के होते हैं। गणतन्त्रीय मंत्री वस्तुतः संघीय सरकार और गणतन्त्रों की सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। रूसी मंत्रिमण्डल का यह रूप विश्व में अनोखा है। -

इसी संसदीय व्यवस्था की तीसरी विचित्र बात यह है कि लोकसेवा के सदस्य भी कभी नहीं सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) के सदस्य हो जाते हैं और उन्हें भी अपने कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था का यह रूप हमें अचानक देखने को नहीं मिलता।

जनतन्त्रात्मक के द्वावे

सोवियत शासन-प्रणाली जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद (Democratic Centralism) के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् जनतन्त्र और केन्द्रीयकरण की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय किया गया है। जनतन्त्रवादी पुट यह है कि नागरिकों का प्राशासनिक कार्यों में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। नागरिक उत्पादक, उपभोक्ता, और साम्यवादी दल का सदस्य इन चार रूपों में एक ही व्यक्ति को यह अवसर मिलता है, कि वह शासन के सम्पर्क में आ सके और उनकी भागीदारी कर सके। सोवियत संघ के अन्तर्गत नागरिकों को विचार-विमर्श वाद विवाद एवं आलोचना प्रत्यालोचना की पूर्ण स्वतन्त्रता है परन्तु यह जनतन्त्र केवल यही पर समाप्त हो जाता है क्योंकि रूस में प्रत्येक शासन अथवा पार्टी का अङ्ग अपने उच्च अङ्ग के अधीन है। उसका अर्थ उसी सीमा तक विचार विमर्श और वाद विवाद करने की स्वतन्त्रता होती है जिस सीमा तक उस पर उच्च अङ्ग प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न स्तर के अङ्ग को चाहे वह दल का हो या सरकार का—अपने उच्च स्तर अंग की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार अन्त में सर्वोच्च राज्य शक्ति एक केन्द्रीय बिंदु में जाकर निहित हो जाती है।



संस्कृतियों के जन-समूह अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा और वृद्धि कर सके। सांस्कृतिक धारा पर ही संघीय इकाइयाँ अपने अपने स्तर के अनुरूप विविध नामों से पुकारी गई हैं। उदाहरणार्थ, सांस्कृतिक दृष्टि से जो सब उन्नत इकाइयाँ हैं उन्हें संघीय गणतन्त्र (Union Republics) कहा गया है। उनसे कम उन्नत इकाइयों से स्वाशासित गणतन्त्र (Autonomous Republics) कहा जाता है। इससे भी कम उन्नत इकाइयों को स्वाशासित प्रदेश (Autonomous Regions) और सब से कम उन्नत इकाइयाँ को राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas) की संज्ञा दी गई है। इसी वजह से अनेक इकाइयों के नाम भी उनकी राष्ट्रीयताओं के नाम पर रखे गये हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन सोवियत समाजवादी गणतन्त्र (Ukrainian Soviet Socialist Republic) उन लोगों का गणतन्त्र है जो यूक्रेनियन जाति के हैं। ठीक इसी प्रकार उजबेक जाति के गणतन्त्र को उजबेक सोवियत समाजवादी गणतन्त्र (Uzbek Soviet Socialist Republic), ताजिक जाति के गणतन्त्र को ताजिक सोवियत समाजवादी गणतन्त्र (Tajik Soviet Socialist Republic) आदि कहा गया है। यही नहीं संविधान द्वारा इन गणतन्त्रों के इस अधिकार को भी मायता दी गई है कि वे केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में भलग अपने-अपने प्रतिनिधि भेजें। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन के लिए संघीय गणतन्त्र (Union Republics) 25, स्वाशासित गणतन्त्र (Autonomous Republics) 11 स्वाशासित शासन-प्रदेश (Autonomous Regions) 5 और राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas) 1 प्रतिनिधियाँ का भेजते हैं। सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए ही रूस में यह व्यवस्था है कि किसी भी प्रदेश पर दूसरे प्रदेश की भाषा नहीं बोली गई है, वरन् सभी गणतन्त्रों की भाषा सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस समय सम्पूर्ण रूस में लगभग 110 भाषाएँ हैं जिनमें से 70 भाषाएँ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और 16 भाषाओं को राज्य भाषाएँ स्वीकार किया गया है। राज्य भाषाओं में ही राजकीय प्रशासन कार्य होता है।

उपयुक्त विवरण से प्रगट है कि विभिन्न राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक समुदायों के अनुसार इकाइयों को मायता देकर, उन्हें केंद्रीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में भलग भलग प्रतिनिधित्व प्रदान करके और सबके लिए भाषा सम्बन्धी स्वतन्त्रता की व्यवस्था करके सोवियत संविधान ने राजनीतिक सभ के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय और एक सांस्कृतिक सभ की स्थापना की है।

एक बलीय शासन

सोवियत संविधान की अन्य विशेषता है—एक दलीय व्यवस्था। इस संबंध में दो बातें उल्लेखनीय हैं—साम्यवादी दल की संवैधानिक स्थिति और केवल एक दल की प्रधानता। प्रजातांत्रिक संविधान में राजनीतिक दल एच्छक संगठन होते हैं और संविधान द्वारा उन्हें मायता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। लेकिन, सोवियत संविधान में साम्यवादी दल को मायता प्रदान की गई है।

जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद केवल शासन ट्रेड यूनियनों और उत्पादक एवं उपभोक्तृ साम्यवादों के दल का संगठन भी जनतन्त्रात्मक इसमें भी स्थानीय, क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय संगठनों में केन्द्रित हो जाती है। यद्यपि विविध धाराएँ पाई जाती हैं, परन्तु सब के सब अपने-से-अपने विभिन्न संगठनों के वाद-विवाद और विचार-निर्णय अन्ततः केन्द्रीय संगठन तक पहुँच जाते जाते हैं। ये नियम और आदेश सभी हैं। यही जनतन्त्रात्मक केन्द्रवाद है जिसको हम सामूहिक सत्य की एक निरंकुश, एकात्मक एवं राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सत्य

सोवियत संविधान द्वारा रूस में एक ही स्थापना की गई है। राजनीतिक सत्तात्मकता के संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत आदि सभी संविधानों की धारा 13 में कहा गया है कि "सभी एक सत्तात्मक राज्य हैं जो सोवियत समाजवादी आधार पर निर्मित हुए हैं।" इस तरह वर्धा सत्य वस्तुतः ऐसे गणतन्त्रों का सत्य है जिन्हें उस है। इस दृष्टि से रूस का सत्य अमेरिकन, स्विट्स ए वगैरह इन देशों के संविधानों में सत्तीय इकाइयों नहीं की गई है। सोवियत संविधान में सत्तात्मक रू विरोधताएँ भी विद्यमान हैं। अन्य सभी की भाँति स संविधान है जो सत्तीय सरकार और अवयवी इकाइयों प्रतिरिक्त संविधान द्वारा सत्य एवं इकाइयों के बीच व और इकाइयों को क्षेत्रीय विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदा सोवियत सत्य में कानूनी दृष्टि से सत्तीय प्रणाली की वय है, यह अवयव है कि अमेरिका अथवा भारत के समान व को संविधान का रक्षक और व्याख्याकर्ता नहीं बनाया गया

रूसी संविधान के सत्तात्मक स्वरूप के विषय में यह सत्य का महत्व उसको राजनीतिक सत्तात्मकता (Political कारण जितना है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसकी सांस्कृतिक (ultural Federalism) के कारण है। सोवियत सत्य वास्तव में ए का एक सत्य है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक जन-समूह को पूरी तरह से प्राप्त रहे, इसके लिए रूसी सत्तीय सीमाएँ विविध राष्ट्रीय सांस्कृतिक के अनुसार निर्धारित की गई हैं ता

अधिकारों की समाजवादी व्यवस्था

सोवियत संविधान में भी अग्र देशों के प्रजातान्त्रिक संविधानों की भांति मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता मूलतः इस बात में है कि अधिकारों का रूप केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक भी है तथा यही माना गया है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता। अग्र प्रजातान्त्रिक देशों के विपरीत सोवियत रूस में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्रथम स्थान दिया गया है और नागरिक अधिकारों को गौण। सोवियत संविधान में अग्र अधिकारों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना व्यक्ति के इन अधिकारों पर कि उसे काम करने का निश्चित अवसर प्राप्त हो वह आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहे और भोजन, वस्त्र आवास आदि की बिना न करते हुए अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करे। सोवियत व्यवस्था राज्य पर यह उत्तर दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान करे।

सोवियत अधिकार पत्र की यह भी विशेषता है कि नागरिकों को दिये गये अधिकारों का सवहारा वर्ग के अधिकारों के हितों से न टकराये और उनसे देश की समाजवादी व्यवस्था को आवश्यक बल मिले। एक अग्र विशेषता यह है कि अधिकारों के साथ-साथ संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की भी व्यवस्था है। नागरिकों पर समाज तथा राज्य के प्रति कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य आरोपित किये गये हैं। समाजवाद का निर्वाह विधि का पालन, देश की रक्षा, अनिवार्य सैनिक सेवा, धर्म सम्बन्धी अनुशासन की रक्षा आदि कुछ विशिष्ट कर्तव्य गिनाये गये हैं।

सोवियत नागरिकों को दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है संविधान में इनकी रक्षा के लिए यादिक पुनरावलोकन का अस्तित्व नहीं है। फलस्वरूप कुछ अधिकारों की व्यवस्था अग्र प्रजातान्त्रिक देशों की तुलना में अवास्तविक सी हो गई है। इस सम्बन्ध में टाउम्स्टर (Towster) का तर्क है कि स्वतन्त्रता के क्षेत्र के विषय में रूस और पश्चिमी लोकतन्त्रों में प्रमुख अंतर यह नहीं है कि रूस ने स्वतन्त्रताओं को विल्कुल समाप्त कर दिया है, अपितु यह है कि उनमें से अनेकों का अर्थ अग्र और भाव दे दिया गया है।

जो भी हो सोवियत शासन-व्यवस्था संविधानवाद (Constitutionalism) को एक अनुपम भेद है। यह परम्परागत मानव मूल्यों नतिकता और शासन प्रणालियों के लिए एक चुनौती है जिसकी संरचना अविष्य में मानव इतिहास को एक नयी दिशा में मोड़ सकती है।

एक नवोन्मत्त संविधान की योजना

आज की परिवर्तित परिस्थितियों में सोवियत रूस के राष्ट्रपति के लिए एक नये संविधान का निर्माण करना चाहते हैं अथवा वर्तमान संविधान का मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। इन सम्बन्ध में पहले जनवरी, 1959 में

संविधान के अंतर्गत नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि संविधान द्वारा साम्यवादी दल को देश की राजनीति का प्रमुख दल माना गया है और व्यवहार में रूस में एकमात्र राजनीतिक दल साम्यवादी दल के हाथ में ही समस्त सत्ता है। उसका अनुशासन ऐसा कठोर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और प्रजातन्त्र एक प्रहसन (Farce) मान रह गया है। व्यवहार में साम्यवादी दल ही शासन का सर्वोच्च है। सोवियत संघ में विरोधी आर्थिक बग नहीं है, वहाँ केवल एक ही बग है—सवहारा बग। अतः वहाँ विभिन्न विरोधी दलों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती।

अनोखी 'यायपालिका'

आदर्श सघात्मक संविधानों में यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है, पर सोवियत संविधान में यायपालिका शासन का एक अवीरल्य अंग है। अल्प प्रजातान्त्रिक देशों में यायालय सामान्य नागरिकों के हितों की निष्पक्ष रूप से रक्षा करते हैं, किन्तु सोवियत रूस में यायालयों का सर्वांगीण उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहयोग प्रदान करना है। वहाँ यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे सोवियत शासन के विरोधियों से रोका लें, प्रत्येक कदम नवीन समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ करने वाला उठाये और शासन की सामान्य नीति को कार्यान्वित करने में सहायता करे। सोवियत रूस में अमेरिका के समान, यायालयों को 'यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

एक अन्य विशेषता यह है कि सोवियत यायाधीश निर्वाचित होते हैं। सर्वोच्च यायालय के यायाधीश 5 वर्ष के लिए सर्वोच्च सोवियत द्वारा और निम्नतम यायालयों (People's Courts) के यायाधीश 3 वर्ष के लिए नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रायः उन व्यक्तियों को यायाधीश चुना जाता है जो साम्यवादी दल के अनुयायी होते हैं। मानसवाद का पूर्ण गान रखते हैं और दल के नियमों को कार्यान्वित करने की क्षमता रखते हैं। सोवियत यायालय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं करता है।

सोवियत पद्धति

रूस की संवैधानिक प्रणाली की एक अन्य विशेषता "सोवियत पद्धति" (Soviet System) है। 'सोवियत' शब्द का अर्थ श्रमिका एवं कृषकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक परिषद् से होता है। रूस में ग्राम, नगर, जिला, गणराज्य आदि सभी स्तरों पर 'सोवियत' हैं। वारसना में श्रमिका की और रेजिमेन्टा में सैनिकों का कार्य होता है। ये सोवियत प्रस्तुत रूस की संवैधानिक पद्धति का आधार एवं जनशक्ति के नये उपकरण हैं जिनके माध्यम से सोवियत शासन अपनी नीतियों को कार्यान्वित करता है। इन सोवियतों का शासन-संगठन में कितना

एक व्यापक स्थान है, यह इसी बात में विदित हो जाता है कि इनकी संख्या में लगभग 70 000 या इससे अधिक हैं।

अधिकारों की समाजवादी व्यवस्था

सोवियत संविधान में भी अग्र दशो के प्रजातान्त्रिक संविधानों की भांति मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता भूलतः इस बात में है कि अधिकारों का रूप केवल राजनीतिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक व आर्थिक भी है तथा यही माना गया है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रभावों में राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता। अग्र प्रजातान्त्रिक देशों के विपरीत सोवियत रूस में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्रथम स्थान दिया गया है और नागरिक अधिकारों को गौण। सोवियत संविधान में अग्र अधिकारों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना व्यक्ति के इस अधिकार पर कि उसे काम करने का निश्चित आसुर प्राप्त हो वह आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहे और भोजन, वस्त्र आवास आदि की चिंता न करते हुए अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करे। सोवियत व्यवस्था राज्य पर यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान करे।

सोवियत अधिकार पत्र की यह भी विशेषता है कि नागरिकों को दिये गये अधिकारों के द्वारा वगैरे अधिकारों के हितों से न टकराये और उनसे देश की समाजवादी व्यवस्था को आवश्यक बल मिले। एक अग्र विशेषता यह है कि अधिकारों के साथ-साथ संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की भी व्यवस्था है। नागरिकों पर समाज तथा राज्य के प्रति कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य आरोपित किये गये हैं। समाजवाद का निर्वाह, विधि का पालन, देश की रक्षा, अनिवार्य सैनिक सेवा, धर्म सम्प्रदायों की रक्षा आदि कुछ विनिश्चित कर्तव्य गिनाये गये हैं।

सोवियत नागरिकों को दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है संविधान में इनकी रक्षा के लिए यायिक पुनरावलोकन का अस्तित्व नहीं है। फलस्वरूप कुछ अधिकारों की व्यवस्था अग्र प्रजातान्त्रिक देशों की तुलना में अत्यन्त स्थिर हो गई है। इस सम्बन्ध में टाउमस्टर (Towster) का तर्क है कि 'स्वतंत्रता के क्षेत्र के विषय में रूस और पश्चिमी लोकतन्त्रों में प्रमुख अंतर यह नहीं है कि रूस ने स्वतंत्रताओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, अपितु यह है कि उनमें से प्रत्येक को नवीन अर्थ और भाव दे दिया गया है।

जो भा है सोवियत शासन-व्यवस्था संविधानवाद (Constitutionalism) को एक अनुपम भेंट है। यह परम्परागत मानव मूल्यों नतिकता और शासन प्रणालियाँ के लिए एक चुनौती है जिनकी सफलता अवश्य ही मानव इतिहास का एक नया दिना में मोड़ सकती है।

एक नवीन संविधान की योजना

भाज की परिवर्तित परिस्थितियों में सोवियत रूस के दृग्गोचर देश के लिए एक नये संविधान का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान संविधान को मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पहल जनवरी 1959 में

संविधान के अंतर्गत नागरिका को संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि संविधान द्वारा साम्यवादी दल को देश की राजनीति का प्रमुख दल माना गया है और व्यवहार में रूस में एकमात्र राजनीतिक दल साम्यवादी दल के हाथ में ही समस्त सत्ता है। उसका अनुशासन ऐसा कठोर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और प्रजातंत्र एक प्रहसन (Farce) मान रह गया है। व्यवहार में साम्यवादी दल ही शासन का सर्वोच्च है। सोवियत संघ में विरोधी आर्थिक बाधा नहीं है, वहाँ केवल एक ही वग है—सबहारा वग। अतः वहाँ विभिन्न विरोधी दलों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती।

अनोखी न्यायपालिका

आदर्श सघात्मक संविधानों में न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है, पर सोवियत संविधान में न्यायपालिका शासन का एक अधीनस्थ अंग है। अथ प्रजातांत्रिक दशा में न्यायालय सामान्य नागरिकों के हितों की निष्पक्ष रूप से रक्षा करते हैं, किन्तु सोवियत रूस में न्यायालयों का सर्वाधिक उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहयोग प्रदान करना है। वहाँ न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे सोवियत शासन के विरोधियों से जोड़ा नें प्रत्येक कदम नवीन समाजवादी व्यवस्था को हट कराने वाला उठाये और शासन की सामान्य नीति का कार्यान्वित करने में सहायता करें। सोवियत रूस में अमेरिका के समान, न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

एक अन्य विशेषता यह है कि सोवियत न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5 वर्ष के लिए सर्वोच्च सोवियत द्वारा और निम्नतम न्यायालयों (People's Courts) के न्यायाधीश 3 वर्ष के लिए नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रायः उन व्यक्तियों को न्यायाधीश चुना जाता है जो साम्यवादी दल के अनुयायी होते हैं, मार्क्सवाद का पूर्ण ज्ञान रखते हैं और दल के नियुक्त को कार्यान्वित करने की क्षमता रखते हैं। सोवियत न्यायालय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं करता है।

सोवियत पद्धति

रूस की संवैधानिक प्रणाली की एक अन्य विशेषता “सोवियत पद्धति” (Soviet System) है। “सोवियत” शब्द का अर्थ श्रमिका एवं कृषकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक परिषद से होता है। रूस में ग्रामों, नगरों, जिला, गणराज्यों आदि सभी स्तरों पर “सोवियत” है। कारखानों में श्रमिकों की ओर रेजीमेन्टों में सैनिकों को सोवियत हैं। ये सोवियत वस्तुतः रूस की संवैधानिक पद्धति का आधार एवं जनशक्ति के नये उपकरण हैं जिनके माध्यम से सोवियत शासन अपनी नीतियों को कार्यान्वित करता है। इन सोवियतों का शासन संगठन में कितना महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक स्थान है, यह इसी बात से विदित हो जाता है कि इनकी संख्या रूस में लगभग 70,000 या इससे भी अधिक है।

अधिकारों की समाजवादी व्यवस्था

सोवियत संविधान में भी अन्य देशों के प्रजातान्त्रिक संविधानों की भाँति मौलिक अधिकारों का सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठता मूलतः इस बात में है कि अधिकारों का रूप केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक भी है तथा यही माना गया है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता। अतः प्रजातान्त्रिक देशों के विपरीत सोवियत रूस में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्रथम स्थान दिया गया है और नागरिक अधिकारों को गौण। सोवियत संविधान में अन्य अधिकारों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना व्यक्ति के इस अधिकार पर कि उसे काम करने का निश्चित आसर प्राप्त हो वह आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहे और भोजन, वस्त्र आवास आदि की बिना न करते हुए अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करे। सोवियत व्यवस्था राज्य पर यह उतर दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से रोजगार प्रदान करे।

सोवियत अधिकार-पत्र की यह भी विशेषता है कि नागरिकों को दिये गये अधिकारों सबहारा वग के अधिकारों के हितों से न टकराये और उनसे देश की समाजवादी व्यवस्था को आवश्यक बल मिले। एक अन्य विशेषता यह है कि अधिकारों के साथ-साथ संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की भी व्यवस्था है। नागरिकों पर समाज तथा राज्य के प्रति कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य आरोपित किये गये हैं। समाजवाद का निर्वाह, विधि का पालन, देश की रक्षा, अनिवार्य सैनिक सेवा, धर्म सम्बन्धी अनुशासन की रक्षा आदि कुछ विशिष्ट कर्तव्य गिनाये गये हैं।

सोवियत नागरिकों को दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है संविधान में इनकी रक्षा के लिए यायिक पुनरावलोकन का अस्तित्व नहीं है। फलस्वरूप कुछ अधिकारों की व्यवस्था अन्य प्रजातान्त्रिक देशों की तुलना में अवास्तविक सी हो गई है। इस सम्बन्ध में टाउन्टर (Townster) का तर्क है कि 'स्वतन्त्रता के क्षेत्र के विषय में रूस और पश्चिमी लोकतन्त्रों में प्रमुख अंतर यह नहीं है कि रूस ने स्वतन्त्रताओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है अपितु यह है कि उनमें से अनेक को नवीन अर्थ और भाव दे दिया गया है।'

जो भी हो सोवियत शासन-व्यवस्था संविधानवाद (Constitutionalism) को एक अनुपम भेंट है। यह परम्परागत मानव मूल्यों, नतिकता और शासन प्रणालियों के लिए एक चुनौती है जिम्मेवरी सत्तना अविष्य में मानव इतिहास को एक नयी दिशा में मोड़ सकती है।

एक नवीन संविधान की योजना

आज की परिवर्तित परिस्थितियों में सोवियत रूस के कण्ठधार देश के लिए एक नये संविधान का निर्माण करना चाहते हैं अथवा वर्तमान संविधान को मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पहल जनवरी, 1959 में

श्री लुइचेव द्वारा की गयी थी। अप्रैल 1963 में सर्वोच्च सोवियत ने 97 सदस्यों के एक संवैधानिक आयोग को एक निर्देश दिया था कि 1963 के अन्त तक नवीन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया जाय। वस्तुस्थितियों के कारण अब तक इस विषय में कोई ठोस कार्य प्रकाश में नहीं आ पाया है। सन् 1964 में इजवेस्तिया में आयोग की एक बैठक होने के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ था। 1964 से ही आयोग ब्रेज्नेव के नेतृत्व में कार्य करना लगा था। यह आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में ही हम नवीन अथवा संशोधित रूसी संविधान की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

2

सोवियत संघात्मक व्यवस्था (SOVIET FEDERALISM)

‘सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ सोवियत राष्ट्रों का एक भाईचारा है जो मित्रता तथा सहयोग के सूत्रों से समानता के आधार पर एक सघ राज्य में बाँटा गया है।’

—कारपि'सकी

सोवियत रूस की सघात्मक व्यवस्था के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि ‘सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से सघ होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से वह एक एकात्मक राज्य है।’ इस कथन का भास्य यही है कि रूस सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से तो सघ कहा जा सकता है, किन्तु राजनीतिक सघात्मकता के लक्षण उसमें पुष्ट नहीं हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से वह एकात्मकता के अधिक सन्निकट है। प्रस्तुत अध्याय में हम रूस का सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक—तीनों ही प्रकार का सघात्मकता का परीक्षण करेगे—विशेष रूप से राजनीतिक सघात्मकता का—वृ कि यही विशेष विवादास्पद एवं प्रासंगिक है।

सोवियत रूस—सांस्कृतिक सघ के रूप में (The U S S R as a Cultural Federation)

सोवियत रूस बहुजातियो (Multinational) का देश है जिसमें विविध जातियो धर्मों भाषाभाषा और सस्कृतियों का समावेश है।

सोवियत सघ की नीति-भाति के बाद से ही राष्ट्रीय अल्पमस्यको और जातीय समूहों के प्रति सहानुभूति पूरा रही है और उसका उद्देश्य रहे अपन सांस्कृतिक विकास का पूरा अवसर प्रदान करना रहा है। वर्तमान सोवियत संविधान में सघीय गणराज्य (Union Republics) स्वायत्त या स्वशासित गणराज्य (Autonomous Republics) स्वशासित क्षेत्र (Autonomous Regions) तथा राष्ट्रीय प्रदेश (National Areas) नामक प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था की गई है। इतने प्रकार की इकाइया को व्यवस्था करने के मूल में यही उद्देश्य निहित रहा है कि विविध राष्ट्रीयताभा (Nationalities) का अधिकधिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे। सघीय गणराज्यों का संगठन राष्ट्रीयताभा के आधार पर किया गया है और उनके नाम भी गणराज्यों के निवासियों की राष्ट्रीयता के नाम पर रखे गये हैं। उदाहरणार्थ—यूक्रेन सोवियत समाजवादी गणराज्य (Ukrainian Soviet Socialist Republic) उन लोगों का गणराज्य है जो यूक्रेनियन जाति के

है। इसी तरह उजबेक जाति के गणतन्त्र का नाम उजबेक सोवियत समाजवादी गणतन्त्र (Uzbek Soviet Socialist Republic) और ताजिक जाति के गणतन्त्र का नाम ताजिक सोवियत समाजवादी गणतन्त्र (Tajik Soviet Socialist Republic) रखा गया है। सभी गणतन्त्र के अंतर्गत स्वशासित गणतन्त्रा (Autonomous Republics) को छोटी-छोटी विविध जातीयताओं के आधार पर संगठित किया गया है। इनके निवासियों को संस्कृति एवं अन्य स्थानीय मामलों में स्वशासन का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह स्वशासित क्षेत्रों (Autonomous Regions) की व्यवस्था उन जातीय समुदायों के आधार पर की गई है जिन्हें सांस्कृतिक आधार पर स्वशासन का अधिकार मिलना आवश्यक है। अर्थात् छोटे-छोटे जातीय समुदायों के सत्त्वों के लिए राष्ट्रीय प्रदेशों (National Areas) की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त व्यवस्था मात्र से ही लोगों की सांस्कृतिक भावनाएँ सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगी—यह समझत हुए बोल्शेविक नेताओं ने कुछ अन्य व्यवस्थाएँ भी की। एक व्यवस्था के अनुसार सभी गणतन्त्रों को अपना संवैधानिक ढांचा स्वच्छात्तुसार बनाने का अधिकार है। दूसरी व्यवस्था के अनुसार सभी क्षेत्रीय भागों की व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है—प्रत्येक सभी गणतन्त्र को 25, स्वशासित गणतन्त्र को 11 स्वशासित प्रदेश को 5 और राष्ट्रीय क्षेत्र को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तीसरी व्यवस्था के अनुसार जातीय विशेषाधिकारों का अंत करके सभी जातीयताओं के लोगों को समान स्तर पर रखा गया है। चौथी व्यवस्था के अनुसार सभी गणतन्त्रों को भाषा संबंधी स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, अर्थात् सम्पूर्ण सभ पर एक ही भाषा बोधन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। संविधान की 40वीं धारा में स्पष्टतः उल्लिखित है कि 'भाषाओं की कार्यवाही गणतन्त्रों की प्रत्येक प्रत्येक भाषाओं में होगी। इतना ही नहीं, सभी कानून और आदेश सभी गणतन्त्रों में साधारणतः बोली जाने वाली भाषाओं में छापे जाते हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक रूप से सोवियत रूस एक सभ है।

सोवियत रूस—आर्थिक सभ के रूप में (The U S S R as a Economic Federation)

सोवियत रूस को आर्थिक दृष्टि से भी सभ कहा जाता है, किन्तु यह मायता पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि वहाँ आर्थिक दृष्टि से इकाइयाँ उतनी स्वतन्त्र नहीं हैं जितनी एक गणतन्त्र सभ में होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक केन्द्रीयकरण है। विश्व के सम्भवतः किसी भी सभ में केन्द्र द्वारा इतने उद्योगों और व्यवसायों का संचालन एवं नियंत्रण नहीं किया जाता जितना सोवियत सभ में केन्द्र द्वारा होता है। केन्द्रीय सरकार ही सम्पूर्ण सभ के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण करती है और सभी महत्वपूर्ण तथा भारी उद्योग और व्यवसाय केन्द्र के एकाधिकार की वस्तुएँ हैं। सच्चाई यह है कि आर्थिक रूप से सोवियत रूस का ढांचा सघातम होने प्रवृत्ति एकात्मक अधिक है।

सोवियत रूस—एक राजनैतिक सघ के रूप में (The U S S R as a Political Federation)

राजनैतिक दृष्टि से सोवियत रूस की सघात्मकता बहुत विवादास्पद है। सोवियत नेता अपनी शासन-व्यवस्था को पूरुत आदर्श सघीय व्यवस्था बताते हैं जबकि पाश्चात्य विचारक इस मत से सहमत नहीं हैं। प्रो० व्हीयर के अनुसार रूस का सन् 1936 का संविधान अधिक से अधिक अर्द्ध-सघात्मक है। तो प्रो० स्ट्रान के मत में “सोवियत समाजवादी गणतन्त्रों का समूह निम्नाधिक एक सघीय राज्य है।” सोवियत रूस की सघात्मकता को हम अभी समझ सकते हैं जब वहाँ पाये जाने वाले सिद्धान्त और व्यवहार के अन्तर को भी ध्यान में रखा जाय।

किसी भी सघात्मक संविधान को चार मौलिक विशेषताएँ होती हैं—

- (1) दोहरी शासन-व्यवस्था,
- (2) केन्द्र और इकाइयों के बीच शक्तियाँ का विभाजन,
- (3) संविधान की सर्वोच्चता और दुष्परिवर्तनशीलता, एवं
- (4) “यायपातिका” की सर्वोच्चता।

दोहरी शासन व्यवस्था

सोवियत सघ में दो प्रकार की सरकारें हैं—सघीय सरकार और इकाई गणराज्यों की सरकारें। रूस में इस समय 15 सघीय गणराज्य (Union Republics) हैं। इकाई राज्य चार स्तर के हैं—सघीय गणराज्य (Union Republics), स्वशासी क्षेत्र (Autonomous Regions) और राष्ट्रीय प्रदेस या क्षेत्र (National Areas)। इन इकाइयों में अन्तर यह है कि सघीय गणराज्य (Union Republics) को ही प्रत्यक्ष सघ की मूल इकाई माना गया है और अन्य तीन प्रकार की इकाइयाँ गणराज्यों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता का उपयोग करती हैं।

सोवियत संविधान में गणराज्यों की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया हुआ है, जिसके अनुसार वे निजी संविधान का निर्माण कर सकते हैं। स्वशासी गणराज्यों का भी अपना अलग अलग संविधान होता है, जो सम्बन्धित सघीय गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वशासी क्षेत्रों और राष्ट्रीय प्रदेशों को निजा संविधान रखने का अधिकार नहीं है।

सघीय गणराज्यों के प्रशासनिक अंगों में सघीय सरकार के अनुरूप ही एक सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम, मन्त्रीपरिषद् और सर्वोच्च न्यायालय होने हैं। इसी तरह दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था है। जिस प्रकार अन्य सघ राज्यो में अवश्य ही इकाईयों की सघीय व्यवस्थापिका के उच्चतम प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है उसी प्रकार सोवियत सघ में भी प्रत्येक इकाई को पृथक्-पृथक् राष्ट्रीयताओं की सोवियत (Soviet of Nationalities) में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह अवश्य है कि अमेरिका के समान उहे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

सघीय सरकार एवं गणराज्यों की सरकारें एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। दोनों अपने अस्तित्व के लिए संविधान पर आश्रित हैं। सर्वोपरि बात यह है कि

संविधान की धारा 17 में यह स्पष्ट कहा गया है कि "संघ के प्रत्येक गणतन्त्र को सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से स्वेच्छा से अलग होने का अधिकार प्राप्त है।" अगली धारा 18 में उल्लिखित है कि "संघ के प्रत्येक गणतन्त्र को विदेशों से सीधे सम्बन्ध स्थापित करने और उनसे समझौता आदि करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 18 में ही यह भी कहा गया है कि "संघ के प्रत्येक गणतन्त्र का अपनी सभा का संगठन है।"

उपयुक्त सभी आधारों पर सोवियत नेताओं का दावा है कि रूसी संघ की व्यवस्था सच्ची सघीय व्यवस्था है। लेकिन यह सब कुछ चित्र का केवल सद्धान्तिक पहलु है। सोवियत संघ में व्यवहारतः इकाइयों की राजनीतिक स्वतन्त्रता नगण्य है और वे संघ की प्रशासनिक इकाईयाँ मात्र रह गई हैं। केन्द्रीयकरण इतना अधिक है कि इकाइयों को केवल सांस्कृतिक एवं विद्युत् स्थानीय प्रकृति के कार्यों में ही स्वतन्त्रता प्राप्त है अन्यथा राजनीतिक दृष्टि से उन्हें लगभग पूरी तरह सघीय शासन की इच्छानुसार चलना पड़ता है। केन्द्रीयकरण की यह प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। गणराज्यों के प्रशासन का निर्देशन और नियन्त्रण सघीय सरकार विभिन्न साधनों द्वारा करती है। सम्पूर्ण देश की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था पर संघ सरकार का नियन्त्रण रहता है और राज्यों को इस क्षेत्र में संघ सरकार के आदेशों का पालन करना होता है यहाँ तक कि गणराज्यों के वजह तक पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है। आर्थिक, औद्योगिक एवं कृषि सम्बंधी सभी समस्याओं का नियमन व संचालन केन्द्रीय सरकार करती है। इकाई राज्यों को संघ से स्वेच्छा से अलग होने की बात भी केवल कागजी है। सोवियत रूस में साम्यवादी दल की उच्च सत्ता की नाति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कहने या करने की हिम्मत करता है तो उसे राजनीतिक जीवन से बाफ कर दिया जाता है और रूसी राजनीति के इतिहास में ऐसी सफाईयों (Purges) के उन्हाहरण कम नहीं हैं।

संघ के प्रत्येक गणतन्त्र के अपने अपने अलग अलग सैनिक संगठन हान की बात का और पर-राष्ट्र सम्बंधों के स्वतन्त्र संचालन की बात का भी व्यावहारिक मूल्य नहीं सा है। संविधान की एक धारा जहाँ यह स्वीकार करती है कि संघ के प्रत्येक गणतन्त्र का अपना अलग सैनिक संगठन है, वहाँ संविधान की दूसरी धारा केन्द्र को यह अधिकार सौंपती है कि वह गणतन्त्रों के सैनिक संगठनों के विषय में सिद्धांतों का निश्चय करेगी। धारा 14 में स्पष्ट है कि सघीय गणतन्त्रों के सैनिक संगठनों के निर्माण के संचालन के सिद्धांतों का निश्चय करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा। गणतन्त्रों के परराष्ट्र सम्बंधों के स्वतन्त्र संचालन का अधिकार भी संविधान की धारा 14 (घ) में प्राप्त हो जाता है जिसके अन्तर्गत संघ की सरकार को इस बात का पूर्ण अधिकार दिया गया है कि गणतन्त्रों द्वारा परराष्ट्र सम्बंधों के संचालन के विषय में सामान्य नियम बनाकर वह उन पर पूरा नियन्त्रण रखेगी। इस प्रकार स्वयं संविधान की धाराओं से ही गणतन्त्रों की सभा व परराष्ट्र के विषय की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है।

शक्तियों का विभाजन

सोवियत संविधान में शक्ति विभाजन अमेरिकन संविधान के अनुरूप किया गया है। संविधान की धारा 14 में सघ-सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों का उल्लेख है। धारा 15 में कहा गया है कि सघीय गणराज्यों को सार्वभौमिकता केवल धारा 14 में परिगणित सघीय सरकार के अधिकारों से सीमित है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में सघीय गणराज्यों को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में सघीय सूची को छोड़कर अवशिष्ट शक्तियाँ गणराज्यों में निहित कर दी गई हैं। सघीय सरकार गणराज्यों के सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षक है।

शक्ति विभाजन की यह व्यवस्था सद्भावितक अधिक है, व्यावहारिक कम। अधिकारों के बंटवारे में अधिक संख्या में और समस्त महत्वपूर्ण बातों पर केन्द्र का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सघीय कानूनों और गणराज्यों के कानूनों में विरोध होने पर सघीय कानून ही लागू होते हैं। यही नहीं, संविधान के संशोधन का अधिकार सर्वोच्च सोवियत के हाथ में होने के कारण सघीय सरकार अधिकार विभाजन में भी अपने हित में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह व्यावहारिक दृष्टि से सघीय गणराज्यों की सरकारें सघ-सरकार का इच्छानुसार ही आचरण करती हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग व्यवहार में उसी सीमा तक कर पाती हैं जिस सीमा तक सघ सरकार उन्हें छूट दे।

संविधान की सर्वोच्चता और दुष्परिवर्तनशीलता

सोवियत संघीयता और नेता यह स्वीकार करते हैं कि उनका संविधान राज्य का सर्वोच्च संविधान है। किसी भी गणराज्य और सघीय सोवियत सर्वोच्च द्वारा बनाया हुआ कानून सघीय संविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता। कार्यपालिका के समस्त आदेश और कार्य पूरा संविधान के अनुकूल होने आवश्यक हैं। सोवियत संविधान इस दृष्टि से कठोर है कि उसके संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया है, जो सामान्य कानून के निर्माण या परिवर्तन की प्रक्रिया से भिन्न है। इसके अतिरिक्त संविधान विहित स्पष्ट और सुनिश्चित है जिसकी रचना एक संवैधानिक आयोग द्वारा की गई थी।

आय आलोचना की जाती है कि इस में साम्यवादी दल का इतना कठोर नियंत्रण है कि समाजवाद व्यवस्था को मुटु बनाये रखने के निम्ने व्यावहारिक रूप में संविधानिक उपबंधों का उल्लंघन घासत और दब द्वारा किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। सोवियत शासन व्यवस्था में सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बहुधा संविधान के विरुद्ध कार्य कर लिये जाते हैं और उन्हें संवैधानिक घोषित नहीं किया जाता प्रत्युत उनके अनुरूप बाद में संविधान में यदि आवश्यक समझा जाता है तो संशोधन कर लिया जाता है। पुनश्च सोवियत सघीय व्यवस्था में संविधान को दुष्परिवर्तनशीलता या कठोरता उस सीमा तक नहीं पायी जाती जिस सीमा तक वह अमेरिका या भारत के संघात्मक संविधान में पायी जाती है। -

में प्रथम तो संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक नहीं है कि वह सदन के (जिसमें प्रस्ताव पेश किया गया हो) के निश्चित बहुमत द्वारा प्रस्तुत किया जाय। दूसरे संशोधन प्रस्तावित करने के विषय में संघीय इकाईयाँ का कोई अधिकार नहीं है। तीसरे संशोधन के अंतिम रूप से पारित होने के लिये केवल यह आवश्यक है कि उसे व्यवस्थापिका के प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में गणतन्त्रा को संशोधन के पुष्टीकरण आदि का कोई अधिकार नहीं है।

“यायपालिका की सर्वोच्चता

सोवियत संघ में सर्वोच्च “यायालय व्यवस्था सभात्मक “यायपालिका के अनुरूप नहीं है। उसे “यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संविधान की व्याख्या का कार्य देश के सर्वोच्च “यायालय के स्थान पर प्रसिद्धियम के सुपुर्द किया गया है जो स्वतन्त्र “यायपालिका न होकर केन्द्रीय कार्यपालिका का ही एक अङ्ग माना है। इस व्यवस्था का यह परिणाम निकल सकता है कि केन्द्रीय कार्यपालिका संविधान की व्याख्या इस प्रकार करे कि इकाईयाँ के अधिकारों पर कुठाराघात हो जाय और उनका स्थानीय स्वशासन ही समाप्त हो जाय।

स्पष्ट है कि “राजनैतिक” रूप से सोवियत संघ की व्यवस्था पूर्णतया सभात्मक नहीं है और उसमें ये लक्षण प्राप्य नहीं हैं जो सामान्यतः सभात्मक व्यवस्था में हान चाहिये। सोवियत रूस एक सांस्कृतिक संघ कहा जा सकता है जिसकी इकाईयाँ का संगठन विविध जातीयताओं के आधार पर किया गया है पर धार्मिक एवं राजनैतिक दृष्टि से उनकी सभात्मक व्यवस्था उतनी पूर्ण नहीं है, जितनी पूर्ण होनी चाहिये। वास्तविकता यही है कि रूस में सभात्मकता की अपेक्षा वैदेशीकरण और एकात्मकता के लक्षण विशेष रूप से विद्यमान हैं।

सोवियत संघ की एकात्मकता के लक्षण

शक्ति के केन्द्रीयकरण और एकात्मकता के जो लक्षण सोवियत संघ में पाये जाते हैं और उसके सभात्मक आधार का चाट पट्टाते हैं, वे प्रमुखतः निम्न-लिखित हैं—

1 सोवियत संघीय मन्त्रिमण्डल में दो प्रकार के मन्त्रालयों की व्यवस्था है—घरिले मण्डलीय मन्त्रालय (All Union Ministries) एवं मण्डलीय गणराज्यों के मन्त्रालय (Union Republican Ministries)। इन दूसरे प्रकार के मन्त्रालयों का कार्य संघ की इकाईयाँ के मन्त्रालयों का निर्देशन व नियंत्रण करना है और “नव” अधिवार इसमें व्यापक तथा विस्तृत है कि इकाईयाँ व विधि निर्माण प्रथम प्रमाणन के किसी भी धर्म में हेतुधार कर सकते हैं।

2 मण्डलीय सर्वोच्च सोवियत के प्रसादित्यम की गणराज्यों के मन्त्रालयों के नियुक्ति का रद्द करने का अधिकार है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल तक इनके नियुक्ति का स्थगित कर सकता है।

3 सोवियत सघ के प्रोक्क्रेटर जनरल के प्रतिनिधि समस्त देश में इस बात का निरीक्षण करते हैं कि सघीय कानूनों और आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।

4 सघ सरकार पर यायालय का अक्रुश नहीं है, अतः उस मनमाने का पूर्ण अवसर मिल जाता है।

5 आर्थिक दृष्टि से इकाइया की सरकारें काफी हद तक केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहती हैं। केन्द्र ही सम्पूर्ण सोवियत समाजवादी सघ के लिये इकट्ठा बजट बनाता है। वका औद्योगिक एवं कृषि संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के अर्थ व्यवसायों का संचालन भी केन्द्र के हाथ में है। इस प्रकार सम्पूर्ण देश के वित्त पर और राष्ट्र के महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे पर केन्द्र का ऐसा अधिकार रहता है जसा विश्व के किसी अर्थ सघ में नहीं पाया जाता।

6 रूस में साम्यवादी दल स्वयं एक ऐसी सर्वोपरि शक्ति है जिसके क्रिया-कलापों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को सर्वाधिक बल मिलता है। रूस में समस्त शासन की शक्तियाँ का ज्ञात साम्यवादी दल है। केन्द्रीय सरकार ही या राज्यों की सरकारें, सभी को साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित आज्ञाओं और नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है। राज्य का सघात्मक ढांचा केवल साम्यवादी दल द्वारा आदेशित कार्यों की कुशलतापूर्वक पूर्ति के लिये एक संगठन है।

निष्कर्ष रूप में यही प्रकट होता है कि सोवियत सघ में इकाई सरकारों की स्थिति केन्द्रीय सरकार की अधीनस्थ सरकारों जैसी है और राज्यों की स्वायत्तता केवल नाममात्र की है। सोवियत सघ में न तो संविधान की सर्वोच्चता को और न इकाईयों की स्वायत्तता को ही व्यावहारिक सत्य माना गया है। सिद्धांततः भले ही सघवाद की अनेक विशेषताओं को अपनाया गया है, लेकिन व्यवहार में केन्द्रीयकरण पर इतना जोर दिया गया है कि अतः सोवियत सघ ने एकात्मक राज्य का रूप धारण कर लिया है।



3

नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य (FUNDAMENTAL RIGHTS & DUTIES OF CITIZENS)

‘स्टालिन सचिवान सोवियत नागरिकों को ऐसे अधिकार और
ऐसी स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है जो किसी
पूँजीवादी देश में न तो पायी
जाती हैं और न पायी
जा सकती हैं।’

—कारपिन्स्की

सन् 1918 और 1924 के सोवियत सचिवानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का बरतन नहीं था, किन्तु 1936 का वर्तमान स्टालिन सचिवान अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों को भी व्यवस्था करता है। प्रस्तुत अध्याय में हम पहले सोवियत नागरिक अधिकारों का विश्लेषण करेंगे और तब कर्तव्यों का।

सोवियत नागरिक अधिकारों की विशेषताएँ (Salient Features of the Soviet Civil Rights)

सोवियत नागरिक अधिकारों की कतिपय निजी विशेषताएँ हैं जिन पर सोवियत नागरिक और नेता गव करते हैं। बिनिस्की के शब्दों में इन अधिकारों की सूची इतनी विशाल और विलक्षण है तथा यह इतनी नवीन और मौलिक है कि ऐसे विशिष्ट अधिकार किसी भी बुद्धिमान लोकतन्त्र में नहीं हैं। इन अधिकारों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार अंकित किया जा सकता है—

समाजवादी स्वरूप

सोवियत व्यवस्था में मौलिक अधिकारों का स्वरूप व्यक्तिवादी न होकर समाजवादी है। यह योजना पूरे समाज को केन्द्र मान कर चलती है और नियोजित व्यवस्था पर आधारित है। व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति को अधिकार दान रूप में प्राप्त हैं कि उनका प्रयोग करके वह अपने कल्याण के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज का भी कल्याण कर सके। उदाहरणार्थ, व्यक्ति कार्य करने के अधिकार का उपयोग स्वयं को और समाज को हित साधना के लिए कर सकता है किन्तु सम्पत्ति का एकाग्रण द्वारा समाज के अन्य लोगों की मुक्तिप्राप्ति का नहीं ध्यान रखता है।

उद्देश्य और साधनों का सामंजस्य

पश्चिमी संविधानों में केवल अधिकारों की चर्चा है, साधनों को नहीं। इसके विपरीत सोवियत संविधान में नागरिकों के केवल अधिकार ही नहीं गिनाये गये हैं बरन् उन साधनों की भी व्यवस्था की गई है जिनके द्वारा उन अधिकारों का वास्तविक प्रयोग किया जा सके। उदाहरणार्थ—व्यक्ति का काम करने का अधिकार प्रदान किया गया है और साथ ही राज्य की ओर से चलाये जाने वाले इतने व्यवसायों की व्यवस्था भी की गई है कि बेकारी रह ही न सके। इसी तरह व्यक्ति को अवकाश का अधिकार है पर इसके उपभोग के लिए काम के कम घण्टा, अनिवार्य छुट्टियाँ, विधाम-गृहा आदि की व्यवस्था भी की गई है।

अधिकारों के साथ कत्त व्यों का उल्लेख

विश्व के अन्य संविधानों के विपरीत सोवियत संविधान में अधिकारों के साथ कत्त व्यों का भी उल्लेख किया गया है क्योंकि बिना कत्त व्यों के अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता। पूँजीवादी देशों की तरह सोवियत संविधान बिना अधिकारों के किसी पर कोई कत्त व्य नहीं लादता। अधिकार और कत्त व्य अविभाज्य हैं। यदि व्यक्ति को काम का अधिकार है तो साथ ही यह भी कत्त व्य जुड़ा है कि वह काम करे।

यद्यपि अन्य संविधानों में अधिकारों के साथ कत्त व्यों की व्यवस्था नहीं है। पर यह इसी मायता के कारण है कि लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में अधिकारों के साथ-साथ कत्त व्य स्वतः ही जुड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ, भाषण, प्रेस, धर्म आदि की स्वतन्त्रता के अधिकारों में यह कत्त व्य अपने आप निहित कि मैं व्यक्ति इनका दुरुपयोग नहीं करेगा अथवा दूसरों के इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सब व्यापकता

सोवियत संविधान में मौलिक अधिकार सब-व्यापी हैं अथवा प्रत्येक स्त्री-पुरुष को बिना किसी भेद-भाव के सब मौलिक अधिकार दिये गये हैं। इस प्रकार की सब-व्यापकता पश्चिम के अनेक देशों में नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ, ब्रिटन में रोमन कथोलिकों के साथ, स्विट्जरलैंड में स्त्रियों के साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो लोगों के साथ भेद भाव बरता जाता है। भारत में मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं।

सामान्य प्रतिबन्ध

सोवियत संविधान का मौलिक उद्देश्य सबहारा वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना है। अतः नागरिकों पर यह प्रतिबन्ध है कि वे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग समाजवादी मायताओं के विरुद्ध नहीं करेंगे। नागरिकों के सार्वजनिक संगठन सम्बन्धी अधिकार पर भी प्रतिबन्ध है तथा केवल साम्यवादी दल को ही 'राज्य का और सब साधारण का एक सबहारा वर्ग का मुख्य संगठन' कहा गया है। संविधान निर्माण के समय स्टालिन ने कहा भी था कि 'साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक दल को पन पन दया जायेगा।'।

आर्थिक आधार

जहाँ पश्चिमी देशों में नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है वहाँ सोवियत संघ में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है और नागरिक अधिकारों को गौण। सोवियत भाषता यह है कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी सम्भव हो सकती है, जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। भूतन्त्र और बेकारों के लिए जो शोषण के शिकार हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती।

यायपालिका के संरक्षण का अभाव

प्रायः लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष सर्वोच्च यायपालिका को व्यवस्था की जाती है लेकिन सोवियत संघ में नागरिक अधिकारों को यायपालिका का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि सरकार इन अधिकारों पर आक्रमण करे अथवा इनके विरुद्ध कानून बनाये तो नागरिकों के पास ऐसा कोई संवैधानिक साधन नहीं है जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा करें।

विविध मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य (Fundamental Rights & Duties)

स्टालिन संविधान की धारा 118 से लेकर 133 तक में जिन मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का निरूपण किया गया है, वे इतिहास में एक असाधारण अधिकार घोषणापत्र का निर्माण करती हैं। ये अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

काम का अधिकार (Right to Work)—सोवियत संविधान की धारा 12 में काम का कर्तव्य कहा गया है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए काम करना आदेश का सूचक बताया गया है। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसका खाना भी नहीं मिलेगा' यह—रूसी व्यवस्था है। धारा 118 यह स्पष्ट करती है कि काम के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सबको एक सा काम और एक सा वेतन प्राप्त होगा। काम की मात्रा और उसके स्तर के अनुसार वेतन में अंतर होना स्वाभाविक है। यह अंतर सोवियत नागरिकों के वेतन में पाया भी जाता है किन्तु यह इतना अधिक नहीं है जितना पूँजीवादो व्यवस्था वाले विभिन्न देशों में पाया जाता है। वहाँ कम से कम और अधिक से अधिक वेतन का अनुपात लगभग 1:50 का है। सोवियत नेता संविधान के इस अनुपात का समाजवाद के अनुकूल मानते हैं। उनकी भाषा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति भी पूँजीपति नहीं बन सकता और वह दूसरों का शोषण करने की स्थिति में किसी भी रूप में नहीं आ सकता।

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक के लिए नौकरी की व्यवस्था उपस्थित है। वहाँ की अन्य व्यवस्था के समाजवादो संगठन में नागरिकों के काम पाने का अधिकार को सुनिश्चित कर दिया गया है। सबको काम पर लगाये रखने का उद्देश्य की पूर्ति के

लिए ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व का व्यवस्था की गई है और भारी उद्योग सामूहिक कृषि, राक्षसिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण आदि के कार्यों का संचालन राज्य ने अपने हाथ में ले रखा है। इस व्यवस्था का सु-फल यह है कि जहाँ प्रशिक्षण द्वारा एक ओर व्यक्ति रोजगार में लगने के योग्य बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर राजकीय उद्योग आदि में उन्हें सुगमतापूर्वक रोजगार मिल जाता है। इनो व्यवस्था का यह सुपरिणाम है कि रूस में बेकारी की समस्या नहीं है।

श्रमकाश और आराम का अधिकार (Right to rest and leisure)—सोवियत-नागरिकों को विश्राम और श्रमकाश प्राप्त करने का मानवीय अधिकार दिया गया है। यह अधिकार व्यावहारिक रूप से श्रमकाल में भी लाया गया है। बहुसंख्यक श्रमिकों के काम के घंटे घटाकर, सात घण्टों का काम करने का दिन बनाकर, वेतन सहित वार्षिक श्रमकाश की व्यवस्था करके, इस अधिकार का निश्चित कर दिया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत ही विश्राम घंटों और कलवा का प्रबंध किया गया है। सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की भी व्यवस्था है जहाँ कमचारी अपने स्वास्थ्य-सुधार के लिए जा सकता है। इसी तरह की प्रयाय सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। ताकि सोवियत कर्मचारी अपने श्रमकाश के समय का उचित प्रयोग कर सकें।

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Security)—सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को बुढ़ापे या बीमारी में या काम करने के लिए अयोग्य हो जाने पर राज्य की ओर से पोषण पाने का अधिकार है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक बीमा की व्यवस्था, मुक्त इलाज और देश भर में स्वास्थ्य-सुधार के लिए स्थानों का प्रबंध करके राज्य ने इस अधिकार को सुरक्षित बनाया है। 1 जनवरी, 1965 से वह विधि भी लागू हो गई है जिसके अनुसार कृषकों का बुढ़ापे का पंशन मिलेगी।

शिक्षा का अधिकार (Right to Education)—शिक्षा के सम्बन्ध में सोवियत संविधान में नागरिकों का ऐसी अधिकार प्रदान किया गया है जिनका उत्कृष्ट विश्व के अन्य संविधान में नहीं मिलता। यही कारण है कि रूस में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। संविधान की धारा 121 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को प्रारम्भिक शिक्षा को सावजनिक और अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल-पद्धति पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। कारखानों में, राजकीय कार्यों में, मशीन और ट्रेक्टर तथा सामूहिक खेलों में श्रमिक जनता को यह सम्बन्धी, विशेष काम सम्बन्धी और कृषि सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाती है। सोवियत संघ में पढ़ने और निपट निपट विद्यार्थियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को आवश्यकतानुसार संपत्ति, स्थान और अवसर प्राप्त होते रहते हैं। उच्च शिक्षा का व्यय भी बहुत बड़ी सीमा तक राज्य ही वहन करता है। नागरिकों को इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। संगीत और साहित्य की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, लेकिन तकनीकी शिक्षा अत्यन्त ही उच्च स्तर की है। प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है ताकि विषय पर सवागीण प्रकाश पड़ सके। सोवियत स्कूलों के

कायक्रम और पाठ्यक्रम का निर्धारण राज्य करता है, जो सभी स्कूलों पर लागू होता है। शिक्षा का यह अधिकार इतना वास्तविक है कि 80 प्रतिशत से भी अधिक जनता प्रारम्भिक रूप से शिक्षित हो चुकी है।

संगठन का अधिकार (Right to Organisation)—सोवियत नागरिकों को सावजनिक संगठन सहकारी समितियाँ, श्रमिक सघो, खेलकूद और सुरक्षात्मक संगठनों, वधानिक समुदायों आदि में संगठित होने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार वास्तविक नहीं है क्योंकि संविधान द्वारा ही यह अधिकार इस घोषणा से अत्यन्त सीमित हो गया है कि सम्पूर्ण राजनीतिक संगठनों का केन्द्र साम्यवादी दल ही होगा। साम्यवादी दल को सवहारा वग के सर्वाधिक कार्याशील और सचेत सदस्यों का संगठन कहा गया है।

भाषण, प्रेस, सभा और प्रदर्शन, जुलूस आदि की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech, Press, Assembly, Street Procession and Demonstration)—सोवियत नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान की धारा 145 उपर्युक्त करती है कि—

“श्रमिक जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और समाजवादी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य सच के नागरिकों के लिए कागज़ द्वारा निम्नांकित बातों की गारंटी होगी—(क) भाषण की स्वतन्त्रता (ख) प्रकाशन की स्वतन्त्रता (ग) सभा करने की स्वतन्त्रता, जिसमें सावजनिक सभाएँ करना भी सम्मिलित हैं एवं सड़कों पर जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता। उपर्युक्त अधिकारों के उपभोग के लिए मुद्रणालयों, कागज़ के स्टॉकिस्टों, सावजनिक ईमारतों सड़कें सूचना सम्बन्धी सुविधाओं और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को श्रमिक जनता एवं उसके संगठनों को प्रदान किये गये हैं। पर इन अधिकारों के साथ वह शत जुड़ी है कि वे सवहारा वग के हितों से टकराते न हों और समाजवादी व्यवस्था को हट करने में सहायक हों। इन प्रतिबंधों का स्वाभाविक अर्थ यह है कि समाजवाद विरोधी वक्ता की अभिव्यक्ति के लिए कोई स्वतन्त्रता नहीं है। वस्तुतः रूस में रेडियो प्रेस और समाचारपत्रों, आदि समस्त प्रसार-प्रचार-साधनों पर साम्यवादी दल का एकाधिकार है। व्यवहार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ केवल इतना ही है कि लोगों में केवल समाजवादियों के रूप में यूनाधिक मतभेद हो सकते हैं, अथवा समाजवाद विरोधी मतभेद को किसी भी दशा में मनपने नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में भी साम्यवादी दल की प्रभुता ही सर्वोच्च है और वही यह दखता है भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग सवहारा वग की हित-साधना और समाजवादी व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में हो रहा है या नहीं। सोवियत नागरिकों को दिये गये इन राजनीतिक अधिकारों की प्रालोचना करते हुए फाइनर ने ठीक ही लिखा है कि ‘व्यवहार में ये सभी अधिकार नियंत्रित हैं। सभी सभाओं के लिए सरकारी भग्ना जैनी पड़ती हैं। संचार के और प्रेस पर पूर्णतः सरकार और दल का नियन्त्रण है। कठोर सन्तर

की व्यवस्था है। अतः रूस में विचार और चेतना पर, लोह आवरण (Iron blanket) है।”

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व गृह सुरक्षा का अधिकार (Right to Personal Freedom in Violability of Home)—सोवियत नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कुछ व्यक्तिगत एवं गृह-सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों का समावेश है। इस सम्बन्ध में संविधान की धारा 127 में कहा गया है कि “सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के नागरिकों को व्यक्ति की अनुल्लंघनीयता की गारंटी मिली हुई है। प्रदालत के फसले या प्रोब्यूरेटर की अनुमति के बिना किसी भी नागरिक को बन्दी नहीं बनाया जा सकता है।” पर इस सम्बन्ध में भी यह शर्त रख दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति पर राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने का संदेह है तो उसके साथ राज्य की ओर से इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। इसका भाव्य यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं अथवा उससे सहानुभूति रखने वाले हैं। समाजवादी विचारधारा के विरोधियों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार केवल उसी सीमा तक है जिस सीमा तक सरकार उन्हें वह अधिकार प्रदान करे।

संविधान की धारा 128 नागरिक के निवास स्थान की अनुल्लंघनीयता और पत्र व्यवहार की गोपनीयता की गारंटी करती है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि सरकार नागरिकों के घर में घुस नहीं सकती अथवा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सोवियत रूस में सर्वोपरि बात समाजवादी व्यवस्था के संरक्षण की है। कानून भी इसी व्यवस्था को रक्षित करने के लिये बनाये गये हैं। अतः कोई भी सरकारी अधिकारी नागरिकों के घरों में बिना उनकी आज्ञा के भी प्रवेश कर सकता है, यदि समाजवादी कानून और राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक हो।

सोवियत रूस में अभिव्यक्ति को वैधानिक बचाव का भी अधिकार है। इस सम्बन्ध में कोई दूसरा नियम नहीं तो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सभी प्रदालतों में मुकदमों की खुली सुनवाई होगी, और अभिव्यक्ति को अपने बचाव करने के अधिकार की गारंटी होगी। इसका भाव्य यह है कि अभिव्यक्ति के विरुद्ध जो कुछ भी किया गया है उसे उसके विरुद्ध परीक्षा करने का अधिकार है और वह अपने मुकदमे के लिए वकील नियुक्त कर सकता है, परन्तु यह अधिकार भी व्यवहारतः पूर्ण वास्तविक नहीं है।

धर्म व अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Religion and Conscience)—सोवियत संविधान सभी नागरिकों को अपने-अपने धार्मिक कृत्या करने का और धर्म में आस्था न रखने वालों को धर्म विरोधी प्रचार करने का अधिकार देता है। नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा के लिए सोवियत संघ में धर्म का राज्य एवं स्कूल से कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है।

जातीयता एवं राष्ट्रीय समानता का अधिकार (Right to Racial and National Equality)—सोवियत संविधान के अन्तर्गत सब नागरिकों का एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वे किसी भी जाति अथवा राष्ट्रीयता या नस्ल के हों। जाति या नस्ल के आधार पर न किसी का विशेषाधिकार दिया जा सकता है और न किसी को अधिकार कम किये जा सकते हैं। किसी जाति या नस्ल के विरुद्ध कोई छुट्टा या ऊच-नीच की भावना नहीं फूट सकती।

स्त्री पुरुषों की समानता का अधिकार (Right to equality of women and men)—सोवियत रूस का संविधान इस दृष्टि से भी निराला है कि धारा 122 में इस बात के लिए पृथक् व्यवस्था है कि स्त्रियाँ को भी सब अधिकार पुरुषों के समान ही प्राप्त होने चाहिए। इस अधिकार का प्रयोग रूस में वास्तविक रूप से हुआ है। इस अधिकार को स्त्रियाँ वास्तव में काम में ले सकें, इस दृष्टि से उन्हें श्रम करने श्रम को भाग्य और स्वरूप के अनुसृत्य पारिश्रमिक पाने और वृद्धावस्था बीमारी आदि की दशा में निर्वाह-राशि पाने की सुविधा दी जाती है। माताओं और शिशुओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बड़े परिवार वाली माताओं को राज्य की ओर से विशेष सहायता व सम्मान प्राप्त होता है। दस या अधिक बच्चे वाली माता का 'मोर माता' (Mother Heroine) की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिशुओं के लालन पालन, खेलकूद और मनोरंजन, पूरा शिक्षा आदि के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाती है।

शरणार्थी अधिकार (Right to Asylum)—यह भी एक बड़ी अनोखी बात है कि सोवियत संविधान ऐसे विदेशी नागरिकों को राजनीतिक शरण प्राप्त करने का अधिकार देता है जो श्रमिका के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए या वित्तीय कष्टों के लिए अपने देश की सरकारों द्वारा सताये गये हों। इस व्यवस्था के कारण ही कहा जाता है कि मास्का, वास्तव में विश्वभर की शरणार्थियों की सुरक्षा का स्थान है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार (Right of Private Property)—यद्यपि मौलिक अधिकारों के अध्याय में इस बात का उल्लेख नहीं है फिर भी संविधान के प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजकीय स्वामित्व और सहकारी तथा सामूहिक स्वामित्व के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वामित्व में भी कुछ सम्पत्ति रहती है। अपनी आय-व्यय निवास के मकान परेनू उपभाग और सुविधा व सजावट का सामान अपने पास रखने का अधिकार है और उनका उत्तराधिकार प्राप्त करना व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। लेकिन इस अधिकार पर इस बात का पूरा प्रभाव है कि अपनी सम्पत्ति का दूसरे के शोषण के लिए प्रयोग नहीं हो सके।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

सोवियत-संविधान अधिकारों और कर्तव्यों को अविभाज्य बनाता है। संविधान की धारा 130 से धारा 133 तक में कर्तव्यों की चर्चा की गई है। चीन के अतिरिक्त अन्य किसी देश के संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है।

प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार तो अधिकारों में ही कर्तव्य अन्तर्निहित है। सोवियत संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित कर्तव्य बतलाये गये हैं।

(1) संविधान और कानूनों का पालन (Observance of Soviet Constitution & Laws)—संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान को अङ्गीकार करें और उन कानूनों का भी पालन करें जो समय समय पर बनाये जाए। ऐसा करने से ही सोवियत रूस की समृद्धि व शक्ति बढ़ेगी और इसी में सोवियत जनता की समृद्धि भी निहित है।

(2) श्रमिक वर्गों के अनुशासन का पालन (Maintenance of Labour Discipline)—सोवियत संविधान प्रत्येक नागरिक से आशा करता है कि श्रमिक वर्ग में पूर्ण अनुशासन बना रहेगा। संविधान में व्यवस्था है कि श्रमिकों को बाह्य कि धन वस्तु के निर्वाहन में वे कर्तव्य भावना का प्रदर्शन करें और सभी के लाभ को ध्यान में रखते हुए मेहनत तथा होशियारी से काम करें।

(3) सामाजिक कर्तव्यों का पालन (Fulfilment of Public Duties)—यह एक स्वाभाविक बात है कि जहाँ किसी और के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था हो वहाँ बेईमानी को जरा भी सहन नहीं किया जा सकता।

(4) सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा (Safe-guarding of Socialist Property)—प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सोवियत संघ की सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा करे। सोवियत संघ में सम्पत्ति मूलतः राज्य के अथवा सहकारी व सामूहिक स्वामित्व में है। अतः उसकी रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है।

(5) समाजवादी व्यवस्था के नियमों के प्रति आदर (Respect for rules of Socialist Intercourse)—सोवियत संविधान में समाजवादी समाज के नियमों का विवरण किया गया है। रूसी नागरिकों का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि वे उन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। इन नियमों का सम्बन्ध व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों, व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध आदि से है।

(6) अनिवार्य सैनिक सेवा एवं देश की रक्षा (Compulsory Military & Defence of the Country)—संविधान के अनुसार देश की सशस्त्र सेनाओं (श्रमिकों और कृषकों की लाल सेना) में भर्ती होना प्रत्येक नागरिक का सम्मानजनक एवं गौरवपूर्ण कार्य है। रूस में सामाजिक सैनिक सेवा का प्रबन्ध है। वहाँ यह नियम है कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर 18 वर्ष की आयु पर अथवा 19 वर्ष की आयु पर सबकी सेना में भर्ती होना पड़ता है। सक्रिय सेना में कार्य करने का समय 2 से 4 वर्ष है। पर इसके बाद 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति का सामाजिक सेवा का अङ्ग समझा जाता है।

सैनिक सेवा के गौरवपूर्ण कर्तव्य के साथ ही सोवियत नागरिकों का यह भी पवित्र कर्तव्य घोषित किया गया है कि वे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। देशद्रोह,

शत्रु से मिल जाने, देश की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाने और किसी अन्य देश की तरफ से गुप्तचर का काम करना आदि को अत्यन्त भयानक अपराध माने गये हैं और उनके लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था है।

सोवियत मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन (Evaluation of Soviet Fundamental Rights)

विषय

रूस के संविधान में दिये गये मूल अधिकार एक ओर तो पश्चिमी मूल अधिकारों से मिलते हैं, दूसरी ओर इनमें कुछ नवामता भी है। मूल अधिकारों की धारणा निश्चय ही पश्चिमी प्रजातंत्रों की देन है। किन्तु जहाँ पश्चिम में यह सिद्धांत निहित है कि मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु कुछ प्राकृतिक अधिकार आवश्यक हैं और शासन द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ रूस में मूल अधिकार एक दूसरे सिद्धांत पर स्वीकृत किये गये हैं और वह सिद्धांत है साम्यवाद। रूस में मूल अधिकारों का स्रोत प्राकृतिक अधिकारों में नहीं है वरन् वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था में है। इनका उद्देश्य रूस की साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अलायका ने कहा है कि सोवियत संघ में मौलिक स्वतंत्रताएँ सीमित हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए वे वहाँ पर साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य राजनैतिक दलों की अनुपस्थिति की बात कहते हैं। रूसी संविधान साम्यवादी दल की वानाशाही का जीना जागता नमूना है। वास्तव में दल का अनुशासन ऐसा कठोर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और प्रजातंत्र एक प्रहसन (Farce) मात्र रह गया है। व्यवहार में साम्यवादी दल ही शासन को नियंत्रित और निर्देशित करता है।

व्यावहारिक रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि अनेक मौलिक अधिकार केवल विधान के लिए हैं। सरकार सारे समाचार पत्रों की मालिक है और वही उन्हें चलाती है। इसी प्रकार छापवाने पाठशालाएँ रेडियो-स्टेशन, सिनेमा संगीत भवन एवं भयाय कला एवं संस्कृति के केन्द्र सभी कुछ सरकार के हाथ में हैं। कोई व्यक्ति ऐसे विचार छपा नहीं सकता और न प्रकट हो कर सकता है जो साम्यवादी दल को अस्वीकार्य हों। संघ बनाने का अधिकार भी केवल उही व्यावसायिक व सामाजिक समूहों को प्राप्त है जिन्हें सरकार की स्वीकृति मिली हुई है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है और विदेश यात्रा निषिद्ध है (विना सरकारी अनुमति के)। सन् 1932 को एक आन्त के अनुसार देश के अन्दर भी भ्रमण करने के लिए व्यक्ति को गृह पासपोर्ट (Home Passport) लेना पड़ता है। पर से 24 घण्टे की अनुपस्थिति की सूचना भी सरकार को देनी होती है। इन सबमें ऊपर एक विशेष बात यह है कि सोवियत नागरिकों का जीवन वहाँ की गुप्त पुलिस (State Secret Police) के हाथ में रहता है जो सब निरीक्षण है और कानूनी प्रणालियों को उठाकर ताल में रखत हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल सकती है।

इस अतिरिक्त सोवियत रूस में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभारिता प्रणाली भारत में समान किसी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, प्रभाव

मावियत "मायपालिका को "मायिक पुनरावलोकन वा कोई अधिकार नहा दिया गया है जिससे अधिकारो की व्यवस्था अवास्तविक-सी हो जाती है। ऐसी दसा म यदि कायपालिका द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारा का अपहरण हो, ता वह उसके विरुद्ध किसी "मायानय की शरण नही ल सकता ।

फेनसड (Merle Fainsod) ने कुछ उदाहरण देकर यह बतलाने का प्रयास किया ह कि सोवियत संविधान म लिखित अधिकार वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण नही है। रूस म व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका अास यह नही है कि वह अपनी इच्छानुसार काम चुन सके अथवा काम की शत निश्चित कर सकें । थमिक अनुशासन का जरा सा भी उत्लघन करना उसके लिये घातक होगा । इसी प्रकार संविधान म सब जातिया और नस्ता की समान अधिकार की व्यवस्था की गई है परन्तु देग म बहुत बड़ी सरपा लगी जाति की है और व्यावहारिक रूप म अल्पसंख्यक जातिया की स्वायत्तता को प्रवृत्तियो का दमन हुआ है । संविधान म भाषा, प्रस, सभा संगठन, प्रदसन आदि के अधिकार घोषित किये गये है किन्तु इन अधिकारा का व्यावहारिक मूल्य नगण्य है । यदि नागरिक शासन को अालाचना कर वा पूर्व राजनीतिक विचार प्रगट करें तो इस प्रकार के कार्या को थमिको के हितों और समाजवादी व्यवस्था के विपरीत माना जाता है । पुनश्च, साम्यवादी दल को ही थमिका के हितों और साम्यवाद की प्रगति का रक्षक राजनीतिक संगठन माना जाता है । राज्य समाज और नागरिक जीवन के प्रत्येक क्षन म साम्यवादी दल के सर्वाच्च नेताओं का आधिपत्य छाया रहता है ।

पक्ष

इसम सदेह नही है कि उपयुक्त आनोचनार्ये पूर्ण असंय नही हैं फिर भी वे अतिरिजित अवश्य है और अधिकारत रूमी तथा पाश्चात्य विचारधाराम्रा के अ तर के कारण प्रगट को जाती हैं ।

गतिवादी समाज म व्यक्ति के केवल राजनीतिक अधिकारा को महत्व दिया जाता है आर्थिक अधिकारा का प्रश्न गेण रहता है । आर्थिक अधिकारो के सम्ब म राज्य व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान नही कर सकता । प्रत्येक व्यक्ति को असीमित व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्र करने का अधिकार हाना है जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता ह कि समाज धनी और निधन दो वर्गों म विभक्त हो जाता है । कुछ लोग ऐश आराम की जि दमी बिताते हैं तो दूसरो को भोजन वस्त्र और आवास की चिंता सताती है । एक तरह के लोग अट्टालिकाओं म निवास करते ह और दूसरी तरह के बहुत स लोगो को अच्छी औपडिया भी नसीब नही होती । इसी तरह कुछ लोग अपने बच्चा को उच्च से उच्च शिक्षा दिलान म सफल होत है जबकि अधिकांश लोग बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा तक दिलाने की स्थिति म नही होत । इस प्रकार की अवस्था समाजवादी समाज म नही होता । बहा राजनीतिक अधिकारो के साथ साथ व्यक्ति को आर्थिक अधिकारा की सुरक्षा भी प्राप्त होनी है । बहा किसी को भी असीमित व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्र करने का अधिकार नहा होता । यदि इस दृष्टि स देखा जाय तो रूस के मौलिक अधिकारा की व्यवस्था सराहनीय है । सोवियत

संविधान निर्माताओं के इस मत से वस्तुतः कोई भिन्न राय नहीं हानी चाहिए कि 'किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का मूल्य हो क्या है, यदि वह व्यक्ति बेकार है अथवा भूखा मरता है अथवा उसकी अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। सच्ची स्वतन्त्रता वही निवास करती है जहाँ शोषण का अन्त कर दिया गया है, जहाँ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति सता नहीं सकते जहाँ बेकारी नहीं है जहाँ कोई भीख नहीं मागता और जहाँ इस बात का अभाव नहीं रहता कि कोई व्यक्ति कल बेकार हो सकता है या उसकी रोजी छीनी जा सकती है।' रूस में आर्थिक सुरक्षा का राजनीतिक समानता और नागरिक स्वतन्त्रता में कहीं अधिक महत्त्व दिया गया है। पश्चिमी प्रजातन्त्रों में मूल अधिकार को केवल नकारात्मक स्वतन्त्रता ही दी है जबकि रूस में सकारात्मक स्वतन्त्रता दी गई है जस—व्यक्ति को बूढ़ावस्था में सहायता देना आराम व अवकाश का अधिकार देना आदि।

पूजोवादी दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि रूस में भाषण अभिव्यक्ति और सगठन का अधिकार अत्यन्त सीमित है तथा उसका प्रयोग व्यक्ति वस्तुतः साम्यवादो सदस्य के रूप में ही कर पाता है, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सीमित अधिकारों की व्यवस्था में ही सोवियत रूस में एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जड़ें जमाई हैं जिसमें सबके लिए उचित रूप से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा विद्यमान है। अधिकारों की समाजवादी व्यवस्था से निःसंदेह रूस समृद्धि के पथ पर बढ़ा है और रूसी अधिकारों की व्यवस्था के कठोर से कठोर आलापक को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ साधारण व्यक्ति सुखी है तथा उस दैनिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की चिन्ता नहीं करती पड़ती।

रूस में यदि मौलिक अधिकार केवलमान दिवाव के लिए ही होने लगे तो सम्भवतः रूस इतना समृद्ध और उत्तम न होता जितना आज वह है। आज के रूसी नागरिक संसार के किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिये ईर्ष्या के विषय और डुनीती हैं। वास्तव में मौलिक अधिकारों का एक नया अर्थ दिया गया है और इस दृष्टि से ये मौलिक अधिकार पश्चिमी प्रजातन्त्रों के मौलिक अधिकारों से अधिक विकसित हैं।

4

रूस की सर्वोच्च सोवियत (THE SUPREME SOVIET OF THE U S S R)

‘सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ की व्यवस्था सार्वधी शक्ति का प्रयोग केवल सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा किया जाता है।’

—सोवियत संविधान

सोवियत सघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों का एक संघीय राज्य है जो समान सोवियत समाजवादी गणराज्यों के ऐच्छिक मिलन के आधार पर बना है। सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (U S S R) का केन्द्रीय अथवा संघीय शासन जिसको सोवियत रूस में अधिकृत सघ शासन (All Union Government) कहते हैं, निम्नलिखित अथवा उपकरणों द्वारा चलता है—

- 1 सर्वोच्च सोवियत (The Supreme Soviet)
- 2 प्रेसीडियम (The Presidium)
- 3 मन्त्रिपरिषद् (The Council of Ministers)
- 4 सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court)

सोवियत सघ की, सर्वोच्च सोवियत के द्वीय व्यवस्थापिका सभा है। संविधान की धारा 30 सर्वोच्च सोवियत को ‘सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ की राज्य सत्ता की सर्वोच्च अंग’ बताती है और अनुच्छेद 32 आदेश देता है कि ‘सोवियत सघ की व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च सोवियत ही करेगी। यह प्रेसीडियम मन्त्रिपरिषद् और सर्वोच्च न्यायालय सभी को अपेक्षा सार्वोच्च है क्योंकि यही इन तीनों का निर्माण करती है और ये तीनों अंग कम से कम सिद्धांत रूप में, इसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

सर्वोच्च सोवियत की रचना एवं कार्यप्रणाली

(The Construction and the Working of the Supreme Soviet)

द्विसदनीय व्यवस्थापिका

सर्वोच्च सोवियत द्विमदनात्मक विधान मण्डल है। इसके दोनो सदन ये हैं—

- 1 संघीय सोवियत (Soviet of the Union)
- 2 जातीय या राष्ट्रीयताओं की सोवियत (Soviet of the Nationalities)

अब सभी संघीय राज्यों के समान संघीय सोवियत निम्न सदन है और समष्टि रूप से सोवियत संघ की प्रतिनिधि है। जातीय सोवियत रूस की व्यवस्थापिका का उच्च मदन है और संघ की विविध इकाइयों एवं अथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है।

सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का निर्वाचन सार्वजनिक एवं बरसक मताधिकार (Universal & Adult Franchise) के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। सभी नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो पागल अथवा किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न हो अथवा अथ किसी कारणवश मताधिकार से वंचित न हो, प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। सोवियत संघ का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कम से कम 23 वर्ष है सर्वोच्च सोवियत के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। प्रत्याशी के सम्बन्ध में जातीय, धर्म, लिंग शिक्षा, सामाजिक स्थिति अथवा पूर्व कार्यवाहियाँ आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

संघीय सोवियत (Soviet of the Union) में प्रति तीन लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि (Deputy) एक निर्वाचन-क्षेत्र (Election District) से चुना जाता है। सोवियत संघ का यह सदन समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन के निर्वाचित प्रतिनिधियों में सोवियत संघ के प्रत्येक प्रदेश के कुछ प्रतिनिधि अवश्य होते हैं। यदि एक और उत्तरी प्रदेश के एकिक्रमों हैं तो दूसरी ओर दक्षिण के काकेशिया निवासी हैं। प्रतिनिधियों में लगभग 38 प्रतिशत श्रमिक, 26 प्रतिशत कृषक तथा 36 प्रतिशत अन्य बुद्धिजीवी सिपाही तथा कार्यालय प्रतिनिधि होते हैं। लगभग 20 प्रतिशत स्त्रियाँ भी होती हैं।

इस दृष्टि में जसा कार्टर (Carter) ने कहा है, “सर्वोच्च सोवियत सामाजिक एवं राष्ट्रीय समानता का बड़ा सुन्दर प्रतीक है। संघीय सोवियत की संसद संख्या लगभग 700 रहती है। यह सदस्य संख्या निश्चित नहीं है और प्रायः बदलती रहती है।

जातीय सोवियत (Soviet of the Nationalities) का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है बल्कि वह विभिन्न राष्ट्रीय हिन्ना और मज्जितियों का प्रतिनिधित्व करती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संख्या, इकाइयों का भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया है—संघीय गणराज्यों (Union Republics) में प्रत्येक 25 स्वशासी गणराज्यों (Autonomous Republics) में प्रत्येक 15 स्वशासी क्षेत्रों (Autonomous Regions) में प्रत्येक 5 और राष्ट्रीय क्षेत्रों (National Areas) में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि भेजता है। जातीय क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या इन प्रकार लगभग 650 रहती है किन्तु सन् 1966 चुनाव के समय से यह संख्या बढ़ाकर 750 बढ़ी गयी है। इन प्रकार के

प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि जिस सभ्य गणराज्य में जितनी अधिक अधिनस्थ इकाइयाँ होती हैं उतनी ही अधिक प्रतिनिधित्व उन्हीं ज्ञानीय सोवियत में प्राप्त होता है ।

सदस्यों के अधिकार और दायित्व

प्रत्येक देशों की भाँति सोवियत रूस में भी व्यवस्थापिका अर्थात् सर्वोच्च सावियत के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार हैं और साथ ही उनके कुछ विशेष दायित्व भी हैं । प्रत्येक सदस्य के लिए यह बाँझ है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों में सम्पर्क रखे उन्हें शासन की बायबाहियाँ की रिपोर्ट देता रहे, अपने क्षेत्र के बन्धुओं के सम्बन्ध में सरकार की ओर से बायबाहरी कराने का प्रयत्न करे, आदि । यह व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य अपने दायित्व को पूरा नहीं कर, तो उसके क्षेत्र के निर्वाचक अपने बहुमत से उसको सदस्यता में वचित कर दें ।

कामकाल एवं क्षेत्र

संविधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का कार्यकाल 4 वर्ष है किन्तु दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत को अवधि से पूर्व भी भंग कर सकती है । ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि प्रेसीडियम दो माह के भीतर दुबारा चुनाव की व्यवस्था करे और नयी चुनी हुई सर्वोच्च सोवियत की बैठक निर्वाचन से तीन महीने के भीतर बुलाये । यह पातक्य है कि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन साथ-साथ ही भंग किये जाते हैं और साथ ही उनकी बैठकें बुलाई जाती हैं । सर्वोच्च सोवियत के सत्र अत्यन्त अल्पकालीन होते हैं, सामान्यतः एक सप्ताह के लिए ।

सर्वोच्च सोवियत का प्रत्येक सदन अपना एक सभापति और 4 उपसभापति चुनता है । अधिनासत इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें ही होती हैं और ऐसी परिस्थिति में दोनों सदन के सभापति या अध्यक्ष बारी बारी से सभापति या अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करने हैं । दोनों सदन औपचारिक विधान और बजट पर विचार करते समय अलग अलग बैठ सकते हैं और मत दे सकते हैं । लेकिन नियुक्तियों या प्रतिवेदनो जैसे अर्थ काय के लिए व एक साथ मत देते हैं ।

संविधान में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दोनों सदनों के सम्मिलित सत्रों की भी व्यवस्था की गई है—1 सर्वोच्च सोवियत का प्रेसीडियम का निर्वाचन करने के लिए, 2 मंत्रिपरिषद् का निर्वाचन करने के लिए 3 सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों का निर्वाचन एवं भंग करने के लिए, 4 सावियत सत्र के प्रोक्कुरेटर जनरल (Procurator General) का निर्वाचन करने के लिए । सर्वोच्च सावियत के विभिन्न आयोगों (Commissions) की रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदनों पर भी विचार करने के लिए सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र ही सम्भवन होता है ।

काय प्रणाली

अध्यक्ष एवं विविध आयोग—सर्वोच्च सोवियत के प्रत्येक सदन का एक अध्यक्ष होता है, जिसे प्रत्येक सदन अलग-अलग चुनता है । अध्यक्ष अपने अपने सदन

की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बैठक का संचालन करते हैं और अनुशासन रखते हैं। दोनों सदन की सम्मिलित बैठक में दोनों सदनों के अध्यक्ष बारी-बारी से अध्यक्षता करते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक नये सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक सदन एक एक परिचय या परमाधिकार आयोग (Credential Commission) का निर्वाचन भी करता है, जिसका प्रमुख कार्य इस बात का प्रमाण-पत्र देना होता है कि सदस्यों का निर्वाचन विधिपूर्वक होता है या नहीं। प्रत्येक सदन कुछ स्थायी आयोगों का निर्वाचन भी करता है। ये आयोग विश्व के अन्य देशों की विधान मण्डल की समितियों की भाँति ही कार्य करती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के नाम ये हैं—बजट आयोग (Budget Commission), वदेशिक विषयों का आयोग (Commission of Foreign Affairs), विधायन आयोग (Legislative Commission), उच्चतर समस्या का आयोग (Commission of the Elders)। विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए और भी विभिन्न आयोग अथवा समितियों का निर्माण किया जाता है। यद्यपि इन स्थायी समितियों का विधिवत् कार्य नहीं किया हुआ होने के तथ्यापि ये अधिवेशन के बीच की अवधि में बड़ा लाभकारी कार्य करती हैं। सोवियत संघ और सोवियत जातियों का वैधानिक प्रस्ताव समितियाँ सर्वोच्च सोवियत के सम्मुख प्रस्तुत विधेयकों पर अपना निर्णय देती हैं और स्वयं अपनी ही ओर से तथा सदन के प्रादेशानुसार विधेयकों का मसविदा तैयार करती हैं। ये समितियाँ अपने कार्य के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिकों और श्रमिकों की एक विभाग मन्त्रियों से नागरिकों के सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए सहायता देती हैं।

व्यवस्थापन प्रक्रिया—रूसी व्यवस्थापिका के दोनों सदन समान-पदी हैं। उन्हें व्यवस्थापन के सम्बन्ध में समान अधिकार प्राप्त हैं। सोवियत संविधान में धारा 85 में और मरदान-सम्बन्धी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया का व्यवहार होता है। कोई भी विधेयक दोनों सदन किसी भी सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह उसी समय विधि का रूप धारण करता है जब वह 111 मन्त्रियों के बहुमत द्वारा स्वीकृत हो जाता है।

है और उसके द्वारा स्वीकृत होने पर ही वह कानून बनता है और प्रेसीडियम के हस्ताक्षर के बाद वह लागू कर दिया जाता है।

चूँकि व्यवस्थापन के विषय में सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन को समान अधिकार प्राप्त हैं, अतः संविधान में उस सभावाक्य के समाधान के लिए भी व्यवस्था की गयी है जहाँ दोनों सदन के बीच मतभेद पड़ा हो जाए। मतभेद की ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त विधेयक को समझौता आयोग (Conciliation Commission) के पास भेजा जाता है। आयोग में दोनों के सदस्यों के बराबर बराबर प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यदि आयोग समझौता कराने में सफल नहीं होता तो उस विषय पर दोनों सदन पुनः विचार करते हैं और यदि फिर भी समझौता नहीं होता तो प्रेसीडियम दोनों सदन को भग्न करके नये आम निर्वाचन का आदेश दे सकता है। तथापि व्यवहार में यही पाया गया है कि साम्यवादी दल के कठोर अनुशासन के कारण कभी कोई गतिरोध पड़ा नहीं जाता। प्रायः कभी ऐसा अवसर नहीं आता जब गतिरोध को दूर करने के लिए उपरोक्त कार्यप्रणाली को अपनाया जाय।

सर्वोच्च सोवियत के अधिकार और कार्य

(Powers and Functions of the Supreme Soviet)

संविधान की चौदहवीं धारा में इसके अधिकारों और कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं—

विधायी अधिकार

व्यवस्थापन पर सर्वोच्च सोवियत का एकाधिकार है। वही सम्पूर्ण सभ के लिए आवश्यक कानून बनाती है। वह इकाइयों के कानून के ऊपर कानून बनाने में भी सक्षम है। संविधान की धारा 20 से स्पष्ट होता है कि यदि सघीय कानून और इकाइयों के कानूनों में प्रतिरोध हो तो सघीय कानून ही माय होगे। सर्वोच्च सोवियत के व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार वास्तव में बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक पद्धति वार्षिक विधि फौजदारी एवं व्यावहारिक संहिता से सम्बन्धित विधान कानूनों को निपटाने नागरिकों तथा विदेशियों से सम्बन्धित कानून बनाने, विवाह और परिवार से सम्बन्धित विधायन कार्यों के सिद्धांतों का निर्धारण करने, श्रमिक विधायन के लिए आधारभूत मिद्धांतों का निश्चय करने आदि का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सोवियत पर ही है।

वित्तीय अधिकार

सन् 1965 के बजट अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च सोवियत ही पूरे देश के लिए बजट पारित करती है। पिछले वर्ष में हुए श्रमिक व्यवस्था के लिए पूरक मांगे भी यही स्वीकृत करती है। सोवियत सभ का वार्षिक योजनाया का निर्धारण और संचालन करने सभ व गणराज्यों तथा स्थानीय बजटों को जाने वाले करो तथा राजस्वों का निषर्गित करने, ऋण लेने-देने आदि का उत्तरदायित्व सर्वोच्च सोवियत पर ही है।

बजट इसके दोना सदना मे से किसी भी मदन म प्रस्तुत किया जा सकना है। दोनो सदनों की बजट सम्बन्धी शक्तिया बराबर हैं। बजट के साथ ही बहुधा आर्थिक नियोजन पर भी वाद विवाद होता है। इस समय दोना सदना को समुक्त बठक म एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिस पर बाद मे दोना सदन पुन अलग अलग विचार करते हैं।

कायपालिका सम्बन्धी अधिकार

सर्वोच्च सोवियत को कायपालिका सम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त है। प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध युद्ध और शांति के प्रश्ना का निवारण, विदेशी-व्यापार, कर-व्यवस्था, आर्थिक नियोजन सोवियत सभ म नये गणराज्यों का प्रवेश, गणराज्यों के सीमा परिवर्तन को मान्यता, राज्य को सुरक्षा, गणराज्यों और सभ सरकार के सम्बन्धों की संवधानिक दृष्टि से सुरक्षा आदि विषया पर सोवियत रूस को नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च सोवियत ही सोवियत सभ को सेनाप्रा का संगठन करने, गणराज्यों के सैनिक संगठन के नियमों के सिद्धांत तय करन, नये प्रदेशों तथा स्वायत्त शासन प्रदत्त गणराज्यों और स्वायत्त जनपदों के निर्माण को मान्यता देने का उत्तरदायित्व वहन करती है। मुद्रा एवं साल प्रणाली का संचालन करने राजकीय बीमा का संगठन करने भूमि, वन खान जल आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में भूत सिद्धांतों को स्थिर करने, बका तथा औद्योगिक व कृषि संस्थानों और व्यावसायिक उद्योगों का प्रबंध करने के लिए वही उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल का बनाने और उस पर नियन्त्रण करने का अधिकार भी उस ही प्राप्त है।

यायिक अधिकार

यायिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सोवियत की विशेष स्थिति है। रूस में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। वहाँ सर्वोच्च सोवियत को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) विशिष्ट न्यायालय (Special Court) तथा प्रोक्यूटोर जनरल (Prosecutor General) आदि का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। वही सभी उच्च न्यायाधिकारियों को चुनती है और न्यायिक संस्थाओं का नियन्त्रण करती है। यायिक पद्धति 'यायिक' विधि फौजदारी एवं व्यावहारिक संहिता से सम्बन्धित विवायन कार्यों को निपटान, सभ के सभी बंदिबा को मुक्त करन तथा क्षमा प्रदान करने आदि का अधिकार भी सर्वोच्च सोवियत को है।

अन्य अधिकार

सर्वोच्च सोवियत को कुछ और भी महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सोवियत रूस का प्रतिनिधित्व करना विदेश से संधिया तथा संधि विच्छेद करना तथा संधीय गणराज्यों और विदेशों में सम्बन्ध स्थापित करने की सामान्य विधि निर्धारित करना, सर्वोच्च सोवियत का ही काम है। उनके प्रतिरक्त सर्वोच्च सोवियत को ही केवल यह अधिकार है कि वह मविधान में

संशोधन करे। उसके प्रत्येक सदन में मन्त्रों का कम-से-कम दो तिहाई बहुमत होने पर ही संशोधन प्रस्ताव पारित हो सकता है।

स्पष्ट है कि सर्वोच्च सोवियत का अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापन, काय गलन और न्यायपालन सभी क्षेत्रों तक व्यापक है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका का सर्वोच्च नियम पूर्णरूप से लागू किया गया है।

सर्वोच्च सोवियत का मूल्यांकन (Evaluation of the Supreme Soviet)

प्रकट है कि सर्वोच्च सोवियत रूस के संविधान में अत्यन्त शक्तिशाली संस्था है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में जिस प्रकार की सर्वोच्चता वहाँ की संसद को प्राप्त है, प्रायः वसी ही सर्वोच्चता रूस में सर्वोच्च सोवियत को प्राप्त है, परन्तु व्यवहार में इंग्लैंड की ही भाँति रूस में भी सर्वोच्च सोवियत अधिकांशतः मन्त्रिमण्डल (Council of Ministers) के नियंत्रण में और उसके पथ प्रदर्शन के अनुसार ही चलती है। टाउ टर ने लिखा है 'अभी तक सर्वोच्च सोवियत का कार्य यह रहा है कि वह पूरे नियमों का अनुसमर्थन करती रही है या प्रचार का साधन बनी रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि समय-समय पर अवसरानुकूल शासन की नीति पर प्रतिनिधि निष्ठा के रूप में अपना अनुमोदन और अनुसमर्थन प्रदान करती रहे।'

अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्वोच्च सोवियत न मन्त्रि-परिषद् (Council of Ministers) के प्रति अविश्वास पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो। व्यवस्थापन काम में पहले मन्त्रि-परिषद् ही करती है। सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन के नहीं होने के समय अध्यादेशों के रूप में कानून निर्माण का कार्य प्रेसीडियम द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापन सभा जो प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें प्रायः सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत कर लिये जाते हैं। सर्वोच्च सोवियत का अधिकांश कार्य यही होता है कि वह मन्त्रि-परिषद् अथवा प्रेसीडियम द्वारा प्रस्तुत विविध प्रतिवेदनों, प्रस्तावों और निष्णया की पुष्टि करे।

यह भी कहा जाता है कि सर्वोच्च सोवियत साम्यवादी दल की प्रतिष्ठाया है क्योंकि देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में इसी दल का आधिपत्य है। सर्वोच्च सोवियत में विरोधी दल के अभाव में वाद-विवाद और उत्तर-प्रत्युत्तर प्रायः निष्प्राण होते हैं।

सर्वोच्च सोवियत की स्थिति व्यावहारिक रूप में इसलिए भी क्षीण है कि उसका अधिवेशन वर्ष में केवल दो बार होता है और वह भी अधिक-से अधिक 12 दिन का। स्पष्ट है कि इतने से अल्पकाल में कोई भी इतने बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को नहीं निपटा सकता।

पुनश्च एक बात यह भी है कि सर्वोच्च सोवियत के जितने सदस्य होते हैं वे प्रायः वही न-वही रोजगार से लगे हुए व्यक्ति होते हैं और इस कारण सर्वोच्च सोवियत अपने व्यवस्थापन कार्य का निर्वाह प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाती।

परन्तु इन सब आलोचनाओं से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सर्वोच्च सोवियत केवल प्रचार का रंगमंच है और सरकारी नीति तथा वार्यों पर खर स्टाम्प लगाने वाली मशीन मात्र है। सर्वोच्च सोवियत के आयोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करते हैं। कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत सुझावों का परीक्षण करते हैं, उनमें संशोधन लाते हैं और कभी-कभी उन्हें अस्वीकृत भी कर देते हैं। सर्वोच्च सोवियत का महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है कि इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से मंत्रियों को अवगत कराते हैं। मंत्रिगण तदनुकूल अपनी नीतियों में परिवर्तन और संशोधन करते रहते हैं। इस प्रकार सावजनिक जीवन के नियमन पर सर्वोच्च सोवियत का शक्तिशाली महत्व भी कम नहीं है। इसमें देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि जो विविध राष्ट्रीयताओं, व्यवसायों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं एकत्र होते हैं। वे नेताओं के साम्यवादी सन्देश से अनुप्राणित होकर समाजवाद को अपने अपने क्षेत्रों में डलवाते हैं। साथ ही दलीय नेताओं और सर्वोच्च सोवियत दोनों में काफी सम्पर्क एवं सामंजस्य रहता है, क्योंकि देश के प्रमुख नेता सर्वोच्च सोवियत में अवस्थित रहते हैं। अन्त में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में विश्वव्यापी ह्रास हुआ है और इस प्रवृत्ति से सर्वोच्च सोवियत भी बची नहीं रह सकी है।

5

रूस का प्रेसीडियम (THE PRESIDUM OF THE U S R)

“प्रेसीडियम सरकार के कार्यों का प्रबंध करने में अपनी
जननी अर्थात् सर्वोच्च सोवियत की अपेक्षा अधिक
क्रियाशील रही है।”

—ग्रॉग एव जिंक

सोवियत समाजवादी गणराज्य सभ की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम एक ऐसी सस्था है जिसकी तुलना विश्व के किसी भी राज्य की किसी भी अन्य सस्था से नहीं की जा सकती। स्विस् कायपालिका की भांति इसका संगठन सामूहिक (Collective) है। इसके कार्य मिश्रित हैं। इसके कृत्यों में कुछ कायपालिका सम्बन्धी, कुछ व्यवस्थापिका सम्बन्धी और कुछ न्यायिक प्रकृति के कृत्य हैं। एक ओर तो यह अन्य देशों में पाये जाने वाले राज्याध्यक्ष (Head of the State) के अधिकारों का प्रयोग करती है और दूसरी तरफ अधिवेशन के अंतर्काल में सर्वोच्च सोवियत के स्थान पर कार्य करती है।

प्रेसीडियम का संगठन (The Composition of the Presidium)

निर्वाचन एवं सदस्य संख्या

सोवियत सभ की सर्वोच्च सोवियत अपने दाना सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन में प्रेसीडियम का निर्वाचन करती है। अधिवेशन में इसकी सदस्य संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु इसकी सदस्य संख्या समय और आवश्यकता के अनुसार सदैव बदलती रही है। सन् 1936 में इसकी सदस्य संख्या 37 थी, तो इस समय 32 है। इसमें एक अध्यक्ष (President), सभ के 15 गणराज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में 15 उपाध्यक्ष (Vice Presidents) एवं मंत्रि और 15 अन्य सदस्य सम्मिलित हैं। यह परम्परा बन गई है कि प्रत्येक सघीय गणराज्य (U Republic) की प्रेसीडियम के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष चुन लिया जाना परम्परा हो राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधित्व तथा सघीय एकता के आवश्यक गमभी गया है।

सदस्यता—सामान्यतः सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों में सही प्रेसीडियम के सदस्य चुने जाते हैं लेकिन सांविधानिक रूप में यह अनिवार्य नहीं है। प्रेसीडियम के सदस्यों में प्रायः साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता और सचदल के उच्च पदाधिकारी रहते हैं। सन् 1936 के बाद में इसकी सदस्यता के सम्बन्ध में दो प्रतिबंध लगा दिये गये हैं—प्रथम, मन्त्रिपरिषद् के सदस्य प्रेसीडियम के सदस्य नहीं हो सकते, एवम् द्वितीय, सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों के अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि यह स्वयं सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है।

कार्यकाल—प्रेसीडियम का कार्यकाल सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल पर निर्भर करता है। संविधान में सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल चार वर्ष निर्धारित किया गया है, अतः प्रेसीडियम का कार्यकाल भी चार वर्ष ही है। संकट के समय अथवा युद्धकाल में या अन्य किसी कारण से जब सर्वोच्च सोवियत का कार्यकाल बढ़ जाता है तो प्रेसीडियम का कार्यकाल भी स्वयमेव ही बढ़ जाता है।

अध्यक्ष—प्रेसीडियम का एक अध्यक्ष (Chairman) होता है। अन्य सदस्यों की भांति इसका चुनाव भी सर्वोच्च सोवियत करती है। अध्यक्ष के होने के नाते इसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसका स्थान अन्य सदस्यों के समकक्ष (Equal) ही होता है।

प्रेसीडियम का अध्यक्ष स्वयं प्रेसीडियम को सौंप गये कुछ कार्यों को पूरा करता है, यद्यपि संविधान में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। जब सर्वोच्च सोवियत द्वारा कानूनों को पारित कर दिया जाता है तब उनका प्रकाशन अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के उपरान्त होता है। यही प्रेसीडियम के स्थान पर आज्ञापतियाँ (Decrees) पर हस्ताक्षर करता है। प्रेसीडियम का अध्यक्ष विदेशी राजदूतों एवं कूटनीतिज्ञों का स्वागत करता है, अन्य राज्यों के अध्यक्षों से संधि का आदान-प्रदान करता है और इसा प्रकार के अन्य कार्यों का सम्पादन करता है। वह एक प्रकार से सोवियत संघ का नाम मात्र का शासक (Titular Head) है। विदेशी लेखक अध्यक्ष का सोवियत संघ का राष्ट्रपति मानते हैं क्योंकि वह कुछ ऐसे कार्यों का सम्पन्न करता है जो पाश्चात्य देशों में राज्याध्यक्षों के कार्य हैं।

प्रेसीडियम के अधिकार और कर्तव्य (Powers and Functions of the Presidium)

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सर्वोच्च सोवियत में प्रेसीडियम को संविधान की धारा 49 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं—

- (1) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन आमन्त्रित एवं स्थगित करना।
- (2) सोवियत रूस के प्रचलित अधिनियमों की व्याख्या करना और आदेश देना।
- (3) आज्ञापतियाँ (Decrees) जारी करना।
- (4) सुदृढ पहल-बंदशी (Initiative) करने या किसी एक मस्य प्रस्ताव की मांग पर राष्ट्रव्यापी मतगणना (Referendum) करना।

- (5) सावित्यत सभ के मन्त्री-मण्डल और मन्त्रराज्यों के मन्त्री मण्डल के नियम व आज्ञायें यदि कानून का विरोध करे तो उन्हें रह करना।
- (6) सम्माना (खिताब तथा पदको) और उपाधियों की व्यवस्था करना।
- (7) सर्वोच्च सोवियत की बैठको के अन्तरिम समय में मन्त्रि-मण्डल के प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर किसी मन्त्री को भर्तग करना तथा नियुक्ति करना। किन्तु बाद में इसको सर्वोच्च सोवियत से पुष्टि कराना आवश्यक है।
- (8) क्षमा-दान देना।
- (9) सेना के उच्च अधिकारों का नियुक्त अथवा पदच्युत करना।
- (10) विदेशी आक्रमण के समय युद्ध घोषणा करना यदि सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन न हो रहा हो।
- (11) ऐच्छिक अथवा अनिवार्य भरती की घोषणा करना।
- (12) विदेशी राजदूतों का स्वागत करना और समय आने पर उन्हें वापिस भेजना।
- (13) विदेशों में पूर्ण शक्ति सम्पन्न राजदूत (Pleni Potentiary) को नियुक्त करना अथवा वापिस बुलाना।
- (14) पूरा अथवा आंशिक रूप से नागरिकों का सैनिक सेवा के हतु बाध्य करना।
- (15) विदेशिक मामलों में सर्वोच्च सोवियत का प्रतिनिधित्व ग्रहण करना।
- (16) विशेष स्थानों अथवा सम्पूर्ण सोवियत सभ में देश की प्रतिरक्षा अथवा सावजनिक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा के हित में मासल-ता की घोषणा करना।

उक्त सूची से यह स्पष्ट है कि प्रेसीडियम की शक्तियां महत्वपूर्ण एवं विविध दृष्टिणी हैं। उसे विधायिनी, कार्यपालिका एवं न्यायिक क्षेत्रों में पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। वह सर्वोच्च सोवियत की अपेक्षा सरकार के कार्यों का प्रबंध करने में अधिक भाग लेती है। फाइनर ने ठीक ही लिखा है कि, 'प्रेसीडियम वास्तविक' एवं कानूनी रूप से सोवियत सभ की सतत सरकार है।'

प्रेसीडियम की शक्तियों की व्यावहारिकता सर्वोच्च सोवियत व मन्त्री परिषद् से उसका सम्बंध

इस सम्पूर्ण विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेसीडियम की शक्तियां अत्यन्त व्यापक और बहुमुखी हैं तथा वे यानन के प्रत्येक क्षेत्र को छूती हैं। साविधानिक स्थिति के अनिश्चित उनकी व्यावहारिक स्थिति भी यही है। प्रेसीडियम संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपभोग करती है। टाज्स्टर ने कहा है कि कवल कुछ अधिकारों को छाडकर प्रेसीडियम ने अपने अधिकारों का पूरा उपयोग और प्रयोग किया है। मन्त्रियों का नियुक्ति और पदच्युति, उपाधियों का वितरण क्षमादान, सभा के पदाधिकारियों की पनेतृति और परिवर्तन, मागन

कानून की घोषणा, सेना का प्रचालन और विचलन, सन्धिया की सन्तुष्टि, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और विदेशी राजदूतों की स्वीकृति आदि विधेयाधिकारों का पूरा पूरा प्रयोग प्रेसीडियम के द्वारा किया गया है। इसने अभी तक केवल दो अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है—सर्वोच्च सोवियत को भंग करने के अधिकार का और जनमत संग्रह की व्यवस्था करने का।

कायपालिका और न्यायिक अधिकारों के अतिरिक्त व्यवस्थापन के क्षेत्र में तो प्रेसीडियम ने और भी प्रभावशाली कार्य किये हैं। प्रेसीडियम ने अपनी आज्ञाप्तियों के द्वारा सर्वोच्च सोवियत के विधि निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त हस्तक्षेप किया है। उसने ये आज्ञाप्तियाँ न केवल उस समय प्रसारित की हैं जबकि सर्वोच्च सोवियत का आमंत्रण कठिन था, प्रत्युत् साधारण समय में भी इस शक्ति को प्रयुक्त किया है। सच के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी उसने आज्ञाप्तियाँ प्रसारित की हैं जो संविधान द्वारा स्पष्टतः सर्वोच्च सोवियत के अधिकार क्षेत्र में गिनाई गई हैं और जो प्रेसीडियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, जैसे—विभिन्न संघीय गणराज्यों के मध्य सीमा परिवर्तन का सम्मेलन करना, नवीन स्वशासी गणराज्या और प्रान्तों एवं क्षेत्रों के निर्माण के लिए सम्मति प्रदान करना आदि।

प्रेसीडियम की आज्ञाप्तियों की यद्यपि सर्वोच्च सोवियत द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है लेकिन ये केवल औपचारिक रस्म हैं। सर्वोच्च सोवियत बिना वाद-विवाद अथवा छान बिन के प्रायः अनिवार्य रूप से आज्ञाप्तियों की स्वीकृति दे देता है। अभी तो स्थिति यही है कि प्रेसीडियम की आज्ञाप्तियाँ संविधान में संशोधन तक ला देती हैं।

मन्त्रि-परिषद् एवं प्रेसीडियम का भी परस्पर बहुत कुछ सम्बन्ध है। मन्त्रि-परिषद् के समस्त सदस्य सर्वोच्च सोवियत से लिए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। परिणामस्वरूप जब सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन नहीं होते उस समय वह अपने कार्यों के लिए प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। वस्तुतः प्रेसीडियम मन्त्रि-परिषद् की नीति एवं सभी कार्यों का नियंत्रण करती है। यदि कोई मन्त्री उचित कार्य नहीं करता तो यह उस पदभूत कर सकती है। प्रेसीडियम को नये मन्त्रियों की नियुक्ति का भी अधिकार है। यह मन्त्रि-परिषद् के संविधान विरोधी निर्णयों को रद्द कर सकती है। मन्त्रि-परिषद् का भी महत्त्वपूर्ण कार्य करती है जैसे संधि तथा युद्ध करना, राजदूतों की नियुक्ति करना दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत करना नये पद एवं सम्मान प्रदान करना इत्यादि सभी कार्य में प्रेसीडियम की स्वीकृति अनिवार्य होती है। मन्त्रि-परिषद् के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेसीडियम के निर्णयों और आज्ञाओं को माने। सोवियत रूस का मन्त्रि-परिषद् का रूप वस्तुतः कायपालिका (Executive) मस्या का न होकर प्रशासनिक (Administrative) मस्या का है और उसका कार्य प्रेसीडियम के निर्णयों का क्रियान्वित करना मात्र है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रेसीडियम सिर्फ मित्रान में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी राज्य शक्ति के उच्च अंग" में एक है, जिनमें एक

१. १. न्यायाधीश संस्था की आवश्यकता का पूर्ति की है।

6

रूस की मन्त्रिपरिषद्

(THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE U S S R)

‘सोवियत सरकार तथा सोवियत संघ की राज्य सत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका और प्रशासकीय अङ्ग मन्त्रिपरिषद् है।’

—सोवियत संविधान

सोवियत शासन-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता उसका दुहरापन (Duality) है। कार्यपालिका शक्ति को प्रेसीडियम व मन्त्रिपरिषद् के मध्य बाँटा गया है, किन्तु दोनों शासनांगों में अन्तर यह है कि प्रेसीडियम मुख्यतः सर्वोच्च सोवियत के बदले में विधि-निर्मात्री निकाय है, जबकि मन्त्रिपरिषद् मुख्यतः कार्यपालिका एवं प्रशासकीय संस्था है। स्टालिन-संविधान की धारा 64 में भी कहा गया है कि “सोवियत सरकार और सोवियत संघ की राज्य सत्ता का सर्वोच्च कार्यपालिका और प्रशासकीय अङ्ग मन्त्रिपरिषद् है”। सन् 1946 तक इस कार्यकारिणी समिति को ‘कौमिल भॉफ पीपुल्स कमिस्सर्स’ (Council of Peoples' Commissars) कहा जाता था, किन्तु अब इसका नाम “कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स” (Council of Ministers) है।

मन्त्रिपरिषद् की रचना एवं कार्यप्रणाली

(The Composition and Working of Council of Ministers)

निर्वाचन

मन्त्रिपरिषद् का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाता है। पहले मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री (Chairman) की नियुक्ति होती है और तब उसको सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की। मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार भी सर्वोच्च सोवियत को ही दिया गया है। यदि सर्वोच्च सोवियत अधिवेशन में न रहे तो प्रेसीडियम मंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति करती है। प्रेसीडियम को यह भी अधिकार है कि वह अन्य मंत्रि पदों का उत्पन्न कर सके और उन्हें समाप्त भी कर सके। वह प्रधानमन्त्री की सलाह से मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकती है। पर प्रेसीडियम के इन सत्तारक्षक कार्यों का पुष्टिकरण सर्वोच्च सोवियत द्वारा होना आवश्यक होता है। इस में यह स्मरणीय है कि सोवियत संघ में वैधानिक सत्य एवं राजनीतिक प्रधान मंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति का अन्तिम

की केन्द्रीय समिति के प्रेसीडियम के हाथ में है। सर्वोच्च सोवियत का अधिकार तादिसावामात्र है।

कायकाल

मन्त्रिपरिषद् के कायकाल के विषय में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी इसका कायकाल प्रायः सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल के साथ ही चलता है। सर्वोच्च सोवियत का कायकाल सामान्यतः 4 वर्ष है अतः मन्त्रिपरिषद् भी सामान्यतः 4 वर्षों तक पदारूढ़ रहती है। लेकिन यदि 4 वर्षों के अन्तर्गत ही सर्वोच्च सोवियत भंग कर दी जाए और नयी सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हो, तो नयी मन्त्रिपरिषद् का भी निर्माण होगा। सर्वोच्च सोवियत अवधि से पूर्व भी मन्त्रिपरिषद् को भंग कर सकती है।

रचना

संविधान में मन्त्रिपरिषद् की रचना अथवा उसके समूह का उल्लेख मिलता है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित थे एण्डो में रखा जा सकता है—(1) अध्यक्ष (Chairman), (2) प्रथम उपाध्यक्ष (First Deputy Chairman) (3) उपाध्यक्ष (Deputy Chairmen), (4) सोवियत तन्त्र के मन्त्रिगण (The U S S R Ministers), (5) मन्त्रिपरिषद् की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, यथा—राजकीय योजना समिति (State Planning Committee) का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सामग्री तथा यन्त्र-प्रदायिनी समिति (Committee on Material and Technical Supply of the National Economy) का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में आधुनिकतम कौशल लागू करने के लिए समिति (Committee for introducing advanced techniques in the National Economy) का अध्यक्ष, निर्माण समिति (Committee for Construction Affairs) का अध्यक्ष, कला समिति (Committee on Art Affairs) का अध्यक्ष, राजकीय बैंक परिषद् (Board of State Bank) का अध्यक्ष, उच्च शिक्षा समिति (Committee of Higher Education) का अध्यक्ष आदि।

रूस का मन्त्रिमण्डल इस प्रकार लगभग 50 सन्सों का हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि मन्त्रियों की संख्या में सदैव परिवर्तन होता रहना है। उदाहरणार्थ सन् 1936 में 32, सन् 1947 में 59, 1950 में 51, 1952 में 69 और 1962 में 71 सदस्य थे। वर्तमान परिषद् की सदस्य संख्या लगभग 84 है।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष—मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष की वही स्थिति है जो भारत अथवा इंग्लैंड जैसे संसदीय देशों में प्रधानमन्त्री का है। अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष (Chairman & First Deputy Chairman) दल प्रेसीडियम (Party-Presidium) के भी सदस्य होते हैं। मन्त्रिपरिषद् के अन्दर ये केन्द्रस्थल हैं। इन्हें मन्त्रिपरिषद् का प्रेसीडियम कहा जाता है। पाश्चात्य देशों की राजधानी में इन मन्त्रियों की आंतरिक मन्त्रिमण्डल (Inner Cabinet) कहा जा सकता है।

यह समुदाय मन्त्रिपरिषद् का मस्तिष्क अथवा संचालक मण्डल है जिसका कार्य विभिन्न विभागों का समन्वय करना निरीक्षण करना और नीति-निर्धारण करना है। अथ उपाध्यक्ष भी दल के चोटी के नेता होते हैं और उनमें से अधिकांश दल की प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं।

सोवियत सचिवान में प्रधानमंत्री पद की चर्चा नहीं की गई है, मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष (Chairman) को ही विदेशों में प्रधानमंत्री कहा जाता है। सोवियत मध्य में अथ मंत्री आते-जाते रहते हैं और उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं अथवा जानने का प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री अर्थात् अध्यक्ष की देश-विदेश के घोर हर जगह के लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान सचिव और शासक होता है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वे बहुत प्रभावशाली हुए हैं। मन्त्रिपरिषद् में अध्यक्ष की स्थिति बड़ी महत्व की होती है। वह उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, तथा उसके निर्णयों और अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करता है। वही मन्त्रिपरिषद् के काम का निरीक्षण करता है। उसे यह भी अधिकार है कि व्यक्तिगत मंत्रियों के निर्णयों को रद्द कर दे। उसकी स्थिति इसलिए और भी प्रभावशाली हो जाती है कि वह मन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष होने के साथ-साथ साम्यवादी दल का भी एक अत्यन्त प्रमुख नेता होता है।

दो प्रकार के मंत्री—सोवियत मध्य की मन्त्रिपरिषद् के अन्तर्गत दो विभिन्न प्रकार के मन्त्रालय पाये जाते हैं—(क) अखिल संघीय मन्त्रालय (All Union Ministries) (ख) संघ गणराज्य मन्त्रालय (Union Republican Ministries)। इन दोनों मन्त्रालयों में यही भेद है कि जहाँ प्रथम मन्त्रालय का सम्बन्ध सोवियत मध्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों से है, वहाँ दूसरे मन्त्रालयों का सम्बन्ध संघ गणराज्यों की सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध से है। संघ गणराज्यों के मन्त्रालय मध्य गणराज्यों की सरकार के मन्त्रालयों की क्रिया कलापों में समन्वय व एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। सोवियत संघीय प्रशासन के इन अंगों पर अंतिम नियन्त्रण संघीय मन्त्रिपरिषद् के संघ गणराज्यों के मन्त्रालयों का रहता है। इस प्रकार सोवियत संघ में एकीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस समय सोवियत मन्त्रिपरिषद् में लगभग 30 अखिल संघीय मन्त्रालय और 21 संघीय गणराज्य मन्त्रालय हैं। इनकी संख्या में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। मन्त्रालयों का निर्माण पुनर्गठन और विघटन सोवियत संघ के लिए आम बात है।

सहायोगी अंग—मन्त्रिपरिषद् की एक विशिष्ट शाखा आर्थिक सोवियत है, जिसका कार्य देश के प्रमुख उद्योगों, व्यवसायों आदि पर नियन्त्रण रखकर देश के उद्योग और अर्थ विवरण का निरीक्षण करना है। यह मन्त्रिपरिषद् की एक स्थाई संस्था है।

मन्त्रिपरिषद् के अन्तर्गत और भी अनेक समितियाँ, परिषदों और का संगठन किया जाता है जो मन्त्रिपरिषद् के सहायोगी अंग के रूप में

है। कला, रेडियो, शारीरिक व्यायाम, भौगोलिक समस्याएँ, सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में समितियाँ और सामूहिक चेतना, धार्मिक मामले आदि के सम्बन्ध में परिषदें संगठित की गई हैं। मन्त्रि-परिषद् से सम्बन्धित राजकीय मध्यस्थ आयोग, ग्रन्थि सघीय कृषि प्रदर्शनी सम्बन्धी मुख्य समिति, विज्ञान अकादमी और तात्त ऐजेंसी उत्प्रेक्षनीय हैं।

परिषद् की कार्य प्रणाली

मन्त्रि-परिषद् दैनिक कार्यों की संचालन करने वाली संस्था है, अतः इसकी बैठकें सप्ताह में कई बार होती हैं। प्रत्येक बैठक में आये सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में केवल सदस्यगण ही नियुक्तकारी मतदान कर सकते हैं। विशिष्ट मन्त्रि-परिषद् किसी को भी अपनी बैठक में भाग लेने की अनुमति दे सकती है या नियंत्रित कर सकती है। समितियाँ, परिषदों और आयोगों के अध्यक्ष, दल की राष्ट्रीय कार्यप्रणाली समिति के सदस्य और अन्य प्रभावशाली नेता प्रायः बैठकों में सम्मिलित होते हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। मन्त्रि-परिषद् का सम्बन्धित मन्त्री सर्वोच्च सोवियत में किये गये उसके विभागों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देता है। जिस सदन में वह प्रश्न किया गया हो, उसमें लिखित या मौखिक उत्तर तीन दिन के भीतर दिया जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक मन्त्री अपने प्रधान शासन-विभाग के कार्यों का संचालन करता है और अपने विभाग से सम्बन्धित आदेश निष्पादने तथा इन आदेशों को कार्यान्वित करने की योजना बनाता है। कामपालिका के होते हुए भी मन्त्रि-परिषद् विधि का प्रारूप तैयार करती है और सर्वोच्च सोवियत की विधि बनाने में सहायता देती है।

मन्त्रि-परिषद् के अधिकार एवं कार्य

(Powers and Functions of the Council of Ministers)

संविधान की धारा 68 में मन्त्रि-परिषद् के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (1) सोवियत संघ के विभागों के कार्यों गणराज्यों के शासन विभागों तथा अन्य आर्थिक अथवा सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यों का संचालन करना और उनमें सामंजस्य लाना।
- (2) सोवियत संघ की विधियों के आशय पर तथा उनके प्रावधानों के अनुसार आदेश निष्पादना और उनके अमल होने पर देख रेख रखना।
- (3) राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं एवं आय व्यय के निष्पादनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करना और मुद्रा व्यवस्था को ठीक रखना।
- (4) लोक व्यवस्था ठीक रखना राज्य के हितों की रक्षा करना और नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- (5) पर राष्ट्रीय सम्पत्ति को संचालित करना और उन्हें निश्चित कर, व्यावहारिक रूप देना।

का केन्द्रीय समिति के प्रमुख सदस्य होन हैं और उनकी स्थिति व्यवहारतः ऐसा जाना है कि स्वयं सर्वोच्च सोवियत तथा प्रेसीडियम पर नियन्त्रण रख सकती है। अतः यह स्वाभाविक है कि मन्त्रिपरिषद् प्रेसीडियम या सर्वोच्च सोवियत के नियन्त्रण में नहीं रहती और इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वह उनका प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए कार्य करे।

सोवियत रस में इङ्गलैंड के सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility) जैसा कोई वस्तु नहीं है। सर्वोच्च सोवियत में व्यक्तिगत रूप से मन्त्रियों की प्रालोचना शुरू की जाती है और कभी-कभी उन्हें पदच्युत भी कर दिया जाता है लेकिन व्यक्तिगत मन्त्रियों को पदच्युति से सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् के त्यागपत्र का प्रश्न नहीं उठता।

7

रूस की न्यायपालिका (THE SOVIET JUDICIARY)

‘बुजुआ वर्ग में सवहारा वर्ग की भूतपूर्व विजय
की रक्षा करने और समाजवादी निर्माण को
दृढ़ करने के कार्य में सोवियत न्यायपालिका
अभिक वष के अधिनायकत्व का
एक तेज और महत्वपूर्ण
अस्त्र है।’

—रिचकीव

कानून और न्याय व्यवस्था का पारस्परिक प्रगाढतम सम्बन्ध है और किसी भी देश की यायिक व्यवस्था को असी प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश को कानून विषयक मान्यताओं को ठीक से समझ लिया जाए। सोवियत रूस विद्व का प्रथम और सिरमौर साम्यवादी राष्ट्र है जिसकी न्याय-व्यवस्था कानून की साम्यवादी मान्यता से ओत प्रोत है।

कानून की साम्यवादी मान्यता

परम्परागत मान्यता यह है कि कानून (Law) निष्पक्ष है। लेकिन साम्यवादी मान्यता के अनुसार कानून का स्वरूप राज्य के स्वरूप के अनुसार होता है और वह राज्य की इच्छा का प्रतीक है। कानून राज्य के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा एक निरिवृत्, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे की रक्षा की जाती है। पूँजीवादी राज्यों के कानून के विषय में साम्यवादी मत यह है कि वह राज्य के हाथ में एक ऐसा यन्त्र है जिसका कार्य पूँजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करना है। पूँजीवादी दशा में कानून की समानता (Equality of Law) प्रथवा निष्पक्षता की बात उकोसला मात्र है, केवल बाम्तेविक असमानता को छिपाने की कुशल ढांग है।

साम्यवादी मान्यता के अनुसार राज्य में कानून का यह स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए कि वह सवहारा वर्ग के हितों की रक्षा करे और समाजवाद के निर्माण में सहायक हो। इस प्रकार कानून के स्वरूप के विषय में सोवियत विचारधारा का सार यह है कि उसे सदैव ऐसा होना चाहिए जिसमें समाजवाद को जड़ें अधिकाधिक मुहूर्त बन सकें, चाहे उसके द्वारा व्यक्ति का पूरी तरह राज्य के अधीन हो क्या न बना दिया जाए।

सोवियत न्यायपालिका का उद्देश्य

सोवियत संघ में न्यायपालिका को राज्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सहायक अंग माना गया है। सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग का राज्य है, अतः वहाँ न्यायपालिका का प्रमुख कर्तव्य भूतपूर्व प्रभुसत्ता सम्पन्न वर्गों का दमन करना और राज्यों में साम्यवाद की स्थापना करना एवं उसको दृढ़ बनाने में सहायता देना है। अगस्त 1938 के एक कानून और न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारों के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 'उनका कार्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के नागरिकों को देश के प्रति एवं समाजवाद के प्रति प्रेम की भावना, सोवियत कानूनों के पूरे पालन की भावना, समाज की सम्पत्ति की उचित परवाह, श्रम सम्बन्धी अनुशासन राज्य एवं समाज के कर्तव्य का ईमानदारी से पालन तथा राष्ट्र के नियमों के प्रति आदर की भावना की शिक्षा देना है।' इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत न्यायालयों का शैक्षणिक महत्त्व भी है। वे नागरिकों को समाजवाद की शिक्षा देते हैं।

उपरोक्त प्रसंग में यह याद रखना चाहिए कि सोवियत संघ में व्यवहार में साम्यवादी दल का शासन है, अतः सोवियत न्यायपालिका दल की दास है दल की रक्षा और दलीय नीतियों को लागू करने का साधन है। सारांश में, सोवियत संघ में न्यायपालिका राज्य का एक स्वतंत्र अंग नहीं होकर दल के अधीन और सरकार का एक सहायक अंग है। अमेरिका के समान वह शासन का सर्वोपरि अंग नहीं है। सोवियत रूस में न्यायपालिका का स्वरूप बंधनिक नहीं होकर राजनीतिक है।

सोवियत न्याय व्यवस्था की विशेषताएँ

(Characteristics or features of the Soviet Judiciary)

पश्चिमी प्रजातन्त्रों की तुलना में, न्यायिक क्षेत्र में भी सोवियत प्रणाली की समानता नहीं लाजी जा सकती। सोवियत न्यायपालिका के संगठन और उनकी कार्य-व्यवस्था में विभिन्न अनुपमता है जो उस प्रजावादी राज्यों में पूर्णतः विना कर देती है।

1. सोवियत संघ में न्यायपालिका का उद्देश्य सर्वहारा क्रांति को रक्षा करने और समाजवाद को दृढ़ स्थापना करना है। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में न्यायपालिका को स्थापना किसी वर्ग विशेष अथवा शासन व्यवस्था की रक्षा के लिए नहीं की जाती।

2. सोवियत संघ में न्यायपालिका शासन का ही एक अंग है और वह भी सर्वोच्च नहीं। रूस में न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य प्रशासन के उस अधिकार और उसके अधीन कार्यों के निरन्तर सहयोगी से किया जाता है जिसे प्रोसेक्यूटर जनरल (Prosecutor General) कहा जाता है और जिसका कार्य न्यायनिक सम्पत्ति की रक्षाला करना तथा उसमें सम्बंधित अपराधों के लिए अपराधियों का दण्ड दिनांक है। सोवियत न्यायपालिका का प्रशासकीय अथवा विधायक विभाग नहीं मानना की व्याख्या का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। रूसी न्यायिक व्यवस्था का मुक्त रूप में स्थापित ना करने हैं। कालीनिन (Kalinin) ने कहा कि

“यदि कोई न्यायाधीश कच्चा मात्रसंवादी है जो दल के निर्णयों के लिए शक्ति के साथ तब नही सक्ता तो वह बेकार है।” वस्तुतः सोवियत न्यायपालिका की प्रकृति राजनीतिक है, विधायी नहीं। कानून जो भी हो, 'यायपालिका सदैव इस राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि पूँजीवाद का नाश हो और दलीय नीति को क्रियान्वित किया जाए, कार्य करती है।

3 सोवियत 'याय-ध्वस्था की एक विशेषता यह है कि उसके न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। सर्वोच्च 'यायालय एवं विशिष्ट न्यायालयों के 'यायाधीशों का चुनाव सर्वोच्च सोवियत 5 वर्ष के लिए करती है। विविध गणतन्त्रों तथा अन्य दलीय शास्त्रों के 'यायालयों के 'यायाधीशों का निर्वाचन उनकी सोवियत 5 वर्ष के लिए करती हैं। सबसे नीचे के 'यायालयों और जन 'यायालयों के न्यायाधीशों को जिला के लोग 3 वर्ष के लिए चुनते हैं।

4 सोवियत न्याय प्रणाली में 'यायाधीशों के साथ साथ जन निर्धारक (Assessors) के निर्वाचन की व्यवस्था है। न्यायाधीश नियमित रूप से एक निश्चित कार्य काल तक राज्य की 'यायिक सेवा करता है जबकि जन-निर्धारक (Assessors) मामलों की सुनवाई के समय में ही कार्य करते हैं। निर्वाचक न्यायाधीशों और जन निर्धारकों या एसेसरों का अपने कार्य का प्रतिवेदन अपने निर्वाचन क्षेत्र को देना होता है।

5 सोवियत संघ में 'यायाधीशों को वापिस बुलाने के अतिरिक्त उनके प्रत्यावर्तन (Recall) की भी व्यवस्था है। वही निर्वाचक मण्डल जिसने 'यायाधीशों को निर्वाचित किया है, उनके प्रत्यावर्तन की मांग कर सकता है। नीचे के 'यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध सम्बन्धित गणतन्त्र की प्रेसीडियम की स्वीकृति से जिन के प्रोक््यूरेटर द्वारा और सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशों के विरुद्ध संघ की प्रेसीडियम की स्वीकृति से प्रोक््यूरेटर जनरल द्वारा फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है।

6 सोवियत संघ के सभी न्यायालयों में यदि किसी विशिष्ट मामले के लिए 'यायाधीश पर उपबन्धन कर दिये गये हों, सावजनिक और खुली कार्यवाही होती है। उसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अभियुक्त स्वतन्त्र रूप से निभय होकर अपने पक्ष का समर्थन कर सकता है और उस अपने पक्ष उपस्थित करने का पूरा अधिकार होता है।

7 सोवियत संघ के 'यायालयों में परवी करने वाले व्यक्तिगत वकील नहीं होते। मर्राधों की वाछनीय रक्षा करने के लिए 'यायालय स्वयं ही अधिकारताप्राप्त प्रवच करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि उकीता की फीम मुवकिनों के दल की क्षमता के अनुसार नियमित कर दी गई है। वकीलों को अपने काम के अनुसार 'वकील मण्डल (College of Advocates) से एक प्रकार का विधान मिलता है। सोवियत संघ में कानूनी व्यवसाय (Legal Profession) राज्य द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक स्थान पर जहाँ 'यायालय होते हैं वकाला के संघ हैं जिनमें

कानूनी व्यवसाय करने के योग्यता वाले व्यक्ति सदस्य होते हैं। वकील सभ के सदस्य के लिए उन सभी व्यक्तियों का, जिनको आवश्यकता पड़े, कानूनी सहायता देना अनिवार्य है और वे नियत फीस से अधिक फीस नहीं ले सकते। यदि न्यायालय यह निर्णय दे दे कि कोई व्यक्ति फीस देने योग्य नहीं है, तो उससे काम नहीं ली जाती है। किसी वकील को जो फीस मिलती है, वह उसको व्यक्तिगत फीस न होकर समस्त वकील मण्डल की फीस होती है और महीने के अन्त में कार्य एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर वह फीस सभी वकीलों में बाँट दी जाती है। लास्की का मत है कि इस व्यवस्था से वकीलों में कठोर व्यवहार और उत्तरदायित्व का विकास होता है।

8 सोवियत सभ के प्रत्येक नागरिक को, जिसका साधारण मताधिकार प्राप्त है किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश (Judge) या जन निर्धारक (Assessor) निर्वाचित हो सकता है। वहाँ पर न्यायाधीशों के लिए किसी विशेष योग्यता का होना आवश्यक नहीं। फिर भी प्रायः वे ही व्यक्ति न्यायाधीश, निर्वाचित किये जाते हैं जो साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं अथवा साम्यवाद के प्रति प्रबल समर्थक होते हैं।

9 प्रारम्भिक न्याय-क्षेत्र (Original Jurisdiction) के मामलों की सुनवाई प्रायः दो ऐसेमरा और एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अपील योग्य मामलों में सुनवाई अधिक न्यायाधीशों द्वारा होती है।

10 सोवियत न्याय व्यवस्था द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान की 127वीं धारा में स्पष्ट उल्लिखित है कि 'न्यायालय के निर्णय के बिना या प्रोक्स्यूरटोर की स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।'

11 सोवियत न्यायालयों का मुख्य लक्ष्य दण्ड देना ही नहीं है बल्कि अपराधी को सुधारना भी है। परन्तु जो व्यक्ति जन सम्पत्ति के नाशक हैं अथवा जो सड़ते बाज, लुटरे या अनुशासन को भंग करने वाले हैं उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता है।

12 सोवियत सभ में न्यायिक व्यवस्था में केन्द्रीयकरण अधिक है। यह दो बातों से स्पष्ट है—प्रथम तो रूस में कोई मधीय न्यायालय नहीं है बल्कि सम्पूर्ण सभ (Union) का एक ही न्यायालय है, और दूसरे इस न्यायालय की शक्ति का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है।

13 सोवियत सभ के कानूनों में जातीय नीति के लेनिनवादी सिद्धान्तों की स्पष्ट झलक मिलती है। समस्त नागरिक न्यायालय और कानून के समक्ष समान समझे जाते हैं। जाति, नस्ल अथवा धर्म आदि के आधार पर उन्हें कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता। संविधान की धारा 110 के अनुसार विभिन्न न्यायालयों की कार्यवाही सम्बन्धित प्रदेश की स्थानीय भाषा में ही होती है। यदि कोई व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता, तो वह दुभाषियों की सहायता लेकर सम्बन्धित मुद्दों की कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली भाषा को समझ सकता है।

14 सोवियत रूस में सब के लिए एक ही प्रकार के 'यायालय' न्यायकाय करते हैं। वहाँ प्रशासनिक न्यायालया जसा कोई 'यायालय' नहीं है। सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं।

15 प्रेसीडियम के 26 मई सन् 1947 के एक आदेश के अनुसार मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया था लेकिन 13 जनवरी सन् 1950 के प्रेसीडियम के एक अन्य आदेश के द्वारा यह पुन लागू कर दिया गया है तथा अनुमति दे दी गई है कि देश द्रोह, जासूसी और तोड़ फोड़ करने वाला के मामलो में मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है।

न्यायपालिका का संगठन

(The Organisation of the Soviet Judiciary)

सन् 1936 के सोवियत संविधान द्वारा रूस में एक संघीय सर्वोच्च यायालय और सम्मिलित राज्यों के सर्वोच्च 'यायालयों' (प्रत्येक में एक एक) प्रादेशिक 'यायालयों' क्षेत्रीय 'यायालय' और सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। सोवियत संविधान में 'यायपालिका' के संगठन की केवल मोटी रूपरेखा ही दी गई है। लेकिन 1938 के जिस कानून के आधार पर रूस की यायपालिका के संगठन की व्यवस्था है, उसके अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए एक ही यायिक ढांचे की व्यवस्था है। सोवियत संघ के यायालयों का संगठन केन्द्रीभूत एवं शिखरोमुखी सिद्धांत के आधार पर किया गया है। जिसके अनुसार समान स्तर के अनेक जन-न्यायालय हैं उनके ऊपर उत्तरोत्तर क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक शक्ति वाल न्यायालय संगठित हैं जिनको अपने नीचे के 'यायालयों' पर निरीक्षण और नियंत्रण करने का शक्तिया प्राप्त हैं। इस उत्तरोत्तर क्रम में सबसे ऊपर का 'यायालय' सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का सर्वोच्च 'यायालय' है। यह सम्पूर्ण देश का सर्वोधिक शक्तिशाली यायिक अवयव है जिसको देश के सभी न्यायालयों की कार्यवाही पर दखल-रेख करने का अधिकार है।

जिन 'यायालयों' का उपरोक्त आधार पर निर्माण हुआ है उनमें दो प्रकार के यायालय हैं—पहले प्रकार के 'यायालय' स्थानीय 'यायालय' हैं जिनमें सभी अथवा पचायती न्यायालय (Conradely Courts) तथा जन-यायालय (People's Courts) सम्मिलित हैं। इनके ऊपर के स्तर के 'यायालय' प्रादेशिक (Territorial) और क्षेत्रीय (Regional) हैं। इनसे उच्च स्तर के न्यायालय स्वशासित गणराज्या (Autonomous Republics) और संघीय गणराज्या (Union Republics) के सर्वोच्च 'यायालय' हैं। उच्चतम स्तर के 'यायालय' विशेष यायालय (Special Courts) और संघ का सर्वोच्च यायालय (Federal Supreme Court) हैं।

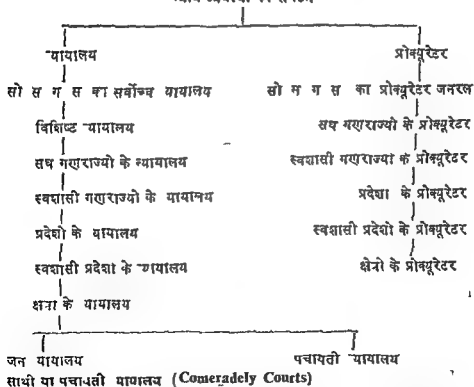
सोवियत संघ की 'यायिक' शृंखला केन्द्रीभूत और शिखरोमुखी होने के साथ साथ दोहरी भी है। न्यायालय के ही साथ-साथ रूस में प्रोक्युरेटरा (Procurators) का भी क्रम चलता रहता है। प्रोक्युरेटरा के क्रम में सर्वोच्च स्थान सोवियत संघ प्रोक्युरेटर जनरल (Procurator General) का है जिसे

सम्पूर्ण सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ के अधिकारियों से सोवियत सघ के कानूनों का पालन कराना का अधिकार होता है। सोवियत सघ के प्राक्पूरेटर जनरल के पास तमारा सघीय गणराज्या के प्रोक्पूरेटर, स्वशासी गणराज्या के प्रोक्पूरेटर और जन पदों व प्रदेशों आदि के प्रोक्पूरेटर होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रोक्पूरेटर जनरल द्वारा की जाती है। इसके नीचे क्षत्र, नगर और जिले के प्रोक्पूरेटर भी होते हैं जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित सघीय गणराज्य के प्रोक्पूरेटर द्वारा की जाती है किन्तु इस पर प्रोक्पूरेटर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सोवियत सघ की 'याय-व्यवस्था' दो प्रकार की संस्थाओं में संगठित है—'यायालय' और प्रोक्पूरेटर। यह दोनों ही संस्थाएँ केन्द्रीभूत एवं शिखरो-मुखी सिद्धांत पर संगठित होती हैं। क्रमशः उच्च-स्तर की संस्था का नीचे की सब संस्थाओं पर नियंत्रण के अधिकार होते हैं।

सोवियत सघ की 'यायिक व्यवस्था' का निम्नांकित चार्ट से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

याय व्यवस्था का संगठन



ये यायालय सोवियत सघ के 'यायान्या' के उत्तरोत्तर क्रम के नियमित अंग नहीं हैं। इनके संगठन द्वारा इनकी कार्यवाही औपचारिक नियमों से प्रतिबंधित नहीं होती। इनके 'यायाधीशों' अथवा पचा का 'याय व्यवस्था' के विषय में प्रायः ज्ञान नहीं होता। वे अपने विवेकानुसार ही याय करते हैं। उन्हें जिस समुदाय

का न्यायालय होता है उसी के व्यक्ति चुनते हैं। ऐसे न्यायालयों की स्थापना फविट्रयो, जेला और ग्रय सस्यामा में की जाती है, जहाँ ये उनमें काम करने वाले लोगों के जन समूहों के पारस्परिक झगडा का निपटारा करती हैं। ये साधारण विवादों को सुनते हैं, सविवेक से अपने न्याय देते हैं और अभियुक्तों की निन्दा भिड़की या लगभग 50 रूबल तक का आर्थिक दण्ड दे सकते हैं।

जन न्यायालय (People's Courts)

नियमित न्यायालयों की शृंखला में सबसे नीचे के न्यायालय जन-न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय (District Courts) भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायः प्रत्येक जिले में एक ऐसा न्यायालय होता है। इनमें प्रायः एक न्यायाधीश (Judge), दो सहायक न्यायाधिकारी या जन-निर्धारक (Assessors) कार्य करते हैं। इनका निर्वाचन जिले के नागरिकों द्वारा सावजनिक प्रत्यक्ष और समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है।

जन-न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र केवल प्रारम्भिक (Original) होता है। दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों की ये सुनवाई करते हैं। दीवानी क्षेत्र में इनके अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति (Property), श्रम संबंधी कानून (Labour Laws), भरण व्यय (Alimony), उत्तराधिकार (Inheritance) तथा सम्बंध-विच्छेद (Divorce) के मुकदमें आते हैं। फौजदारी क्षेत्र में ये न्यायालय मार-पीट, हत्या, नागरिकों की स्वतन्त्रता और सम्मान के अपहरण, सम्पत्ति के अधिकार के दुरुपयोग, गबन, कपट की प्रदायगी चुनाव और कानून के उल्लंघन आदि से सम्बंधित अभियोगों की सुनवाई करते हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वे समय-समय पर अपने कार्यों और अपने न्यायालयों के कार्यों से मतदाताओं को परिचित करावें। जन न्यायालयों के न्यायाधीशों से मतदाता प्रभुत्व होने पर उन्हें वापिन बुला सकते हैं।

जन न्यायालयों और गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच के न्यायालय

जन-न्यायालयों के ऊपर क्षेत्रीय (Territorial) प्रांतीय (Provincial), प्रादेशिक (Regional) और स्वाधीन प्रदेशों (Autonomous regions) के न्यायालय हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीश तथा प्रसन्न क्रम में उनकी सीमितता के द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष की होती है। इन न्यायालयों के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में कुछ अधिक गम्भीर अपराधों वाले मुकदमें जैसे-समाजवाद, श्रम संबंधों के विच्छेद की गई श्राव्यवाहिया, समाजवादी सम्पत्ति की चोरी और व दावानी मुकदमें जिनमें राज्य या सावजनिक संस्थाएँ, वादी या प्रतिवादी हो सकते हैं। ये न्यायालय अपने अपने क्षेत्रों के जन-न्यायालयों के विषय पुनरावलोकन (Review) का भी कार्य करते हैं। एक न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुछ सहायक प्रवक्ता प्रसन्न होते हैं।

स्वाधीन एवं सघीय गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय

इन न्यायालयों का निर्वाचन महा की संसद सीमितता द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। स्वाधीन गणराज्यों और उपाय गणराज्यों में

प्रत्येक में अपना अपना सर्वाच्च न्यायालय होता है। इसके क्षेत्राधिकार में दीवानो तथा फौजदारी, दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण अभियोग आते हैं। इन न्यायालयों का कार्य अपने से नीचे के न्यायालयों के कार्य की देखरेख करना और उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करना होता है। इस प्रकार का पुनर्विचार ये न्यायमय सोवियत संघ के प्रोक््युरेटर जनरल, सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, सघीय गणराज्यों के प्रोक््युरेटर और सघीय गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष के विरोध पर कर सकते हैं।

स्वशासी एवं सघीय गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों को कुछ महत्वपूर्ण दीवानी और फौजदारी मामला में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उदाहरणार्थ, उन मामलों में यह न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं जिनमें उच्च सरकारी अधिकारी फले हों, जो विषय अथवा मामले से सम्बंधित सघीय गणराज्यों की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम ने या उसके प्रोक््युरेटर न अथवा गृह मंत्रालय ने उनके पास विचारार्थ भेजे हों, अथवा जिनकी सुनवाई करने का निर्णय न्यायालय ने स्वयं किया हो।

विशिष्ट न्यायालय (Special Courts)

सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के पश्चात् प्रतिरिक्त नम्बर पर देश में अनेक विशिष्ट न्यायालय (Special Courts) हैं। ये न्यायालय देश के सभी भागों में पाये जाते हैं। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत इन न्यायालयों का क्षेत्र आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकती है और वह ऐसे नवान न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है। इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च संघ के सर्वोच्च न्यायालय में सम्बंधित विभाग (Collegium) के समक्ष की जा सकती है। रूस के विशिष्ट न्यायालय में उदाहरण-स्वरूप तरुण न्यायालय (Juvenile) भूमि न्यायालय (Land Courts) विवाचन न्यायालय (Courts of Arbitration), सैनिक न्यायालय आदि को लिया जा सकता है। सघीय स्तर के न्यायालय होने के कारण इनके प्रावधान सम्पूर्ण देश पर हैं। ये न्याय मुख्य रूप से दो भागों में बाटे जा सकते हैं—(1) सैनिक न्यायालय (Military Tribunals) एवं (2) माथ न्यायालय (Line Courts)।

सैनिक न्यायालय में केवल सैनिकों के ही अभियोग नहीं सुने जाते बल्कि कभी कभी नागरिकों के अभियोगों को भी सुना जाता है। इन न्यायालयों के संगठन का मुख्य लक्ष्य यह है कि सोवियत संघ की सशक्त में अभिवृद्धि हो और सना में अनुशासन बना रहे। सैनिक अपराधों का प्रति विरोधी एवं शासन विरोधी अपराधों के अभियुक्तों के विरुद्ध ये सैनिक न्यायालय कार्य करते हैं। देशद्रोह तथा विश्वासघात के मामले भी इन सैनिक न्यायालयों में ही आते हैं। सैनिक न्यायालयों की स्थापना प्रायः उन स्थानों पर की जाती है जहाँ सना ठहरती है अथवा जहाँ सैनिक संगठन के द्र होते हैं।

माथ अथवा यातायात न्याय की स्थापना यातायात के द्रा पर की जाती है। ये न्यायालय रेल और सड़क यातायात तथा जल यातायात से सम्बंधित मुकदमा

को सुनवाई करते हैं। श्रमिक अनुशासन को भंग करने वाले और यातायात को हानि पहुँचाने वाले अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार इन न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है।

सोवियत संघ में बहुत से अभियोग विवाचन न्यायालयों (Arbitration Tribunals) द्वारा सुने जाते हैं। सोवियत संघ की सरकार इन न्यायालयों को दो या अधिक राज्य व्यवसायियों के झगड़ों को निर्यात करने के लिए नियुक्त करती है।

सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court of the U S S R)

संगठन व कार्यविधि—उपयुक्त सभी न्यायालयों के शीर्ष पर सघीय गणराज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक अध्यक्ष (Chairman), एक उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) अनेक न्यायाधीश और कुछ सहायक न्यायाधीश या जन निर्धारक (Assessors) होते हैं। यह इतना बड़ा निकाय है कि सन् 1951 में इसमें 79 न्यायाधीश तथा 35 एससस थे। इस सर्वोच्च न्यायिक अंग का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन की संयुक्त बैठक द्वारा पांच वर्ष के लिए किया जाता है। पांच वर्ष की अवधि के अन्तर सोवियत न्यायाधीश पदच्युत किये जा सकते हैं, यदि सर्वोच्च सोवियत की सहमति से प्रोक्यूरेटर जनरल पर फौजदारी कार्यवाही कर रखी हो। सोवियत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, अतः यह परिवर्तनशील है।

यह न्यायालय मौलिक तथा अपीलीय दानों क्षेत्राधिकारों का उपभोग करता है। इसको काम की सुविधा के लिए पांच भागों में विभाजित कर दिया गया है— (1) फौजदारी (Criminal), (2) दीवानी (Civil), (3) सैनिक (Military), (4) रेल्वे (Railway), एवं (5) जल यातायात (Water Transport)। न्यायालय का कोई विभाग (Collegium) जब किसी मामले की सुनवाई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में करता है, तो उसमें एक न्यायाधीश और दो एससस न्यायिक कार्य करते हैं। जब कोई विभाग अपीलीय न्यायालय के रूप में किसी मामले की सुनवाई करता है तो उसमें तीन न्यायाधीश कार्य करते हैं। अध्यक्ष (Chairman) किसी भी मुकदमे में किसी भी विभाग की अध्यक्षता कर सकता है। वह किसी विभाग या सघीय गणराज्य के किसी भी न्यायालय के विचाराधीन किसी भी मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण सभा के समक्ष निर्यात रख सकता है। न्यायालय की पूरी बैठक (Full Bench of Plenum) दो महीने में एक बार अवश्य होती है जिसमें न्यायालय के विविध विभागों के उच्च न्यायाधीश (Judgements), अभिमतों (Verdicts) तथा व्यवस्थापना (Rulings) पर पुनर्विचार (Review) किया जाता है जो उसके समक्ष सम्बन्धित न्यायालय के अध्यक्ष अथवा प्रोक्यूरेटर जनरल द्वारा विचाराय प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार की पूरी बैठक में न्यायालय काय विधि सम्बन्धी सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। ऐसी बैठक में प्रोक्यूरेटर जनरल की उपस्थिति अनिवार्य होती है और न्याय में यदि चाहे तो उसमें भाग ले सकता है।

अधिकार व कार्य—सोवियत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बहुमुखी हैं। दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमा में इसके अधिकार प्रारम्भिक (Original) और अपील (Appellate) दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी के वेब-बहुत गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मामले आते हैं, जैसे क्रांति विरोधी काय, या समाजवादी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही सघीय गणराज्यों के मध्य उठने वाले विवाद भी आते हैं। अपीलीय न्यायालय के रूप में यह निम्नतर न्यायालयों के निर्णयों पर पुनर्विचार भी कर सकता है। उक्त निम्नतर न्यायालयों में सघीय गणराज्यों के सर्वोच्च न्यायालय और सोवियत संघ के विशेष न्यायालय भी सम्मिलित हैं। किसी भी न्यायालय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय पुनः अपनी इच्छा से भी पुनर्विचार कर सकता है। अध्यक्ष और प्रोक््यूरैटर जनरल अपनी इच्छा से भी किसी निम्न स्तरीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले को सर्वोच्च न्यायालय के विचाराय उठा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कर्तव्य नायिक कार्य को इस प्रकार संचालित करना है कि जिससे समाजवादी व्यवस्था का संरक्षण हो सके। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अपने निम्न स्तर के न्यायालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और सम्पूर्ण संघ की न्याय व्यवस्था को एकसा बनाना भी उसका प्रमुख कर्तव्य है। अपने निम्न स्तर के न्यायालयों, कानूनों को क्रियान्वित किस प्रकार करते हैं यह देखना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है।

स्थिति—सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सोवियत के कानूनों का, उसके प्रेसीडियम के अध्यादेशों का अथवा मन्त्रिपरिषद् के आदेशों को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता कि ये संविधान की व्यवस्था के प्रतिभूल हैं। संविधान की व्याख्या का कार्य तो सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम करती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा का निर्देशित करते हुए टुरोविनर (Turbiner) कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा करने के लिए कानूनों की बधता (Constitutionality) को संचित (Verification) करने का काम दिया है। हम शक्ति केन्द्रित करने के विचार से यह कार्य केन्द्रीय नायकारिणी समिति और उसके प्रेसीडियम को सौंपते हैं। सघीय सुप्रीम कोर्ट केवल परामर्श देता है।

सोवियत संघ में न्यायपालिका अमेरिका का भाति सरकार का एक स्वतंत्र अंग नहीं है, बल्कि वह प्रशासन का एक विभाग है। सोवियत रूस के एक न्यायाधीश पोलियांस्की (Poljansky) ने स्वयं इस विषय में स्पष्टन कहा है कि वास्तविक मामलों का परीक्षण करते समय सरकार की सामान्य नीति पर ध्यान देने का अनिवार्य न्यायाधीशों का स्वतंत्रता से बाहर का काम मिलता नहीं है। न्यायपालिका राज्य मंत्रालय का एक अंग है और इस कारण वह राजनीति में अलग नहीं हो सकती। न्यायपालिका के राजनीति में अलग रहने का मांग किन्हीं या परिस्थितियों में और नहीं भी पूरा नहीं होता। यही कारण है कि सर्वोच्च सोवियत ने न्यायाधीशों केवल वे ही व्यक्ति बन पाते हैं जिन्होंने साम्यवादी मिशन और नायकता में अपना पूरा विश्वास मिट्ट किया हो अथवा जो साम्यवादी विचारधारा में प्रभुत्व सम्पन्न हों।

इसके अतिरिक्त प्रोक्यूरेटर जनरल तथा 'याय मन्त्री के सर्वोच्च न्यायालय की पूरी बठाना में विधिवत् भाग लेने की व्यवस्था भी यायाधीशों की स्थित-प्रता में बाधक है क्योंकि वे न्यायालयों के निणया में हस्तक्षेप कर सकते हैं और न्यायालयों के निणय सरकारी दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकते हैं।

सोवियत सघ का प्रोक्यूरेटर जनरल (Procurator General of the USSR)

महत्व, पद की श्रृंखला एवं नियुक्ति

सोवियत सघ में प्रोक्यूरेटर जनरल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कानून को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू कराने का कार्य प्रमुखतः इसी का है।

प्रोक्यूरेटर का पद केन्द्र और इकाइयों दोनों में ही होता है। केन्द्र पर उसे सोवियत सघ का प्रोक्यूरेटर जनरल कहा जाता है और उससे नीचे के स्तर पर उसे प्रोक्यूरेटर कहा जाता है। धारा 114 के अनुसार केन्द्र का प्रोक्यूरेटर जनरल सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा 7 वर्ष के लिए चुना जाता है। धारा 115 के अनुसार प्रोक्यूरेटर जनरल ही प्रत्येक सघीय गणतन्त्र (Union Republic), स्वशासन गणतन्त्र (Autonomous Republic), स्वायत्त क्षेत्र (Autonomous region) प्रदेश (Territory) तथा खण्ड (Region) में प्रोक्यूरेटर की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए करते हैं। सघीय गणतन्त्रों (Union Republics) के प्रोक्यूरेटर जिला व नगरों के स्थानीय प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ऐसी नियुक्तियों पर उन्हें प्रोक्यूरेटर जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसका कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होता है।

अधिकार एवं कार्य

सोवियत संविधान की धारा 113 के अनुसार 'सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ के सब मन्त्रियाँ और उनके अधीनस्थ संस्थाओं तथा कमचारियों व नागरिकों द्वारा कानून का पूरा पालन कराने की पर्यवेक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च शक्ति सामान्यतः सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ के प्रोक्यूरेटर जनरल में निहित है।' प्रोक्यूरेटर जनरल और उसके अधीन अन्य प्रोक्यूरेटरगण अभियोग पक्ष (Prosecution) के रूप में कार्य करते हैं चाहे वे राज्य की ओर से अभियोग पक्ष के रूप में कार्य करें अथवा किसी नागरिक की ओर से अभियोगकर्ता बनें। सार्वजनिक अधिकारियों, सरकारी विभागों और प्राइवेट नागरिकों द्वारा कानूनों का ठीक ठाक पालन किया जाता है अथवा नहीं इसकी देखभाल करना प्रोक्यूरेटरों का कर्तव्य है। उन्हें किसी भी राजकीय अङ्ग अथवा कमचारी के अवध निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। वे फौजदारी मामलों, उनमें सम्मिलित परिस्थितियों और संस्थाओं की अधिकार सीमा पर नियन्त्रण रखते हैं। वे राज्य की ओर से फौजदारी मामलों में बकालत करते हैं। वे न्यायालयों के निणयों की वधानिकता का परीक्षण कर उनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। वे यह भी देख सकते हैं कि न्यायालयों के निणय ठीक प्रकार से लागू किये जा रहे हैं या नहीं। उन्हें एम मामलों में हस्तक्षेप करने व अपील का प्रवर्ध कराने का भी अधिकार है जिसमें वह यह समझ कि 'याय

उचित हुआ है अथवा यह समझें कि दण्ड कम या अधिक दिया गया है। उन्हे यह भी अधिकार है कि वे कानून भंग करने वाले किसी भी नागरिक या सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकें। प्रोक्यूरेटर जनरल का यह अधिकार है कि वह किसी भी न्यायालय के किसी भी मुकदमे को हटाकर सघीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए ला सके। वस्तुतः प्रोक्यूरेटर जनरल सांख्यिक अधिकारियों को होश में रखता है जिससे वे कानूना का उल्लंघन नहीं कर पाते। इसीलिये सोवियत लेखक प्रोक्यूरेटर विभाग को सोवियत नागरिका की स्वतन्त्रता और हितों का संरक्षक कहते हैं। प्रोक्यूरेटर जनरल विशेष रूप से क्रांति विरोधी अपराधों के प्रति सजग रहता है। उसका एक विशेष अधिकार यह है कि वह सभ के सर्वोच्च न्यायालय की सम्पूर्ण बैठक में भाग ले सकता है। किसी किसी मामले में तो उसे अभियोगवाक (Prosecutor) व न्यायाधीश (Judge) दोनों ही का काम करना पड़ता है।

प्रोक्यूरेटर जनरल मंत्री-परिषद का सदस्य नहीं होता। वह राज्य मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री के अधीन नहीं होता। वह एक स्वतन्त्र अधिकारी है जो केवल सोवियत सभ की सर्वोच्च संविधान के अधीन रहता है।

स्पष्ट है कि प्रोक्यूरेटर का पद रूस के प्रशासन का एक ऐसा पद है, जो 'न्यायिक' प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस पद पर प्रायः साम्यवादी दल का भाग्य नेता ही नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार 'न्यायिक' व्यवस्था के समान ही प्रोक्यूरेटर जनरल का पद भी साम्यवादी दल के नियंत्रण में सदा के लिए वग के अधिनायकवाद का मुख्य आधार और उसकी मुख्य शक्ति है।

सोवियत न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन (Evaluation of the Soviet Judicial System)

सोवियत न्याय व्यवस्था की पश्चिमी नागरिकों द्वारा कठोर आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि सोवियत न्याय-व्यवस्था के जो कतिपय उच्च आदर्श संविधान में निहित हैं, वे केवल सद्भावपूर्ण रूप में ही मर चुके हैं। संविधान में कानून के समक्ष सबकी समानता का आदेश स्थापित किया गया है परन्तु व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। कानून के समक्ष समानता केवल उन लोगों के लिए है जो साम्यवादी हैं अथवा कम से कम साम्यवाद के भक्त हैं। अन्य लोगों के लिए समानता का अर्थ निश्चय ही यह नहीं होता जो साम्यवाद के भक्तों के लिए होता है। अन्य लोगों को 'लोगों का दुश्मन' (Enemy of the people), 'गद्दार' (Traitor) अथवा ऐसे ही अन्य नामों से सम्बोधित किया जाता है और उनके लिये समानता केवल एक पागली बात बन कर रह जाती है। वस्तुतः सोवियत सभ में न्यायालयों के नियुक्त निष्पक्ष कानून पर आधारित न होकर क्रांतिकारी भावना (Revolutionary Expediency) पर आधारित होते हैं।

सोवियत संविधान की धारा 127 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किसी के नियुक्त या प्रोक्यूरेटर की स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति का

गिरफ्तार नहीं किया जाए।" परन्तु यह व्यवस्था भी व्यवहार में उल्टी है। प्रोक््युरेटर प्रत्येक स्तर पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साम्यवादी दल के जाने माने नेता होते हैं अथवा साम्यवाद के प्रबल भक्त होने हैं। अतः जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तारी करने की आवश्यकता शासक दल समझे, उसको गिरफ्तारी की व्यवस्था बड़ी सुगमता से हो जाती है। साथ ही राजनीतिक पुलिस को भी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही "प्रशासनिक देश निकाला" (Administrative Exile) दे दे। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से सोवियत न्याय-व्यवस्था का कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं रह जाता।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की बात की तो चर्चा ही व्यर्थ है। सोवियत न्याय व्यवस्था इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करती है कि सोवियत संघ में न्यायपालिका को ग्रेट-ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति शासन का एक पृथक एवं स्वतन्त्र अंग नहीं समझा जाता अपितु उसे अथवा प्रशासकीय विभागों के समान राज्य के नियमित प्रशासकीय ढाँचे का एक भाग माना जाता है। सोवियत संघ में विधि-यायालय पाश्चात्य देशों के न्यायालयों की भांति स्वतन्त्र पद का उपभोग नहीं करते यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि उन्हें न्याय का प्रशासन (Administration of Justice) राज्य के विधि-अधिकारियों के सहयोग द्वारा करना होता है। रूस में न्याय विभाग सरकार द्वारा प्रतिपादित नीति को स्वीकार करता है और उसके उल्लंघन-कर्ताओं को दण्ड देता है। वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, किन्तु उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह सरकार द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इन सबके अतिरिक्त न्याय विभाग की स्वतन्त्रता इस दृष्टि से भी सदेहास्पद है कि सोवियत संघ में साम्यवादी दल उसके भी ऊपर है। इसके अतिरिक्त सोवियत न्याय-व्यवस्था केन्द्रीयकरण की शिकार है। साम्यवादी दल के एकछत्र आधिपत्य, प्रोक््युरेटर जनरल और उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों के निरोक्षण के कारण केन्द्रीयकरण की भांति बहुत बढ़ गई है।

इन सब आलोचनाओं में सत्य का यद्यपि पर्याप्त अंश है तथापि यह नहीं माना जा सकता कि सोवियत न्याय व्यवस्था गुणा से सर्वथा होन है। लॉन्की ने सोवियत न्याय व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। वह न्यायालयों के संगठन और कार्य विधि से बड़ा प्रभावित हुआ है। अतः भारतीय न्यायाधीशों और विधि-वेत्ताओं ने जिन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया है सोवियत न्याय-व्यवस्था के अनेक गुणों की बतलाया है। सोवियत न्याय-व्यवस्था ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में जितनी सफलता प्राप्त की है उतनी सफलता शायद ही किसी अन्य देश की न्यायपालिका ने की होगी।

8

अङ्गीभूत इकाइयों का शासन (ADMINISTRATION OF FEDERATING UNITS)

"इकाइयों को सिर्फं विशुद्ध स्थानीय प्रकृति
के सारे मामलों में कुछ इस तक
इच्छानुसार कार्य करने की
स्वतन्त्रता है।"

—कलारिस्की

सोवियत संघ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कि भांति एक सगठनात्मक राज्य है जिसमें प्रादेशिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं। ये प्रादेशिक इकाइयाँ समान स्तर पर कुछ अधिकारों को प्रदान करके एक केन्द्रीय सरकार का निर्माण करती हैं। केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को संविधान की धारा 14 में प्रणालित कर दिया गया है। इसके बाहर केन्द्र को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अवशिष्ट विषयों पर अधिकार केन्द्र का न होकर इकाई राज्यों का रखा गया है। सब मिलाकर निम्नलिखित इकाइयाँ सोवियत संघ में सम्मिलित हैं—

1 संघ गणराज्य (Union Republics)	15
2 स्वशासी गणराज्य (Autonomous Republics)	17
3 स्वशासी क्षेत्र (Autonomous Regions)	9
4 राष्ट्रीय क्षेत्र (National Areas)	10

संघ गणराज्य

इसकी अवयवी इकाइयाँ में सर्वाच्च स्थान प्राप्त है और इनका स्थिति बहुत कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा भारत के राज्यों जैसी है। वर्तमान समय में संविधान की धारा 13 के अन्तर्गत सोवियत संघ में 15 संघ गणराज्य हैं—

- 1 रशियन सोवियत संपात्यक समाजवादी गणराज्य
(The Russian Soviet Federated Socialist Republic)
- 2 यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Ukrainian Soviet Socialist Republic)
- 3 बेलो रशियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Byelo-Russian Soviet Socialist Republic)
- 4 अज़रबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Azerbaijan Soviet Socialist Republic)

- 5 जार्जियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Georgian Soviet Socialist Republic)
- 6 कजाक सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Kazakh Soviet Socialist Republic)
- 7 आर्मीनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Armenian Soviet Socialist Republic)
- 8 तुर्कमान सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Turkman Soviet Socialist Republic)
- 9 टाजिक सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Tajik Soviet Socialist Republic)
- 10 उजबेक सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Uzbek Soviet Socialist Republic)
- 11 किरगीज सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Kirghiz Soviet Socialist Republic)
- 12 लातवियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Latvian Soviet Socialist Republic)
- 13 लिथुवियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Lithuanian Soviet Socialist Republic)
- 14 ऐस्टोनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Estonian Soviet Socialist Republic)
- 15 मोल्डेवियन सोवियत समाजवादी गणराज्य
(The Moldvian Soviet Socialist Republic)

इनमें से अनेक उप-राज्य स्वतन्त्र गणतन्त्र सभ हैं, जिनके अन्दर और छोटे छोटे राज्य हैं। इसी कारण सोवियत सभ को सभा का सभ (Federation of Federations) कहा जाता है। इन में यह सभ गणराज्या में से प्रत्येक स्वशासी गणराज्य स्वशासी क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षेत्र में विभक्त है।

सभ गणराज्य सोवियत सभ की मूलभूत इकाइया हैं। ये सीमित क्षेत्र में प्रभुसत्ता-सम्पन्न हैं। ये स्वेच्छा से सभ के सदस्य हो सकते हैं और स्वेच्छा से अलग भी हो सकते हैं। सघीय सविधान में इन सभ गणराज्या के प्रशासकीय ढांचे को रूपरेखा दी गई है। इसी ढांचे के अन्तर्गत प्रत्येक गणराज्य अपने सविधान का निर्माण कर सकता है। अतः उनके प्रशासन के अवयव के द्वीय अथवा सघीय प्रशासनिक अवयवों की ही भांति हैं और उनकी शासन व्यवस्था अखिल सभ की शासन व्यवस्था के ही समान है। सोवियत सभ के अनुरूप ही सभ गणराज्यों में सर्वोच्च सोवियत, प्रेसीडियम मन्त्रिपरिषद् और सर्वोच्च न्यायालय हैं। इस स्थल पर यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि चूँकि सभ गणराज्यों के प्रशासनिक उपकरणों के नाम के साथ 'सर्वोच्च विधायण' लगता है अतः उनकी सत्ता भी सर्वोच्च ही होगी, अर्थात् उन पर अखिल सभ का नियन्त्रण नहीं होगा। परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है और उन पर अखिल सघीय उपकरणों का पूर्ण नियन्त्रण रहता है।

उदाहरणार्थ, किसी संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की इच्छा के विरुद्ध हो। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित कानून ही भाव्य होता है, यदि वह किसी संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित कानून के विरुद्ध हो।

संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत गणराज्य शासन का सर्वोच्च अंग है। यह गणराज्य की व्यवस्थापिका सभा है जिसे गणराज्य के नागरिकों द्वारा चार वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। यह एक-सदनीय (Unicameral) है। संघीय संविधान में इसके अधिकारों और कार्यों का उल्लेख मिलता है। संविधान की धारा 60 के अनुसार ये अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार हैं—संघीय गणराज्य का शासन विधान पास करना और उसमें सोवियत संघ के संविधान की धारा 16 के उपबन्धों के अंतर्गत संशोधन करना, सम्बन्धित संघ गणराज्य में सम्मिलित स्वशासी गणराज्यों के शासन-विधानों को स्वीकार करना और उनके प्रदेशों की सीमाएँ निर्धारित करना, संघ गणराज्य की क्षत्रिय वार्षिक योजना को और बजट को स्वीकार करना, संघ गणराज्यों के न्यायालयों द्वारा दण्डित अपराधियों को क्षमा प्रदान करना और माफी देना, अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों के निमित्त से संघ गणराज्य के प्रतिनिधित्व के प्रदान को ठम करना, संघ गणराज्य की सशस्ति को संगठित करने की विधि निर्दिष्ट करना आदि। इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम, मंत्र परिषद् आदि का निर्वाचन करना भी संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत के प्रमुख कार्य हैं।

सर्वोच्च सोवियत के सभापति का उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए एक प्रेसीडियम का निर्वाचन होता है। सोवियत संघ के संविधान की धारा 61 के अनुसार संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत अपने प्रेसीडियम का निर्वाचन करती है। इस प्रेसीडियम के अधिकारों को संघ गणराज्य का शासन विधान परिगणित करता है। संघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम की स्थिति अपने क्षेत्र में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम की ही तरह होती है। यह श्रान्तियां जारी करती है और सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है।

संघ गणराज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका और प्रशासकीय शक्ति एक मंत्रि-परिषद् में निहित है जिसका चुनाव सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है। इसमें अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष मंत्रिगण तथा अनेक आयोगों व समितियों के अध्यक्ष होते हैं। संघ सरकार की तरह यहाँ भी दो प्रकार के मंत्रानय होते हैं—संघ गणराज्यिक (Union Republican) और गणराज्यिक (Republican)। संघ गणराज्य की मंत्रि-परिषद् सोवियत संघ गणराज्य के कानूनों तथा आदेशों के आधार पर नियुक्त होती है और उन कानूनों को लागू करने की भी समुचित व्यवस्था करती है। संघ गणराज्य की मंत्रि-परिषद् को स्वशासी गणराज्यों की मंत्रि-परिषद् के नियुक्त और आदेशों को निमित्त करने का अधिकार प्राप्त है। वे अपने जन-पदा, क्षेत्रों और स्वशासी क्षेत्रों की श्रमिक जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों की कार्यकारिणी समितियों के नियुक्त तथा आदेशों को भी रद्द कर सकती हैं। संघ

शाखाओं का संचालन करते हैं। सोवियत संघ और सघ गणराज्य के कानूनों, सोवियत सघ और सघ गणराज्य की मंत्रि-परिषद् के निर्णयों व आदेशों तथा सोवियत सघ के अखिल संघीय मंत्रालयों के आदेशों एवं निर्देशनों के आधार पर उनकी क्रियावित करने के लिए, सघ गणराज्य के मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आदेश प्रदान करते हैं और निर्देश प्रसारित करते हैं।

सघ गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर सोवियत सघ की न्याय व्यवस्था वाले अध्याय में पर्याप्त रूप से प्रकाश डाल दिया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि इनके क्षेत्राधिकार में दोबारी और फौजदारी दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण अभियोग आते हैं इनका भरने-पूरे क्षेत्र के नीचे के सभी न्यायालयों के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। इसके प्रतिरिक्त ये अपने से निम्न न्यायालयों के न्याय-काय का पुनर्निरीक्षण करते हैं।

यह स्मरणीय है कि सघ गणराज्य केवल सीमित क्षेत्र में ही प्रभुसत्ता-सम्पन्न है, यद्यपि उन पर केन्द्र की पूर्ण नज़र रहती है। सोवियत सघ में इकाइयों को सिद्धान्त ही स्वायत्तता प्राप्त है लेकिन व्यवहार में उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नगण्य है और व सघ की प्रशासनिक इकाइयाँ मात्र रह गई हैं। सोवियत सघ में केन्द्रीयकरण इतना अधिक है कि कुछ सांस्कृतिक और विशुद्ध स्थानीय प्रकृति के कार्यों के प्रतिरिक्त इकाइयों को एकदम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। सघ से पृथक् होने का इकाइयों का अधिकार भी व्यवहार की दृष्टि से कोई भ्रूष नहीं रखता। सिद्धान्त और व्यवहार के इस अन्तर पर एक 'पूर्ववर्ती अध्याय रूस की संघीय व्यवस्था' के अन्तर्गत विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

स्वशासी गणराज्य

स्वशासी गणराज्य सघ राज्यों के अन्तर्गत स्थित है परन्तु स्वशासी गणराज्यों के भी अपने अलग अलग सविधान होने हैं जो सम्बंधित सघ गणराज्य की सर्वोच्च सोवियतों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। यह आवश्यक है कि स्वशासी गणराज्य का सविधान सम्बंधित सघ गणराज्य के प्रतिभूत न हो। इसकी शासन व्यवस्था के मुख्य अंग भी लगभग सघ गणराज्य के अंगों जैसे ही होते हैं—सर्वोच्च सांघिक प्रेसिडियम और मंत्रि-परिषद्। व्यवस्थापिका अर्थात् सर्वोच्च सोवियत में निर्वाचित होती है। यहाँ एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है। गणराज्य का सविधान अन्तर्गृहीत करना विधियाँ पारित करना बजट बनाना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। यह अपनी प्रेसिडियम को चुनती है और मंत्रि-परिषद् का नियुक्त करती है। ये दोनों सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रि-परिषद् के प्रमुख कार्य आदेश और निर्णय जारी करना और स्थानीय संस्थाओं को नियंत्रित करना निम्न इकाइयों के आदेशों या निर्णयों को निरन्वित या रद्द करना आदि हैं।

स्वशासी प्रदेश एवं राष्ट्रीय क्षेत्र

कुछ अल्प संख्यक जातियों का स्वशासी प्रदेश और राष्ट्रीय क्षेत्रों के रूप में संगठित किया गया है। इन निम्नतम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों में जनता और

निर्वाचित श्रम-जीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियत (Soviet of the Working Peoples' Deputies) होती है। यह कानून बनाती है और क्षत्र की कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती है। शासन की इकाइयों में प्रेसीडियम की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सोवियत की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार अवश्य होती है।

स्थानीय शासन

(Local Government)

सोवियत-शासन प्रणाली के सबसे निम्न घातल पर स्थानीय शासन की संस्थाएँ हैं—ग्राम, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, नगर और गाँव। प्रत्येक इकाई में श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सोवियत (Soviet of the Working Peoples' Deputies) होती है, जिसका निर्वाचन नागरिकों द्वारा दो वर्ष के लिए किया जाता है। ये सोवियतें शासन की आधार शिला हैं। इन्हें प्रशासकीय, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। ये शासन प्रबंध की अपने अधीनस्थ समितियों के कार्यों का संचालन करती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित रखने, कानूनों के पालन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की, ये गारंटी करती हैं। सोवियत सच और सम्बन्धित सच गणराज्य के कानूनों द्वारा सौंपे गये अधिकारों की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण करने और आदेश जारी करने का इन्हें अधिकार है। इन सोवियतों की कार्यकारिणी समिति भी होती है। प्रत्येक कार्यकारिणी समिति में प्रशासकीय भाग होते हैं—जैसे वित्त, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। स्थानीय संस्थाओं का अपना न्यायालय भी होता है। यह स्मरणीय है कि सोवियत सच में यद्यपि इन स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इसे स्वशासन (Self-Government) की सत्ता देना आमक होगा क्योंकि सोवियत सच में केन्द्रीकरण की भाँसा बहुत अधिक है।

9

रूस की सोवियत प्रणाली (THE SOVIET SYSTEM OF THE USSR)

“सोवियतों ही सवहारा यग
के अधिनायकवाद के शासन
को उपकरण हैं।”

—विशिस्की

सघात्मक राज्य होते हुए भी सोवियत सघ मे पर्याप्त केन्द्रीकृत व्यवस्था पाई जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासनिक अवयव उत्तरोत्तर क्रमशः एक दूसरे के अधीन काम करते हैं। सोवियत सघ मे केन्द्रीयकरण की यह व्यवस्था एक अनुपम पद्धति ‘सोवियत पद्धति’ से प्राप्त एवं व्यवहृत की गई है। सोवियतों सोवियत सघ की विविध सस्यायें हैं जिनकी सहगामी सस्यायें विश्व के अर्य किसी भी राज्य म मिलनी दुलभ हैं। रूसियों को इन पर बहुत गर्व है। उनके मतानुसार सोवियत पद्धति के कारण ही रूस की ससदीय व्यवस्था पाश्चात्य पूञ्जीपति दशों की ससदीय व्यवस्था से श्रेष्ठतर है। सोवियतों की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो रूस की जनता की अपनी व्यवस्था है और जिसम किसी प्रकार की बग भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। सोवियत व्यवस्था के माध्यम से गाव स्तर से लेकर सघ शासन के स्तर तक जन-साधारण शासन काय म भाग ले सकते हैं।

सोवियतों हैं क्या ? उनका स्वरूप

अपने सही अर्थों म सोवियतों रूस की धर्मिक बग की विभिन्न स्तरो पर संगठित निर्वाचित प्रतिनिधि सभायें है। ‘सोवियत’ शब्द रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिषद् अथवा पंचायत। इस प्रकार अपने धाब्दिक अर्थ म सोवियत जन प्रातिनिधिया की एक सभा हुई। परन्तु सोवियत और जन प्रातिनिधि सभा मे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जन प्रातिनिधि सभा तो सभी वर्गों के व्यक्तियों की प्रातिनिधि-सभा हो सकती है लेकिन सोवियत सब वर्गों के व्यक्तियों का प्रातिनिधित्व नहीं करती, उसमे केवल धर्मिक वर्ग ही संगठित होता है। इस प्रकार सोवियत एक नवीन प्रकार की प्रातिनिधि परिषद् है जो विपुल रूप स सवहारा वर्ग की सस्या है। इसमे अर्यान्य प्रातिनिधि सस्याभा की तरह सापक बग अर्थात् पूञ्जीपतिया, जमींदारो आदि के, अथवा मल मालिको या निकम्मो (Idles)

प्रतिनिधियों को स्थान नहीं मिलता। विधिन्को ने लिखा है कि "सोवियतों ही सवहारा वर्ग के अधिनायकवाद के शासन की उपकरण हैं।"

सोवियतों सोवियत समाजवादी गणराज्य सभ की राजनीतिक आधार शिला हैं। सोवियत सभ का सम्पूर्ण धामन सोवियता पर ही आधारित है जो राज्य में विभिन्न स्तर पर संगठित हैं। विभिन्न गणराज्य सोवियत गणराज्य ही कहलाते हैं और उनके सभ को सोवियत सभ कहा जाता है। वास्तव में सरकार को सम्पूर्ण रचना सोवियतों का ही सौपानतन्त्र (Hierarchy) है। सोवियत संविधान की धारा 94 के अनुसार देश के प्रत्येक ग्राम नगर जिले, प्रदेश, स्वशासित गणराज्य सभ गणराज्य तथा सोवियत सभ में सोवियता का होना अनिवार्य है। रूस में इन स्वशासन की इकाइयों को एक शृंखला है जिसमें प्रारम्भिक सोवियत, जिला सोवियत, प्रांतीय सोवियत, सभय गणराज्य की सोवियत, सर्वोच्च सोवियत सम्मिलित हैं। रूसी सोवियतों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रशासकीय तीनों ही प्रकार की संस्थाएँ हैं। उनकी व्यवस्था शक्ति-विभाजन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, प्रत्युत उनमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ निहित की गई हैं। शक्तियों का एकीकरण इतना अधिक है कि मरकारी कर्मचारी जो स्वयं प्रशासन के सहयोगी होते हैं, उनके सदस्य होते हैं। रूसी लेखका न सोवियता को जनता की सही प्रतिनिधि संस्थाएँ तथा सत्तों की अपेक्षा वही अधिक जनतन्त्रात्मक बतलाया है। उनके मतानुसार, सोवियत पद्धति एक ऐसी सत्ता है जो सभी के लिए उभरती है, जो समस्त क्रिया-कलाप सव-साधारण के सामने करती है, जिस पर सवसाधारण की पहुँच है और जिसका आधार तथा स्रोत सवसाधारण ही है।

सोवियतों का प्रारम्भ

सोवियत सन् 1936 के वर्तमान संविधान की ही उत्पत्ति नहीं है। ये पहिले पहल 1905 में क्रांतिकारी उपद्रवों के दिनों में औद्योगिक मजदूरों के संगठनों के रूप में अवतरित हुई और इन्हीं क्रांतिकारी आन्दोलनों के लिए नेतृत्व प्रदान किया, परन्तु इन्हें भी धीरे-धीरे दबा दिया गया। ये सोवियतों उस समय एक प्रकार से हटताल समितियाँ थीं जिनका मुख्य ध्येय ग्राम हड़तालों की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना तथा अपने आपको तदर्थ तैयार करना था। सन् 1917 की क्रांति के समयान फरवरी-मार्च के महीने में ये पुनः उठ खड़ी हुई। इस बार ये बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटे-छोटे गाँवों और सैनिकों तक में फैल गईं। इन सोवियतों में कारखानों, दुकानों, शहरों, गाँवों के किसानों और सैनिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। जोलॉविको ने सवहारा वर्ग के क्रांति सघर्ष के लिए इन सोवियतों को बहुत ही उपयुक्त और सहायक पाया। इसीलिए लनिन ने नारा बुला दिया— 'सारी शक्ति सोवियतों को'। क्रांति के बाद 1918 से ही स्वभावतः सावियतों नवोन साविधानिक पद्धति का आधार बन गई और तभी से ये सोवियत सभ के प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र ग्राम, नगर, जिला या प्रांत, अवयव सभ गणराज्य और अखिर में शासन की मूल धारा हैं।

सोवियतों का निर्वाचन और संगठन

सोवियत रूस में सोवियतों का एक पूरा जाल है जो गाव से प्रारम्भ होकर केन्द्रीय सरकार तक फैला हुआ है। मई 1936 से पहिले सभी सोवियतों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही चुना जाता था लेकिन 1936 के संविधान के लागू होने के बाद से ही प्रत्येक स्तर की सोवियत के प्रतिनिधि जनता द्वारा ही प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। मताधिकार सभी नागरिकों का बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है यदि उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ला हों। सोवियतों के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य करेंगे। यदि जनता इन प्रतिनिधियों से असंतुष्ट हो जाता है तो उसे उन्हें वापिस चुनाव का अधिकार भी है। मत ही उनका वायजाल समाप्त न हो पाया है। सभी चुनाव जन-पदीय आधार पर किये जाते हैं और ग्रामों तथा नगरों की सोवियतों में कोई अन्तर नहीं किया जाता। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र केवल एक प्रतिनिधि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में भेजता है।

वर्तमान सोवियतों के प्रमुख प्रकारों और उनके संगठन की हम संक्षेप में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं—

प्रारम्भिक सोवियतें (Primary Soviets)—प्रारम्भिक सोवियतें जनता की छोटी छोटी समितियाँ हैं जो प्रायः प्रत्येक गाव, प्रत्येक कारखाने, प्रत्येक नगर और सेना के प्रत्येक रेजिमेंट में होती हैं। इनका कार्य उस स्थान के सभी कार्यों का प्रबंध करना होता है जिस स्थान की वे होती हैं। उदाहरणार्थ किसी कारखाने की सोवियत में वहाँ के कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं जो कारखाने का प्रबंध करने हैं। इसी तरह एक ग्राम की सोवियत में गाव के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और वे उस गाव की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सोवियत रूस के प्रथमनिक ढाँचे को प्रारम्भिक इकाई यही प्रारम्भिक सोवियत है।

जिला सोवियतें (District Soviets)—प्रारम्भिक स्तर में ऊपर जिला सोवियतें हैं जिन्हें रेयंस (Raions) कहते हैं। ये सोवियत प्रत्यक्ष रूप से अधिन्यायक होती हैं और इन्हें अधिक व्यापक क्षेत्र का प्रबंध करना पड़ता है। प्रारम्भिक सोवियतों का मांग दर्ज करना इनका सबसे प्रमुख कार्य है। जिला सोवियतें ही वस्तुतः वे कड़ियाँ हैं जो प्रारम्भिक सोवियतों और प्रांतीय सोवियतों का जोड़ती हैं।

प्रांतीय सोवियतें (Provincial Soviets)—जिला सोवियतों से ऊपर प्रांतीय सोवियतें होती हैं जिन्हें ओब्लास्टी (Oblasty) कहा जाता है। इन पर पूरे प्रांत के प्रबंध का दायित्व होता है। स्थानीय विषयों के प्रबंध में इनका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि स्थानीय विषय प्रारम्भिक और जिला सोवियतों का हाथ में रहते हैं। प्रांतीय सोवियतें नीति सम्बन्धी निष्णय लेती हैं और उन निष्णयों का निश्चय करती हैं जिनके अनुसार निम्नतर सोवियतों को अपना कार्य करना होता है।

सब गणराज्यों की सोवियतों (Soviets of Constituent Union Republics)—यह सोवियतें मुख्यतः व्यवस्थापिका संस्थाएँ होती हैं। ये उन सब विषयों पर कानून बनाती हैं जिनके प्रबंध का अधिकार सब गणराज्यों को प्राप्त है। शिक्षा, कृषि, मत्स्य-काय आदि विषय उनके कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इन सोवियतों द्वारा यह नियम भी किया जाता है कि कानून का निम्नतर सोवियतों के प्रागमन द्वारा बिना प्रचार लागू कराया जाए।

सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet)—यह सोवियत केन्द्रीय व्यवस्थापिका है जिसके दो सदन हैं। इस सम्पूर्ण संघीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। सर्वोच्च सोवियत ही रूस की सोवियत व्यवस्था का वह शीर्षस्थ अंग है जिसकी शक्ति सर्वोच्च है। सम्पूर्ण देश का वित्तीय-व्यवस्था का नियंत्रण इसी के हाथ में है क्योंकि यही सम्पूर्ण देश के बजट का स्वीकार करती है। इस सर्वोच्च सोवियत का विस्तृत विवेचन पहिले के एक पृष्ठ पर अभ्यास में किया जा चुका है।

सोवियतों के कार्य

अनुमानत तारे रूस में लगभग 70 हजार सोवियतें हैं। ये स्वयंसेवक की भाँति हैं जिसका कार्य व्यवस्थापन सम्बन्धी और नियंत्रण सम्बन्धी दोनों प्रकार का है क्योंकि ये कानून भी बनाती हैं और उन्हें क्रियार्थित करने के लिए कार्यकारिणी समिति का भी निर्वाचन करती हैं। प्रत्येक सोवियत का कार्य अपने क्षेत्र का प्रबंध करना और अपने में निम्न-स्तर की सोवियतों के कार्य का निरीक्षण करना होता है। लेकिन निम्नतर स्तर की सोवियतों के कार्य का निरीक्षण करने में उच्चतर स्तर की सोवियत का यह ध्यान रखना पड़ता है कि निम्नतर सोवियतों के स्वशासन का अधिकार अनावश्यक रूप से भंग न हो। प्रायः छोटी-छोटी सोवियतें भी अपने अपने क्षेत्र में पूरा स्वाधीन होती हैं और उसे व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। वस्तुतः यह एक महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे देशों में स्थानीय निकाय जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उस में निम्न स्तर की सोवियतें भी उनसे कहीं अधिक व्यापक शक्तियों का प्रयोग करती हैं। एक प्रारम्भिक सोवियत के बराबर अधिकार हैं और उसका कार्य क्षेत्र कितना व्यापक है? इसका सुन्दर चित्रण रब दम्पति (Sidney and Beatrice Webb) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोवियत साम्यवाद एक नई सभ्यता (Soviet Communism—A New Civilisation) में किया है। उन्होंने लिखा है कि—

अपनी प्रादेशिक सोमात्रा के अन्दर ग्राम सोवियत को नागरिकों और कर्मचारियों द्वारा सरकार के आदेशों व कानूनों का पालन कराने का अधिकार है। ग्राम सोवियत संविधान के अन्तर्गत अपने व्यापक क्षमता के भीतर वकल्पिक प्रयत्न जारी कर सकती है तथा प्रशासनिक दण्ड और जुर्माने लागू कर सकती है। यह एक न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जिसे मजदूरी नियोजन की शर्तों तथा अन्य छोटे-मोटे अपराधों के समूहों को ठीक करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सोवियत का यह कार्य है कि वह शासन का तत्वावधान करे तथा समस्त क्षमता

कानून-पालन और नियमना की पूर्ति का आदेश दे, उनका निरीक्षण एवं पयवक्षण कर तथा उन पर चल दे। इसके अतिरिक्त यह भी ग्राम सोवियत के कर्तव्य का अङ्ग है कि वह प्रदेश के राष्ट्रीय निमाण और वाणिज्य विभागों के कार्य-व्यापारों पर अपनी दृष्टि रखे। गाव के भीतर ऐसा कोई प्रबंध नहीं रह जाता जिस ग्राम सोवियत अथवा ग्राम पंचायत नहीं कर सकती हो अथवा जिसकी व्यवस्था सरकारी व्यय पर लोक-व्याख्याय नहीं कर सकती हो। वह ग्राम के भीतर सड़का जल-व्यवस्था, नृत्य-गृहा, क्लबा, पाठशालाया, नाटक धरा और अस्पतालों आदि सब का प्रबंध कर सकती है।'

नगरों की सोवियतें ग्रामों की सोवियतें से बड़ी होती हैं। उनमें स्थायी समितियाँ की भी व्यवस्था रहती है जमें जन-स्वास्थ्य शिक्षा वित्त आदि की समितियाँ। रूस में लगभग 10 हजार नगर सोवियतें हैं।

रूस का संविधान व्यवस्था करता है कि सोवियतें सोवियत सभ अथवा सभ गणराज्य व कानूना द्वारा प्राप्त शक्ति के अंतर्गत नियंत्रण करेगी और आदेश देगी। वे अपने अधीन प्रशासकीय अङ्गों के कार्यों का निर्देशन करती हैं और राज्य व्यवस्था का ठीक रखती हैं। कानूना का पालन कराना और नागरिका के अधिकारों की रक्षा करना भी उनका ही कार्य है। वे स्थानीय आर्थिक एवं सांस्कृतिक निर्माण कार्यों का निर्देशन करती हैं तथा स्थानीय बजट का स्थापित करती हैं। सोवियतें कार्यकारी समितियों को चुनती हैं जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्य होते हैं।

वास्तव में सोवियता के द्वारा सरकार का लाखों बिस्ताना और श्रमिका में सम्पक होता है। वस्तुतः सोवियतें लाखों व्यक्तियों के लिए राज्य शिक्षा की पाठशालाएँ हैं। उनके होने से राज्य तब लाखों व्यक्तियों से पूरक नहीं हो पाता बल्कि मगठना, सब प्रकार के आयोगों विभागों, परामर्श प्रतिनिधि सम्मेलना आदि के द्वारा उनमें एका रूप हो जाता है और उस प्रकार वह सरकार के उपकरणों (Organs) को सहारा देता है।

सोवियतें और साम्यवादी दल

सोवियत सभ की शासन-व्यवस्था में सोवियत महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। लेकिन यह भी स्मरणीय है कि समस्त सोवियत-चाहे वे प्रारम्भिक सोवियतें हों अथवा अखिल सघीय महत्व की सोवियतें हैं—अपने अपने प्रदेश अथवा क्षेत्र के साम्यवादी दल के संगठन के साथ मिल कर उनके मंचालन और निरीक्षण में कार्य करती रहती हैं। वस्तुतः सोवियता के उत्तरोत्तर संगठन के साथ साम्यवादी दल का उत्तरोत्तर संगठन (Pyramid of Party Organisation) भी निवृट्ट सहयोग के साथ कार्य करता है और साम्यवादी दल की शाखाएँ प्रत्यक्ष या पराध रूप में सोवियता के कार्य का नियंत्रित करती रहती हैं। स्टालिन ने स्पष्टतः कहा था 'साम्यवादी दल के आदेश प्राप्त हुए बिना हमारा सोवियतें कभी कोई महत्वपूर्ण राजनैतिक अथवा संगठन सम्बन्धी निश्चय नहीं करता। साम्यवादी दल सोवियता के विस्तृत संगठन के द्वारा ही सब माधारण में अपने प्रभाव की अभिवृद्धि करता है और सोवियता व द्वारा ही महानुभूतिशील गर-साम्यवादी तत्व का शासन सहयोग प्राप्त करता है।

रूस का साम्यवादी दल (THE COMMUNIST PARTY OF THE U.S.S.R.)

साम्यवादी दल समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसे विकसित करने के लिए किये जाने वाले श्रमजीवी जनता के मांगदस्तान और श्रमजीवी जनता की सभी सावजनिक एवं राजकीय समस्याओं का मूल बैज्ञ है।”

—सोवियत संविधान

आधुनिक युग में शासन-सत्ता के पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक दल होने है। वे शासन रूपी गाड़ी को चनाने के लिए ईंधन का काम करते हैं। सोवियत रूस की शासन-व्यवस्था में और पाश्चात्य प्रजातन्त्रों की शासन-व्यवस्थाओं में इस दृष्टि से मुख्य अन्तर यही है कि जहाँ रूस में सम्पूर्ण राजनीतिक-सत्ता पर केवल मात्र साम्यवादी दल का एकाधिकार है वहाँ पश्चिमी प्रजातन्त्रों में दो-तीन या अधिक दलों का अस्तित्व है। आधुनिक राज्यों में सोवियत रूस प्रथम एकदलीय राज्य है। विगिन्सकी के शब्दों में सबहारा के अधिनायकवाद का अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त और सोवियत समाजवादी सभ की समस्त राजनीतिक हलचलों के केन्द्र-बिन्दु साम्यवादी दल की समस्त राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एकाधिकार पूर्ण स्थिति है। रूसी नेता एकदलीय व्यवस्था को ही पूर्ण रूप में उचित समझते हैं। उनकी मान्यता है कि राजनीतिक दल का निर्माण लोगों के किसी विशेष समुदाय के विशिष्ट हितों के आधार पर होता है, अतः एक से अधिक दल तो वहीं उचित हो सकते हैं जहाँ समाज के विविध समुदायों और वर्गों के विविध हित हों। किन्तु सोवियत व्यवस्था तो वर्गविहीन समाज की है। सोवियत रूस में केवल कृषकों और श्रमिकों का वर्ग ही है जिसके सब सदस्यों का एक ही सामान्य हित है। अतः रूस में केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व हो सकता है। सोवियत संविधान की धारा 126 में भी साम्यवादी दल की एकाधिकारपूर्ण स्थिति का स्वीकार किया गया है।

सोवियत सभ में साम्यवादी दल ही वास्तव में शासन करता है। दल द्वारा और निर्धारित नीति पर ही सरकार चलती है। सदातिक रूप में

दल और सर्वान्तरिक कानूनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु व्यवहार में शासन के सभी महत्वपूर्ण नीतियों पर पहले दल नियंत्रण करता है और फिर सरकार उस अपना कर उन्हें कार्य रूप में परिणत करती है। सोवियत संघ में शासन और दल राज पर एक-दूसरे से पृथक् हैं किन्तु भास्को में नीचे गणराज्यों, क्षेत्रों विलों और दूरस्थ गाँवों तक दल एक-दूसरे के नमानान्तर है। सोवियत राज्य में साम्यवादी दल ही वह है और सरकार किसी दूसरे दल के निर्माण को मान्य नहीं देती।

साम्यवादी दल का यह एकाधिकार स्वरूप प्रारम्भ से ही रहा है। जारशाही के पलायन के बाद तब यह हो रहा है कि रूस को 'अंधेर' युग से उठाकर क्रांति द्वारा नये युग में लाने के बाद साम्यवादी दल का सर्वोपरि उद्देश्य यही रहा है कि क्रांति को स्थायी बना दिया जाय। इसके लिए दल में सभी प्रजावादी और ध्वजधरित तत्वों का कुचला तथा देश के बाहर की शक्तियों का प्रदुष्ट कौशल और साहस से सामना किया गया है और इस प्रकार धीरे-धीरे सोवियत शासन की जड़ें जमा दी गयीं। दल ने सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधित्व का बनाए रखने के लिए दल को परोक्ष प्रपरोक्ष दोनों रूपों में शासन का कामा पहनाया गया और संविधान की धारा 126 में भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि 'साम्यवादी दल समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसे विकसित करने के लिए किये जाने वाले संघर्ष में श्रमजीवी जनता का मार्गदर्शक है।

दल के संगठन सम्बन्धी सिद्धान्त (Principles of Party Organisation)

साम्यवादी दल का संगठन बाह्य और आन्तरिक दोनों ही पक्षों में पूर्ण एकाधिकारवादी है। इसका यह सवाधिकारवादी (Totalitarian) स्वरूप निम्नलिखित दोषीय सिद्धान्तों से प्रकट है—

बाह्य एकाधिकारवाद (External Totalitarianism)

साम्यवादी दल की यह स्पष्ट नीति है कि देश में अपने समानान्तर अन्य किसी राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाय। राजनीतिक सत्ता का अधिकारी केवल वही रहे। केवल उसी का देश के सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर संचालन एवं नियंत्रण रहे। इस दलीय सिद्धान्त का ही परिणाम है कि रूस में आज तक कोई अन्य दल अस्तित्व में नहीं आ पाया है। साम्यवादी दल का ही एकाधिकार साम्राज्य है और इस बात की कोई सम्भावना नजर नहीं आती कि वर्तमान व्यवस्था में कोई दूसरा दल कभी अस्तित्व में आ सकता है। रूस के नेतागण या समय-समय पर एकमात्र साम्यवादी दल की शक्ति का ही समर्थन करते रहते हैं।

आन्तरिक एकाधिकारवाद (Internal Totalitarianism)

दल के इस दूसरे सिद्धान्त का प्रभाव है कि आन्तरिक दृष्टि से दल में एक सकल्प और एक आदेश तथा एक इच्छा और एक संचालन

Will and One Command, One Will and One Direction) माय होगा। दल के भीतर किसी प्रकार के मतभेद सहन नहीं किए जायेंगे और किसी प्रकार की फूट और गुटबन्दी का कोई स्थान नहीं होगा। वस्तुतः दल का आन्तरिक एकाधिकारवादी रूप इतना सशक्त है कि दल का नीतियों से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन ही समाप्त कर दिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी दल में विरोधी गुट पदा हुए तभी दलशास्त्री गुट न कमजोर गुट का निममतापूर्वक कुचल दिया। साम्यवादी दल में समय-समय पर की जाने वाली सफाईया (Purges) इस बात की प्रमाण हैं। दल चाहता है कि उसके सभी सदस्य सदैव एकमत हों और कठोरतम अनुशासन के अधीन कार्य करें। सभी नियमित ढंग में ठोक ठाक समय पर बिना किसी हिवकिचाहट के कार्यान्वित किए जायें।

लोकतांत्रिक केन्द्रवाद (Democratic Centralism)

सोवियत संघ में शासन और राजनीतिक दल दोनों का ही संगठन लोकतांत्रिक केन्द्रवाद पर आधारित है। परन्तु दलीय संगठन के संदर्भ में इसका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। प्रचलित पाश्चात्य परम्परा के अनुसार लाफ़्टन और केन्द्रवाद—ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं किंतु रूसी विचारका को इस सम्प्रदाय में अपनी अलग व्याख्या है। ये दोनों के सामंजस्य को उचित और जायसंगत ठहराते हैं।

रूस में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद का अभिप्राय है 'नियुक्त और नेताओं के निर्वाचन में एकता तथा नीतियों के क्रिया-व्ययन में केन्द्रीकरण अथवा एकाधिकारवाद।' सोवियत संघ में प्रत्येक निम्न-स्तर की दल-संस्था अपने में उच्च स्तर की दलसंस्था का निर्वाचन करती है। किन्तु प्रत्येक निम्न-संगठन अपने में उच्च संगठन के अधीन होता है और उसके आदेशानुसार ही कोई कार्य कर सकता है। इस प्रकार नीचे के स्तर पर संगठन का रूप लोकतन्त्रात्मक और शीर्ष पर एकात्मक होता है। नीचे के स्तर पर संगठन की नीति और नेताओं के चयन के बारे में नियुक्त करने के लिए सामान्य जनता स्वतंत्र होती है लेकिन इसके बाद वह अपने द्वारा नियमित नीतियों और निर्वाचित नेताओं से बंध जाती है। नतागण या आदेश निषालत है, जनमाधारण के लिए उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह अंतिम रूप से शासन की सम्पूर्ण शक्ति नेताओं में केंद्रित हो जाता है। लाफ़्टन केन्द्रवाद का यह सिद्धांत वस्तुतः वास्तविक दल का मन् 1917 के छठे अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया गया था।

राज्यतांत्रिक केन्द्रवाद के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग भिन्न भिन्न समयों पर और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न रहा है, फिर भी कुछ मूलभूत प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ही रही है और नाकतन्त्रात्मक तत्व का मन-मन हटा-हटाया गया है। आज प्रायः सभी प्रमुख समितिओं में निर्वाचन का स्थान निरुत्तिमान हो गया है। दल में इतनी प्रजातन्त्र भावना प्रचलित है कि मन्त्र्य एवं राज्यकारि

का विवाद कर सकते हैं जो दल में एकता बना रहने में सहायक है।' पर इस सम्प्रदाय में भी यह कठोर प्रतिपक्ष है कि सदस्य दलीय नियमों के अधीन हो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और दलीय नीति पर किसी भी प्रकार से आक्रमण करना पाप और अपराध माना जाता है।

प्रमाणिक ढाँचे में भी सोवियत क्रांतिवाद का बीजबाला है। सगठन के निम्नस्तर के अंग प्रशासन के निम्न स्तर पर सक्रिय रहते हैं पर उन पर उत्तरोत्तर उच्चस्तरों के अंगों का कठोर नियंत्रण रहता है। यह अवश्य है कि मतदान के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग काम करने के कर्तव्य के साथ जोड़कर प्रशासन में जन माथारण के महत्व को अभिवृद्धि पा गयी है। जन साधारण प्रशासनिक कार्यों में भाग्यपूर्ण रूप से भाग ले, इसकी व्यापक व्यवस्था है। सोवियत सम्मेलन (Soviet Assemblies) तथा प्रशासनिक अंगों में उन्हें सक्रिय बनाया गया है। प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा स्थानीय सोवियत (Local Soviets) का निर्माण होता है। सम्पूर्ण रूस में विभिन्न स्तरों पर इन सोवियतों का गठन किया गया है जिनके माध्यम में रूसी जनता प्रशासन में भाग लेती है।

कठोर दलीय अनुशासन (Strict Party Discipline)

दलीय अनुशासन की यह कठोर भाग है कि दल के भीतर पूर्ण अनुशासन रहे। दल की सदस्यता भी सभी के लिए खुली नहीं है। केवल उन्हीं लोगों का सम्मेलन बनाया जाता है जो दलीय कार्यक्रमों में प्रवृत्त विश्वास रखते हैं तथा दलीय निर्णयों का पालन करने और दल का बँदा देने को तैयार हों। दल का सदस्य बनने से पहले व्यक्ति का एक लम्बी उम्मीदवारी करनी होती है तथा अपने कार्य में महत्व के कार्य करने योग्य बनाने रखना पड़ता है। दल के सदस्य को दल के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण करना पड़ता है।

निष्पक्ष रूप में साम्यवाद का 'मोनोलिथिक' (Monolithic) दल है और 'मोनोलिथिक' का अर्थ होता है—एक ठोस पत्थर का बना हुआ खम्भा। सोवियत साम्यवादी दल पूर्णतः केंद्रीकृत और एकरूप संगठन है जिसके सदस्य कठोरतम अनुशासन में बंधे हुए हैं और जिसमें गुटबंदी अथवा शक्ति विभाजन का कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

साम्यवादी दल की सदस्यता (Membership of the Communist Party)

प्रजातांत्रिक देशों में दल की लोकप्रियता का आधार है अधिकाधिक व्यक्तियों का सदस्य बनना जबकि साम्यवादी दल की सदस्यता का सार इन शब्दों में है कि "सदस्यता कम करो और दल की शक्ति बढ़ाओ। सोवियत साम्यवादी दल वस्तुतः एक बन्द या बंदखुल समाज (Closed Society) है जिसकी सदस्यता का अत्यन्त सामित रखा गया है ताकि दल में कठोर एकता और अनुशासन बना रहे। दल सदस्यता रूढ़ी जनसंख्या के केवल लगभग 3-5 प्रतिशत भाग तक ही जबकि इसका शासन दल की सम्पूर्ण जनसंख्या पर है।

Will and One Command, One Will and One Direction) माना होगा। दल के भीतर किसी प्रकार के मतभेद सहन नहीं किए जायेंगे और किसी प्रकार की फूट और गुटबन्दी का कोई स्थान नहीं होगा। वस्तुतः दल का वास्तविक एकाधिकारवादी रूप इतना सशक्त है कि दल की नीतियों से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन ही समाप्त कर दिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी दल में विरोधी गुट पदा दूएँ तभी शक्तिशाली गुट ने कमजोर गुट का निममनापूर्वक विलीन किया। साम्यवादी दल में समय-समय पर की जाने वाली 'सफाई' (Purges) रूस की प्रमाण है। दल चाहता है कि उसके सभी सदस्य मदद एकमत हो और कठोरतम अनुशासन के अधीन कार्य करें। सभी नियम नियमित ढंग में ठीक ठीक समय पर बिना किसी हिचकिचाहट के कार्यान्वित किए जायें।

लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद (Democratic Centralism)

सोवियत संघ में शासन और राजनीतिक दल दोनों का ही संगठन लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद पर आधारित है। परन्तु इसी संगठन के संदर्भ में इसका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। प्रचलित पाश्चात्य परम्परा के अनुसार लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद—ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, किन्तु रूसी विचारका की इस सम्बन्ध में अपनी अलग व्याख्या है। वे दोनों के सामंजस्य को उचित और सामंजस्यपूर्ण ठहराते हैं।

हम में लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद का अभिप्राय है 'नियम और नताभा के निर्वाचन में एकता तथा नीतियों के क्रियान्वयन में केन्द्रीकरण' अर्थात् एकाधिकारवाद। सोवियत संघ में प्रत्येक निम्न-स्तर की दल-संस्था अपने से ऊच्च स्तर की दलसंस्था का निर्वाचन करती है। किन्तु प्रत्येक निम्न संगठन अपने से ऊच्च संगठन के अधीन होता है और उसके आदेशानुसार ही कोई कार्य कर सकता है। इस प्रकार नीचे के स्तर पर संगठन का रूप लोकतान्त्रिक और शीर्ष पर एकात्मक होता है। नीचे के स्तर पर संगठन की नीति और नताभा के चयन के बारे में निर्णय करने के लिए सामान्य जनता स्वतंत्र होती है लेकिन इसके बाद वह अपने द्वारा निर्धारित नीतियों और निर्वाचित नेतृत्व से बंध जाती है। नताभा का आदेश निराला है, जनसाधारण के लिए उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह अन्तिम रूप में शासन की सम्पूर्ण शक्ति नेताओं में केंद्रित हो जाती है। लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद का यह सिद्धांत वस्तुतः बोल्शेविक दल ने मई 1917 के छठे अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया गया था।

लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग भिन्न भिन्न समयों पर और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न रहा है, फिर भी कुछ मिलाकर प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ही रही है और लोकतान्त्रिक तत्व का गन धन हासल होना गया है। आज प्रायः सभी प्रमुख समितियों में निर्वाचन का स्थान नियुक्तियों से लिया है। दल में इसी प्रकार का मान्य है कि 'मनुष्य एक प्राकृतिक'।

वाट विवाद कर सकते हैं जो दल में एकता पैदा करने में सहायक है।' पर इस सम्प्रदाय में भी यह कठोर प्रतिबंध है कि सदस्य दलीय नियमों के अधीन हैं अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और दलीय नीति पर किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया करना घोर अपराध समझा जाता है।

प्रशासनिक ढांचे में भी लोकतांत्रिक कट्टरवाद का बोधना है। मगठन के निम्न स्तर के अंग प्रशासन के निम्न स्तर पर सक्रिय रहते हैं पर उन पर उत्तरोत्तर उच्चस्तरीय अंगों का कठोर नियंत्रण रहता है। यह अवश्य है कि मतदान के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग काम करने के कर्तव्य के साथ जोड़कर प्रशासन में जन साधारण के महत्व की अभिवृद्धि का गयी है। जन साधारण प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक रूप से भाग ले, इसकी व्यापक व्यवस्था है। सोवियत सभ्यता (Soviet Assemblies) तथा प्रशासनिक अंगों में उन्हें सक्रिय बनाया गया है। प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा स्थानीय सोवियत (Local Soviets) का निर्माण होता है। सम्पूर्ण रूस में विभिन्न स्तरों पर जन सोवियतों का गठन किया गया है जिनके माध्यम से रूसी जनता प्रशासन में भाग लेती है।

कठोर दलीय अनुशासन

(Strict Party Discipline)

दलीय अनुशासन की यह कठोर भाव है कि दल के भीतर पूर्ण अनुशासन रहे। दल की सदस्यता भी सभी के लिए खुली नहीं है। केवल उन्हीं लोगों का सदस्य बनाया जाता है जो दलीय कार्यक्रमों में अटूट विश्वास रखते हैं तथा दलीय नियमों का पालन करने और दल का बंधन देने को तैयार हैं। दल का सदस्य बनने से पहले व्यक्ति को एक लम्बी उम्मीदवारी करनी होती है तथा अपने कार्य के महत्व के कार्य करने योग्य बनाने रखना पड़ता है। दल के सदस्य को दल के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण करना पड़ता है।

निष्कप रूप में साम्यवादी दल 'मोनोलिथिक' (Monolithic) दल है और 'मोनोलिथिक' का अर्थ होता है—एक ठोस पत्थर का बना हुआ पत्थर। सावित्र साम्यवादी दल पूर्णतः केन्द्रीयकृत और एकरूप संगठन है जिसके सदस्य कठोरतम अनुशासन में बंधे हुए हैं और जिसमें गुटबन्दी अथवा शक्ति विभाजन का कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

साम्यवादी दल की सदस्यता

(Membership of the Communist Party)

प्रजातांत्रिक देशों में दल की लोकप्रियता का आधार है अधिकाधिक व्यक्तियों का सदस्य बनना जबकि साम्यवादी दल की सदस्यता का धार इन शर्तों में है कि 'सदस्यता बम करो और दल की शक्ति बढ़ाओ। सोवियत साम्यवादी दल वस्तुतः एक बन्द या तगदिल समाज (Closed Society) है जिसकी सदस्यता का अत्यन्त सावधान रखा गया है ताकि दल में कठोर एकता और अनुशासन बना रहे। दल की सम्प्रति रूसी जनसंख्या के केवल लगभग 3-15 प्रतिशत भाग तक ही सीमित है जबकि इसका शासन दल की सम्पूर्ण जनसंख्या पर है।

दल की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। तीन सदस्यों की सिफारिश और प्रारम्भिक समिति की स्वीकृति पर ही प्रायः प्रत्यायी सदस्यता प्राप्त होती है और उसके बाद पूर्ण प्रशिक्षण के पश्चात् पूर्ण सदस्यता (Full Membership) दी जाती है। व्यक्ति जो बहुधा एक से लेकर पांच वर्ष तक के लिए प्रत्यायी (Candidate) के रूप में रहना पड़ता है। यह समय उसका परीक्षा का होता है। इस अवधि में यदि यह स्पष्ट हो मिट्ट हो जाता है कि प्रत्यायी साम्यवादी सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास करने लगा है उसकी बुद्धि और वृत्ति में पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और यह दलीय दायित्वों को वहन करने की दृष्टि से पूर्ण सक्षम बन सजा है, तब वही उस दल का पूर्ण सदस्य माना जाता है। कितने व्यक्ति प्रायः-पत्र पर सिफारिश करें और कितने दिन के समय का प्रत्यायी रहने के लिए निश्चित किया जाए, यह सब प्रायः प्रार्थी के स्तर और पेशे पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति काम करने वाले और मेहनतकश हैं, उन्हें अत्यधिक व्यक्तिता की अपेक्षा सदस्यता के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है और उनके प्रबंध की शर्तें अधिक सरल रखी जाती हैं। सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी एवं अन्य उच्च व्यवसाय वाले लोगों का दल की सदस्यता प्रायः बड़ी सावधानी से दी जाती है। उनके लिए प्रायः 10 वर्ष की छोटी सदस्यता के पांच समझौते की आवश्यकता होती है और उन्हें आवश्यक रूप से पांच वर्ष तक प्रत्यायी रहना पड़ता है। साथ ही यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति दल की सदस्यता के लिए प्रायः-पत्र देने का अधिकारी नहीं होता। पुजारी (Priests) सट्टेबाज (Speculators) व्यक्तिगत व्यापारी (Private Merchants) और सामूहिक कृषि के विरोधी कुलक किसान (Kulak Farmers) दल की सदस्यता के लिए प्रायः-पत्र नहीं दे सकते।

दल के सदस्यों के कर्तव्य—साम्यवादी दल का अनुशासन बड़ा दृढ़ है और सदस्यों पर नियंत्रण भी कठोर है। दल का अनुशासन भंग करने पर बहुधा सदस्य दल से निकाल दिये जाते हैं।

सदस्यों द्वारा अनिवार्यतः किए जाने वाले कार्यों में से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. प्रारम्भिक फीस देने के बाद दल का अपनी आय के अनुसार कुछ माहवारी चन्दा देना। सामान्यतः यह चल्ता ग्रामदली के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।
2. दल का एकता की रक्षा करना एवं दल के निरुध्दा को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहना।
3. राष्ट्रीय अनुशासन का दृढ़ता से पालन करना अपने काम में आदेश और पूर्ण कौशल प्राप्त करना, निरंतर अपना कार्य करने का योग्यता बढ़ाना और समाजवादी व्यवस्था के पवित्र आधार के नाते सावजनिक समाजवादी सम्पत्ति का सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना।

- 4 दल और देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेना, जनता से सम्पर्क बढ़ाना एवं धार्मिक जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं पर ध्यान देना ।
- 5 अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए माक्स और लेनिन के सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ।
- 6 दल तथा राज्य के गुप्त भेदों को न खोलना ।
7. ऐसे व्यापारों से स्वयं को बचाना जिसका ध्येय पूँजी लाभ हो ।
- 8 दल के सम्मुख सत्य एवं ईमानदारी का व्यवहार करना तथा कृत व्यपरायणता नतिकता और सदाचार का आदर्श रखना ।
- 9 नीचे से आत्मलोचन तथा समालोचना का विकास करना ।
- 10 दल के द्वारा किसी भी पद पर नियुक्त किये जाने पर आवश्यक रूप से दल की आज्ञाओं का पालन करना ।

दल के प्रत्येक सदस्य का सर्वोच्च ध्येय साम्यवाद की निःस्वार्थ सेवा करना होता है । ऐसे सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता जो अपने उदात्त कृत्यों की निभा न सकें । पिछले 6 वर्षों में लगभग 2,00,000 व्यक्ति विभिन्न कारणों से दल से निष्कासित किये गये हैं और कहा गया है कि संयोगवश भाँजने वाले इन व्यक्तियों को निकाल देने से दल अधिक शक्तिशाली और ठोस बन गया है ।

साम्यवादी दल के सदस्यों के अनेक विशेषाधिकार भी हैं । समाज में उनका बड़ा सम्मान होता है और उन्हें जनता का नेता समझा जाता है ।

साम्यवादी दल का संगठन

(Organization of the Communist Party)

सोवियत संघ के साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड (Pyramid) के आकार का है । नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अंग शृंखलाबद्ध (Hierarchical) हैं । इस पिरामिड का आधार प्रारम्भिक दल-उपकरण (Primary Party Organs) हैं और शीर्ष पर दल की केन्द्रीय समिति का प्रेसीडियम है जो अन्तिम शक्ति से परिपूर्ण केन्द्र है । संगठन का स्वरूप जनतन्त्रात्मक केन्द्र का होने से प्रत्येक नीचे की इकाई पर उससे ऊपर की इकाई का कठोर नियन्त्रण है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक अंग की वास्तविक शक्ति उसका एक छोटी समिति में निहित है । संगठन की अन्तिम इकाई प्रेसीडियम सब इकाइयों में छोटी है किन्तु सबसे अधिक शक्तिशाली है और अन्य सब नीचे की इकाइयों पर नियन्त्रण रखती है । दल-संगठन के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं—

प्रारम्भिक दल उपकरण (Primary Party Organs)

प्रारम्भिक दल उपकरण निम्नवत् संगठन हैं जिन्हें मुनरा ने "दल की आँखें कान" (Eyes and ears of the Party) कहा है । इनका अस्तित्व प्रत्येक कारखाने प्रत्येक बड़ी दुकान के कार्यालय प्रत्येक स्कूल तथा प्रत्येक रजिमेंट में है । इनका कम से कम सदस्य संख्या 3 हो सकती है । जहाँ इकाई का बड़ा होता है और सदस्य संख्या प्रायः 15 से अधिक बढ़ जाती है तो

लोग एक कार्यकारिणी समिति या केन्द्रीय समिति का निर्वाचन कर लेते हैं जिसे ब्यूरो (Bureau) कहा जाता है। प्रारम्भिक दल उपकरण का एक सचिव होता है, जो समिति का प्रधान (Chairman) भी होता है। इन प्रारम्भिक दल उपकरणों या इकाइयों की सदस्यता की शर्त यह है कि सदस्य व्यक्ति दल के कार्यक्रम में विश्वास करे, दल के नियमों को माने और सदस्यता शुल्क दे। रूस के साम्यवादी दल के आधार का निर्माण ये प्रारम्भिक उपकरण ही करते हैं। सम्पूर्ण रूस में लगभग 21 लाख से अधिक प्रारम्भिक दल उपकरण हैं। सन् 1952 की दल की नियमावली के अनुसार इनके निम्नलिखित कार्य हैं—

- (क) पत्रों, घोषणापत्रों, भाषणा आदि द्वारा दल की नीति एवं निर्णयों को प्रसारित करना और लोगों को उसे समझाना।
- (ख) नये सदस्यों को भर्ती करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (ग) दल के सदस्यों की राजनीतिक परीक्षा का आयोजन करना और यह देखना कि उनको मानस तथा लेनिन के सिद्धान्तों से कुछ परिचय हुआ है या नहीं।
- (घ) राजनीतिक विभाग को (रकोम तथा गोरको—(Raikom and Gorko) कायम में सहायता देना।
- (ङ) फैक्ट्री, फार्म, मिला आदि सभी जगह यमिकों को संगठित करना एवं दल की शक्ति बढ़ाने हेतु जनमत को जाग्रत करने का प्रयत्न करना।
- (च) देश की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भाग लेना।

नगर तथा जिलों के दलीय सम्मेलन

(City & District Party Conferences)

प्रारम्भिक दल उपकरण के ऊपर नगर तथा जिलों के दलीय सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों का निर्वाचन प्रारम्भिक दल उपकरण करते हैं। ये प्रत्येक सम्मेलन अपनी समिति (Bureau), अपने सचिव (Secretary) तथा दो स्थानापन्न सचिवों (Substitute Secretaries) का चुनाव करते हैं, जिनकी पुष्टि उसके ऊपर वाली इकाई द्वारा होना आवश्यक होती है। दल के नगर या जिला के सम्मेलन की वर्ष में एक बार बैठक अवश्य होती है, लेकिन ब्यूरो अपना केन्द्रीय समिति के अधिवेशन सदैव हाते रहते हैं। केन्द्रीय समिति अपने क्षेत्र के प्रारम्भिक उपकरणों के सचिवों से सम्पर्क रखती है, उनको नीति सम्बन्धी निर्देश देती है और उनके कार्यों का निरीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त यह समिति उन साम्यवादी गुटों के काम की भी देखभाल करती है जो विविध ट्रेड यूनियनों, सरकारी संस्थाओं युवक संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों में किये जाते हैं।

क्षेत्रीय प्रदेशीय व गणराज्यीय सम्मेलन

(Regional, Territorial and Republican Conferences)

नगर तथा जिलों के दलीय संगठनों के ऊपर क्षेत्रों, प्रदेशों, स्वशासी गणराज्यों और संघ गणराज्यों के संगठन आते हैं। इन संगठनों अपना सम्मेलन

के प्रतिनिधि जिला तथा नगर समितियों के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इनकी सर्वोच्च सत्ता पूरा सम्मेलनो मे निहित होती है। इसमे से प्रत्येक अपनी अपनी कार्यकारिणी समिति (Bureau) का निर्वाचन करता है, जो सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार कार्य करती है। कार्यकारिणी समिति अपने क्षेत्र मे दलीय नीति एवं कार्यों का संचालन करती है। यह अपने क्षेत्र के नीचे की इकाइयों के कार्य का प्रबंध करती है, उस सम्बंध मे आवश्यक आदेश जारी करती है और उनकी सामान्य देखभाल करती है। क्षेत्रीय, प्रदेशीय व गणराज्यीय सम्मेलन अपने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत दल के प्रशासकों की व्यवस्था करने के लिए सम्पादक परिषदों का चुनाव भी करते हैं और दल से बाहर जो साम्यवादी दल के गुट काम करते हैं, उनके कार्यों की देखभाल भी करते हैं।

अखिल सघीय कांग्रेस (All Union Congress)

उपयुक्त समस्त दलीय संगठनों के ऊपर सम्पूर्ण देश के लिए दल की अखिल सघीय कांग्रेस होती है। इसकी सदस्य संख्या हजारों मे है। इसके सदस्यों का चुनाव उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय, प्रदेशीय एवं गणतन्त्रीय इकाइयों द्वारा किया जाता है। यह साम्यवादी दल की केन्द्रीय सत्ता है और इसके द्वारा समस्त निम्न सम्पन्न किये जाते हैं। नियमों के अनुसार अखिल सघीय कांग्रेस का सम्मेलन तीन वर्षों मे कम से कम एक बार अवश्य होता है। इसका सम्मेलन मास्को मे होता है और उसमे साम्यवादी दल के सभी बड़ी के नेता सम्मिलित होते हैं। साधारणतः इसका अधिवेशन दो सप्ताह से अधिक नहीं चलता। यह दल के कार्यक्रम एवं नीति मे परिवर्तन कर सकती है एवं चानू नीति की प्रमुख समस्याओं के विषय मे कार्यनीति भी निश्चित करती है।

अखिल सघ दलीय सम्मेलन (All-Union Party Conference)

अखिल सघीय कांग्रेस के अधिवेशनों के मध्यवर्ती समय मे केन्द्रीय समिति समय-समय पर अखिल सघ दलीय सम्मेलन को बुलाती है। कभी इसका सम्मेलन एक वर्ष मे, तो कभी ठाई वर्ष मे होता है। इसमे समस्त देश के स्थानीय समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके सभी निम्न केन्द्रीय समिति की पुष्टि के विषय होते हैं।

केन्द्रीय समिति (Central Committee)

साम्यवादी दल के संगठन का एक बड़ा प्रमुख अंग केन्द्रीय समिति है। इस समिति का निर्वाचन अखिल सघीय कांग्रेस द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। इसमे लगभग 125 सदस्य तथा 111 प्रत्याशी होते हैं। इसके सदस्य अधिकतर सघ गणराज्या, स्वशासी गणराज्या एवं अथ प्रदेशों के दलीय सचिव होते हैं। इसमे सोवियत सघ की मन्त्रिपरिषद् के प्रभावी सदस्यों की पर्याप्त संख्या होती है। इसके अतिरिक्त गणराज्या की मन्त्रिपरिषदा के प्रभावशाली सदस्य, उनके प्रधान, उच्च सैनिक कमान के सदस्य उच्च पुलिस अधिकारी तथा बुद्धिजीवी और कुछ विचारक लोग भी सम्मिलित होते हैं। दल का दृष्टि से केन्द्रीय समिति एक अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। नियमों के अनुसार कांग्रेस के मध्य-काल मे केन्द्रीय समिति दल के सारे काम चलाती है। अथ सत्ताप्राप्त, संगठना तथा दलों से सम्बंध बनाने मे दल का प्रतिनिधित्व करती है। दल के अनेक

स्थापित करके उनके कार्य का संचालन करती है। अपने नियंत्रण में काम करने वाले केन्द्रीय अखबारा के सम्पादक-मण्डल का नियुक्त करती है तथा बड़ी स्थानीय संस्थाओं के दलीय अखबारा के सम्पादकों की नियुक्ति का पुष्ट करती है। सावजनिक महत्व के व्यवसायों को संगठित करके उनका प्रबंध करती है। वह दल की शक्तियाँ और साधना का बटवारा तथा केन्द्रीय-बोप की व्यवस्था करती है। केन्द्रीय समिति दल के गुणों द्वारा केन्द्रीय सोवियत और जन-संगठना के कार्य का निर्देशन करती है।"

केन्द्रीय समिति का प्रेसीडियम (Presidium)

साम्यवादी दल का सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण अंग प्रेसीडियम (Presidium) है। यह सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम से सदाया भिन्न है। 19वीं कांग्रेस ने इसके 23 सदस्य व 11 वकल्पिक सदस्य निर्वाचित किये थे। आजकल इसमें 12 सदस्य तथा 5 वकल्पिक सदस्य हैं। इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। प्रेसीडियम में दल के चोटी के नेतागण होते हैं जो सरकार के भी सदस्य होते हैं। प्रेसीडियम ही वास्तव में उन सब नियुक्तियों को करती है जिन्हें सरकार क्रियान्वित करती है। इस छोटी-सी समिति में साम्यवादी दल की सर्वोच्च शक्ति निहित है और यह समाजवादी निर्माण की समस्त शाखाओं का काम दिना को निर्देशन करती है। इसका एक सभापति होता है। प्रेसीडियम की बैठकें कई बार कई कई सप्ताह के लिए होती हैं। ये बैठकें अत्यन्त भोगनीय होती हैं और बहुधा रात्रि के समय होती हैं। ये बैठकें कभी-कभी इसनी सम्बो होती हैं कि दूसरा दिन निकल जाता है।

अन्य सहायक अंग (Subsidiary Agencies)

प्रेसीडियम के अतिरिक्त साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के दो अन्य बड़े प्रवयव और हैं—सचिवालय (Secretariat) तथा दल नियंत्रण आयोग (Party Control Commission)

1 सचिवालय—साम्यवादी दल का मास्को में एक केन्द्रीय कार्यालय है। इसका एक महामंत्री होता है। इस सचिवालय अथवा केन्द्रीय कार्यालय के अनेक भाग हैं। यह देश-विदेश से सम्बंधित विषयों की दमभाज करता है। राज्य के अधिकांश नियुक्त साम्यवादी दल के सचिवालय में ही किये जाते हैं। सचिवालय वस्तुतः साम्यवादी दल एवं सोवियत पद्धति का चालक मन है। इसका अस्तित्व एवं इसकी कार्यक्षमता नीति के केन्द्रीयकरण तथा एकीकरण की अत्यंत उत्कृष्ट रूप से प्रभावित करत है।

2 दल नियंत्रण आयोग—यह आयोग दल का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय प्रवयव है जिसका काम दल के सदस्यों में अनुगमन व नतिकता बनाये रखना है। केन्द्रीय एवं प्रादेशिक दल समितियाँ सब गणराज्य की केन्द्रीय समितियाँ आदि के विरुद्ध की गई उन अपीलों पर पुनर्विचार करना भी इसका काम है जिनके अनुसार दल के सदस्यों को दल से बहिष्कृत कर दिया गया हो।

साम्यवादी दल के युवक संगठन (Youth Organisation of the Communist Party)

सोवियत मध्य में साम्यवादी दल से सम्बंधित अनेक युवक संगठन हैं। इन संगठनों द्वारा दल का प्रचार व प्रसार होता रहता है। यह संगठन निम्न हैं—

(1) कॉमसोमॉल्स (Comsomols) १ १

(2) पायनियर्स और ओक्टोब्रिस्ट्स (Pioneers and Octobrists)

कॉमसोमॉल्स 15 से 26 वर्ष तक के किशोरो (लड़का और लड़कियाँ) का संगठन है। इनके लक्ष्यो सदस्य हैं। इनका प्रमुख कार्य, मार्क्स के सिद्धान्तों का अध्ययन करना तथा दल के कार्यक्रमों का कार्यान्वित करने के लिए रचनात्मक सहयोग प्रदान करना है। ये सोवियत शक्ति के चारों ओर साम्यवादी विचारों से परिपूर्ण युवकों को संगठित करते हैं। इनके द्वारा देश की सत्ताप्राप्ति तथा दल के संगठनों को उपयुक्त व्यक्ति प्रदान किये जाते हैं। इनका नियंत्रण साम्यवादी दल द्वारा किया जाता है।

पायनियर्स और ओक्टोब्रिस्ट्स छोटे लड़कों और लड़कियों के दो ग्रुप संगठन हैं। 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे पायनियर्स में तथा 9 से 11 तक के बच्चे ओक्टोब्रिस्ट्स में भर्ती किये जाते हैं। कॉमसोमॉल्स इन संगठनों में साम्यवादी विचारधारा की शिक्षा देते हैं और इस भाँति देश के भविष्य के लिए तैयार करते हैं।

साम्यवादी दल का महत्व एवं कार्य

(Importance and Functions of the Communist Party)

साम्यवादी दल का वास्तविक महत्व उसके महान् कार्यों में छिपा है। दल ने रूसी लोगों के सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक जीवन के संगठन में निर्णायक भूमिका प्रदान की है और आज भी रूसी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका महत्व एवं महान् मार्ग-दर्शक शासक उपदेशक एवं नियन्त्रक का है। यह दल सोवियत शासन और समाज का प्रभु और उसकी निर्देशक शक्ति है।

साम्यवादी दल समाजवादी व्यवस्था का नियन्त्रक एवं रक्षक

रूस में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का एवं उसकी रक्षा तथा उत्थिति का श्रेष्ठ साम्यवादी दल का है। देश में दल का कार्य, उन लोगों का वैचारिक और क्रियात्मक पथ प्रदर्शन करना है जो देश में समाजवादी व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं। इस रूप में दल एक प्रेरक आदर्श और शिक्षक है। जनता को मार्क्सवाद लेनिनवाद की शिक्षा देना दल का सर्वोपरि कर्तव्य है। यही कारण है कि रूसी संविधान में इसे 'समाजवादी व्यवस्था का विकास करने व उसे शक्तिशाली बनाने के उनके सपने में काम करने वाले लोगों का रक्षक' कहा गया है।

साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक

सोवियत साम्यवादी दल देश का वास्तविक शासक है। पश्चात्त्य देशों की भाँति यह सरकार का निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संचालक तो है ही, लेकिन साथ ही यह शासन से इतना घुल मिल गया है कि दल और सरकार को अलग अलग करना मुश्किल है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णय व्यावहारिक रूप से दल ही करता है। सरकार के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति दल के द्वारा की जाती है। सोवियत संघ के शासन के सम्पूर्ण अवयवों पर साम्यवादी दल का पूर्ण एवं एकाधिकारी नियंत्रण है। कार्टर (Carter) के शब्दों में "साम्यवादों, दल ही समस्त व्यवस्थापन और प्रशासन के क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण रखता है और यह निश्चित करता है कि क्या होना चाहिये, कब होना चाहिये, किस प्रकार होना चाहिये तथा किसके द्वारा होना चाहिये?"

पुनश्च, दल जनता को मार्क्सवाद लेनिनवाद की शिक्षा विभिन्न ढंगों के माध्यम से देता है। यह शिक्षण इतना प्रभावशाली है कि संगीत, कला, साहित्य, विज्ञान आदि प्रत्येक क्षेत्र को इस तरह नियमित किया जाता है कि वे साम्यवादी प्रवृत्ति को परिलक्षित करें। दल का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है और प्रत्येक साम्यवादी सफलता को राष्ट्रीयता की भावना को हट्ट बनाने के लिए प्रभावशाली अस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल नेतागण और जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, अर्थात् यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से नेतागण अपने कार्यों का विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दल सरकारी नीतियाँ और कार्यों से जनता को परिचित कराता है और उनकी स्पष्ट व्याख्या जनता के समक्ष रखता है। इसके लिये अन्य सूचना-साधना के अतिरिक्त 'संगठित वाद-विवाद' (Organised discussion) के साधन को काफी प्रयोग में लाया जाता है।

दल केवल सरकार के कार्यों को ही सूचना जनता को नहीं देता प्रत्युत जनता की इच्छा और प्रतिक्रियाओं की सूचना भी सरकार व दल के नेतागण को देता है। इस तरह वह एक प्रभावशाली सूचना केन्द्र का काम करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य

सोवियत साम्यवादी दल के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। साम्यवादी विश्व क्रान्ति और विश्व-साम्यवादी समाज में विश्वास करता है अतः रूसी साम्यवादी दल ना यह एक आधारभूत उद्देश्य है कि संसार के पूँजीवादी देशों में साम्यवाद की स्थापना की जाए। प्रारम्भ से ही साम्यवादी दल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहा है। प्रारम्भ में इसके लिये कम्युनिस्ट इंटरनैशनल (Communist International) की स्थापना की गई थी, किन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में इसके स्थान पर 'कॉम्युनिस्ट इनफार्मेशन ब्यूरो' (Cominform) की स्थापना की गई। यद्यपि 1956 में इस समाप्त कर दिया गया है, किन्तु फिर भी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सोवियत साम्यवादी दल अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रसार लिये प्रयत्नशील है। सोवियत साम्यवादी दल के इसारा पर ही अधिकांश देशों के साम्यवादी दल संचालित होते हैं।

साम्यवादी दल तथा अन्य संगठन

सोवियत संघ में कुछ सार्वजनिक निंदनीय संगठन हैं, जमे—धार्मिक संघ (Trade Unions), सहकारी सङ्घ (Co-operatives) सांस्कृतिक संगठन (Cultural Societies) आदि। दूर से देखने से यही प्रतीत होता है कि ये स्वायत्त संगठन हैं जिन्हें देश के विभिन्न सावियता ने लिए प्रत्याक्षी नामांकित करन का अधिकार है। लेकिन तथ्य यह कि ये सभी संगठन किसी न किसी रूप में साम्यवादी दल द्वारा ही नियंत्रित रहते हैं और दल के सदस्य इन सभी संगठनों में महत्वपूर्ण पदा पर जमे हुए हैं। स्टालिन का कहना था कि ये निंदनीय संगठन एक प्रकार के 'संदेशवाहक साधन' (Transmission belts) हैं जो दल का विशाल संघ से मिलाते हैं।

॥

रूस में प्रजातन्त्र (THE DEMOCRACY IN THE U S S R)

“सोवियत समाजवादी गणराज्य सद्य एक कठोर
अधिनायकतन्त्र है यद्यपि उसके कुछ तत्त्व
स्पष्टतः प्रजातन्त्रीय हैं, जो प्रजातांत्रिक
केन्द्रीयकरण नामक सिद्धांत के
अनुसार कार्यान्वित हुए हैं।”

—हाउस्डर

सोवियत रूस में वास्तविक प्रजातन्त्र है भयवा नहीं, यह प्रश्न बड़ा
विवादास्पद है। एक ओर पाश्चात्य देशों के ऐसे विद्वान् हैं जिन्होंने सोवियत शासन-
पद्धति को अप्रजातांत्रिक, स्वायत्तवादी, अधिनायकवादी और निरक्षर कहा है।
दूसरी ओर ओक पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी खुल कर प्रशंसा भी की है।
पक्ष में तर्क

(1) सोवियत जनता को सर्वाधिक जनतन्त्रीय स्वतन्त्रता एवं अधिकार—
सोवियत संविधान सोवियत जनता को सत्तार के किसी भी प्रजातन्त्रीय देश से अधिक
जनतन्त्रीय स्वतन्त्रता व अधिकार प्रदान करता है। 18 वर्ष से अधिक कितनी भी
नस्ल, धर्म और विचार के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति, शिक्षा आदि
पर कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ तक कि विदेशियों को भी यह अधिकार सुलभ है।
इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था कम से कम 23 वर्ष की है, सर्वोच्च
सोवियत की सभा के लिए खड़ा हो सकता है। निर्वाचन में भाग लेने व निर्वाचित
होने का अधिकार सनिका को भी प्राप्त है। समस्त प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष
निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित हो नहीं होते हैं अपितु उन्हें अपने कार्य के विषयों में
निर्वाचकों को जानकारी भी देनी होती है। सोवियत विधि के अनुसार निर्वाचक
बहुमत के द्वारा अपने क्षेत्र के किसी भी अवाचित निर्वाचित सदस्य को वापिस भी
बुला सकते हैं। इस प्रकार सोवियत रूस में पूरा जनतन्त्र है और वह जनतन्त्र केवल
प्रदर्शनीय नहीं है, अपितु व्यावहारिक है। सोवियत संविधान, ने अपने नागरिकों को
जा मूलभूत अधिकार दिए हैं, सभा और विस्तार की दृष्टि से सत्तार का कोई भी
लोकतांत्रिक दृष्ट उनके सामने नहीं ठहर सकता। सोवियत रूस में नागरिकों को न
केवल राजनीतिक अधिकार हैं बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार भी हैं।

पर वग-व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। राज्य की ओर से प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय पाने का अधिकार, 'यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार एवं विधाम तथा मनोरंजन पाने का अधिकार भी है। प्रत्येक छात्र को लगभग नि:शुल्क शिक्षा वृद्धावस्था तथा रुग्णावस्था में पेंशन, मुक्त चिकित्सा आदि समस्त सुविधायें सोवियत रूस में उपलब्ध हैं। सोवियत नागरिकों को भाषण, प्रेस, सभा, जुलूस, प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता है। इन नाना सुविधाओं में से अनेक सुविधायें तो वे देश भी अपने नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा सके हैं जिन्हें अपनी प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर गर्व है।

(2) सोवियत जनता के लिए संविधान द्वारा निश्चित कृतव्य—सोवियत संविधान इस दृष्टि से भी पूर्ण प्रजातान्त्रिक है कि 'उमम सोवियत जनता को जो भी अधिकार प्रदान किये गये हैं उन्हें सीमित करने वाला कोई प्रतिपक्ष नहीं लगाया गया है और साथ ही अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेदों में इस बात का भी प्रबंध किया गया है कि यह अधिकार केवल किताबों या प्रदर्शन की वस्तु बन कर न रह जाय अपितु व्यवहार में भी इनका पूर्ण लाभ उठाया जा सक। सोवियत संविधान अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों पर समान और राज्यों के प्रति कुछ कृतव्य भी आरोपित करता है। रूस में अधिकार और कृतव्य अविभाज्य हैं। इस प्रकार सोवियत संविधान इस कथन पर खरा खतरता है कि कृतव्यों के अभाव में अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। यह सब कुछ रूस को सच्चा प्रजातान्त्रिक देश सिद्ध करने को पर्याप्त है।

(3) वगहीन-समाज—रूस में वगहीन समाज है। वहां पर केवल धर्म-जीविका का समाज है। पश्चिमी राज्यों में पाये जाने वाले पूजोपतियों जसा गोपक वग वहां नहीं पाया जाता। सोवियत रूस में समाज में सभी को समान स्थान है सभी में बंधुत्व की भावना है और इस प्रकार वहां प्रजातंत्र के दो आधार-भूत स्तम्भों—स्वतंत्रता एवं समानता के प्रत्यक्ष स्थान होते हैं। लान्की जसा प्रजातंत्र का कट्टर समर्थक भी स्वीकार करता है कि इङ्गलैंड जैसे प्रजातंत्रीय राज्य में अभी प्रजातान्त्रिक समाज का निर्माण होना शक्य है। इङ्गलैंड में आज भी केवल धनिक वर्ग का बोलबाला है, धन के बल पर ही यह वर्ग निर्वाचनों में विजयश्री अर्जित करता है। सत्य तो यह है कि पाश्चात्य प्रजातान्त्रिक राज्यों में ऊंच-नीच अमीर-गरीब, आदि की अप्रजातान्त्रिक भावनायें विद्यमान हैं। इन देशों की तुलना में रूस में वास्तविक स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं।

(4) अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता—सोवियत रूस में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भी पूर्ण समानता का व्यवहार है। सोवियत संविधान का अनुच्छेद 123 यह स्थापित करता है कि जाति या राष्ट्रीय समूह के आधार पर किसी नागरिक के अधिकारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीमित करना अथवा इन आधार पर किसी को विजयधिकार प्रदान करना या साम्प्रदायिक घृणा द्वेष का प्रचार करना एक भ्रष्टाचार अपराध है। इङ्गलैंड और अमेरिका जैसे महान् प्रजातान्त्रिक राज्यों में भी अल्पसंख्यकों के साथ समानता का ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिलता। समानता और बंधुत्व के प्रजातान्त्रिक आदर्शों के गौरव मान माना देश

संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्या में आज भी नीग्रो जाति के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है। प्रजातन्त्र की जननी कहे जाने वाले इंग्लैंड जैसे देश तक में काली जातियों को उपेक्षा से देखा जाता है। यदि प्रजातन्त्र वास्तव में मानव को मानव के रूप में देखने का आदर्श है तो निश्चयतः विश्व के सभी प्रजातान्त्रिक देशों की तुलना में वह रूस में अधिक मात्रा में विद्यमान है।

विपक्ष में तर्क

(1) विचार स्वातन्त्र्य केवल मात्र दिखावा—रूस में नागरिकों को विचार-स्वातन्त्र्य नहीं है। वहाँ भाषण और प्रेस-स्वतन्त्रता से सम्बन्धित मौलिक अधिकारों की सीमा व्यवहार में इतनी मरुचित कर दी गई है कि इन स्वतन्त्रताओं की वास्तविक महत्ता कुछ भी नहीं रह जाती। रूस में केवल एक ही विचारधारा को पनपने की आज्ञा है और वह है रूसी साम्यवादी विचारधारा। सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक पूणतया सरकार के शिकजे में दबा हुआ है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की धाराएँ हाथी के दाँतों के समान एक दिखावा है। समस्त शिक्षा प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण है। शिक्षण संस्थाओं में साम्यवादी दल की बातें बतलाई जाती हैं और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया जाता है। मसलान, रेडियो, सिनेमा और यहाँ तक कि चर्च भी साम्यवादी दल के प्रचारार्थ काम में लाये जाते हैं। साम्यवादी विचारधारा का विरोधी साहित्य वहाँ छपना तो दूर रहा प्रवेश भी नहीं पा सकता। इस बात को सोवियत नेता खुल्लम-खुल्ला स्वीकार करते हैं कि साम्यवादियों के शत्रुओं को भाषण और प्रेस की कोई स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। सोवियत सरकार व धर्मजीवियों की तानाशाही के विरुद्ध वहाँ कोई प्रचार या आन्दोलन नहीं किया जा सकता।

(2) एक दल प्रणाली (साम्यवादी दल की तानाशाही)—सोवियत संघ में एक दल प्रणाली जनतन्त्र का गला घोटती है। तानाशाही को रोकने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करने और शासन की सफलता तथा सुखलता के लिए विरोधी दल का होना आवश्यक है। किन्तु रूस में साम्यवादी दल का एकछत्र राज्य है और उसका अनुशासन ऐसा कठोर है कि व्यक्तिगत एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई है और व्यवहार में साम्यवादी दल सरकार की कार्याकारिणी पर शासन करता है, समस्त राजकीय कार्यों का निर्वहन करता है और रूस की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। रूसी साहित्य में उसी की छाप है और ज्ञान के सब विभागों में उसी की भ्रमण है।

रूस में दूसरा कोई राजनैतिक दल कार्य नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति चाहे साम्यवादी दल का सदस्य बने चाहे न बने किन्तु वह इससे भिन्न आदर्श वाली किसी राजनीतिक पार्टी को संगठित नहीं कर सकता। धर्म एवं चिर के धर्म में 'वास्तव' में केवल स्वरूप की छोछर हर प्रकार से रूस में साम्यवादी दल ही सरकार है और साम्यवादी तानाशाही, साम्यवादी दल की तानाशाही है यही नहीं, रूस एक राजनैतिक राज्य है, जहाँ मार्शल-लॉ (Martial Law) के अन्तर्गत राज्य चलता प्रचलित है। ऐसी परिस्थितियाँ में यह नतीजा प्रकट होता है कि रूस में व्यक्ति की स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र नहीं तब विद्यमान है।"

(3) ध्वंस विधायिका (Facade Legislative)—सर्वोच्च सोवियत में अथवा प्रशासकीय क्षेत्रों को अथवा सोवियतों में प्रतिनिधिया का निर्वाचन एक दिखाना मात्र है। फाइनर (Finer) ने इसे 'एन प्रदर्शन' (Public Demonstration) तथा 'अन' (Illusion) कहा है। सोवियत रूस में जनता पश्चिमी देशों की जनता की भांति प्रतिनिधिया का स्वतन्त्र रूप से नहीं चुन पाती। वहाँ प्रतिनिधिया का नामांकन साम्यवादो दल द्वारा होता है और केवल साम्यवादो दल के सदस्य या उसके समर्थक ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ज़रता एक प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधिया को ही मत देती है। न कि सोवियत रूस में किसी विरोधी दल का अस्तित्व नहीं है, मत यह चुनाव एक तमाशा है।

पुनश्च मन्त्रिण द्वारा सोवियत व्यवस्थापिका अर्थात् सघोय सर्वोच्च सोवियत का एक दश की मन्त्रिण सोवियतों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गये हैं। लेकिन यह एक असम्भव-सी बात है कि कोई संस्था वष भर में 10-15 दिनों की बैठक में सोवियत रूस जैसे विस्तृत एवं विविधता से भरे हुए देश के लिए कानून बना सके। वास्तविकता यह है कि कानूनों का निर्माण साम्यवादी दल द्वारा होता है। सोवियत व्यवस्थापिका में तो केवल हाँ भर करती है। इसके अतिरिक्त प्रजातन्त्र का एक प्रमुख लक्षण देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना है। लेकिन सोवियत संघ में जनता के प्रति उत्तरदायित्व केवल नाममात्र का है। शासन ने किसी भी अङ्ग पर जनता का कोई नियन्त्रण नहीं है और सघोय व्यवस्थापिका जनता के प्रति नहीं बल्कि दल के प्रति उत्तरदायी है। देश के सभी गणराज्यों व प्रदेशों की व्यवस्थापिकाओं की भी स्थिति यही है। मन्त्रि-परिषद् का ससद् के प्रति उत्तरदायित्व भी केवल प्रदर्शन के लिए है। संविधान भाषण की स्वतन्त्रता देता है, परन्तु इसका उपयोग/घावट ही नहीं कर पाता है। ससद् में अथवा ससद् के बाहर शासन की नीति के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाया जा सकती।

(4) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता नहीं—रूस में न्याय विभाग सरकार का स्वतन्त्र अङ्ग नहीं है बल्कि एक प्रकार का प्रशासकीय विभाग है जो सरकार द्वारा प्रतिपादित नीति को स्वीकार करता है और उसने उत्पन्नकर्ता का दण्ड देता है। सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का कोई स्वतन्त्रता नहीं है क्योंकि उसके निर्णय वहाँ की प्रेसोडियम तथा साम्यवादी दल की कन्द्रीय कार्यालयों समिति के द्वारा सपुष्टि के विषय हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समर्थक एवं पुनर्निर्धारण नहीं बनाया गया है इसलिए वह सोवियत शासन के कानूनों का प्रवर्धन पोषित कर सकता है और ही मन्त्रिण की व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार रूसी न्यायपालिका वादपालिका के हाथों का और दल की यज्जों की बैठकियों में बन गई है। यह तन्त्र प्रजातन्त्र का जड़ पर कुटारापात का संधान है।

(5) मन्त्रिपरिषद्—सोवियत रूस में मन्त्रिपरिषद् का अस्तित्व है जब कि प्रजातन्त्रात्मक शासन के अनुस्यू शासन गति का अर्थनायक विमर्श-परण होना चाहिए ताकि जनता शासन में अधिकारों का भाग ले सके। रूस में

आर्थिक साधनों पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है। देश की आर्थिक व्यवस्था का संचालन और निर्देशन एक केन्द्र से होता है। नागरिकों के व्यक्तिगत आर्थिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न प्रगों के मध्य विभाजित है तथापि अंतिम रूप से और व्यावहारिक रूप से समस्त शक्तियाँ साम्यवादी दल में ही समाहित हैं। व्यवहारतः साम्यवादी दल का महासचिव (Secretary General) ही शासन का वास्तविक प्रधान होता है, न कि भारत या ब्रिटेन के समान जनता का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री। इस केन्द्रीकरण को बनाये रखने के लिए प्रचार और आतंक दोनों मार्गों को अपनाया जाता है। शासन के समस्त धन सरकार और दल की प्रशंसा में लगे रहते हैं। प्रचार एवं प्रसार के समस्त साधनों पर सरकार तथा दल का एकाधिकार है। आतंक का मार्ग ग्रहण करने हुए सरकार या दल के विरोधी को कठोरतम सजा दी जाती है। समय समय पर खूनी शुद्धिकरण (Bloody Purges) सोवियत रूस के लिए आम बात है। गुप्त पुलिस (Secret Police), गुप्तचर (Spies), श्रमिक कैंम्प (Labour Camps) आदि के द्वारा रूसी जनता में सदैव आतंक फैला रहता है।

वस्तु स्थिति

सोवियत रूस का सच लोकतन्त्र है या अधिनायकतन्त्र—इसके पक्ष विपक्ष में दिये गये उपयुक्त तर्कों के निष्पक्ष विश्लेषण से और रूसी समाज की व्यावहारिक स्थिति से यही निष्पक्ष निष्कर्ष है कि रूस यदि आर्थिक दृष्टि से लोकतन्त्र के बहुत अधिक समृद्ध है तो राजनीतिक दृष्टि से लोकतन्त्र से दूर है। परन्तु किसी भी रूप में रूसी शासन व्यवस्था को फासीवादी अथवा नाज़ीवादी अधिनायकतन्त्र कहना उचित नहीं है क्योंकि रूसी सरकार चाहें जनता के द्वारा बनाई हुई—और जनता की सरकार भले ही न हो पर वह जनता का हित साधन करने वाली सरकार, अवश्य है। सोवियत 'अधिनायकतन्त्र' न रूसी जनता की विपुल सेवा की है, उसके हितों की साधना की है, समाज से बेकारी और बेरोजगारी को समाप्त किया है और प्रत्येक नागरिक को ऐसा, अवसर मुलभ कर दिया है कि वह अपना जीवन यदि अधिक उच्च स्तर से नहीं तो मानवोचित स्तर से तो व्यतीत कर ही सके और उचित अवकाश का समय भी उस प्राप्त हो सके। जनता के कल्याण-साधन की दृष्टि से रूस में लोकतन्त्र का निश्चित रूप से अस्तित्व है इससे इन्कार करना सत्य से मुख मोड़ना है। आर्थिक परेगानियों से मुक्ति लोकतन्त्र की सबसे बड़ी कसौटी है और रूसी शासन व्यवस्था इस कसौटी पर विश्व की अन्य किसी भी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था से अधिक खरी उत्तरती है।

17

5

पुनश्च लोकतन्त्र का अर्थ यदि सावजनिक कार्यों में जनता द्वारा अधिक से अधिक भाग लेना है तो रूस अथवा भी सोवियत संघ विश्व का सबसे अप्रणीतनीय देश है। रूस में सोवियतों के माध्यम से रूस की जनसंख्या का विशाल भाग शासन कार्य में भाग लेता है। सोवियतों के माध्यम से ही रूस के लोग वहाँ के आर्थिक जीवन के निर्माण का भी प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। आर्थिक

सधो, उपभोक्ता सहकारी सभा, युवक संगठनो आदि की रूसी जनता की सदस्यता इतनी है कि उसका अनुपात प्रायः अन्य सभी देशों से बढ़कर है।

वस्तुतः सरकार का स्वरूप ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता। सरकार किस कुशलता से काम कर रही है, समाज और व्यक्ति की उन्नति कितनी हो रही है, यह अधिक महत्वपूर्ण है और रूसी सामन्य व्यवस्था इस दृष्टि से विश्व की अनेक अप्रणीत लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। पाश्चात्य विद्वानों का यह आरोप कि रूसी शासन के अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है भ्रमात्मक है, क्योंकि बिना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में उतनी उन्नति प्राप्त करना असम्भवप्रायः है जितनी रूस में हो चुकी है। ड्रिजर (Dreiser) के शब्दों में—“रूस बौद्धिक कला और सलोत कला सम्बन्धी तथा व्यावहारिक सफलताओं के दृष्टिकोण से विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है।”

किर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतन्त्र शासन का आधार जन-इच्छा होती है। सोवियत रूस में साम्यवादी शासन, स्थापित हुए मात्र लगभग 54 वर्ष हो गये हैं और इस लम्बी अवधि में जनता ने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिससे यह संकेत मिलता हो कि रूसी नागरिक साम्यवादी व्यवस्था का विरोधी है। इस आधी शताब्दी के रूसी सामाजिक व नागरिक जीवन के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि रूस के साम्यवादी शासन को वहाँ के नागरिक हृदय से स्वीकार करते हैं और वह एक प्रकार से उनका अपना शासन है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि रूस के साम्यवादी स्वयं अपने देश की व्यवस्था को अधिनायकतन्त्रीय मानते हैं, परन्तु साथ ही उनका मत है कि सबहारा वग का होने के कारण वह अधिनायकतन्त्र होते हुए भी लोकतन्त्र है। रूसी शासन-व्यवस्था वास्तव में सावजनिक समर्थन प्राप्त एकाधिकारतन्त्र बही जा सकती है। रूस की लोकतन्त्र की कल्पना में जनता और उसके द्वारा सावजनिक कार्यों में भाग लेने पर बल दिया जाता है। रूसी लोग अपने द्वारा निर्वाचित उस नेतृत्व के नियन्त्रण में आस्था रखते हैं जो सावजनिक हित में शासन करता है।

परन्तु केवल अधिक लोक कल्याण और सावजनिक हित की साधना को ही पूर्ण लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सम्पूर्ण समीचीन अधिक स्वतन्त्रता ही नहीं है। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता भी लोकतन्त्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें कई प्रकार की स्वतन्त्रताएँ सम्मिलित होती हैं। चूँकि रूस में वंचारिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राजनितिक संगठन की व अल्प संख्या की स्वतन्त्रता व्यावहारिक दृष्टि से लगभग पूरी तरह प्रतिनिधित है, अतः इस दृष्टि से रूसी शासन व्यवस्था लाकतन्त्रीय नहीं ठहरती।

इस सम्पूर्ण विवेचना से हम इसी वस्तु स्थिति पर पहुँचते हैं कि सोवियत सरकार जनता की तथा जनता के लिए होने हुए भी अद्वैत-लोकतन्त्रात्मक सरकार है। सोवियत रूस में परम्परागत प्रकार का लाकतन्त्र नहीं है जिसकी तुलना पश्चिमी लाकतन्त्रों से की जा सके। सोवियत शासन व्यवस्था को एक नये प्रकार के प्रजातन्त्र का प्रयोग कहना सम्भवतः अधिक ठीक होगा।

EXERCISES

Chapter I

- 1 Trace the Constitutional Development of Soviet Russia till to day
आज तक सोवियत रूस के सांविधानिक विकास का वर्णन कीजिये।
- 2 Mention the salient features of the Constitution of the U S S R adopted in 1936
1936 के सोवियत संविधान की विशेषताओं को बतलाइये।

Chapter II

- 1 Comment on the view that the Soviet Union is a federal State with a unitary bias
इस कथन की समीक्षा कीजिये कि सोवियत संघ एक सघातमय राज्य है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है।
- 2 Examine the distribution of powers and functions between the U S S R and its component units Do you consider the U.S S R to be a federal union ? If so, why ?
सोवियत रूस में संघ सरकार तथा एककों की सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का विवरण दीजिये। क्या आप सोवियत रूस को एक संघ राज्य कह सकते हैं ? यदि हाँ तो कारण बतलाइये।

Chapter III

- 1 Examine the fundamental Rights and Duties as embodied in the Constitution of the U S S R How far they are effective ?
सोवियत संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की समीक्षा कीजिये। ये कहाँ तक प्रभावपूर्ण हैं ?
- 2 Examine the nature and reality of the fundamental rights in the U S S R
सोवियत संविधान के मौलिक अधिकारों की वास्तविकता तथा स्वभाव का विवरण कीजिये।

Chapter IV

- 1 Describe the organisation, composition and functions of the Supreme Soviet of the U S S R
सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के संगठन, रचना तथा कार्यों का विवरण दीजिये।
- 2 Discuss the Legislative procedure of the Supreme Soviet
सर्वोच्च सोवियत की विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- 3 "The Supreme Soviet, as it is more often called the Supreme Council is regarded as the highest organ of State power in the U S S R." Discuss
'सर्वोच्च सोवियत, जिसे सर्वोच्च परिषद् भी कहते हैं, सोवियत रूस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है।' इस कथन की विवेचना कीजिये।

सपा, उपभोक्ता सहकारी सपा, युवक संगठनो आदि की रूसी जनता की सदस्यता इतनी है कि उसका अनुपात प्रायः अन्य सभी देशों से बढ़कर है।

वस्तुतः सरकार का स्वरूप ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होता। सरकार किस कुरालता से काम कर रही है, समाज और व्यक्ति की उन्नति कितनी हो रही है, यह अधिक महत्वपूर्ण है और रूसी शासन-व्यवस्था इस दृष्टि से विश्व की अनेक अग्रणी लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। पाश्चात्य विद्वानों का यह आरोप कि रूसी शासन के अंतर्गत व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है भ्रमात्मक है, क्योंकि बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में उतनी उन्नति प्राप्त करना असम्भवप्रायः है जितनी रूस में हो चुकी है। ड्रिजर (Dreiser) के शब्दों में—“रूस बौद्धिक कला और ललित कला सम्बन्धी तथा व्यावहारिक सफलताओं के दृष्टिकोण से विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है।”

फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतन्त्र शासन का आधार जन इच्छा होती है। सोवियत रूस में साम्यवादी शासन, स्थापित हुए आज लगभग 54 वर्ष हो गये हैं और इस लम्बी अवधि में जनता ने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिससे यह संकेत मिलता हो कि रूसी नागरिक साम्यवादी व्यवस्था का विरोधी है। इस आधी शताब्दी के रूसी सामाजिक व नागरिक जीवन के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि रूस के साम्यवादी शासन को वहाँ के नागरिक हृदय से स्वीकार करते हैं और वह एक प्रकार से उनका अपना शासन है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि रूस के साम्यवादी स्वयं अपने देश की व्यवस्था को अधिनायकतन्त्रीय मानते हैं, परन्तु साथ ही उनका मत है कि सवहारा वग का होन के कारण वह अधिनायकतन्त्र होते हुए भी लोकतन्त्र है। रूसी शासन-व्यवस्था वास्तव में सावजनिक समर्थन प्राप्त एकाधिकारतन्त्र कही जा सकती है। रूस की लोकतन्त्र की कल्पना में जनता और उसके द्वारा सावजनिक कार्यों में भाग लेने पर बल दिया जाता है। रूसी लोग अपने द्वारा निर्वाचित उस नेतृत्व के नियन्त्रण में आस्था रखते हैं जो सावजनिक हित में शासन करता है।

परन्तु केवल अधिक लोक कल्याण और सावजनिक हित की साधना को ही पूर्ण लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सम्पूर्ण कसौटी आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं है। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता भी लोकतन्त्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएँ सम्मिलित होती हैं। चूंकि रूस में वंचारिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनसिक संगठन की व अल्प संख्या की स्वतंत्रता व्यावहारिक दृष्टि से लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है, अतः इस दृष्टि से रूसी शासन व्यवस्था लाकतन्त्राय नहीं ठहरती।

इस सम्पूर्ण विवेचन से हम इसी वस्तुस्थिति पर पहुँचते हैं कि सोवियत सरकार जनता की तथा जनता के लिए होन हुए भी अत्यन्त-लोकतन्त्रात्मक सरकार है। सोवियत रूस में परम्परागत प्रकार का लोकतन्त्र नहीं है जिसकी तुलना पश्चिमी लोकतन्त्रों से की जा सके। सोवियत शासन व्यवस्था को एक ‘नये प्रकार के प्रजातन्त्र’ का प्रयोग कहना सम्भवतः अधिक ठीक होगा।

EXERCISES

r I

Trace the Constitutional Development of Soviet Russia till today

गणतन्त्र सोवियत रूस के सांविधानिक विकास का वर्णन कीजिये।

Mention the salient features of the Constitution of the U S S R adopted in 1936

1936 के सोवियत संविधान की विशेषताओं को बतलाइये।

ter II

Comment on the view that the Soviet Union is a federal State with a unitary bias

इस कथन की समीक्षा कीजिये कि सोवियत संघ एक संघात्मक राज्य है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है।

Examine the distribution of powers and functions between the U S S R and its component units Do you consider the U S S R to be a federal union ? If so, why ?

सोवियत रूस में संघ सरकार तथा एक-एक की सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का विवरण दीजिये। क्या आप सोवियत रूस को एक संघ राज्य कह सकते हैं ? यदि हाँ तो कारण बतलाइये।

apter III

Examine the fundamental Rights and Duties as embodied in the Constitution of the U S S R How far they are effective ?

सोवियत संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की समीक्षा कीजिये। ये कहाँ तक प्रभावपूर्ण हैं ?

2 Examine the nature and reality of the fundamental rights in the U S S R,

सोवियत संविधान के मौलिक अधिकारों की वास्तविकता तथा स्वभाव का विवरण कीजिये।

Chapter IV

1 Describe the organisation, composition and functions of the Supreme Soviet of the U S S R

सोवियत संघ की सर्वोच्च सांविधानिक सभा के संगठन, रचना तथा कार्यों का विवरण दीजिये।

2 Discuss the Legislative procedure of the Supreme Soviet
सर्वोच्च सोवियत की विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

3 "The Supreme Soviet, as it is more often called the Supreme Council is regarded as the highest organ of State power in the U S S R" Discuss

'सर्वोच्च सोवियत, जिसे सर्वोच्च परिषद् भी कहते हैं सोवियत रूस की राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है।' इस कथन की विवेचना कीजिये।

- 4 What limitations, if any, do you find on the supremacy of the Supreme Soviet of the U S S R ?
सर्वोच्च सोवियत की सर्वोच्चता पर कौन से प्रतिबंध हैं ?
- 5 Describe the Committee System as it obtains in the U S S R.
सोवियत रूस में प्रचलित समिति पद्धति की विवेचना कीजिये ।
- 6 Describe and discuss the Soviet of Nationalities
राष्ट्रीयताओं की सोवियत का वर्णन कीजिये ।

Chapter V

- 1 Describe the composition, powers and functions of the Presidium and show its relation with the Council of Ministers in U S S R
सोवियत संघ के प्रेसिडियम के संघटन, शक्तियाँ तथा कृत्यों का वर्णन कीजिये और मंत्रिपरिषद् से उसका सम्बन्ध बतलाइये ।
- 2 How far do you agree with the statement that the Soviet Presidium is the unique institution in the World ?
आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि सोवियत रूस की प्रेसिडियम संसार में एक अनोखी संस्था है ?

Chapter VI

- 1 Explain the composition, powers and functions of the Council of Ministers under the Soviet Constitution
सोवियत संविधान में मंत्रिपरिषद् के संघटन शक्तियाँ तथा कार्यों की व्याख्या कीजिये ।
- 2 To what extent does the Soviet Union possess a responsible parliamentary type of Government ? Compare and contrast it with that in Britain
सोवियत संघ में कहाँ तक एक उत्तरदायी संसदात्मक सरकार है ? ब्रिटिश व्यवस्था के साथ इसकी तुलना कीजिये ।

Chapter VII

- 1 Discuss the purpose and organisation of Soviet Judiciary
सोवियत न्यायपालिका का उद्देश्य तथा संगठन का वर्णन कीजिये ।
- 2 What are the distinguishing features of the Soviet Judicial System ?
सोवियत न्याय व्यवस्था की विशेषताएँ क्या हैं ?
- 3 Compare the organisation and powers of the Supreme Court of the U S S R with that of the Federal Tribunal of Switzerland and Supreme Court of U S A
सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय के संघटन तथा शक्तियाँ का तुलना स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय तथा संघीय सर्वोच्च न्यायालय से कीजिये ।

- 4 Examine the powers and position of the Procurator General of the U S S R

सोवियत संघ के महान्यायवादी की शक्तियाँ तथा स्थिति की समीक्षा कीजिये।

Chapter VIII

- 1 Write a short note on local government in the Soviet Union
सोवियत संघ में स्थानीय शासन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये।
- 2 Describe the salient features of the Constitutions of the Union Republics It is correct to call Russia a Federation ?
सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संविधानों की प्रमुख विशेषताएँ बताइये। क्या रूस को एक संघ कहना ठीक है ?

Chapter IX

- 1 What do you understand by the "Soviet System" ? How are the Soviets formed ? What are their functions and importance ?
'सोवियत प्रणाली' से आप क्या समझते हैं ? सोवियतों का निर्माण कैसे होता है ? उनके कर्तव्य तथा उनका महत्व क्या है ?
- 2 "The Soviets are the State organs of the dictatorship of the proletariat ?" Discuss
सोवियतों ही सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के शासन की उपकरण हैं।" विवेचना कीजिये।

Chapter X

- 1 "The Communist Party is the vanguard of the proletariat dictatorship and has assumed the ruling position in the Soviet Union" Discuss
"साम्यवादी दल सर्वहारा अधिनायकत्व का मार्ग-दर्शक तथा सोवियत संघ का वास्तविक शासक है।" विवेचना कीजिये।
- 2 Briefly describe the organisation of the Communist Party of the Soviet Union How far can this party be said to control the Government ?
सोवियत संघ के साम्यवादी दल के संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। इस दल का शासन पर कहा तक नियंत्रण है ?

Chapter XI

- 1 Discuss critically the view that democracy in U S S R is a veiled dictatorship
इस विचार की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये कि सोवियत प्रजातंत्र एक आवरित अधिनायकत्व है।
- 2 "A million times more democratic than the most democratic bourgeois republic Examine this claim with reference to the presence of democratic element in the constitution of the U S S R

बुद्धिमान प्रजातान्त्रिक गणतंत्र से लाख गुना अधिक प्रजातान्त्रिक है।" सोवियत रूस के प्रसंग में इस कथन की समीक्षा कीजिये।

SELECTED READINGS

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Adams and others | Foreign Governments and their Backgrounds |
| 2 Ogg and Zink | Modern Foreign Governments |
| 3 Wheare | Federal Government |
| 4 Williams, A R | The Soviets |
| 5 Caster and Others | , Government of the Soviet Union 1954 |
| 6 Fainshold, M | How Russia is Ruled ? |
| 7 Florinsky, M T | Russia - A History and an Interpretation, 1953 |
| 8 Harper, S N | The Government of the Soviet Union |
| 9 Hazard, J H | The Soviet System of Government |
| 10 Karpinsky, V | The Social and State Structure of the U S S R |
| 11, Kirichinko, A D | Soviet State Law, 1960 |
| 12 Kulski W W | The Soviet Regime 1954 |
| 13 Scott, D J R | Russian Political Institutions |
| 14 Strong, A L | The New Soviet Constitution |
| 15 Towster, J' | Political Power in the U S S R. |
| 16 Vyshinsky, A Y | The Law of the Soviet State |
| 17 Eimer | The Governments of Europe |
| 18 Ogg | European Governments and Politics |
| 19 Neuman | European and Comparative Governments |
| 20 Poliansky | The Stalin Constitution on Judiciary and the Procurator's Office |
| 21 Berman, H J | Justice in Russia, 1950 |
| 22. Sidney and Beatrice Webb | Soviet Communism-A New Civilization |
| 23 Mikhailov, Nikolai | Sixteen Soviet Republics |
| 24 Batsell, W R | Soviet Rule in Russia, |
| 25. Gibberd | Soviet Russia |
| 26 Rostow and Lewin | The Dynamics of Soviet Society |
-

जापान का संविधान
(THE CONSTITUTION OF JAPAN)

‘जापान में सम्राट और जनता एक है। सारी जनता उन धार्मिक
 मन्त्रों द्वारा सम्राट से सम्बद्ध है जिनकी जड़ें उनके हृदय की तली
 में गहराई से लगी हैं और यही एवता राज्य की स्थिति की
 नींव बनी है।’

—३१० कानामोरा तोकुजिरो

‘जापान के प्राचीन सविधान के अन्तर्गत एक मन्त्रिपरिषद् थी, पर मन्त्रि
 परिषद्-व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान सविधान सर्वाधिक स्वोक्त
 शासनात्मक आधार पर एक संसदीय या मन्त्रिपरिषदात्मक
 व्यवस्था का उपबन्ध करता है।’

जापान के संविधान की विशेषताएँ **(SALIENT FEATURES OF THE JAPANESE CONSTITUTION)**

जापान अपने वर्तमान संविधान से पूर्व मेइजी संविधान (Meiji Constitution) द्वारा शासित था जो 1889 में लागू किया गया था और 1945 में जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के पश्चात् समाप्त हो गया था। अतः वर्तमान संविधान का अध्ययन करने में पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में इस मेइजी संविधान की रूपरेखा समझ लेना उपयोगी रहेगा।

मेइजी संविधान एक लिखित संविधान था जिसने एकात्मक प्रणाली की स्थापना की थी। सरकार की समस्त शक्तियाँ—कार्यवाहिका, विधायी एवं याचिका-केवल सम्राट में ही समिष्ट थी। इस संविधान में स्थानीय सम्राट को पूज्य एवं अनुत्लङ्घनीय (Sacred and Inviolable) घोषित किया गया था। स्वशासन का कहीं भी उल्लेख नहीं था। सम्राट तानून से ऊपर था। वह मामलाज्य का प्रधान था और राजसत्ता के समस्त अधिकार उसी में केन्द्रित थे। सम्राट ही सैनिक शक्तियाँ का प्रधान था। सम्राट के लिए अनुभवों राजनीतिज्ञों की जेनरो (Genero) नामक छोटी-सी सलाहकार समिति थी। सम्राट के अधीन इस समिति की इच्छा सब-सत्तावादी थी। सम्राट जेनरो की मंत्रणा पर जापान के प्रधानमंत्री को चुनता था और प्रधान मंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव करता था जो उसकी कैबिनेट के सदस्य होते थे। मंत्रियों के लिए सदन (Diet) का सदस्य होना आवश्यक नहीं था। जापान का राजनीति पर सैनिक प्रभाव बना रहता था। सदन में पराजित होने पर अथवा अविश्वास का प्रदर्शन करने पर भी कैबिनेट अपना त्यागपत्र नहीं देता थी। कैबिनेट के अतिरिक्त एक प्रिवी परिषद् (Privy Council) भी थी जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, 12 मंत्रिगण और सम्राट द्वारा मनानीय 24 सदस्य होते थे। प्रिवी परिषद् केवल आवश्यकता के समय सम्राट को परामर्श देती थी। मंत्रिगण परिषद् के पदेन

सदस्य होते थे। परिपक्व म सदस्य का कार्यकाल जीवन पथत था, इसलिए यह संस्था प्रजातन्त्र एवं ससदीय प्रणाली के प्रतिकूल थी।

जापान की व्यवस्थापिका को डाइट (Diet) कहते थे। इसमें दो सदन थे। बड़े सदन का नाम 'पीयर्स सभा' (House of Peers) था जिसकी सदस्य संख्या 409 थी। छोटे सदन का नाम प्रतिनिधि-सभा (House of Representatives) था जिसमें 450 सदस्य थे। मेइजा संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका शासन का प्रभावशाली अंग नहीं थी। यद्यपि मंत्रिमण्डल के निर्णयों और नीतियों का व्यवस्थापिका संस्था समर्थन करती थी, तथापि उसमें ऐसे दलों का नितांत अभाव था जिनकी निश्चित एवं भिन्न नीतियां हों। यही नहीं, मंत्रिमण्डल के निर्णयों को दोहराने का अधिकार अन्य अधिशासी अंगों जैसे प्रिंसीपल को भी था। संक्षेप में डाइट केवल मात्र एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसका उपयोग केवल राज्यों के प्रधान को अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देना था। वस्तुतः प्रजातन्त्र के बाह्य आडम्बर के रूप में जापान में राजतन्त्र ही प्रचलित था।

मेइजी संविधान के अंतर्गत एक सर्वोच्च युद्ध समिति (The Supreme War Council) की भी व्यवस्था थी। इस संविधान में सैनिक तत्त्वों का प्राधिकार होने के फलस्वरूप संसद्वाद का प्राधान्य था। मंत्रिमण्डल में भी युद्ध एवं जन सभा के मंत्री सैनिक अधिकारी ही नियुक्त किये जाते थे। सर्वोच्च युद्ध समिति में सभा के प्रधान अफसर होने थे। इस तरह शासन में नागरिक और सैनिक अधिकारों में प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया गया था जो देश के लिए एक घातक नीति थी। नौकरशाही और संसद्वाद के इसी तत्त्वा ने जापान को अंततः साम्राज्यवाद के उस विनाशकारी विस्फोट की ओर धकेल दिया जो द्वितीय महायुद्ध के रूप में प्रगट हुआ और जिसने अंत में जापान के चेहरे पर पराजय की कालिख पोत दी।

जापान के वर्तमान संविधान की विशेषताएँ

(Salient Features of the Modern Constitution of Japan)

द्वितीय महायुद्ध में फासिस्ट खेमे को पूरी तरह पराजय का मुख देखना पड़ा और अगस्त सन् 1945 में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पराजित जापान में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैकआर्थर ने 11 अक्टूबर, 1945 का जापानी कैबिनेट का बतला दिया कि देश के लिए नवीन संविधान प्रस्तावित होगा। फलस्वरूप सरकार ने एक संवैधानिक समस्या की अनुसंधान समिति (Constitution Problem Investigation Committee) की स्थापना की लेकिन इसने कोई विषय कार्य नहीं किया। नवीन संविधान संघर्ष में मैकआर्थर द्वारा ही जापानी मंत्रिमण्डल के साथ बनाया

गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक संविधान-वेत्ताओं को बुनवाकर नवीन संविधान तैयार करवाया गया। संविधान के अन्तिम प्राव्य का जापान की केबिनेट ने मार्च, 1946 में स्वीकार किया और कुछ साधारण परिवर्तना के बाद नवम्बर, 1946 में डायट (जापानी संसद) द्वारा भी इस स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात् 3 मई 1947 को यह नवीन संविधान कार्यान्वित कर दिया गया जिसकी मुख्य विशेषताओं को हम संक्षेप में निम्नवत् प्रकट कर सकते हैं—

संक्षिप्त व सरल संविधान

जापान के नये संविधान को जापान का संविधान कहा जाता है, जब कि 1889 के संविधान को 'जापानी साम्राज्य का संविधान' का नाम दिया गया था। जापान के वर्तमान संविधान का आकार बहुत ही छोटा है। इसमें एक प्रस्तावना (Preamble) और 103 धारार्य हैं। इसमें अमेरिकन ब्रिटिश एवं अंतराष्ट्रीय सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इसके द्वारा जापान में प्रजातन्त्र की प्राप्ति का प्रशसनीय प्रयत्न किया गया है। 11 अध्यायों का यह संविधान लगभग 20 पृष्ठों मात्र में है। इसकी भाषा बड़ी सरल और सुस्पष्ट है।

संविधान एक सर्वोच्च कानून

नवीन संविधान जापान का 'सर्वोच्च कानून' (Supreme Law) है। शासन का कोई भी अंग संविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि शासन की प्रत्येक शाखा के कमचारियों को संविधान की पूरी मान्यता देनी होगी, अर्थात् सम्राट् तथा संसद सदस्य, यायागीश आदि इस संविधान के अधीन अपने क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभायेंगे और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे।

अनुपम प्रस्तावना: जन प्रभुसत्ता एवं उदात्त आदर्शों की स्थापना

संविधान का प्रमुख भावपूर्ण इसकी प्रस्तावना है जिसमें जनता की शक्ति का आदि स्रोत घोषित किया गया है। ऐसी सुंदर प्रस्तावना अल्प देशों का कम ही मिलती है। इस प्रस्तावना में—

- 1 सभा राष्ट्रीय के साथ गति एवं सहयोग रखने पर बल दिया गया है।
- 2 युद्ध की निन्दा की गई है।
- 3 शासन को एक पवित्र धरोहर (Sacred Trust) घोषित किया गया है।
- 4 शासन-सत्ता का स्रोत जनता है और उसका संचालन भी जनता के प्रतिनिधियों का ही सौंपा गया है।
- 5 जापान की जनता ने अपनी सुरक्षा एवं अपने वंचन के लिए विश्व

के शांतिप्रिय राष्ट्री को यायभावना और सद्भावना में विश्वास प्रगट किया है।

6 जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करने की दृढ़ आकांक्षा प्रकट की है।

7 जापानी विश्व में दासता, भ्रष्टाचार, गणित एवं असहिष्णुता को मिटाना चाहते हैं।

8 अतः, जापानी जनता अपने राष्ट्रीय सम्मान, दृढ़ मूल्य और समाज-भाषनों को उद्देश्य की सिद्धि में लगाने की प्रतीति करती है।

युद्ध का परिष्कार

वर्तमान संविधान में जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया है। संसार में अन्य किसी भी देश के संविधान में युद्ध के परिष्कार की बात का समावेश नहीं किया गया है।

वास्तव में देखा जाए तो युद्ध त्याग का यह घादर्स बड़ा ही सुंदर और अनुकरणीय है। लेकिन अब तक विश्व के अन्य राष्ट्र भी ऐसा करने का उद्यत न हो तब तक एक राष्ट्र द्वारा प्रगट किया गया इस प्रकार का निश्चय व्यावहारिक ही प्रतीत होता है।

जनतन्त्र का समर्थक

वर्तमान संविधान में सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए अनेक प्रगतिशील पग उठाये गये हैं। इसमें लोकप्रिय प्रभुता का समावेश (Assertion of Popular Sovereignty) किया गया है। सम्राट की वास्तविक शक्तियां छीन ली गई हैं। अब नेशनल डायट (जापान की संसद) शासन-सत्ता का सर्वोच्च अंग है। डायट के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है। निम्न सदन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से निर्वाचित होता है इसीलिये यह लोकप्रिय सदन है तथा ऊपर वाले सदन में अधिक शक्तिशाली है। कैबिनेट वास्तव में जापान की संसद के प्रति उत्तरदायी है। संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को मतदाधिकार प्राप्त हो गया है। स्त्रियों को पहली बार मतदाधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का भी संविधान में उल्लेख किया गया है।

एकात्मक संविधान

जापान का संविधान एकात्मक है। प्रशासन की दृष्टि से विदेशीकरण को व्यवस्था आवश्यक है, किन्तु शासन का स्वरूप एकात्मक हो रखा गया है। संविधान द्वारा शक्तियों का कोई विभाजन नहीं किया गया है। सम्पूर्ण शक्तियां केन्द्र में निकलती हैं। प्रान्त 'डायट' (Diet) के अधिनियमों से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और डायट की इच्छानुसार इन शक्तियों का

विस्तृत या संकुचित किया जा सकता है। प्रातः अधीनस्थ इकाइयाँ हैं जिन्हें केवल वे ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो केन्द्रीय सरकार ने चाही हैं।

संसदीय शासन

संविधान जापान के लिए संसदीय शासन की व्यवस्था करता है। संसदीय शासन के अनुरूप जापानी राष्ट्र का अध्यक्ष सम्राट नामधारी कार्यपालिका है, जिसके हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और जिसकी स्थिति अधिकांश रूप में ब्रिटिश राजा के ही समान है। अधिशासनिक सत्ता कैबिनेट है, जिसका प्रधान प्रधान मंत्री है।

संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका के सदस्यों में से होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव डायट ही करती है। अग्र मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करता है जिनमें से अधिकांश का डायट का सदस्य होना अनिवार्य होता है। जापानी संविधान के अन्तर्गत जापान में डायट के हर सदस्य व्यक्ति भी मंत्री बनाये जा सकते हैं। ब्रिटन में ऐसा नहीं हो सकता। संविधान यह भी घोषित करता है कि कैबिनेट का उत्तरदायित्व डायट के प्रति होगा और डायट में विश्वास खो बैठने पर कैबिनेट को त्यागपत्र दे देना होगा, यदि वह 10 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन का भंग नहीं कर देगी।

“कार्यपालिका की स्वतंत्रता”

संविधान में एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायालयों के न्यायाधीश केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाये जा सकते हैं और उनके कार्यकाल में तथा उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। कार्यपालिका को किसी अग्र अथवा अभिकरण की अन्तिम शक्ति नहीं दी गई है। सभी न्यायाधीश अपने कार्य में स्वतंत्र हैं।

संविधान की धारा 81 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन को भी व्यवस्था है अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और डायट द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार रखता है। जापानी कार्यपालिका की एक अन्य विशेषता है—न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जन साधारण का सामान्य निर्वाचन में अनुमोदन प्राप्त करना। इस प्रकार की व्यवस्था भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में उपलब्ध नहीं है।

प्रचल संविधान

जापानी संविधान प्रचल अथवा अनमोदित (Rigid) है और इनके संशोधन की कार्यविधि भी काफी बड़ी है। परन्तु यह किसी भी तरह से इतना कठिन नहीं है कि इसे संयुक्त राज्य की भाँति व्यवहार में ही बड़ी कठिनाई से लाया जा सके। जापानी संविधान के संशोधन का तरीका संविधान की धारा 96 में इस प्रकार दिया गया है—

संविधान में संशोधन के प्रस्ताव का प्रारम्भ हाउस द्वारा किया जायगा, जिसके पक्ष में प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों में से दो तिहाई अथवा उससे भी अधिक सदस्यों का मत होना आवश्यक है। उसके बाद संशोधन के प्रस्ताव पर लोक निर्णय (Referendum) कराया जायगा। लोक-निर्णय में भाग लेने वाले मतदाताओं की बहुसंख्या का मत संशोधन के पक्ष में होने पर संशोधन स्वीकृत होगा। उसके पुरस्तर बाद संसद ऐसे संशोधन को जनता के नाम से संविधान के आवश्यक अंग के रूप में घोषित करेगा।”

स्पष्ट है कि जापान के संविधान में संशोधन करना सुगम नहीं है, क्योंकि हाउस के दोना सदनों के दो तिहाई बहुमत से पास होने पर भी संशोधित प्रस्ताव को जनता के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है और यदि वे जनमत संग्रह (Referendum) में बहुमत से पास हो जाते हैं, तभी उनको स्वीकार किया जाता है।

मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश

संविधान में जनता के अधिकारों व कर्तव्यों की चर्चा तीसरे अध्याय में की गई है और 10 से लेकर 40 तक की धाराओं का सम्बन्ध इसी महत्त्वपूर्ण विषय से है। संविधान में घोषणा की गई है कि ये अधिकार शाश्वत और अनुत्तल्य हैं तथा ये स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सूची बहुत बड़ी है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, गर कानूनी बन्दीकरण से मुक्त होना की स्वतन्त्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार धार्मिक स्वतन्त्रता आदि विभिन्न अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान प्रजाजना के काम करने के अधिकार को भी मानता देता है।

संविधान ने कुछ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए संविधान की धारा 30 के अनुसार यह व्यवस्था है कि प्रजाजन कानून द्वारा निर्धारित करा का भुगतान करेंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की व्यवस्था के विपरीत जापानी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक नहीं बनाया गया है।

द्वितीय सदन की रचना

ब्रिटन, भारत अमेरिका आदि देशों की भांति जापानी व्यवस्थापिका हाउस के दो सदस्य हैं लेकिन हाउस के दूसरे सदन की रचना का आधार उक्त तीनों ही देशों के द्वितीय सदन से भिन्न है। जापान का द्वितीय सदन भी जनता का प्रतिनिधि है और उसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किये जाते हैं। इस प्रकार जापान में रचना के दृष्टिकोण से दोनों ही सदन में समानता स्थापित की गई है लेकिन शक्तियाँ की दृष्टि से वे समान नहीं हैं। द्वितीय सदन की शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा कम हैं।

2

नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य (RIGHTS AND DUTIES OF THE CITIZENS)

सन् 1946 के जापानी संविधान में अधिकार पत्र (Bill of Rights) का समावेश किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन स्वतंत्रता समानता शिक्षा, रोजगार आदि के विभिन्न मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मर्यापि 1889 के संविधान में भी मौलिक अधिकारों का समावेश था लेकिन उसमें यह अत्यन्त सूक्ष्म, अपूर्ण एवं प्रभावहीन थे। नवीन संविधान के अतिसत मूल अधिकारों की प्रभावपूर्ण व्यवस्था है और साथ ही साथ उनकी परिसीमनों (Limitations) का भी वणन कर दिया गया है। अधिकारों के साथ कतिपय कर्तव्यों का भी उल्लेख है। अधिकारों का वणन पर्याप्त रूप से विस्तृत है। संविधान के एन सम्पूर्ण अध्याय में जनता के अधिकारों व कर्तव्यों का वणन दिया हुआ है। इस अध्याय में 10 से 40 तक अर्थात् 31 धाराएँ हैं जिनमें से केवल तीन धाराओं में ही कर्तव्यों का वणन है दोष 28 धाराओं में अधिकारों का वणन किया गया है।

जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जो अ य प्रजात त्रिय देशों के संविधानों में पाये जाते हैं। पर दा ऐसे अधिकारों का भी वणन है जो दूसरे देशों के संविधानों में दिखाई नहीं पड़ते। यह अधिकार विदेश जाने और राष्ट्रियता त्याग करने के हैं। अधिकारों के परिसीमन भी अमरलड या भारत के समान अधिकारों का व्यापक नहीं हैं। सकटकाल में उनके स्थगन आदि के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है।

अधिकार (Rights)

जापानी संविधान में अधिकारों के वणन में कोई क्रम नहीं है। अतः निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि संविधान कितन प्रकार के अधिकार प्रदान करता है ? फिर भी वणन की स्वतंत्रता का दृष्टि से हम उसको निम्नांकित शोषकों में विभाजित कर सकते हैं—

वैयक्तिक अधिकार—संविधान की 13वीं धारा में कहा गया है कि 'जनता के प्रत्येक सदस्य का व्यक्ति के रूप में आदर किया जायेगा।

व्यवस्थापिका तथा अन्य शासन सम्बन्धी कार्या में जीवन, स्वतन्त्रता तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जहाँ तक वह सावजनिक कल्याण में बाधक न हो मुख्य विचार का विषय होगा।” स्पष्ट है कि जापानी संविधान में व्यक्ति को समाज का अवयव (Organ) स्वीकार करते हुए उसको व्यक्तिगतता (Individuality) का महत्त्व दिया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व (Personality) का विकास करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके।

समानता का अधिकार—जापानी संविधान की धारा 14 घोषित करती है कि ‘कानून के अन्तर्गत सभी व्यक्ति समान हैं और जाति पति, सामाजिक स्थिति या बगैर सद्भव के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विभेद नहीं किया जायेगा।’ इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को लॉर्ड की उपाधियों को मान्यता देने से निषिद्ध कर दिया गया है। संविधान ने ‘पीयर’ (Peer) की उपाधि को मान्यता नहीं दी है। साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सम्माननीय उपाधि प्रथम या अन्य किसी प्रकार का आदर चिह्न प्राप्त हो तो वह उससे आचार पर किसी विशेषाधिकार का प्रयोग धार्मिक रूप में नहीं कर सकेगा। साथ ही इस प्रकार की सम्माननीय उपाधियाँ केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहेंगी उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होंगी, जसा कि ब्रिटन में है।

धारा 24 के अनुसार विवाह केवल स्त्री-पुरुष की सहमति से ही संभव है और उसे पति-पत्नी के समान अधिकारों के आधार पर पारस्परिक सहयोग स्थापित रखने का निर्देश है। धारा 24 ही यह उपरिष्ठित करती है कि राज्य पति-पत्नी के चुनाव, सम्पत्ति अधिकार उत्तराधिकार, निवास चुनाव, तलाक तथा विवाह और परिवार सम्बन्धी अन्य विषयों में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और स्त्री-पुरुष की मारभूत समानता के दृष्टिकोण की विधि निर्माण करेगा।

धारा 24 के अनुसार उत्तरदायी विधि में लिंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है और दृष्टि-भूमि तथा अन्य सम्पत्ति में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार दिये गये हैं तबिय प्रयोग रूप में प्रायः लहरिया पितृ की सम्पत्ति में भाग नहीं लेती। जापान में वसना-वृत्ति नियंत्रण कानून विधि भी लागू कर दी गई है और अन्य प्रकार का मानवतावादी का भी स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। उन्नीसवाँ है कि अधिकांश जापानी महिला अपने अधिकारों के प्रयोग का धार ध्यान नहीं देना।

राजनीतिक अधिकारियों को चुनने व हटाने का अधिकार—संविधान की धारा 15 के अनुसार सर्वोच्च अधिकारियों के निर्वाचन व सम्बन्ध में जापानी राजा-रानी का शासकीय वस्तुतः शासकीय प्रभुत्व निम्न है। “रा

निर्वाचनों में गुप्त मतदान का व्यवस्था की गई है क्योंकि इसे अभाव में व्यक्तियों को अपने मत परम्परा के अनुसार मत देने की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो पाती।

याचिका का अधिकार—धारा 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए सावधानी अधिनियम के निष्कासन के लिए कानूनी प्रयासों या विनियमों के निर्माण या विच्छेदन या संशोधन के लिए तथा अन्य इसी प्रकार के मामलों के लिए क्षतिपूर्ति का याचिका करने का अधिकार दिया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे याचिका के करण के कारण किसी व्यक्ति को विच्छेद विभेद नहीं किया जायेगा।

यह अधिकार विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ही भाँति जापान में भी व्यक्त्यापिका प्रत्येक अधिवेशन में हजारों याचिकाएँ प्राप्त करती हैं जो उसके द्वारा समितियाँ भी भेज दी जाती हैं और अधिकांश उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती।

क्षतिपूर्ति का अधिकार—संविधान अपनी धारा 17 और 40 के द्वारा नागरिका का क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देता है। धारा 40 में उल्लिखित है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी और नजरबन्दी के पश्चात् निर्दोष घोषित कर लिया जाता है तो वह जिस कानून द्वारा उपबन्धित है, क्षतिपूर्ति हेतु राज्य का प्रायश्चित्त कर सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार—संविधान की धारा 18 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह में बधन में नहीं रखा जा सकता। किसी भी व्यक्ति से उसकी सम्मति के बिना बलपूर्वक कोई काम नहीं कराया जा सकता। दूसरे शब्दों में बेगारी को प्रथा का निषेध कर दिया गया है। बलपूर्वक दासता केवल वहाँ पर लागू हो सकती है जो किसी अपराध के लिए दण्डित किये गये हों।

विचार अन्त करण एवं धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार—संविधान अपनी 19वीं धारा में विचार अन्त करण और धर्म की स्वतन्त्रताओं की गारण्टी करता है। धारा 20 में उल्लिखित है कि किसी भी धार्मिक संगठन को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और न वह कोई राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। किसी धार्मिक कृत्य, पर्व रिवाज या अवसर पर भागी बनने का किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जायेगा। राज्य और उसका प्रत्येक विभाग धार्मिक शिक्षा एवं प्रत्येक प्रकार के धार्मिक कृत्यों से दूर रहेंगा। स्पष्ट है कि जापान भी भारत की भाँति एक धर्म निरपेक्ष राज्य है।

अभिव्यक्ति का तथा जीवन एवं स्वाधीनता का अधिकार—संविधान की धारा 21 जापानी प्रजा-जना की संगठन, सभा भाषण मुद्रण तथा

अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को व्यवस्था करती है। परन्तु इस अधिकार का कहीं दुरुपयोग न हान लगे, इसलिये इसे अप्रतिबन्धित नहीं छोड़ा गया है। असाधारण परिस्थिति अथवा संकटकाल में इस प्रकार की स्वतंत्रता के स्थगन की प्रथा है।

जापान के संविधान की धारा 31 यह उपबन्धित करती है कि 'किसी व्यक्ति का कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार में जीवन या स्वाधीनता में वंचित नहीं किया जायेगा और न उस पर फौजदारी कायवाही ही की जा सकेगी।' इस धारा से स्पष्ट है कि जापान में अवयव बंदाकरण नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दण्डित किया जा सकता है या बंदी बनाया जा सकता है।

जीवन और स्वाधीनता के अपहरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया स्थापित करने के राजकीय अधिकार को धारा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 के द्वारा परिसीमित किया गया है।

धारा 32 में कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति का न्यायालय प्रवेश के अधिकार से इन्कार नहीं किया जायेगा। संविधान की 33वीं और 34वीं धाराओं व्यक्तियों को अवयव गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाती है। धारा 34 के अनुसार उपबन्धित किया गया है कि 'किसी भी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब तक उसे उसके अपराधों के बारे में बताया नहीं दिया जाए। उसे अविलम्ब वकाल करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक बंदी नहीं रखा जायेगा जब तक बंदी बनाये जाने का पर्याप्त कारण मौजूद न हो। यदि व्यक्ति उस कारण को जानना चाहेगा तो वह उसके तथा उसके वकाल की उपस्थिति में न्यायालय में बतलाया जायेगा।' धारा 35 में उल्लिखित है कि 'सभी व्यक्तियों का अपना गृह प्रवेश और सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रवेश, तलाशियाँ और अभिग्राहण के विरुद्ध सुरक्षित हान का अधिकार बिना पर्याप्त कारण पर जारी किये गये और विशेष रूप से तलाशी किये जाने वाले स्थानों और अभिग्राहण की जान वाली वस्तुओं का वणन करने वाले अधिपत्र या जसा धारा 33 में उपबन्धित है के अतिरिक्त विनष्ट नहीं किया जाएगा।' उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया में इस धारा की व्यवस्था का आदर किया गया है पर प्रशासनात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना अधिपत्र (Warrant) के भी उपयुक्त कार्य किये जा सकते हैं।

धारा 36 के अनुसार लोक अधिकारियों द्वारा याचना देने या निदयता-पूर्ण दण्ड देना वर्जित है। धारा 37 के अनुसार व्यवस्था है कि 'फौजदारी मामलों में अपराधी का औपचारिकतापूर्वक मावजनिष्ठ सुनवाई की सुविधा प्रदान

की जायेगी। उस सब गवाहों की परीक्षा करने का अवसर दिया जायेगा तथा उसको सार्वजनिक ध्वज पर अपनी ओर से गवाहों का प्राप्त करने की अनिवार्य प्रक्रिया का अधिकार होगा। अभियुक्त को हर समय एक योग्य वकील की सहायता रहेगी जिस यदि स्वयं के प्रयत्न द्वारा प्राप्त करने में सफल न हो तो यह नाम राज्य को सौंप दिया जायेगा।”

धारा 38 में उपर्युक्त है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने के लिये विवश नहीं किया जायेगा। किसी दवाब यातना या धमकी अथवा दीपवालीन बदीकरण के कारण की गई अपराध स्वीकृति को प्रमाण नहीं समझा जायेगा। किसी व्यक्ति को उन मामलों में दोषी नहीं ठहराया जायेगा और दण्डित नहीं किया जायेगा जिसमें प्रमाण केवल उस व्यक्ति की अपराध स्वीकृति ही हो।

धारा 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिये अपराधी नहीं ठहराया जायेगा जो विये जाने के समय कानून की दृष्टि से अपराधी न हो। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जायेगा और न ही उसे दो बार दण्डित किया जायेगा।

निवास व्यवस्था, विदेश-गमन, राष्ट्रीयता के परित्याग आदि के वैयक्तिक अधिकार—संविधान की धारा 22 उपर्युक्त करती है कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को निवास के चुनने तथा परिवर्तित करने और उस सीमा तक जहाँ तक कि सार्वजनिक कल्याण में बाध न हो व्यवसाय को चुनने की स्वाधीनता रहेगी। कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय नहीं चुन सकेगा, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पड़ती हो।’

धारा 22 के ही अनुसार यह व्यवस्था भी की गई है कि सभी व्यक्तियों की विदेश जाने तथा अपनी राष्ट्रीयता का परित्याग करने की स्वतन्त्रता अक्षत रहेगी। विदेश जाने और राष्ट्रीयता त्याग करने के ये दोनों अधिकार अन्य देशों के संविधानों में दिखाई नहीं पड़ते हैं।

शिक्षा का अधिकार—नागरिकों को नागरिकता के कार्यों के लिये उपयुक्त बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उन्हें उन उपादानों से मुग्धजित किया जाए जिससे वे नागरिकता के कार्यों को कर सकें। इसके लिए शिक्षा परमावश्यक है। ततोगत्वा शक्ति भी उन्हीं के हाथों में होती है जो विचारों को समायोजित कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। शिक्षा के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को समान शिक्षा दी जाए बल्कि इसका अर्थ यह है कि एक आवश्यक स्तर तक सबका समान शिक्षा दी जाए और इसके उपरान्त प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। जापान के संविधान में इस सिद्धान्त का ही समर्थन किया गया है। धारा 23 में घोषणा कर दी गई है कि शिक्षा स्वतन्त्रता

प्रत्याभूति की जाती है। धारा 26 में बतलाया गया है कि कानून द्वारा निर्धारित ता मई साधारण शिक्षा को लेकर और तद्वर्षिका को प्राप्त कराना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा और एसी प्रतिवार्षिक शिक्षा निःशुल्क होगी। उत्तमनायक है कि शिक्षा का जापान में अब प्रायः लोप हो चुका है।

भौतिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य का आधार— जापान का संविधान नागरिकों को भौतिक कल्याण सामाजिक सुरक्षा व कार्य के महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की प्रेरणा जापान का सम्भवतः समाजवादी सिद्धांतों से प्राप्त हुई है। संविधान की धारा 27 में सभी व्यक्तियों का काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस धारा का शब्दावली इस प्रकार है—‘सभी व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार रहेगा। कार्य करना उनका कर्तव्य भी होगा। वतन काम करने के पट आराम की अवस्थायें तथा कार्य सम्बन्धी अन्य दसायें कानून द्वारा निश्चित हो जायेंगी। वृत्ता का शोषण नहीं किया जाएगा। संविधान का धारा 25 भी सभी लोगों को स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन के उत्कृष्टतम स्तर का पोषण करने का अधिकार प्रदान करती है और सरकार को यह निर्देश देती है कि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में लोक कल्याण और सुरक्षा तथा लोक स्वास्थ्य का उन्नति और विस्तार करने में अपने प्रयासों का प्रयोग में लाये। पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 25वीं धारा की व्याख्या करते हुए घोषित किया है कि यह एक वैधानिक अधिकार नहीं होकर एक नीति निर्देशक तत्त्व मात्र है। इसलिये संविधान की धारा 28 कमचारियों को संगठित होने और सामूहिक रूप से सौदा करने तथा कार्य करने का अधिकार देती है।

सम्पत्ति का अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार एक विवादग्रस्त अधिकार है। इस अधिकार को उस समय तक मायोचित ठहराया जा सकता है जब तक वह एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और दूसरे व्यक्ति के समान विकास में बाधक नहीं सिद्ध होता हो। अतः इस दृष्टि से सम्पत्ति का अधिकार कभी भी पूरा नहीं कहा जा सकता।

जापान का संविधान इसीलिये अत्यंत रक्षित शब्दा में सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करता है। धारा 29 में सम्पत्ति के स्वामित्व और धारणा के अधिकार का अलक्ष्य घोषित किया गया है पर साथ ही यह भी कहा गया है कि सम्पत्ति का अधिकार लोक-व्यवस्था की अनुकूलता में कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा और व्यक्तिगत सम्पत्ति सामाजिक प्रयोग के लिए उचित क्षतिपूर्ति देकर राज्य द्वारा ली जा सकेगी।

कर्तव्य (Duties)

संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बखाना किया गया है जो निम्न हैं—

1 धारा 12 के अनुसार जनता सविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को सतत् रूप से पोषित करने का प्रयत्न करेगी।

2 धारा 12 के ही अनुसार जनता अधिकारों के दुरुपयोग से दूर रहेगी।

3 जनता अधिकारों का लोक-कल्याण में प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होगी।

4 जनता अपने लड़के लड़कियों को विधि द्वारा निश्चित नि गृह्य अनिवार्य शिक्षा देगी।

5 कोई बच्चा वा शोषण नहीं करेगा।

6 सभी योग्यता का कार्य का धामार है।

7 जनता कानून द्वारा निश्चित कर देने का कानून निभायेगी।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त कर्तव्य न तो अधिक है और न असाधारण ही। वस्तुतः जापानी सविधान के अन्तर्गत नागरिकों के कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है।

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था

जापान के सविधान की धारा 10 केवल इतना निश्चित करती है कि नागरिकता के सम्बन्ध में कानून द्वारा व्यवस्था की जाएगी। तदनुसार 1947 व 1950 में राष्ट्रीय कानून द्वारा नागरिकता के प्रश्न का समाधान किया गया है जिसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के निम्नांकित नियम बनाये गये हैं—

1 सबसे प्रथम जन्म सिद्धांत है अर्थात् जापानी नागरिक के बच्चे जो जापान में पैदा होंगे वे जापानी नागरिक हों जायेंगे।

2 जो विदेशी स्त्रियाँ जापानी नागरिक से विवाह करेंगी, वे जापान की नागरिक हों जायेंगी। इसी प्रकार यदि कोई विदेशी जापानी स्त्री से विवाह करके उसके परिवार का सदस्य हो जाएगा या किसी जापानी के द्वारा गोद लिया जाएगा तो वह भी जापानी नागरिक हो जाएगा।

3 देशीकरण (Naturalisation) द्वारा भी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कुछ निश्चित दिनों के निवास के बाद कोई भी विदेशी जापानी नागरिकता प्राप्त करने का अर्ज दे सकता है और यदि वह जापान में पैदा हुआ हो या उसका कोई सम्बन्धी हो तो अधिक सुविधा होगी है।

यदि जापानी नागरिक के बच्चे ऐसे देश में हों जाएँ जहाँ जन्मतः नागरिकता प्राप्त होती हो (अमेरिका, कनाडा, मक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पेरू में) तो वे उसी देश के नागरिक मान जायेंगे जब तक कि वे जापानी नागरिक बनने से इच्छा प्रकट न करें, परन्तु दा मात देश के

अलावा अन्य देशों में जन्म जापानी बच्चे तब तक जापानी नागरिक माने जाते रहेगे जब तक कि वे अपनी जापानी नागरिकता का परित्याग न कर दें।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Evaluation)

जापान के वर्तमान संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बड़ा उच्च स्तर प्रदान किया गया है और पूँजीवादी तथा साम्यवादी दोनों प्रकार के संविधानों में पाये जाने वाले अधिकारों को प्रतीकृत किया गया है तथापि कुछ दृष्टियों से यह अधिकार-व्यवस्था घुटिपूर्ण है—

(1) मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष एवं स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार नहीं सौंपता है कि वे उनकी रक्षा के लिए पूरा अधिकार भरण पा सकें। धारा 81 द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सर्वोच्च न्यायालय पर मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

(2) संविधान में अधिकारों का वर्णन क्रम ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ धारा 23 और 26 शिक्षा के अधिकार से सम्बंधित है और उन्हीं के बीच दाम्पत्य सम्बंध, जीवन-स्तर आदि के अधिकारों से सम्बंधित अन्य धाराएँ रख दी गई हैं।

(3) अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से पृथक् पृथक् नहीं किया गया है। साथ ही अधिकार सम्बंधी कुछ धाराएँ ऐसा हैं जिन्हें प्रवृत्त करने के लिए सरकार को विवश नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ धारा 25 ऐसी ही है।

(4) अधिकारों की सूची में पुनरावृत्ति भी है और कुछ अनावश्यक बातों का समावेश भी है।

(5) संविधान की धारा 11 में व्यक्तियों के अधिकारों को पवित्र वस्तु माना गया है तथापि संविधान उनकी रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त व्यवस्था नहीं करता। सरकार ने लोक स्वाधीनताप्राप्ति के रक्षण के लिए मायोग और ज्यूरो स्थापित किये हैं, पर ये भवया अपर्याप्त हैं। नई सावजनिक और व्यक्तिगत संस्थापना में प्रतिनिधित्व आदर्शवाद व्यवहार में प्रवर्तित नहीं है।

(6) अनेक कानून एन पारित कर दिये गए हैं जो संविधान का धाराप्राप्ति के प्रतिकूल कह जाते हैं। संविधान में पाई जाने वाली असंगत शब्दावली बहुत कुछ इस काम के लिए उत्तरदायी है।

(7) मौलिक अधिकार सम्बंधी प्रत्येक धारा में उस अधिकार का परिसमाहित करने वाला आधार का वर्णन नहीं किया गया है। कुछ धाराओं

में लोक-कल्याण के आधार का वर्णन कर दिया गया है और जिनमें परिसीमन के आधार का वर्णन नहीं है उनमें से कुछ तो वधानिक अधिकार ही नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ धारा 25 में वर्णित पूर्ण और सुसंस्कृत जीवन के निम्नतम स्तर को प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने 1948 के प्रपन एक नियम में वधानिक अधिकार मानने से इन्कार कर दिया था।

वस्तुतः संविधान से प्रकट यही होता है कि जापान में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सरकार पर ही छोड़ दिये गये हैं। सरकार से यह आशा की गई है कि वह इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगी। संवधानिक उपचार का अधिकार न होने से अन्य मौलिक अधिकारों की सूची अधूरी ही है। फिर भी यह निश्चित है कि सन् 1889 के संविधान की तुलना में वर्तमान संविधान अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली अधिकारों की व्यवस्था करता है।

3

सम्राट (THE EMPEROR)

सम्राट की प्राचीन स्थिति

जापान में प्रारम्भ से ही सम्राट का बहुत अधिक महत्त्व रहा है। पूर्वगामी संविधान के अन्तर्गत सम्राट साम्राज्य का अध्यक्ष था जिसमें प्रभुता के सभी अधिकार केन्द्रित थे। वह शासन का मुख्य स्तम्भ तथा आधार था लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार करता था। जापान की जनता सम्राट को ईश्वर का स्वरूप, पवित्र एवं पूर्ण गुणवान समझती थी। वह सम्राट का आज्ञा आज्ञा की ईश्वरीय आज्ञायें मानती थी। आइसो के कथनानुसार राज्य की सभी विधायी व कार्यपालिका शक्तियाँ उसके हाथों में केन्द्रीभूत थी। देश के राजनितिक जीवन के सभी सूत्र उसके नियंत्रण में इस प्रकार थे जैसे कि शरीर के सभी अंगों पर मस्तिष्क का नियन्त्रण रहता है।

द्वितीय महायुद्ध में पूर्व सम्राट की स्थिति वास्तव में महान थी। जापान की जनता सम्राट तथा अपने बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध समझती थी। उस समय जनता इस सम्बन्ध के सुगोचन के विषय में सोच भी नहीं सकती थी।

सम्राट की वर्तमान स्थिति

वधानिक अध्यक्ष—द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान में सम्राट और जनता के मध्य उपरोक्त संविधानिक सिद्धान्त में परिवर्तन आ गया। 3 मई, 1947 का नवीन संविधान कार्यान्वित किया गया और साथ ही सम्राट की स्थिति पूर्णतया बदल गई और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया।

इस नवीन संविधान के अन्तर्गत सम्राट का पद शक्ति का पद नहीं रहकर वधानिक अध्यक्ष का पद ही रह गया है। सम्राट अब शासन का अध्यक्ष नहीं रहकर राज्य का प्रतीक मात्र है। अब राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्राट में निहित नहीं रहकर प्रजाजनों में निहित है। सम्राट पद के मूल में प्रजाजनों की इच्छा है अर्थात् जनता ही सम्राट की इच्छा का सात है। शासन काय में किसी प्रकार की पहल

सम्राट को धार 1 त्ही ती जा सती, यगरी मे गसत सम्बन्धी कोई ना बाय व्यवस्थित रूप म सम्राट त्ही करता ।

सम्राट की मजिधारी स्थिति म इस परिवर्तन का ह्री यह परिणाम निकला है कि सम्राट ने विषय म प्रारम्भित तात प्रपक्षिणी प्रवाषा घोर कहानिया की ममाप्ति हो गई है । अब सम्राट के विषय म गद-विवाद किया जा सता है उसका व्यक्तिगत एव सम्पादन धारिता हो सती है । कुछ स पूर्व एका करना सम्भव था । एव परिणाम यह निता है कि सम्राट का ईश्वरत्व रूप म न मानकर उने एव मान्य बनाने का प्रयाग किया गया है । आज सम्राट जीवा व निरट धाता जा रहा है ।

इसके प्रतिरिक्त वतमान संविधान के अंतगत सम्राट का परामर्श त्ही वाली प्रवर्गमी उत्थापना जुगिन घोर प्रिया यौमिन का धन हो गया है । 'संवर्धित दृष्टि स घर सम्राट का मानन म भाग गिटा ने राजा के समान रह गया है । युनातना धावन समाप्त हो गया है तथा सम्राट की प्रभावित करने धान धाय धातरिख सगा का तानूा द्वारा मिटा लिया गया है ।'

धारागत वर-मजिधान की धारा 2 व्यवस्था त्ही है कि साम्राज्यीय सिंहासन राजरम्भरातुल्ल हाग घोर उसका उत्तराधिकारी डायट द्वारा धारित साम्राज्यीय वृह वानून के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा ।

अधिकार एव धर्म—तुरगमी संविधान म केबिनेट का कोई स्थान न्ही था जबकि वतमान संविधान म समस्त राजकीय कार्या म केबिनेट का परामर्श घोर स्वीकृति आवश्यक है तथा इन कार्या के चिये केबिनेट ही उत्तरदायी है । मजिधान की धारा 4 म यह स्पष्ट रूप स उल्लिखित कर दिया गया है कि राजकीय मामला म सम्राट केवल उन्ही कार्यों को करगा जिनकी संविधान म व्यवस्था की गई है । धासन क सम्बन्ध म उसका कोई शक्तिया न होगी ।

संविधान की धारा 7 म राजकीय मामला स सम्बन्धित व काय गिराये गये हैं जि हे सम्राट जनता के नाम म करता है । इनम से प्रमुख काय निम्न हैं—

1 संविधान के संशोधना, वानूना, केबिनेट क आदेशा एव सधियों की धोषणा करना ।

2 डायट का सत्र बुनाना, प्रतिनिधि-सदन का विघटन करना एव डायट के सदस्यों के आम निर्वाचन की धोषणा करना ।

3 राज्य व मंत्रिया की नियुक्ति करना घोर उनकी पदच्युति प्रमाणित करना ।

4 कानून द्वारा व्यवस्थित अय अधिकारियों की नियुक्ति एव का प्रमाणित करना ।

5 राजदूतों एवं मंत्रियों की शक्तियां तथा प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित करना ।

6 सम्मानसूचक उपाधियां देना ।

7 विदेशी राजदूतों तथा मंत्रियों का स्वागत करना एवं ग्राम शिष्टाचार के कार्यों को करना ।

8 साधारण तथा विशेष क्षमादान दण्ड को कम करने और अधिकारों का पुनः प्रदान करने को पुनः प्रमाणित करना ।

9 प्राणदण्ड को कुछ समय के लिये स्थगित करने को प्रमाणित करना ।

10 पुष्टिकरण आलेखों को प्रमाणित करना ।

11 कानून द्वारा व्यवस्थित ग्राम कूटनीतिक आलेखों को प्रमाणित करना ।

उपरोक्त सूची में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त सम्राट को शासन के सम्बन्ध में अन्य कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं । राज्य के सर्वोच्च अधिकार के रूप में सम्राट नियुक्ति सम्बन्धी कुछ कार्य अवश्य करता है । वह प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । इस सम्बन्ध में संविधान की धारा 6 इस प्रकार है—“सम्राट डायमंड के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल ने निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा ।”

संविधान की धारा 4 के अनुसार सम्राट की अपन करवाये के सम्पादन के अधिकार का किसी और को सौंपने का भी अधिकार है । इसका आशय यह है कि संविधान द्वारा जिन कृत्यों की व्यवस्था की गई है उनको सम्राट स्वयं कर सकता है और यदि चाहे तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी सौंप सकता है । सम्राट के अस्वस्थ हो जाने की दशा में अथवा किसी कारण से कार्य करने में उसके असमर्थ हो जाने पर, एक सरक्षक की व्यवस्था की जा सकती है जो सम्राट के नाम में ही कार्य करेगा । सरक्षक को अपने काल में उन सभी कार्यों को करने का अधिकार होगा जिन्हें संविधान ने सम्राट को सौंपा है ।

यह स्मरणीय है कि संविधान में सम्राट के जो उपरोक्त कृत्य बतलाए गए हैं वे प्रधानतः औपचारिक हैं, जिन्हें वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में करता है । संवैधानिक धारा 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्राट के पक्ष में राजकीय मामलों में सम्बन्धित हैं और उन्हें भी वह केबिनेट के परामर्श व सहमति से ही कर सकता है और उनके लिए मंत्रिमण्डल (Cabinet) ही उत्तरदायी भी होगी ।

सविधान की इस धारा से स्पष्ट है कि ब्रिटिश राजा की भाँति जापानी सम्राट का भी किसी काय के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। वृत्ति उसके सभी काम मंत्रिया द्वारा सम्पादित किये जाते हैं और उन कामों के लिए उत्तरदायित्व भी मंत्रिया का ही होता है। सविधान ने सम्राट के कार्यों को स्पष्टतः प्रमाणित करके उसके लिये किसी प्रकार के अधिकारों की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। डायट के अधिवेशन को आमन्त्रित करने तक का सम्राट का अधिकार व्यावहारिक दृष्टि से औपचारिक ही है क्योंकि सविधान की धारा 52 के अनुसार प्रतिवर्ष डायट का एक अधिवेशन आमन्त्रित करना अनिवार्य है। अतः सम्राट इच्छानुसार डायट को निलम्बित नहीं कर सकता, उसे वर्ष में कम से कम एक बार तो डायट को निश्चित रूप से आमन्त्रित करना ही पड़ेगा। फिर इसमें भी वह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता क्योंकि डायट का अधिवेशन प्रधानमन्त्री के कहने पर अवश्य ही आमन्त्रित करना होगा। यही बात प्रतिनिधि सदन के विघटन के सम्बन्ध में लागू होती है। यद्यपि सविधान में उल्लिखित है कि सम्राट प्रतिनिधि सदन को विघटित करेगा परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह अपनी इच्छा से कभी भी ऐसा कार्य विघटित कर सकेगा। वास्तव में इस कार्य के सम्पादन में भी सम्राट मंत्रि मण्डल के परामर्श पर ही निर्भर रहेगा और जब मंत्रि मण्डल उपाय करेगा तभी वह सदन को विघटित कर सकेगा अन्यथा नहीं।

सम्राट सर्वाधिक सम्मानित, नतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति—जापान सविधान में भी सम्राट जापान का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। सम्राट अत्यन्त प्राचीन काल से राष्ट्र के इतिहास, उसका संस्कृति और धर्म की एकता का प्रतीक समझा जाता रहा है तथा सामान्य सविधान की भाँति और जनता की एकता का प्रतीक होने का पापमान करता है। जापान-वासी अपने सम्राट का सम्मान मंत्रि राजा द्वारा उनका आग्रह या सम्राट के प्रति किये जाने वाले सम्मान में अधिक ही करते हैं। जापानियों का अर्थ सम्राट के साथ ऐसी नायुकता का सम्बन्ध है जिसमें वे उसे ही मानते हैं।

जापान के इतिहास में सम्राट की भूमिका और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में सदैव ही उच्चतम रही है और वे ही हैं। नवम्बर 1906 पर वाद विवाद बरत हुए प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, जापानियों की सम्राट के दृष्टि में ही सम्राट के सम्मान के लिए और उनकी यह मानना कि सम्राट ही हैं और नतिक है। जापानियों के दृष्टि में ही सम्राट ही हैं किंचित मात्र भाव प्रकटित करने के लिए सम्राट को रखता है या नहीं।

जापानी सम्राट की ब्रिटिश सम्राट से तुलना

ब्रिटन और जापान दोनों ही देशों में वधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश राजा और जापानी सम्राट दोनों ही अपने अपने राज्या के नाम-मात्र के अधिपति हैं। दोनों को ही व्यवहार में शासन सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। पर यह साम्य होते हुए भी पदशक्तियों में ब्रिटिश राजा की स्थिति जापानी सम्राट की अपेक्षा कुछ दृष्टियों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विद्वान सी० एम० ए० गार्डो ने "अब यह पूर्वविद्या अधिक स्पष्ट हो गया है कि जापान का सम्राट राज्य करता है शासन नहीं। ब्रिटन के सम्राट से भी उसकी शक्तियाँ बहुत कम हैं। ब्रिटन का सम्राट अब भी शासन के कार्यों में भाग लेता है। ब्रिटेन के सम्राट का अधिकार है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसमें परामर्श ले। वह कुछ कार्यों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा कुछ के विरुद्ध सावधान कर सकता है। जापान के सम्राट को इस प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दोनों की शक्तियों का अंतर कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है—

सबसे प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लिया जा सकता है। यह ठीक है कि राजा और सम्राट दोनों को ही इस विषय में व्यक्तिगत रीति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है। ब्रिटिश राजा को उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जापानी सम्राट का भी उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है जिसका चुनाव डाइट ने कर लिया है लेकिन इतनी समझौता होना ही इस विषय में ब्रिटिश राजा को कमी-जमा अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करने का अवसर मिल जाता है जबकि जापानी सम्राट को इस प्रकार के अवसर का प्राप्त होना सम्भव नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ब्रिटिश राजा का प्रधानमंत्री की छान्द क सामित अधिकार और विवेक प्रयोग के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन जापान का सम्राट किसी भी परिस्थिति में दलीय नेता को केबिनेट निर्माण के लिए आमन्त्रित नहीं कर सकता। जापान में प्रधानमंत्री की छान्द शक्ति द्वारा की जाती है और सम्राट का केवल उसकी नियुक्ति को औपचारिक रस्म पूरी करनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कुछ अभिसमया (Conventions) के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश राजा को यह परमाधिकार (Prerogative) प्राप्त है कि वह हाउस आफ कॉमन्स के विघटन के लिए दिये गये परामर्श को अस्वीकार कर दे, किन्तु जापान का सम्राट डाइट का विघटन करने से इन्कार नहीं कर सकता।

पुनश्च जापान का सम्राट राजनीति प्रदान पर सावजनिक रूप से मत प्रकट नहीं कर सकता। महत्त्वपूर्ण निर्णयों के करण में अपने प्रभाव का

प्रयोग भी नहीं कर सकती। इसके विरोध ब्रिटन के सम्राट को मंत्रिग को नेताओं व परामर्श दल का अधिकार प्राप्त है चाहे व उन्हें मानने के लिए बाध्य न हो। साथ ही ऐसे भी घनेक अवसर आए हैं जब ब्रिटिश सम्राट अपनी राजनतिक सूझ-बूझ, निष्पक्षता एवं प्रभाव के कारण राजनतिक महत्वपूर्ण निणयों को एक सीमा तक प्रभावित कर पाया है।

परन्तु उपर्युक्त विवरण से यह नहीं समझना चाहिये कि वर्तमान राजधानिक व्यवस्था ही जाने से जापान के सम्राट का महत्व बिलकुल समाप्त हो गया है। शासन के क्षेत्र में चाहे उसका प्रभाव सुप्त प्राय हो चुका है, उसका नतिक प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है। मनागा के मतानुसार "सम्राट की शान्तिव शक्तियों के लोप के कारण उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं हुई है। जहाँ तक जनता के सम्राट के प्रति रुचि का सम्बन्ध है, आजकल भी कम से कम चिन्ह के रूप में सम्राट को ही राजा माना जा सकता है। सम्राट आज भी राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय एकता का द्योतक है।"

सदस्यों को प्रधिकाश डायट के सदस्यों में से लिया जाए। इस व्यवस्था से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि जापानी कैबिनेट में भ्रष्ट मंत्री डायट के बाहर भी लिये जा सकते हैं और इस प्रकार मंत्रियों के दो वर्ग हो सकते हैं—एक वह जो डायट का सदस्य हो और दूसरा वह जो डायट का सदस्य न हो। लेकिन व्यावहारिक रूप यही है कि जापान में लगभग सभी मंत्रियों को डायट में ही लिया जाता है, डायट के बाहर के व्यक्ति मंत्री बहाने कम बनते हैं। चूंकि उनकी सराया कैबिनेट में नगण्य होती है, अतः कैबिनेट व्यवस्था की विशेषता का महत्वपूर्ण रूप से छण्डन नहीं होता।

कायपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व—व्यवस्थापिका के प्रति कायपालिका के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त वेबिनेट पद्धति का प्राण तत्व है। जापानी संविधान की धारा 66 में स्पष्टतः कहा गया है कि अपने सभी कार्यों के लिए कैबिनेट डायट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। धारा 69 व्यवस्था करती है कि प्रतिनिधि सदन का विश्वास खो देने पर सम्पूर्ण कैबिनेट को त्याग पत्र देना पड़ेगा यदि 10 दिन के भीतर प्रतिनिधि सदन का विघटन न कर दिया जाय।

वस्तुतः डायट को वेबिनेट के उत्तर नियंत्रण करने का बसा ही अधिकार प्राप्त है जसा संसदीय प्रणाली के देशों में व्यवस्थापिका को कायपालिकाओं पर प्राप्त होता है। डायट अपने उपायों से कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है। डायट के सदस्य मंत्रियों से नीति-विषयक प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर मंत्रियों को देना पड़ता है। यद्यपि मंत्री उत्तर देने के लिए सदैव बाध्य नहीं होते, तथापि सदस्यों के प्रश्न का भय उनकी स्वेच्छाचारिता पर प्रकुश लगाने रहता है। डायट के सदस्य प्रश्न के अतिरिक्त मंत्रियों की प्रालोचना भी करते हैं।

राजनीतिक सजातीयता—जापानी संविधान भी सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था करता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व को मजबूत बनाने के लिए और मंत्रियों के इष्टिबोध में एकता बनाये रखने के लिए जापान में भी ब्रिटेन की ही भांति दल प्रथा का विकास हुआ है। राजनीतिक दलों का सरकार के निर्माण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और मंत्रियों की नियुक्ति बहुत कुछ दलों के सदस्यों पर ही निर्भर करती है। डायट के वे सदस्य जो मंत्री बनाये जाते हैं, प्रायः एक ही राजनीतिक विचारधारा के होते हैं और इसीलिए वे एक-इकाई के रूप में कार्य करते हैं। डायट के बाहर के व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाने वाले मंत्री इस बात के प्रपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मंत्रियों की संख्या सामान्यतः नगण्य अथवा शून्य ही रहती है।

संगठन-कार्य प्रणाली, अधिकार एवं कर्तव्य

(The Composition, Working, Powers
& Functions of the Cabinet)

आकार एवं रचना

कैबिनेट के आकार ग्रथवा मंत्रियों की संख्या एवं धींगिया क बारे म संविधान म विस्तार से वर्णन ना किया गया है । संविधान की धारा 66 म केवल यह व्यवस्था दी गई है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होगा । उसके प्रतिरिक्त कैबिनेट म कानून द्वारा वा गई व्यवस्था के अनुसार राज्य के प्रत्येक मंत्री होंगे । इसी धारा के अनुसार यह व्यवस्था भी है कि प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों का मननित होना आवश्यक है । संविधान की धारा 67 के अनुसार प्रधानमंत्री का नाम, डायट के सदस्य म से डायट के संकल्प (Resolution) द्वारा तयार किया जाता है । प्रधानमंत्री की छान् क प्रश्न पर डायट के दोनों सदन के मध्य मतभेद होने का मूरत म दाना मदन की संयुक्त समिति प्रयत्न करती है । यदि संयुक्त समिति क प्रयत्न से भी सहमति प्राप्त न हो मके अथवा प्रतिनिधि सदन द्वारा नाम तय कर जेन पर ना विमामकाल का डायट 10 दिन के मध्य कंसिलर सन्न नाम तय न कर सक तो संविधान की धारा 67 के अनुसार प्रतिनिधि-सदन के निणय को ही डायट का निणय समक लिया जायगा । डायट द्वारा प्रधानमंत्री का नाम तय हो जाने पर उसका औपचारिक नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है । इस धारा से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के नामांकन के विषय म सभासद सदन (House of the Councillors) की शक्तिवा प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) की तुलना म कम है ।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है । संविधान की धारा 68 के अनुसार अधिकांश मंत्री राष्ट्रीय डायट के सदस्य होने चाहिए । मंत्रियों को अपने पद से हटाने का अधिकार प्रधानमंत्री की है ।

अवधि

जापान की कैबिनेट की भी कोई निश्चित अवधि नहीं है । वह डायट के निम्न सदन अर्थात् प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थन तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है । यदि निम्न सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पार कर देता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव का अस्वीकार कर देता है तो कैबिनेट को दस दिन के भीतर या तो स्वयं को त्यागपत्र दे देना चाहिये अथवा प्रतिनिधि सदन का भंग कर देना चाहिये एवं दस म द्वारा निर्वाचन कराने चाहिये । जब कैबिनेट का त्यागपत्र देना होता है तो वह दोनों सदन के अध्यक्षों का दस बात की लिखित सूचना देती है । यह सूचना प्राप्त होने पर डायट नये प्रधानमंत्री का छान् का कार्य आरम्भ कर देती है ।

संगठन एवं कार्यप्रणाली

केबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सरकार का केन्द्रीय कार्यालय होता है। इस कार्यालय का मुख्य सचिव केबिनेट सचिवालय का निदेशक (Director of Cabinet Secretariat) होता है। इसकी सहायता के लिये उप निदेशक (Deputy Directors) होते हैं। सचिवालय केबिनेट की सभाया का कार्यक्रम तयार करता है, आवश्यक पत्र तयार करता है एवं अन्य मामला का प्रबन्ध करता है। सचिवालय के अलावा एक विधि निर्माण ब्यूरो (Bureau of the Legislation) भी होता है। इसका निदेशक विधि निर्माण के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री एवं केबिनेट का कानूनी परामर्श देता है। मनक बाड और कमिशन इन ब्यूरो के सहायक अङ्ग होते हैं।

केबिनेट की बैठके साधारणतया सप्ताह में दो बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सरकारी भवन में होती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री सम्भापित्व करता है।

केबिनेट की सभा के लिये कोई गणपूर्ति (Quorum) निश्चित नहीं है। यदि बहुमत से कोई निर्णय लिया जाता है तो अनुपस्थित सदस्या के हस्ताक्षर बाद में कराये जा सकते हैं। केबिनेट के वाद विज्ञापन गोपनीय होने हैं और कायबाही प्रकाशित नहीं की जाती।

केबिनेट मंत्रियों के अधीन उपमंत्री भी होते हैं। ये स्थायी सरकारी अधिकारी (Career Officials) होते हैं। इनका महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इनकी बैठका में हुए निर्णय का केबिनेट की स्वीकृति पर ही लागू किया जा सकता है।

सी यनागा के मतानुसार केबिनेट के कार्य दो प्रकार के होते हैं— (1) केबिनेट निर्णय (Cabinet decisions), एवं (2) केबिनेट समझौते (Cabinet Understanding)। महत्त्वपूर्व प्रश्न एवं संवैधानिक तथा कानूनी मामला पर केबिनेट निर्णय करती है। अन्य साधारण मामला पर केबिनेट के सदस्या में आपसी समझौते होते हैं।

अधिकार एवं कार्य

सविधान की धारा 65 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति केबिनेट में निहित की गई है। जापानी केबिनेट की सविधान से वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, जसा कि व्यवहार में गिटन में है। केबिनेट के सभी नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय एकरूप होत हैं और यदि विमा मंत्री का ऐसा कोई निर्णय स्वीकार न हो तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। केबिनेट के कार्यों की स्थापन निम्नवत् रखा जा सकता है—

प्रशासनिक अधिकार—संविधान के अनुसार देश की सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ कैबिनेट में निहित हैं। वही इनका व्यावहारिक रूप में प्रयोग करता है। कैबिनेट की प्रशासनिक शक्तियों को हम संक्षेप में निम्नवत् गिना सकते हैं—

(1) कैबिनेट राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करती है तथा सब-सम्मति से निर्णय लेती है। नाति निर्धारण के सम्बन्ध में उनके अधिकार अतिम तथा पूर्ण हैं।

(2) अपने द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियावित्त करने तथा उन्हें अभिव्यक्त करने वाले कानूनों को लागू करने का काम कैबिनेट का ही है।

(3) कैबिनेट लोक-सेवका (Civil Servants) पर नियन्त्रण रखती है। उसे स्थायी तथा विशेष वर्गों की लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त है। कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वह सरकारी अधिकारियों का पदच्युत कर सकती है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है।

(4) राज्य के उच्च लोक पेश्वों और राजनीतिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का भी अधिकार उसे ही प्राप्त है।

(5) विदेश-नीति का निर्धारण और संचालन करने का उत्तरदायित्व कैबिनेट का ही है। विदेशों से संधि करने का उसे अधिकार है, किन्तु उन पर डायट की स्वीकृति लनी पड़ती है। यह स्वीकृति संधि करने से पहिले या बाद में ला जा सकती है।

(6) शासन के विभिन्न विभागों का मागदर्शन करने और उनके कार्यों में समय लाने का मुख्य कार्य कैबिनेट ही पूरा करती है।

विधायी अधिकार—कानून निर्माण में प्रत्यक्ष सम्पन्न हान पर भी इस क्षेत्र में कैबिनेट का भूमिका बड़े महत्व की है। समन्वय व्यवस्था के अनुरूप जापानी कैबिनेट भी विधायी क्षेत्र में व्यवस्थापिका को समूह प्रदान करती है। आवश्यक विधेयकों का तयार करने, डायट के समक्ष रखने और अपने बहुमत के बल पर उन्हें डायट से स्वीकृत करा लेने का सम्पूर्ण कार्य कैबिनेट का ही है। उसे मन्त्रि मण्डलीय आदेश (Cabinet orders) भी जारी करने का अधिकार है। इस माध्यम का प्रभाव संसदीय कानूना जैसा ही होता है। डायट को वडा बुलान, निम्न सदन को विघटित करने के लिए सम्राट को परामर्श देना, ग्राम चुनावों को घोषणा करना तथा संविधान में संशोधन लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने आदि के दायित्वा का निर्वाह भी कैबिनेट ही करती है। एक उत्पत्तिय तथ्य यह है कि जापानी कार्यपालिका को विधायक के सम्बन्ध में विधायी अधिकार (Veto) का तथा अध्यादेश (Ordinances) निष्पादने का अधिकार नहीं है।

वित्तीय अधिकार—सविधान की धारा 83 ने राष्ट्रीय वित्त के प्रशासन का उत्तरदायित्व डायट पर डाला है, लेकिन व्यवहार में केबिनेट ही इस उत्तरदायित्व का अधिकांशतः निवाह करती है। बजट तैयार करने और उसे डायट के सामने रखने का काम केबिनेट का ही है। केबिनेट द्वारा तैयार किये गये बजट में डायट प्रायः नाममात्र ही हेर फेर करती है। आकस्मिक परिस्थिति में डायट द्वारा सुरक्षित धनराशि के व्यय का उत्तरदायित्व केबिनेट पर ही है, यद्यपि धन खच करने के बाद उसे अविलम्ब डायट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। राज्य के सभी प्रकार के व्ययों और राजस्वों की जो वार्षिक रिपोर्ट आडिट बोर्ड प्रस्तुत करता है उस डायट के सामने पेश करने का काम केबिनेट का ही है। सविधान द्वारा केबिनेट पर ही यह भार डाला गया है कि यह नियत अवधि पर कम से कम वर्ष में एक बार राष्ट्रीय वित्त के बारे में डायट और जनता के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आमिक्त अधिकार—सविधान ने केबिनेट को सामान्य क्षमादान (General Amnesty), विशिष्ट क्षमादान (Special Amnesty), दण्ड को कम करने मृत्यु-दण्ड को अल्पकाल के लिए स्थगित करने तथा अधिकारों को पुनः प्रदान करने आदि के प्रश्नों पर विचार देने का अधिकार दिया है। इस सम्बन्ध में केबिनेट द्वारा किये गये कार्यों को सम्राट प्रमाणित करता है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण अधिकारों के अलावा केबिनेट को प्रतिनिधि मदन को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रतिनिधि-मदन को भंग करके वह हाउस ऑफ कौंसिलर्स (House of Councillors) या मण्डलाधीन अधिवेशन बुला सकती है। मारगट, वर्तमान जापानी शासन-व्यवस्था का केबिनेट प्रमुख अंग है और उसी के हाथ में व्यवहार में शासन की समस्त सत्ता है यद्यपि वह डायट के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी है। यदि निम्न मदन में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

प्रधानमंत्री

(The Prime Minister)

नियुक्ति एवं योग्यता

संविधानिक व्यवस्था के अनुसार सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डायट ने होता सदन सदन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा अथवा राज के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

विधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए दो योग्यताएँ निर्दिष्ट की गई हैं—

(क) उस डायट का सदस्य होना चाहिए, एवं

(ख) उस धर्माली (Civilian) होना चाहिए।

संविधान के प्रधानमंत्री डायट के विषयों में मदन का अध्यक्ष हो सकता है परन्तु वह उसे मनोनाम करने में प्रतिनिधि मदन का अधिकार सम्भालता है।

की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, अतः यह आशा रहती है कि प्रतिनिधि मदन के सदस्य के प्रधानमन्त्री बनने की सम्भावनाये ही अधिक हानी।

स्थिति एवं शक्तियाँ

संविधान की धारा 65 के अनुसार राज्य की अधिशासी शक्ति कैबिनेट में निहित है और कैबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में राज्य अधिशासी शक्ति पर यथिम अधिकार प्रधानमन्त्री का ही प्राप्त है। डायट में बहुमत दल और जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण उसे राष्ट्र का सर्वोच्च राजनीतिक निकाय प्राप्त होता है। अतः नेतृत्व के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से डायट के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है।

प्रधानमन्त्री की स्थिति और शक्तियों को हम निम्नानुसार वर्णन कर सका है—

मन्त्री मण्डल के निर्माण, जीवन और मरण का केन्द्रस्थल—मन्त्री मण्डल में प्रधानमन्त्री की स्थिति सर्वोच्च होती है। वहाँ मंत्रियों को नियुक्त करता है और उनमें से एक को उप-प्रधानमन्त्री बनाना है। मंत्रियों को विभागों के विवरण में उसका नियुक्ति अतिम होता है। वही मंत्रियों को कदम बढ़ाकर उन्हें ज्योत्सना प्रदान करता है। वह अपनी इच्छानुसार मन्त्री मण्डल में उनको फेर कर सकता है। मन्त्रीमण्डल की समस्त कार्यवाहियों का वह केन्द्र होता है। यह देखता है कि सब विभाग ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। मन्त्री मण्डलीय बैठक या सभापतित्व करने निरीक्षण करने और कार्यवाहियों का संचालन करने का अधिकार उसी का है। मन्त्री मण्डल में नियुक्ति और तानि निर्धारण में उसका सर्वोपरि हाथ रहता है। मंत्रियों के कार्यों में वह सामञ्जस्य स्थापित करता है। कोई भी प्रशासनिक विभाग का मन्त्री मिले ही कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। किसी राज्य मन्त्री द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है उस पर मन्त्री के हस्ताक्षर होने के साथ-साथ प्रधानमन्त्री के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। दूसरे दृष्टि में मन्त्री मण्डल का कोई भी नियुक्ति भी मान्य समझा जाता है जब तक कि प्रधानमन्त्री के हस्ताक्षर ही जाय।

मन्त्री मण्डल की सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमन्त्री ही करता है। मन्त्री मण्डल की ओर से डायट के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले सभी पत्र आदि उसी के द्वारा पत्र किये जाते हैं।

मंत्रियों की पदचुनौ करने या भी प्रधानमन्त्री का अधिकार है। संविधान की धारा 68 स्पष्टतः उल्लेख करता है कि प्रधानमन्त्री मन्त्री नियुक्ति द्वारा राज्य के मंत्रियों का नियुक्ति कर सकता है। सभी मंत्रियों का नियुक्ति उक्त मान्य बना हुआ है। उसके त्यागपत्र का प्राप्त पूरा मन्त्री मण्डल द्वारा जाना है। यदि कोई मन्त्री उसका पद पर त्यागपत्र नहीं देता तो वह समझा जाता है कि वह मन्त्री का पदचुनौ कर सकता है मन्त्री द्वारा

5

डायट (संसद) (DIET)

जापान की संसद को मंत्रिजी भाषा में डायट (Diet) और जापानी भाषा में कोक्काई (Kokkai) कहते हैं। यह घर पश्चिमी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और अनुभवी व्यवस्थापिका है। इसकी स्थापना सन् 1889 में मेइजी संविधान के अंतर्गत की गई थी। संसद के दो सदन थे—प्रथम प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) और द्वितीय अभिजात सदन (House of Councillors)। प्रतिनिधि सदन का निर्वाचन सुविधा की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों से होता था पर प्रत्येक सदस्य सारे राज्य की ओर से वोलता था। मतदाता केवल पुरुषों को प्राप्त थे। इसकी अवधि चार वर्ष थी पर यह सदन इससे पहले भी विघटित किया जा सकता था। अभिजात सदन एक स्थायी सदन था जिसमें केवल अभिजात वर्ग के ही व्यक्ति होते थे। यह 'युद्ध पूर्व की साम्राज्यीय संसद मूल रूप से एक मंत्रणा निकाय थी जिसने कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न किया, परन्तु वह बहुधा असफल हुआ।' यह संसद अपने असीमित अधिकारों और सामन्तवादी अभिजात सदन के साथ सन् 1940 तक सफलतापूर्वक कार्य करती रही, पर उस वर्ष राजनैतिक दलों के अवधि घोषित हो जाने से संसदीय प्रणाली का अन्त हो गया और सैनिक नरता देश के वास्तविक शासक बन गये।

द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान का जो वर्तमान संविधान बना उसमें भी संसद का द्विसदनात्मक रूप बने रहने दिया गया है, लेकिन शक्तियों व संगठन की दृष्टि में यह रूप पूर्ववर्ती रूप से बहुत भिन्न रहा गया है। इनके अनुसार नई राष्ट्रीय डायट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। संविधान की धारा 41 में कहा गया है कि "डायट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी और राज्य का एक मात्र विधि-निर्माण करने वाला अंग होगा।"

रचना

राष्ट्रीय डायट के दो सदन हैं—

1 प्रतिनिधि सदन (House of Representatives)

2 सभासद सदन (House of Councillors)

सविधान की धारा 43 के अनुसार दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को सत्या कानून द्वारा निश्चित की गई है।

प्रतिनिधि सदन जापान की सदन का निम्न सदन है। इसमें 467 सदस्य हैं। पर यह सत्या सविधान द्वारा निश्चित नहीं है। इस सस्रीय कानून द्वारा निश्चित किया गया है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए सारा देश 118 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। निर्वाचन क्षेत्र किसी प्रशासकीय सीमा पर आधारित नहीं है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से पांच सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं किन्तु प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य सीमित रूप में सवा दो लाख व्यक्तियों की जनसंख्या पर निर्वाचित किया जाता है।

प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है। 4 वर्ष की अवधि के उपरांत नवीन सदन के लिए देश में चुनाव होना अनिवार्य है। जब प्रतिनिधि सदन की अवधि पूरा हो जाती है तो उसको भंग करने की घोषणा सम्राट द्वारा की जाती है और सम्राट द्वारा ही नवीन सदन के निर्वाचन के लिए आदेश प्रसारित होते हैं। उनके आदेश के प्रसारित होने के कुछ काल बाद नवीन चुनाव होने हैं। प्रतिनिधि सदन की अवधि से पूर्व भी कैबिनेट के परामर्श पर सम्राट द्वारा विधित किया जा सकता है।

जापान के उच्च सदन का नाम सभासद सदन है। इसकी व्यवस्था नवीन सविधान के प्राचीन अभिजात सदन के स्थान पर की गई है। सभासद सदन का निर्वाचन भी सावर्भौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक जापानी स्त्री-पुरुष जिसकी आयु 20 वर्ष की है निर्वाचन में मतदान का अधिकारी है। इस सदन के 250 सदस्यों में से 100 सदस्य तो राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (National Constituencies) से चुने जाते हैं और शेष सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (Prefectural Constituencies) में निर्वाचित होते हैं। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् प्रीफेक्चर को 2 से 8 तक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रत्येक निर्वाचक दो मत प्रदान करता है— एक प्रीफेक्चर सदस्य के लिए और दूसरा राष्ट्रीय सदस्य के लिए। सभासद सदन का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। आधे सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव होता रहता है। यह स्थाई सदन है, जिस भंग नहीं किया जा सकता।

सदस्यों की योग्यताएँ

डायट के सदस्यों की योग्यताएँ कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं—

1) प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन के सदस्यों की आयु क्रमशः कम से कम 25 और 30 वर्ष होनी चाहिए, (2) डायट के सदस्य केवल जापान के जन्मजात सदस्य ही हो सकते हैं।

जापान में कोई भी सदस्य देश के किसी भी निवाचन क्षेत्र में खड़ा हो सकता है और उसके लिए आय योग्यताएँ वही हैं जो मतदाताओं के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह (i) जापानी सरकार में किसी लाभ के पद पर हो, (ii) न्यायालय द्वारा पागल करार दिया गया हो, (iii) दिवालिया हो (iv) जापान का नागरिक न हो अथवा (v) डायट के किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य सिद्ध हो गया हो।

वेतन और विशेषाधिकार

डायट के साधारण सदस्यों को 78 हजार येन मासिक वेतन मिलता है। सदस्यों को सत्र के दिनों में प्रतिदिन भत्ता दिये जाने और पत्र व्यवहार आदि के लिए खर्चा देने की व्यवस्था है। निजी सचिव और कार्यालय रखने के लिए भी उन्हें कुछ खर्चा दिया जाता है। रेल के पास और रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है।

डायट के सदस्यों को सम्भवतः अन्य किसी भी देश के विधायी सदस्यों से अधिक सम्मान दिया जाता है। जापान में उन्हें 'सावजनिक अधिकारी' कहा जाता है। सदस्यों को डायट में भाषण का पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सदन में दिये गये भाषण और मतदान के लिए उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सत्र के दौरान उन्हें दण्डनीय अपराधों के सिवाय अन्य मामलों के सम्बन्ध में बन्दी नहीं बनाया जा सकता। डायट में किये गये अवाचित आचरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

कामविधि

डायट के तीन प्रकार के अधिवेशन होते हैं—माधारण, अमाधारण और विशेष। सम्राट के आदेश द्वारा डायट के सत्र की तारीख घोषित की जाती है। साधारण सत्र प्रतिवर्ष साधारणतया दिसम्बर में बुलाया जाता है जो लगभग 150 दिन तक चल सकता है। माधारण सत्र के साथ-साथ विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। जब प्रतिनिधि सदन का आम चुनाव और वास्तविक सदन का नियमित चुनाव होता है तो जिस तारीख से दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा उसके 30 दिन के भीतर डायट का विशेष सत्र बुलाया जायगा। इसके अलावा किसी भी सदन के कम से कम

चीथार्ड सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की कैबिनेट को लिखित प्रार्थना करके असाधारण सत्र की मांग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए ऐसा सत्र बुलाना आवश्यक है। सरकार जब भी आवश्यक हो तभी महत्वपूर्ण अथवा आपातकालीन मामलों पर विचार करने के लिए असाधारण सत्र बुला सकती है। कोसिलर मदन का असाधारण सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री को अध्यक्ष से प्रार्थना करनी पड़ती है। इस प्रार्थना में एकत्र होने की तारीख तथा विचारणीय विषयों का संकेत भी होता है।

सम्राट के आदेश में दी गई तारीख पर डायट के सदस्य अपने अपने सदन में एकत्र होते हैं। पहले ही दिन प्रत्येक सदन को स्थान रिक्त होने की हालत में, अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है। चुनाव न होने तक सैक्रेटरी जनरल अध्यक्ष का कार्य करता है। प्रत्येक सत्र के आरम्भ में डायट का उद्घाटन समारोह होता है और हम अवसर पर सम्राट स्वयं उपस्थित होकर अपना छोटा सा संबोधन पढ़ता है। संविधान की धारा 56 में गणपूर्ति के विषय में कहा गया है कि किसी भी सदन में उस समय तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकेगी जब तक उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों। प्रत्येक सदन में सब मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत व समान से ही हो सकता है। यदि किसी स्थान पर संविधान कोई और व्यवस्था कर दे तो यह नियम लागू नहीं होंगे। यदि किसी विषय पर समान मत प्राप्त होते हैं तो सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

पदाधिकारी

प्रत्येक सदन के जो अधिकारी होते हैं उनमें प्रमुख ये हैं—अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चीथार्ड अध्यक्ष (President Protomptore), चीथार्ड समितियाँ के सभापति तथा सैक्रेटरी जनरल। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर और सभासद सदन के अध्यक्ष को प्रसीडेन्ट कहा जाता है।

सदनों की प्रथम बैठक होने पर सदस्यों द्वारा अपने-अपने में से अध्यक्षों का चुनाव करना होता है। सभासद सदन के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा और प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष का चुनाव सदन के निर्णय के अनुसार गुप्त या हस्ताक्षरित मतपत्र द्वारा होता है। इसके उपरान्त इसी रीति से उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव के समय पूर्व अध्यक्ष सदन का सभापतित्व करते हैं। पूर्व अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूर्व उपाध्यक्ष और उनकी भी अनुपस्थिति में सैक्रेटरी जनरल सभापति या सभासद ग्रहण करते हैं। सैक्रेटरी जनरल या महा-सचिव भी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

अध्यक्षों के अधिकार और उनकी स्थिति

अध्यक्षों को अपने अपने सदन में अपने अधिकार प्राप्त हैं। वे सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनके बाहर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अध्यक्ष अपने सदन की सदन व्यवस्थापिका समिति (House of Management) के परामर्श से अपने सदन की समितियों के सदस्यों को मनोनीत करते हैं और एक सदस्य को एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरित कर सकते हैं। सदन के निर्देश से वह समितियों के अध्यक्षों को भी मनोनीत कर सकते हैं और समितियों के अध्यक्ष प्रायः सदन के अध्यक्षों द्वारा ही मनोनीत किये जाते हैं।

सदन का अध्यक्ष ही सदन के सदस्यों के स्थान नियत करता है। वही सदन का कार्यक्रम निर्धारित करता है विधेयकों को विषयानुसार समितियों के हवाले करता है, प्रश्नों तथा वाद विवादों के लिए समय निर्धारित करता है और उसी के निश्चय पर वाद विवाद का अन्त होता है। सदन में शांति और सुव्यवस्था रखता है मंत्रियों का सदन में सहायता देने के लिए सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पर स्वाकृति देता है, सदन की बैठक न होने के समय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जान पर उस में दूर करता है और किसी विधेयक या प्रस्ताव पर समान मत आने पर अपना निर्णायक मत देता है। वही यह निश्चय करता है कि किसी विषय पर सदन का मत ध्वनि-मत से सदस्यों को खड़ा करके, हस्ताक्षरित मतपत्र या गुप्त मतदान—किस पद्धति से लिया जाए और सदस्यों का तदर्थ आना देता है।

सदन का अध्यक्ष सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। सदन की पुलिस अध्यक्ष के अधीन होती है और आवश्यकता पड़ने पर वह किसी सदस्य को गिरफ्तार भी कर सकती है। वह सदन से प्रायः अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही हेतु सदन व्यवस्थापिका समिति के पास भेज सकता है। अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों के नाम भी वह समिति के पास भेज सकता है और समिति की प्रार्थना पर किसी सदस्य को सदन से निष्कासित भी कर सकता है, पर ऐसा प्रस्ताव सदन के दाहिनाई बहुमत से पास होना आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो जाता है तो उसे स्थान देना पड़ता है। अध्यक्ष सदन की बैठकों को स्थगित भी कर सकता है। सदन की कार्यवाही का विवरण अध्यक्ष की देखरेख में तैयार और प्रकाशित किया जाता है और वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। वह समिति के अध्यक्ष की प्रार्थना पर किसी विधेयक पर सावजनिक मुनबाई की अनुमति भी दे सकता है। जब किसी विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जान के लिए तैयार होता है तो अध्यक्ष व्यवस्थापिका समिति के परामर्श से उसे सदन के वाचनालय में सम्मिलित करता है। अध्यक्ष

हो विभिन्न समितियों के मध्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों का निर्णय करता है। वह सदन के अधिवेशन के समय किसी समिति को बँटक करने का प्रादेश दे सकता है।

दोनों सदनों के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के साथ परामर्श करके सम्राट द्वारा मसद के औपचारिक उद्घाटन का दिन व समय निश्चित करते हैं। यह उद्घाटन सभासद सदन में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में होता है। संयुक्त बैठक का स्पीकर वही होता है जो प्रारम्भिक भाषण देता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में यह कार्य प्रेसिडेंट करता है।

जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की सदन में स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और ब्रिटेन की लोकसभा के अध्यक्षों की स्थिति के मध्य में है। जापान का स्पीकर दलगत आधार पर चुना जाता है। वह 'गामब' दल या दलों का प्रधानमन्त्री के पास सबसे शक्तिशाली नेता होता है। उसका वेतन प्रधानमन्त्री के वेतन के बराबर होता है। निर्वाचन के बाद प्रायः वह अपनी दलीय सदस्यता का त्याग नहीं करता। दल का बहुमत न रहने पर उसने स्थान पर दूसरा व्यक्ति स्पीकर चुना जाता है। फिर भी वह यथासम्भव निष्ठापूर्वक ससदीय नियमों को लागू करने का और सभी सदस्यों के साथ उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। मन्त्रिपरिषद् का स्वयं एक ससदीय समिति और प्रधानमन्त्री का प्रतिनिधि सदन के नेता होने के कारण सदन की कार्यवाही पर उनका इतना प्रभाव नहीं होना जितना संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पीकर का होता है और दलीय सम्बन्ध के कारण उसका उतना सम्मान भी नहीं होता जितना ब्रिटिश स्पीकर का होता है। जापानी स्पीकर की स्थिति दोनों के मध्य में है। उसको थोड़ा न्यून भी होता है और थोड़ा सम्मान भी, लेकिन उसकी स्थिति कुल मिलाकर भारतीय स्पीकर से अच्छी है।

ससद की समितियाँ

प्रत्येक देशों की ससदीय व्यवस्था के अनुरूप जापानी डायट में भी समितियाँ हैं। अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। मेइजी विधान में भी समितियों का स्थान महत्त्वपूर्ण था किन्तु कार्यक्षमता की दृष्टि से वे बहुत दुर्बल थीं।

वर्तमान व्यवस्था के अधीन चार प्रकार की समितियाँ पाई जाती हैं—
(i) स्थायी समितियाँ, (ii) विशिष्ट समितियाँ, (iii) विधायी समिति एवं (iv) संयुक्त समिति। यह व्यवस्था है कि कोई भी एक सदस्य एक साथ तीन समितियों से अधिक का सदस्य नहीं बनाया जा सकता।

स्थायी समितियाँ (Standing Committees)—डायट के प्रत्येक सदन में 15 स्थायी समितियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में लगभग 20 सदस्य होते हैं। केवल बजट समिति में 50 के आसपास सदस्य

है। समितियाँ में दला की सरया सदन में उनकी शक्ति के अनुपात में होनी है। समितियों के अध्यक्ष पूर्ण सदन द्वारा चुने जाते हैं। विभिन्न समितियों के क्षेत्राधिकार सम्प्रती विवादों का नियुक्त सदन का अध्यक्ष करता है। स्थायी समितियों का मुख्य कार्य विधायी प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना, उनकी आवश्यक जाच-पड़ताल करना, उनमें विभिन्न पक्षों की सुनवाई करना और उनका प्रारूप तैयार करना है। सदन भी विधेयक पर सम्बन्धित समिति का परामर्श लेकर ही प्रायः प्रागे बढ़ता है। अमेरिकन कांग्रेस को समितियों की भाँति जापानी समितियाँ सभी विधेयकों की प्रगति पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। वे ही यह निश्चय करती हैं कि किन विधायी प्रस्तावों को सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय और किन्हीं नहीं?

विशिष्ट समितियाँ (Special Committees)—ये समितियाँ किसी विशेष जाच-पड़ताल के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। स्वभावतः इन्हें विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। समिति के अध्यक्ष का निर्णायक मत प्राप्ति होता है। समिति विभिन्न पक्षों से गवाहियाँ लेकर और सरकारी कागजातों का परीक्षण करके सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

विधायी समिति (Legislative Committee)—डायट के दोनों ही सदनों को एक मिला हुआ विधायी समिति होती है जिसका कार्य दोनों सदनों के आपसी सम्बन्ध, विधि निर्माण के नये तरीक़ों, विधि निर्माण प्रणाली के मरलीकरण और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करना होता है। इसमें दस सदस्य प्रतिनिधि सदन के और आठ सभासद सदन के होते हैं। जहाँ अन्य समितियाँ दलबन्दी के पृथक्कृत होती हैं वहाँ संयुक्त विधायी समिति पर दलबन्दी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इस समिति से यही आशा की जाती है कि वह सदस्य आचरण रखने हुए सदनों की संतुलन में रखेगी।

संयुक्त समिति (Joint Committee)—डायट के दोनों सदनों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त समिति की निर्माण किया जाता है जिसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं। दोनों ही सदनों से बराबर संख्या में सम्मनित होते हैं। गण-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदन के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों। समिति की सम्पत्ति दोनों ही सदनों के सम्मनकारी बारी बारी करते हैं। मतभेद सम्बन्धी समाधान पर पूर्ण सहमति हो जाने पर समिति को रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की जाती है। यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित रिपोर्ट समिति के द्वाँतिहाई बहुमत से स्वीकृत का गई है।

स्पष्ट है कि जापान में समिति-प्रवस्था पर्याप्त सुव्यवस्था और प्रभावी में सम्मनित है। यद्यपि समितियों की बहुतायत है और स्थायी

समितिया भ्रलग-भ्रलग मन्त्रालयो से सम्बन्धित रहने के कारण अपन अपने विभागो की वकील बन जाती है तथापि समितिया ने 'लघु विधान मण्डल' (Little Legislative) का रूप धारण कर लिया है। उहे हम सदन के भ्रात्र, कान ग्रीर मस्तिष्क की सना दे सकते है।

ससद की शक्तिया एव कार्य

(Powers & Functions of the Diet)

सविधान की धारा 41 के अनुसार 'डायट अर्थात् ससद राज्य शक्ति का सर्वोच्च अवयव है' और इस दृष्टि से उसे अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त है जिहे निम्नांकित भागा म बाटा जा सकता है—

विधायी शक्ति

डायट का अत्यन्त महत्वपूर्ण काय विधि निर्माण करना है। जापान मे एकात्मक सविधान है। अत यहाँ सभी प्रकार के कानून डायट बनाती है। डायट के विधि निर्माण का व्यापक क्षेत्र सभी प्रकार के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओ और व्यक्ति के भ्राय सम्पूर्ण जीवन तक फना हुआ है। डायट को प्रतिवष बहुत बडी सख्या म कानून बनाने पडते हैं। अय दशो की व्यवस्थापिकाओ के समान जापान की डायट भी कानून बनाने वाली कस्टो बन गई है।

इस सदन मे यह स्मरणीय है कि जापान म वायपालिका को सिद्धान्त रूप म भी ससद द्वारा पारित किये गये विधेयको पर निपेधाधिकार नही है। फिर भी ससद का प्रमुख काय कानून को योजना बनाना अयवा उसका उपक्रम करना नही है धरन् प्रस्तावो पर विचार करना, उहे सशोधित करना और उहे स्वीकार या अस्वीकार करना है। उनकी योजना बनाना और उपक्रम या पहल करना तो केबिनेट के हाथ म है। ससद का काय मुख्य रूप से निपेधाधिकार का प्रयोग करना है। जापान म विधायी कार्य पर केबिनेट का इतना व्यापक प्रभाव नही है जितना भारत ग्रीर ग्रीटेन म है तथापि डायट का अधिकार न तो असोमित है और न अनय हो। डायट का विधायी अधिकार देश के लिखित सविधान ने अनुकूल होना चाहिये अयथा सर्वोच्च न्यायालय उसे प्रभवधानिक पोषित कर सकता है। सविधान म वर्णित जनता के मूल अधिकार डायट क विधायी धन को सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी एक स्थानीय सत्ता क लिए डायट द्वारा बनाया गया कानून बिना उस क्षेत्र की जनता की स्वीकृति के प्रवत नही चिया जा सकता। डायट का उचित अनय ना नही है, सदन अपन नियम स्वय बनात है। केबिनेट अपनी आचार्य दतो द और सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम बनाता है। इन संस्थाओ ने अधिकार सविधान प्रदत्त है

और सर्वोच्च न्यायालय के नियम ता कहीं कहीं स्पष्ट रूप से मसदीय कानूनों के विपरीत है।

कायपालिका शक्ति

डायट का दूसरा अधिकार कायपालिका सम्बन्धी है। डायट का कायपालिका के काय के विषय में जाच पड़ताल करने का अधिकार है। वह सरकार के भ्रष्टाचार के विषय में एवं सरकारी सम्पत्तियों के काय के विषय में अनेक बार जाच पड़ताल कर चुका है। डायट कायपालिका पर कई रीतियों से नियंत्रण रखनी है। प्रधानमंत्री को डायट द्वारा ही मनोनीत किया जाना है और डायट किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे त्याग पत्र देने को बाध्य कर सकती है। डायट प्रशासन काय की दखल रख और जाच-पड़ताल के लिए आयोग तथा समिति बना नियुक्ति कर सकती है। वह प्रशासनिक अधिकारियों से उनके रिकाइ और रिपोर्टें मांग सकती है तथा साक्षियों को बुला सकती है। संविधान की धारा 72 के अनुसार केबिनेट का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री उसके समक्ष सामान्य राष्ट्रीय मामला और विदेशी सम्बन्धों पर प्रतिवेदन संप्रेषित करना है और दोनों सदनों के सदस्य प्रशासन के किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। अतः मांग पर सात दिन के अंदर उत्तर देना होता है।

वित्तीय शक्ति

डायट का राष्ट्रीय धन व्यवस्था पर भी पूर्ण अधिकार है। संविधान की धारा 83 उपबोधित करती है कि "राष्ट्रीय वित्त को परिचालित करने की शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार डायट निर्वित्त करेगी।" केबिनेट द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उस डायट ही पास करता है। डायट को उस बजट की जाच करने का पूरा अधिकार होता है। सदस्यगण प्रत्येक मद की आलोचना कर सकते हैं। डायट के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर ही आय व्यय हो सकता है। बजट के सम्बन्ध में एक व्याप्त दलील यह बात यह है कि व्यय को सभी मदों डायट के अनुमोदन के लिए रखी जानी आवश्यक है। व्यय की कोई ऐसी मद नहीं है जो डायट के क्षेत्राधिकार के बाहर हो।

सम्राट के परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति वर्तमान संविधान के अनुसार राज्य की सम्पत्ति है। सम्राट के परिवार के लिये सभी प्रकार के व्यय डायट ही स्वीकार करती है। इस सम्बन्ध में संविधान की धारा 8 अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है—'डायट का अनुमोदन प्राप्त किए बिना राज्य परिवार द्वारा न तो कोई सम्पत्ति ग्रहण या जा सकती है और न ही हो जा सकती

है। राज्य परिवार से कोई भेंट आदि भी नहीं दी जा सकती है। स्पष्ट है कि सम्राट और उसके परिवार के सभी व्यय भी डायट के ही अधीन हैं।

घाय और व्यय के अंतिम लेखों की प्रति वर्ष आडिट बोर्ड द्वारा जांच होती है और यह जांच रिपोर्ट कैबिनेट में ही रखी जाती है।

संसद के वित्तीय अधिकार पर एक प्रतिबन्ध है। धारा 89 के अनुसार वित्तीय धार्मिक सस्या के प्रयोग लाभ अथवा पोषण के लिये और ऐसी शिक्षा सम्बन्धी या उदार उद्योगों के लिए जो सावजनिक पदाधिकारों में नहीं है, कोई धन विनियोजित नहीं कर सकती। लेकिन यह प्रबन्ध व्यावहारिक रूप में प्रवृत्त नहीं होता। धार्मिक सस्या को उनके सांस्कृतिक तत्वा को रक्षा के नाम पर आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाती है और व्यक्तिगत विद्यालय विधि लोक कल्याण सेवा विधि तथा शिशु कल्याण सेवा विधि के अन्तर्गत संसद ने सरकार को व्यक्तिगत विद्यालयों और उदार उद्योगों को आर्थिक अनुदान देने की स्वीकृति दी है।

वैदेशिक शक्ति

डायट को देश की वैदेशिक नीति और वैदेशिक सम्बन्धों पर अधिकार है। प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष कैबिनेट की ओर से देश के वैदेशिक सम्बन्धों के बारे में संसद को प्रतिवेदित करता है। यद्यपि संधि करने का अधिकार कैबिनेट को है पर संविधान की धारा 73 (3) के अन्तर्गत कैबिनेट के लिये यह आवश्यक है कि वह संधि के पहले या उसके पश्चात् उस पर संसद का अनुमोदन प्राप्त करे। संसद के अनुमोदन के अभाव में कोई संधि प्रवृत्त नहीं की जा सकती। फिर भी व्यावहारिक रूप में इस धारा का प्रक्षरण पालन नहीं किया जाता। कुछ संधियों को प्रशासकीय समझौते का नाम दे दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें संसद की पूर्व या तदनन्तर स्वीकृति के लिये प्रस्तुत नहीं किया जाता।

न्यायिक शक्ति

डायट को कुछ न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। वह कानून द्वारा संविधान की धाराओं के अन्तर्गत न्यायपालिका का संगठन, न्यायाधीशों द्वारा अथवा कमचारियों का वेतन तथा न्यायालयों की कार्यप्रणाली निर्दिष्ट करता है। डायट द्वारा निर्मित व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय के पूरे प्रक्रिया क्षेत्र को प्राबल्य दिये हुए हैं। पर संविधान की धारा 77 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रक्रिया और प्रवृत्ति, न्यायाधीशों, न्यायालयों के आन्तरिक अनुशासन और न्यायिक विषयों के प्रणामन के लिये नियम बनाने का अधिकार है। डायट कृतव्य को उपेक्षा करने वाले और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पञ्चुत करा सकती है। इस कार्य के

डायट दोनों सदनों को समान संख्या के सदस्यों के एक महाभियोग याचानयनी स्थापना करता है। यह न्यायालय उन न्यायाधीशों पर दोषारोपण समिति द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करता है।

संवैधानिक कार्य

डायट का संविधान के मसौधों के सम्बन्ध में भी कुछ कार्य है। मसौधों के प्रस्ताव डायट में ही पेश किये जाते हैं। किसी भी सदन में ऐसे प्रस्तावों के पारित होने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सदन के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की सम्मति प्राप्त है। जब दोनों सदनों से यह प्रस्ताव इस प्रकार पारित हो जाते हैं तो उनका जनमत मसौह के लिये रखा जाता है। यदि जनमत मसौह में बहुमत का समयन प्राप्त हो जाता है तो वे पास समझे जाते हैं और सम्राट द्वारा संविधान के रूप में घोषित कर दिये जाते हैं।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

डायट का एक महत्वपूर्ण अधिकार अनावेदन सम्बन्धी अधिकार है। सर्वोच्च शासक संस्था के रूप में डायट के दोनों सदनों पृथक्-पृथक् रूप में जनता के विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार करती है और उचित आवेदन पत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कैबिनेट के पास भेज देती है जो उन पर विचार करती है और अपनी कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदन में देती है। जापान में आवेदन प्रथा अत्यधिक लोकप्रिय है।

इसके अतिरिक्त डायट को राज्याभिषेक के उत्तराधिकार विषयक कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त है।

इस विवरण से प्रकट यही होता है कि जापान की संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। राज्य शक्ति का 'सर्वोच्च अवयव' है। लेकिन संविधान शासिनियों का मत है कि यह वरून संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य अवयवों के अधिकारों की दृष्टि से अतिशक्तिपूर्ण है। जब कैबिनेट संसद के अधीन शक्तिशाली मदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकती है बजट पर कार्यपालिका को उपक्रम अधिकार प्राप्त है, मन्त्रिपरिषद् में प्रशासकीय नेतृत्व स्थापित है और न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन करने दिया जा सकता है तो संसद को राज्य का 'सर्वोच्च अवयव' कहना समीचीन नहीं है। इतना ही नहीं व्यावहारिक रूप में भी संसद सर्वोच्च अवयव के रूप में प्रतिष्ठित नहीं पाई जा सकती। कैबिनेट में निहित आन्तरिक दलीय अनुशासन, प्रतिनिधि मदन को भंग करने के अधिकार और कार्यपालिका की वरून विमुक्तता आदि ने समस्त प्रभाव का हास कर दिया है। फिर भी कुछ मिलान यह कहा जा सकता है कि डायट की शक्तिशास्त्रात्मक रूप से विस्तृत और वास्तविक तथा प्रभावी हैं।

डाइट के दोनों सदनों से सम्बन्ध

जापानी संसद डाइट के दोना सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों को हम निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

- 1 साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में
- 2 वित्तीय व्यय विधेयकों के सम्बन्ध में,
- 3 प्रधान मंत्री के निर्वाचन के विषय में
- 4 कैबिनेट के उत्तरदायित्व के विषय में, एवम्
- 5 सर्वप्राणिक संसद के सम्बन्ध में ।

साधारण विधेयकों के विषय में स्थिति यही है कि इन्हें दोना सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उन्हें कानून का रूप तब ही प्राप्त होता है जब उन पर दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जाए । किन्तु इस क्षेत्र में अन्ततः प्रतिनिधि सदन का शक्ति सभासद सदन से अधिक है । यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किसी विधेयक को सभासद सदन स्वीकार नहीं करता अथवा उसमें ऐसा सुशोधन कर देता है जो प्रतिनिधि सदन को स्वीकार न हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता प्रत्युत उस भरेला प्रतिनिधि सदन ही पास कर सकता है बशर्ते कि वह उस दोबारा अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करदे । ऐसे विधेयक पर यदि 60 दिन के अन्दर सभासद सदन अपना निर्णय नहीं भेजता तो प्रतिनिधि सदन विधेयक का उपर्युक्त विधि से अकेल ही पास कर सकती है ।

वित्त विधेयकों के क्षेत्र में तो सभासद सदन की स्थिति और भी कमजोर है । प्रथम तो वित्तीय विधेयक सभासद सदन में प्रस्तुत ही नहीं किये जा सकते वे सदैव प्रतिनिधि सदन में ही आरम्भ किये जाते हैं और वहाँ से पारित होने के बाद ही सभासद सदन के समक्ष विचार के लिये आते हैं । इसमें यदि सभासद सदन प्रतिनिधि सदन के निर्णय से विरुद्ध कोई निर्णय देता है और यदि दोनों सदनों में कानून द्वारा उपबन्धित का हुई संयुक्त समिति द्वारा भी कोई समझौता नहीं हो पाता है अथवा यदि सभासद सदन 30 दिन की अवधि के अन्दर भी उस वित्त विधेयक या बजट पर कोई निर्णय नहीं करता है तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही संसद (डाइट) का निर्णय माना जाता है । इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित दी गई है और द्वितीय सदन का गौण स्थान दिया गया है । इस क्षेत्र में द्वितीय सदन को केवल 30 दिन का विलम्ब करने की ही शक्ति है ।

प्रधान मंत्री के निर्वाचन के विषय में भी सभासद सदन की स्थिति प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा दुर्बल है । यदि प्रधान मंत्री के निर्वाचन पर दोनों सदनों में मतभेद नहीं होता और उन दोनों में संयुक्त समिति के माध्यम से भी कोई समझौता नहीं हो पाता अथवा प्रतिनिधि सदन द्वारा किये

निर्वाचन के बाद 10 दिन के अन्दर सभासद सदन कोई निर्णय नहीं दे तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डायट का निर्णय समझ लिया जाता है। इस प्रकार प्रधान मंत्री के निर्वाचन के विषय में भी उच्च सदन को केवल 10 दिन की देरी करने का ही अधिकार है।

केबिनेट के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी उच्च सदन की स्थिति निम्न सदन की अपेक्षा शक्तिहीन है। संविधान द्वारा मर्यादा केबिनेट का उत्तरदायित्व डायट के प्रति रखा गया है, तथापि व्यवहार में केबिनेट प्रतिनिधि सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रतिनिधि सदन अपने अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा केबिनेट को अपदस्त करने का अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में यदि केबिनेट स्वयं त्याग पत्र देकर 10 दिन के अन्दर प्रतिनिधि सदन को ही भंग करा देती है तो सभासद सदन केवल स्थगित हो जाता है, भंग नहीं होता। इस मध्य आवश्यकता पड़ने पर केबिनेट सभासद सदन का विशेष अधिवेशन बुला कर वाप कर सकती है लेकिन इन कार्यों पर अधिवेशन में आने पर प्रतिनिधि सदन की 10 दिन के अन्दर परवर्ती अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा वे समाप्त समझे जाएंगे।

संवैधानिक संशोधन के सम्बन्ध में दोनों की शक्ति समान हैं क्योंकि संशोधन के प्रस्तावों पर दोनों ही सदनों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत की सहमति अनिवार्य होती है।

विधायी प्रक्रिया

(Legislative Procedure)

जापान में बिलों को दो वर्गों में बांटा जाता है—सरकारी बिल और सरकारी सदस्यों के बिल। विषय वस्तु की दृष्टि से सरकारी बिल और सरकारी सदस्यों के बिल एक जैसे होते हैं लेकिन उनका उद्गम अलग अलग होता है। सरकारी बिल सरकार की ओर से मंत्री द्वारा प्रारम्भ किये जाते हैं जबकि सरकारी सदस्यों का बिल डायट के ऐसे सदस्य द्वारा प्रारम्भ किया जाता है, जो सरकार का सदस्य नहीं है। जापान में समिति भी विधायन का प्रारम्भ कर सकती है।

सरकारी विधेयकों की प्रक्रिया

समस्त सभी सरकारी विधेयक स्वयं विभाग में ही प्रारम्भ किये जाते हैं। उन्हीं विभाग के अधिकारी तैयार करके सम्बन्धित मंत्री के पास भेज देते हैं। मंत्री द्वारा विधेयक के अनुमोदन के पश्चात् वे उसका नाम पर विधायन कार्य मंत्री को भेज दिये जाते हैं। मंत्री विधेयक का अध्ययन करता है और इनके बानूनों, संवैधानिक एवं प्रशासनिक पहलुओं की जांच करता है। प्रत्येक विधेयक का संशोधन और संशोधन के पदचान् केबिनेट में भेज दिया जाता है और कार्य-मूला में शामिल कर लिया जाता है। विधेयक पर केबिनेट का

समिति व्यवस्था—प्रस्तावना के बाद समिति व्यवस्था घायी है। विधेयक को किसी एक म्याई समिति या विशेष समिति का निर्देशन कर दिया जाता है। समिति में वरिष्ठता से विधेयक पर ध्यानपूर्वक विचार होता है और उसके आवश्यक विषयों की जांच की जाती है। समिति किसी मंत्री को या सदस्य के किसी सदस्य का अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर सकती है प्रपचा कोई भी सदस्य समिति की प्रार्थना कर सकता है कि वह उसके विचार सुने। समिति विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है। इसके प्रतिरिक्त वाणी सभा के लिए वह डायट के विधायन-काय ब्यूरो को भी आमंत्रित कर सकती है। समिति जनता में सभी व्यक्तियों को, सम्बन्धित विषय के बारे में विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित कर सकती है।

सदन में विचार—समिति द्वारा विधेयक के समर्थन और विरोध में तर्कों पर चर्चा करने के पश्चात् इसे समिति के अध्यक्ष द्वारा सदन को प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि विधेयक के किसी पहलू पर कोई भ्रम भवित रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को भी सदन के समक्ष रखा दिया जाता है। सदन में कोई भी सदस्य विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है, ऐसे किसी भी संशोधन की प्रतिनिधि सदन कम से कम 20 सदस्यों का और सभा सदस्य में कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन आवश्यक प्राप्त होता पारित है। विधेयक का बजट में संशोधन के लिए प्रतिनिधि सभा में कम से कम 50 और सभा सदस्य सदन में कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन होता आवश्यक है। विधेयक के सभी खण्डों पर वाचन और मतदान के पश्चात् सम्पूर्ण मतदान लिया जाता है और एक सदन द्वारा पारित विधेयक को

दूसरे सदन में भेजा जाता है जहाँ विधेयक उपयुक्त व्यवस्थाओं से पुनः गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक पारित कर देता है तो फिर इसे सम्राट के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। विधेयक पर मत भेद की स्थिति में हायट द्वारा समाधान के लिए समाधान-समिति नियुक्त की जाती है जो यदि किन्हीं समस्याओं पर नहीं पहुँच पाती तो प्रतिनिधि सदन विधेयक पर सभा सदन के विरोध में अपने दो तिहाई बहुमत के आधार पर अपनी बात मनवा सकता है।

सम्राट का अनुमोदन—हायट के दो सदन द्वारा इस प्रकार विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद इसे सदन के स्पीकर द्वारा कैबिनेट के माध्यम से सम्राट के पास भेजा जाता है। समिति इसके प्रावधानों के बारे में सरकारी तौर पर ऐलान करती है और मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद इस सम्राट को पेश करती है तथा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिये जाने के बाद कानून का ऐलान कर दिया जाता है।

बजट

बजट का अधिनियम साधारण विधेयक के अधिनियम से भिन्न है। वित्त विधेयक या बजट अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि सदन द्वारा आरम्भ किया जाता है और साधारण विधेयकों के विपरीत, सभा सदन इसे 30 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रोक सकता। इस अवधि की समाप्ति के बाद वित्त विधेयक कानून बन जाता है चाहे सभा-सदन का विरोधी मत हो क्यों न हो।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक (Private Member's Bill) वह सावजनिक विधेयक है जो हायट के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो सरकार का सदस्य नहीं है। ये विधेयक सामान्यतः कई सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हायट में पेश किये जाते हैं और अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। हायट में पेश किये गये अधिकांश विधेयकों का उद्देश्य प्रचार द्वारा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या निर्वाचन आंदोलन में मत प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त करना होता है। इनको पारित करने की प्रक्रिया भ्रष्ट गरीब विधेयकों के समान ही है।

6

न्यायपालिका (THE JUDICIARY)

जापान की न्याय व्यवस्था उच्च स्तर की है। प्राचीन सविधान के अन्तर्गत जापानी न्याय-व्यवस्था में जो अनेक दोष थे, उन्हें नवीन सविधान के अन्तर्गत लगभग दूर कर दिया गया है। जापान की वर्तमान न्यायपालिका अपने संगठन और स्वरूप में अमेरिकन एवं भारतीय न्यायपालिका से पर्याप्त प्रभाव में मिलती-जुलती है।

जापान की न्यायपालिका की विशेषताएँ

न्यायपालिका की पृथक्ता—जापान में न्यायपालिका को शासन के अथवा प्रशासन से पृथक् और उनके नियन्त्रण में मुक्त रखा गया है। न्यायालय का संगठन पूर्णतः पृथक् है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी जाय-विधि आदि से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार है। न्यायाधीशों पर न्यायपालिका द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती और न ही न्यायाधीशों को हटा सकती है। सविधान की धारा 87 द्वारा स्पष्ट शब्दों में उपबोधित किया गया है कि न्यायाधीशों को सावजनिक महाभियोगों को छोड़कर उस समय तक नहीं निकाला जायेगा जब तक वे न्यायिक रूप से मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से अपने कर्तव्य पालन में अशक्त घोषित न कर दिये जायें। न्यायाधीश ईमानदारी के साथ कार्य कर सकें और किसी प्रकार के प्रलोभन में न फँस सकें, इसके लिए उन्हें समुचित वेतन और अन्य समुचित सुविधायें प्रदान की गई हैं। यह व्यवस्था है कि न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्य-काल में नहीं घटाया जा सकता।

न्याय व्यवस्था की एकरूपता—जापान की सम्पूर्ण व्यवस्था को एक ही मूल में संगठित कर दिया गया है। सविधान की धारा 76 निर्देशित करती है कि 'समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और ऐन अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है जो कानून द्वारा स्थापित किये जाते हैं। किसी असाधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की जायेगी और न ही

कार्यपालिका के किसी भवनय भववा एजेसी को प्रतिम 'यायिक शक्ति दी जायेगी ।'

यायिक पुनरावलोकन—संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के सर्वाच्च 'यायानया की भांति ही जापान के सर्वाच्च 'यायालय की भी 'यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। जापान में 'यायपालिका की प्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है, ट्रिटन को भाति ममदीय प्रभुता का नहीं। जापानी केबिनेट कोई ऐसा काम नहीं कर सकता भववा ससद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान में भवगत हो। संविधान की धारा 81 में प्रदत्त अधिकार के भवगत सर्वाच्च 'यायालय संविधान की व्याख्या करके यह निणय कर सकता है कि ससद द्वारा निर्मित कोई कानून भववा कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य संविधान के अनुकूल है भववा नहीं और इस सम्बन्ध में उसका निणय सर्वमाय समका जायेगा।

प्रशासकीय 'यायालयों का अभाव—जापान के वर्तमान संविधान में पृथक प्रशासकीय 'यायालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्य न्यायालयों की ही प्रशासनिक विषयों पर विचार करने का अधिकार है और साधारण नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उन 'यायालयों में पहुँचने के अधिकारी हैं।

सर्वाच्च 'यायालयों के यायाधीशों की नियुक्ति का प्रजाजनो द्वारा पुनर्निरीक्षण—जापान की यायिक व्यवस्था को एक अनुपम विशेषता यह है कि सर्वाच्च 'यायालय के यायाधीशों के पदों पर प्रजाजनो का मत लिया जाता है। यदि प्रजाजन जनमत-संग्रह में यायाधीशों का समर्थन करते हैं तो उन्हें पद पर बना रहन दिया जाता है अथवा पद-मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के जनमत संग्रह सम्बन्धी नीतियों का निर्माण डाइट द्वारा किया जाता है। यह जनमत संग्रह यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात् होने वाले डाइट के सदस्यों के प्रथम चुनाव के समय और उसके बाद प्रति दस वर्ष के अन्तर पर होता रहता है। इस तरह सर्वाच्च 'यायालय के यायाधीशों का पद अन्तिम रूप में निर्वाचकों के निणय पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यायाधीश ईमानदारी से कार्य करन रहन और संविधान की मर्यादाओं के भवगत बने रहने के प्रति हाते हैं।

सावजनिक यायिक कार्यवाही—जापानी संविधान यह व्यवस्था है कि 'यायानया में अभियोगों पर सावजनिक रूप में विचार किया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में गोपनीय विचार की व्यवस्था की गई है। किता मामलों पर गोपनीय रूप में विचार तभी सम्भव है जब किसी 'यायानय के 'यायाधीश

सबसम्मति से यह निर्णय करें कि अमुक मामले में सावजनिक-निर्णय शान्ति, व्यवस्था तथा नतिकता के विरुद्ध होगा।

न्यायपालिका का संगठन (Organisation of the Judiciary)

जापान का वर्तमान न्यायालय संगठन 16 अप्रैल, 1947 को प्रास्थापित हुए न्यायालय संगठन-कानून (The Judiciary Organisation Law) पर आधारित है। जापान में 5 तरह के न्यायालय हैं—

- 1 सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Courts)
- 2 उच्च न्यायालय (High Courts)
- 3 जिला न्यायालय (District Courts)
- 4 पारिवारिक न्यायालय (Courts of Domestic Relations)
- 5 समरी न्यायालय (Summary Courts)

इन सभी न्यायालयों का वर्णन क्रमशः निम्न प्रकार है—

सर्वोच्च न्यायालय

संगठन—जापान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। इस समय प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कानून के अनुसार इनमें से 10 न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो कानूनी जगत में उच्च व्यावसायिक योग्यताएं रखते हैं। शेष व्यक्ति अन्य क्षेत्रों से भी लिए जा सकते हैं।

योग्यताएं—कानून द्वारा न्यायाधीशों को निम्नांकित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं—

- 1 वह कम से कम 40 वर्ष की आयु का हो,
- 2 विधि-वेत्ता हो

3 न्यायाधीशों में से कम से कम 10 व्यक्तिगत रूप से कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अध्यक्ष अथवा न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा 20 वर्षों तक शीघ्र निर्णायक न्यायालय के न्यायाधीश, लोक अभियोजक वकील या कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो। इन चारों पदों पर कुल मिलाकर 20 वर्ष की सेवा भी माय है।

पदावधि—यह व्यवस्था है कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर रह सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित तीन दशाओं में उन्हें अवधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है—

- 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर पञ्चावर्षीय लिखा जाता है। यदि प्रजाजन जनमत यह भी न्यायाधीशों का

है तो उनको पद पर बने रहने दिया जाता है अथवा उ हें निकाल दिया जाता है। जनमत संग्रह न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात् होने वाले डायट के सदस्यों के प्रथम चुनाव के समय तथा उसके पश्चात् प्रति 10 वर्ष के अंतर पर होता रहता है।

2 न्यायाधीशों को सदाचार के अपराध पर पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का आरोप प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इसका परीक्षण और निणय 14 सदस्यों की एक समिति द्वारा किये जान की व्यवस्था है जिसमें दोनों सदनों के 7-7 सदस्य सम्मिलित होंगे।

3 तीसरी व्यवस्था 'यायिक निणय' की है। इसके अनुसार यायालय स्वयं 'यायाधीशों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का जाव करता है। उसके किसी अपराध पर उ हें दण्डित भी किया जाना है।

निम्न-धन—सर्वोच्च 'यायालय' के 'यायाधीशों' एवं अन्य 'यायाधीशों' के लिये निम्नांकित कार्यों का निषेध कर दिया गया है—

(क) संसद अथवा स्थानीय लोक सभाओं की सभाओं का सदस्य होना या राजनीतिक भादोलनों में भाग लेना

(ख) सर्वोच्च न्यायालय की स्वाकृति प्राप्त किये बिना कोई अन्य वैतनिक पद धारण करना एवं

(ग) कोई वाणिज्य सम्बन्धी व्यवसाय करना अथवा ऐसे व्यवसाय करना जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ हो।

अधिकार एवं कार्य

(क) 'यायिक कार्य—सर्वोच्च 'यायालय' के अधिकांश यायिक कार्य नीचे के 'यायालयों' के निणयों के विरुद्ध अपीलें सुनना है। अंतिम 'यायालय' के रूप में वह किसी भी प्रकार की अपील सुन सकता है लेकिन सामान्यतः वह फौजदारी और दोषी होने के विवादों में अपीलें सुनता है—

1 उच्च न्यायालयों के निणय के विरुद्ध द्वितीय स्थिति के 'यायालय' के रूप में निम्न प्रकार के वादों में द्वितीय अपीलों को सुनना—(क) संविधान से सम्बन्धित प्रश्नों वाले वाद, (ख) 'यायिक' दृष्टता के प्रतिभूल निणय वाले वाद, एवं (ग) कानूनों तथा अध्यादेशों के महत्वपूर्ण उत्प्लवन के।

2 प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया सम्बन्धी विरोध शक्तियाँ का सुनना।

उपयुक्त कार्यों के प्रतिरिक्त अपने और उच्च-न्यायालय के 'यायाधीशों' के 'यायिक सेवा' के स्तर के विरुद्ध अपराधों और उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता सम्बन्धी विवादों का निणय करना तथा नेशनल परमोनल अपारिटी के प्रावधानों के विरुद्ध संसद द्वारा लाये गये महाभियोग आरोपण के परीक्षण

न्यायाधीशों को अधिकार प्राप्त है। यह इसके मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है।

संविधान की धारा 81 के अनुसार किसी कानून, आज्ञा, नियम अथवा प्रशासनिक कार्य की संवैधानिकता की परीक्षा करना और इस कार्य के लिये संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय का ही है। न्यायिक पुनरावलोकन का यह कार्य सम्पूर्ण न्यायाधीशों की बड़ी बैठक द्वारा किया जा सकता है और किसी विधि, नियम या आज्ञा को असंवैधानिक घोषित करने के लिये कम से कम 9 व्यक्तियों के बहुमत की आवश्यकता होती है। संवैधानिकता के प्रश्न पर जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील साधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है।

(ख) नियम निर्माण सम्बन्धी कार्य—न्याय से सम्बन्धित विषयों पर व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये कानूनों को क्रियान्वित करने के लिये और जिन विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया ही नहीं है, उन्हें नियमित करने के लिए धारा 77 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय नियम बनाता है।

उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और न्यायिक प्रशासनिक अधिकारियों न्यायालय के सचिव लिपिक एवं महायन्त्र लिपिका आदि अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा सम्बन्धी नियमों का भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही बनाया जाता है। यह कार्य प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक गुप्त न्यायिक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रायः पाँच से अधिक न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं।

(ग) न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य—सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक प्रशासन में सम्बन्ध भी घनत्व में महत्वपूर्ण अधिकारों में है। वह न्यायिक प्रशासन द्वारा की जाने वाली सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये योग्य व्यक्तियों की सूची बनाता है और न्यायिक प्रशासन द्वारा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों का ही न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति कर सकता है। इसके अधिकारिता में ही उच्च न्यायालय के क्षेत्र में उच्च न्यायालय का प्रशासन भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की जाता है। विषय परिमिति में सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सूची में उच्च न्यायालय में ही उच्च न्यायालय के ही क्षेत्र के क्षेत्र में ही परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के क्षेत्र में ही कार्य करने का अधिकार करता है। इस प्रकार विषय परिमिति में सर्वोच्च न्यायालय एक ही न्यायालय के न्यायाधीशों की सूची में ही न्यायालय में ही कार्य करने का अधिकार करता है। सर्वोच्च न्यायालय विषय परिमिति में ही न्यायालय की ही कार्य करने करता है और उच्च

कार्य करने के लिए 'यायाधीश' नामांकित कर सकता है। सर्वोच्च 'यायालय' ही निम्न 'यायालयों' के 'यायाधीशों' को उनके पदों पर नियत करता है। वही उच्च 'यायालय', जिला 'यायालय' और परिवार 'यायालय' के सचिवालयों के मुख्य अधिकारियों को 'यायालयों' के सचिवों में से नियुक्त करता है।

(घ) प्रशिक्षणात्मक एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य—सर्वोच्च 'यायालय' के अंतर्गत तीन संस्थान हैं—विधि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 'यायालय' लिपिक हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान एवं परिवार तथा 'यायालय' परिवर्धन अधिकारी (Probation Officer) संस्थान। ये संस्थान सर्वोच्च 'यायालय' की दखरेख में कार्य करते हैं। ये 'यायाधीशों', अन्य अधिकारियों, लिपिकों, एपरटिसों आदि का प्रशिक्षण देते हैं। विधि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में उच्च लोकसेवा की न्यायिक परीक्षा पास विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं।

'न्यायिक विषयों' पर अनुसंधान का कार्य विधि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान और 'यायालय' लिपिक हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। प्रथम संस्था न्यायिक विषयों पर और द्वितीय लिपिकीय कार्यों पर अनुसंधान करता है। कुछ न्यायिक अनुसंधान अधिकारी सर्वोच्च 'यायालय' में भी होते हैं। वे न्यायाधीशों की भांति पर 'न्यायिक प्रक्रिया' पर अनुसंधान करते हैं।

(ङ) पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य—सर्वोच्च 'यायालय' की अपने अधिकारियों एवं निम्न 'यायालयों' के अधिकारियों से सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकार भी प्राप्त हैं। वह अपने अधिकारियों, निम्न 'यायालयों' और उनके अधिकारियों के कार्यों का सर्वेक्षण करता है। लेकिन यह पर्यवेक्षण अधिकार 'यायालयों' की न्यायिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता।

उच्च 'यायालय' (High Courts)

सर्वोच्च 'यायालय' के नीचे उच्च 'यायालय' हैं। सम्पूर्ण जापान 8 क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक उच्च 'यायालय' है। ये अधिकांशतः अपील के 'यायालय' हैं और अपने क्षेत्र में इनका निर्णय अंतिम होता है। उच्च 'यायालय' का 'यायाधीश' 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकता है। इनकी संख्या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। ये मुकदमों को प्रायः तीन-तीन की बचों के रूप में सुनते हैं और उन पर निर्णय देते हैं। राज-द्रोह के मुकदमों में 5 'यायाधीशों' की बच बठती है क्योंकि यह इनके प्रारम्भिक क्षेत्र में आते हैं।

जिला 'यायालय' (District Courts)

जापान में उच्च 'यायालयों' के नीचे 49 जिला 'यायालय' और उनकी

संग्रह 240 शाखाएँ हैं। जिना यायालयों में कुछ न्यायाधीश और कुछ सहायक यायाधीश होते हैं। न्यायालय का प्रशासन सम्बन्धी कार्य एक यायिक सभा द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य सभी न्यायाधीश होने हैं और मुख्य यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय जिला यायालय की शाखाएँ स्थापित कर सकता है। जिना न्यायालय में दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले आते हैं तथा नीचे की अदालतों की अपीलें भी आती हैं। माधारण एक ही यायाधीश मुकदमा सुनता है और निर्णय देता है परन्तु गम्भीर मामला में तीन न्यायाधीशों की बच भी बैठती है।

पारिवारिक न्यायालय (Courts of Domestic Relations)

ये न्यायालय जापान का पचायता के क्षेत्रों में अभी प्रयोग हैं। वस्तुतः ये न्यायालय जिला न्यायालयों के ही अङ्ग हैं जिनके निर्माण का उद्देश्य पारिवारिक झगड़ों को निपटाने में सहायता देना है। फलस्वरूप इनमें तलाक, जायदाद के बंटवारे, गोद लेने, बचन तोड़ने आदि से सम्बन्धित मामले आते हैं। विधान ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देकर जो एक सामाजिक नीति का सिलसिला चलाया है, उसके कारण इन पारिवारिक अदालतों में मुख्यतः तलाक के मामले आते हैं। यह न्यायालय एक प्रकार के अर्द्ध पचायती न्यायालय हैं जिनमें यायाधीशों के अतिरिक्त साधारण नागरिक भी याय करने बैठते हैं और कानूनी प्रक्रिया को जटिलता हटा दी जाती है।

समरी न्यायालय (Summary Courts)

जापान में सबसे नीचे के न्यायालय समरी न्यायालय हैं जो ब्रिटेन के जस्टिस आफ पीस न्यायालयों का भाति हैं। इनमें दीवानी और फौजदारी के छोटे मुकदमे आते हैं। मुकदमा का फल तुरन्त होता है। इनलिये भी इन्हें समरी न्यायालय कहा जाता है।

प्रोक्यूरेटर्स (Procurators)

जापान में यायाधीशों के साथ सरकार का भी एक संगठन है जिसके प्रमुख को प्रोक्यूरेटर जनरल (Procurator General) कहा जाता है। इसी के द्वारा याय मंत्रालय कार्य करता है। इसके और इसके सहायकों को नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाती है और सम्राट इस नियुक्ति की पुष्टि (Attest) करता है। दूसरी श्रेणी के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है। प्रोक्यूरेटर जनरल 65 वर्ष की आयु में और अन्य प्रोक्यूरेटर 63 वर्ष की आयु में पद-निवृत्त होना है। इनके वतन प्रविष्टि, योग्यता आदि के विषय में कानून बने हुए हैं। इनका मुख्य काम फौजदारी मुकदमा में सरकारी पक्ष रचना होता है।

कार्य करने के लिए न्यायाधीश नामांकित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ही निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पदों पर नियत करता है। वही उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और परिवार न्यायालय के सचिवालयों के मुख्य अधिकारी को न्यायालयों के सचिवों में से नियुक्त करता है।

(घ) प्रशिक्षणात्मक एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य—सर्वोच्च न्यायालय के अतहत तीन संस्थान हैं—विधि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, न्यायालय लिपिक हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान एवं परिवार तथा न्यायालय परीक्षण अधिकारी (Probation Officer) संस्थान। ये संस्थान सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं। ये न्यायाधीशों और अधिकारियों लिपिकों एवरटिसों आदि का प्रशिक्षण देते हैं। विधि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ये उच्च लोकसेवा की न्यायिक परीक्षा पास विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं।

न्यायिक विषयों पर अनुसंधान का कार्य विधि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान और न्यायालय लिपिक हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। प्रथम संस्था न्यायिक विषयों पर और द्वितीय लिपिकों के कार्यों पर अनुसंधान करता है। कुछ न्यायिक अनुसंधान अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में भी होते हैं। वे न्यायाधीशों की आज्ञा पर न्यायिक प्रक्रिया पर अनुसंधान करते हैं।

(ङ) परीक्षण सम्बन्धी कार्य—सर्वोच्च न्यायालय अधिकारियों एवं निम्न न्यायालयों के अधिकारियों से सम्बन्धित अधिकार भी प्राप्त है। वह अपने अधिकारियों, निम्न अधिकारियों के कार्यों का सर्वेक्षण करता है। लेकिन यह न्यायालयों की न्यायिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर उच्च न्यायालय (High Courts)

सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय 8 क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र में एक एक अधिकारी अधीन के न्यायालय हैं और अपने क्षेत्र होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक रहता है। इनकी संख्या अलग-अलग क्षेत्रों में प्रायः तीन-तीन की संख्या के रूप में गुणित हैं और दोहरे के मुकदमा में 5 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है क्षेत्रों में होते हैं।

जिला न्यायालय (District Courts)

जापान में उच्च न्यायालयों के नीचे 49

लगभग 240 शाखाये हैं। जिना यायालय मे कुछ न्यायाधीश और कुछ सहायक न्यायाधीश होते है। यायालय का प्रशासन सम्बन्धी कार्य एक दायिक सभा द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य सभी यायाधीश होने हैं और मुख्य यायाधीश इनका अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च यायालय जिला यायालय को शाखाएँ स्थापित कर सकता है। जिना यायालय मे दीवानो और फौजदारी दोनों तरह के मामले आते है तथा नीच को भेदालना की अपीलें भी आते है। माधारणत एक ही न्यायाधीश मुकदमा सुनता है और निर्णय देता है परन्तु गम्भीर मामला मे तीन न्यायाधीशों की बच भी बढती है।

पारिवारिक यायालय (Courts of Domestic Relations)

ये यायालय जापान का पचायती के क्षेत्र मे अभी प्रयोग है। वस्तुतः य यायालय जिला यायालयों के ही अङ्ग है जिनके निर्माण का उद्देश्य पारिवारिक झगड़ों को निपटान मे सहायता देना है। फलस्वरूप इनमे तलाक, जायशद के बन्वारे गोद लने बचन तोड़न आदि से सम्बन्धित मामल आते हैं। विधान ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देकर जो एक सामाजिक क्रांति का सिर्नासिला चलाया है उसके कारण इन पारिवारिक भेदान्तों मे मुख्यत तलाक के मामले आते है। यह न्यायालय एक प्रकार के अद्वैतवायती यायालय है जिनमे न्यायाधीशों के अतिरिक्त साधारण नागरिक भी वाय करने बैठते है और वानूनी प्रक्रिया को जटिलता हटा दी जाती है।

समरी यायालय (Summary Courts)

जापान मे सबसे नीचे के न्यायालय समरी न्यायालय है जो रिटेल के जस्टिस आफ पीस यायालयों का भाति है। इनमे दीवानो और फौजदारी के छोटे मुकदमे आते है। मुकदमा का फलता तुरन्त होता है। इसलिये भी इसे समरी न्यायालय कहा जाता है।

प्रोक्यूरेटर्स (Procurators)

जापान मे यायाधीशों के साथ सरकारी वकीलों का भी एक संगठन है जिसके प्रमुख को प्रोक्यूरेटर जनरल (Procurator General) कहा जाता है। इसी के द्वारा वाय मन्त्रालय कार्य करना है। इनके और इसके सहायकों को नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाती है और सम्राट इस नियुक्ति को पुष्टि (Attest) करता है। दूसरी थोड़ी के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है। प्रोक्यूरेटर जनरल 65 वर्ष की आयु मे और अन्य प्रोक्यूरेटर 63 वर्ष की आयु मे पद निवृत्त होता है। इनके वतन प्रशिक्षण, योग्यताओं आदि के विषय मे कानून बने हुए है। इनका मुख्य काम फौजदारी मुकदमों मे सरकारी पक्ष रखना होता है।

7

स्थानीय शासन

(LOCAL GOVERNMENT)

जापान के नवीन संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को विशेष महत्व दिया गया है और अध्याय 8 में उसके मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। संविधान की धारा 92 में कहा गया है कि स्थानीय लोक संस्थाओं के संगठन और कार्य संचालन सम्बंधी विनियम, स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत के अनुसार कानून द्वारा निश्चित किया जायेगा। धारा 93 के अनुसार 'स्थानीय लोक संस्थायें अपने ऐच्छिक अवयवों के रूप में कानून के अनुकूल सभाओं की स्थापना करेंगी। सभी स्थानीय लोक संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी कमचारी उनकी सभाओं के सदस्य और कानून द्वारा निर्धारित अन्य स्थानीय अधिकारी, अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकमत द्वारा चुने जायेंगे।' धारा 94 यह उपबोधित करती है कि स्थानीय लोक संस्थाओं को अपनी सम्पत्ति का प्रबंध करने और अपने कार्याएँ प्रशासन का उपबोध करने तथा कानून के अंतर्गत अपने विनियम बनाने का अधिकार होगा। धारा 95 में उल्लिखित है कि किसी एक ही स्थानीय लोक संस्था पर लागू होने वाला कोई एक कानून डायट द्वारा तद्विषयक स्थानीय लोक संस्था के निर्वाचकों की बहुसंख्या के अनुकूल प्राप्त की हुई सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता।'

स्थानीय सरकार का संगठन एवं कार्य

(Organisation & Functions of the Local Government in Japan)

संविधान के अंतर्गत निर्देश के अनुरूप वर्तमान स्थानीय शासन-संस्थाओं का संगठन मूलतः स्थानीय स्वायत्तता कानून (Local Autonomy Law) 1947 एवं बाद में समय-समय पर होने वाले संशोधनों के आधार पर किया गया है।

जापान में स्थानीय शासन की संस्थायें दो श्रेणियों की हैं—एक प्रीफेक्चरल (Prefectural) जिसमें चार प्रकार का मन्थार्य है तथा दूसरी नगरपालिकाएँ जिनके अंतर्गत नगर, कस्बे और गांव का प्रशासन आता है।

प्रीफेक्चर की स्थानीय सरकार (Prefectural Local Government)

गवर्नर—इस समय होकेडो को छोड़कर सम्पूर्ण देश 46 प्रीफेक्चर (प्रशासनिक इकाइयाँ) में बंटा हुआ है। प्रीफेक्चर का प्रमुख गवर्नर कहलाता है। गवर्नर के लिए यह आवश्यक है कि वह जापान का निवासी हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो। लिंग के आधार पर कोई बंदिश नहीं है। गवर्नर एक साथ डायट और स्थानीय-सभा का सदस्य नहीं हो सकता। वह प्रीफेक्चर के लोग द्वारा चुना जाता है और चार वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है बशर्ते कि वह इससे पहले त्याग पत्र न दे दे या प्रीफेक्चर का सभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पार न कर दिया जाए। अविश्वास का प्रस्ताव कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास किया जा सकता है। यह गवर्नर की इच्छा पर है कि वह या तो सभा का भाग ले कर दे और नये निर्वाचन के लिये वह या फिर त्याग पत्र दे दे। नव निर्वाचित सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके गवर्नर को पद से हटा सकती है और इसमें उसे कुल सदस्यों की संख्या का साधारण बहुमत चाहिए। गवर्नर का 'लोकप्रिय प्रत्याहरण' (Popular Recall) द्वारा भी पदच्युत किया जा सकता है। व्यवस्था यह है कि यदि प्रीफेक्चर के एक तिहाई निर्वाचक गवर्नर को उसके पद से हटाने की याचिका करते हैं और इस याचिका को प्रत्याहरण निर्वाचन (Recall Election) में बहुमत प्राप्त हो जाता है तो गवर्नर का अपना स्थान छोड़ना पड़ता है।

सहायक गवर्नर—गवर्नर एक से तीन तक सहायक गवर्नर नियुक्त कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। गवर्नर ही अपने महायुक्त के कर्तव्य का निर्धारण करता है। इन सहायक गवर्नरों के कर्तव्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों हैं। गवर्नर की अनुपस्थिति में उसके पद पर ये ही कार्य करते हैं। यदि किसी कारणवश गवर्नर और सहायक गवर्नर दोनों ही प्रीफेक्चर में नहीं हों तो प्रधान मंत्री का अधिकार है कि वह किसी को भी उस अवधि के लिए कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त कर दे। स्टाफ के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त प्रीफेक्चर में एक लेखापाल एक कोषाध्यक्ष एक लेखा परीक्षक और उपनिमित्तों के अनुसार कुछ अन्य कर्मचारी होते हैं।

गवर्नर की कार्यकारी शक्तियाँ और स्थिति—जापानी प्रीफेक्चर के गवर्नर को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं और उसकी शक्तियाँ बहुत कुछ वे ही हैं जैसा कि परतंत्र भारत में भारतीय प्रान्त के गवर्नर को प्राप्त थी। गवर्नर अपने प्रशासन का मग्न करेता है और अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। उसे दो समितियाँ में काम करना पड़ता है—राष्ट्रीय मामलों में वह केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है और स्थानीय मामलों

मे प्रीफेचर के अधिकारी की हैसियत से वाय करता है। गवर्नर द्वारा किये जाने वाले वाय निम्नलिखित हैं—

- 1 इलाके के महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करना, उन्हें उनके पद से हटाना और उनका पर्यवेक्षण करना।
- 2 सरकारी दस्तावेजों और अन्य आवश्यक कागजातों का अभिरक्षण करना।
- 3 प्रीफेचर के बजट पर नियंत्रण रखना और अपने मागदस्तान में उसे तयार करना।
- 4 सभी वरों के समाहरण और व्यय के भुगतान तथा लेखा परीक्षा व सम्पत्ति की व्यवस्था का दायित्व वहन करना।
- 5 प्रीफेचर को सभा के निर्धारण किये बिना ही आवश्यकतानुसार विनियम और अध्यादेश जारी करना।
- 6 उपयुक्त मुद्रावजा देकर सम्पत्ति का ध्वज करना।
- 7 विनियमों या अध्यादेशों के अतिक्रमण के लिए दो हजार येन तक जुर्माने का आदेश देना।
- 8 मकटवाल की अवधि में प्रीफेचर द्वारा सभा के सभी या कुछ अधिकार आवश्यकतानुसार ग्रहण करना और विनियम जारी करना, आवश्यकतानुसार विधिवन् अधिकृत कार्यों के लिए धन खर्च करना, चाहे यह खर्च व्यवस्थापिका के नियमांक विरुद्ध ही क्यों न हो।

गवर्नर को स्थानीय सरकार पर निदेशात्मक शक्ति प्राप्त है वह मेयर का नियंत्रण करता है, यद्यपि उस मेयर का बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है फिर भी वह उस कानूनी कर्तव्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। गवर्नर अपनी व्यापक शक्तियों के आधार पर नगरपालिकाया को निर्देश दे सकता है उनका पर्यवेक्षण कर सकता है तथा उनके रेकार्ड तथा लेखा को जांच कर सकता है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी वहन करने पड़ते हैं। गवर्नर सरकार का प्रवक्ता होता है अतः उसका प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक और बड़ सम्मान के साथ सुना जाता है।

प्रीफेचर का विधान मण्डल—प्रीफेचर की सभाया की सदस्य संख्या इत्यादी की आबादी के अनुसार अलग-अलग है। यह 40 से 120 सदस्यों तक है। प्रीफेचर के निवासी सदस्यों का निर्वाचन करने हैं। मतदाता की 20 वर्ष या इससे अधिक की आयु का होना आवश्यक है। विधान मण्डल के लिए प्रत्याशी की 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। विधान मण्डल का अवधि 4 वर्ष का है। प्रीफेचर व विधान मण्डल का सदस्य न

तो डायट का सदस्य हो सकता है और न स्थानीय प्रशासन का। विधान मण्डल के नियमित अधिवेशन वर्ष में ६ बार होते हैं तथा सभा के एक चौथाई सदस्यों द्वारा मांग किये जाने पर उसके असाधारण अधिवेशन भी बुलाये जा सकते हैं।

प्रीफेक्चर की विधान सभा को इसकी सीमाओं और अधिकारों के अन्तर्गत उपनियमों के अधिनियमन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उपनियमों के अतिक्रमण के लिए दो वर्ष तक के कारावास का या एक लाख पैन तक के जुमाने का दण्ड दे सकती है। प्रीफेक्चर की सभा वार्षिक बजट निर्धारित करती है और लेखा परीक्षका की रिपोर्टों को चर्चा करता है। यह करा का आरोपण करती है और लोक-सभाओं के लिए फीस नियत करती है। सावजनिक सम्पत्ति का प्रबंध करने के लिए सविदा भी यही करती है। पुस्तकालय कायम करने और नगरों तथा सभा के सदस्यों के प्रयोग के लिये सरकारी राजपत्रों व अन्य सामग्री की व्यवस्था करना भी प्रीफेक्चर सभा अथवा विधान मण्डल का कर्तव्य है।

गवर्नर और विधान मण्डल का सम्बन्ध—दोनों का सम्बन्ध समदीय प्रकार का है। गवर्नर विधेयकों को प्रारम्भ करता है विधान मण्डल द्वारा पारित किये गये विधेयकों को हस्ताक्षरित करता है। उसे सीमित वीटो का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने की सुरत में वह विधान मण्डल को भंग कर सकता है। इसी प्रकार विधान मण्डल भी गवर्नर को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है यदि वह अपने पुनर्निर्वाचन के पश्चात् साधारण बहुमत से गवर्नर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे। गवर्नर विशेष शक्तियाँ का प्रयोग करके विधान-मण्डल पर नियन्त्रण कर सकता है। यह विशेष शक्तियाँ प्रमुखतः ये हैं—गवर्नर विधान मण्डल के किसी सकल्प का पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और इस प्रकार इसके पास होने में देरी कर सकता है अथवा इसे समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि विधान-मण्डल इसे दुबारा पास कर देती है और इसे दो तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाता है तो इसे अन्तिम रूप से पास कर दिया जाता है। यदि सभा का अधिवेशन नहीं होता है तो गवर्नर उपनियम जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त गवर्नर प्रशासनिक सेवाओं के लिए धन खर्च करने के विशेष अधिकार का इस्तेमाल करने की धमकी देकर विधान-मण्डल को प्रभावित कर सकता है। पुनश्च गवर्नर किसी भी उपनियम या सकल्प को लौटा सकता है, यदि वह इसे असंवधानिक अथवा गर-कानूनी समझे। वह इसके विरुद्ध अदालत में कायवाही भी कर सकता है।

यद्यपि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों और अपनी विवेक शक्ति के बल

मेयर के ही कर्तव्य हैं। सकटकाल के दौरान मेयर उपनियमों के महत्त्व के विनियम जारी कर सकता है, विधिवत् प्राधिकृत कार्यों के लिए धन खर्च कर सकता है और बजट को कम कर सकता है।

नगर-सभा (Municipal Assembly)—इसके सदस्यों का चुनाव जापान के उन नागरिकों द्वारा किया जाता है जो 20 वर्ष या अधिक का आयु के हों और उस इलाके के लगातार 3 मास तक निवासी रहे हों। नगर-सभा के प्रत्यासी की कम से कम आयु 25 है। नगर सभा की सदस्य संख्या कम से कम 12 और अधिक से अधिक 48 है। यह आकार जनसंख्या के अनुपात से बदलता रहता है। नगर-सभा के सदस्य इनके साथ डायट और प्रीफेक्चर की सभा के सदस्य नहीं हो सकते। सदस्य की अवधि 4 वर्ष की है और उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। कम आयवादी वाले छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामों में निर्वाचकों की सामान्य बैठकें ही नगर सभाओं का स्थान ले लेती हैं।

नगर-सभा का अधिवेशन वर्ष में 6 बार नियमित अधिवेशन के रूप में होता है। मेयर अथवा कुल सदस्यों के एक चौथाई भाग के कहने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। नगर-सभा को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह वार्षिक बजट पेश करती है और अपने उपनियमों के उल्लंघन करने के लिए दण्ड निहित करती है। यह करारोपण भी करती है और सार्वजनिक सेवाओं के लिये शुल्क नियत करती है। सभा स्थानीय मामलों की जांच कर सकती है तथा स्थानीय अधिकारियों को गवाही देने के लिए अपने सामने पेश होने के लिए कह सकती है।

सारांश में, जापान में नवीन संविधान के अंतर्गत जिस प्रकार के स्थानीय प्रशासन के संगठन की परिकल्पना की गई है, वह लोकतन्त्रात्मक पद्धति के अनुकूल है।

मेयर के ही कत्तब्य हैं। सकटकाल के दौरान मेयर अनियमा के महत्त्व के विनियम जारी कर सकता है, विधिवत् प्राधिकृत कार्यों के लिए धन खच कर सकता है और बजट को कम कर सकता है।

नगर-सभा (Municipal Assembly)—इसके सदस्यों का चुनाव जापान के उन नागरिकों द्वारा किया जाता है जो 20 वर्ष या अधिक की उम्र हो और उस इलाके के लगातार 3 मास तक निवासी रहे हों। इनके प्रत्याशियों की कम से कम आयु 25 है। नगर सभा की कम से कम 12 और अधिक से अधिक 48 है। यह प्राकार न्यूनतम से बदलता रहता है। नगर-सभा के सदस्य इमक प्रोफेक्टर की सभा के सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यों की उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। कम प्रावादों वाले ग्रामों में निर्वाचकों की संख्या बढें ही नगर

पर विधान-मण्डल की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, लेकिन दोनों के वर्तमान सम्बन्धों से ऐसा नहीं लगता कि एक दूसरे से विरुद्ध हैं। वास्तविक व्यवहार के अन्दर ऐसा हो कि उसमें समाधान की कोई संभावना नहीं हो तो उनमें से एक अपने पद से त्याग पत्र दे देगा।

नगरपालिका (Municipality)

ऊपर हमने प्रीफेक्चर की स्थानीय सरकार का वर्णन किया है। नगर, कस्बों और ग्रामों की स्थानीय सरकारें नगरपालिकाओं द्वारा चलाई जाती हैं। नगरपालिका की कार्यपालिका शक्ति मेयर (Mayor) में निहित है और विधायी शक्तियाँ नगरपालिका में ही।

मेयर—जापान का कोई भी नागरिक, जो 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाला हो, मेयर चुना जा सकता है। मेयर भी एक ही समय में डायट द्वारा स्थानीय असेम्बली या सभा का सदस्य नहीं हो सकता। वह सांख्यिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इलाके के लोगों द्वारा चुना जाता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे नियमित वेतन दिया जाता है। कानून के अनुसार कर्तव्य पालन न करने पर गवर्नर उसे पदच्युत कर सकता है। इसके प्रतिरूप नगरपालिका अपनी कुल सदस्य सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रतिस्पर्धा प्रस्ताव पास करके भी मेयर को त्याग पत्र देने के लिये विवश कर सकती है। एक और भी तरीका है जिसमें मेयर पदच्युत किया जा सकता है और वह है प्रत्याह्वय (Recall) का। इसके लिए निर्वाचकों का एक तिहाई भाग याचिका रखता है और इस विषय को नगरपालिका के मतदाताओं के निष्पक्षों के लिए उनके समक्ष रखा जाता है, यदि निष्पक्ष मेयर के विरुद्ध होता है तो उन त्यागपत्र देना ही पड़ता है।

सहायक मेयर—मेयर के कर्तव्य पालन में सहायता के लिए एक सहायक मेयर की भी व्यवस्था की गई है जिसे मेयर ही नियुक्त करता है और वही उसे हटा भी सकता है। सहायक मेयर को उन सभी कार्यों को करना पड़ता है जो मेयर द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। मेयर के कर्तव्य अथवा राजनीतिक और प्रशासनिक हैं और उसकी अनुपस्थिति में सहायक मेयर उसके सभी कार्य करता है।

मेयर के भी दोहरे उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय मामलों पर विचार करता है और इसके लिए अपने प्रीफेक्चर के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता है। स्थानीय मामलों के लिए वह अपनी नगरपालिका का कार्यकारी अधिकारी है और इस नाते वह स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति करता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, नगरपालिका का बजट तैयार करता है तथा इसे संप्रति के विचारार्थ प्रस्तुत करता है। सभी कर और शुल्क वसूल करना एवं सभी विनियोगों की लेखा परीक्षा भी

मेयर के ही कर्तव्य हैं। मकटकाल के दौरान मेयर उपनियमों के महत्व के विनियम जारी कर सकता है, विधिवत् प्राधिकृत कार्यों के लिए धन खर्च कर सकता है और बजट को कम कर सकता है।

नगर-सभा (Municipal Assembly)—इसके सदस्यों का चुनाव जापान के उन नागरिकों द्वारा किया जाता है जो 20 वर्ष या अधिक का आयु के हों और उस इलाके के लगातार 3 मास तक निवासी रहे हों। नगर-सभा के प्रत्याशी की कम से कम आयु 25 है। नगर-सभा की सदस्य संख्या कम से कम 12 और अधिक से अधिक 48 है। यह आकार जनसंख्या के अनुपात से बदलता रहता है। नगर-सभा के सदस्य इसके साथ डायट और प्रीफेक्चर की सभा के सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यों की अवधि 4 वर्ष की है और उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। कम आयुवादी वाले छोटे छोटे कस्बा और ग्रामों में निर्वाचकों की सामान्य बैठकें ही नगर सभाओं का स्थान ले लेती हैं।

नगर-सभा का अधिवेशन वर्ष में 6 बार नियमित अधिवेशन का रूप में होता है। मेयर अथवा कुल सदस्यों के एक चौथाई भाग के बहने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। नगर-सभा को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह वार्षिक बजट पेश करती है और अपने उपनियमों के उद्घाटन करने के लिए दण्ड निहित करती है। यह करारोपण भी करती है और सावजनिक सेवाओं के लिये शुल्क नियत करती है। सभा स्थानीय मामलों की जांच कर सकती है तथा स्थानीय अधिकारियों को गवाही देने के लिए अपने सामने पेश हान के लिए कह सकती है।

सारासरी में, जापान में नवीन विधान के अंतर्गत जिस प्रकार के स्थानीय प्रशासन के संगठन की परिकल्पना की गई है, वह लोकतन्त्रात्मक पद्धति के अनुरूप है।

पर विधान मण्डल की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, लेकिन दोनों के वर्तमान सम्बन्ध से ऐसा नहीं लगता कि एक दूसरे से विरुद्ध हैं। वास्तविक व्यवहार के अन्दर ऐसा हो कि उसमें समाधान की कोई सम्भावना नहीं हो तो उनमें से एक अपने पद से त्याग पत्र दे देगा।

नगरपालिका (Municipality)

ऊपर हमने प्रीफेक्चर की स्थानीय सरकार का वर्णन किया है। नगरों के स्थायी और ग्रामों की स्थानीय सरकारें नगरपालिकाओं द्वारा चलायी जाती हैं। नगरपालिका को कार्यपालिका शक्ति मेयर (Mayor) में निहित है और विधायी शक्तियाँ नगरपालिका में ही।

मेयर—जापान का कोई भी नागरिक, जो 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाला हो मेयर चुना जा सकता है। मेयर भी एक ही समय में डाक्टरेट द्वारा स्थानीय प्रसेम्बली या सभा का सदस्य नहीं हो सकता। वह सार्वजनिक व्यवस्था के अधिकार के आधार पर इनके के लोग द्वारा चुना जाता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे नियमित वेतन दिया जाता है। कानून के अनुसार कर्तव्य पालन न करने पर गवर्नर उसे पदच्युत कर सकता है। इसके प्रतिरक्षण नगरपालिका अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रतिस्पर्धा प्रस्ताव पास करके भी मेयर को त्याग-पत्र देने के लिये विवश कर सकती है। एक और भी तरीका है जिसमें मेयर पदच्युत किया जा सकता है और वह है प्रत्याह्वान (Recall) का। इसके लिए निर्वाचकों का एक तिहाई भाग याचिका रखता है और इस विषय को नगरपालिका के मतदाताओं के लिए उनके समक्ष रखा जाता है, यदि नियम मेयर के विरुद्ध होता है तो उन त्यागपत्र देना ही पड़ता है।

सहायक मेयर—मेयर के कर्तव्य पालन में सहायता के लिए एक सहायक मेयर की भी व्यवस्था की गई है जिसे मेयर ही नियुक्त करता है और वही उसे हटा भी सकता है। सहायक मेयर को उन सभी कार्यों को करना पड़ता है जो मेयर द्वारा उस सौंपे जाते हैं। मेयर के कर्तव्य प्रसार राजनीतिक और प्रशासनिक हैं और उसकी अनुपस्थिति में सहायक मेयर उसके सभी कार्य करता है।

मेयर के भी दोहर उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय मामलों पर विचार करता है और इसके लिए अपने प्रीफेक्चर के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता है। स्थानीय मामलों के लिए वह अपनी नगरपालिका का कार्यकारी अधिकारी है और इन बातों में वह स्थानीय अधिकारियों को नियुक्ति व पदच्युति करता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, नगरपालिका का बजट तैयार करता है तथा इसे समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करता है। सभी कर और शुल्क वसूल करना एवं सभी विनियोगों को लक्षात् परोक्ष भी

मेयर के ही कर्तव्य हैं। सकटकाल के दौरान मेयर उपनियमों के महत्व के विनियम जारी कर सकता है, विधिवत् प्राधिकृत कार्यों के लिए धन खर्च कर सकता है और बजट को कम कर सकता है।

नगर सभा (Municipal Assembly)—इसके सदस्यों का चुनाव जापान के उन नागरिकों द्वारा किया जाता है जो 20 वर्ष या अधिक की आयु के हों और उस इलाके के लगातार 3 मास तक निवासी रहे हों। नगर-सभा के प्रत्याशी की कम से कम आयु 25 है। नगर सभा की सदस्य संख्या कम से कम 12 और अधिक से अधिक 48 है। यह प्रकार जनसंख्या के अनुपात से बदलता रहता है। नगर-सभा के सदस्य इसका साथ डायट और प्रीफेक्चर की सभा के सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यों की अवधि 4 वर्ष की है और उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। कम आयुवादी वाले छोटे छोटे कस्बा और ग्रामों में निर्वाचकों की सामान्य बैठक ही नगर सभा का स्थान ले लेती है।

नगर-सभा का अधिवेशन वर्ष में 6 बार नियमित अधिवेशन का रूप में होता है। मेयर अथवा कुल सदस्यों के एक चौथाई भाग के कहने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। नगर-सभा को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह वाणिज्य बजट पेश करती है और अपने उपनियमों के उल्लंघन करने के लिए दण्ड निहित करती है। यह करारोपण भी करती है और सावजनिक सेवाओं के लिये शुल्क नियत करती है। सभा स्थानीय मामलों की जांच कर सकती है तथा स्थानीय अधिकारियों को गवाही देने के लिए अपने सामने पेश होने के लिए कह सकती है।

सारासरी में, जापान में नवीन संविधान के अन्तर्गत जिस प्रकार के स्थानीय प्रशासन के संगठन की परिकल्पना की गई है, वह लोकतन्त्रात्मक पद्धति के अनुकूल है।

राजनीतिक दल (POLITICAL PARTIES)

द्वितीय महायुद्ध के दौरान सन् 1940 में जापान में एक नवीन शासन प्रणाली स्थापित हुई, जिससे सना अत्यन्त शक्तिशाली स्थित में आ गई। सैनिक शासन के अन्तगत राजनीतिक दलों के समाप्त हो जाने से जापान में प्रजातन्त्र का प्रत्येक चिह्न मिट गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद जब 1947 में वर्तमान नवीन जापानी संविधान लागू हुआ तो राजनीतिक दलों का पुनर्स्थापन हुआ। वैसे यथाथ में इस संविधान के लागू होने से पूर्व ही प्राचीन राजनीतिक दल फिर से उत्पन्न होकर जोर पकड़ने लग गये थे। इन नवें राजनीतिक दलों ने नये सिरे से अपने संगठन स्थापित कर लिये और आज जापान में निम्न लिखित प्रमुख राजनीतिक दल वहाँ की राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं—

उदार प्रजातान्त्रिक दल (Liberal Democratic Party)

इस दल का जन्म उदार (Liberal) एवं प्रजातांत्रिक (Democratic) दलों को मिलाकर हुआ। इन दोनों ही दलों का विलय सन् 1955 में हुआ। इसके पूर्व यह दोनों पृथक्-पृथक् दल थे। नवीन दल अत्यन्त शक्तिशाली सिद्ध हुआ और वर्तमान जापान में इसका अति प्रमुख स्थान है। यही दल जापान का एकमात्र रूढ़िवादी दल है जिसका सम्बन्ध बड़े बड़े व्यापारियों और राजवश के लोग और शासन के अधिकारियों में है। संगठन की दृष्टि में यह केंद्रीभूत दल है। यद्यपि जिन्ता-मन्त्र पर एक स्थानाय स्तर पर इसका गान्धार्य है, लेकिन इसका स्थानीय संगठन विवक्षित नहीं है। सारा कार्य केंद्रीय संगठन के द्वारा ही संचालित होता है। दल के अधिकारियों में चार प्रमुख व्यक्ति होते हैं—प्रध्यक्ष (President), महासचिव (Secretary General) नीति अनुसंधान समिति का अध्यक्ष (Chairman of Policy Research) एवं कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष (Chairman of the Executive Council)। इसके प्रतिरिक्त एक परामर्शदाता भी होता है जिसको सम्मिलित करने पर इन पाँचों प्रमुख व्यक्तियों का 'हार्ड केम्प' बनता है। पदाधिकारियों में प्रध्यक्ष का पद बड़ा महत्त्व का होता है। प्रध्यक्ष का निर्वाचन में एक सहायक वस्तु यह है कि वह सम्पूर्ण और प्रभावशाली रहता है। प्रायः धरणी प्राप्त उच्च नरवास अधिकार इस पद के लिए

अधिक उपयुक्त माना जाता है। महासचिव दल का प्रमुख प्रवक्ता होता है जिसका मुख्य कार्य धन संग्रह करना होता है।

दल के प्रत्येक सदस्य को 200 येन चन्दा प्रति वर्ष देना पड़ता है। चूंकि यह सदस्यता शुल्क कुछ भारी पड़ती है, अतः अपेक्षाकृत कुछ अधिक सम्पन्न वर्ग के लोग ही दल की सदस्यता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। दल के सदस्यों में अधिकांश व्यक्ति व्यावसायिक राजनीतिज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त देहाती के कृषक वर्ग के बड़े प्रतिनिधि, नगरों के बाणिज्य एवं उद्योग संस्थानों के स्वामी, लघु उद्योगों के कमचारी, उच्च-स्तर के प्रशासकीय अधिकारी, वकील, पत्रकार आदि इसके सदस्य होने हैं।

सद्भाषितिक दृष्टि से यह दल अनुदार एवं प्रतिक्रियावादी है और युद्ध पूर्व की सामाजिक राजनीतिक एवं सर्वेधानिक स्थिति को पुनः स्थापित करना चाहता है। दल स्थानीय स्वायत्त शासन के विरुद्ध है और स्वयं लोकसेवा व्यवस्था का समर्थक भी नहीं है। इस प्रकार यह दल केन्द्रीयभूत स्थानीय शासन और पूर्ण रूपेण शासनाधीन लोकसेवा स्थापित करने के पक्ष में है। लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का यह समर्थक है। यद्यपि युद्ध स्थान का यह समर्थन करता है तथापि राष्ट्रीय शस्त्रीकरण को भी आवश्यक मानता है। इसके साथ ही यह दल व्यापार स्वातन्त्र्य एवं व्यक्तिगत उपक्रम का समर्थक है एवं पूर्ण स्वतन्त्र न्याय पालिका का विरोधी। परन्तु इतनी अनुदार नीतियों को रखते हुए भी लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का यह विरोधी नहीं है। जन-साधारण के जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए यह लोक-स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध एवं अमहाय्य व्यक्तियों के लिए सहायता साधारण मूल्य की भावना व्यवस्था आदि पर जोर देता है। उद्योगों को यह इस आधार पर व्यवस्थित करना चाहता है जिससे जनहित नर्वातम रूप में हो सके।

विदेश-नीति की दृष्टि से यह दल रूस विरोधी और अमेरिका समर्थक दृष्टिकोण लिए हुए है। अमेरिका के साथ जापान के सहयोग की इच्छा रखते हुए उसके साथ रक्षा संधि का भी यह समर्थक है। इस दल की माँग है कि रूस द्वारा कुरारन द्वीप जापान का लौटा दिया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्वतन्त्रता के लिए प्रयासों का समर्थन करते हुए यह दल एवं पूर्ण आत्मनिर्भर एवं प्रत्येक दृष्टि से स्वतन्त्र जापान की स्थापना का पाथन है। अन्य देशों के साथ जापान के व्यापार में वृद्धि को भी यह दल रक्षित करता है। व्यापारिक दृष्टि से साम्यवादी चीन के साथ सहयोग करने का भी यह पक्षपाती है। अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए भी इस दल की माँग है कि जापान स्थित अमेरिकन मनिन प्रहृडा का समाप्त कर दिया जाना चाहिए। समाजवादी दल (The Socialist Party)

जापान का समाजवादी दल देश का दूसरा दल है। यह दल गुगु म

विभाजित है—दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग गुट दल को प्रजातन्त्र समाजवादी-दल और वाम मार्ग गुट का जापान समाजवाद कहते हैं। यह विभाजन मनु 1958 में हुआ था।

दक्षिण मार्ग दल सशक्ति सधि और उसमें सम्बन्धित जापान अमेरिका सुरक्षा सधि एवं सीमित पुनश्चस्त्रीकरण का समर्थक है जबकि वाम मार्ग इसका विरोध करता है। परन्तु इन अंतरों के होते हुए भी संगठन की दृष्टि से दोनों दलों के संगठन में एकरूपता है। दोनों के संगठनों में केन्द्रीय कार्यपालिका समिति एवं उसका सभापति, महासचिव, नीति निर्देश समिति एवं उसका सभापति तथा कार्यवाहक होते हैं। समाजवादी दल में उदार प्रजातांत्रिक दल के समान कोई अध्यक्ष (President) नहीं होता। दल में केन्द्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार के संगठन सुदृढ़ हैं। स्थानीय संगठन और केन्द्रीय कार्यालयों का सम्बन्ध भी बहुत नजदीक का है। इस दल को धर्मिका का भारी सख्या में समर्थन प्राप्त है। दल के सदस्यों में प्रोफेसर, लेखक, छात्र, लिपिक वगैरह विभिन्नता एवं अल्प-व्ययनभोगी व्यक्ति सम्मिलित हैं।

समाजवादी दल पूर्ण नियोजन, लोक कल्याण में सुधार, निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, एवं स्वतन्त्र विदेशी नीति के संचालन का पक्षपाती है। यह दल अग्रगण्यता के प्रशिक्षण का निषेध करता है। दल चाहता है कि चीन को साम्यता मिल जाए और उसके साथ जापान का अधिकाधिक व्यापार हो। एशियायी अफ्रीकाय देशों के साथ जापान के सम्बन्धों को दृढ़ करने का भी यह पक्षपाती है। रूस चीन और अमेरिका के साथ सामूहिक सुरक्षा सधि के निमाण पर भी यह दल जोर देता है।

साम्यवादी दल (The Communist Party)

साम्यवादी दल देश का प्राचीन दल है। इसका दावा है कि यह दल जापान में 1922 से नियमित रूप से मौजूद रहा है। 1949 में इस दल का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इसने डायट में 63 स्थान प्राप्त किए थे। इसकी सदस्य सख्या भी उस समय लगभग एक लाख थी लेकिन बाद में इस दल का ह्रास होता गया। 1952 में इसकी सदस्य सख्या केवल 50 हजार ही रह गई और डायट में भी यह कोई स्थान ग्रहण नहीं कर सका। आजकल इस दल के समर्थक जापान में रहने वाले कुछ मन्थुरियावासी ही हैं जो अत्यन्त अल्पसंख्या में हैं और साम्यवादी दल का समर्थन अपनी उन कटु भावनाओं के कारण करते हैं जिनका जन्म उसमें उस समय हुआ था जब जापानियों ने उनका शोषण किया था। जापान में साम्यवादी दल के पक्ष में सक्ने का कारण सोवियत रूस पक्षपाती विचार और नास्तिक दृष्टिकोण है।

उपयुक्त प्रमुख दलों ने अतिरिक्त जापान में ग्रोन प्रोजेक्सायटी एवं कुछ संगठन और भी हैं। ग्रोन संगठनों में प्रबंधकों का संगठन (Japan Management Association), मालिकों के सघों का फेडरेशन (Japan

Federation of Employers Association), जनरल काउंसिल का ट्रेड यूनियन कांग्रेस (General Council of Trade Union Congress), जापान फार्मर्स यूनियन (Japan Farmers Union) आदि मुख्य हैं।

राजनीतिक दलों का संगठन और स्वरूप

जापान के सभी दलों का संगठन मोट रूप में एक सा है। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता दिखलाई देती है। सभी दलों की प्रेसीडेन्सी (Presidencies) हैं और सभी के निदेशालय (Directorates) हैं। उनके अन्तर्गत विभाग (Inner Core) भी हैं। अनुशासन और वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है।

जापान के राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में संविधान मौन है। यह व्यवस्था अमेरिकन और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था जैसी है। इस सम्बन्ध में चिंतोशी यानागि ने ठीक ही लिखा है कि स्वयं दल की यद्यपि संविधान में कोई ज़रूरी नहीं है तथापि संविधान की मायता इस बारे में स्पष्ट है, क्योंकि राजनीतिक दलों के अभाव में उत्तरदायी संसदीय सरकार का न तो अस्तित्व ही रह सकता है और न उसका संचालन ही सम्भव है। जापान के राजनीतिक दलों में व्यक्तियों का महत्त्व अधिक काम करता है। नेताओं को काफी मायता दी जाती है। नेताओं के व्यक्तिगत टकराव तथा व्यक्तित्व के आधार पर दलों की आंतरिक गुट-बन्दी चलती रहती है। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ प्राप्त करने के ढंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे युद्ध से पहले थे। दलों पर पार्ष्वात्य सम्मति का भी स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता है। अमेरिकन और ब्रिटिश अनुकरण तथा प्रभाव के होते हुए भी दलीय जीवन का वह आधार प्राप्त नहीं किया जा सका है जो अमेरिका और ब्रिटेन में पाया जाता है। दलों का रूप क्षेत्रीय अधिक और राष्ट्रीय कम है किन्तु अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय रूप धारण बिना जीवित नहीं रह सकता।

जापान की दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

Main Features of Japanese Party System

(1) धर्म निरपेक्षता—जापानी दलों के निर्माण और पारस्परिक व्यवहार में धार्मिक आधार को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। दलों के संगठन और विस्तार में धर्म का कोई मुख्य हाथ नहीं है।

(2) दलों की बहुतायत—जापान बहुदल प्रणाली का देश है। द्वितीय महायुद्ध के बाद होने वाले प्रथम चुनाव में लगभग 260 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इनके अलावा और भी सैकड़ों राजनीतिक संगठन थे। वास्तव में जापानी राजन स्वभाव के कारण घनत्व और विभिन्नता के

नीकीन हैं। वे छोटे छोटे मतभेदों के आधार पर राजनीतिक दलों का संगठन कर लेते हैं। दलों का केन्द्रीय आधार व्यक्ति अथवा नेता होता है अतः उनके बनने बिगड़ने का क्रम चलता रहता है। प्रत्येक दल अपने को नवीनतम मिश्र करने के प्रयत्न में लगा रहता है।

(3) गुट-बन्धो—दलों में बहुत अधिक गुटबन्धी पाई जाती है जिसके कारण राजनीतिक आवागमन काफी व्याप्त है। इस गुटबन्धी और दलों की अस्थिरता के कारण कोई भी एक दल प्रायः सरकार बनाने की मुश्किल स्थिति में नहीं होता। यही कारण है कि जापान में प्रायः मिश्रित या सम्मिलित सरकारें (Coalition Government) ही बनती रही हैं।

(4) पूँजीपतियों एवं राजनीतिक दलों में गठजोड़—जापान में बड़े बड़े पूँजीपतियों और व्यवसायियों तथा राजनीतिक दलों में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। एकाधिकारी पूँजीवाद के साथ दलीय गठबन्धन के कारण सरकारी नीतियाँ प्रायः बड़े बड़े उद्योगों और व्यवसायों के अनुकूल रहती हैं। सरकार और दलों को धन के लिए भी प्रायः उही पर निर्भर रहना पड़ता है।

(5) दलों पर नौकरशाही का प्रभाव—राजनीतिक दलों पर नौकरशाही का काफी प्रभाव पाया जाता है। दलों में सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में निरन्तर प्रवेश करते रहते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक दलों का कर्मचारी-स्तरीकरण हो गया है। दलों में सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव के कारण डायट में भी नौकरशाही का प्रभाव बहुत बढ़ गया है।

अन्त में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जापान में ढेर सारे दल हैं किन्तु विशेष रूप से प्रमुखता दो ही दलों को प्राप्त है—उदार प्रजातान्त्रिक दल (Liberal Democratic Party) तथा समाजवादी दल (The Socialist Party)। ये दोनों ही दल डायट में प्रमुख रूप में सक्रिय रहते हैं। फिर भी जापान द्वि-दलीय व्यवस्था की देश नहीं माना जा सकता। जापानी लोगों की प्रवृत्ति और परम्परा को देखते हुए निकट भविष्य में यह सम्भावना नहीं दिखाई देती कि वहाँ द्वि-दलीय व्यवस्था पनप सकेगी।

EXERCISES

- 1 Describe the important characteristics of the Modern Constitution of Japan

जापान के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

- 2 Briefly describe the rights and duties granted to the citizens by the Japanese Constitution Add a short note on the Laws of Citizenship

जापानी नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों व कर्तव्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । नागरिकता पर एक छोटा नोट दीजिये ।

- 3 "Japanese Emperor rules but does not govern" Discuss the position of Emperor under present Constitution

"जापान का सम्राट राज्य करता है शासन नहीं ।" वर्तमान संविधान के अन्तर्गत जापानी सम्राट की स्थिति को स्पष्ट कीजिये ।

- 4 Explain the position, functions and powers of the Emperor in the present Constitution of Japan Compare and contrast his position with that of the King in England

जापान के वर्तमान संविधान के अन्तर्गत सम्राट की स्थिति, उसके कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन कीजिये । इंग्लैंड के राजा की स्थिति के साथ जापानी सम्राट की स्थिति की तुलना भी कीजिये ।

- 5 Describe the organisation and working of Japanese Cabinet under the present Constitution

वर्तमान संविधान के अन्तर्गत जापान की कैबिनेट के संगठन तथा कार्य-विधि का वर्णन कीजिए ।

- 6 What are the nature, size and composition of the Japanese Cabinet after the Second World War ? Also describe its organisation and working

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की जापान की कैबिनेट के स्वरूप, आकार और उसकी रचना क्या रही है ? इसके अंगों और इसकी कार्यप्रणाली का भी वर्णन कीजिये ।

- 7 How is the Prime Minister of Japan appointed ? Describe his powers and functions.

जापान के प्रधानमंत्री का नियुक्ति किस प्रकार होता है ? उनका अधिकार एवं कार्य का वर्णन कीजिये ।

- 8 Describe the composition, organisation and powers of the Imperial Diet under the present Constitution of Japan
जापान के वर्तमान संविधान के अंतर्गत इम्पीरियल डायट की रचना, संगठन और उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिये।
- 9 Give an account of the Committee System in the Japanese Diet
जापान की डायट में विभिन्न प्रकार की समितियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिये।
- 10 How a bill becomes an act in Japanese Parliament ? What ways the procedure differs in case of money bills ? जापानी संसद के विधेयक किस प्रकार पारित होते हैं ? वित्तीय विधेयकों के सम्बंध में क्या विशेषता रहती है ?
- 11 Describe the various functions of the Diet and briefly explain the relationship between the two houses of Parliament
डायट के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये तथा संसद में दोनों सदन के आपसी सम्बंधों को स्पष्ट कीजिये।
- 12 Describe the function of the Speaker of the House of Representatives. How does he differ from the speaker of the British House of Commons ?
प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के कृत्यों का वर्णन कीजिए। वह ब्रिटिश लोक-सभा के अध्यक्ष से कहाँ तक भिन्न है ?
- 13 Discuss briefly the organisation and jurisdiction of the courts in Japan and how far do you think it works as the guardian of the Constitution ?
जापान के न्यायालयों के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिये। यह न्यायपालिका कहाँ तक संविधान की संरक्षक है ?
- 14 Describe the organisation and functions of the Local Government in Japan
जापान में स्थानीय स्वशासन की समस्याओं के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।
- 15 Give an account of the special features of Japanese Party System
जापानी दल व्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों का विवरण दीजिये।
- 16 Describe some of the Major Political Parties of Japan
जापान के प्रमुख राजनीतिक दलों में से कुछ का वर्णन कीजिये।

SELECTED READINGS

- 1 Bisson, T A Shadow over Asia (1941)
- 2 Colegrove, K W The Constitution Development of Japan (1951)
- 3 Douglas V Verney The analysis of Political Systems (1959)
- 4 Embree, J F The Japanese Nation A Social Survey (1945)
- 5 E Dening Japan
- 6 Francis Low Struggle for Asia (1955)
- 7 Francis, J Horner A Case History of Japan (1948)
- 8 G Lowell Field Governments in Modern Society (1959)
- 9 G T Trewartha Japan A Physical, Cultural and Regional Geography (1945)
- 10 Gunther John Inside Asia (1942)
- 11 Hinton Ike, Palmer, Major Governments of Asia Callard & Kahn (1958)
- 12 Ito Commentaries on the Constitution (Tokyo 1889)
- 13 Iko Nobutaka The Beginnings of the Political Democracy in Japan (1950)
- 14 J Monaki The Governments and Politics of Japan
- 15 Kitazawa N The Government of Japan (1929)
- 16 Kikuo Nakamura and Political Hand book of Japan Yutaka Matsumura (1958)
- 17 arger, Chu and Far Eastern Governments and Burks Politics China and Japan (1954)
- 18 Nanporia N J Japan's Pacific Adventure (1946)
- 19 Norman, E Herbert Japan's Emergence as a Modern State
- 20 Pannikar K M Asia and Western Domin (1959)

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 21 | Quigley, H S | Japanese Government and Politics (1932) |
| 22 | Quigley, H S | The New Japan Government and Politics (1950) |
| 23 | Reischauer, R K | Japan Government and Politics (1939) |
| 24 | Reischauer E O | Japan Past and Present (1947) |
| 25 | Rodger, S and Paul, L | Red Flag in Japan International Commission in Action (1952) |
| 26 | Janin and Yohan | Militarism and Fascism in Japans (1934) |
| 27 | Uyehara | Political Development of Japan (1867-1909) |

